

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DTATE	SIGNATURE

भारतीय कृषि का अर्थतन्त्र

(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा
डॉ० राजेन्द्रप्रसाद पुरस्कार 1978 से पुरस्कृत)

लेखक

डॉ० एन० एल० अग्रवाल

कृषि धर्मशास्त्र विभाग

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय

श्री क० न० कृषि महाविद्यालय

जोधनेर (जयपुर-राजस्थान)



राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
जयपुर

मानव ससाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रन्थ-निर्माण योजना के अन्तर्गत, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर द्वारा प्रकाशित ।

प्रथम संस्करण 1977

द्वितीय संशोधित व परिवर्द्धित संस्करण 1983

तृतीय संशोधित व परिवर्द्धित संस्करण 1986

चतुर्थ संशोधित व परिवर्द्धित संस्करण 1990

पञ्चम संशोधित व परिवर्द्धित संस्करण, 1993

Bhāratīya Kṛishi Ka Arthatantra

1 S B N 81-2137-114-0

मूल्य ₹20.00 रुपये

© सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन

प्रकाशक

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

ए-26/2, विद्यानगर मार्ग, तिलक नगर

जयपुर-302 004

मुद्रक

जेफ प्रिन्टर्स

पी. 47, मधुबन पश्चिम द्वितीय

किसान मार्ग, टोक रोड, जयपुर ।

प्रकाशनीय भूमिका No

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी अपनी स्थापना के 24 वर्ष पूरे करके 15 जुलाई, 1993 को 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इस अवधि में विश्व साहित्य के विभिन्न विषयों के उत्कृष्ट ग्रन्थों के हिन्दी अनुवाद तथा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर के मौलिक ग्रन्थों को हिन्दी में प्रकाशित कर अकादमी ने शिक्षकों, छात्रों एवं अन्य पाठकों की सेवा करने का महत्वपूर्ण कार्य निभाया है और इस प्रकार विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी में शिक्षण के मार्गों को सुगम बनाया है।

अकादमी की नीति हिन्दी में ऐसे ग्रन्थों का प्रकाशन करने की रही है जो विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अनुकूल हों। विश्वविद्यालय स्तर के ऐसे उत्कृष्ट मानक ग्रन्थ जो उपयोगी होते हुए भी पुस्तक प्रकाशन की व्यावसायिकता की दौड़ में अपना समुचित स्थान नहीं पा सकते हों, और ऐसे ग्रन्थ भी जो अग्रणी की प्रतियोगिता के सामने टिक नहीं पाते हों, अकादमी प्रकाशित करती है। इस प्रकार अकादमी ज्ञान विज्ञान के हर विषय में उन दुर्लभ मानक ग्रन्थों को प्रकाशित कर रही है और करेगी जिनको पाकर हिन्दी के पाठक लाभान्वित ही नहीं गौरवान्वित भी हो सकें। हमें यह कहते हुए हर्ष होता है कि अकादमी ने 375 से भी अधिक ऐसे दुर्लभ और महत्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन किया है जिनमें एकाधिक केन्द्र राज्यों के बोर्डों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत किये गये हैं तथा अनेक विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा अनुससित।

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी को अपने स्थापना काल से ही भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय से प्रेरणा और सहयोग प्राप्त होता रहा है तथा राजस्थान सरकार ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अतः अकादमी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में दोनों सरकारों की भूमिका के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है।

‘भारतीय कृषि का अर्थतंत्र’ के संशोधित व परिवर्द्धित पंचम संस्करण को प्रकाशित करते हुए हमें अत्यधिक प्रसन्नता है। पुस्तक के प्रथम संस्करण का घन्टा स्वागत हुआ और इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा ‘डॉ० राजेन्द्रप्रसाद पुरस्कार’ से पुरस्कृत किया गया। प्रस्तुत पुस्तक अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र आदि विषयों के स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों, राष्ट्रीय स्तर की

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों एवं अध्यापकों हेतु पर्याप्त लाभप्रद सिद्ध हुई है तथा हमें आशा है कि अपने नवीन रूप में और भी अधिक उपयोगी सिद्ध होगी। पुस्तक में कुछ दोष भी विभिन्न समर्याओं उनके निराकरण के उपाय, सम्बन्धित सरकारी नीतियों आदि का निवेदन तत्पश्चात् एव सुयोग शैली में किया गया है।

हम इसके रीतन डॉ० एन० एल० अग्रवाल, जोबनेर में प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं।

(डॉ. वेदप्रकाश)

निदेशक

राजरथान हिन्दी ग्रन्थ भण्डार

जयपुर

पंचम संस्करण की भूमिका

पुस्तक के चतुर्थ संस्करण को कृषि के स्नातक, ग्रंथशास्त्र के स्नातकोत्तर एवं विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा उत्साहपूर्वक स्वागत के कारण प्रस्तुत पंचम संस्करण अतिशीघ्र बाजार में आ सका है। पुस्तक के इस संस्करण में नवीनतम आंकड़ों का समावेश करके अनेक अध्यायों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। कुछ अध्यायों में नवीनतम सामग्री—नई कृषि नीति, आठवीं पंचवर्षीय योजना, बेरोजगारों के लिए सृजित ऋण व्यवस्थापन के 'पी' सिद्धान्त एवं कृषि उत्पादों के वैज्ञानिक विपणन नियम सम्मिलित की गई है। आशा है पुस्तक के इस संस्करण का भी विभिन्न स्तर की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्रों द्वारा उत्साहपूर्वक स्वागत किया जायेगा।

—एन. एल. अप्रवाल

चतुर्थ संस्करण की भूमिका

पुस्तक के तृतीय संस्करण का भी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा उत्साहपूर्वक स्वागत के कारण अल्पकाल में सशोधित करके चतुर्थ संस्करण प्रस्तुत करते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है। पुस्तक के इस संस्करण में नवीनतम ग्रंथों एवं सरकार की घोषित नीति के अनुसार सशोधन करने के अतिरिक्त अनेक अध्यायों में नवीनतम सामग्री भी सम्मिलित की गई है, जैसे—जवाहर रोजगार योजना, लागत सकल्पना के नए आधार, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, हरित क्रांति आदि। 'भारत में गरीबी' का नया अध्याय जोड़ा गया है। आशा है पुस्तक के इस संस्करण का भी कृषि स्नातकों एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों तथा कृषि विकास एवं नीति से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा स्वागत किया जावेगा।

एन. एल. अग्रवाल

मई, 1990

तृतीय संस्करण की भूमिका

पुस्तक के द्वितीय संस्करण का विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा उत्साहपूर्वक स्वागत करने के कारण पुस्तक का यह संस्करण दो वर्ष के अल्पकाल में ही समाप्त हो जाने के फलस्वरूप आवश्यक सशोधन करके तृतीय संस्करण प्रस्तुत करते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है। पुस्तक के इस संस्करण में नवीनतम ग्रॉफ़ों एवं सरकार की वर्तमान नीति को सम्मिलित करके पाठकों की आवश्यकता एवं आशा के अनुकूल बनाने का प्रयास किया गया है। बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का नया अध्याय भी जोड़ा गया है।

आशा है कि पुस्तक के इस संस्करण का भी बी० एस-सी० कृषि, एम० एस-सी० कृषि, अर्थशास्त्र, एम० ए० अर्थशास्त्र, विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि वित्त अधिकारी के चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले तथा कृषि विकास एवं कृषि नीति से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा स्वागत किया जावेगा।

एन. एल. अग्रवाल

द्वितीय संस्करण की भूमिका

पुस्तक के प्रथम संस्करण का विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा उत्साहपूर्वक स्वागत करने के परिणामस्वरूप, पुस्तक का प्रथम संस्करण अल्पकाल में ही समाप्त हो गया। पुस्तक के प्रथम संस्करण को विश्वविद्यालय स्तर के कृषि विषय का मानक ग्रन्थ हिन्दी भाषा में उच्चकोटि का स्वीकार करते हुए, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली द्वारा डा० राजेन्द्रप्रसाद पुरस्कार 1978 प्रदान किया गया है। विद्यार्थियों के उत्साह एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त पुरस्कार से प्रेरित होकर पुस्तक का द्वितीय संस्करण पाठकों की आवश्यकतानुसार सशोधित करके प्रस्तुत कर रहा हूँ।

पुस्तक के इस संस्करण में कृषि क्षेत्र में हो रहे द्रुतगति से विकास, उपलब्ध साहित्य एवं विश्वविद्यालयों एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुकूल सशोधन किया गया है। पुस्तक में नवीनतम आँकड़ों को सम्मिलित करके भी पाठ्य-समग्रों को पाठकों की आवश्यकता एवं आशा के अनुकूल बनाया गया है। पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में नए विषयों—बागदा बाजार, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में अधिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु गुरु की गई योजनाएँ जैसे ग्राम अभिग्रहण योजना, बहुभूमिकरण पहुँच, अन्तरीय व्याज दर नीति, कृषक सेवा समितियाँ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नावाइँ, राष्ट्रीय कृषि आयोग की विभिन्न क्षेत्रों में की गई सिफारिशें, कृषि श्रमिकों के विकास के लिए गुरु की गई योजनाएँ एवं छठी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य एवं परिचय को समाविष्ट किया गया है। कृषि क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान के उपयोग से बढ़ती हुई जोखिम एवं कृषि के क्षेत्र में मिनजुन कर कार्य करने के महत्व के परिप्रेक्ष्य में पुस्तक में 'कृषि बीमा' एवं 'भारत में सहकारिता' अध्याय जोड़े गए हैं। पुस्तक के अध्याय 2, 3, 4, 10 एवं 20 को नवीनतम ज्ञान परिप्रेक्ष्य के सन्दर्भ में पुन लिखा गया है।

आशा है कि पुस्तक के इस संस्करण का भी शिक्षकों, बी० एस-सी० कृषि, एम० ए० अर्थशास्त्र, एवं विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं—भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय आर्थिक सेवाओं में कृषि अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों एवं कृषि-विक्रम व कृषि नीति में सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा स्वागत किया जाएगा।

प्रथम संस्करण की भूमिका

भारत जैसे विकासोन्मुख देश के आर्थिक विकास के लिए कृषि का विकास आवश्यक है। कृषि-विकास द्वारा ही ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति एवं औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था का निर्माण सम्भव है। कृषि विकास का स्तर ही देश की उन्नति का सूचकांक एवं आर्थिक सृद्धि का प्रतीक होता है। वर्तमान में कृषि-परिवर्तनों के सन्दर्भ में कृषि से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के प्रामाणिक साहित्य का हिन्दी भाषा में अभाव है। राष्ट्रभाषा के माध्यम से कृषि-शिक्षा प्रदान करने में पाठ्य-पुस्तकों का यह अभाव विद्यार्थियों एवं प्राध्यापकों के सम्मुख प्रमुख समस्या है।

प्रस्तुत पुस्तक 'भारतीय कृषि का अर्थशास्त्र' स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों की पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी आवश्यकता को ध्यान में रखकर लिखी गई है। इसमें भारतीय कृषि की विभिन्न समस्याओं एवं उनके समाधान से सम्बन्धित प्रामाणिक तथ्यों एवं सरकार की नीतियों का तर्कपूर्ण विवेचन किया गया है। कृषि समस्याओं से सम्बन्धित शोध-परिणामों को भी पुस्तक में समाविष्ट किया गया है, जिससे आधुनिक प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में विद्यार्थियों को सही जानकारी प्राप्त हो सके। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग करते हुए पाठ्यसामग्री को तर्कसंगत, सुसम्बद्ध एवं व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत किया गया है।

देश के सभी विश्वविद्यालयों में कृषि अर्थशास्त्र एवं फार्म-व्यवस्थापन विषय कृषि-स्नातक एवं कृषि-अर्थशास्त्र स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में अनिवार्य विषय तथा एम. ए. अर्थशास्त्र में वैकल्पिक विषय के रूप में सम्मिलित है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कृषि-अर्थशास्त्र एक वैकल्पिक विषय होता है। प्रस्तुत रचना कृषि-अर्थशास्त्र, फार्म व्यवस्थापन, कृषि-वित्त एवं कृषि विपणन व कीमतें विषय पर हिन्दी में उपलब्ध साहित्य के अभाव की पूर्ति की ओर एक प्रयास है। आशा है, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार एवं हरियाणा राज्यों के विद्यार्थियों के लिए जहाँ हिन्दी माध्यम से स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कृषि-अर्थशास्त्र, फार्म-व्यवस्थापन, कृषि वित्त एवं कृषि विपणन व कीमतें विषय का अध्ययन-अवधान किया जाता है, वहाँ यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी।

पुस्तक में सरल हिन्दी का प्रयोग किया गया है जिससे पाठ्यसामग्री को सहज में ही समझा जा सके। साथ ही विषय-ज्ञान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को निरन्तर बनाये रखने का पूरा ध्यान रखा गया है। तकनीकी शब्दों का हिन्दी रूपान्तर

भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित शब्दावली के अनुरूप किया गया है। अन्य शब्दों का हिन्दी रूपान्तर 'फादर कामिल बुल्के' के अंग्रेजी-हिन्दी कोष के आधार पर किया गया है। पाठकों की सुविधा के लिए पुस्तक के अन्त में पारिभाषिक शब्दावली दी गई है।

पुस्तक लेखन की अनुज्ञा प्रदान करने एवं आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए उदयपुर विश्वविद्यालय (वर्तमान में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय) के कुलपति का मैं हृदय से आभारी हूँ। डा० भार एम सिंह एवं डा० भार एस. रावत अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, जोबनेर द्वारा प्रदत्त मार्ग-दर्शन एवं प्रेरणा के लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापन कर उद्धरण नहीं हो सकता। मैं डॉ० एस एस आचार्य, सह-प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, कृषि अर्थशास्त्र का विशेष आभारी हूँ जिन्होंने पाण्डुलिपि के कई अध्यायों में अपने सुझावों से मुझे लाभान्वित किया है।

उन सभी विशेषज्ञों एवं साथियों, विशेष रूप से डॉ० बी एस राठौड़ प्राध्यापक, श्रीगिरीशचन्द्र, सहायक प्राध्यापक, श्री भार बी सिंह, सहायक निदेशक अनुसन्धान के निष्कास सहयोग, प्रोत्साहन एवं रचनात्मक सुझावों के लिए भी कृतज्ञता प्रदर्शित करता हूँ। लेखन में सहयोग के लिए श्री सीताराम पारीक, डॉ० रामचन्द्र वर्मा, डॉ० माहनलाल पुरोहित एवं अनेक विद्यार्थी भी धन्यवाद के पात्र हैं। पुस्तक लेखन में जिन विद्वानों की कृतियों का उपयोग किया गया है उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूँ।

पुस्तक के समीक्षक डा सी. एस बरसा, अर्थशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूँ जिनके सुझावों से मुझे बहुत लाभ हुआ।

मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों का ऋणी हूँ जिन्होंने इस कार्य को समय पर पूरा करने एवं कार्य में आई कठिनाइयों में बचाने के लिए मुझे हर सम्भव सहयोग देकर मुसीबतों का स्वयं सामना किया है।

पुस्तक में कुछ कमियों एवं त्रुटियों का रह जाना स्वामाविक है। प्रबुद्ध पाठकों से अनुरोध है कि इस रचना की अधिक उपयोगी बनाने एवं कमियों/त्रुटियों को दूर करने के लिए रचनात्मक सुझाव देकर अनुग्रहीत करें।

जोबनेर

ज्येष्ठ पूर्णिमा, 2034

जून, 1, 1977

एन. एत, अप्रवान

कृषि यन्त्रीकरण एवं हरित क्रान्ति का कृषि श्रम पर प्रभाव 145	
कृषि श्रमिकों का प्रवसन 151	
पूँजी 151	
कृषि पूँजी अधिग्रहण के स्रोत 152	
कृषि पूँजी के प्रकार 154	
प्रबन्ध 155	
कृषि व्यवसाय में कुशल प्रबन्ध की आवश्यकता 156	
कृषि प्रबन्ध/व्यवस्थापक के गुण 157	
5. फार्म प्रबन्ध—परिभाषा एवं क्षेत्र 158-170	
फार्म एवं प्रबन्ध की परिभाषा 158	
फार्म प्रबन्ध के उद्देश्य 162	
फार्म प्रबन्ध का कृषि विज्ञान के अन्य विषयों से सम्बन्ध 164	
फार्म प्रबन्ध का क्षेत्र 166	
कृषि व्यवसाय की सफलता के नियम 167	
6. फार्म प्रबन्ध के सिद्धान्त 171-226	
प्रतिफल का सिद्धान्त 171	
न्यूनतम लागत का सिद्धान्त/साधनों या क्रियाओं के प्रतिस्थापन का सिद्धान्त 193	
सम-सीमान्त प्रतिफल का प्रतिफल अथवा सीमित-साधन और भवित्तर परिवर्त्य वैकल्पिक लागत का सिद्धान्त 205	
लागत का सिद्धान्त 208	
उद्यमों के संयोग/प्रतिस्थापन का सिद्धान्त 212	
तुलनात्मक समय का सिद्धान्त 221	
तुलनात्मक लाभ का सिद्धान्त 225	
7. फार्म-योजना एवं बजट 227-252	
फार्म-योजना एवं फार्म बजट अर्थ, आवश्यकता 228	
फार्म-योजना एवं बजट की विधि 233	
रेखीय प्रोग्रामिंग 240	
लागत संकल्पना 250	
8. कृषि के विभिन्न रूप एवं प्रणालियाँ 253-280	
कृषि के रूप एवं कृषि प्रणालियों से तात्पर्य 253	
कृषि के विभिन्न रूपों का वर्गीकरण 256	
कृषि के रूप 257	
कृषि प्रणालियाँ 272	

9. कृषि-वित्त	281-298
कृषको के लिए ऋण की आवश्यकता 282	
कृषि ऋण का वर्गीकरण 282	
कृषि ऋण की समस्याएँ 286	
कृषि में पूँजी एवं ऋण की आवश्यकता 287	
ग्रामीण ऋणश्रृंखला 292	
10 कृषि ऋण के स्रोत	299-360
कृषि ऋण प्राप्ति के प्रमुख स्रोत 299	
कृषि ऋण के प्रमुख सत्यागत भूमिकरण 302	
कृषि ऋण के गैर-सत्यागत या निजी भूमिकरण 353	
रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया 357	
कृषि ऋण की विपणन से सम्बद्धता 358	
11 ऋण-प्रबन्ध के सिद्धान्त	361-380
ऋण-प्रबन्ध के 'भार' सिद्धान्त 362	
ऋण प्रबन्ध के 'भार' सिद्धान्तों की जाँच करने की विधि 363	
ऋण-प्रबन्ध के 'सी' सिद्धान्त 378	
12 कृषि विपणन	381-405
कृषि-विपणन की परिभाषा एवं उद्देश्य 380-82	
कृषि-विपणन का आर्थिक विकास में महत्त्व 385	
बाजार मण्डी 387	
विपणन मध्यमन के दृष्टिकोण 397	
खाद्यान्न के विपणन में पाये जाने वाले विपणन-मध्यस्थ 398	
कृषको का उत्पादन-भविष्य 400	
विपणन-माध्यम 403	
13 विपणन-कार्य	406-439
विपणन कार्य का वर्गीकरण 407	
पैकेजिंग/सुवेष्टन 408	
परिवहन 409	
श्रेणीचयन, मानकीकरण एवं किस्म नियन्त्रण 412	
संग्रहण एवं भण्डार व्यवस्था 421	
वित्त-व्यवस्था 428	
परिष्करण/प्रोसेसिंग 428	
नय-विक्रय 429	

जोखिम-बहुन	434
कीमत-निर्धारण एवं कीमतों का पता लगाना	436
विपणन-सूचना सेवा	437
14 विपणन लागत, विपणन-लाभ एवं विपणन दक्षता	440-461
विपणन-लागत	440
विपणन-लाभ	444
विपणन-दक्षता	456
15 भारत में कृषि विपणन-व्यवस्था	462-497
वर्तमान कृषि विपणन-व्यवस्था के दोष	462
कृषि विपणन व्यवस्था के दोष निवारण के उपाय	465
नियन्त्रित मण्डिया	466
सहकारी-विपणन समितियाँ	478
भारतीय मानक संस्था	490
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय	491
कृषि विपणन के क्षेत्र में पारित प्रमुख अधिनियम	493
सादासो के थोक व्यापार का सरकार द्वारा अधिग्रहण	495
16. कृषि-कीमतें एवं उनमें उतार-चढ़ाव	498-522
कृषि कीमतों से तात्पर्य एवं कार्य	498
कृषि कीमतों के अध्ययन की आवश्यकता	500
कृषि कीमतों में उतार-चढ़ाव	502
कीमत-स्फीति	521
17 कृषि-कीमत स्थिरीकरण एवं कृषि कीमत नीति	523-544
कृषि कीमत स्थिरीकरण	523
कृषि कीमत नीति	535
18. कृषि-उत्पादों की कीमत-निर्धारण	545-562
कृषि कीमतों के निर्धारण के आधार	546
कीमत निर्धारण की विधियाँ	550
कृषि-वस्तुओं की कीमतों के निर्धारण में समय का महत्त्व	555
19. कृषि-कराधान	563-584
कराधान के अधिनियम	563
कृषि कर	564

20	पञ्चवर्षीय योजनाओं में कृषि	585-597
	योजना आयोग की स्थापना के उद्देश्य 585	
	विभिन्न पञ्चवर्षीय योजनाएँ 586	
21	कृषि में तकनीकी ज्ञान का विकास	598 627
	अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम 598	
	पैकेज-कार्यक्रम 600	
	कृषि क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान विकास	
	हरित-क्रान्ति 617	
22	कृषि-बीमा	628-639
	फसल-बीमा 628	
	पशु-बीमा 637	
23	भारत में सहकारिता	640-647
	सहकारिता से तात्पर्य 640	
	भारत में सहकारिता का विकास 642	
	सहकारी समितियों का वर्गीकरण 644	
	सहकारिता की प्रगति में बाधक कारक 645	
24	बोस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम एवं गई कृषि नीति	648-651
25	भारत में गरीबी	652-669
	गरीबी रेखा 653	
	गरीबी का मापदण्ड 654	
	भारत में गरीबी का अनुमान 655	
	गरीबी उन्मूलन 659	
	पारिभाषिक शब्दावली	661-675
	नामानुक्रमणिका	676-696

अध्याय 1

कृषि-अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं क्षेत्र

अर्थशास्त्र की एक प्रमुख शाखा कृषि-अर्थशास्त्र है। पृथक् विषय के रूप में कृषि-अर्थशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में प्रारम्भ हुआ था। आधुनिक कृषि एक व्यवसाय है। इसमें वे सभी उद्योग सम्मिलित किये जाते हैं, जो कृषि के विकास के लिए उत्पादन-साधनों को निर्मित करते हैं तथा कृषि-मत पदार्थों का परिष्करण (प्रोसेसिंग) के द्वारा रूप परिवर्तित करते हैं।

अर्थशास्त्र में मनुष्य की धन से सम्बन्धित समस्त क्रियाओं का समावेश होता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को विभिन्न शब्दों में परिभाषित किया है। एडमस्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। बाकर के अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से सम्बन्धित है। मार्शल ने मनुष्य की अनोपाजन एवं धन के व्यय से सम्बन्धित समस्त क्रियाओं के अध्ययन का समावेश अर्थशास्त्र में किया है। उपर्युक्त परिभाषाएँ संकुचित हैं क्योंकि अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं का तथा सामाजिक मनुष्य के अतिरिक्त समाज के बाहर रहने वाले मनुष्य का अध्ययन भी होता है। वर्तमान में रोबिन्स द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा का ही सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। रोबिन्स¹ के अनुसार, "अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो उद्देश्यों एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों के परस्पर सम्बन्ध के रूप में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है।"

अर्थशास्त्र की उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएँ अनन्त होती हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सीमित होते हैं और सीमित साधनों के

1 "Economics is the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses"

•L. Robbins, Nature and Significance of Economic Science, p 1.

2/भारतीय कृषि का अर्थतन्त्र

अनेक उपयोग होते हैं। अतः अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है कि सीमित साधनों का कौनसी आवश्यकताओं की पूर्ति में उपयोग किया जाये जिससे मनुष्य को अधिक से अधिक सन्तोष की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार अर्थशास्त्र समस्त मानवीय क्रियाओं के आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करता है। विभिन्न आर्थिक पहलुओं के विकास के साथ-साथ अर्थशास्त्र में भी नयी-नयी शाखाएँ उत्पन्न हुई हैं, जिनमें से कृषि अर्थशास्त्र एक है।

कृषि-अर्थव्यवस्था की परिभाषा:

कृषि-अर्थशास्त्र को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न-भिन्न शब्दों में परिभाषित किया है। प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा दी गई कृषि-अर्थशास्त्र की परिभाषाएँ निम्नांकित हैं—

जौजियर² “कृषि अर्थशास्त्र कृषि-विज्ञान की शाखा है जो कृषकों के यहाँ उपलब्ध विभिन्न उत्पादन साधनों के पारस्परिक एवं मानवगत सम्बन्धों को नियमित करने की विधि का विचार करती है, जिसमें उद्यमों में अधिकतम समृद्धि प्राप्त की जा सके।”

उपयुक्त परिभाषा की अन्य लेखकों द्वारा की गई आलोचना में कहा गया है कि लेखक ने कृषकों के ‘दुर्लभ साधनों से अधिकतम सन्तोष प्राप्ति’ के स्थान पर ‘अधिकतम समृद्धि’ का उपयोग किया है जो अनावश्यक है। साथ ही इसमें ग्रामीण समाज के आर्थिक विकास को उचित महत्त्व नहीं दिया गया है।

टेलर³ “कृषि अर्थशास्त्र में फार्म के लिए भूमि, श्रम, औजारों का चयन, फसलों एवं पशु-उद्यमों का चुनाव और विभिन्न उद्यमों के उचित अनुपात में संयोजन का अध्ययन किया जाता है। मुख्यतया लागत एवं प्राप्त मूल्यों के आधार पर उपयुक्त प्रश्नों का हल खोजा जाता है।”

- 2 “Agricultural economics is that branch of agricultural science which treats of the manner of regulating the relations of the different elements comprising the resources of the farmer, whether it be the relations to each other or to human beings in order to secure the greatest degree of prosperity to the enterprise.”
Jouzier, *Economie Rurale*, Paris, 1920.

3. “Agricultural economics treats of the selection of land, labour and equipment for a farm, the choice of crops to be grown. The selection of livestock enterprises to be carried on and whole question of the proportions in which all these agencies should be combined. These questions are treated primarily from the point of view of costs and prices.”

-H. C. Taylor, *Outlines of Agricultural Economics*, The Macmillan Company, New York, 1931.

अन्य लेखकों ने उपर्युक्त परिभाषा की आलोचना करते हुए लिखा है कि लेखक ने कृषि अर्थशास्त्र की सूक्ष्म-स्तर पर फार्म-प्रबन्ध के रूप में विवेचना की है, जबकि कृषि अर्थशास्त्र की व्याख्या बृहत् स्तर पर की जानी चाहिए। साथ ही लेखक ने कृषि अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण समस्याएँ, जैसे-कराधान, मुद्रा, भू-वृत्ति आदि का विवेचन भी नहीं किया है।

प्रे⁴ "कृषि-अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें कृषि उद्योग की विशेष परिस्थितियों में अर्थशास्त्र के सिद्धान्त एवं विधियों का प्रयोग किया जाता है।"

रोस⁵ "कृषि-अर्थशास्त्र का अध्ययन दो विस्तृत दृष्टिकोणों में किया जा सकता है, प्रथम के अन्तर्गत सामान्य कृषि का अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धों का समावेश होता है जबकि द्वितीय दृष्टिकोण में एकल फार्म इकाइयों के प्रबन्ध एवं संचालन पर विचार किया जाता है।"

लेखक ने कृषि-अर्थशास्त्र की परिभाषा में कृषि-अर्थशास्त्र एवं फार्म-प्रबन्ध दोनों ही दृष्टिकोणों को सम्मिलित कर दिया है, जबकि दोनों के क्षेत्र अलग-अलग हैं।

फिलिप टेलर⁶ "कृषि-अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें कृषि-वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण की क्रियाओं और कृषि उद्योग से सम्बन्धित संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है।"

4. "Agricultural economics may be defined as the science in which the principles and methods of economics are applied to the special conditions of agricultural industry."

-L. C. Gray, Introduction to Agricultural Economics, The Macmillan Company, New York, 1922, Chapter 1

5. "Agricultural economics may be approached from two broader aspects, the first involves the general economic relationship of agriculture to other groups, the second applies to the management and operations of individual farm units."

-R. C. Ross, An Introduction to Agricultural Economics, McGraw Hill Book Company, INC, New York, 1951 p 4

6. "Agricultural economics is the branch of economics dealing with the production and distribution of agricultural commodities and the institutions associated with agriculture."

-Philip Taylor, A New Dictionary of Economics, Routledge and Kegan Paul, 1966

4/भारतीय कृषि का अर्थतन्त्र

हिन्दाई⁷ “कृषि-अर्थशास्त्र मनुष्य की कृषि-क्रियाओं में धन के उपार्जन एवं उसके व्यय के सम्बन्धों का अध्ययन है।”

यद्यपि विभिन्न लेखकों ने कृषि-अर्थशास्त्र की भिन्न-भिन्न शब्दों में परिभाषा की है, लेकिन सभी लेखकों ने कृषि अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया है—

- (प्र) कृषि-अर्थशास्त्र में कृषकों की धन से सम्बन्धित सामाजिक एवं अन्य क्रियाओं के अध्ययन का समावेश होता है।
- (व) कृषि-अर्थशास्त्र में कृषकों की उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण एवं सार्वजनिक वित्त सम्बन्धी सभी क्रियाओं का अध्ययन सम्मिलित होता है।
- (स) कृषि-अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य कृषकों को सीमित उत्पादन साधनों द्वारा अधिकतम सन्तोष की प्राप्ति कराना है।

कृषि-अर्थशास्त्र का क्षेत्र

कृषि-अर्थशास्त्र के अन्तर्गत मनुष्य की कृषि-क्रियाओं और कृषि-उत्पादन के भौतिक, जैविक, आर्थिक व सामाजिक पहलुओं के सम्बन्धों का कृषि व्यवसाय के रूप में अध्ययन किया जाता है। कृषि-अर्थशास्त्र में कृषि की निम्न क्रियाओं का अध्ययन सम्मिलित होता है—

- (प्र) विभिन्न उद्यमों के समूह-फल उत्पादन, पशुपालन, फल उत्पादन तथा विभिन्न उद्यमों में आपसी सम्बन्ध का अध्ययन जिससे उद्यमों के सही चुनाव द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके।
- (व) उत्पादन के सीमित साधनों का विभिन्न उद्यमों में अधिकतम लाभ की प्राप्ति के लिए अनुकूलतम प्रयोग, उत्पादन साधनों का प्रतिस्थापन एवं विभिन्न साधनों का उचित मात्रा में संयोजन।
- (स) उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के बीच श्रय-विक्रय के लिए उचित सम्बन्ध बनाये रखना।
- (द) विभिन्न उत्पादन साधनों एवं उत्पादित वस्तुओं की लागत एवं आय के सम्बन्धों पर विचार करना।

7. “Agricultural economics is the study of relationships arising from the wealth getting and wealth using activity of man in agriculture”

-B. H. Hibbard, Agricultural Economics, McGraw Hill Book Company, INC, New York, 1948, p. 3

कृषि-अर्थशास्त्र ये अर्थशास्त्र के चारो विभागो—उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं वितरण के अध्ययन का समावेश होता है। कृषि-अर्थशास्त्र में उत्पादन करने से सम्बन्धित निर्णय—क्या, कितना और कैसे, उपभोग सम्बन्धित निर्णय—कितनी मात्रा में एवं किस समय करें, विनिमय सम्बन्धित निर्णय—वस्तुओं का क्रय-विक्रय का समय, स्थान एवं क्रय-विक्रय पद्धति में सुधार कैसे करें, वितरण सम्बन्धित निर्णय—प्राप्त लाभ को उत्पादन साधनों के स्वामियों में किस प्रकार व किस अनुपात में वितरण करें, आदि समस्याओं का समावेश होता है। इसके अतिरिक्त कृषि-अर्थशास्त्र में कृषि से राज्य को प्राप्त आय एवं राज्य की ओर से कृषि सुधार पर किये जाने वाले व्यय का अध्ययन भी सम्मिलित होता है। यह अध्ययन सार्वजनिक वित्त (Public Finance) के अन्तर्गत किया जाता है।

कृषि अर्थशास्त्र के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य सम्पूर्ण समुदाय को सामाजिक कल्याण उपलब्ध कराना है। अनुसन्धान के प्रसार से कृषि अर्थशास्त्र का क्षेत्र और भी व्यापक होता जा रहा है। इसके अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में आने वाली सभी आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं की विवेचना की जान लगी है।

कृषि-अर्थशास्त्र की प्रकृति

कृषि-अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान? धनात्मक या यथार्थमूलक विज्ञान (Positive Science) है या आदर्श-मूलक विज्ञान (Normative Science)? व्यावहारिक विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान? आदि प्रश्नों का धिवेचन कृषि-अर्थशास्त्र की प्रकृति के अन्तर्गत आता है। फलतः कृषि-अर्थशास्त्र की प्रकृति में निम्न बातों की विवेचना की जाती है :—

(अ) कृषि-अर्थशास्त्र विज्ञान है। विज्ञान से यहाँ तात्पर्य सुव्यवस्थित ज्ञान (Systematised body of knowledge) से है। कृषि-अर्थशास्त्र, विज्ञान की भाँति ही, जाँच, वर्णन एवं विवेचन करता है। कृषि-अर्थशास्त्र कला भी है। कला से तात्पर्य सुव्यवस्थित क्रिया (Systematised action) से है। सुव्यवस्थित विधि से कार्य करने का ज्ञान भी कृषि-अर्थशास्त्र प्रदान करता है।

(ब) कृषि-अर्थशास्त्र एक व्यावहारिक विज्ञान है जिसमें कृषि के क्षेत्र में क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कृषि-अर्थशास्त्र विज्ञान केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही नहीं है, बल्कि वह प्राप्त ज्ञान का अधिकतम लाभ की प्राप्ति के लिए कृषि में उपयोग करने की विधि भी प्रदर्शित करता है।

6/भारतीय कृषि का अर्थतन्त्र

- (म) कृषि-अर्थशास्त्र सही रूप में एक विजिष्ट विज्ञान है ।
- (द) कृषि-अर्थशास्त्र का अध्ययन सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक दोनों ही प्रकार का है । सैद्धान्तिक रूप में इसमें अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का विवेचन होता है एवं प्रायोगिक रूप में प्राप्त परिणामों का विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में प्रयोग किया जाता है ।
- (य) कृषि-अर्थशास्त्र एक समष्टिभूतक अध्ययन है । इसके अन्तर्गत विभिन्न ज़ातों के समूह का एक साथ अध्ययन किया जाता है ।
- (र) कृषि-अर्थशास्त्र सामाजिक अध्ययन भी है क्योंकि इसमें मनुष्यों के व्यवहार एवं सीमित साधनों में उनके विविध उद्देश्यों की प्राप्ति का अध्ययन भी सम्मिलित होता है ।
- (स) कृषि-अर्थशास्त्र के अध्ययन में भूमि-अर्थशास्त्र, धन-अर्थशास्त्र, उत्पादन-अर्थशास्त्र, फार्म-प्रबन्ध, कृषि-वित्त, कृषि-विपणन कृषि-कीमते, कृषि-नीतियाँ आदि सम्मिलित होते हैं ।

कृषि-अर्थशास्त्र के विभाग

अध्ययन की दृष्टि से कृषि-अर्थशास्त्र को कई विभागों में विभक्त किया जाता है । कृषि-अर्थशास्त्र के प्रमुख विभाग निम्नांकित हैं, जो परस्पर घनिष्ठत सम्बन्धित भी हैं^१ —

- 1 उत्पादन-अर्थशास्त्र — इसमें उत्पादन के विभिन्न साधनों द्वारा अधिकतम उत्पादन मात्रा की प्राप्ति की प्राप्ति का अध्ययन किया जाता है ।
- 2 फार्म-प्रबन्ध — इसके अन्तर्गत प्रत्येक कृषक की उत्पादन, संचालन एवं प्रबन्ध सम्बन्धी क्रियाओं में अधिकतम लाभ की प्राप्ति के लिए अध्ययन अपेक्षित है ।
- 3 भूमि-अर्थशास्त्र — भू-भूति, भूमि सुधार एवं जेत सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन इसके अन्तर्गत आता है ।
- 4 धन-अर्थशास्त्र — इसमें श्रमिकों की समस्याएँ, मजदूरी, धमिकों में व्याप्त बेरोजगारी, धन-सम्बन्धी कानूना व अध्ययन का समावेश होता है ।
5. कृषि-वित्त — कृषकों की ऋण आवश्यकता, ऋण के स्रोत, ऋण प्रबन्ध एवं ऋण सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन इसमें आता है ।

6 कृषि-विपणन—इसके अन्तर्गत कृषि से प्राप्त उत्पादों का विपणन, विपणन-कार्य, विपणन-संस्थाएँ एवं उत्पादक कृषकों की क्रय-विक्रय सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन सम्मिलित होता है।

7. कृषि-संवृद्धि, विकास एवं योजना—इसके अन्तर्गत कृषि की सामान्य समस्याओं जैसे, कृषि में संवृद्धि, कृषि-विकास नीति, कृषि-योजनाओं आदि का समावेश होता है।

8. ग्राम्य समाजशास्त्र—इसमें समाज की समस्याएँ जैसे, गरीबी, समाज में व्याप्त बाधक कारकों के अध्ययन का समावेश होता है।

कृषि अर्थशास्त्र के अध्ययन की सीमाएँ

कृषि-अर्थशास्त्र के अध्ययन की सीमाएँ निम्नलिखित हैं —

1 कृषि-अर्थशास्त्र के अन्तर्गत कृषकों की कृषि-परक आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। कृषकों की अन्य समस्याएँ, जो धन से सम्बन्धित नहीं होती हैं, इसमें सम्मिलित नहीं की जाती हैं।

2 कृषि-अर्थशास्त्र में कृषक समाज या कृषक-समूह की कृषिगत समस्याओं की ही विवेचना की जाती है। इसमें कृषकों की वैयक्तिक समस्याओं का समावेश नहीं होता है।

3 कृषि-अर्थशास्त्र का मापदण्ड मुद्रा है। क्रियाओं के करने से प्राप्त परिणामों को मुद्रा के रूप में ही प्रकट किया जाता है।

कृषि एवं औद्योगिक अर्थव्यवस्था में अन्तर

कृषि एवं औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था में कार्यों एवं उत्पादों की प्रकृति में विभिन्नता के अनुसार निम्नांकित अन्तर पाये जाते हैं :—

1. कृषि कार्यों एवं औद्योगिक कार्यों की प्रकृति में भिन्नता का होना

कृषि एवं अन्य उद्योगों की क्रियाओं में निम्न अन्तर हैं—

1. फलित्व का सिद्धान्त—कृषि में ह्रासमान प्रतिफल का सिद्धान्त व उद्योगों में वृद्धमान प्रतिफल का सिद्धान्त लागू होता है। कृषि में उद्योगों की अपेक्षा ह्रासमान प्रतिफल का सिद्धान्त निम्न कारणों से अधिक प्रबल होता है —

(अ) कृषि-व्यवसाय पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति में परिवर्तन लाना मनुष्य की शक्ति के बाहर है। उद्योगों में उत्पादन पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर नहीं होता है। अतः उद्योगों में उत्पादन-साधनों की

मात्रा को निरन्तर बढ़ाकर पहले की अपेक्षा अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है ।

- (ब) भूमि पर निरन्तर कृषि-उत्पादन करने के कारण भूमि की उर्वरता-शक्ति कम होती जाती है । परिणामतः कृषि क्षेत्र में हासमान प्रतिफल का सिद्धान्त लागू होता है ।
- (स) कृषि में यन्त्रीकरण के प्रयोग का क्षेत्र उद्योगों की भाँति विस्तृत नहीं है । फलस्वरूप कृषि में उत्पादन वृद्धि उद्योगों के समकक्ष नहीं हो पाती है ।
- (ड) कृषि का क्षेत्र सीमित न होकर विस्तृत है । इस कारण व्यवसाय की सुचारु रूप से देखभाल नहीं हो पाती है ।
- (य) कृषि व्यवसाय में धर्म-विभाजन का क्षेत्र सीमित होने के कारण उत्पादन में वृद्धमान दर से प्रगति नहीं हो पाती है ।

2. प्रकृति पर निर्भरता—कृषि में उत्पादन मुख्यतया प्रकृति की देन है । जिस वर्ष मौसम अनुकूल होता है, कृषि-उत्पादन अधिक होता है और प्रतिकूल मौसम वाले वर्ष में उत्पादन कम होता है । मौसम की अनुकूलता व प्रतिकूलता का उद्योगों के उत्पादन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है ।

3 अनिश्चितता कृषि में उत्पादन, कीमतें एवं क्रियाएँ अनिश्चित होती हैं । उद्योगों में ये क्रियाएँ अपेक्षाकृत अधिक निश्चित होती हैं । इसलिए उद्योगों में कृषि की अपेक्षा जोखिम कम होती है । कृषि व्यवसाय में अनिश्चितता निम्न कारणों से बनी रहती है :—

- (अ) कृषि में उत्पादन की होने वाली मात्रा एवं कृषि-क्रियाओं का समय पर हो पाना मौसम की अनुकूलता/प्रतिकूलता पर निर्भर है । असामयिक वर्षा, सूखा, धोल, अतिवृष्टि, शीतलहर, तूफान आदि के कारण कृषि उत्पादन कम होता है, जिससे उत्पादों की विपणन की जाने वाली मात्रा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है एवं कीमतों में भी अनिश्चितता आ जाती है ।
- (ब) कृषि के क्षेत्र में असह्य उत्पादक होने के कारण कृषि के क्षेत्र में कुल उत्पादन, पूँति आदि की मात्रा का सही आकलन कृषकों के लिए सम्भव नहीं हो पाता है जबकि उद्योगों में उत्पादकों की संख्या एवं उनकी उत्पादन क्षमता का अन्य उत्पादकों को पूर्ण ज्ञान होता है । अतः कृषकों को उत्पाद के विनय से प्राप्त होने वाली कीमतों की अनिश्चितता बनी रहती है ।

(स) कृषि वस्तुएँ देश के उपभोक्ताओं की प्रमुख आवश्यकता की वस्तुएँ होने के कारण सरकार समय-समय पर इनके उत्पादन व कीमतों के निर्धारण की नीति में परिवर्तन करती है। इस कारण भी कृषि के क्षेत्र में अनिश्चितता बनी रहती है।

4 उत्पादन का पैमाना—कृषि व्यवसाय में असह्य दृष्टिकोण के कारण जौन का आकार छोटा होता है। इसलिए उत्पादन छोटे पैमाने पर होगा है। उद्योगों में उत्पादन बड़े पैमाने पर होने से उत्पादन की मात्रा अधिक होती है।

5. उत्पादन में समय पराधता (Time lag in Production)—कृषि वस्तुओं के उत्पादन का एक निश्चित मौसम होता है तथा उनके उत्पादन में भी एक निश्चित समय लगता है। कृषि-वस्तुओं के उत्पादन-मौसम एवं उत्पादन-काल में विशेष परिवर्तन करना सम्भव नहीं है, जबकि औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में लगने वाला समय मनुष्य के नियन्त्रण में होता है, जिसकी न्यूनाधिकता से उत्पादन में आवश्यकतानुसार कमी व वृद्धि की जा सकती है। कुछ कृषि वस्तुओं में समय पराधता के कारण पूर्तिफलन काँबवेब प्रमेय (Cob-Web Theorem) के अनुरूप होता है। पशुधन तथा फलों वाली फसलों के उत्पादन में एक निश्चित समय लगता है, जिसमें कीमतों में अन्वीय उतार-चढ़ाव पाया जाता है। विभिन्न उत्पादों में यह चक्र विभिन्न समय का होता है। काँबवेब प्रमेय स्पष्ट करता है कि कुछ कृषि वस्तुओं की माग एवं पूर्ति के सन्तुलन बिन्दु पर निर्धारित नहीं होकर इसके आस-पास परिवर्तित होती रहती है।

काँबवेब प्रमेय की विभिन्न स्थितियाँ [उपसारी (Convergent), अभिसारी (Divergent) एवं सतत (Continuous)] बहुत कुछ मकड़ी के जाल के समान होती हैं। इस प्रमेय की मुख्य कल्पना है कि किसी विशेष उत्पाद से अधिक कीमत प्राप्त होने पर कृषक उस उत्पाद हेतु अधिक क्षेत्र का संयोजन करता है जिसके कारण अगले वर्ष उत्पत्ति की मात्रा में वृद्धि होती है और कीमते गिर जाती हैं। कीमतों के गिर जाने के कारण कृषक अगले वाले वर्ष में उस फसल के अन्तर्गत क्षेत्रफल कम कर देते हैं। इस प्रकार उत्पादन में कमी होती है और कीमतें बढ़नी शुरू होती हैं। कीमतों के बढ़ने के कारण कृषक फसल के उत्पादन में वृद्धि करने की पुनः कोशिश करते हैं लेकिन उत्पादन वृद्धि में समय अधिक लगता है। जैसे—सुअर पालने में 2 वर्ष, दुधारू पशुओं में 4 वर्ष, फलों में 5 से 10 वर्ष आदि। इस उत्पादन काल में कीमतों में फिर से परिवर्तन हो जाते हैं। अतः वस्तु के उत्पादन व कीमतों का चक्र चलता रहता है जिससे कीमतों का सन्तुलन बिन्दु स्थापित नहीं हो पाता है।

6. कीमतों के परिवर्तन के साथ उत्पादन के समझन की सम्भावना—कृषि वस्तुओं की कीमतों में औद्योगिक वस्तुओं की अपेक्षा उतार-चढ़ाव अधिक होता है। कृषि उत्पादों के उत्पादन में, कीमतों में परिवर्तन के साथ वृद्धि या कमी करना सम्भव नहीं है, जिससे उनके उत्पादन में कीमतों के साथ समझन नहीं हो पाता है। लेकिन औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में कीमतों के परिवर्तन के साथ वृद्धि या कमी की जा सकती है। इस कारण औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में कीमतों के परिवर्तन के साथ समझन करना सरल है।

7. धर्म विभाजन—कृषि व्यवसाय में धर्मिकों को विभिन्न कृषि-कार्य फार्म पर करने होते हैं। छोटे पैमाने पर होने के कारण कृषि व्यवसाय में अधिक मात्रा में धर्म-विभाजन करना सम्भव नहीं होता है। औद्योगिक व्यवसायों में उनकी विशालता के कारण धर्म-विभाजन सम्भव होता है।

8. व्यवसाय का प्राकृत्य—कृषक प्रायः कृषि को व्यवसाय के रूप में न लेकर जीवितयापन के रूप में अपनाते हैं, लेकिन उद्योगपति उद्योग को व्यवसाय के रूप में लेते हैं।

9. वित्त पूर्णता—कृषि व्यवसाय में पूँजी के अधिक समय तक निवेश होने तथा जोखिम की अधिकता के कारण ऋणदात्री संस्थाएँ ऋण स्वीकृत करना नहीं चाहती हैं। उद्योगों में जोखिम कम होने के कारण ऋणदात्री संस्थाएँ आवश्यक मात्रा में ऋण स्वीकृत करने को तैयार होती हैं जिससे उद्योगों की वित्त आवश्यकता पूर्ण हो जाती है।

10. जोखिम बीमा सुविधा—कृषि क्षेत्र में होने वाली जोखिम का बीमा कराना सम्भव नहीं होता है जबकि औद्योगिक व्यवसायों में होने वाली सभी प्रकार की जोखिमों—आग, दुर्घटना आदि का बीमा, बीमा कम्पनी के यहाँ कराया जा सकता है और उद्योग, व्यवसायी सम्भावित नुकसान से बच जाते हैं। कृषकों को प्राकृतिक प्रकोपों के कारण होने वाला नुकसान स्वयं को वहन करना होता है।

11. निर्णय की शीघ्रता—कृषि व्यवसाय में निर्णय शीघ्रता से लेने होते हैं। निर्णयों के शीघ्रता से नहीं लेने की अवस्था में कृषि व्यवसाय के जीपट होने की सम्भावना हो जाती है। उद्योगों में कृषि क्षेत्र के समान शीघ्रता से निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार लिया गया निर्णय अनेक वर्षों तक उद्योगों में चलता रहता है।

II. कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों की प्रकृति में भिन्नता का होना :

उत्पादों की प्रकृति में भिन्नता के अनुसार कृषि व औद्योगिक व्यवसाय में निम्न अन्तर पाये जाते हैं—

1. **संयुक्त उत्पाद**—कृषि क्षेत्र में मुख्यतया संयुक्त उत्पाद प्राप्त होते हैं अर्थात् मुख्य उत्पाद के साथ साथ उपोत्पाद (By products) भी प्राप्त होते हैं, जैसे—गेहूँ के साथ भूसा, कपास के साथ कपास की लकड़ियाँ, चावल के साथ भूसी आदि। औद्योगिक क्षेत्र में संयुक्त उत्पाद कम होते हैं। अतः कृषि व्यवसाय में मुख्य उत्पाद की उत्पादन लागत ज्ञात करने का कार्य कठिन होता है।

2. **वस्तुओं के गुणों में भिन्नता**—कृषि क्षेत्र में भिन्न-भिन्न खेती एवं एक ही खेत से प्राप्त उत्पाद के गुणों में भिन्नता पायी जाती है। औद्योगिक व्यवसायों में प्रायः समान गुण वाली वस्तुएँ उत्पादित होती हैं।

3. **विपणन लागत की विभिन्नता**—कृषि व्यवसाय में कृषक फार्म पर विभिन्न उत्पाद उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक उत्पाद की विक्रय अधिशेष की मात्रा के कम होने के कारण उत्पाद की प्रति इकाई पर विपणन लागत अधिक आती है। औद्योगिक व्यवसायों में एक ही वस्तु के अधिक मात्रा में उत्पादित होने से उत्पाद की विक्रय अधिशेष की मात्रा अधिक होती है जिससे प्रति इकाई उत्पाद की विपणन-लागत कम आती है।

4. **उत्पादन मौसम की निश्चितता**—कृषि वस्तुओं के उत्पादन का निश्चित मौसम होने के कारण मौसम विशेष में कृषि वस्तुओं की पूर्ति अधिक होती है। औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन का निश्चित मौसम नहीं होता है। वे निरन्तर उत्पादित किये जा सकते हैं, जिससे उनकी पूर्ति वर्ष भर होती है।

5. **उत्पादों में विनाशशीलता का गुण**—कृषि वस्तुओं में शीघ्र नष्ट होने के गुण के कारण उन्हें अधिक समय तक संग्रहीत नहीं किया जा सकता है। उद्योगों से प्राप्त उत्पादों में प्रायः शीघ्र नष्ट होने का गुण विद्यमान नहीं होता है। फलतः उन्हें अधिक समय तक संग्रहीत किया जा सकता है।

6. **वस्तुओं का भार**—कृषि वस्तुएँ बहुधा भारी होती हैं। वे अधिक स्थान घेरती हैं, जैसे—कपास, जूट, मिर्च, मूँगफली चारा, आदि। औद्योगिक वस्तुओं का भार कम होता है। वे स्थान कम घेरती हैं। अतः कृषि वस्तुओं में संग्रहण एवं परिवहन लागत अधिक आती है।

7. **उत्पादों की मांग की लोच**—कृषि उत्पाद आवश्यकता की प्रमुख वस्तुएँ होने के कारण उनकी माँग प्रायः बेलोचदार (Inelastic) होती है, लेकिन औद्योगिक वस्तुओं की माँग प्रायः लोचदार (Elastic) होती है।

8. **उत्पादों की पूर्ति**—कृषि उत्पादों की पूर्ति की मात्रा अनिश्चित एवं अनियमित होती है, जबकि औद्योगिक वस्तुओं की पूर्ति की मात्रा निश्चित एवं नियमित होती है।

9. उत्पादों की कीमतों में परिवर्तन—कृषि-उत्पादों की कीमतों में परिवर्तन औद्योगिक वस्तुओं की अपेक्षा अधिक होता है। कृषि उत्पादों की कीमतें भिन्न-भिन्न समय एवं स्थान पर विभिन्न होती हैं जबकि औद्योगिक वस्तुओं की कीमतें प्रायः सभी स्थानों एवं समयों में समान होती हैं। कृषि वस्तुओं की कीमतों में औद्योगिक वस्तुओं की कीमतों की अपेक्षा अधिक परिवर्तन होने के साथ साथ कृषि वस्तुओं की कीमतों में मौसमी एवं चक्रीय परिवर्तन (Seasonal and Cyclical price movements) भी पाये जाते हैं जो औद्योगिक वस्तुओं में कम पाये जाते हैं। कृषि वस्तुओं के उत्पादन का एक विशेष मौसम होने के कारण कीमतों में उतार-चढ़ाव पाये जाते हैं। मौसम विशेष में उत्पादन अधिक होने के कारण कीमतें कम एवं अन्य मौसम में पूर्ति के कम होने के कारण कीमतें अधिक होती हैं। शीघ्रताओं वस्तुओं में कीमतों के मौसमी परिवर्तन सगृहीत की जा सकने वाली वस्तुओं की अपेक्षा अधिक होते हैं। कुछ कृषि वस्तुओं की कीमतों में चक्रीय कीमत-परिवर्तन भी पाये जाते हैं, क्योंकि उनके उत्पादन में एक निश्चित समय लगता है जिसके कारण कीमतों में परिवर्तन के साथ साथ पूर्ति में समन्वय नहीं हो पाता है। चक्रीय कीमत परिवर्तन उन्हीं वस्तुओं में पाये जाते हैं जिनकी माग एवं पूर्ति में शीघ्रता से समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है। औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन मौसमी नहीं होकर बर्यम्बर निरन्तर होता रहता है जिससे उनकी माग एवं पूर्ति में समन्वय शीघ्रता से स्थापित किया जा सकता है। स्पष्टतः उनमें मौसमी एवं चक्रीय कीमत परिवर्तन के लिए अवकाश ही नहीं होता है।

कृषि उद्योग में असह्य, असिखित, असंगठित, रुढ़िवाद कृषक हैं जो उत्पादन हेतु अन्य साधनों की अपेक्षा श्रम-साधन का अधिक उपयोग करके जीविकोपार्जन करते हैं। साथ ही कृषि उद्योग में प्रकृति पर निर्भरता के कारण जोखिम अधिक होती है। औद्योगिक व्यवसाय संगठित होता है जिसमें अनिश्चितता एवं जोखिम कम पाई जाती है। अतः सामान्य अर्थशास्त्र के सिद्धान्त कृषि-उद्योग की विशेषताओं के अनुसार परिवर्तित एवं परिवर्द्धित होकर ही लागू हो सकते हैं।

अध्याय 2

भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कृषि

प्राचीनकाल से ही भारत कृषि-प्रधान देश रहा है। उस समय देश में विस्तृत कृषि पद्धति प्रचलित थी। ग्रामवासी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में स्वावलम्बी थे। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण स्वतन्त्रता के समयसे ही खाद्यान्नों की कमी प्रतीत होनी शुरू हुई। खाद्यान्नों का भारी मात्रा में प्रतिवर्ष आयात किया गया। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए देश की विभिन्न पञ्चवर्षीय योजनाओं में कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई। कृषि विकास के लिए देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम सघन कृषि योजना, उन्नत बीजों का आविष्कार एवं उपयोग, उर्वरकों व कीटनाशी दवाइयों का अधिक उत्पादन एवं उनका उपयोग, कृषि की उन्नत विधियों का आविष्कार, लघु एवं सीमान्त कृषक विकास योजनाएँ, कृषि क्षेत्र में आवश्यक ऋण की उपलब्धि हेतु बैंकों का राष्ट्रीयकरण कृषि बीमा आदि कार्यक्रम शुरू किये गये। कृषि विकास के इन कार्यक्रमों के फलस्वरूप देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन देश अनेक कृषि उत्पादों के उत्पादन में आत्म-निर्भर नहीं हो सका। भारत कृषि-प्रधान देश होते हुए भी कृषि के क्षेत्र में अन्य विकसित देशों के समान प्रगति नहीं कर सका। इसका प्रमुख कारण भारतीय कृषि की अपनी ही कुछ विशेषताओं का होना है।

भारतीय कृषि की विशेषताएँ

भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएँ हैं—

(1) जोतों की संख्या एवं जोत का आकार कम होना :

भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता जोत इकाइयों की संख्या बहुत अधिक होना एवं अधिकांश जोतों का आकार कम होना है। कृषि जनगणना 1970-71 के अनुसार देश में कार्यशील जोतों की संख्या 71 01 मिलियन थी। कृषि जनगणना 1985-86 के अनुसार जोतों की संख्या बढ़कर 97 73 मिलियन हो गई। इस काल में प्रति जोत औसत क्षेत्रफल 2 28 हेक्टर से कम होकर 1 68 हेक्टर हो रहा गया। देश में जोतों के आकार के अनुसार कार्यशील जोतों की संख्या व उनके अन्तर्गत क्षेत्रफल सारणी 2.1 व 2.2 में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 21

भारत में कार्यशील जोतो की संख्या

(सहस्रा मिलियन में)

जोत का आकार	1970-71 कृषि जन- गणना	1976-77 कृषि जन- गणना	1980-81 कृषि जन- गणना	1985-86 कृषि जन- गणना
1. सीमान्त जोत (एक हेक्टर से कम)	36.20 (51.0)	44.52 (54.6)	50.12 (56.4)	56.75 (58.1)
2. लघु जोत (1 से 2 हेक्टर)	13.43 (18.9)	14.73 (18.1)	16.07 (18.1)	17.88 (18.3)
3. भ्रष्ट मध्यम जोत (2 से 4 हेक्टर)	10.68 (15.0)	11.67 (14.3)	12.45 (14.0)	13.25 (13.5)
4. मध्यम जोत (4 से 10 हेक्टर)	7.93 (11.2)	8.21 (10.0)	8.07 (9.1)	7.92 (8.1)
5. दीर्घ जोत (10 हेक्टर से अधिक)	2.77 (3.9)	2.44 (3.0)	2.17 (2.4)	1.93 (2.0)
कुल जोत	71.01 (100)	81.57 (100)	88.88 (100)	97.73 (100)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल जोत संख्या का प्रतिशत हैं।

स्रोत :—V M. Rao, Land Reform Experiences, Economic and Political weekly-Review of Agriculture, 27 June 1992, P. A-51.

भारत में कार्यशील जोती के अत्यंत क्षेत्रफल

(क्षेत्रफल मिलियन हेक्टर में)

जोत का प्रकार	कृषि जन- गणना 1970-71	कृषि जन- गणना 1976-77	कृषि जन- गणना 1980-81	कृषि जन- गणना 1985-86	प्रोसत जोत प्रकार 1985-86 में
1 सीमान्त जोत (1 हेक्टर से कम)	1456 (90)	1751 (107)	1974 (121)	2160 (132)	038
2 लघु जोत (1 से 2 हेक्टर)	1928 (119)	2090 (128)	2316 (141)	2553 (156)	143
3 अर्ध-मध्यम जोत (2 से 4 हेक्टर)	3000 (185)	3243 (199)	3465 (211)	3658 (223)	276
4 मध्यम जोत (4 से 10 हेक्टर)	4824 (297)	4963 (304)	4854 (296)	4701 (287)	594
5 दीर्घ जोत (10 हेक्टर से अधिक)	5006 (300)	4287 (262)	3771 (230)	3319 (202)	1720
कुल	1214 (100)	16334 (100)	16380 (100)	16391 (100)	1168

कोष्ठक में दिए गए भागड़े कुल जोत क्षेत्रफल का प्रतिशत है।

स्रोत — V M Rao Land Reform Experiences, Economic and Political weekly Review of Agriculture, June

27, 1992 P—A 51

16/भारतीय कृषि का वर्तमान

देश में दो हैक्टर क्षेत्र तक की ज़ोनों, कुल जोत मर्यादा का 76.4 प्रतिशत है तथा इनके पास ज़ोनों में कृषि क्षेत्र का मात्र 28.8 प्रतिशत भाग ही है। दूसरी ओर 10.1 प्रतिशत दोघेक्षेत्र की ज़ोनों (4 हैक्टर क्षेत्र से अधिक) के पास कुल कृषि क्षेत्र का 48.9 प्रतिशत भाग है। देश में मात्र 2.0 प्रतिशत ज़ोनों का आकार 10-10 हैक्टर से अधिक है, लेकिन इनके पास कुल भूमि का 20.2 प्रतिशत भाग है। अब स्पष्ट है कि देश में भू-स्वामित्व का अनमानित स्वरूप विद्यमान है, जो देश में विभिन्न भूमि-सुधार के कार्यक्रम अपनाने के बावजूद वर्तमान में भी प्रचलित है।

वर्ष 1970-71 की तुलना में वर्ष 1980-81 एवं 1985-86 में सभी ज़ोनों (दीर्घ एवं मध्यम ज़ोनों के अतिरिक्त) की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन यह वृद्धि सर्वाधिक सीमान्त ज़ोनों के अन्तर्गत हुई है। पिछले 15 वर्षों में कुल 26.72 मिलियन ज़ोनों संख्या में वृद्धि हुई है, इनमें से 20.55 मिलियन की वृद्धि सीमान्त ज़ोनों की संख्या में हुई है। इस काल में ज़ोनों के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में मात्र 1.80 मिलियन हैक्टर की ही वृद्धि हुई है। इस कारण विभिन्न ज़ोनों के औसत आकार में कमी हुई है। अब स्पष्ट है कि देश में ज़ोनों की संख्या अधिक है एवं उनकी संख्या में निरन्तर तीव्र गति में वृद्धि हो रही है। साथ ही उनके अन्तर्गत भूमि के क्षेत्र में असमानता बढ़ती जा रही है। लघु एवं सीमान्त ज़ोनों पर उन्नत कृषि विधियाँ एवं मशीनों का उपयोग करना सम्भव नहीं होता है। परिणामस्वरूप ज़ोनों के प्रति इकाई क्षेत्र से उत्पादन की मात्रा कम प्राप्त होती है एवं उत्पादन की प्रति इकाई मात्रा पर उत्पादन लागत अधिक आती है।

भारत में ज़ोनों का औसत आकार अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। वर्ष 1970-71 की कृषि जनगणना के अनुसार देश में ज़ोनों का औसत आकार 2.28 हैक्टर था, जो कम होकर वर्ष 1976-77 में 2.0 हैक्टर वर्ष 1980-81 में 1.82 हैक्टर एवं 1985-86 में 1.68 हैक्टर हो रहा था। ज़ोनों का यह औसत आकार अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। वर्ष 1970 में ज़ोनों का औसत आकार आस्ट्रेलिया देश में 1992.58 हैक्टर, अर्जेंटीना में 270.13 हैक्टर, कनाडा में 187.54 हैक्टर, अमेरिका में 157.61 हैक्टर, मैक्सिको में 142.28 हैक्टर, इंग्लैंड में 55.07 हैक्टर, फ्रान्स में 22.07 हैक्टर, जापान में 17.64 हैक्टर एवं ब्रिटेन में 8.35 हैक्टर था।¹

2 ज़ोनों-अपवर्णन

भारतीय कृषि की दूसरी विशेषता ज़ोनों के अन्तर्गत कुल भूमि का क्षेत्रफल एक खण्ड में नहीं होकर एक खण्ड में विभक्त होना है। भूमि के यह खण्ड एक-

दूसरे से बहुत दूरी पर स्थित होते हैं। जोत के अन्तर्गत भूमि का क्षेत्र विभिन्न खण्डों में विभक्त होने एवं उन भू-खण्डों का एक-दूसरे से दूर स्थित होने के कारण कृषक सभी भू-खण्डों पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं कर पाते हैं। विभिन्न खण्डों की देख रेख भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है। प्रत्येक भू-खण्ड पर बहुत-सा क्षेत्रफल मेड़, नालियों, भवन, सड़क बनाने में निकल जाता है, जिससे कृषक की जोत का कृषित क्षेत्र कम हो जाता है। भारत में कृषकों की जोत औसतन 4.04 खण्डों में विभक्त है, जबकि अन्य देशों में कृषकों की जोत एक या दो खण्डों में ही होती है। भारत में जोत के बिखरे हुए खण्डों को एक खण्ड में लाने का प्रयास चक्रवर्ती विधि द्वारा किया जा रहा है।

3. भारतीय कृषि में पूँजी निवेश कम होना :

भारतीय कृषि की तीसरी प्रमुख विशेषता कृषि क्षेत्र में पूँजी निवेश का कम होना है। भारतीय कृषक मुख्यतया गरीब हैं। गरीबी के कारण कृषि व्यवसाय में पूँजी निवेश कम मात्रा में कर पाते हैं। पूँजी के अभाव में कृषक फार्म पर कृषि उत्पादन में उन्नत तकनीकी विधियों एवं प्रस्तावित मात्रा में उत्पादन-साधनों का उपयोग कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं। इससे उनकी भूमि की उत्पादकता का स्तर कम प्राप्त होता है। वर्ष 1950-51 में कृषि क्षेत्र में निवेश की गई पूँजी, कृषि क्षेत्र से प्राप्त आय की 6.3 प्रतिशत थी, जो वर्ष 1960-61 तक समान प्रतिशत में बनी रही। पूँजी निवेश की राशि कम होकर वर्ष 1961-62 में 5.3 प्रतिशत, 1963-64 में 5.0 प्रतिशत व 1967-68 में मात्र 4.9 प्रतिशत ही रह गई।² कृषकों द्वारा सामाजिक उत्सवों पर अधिक व्यय करने एवं कृषि में उन्नत तकनीकी ज्ञान के स्तर का कम उपयोग करने से उनकी कृषि व्यवसाय से वृद्धि की राशि कम प्राप्त होती है। अन्य देशों में कृषि व्यवसाय में वृद्धि की राशि अधिक होने से वहाँ के कृषक निरन्तर कृषि व्यवसाय में पूँजी अधिक निवेश करते हैं। कृषि में पूँजी निवेश की राशि एवं उत्पादकता में घनात्मक सम्बन्ध होता है।

4. खाद्यान्न उत्पादन को प्राथमिकता प्रदान करना :

भारतीय कृषक खाद्यान्न वाली फसलों के अन्तर्गत गैर खाद्यान्नों वाणिज्यिक एवं नकदी फसलों की अपेक्षा अधिक क्षेत्रफल फार्म पर लेते हैं। इसका प्रमुख कारण कृषकों द्वारा पारिवारिक आवश्यकता वाले उत्पादों के उत्पादन को प्राथमिकता देना एवं वाणिज्यिक तथा नकदी फसलों के उत्पादन की विधि एवं उनसे प्राप्त होने वाले लाभ की अज्ञानता का होना है। खाद्यान्नों के अन्तर्गत अधिक क्षेत्रफल लेने से कृषकों

2. Baldev Kumar, Capital Formation in Agriculture, Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. XXIV, No. 4, October-December, 1969, pp 13-17.

को प्रति हेक्टर भूमि के क्षेत्र एवं कुल फार्म क्षेत्र से लाभ कम प्राप्त होता है। नकदी फसलों से प्रति हेक्टर लाभ खाद्यान्नों की अपेक्षा अधिक प्राप्त होता है। भारत में खाद्यान्नों की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल वर्ष 1950-51 से निरन्तर 70 से 75 प्रतिशत के मध्य रहा है। भारतीय कृषि प्रमुखतया खाद्यान्न आधारित है।

5. भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार .

भारत की अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में कृषि पर निर्भर है। कृषि में अधिक जनसंख्या के होने से भूमि पर जनसंख्या का भार अधिक होता है और प्रति व्यक्ति उपलब्ध कृषित क्षेत्र कम होता जाता है। विकसित देशों में विकासशील देशों की अपेक्षा कम जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर आधारित होती है। वर्ष 1980 में भारत की कुल कार्यरत जनसंख्या की 63.2 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कृषि पर आधारित थी। विकसित देश जैसे-अमेरिका एवं इंग्लैंड में 2.0 प्रतिशत पश्चिमी जर्मनी में 4 प्रतिशत, फ्रांस में 8.6 प्रतिशत एवं जापान में 11 प्रतिशत जनसंख्या ही कृषि पर आधारित थी।³ विकसित देशों में कृषि क्षेत्र पर आधारित जनसंख्या का भार निरन्तर कम होता जा रहा है, जबकि विकासोन्मुख देशों में यह प्रतिशत बढ़ा है। भारत में यह प्रतिशत पिछले दशक में 60 से 70 के मध्य में बनी हुई है। यह विशेषता भारत के लिए अभिशाप है।

6 कृषि उत्पादन का प्रकृति पर निर्भर होना

भारत में कृषि उत्पादन प्रकृति की अनुकूलता पर निर्भर है। प्रकृति की अनुकूलता वाले वर्ष में देश में खाद्यान्नों का उत्पादन अधिक होता है तथा प्रतिकूलता वाले वर्ष में खाद्यान्नों का उत्पादन कम होता है। भारतीय कृषि का प्रकृति पर निर्भरता का मुख्य कारण देश में सिंचाई के पानी की पर्याप्त सुविधा का नहीं होना है। भारत में वर्ष 1951-52 में 23.2 मिलियन हेक्टर क्षेत्र (कुल कृषित क्षेत्र का 17.4 प्रतिशत) में सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी। योजना काल में सिंचाई सुविधाओं के निरन्तर विस्तार के फलस्वरूप सिंचित क्षेत्र वर्ष 1988-89 में 69.7 मिलियन हेक्टर (कुल कृषित क्षेत्र का 36.5 प्रतिशत) हो गया। अतः सिंचाई सुविधाओं के विकास पर बहुत धन व्यय करने के बाद आज भी देश का 63.5 प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि उत्पादन के लिए वर्षा पर निर्भर है। इससे कृषि उत्पादन में अनिश्चितता होती है। देश में सूखा का प्रकोप निरन्तर होता रहता है। वर्ष 1965 से 1987 के मध्य में 12 वर्ष विभिन्न स्तर के सूखा वाले वर्ष थे।

7. भारतीय कृषि में पशु शक्ति का प्रमुख स्थान :

भारतीय कृषि में अधिकांश कृषि कार्य जैसे—जुताई, बुवाई, सिंचाई, खाद

3. NABARD News Review, NABARD, Bombay Vol. 1, No. 3, July-September, 1984, pp. 8-9.

डालना, उत्पाद का गायटा, उत्पाद की दुलाई आदि पशुओं की सहायता से ही किये जाते हैं। पशु-शक्ति के उपयोग के कारण उत्पादन लागत अधिक आती है तथा कार्य भी समय पर पूरा कर पाना सम्भव नहीं होता है। विकसित देशों में कृषि क्षेत्र में पशु-शक्ति के स्थान पर यान्त्रिक-शक्ति ट्रैक्टर, सिंचाई के लिए डीजल एवं विद्युत-इंजन, रीपर, सीड ड्रिल आदि का उपयोग अधिक होता है। भारत में प्रति एक लाख हैक्टर समग्र कृषित क्षेत्र पर वर्ष 1950-51 में 7 ट्रैक्टर, 50 सेल चलित इंजिन, 16 विद्युत पम्पसेट या ट्रूबवैल थे, जो बढ़कर 1984-85 में क्रमशः 450, 2,240 व 2,980 हो गये। लेकिन कृषि यन्त्रीकरण का यह स्तर विकसित देशों की अपेक्षा बहुत कम है।⁴

8 देश में भू-धृति की दोषयुक्त पद्धति का प्रचलित होना

भारतीय कृषि में भू-धृति की दोषयुक्त पद्धति प्रचलित है, जिससे कृषक भूमि से उत्पादकता बढ़ाने में इच्छुक नहीं होते हैं। प्रचलित दोषयुक्त पद्धतियों में कृषक एवं सरकार के मध्य मध्यस्थों का होना, जोत अपखण्डन, जोत का क्षेत्रफल कम व असमान होना, भू-राजस्व की अधिक राशि वसूल करना, आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार की दोषयुक्त भू धृति पद्धतियों के होने से कृषि विकास में बाधा पहुँचती है। सरकार ने स्वतन्त्रता के पश्चात् इन पद्धतियों की समाप्ति के लिए अनेक भूमि-सुधार कार्यक्रम अपनाए हैं।

9 कृषि जीवन निर्वाह का साधन :

भारत में कृषको द्वारा कृषि को व्यवसाय के रूप में न अपनाकर जीवन-निर्वाह के रूप में अपनाया जाता है। कृषक कृषि में होने वाले आय-व्यय का लेखा नहीं रखते हैं और न ही उत्पादन, आय में वृद्धि के लिए व्यावसायिक सिद्धान्तों का उपयोग करते हैं। अन्य देशों में कृषि को भी अन्य उद्योगों के समान व्यवसाय के रूप में अपनाया जाता है और व्यवसाय से व्यापारिक बुद्धिमत्ता के आधार पर अधिक लाभ कमाने का प्रयास किया जाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्व

निम्न तथ्य भारतीय अर्थ व्यवस्था में कृषि का महत्त्व प्रदर्शित करते हैं :

- (1) कृषि क्षेत्र राष्ट्रीय आय का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। वर्ष 1990-91 में कृषि क्षेत्र ने समग्र घरेलू उत्पाद का 24.8 प्रतिशत अंश प्रदान किया है। कृषि के अतिरिक्त अन्य सभी क्षेत्रों से सम्मिलित रूप में क्षेत्र 75.2 प्रतिशत समग्र घरेलू उत्पाद की राशि प्राप्त हुई है। कृषि क्षेत्र

के अग्रदान में वर्ष 1950-51 में निरन्तर गिरावट आई है, लेकिन अभी भी यह क्षेत्र प्रथम स्थान पर है।

- (2) कृषि क्षेत्र देश के 84.39 करोड़ नागरिकों एवं 36 98 करोड़ पशुओं के लिए आवश्यक भोजन-खाद्यान्न एवं चारे के रूप में उपलब्ध कराता है।
- (3) देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में जीवन-निर्वाह के लिए निर्भर है। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र सम्मिलित रूप से शेष 30 प्रतिशत जनसंख्या को जीवन-निर्वाह के साधन उपलब्ध कराते हैं।

कृषि क्षेत्र कुल रोजगार उपलब्धि का लगभग आधा भाग उपलब्ध कराता है।

- (4) देश को निर्यात में प्राप्त कुल आय में से लगभग एक तिहाई (33 प्रतिशत) अथवा कृषि-क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों के निर्यात से प्राप्त होता है। कृषि क्षेत्र से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में चाय, काफी, तम्बाकू, काजू, जूट कपास, ऊन बादाम, खाद्य तेल, सुपारी, गोंद, विशामिस, चमड़ा, मसाले, खली एवं फल प्रमुख हैं।
- (5) कृषि क्षेत्र देश के प्रमुख उद्योगों—कपड़ा, जूट, चीनी, तिलहन, वनस्पति, चाय, रबर, कागज आदि के लिए आवश्यक कच्चा माल प्रदान करता है। इन उद्योगों के विकास में कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
- (6) देश के आन्तरिक व्यापार, परिवहन, संचार, संग्रहण, ससाधन, बैंकिंग एवं अन्य सहायक क्षेत्रों के विकास में कृषि-क्षेत्र महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन क्षेत्रों को व्यवसाय मुरयतया कृषि-क्षेत्र से प्राप्त होता है। कृषि-क्षेत्र में उत्पादन अधिक होने से इन आधारित उद्योगों को भी व्यवसाय अधिक प्राप्त होता है।
- (7) देश के अनेक उद्योगों से निर्मित वस्तुएँ—जैसे—उर्वरक, कीटनाशक दवाईयाँ, कृषि-यन्त्र एवं मशीनें बीज आदि का उपयोग कृषि क्षेत्र में ही होता है। अतः इन उद्योगों का विकास कृषि क्षेत्र के विकास पर ही निर्भर करता है। कृषि एवं उद्योग एक-दूसरे के पूरक कहलाते हैं क्योंकि एक उद्योग का विकास दूसरे उद्योग के विकास में सहायक होता है।
- (8) देश में व्याप्त निर्धनता के स्तर की प्रतिशतता को कम करने में भी कृषि-क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। देश में गरीबी की

रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही जनसंख्या का प्रतिशतता में कमी भी कृषि-क्षेत्र के विकास द्वारा ही हो पाना सम्भव है ।

- (9) देश के उपभोक्ताओं की आय का लगभग 70 से 80 प्रतिशत भाग कृषि वस्तुओं के त्रय पर ही व्यय होता है । अतः उपभोक्ताओं को उचित जीवन स्तर प्रदान करने में कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण स्थान रखता है ।

खाद्यान्नों की माँग की लोच (Income elasticity of demand for foodgrains) के अधिक होने के कारण कीमतों में उतार-चढ़ाव का प्रभाव उपभोक्ताओं के रहन-सहन के स्तर को प्रभावित करता है ।

भारतीय अर्थ-व्यवस्था

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विकसित, अर्द्ध-विकसित एवं विकासोन्मुख अर्थ व्यवस्था की श्रेणी में विभक्त किया जा सकता है । विकसित अर्थ-व्यवस्था से तात्पर्य उस अर्थ-व्यवस्था से है जिसमें देश में उपलब्ध उत्पादन के साधन पूर्ण रूप से उपयोग में आ रहे हैं । ऐसी अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रों के निवासियों की आय अधिक एवं रहन सहन का स्तर ऊँचा होता है । अर्द्ध विकसित अर्थ-व्यवस्था से तात्पर्य उस अर्थ-व्यवस्था से है जिनमें उपलब्ध उत्पादन-साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं होता है । ऐसे क्षेत्रों के निवासियों की आय कम होती है जिनसे उनके रहन सहन का स्तर भी नीचा होता है । इन दोनों श्रेणियों के बीच की अर्थव्यवस्था जिसमें उपलब्ध उत्पादन-साधनों का निरन्तर उपयोग विकास के लिए हो रहा होता है तथा वहाँ के निवासियों की आय का स्तर मध्यम श्रेणी में आता है, उनको विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था कहते हैं । अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, आस्ट्रेलिया एवं रूस विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में वर्गीकृत किए जाते हैं जबकि अनेक अफ्रीकन एवं एशियाई देश अर्द्ध-विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं । भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की ओर अग्रसर होने वाली अर्थव्यवस्था अर्थात् विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आती है । वर्तमान में अर्थव्यवस्था को दो ही श्रेणी अर्थात् विकासशील एवं विकसित में ही वर्गीकृत किया जाता है ।

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में वर्गीकृत करने के लिए निम्न प्रमुख आधार उपयोग में लिये जाते हैं :—

(1) प्रति व्यक्ति आय—देश के निवासियों की प्रति व्यक्ति औसत आय देश की अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास की सूचकांक एवं व्यक्तियों की समृद्धि का प्रतीक होती है । विकसित राज्यों में प्रति व्यक्ति औसत आय अधिक होती है । वर्ष 1985 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अमेरिका में 16,690 अमेरिकन डॉलर, स्वीट्जरलैंड में

16,370 अमेरिकन डालर, डेनमार्क में 11,200 डालर, इंग्लैंड में 8,460 डालर, इण्डोनेशिया में 530 डालर, पाकिस्तान में 380 डालर, चीन में 310 डालर एवं भारत में 270 डालर थी।⁵ भारत में प्रति व्यक्ति औसत आय का स्तर उद्योग प्रधान विकसित देशों एवं तेल उत्पादक देशों की अपेक्षा बहुत कम है।

(2) कृषि उत्पादों की उत्पादकता का स्तर—अर्थ-व्यवस्था को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए दूसरा प्रमुख आधार कृषि क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं की उत्पादकता का स्तर है। विकसित देशों में उत्पादकता का स्तर अधिक एवं विकास-शील देशों में उत्पादकता का स्तर कम होता है। चावल का प्रति हेक्टर औसत उत्पादन वर्ष 1985-86 में जापान एवं अमेरिका में 42 क्विण्टल प्रति हेक्टर तथा भारत में 16 क्विण्टल प्रति हेक्टर था। गेहूँ का औसत उत्पादन जर्मनी में 63 क्विण्टल, फ्रांस में 55 क्विण्टल एवं भारत में 20 क्विण्टल प्रति हेक्टर ही था। मक्का का औसत उत्पादन अमेरिका एवं इटली में 75 क्विण्टल तथा भारत में 15 क्विण्टल प्रति हेक्टर है। अतः स्पष्ट है कि भारत में विभिन्न फसलों की औसत उत्पादकता का स्तर भी विकसित देशों की अपेक्षा कम है।

(3) कृषि व्यवसाय में पूँजी निवेश की दर—अर्थ-व्यवस्था को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने का तीसरा आधार कृषि व्यवसाय में पूँजी निवेश की दर है। भारत में कृषि व्यवसाय में पूँजी निवेश की दर 1957-58 में 4.57 प्रतिशत थी।⁶ कृषि क्षेत्र में पूँजी निवेश की दर में हरित क्रांति के फलस्वरूप वृद्धि हुई है। लेकिन वर्तमान में भी भारतीय कृषि में पूँजी निवेश की दर विकसित देशों की अपेक्षा कम है। कृषकों के फार्म पर उपलब्ध परिसम्पत्ति की राशि द्वारा कृषि क्षेत्र में निवेशित पूँजी का अनुमान लगाया जाता है। भारतीय कृषकों के फार्म पर भूमि एवं कुम्भों में निवेशित पूँजी के अतिरिक्त अन्य परिसम्पत्ति की राशि बहुत कम है।

(4) विभिन्न क्षेत्रों की विकास दर—विकसित देशों में अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों (कृषि, उद्योग, सहायक उद्योग, व्यापार, परिवहन) के विकास की ओर समान स्तर पर प्रयास किये जाते हैं, जिसके कारण विकास की दर अधिक होती है। भारत में सभी क्षेत्रों के विकास की ओर समान ध्यान नहीं दिया गया है। भारत में कृषि-क्षेत्र के विकास की ओर अन्य क्षेत्रों के विकास की अपेक्षा अधिक ध्यान दिया गया है, जिससे अनेक उद्योग प्रभावित हुए हैं। अनेक उद्योग कृषि के पूरक उद्योग हैं जो एक-दूसरे के विकास में सहायक होते हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रों के असन्तुलित विकास के कारण अर्थ-व्यवस्था की प्रगति कम हो पाई है।

5. Bepko Behari, *The Rural Development—The Task Ahead*, Yojana, vol. 32, No. 20, 1-15 Nov. 1988, p. 26.

6. *Economic Survey of Asia and the Far-East 1966* United Nations.

(5) कृषि क्षेत्र पर व्यक्तियों की निर्भरता का प्रतिशत—कृषि क्षेत्र पर व्यक्तियों की निर्भरता का प्रतिशत भी देश की अर्थव्यवस्था को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने में प्रयुक्त किया जाता है। विकसित देशों में कृषि व्यवसाय पर आधारित व्यक्तियों का प्रतिशत कम होता है, जबकि कम विकसित देशों में कृषि व्यवसाय पर आधारित व्यक्तियों का प्रतिशत अधिक होता है। वर्ष 1980 में कृषि व्यवसाय पर आधारित व्यक्तियों की प्रतिशतता के अनुसार विभिन्न देशों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है—

श्रेणी	देश	कृषि पर आधारित व्यक्तियों का प्रतिशत
सबसे अधिक कृषि व्यवसाय पर आधारित व्यक्तियों की प्रतिशतता वाले देश	नेपाल	92.6
	अफगानिस्तान	77.8
	सूडान	76.9
	पाकिस्तान	55.9
	बंगलादेश	83.8
	इन्डोनेशिया	58.9
	भारत	63.2
मध्यम कृषि व्यवसाय पर आधारित व्यक्तियों की प्रतिशतता वाले देश	चीन	59.8
	यूगोस्लाविया	37.4
	मेक्सिको	36.0
	रूस	16.4
	इटली	11.2
	जपान	11.0
सबसे कम कृषि व्यवसाय पर आधारित व्यक्तियों की प्रतिशतता वाले देश	फ्रांस	8.6
	ऑस्ट्रेलिया	5.6
	कनाडा	5.0
	बेल्जियम	3.1
	अमेरिका	2.2
	इंग्लैंड	2.0

उपर्युक्त आधारों के अनुसार कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था में वर्गीकृत न होकर विकासोन्मुख या विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आती है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की ओर अग्रसर अर्थव्यवस्था है।

भारत में कृषि उत्पादकता

उत्पादन के किसी साधन की एक इकाई द्वारा प्राप्त उत्पादन की मात्रा उस साधन की उत्पादकता कहलाती है। कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता साधारणतया भूमि प्रथम अथवा भूमि साधन के आधार पर व्यक्त की जाती है।

भूमि की उत्पादकता—भूमि की उत्पादकता से तात्पर्य भूमि के एक इकाई क्षेत्र से प्राप्त होने वाले उत्पादन की मात्रा से है, जो प्रति हेक्टेयर उपज किशटल के रूप में प्रकट की जाती है। भूमि की उत्पादकता कुल उत्पादन की मात्रा तथा भूमि के क्षेत्रफल के मध्य बदलते हुए सम्बन्धों का विवेचन करती है। उत्पादकता प्रकट करने की यह विधि भौतिक है, क्योंकि इसमें उत्पादों के मूल्य का समावेश नहीं होता है। भूमि उत्पादन-साधन के आधार पर उत्पादकता प्रकट करने का कार्य सरल है, क्योंकि इसे सुगमता से ज्ञात किया जा सकता है।

सरकार कृषि-उत्पादों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से निरन्तर प्रयास कर रही है। उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए निरन्तर कृषि क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम जैसे—अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम, पँकेज कार्यक्रम, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, उत्पादन साधनों के उत्पादन एवं उपयोग में वृद्धि, कृषि विस्तार कार्यक्रम आदि शुरु किये गये हैं। उत्पादकता में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास वर्ष 1965-66 के उपरान्त काल में किये गये। इस काल में उन्नत किस्म के बीजों का आविष्कार, सिंचाई के साधनों का विकास, कृषि में यन्त्रीकरण, कृषि अनुसन्धान द्वारा नई तकनीकी विधियों का आविष्कार एवं कृषि विस्तार की नई योजनाएँ प्रमुख हैं। देश में हरित-क्रान्ति के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन विशेषकर चावल एवं गेहूँ की उत्पादकता में वर्ष 1967-68 के उपरान्त काल में विशेष तेजी से वृद्धि हुई है।

सारणी 2 3 भारत में विभिन्न फसलों एवं फसलों के समूहों की उत्पादकता विभिन्न दशकों में प्रदर्शित करती है। सारणी से स्पष्ट है कि सभी फसलों के समूहों की उत्पादकता में पिछले 40 वर्षों में वृद्धि हुई है। विभिन्न फसल समूहों में अनाज एवं खाद्यान्नों के समूह की उत्पादकता में वृद्धि सर्वाधिक हुई है।

सारणी 2.3

देश में विभिन्न फसलों एवं फसल समूहों की उत्पादकता

(किलोग्राम/हेक्टर)

फसल/फसल समूह	1949-50	1959-60	1970-71	1980-81	1985-86	1989-90
1. चावल	668	937	1,123	1,336	1,552	1,756
2. गेहूँ	663	772	1,307	1,630	2,046	2,117
3. ज्वार	NA	NA	663	657	742	
4. मूँगफली	NA	708	834	736	719	
5. सरसो	NA	365	594	560	674	
6. गन्ना	34,201	36,414	48,322	57,844	60,000	
7. कपास रेशम	95	86	106	152	197	
8. जूट एंव मेस्टा	1,190	1,050	1,032	1,130	1,524	
9. अनाज	591	713	949	1,142	1,323	1,887
10. दालें	405	475	524	473	547	553
11. खाद्यान्न	553	662	872	1,023	1,175	1,644
12. तिलहन	519	470	579	532	591	729

NA—Not available.

स्रोत : (i) Seeds and Farms Journal, January, 1980, P. 24.

(ii) Economic Survey Ministry of Finance, Government of India, New Delhi

(iii) Yojana, Vol. 36(12), 15, July 1992.

26/भारतीय कृषि का अर्थतन्त्र

सारणी 24 भारत में विभिन्न फसलों की उत्पादकता में हुई चक्रवृद्धि दर से वृद्धि विभिन्न समय में प्रदर्शित करती है।

सारणी 24

भारत में विभिन्न फसलों की उत्पादकता में हुई चक्र वृद्धि दर से वृद्धि
(प्रतिशत प्रतिवर्ष)

फसल/फसल समूह	1949-50 से 1964-65 के काल में	1967-68 से 1986-87 के काल में	1949-50 से 1986-87 के काल में
1 चावल	2 13	1 93	1 61
2 गेहूँ	1 27	3 17	3 20
3 सभी खाद्यान्न	1 43	2 32	1 76
4 मूंगफली	0 31	0 85	0 53
5 तिल	-0 36	1 62	0 60
6 सरसो	0 37	2 00	0 57
7 सभी तिलहन फसलें	0 20	1 20	0 71
8 सभी फसलें	1 30	2 05	1 57

स्रोत Indian Agriculture in Brief-22nd Edition Directorate of Economics and Statistics Ministry of Agriculture, Government of India, New Delhi,

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि देश में पिछले 40 वर्षों में विभिन्न कृषि उत्पादों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। उत्पादकता वृद्धि दर खाद्यान्नों में तिलहन फसलों की अपेक्षा अधिक है। गेहूँ में उत्पादकता वृद्धि दर 3 20 प्रतिशत प्रति वर्ष पाई गई जो चावल में हुई उत्पादकता वृद्धि से दुगुनी है। तिलहन फसलों में उत्पादकता वृद्धि की दर एक प्रतिशत से भी कम पाई गई। चावल के अतिरिक्त सभी फसलों की उत्पादकता में हुई वृद्धि दर हरित क्रान्ति के बाद के काल (1967-68 से 1986-87) में हरित क्रान्ति के पूर्व (1949-50 से 1964-65) की अपेक्षा अधिक है।

उत्पादकता मे हुई इस वृद्धि दर के बावजूद आज भी भारत मे उत्पादकता का स्तर अन्य देशो की तुलना मे बहुत कम है । सारणी 25 विश्व के विभिन्न देशो मे खाद्यान्न एवं वाणिज्यिक फसलो की प्रति हेक्टर भूमि क्षेत्र से प्राप्त उत्पादकता प्रदर्शित करती है ।

सारणी 25

विश्व के विभिन्न देशों में फसलो की उत्पादकता

(किग्रा/हेक्टर)

फसल/फसल समूह	देश	उत्पाद- कता(वर्ष 1989- 90)	फसल	देश	उत्पादकता (वर्ष 1985 -86)
1. चावल (धान)	भारत चीन संसार	2691 5725 3557	1. गन्ना	भारत पेरू मलावी इथोपिया	60,000 137,000 119,000 165,000
2. गेहूँ	भारत चीन संसार	2117 3179 2570	2. कपास (रेशा)	भारत रूस चीन	196 717 890
3. मक्का (समी)	भारत चीन संसार	1887 4199 2763	3. मूंगफली (छिलके सहित)	भारत अमेरिका मलेशिया इटली इजरायल	952 3270 3500 3868 4074
4. दालें (समी)	भारत चीन संसार	553 1475 863	4. जूट	भारत मिश्र रूस चीन	1306 2444 2942 6587
5. समी खाद्यान्न	भारत चीन संसार	1644 4075 2595	5. विनोला (कपास के बीज)	भारत ऑस्ट्रेलिया इजरायल थीलका	469 3475 4383 5294

सारणी 2.6 में विभिन्न फसलों की औसत उत्पादकता एवं राष्ट्रीय प्रदर्शन क्षेत्रों से प्राप्त औसत एवं अधिकतम उत्पादकता प्रदर्शित की गई है। सारणी से स्पष्ट है कि वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त औसत उत्पादकता का स्तर राष्ट्रीय प्रदर्शन क्षेत्रों से प्राप्त औसत उत्पादकता स्तर से बहुत कम है। यह स्तर धान, गेहूँ एवं मक्का में 50 से 60 प्रतिशत एवं ज्वार एवं बाजरा में 25 से 30 प्रतिशत ही है। अतः स्पष्ट है कि देश में विभिन्न फसलों की औसत उत्पादकता स्तर में तकनीकी ज्ञान के पूर्ण एवं सही स्तर पर उपयोग करने से वृद्धि की प्रबल सम्भावना है।

सारणी 26

विभिन्न फसलों (खाद्यान्न) की राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त औसत उत्पादकता एवं राष्ट्रीय प्रदर्शन क्षेत्रों की उत्पादकता स्तर

(किलोग्राम प्रति हेक्टर)

फसल	राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त औसत उत्पादकता (1989-90)	राष्ट्रीय प्रदर्शन क्षेत्र से	
		प्राप्त औसत उत्पादकता (1986-87)	अधिकतम प्राप्त उत्पादकता (1986-87)
1. धान	2640	4750	8932
2. गेहूँ	2120	3508	5260
3. मक्का	1606	2916	4500
4. ज्वार	864	3270	7050
5. बाजरा	608	1705	4500

स्रोत : B. C. Biswas and T.K. Chanda; A Comparative Analysis of Agriculture and Fertilizer Scenario in India and China, Yajona, Vol. 36 (12), 15 July 1992, P. 16.

भारत के विभिन्न राज्यों एवं राज्यों के सिंचित एवं अशिरूचित क्षेत्रों की भूमि उत्पादकता में बहुत भिन्नता पाई जाती है। सारणी 27 में प्रस्तुत आकड़े इन तथ्यों की पुष्टि करते हैं।

सारणी 2-7

विभिन्न राज्यों में सिंचित एवं असिंचित क्षेत्रों में खाद्यान्नों की उत्पादकता
(1985-86)

खाद्यान्न	राज्य	उत्पादकता (किलोग्राम प्रति हेक्टर)	
		सिंचित क्षेत्र	असिंचित क्षेत्र
1 चावल	असम	1635	851
	उड़ीसा	1873	911
	पश्चिम बंगाल	2787	1287
	पंजाब	3070	1477
	तमिलनाडू	2559	1692
	महाराष्ट्र	1988	1423
2 गेहूँ	पंजाब	3410	1799
	हरियाणा	3125	1980
	उत्तरप्रदेश	2006	1171
	बिहार	1735	1098
	मध्य प्रदेश	1850	843
	राजस्थान	1681	956
3 ज्वार	महाराष्ट्र	758	295
	तमिलनाडू	1728	994
	गुजरात	1048	326
	आन्ध्र प्रदेश	2726	516
4 बाजरा	गुजरात	1016	319
	हरियाणा	805	384
	मध्यप्रदेश	921	589
	महाराष्ट्र	424	242
5 मक्का	आन्ध्र प्रदेश	2624	764
	हरियाणा	1290	888
	पंजाब	1911	1737
	राजस्थान	1523	1215
6 चना	गुजरात	663	502
	महाराष्ट्र	479	284
	राजस्थान	880	562

स्रोत Area and Production of Principal Crops in India, Directorate of Economics and Statistics Ministry of Agriculture, Government of India, New Delhi

कृषि में उत्पादकता स्तर के कम होने के कारण

स्पष्ट है कि भारत में खाद्यान्नों एवं विभिन्न कृषि उत्पादों की औसत उत्पादकता का स्तर विकसित देशों एवं देश में ही राष्ट्रीय प्रदर्शन क्षेत्रों से प्राप्त औसत उत्पादकता एवं देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत कम है। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता के कम होने के कारणों को निम्न तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है—

- (I) **संस्थामय कारक**—इसके अन्तर्गत जोत का आकार कम एवं अपखंडन होना, भू-चूनी की दोषयुक्त प्रणाली का होना, कुल भूमि का बहुत बड़ा भाग कृषि ध्वंश भूमि के अन्तर्गत होना प्रमुख है। इनके होने से उत्पादकता वृद्धि के प्रयास पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं हो पाते हैं।
- (II) **तकनीकी कारक**—इसके अन्तर्गत सिंचाई सुविधा की अपर्याप्तता, उन्नत कृषि विधियों का विकास न होना, उत्पादन-साधनों का पर्याप्त मात्रा में देश में उपलब्ध नहीं होना आदि प्रमुख हैं। उत्पादन साधनों एवं उन्नत तकनीकी के अभाव में देश के कृषक अन्य देशों के कृषकों के समान उत्पादकता का स्तर प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
- (III) **सामान्य कारक**—इसके अन्तर्गत कृषकों द्वारा उपलब्ध उत्पादन साधनों का प्रस्तावित मात्रा एवं विधि से प्रयोग नहीं करना, कृषि की प्रचलित विधि को काम में लेना, कृषि प्रसार सेवाओं का लाभ नहीं उठाना आदि प्रमुख हैं। इसका प्रमुख कारण कृषकों में शिक्षा का अभाव, कृषि को व्यवसाय के रूप में नहीं लेना एवं उनमें व्यवसाय के प्रति जागरूकता का न होना है।

थम उत्पादकता—थम-उत्पादकता से तात्पर्य प्रति श्रमिक इकाई से प्राप्त उत्पादन की मात्रा से है, जो उत्पादन की मात्रा एवं श्रमिकों की संख्या के मध्य बदलते हुए सम्बन्ध का अध्ययन है। थम उत्पादकता ज्ञात करने का कार्य कठिन होने के कारण, उत्पादकता ज्ञात करने की यह विधि बहुत कम काम में ली जाती है। इस विधि के अपनाने में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों (पुरुष, स्त्री एवं बच्चों) को एक श्रेणी में एवं विभिन्न उत्पादों की उत्पादन मात्रा को रुपये के रूप में परिवर्तन करना होता है। थम-उत्पादकता उस क्षेत्र के श्रमिकों के रहन-सहन के स्तर की सूचक होती है।

एक अध्ययन⁸ के अनुसार भारत में प्रति पुरुष कृषि श्रमिक औसत उत्पादकता

8. G. S. Bhatia and Y. K. Alagh, Labour Productivity in Indian Agriculture; Economic and Political weekly, Vol. XVIII (19-21) Annual Number, 1983 p. 83।

वर्ष 1970-73 में 1596 रु. थी। भारत के विभिन्न जिलों में भूमि उत्पादकता की माँति श्रमिक उत्पादकता में बहुत भिन्नता पाई गई है। अध्ययन के अनुसार देश के 53 जिलों में श्रम उत्पादकता 2200 रु. प्रति पुरुष कृषि श्रमिक से अधिक है, जबकि 41 जिलों में श्रम उत्पादकता 1000 रु. प्रति पुरुष कृषि श्रमिक से भी कम है। इस प्रकार 44 जिलों में प्रति पुरुष कृषि श्रमिक औसत उत्पादकता 1800 से 2200 रु., 65 जिलों में 1400 से 1800 रु. एवं 78 जिलों में 1000 से 1400 रु. है। पंजाब राज्य के सभी 11 जिलों में प्रति पुरुष कृषि श्रम-उत्पादकता 2200 रु. से अधिक थी, जबकि पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार एवं जम्मू व कश्मीर राज्य के किसी भी जिले में प्रति पुरुष कृषि श्रम-उत्पादकता 2200 रु. से अधिक नहीं पाई गई।

भारत में श्रम-उत्पादकता वर्ष 1962 से 1965 के काल में 1640 रु. प्रति पुरुष कृषि श्रमिक थी, वह कम होकर वर्ष 1970-1973 में 1596 रु. हो गई। अधिक उत्पादन वाले जिलों में श्रम-उत्पादकता अधिक एवं स्थिर उत्पादन या कम कृषि उत्पादन वाले जिलों में श्रम-उत्पादकता कम पाई गई। अतः देश में निर्धनता-उन्मूलन के लिए भूमि उत्पादकता के साथ-साथ श्रम-उत्पादकता में भी वृद्धि करना आवश्यक है। प्रो गुन्नार मिर्डाल के अध्ययन के अनुसार, भारत में न केवल प्रति इकाई भूमि की उत्पादकता कम है, बल्कि श्रमिकों की उत्पादकता का स्तर भी कम है। भूमि एवं श्रम-उत्पादकता में वृद्धि देश की समृद्धि के लिए आवश्यक है।

राष्ट्रीय-आय

देश की अर्थव्यवस्था के अध्ययन में राष्ट्रीय-आय का स्थान महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय-आय देश की अर्थव्यवस्था के विकास की सूचकांक होती है। प्रो साइमन कुजनेट्स⁹ के अनुसार "राष्ट्रीय-आय, वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पत्ति की वह मात्रा है जो एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन प्रणाली से अन्तिम उपभोक्तानों तक पहुँचती है अथवा देश के पूँजीगत वस्तुओं के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि करती है।" राष्ट्रीय-आय में उत्पादन एवं उपभोग दोनों ही प्रकार की वस्तुओं का मूल्य सम्मिलित किया जाता है। राष्ट्रीय आय समिति, 1951 के अनुसार एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य बिना किसी प्रकार के दोहराव (Duplication) के राष्ट्रीय आय कहलाता है।

9 "National income is the output of commodities and services flowing during the year from the country's productive system into the hands of the ultimate consumer or into net additions to the country's stock of capital goods, Simon Kuznets, Economic's Change, Prentice Hall of India Pvt LTD, New Delhi, p. 148.

राष्ट्रीय-धाय से सम्बन्धित शब्दों की परिभाषा :

समग्र राष्ट्रीय उत्पाद—समग्र राष्ट्रीय उत्पाद से तात्पर्य एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य से है।¹⁰ समग्र राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को सम्मिलित नहीं किया जाता है, बल्कि उत्पादित अन्तिम उपयोग की वस्तुओं के मूल्य को ही सम्मिलित किया जाता है। देश के उपभोक्ताओं एवं सरकार द्वारा न्य की गई वस्तुओं की मात्रा, व्यापारियों द्वारा न्य करके अपने स्टॉक में की गई परिवर्तन की मात्रा एवं विदेशों में निर्यातित वस्तुओं की मात्रा के मूल्य को सम्मिलित करके समग्र राष्ट्रीय उत्पाद की मात्रा ज्ञात की जाती है।

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद/राष्ट्रीय-धाय बाजार कीमत पर—समग्र राष्ट्रीय उत्पाद की मात्रा में से वस्तुओं के मूल्य-ह्रास (Depreciation) की राशि घटाने पर जो राशि शेष रहती है वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या बाजार कीमत पर राष्ट्रीय धाय कहलाती है। **उर्ध्वग**¹¹ के शब्दों में, शुद्ध राष्ट्रीय-धाय से तात्पर्य एक वर्ष की अवधि में अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्रियाओं से उत्पादित की जाने वाली नई शुद्ध सम्पत्ति की मात्रा से है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन प्रचलित बाजार कीमत के आधार पर किया जाता है। सूत्र के अनुसार,

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद = समग्र राष्ट्रीय उत्पाद — वस्तुओं के मूल्य-ह्रास की राशि।

साधनों की लागत के अनुसार राष्ट्रीय-धाय—शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की राशि में से दिये गये परोक्ष करों की राशि को घटाने पर जो राशि शेष रहती है वह साधनों की लागत के अनुसार राष्ट्रीय-धाय कहलाती है। **सूत्र**¹² के अनुसार समग्र राष्ट्रीय उत्पाद के उत्पादन में विभिन्न उत्पादन साधनों के स्वामियों को प्राप्त धाय (मजदूरी, लाभ, लगान, भ्याज, आदि) का योग ही राष्ट्रीय-धाय होती है। सूत्र के अनुसार,

10. "The GNP is the value of all goods and services produced annually in the nation", Charles L. Schultze, National Income Analysis, Prentice-Hall of India Private LTD, New Delhi, 1965 p. 19

11. "Net national product is the net creation of new wealth resulting from the productive activity of the economy during the accounting period."

—T P Dernburg & D. M. MC Dougall, Macro-Economics, McGraw Hill Book Company, New York, 1968, p. 24.

12. "Gross national income is the sum of all incomes (wages, profit, rent, interest etc.) earned in the production of gross national product"

—Charles L. Schultze, National Income Analysis; Prentice Hall of India Private LTD., New Delhi, 1965 p. 20

राष्ट्रीय-प्राय = शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद — परोक्ष करो की राशि

राष्ट्रीय-प्राय के अध्ययन की उपयोगिता — राष्ट्रीय आय के अध्ययन के मुख्य उपयोग निम्न हैं —

(i) राष्ट्रीय-आय देश की अर्थव्यवस्था के विकास की सूचकांक होती है।

(ii) राष्ट्रीय-आय देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों की महत्ता का द्योतक होती है।

(iii) राष्ट्रीय-आय विभिन्न देशों एवं राज्यों के आर्थिक विकास का प्रतीक होती है।

(iv) राष्ट्रीय-प्राय देश के अन्तर्गत हो रहे आर्थिक विकास कार्यक्रमों का देश के नागरिकों के जीवन-स्तर पर होने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करती है।

(v) सरकार को देश के विकास के लिए विभिन्न नीतियों — करारान, बचत एवं निवेश, रोजगार उपनद्धि; मजदूरी एवं विकास योजनाओं के लक्ष्य निर्धारित करने में भी राष्ट्रीय-प्राय का ज्ञान आवश्यक है।

राष्ट्रीय-प्राय के आकलन की विधियाँ — राष्ट्रीय-प्राय को आकलन करने की मुख्यतया निम्न तीन विधियाँ प्रचलित हैं :

(1) उत्पाद विधि — इस विधि के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों (कृषि, खनिज पदार्थों, निर्मित एवं सहायक उद्योगों) के क्षेत्र में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं का शुद्ध मूल्य ज्ञात किया जाता है। सूत्र के अनुसार,

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद = [कुल उत्पाद (बिजली + निजी उपभोग + विक्रेताओं के स्टॉक में वृद्धि + शुद्ध निर्यात) - मूल्य-ह्रास लागत + माध्यमिक उत्पादित वस्तुओं का मूल्य]

इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त शुद्ध उत्पाद मूल्य को सम्मिलित करके शुद्ध राष्ट्रीय-प्राय ज्ञात की जाती है। इस विधि से विभिन्न क्षेत्रों का राष्ट्रीय-प्राय में अंश भी ज्ञात हो जाता है।

(2) आय विधि — राष्ट्रीय-प्राय ज्ञात करने की इस विधि में विभिन्न उत्पादन-साधनों के स्वामियों द्वारा वर्ष में प्राप्त आय (लभान, मजदूरी, न्याज एवं लाभान) की राशि को सम्मिलित किया जाता है। इस विधि से विभिन्न वर्गों, जैसे — कृषकों, पूँजीपतियों एवं प्रबन्धकों तथा उद्यमकर्त्ताओं को प्राप्त आय के वितरण की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है।

(3) लागत विधि — इस विधि में वैयक्तिक तथा सरकार द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं पर किये गये उपभोग खर्च एवं निवेश की राशि को सम्मिलित करते हुए राष्ट्रीय आय आकलित की जाती है।

भारत में राष्ट्रीय आय समिति ने राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए उत्पाद विधि एवं आय विधि ही प्रयोग में ली है, क्योंकि लागत विधि में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं पर किये गये उपभोग लागत एवं निवेश की राशि के विश्वसनीय आँकड़े एकत्रित करने का कार्य कठिन होता है। वर्तमान में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के व्यक्तियों के व्यय के आँकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं, जिनके आधार पर लागत विधि भी राष्ट्रीय आय के आकलन में प्रयुक्त की जा सकती है।

भारत में राष्ट्रीय-आय का आकलन

भारत में राष्ट्रीय-आय का आकलन सर्वप्रथम वर्ष 1868 में दादाभाई नौरोजी ने किया था। उसके पश्चात् विभिन्न व्यक्तियों/आयोगों/संस्थाओं ने समय-समय पर राष्ट्रीय-आय का आकलन किया, किन्तु प्रत्येक संस्था/व्यक्ति द्वारा दिये गये आँकड़ों में बहुत अन्तर पाया गया। अतः वर्ष 1949 में भारत सरकार ने पी. सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति नियुक्त की। समिति ने वर्ष 1948-49 से 1950-51 के लिए राष्ट्रीय आय का आकलन अप्रैल, 1951 के प्रतिवेदन में सरकार को दिया। तत्पश्चात् राष्ट्रीय आय का आकलन करने का कार्य केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (Central Statistical Organization) को दिया गया। यह संगठन राष्ट्रीय-आय के आँकड़ों का वार्षिक परिपत्र प्रकाशित करता है। भारत में राष्ट्रीय आय के आँकड़े वर्ष 1948-49, 1960-61, 1970-71 व 1980-81 के कीमतों पर प्रकाशित किये गये हैं। वर्तमान में 1950-51 से 1986-87 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय आय के आँकड़े प्रचलित कीमतों व 1970-71 की कीमतों पर उपलब्ध हैं। सारणी 2.8 में भारत में राष्ट्रीय-आय एवं प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों व वर्ष 1970-71 की कीमतों के स्तर पर वर्ष 1950-51 से 1986-87 तथा वर्ष 1980-81 की कीमत स्तर पर 1980-81 से 1988-89 के काल में दी गई है।

सारणी 2.8

भारत में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय

वर्ष	शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद-साधन लागत पर (करोड़ रुपये में)		प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय (रुपये में)	
	प्रचलित कीमत स्तर पर	वर्ष 1970-71 की कीमत स्तर पर	प्रचलित कीमत स्तर पर	वर्ष 1970-71 की कीमत स्तर पर
1950-51	8,821	16,731	246	466
1955-56	9,262	19,953	236	508
1960-61	13,263	24,250	306	559
1965-66	20,637	27,103	426	559
1970-71	34,235	34,235	633	633
1975-76	62,302	40,274	1,026	664
1980-81	1,05,743	47,414	1,557	698
1981-82	1,28,547	49,935	1,743	720
1982-83	1,33,807	51,154	1,887	722
1983-84	1,58,265	55,300	2,186	764
1984-85	1,74,018	57,243	2,355	775
1985-86	1,95,707	60,143	2,596	798
1986-87	2,15,770	63,150	2,800	820

नई सीरीज वर्ष 1980-81 की कीमत स्तर पर

1980-81	110,340	110,340	1627	1627
1981-82	128,757	117,101	1851	1684
1982-83	142,509	120,320	1993	1682
1983-84	167,494	130,396	2290	1780
1984-85	186,486	135,021	2495	1804
1985-86	207,239	140,260	2735	1852
1986-87	229,232	145,418	2970	1881
1987-88	260,580	151,764	3286	1910
1988-89	312,634	168,382	3835	2082

स्रोत : Economic Survey, Ministry of Finance, Government of India New Delhi.

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि देश की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में निरन्तर वृद्धि हुई है। प्रचलित कीमत स्तर पर वर्ष 1950-51 में देश की राष्ट्रीय आय 8,821 करोड़ रुपये थी, वह बढ़कर 1986-87 में 2,15,770 करोड़ रुपये हो गई। राष्ट्रीय आय में वृद्धि 1970-71 की कीमत एवं 1980-81 की कीमत स्तर में भी हुई है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय प्रचलित कीमत पर वर्ष 1950-51 में मात्र 246 रुपये थी, जो बढ़कर 1986-87 में 2,800 रुपये एवं 1987-88 में 3 286 रुपये हो गई। इस प्रकार देश में पिछले 38 वर्षों में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में तीव्र गति दर से वृद्धि हुई है। जब अन्य देशों की प्रति व्यक्ति औसत आय से भारत की तुलना करते हैं, तो उद्योग प्रधान विकसित देश और तेल उत्पादक देशों की तुलना में भारत का स्थान बहुत नीचे है। अर्थविकाश विकासशील देशों में भी भारत पिछड़ा हुआ ही है, जबकि कहा जाता है कि औद्योगिक विकास में भारत का स्थान सम्पूर्ण देशों में दसवें स्थान पर है।

सारणी 2.9 भारत के विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति औसत आय प्रदर्शित करती है। प्रचलित कीमत स्तर एवं वर्ष 1980-81 की कीमतों के स्तर पर राज्यों में प्रति व्यक्ति औसत आय में बहुत विभिन्नता है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र व हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत आय भारत की औसत आय से अधिक है, जबकि अन्य राज्यों में प्रति व्यक्ति औसत आय भारत के समतुल्य अथवा उससे कम है। राज्यों में पिछले दशक में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की प्रतिशतता में भी बहुत भिन्नता है।

सारणी 2.9

भारत के विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति औसत आय

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	प्रचलित कीमत स्तर पर				वर्ष 1980-81 की कीमत स्तर पर	
	1960-61	1970-71	1980-81	1988-89	1980-81	1988-89
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	314	586	1380	3211	1380	1692
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—	1557	4599	1557	2429
3. असम	349	570	1200	2756	1200	1558
4. बिहार	216	418	896	2266	896	1071
5. गोवा	—	—	3145	6231	3145	3523
6. गुजरात	380	845	1970	4742	1970	2506

1	2	3	4	5	6	7
7 हरियाणा	—	932	2370	5274	2370	3086
8 हिमाचल प्रदेश	—	676	1664	3614	1664	1948
9 जम्मू एंव कश्मीर*	267	557	1455	NA	642	NA
10 कर्नाटका	295	675	1612	3602	1612	2041
11 केरल	278	636	1463	3054	1463	1447
12. मध्य प्रदेश*	274	489	1183	2739	517	680
13 महाराष्ट्र	419	811	2427	5155	2427	2960
14 मणीपुर	—	408	1449	2897	1449	1775
15. मेघालय	—	644	1361	NA	1361	NA
16. मिजोरम	—	—	1289	NA	NA	NA
17. नागालैण्ड	—	508	1383	3463	NA	NA
18. उड़ीसा	266	541	1231	2625	1231	1455
19. पंजाब	383	1067	2724	6227	2724	3552
20 राजस्थान	271	629	1199	2923	1199	1620
21. सिक्किम	—	—	1571	NA	1571	NA
22. तमिलनाडु	344	616	1498	3593	1498	2030
23 त्रिपुरा	—	563	1323	NA	1323	NA
24. उत्तर प्रदेश	244	493	1284	2698	1284	1547
25. पश्चिम बंगाल	286	729	1612	3423	1612	1930
26. दिल्ली*	—	—	3127	NA	1455	NA
27 पाण्डीचेरी	—	—	3159	5421	3159	3067
भारत	306	631	1627	3835	1627	2082

*Based on old 1970-71 base.

Source Estimates of State Domestic Product and Capital Formation, 1990, Central Statistical Organisation, Department of Statistics, Ministry of Planning, Government of India, New Delhi,

सारणी 2 10 व 2.11 देश के समग्र घरेलू उत्पाद मे ग्रथव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो का ग्रथ प्रदर्शित करती है ।

सारणी 2 10

सारणी 2-10 व 2-11 देश के समग्र घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का अंश प्रदर्शित करती है ।

देश के समग्र घरेलू उत्पाद-सागत मूल्य में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का अंशदान (वर्ष 1970-71 की कीमतों पर)

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कृषि क्षेत्र (हृषि, वन, मत्स्य पालन आदि)	द्वितीय क्षेत्र (निर्मित निर्माण विद्युत, जल पूर्ति)	तृतीय क्षेत्र (परिवहन, संचार एवं व्यापार)	चतुर्थ क्षेत्र (वैज्ञानिक, बीमा आदि)	अन्य (रक्षा, लोक प्रशासन आदि)	कुल समग्र घरेलू उत्पाद
योजना काल से पूर्व						
1950-51	10,453 (59 61)	2,538 (14 47)	2,085 (11 89)	919 (5 24)	1,541 (8 79)	17,536 (100)
1955-56	12,123 (58 09)	3,229 (15 47)	2 639 (12 64)	1 095 (5 25)	1 784 (8 55)	20,870 (100)
1960-61	14,078 (55 13)	4,413 (17 28)	3,523 (13 80)	1,292 (5 06)	2,228 (8 73)	25,534 (100)
1965-66	13 559 (46 72)	6,297 (21 70)	4 735 (6 131)	1 659 (5 72)	2 773 (9 55)	29,023 (100)
1970-71	17,802 (48 46)	7,594 (20 67)	5,912 (16 09)	2,114 (5 75)	3 314 (9 03)	36,736 (100)
1975-76	19,934 (46 48)	8,782 (20 47)	7,461 (17 40)	2,574 (6 00)	4,139 (9 65)	42,890 (100)
1980-81	21,015 (41 51)	10,937 (21 60)	9,554 (18 87)	3,358 (6 64)	5,759 (11 38)	50,623 (100)

स्रोत Economic Survey, 1988-89. Ministry of Finance
Government of India, New Delhi 1989, P S-6

सारणी 2 11

देश के समग्र घरेलू उत्पाद लागत मूल्य पर मे ग्रथव्यवस्था के विभिन्न
क्षत्रो का ग्रशदान (वर्ष 1980-81 को कीमतो पर)

(करोड रुपयो मे)

क्षेत्र	1980-81	1985-86	1988-89
(1) कृषि, वन एव मत्स्य पालन	46,649 (38 2)	54,252 (34 6)	61,789 (32 9)
(2) खान एव खदान	1,887 (1 5)	2,623 (1 7)	3,339 (1 8)
(3) निर्मित क्षेत्र	21,644 (17 6)	30,320 (19 4)	37,710 (20 1)
(4) विद्युत, गैस एव जलपूरति	2,070 (1 7)	3,099 (2 0)	4,127 (2 2)
(5) निर्माण	6,114 (5.0)	7,183 (4 6)	8,068 (4 3)
(6) व्यापार, होटल एव रेस्टोरेन्ट	14,713 (12 0)	19,649 (12 5)	23,920 (12.8)
(7) परिवहन, सफ़ाई एव संचार	5,724 (4 7)	7,951 (5 1)	9,893 (5 3)
(8) वित्त, बीमा, स्थायी सम्पदा एव व्यापारिक सेवाए	10,791 (8 8)	14,708 (9 4)	18,456 (9 9)
(9) सामूहिक, सामाजिक एव वैयक्तिक सेवाए	12,835 (10 5)	16,815 (10 7)	20,423 (10 9)
कुल समग्र उत्पाद लागत मूल्य पर	122,427 (100)	156,600 (100)	187,725 (100)

Source . National Accounts Statistics 1991, Central Statistical Organisation Department of Statistics, Ministry of Planning, Government of India, New Delhi.

अर्थ-व्यवस्था को 5 क्षेत्रों-कृषि-क्षेत्र, निमित्त, निर्माण, विद्युत् एवं जलपूर्ति, परिवहन, संचार एवं व्यापार, बैंक बीमा एवं अन्य क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। योजना काल से पूर्व कृषि क्षेत्र से समग्र राष्ट्रीय उत्पाद का 59.61 प्रतिशत अंश प्राप्त होता था तथा अर्थ-व्यवस्था के अन्य चारों क्षेत्रों में 40.39 प्रतिशत अंश प्रदान करते थे। योजना काल में सभी क्षेत्रों का निरन्तर विकास हुआ है। सभी क्षेत्रों के विकास के बावजूद आज (1987-88) भी कृषि-क्षेत्र समग्र राष्ट्रीय उत्पाद का एक-तिहाई भाग प्रदान करता है। अतः भारत के समग्र राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि क्षेत्र प्रमुख भूमिका निभाता है। विकसित देशों में कृषि-क्षेत्र का अंशदान कम एवं निमित्त व उद्योग क्षेत्र का अंश अधिक होता है। भारत में कृषि-क्षेत्र की आय का 18 प्रतिशत अर्थात् पाँचवा भाग पशुओं से प्राप्त होता है। पशुओं से प्राप्त आय का यह स्तर आयरलैंड, स्वीडन एवं नार्वे देशों की तुलना में बहुत कम है। इन देशों में 80 प्रतिशत से अधिक आय पशुधन से प्राप्त होती है।

भारतीय कृषि की समस्याएँ

भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएँ निम्न हैं जो विभिन्न उत्पादन-साधनों के अनुसार वर्गीकृत की गई हैं—

1. भूमि सम्बन्धी समस्याएँ :

भारतीय कृषि में भूमि सम्बन्धी निम्न प्रमुख समस्याओं के कारण भूमि की उत्पादकता का स्तर अन्य देशों की अपेक्षा कम है—

(अ) भूमि की उर्वरा शक्ति में ह्रास—उत्पादकता में बाधक प्रथम तत्त्व भूमि की उर्वरा शक्ति में निरन्तर ह्रास होना है। खूँको द्वारा भूमि पर निरन्तर फसलों के उत्पादन करने एवं उनकी कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का उपयोग नहीं करने से भूमि की उर्वरा शक्ति निरन्तर कम होती जाती है। हवा व पानी से भूमि के कटाव, भूमि पर निरन्तर पानी भरा रहने, उचित फसल-चक्र का अभाव भी भूमि की उर्वरा-शक्ति के ह्रास में वृद्धि करते हैं।

(ब) जोत उप-विभाजन एवं अपखण्डन—भूमि सम्बन्धी दूसरी प्रमुख समस्या देश में प्रचलित उत्तराधिकार कानून के कारण जोत का उप-विभाजन एवं अपखण्डन की है। इस समस्या के कारण जोत का आकार निरन्तर कम होता जाता है। भूमि के खण्ड एक-दूसरे से दूर होते जाते हैं। अतः जोत आर्थिक दृष्टि से लाभकर नहीं होती है।

(स) भू-धृति की दोष-युक्त पद्धति—देश में जागीरदारी, जमींदारी, पट्टेदारी, बटाईदारी, अनुपस्थित जमींदारी (Absentee landlordism) आदि अनेक प्रकार की भू-धृति कुरीतियाँ शताब्दियों से प्रचलित हैं। इनके कारण भूमि के स्वामी वास्तविक कृषक न होकर जमींदार होते हैं। जमींदार कृषकों से उत्पादन का अधिक

भाग लगान के रूप में प्राप्त करते हैं, जिसके कारण कृषकों में उत्पादन-वृद्धि की प्रेरणा का ह्रास होता है।

(ब) **अनाधिक जोतें**—देश में जोत का औसत आकार बहुत कम (1.68 हेक्टर) है। कृषि जनगणना 1985-86 के अनुसार देश में 58.1 प्रतिशत, जोतें एक हेक्टर से कम भूमि के क्षेत्र की हैं तथा इनके पास कुल कृषित भूमि का 13.2 प्रतिशत भू-क्षेत्र ही है। जोत के आकार के कम होने से जोत आर्थिक दृष्टि से लाभकर नहीं होती है। प्रति इकाई क्षेत्र से उत्पादन कम प्राप्त होता है एवं उत्पादन लागत अधिक घाती है। दूसरी ओर अनेक जोतें काफी बड़े आकार की हैं जिनके पास उत्पादन के लिए पर्याप्त साधन नहीं होने से काफी भूमि अकृषित रहती है।

2. भ्रम/सम्बन्धी समस्याएं :

कृषि-क्षेत्र में भ्रम सम्बन्धी निम्न समस्याओं के कारण भूमिको की कार्य-क्षमता कम होती है—

(अ) **भूमिकों का भूमि पर अधिक भार**—देश में जनसंख्या की अधिकता, कृषि व्यवसाय को उत्तम व्यवसाय मानने, गांवों में रोजगार के लिए कुटीर उद्योगों का अभाव आदि के कारण कृषि क्षेत्र में भूमिकों का भार अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। भारत में प्रति कृषि भूमिक 1.2 हेक्टर भूमि है जबकि इजरायल में 4.1 हेक्टर, अर्जेंटीना में 13.1 हेक्टर, स्पेन में 4.4 हेक्टर, मैक्सिको में 4.1 हेक्टर, टर्की में 2.6 हेक्टर एवं पाकिस्तान में 1.5 हेक्टर भूमि क्षेत्र है।¹³

भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्र मात्र 0.33 हेक्टर ही है जोकि अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि एवं भूमि के क्षेत्र की सीमितता के कारण प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्र निरन्तर कम होता जा रहा है। भारत के विभिन्न राज्यों में मानव-भूमि-अनुपात में बहुत विभिन्नता है। भारत में प्रति व्यक्ति भूमि क्षेत्र वर्ष 1969-70 में आकड़ों के अनुसार केरल में 0.18 हेक्टर, पश्चिमी बंगाल में 0.19 हेक्टर, बिहार में 0.30 हेक्टर, उत्तर प्रदेश में 0.32 हेक्टर, तमिलनाडु में 0.33 हेक्टर, जम्मू एवं कश्मीर में 5.50 हेक्टर, नागालैंड में 3.83 हेक्टर, राजस्थान में 1.30 हेक्टर व मध्य प्रदेश में 1.09 हेक्टर है।¹⁴

(ब) **कृषि भूमिकों में व्याप्त बेरोजगारी**—भारतीय कृषि मौसमी व्यवसाय है। मौसम के प्रारम्भ (फसल की बुवाई) व अन्त (फसल की कटाई) में कार्य की

13 B M Bhatta, *India's Food Problem and Policy Since Independence*, Somaya Publications PVT LTD, Bombay, 1970, P 72

14 I J Singh, *Land Fertilizer Ratio to Attain Foodgrain Self Sufficiency in India*, Haryana Agriculture University Journal of Research, Vol IV, No 2 June 1974, P P 127-132.

अधिकता के कारण कृषि श्रमिकों की मांग अधिक होती है। अन्य समय में कार्य उपलब्ध नहीं होने में श्रमिक बेकार रहते हैं। कृषि श्रमिकों को वर्ष में औसतन 5-6 माह रोजगार उपलब्ध होता है और शेष समय वे बेकार रहते हैं। रोजगार की निरन्तर उपलब्ध नहीं होने से श्रमिकों की कार्य-क्षमता पर विपरीत प्रभाव आता है।

(स) कृषि श्रमिकों की मजदूरी का स्तर अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम होना—कृषि श्रमिकों में व्याप्त बेरोजगारी के साथ-साथ उनको उपलब्ध कार्य की मजदूरी भी अन्य उद्योगों की अपेक्षा कम मिलती है। इसका मुख्य कारण कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों का संगठित नहीं होना, कृषि श्रमिकों की मांग एवं पूर्ति में असन्तुलन श्रमिकों का गांव छोड़कर शहर में कार्य के लिए जाने को तैयार नहीं होना तथा श्रमिकों द्वारा कृषि व्यवसाय को उत्तम व्यवसाय मानना है। कृषि श्रमिकों की मजदूरी कम प्राप्त होने के कारण उनका रहन सहन का स्तर अन्य उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की अपेक्षा न्यूनतम होता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।

3 पूँजी सम्बन्धी समस्याएँ

कृषि क्षेत्र में पूँजी सम्बन्धी प्रमुख समस्याएँ निम्न हैं, जो उत्पादन वृद्धि में बाधक होती हैं—

(अ) कृषि में स्थायी पूँजी की अधिक आवश्यकता—कृषि व्यवसाय में अन्य उद्योगों की अपेक्षा भूमि सुधार कार्य करना, कुआँ बनाने, सिंचाई की नालियाँ बनाने, खेत की बाड़ लगाना, ट्रैक्टर एवं अन्य मशीनें खरीदना आदि कार्यों के लिए अधिक स्थायी पूँजी की आवश्यकता होती है। कृषि क्षेत्र में बचत के कम होने के कारण कृषक आवश्यक राशि में स्थायी पूँजी निवेश नहीं कर पाते हैं। कृषि में स्थायी पूँजी की राशि अधिक समय तक निवेश रहने के कारण ऋणदात्री संस्थाएँ कृषकों को लम्बे समय के लिए ऋण देने में हिचकिचाती हैं। कृषकों को आवश्यक मात्रा में स्थायी पूँजी उपलब्ध नहीं होती है एवं उपलब्ध होने पर स्वीकृत ऋण-राशि पर व्याज की दर अधिक दनी होती है।

(ब) कायगत पूँजी का अभाव—कृषि व्यवसाय में उत्पादन साधना बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों के त्रय करने श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान करना बिजली व तेल के भुगतान आदि कार्यों के लिए कायगत पूँजी की अधिक आवश्यकता होती है। कृषि में आवश्यक बचत के अभाव में कृषक कायगत पूँजी में ऋणदात्री संस्थाओं से उधार लेते हैं। लघु कृषक आवश्यक प्रतिभूति के अभाव में कायगत पूँजी ऋण के रूप में प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिससे उचित मात्रा में उत्पादन साधना का उपयोग नहीं हो पाता है और फार्म पर उत्पादन कम होता है।

4 प्रबन्ध सम्बन्धी समस्याएँ •

प्रबन्ध सम्बन्धी समस्याओं में कृषकों को फार्म प्रबन्ध सिद्धान्तों का ज्ञान न होना, कृषकों की रुढ़िवादिता, जोखिम वहन क्षमता का अभाव एवं कृषि की उन्नत विधियों का ज्ञान न होना प्रमुख है। फार्म प्रबन्ध ज्ञान कृषकों को फार्म पर लागत में कमी करने तथा आय में वृद्धि करने में सहायक होता है। फार्म उत्पादन के सभी उत्पादन-साधन कृषकों के पास होते हुए भी, प्रबन्ध ज्ञान के अभाव में वे फार्म से अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

5 अन्य समस्याएँ

कृषकों की अन्य प्रमुख समस्याएँ निम्न हैं—

(अ) ठोस कृषि नीति का अभाव—सरकार स्वतन्त्रता के समय से ही कृषि-उत्पादन में वृद्धि की नीति को प्राथमिकता प्रदान कर रही है, लेकिन इस विषय पर सरकार की वर्तमान में भी कोई ठोस नीति नहीं है। उदाहरणतया सरकार भूमि की अधिकतम सीमा, भू-धृति पद्धति, कृषि कर, कृषि-उत्पाद एवं उत्पादन-साधनों की कीमत नीति में निरन्तर परिवर्तन करती रही है। परिवर्तनों की सम्भावना की अवस्था में निर्धारित नीतियाँ पूर्णरूप से कार्यान्वित नहीं हो पाती हैं। निर्धारित नीति के समय पर कार्यान्वित नहीं होने से निर्धारित लक्ष्य भी प्राप्त नहीं होते हैं। परिवर्तनशील नीतियाँ अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न करती हैं।

(ब) विपणन एवं कीमतों सम्बन्धी समस्याएँ—कृषि उत्पादन में वृद्धि होते हुए भी कृषकों को कृषि व्यवसाय से उत्पादों का उचित विपणन व्यवस्था व कीमत-नीति के अभाव में अनुकूलतम लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। कृषि वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव, मण्डी में विपणन मध्यस्थों की अधिकता, खान्दानों के विपणन में विपणन लागत की अधिकता, विपणन कुरीतियाँ, नियन्त्रित मण्डियों का अभाव कृषकों में कीमत अज्ञानता, संग्रहण के लिए गोदामों का अभाव आदि समस्याओं के कारण कृषकों को उत्पाद के विक्रय से उचित कीमत प्राप्त नहीं होती है।

(स) सिंचाई एवं विद्युतीकरण की समस्याएँ—भारतीय कृषि की अन्य समस्या देश में सिंचाई की सुविधा का आवश्यक मात्रा में उपलब्ध नहीं होना, विद्युतीकरण की सुविधाओं का गावों में विकास न होना, समय पर विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं होना।

(द) उत्पादन-साधनों का उचित समय एवं उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं होने की समस्या—हरितक्रांति एवं तकनीकी ज्ञान के प्रसार के कारण, कृषक उत्पादन साधनों-सकर एवं बोने किस्म के बीज, उर्वरक, कीटनाशी द्रव्य आदि का अधिक मात्रा में उपयोग करने लगे हैं, किन्तु उत्पादन के ये साधन उन्हें

समय एवं उचित कीमत पर आवश्यक मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अतः समय पर उत्पादन-साधनों के अभाव में फार्म में उत्पादन कम प्राप्त होता है।

(य) फसल व पशु बीमा सुविधा न होना—कृषि-क्षेत्र में जोखिम के कारण उत्पादन में अनिश्चितता बनी रहती है। प्रतिवर्ष किसी न किसी क्षेत्र के कृषक बीला, सूखा, समय पर वर्षा के नहीं होने, आग, बीमारियों आदि से प्रभावित होते रहते हैं, इससे उनके भावी उत्पादन पर विपरीत प्रभाव आता है।

(१) कृषि विस्तार सेवाओं का कृषकों द्वारा लाभ नहीं उठाना—अनेक क्षेत्र में कृषि विस्तार सेवाएँ विकसित नहीं हैं तथा अन्य क्षेत्रों में कृषक अज्ञानता के कारण उनका लाभ नहीं उठा रहे हैं।

उपयुक्त समस्याओं के कारण कृषकों में उत्पादन वृद्धि की प्रेरणा का हास होता है। अतः कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उपयुक्त समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है।

□□□□

अध्याय 3

भारत में खाद्य-समस्या

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में देश खाद्यान्न उत्पादन में आरम्भ-निर्भर था। देश में समय समय पर अकाल के कारण खाद्यान्न की कमी महसूस होती रही है, लेकिन वर्ष 1860 के पश्चात् खाद्यान्न की विशेष कमी महसूस हुई। भारत में सर्व-प्रथम, अकाल प्रायोग ने वर्ष 1880 में चेतावनी दी कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धि में कमी होगी। देश में वर्ष 1860 से 1909 के 50 वर्षों में 20 वर्ष अकाल या कम उत्पादन वाले थे। इनमें से वर्ष 1865-66 में उड़ीसा में एवं 1896-97 में सम्पूर्ण देश में भीषण अकाल पड़े थे, जिन्होंने खाद्य समस्या को अधिक जटिल बना दिया था। वर्ष 1895-96 में देश में 2.4 मिलियन टन, 1896-97 में 1.5 मिलियन टन एवं 1899-1900 में 2.2 मिलियन टन खाद्यान्न का आयात किया गया था।

वर्ष 1893-94 से 1945-46 की अवधि में जनसंख्या में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि कृषि क्षेत्र एवं भूमि की उत्पादकता में विशेष वृद्धि नहीं होने के कारण इस अवधि में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न के उत्पादन स्तर में 32% की गिरावट हुई।¹ वर्ष 1921 के उपरान्त जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, कृषि क्षेत्र के स्थिर रहने, खाद्यान्न से वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल के स्थानान्तरण होने एवं वर्ष 1937 में देश में वर्मा के अन्तर्भ होने से खाद्य स्थिति निरन्तर खराब होती गई। वर्ष 1910 से 1940 के तीस वर्षों में 18 वर्ष कम उत्पादन वाले वर्ष थे। वर्ष 1943 का बंगाल अकाल विशेष उल्लेखनीय माना गया है। स्वतन्त्रता से पूर्व देश में खाद्यान्न का निरन्तर आयात किया गया। स्वतन्त्रता के पूर्व वर्ष में देश में 2.58 मिलियन टन खाद्यान्न का आयात किया गया।

वर्ष 1943 के अकाल ने सरकार को उत्पादन वृद्धि की ओर ध्यान देने को

1 B M Bhatia, India's Food Problem and Policy Since Independence, Somaiya Publications Pvt Ltd, Bombay, 1970

2. Blyn, George, The Agricultural Crops of India, 1893-1946

विद्यमान किया। सरकार ने “अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन” (Grow More Food Campaign) शुरू किया। वर्ष 1947 में देश के विभाजन के कारण अधिक उत्पादन वाले क्षेत्र, जैसे—पंजाब का एक भाग एवं सिंध का क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये। विभाजन में पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल का 44 प्रतिशत एवं भारत को 19 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र ही प्राप्त हुआ।

योजना काल में पूर्व भारत में खाद्य स्थिति—स्वतन्त्र भारत के प्रथम चार वर्षों (योजनाकाल से पूर्व 1947-51) खाद्य स्थिति के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। प्रथम तो देश में स्वतन्त्रता के पूर्व में चली आ रही खाद्यान्नों की कमी, वर्ष 1948 में उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बाढ़ तथा गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में सूखे ने खाद्य स्थिति को और खराब कर दिया, जिसके कारण कीमती का बढ़ता शुरू हुआ। वर्ष 1950 में आनाहुट्टि एवं भीलहर में देश के विभिन्न भागों में फसल की नुकसान हुआ। खाद्यान्नों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनके आयात की मात्रा में वृद्धि की गई।

प्रथम पंचवर्षीय योजना एवं खाद्य स्थिति—प्रथम पंचवर्षीय योजना के पाँचों वर्षों (1951-56) खाद्य स्थिति के लिए अच्छे वर्षों थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्षों (1955-56) में 69.34 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ। फलस्वरूप खाद्यान्न की आपातिग मात्रा जो वर्ष 1951-52 में 3.92 मिलियन टन थी, वह कम होकर योजना के अन्तिम वर्षों (1955-56) में मात्र 1.37 मिलियन टन ही रह गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में 1953-54 का वर्ष कृषि उत्पादन की दृष्टि में सबसे अच्छा वर्ष था। इस वर्ष 72.34 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना एवं खाद्य स्थिति—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ही देश में खाद्य समस्या उत्पन्न हो गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्षों (1955-56) खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि में पहले वर्षों के समान अच्छा वर्ष नहीं था। बम्बई, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार एवं उड़ीसा के अनेक भागों में सूख की स्थिति थी, जबकि असम, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं पंजाब बाढ़ में एवं तमिलनाडु राज्य के कुछ जिलों में सूफान में प्रभावित हुए। इन सबके कारण देश में गन्धक, बाजरा एवं अन्य खाद्य पदार्थों का उत्पादन में गिरावट आई और वर्ष 1957-58 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 66.63 मिलियन टन ही हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्षों में 3.62 मिलियन टन एवं वर्ष 1957-58 में 3.21 मिलियन टन खाद्यान्न का आयात किया गया। उत्पादन में वृद्धि के प्रयास एवं मौसम की अनुपस्थिति के कारण वर्ष 1958-59 में खाद्यान्न उत्पादन 78.80 मिलियन टन हुआ, जो पिछले वर्षों की अपेक्षा 12.2 मिलियन टन अधिक था। वर्ष 1959-60 में 1958-59 की अपेक्षा 1.7 मिलियन टन कम खाद्यान्न उत्पादन हुआ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति वाले वर्ष में खाद्यान्न का उत्पादन 82.33 मिलियन टन प्राप्त हुआ, जो निर्धारित लक्ष्य 80 मिलियन टन से अधिक था। खाद्यान्न उत्पादन में इस असाधारण गति से वृद्धि के होते हुए भी देश में आयातित खाद्यान्नों की मात्रा में निरन्तर वृद्धि हुई। वर्ष 1959-60 में सर्वाधिक आयात 5.12 मिलियन टन का किया गया। भारत सरकार के कृषि एवं खाद्य मन्त्रालय द्वारा निम्नलिखित फोर्ड संस्था के कृषि-उत्पादन दल ने भारत भ्रमण के पश्चात् 3 अप्रैल, 1959 को "भारत में खाद्य-समस्या एवं पूर्ति के उपाय (India's Food Crisis and Steps to Meet it)" नामक प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया। दल ने आकलन किया कि खाद्यान्न-उत्पादन वृद्धि की वर्तमान दर एवं अन्य कारकों को मद्देनजर रखते हुए तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (1965-66) में देश में 28 मिलियन टन खाद्यान्नों की कमी होगी। अतः दल ने तृतीय पंचवर्षीय योजना का खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 120 मिलियन टन रखने का सुझाव दिया।³

तृतीय पंचवर्षीय योजना एवं खाद्य स्थिति—खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता के लिए योजना आयोग ने तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66) का खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 100 मिलियन टन निर्धारित किया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई तथा कृषि-उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रयास किये गये।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के 5 वर्षों में से चार वर्ष (वर्ष 1964-65 के प्रतिरिक्त) में मौसम अनुकूल नहीं होने के कारण खाद्यान्न उत्पादन का स्तर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (वर्ष 1960-61) के बराबर भी प्राप्त नहीं हो सका। वर्ष 1961-62 में 82.40 मिलियन टन, वर्ष 1962-63 में 80.33 मिलियन टन, एवं वर्ष 1963-64 में 80.70 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। इस योजनाकाल का सर्वाधिक उत्पादन वर्ष 1964-65 में 89.37 मिलियन टन था। देश के अधिकांश भाग में सूखे के कारण वर्ष 1965-66 में खाद्यान्न उत्पादन मात्रा 72.35 मिलियन टन ही हुआ। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाने के कारण सरकार ने प्रतिवर्ष पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में खाद्यान्नों का आयात किया। वर्ष 1961-62 में खाद्यान्नों की आयातित मात्रा 3.63 मिलियन टन थी जो योजना काल के अन्तिम वर्ष (1965-66) में बढ़कर 10.31 मिलियन टन हो गई, जो अब तक स्वतन्त्र भारत में आयातित खाद्यान्नों की मात्रा का सर्वाधिक रिकार्ड है। वर्ष 1961-62 में आयातित खाद्यान्नों का मूल्य 130 करोड़ रु था, जो बढ़कर वर्ष 1965-66 में 524 करोड़ रु हो गया। वर्ष 1962 में चीन के आक्रमण से भी कृषि उत्पादन को धक्का लगा।

3 Report on India's Food Crisis and Steps to Meet it, Government of India, New Delhi, April 1959, p. 1

इत बढती हुई खाद्यान्नों की समस्या का मुकाबला करने के लिए सरकार ने उत्पादन वृद्धि के लिए नवधन कृषि योजना जनसत्ता में वृद्धि की गति को रोकने के लिए परिवार नियोजन एवं खाद्यान्नों की बढती हुई माग को पूरा करने के लिये विनरए-प्रणाली में मुद्धार के कदम उठाये । उठाये गये कदमों में से कृषको, मिन-मालिकों एवं व्यापारियों से नैवी द्वारा खाद्यान्न प्राप्त, उद्दीप्ता, महाराष्ट्र एवं प्रसम राज्य न खाद्यान्न की सरकार द्वारा एकाधिकार अधिप्राप्ति-पद्धति, खाद्यान्न के सत्ता-सन की क्षेत्रीय पद्धति एवं कानूनन राजनिग प्रमुख कदम थे ।

वार्षिक योजनाएं एवं खाद्य स्थिति (1966-69)—जून, 1966 में भारत के रुपये का प्रवृत्त्यन एद विहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं अन्य प्रान्तों में सूखे की स्थिति के कारण खाद्य समस्या में विशेष मुद्धार नहीं हो सका । वर्ष 1966-67 में खाद्यान्न का उत्पादन 74.23 मिलियन टन हुआ । वर्ष 1967-68 में अच्छी वर्षा एवं मौसम की अनुकूलता के कारण खाद्यान्न उत्पादन 95.05 मिलियन टन हुआ, जो पिछले वर्ष (1966-67) की अपेक्षा 20.8 मिलियन टन अधिक था । उत्पादन वृद्धि के कारण आयातित खाद्यान्नों की मात्रा में निरन्तर कमी हुई । वर्ष 1966-67 में आयातित खाद्यान्नों की मात्रा 8.66 मिलियन टन थी, जो उत्पादन वृद्धि के कारण कम होकर वर्ष 1967-68 में 5.59 मिलियन टन एवं 1968-69 में 3.82 मिलियन टन हो रह गई ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना एवं खाद्य स्थिति (1969-74)—खाद्यान्न-उत्पादन में वृद्धि के लिए उन्नत किस्म के बीजों का आविष्कार वर्ष 1966 में हुआ । उन्नत किस्म के बीजों के उपयोग के साथ-साथ उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग, सिंचाई के साधनों में वृद्धि, कीटनाशी दवाइयों का उपयोग भी गुरु हुआ । इन उपायों के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसको हरित-क्रान्ति का नाम दिया गया । हरित-क्रान्ति के कारण देश में खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1970-71 में 108.42 मिलियन टन हुआ । वर्ष 1971-72 में खाद्यान्न के उत्पादन-स्तर में 3.25 मिलियन टन की गिरावट हुई । वर्ष 1972-73 में देश के अधिकतर भाग में सूखा पडने से उत्पादन-स्तर मात्र 97.03 मिलियन टन हुआ । देश के कुछ भागों में समय पर वर्षा नहीं होने एवं कम वर्षा होने के फलस्वरूप वर्ष 1973-74 में खाद्यान्न उत्पादन में पिछले वर्ष की अपेक्षा वृद्धि हुई, लेकिन यह वृद्धि वर्ष 1970-71 के उत्पादन-स्तर को नहीं पहुच सकी । योजना आयोग ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए 129 मिलियन टन खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया था, जो बाद में संशोधित करके 115 मिलियन टन दिया गया । दुर्भाग्यवश खाद्यान्नों के उत्पादन का यह स्तर भी योजना-काल के अन्त तक प्राप्त नहीं हो सका । वर्ष 1973-74 में निर्धारित उत्पादन लक्ष्य से 19.4 मिलियन टन खाद्यान्न कम प्राप्त हुआ । इस योजना काल में आयातित

खाद्यान्नों की मात्रा में निरन्तर कमी हुई। वर्ष 1969-70 में खाद्यान्नों की आयातित मात्रा 3.55 मिलियन टन थी। वर्ष 1971-72 में 0.49 मिलियन टन खाद्यान्नों का निर्यात किया गया। वर्ष 1972-73 व 1973-74 में सूखे की स्थिति के कारण खाद्यान्नों की आयातित मात्रा में पुनः वृद्धि हुई।

पाचवी पंचवर्षीय योजना एवं खाद्य स्थिति (1974-80)—इस योजना काल में खाद्यान्नों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के प्रारम्भिक वर्ष 1974-75 में देश में खाद्यान्नों का उत्पादन 99.83 मिलियन टन था, जो बढ़कर 1978-79 में 131.90 मिलियन टन हो गया। इस प्रकार इस योजना काल में 32 मिलियन टन खाद्यान्नों की उत्पादन वृद्धि हुई। फलस्वरूप खाद्यान्नों का आयात जो वर्ष 1974-75 में 7.53 मिलियन टन था वह कम होकर देश निर्यात करने की स्थिति में आ गया। वर्ष 1977-78 में लगभग एक मिलियन टन खाद्यान्नों का निर्यात किया गया था। वर्ष 1978-79 में मौसम की प्रतिकूलता के कारण खाद्यान्न उत्पादन में भारी गिरावट आई एवं उत्पादन मात्र 109.70 मिलियन टन ही प्राप्त हो सका। इससे भारत की खाद्य-स्थिति को भारी धक्का लगा।

छठी पंचवर्षीय योजना एवं खाद्य स्थिति (1980-85)—इस योजना के प्रथम वर्ष में खाद्यान्नों का उत्पादन 129.90 मिलियन टन था, जो बढ़कर 1983-84 में सर्वाधिक 152.37 मिलियन टन हो गया। वर्ष 1982-83 व 1984-85 उत्पादन की दृष्टि से अच्छे नहीं थे। योजना के प्रथम चार वर्ष में खाद्यान्नों का आयात किया गया। सर्वाधिक आयात वर्ष 1982-83 में 4.07 मिलियन टन का किया गया। योजना के अन्तिम वर्ष 1984-85 में उत्पादन कम प्राप्त होते हुये भी खाद्यान्नों का निर्यात (11.35 मिलियन टन) किया गया। 100042

सातवीं पंचवर्षीय योजना एवं खाद्य स्थिति (1985-90)—इस योजना के प्रथम तीन वर्ष में देश के विभिन्न भागों में सूखा के कारण खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य से कम प्राप्त हुआ। वर्ष 1987-88 के भयंकर सूखा के कारण खाद्यान्न का उत्पादन 140.35 मिलियन टन ही हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3 मिलियन टन कम था। अतः देश जो खाद्यान्नों की निर्यात स्थिति में था, वह पुनः आयात करने की स्थिति में आ गया। इस वर्ष 1.87 मिलियन टन खाद्यान्न का आयात किया गया। वर्ष 1988-89 उत्पादन की दृष्टि से अच्छा होने के फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन 170.25 मिलियन टन हुआ, जो शत वर्ष की अपेक्षा 30 मिलियन टन अधिक था। योजना के अन्तिम वर्ष 1989-90 में खाद्यान्न का उत्पादन पूर्व वर्ष के स्तर पर 169.92 मिलियन टन ही रहा।

वार्षिक योजनाएँ (1990-91 व 1991-92) में खाद्य स्थिति वर्ष 1990-91 में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के कारण उत्पादन स्तर 176.50 मिलियन

टन हुआ, जो अब तक के खाद्यान्न उत्पादन का कीर्तिमान है। वर्ष 1991-92, खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि में सन्तुष्ट नहीं था, अतः इस वर्ष उत्पादन का स्तर 171 0 मिलियन टन ही प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 5 5 मिलियन टन कम था।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में खाद्यान्न उत्पादन 210 मिलियन टन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

सारणी 3 1 भारत में वर्ष 1948-49 से 1991-92 की अवधि में खाद्यान्न उत्पादन, आयातित खाद्यान्न एवं प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धि की मात्रा प्रदर्शित करती है। देश में खाद्यान्न उत्पादन स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय की अपेक्षा वर्तमान में 3 5 गुना से अधिक हो रहा है लेकिन प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धि के स्तर में वृद्धि का स्तर बहुत कम है। वर्तमान में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धि का स्तर 475 ग्राम प्रतिदिन है।

सारणी 3 1

भारत में खाद्यान्न उत्पादन, आयात एवं प्रति व्यक्ति उपलब्धि

पंचवर्षीय योजना	कृषि वर्ष	खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)	आयातित खाद्यान्न (मिलियन टन)	प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धि (ग्राम प्रतिदिन)
योजना काल से पूर्व	1948-49	51 750	2 887	—
	1949-50	50 050	3 765	—
	1950-51	55 011	4 801	394.8
प्रथम पंचवर्षीय योजना	1951-52	55 603	3,926	384.5
	1952-53	61,784	2 035	412.6
	1953-54	72 336	0 832	457.8
	1954-55	70 739	0 513	444.0
	1955-56	69 335	1 372	430.7
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	1956-57	72 457	3 620	447.1
	1957-58	66 629	3 210	408.8
	1958-59	78 803	1 851	468.5
	1959-60	77 120	5,119	449.0
	1960-61	82,326	3,486	468.7

तृतीय पञ्चवर्षीय योजना	1961-62	82 397	3.629	460.9
	1962-63	80.330	4.536	443.8
	1963-64	80 699	6 252	452.0
	1964-65	89 367	7 439	480.1
	1965-66	72 347	10 311	408.1
वार्षिक योजनाएँ	1966-67	74 231	8 569	401.4
	1967-68	95 052	5.671	460.2
	1968-69	94.013	3.824	445.1
चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना	1969-70	99 501	3.547	455.0
	1970-71	108 422	2 010	468.8
	1971-72	105 168	-0.49	466.1
	1972-73	97 026	3 59	421.6
	1973-74	104.665	5 16	451.2
पाचवी पञ्चवर्षीय योजना	1974-75	99 826	7 53	405.5
	1975-76	121 034	0 66	424.3
	1976-77	111 167	0 08	429.6
	1977-78	126 407	-0 82	468.0
	1978-79	131 902	-0 32	476.5
वार्षिक योजना	1979-80	109 700	-0 48	410.4
छठी पञ्चवर्षीय योजना	1980-81	129 900	0 52	453.7
	1981-82	133 000	1 58	455.0
	1982-83	129 520	4 07	436.4
	1983-84	152 370	2 37	477.9
	1984-85	145 540	-0 35	453.7
सातवी पञ्चवर्षीय योजना	1985-86	150 440	-0 06	478.3
	1986-87	143 420	-0 37	472.7
	1987-88	140 350	1 87	451.2
	1988-89	170 250	—	497.2
	1989-90	169.92	—	474.6

वार्षिक योजना	1990-91	176 50
	1991-92	171 00
आठवीं पंचवर्षीय योजना	1992-97	210 00
का लक्ष्य		

स्रोत : (i) Bulletin on Food Statistics, Ministry of Agriculture, Government of India, New Delhi.

(ii) Economic Survey, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi

खाद्यान्नों के उत्पादन वृद्धि में क्षेत्रफल एवं उत्पादकता का योगदान

खाद्यान्नों के उत्पादन वृद्धि के लिए दो प्रमुख अवयव उनके अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि एवं उत्पादकता में वृद्धि है। स्वतन्त्रता के समय से ही खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कृषित क्षेत्रफल में वृद्धि की जा रही है। साथ ही भूमि के प्रति इकाई क्षेत्रफल से उत्पादकता में वृद्धि के लिए भी प्रयास किए गए हैं। फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में देश में वृद्धि हुई है। सारणी 3.2 में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए क्षेत्रफल एवं उत्पादकता के सापेक्ष योगदान को प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 3-2

क्षेत्रफल एवं उत्पादकता का खाद्यान्नों के उत्पादन वृद्धि में योगदान

समय	प्रतिघन वृद्धि		
	क्षेत्रफल	उत्पादकता	कुल
1949-50 से 1958-59	46 58	53 42	100
के काल में	(1 84)***	(2 11)***	(3 95)***
1959-60 से 1968-69	25 58	74 42	100
के काल में	(0 33)*	(0 96)	(1 29)
1969-70 से 1978-79	17 95	82 05	100
के काल में	(0 49)*	(2 24)***	(2 73)***
1979-80 से 1988-89	-4 06	104 06	100
के काल में	(-0 13)	(3 33)***	(3 20)***

*=significant at 10 percent level.

***=significant at 1 percent level.

Note—Figures in porenthesis indicate growth rate in percentage terms per annum and the figures above represent percentage contribution of different factors to growth of production

Source Shaik Haffis, Y V R Reddy, P Lakshmi and R K Raju, Growth Patterns in Food grains Economy of India, Agricultural situation in India, Vol 46(2), March 1992, p 907

स्पष्ट है कि पिछले चार दशकों में क्षेत्रफल के अंश में निरन्तर कमी आई है। स्वतन्त्रता के बाद के प्रथम दशक में क्षेत्रफल का उत्पादन वृद्धि में अंश 46.58 प्रतिशत था, जो कम होकर अन्तिम दशक में ऋणात्मक (-4.06 प्रतिशत) हो गया। इसके विपरीत उत्पादकता का अंशदान इसी काल में 53.42 प्रतिशत से बढ़कर 104.06 प्रतिशत हो गया। देश का भौगोलिक क्षेत्र सीमित होने के कारण कृषित क्षेत्र में वृद्धि करके उत्पादन बढ़ाना अब संभव नहीं है क्योंकि वर्तमान अकृष्य क्षेत्र को कृषित क्षेत्र में परिवर्तित करने में पूँजी का निवेश बहुत करना होता है तथा यह क्षेत्र भी सीमित ही है। अतः भविष्य में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि उत्पादकता में वृद्धि करके ही की जा सकेगी।

भारत में खाद्यान्नों की माँग एवं पूर्ति

देश में खाद्यान्न समस्या की गम्भीरता के अध्ययन के लिए खाद्यान्नों की माँग एवं पूर्ति का अध्ययन करना आवश्यक है। खाद्यान्नों की पूर्ति से तात्पर्य खाद्यान्नों के आन्तरिक उत्पादन एवं आयातित खाद्यान्नों की सम्मिलित मात्रा में लगाया जाता है। खाद्यान्नों की माँग से तात्पर्य देश के निवासियों के लिए भोजन की आवश्यक मात्रा, पशुओं के लिए दाने की आवश्यकता एवं बीज के लिए आवश्यक मात्रा के योग से है।

देश में खाद्यान्नों की माँग के आकलन समय-समय पर विभिन्न अर्धशास्त्रियों, पोषण विशेषज्ञों एवं अनेक संस्थानों द्वारा विभिन्न वर्षों के लिए किये गये हैं, लेकिन उनके प्राप्त आकलन परिणामों में बहुत विभिन्नता पाई गई है। माँग के आकलनों में विभिन्नता के प्रमुख कारणों में विभिन्न कारणों के लिए की गई मान्यताओं में भिन्नता का होना है। खाद्यान्नों की माँग का आकलन करने से पूर्व, माँग में परिवर्तन लाने वाले कारकों के सम्बन्ध में आकलन करने होते हैं। खाद्यान्नों की माँग के आकलन में निम्न कारक परिवर्तन लाते हैं—

- (अ) देश में जनसंख्या की वृद्धि दर,
- (ब) नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर,
- (स) देश के विभिन्न व्यक्तियों की आय का बँटवारा एवं उनसे खाद्यान्न के उपयोग पर प्रभाव।

देश में वर्ष 1970 से 1980 के काल में खाद्यान्नों की मांग के लिये किये गये आकलनों में विभिन्नता आकलन कर्त्ताओं/संस्थाओं के परिणामों से स्पष्ट है जो सारणी 3.3 में प्रदर्शित है

सारणी 3.3

भारत में वर्ष 1970 से 1980 के काल में खाद्यान्नों की मांग का आकलन
(मिलियन टन)

आकलनकर्त्ता/संस्था	मान्यताएँ	आकलन वर्ष	
		1975-76	1980
1 प्रो० पी वी सुखात्मे	585 मिलियन जनसंख्या	108 26	—
	625 मिलियन जनसंख्या	115 66	—
2 राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद्	—	133 44	—
3 प्रो मदालगी	630 मिलियन जनसंख्या	131 20	—
4 ब्राय एव कृषि सच, रोम	—	111 75	129 51

स्रोत 1 P V Sukhatme, Feeding India's Growing Millions, Asia Publishing House, London, 1965

2 Long Term Demand and Supply Projections of Agricultural Commodities, NCAER, New Delhi, 1960-61 to 1975-76.

3, Reserve Bank of India Bulletin, January 1967, pp. 27-31.

योजना आयोग के परिप्रेक्ष्य योजना विभाग (Perspective Planning Division) द्वारा किये गये आकलन के अनुसार देश में वर्ष 1985-86 में 190 मिलियन टन खाद्यान्न (168 मिलियन टन अनाज एवं 22 मिलियन टन दालें) की आवश्यकता होगी।⁴

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने वर्ष 1971 के आधार पर वर्ष 2000 के लिए प्रमुख कृषि वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति का आकलन किया था, जो सारणी 3.4 में प्रदर्शित है।

सारणी 3 4

राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार वर्ष 2000 में खाद्यान्न एवं अन्य
कृषि वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति का आकलन

(मिलियन टन में)

कृषि वस्तुएँ	आधार वर्ष 1971	मांग		पूर्ति का आकलन
		निम्न स्तर आकलन	उच्च स्तर आकलन	
धानाज	95 99	182 21	194 32	195 0
दालें	11 79	25 56	30 49	35 0
खाद्यान्न	107 78	207 77	224 81	230 0
खाद्य तेल	—	8 30	10 20	9 7
चीनी एवं गुड़	—	24 0	29 9	32 5
दूध	—	49 4	64 4	64 4
घण्डे (मिलियन सक्या)	—	17,419	28,513	27,882
मास	—	1 57	2 11	2 10
मछली	—	4 6	5 55	8 0

स्रोत National Commission on Agriculture, Part III of the Report
Ministry of Agriculture, Government of India, New Delhi,
1976

स्पष्ट है कि देश में खाद्यान्नों की पूर्ति मांग के अनुरूप हो सकेगी। खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त होने की सम्भावना प्रतीत नहीं हो रही है, जिसके लिए सरकार को विशेष प्रयास करने होंगे।

श्री आर कन्नान एवं श्री टी के चक्रवर्ती ने 1985-86 से 2000-2001 वर्ष के लिए खाद्यान्नों एवं खाद्य वस्तुओं की मांग का आकलन, जनसंख्या के दो आकलनों के स्तर पर (मॉडल A छठी पंचवर्षीय योजना में दिये गये चक्रवृद्धि दर एवं मॉडल B, 1970-79 के काल में वास्तविक जनसंख्या वृद्धि दर) तथा उपभोग व्यय स्तर के आधार पर दिया है जो सारणी 3 5 में दिए गए हैं—

सारणी 35

खाद्य वस्तुओं की माँग का आकलन वर्ष 1985-86 से 2000-2001

(मिलियन टन में)

साद्य वस्तु	आधार वर्ष 1970-71 की मांग	मांग का आकलन							
		1985-86		1990-91		1995-96		2000-2001	
		A	B	A	B	A	B	A	B
1 कुल आयात	94.32	138.72	138.72	160.79	161.20	187.29	188.94	218.19	221.23
अनाज	83.99	122.42	122.42	141.33	141.71	163.84	165.29	189.59	192.76
दालें	10.33	16.30	16.30	19.46	19.49	23.45	23.55	28.30	28.47
2 चीनी	4.03	7.19	7.19	9.02	9.01	11.51	11.48	14.62	14.54
3 साद्य तेल	1.71	2.92	2.92	3.59	3.60	4.47	4.47	5.57	5.56
4 दूध	20.10	39.79	39.69	52.03	51.85	69.48	68.65	91.10	89.85
5 मीस	0.90	1.74	1.74	2.18	2.18	2.76	2.75	3.48	3.47
6 मछली	1.70	2.96	2.96	3.71	3.70	4.68	4.68	5.92	5.90
7 ग्रन्थे(मिलियन में)	2.93	5.21	5.21	6.52	6.51	8.23	8.22	10.41	10.39

स्रोत Kannan, R and T K Chakrabarty, Dem and Projections For Selected Food Items in India 1985-86 to 2000-01, Economic and Political weekly, Review of Agriculture, Vol. XVIII (52 & 53), December 24-31, 1983, pp A-135 to 142

स्पष्ट है कि दोनों मॉडल के स्तर पर अनेक खाद्य पदार्थों की मांग का आकलन लगभग समान है। उक्त आंकड़ों से यह भी स्पष्ट है कि खाद्यान्नों की मांग प्रति 5 वर्षों में औसतन 16 प्रतिशत (2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष चक्र-वृद्धि दर से) की दर से बढ़ने का अनुमान है। दूसरे खाद्य वस्तुओं की मांग में वृद्धि अधिक तीव्र गति से होने की आशा है। जैसे दूध की मांग में वृद्धि 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष, चीनी की मांग में वृद्धि 4.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष, मांस, मछली एवं भण्डों की मांग में वृद्धि 4.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष एवं खाद्य तेलों की मांग में 3.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से होने का आकलन किया है। इसके अनुसार वर्ष 2001 में खाद्यान्नों की कुल मांग 218.19 से 221.23 मिलियन टन, दूध की मांग 89.85 से 91.10 मिलियन टन, चीनी की मांग 14.54 से 14.62 मिलियन टन होने का आकलन है।

भारत में खाद्य समस्या के पहलू :

देश की खाद्य समस्या को निम्न चार महत्वपूर्ण पहलुओं के अन्तर्गत विभाजित करके अध्ययन किया जाता है—

(1) **भारतात्मक पहलू**—खाद्य समस्या का प्रथम पहलू देश में आवश्यक मात्रा में खाद्यान्नों का उपलब्ध नहीं होना है। देश में खाद्यान्नों का उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं होने के कारण स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से ही खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही पूर्ति को मांग के अनुरूप करने के लिए खाद्यान्नों का आयात भी किया गया है। खाद्यान्नों के इस आयात पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में व्यय किये जा रहे हैं। देश में कृषि क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि के कार्यक्रमों के अपनाने से खाद्यान्न उत्पादन में तीन गुना से अधिक वृद्धि (1948-49 में 51.75 मिलियन टन से 1991-92 में 171.00 मिलियन टन) हुई है, लेकिन प्रति व्यक्ति उपलब्धि में विशेष वृद्धि नहीं हुई है। सारणी 3.6 देश में विभिन्न वर्षों में विभिन्न खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि प्रदर्शित करती है।

सारणी 3.6

भारत में प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की उपलब्धि

(ग्राम प्रतिदिन)

वर्ष	अनाज	दालें	खाद्यान्न
1951	334.2	60.7	394.9
1956	360.4	70.3	430.7
1961	399.7	69.0	468.7
1966	359.9	48.2	408.1
1971	417.6	51.2	468.8
1976	373.8	50.5	424.3
1981	416.2	37.5	453.7
1986	434.3	44.0	478.3
1988	413.2	38.0	451.2
1989	455.0	42.2	497.2
1990	438.1	36.5	474.6

स्रोत Economic Survey, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi.

स्पष्ट है कि पिछले 40 वर्षों में देश में अनाज की उपलब्धि में वृद्धि हुई है लेकिन दालों की उपलब्धि में निरन्तर कमी हुई है। दालों की उपलब्धि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के द्वारा की गई सिफारिश मात्रा से बहुत कम है। परिषद् के अनुसार एक वयस्क शाकाहारी के लिए 350 से 475 ग्राम अनाज एवं 70 से 80 ग्राम दाल प्रतिदिन तथा बच्चों के लिए 200 से 450 ग्राम अनाज एवं 60 से 70 ग्राम दालें प्रतिदिन उपलब्ध होना चाहिये।⁵ दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धि की मात्रा में निरन्तर कमी हुई है। अतः खाद्यान्नों की प्रथम समस्या उनके उत्पादन में वृद्धि करने की है, जिससे उनकी उपलब्धि निर्धारित मात्रा में देश के निवासियों को हो सके।

(2) गुणात्मक पहलू—भारत में खाद्यान्न समस्या का दूसरा पहलू गुणात्मक है जिसके अनुसार उपभोक्ताओं को उपलब्ध खाद्यान्नों की मात्रा में आवश्यक मोजन तत्वों (कैलोरी, प्रोटीन आदि) का सन्तुलित मात्रा में उपलब्ध नहीं होना है। इसके कारण देश के नागरिक कुपोषण के शिकार होते हैं। गुणात्मक पहलू के आकलन का कार्य कठिन होता है।

भारत में पुरुषों को कार्य के अनुसार 2430 से 3880 कैलोरी एव स्त्रियों को 1790 से 2880 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है जबकि भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत कैलोरी की उपलब्धि 1860 ही है। उपलब्ध कैलोरी की मात्रा के कम होने के कारण नागरिक बीमारियों से जल्दी ही ग्रसित हो जाते हैं। अन्य देशों में कैलोरी उपलब्धि की मात्रा भारत से अधिक है। न्यूजीलैंड में 3490, स्वीट्जरलैंड में 3570, डेनमार्क में 3340, कनाडा में 3140, अमेरिका में 3120 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध होती है।

सन्तुलित भोजन में कैलोरी के अतिरिक्त प्रोटीन, विटामिन, खनिज, आदि की भी आवश्यकता होती है। भारतीयों के भोजन में यह तत्व भी आवश्यक मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं। एक नागरिक को देश में 59 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, जो उपलब्ध नहीं है। भारत में एक चौथाई से एक-तिहाई व्यक्ति शरीर के विकास के लिए आवश्यक मात्रा से भी कम मात्रा में प्रोटीन का उपभोग कर रहे हैं। कम आय वाले व्यक्तियों के भोजन में प्रोटीन की कमी अधिक पायी जाती है। वे अपनी सीमित आय से अधिक प्रोटीन की मात्रा वाले खाद्य-पदार्थों जैसे—सब्जी, फल, दूध, अण्डे खरीदने में सक्षम नहीं होते हैं क्योंकि ये महँगे होते हैं। अतः देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ अधिक प्रोटीन युक्त एवं अन्य पोषक भोजन तत्वों वाले खाद्य-पदार्थों के उत्पादन में भी वृद्धि करनी चाहिये।

(3) आर्थिक पहलू—खाद्य समस्या का तीसरा पहलू देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय का कम होना है, जिसके कारण वे आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न खरीद नहीं कर पाते हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों/संस्थाओं ने समय-समय पर देश में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का आकलन किया है और प्राप्त परिणामों से स्पष्ट है कि देश की लगभग 39.4 प्रतिशत जनसंख्या वर्तमान में गरीबी की रेखा से नीचे है। गरीबी की रेखा का आकलन देश में 20 रु प्रति व्यक्ति प्रतिमाह के उपभोग स्तर ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 25 रु प्रति व्यक्ति प्रतिमाह शहरी क्षेत्रों में वर्ष 1960-61 की कीमतों पर किया गया है, जो वर्ष 1980-85 की कीमतों पर 107 रु एवं 122 रु आता है। यह उपभोग स्तर भी बहुत कम है।

(4) प्रशासनिक पहलू—खाद्य समस्या का चौथा पहलू देश में खाद्यान्नों की उचित वितरण व्यवस्था का नहीं होना है। देश में पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन होने वाले वर्षों में भी उपभोक्ताओं को खाद्यान्न की उपलब्धि में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें निर्धारित कीमत से अधिक कीमत का भुगतान करना पड़ता है। व्यापारी, सम्पन्न कृषक एवं अन्य व्यक्ति लाभ की प्राप्ति के लिए खाद्यान्नों का संग्रहण कर लेते हैं और उसमें सट्टे की प्रवृत्ति प्रपनाते हैं। बाजार में खाद्यान्नों की कृत्रिम कमी उत्पन्न करते हैं तथा कालाबाजारी करके उपभोक्ताओं

से अधिक कीमत प्राप्त करने हैं। उन खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के उपायों के माध्यम-माध्यम दश में खाद्यान्नों की उचित वितरण प्रणाली का होना भी आवश्यक है। सरकार समय-समय पर इस वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय जैसे—व्यापारियों का अनुनायक जारी करना, उनके स्टॉक रखने की सीमा नियत करना, खाद्यान्नों की अधिशक्ति करके बफर स्टॉक बनाना, उचित दुकानों के माध्यम से वितरण करना, खाद्यान्नों का राशनिंग करना तथा खाद्यान्नों के व्यापार का अधिग्रहण करके वितरण प्रणाली में सुधार लाती है। अनेक बार इनके होते हुए भी उपभोक्ता को राहत नहीं मिलती है।

भारत में खाद्यान्नों की कमी के कारण

भारत में खाद्यान्नों की कमी उत्पन्न होने के प्रमुख कारण निम्न हैं—

(1) देश का विभाजन—स्वतन्त्र भारत में खाद्यान्नों की कमी उत्पन्न होने का प्रथम कारण देश का विभाजन होना था। देश के विभाजन में खाद्यान्न उत्पादन में अधिशेष वाले क्षेत्र जैसे—पश्चिमी पंजाब, सिन्ध एवं पूर्वी बंगाल प्रान्त पाकिस्तान देश में चले गए तथा खाद्यान्न उत्पादन में कमी वाले क्षेत्र जैसे तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल आदि प्रांत भारत में रह गये। विभाजन में भारत वर्ष को 81 प्रतिशत जनसंख्या के साथ 77 प्रतिशत क्षेत्रफल ही प्राप्त हुआ। अधिकांश सिंचित क्षेत्र भी पाकिस्तान में चला गया। इस कारण स्वतन्त्र भारत में खाद्य समस्या उत्पन्न हुई।

(2) जनसंख्या में तीव्रगति से वृद्धि—देश में खाद्यान्न समस्या उत्पन्न होने का दूसरा कारण जनसंख्या में तीव्रगति से वृद्धि होना है। देश की जनसंख्या वर्ष 1901 में 238.4 मिलियन थी, जो बढ़कर वर्ष 1981 में 683.8 मिलियन व वर्ष 1991 में 843.9 मिलियन हो गई। पिछले दो दशकों में से वर्ष 1911 से 1921 के दशक के प्रतिरक्त सन्नी दशकों में जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 1951 से 1961 के दशक में जनसंख्या में 21.51 प्रतिशत, वर्ष 1961 से 1971 के दशक में 24.80 प्रतिशत, 1971 से 1981 के दशक में 24.75 प्रतिशत एवं 1981 से 1991 के दशक में 23.41 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। सारणी 3.7 से यह भी स्पष्ट है कि देश में ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या का कुल जनसंख्या में प्रतिशत में निरन्तर गिरावट आई है जो वर्तमान में 76.27 प्रतिशत है तथा शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है जो वर्तमान में 23.73 प्रतिशत हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का प्रवाह होने के कारण भी शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अतः स्पष्ट है कि भारत में जनसंख्या निरन्तर तीव्रगति से प्रत्येक दशक में बढ़ी है।

¹ सारणी 3 8 में भारत में भविष्य में होने वाली जनसंख्या का आकलन दिया गया है। श्री आर काशन एव टी के चक्रवर्ती ने दो दर पर आकलन दिए हैं। उनके अनुसार वर्ष 2001 में 1016 मिलियन, डा थामाराजवसी के अनुसार 864 मिलियन एव भारत सरकार के जनसंख्या रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार 959 से 1052 मिलियन जनसंख्या होने का आकलन है। डा थामाराजवसी का आकलन का स्तर निम्न है क्योंकि वर्ष 1991 में जनसंख्या 844 मिलियन स्तर पर पहुँच चुकी है। जनसंख्या का इस दशक के अन्त तक 100 करोड़ पहुँचने का अनुमान सत्य होने की आशा की जा रही है। अतः इन आकलनों से भी स्पष्ट है कि जनसंख्या में भविष्य में भी वृद्धि तीव्र गति से होगी, जो खाद्यान्नों की कमी उत्पन्न करने का एक कारण बना रहेगा।

जनगणना 1991 के अनुसार, जनसंख्या का घनत्व 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है जो वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 221 ही था। विभिन्न राज्यों में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक पश्चिम वंगाल में एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में है। भारत में वर्ष 1981 से 1991 के काल में 16 06 करोड़ जनसंख्या में वृद्धि हुई है जो जापान देश की कुल जनसंख्या से भी अधिक है।

सारणी 37

भारत में विभिन्न वर्षों में जनसंख्या

जनगणना वर्ष	कुल जनसंख्या (मिलियन)	ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या (मिलियन)	शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या (मिलियन)	जनसंख्या में प्रति दशक वृद्धि दर (प्रतिशत)	जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग किलो मीटर)
1901	238.4	212.5 (89.10)	25.9 (10.90)	—	NA
1911	252.1	226.2 (89.71)	25.9 (10.29)	+ 5.75	NA
1921	251.3	223.2 (88.82)	28.1 (11.18)	— 0.31	81
1931	279.0	245.5 (88.00)	33.5 (12.00)	+ 11.00	90
1941	318.7	274.5 (86.14)	44.2 (13.86)	+ 14.22	103
1951	361.1	298.7 (82.72)	62.4 (17.28)	+ 13.31	117
1961	439.2	360.3 (82.02)	78.9 (17.98)	+ 21.51	142
1971	548.2	439.1 (80.69)	109.1 (19.31)	+ 24.80	177
1981	683.8	521.5 (76.27)	162.3 (23.73)	+ 24.75	221
1991	843.9	626.8 (74.28)	217.1 (25.72)	+ 23.50	267

Note: Figures in Parentheses are Percentages of total Population

स्रोत : Registrar General and Census Commissioner of India

सारणी 3 8

भारत में जनसंख्या का आकलन

(मिलियन में)

वर्ष आकलन कर्ता	जनसंख्या		
	कुल जनसंख्या	ग्रामीण क्षेत्रों की	शहरी क्षेत्रों की
श्री आर. कन्नन एंव टी.के. चक्रवर्ती द्वारा दिए गए आकलन			
1986 मॉडल A	754.98	567.06	187.92
मॉडल B	754.98	567.06	187.92
1991 मॉडल A	827.56	611.54	216.32
मॉडल B	833.86	615.75	217.81
1996 मॉडल A	902.88	655.13	247.75
मॉडल B	920.32	667.78	252.54
2001 मॉडल A	979.87	697.57	282.30
मॉडल B	1016.10	723.36	292.74
डा. आर. धामाराजन्सी के द्वारा दिए गए आकलन			
जुलाई 1985	703.00	—	—
जुलाई 2001	864.00	—	—
भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा सशोधित आकलन			
1991-1996	925.13	667.77 (72.18)	257.36 (27.82)
1992-1997	941.37	674.80 (71.68)	266.57 (28.32)
1996-2001	1006.20	699.33 (69.50)	306.87 (30.50)
2001-2006	1085.98	722.34 (66.52)	363.64 (33.48)
2006-2011	1164.25	738.52 (63.43)	425.73 (36.57)

Notes : (1) In the R. Kannan and T. K. Chakarbarty the model A & B means —

Model A=Based on projections of compound growth rate of 2.0, 1.86, 1.75 and 1.65 percent per annum during the period 1981-86, 1986-91, 1991-96 and 1996-2001 period.

Model B=Based on natural increase of 2.0 per cent per annum as was there in 1970-79.

- (2) Dr. R. Thamarajakshi's estimates of population are based on a growth of 1.55 percent during 1981-1991 and 1.30 per cent per annum during 1991-2000
- (3) The projections given by Registrar General of India have been adjusted in the light of the 1991 census results and are based on similar projections as adopted by the standing Committee of Experts on population projections i.e. at a growth rate of 1.81 per cent per annum during 1991-96 and 1.65 per cent during 1996-2001.

Sources : (1) R. Kannan and T. K. Chakarbarty; Demand Projections for selected Food Items in India, 1985-86 to 2000-2001, Economic and Political Weekly—Review of Agriculture, Vol. 18 (52 & 53) December 24-31, 1983, pp A-135 to 142.

(2) Yojana, Vol 17(1), January 26, 1973, p. 8.

(3) Registrar General of India, Taken from Eighth Five Year Plan (1992-97), Planning Commission, Government of India, New Delhi.

(3) कृषि उत्पादकता कम होना—देश में खाद्यान्नों की बढ़ती हुई समस्या का तृतीय कारण कृषि उत्पादकता का कम होना है। भारत में भूमि एवं श्रम उत्पादकता विकसित देशों की अपेक्षा कम है। भारत में वर्ष 1989-90 में प्रति हेक्टर औसतन उत्पादन चावल का 17 56 क्विण्टल एवं गेहूँ का 21 17 क्विण्टल था जो विकसित देशों एवं देश में ही राष्ट्रीय प्रदर्शनो की औसत उत्पादकता से बहुत कम है। कृषकों द्वारा भूमि पर निरन्तर फसलों के उत्पन्न करने व आवश्यक खाद्य तत्वों की भूमि में प्रति वर्ष पूति नहीं करने से भूमि की उर्वरता निरन्तर कम होती जा रही है। भूमि उत्पादकता के समान श्रम उत्पादकता भी भारत में कम है और उसमें निरन्तर गिरावट हो रही है।

(4) प्राकृतिक प्रकोपों का होना—भारतीय कृषि मुख्यतया प्रकृति पर निर्भर करती है। भारत में प्रतिवर्ष किसी न किसी क्षेत्र में कोई न कोई प्राकृतिक प्रकोप होता रहता है। प्राकृतिक प्रकोपों में समय पर वर्षा का न होना, सूखा पड़ना, अतिवृष्टि, बाढ़ आदि प्रमुख हैं, जिनके कारण कृषि उत्पादन कम होता है और खाद्यान्नों की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

कृषि-उत्पादन के लिए सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था का होना आवश्यक है। भारत में 36.5 प्रतिशत क्षेत्र में ही सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है और देश का शेष 63.5 प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि-उत्पादन के लिए वर्षा पर निर्भर है। सतार में भारत के अनिरिक्त अन्य कोई देश नहीं है जहाँ पर कृषि क्षेत्र का इतना अधिक भाग कृषि उत्पादन के लिए वर्षा पर निर्भर करता हो। भारत में समय समय पर सूखा पड़ना रहा है। वर्षा के नहीं होने, कम होने अथवा समय पर नहीं होने के कारण सूखा पड़ता है। सूखे का प्रकोप सबसे अधिक उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर औसतन वर्षा प्रतिवर्ष 15 से 30 इंच या इससे कम होती है। भारत में सूखा अधिकतर बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्यों में पड़ा है, क्योंकि इन राज्यों में वर्षा कम होती है तथा राज्य की अधिकांश कृषि भूमि कृषि उत्पादन के लिए वर्षा पर निर्भर करती है। इन क्षेत्रों में वर्षा के कम होने के साथ-साथ वर्षा समय पर भी नहीं होती है। देश में वर्षा के पिछले आकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक या दो अच्छी वर्षा वाले वर्ष, एक या दो कम वर्षा वाले वर्ष एवं शेष औसत वर्षा वाले वर्ष होते हैं। सूखे के कारण देश में खाद्यान्न उत्पादन कम होता है एवं सूखे से क्षेत्र के निवासियों की रक्षा करने पर सरकार की धन्यता का बहुत बड़ा भाग व्यय होता है।

वर्ष 1962-63 से 1973-74 के दशक में देश में सूखे का प्रकोप अधिक हुआ है। वर्ष 1965-66 व 1966-67 का सूखा विशेष उल्लेखनीय है। यह सूखा भारत के अधिकांश राज्यों में था। सूखे के कारण देश में खाद्यान्नो का उत्पादन 1965-66 में 72.34 मिलियन टन एवं 1966-67 में 74.23 मिलियन टन ही प्राप्त हुआ, जो सूखा से पहले के वर्ष 1964-65 की अपेक्षा 17 मिलियन टन कम था।

कम एवं असामयिक वर्षा के कारण 1972-73 का सूखा इस दशक का महत्वपूर्ण सूखा था। इस सूखे से देश के 340 जिलों में से 230 जिले एवं 56 करोड़ जनसंख्या में से 20 करोड़ में अधिक जनसंख्या प्रभावित हुई। सूखे के कारण 1972-73 में देश में खाद्यान्न-उत्पादन 1970-71 की तुलना में 13.25 मिलियन टन कम हुआ। व्यापारिक एवं अन्य फसलों के उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। देश की अर्थव्यवस्था डीबा डोल होना शुरू हो गई। सूखे का मुकाबला करने के लिए सरकार ने अनेक सूखा-राहत कार्य शुरू किये, जिनका मुख्य उद्देश्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों के निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराना, क्षेत्र के नागरिकों के लिए खाने-पीने की व्यवस्था करना, पशुओं के लिए चारे का प्रबंध करना एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि के उपाय अपनाना है। वर्ष 1973-74 में भी असम, बिहार, गुजरात,

मध्य-प्रदेश, राजस्थान, पंजाब एवं जम्मू-कश्मीर राज्यों के कई भागों में बाढ़ से फसल को हानि हुई है। अक्टूबर, 1973 में आये तूफान ने उड़ीसा राज्य में खड़ी फसल को नुकसान पहुँचाया। वर्ष 1978-79, 1981-82, 1984-85, 1985-86 व 1986-87 में भी सूखे के कारण उत्पादन कम प्राप्त हुआ।

देश में सूखे के निरन्तर प्रकोपों के कारण विभिन्न राज्य सरकारों को सूखा-राहत कार्यों में भारी मात्रा में धन व्यय करना पड़ा है। विभिन्न राज्य सरकारों ने सूखा-राहत कार्यों पर वर्ष 1966 से 1969 के तीन वर्षों में 236 करोड़ रुपये एवं 1969 से 1972 के तीन वर्षों में 410 करोड़ रुपये व्यय किये।

(5) सग्रहण काल में खाद्यान्नों का कीड़ा, बीमारियों एवं चूहों द्वारा नुकसान—खाद्यान्नों का बहुत बड़ा भाग प्रतिवर्ष सग्रहण-काल में कीड़ा, बीमारियों, चूहों एवं नमी आदि के कारण खराब हो जाता है। इसका प्रमुख कारण उचित एवं वैज्ञानिक सग्रहण-सुविधा का अभाव एवं सग्रहण-काल में खाद्यान्नों की सुरक्षा की उचित व्यवस्था का न होना है।

(6) वितरण की दोषयुक्त प्रणाली का होना—देश में खाद्यान्न समस्या का एक कारण वितरण की दोष-युक्त प्रणाली का होना भी है। देश में खाद्यान्नों की आवश्यक मात्रा उत्पादित होते हुए भी प्रायः उपभोक्ताओं को उचित समय एवं उचित कीमत पर साद्यान्न उपलब्ध नहीं होते हैं। समाज-विरोधी तत्त्वों, ध्यापारियों एवं बिचौलियों द्वारा खाद्यान्नों का सग्रहण करके कृत्रिम कमी उत्पन्न करना, इसका प्रमुख कारण है। खाद्यान्नों की कमी उत्पन्न होने के अन्य कारणों में समय पर परिवहन सुविधा उपलब्ध न होना, राजनैतिक हस्तक्षेप से खाद्यान्नों के आयात-निर्यात पर प्रतिबन्ध होना एवं वितरण के लिए सरकार के पास पर्याप्त व्यवस्था का न होना है।

(7) खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमतें—खाद्यान्नों की कीमतों में निरन्तर वृद्धि होने के कारण भी देश के उपभोक्ता अपनी सीमित आय से आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न क्रय नहीं कर पाते हैं। वर्ष 1955-56 से सभी कृषि वस्तुओं की कीमतों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। कीमतों में वृद्धि के कारण उपभोक्ता अपनी सीमित आय से आवश्यक मात्रा में अच्छी किस्म के खाद्यान्न क्रय नहीं कर पाते हैं एवं वे सीमित आय से सस्ते खाद्यान्न क्रय करते हैं, जिससे खाद्यान्न की मात्रात्मक समस्या के साथ-साथ गुणात्मक समस्या भी उत्पन्न होती जाती है।

भारत में खाद्य समस्या का समाधान

देश की खाद्य समस्या को निम्न उपाय अपनाकर हल किया जा सकता है—

1. देश में कृषि के अन्तर्गत कृषित एवं सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि करना—खाद्यान्न की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कृषि-क्षेत्र जो वर्षों से अक्रिय होने

अथवा अन्य कारणों से कृषित नहीं किया जाता था, उसे कृषि योग्य बनाकर खाद्यान्नों के उत्पादन बढ़ाना चाहिए। कृषित क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ साथ देश में सिंचाई की सुविधाओं का भी विकास करना आवश्यक है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में नहरें, बाध, कुएँ बनाकर सिंचित क्षेत्रों में वृद्धि की जा सकती है।

2 कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना—नये तकनीकी ज्ञान के उपयोग से देश में कृषि उत्पादकता में वृद्धि की बहुत सम्भावना है। कृषक मोबर की खाद, उर्वरकों का उपयोग, उन्नत किस्मों के बीजों का उपयोग, उचित गहराई तक जुताई एवं बीमारियों एवं कीड़ों द्वारा होने वाली हानि को कम करके कृषि उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। वर्तमान में देश में हरित-क्रान्ति के फलस्वरूप विभिन्न खाद्यान्नों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। तिलहन एवं दलहन की उत्पादकता में वृद्धि करना अति आवश्यक है।

3 सप्रहण-काल में होने वाली क्षति को कम करना—सप्रहण काल में होने वाली क्षति को रोकथाम करके भी देश में खाद्यान्न उपलब्धि की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। खाद्यान्न की इस क्षति को उचित मण्डारण व्यवस्था, सप्रहण काल में कीटनाशो दवाइयों के छिड़काव एवं तापक्रम व नमी का नियन्त्रित करके कम किया जा सकता है।

4 कृषकों को उत्पादन वृद्धि के नये तरीकों का ज्ञान प्रदान करना—कृषकों को तकनीकी ज्ञान प्रदान करके एवं उत्पादन वृद्धि की प्रेरणा देकर भी खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है।

5 देश में जनसंख्या वृद्धि की दर को कम करना—खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होते हुए भी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियन्त्रण नहीं करने की अवस्था में देश में होने वाली खाद्यान्नों की कमी को स्थायी रूप से दूर करना सम्भव नहीं है। अतः खाद्यान्न समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए जनसंख्या पर नियन्त्रण करना आवश्यक है। वर्तमान में सरकार द्वारा जनसंख्या को कम करने के लिए विविध उपाय अपनाये जा रहे हैं।

6 उपभोक्ताओं की उपभोग आदतों में परिवर्तन करना—वर्तमान में देश के उपभोक्ता अधिकांश मात्रा में खाद्यान्नों का उपयोग करते हैं। उपभोक्ता अन्न वस्तुएँ जैसे—सब्जियाँ, फल, अण्डे, मांस, मछली का बहुत कम मात्रा में उपभोग करते हैं। उपभोक्ताओं को इस प्रकार की आदतों का प्रमुख कारण उनमें रुढ़िवादिता, अशिक्षा, अज्ञानता आदि कुरीतियों का व्याप्त होना है। अतः खाद्यान्नों की बढ़ती हुई मांग को कम करने के लिए उपभोक्ताओं की उपभोग की आदतों में परिवर्तन करना भी आवश्यक है, जो कि शिक्षा के माध्यम से सम्भव है।

उपर्युक्त प्रथम चार विधियाँ खाद्य-समस्या को परोक्ष रूप से हल करने में सहायक होती हैं जबकि अन्तिम दो विधियाँ खाद्य-समस्या को प्रत्यक्ष रूप से हल करती हैं। इन दोनों विधियों को अपनाने से देश में खाद्यान्नों की माँग में कमी होती है।

भारत की खाद्य-नीति

वर्ष 1943 में देश में बंगाल-ग्रहण के कारण सर्वप्रथम खाद्य-नीति निर्धारित की गई थी। खाद्य-नीति के निर्धारण में सरकार द्वारा निम्न पहलुओं को महँजर रखा गया था—

- (1) खाद्यान्नों की कीमतों में विशेष वृद्धि नहीं होने पाये, जिससे समाज के स्थायी आय वाले नागरिकों एवं भ्रष्ट-वर्ग के व्यक्तियों के रहन-सहन स्तर पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े।
- (11) देश में खाद्यान्नों की कमी भ्रष्टाचार से कोई व्यक्ति मरने नहीं पाये।

भारत की खाद्य-नीति आज भी उपर्युक्त पहलुओं पर आधारित है। खाद्य-नीति के उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार, व्यापारियों एवं राज्य सरकार की संस्थाओं के माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण की व्यवस्था कर रही है।

वंगाल-ग्रहण के समय से ही देश में खाद्यान्नों की कमी चली आ रही है। यह खाद्यान्नों की कमी किसी वर्ष उत्पादन के कम होने से एवं अन्य वर्षों में वस्तुओं की पूर्ति, सरकार की नीति, व्यापारियों के लाभ कमाने की इच्छा, परिवहन साधनों की कमी आदि कारणों से माँग के अनुकूल नहीं होने से उत्पन्न होती रही है। इस खण्ड में खाद्यान्नों की बाजार में पूर्ति एवं माँग से असंतुलन के कारण उत्पन्न खाद्य समस्या के निराकरण के लिए सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। खाद्यान्नों की उत्पादन वृद्धि के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का विस्तृत विवेचन अध्याय 21 'कृषि में तकनीकी ज्ञान का विकास' में किया गया है।

स्वतन्त्रता के समय से ही खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए किए गए प्रयासों के फलस्वरूप देश में इनके उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हुई है, लेकिन उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होते हुए भी खाद्यान्नों की कीमतों में तीव्रगति से वृद्धि हुई है एवं देश में आज भी खाद्य समस्या बनी हुई है। खाद्यान्नों की यह समस्या माँग के अनुकूल उत्पादन नहीं होने के अतिरिक्त, मानव द्वारा उत्पन्न की गई कृत्रिम समस्या भी है, जिसके प्रमुख कारणों में सरकार की दोष-पूर्ण नीति, व्यापारियों द्वारा सग्रहण करके कृत्रिम कमी उत्पन्न करने की प्रवृत्ति आदि मुख्य हैं। इस कमी का प्रमुख

प्रभाव समाज के गरीब वर्ग पर पड़ता है, जिन्हें उचित कीमत एवं आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाते हैं।

सरकार द्वारा इस दिशा में उठाये गये प्रमुख कदम निम्न हैं—

(1) खाद्य क्षेत्रों का निर्माण—सरकार इस नीति के अन्तर्गत खाद्यान्नों के एक क्षेत्र अथवा राज्य से दूसरे क्षेत्र/राज्य में ले जाने अथवा लाने पर रोक लगाती है, ताकि एक क्षेत्र/राज्य में खाद्यान्न की कमी से उत्पन्न समस्या का प्रभाव दूसरे क्षेत्र/राज्य की खाद्यान्न की कीमतों पर नहीं आ पाये। सरकार की यह खाद्यान्न संचालन-नीति व्यापारियों की कार्य प्रणाली पर रोक लगाने में सक्षम होती है। अन्यथा व्यापारी वर्ग अधिपूर्ति वाले क्षेत्रों से कम कीमत पर खाद्यान्न क्रय करके कमी वाले क्षेत्रों में अधिक कीमतों पर विक्रय करके अधिक लाभ कमाते हैं। यह लाभ देश के सभी क्षेत्रों में खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि करने में सहायक होता है। सरकार द्वारा खाद्य क्षेत्रों के निर्माण की नीति से विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित खाद्यान्नों की कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं आता है। इस नीति में सरकार स्वयं अधिपूर्ति वाले क्षेत्रों से खाद्यान्न न्य करके कमी वाले क्षेत्रों में निर्धारित कीमतों पर विक्रय करती है।

सरकार द्वारा सर्वप्रथम इस नीति को बंगाल सरकार के समय 1943 में अपनाया गया था, जिसमें समय समय पर आवश्यक संशोधन किये गये, लेकिन यह प्रणाली भारत में एक राज्य अथवा दूसरे राज्य में निरन्तर लागू रही है। सरकार खाद्य क्षेत्रों का निर्माण एक या अधिक राज्यों को सम्मिलित करके करती है। निर्मित खाद्य क्षेत्रों में खाद्यान्न अधिपूर्ति एवं कमी वाले दोनों ही प्रकार के राज्यों को सम्मिलित किया जाता है जिससे निर्धारित खाद्य-क्षेत्र खाद्यान्न में पूर्ण स्वावलम्बी क्षेत्र बने।

(2) खुले बाजार में खाद्यान्नों की खरीद—खाद्यान्नों की वितरण प्रणाली के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति एवं बफर स्टॉक का निर्माण करने के लिए खाद्यान्नों को खुले बाजार में सरकार क्रय भी करती है। प्राप्त खाद्यान्नों से सरकार गरीब उपभोक्ताओं के लिए जो बढ़ती हुई कीमतों पर खाद्यान्नों को क्रय कर पाने में सक्षम नहीं है, उचित कीमत पर विनरण की व्यवस्था करती है। इसके लिए सरकार निम्न विविधों से खाद्यान्न एकत्रित करती है—

(अ) खुले बाजार से खाद्यान्नों का क्रय—खाद्यान्नों की प्राप्ति की यह विधि सरकार के लिए सबसे सरल है। इस विधि के अन्तर्गत सरकार बाजार में अन्य व्यापारियों की तरह प्रवेश करती है और आवश्यक मात्रा में स्वयं अथवा निर्धारित एजेंटों के द्वारा बाजार से विक्रय के लिए आये खाद्यान्नों को उठा ली जाती है। खाद्यान्नों के क्रय की इस विधि में कई प्रकार के दोष होते हैं—

एव मिल मालिकों से उसके द्वारा क्रय अथवा ससाधित की गई मात्रा के प्रतिशत के रूप में वसूल करती है।

(द) सरकार द्वारा एकाधिकारी क्रय—खाद्यान्नों के क्रय की यह विधि सरकार तब कार्यान्वित करती है जब खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति की अन्य विधियों से सफरना प्राप्त नहीं होती है एव कीमतों के बढ़ने से उपभोक्ता वर्ग में असन्तोष की लहर फैलती है। इस विधि में सरकार बाजार में कार्य करने वाली सभी संस्थाओं के अधिकार छीन लेती है। वर्ष 1973-74 में अनेक राज्यों में चावल, गेहूँ एव ज्वार की अधिप्राप्ति के लिए सरकार द्वारा यह विधि अपनाई गई थी। गेहूँ के धोक व्यापार को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के कारण अधिकांश राज्यों में गेहूँ निर्धारित कीमतों पर एकाधिकारी-पद्धति के द्वारा बिक्रय किया गया। चावल के लिए एकाधिकारी-क्रय की पद्धति असम, महाराष्ट्र एव उड़ीसा राज्य में अपनाई गई। महाराष्ट्र में ज्वार के लिए एकाधिकारी क्रय पद्धति अपनाई गई।

3. कृषि लागत एवं कीमत आयोग द्वारा कीमतों की घोषणा—भारत सरकार ने विभिन्न कृषि उत्पादों की सन्तुलित एवं एकीकृत कीमतों के ढांचे का निर्धारण करने, सरकार को कीमतों के नियतन एवं कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक सलाह देने तथा कृषि वस्तुओं की कीमतों में होने वाले अत्यधिक उतार-चढ़ावों को कम करने के सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव देने के लिए जनवरी, 1965 में कृषि-कीमत आयोग की स्थापना की। कृषि कीमत आयोग निरन्तर खरीफ एवं रबी की फसलों की कीमतों के नियतन के लिए सरकार को सिफारिश करता है। सरकार उपयुक्त कीमतों पर राज्यों के मुख्यमन्त्रियों एवं कृषि मन्त्रियों की सलाह के आधार पर कृषि-उत्पादों की विभिन्न किस्मों के लिए कीमतें नियत करती है। कृषि लागत एवं कीमत-आयोग निम्न दो प्रकार की कीमतों की घोषणा के लिए सरकार को सुझाव देता है—

1000 42

(अ) न्यूनतम समर्थित कीमत—न्यूनतम समर्थित कीमत कृषकों के लिए एक दीर्घकालीन प्रतिभूति का कार्य करती है। न्यूनतम समर्थित कीमत कृषकों को विश्वास दिलाती है कि अधिक उत्पादन अथवा अन्य किसी कारण से वस्तुओं की पूर्ति के बढ़ने पर भी कीमतों को निर्धारित न्यूनतम समर्थित स्तर में नीचे नहीं गिरने दिया जायेगा। निर्धारित न्यूनतम स्तर से नीचे कीमतों के गिरने की अवस्था में सरकार कृषकों से नियत कीमतों पर खाद्यान्न क्रय करती है। न्यूनतम समर्थित कीमतों की घोषणा सरकार फसल की बुवाई के समय से पूर्व करती है, जिससे कृषकों विभिन्न फसलों के अन्तर्गत लिए जाने वाले क्षेत्रफल का सही निर्णय ले सकें। विभिन्न फसलों की न्यूनतम समर्थित कीमत अध्याय 17 में दी गई है।

(ब) अधिप्राप्ति/बसूली कीमत—अधिप्राप्ति कीमतें वे हैं जिन पर सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं बफर स्टॉक निर्माण के लिए आवश्यक मात्रा में

खाद्यान्नों का क्रय करती है। ये कीमतें बाजार में प्रचलित कीमतों से नीचे स्तर पर होती हैं, ताकि सरकार उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध करा सके। विभिन्न खाद्यान्नों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित अधिप्राप्ति कीमत अध्याय 17 में दी गई है।

4 गेहूँ की थोक व्यापार नीति—खाद्यान्नों की अत्यधिक दर से बढ़ती हुई कीमतों को रोकने एवं कीमतों में वृद्धि से उपभोक्ताओं के रहन सहन के स्तर पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) के थोक व्यापार को वर्ष 1973-74 में अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया था। इस निर्णय का ध्येय यह था कि गेहूँ की थोक व्यापार नीति के अन्तर्गत थोक व्यापारी गेहूँ का क्रय-विक्रय नहीं कर सकेंगे। सरकार, भारतीय खाद्य निगम, राज्य सहकारी विपणन संघ एवं खाद्य व पौष्टि विभाग के माध्यम से गेहूँ का क्रय करेगी और इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य में गेहूँ का संचालन हो सकेगा। गेहूँ के थोक व्यापार को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के निर्णय के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे—

- (1) गेहूँ की कीमतों में होने वाले अत्यधिक उतार-चढ़ावों को कम करना।
- (II) सभी राज्यों में गेहूँ की समुचित वितरण व्यवस्था कायम करना।
- (III) गेहूँ की जमाखारी प्रवृत्ति पर नियन्त्रण लगाना, जिससे अनाज का वितरण सुव्यवस्थित रूप से चलता रहे।

सरकार द्वारा उपर्युक्त नीति को कार्यान्वित करने के सभी प्रयास किये गये लेकिन सरकार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में मफल नहीं हो सकी। इसका प्रमुख कारण बाजार में गेहूँ की अधिक कीमत का प्रचलित होना था। अतः कृषक सरकार को निर्धारित कीमतों पर गेहूँ विक्रय नहीं करके, उपभोक्ताओं एवं व्यापारियों को सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से लगभग 50 से 60 प्रतिशत अधिक कीमत पर विक्रय करते थे। दूसरी ओर उपभोक्ता वर्ग भी नबिध्य में सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर खाद्यान्नों की उपलब्धि के प्रति शकशील थे। इस कारण सरकार निर्धारित वसूली के लक्ष्य (गेहूँ 8.1 मिलियन टन) से बहुत कम मात्रा में गेहूँ वसूल कर पायी। साथ ही सरकार द्वारा प्राप्त गेहूँ, औसत किस्म के गेहूँ की प्रपेक्षा अनेक क्षेत्रों में निम्न श्रेणी के थे। निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाने की स्थिति में, सरकार ने उत्पादकों से लेवी के माध्यम से गेहूँ वसूल करने का प्रयास किया। खाद्यान्न व्यवसाय में लगे हुए व्यापारी वर्ग ने बेरोजगारी के कारण सरकार की इस नीति का विरोध किया। अतः सरकार ने 1974 में गेहूँ की थोक व्यापार नीति का निरस्तीकरण कर दिया।

5. खाद्यान्नों की वितरण प्रणाली—खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति के साथ-साथ उचित कीमत पर उनके वितरण की व्यवस्था का भी सरकार प्रबन्ध करती है, जिससे समाज के निर्धन वर्ग को उचित कीमत पर न्यूनतम आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो सके और बढ़ती हुई कीमतों से उन्हें राहत मिल सके। खाद्यान्न की वितरण प्रणाली को बनाये रखने के लिए सरकार आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न आन्तरिक अधिप्राप्ति एवं आयातित खाद्यान्नों की मात्रा से पूरी करती है। सरकार खाद्यान्नों के वितरण की व्यवस्था राशन की दुकानों एवं उचित कीमत की दुकानों के माध्यम से करती है। उचित कीमत की दुकानों के माध्यम से वितरित किये जाने वाले खाद्यान्नों की कीमतें खुले बाजार की कीमतों से कम स्तर पर नियत की जाती हैं, जिससे निर्धन-वर्ग के व्यक्तियों को राहत मिलती है। सारणी 3.9 सरकार द्वारा विभिन्न खाद्यान्नों की उचित कीमत राशन की दुकानों के माध्यम से विक्रय के लिए विभिन्न वर्षों में नियत बिक्री कीमतें (Issue Prices) प्रदर्शित करती हैं। भारत में वर्ष 1968 के अन्त में 1.40 लाख उचित कीमत की दुकानें थीं, जो निरन्तर बढ़कर वर्ष 1991 में 3 60 लाख हो गईं। वर्तमान में यह दुकानें 792 5 मिलियन जन-संख्या को आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुएं जैसे चीनी, केरोसीन तेल, खाद्य तेल, कोयला, चाय एवं कपड़ा उपलब्ध करा रही हैं। सरकार दिसम्बर, 1985 से एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रम क्षेत्र एवं आदिवासी बाहुल्य राज्यों के निवासियों को गेहूँ एवं चावल सहाय्यतार्थ कीमत (Subsidised prices) पर उपलब्ध करा रही है।

सारणी 39

खाद्यान्नो के वितरण के लिए नियत बिन्धी कीमतें

(रुपये प्रति बिन्०)

खाद्यान्न	प्रभावशील दिनांक	किस्म एवं कीमत
1	2	3
1. गेहूँ	4 मई, 1969	84 00 अच्छी किस्म एवं 78.00 ग्रान्य किस्म
	29 मई, 1973	84 00 अच्छी किस्म एवं 78.00 देशी एवं मैक्सिम किस्म
	8 नवम्बर, 1973	96 00 अच्छी किस्म एवं 90 00 देशी, मैक्सिम एवं लाल किस्म
	15 अप्रैल, 1974	125.00 सभी किस्में
	1 दिसम्बर, 1978	130 00 सभी किस्में
	1 अप्रैल, 1981	145 00 सभी किस्में
	1 अगस्त, 1982	160 00 सभी किस्में
	15 अप्रैल 1983	172 00 सभी किस्में एवं रोलर आटे मिल के लिए 208। यह दर 10-8-84 से पुनः 172 की गई।
	1 फरवरी, 1986	190 00 सभी किस्में व रोलर मिल के लिए 190 जो 1-4-1986 से वृद्धि करके 220 एवं 16-7 1986 से कम करके पुनः 205 की गई।
	1 मई, 1987	195 00 सभी किस्में
	25 मार्च, 1988	204 00 सभी किस्मों के लिए
	1 मई, 1990	245 00 सभी किस्मों के लिए
	28 दिसम्बर, 1991	280 00 सभी किस्मों के लिए
	1992	320 00 सभी किस्मों के लिए
	11 जनवरी, 1993	370 00 सभी किस्मों के लिए

1	2	3
2 मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा, मक्का एवं रागी)	1 दिसम्बर, 1972 1 नवम्बर, 1973 1 जनवरी, 1975 25 अक्टूबर, 1979 1 जनवरी 1981 1 अक्टूबर, 1981 29 दिसम्बर, 1983 1 अक्टूबर, 1990	65.00 साधारण किस्म 80 00 साधारण किस्म 86 00 साधारण किस्म 96 00 साधारण किस्म 106 00 साधारण किस्म 117 00 साधारण किस्म 157 00 बाजरा के लिए 199 00 सभी मोटे अनाजों के लिए
3 चावल	4 मई, 1969 1 नवम्बर, 1973 1 जनवरी, 1975 15 अक्टू. 1976 (कच्चा) पारबोइल्ट 25 अक्टू. 1979* (कच्चा) पारबोइल्ट 1 जनवरी, 1981 1 अक्टूबर, 1981 1 अक्टूबर, 1982 16 जनवरी, 1984 10 अक्टूबर, 1985 1 फरवरी, 1986 1 अक्टूबर, 1986 1 अक्टूबर 1987 1 जनवरी, 1989 1 जून, 1990 28 दिसम्बर 1991 11 जनवरी, 1993	मोटी मध्यम अच्छी बहुत अच्छी किस्म 100 111 120 128 125 140 150 160 135 150 162 172 135 150 162 172 137 152 164 174 — 150 162 172 — 152 164 174 — 165 177 192 — 175 187 202 — 188 200 215 — 208 220 235 — 217 229 244 — 231 243 258 — 239 251 266 — 239 264 279 — 244 304 325 — 289 349 370 — 377 437 458 — 485 545 565

*दिनांक 25 अक्टूबर 1979 से चावल की मोटी एवं मध्यम किस्म को सम्मिलित रूप से साधारण किस्म में वर्गीकृत किया गया है।

स्रोत Directorate of Economics and Statistics, Ministry of Agriculture, Government of India, New Delhi

अध्याय 4

भारतीय कृषि में उत्पादन के कारक

कृषि-व्यवसाय में उत्पादन के चार प्रमुख कारक—भूमि, श्रम, पूँजी एवं प्रबन्ध हैं। उत्पादन के कारकों की पूर्ति करने वाले उत्पादन कारकों के स्वामी (Owners or Agents of Production) कहलाते हैं। भूमि कारक की पूर्ति करने वाला भू-स्वामी, श्रम-कारक की पूर्ति करने वाला श्रमिक, पूँजी-कारक की पूर्ति करने वाला पूँजीपति एवं प्रबन्ध करने वाला प्रबन्धक/व्यवस्थापक कहलाता है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में उपयुक्त चारों ही कारक समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी कारक की सीमितता की अवस्था में फार्म से उत्पादन की इच्छित मात्रा प्राप्त नहीं हो सकती है। उत्पादन की अधिकतम मात्रा प्राप्त करने के लिए उत्पादन के विभिन्न कारकों को निम्न-निम्न मात्राओं में कुशल उपयोग करते हैं। उत्पादन के कारकों का अनुकूलतम संयोग करने से फार्म पर उत्पाद की उत्पादन लागत में कमी होती है एवं फार्म से लाभ अधिक प्राप्त होता है। इस अध्याय में उत्पादन के विभिन्न कारकों एवं उनसे सम्बन्धित समस्याओं का विस्तृत विवेचन किया गया है।

भूमि

कृषि-उत्पादन का प्रथम मुख्य उत्पादन-कारक भूमि है। यहाँ पर भूमि से तात्पर्य भू-तल, उसके ऊपर एवं नीचे मिलने वाली सभी प्राकृतिक वस्तुएँ, जैसे—पहाड़, नदी, झरने, खनिज पदार्थ से है। भूमि प्रकृति का उपहार है। जिन देशों में प्राकृतिक देन विद्याल होनी है वे देश आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न होते हैं। इसके विपरीत प्राकृतिक उपहारों में सीमितता वाला देश बुगमता से आर्थिक समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। देश के सभी प्राथमिक उद्योग उत्पादन के लिए मुख्यतया भूमि

पर निर्भर होते हैं। निर्मित उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल भी भूमि से ही प्राप्त होता है।

भारत में भूमि का उपयोग—उपयोग की दृष्टि में भूमि को निम्नलिखित 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है

(1) वन भूमि/जंगल—वन-भूमि फसल उत्पादन के उपयोग में नहीं आ सकती है। इस भूमि पर स्वतः घास, बांस एवं अन्य पेड़-पौधे उग आते हैं। जंगलों को कृषि योग्य बनाने के लिए साफ करना होता है जिस पर काफी धन व्यय करना होता है।

(2) कृषि के लिए उपलब्ध न होने वाला क्षेत्र—यह दो प्रकार का होता है—

(अ) बंजर एवं अकृष्य भूमि—इसके अन्तर्गत पहाड़, टीले, रेगिस्तान आदि की भूमि आती है जिस पर या तो कृषि करना सम्भव नहीं है अथवा उस भूमि पर कृषि करना आर्थिक दृष्टि से लाभकर नहीं होता है।

(ब) गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि—इसके अन्तर्गत भवन, सड़क, रेल, नहर आदि के नीचे आने वाली भूमि आती है जो कृषि करने के लिए उपलब्ध नहीं होती है।

(3) परती भूमि के अतिरिक्त अकृष्य भूमि—यह तीन प्रकार की होती है—

(अ) स्थायी चरागाह एवं गोबर भूमि—यह पशुओं की चराई के लिए प्रयुक्त भूमि है।

(ब) विविध वृक्ष एवं फूलों के अन्तर्गत की भूमि जो शुद्ध कृषित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं की गई है।

(स) कृषि योग्य व्यर्थ भूमि (Culturable waste land)—यह वह भूमि है जिसका कृषि कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है लेकिन अभी तक वह व्यर्थ पड़ी हुई है। इस भूमि के क्षेत्र पर उचित लागत लगाकर उसे कृषि के अन्तर्गत लाया जा सकता है।

(4) परती भूमि—यह दो प्रकार की होती है—

(अ) चालू परती भूमि—यह वह भूमि है जो कृषि योग्य होते हुए भी चालू वर्ष में कृषित नहीं की गई है। साधारणतया कृषक भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने के लिए भूमि को चालू वर्ष में परती छोड़ देते हैं।

(ब) चालू परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि—यह वह भूमि है जो एक वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय के लिए परती छोड़ी जाती है। इस प्रकार की परती भूमि कृषकों द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने, कृषकों के पास पर्याप्त धनराशि न होने, फाम पर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होने तथा भूमि के खराब होने की व्यवस्था में छोड़ी जाती है।

(5) कृषित क्षेत्र—यह भूमि का वह क्षेत्र है जो कृषि के लिए उपयोग में लिया जाता है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से उपर्युक्त चारों श्रेणियों की भूमि का क्षेत्र घटाने पर जो भूमि का क्षेत्र शेष रहता है, वह शुद्ध कृषित क्षेत्र कहलाता है। शुद्ध कृषित क्षेत्र में वर्ष में एक से अधिक बार कृषित किये जाने वाले क्षेत्र को सम्मिलित करने पर प्राप्त भूमि का क्षेत्र सकल कृषित क्षेत्र (Gross cropped area) कहलाता है।

उपर्युक्त श्रेणियों के अनुसार भारत में भूमि के उपयोग के आकड़े सारणी 4.1 (पृष्ठ 79-80) में दिये गए हैं।

देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 328.726 मिलियन हेक्टर है। उसमें से शुद्ध कृषित क्षेत्रफल वर्ष 1950-51 में 118.746 मिलियन हेक्टर (41.8 प्रतिशत) था, जो बढ़कर वर्ष 1980-81 में 140.0 मिलियन हेक्टर एवं वर्ष 1988-89 में 141.731 मिलियन हेक्टर (46.50 प्रतिशत) हो गया। इस प्रकार 38 वर्षों में शुद्ध कृषित क्षेत्र में 22.985 मिलियन हेक्टर या 4.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस काल में सकल कृषित क्षेत्रफल में 48.216 मिलियन हेक्टर की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि वर्ष में एक बार से अधिक कृषित किये जाने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि के कारण हुई है। पिछले 38 वर्षों में वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि 26.60 मिलियन हेक्टर या 60 प्रतिशत की हुई है। कृषित क्षेत्र एवं वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि, परती भूमि, वज्र एवं अकृष्य भूमि एवं विविध वृक्षों एवं कुओं के अन्तर्गत भूमि के क्षेत्रफल में कमी के कारण हो पाई है।

कृषि जोत

कृषि जोत में सामान्यतः तात्पर्य फार्म की प्रबन्ध इकाई से होता है अर्थात् भूमि का वह क्षेत्र जो कृषि करने के लिए व्यक्ति/परिवार के पास सम्मिलित रूप में होता है। कृषि जोत का यह क्षेत्रफल स्वयं की भूमि, लगान पर ली हुई भूमि तथा अशतः निजी एवं अशतः लगान पर ली हुई भूमि का हो सकता है। कृषि जोत का क्षेत्रफल कृषि उत्पादन-क्षमता में परिवर्तन साता है। इसी प्रकार सम्पूर्ण कृषि जोत एक खण्ड में न होकर अनेक खण्डों में विभक्त हो सकती है जो उत्पादन-क्षमता को प्रभावित करती है।

देश अथवा राज्य में जोत का औसत आकार ज्ञात करने के लिए देश/राज्य के कुल जोत के अन्तर्गत क्षेत्रफल में कृषित जोतों की संख्या का भाग दिया जाता है। जोत का औसत आकार देश, राज्य में भूमि पर जनसंख्या का भार एवं कृषि की औसत इकाई के क्षेत्रफल का चोतक होता है। कृषि जोत के एक इकाई क्षेत्रफल से प्राप्त उत्पादन की मात्रा एवं आय में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत असमानता होती है, क्योंकि देश/राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि की उर्वरा शक्ति, जलवायु, कृषि के

सारणी 4.1
भारत में भूमि का उपयोग

भूमि का उपयोग	(क्षेत्रफल मिलियन हेक्टर में)					
	1950-51 1	1950-51 2	1960-61 3	1970-71 4	1980-81 5	1988-89 6
1. देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	328,726	328,726	328,726	328,726	328,726	328,726
2. कुल क्षेत्रफल जिसके लिए प्राकृत उपलब्ध है	284,315	284,315	298,458	303,758	304,159	304,827
3. विभिन्न उपयोगों के प्रत्यक्ष (अ) वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	40,482	40,482	54,052	63,917	67,473	67,082
(ब) कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध नहीं होने वाला क्षेत्रफल	(142)	(142)	(181)	(2104)	(2218)	(2201)
(व) कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध नहीं होने वाला क्षेत्रफल	47,157	47,157	50,751	44,639	39,618	41,238
(घ) गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि वा क्षेत्रफल	(167)	(167)	(170)	(1470)	(1303)	(1353)
(1) गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि वा क्षेत्रफल	9,357	9,357	14,840	10,478	19,656	21,249
(ii) बज्जर एवं अदृश्य भूमि का क्षेत्रफल	(3.3)	(3.3)	(50)	(543)	(647)	(697)
(iii) परती भूमि के अतिरिक्त अदृश्य भूमि का क्षेत्रफल	38,160	38,160	35,911	28,161	19,962	19,989
(iv) परती भूमि के अतिरिक्त अदृश्य भूमि का क्षेत्रफल	(13.4)	(13.4)	(120)	(927)	(656)	(656)
(v) परती भूमि के अतिरिक्त अदृश्य भूमि का क्षेत्रफल	49,446	49,446	37,637	35,060	32,318	30,476
(vi) परती भूमि के अतिरिक्त अदृश्य भूमि का क्षेत्रफल	(17.4)	(17.4)	(126)	(1154)	(1063)	(1000)

1	2	3	4	5	6
(i) स्थायी चरागाह एवं गोचर भूमि का क्षेत्रफल	6 675 (23)	13 966 (4.7)	13 261 (436)	11 974 (394)	11 796 (387)
(ii) विविध वृक्षों एवं फुसों के अन्तर्गत भूमि का क्षेत्रफल	19 828 (70)	4 459 (15)	4 299 (142)	3 600 (118)	3 452 (113)
(iii) कृषि योग्य व्यर्थ भूमि का क्षेत्रफल	22 943 (81)	19 212 (64)	17 500 (576)	16 744 (551)	15 228 (500)
(iv) परत भूमि का क्षेत्रफल	28 124 (99)	22 819 (77)	19 875 (654)	24 748 (814)	24 300 (797)
(v) चानू परती भूमि का क्षेत्रफल	10 679 (38)	11 639 (39)	11 116 (366)	14 832 (488)	13 842 (454)
(vi) अन्य परती भूमि का क्षेत्रफल	17 445 (61)	11 180 (38)	8 759 (288)	9 216 (303)	10 458 (343)
(vii) शुद्ध कृषित क्षेत्रफल	118 746 (418)	133 199 (446)	140 267 (4618)	140 002 (4603)	141 731 (4650)
(viii) सकल कृषि क्षेत्रफल वष में एक बार से अधिक कृषित क्षेत्रफल	131 893 (418)	152 772 (446)	165 791 (4618)	172 630 (4603)	180 109 (4650)
	13 147	19 573	25 524	32 628	38 378

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े, कुल क्षेत्रफल जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं के प्रतिशत हैं।

स्रोत Agricultural situation in India, Vol X LVI (12), March 1992, pp 960-61.

प्रकार एवं प्रणालियों में बहुत असमानता पायी जाती है। भूत जोत के औसत आकार से कृषकों को प्राप्त होने वाली आय तथा कृषकों के रहन-सहन के स्तर के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। सारणी 4.2 विभिन्न राज्यों में जोत की संख्या एवं उनके औसत आकार के आंकड़े प्रदर्शित करती है।

देश के विभिन्न राज्यों में जोत के औसत आकार में बहुत विभिन्नता है। असम, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, पश्चिमी बंगाल एवं हिमाचल प्रदेश राज्य में जोत का औसत आकार भारत के औसत से कम है, जबकि गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब एवं राजस्थान राज्य में जोत का औसत आकार देश के औसत से अधिक है। केरल राज्य में जोत का औसत आकार सबसे कम है।

सारणी से स्पष्ट है कि विभिन्न राज्यों में जोतों की संख्या में पिछले 15 वर्षों में निरन्तर वृद्धि हुई है। भारत में कृषित जोतों की संख्या 1970-71 की कृषि जनगणना के अनुसार 70 493 मिलियन थी, जो बढ़कर 1976-77 की कृषि जनगणना के अनुसार, 81 57 मिलियन 1980-81 की कृषि जनगणना के अनुसार, 89 393 मिलियन एवं 1985-86 की कृषि जनगणना के अनुसार 97 73 मिलियन हो गई। विभिन्न राज्यों में जोतों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि बिहार एवं जम्मू एवं कश्मीर राज्य में हुई है। सारणी से यह भी स्पष्ट है कि इस काल में जोत के औसत आकार में निरन्तर कमी हुई है। भारत में जोत का औसत आकार वर्ष 1970-71 में 2.28 हेक्टर था, जो कम होकर 1976-77 में 2.0 हेक्टर, 1980-81 में 1.82 हेक्टर एवं 1985-86 में 1.68 हेक्टर हो रहा गया। इसी प्रकार जोत के औसत आकार में कमी राज्यों में भी हुई है। मात्र पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जहाँ जोत के औसत आकार में वृद्धि हुई है। पंजाब में जोत का औसत आकार वर्ष 1970-71 में 2.89 हेक्टर था, जो बढ़कर वर्ष 1985-86 में 3.7 हेक्टर हो गया। इसका प्रमुख कारण राज्य में औद्योगीकरण में वृद्धि होना है। जिससे सीमान्त एवं लघु कृषक गांवों से शहर की ओर प्रवासन करते जा रहे हैं, क्योंकि कृषि उनके लिए अन्य व्यवसायों की अपेक्षा कम लाभप्रद होती जा रही है।¹

कृषि-जोतों का वर्गीकरण :

1. कृषि-जोतों का निम्न आधारों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है—

1 I J Singh, Agricultural Instability and Farm Poverty in India, Presidential Address at 48th Annual Conference of the Indian Society of Agricultural Economics held at Banaras Hindu University, 27-29 December, 1988, p. 8

सारणी 42

भारत के विभिन्न राज्यों में जलोढ़ की सख्या एवं जलोढ़ का औसत आकार

राज्य	जोतो की सुरखा (मिलियन म)				जोत का औसत आकार (हेक्टर में)				
	कृषि जनगणना 1970-71	कृषि जनगणना 1980-81	कृषि जनगणना 1985-86	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 1961-62	कृषि जनगणना 1970-71	कृषि जनगणना 1976-77	कृषि जनगणना 1980-81	कृषि जनगणना 1985-86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1 आन्ध्र प्रदेश	5 420	7 370	8 231	3 18	2 51	2 34	1 87	1 72	
2 असम	1 964	2 297	2 419	1 53	1 47	1 37	1 36	1 31	
3 बिहार	7 577	11 030	11 800	1 80	1 50	1 11	0 99	0 87	
4 गुजरात	2 433	2 930	3 08	4 49	4 11	3 71	3 45	3 15	
5 हरियाणा	0 913	1 010	1 35	NA	3 77	3 58	3 52	2 76	
6 हिमाचल प्रदेश	0 609	0 638	0 82	NA	1 53	1 63	1 54	1 30	
7 जम्मू एवं कश्मीर	0 979	1 035	1 18	NA	0 94	1 07	1 00	0 86	
8 केरल	2 305	0 418	0 489	1 13	0 57	0 49	0 43	0 36	
9 कर्नाटक	3 551	4 309	4 919	4 03	3 20	2 98	2 73	2 41	
10 मध्य प्रदेश	5 299	6 410	7 600	4 11	4 00	3 58	3 42	2 91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 महाराष्ट्र	4.951	6 860	8 080	4 85	4 28	3 68	2 95	2 65
12 मेघालय	—	0 170	0 171	NA	1 70	1 74	1 74	1 76
13 मणिपुर	—	0 136	0 139	NA	1 15	1 12	1 24	1 24
14 मिजोरम	—	0 466	0 519	NA	NA	1 46	1 49	1 57
15 नागालैण्ड	—	0 116	0 125	NA	5 40	7 61	7 41	7 46
16 छडीसा	3 407	3 328	3 586	2 12	1 89	1 60	1 59	1 47
17 पंजाब	1 375	1 020	1 088	4 06	2 89	2 74	3 79	3 77
18 राजस्थान	3 727	4 486	4 760	5 82	5 46	4 65	4 44	4 34
19 तमिलनाडु	5 314	7 190	7 710	1 62	1 45	1 25	1 08	1 01
20 त्रिपुरा	—	0 308	0 312	NA	1 02	1 25	1 08	1 01
21 उत्तर प्रदेश	15 639	17 820	18 79	1 62	1 16	1 05	1 01	0 93
22 पश्चिम बंगाल	4 216	0 588	0 615	1 74	1 20	0 99	0 95	0 92
23 सिक्किम	NA	0 562	0 368	NA	NA	2 50	1 94	2 77
24 केन्द्र शासित प्र	NA	0 925	0 953	NA	NA	NA	NA	NA
भारत	70 493	89 393	97 73	NA	2 28	2 00	1 82	1 68

स्रोत (i) National Sample Survey 17th Round, September, 1961 to July 1962, Government of India, New Delhi

(ii) Agricultural Situation in India—Various issues, Directorate of Economics and Statistics, Ministry of Agricultural, Government of India, New Delhi.

1 स्वामित्व के अनुसार—स्वामित्व के अनुसार कृषि-जोत दो प्रकार की होती है—

(अ) निजी जोत—निजी जोत से तात्पर्य भूमि के उस क्षेत्र से है जिस पर एक व्यक्ति या परिवार का स्वामित्व होता है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि जोत के कुल क्षेत्र पर परिवार द्वारा कृषि की जाए। जोत का यह क्षेत्र परिवार द्वारा अथवा अशत, लगान पर दिया जाकर भी कृषि किया जा सकता है। निजी जोतों पर कृषकों को स्थायी वंशागत अधिकार (Heritable possession rights) प्राप्त होते हैं।

(ब) कृषि जोत—कृषि जोत से तात्पर्य भूमि के उस क्षेत्र से है जो कृषि करने के लिए एक प्रबन्धकर्ता के अधिकार में होता है। जोत के उस क्षेत्र पर कृषक का स्वामित्व होना आवश्यक नहीं है। कृषि जोत एक कृषक, परिवार तथा अनेक कृषकों के पास सम्मिलित अधिकार में हो सकती है। कृषि जोत का क्षेत्र निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। कृषि जोत के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उस भूमि के कुल क्षेत्र पर निरन्तर कृषि की ही जावे। कृषि जोत के क्षेत्र में परती भूमि

१। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि का क्षेत्र भी सम्मिलित होता है। कृषि जोत की भूमि २५ स्थान अथवा विभिन्न स्थानों पर भी हो सकती है।

कृषि जोत का = निजी जोत + बंटाई पर सी गई भूमि का क्षेत्र - बंटाई पर दी गई भूमि का क्षेत्र

2. जोत के अन्तर्गत भूमि के क्षेत्र के अनुसार—जोत के अन्तर्गत भूमि के क्षेत्र के अनुसार कृषि जोत चार प्रकार की होती है।

(अ) आधार जोत—कांग्रेस भूमि-सुधार समिति², 1951 के अनुसार आधार जोत (Basic holding) का क्षेत्र वह है “जो कृषकों को न्यूनतम आवश्यक जीवन-स्तर प्राप्त कराने की दृष्टि से अनाधिक हो सकता है लेकिन कृषि कार्यों के करने की दृष्टि से अदक्ष नहीं होता है।” आधार जोत मुख्यतया अधिक नहीं होनी है। आधार जोत का सामाजिक महत्त्व है। समाज के सभी सदस्यों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए जोत को न्यूनतम आधार के क्षेत्र तक विभाजित किया जाता है। आधार जोत साधारणतया पारिवारिक जोत के क्षेत्र की एक-तिहाई होता है। भूमि की जोत के तीन आधार—कार्य इकाई, हल की इकाई एवं आय की इकाई में से आधार जोत, प्रथम दो आधारों की ही पूर्ति करती है। आधार जोत पर्याप्त आय की राशि प्रदान नहीं करती है।

2. “Basic holding which though uneconomic in the sense of being unable to provide a reasonable standard of living to the cultivator may not be inefficient for the purpose of agricultural operations.”

—Report of the Congress Agrarian Reforms Committee, AICC, 1951.

(ब) अनुकूलतम जोत—अनुकूलतम जोत (Optimum holding) क्षेत्र वह है जहाँ पर वस्तुओं की प्रति इकाई मात्रा की औसत उत्पादन लागत दीर्घकाल में कम से कम आती है।³ अनुकूलतम जोत का यह क्षेत्र उत्पादन फलन विश्लेषण विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। कांग्रेस भूमि सुधार समिति के अनुसार एक औसत कृषक के पास उपलब्ध वित्तीय एवं अन्य उत्पादन साधनों की मात्रा, प्रबन्ध क्षमता आदि के अनुसार जोत का अनुकूलतम क्षेत्र निर्धारण करना चाहिए। अनुकूलतम जोत का क्षेत्र कृषक एवं उसके परिवार को उचित जीवन स्तर प्राप्त कराने के लिए आवश्यक आय प्रदान करने वाला होना चाहिए। समिति के अनुसार एक परिवार के लिए अनुकूलतम जोत का क्षेत्र आर्थिक जोत के क्षेत्र के तीन गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। सयुक्त-परिवार एवं धार्मिक संस्थाओं के लिए अनुकूलतम जोत का क्षेत्र अधिक हो सकता है।

(स) न्यूनतम जोत—जोत के न्यूनतम आकार से तात्पर्य जोत के उस आकार से है जो कृषक के परिवार एवं एक जोड़ी बैल को वर्ष में पूर्ण समय कार्यरत रख सके तथा परिवार के जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक आय की राशि प्राप्त कराये। जोत का न्यूनतम आकार विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित कृषि-विधियों एवं जलवायु की विभिन्नता के कारण विभिन्न होता है। देश के विभिन्न राज्यों में किए गए फार्म प्रबन्ध अध्ययनों के अनुसार न्यूनतम जोत आकार 7.5 से 10.0 एकड़ के मध्य में होना चाहिए। वर्तमान में कृषि में तकनीकी ज्ञान के उपयोग से कृषकों की आय में वृद्धि हुई है जिससे सम्भवतः यह क्षेत्र कम होकर 5.0 एकड़ के समीप हो गया है। यह क्षेत्र एक कार्य इकाई, हल इकाई एवं आय की इकाई के समतुल्य होता है। साथ ही जोत का न्यूनतम आकार, दक्ष एवं अदक्ष फर्मों के विभाजन का विन्दु होता है।

(द) आर्थिक जोत—आर्थिक जोत से तात्पर्य जोत के उस आकार से है जो कृषक एवं उसके परिवार को उचित जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक आय एवं रोजगार उपलब्ध करा सके। आर्थिक जोत को विभिन्न शब्दों में परिभाषित किया गया है—

कीटिंग⁴—“आर्थिक जोत भूमि का वह क्षेत्र है जो कृषक को आवश्यक आय उत्पादित करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे कृषक तथा उसका

3 'The size at which the long run average cost of production per unit of output would be the lowest'

—A. M. Khusro The Economics of Land Reform and Farm Size in India, The Macmillan Company of India Limited, 1973, p. 39

4 Economic holding is one which allows a man the chance of producing sufficient to support himself and his family in reasonable comfort after paying his necessary expenses" Keatinge, Rural Economy of Bombay Deccan

परिवार आवश्यक खर्चों का भुगतान करके सुख-पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके।”

कांग्रेस भूमि-सुधार समिति⁵ (1951)—वार्षिक जोत विभिन्न क्षेत्रों की कृषि-जलवायु स्थिति के अनुसार भूमि का वह क्षेत्र है जो कृषक के परिवार को जीवन-निर्वाह का उचित स्तर एवं सामान्य परिवार के सदस्यों एवं एक जोड़ी बैल को वर्ष भर पर्याप्त कार्य उपलब्ध करा सके।

उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर वार्षिक जोत का क्षेत्र निश्चित करना कठिन होता है। कृषक तथा उसके परिवार को उचित जीवन-निर्वाह का स्तर प्रदान करने की सम्पत्ति व्यक्तिपरक (Subjective) होती है। विभिन्न स्थानों की परिस्थितियों एवं परिवार की आवश्यकताओं में विभिन्नता के कारण वार्षिक जोत के क्षेत्र में बहुत भिन्नता पायी जाती है। अधिक उपजाऊ भूमि के क्षेत्रों में 10 से 15 एकड़ भूमि से एक परिवार के लिए उचित जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक आय सुगमता से प्राप्त हो सकती है।

पारिवारिक जोत—योजना आयोग ने पञ्चवर्षीय योजना की शुरुआत में वार्षिक जोत के स्थान पर पारिवारिक जोत शब्द का उपयोग किया था और उसे निम्न शब्दों में परिभाषित किया है।⁶

“पारिवारिक जोत स्वामीय परिस्थितियों एवं कृषि पद्धतियों के अनुसार एक औसत परिवार के लिए कृषि ऋायों में दूसरों से सहायता प्राप्त करके एक हल की इकाई या कार्य की इकाई के समतुल्य होती है। पारिवारिक जोत से 1,200 रु प्रति वर्ष की शुद्ध आय प्राप्त होनी चाहिए। पारिवारिक जोत का निश्चित क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारकों जैसे भूमि की किस्म, फसलों की प्रकृति आदि के अनुसार निश्चित किया जाता है।”

पारिवारिक जोत के लिए 1,200 रु प्रतिवर्ष की शुद्ध आय, वर्ष 1951 की कीमतों के स्तर पर निर्धारित की गई थी। पारिवारिक जोत की यह परिभाषा

5. The economic holding which under given agronomic conditions would provide (i) a reasonable standard of living and (ii) full employment for a family of normal size and at least a pair of bullocks

Congress Agrarian Reforms Committee Report A-I C C, 1951, p 8.

6. “Family holding was to be equivalent according to the local conditions and under the existing conditions of techniques either to a plough unit or to a work unit for a family of average size working with such assistance as is customary in agricultural operations. Moreover, a family holding was conceived as yielding a net income from agriculture of Rs. 1,200 per annum. The exact area of family holding was to be fixed in each region separately according to various factors such as type of soil, nature of crops, etc.” First Five Year Plan, Planning Commission, Government of India, New Delhi.”

वर्ष 1950 में 60 के दशक में बहुत से राज्यों द्वारा अपनाई गई थी। वर्तमान में बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए 1,200 रु. प्रतिवर्ष की शुद्ध आय एक औसत परिवार के लिए बहुत कम है। इस आय स्तर से एक कृषक परिवार वर्तमान में उचित जीवन-स्तर प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः वर्तमान में पारिवारिक जोत के लिए वार्षिक शुद्ध आय की राशि 1,200 रु. का प्रचलित औसत स्तर (वर्ष 1951 की कीमतों को आधार मानकर) के औसत सूचकांक से गुणा करके ज्ञात करना चाहिए।

आर्थिक जोत एवं पारिवारिक जोत निर्धारण के तीन मुख्य आधार हैं—

(i) कार्य-इकाई—फार्म का वह न्यूनतम आकार जिससे कम होने पर परिवार के सदस्यों को वर्ष भर पर्याप्त आय प्रदान करने वाला पूर्ण रोजगार उपलब्ध नहीं होता हो, उस क्षेत्र को एक कार्य इकाई कहते हैं।

(ii) हल-इकाई—फार्म का वह न्यूनतम आकार जिसमें कम होने पर फार्म पर उपलब्ध एक जोड़ी बैल को वर्ष भर कार्यरत नहीं रखा जा सके, उस क्षेत्र को एक हल-इकाई माना जाता है।

(iii) आय-इकाई—फार्म का वह न्यूनतम आकार जिससे कम होने पर जो आय प्राप्त होती है उसमें से उत्पादन-लागत भय बैलों के रख रखाव एवं यन्त्रों की मरम्मत की राशि को बाकी निकालने पर जो आय शेष रहती है उससे परिवार को उचित-जीवन-स्तर प्रदान नहीं किया जा सके, उस क्षेत्र को एक आय-इकाई के सम-मुख्य माना जाता है।

विभिन्न राज्यों में वर्ष 1954-55 से 1957-58 के काल में किये गये फार्म प्रबन्ध अध्ययनों⁷ के अनुसार वर्तमान प्रचलित तकनीकी ज्ञान-स्तर पर एक कार्य-इकाई, हल-इकाई एवं आय-इकाई के लिए विभिन्न राज्यों में भूमि का न्यूनतम क्षेत्र निम्न होना चाहिए :

सारणी 4.६

विभिन्न राज्यों में एक कार्य, हल एवं भाय-इकाई के लिए भूमि का न्यूनतम क्षेत्र
(एकड़ में)

राज्य	कार्य-इकाई	हल-इकाई	भाय-इकाई
1. आन्ध्र-प्रदेश	50	100	100
2 पंजाब	100	75	200
3 उत्तर-प्रदेश	75	100	100
4 तमिलनाडु	7.5	50	—
भारत	7.5	75	15.0

आर्थिक जोत के आकार के निर्धारक तत्व :

आर्थिक जोत के आकार का मुख्य निर्धारक तत्व भूमि का क्षेत्र न होकर भूमि की उत्पादकता माना जाता है। प्रति इकाई भूमि के क्षेत्र की उत्पादकता अधिक होने पर आर्थिक जोत का आकार कम होता है तथा उत्पादकता के कम होने पर आर्थिक जोत का आकार अधिक होता है। भूमि की उत्पादकता अनेक कारकों पर निर्भर करती है। अतः आर्थिक जोत के आकार के मुख्य निर्धारक तत्व उत्पादकता के तत्व ही होते हैं जो निम्नांकित हैं।

(i) भूमि की उर्वरा शक्ति—भूमि की उर्वरा शक्ति एवं आर्थिक जोत में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। भूमि की उर्वरा शक्ति के अधिक होने पर आर्थिक जोत का आकार कम तथा उर्वरा शक्ति के कम होने पर अधिक जोत का आकार अधिक होता है। भूमि की उर्वरा शक्ति में खाद एवं उर्वरकों के उपयोग से वृद्धि करके आर्थिक जोत का आकार कम किया जा सकता है।

(ii) सिंचाई की सुविधा—पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने वाले क्षेत्रों में आर्थिक जोत का आकार कम होता है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर अधिक भाय देने वाली फसलों का चुनाव करके एवं भूमि पर बहुफसलीय कार्यक्रम अपनाकर आर्थिक जोत के आकार को कम किया जा सकता है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होने अथवा कम उपलब्ध होने वाले क्षेत्रों में आर्थिक जोत का आकार अधिक होता है।

(iii) जनसंख्या का कृषि पर भार—अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में आर्थिक जोत का आकार कम होता है क्योंकि इन क्षेत्रों में भूमि की सीमितता के कारण सघन कृषि पद्धति अपनायी जाती है। कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में आर्थिक जोत का आकार अधिक होता है।

(iv) कृषि का प्रारूप—विस्तृत कृषि पद्धति के अन्तर्गत सामान्य परिवार को जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक आय प्राप्त करने के लिए भूमि के अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। सघन कृषि पद्धति वाले क्षेत्रों में कम भूमि के क्षेत्र से आवश्यक आय प्राप्त हो जाती है। जिससे आर्थिक जोत का आकार कम होता है।

(v) फसलों की प्रकृति—खाद्यान्न फसलों के उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में आर्थिक जोत का आकार अधिक तथा सब्जियों एवं वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में अधिक जोत का आकार कम होता है क्योंकि सब्जियों एवं वाणिज्यिक फसलों द्वारा खाद्यान्नों की अपेक्षा प्रति इकाई भूमि से लाभ अधिक प्राप्त होता है।

(vi) कृषकों की कार्य कुशलता—कृषकों के अधिक मेहनती एवं कार्यकुशल होने पर सम्बन्धित क्षेत्रों में आर्थिक जोत का आकार कम एवं कम कार्यकुशल होने वाले क्षेत्रों में आर्थिक जोत का आकार अधिक होता है।

(vii) उत्पादन साधनों की उपलब्धि—कृषकों को आवश्यक उत्पादन-साधन, जैसे—बीज, उर्वरक, उन्नत, कृषि यन्त्र, कीटनाशी दवाइयाँ उचित समय पर उपलब्ध होने वाले क्षेत्रों में आर्थिक जोत का आकार कम होता है।

(viii) शहर से दूरी—शहर के नजदीक वाले क्षेत्रों में आर्थिक जोत का आकार कम होता है क्योंकि इन क्षेत्रों में कृषक सब्जी, फल, फूल एवं पशुओं के लिए बारा उत्पादन करके एवं उसे शहर में विक्रय करके अधिक आय प्राप्त करते हैं। खेत की शहर से दूरी बढ़ने पर उपर्युक्त फसलों का उत्पादन विपणन की दृष्टि से लाभकर नहीं होता है। शहर से दूरी बढ़ने पर भूमि में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है जिससे आर्थिक जोत का आकार अधिक होता है।

(ix) क्षेत्र की जलवायु—क्षेत्र की जलवायु विभिन्न फसलों की उत्पादकता में परिवर्तन लाती है जिसके कारण भी आर्थिक जोत के आकार में परिवर्तन होता है।

अनाधिक जोतों को आर्थिक जोतों में परिवर्तित करने के लिए सुझाव

निम्न सुझावों को अपनाकर अनाधिक जोत को आर्थिक बनाया जा सकता है —

(1) जोत की उच्चतम सीमा निर्धारण करना—विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जोत की उच्चतम सीमा निर्धारित करने से बड़े कृषकों। जमींदारों से प्राप्त अधिशेष भूमि को सीमान्त एवं लघु कृषकों में वितरण करने से उनकी अनाधिक जोत आर्थिक जोत में परिणत की जा सकती है।

(ii) जोत चक्रवर्ती द्वारा—कृषकों की जोत के विभिन्न भू-खण्डों को जो

विभिन्न दूरी पर स्थित होते हैं, उन्हें चकबन्दी द्वारा एक संयुक्त चक्र में करने में अनाधिक जोत का क्षेत्र अधिक बन जाता है।

(iii) जोत उप-विभाजन एवं अपखण्डन पर रोक लगाकर—जोत को न्यूनतम सीमा के पश्चात् जोत उप-विभाजन एवं अपखण्डन पर रोक लगाकर एवं प्रचलित वर्तमान कानून में परिवर्तन करके अनाधिक जोतो की सत्या पर रोक लगाई जा सकती है।

(iv) सहकारी कृषि-पद्धति अपनाकर—सहकारी कृषि बड़े पैमाने पर की जाने से उन्नत यन्त्रों, बड़ी मशीनों एवं ट्रैक्टरों का उपयोग होने से भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक लाभ प्राप्त होता है। वस्तुओं के सामूहिक विपणन से प्रति इकाई मात्रा पर विपणन लागत कम आती है। लघु कृषक सहकारी कृषि पद्धति अपनाकर अपनी अनाधिक जोत को अधिक बना सकते हैं।

(v) सघन कृषि-पद्धति को प्रोत्साहन देना—लघु कृषक फार्म पर सघन कृषि पद्धति अपनाकर, अपने सीमित भूमि क्षेत्र से अधिक धान प्राप्त कर सकते हैं और अनाधिक जोत को अधिक बना सकते हैं।

भूमि-सुधार

भूमि-सुधार से तात्पर्य देश में भूमि-व्यवस्था में उन परिवर्तनों के करने से है जिनके द्वारा भूमि-व्यवस्था में सुधार करके कृषकों को भूमि की उत्पादकता बढ़ाने एवं उन्हें उच्च जीवन-स्तर प्रदान करने के प्रयास किए जाते हैं। भूमि-सुधार शब्द का अर्थ बड़ा विस्तृत है जिसके अन्तर्गत न केवल भूमि-व्यवस्था का सुधार ही सम्मिलित है, बल्कि इसके अन्तर्गत मध्यस्थों की समाप्ति, कारगरकारी व्यवस्था में सुधार, भू-सीमा का निर्धारण, जोत-उपविभाजन एवं अपखण्डन पर रोक, जोत चकबन्दी, सहकारी खेती एवं कृषि का पुनर्गठन आदि कार्य भी सम्मिलित होते हैं।⁸

भूमि-सुधार कार्य कृषि नीति के साथ-साथ एक सामाजिक नीति सम्बन्धी कार्यक्रम भी है। भूमि-सुधार कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य निम्नांकित हैं—

- (i) कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में आने वाली बाधाओं को दूर करना।
- (ii) कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करना।
- (iii) कृषि में तकनीकी ज्ञान के विस्तार के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करना।

भूमि सुधार कार्यक्रम नया नहीं है। वर्ष 1946 में कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में भूमि-सुधार के लिए निर्णय लिया गया था कि कृषक एवं सरकार के मध्य पाए जाने वाले मध्यस्थों को समाप्त किया जाये और मध्यस्थों को भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाये। वर्ष 1948 में स्थापित ग्राम्य-सुधार समिति (Agrarian Reform Committee) ने सुझाव दिया कि भूमि पर स्वामित्व कृषक का होना चाहिए। समिति ने सुझाव दिया कि जो कृषक पिछले 6 वर्षों से निरन्तर किसी भू-खण्ड पर खेती कर रहे हैं, उन्हें उस भूमि पर स्वामित्व दे देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भूमि-सुधार वृत्तान्त में बताया कि भारत में भूमि-सम्बन्धी पद्धति उचित नहीं होने से आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। भारत में भूमि-सुधार के लिए समय-समय पर विभिन्न कानून पारित किये गये हैं। भूमि-सुधार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का दायित्व राज्य सरकारों का होता है। अतः भूमि-सुधार कार्यक्रम की प्रगति सभी राज्यों में समान नहीं है।

भारत में भूमि-सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत पारित अधिनियमों को उनके उद्देश्यों के अनुसार निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है—

- I. मध्यस्थों की समाप्ति के लिए पारित अधिनियम;
- II. काश्तकारी सुधार अधिनियम,
- III. जोत उप-विभाजन एवं अपखण्डन पर रोक लगाना एवं जोत चक्रबन्दी अधिनियम,
- IV. भू-सीमा निर्धारण अधिनियम; तथा
- V. सहकारी खेती एवं सहकारी ग्राम प्रबन्ध अधिनियम।

1. मध्यस्थों की समाप्ति

भूमि सुधार के लिए किए गए प्रयासों में प्रथम कार्य मध्यस्थों की समाप्ति का है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार एवं कृषकों के मध्य पाए जाने वाले मध्यस्थों की समाप्ति करना एवं कृषकों को सरकार के सीधे सम्पर्क में लाना है।

भू-धृति (Land Tenure)—भू-धृति शब्द का उद्गम लेटिन शब्द टिनियो (Tenco) से है, जिसका तात्पर्य प्रबन्ध से है। अर्थात् भू-धृति शब्द का अर्थ भूमि को पट्टे (Lease) पर देने की शर्तों एवं अन्य परिस्थितियों के ज्ञान से है। भू-धृति में कृषि करने हेतु ती गई भूमि के अधिकार, स्वामित्व, राजस्व भुगतान आदि सम्मिलित होता है। भूमि के प्रबन्ध में निम्न सस्थाएँ/व्यक्ति सम्बन्धित होते हैं—

- (i) सरकार—देश की समस्त भूमि पर राज्य सरकार का सर्वोच्च स्वामित्व/अधिकार होता है।

(ii) **कृषक परिवार**—यह वह वर्ग है जो भूमि पर कृषि कार्य करता है। स्वामित्व व अन्य प्राप्त अधिकारों के अनुसार कृषक तीन प्रकार के होते हैं—

(अ) वे कृषक जो स्वयं भूमि के स्वामी होते हैं स्वयं ही भूमि पर कृषि करते हैं और उनका सरकार से सीधा सम्पर्क होता है,

(ब) वे कृषक जिन्हें भूमि पर स्वामित्व अधिकार तो प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन भूमि पर कृषि करने के अधिकार प्राप्त होते हैं। सरकार का इनसे सीधा सम्पर्क नहीं होता है। इन कृषकों एवं सरकार के मध्य में जमींदार, जमींदार आदि मध्यस्थ होते हैं।

(स) वे कृषक जो भूमि पर स्वयं कृषि करते हैं, कृषि कार्यों के करने की उत्पादन लागत बढ़ाने करते हैं, लेकिन इन्हें भूमि पर शासककारी अधिकारों के सम्बन्ध में कोई निश्चितता प्राप्त नहीं होती है। इन्हें गैर-मौकसी (Non-Occupancy) शासककार कहते हैं।

(iii) **मध्यस्थ**—मध्यस्थ भूमि के सर्वोच्च स्वामी (सरकार) एवं भूमि पर कृषि करने वाले शासककारों के मध्य कार्य करने वाला वर्ग होता है। यह वर्ग सरकार से नियत शर्तों पर भूमि प्राप्त करते हैं। कुछ मध्यस्थों को उनके द्वारा सरकार को प्रदान की गई सेवाओं के लिए भूमि प्राप्त होती है। मध्यस्थ भूमि के अस्थायी भू-स्वामी होते हैं। मध्यस्थ सरकार को राजस्व की नियत राशि जमा कराते हैं और भूमि को कृषकों को कृषि करने के लिए देकर उनसे लगान वसूल करते हैं। प्राप्त लाभ से आरामप्रद जीवन यापन करते हैं। विभिन्न राज्यों में मध्यस्थों के भिन्न-भिन्न नाम प्रचलित हैं, जैसे—जमींदार, जमींदार, बिस्वेदार, ईनामदार आदि।

(iv) **कृषि श्रमिक**—भूमि के प्रबन्ध से सम्बन्धित चौथी श्रेणी कृषि श्रमिकों की होती है जो भूमि पर श्रम करके मजदूरी प्राप्त करते हैं। इनकी आय का प्रमुख स्रोत मजदूरी होता है। इन्हें भूमि पर स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है। साथ ही कृषि कार्यों के करने से सम्बन्धित निर्णय लेने का अधिकार भी इन्हें प्राप्त नहीं होता है।

भू-धृति पद्धति—भू-धृति पद्धति को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है।

1 स्वामित्व के आधार पर—यह पद्धति भूमिधारी एवं सरकार के मध्य पाये जाने वाले मध्यस्थों के परस्पर सम्बन्धों की प्रकृति पर आधारित होती है। वेडेन बोवेल⁹ के अनुसार स्वामित्व के आधार पर भू-धृति तीन प्रकार की होती है :

(अ) रयतवारी पद्धति—भू-धृति की यह पद्धति सर्वप्रथम मद्रास राज्य के बड़ा महल जिले में वर्ष 1872 में शुरू हुई थी, जो धीरे-धीरे दूसरे जिलों में भी प्रचलित हुई। इस पद्धति के अन्तर्गत, रयत (कृषक) सरकार से सीधे भूमि प्राप्त करते हैं। भूमि पर स्वामित्व सरकार का होता है। कृषकों को भूमि पर मौजूसी अधिकार (Occupancy Rights) प्राप्त होते हैं, जिसके अनुसार उन्हें भूमि को कृषित करने, भूमि को बटाई पर देने, विन्य करने एवं इनाम में देने की छूट होती है। कृषकों को भूमि के स्थायी अधिकार प्राप्त होते हैं, जिससे जब तक वे सरकार को लगान देते रहते हैं सरकार उन्हें भूमि से वेदखल नहीं कर सकती है। आसामियों को भूमि पर स्वामित्व के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। रयतवारी पद्धति में कृषकों की भूमि को आसामियों को उप पट्टेधारी (Sub-letting) पर देने की स्वतन्त्रता होने के कारण भूमि छोटे-छोटे खण्डों में विभक्त हो जाती है तथा कृषक व सरकार के मध्य सीधे सम्बन्धों से जो लाभ प्राप्त होते हैं वे नहीं मिलते हैं। आसामी कृषक भूमि-सुधार एवं उत्पादन वृद्धि के स्थायी साधनों के विकास कार्यक्रमों में पूर्ण निवेश नहीं करते हैं जिससे उत्पादन कम प्राप्त होता है।

(ब) महलवारी पद्धति—महलवारी पद्धति सर्वप्रथम आगरा व अवध प्रान्त में वर्ष 1883 में प्रचलित हुई थी, जो बाद में पंजाब राज्य में भी प्रचलित हुई। भू-धृति की इस पद्धति में भूमि का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के पास न होकर पूरे ग्राम-समूह को प्राप्त होता था। भूमि का राजस्व सरकार को जमा कराने की जिम्मेवारी ग्राम के सभी कृषकों की सामूहिक रूप से होती थी।

(स) जमींदारी एवं जागीरदारी पद्धति—इस पद्धति में जमींदार एवं जागीरदार मध्यस्थों के रूप में काम करते हैं। जमींदार एवं जागीरदार कृषकों से भूमि का लगान वसूल करके प्राप्त लगान राशि में से एक भाग सरकार को जमा कराते थे और शेष राशि से वे अपना जीवन-निर्वाह करते थे। इस पद्धति में भूमि पर स्वामित्व कृषकों का न होकर, जमींदार अथवा जागीरदार का होता था। जमींदारी एवं जागीरदारी प्रथा देश में 18वीं शताब्दी के अन्त एवं 19वीं शताब्दी के आरम्भ में विकसित हुई थी। जमींदार अथवा जागीरदार क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति होते थे। देश में जागीरदारी एवं जमींदारी प्रथा का प्रचलन ब्रिटिश सरकार के काल में हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने देश में कृषकों की भू-राजस्व राशि के

निर्धारण, वसूली एवं इसके सशोधन में होने वाली कठिनाई से मुक्ति पाने के लिए इस प्रथा को चुना था।

जमींदार प्रथा उत्तरप्रदेश एवं बंगाल राज्य में प्रचलित थी। इसके अन्तर्गत भूमि पर स्वामित्व का अधिकार सरकार ऐसे व्यक्तियों को देती थी, जो स्वयं काशतकार नहीं होते थे, पर जो काशतकारों पर अपना प्रभाव रखते थे। जागीरदारी प्रथा राजस्थान, मध्यप्रदेश एवं हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश) राज्यों में मुख्यतया प्रचलित थी। इस प्रथा के अन्तर्गत भूमि का प्रबन्ध बड़े राजा-महाराजाओं द्वारा घरबारी एवं कुलीन पुरुषों (Noblemen) को उनकी सैनिक अथवा प्रशासनिक सेवाओं के लिए दे दिया जाता था, जिन्हें जागीरदार कहते थे। ये जागीरदार भूमि के स्वामी नहीं होते थे, बल्कि प्रशासन का कार्य करते थे। ये कृषकों से लगान वसूल करते थे। कुछ जागीरदार स्वयं अथवा काशतकारों की सहायता से भूमि पर कृषि भी करते थे। कुछ राज्यों में जागीरदारी एवं जमींदारी प्रथा के प्रतिरिक्त अन्य प्रकार की भू-धृति पद्धतियाँ भी प्रचलित थीं जैसे बिस्वेदारी प्रथा, मालगुजारी प्रथा, इनामदारी एवं माफीदारी प्रथा आदि।

II कृषि सम्बन्धी अधिकारों के अनुसार देश में जमींदार/बड़े कृषक भूमि को स्वयं कृषित नहीं करके आसामियों को कृषि करवाने के लिए बटाई पर दे देते थे। आसामी भूमि पर कृषि करते थे और भू-स्वामियों को लगान देते थे। आसामियों के मौरूसी अधिकारों के अनुसार भू-धृति दो प्रकार की होती है :

(अ) मौरूसी काशतकार—इन काशतकारों की भूमि के मौरूसी/दखलकारी अधिकार वशागत प्राप्त होते हैं। आसामियों को भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। आसामियों द्वारा दिए जाने वाले लगान की राशि निश्चित होती है।

(ब) गैर-मौरूसी काशतकार—इसमें आसामियों को भूमि पर काशतकारी के अधिकारों की कोई निश्चितता नहीं होती है। जमींदार कृषक को भूमि से किसी भी समय बेदखल कर सकता है। इसमें भू-राजस्व की राशि निश्चित नहीं होती है। अतः प्रत्येक वर्ष जमींदार एवं आसामी में राजस्व राशि निश्चित की जाती है।

भू-धृति पद्धति की समाप्ति

उपर्युक्त सभी प्रकार की भू-धृति पद्धतियों में कृषकों से भू-राजस्व उपज के एक हिस्से के रूप में अधिक मात्रा में वसूल किया जाता था, जिससे कृषकों के पास बहुत कम उपज की मात्रा शेष रहती थी। खाद्यान्नों की यह शेष मात्रा उनके वर्ष भर खाने के लिए भी पूरी नहीं होती थी। अतः वे कृषि के विकास के लिए अधिक पूंजी का कृषि क्षेत्र में निवेश नहीं कर पाते थे। इस प्रकार भूमि के क्षेत्र से उत्पादन कम प्राप्त होता था। जमींदार एवं जागीरदार राजस्व के रूप में प्राप्त धन को कृषि क्षेत्र में निवेश न करके विलासी उपभोग एवं ऐश्वर्य-आराम पर खर्च करते थे।

कृषको को भूमि पर स्वामित्व प्राप्त न होने के कारण तथा भूमि पर कृषि करने के अधिकारों की अनिश्चितता की अवस्था में आसामी कृषक (Tenant farmers) भूमि सुधार तथा कृषि विकास के लिए आवश्यक साधनों जैसे—कुओं का निर्माण भूमि को समतल करना, सिंचाई के लिए पक्की नालियाँ बनाना, खाद डालना आदि विकास कार्यों पर पूँजी निवेश नहीं करते थे, क्योंकि जमींदार/जागीरदार इन्हें किसी भी समय भूमि से बेदखल कर सकता था। इनके कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं कृषि में दक्षता नहीं आ सकी। कृषको को अधिक प्राप्त होने से देश आर्थिक समृद्धि के क्षेत्र में अग्रसर नहीं हो पाता है। भू-धृति पद्धति समाज के विभिन्न समूहों—जमींदार, कृषक, कृषि श्रमिक एवं आसामी कृषक-कारो के बीच विषमता को जन्म देती है। भूमि समाज में प्रतिष्ठा की सूचकांक है। उन व्यक्तियों की समाज में प्रतिष्ठा अधिक जाती है जिन्हें भू-स्वामित्व के अधिकार प्राप्त होते हैं। अतः स्वतन्त्र भारत में भू-धृति प्रथाओं की समाप्ति की आवश्यकता प्रतीत हुई।

भू-धृति में व्याप्त मध्यस्थों की समाप्ति के लिए विभिन्न राज्यों में प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व से ही कदम उठाने शुरू कर दिए गये थे, लेकिन निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति वर्ष 1951 के उपरान्त ही हो पाई। मध्यस्थों की समाप्ति के लिए सर्वप्रथम प्रयास उत्तरप्रदेश राज्य में किए गए और उसके बाद दूसरे राज्यों में किए गए। भारत के सभी राज्यों में कानून पारित करके मध्यस्थों की समाप्ति वर्ष 1950 से 1960 के दशक में पूर्ण हो पाई। चूँकि भूमि-सुधार क्रियान्वित करने का दायित्व राज्य सरकारों पर है, अतः विभिन्न राज्यों में पृथक् कानून पारित किए गए, जिससे उनमें भिन्नता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। भूमि के जोतने वाले तथा सरकार के मध्य व्याप्त मध्यस्थों का उन्मूलन करने से 20 मिलियन कृषको का सरकार से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया है।

जमींदारी तथा जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन की प्रमुख विशेषताएँ निम्नांकित हैं—

- (i) सरकार ने जमींदारों एवं जागीरदारों से भूमि का स्वामित्व-अधिकार मुआवजे की राशि का भुगतान करके क्रय कर लिया।
- (ii) जागीरदारों एवं जमींदारों को खुदकास्त के लिए निर्धारित सीमा तक भूमि रखने की छूट दी गई।
- (iii) मध्यस्थों की समाप्ति से आसामी कृषको को भू-राजस्व सरकार को सीधे रूप में जमा कराना होता है।
- (iv) जमींदारी एवं जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन से कृषको का शोषण समाप्त हो गया। अब कृषको को भू-राजस्व उत्पादन के आगे भाग

के स्थान पर एक निश्चित भू-राजस्व राशि ही सरकार को जमा करानी होती है। कृषको से ली जाने वाली बेगार प्रथा (Forced labour system) भी समाप्त हो गई है।

मध्यस्थों की समाप्ति के लिए भूमि-सुधार एवं जागीर उन्मूलन कानून, 1951 महत्वपूर्ण है। इस कानून की प्रमुख विशेषताएँ निम्नांकित हैं—

- (i) कृषको से लिये जाने वाले लगान (उत्पाद के एक हिस्से के रूप में) की दर में कमी करना। यह दर सर्वप्रथम एक-तिहाई से एक-चौथाई तथा अप्रैल, 1952 से 1/6 कर दी गई।
- (ii) पांच हजार रुपये वार्षिक से अधिक आय प्राप्त होने वाली सभी जोतों का पुनर्गठन करना।
- (iii) भूमि की पट्टेदारी एवं उप पट्टेदारी प्रथा पर रोक लगाना।
- (iv) जागीरदारों द्वारा खुदकाश के लिए रखी गई भूमि के लिए उन्हें काशतकार मानना।
- (v) जागीरदारों एवं जमींदारों से प्राप्त भूमि के लिए सरकार द्वारा भूमि से प्राप्त शुद्ध आय का दस गुना मुआवजे के रूप में समान किशतों में 15 वर्ष में मुग्तान करना।

राजस्थान में जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन

राजस्थान राज्य में जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन वर्ष 1952 में प्रारम्भ हुआ, लेकिन जागीरदारों द्वारा कानून के विरुद्ध कोर्ट में जाने एवं राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण वास्तविक उन्मूलन कुछ देर से हुआ। राजस्थान में मध्यस्थों की समाप्ति के लिए निम्न कानून पारित किए गए—

- (i) राजस्थान भूमि-सुधार एवं जागीर पुनर्गठन कानून, 1952—इसका मुख्य उद्देश्य जागीरदारों के अधिकार समाप्त करना था। राज्य में जागीर उन्मूलन कार्य 1954 में प्रारम्भ हुआ।
- (ii) राजस्थान जमींदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959—इसके तहत जमींदारी एवं बिस्वेदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया।
- (iii) धार्मिक कार्यों के लिए दी गई जागीर का उन्मूलन वर्ष 1959 से 1963 के मध्य किया गया।

2. काशतकारी सुधार अधिनियम

काशतकारी सुधार कानूनों का मुख्य उद्देश्य कृषको को अग्र तीन प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराना है जिन्हें काशतकारी सुधार के तीन 'एफ' (3 F's of Tenancy Reforms) भी कहते हैं—

- (i) कृषकों के भूमि पर अधिकार (भू-धारण) की निश्चिता (Fixity of Tenure) ।
- (ii) कृषकों के लिए भूमि का उचित लगान नियत करना (Fair Rent) ।
- (iii) कृषकों को भूमि के विनय, बन्धक अर्थात् भू-स्वामित्व के अन्तरण की स्वतन्त्रता होना (Free Transferability of Land) ।

काश्तकारी सुधार के लिए विभिन्न राज्यों में वर्ष 1948 से 1955 की अवधि में कानून पारित किए गए । जैसे—राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, बम्बई काश्तकारी तथा कृषि अधिनियम 1948, बिहार भूमि-सुधार कानून 1950, उत्तरप्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि-सुधार अधिनियम 1950, मध्यप्रदेश स्वामित्व अधिकार उन्मूलन (सम्पदा, महाल पराधीन भूमि) अधिनियम, 1950 आदि । विभिन्न राज्यों में पारित काश्तकारी अधिनियमों के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे—

- (i) जमींदारों एवं जागीरदारों द्वारा स्वेच्छा से कृषकों की भूमि से बेदखल करने पर रोक लगाना ।
- (ii) भूमि के लगान की दर में कमी करना ।
- (iii) कृषकों को भूमि के मौरूसी अधिकार प्राप्त करना, जिससे कृषक के मरणोपरान्त भूमि उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त हो सके ।
- (iv) जमींदारों एवं जागीरदारों द्वारा कृषकों से लगान के अतिरिक्त ली जाने वाली विभिन्न प्रकार की लाग, जैसे—तजराणा, इलान, बेगार, सलामी आदि समाप्त करना ।
- (v) सरकार एवं कृषकों के बीच होने वाले मध्यस्थों को समाप्त करके भूमि जोतने वाले को दिलाना ।
- (vi) कृषकों को मौसम की प्रतिकूलता, जैसे—सूखा, अतिवृष्टि आदि के कारण उत्पादन कम प्राप्त होने की स्थिति में भू-राजस्व की राशि में छूट देना ।
- (vii) भूमि पर स्थायी सुधार करने के लिए कृषकों को ऋण अथवा अनुदान स्वीकृत करना, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सके ।

सभी राज्यों में काश्तकारी सुधार अधिनियमों के पारित हो जाने से कृषकों को अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं, जैसे—भू-राजस्व की राशि में कमी होना, काश्तकारों को भूमि पर कृषि करने के स्थायी अधिकार प्राप्त होना एवं भूमि से बेदखल किये जाने की अनिश्चितता का समाप्त होना । पारित काश्तकारी सुधार अधिनियमों में ऋणियों के कारण कृषकों को पूरा लाभ नहीं मिल रहा है । पारित काश्तकारी सुधार अधिनियमों में मुख्य कमियाँ निम्न हैं—

- (i) विभिन्न राज्यों में आसामी कृषकों की परिभाषा में भिन्नता है । सभी में कृषि करने वालों (Share croppers) को आसामी की परिभाषा

में सम्मिलित नहीं किये जाने के कारण अनेक राज्यों में भूमि-माफ़े-दारी पट्टे पर दी जाती है।

- (ii) पारित अधिनियमों में अनेक कारणों के आधार पर आसामी को भूमि से पृथक् करने की व्यवस्था है। जैसे—लगान का समय पर भुगतान न करना, भूमि को खण्डों में विभक्त करना, भूमि को उप-पट्टेदारी पर देना, भूमि पर स्वयं अथवा दस्तैता से वास्त नही करना, भूमि को परेन्नी छोड़ना अथवा गैर कृषि-कार्यों में उपयोग करना। जमींदार/जमीरदार इन व्यवस्थाओं का लाभ उठाकर आसामी को भूमि में पृथक् करने में सक्षम हो जाते हैं।

- (iii) जमींदार एवं जमीरदार कृषकों को अनेक उपाय अपनाकर परेशान करते हैं और यह लिखवाने में सफल हो जाते हैं कि वह भूमि स्वच्छा के छोड़ रहा है। ऐसी स्थिति में स्वच्छा में भूमि-पर अधिकार छोड़ने की व्यवस्था कानूनन समाप्त होनी चाहिये।

- (iv) जमींदार एवं जमीरदारों द्वारा आसामियों से स्वयं के कृषि करने के लिए भूमि-पुनर्ग्रहण कर लेना यह व्यवस्था भी समाप्त होनी चाहिये।

- (v) अनेक राज्यों में आसामियों से वसूल किये जाने वाले "उचित लगान" की परिभाषा का अधिनियम में नहीं होना और साथ ही कटाई पर कृषि करने वाले कृषकों से मनमाना राशि में राजस्व वसूल करना।

- (vi) आसामी कृषकों को भूमि पर अधिकार प्राप्त करने के लिए कानूनन परेशानी का होना। आसामी कृषक यह प्रमाण नहीं दे पाते हैं कि वे इस भूमि पर अनेक वर्षों से कृषि कर रहे हैं क्योंकि राजस्व विभाग के अधिकारी भू-स्वामी के नाम से ही रिकार्ड में इन्दाज कर रहे हैं।

- (vii) भूमि पर स्थायी अधिकार प्राप्त करने के लिए दी जाने वाली मुआवजे की राशि अधिक होना, जिसे कृषक जमा कराने में सक्षम नहीं होते हैं।

3.3. जोत-उपविभाजन एवं अपसंख्यन पर रोक

जोत उपविभाजन से तात्पर्य जोत के क्षेत्र को अनेक छोटे-छोटे खण्डों में विभक्त होने से है। जोत-उपविभाजन के कारण जात के खण्डों का क्षेत्र निरन्तर कम होता जाता है। भारत में जोतों के उपविभाजन का प्रमुख कारण वंशागत कानून का होना है। वंशागत कानून के होने से प्रत्येक उत्तराधिकारी पिता की

सम्पत्ति में समान हिस्सा चाहेंगे हैं। भूमि भी प्रत्येक उत्तराधिकारी में विभाजित होती है, जिससे बड़े खेत छोटे छोटे खण्डों अथवा खेतों में परिणत हो जाते हैं। जोत उपविभाजन के कारण देश में अनेक छोटे-छोटे आकार इतना कम हो गया है कि जोत पर कृषि कार्यों के लिए बैल चसाना भी सम्भव नहीं है। जोत अपखण्डन से तात्पर्य खेतों के विभिन्न खण्डों का विभिन्न स्थानों पर होना है। जोत-अपखण्डन के कारण प्रत्येक कृषक का भू-जोत का कुल क्षेत्र एक स्थान पर नहीं होकर अनेक स्थानों पर होता है। जोत-अपखण्डन का प्रमुख कारण प्रत्येक उत्तराधिकारी द्वारा पिता की भू-सम्पत्ति में समान हिस्सा चाहना है। जोत उपविभाजन ही जोत अपखण्डन का एक मुख्य कारण है।

उदाहरण—एक कृषक के पास 8 एकड़ एवं 6 एकड़ के क्रमशः दो खेत हैं जो एक दूसरे से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। कृषक के चार पुत्र हैं। भारत में वंशानुगत कानून के कारण कृषक की मृत्यु के उपरान्त भूमि चारों पुत्रों में समान रूप से विभाजित होती है। प्रत्येक पुत्र पिता के दोनों खेतों में समान हिस्सा चाहता है। अतः प्रत्येक खेत चार खण्डों में विभाजित होता है। इस प्रकार कृषक के दोनों खेत आठ खण्डों में विभक्त हो जाते हैं। प्रत्येक पुत्र को दोनों खेतों में से एक-एक खण्ड प्राप्त होता है। इस प्रकार भूमि के बँटवारे के साथ-साथ भूमि का छोटे-छोटे खण्डों में उपविभाजन एवं अपखण्डन होता है।

भारत में जोत का औसत आकार वर्तमान में कम होते हुए भी जोत-उप-विभाजन एवं अपखण्डन प्रवृत्ति के होने से खण्डों का आकार निरन्तर कम होता जा रहा है और जोत के खण्ड बिखरते जा रहे हैं। प्रत्येक कृषक के पास अनेक छोटे-छोटे खेत होते हैं जो एक दूसरे से दूरी पर स्थित होते हैं। देश में एक जोत में औसतन 5 टुकड़े पाये जाते हैं। जोत के अपखण्डों की संख्या बड़े कृषकों के पास लघु कृषकों की अपेक्षा अधिक होती है।

जोत के अनेक खण्डों में होने के कारण, कृषक सभी खेतों की पूर्ण व्यवस्था नहीं कर पाते हैं जिससे भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र से उत्पादन कम प्राप्त होता है। देश में कृषि उत्पादकों के कम होने का एक कारण भूमि का उपविभाजन एवं अपखण्डन होता है।

जोत-उपविभाजन एवं अपखण्डन के कारण

भारत में जोत उपविभाजन एवं अपखण्डन के मुख्य कारण निम्न हैं—

(1) देश की जनसंख्या में वृद्धि—जोत उपविभाजन का प्रथम कारण देश की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होना है। जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति कृषित भूमि की उपलब्ध मात्रा कम होती जा रही है। देश की जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ देश में शिक्षा का अभाव, परिवहन एवं संचार व्यवस्था की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों में कार्य के लिए उत्तर निष्क्रमण का अभाव आदि

के कारण भी कृषि पर आधारित जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है जो जोत के उप-विभाजन एवं अपखण्डन में सहायक होती है।

(2) देश में वशागत कानून का होना—देश में वशागत कानून के होने से प्रत्येक कृषक की भूमि उसके उत्तराधिकारियों में समान रूप से विभाजित होती है। अतः पीढ़ी-दर-पीढ़ी जोत का आकार कम होता जाता है एवं जोत के खण्डों की संख्या में वृद्धि होती जाती है।

(3) कृषकों का भूमि के प्रति लगाव—समाज में भूमि प्रतिष्ठा का सूचक होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति भूमि पर स्वामित्व चाहता है जिसके कारण भूमि की माँग अधिक होती है। भूमि की बढ़ती हुई माँग के कारण छोटे कृषक खराब वित्तीय स्थिति से विवश होकर भूमि विक्रय करते रहते हैं, जिसके कारण भी भूमि खण्डों में विभक्त होती रहती है।

(4) रोजगार उपलब्धि के लिए गांवों में कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों का प्रभाव होना—गांवों में व्यवसायों के प्रभाव में कृषक भूमि पर अधिक ध्यान देते हैं जिससे भूमि पर व्यक्तियों का भार बढ़ता है और भूमि खण्डों में विभक्त होती रहती है।

(5) भौगोलिक एवं मानव-निर्मित कारक—वर्षा के कारण खेतों के मध्य से नाले बनने सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में सड़कें, नहरें एवं नालियाँ बनाने से भी खेत खण्डों में विभक्त हो जाते हैं।

(6) संयुक्त परिवार प्रथा का विघटन—पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण वर्तमान में प्रचलित संयुक्त परिवार प्रथा के विघटन के कारण भी जोत का उप-विभाजन होता जा रहा है।

जोत-उपविभाजन एवं अपखण्डन से लाभ

जोत-उपविभाजन एवं अपखण्डन के प्रमुख लाभ निम्न हैं—

(1) देश में भूमिहीन श्रमिकों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है।

(2) जोत के छोटे छोटे खण्डों पर उत्पादन वृद्धि की सघन कृषि-पद्धति सरलता से अपनाई जा सकती है जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है।

(3) देश में उपलब्ध भूमि का क्षेत्र कुछ व्यक्तियों के पास न होकर समाज के सभी सदस्यों में वितरित होता है जिससे समाज दो विरोधी श्रेणियों—जमींदारों एवं भूमिहीन श्रमिकों से विभक्त नहीं होता है। समाज में आर्थिक विषमता उत्पन्न नहीं होती है।

(4) भूमि के विभिन्न खण्डों में होने से प्राकृतिक प्रकोपों—सूखा, पाला, बीमारी आदि से होने वाली हानि कम होती है।

जोत-उपविभाजन एवं अपखण्डन के दोष

जोत-उपविभाजन एवं अपखण्डन के दोष यह हैं—

(1) जोत-उपविभाजन एवं अपखण्डन के कारण प्रत्येक जोत पर मेड, रास्ते एवं सिचाई की नालियाँ बनाने के कारण फार्म पर उपलब्ध कृषित क्षेत्र कम हो जाता है।

(2) प्रत्येक छोटे-छोटे भूखण्ड पर स्थायी सुधार कार्य जैसे—कुआँ का निर्माण, पम्पिंग सैट लगाना आर्थिक दृष्टि से लाभकर नहीं होता है।

(3) प्रत्येक छोटे भूखण्ड पर यन्त्रोपकरण जैसे—ट्रैक्टर, रीपर, ब्रॉसर आदि का उपयोग आर्थिक दृष्टि से लाभकर नहीं होता है।

(4) जोत उप-विभाजन के कारण कृषकों में आपस में जोत की परिधीमा सम्बन्धी झगड़े होते रहते हैं, जिससे कृषकों का समय एवं धन काफ़ी व्यय होता है।

(5) जोत के खण्डों को दूर-दूर पर होने के कारण बंलो एवं श्रमिकों को एक खेत से दूसरे खेत पर ले जाने में समय अधिक खर्च होता है एवं लागत अधिक आती है।

(6) जोत के खण्डों के दूर-दूर पर होने से चोरी एवं अन्य नुकसान होने की संभावना अधिक होती है एवं चौकीदारी की लागत अधिक आती है।

(7) फार्म पर उपलब्ध मशीनों अधिक समय तक बेकार रहती हैं जिसके कारण उनकी कार्यकारी लागत अधिक आती है।

जोत-उपविभाजन एवं अपखण्डन रोकने के उपाय .

जोत-उपविभाजन एवं अपखण्डन को निम्न उपाय अपनाकर रोका जा सकता है :

1) लघु प्रसारित जोतों को आर्थिक जोतों में परिवर्तित करने के उपाय

इस विधि में ये उपाय सम्मिलित हैं जो कृषि की विधि में परिवर्तन करके प्रस्थायी रूप में जोत के आकार में वृद्धि करते हैं।

(अ) सहकारी संयुक्त कृषि पद्धति द्वारा—सहकारी संयुक्त कृषि से तात्पर्य कृषि को उस प्रणाली से है जिसके अन्तर्गत कृषक भूमि का प्रबन्ध सम्मिलित रूप से करते हैं। इनमें अनेक कृषक अपनी भूमि को एक इकाई के रूप में सम्मिलित करके खेती करते हैं। सहकारी संयुक्त कृषि द्वारा छोटी-छोटी जोतें एक बड़े फार्म के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे लघु कृषकों को भी बड़े कृषकों के समान लाभ प्राप्त होता है। इस विधि में प्रत्येक कृषक को अपनी भूमि पर स्वामित्व के अधिकार प्राप्त होते हैं।

(ब) सहकारी सामूहिक कृषि पद्धति द्वारा—इस विधि में सभी सदस्य-कृषकों की भूमि एवं उत्पादन-साधनों को सम्मिलित करके एक सामूहिक फार्म के रूप में कृषित किया जाता है। इस विधि में भूमि पर स्वामित्व व्यक्तिगत न होकर सामूहिक (प्रबन्ध-समिति का) होता है। फार्म की व्यवस्था प्रबन्ध-समिति करती है। इस विधि में भी लघु जोत कृषकों को पूर्व की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त होता है।

(II) भूमि के उपविभाजन एवं अपखण्डन पर रोक लगाने के उपाय

इस विधि में वे उपाय सम्मिलित हैं जो वर्तमान में जोत का आर्थिक आकार आने के पश्चात् होने वाले जोत के खण्डों पर रोक लगाते हैं। प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं—

(अ) प्रचलित अशासित कानून में परिवर्तन करना—इस कानून के अन्तर्गत प्रत्येक उत्तराधिकारी को भूमि में समान हिस्सा प्राप्त होता है। इस कानून को व्यवस्थाधिकार कानून में परिवर्तित करने से भूमि की सम्पूर्ण जोत बड़े पुत्र को प्राप्त होती है तथा अन्य उत्तराधिकारियों को भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त होता है। इस प्रकार भूमि के उपविभाजन एवं अपखण्डन पर रोक लगती है। बेल्जियम देश में प्रचलित कानून के अनुसार एक उत्तराधिकारी सभी उत्तराधिकारियों को धारण के बाँड पत्र देकर उनसे भूमि खरीद लेता है। भूमि का बँटवारा तो उत्तराधिकारियों में हो जाता है, लेकिन भूमि सभी उत्तराधिकारियों द्वारा पृथक् रूप में कृषि नहीं की जाकर एक उत्तराधिकारी को कृषि करने के लिए दे दी जाती है। इस प्रकार प्रचलित कानून में परिवर्तन करके भूमि के उपविभाजन एवं अपखण्डन पर रोक लगाई जा सकती है।

(ब) विभिन्न राज्यों में अधिक जोत की सीमा आधिकारिक पश्चात् भूमि के विभाजन पर कानूनन नियन्त्रण लगाया जाने चाहिए। इसके लिए अनेक राज्यों ने प्रयास किये हैं।

(स) लघु एवं सीमांत कृषकों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के कृषकों की भूमि के हस्तान्तरण पर कानूनन रोक लगाई जानी चाहिये, क्योंकि ग्रह वर्ग बन की आवश्यकता होने पर भूमि के छोटे छोटे खण्ड आवश्यकतानुसार विक्रय करते रहते हैं। साथ ही इनके द्वारा विक्रय करने की अवस्था में उस भूमि के खप में पड़ोसी कृषकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिससे भूमि का पृथक् खण्ड नहीं बनने पाये।

(III) जोत के वर्तमान आकार में वृद्धि करने वाले उपाय

जोत के वर्तमान आकार में चकबन्दी विधि द्वारा वृद्धि की जा सकती है। चकबन्दी के द्वारा कृषकों के विभिन्न स्थानों पर होने वाले अनेक भू खण्डों को एक स्थान पर एकत्र कर दिया जाता है जिससे जोत का आकार बढ़ जाता है।

जोत-चकबन्दी

जोत-चकबन्दी से तात्पर्य कृषकों की भूमि के छोटे-छोटे तथा बिखरे हुए खण्डों को एक स्थान पर एकीकृत खण्ड में परिवर्तित करने से है। अग्रवाल एवं

वासिल¹⁰ के अनुसार "जोत चकबन्दी का अर्थ कृषकों के खेतों का एकीकरण एवं पुनः विभाजन करने से है जिससे जोत के खण्डों की संख्या कम हो जाए।",

जोत-चकबन्दी के द्वारा कृषकों को उनके विभिन्न स्थानों पर होने वाले भूमि के खण्डों के बदले में एक स्थान पर सम्पूर्ण खण्डों के क्षेत्र के समतुल्य भूमि दी जाती है। कृषकों की भूमि एक स्थान पर होने से कृषक मशीन, ग्रीजार्, सिंचाई के साधनों का उपयोग सामर्थ्य तरीकों से करके उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। जोत-चकबन्दी के अन्तर्गत कृषकों को एक ही क्षेत्र में उनकी भूमि के समतुल्य मूल्य/उत्पादकता के आधार की भूमि का क्षेत्र देने की कोशिश की जाती है। जोत-चकबन्दी बिखरी हुई जोतों के कारण उत्पन्न समस्या का हल करती है, लेकिन यह लघु, सीमान्त एवं अर्थव्यवस्थात्मक जोतों की समस्या को हल नहीं करती है।

जोत चकबन्दी से लाभ— जोतों की चकबन्दी करने से, कृषकों को निम्न-लिखित लाभ प्राप्त होते हैं—

(1) जोत-चकबन्दी, कृषकों को सिंचाई की समस्या सुलझाने में सहायक होती है। चकबन्दी करने से, कृषक खेत पर कुआँ बनाकर अथवा नलकूप लगाकर पूरे फार्म में सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। भूमि के अलग-अलग खण्डों में होने से, प्रत्येक खेत पर कुआँ बनाकर आर्थिक दृष्टि से लाभकर नहीं होता है।

(2) जोत चकबन्दी द्वारा लघु एवं विखण्डित जोतों के आकार में वृद्धि करने से उन्नत कृषि मशीनों एवं मशीनों, जैसे—ट्रैक्टर, पावर टिलर, प्रेसर का उपयोग सुगम एवं आर्थिक दृष्टि से लाभकर होता है।

(3) जोत-चकबन्दी करने से कृषक फार्म पर उन्नत फसल-पत्र अपना सकते हैं जो-सघन कृषि के लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होता है।

(4) जोत-चकबन्दी से, छोटे-छोटे खण्डों की मोड़ों को जोड़ने से फार्म पर भूमि के क्षेत्र में वृद्धि होती है जिससे राज्य में कुल कृषि-योग्य भूमि के क्षेत्र में वृद्धि होती है।

(5) चकबन्दी से खेत की देखभाल में आसानी रहती है। पशुओं द्वारा फसल का नुकसान एवं चोरी की सम्भावना कम हो जाती है।

(6) चकबन्दी से फार्म पर कृषि-कार्यों का समय श्रम, पूरा करता सम्भव होता है जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है।

(7) चकबन्दी करने से श्रमिकों एवं बैलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर

¹⁰ Consolidation of holdings may be defined as the amalgamation and re distribution of fields constituting individual holding or estates so as to reduce the number of fragments in the holdings

ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है जिससे समय की बचत होती है एवं कार्य अधिक होता है।

(8) चकबन्दी से फार्म पर व्यावहारिक दक्षता में वृद्धि होती है।

जोत-चकबन्दी की विधि—किसी भी क्षेत्र में चकबन्दी का कार्य शुरू करने के पूर्व चकबन्दी अधिकारी ग्राम-सलाहकार समिति से विचार-विमर्श करके चकबन्दी की योजना तैयार करते हैं और चकबन्दी का प्रस्तावित नक्शा प्रकाशित करते हैं। चकबन्दी का नक्शा प्रकाशित करने के उपरान्त प्रभावित कृषक नियत समयावधि में चकबन्दी से होने वाली हानियों के लिए एतराज पेश कर सकते हैं। चकबन्दी, अधिकारी एवं अन्य अधिकारी प्राप्त एतराजों पर विचार-विमर्श करके चकबन्दी-योजना में आवश्यक परिवर्तन करते हैं और सशोचित योजना के अनुसार चकबन्दी को कार्यान्वित करते हैं।

चकबन्दी के अन्तर्गत अधिक उर्वरा-शक्ति वाली भूमि के बदले में कृषक को कम उर्वरा-शक्ति वाली भूमि के प्राप्त होने से होने वाली हानि की पूर्ति के लिए मुआवजे की राशि का नुगतान किया जाता है। मुआवजे की राशि विभिन्न श्रेणियों की भूमि के लिए स्थिर-निम्न होती है। चकबन्दी करते समय यह कोशिश की जाती है कि कृषक को जिस क्षेत्र में भूमि अधिक होती है, उसको उसी क्षेत्र में भूमि एक खण्ड में प्रदान की जावे।

जोत-चकबन्दी की प्रगति—जोत-चकबन्दी सर्वप्रथम भारत में वर्ष 1905 में स्वेच्छा के आधार पर देश के मध्यवर्ती प्रदेशों में शुरू हुई। यह वर्ष 1912 में पंजाब में, 1925-26 में उत्तरप्रदेश में एवं उसके बाद अनेक राज्यों में शुरू की गई, लेकिन जोत-चकबन्दी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि इसका आधार स्वेच्छिक था। स्वतन्त्रता के उपरान्त देश में स्वेच्छा से चकबन्दी के स्थान पर अनिवार्य चकबन्दी अपनाई गयी। विभिन्न पञ्चवर्षीय योजनाओं में जोत-चकबन्दी के महत्त्व को ध्यान में रखत हुए इसे प्राथमिकता के स्तर पर कार्यान्वित करने पर बल दिया गया है।

देश के सभी राज्यों (तमिलनाडु एवं केरल के अतिरिक्त) में जोत-चकबन्दी के लिए कानून पारित हो चुके हैं। उनमें से जोत-उपविभाजन एवं अपखण्डन निवारण अधिनियम वर्ष 1947 एवं पंजाब 1948 महत्त्वपूर्ण अधिनियम हैं। अन्य राज्यों में जोत-चकबन्दी कानून बाद में पारित किये गये। राजस्थान ने 1954, बिहार ने 1956, असम एवं कर्नाटक ने 1960, उत्तरप्रदेश एवं जम्मू-कश्मीर ने 1962 में जोत-चकबन्दी के लिये कानून पारित किये। भारत में विभिन्न पञ्चवर्षीय योजनाओं में जोत-चकबन्दी के अन्तर्गत साया गया क्षेत्रफल सारणी 4.3 में दर्शाया गया है।

सारणी 43

भारत में जोत-चकबन्दी के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्रफल

पञ्चवर्षीय योजना	चकबन्दी किया गया क्षेत्र (मिलियन हेक्टर)
प्रथम पञ्चवर्षीय योजना से पूर्व	(मार्च 1951) 1 209
प्रथम पञ्चवर्षीय योजना काल में	(1951-56) 3 220
द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना काल में	(1956-61) 7 510
तृतीय पञ्चवर्षीय योजना काल में	(1961-66) 12 150
तीन वार्षिक योजनाओं के काल में	(1966-69) 4 890
चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना काल में	(1969-74) 10 347
पञ्चम पञ्चवर्षीय योजना काल में	(1974-80) 6 874
छठी पञ्चवर्षीय योजना काल में	(1980-85) 5 600
सातवी पञ्चवर्षीय योजना काल में	(1985-90) 7 960
कुल चकबन्दी किया गया क्षेत्र	59 760

इस प्रकार सातवी पञ्चवर्षीय योजना तक 59 76 मिलियन हेक्टर भूमि क्षेत्र में चकबन्दी की जा चुकी है, जो देश की कुल कृषित भूमि का 33 प्रतिशत है। पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्यों में चकबन्दी का कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्य राज्यों में प्रगति की गति में बहुत भिन्नता है। अतः जोत चकबन्दी की प्रगति के आधार पर भारत के राज्यों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है—

- वे राज्य जहाँ तक प्रगति की रफ्तार बहुत अच्छी है और जो सम्पूर्ण क्षेत्र में चकबन्दी करने का मक्य रखते हैं, जैसे—पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश।
- वे राज्य जहाँ प्रगति की रफ्तार बहुत अच्छी है, लेकिन इनमें पूर्ण क्षेत्र में जोतो की चकबन्दी की आशा नहीं है, जैसे—महाराष्ट्र एवं हिमाचल प्रदेश।
- वे राज्य जहाँ जोत-चकबन्दी के लिए कुछ कार्य हुआ है, जैसे—मध्य-प्रदेश, राजस्थान, गुजरात व कर्नाटक।
- वे राज्य जहाँ जोत-चकबन्दी प्रयोगात्मक स्तर पर है, जैसे—बिहार, आन्ध्रप्रदेश व जम्मू एवं कश्मीर।

(v) वे राज्य जहाँ कानून के अंगे हुए भी जोत-चकवन्दी की प्रगति नगण्य है, जैसे-असम, उड़ीसा एवं पश्चिमी बंगाल ।

(vi) वे राज्य जहाँ जोत-चकवन्दी के लिए कानून नहीं बना है, जैसे-तमिल नाडु, केरल, पाण्डिचेरी एवं उत्तरी पूर्वी राज्य ।

जोत-चकवन्दी के कार्य में आने वाली कठिनाइयाँ—जोत चकवन्दी कृषकों के लिए लाभकर होने हुए भी इस क्षेत्र में हुई प्रगति मनोपजनक नहीं है । जोत-चकवन्दी के कार्य में आने वाली कठिनाइयाँ निम्न हैं—

(1) कृषकों का पैतृक भूमि से लगाव-कृषकों का पैतृक भूमि से लगाव होने के कारण वे अनिश्चित भूमि जो उपजाऊ अथवा खण्डों में विभक्त अथवा बजर ही पड़ी न हो, विनिमय करना नहीं चाहते हैं ।

(2) समान उर्वरता वाली भूमि उपलब्ध नहीं होना—चकवन्दी की प्रगति में दूसरा बाधक कारक भूमि के विनिमय के लिए समान उर्वरता वाली भूमि का क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होना है, जिसके कारण कृषक चकवन्दी के लिए इच्छुक नहीं होते हैं ।

(3) जोत-चकवन्दी के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव—दक्ष एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव भी चकवन्दी के विकास में बाधक होता है । दक्ष कर्मचारियों के अभाव में विभिन्न कृषकों की भूमि को चकवन्दी करते समय उन्हें पूर्ण न्याय नहीं मिल पाता है और झगड़े उत्पन्न होते रहते हैं ।

(4) भूमि के स्वामित्व के सही अनिलेख उपलब्ध नहीं होना—भूमि के स्वामित्व के सही एवं विश्वसनीय अनिलेख उपलब्ध नहीं होने से कृषकों में चकवन्दी करते समय स्वामित्व सम्बन्धी अनेक विवाद उत्पन्न हो जाते हैं जो चकवन्दी की प्रगति में बाधक बन जाते हैं ।

(5) जमींदारों, कृषकों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा चकवन्दी का विरोध करना एवं उनके द्वारा झूठे दावे प्रस्तुत करने से कार्य की प्रगति में रुकावट आती है ।

4. जोत की उच्चतम सीमा/नू-सीमा निर्धारण :

भूमि से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या जोत का क्षेत्रफल कृषकों के पास असमान माना में होना है । जोत के क्षेत्र में असमानता के कारण समाज के विभिन्न वर्गों में वैमनस्यता उत्पन्न होती है और साथ ही लघु जोतों पर दीर्घ जोतों की अपेक्षा उत्पादकता कम होती है । फलस्वरूप कृषकों की भूमि के क्षेत्र से उत्पादन कम प्राप्त होने के साथ-साथ देश को आर्थिक हानि भी होती है वर्ष 1980-81 की कृषि जनगणना के अनुसार भारत में 74.6 प्रतिशत जोतें दो हेक्टर से कम क्षेत्र की हैं किन्तु इनके अन्तर्गत कुल कृषित भूमि का 26.3 प्रतिशत क्षेत्र ही

समाया हुआ है। तीन प्रतिशत से कम जोतें ही 10 हेक्टर एव इससे अधिक क्षेत्र की हैं और इनके घनत्व 22.8 प्रतिशत भूमि है। भूमि के वितरण की यह असमानता एक और सामाजिक असन्तोष को जन्म देती है तो दूसरी ओर गलामकर जोतों के लिए भी उत्तरदायी है। अतः समाजवादी समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश में भूमि का समान बँटवारा करने की माग काफी प्रबल हो रही है। अतः देश में नू-सीमा का निर्धारण करना आवश्यक हो गया है।

भारत में जोत-केन्द्रीयकरण अनुपात (Holding-Concentration-Ratio) 0.62 है।¹¹ यह अनुपात भारत में जोतों के असमान वितरण का द्योतक है। जोतों के समान वितरण की अवस्था में यह अनुपात शून्य होता है।

जोत की उच्चतम सीमा/नू-सीमा से तात्पर्य एक व्यक्ति अथवा परिवार के लिए भूमि के नियत क्षेत्र पर स्वामित्व प्राप्त होने के उपरान्त अधिक भूमि रखने पर कानूनन नियन्त्रण से है। नू-सीमा एक कृषक परिवार के लिए भूमि का अधिकतम क्षेत्र नियत करती है। नू-सीमा, भूमि के पुनर्वितरण का एक तरीका है। एक कृषक के पास निर्धारित सीमा से अधिक भूमि के होने पर अतिरिक्त भूमि कृषक से लेकर लघु एव सीमान्त कृषकों, कृषि-श्रमिकों में निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार वितरित की जाती है, जिससे इस वर्ग के कृषकों एव कृषि-श्रमिकों की जोत को आर्थिक बनाया जा सके, देश में भूमिहीन-श्रमिकों की संख्या में कमी की जा सके एव कृषि-जोतों के क्षेत्र में व्याप्त असमानता समाप्त की जा सके। जोत की उच्चतम सीमा निर्धारित करने का उद्देश्य अनुकूलतम जोत के क्षेत्र वाले फार्मों का निर्माण करना है। इन जोतों पर प्रति इकाई भूमि के क्षेत्र से उत्पादन अधिक प्राप्त होता है, उत्पादन लागत कम आती है और शुद्ध लाभ की प्राप्ति अधिक होती है।

भूमि की उच्चतम सीमा के निर्धारण का प्रश्न भूमि की कमी से जुड़ा है। भूमि की सीमितता एव बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रत्येक व्यक्ति भूमि को प्राप्त करने की लालसा रखता है। इस लालसा को पूरा करने के लिए भूमि का पुनर्वितरण किया जाता है। यह पुनर्वितरण भूमि की उच्चतम सीमा नियत करने के बाद किया जाता है। बढ़ती हुई भूमि की लालसा को कम करने का दूसरा उपाय भूमि पर आश्रित जनसंख्या की कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों (उद्योगों, परिवहन आदि) में स्थानान्तरित करना है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा करने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है।

नू-सीमा निर्धारण के लाभ-नू-सीमा निर्धारण करने से अप्रलिखित लाभ प्राप्त होते हैं-

(1) भू-सीमा निर्धारण में जमीन के अनन्त विभिन्न व्यक्तियों के पास उपलब्ध भूमि के स्वामित्व में अध्याप्त समानता सम्पादित हो जाती है। राष्ट्र-समानवाद के तत्त्व का प्राप्ति के लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है।

(2) भू-सीमा के निवारण में प्राप्त अतिरिक्त भूमि को लघु एवं सीमान्त कृषकों में वितरित करके उनकी जमीन का आर्थिक बनावड़ा जा सकता है। भूमिहीन कृषि श्रमिका का अनिवार्य जमीन वितरित करके उनकी संख्या में कमी की जा सकती है।

(3) भू-सीमा के निवारण से बड़े कृषकों के यहाँ उत्पादन-साधनों के अभाव के कारण जो भूमि अछूटिनी अथवा पड़ी पड़ी रहती थी वह पड़ी नहीं रहती है। कृषक उपलब्ध मामूली भूमि का पूर्णतया इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। इससे जमीन में कुल कृषि उत्पादन एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है।

(4) भू-सीमा का नियामित करने से कृषक उपलब्ध भूमि पर सघन कृषि पद्धति अपनाते हैं, जिससे उन्हें लाभ अधिक प्राप्त होता है।

(5) भू-सीमा के नियामित करने से समाज में व्याप्त वैमनस्यता समाप्त होती है।

भू-सीमा निर्धारण के विपक्ष में तर्क—कुछ व्यक्तियों का मत है कि भू-सीमा के निवारण में कृषि उत्पादन में कमी होगी। उनकी यह धारणा है कि दीर्घ जोतों पर लघु जोतों की अपेक्षा प्रति इकाई भूमि के क्षयफल से अधिक उत्पादकता प्राप्त होती है। अतः अनुसंधानों के परिणामों से स्पष्ट है कि लघु जोता (अनाधिक जोता के अतिरिक्त) पर उत्पादकता का स्तर दीर्घ जोता की अपेक्षा अधिक होता है। एक सीमा के बाद जोता के आकार में वृद्धि होने से उत्पादकता कम होती जाती है। अतः जोत के क्षयफल पर उच्चतम सीमा का कानून लागू करने से उत्पादन कम नहीं प्राप्त होता है बल्कि लघु एवं सीमान्त अनाधिक जोता वाले कृषकों को अतिरिक्त भूमि प्राप्त होने से उनकी जमीन अधिक हो जाती है जोतों का क्षयफल अनुकूलतम हो जाता है और प्रति इकाई भूमि के क्षयफल में उत्पादकता में वृद्धि एवं कुल उत्पादन की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। अतः भू-सीमा के निर्धारण के विपक्ष में दिया जाना यह तर्क उचित नहीं है। यह तर्क मुख्यतया जमीनारों, जागीरदारों व उनके कृषकों के द्वारा दिया जाता है जिनकी भूमि भू-सीमा के अंतर्गत आती है और उनसे अतिरिक्त भूमि लेकर दूसरे कृषकों को दी जाती है।

भू-सीमा का निर्धारण—भू-सीमा निवारण का मुख्य आधार भूमि के उस क्षयफल के निर्धारण में है जिससे प्राप्त आय से कृषक परिवार उचित जीवन-स्तर एवं आवश्यक मूल्य मुविषा प्राप्त कर सकें। अतः भू-सीमा निर्धारण का स्तर समान नहीं होकर पृथक्-पृथक् होना है। जोत की उच्चतम सीमा के निर्धारण में भूमि की किस्म का प्रमुखतया ध्यान रखा जाता है। विभिन्न श्रेणियों की भूमि के लिए जोत की

उच्चतम सीमा विभिन्न होती है। भूमि की विभिन्न किस्मों के लिए जोत की उच्चतम सीमा इस प्रकार निर्धारित की जाती है कि सभी प्रकार की उच्चतम सीमा वाले क्षेत्रों में कृषकों को लगभग समान आय प्राप्त हो सके। समान आय का यह उद्देश्य ही विभिन्न प्रकार की भूमि के लिए भू-सीमा हेतु जोत का समतुल्य क्षेत्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। भू-क्षेत्र का उपयुक्त समतुल्य स्तर ज्ञात करने के उपरान्त आय के प्रश्न को ध्यान में नहीं रखा जाता है। अतः स्पष्ट है कि भू-सीमा भूमि के क्षेत्र पर होती है, न कि भूमि से प्राप्त आय पर। भूमि-सुधार पैनल की रिपोर्ट में भू-सीमा का क्षेत्र, आधिक जोत के क्षेत्र से तीन गुना रखने का सुझाव दिया है।—

भू-सीमा के लिए क्षेत्रफल का निर्धारण करते समय निम्न कारकों को ध्यान में रखना चाहिए—

- (i) भूमि की उर्वरा शक्ति,
- (ii) भूमि पर उपलब्ध सिंचाई की सुविधा एवं सिंचाई के साधन,
- (iii) भूमि पर उत्पन्न की जा सकने वाली फसलें,
- (iv) विभिन्न फसलों से प्रति हेक्टर प्राप्त सम्भावित लाभ,
- (v) भूमि के क्षेत्र पर मौसम की प्रतिक्रिया के कारण उत्पादन में कमी की प्रत्याक्षित सम्भावना,
- (vi) जनसंख्या का घनत्व।

भारत में भू-सीमा स्वतन्त्र भारत में भू-सीमा निर्धारण के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम सुझाव दिया गया था कि सभी राज्यों में एक परिवार अथवा व्यक्ति के लिये भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए। भूमि-सुधार-पैनल ने भी एक परिवार के लिए अधिकतम भू-सीमा निर्धारित करने की सिफारिश की तथा भू-सीमा से अधिक भूमि को उनसे लेकर भूमिहीन श्रमिकों तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों में वितरण करने का सुझाव दिया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी भू-सीमा के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जनवरी, 1959 में नागपुर अधिवेशन में निर्णय लिया कि वर्ष 1959 के अन्त तक भू-सीमा के लिए सभी राज्यों में कानून बन जाना चाहिए। फलस्वरूप देश में अनेक राज्यों ने भू-सीमा के निर्धारण के लिए वर्ष 1961 तक कानून पारित किए, लेकिन पारित कानूनों का अनेक कारणों से पूर्णतया पालन नहीं किया जा सका। भू-सीमा के लिए विभिन्न राज्यों में निर्धारित अधिकतम भूमि का क्षेत्रफल सारणी 4.4 में दिया गया है—

भारत के विभिन्न राज्यों में जल की उच्चतम सीमा

(क्षेत्रफल हैक्टर में)

राज्य	1960 से 1970 के काल में		1972 के उपरान्त संशोधित भू-सीमा प्रति परिवार			
	इकाई	भू-सीमा	सिंचित भूमि जिसमें दो फसलें प्रति वर्ष ली जा सकें	सिंचित भूमि जिसमें एक फसल प्रति वर्ष ली जा सके	शुष्क भूमि	
1. आन्ध्रप्रदेश	प्रति व्यक्ति	10 93-131 12	4 05-7 28	6 07-10 93	14 16-21 85	
2. असम	"	20 234	6 74	6 74	6 74	
3. बिहार	"	9.71-29 14	6 07-7 28	10 12	12 14-28 21	
4. गुजरात	प्रति परिवार	4 05-53 14	4 05-7 28	6 07-10 93	8.09-21.85	
5. हरियाणा	प्रति व्यक्ति	12 14-24 28	7 28	10 92	21 85	
6. हिमाचल प्रदेश	"	12 14	4 05	6 07	12 14-28 33	
7. जम्मू एवं कश्मीर	"	9 206	3 6 -5 06	—	5 95-9 20	
8. कर्नाटक	प्रति परिवार	10 926-87 435	4 05-8 10	10 12-12 14	21 85	
9. केरल	"	6 07-15 18	4 86-6 07	4 86-6 07	4 86-6 07	
10. मध्यप्रदेश	"	10 12	7 28	10 93	21 85	
11. महाराष्ट्र	"	7 284-50 995	7 28	10 93-14 57	21 85	
12. मणिपुर	"	—	5 0	5 0	6 0	

13 उद्योग	प्रति व्यक्ति	8 09-32 37	4 05	6 07	12 14-18 21
14 पञ्जाब	,	12 14-24 28	7 0	11 0	20 50
15 राजस्थान	प्रति परिवार	8 90-135 97	7 28	10 93	21 85-70 82
16 तमिलनाडू	"	12 14-48 56	4 86	12 14	24 28
17 सिक्किम	—	—	5 06	—	20 23
18 त्रिपुरा	—	—	4 0	4 0	12 00
19 उत्तरप्रदेश	प्रति व्यक्ति	16 19-32 37	7 30	10 95	18 25
20 पश्चिमी बंगाल	"	10 12	5 0	—	7 0

- Note (1) The actual ceiling limits for land having two crops and one crop respectively irrigated in Karnataka and Uttar Pradesh are marginally higher due to classification of land
- (2) The actual ceiling limits in respect of dry land in Himachal Pradesh and Rajasthan are higher due to hilly terrain and being desert respectively
- (3) The ceiling limit suggested in National guidelines of 1972 is 4 05 to 7 28 ha for irrigated land with two crops, 10 93 ha for irrigated land with one crop and 21 85 ha. for dry land

Source Agricultural Statistics at a Glance, February, 1990, Ministry of Agriculture, Government of India, New Delhi

पारित भू-सीमा कानूनो में अनेक कमियों के होने तथा राजनैतिक दलों का सहयोग प्राप्त नहीं होने के कारण भू सीमा से उपलब्ध होने वाले क्षेत्रफल की प्राप्ति में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। इस काल में पारित कानूनों में प्रमुख कामयाँ निम्न थी—

(1) अनेक राज्यों में भू-सीमा क्षेत्र में विस्तृत परिसीमा का होना (Wide Range of Ceiling Limit)—अनेक राज्यों में निर्धारित भू-सीमा में विस्तृत परिसीमा के होने से भू-सीमा कानून के होते हुए भी सरकार को अधिशेष भूमि अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं हो सकी। जैसे—आन्ध्रप्रदेश में भू-सीमा 10 93 से 131 12 हैक्टर, राजस्थान में 8 90 से 135 97 हैक्टर, गुजरात में 4 05 से 53 14 हैक्टर, कर्नाटक में 10 926 से 87 435 हैक्टर, पंजाब एवं हरियाणा में 12 14 से 24 28 हैक्टर एवं महाराष्ट्र में 7 284 से 50 995 हैक्टर प्रति व्यक्ति/परिवार थी।

(2) अनेक राज्यों में भू-सीमा का क्षेत्रफल परिवार के आधार पर न होकर प्रति व्यक्ति के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसके कारण अधिकांश कृषक भू-सीमा कानून से मुक्त हो गये। आन्ध्रप्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा व पंजाब राज्यों में भू-सीमा प्रति व्यक्ति नियत की गई है।

(3) भू-सीमा कानून ने विभिन्न राज्यों में अनेक प्रकार के फार्मों को छूट दी है, जैसे—चीनी मिल मालिकों के बन्ने के फार्म, पशु प्रजनन फार्म, फलों के एकीकृत बाग, चाय, काफी, रबर के बागान, चारागाह भूमि, सहकारी फार्म, वृक्ष उत्पादन फार्म, यान्त्रिक फार्म, धार्मिक फार्म एवं ऐसे फार्म जो फार्म उत्पादन दक्षता से कर रहे हैं। इन श्रेणियों के फार्मों पर भू-सीमा लागू नहीं होती है। विविध प्रकार की छूटों के होने से कृषक इनका भूठा सहारा लेकर भू-सीमा कानून से बच जाते हैं।

(4) भू-सीमा कानून के अन्तर्गत प्राप्त अतिरिक्त भूमि के मुआवजे का भुगतान कृषकों को बाजार मूल्य के अनुसार नहीं करने के कारण भी कृषक अपनी अधिशेष भूमि को छोड़ना नहीं चाहते हैं।

(5) भू-सीमा कानून के पारित करने एवं उसके कार्यान्वित करने के समय में बहुत अन्तराल रहा है, जिससे कृषक इस काल में अपनी अतिरिक्त भूमि को दूसरे कृषकों को विक्रय करके अथवा अपने सम्बन्धियों के नाम करके अथवा घर के सदस्यों को शामिल करके सहकारी समिति बनाकर कानून से बचने में सफल हुए हैं।

(6) भू-सीमा केवल स्वामित्व वाली भूमि पर लागू की गई, लेकिन कृषक

अन्य कृषकों से भूमि बँटाई पर लेकर कृषित क्षेत्र भू-सीमा क्षेत्र से अधिक रखने में समर्थ होते हैं। कृषित क्षेत्र पर भू-सीमा कानून लागू नहीं होता है।

अतः भू-सीमा कानून में व्याप्त उपर्युक्त कमियों को दूर करने एवं जोत की सशोधित भू-सीमा निर्धारण करने के लिये सरकार ने तत्कालीन कृषि मन्त्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद की अध्यक्षता में वर्ष 1971 में केन्द्रीय भूमि-सुधार समिति नियुक्त की थी। समिति ने भू-सीमा के लिए क्षेत्र का निर्धारण उस स्तर पर करने की सिफारिश की जो भू-क्षेत्र कृषकों के एक जोड़ी बैल को वर्ष भर पूर्णरूप से कार्यरत रख सके, परिवार के सदस्यों को पूर्ण रोजगार उपलब्ध करा सके तथा परिवार के सदस्यों के लिये उचित जीवन-स्तर की प्राप्ति के लिये पर्याप्त आय प्रदान कर सके। समिति ने उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुये एक परिवार के लिये 10 से 18 एकड़ सिंचित भूमि का क्षेत्र भू-सीमा में रखने का सुझाव दिया था। समिति का मानना था कि इस भूमि के क्षेत्र से वर्ष 1970-71 की कीमतों के स्तर पर 15,000 रु० वार्षिक आय प्राप्त हो सकती है, जो एक औसत परिवार के लिये उचित जीवन-स्तर प्राप्त करने के लिये पर्याप्त है। अन्य किस्म की भूमि के लिये भू-सीमा 18 से 54 एकड़ पर रखने की सिफारिश की गई थी। परिवार में औसत से अधिक सदस्यों के होने पर अधिकतम सीमा के क्षेत्र में छूट दी गई। समिति ने यह भी सिफारिश की कि वर्तमान में भू-सीमा में दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की छूटों की सख्याओं में कमी की जाये।

केन्द्रीय भूमि-सुधार समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् सभी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ने जुलाई, 1972 की बैठक में भू-सीमा के लिये राष्ट्रीय नीति अपनाने पर सहमति प्रकट की और कृषि की स्थिति एवं जलवायु की विभिन्नता के अनुसार एक औसत परिवार के लिये भू-सीमा निम्न प्रकार से रखने का निर्णय लिया—

(1) उन क्षेत्रों में जहाँ वर्ष भर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है तथा उस भूमि से वर्ष में दो फसलें ली जा सकती हैं, वहाँ भू-सीमा 4.05 से 7.28 हेक्टर; जहाँ एक ही फसल उत्पन्न की जा सकती है वहाँ 10.93 हेक्टर एवं अन्य किस्म की भूमि के लिये 21.85 हेक्टर रखने के लिये सहमति प्रकट की।

(2) परिवार में औसत से अधिक सदस्यों के होने पर अतिरिक्त भूमि का क्षेत्र रखने का प्रावधान किया गया है, लेकिन किसी भी परिवार के लिये अधिकतम भूमि का क्षेत्रफल, भू-सीमा के लिये निर्धारित क्षेत्रफल से दुगने से अधिक नहीं होगा।

विभिन्न राज्यों में वर्ष 1972 में पारित कानूनों के अनुसार सशोधित भू-सीमा का क्षेत्रफल सारणी 4.4 में प्रदर्शित किया गया है। भू-सीमा के निर्धारण में भूमि की किस्म, भूमि की उर्वरता तथा सिंचाई सुविधा को मद्देनजर रखना होता

है, जिसके कारण विभिन्न राज्यों के लिये भू-सीमा के अन्तर्गत एक निश्चित क्षेत्रफल नहीं होकर भूमि की एक परिसीमा दी गई है। भू-सीमा का उपर्युक्त क्षेत्रफल एक औसत परिवार के लिए है। परिवार में औसत से अधिक सदस्यों के होने पर अनिश्चित भूमि का क्षेत्रफल रखने का कानून में प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के 34वें विधेयक (जो 26 अगस्त, 1947 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था) के अनुसार विभिन्न राज्यों द्वारा भूमि के उचित वितरण सम्बन्धी कानूनों को बंध करार दिया गया एवं किसी भी राज्य द्वारा पारित भू-सीमा कानून को चुनौती देने के लिये अदालत में जाने पर पाबन्दी लगा दी गई है।

भू-सीमा की प्रगति—राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 16वें दौर (1960-61) के अनुसार 8 87 मिलियन हेक्टर, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 26वें दौर (1971-72) के अनुसार 4 80 मिलियन हेक्टर, कृषि जनगणना 1970-71 के अनुसार 12 10 मिलियन हेक्टर एवं कृषि जनगणना 1976-77 के अनुसार देश में 8 88 मिलियन हेक्टर भूमि का क्षेत्र अधिशेष होने का आकलन किया गया था।¹² लेकिन वास्तविक भूमि का क्षेत्र जो भू-सीमा लागू करने के पश्चात् उपलब्ध हुआ है वह अनुमानित क्षेत्र में बहुत कम है। दिसम्बर, 1987 तक मात्र 1 97 मिलियन हेक्टर क्षेत्र ही अधिशेष घोषित हो पाया है जो कुल कृषि क्षेत्र का दो प्रतिशत से भी कम है। सरकार इस सम्पूर्ण घोषित क्षेत्र में से 1 39 मिलियन हेक्टर क्षेत्र को ही अपने अधिकार में ले पाई, क्योंकि भूमि के स्वामित्व के अनेक भ्रमों अदालतों में निर्णय हेतु दर्ज है। इसमें से 0 97 मिलियन हेक्टर क्षेत्र भूमि का सीमान्त एवं लघु कृषकों, कृषि श्रमिकों एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को वितरित कर पाई है। अतः स्पष्ट है कि भू-सीमा लागू करने से प्राप्त परिणाम उद्देश्यों के परिपेक्ष्य में सन्तोषप्रद नहीं है।

5 सहकारी खेती एवं सहकारी ग्राम प्रबन्ध

सहकारी कृषि पद्धति के अन्तर्गत विभिन्न कृषकों द्वारा जोतों पर संयुक्त रूप से कृषि की जाती है जिसके कारण लघु कृषकों को प्रति इकाई भूमि के क्षेत्र से उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि बड़े कृषकों को भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होता है।

सहकारी ग्राम प्रबन्ध के अन्तर्गत पूरे ग्राम के विकास की योजना बनाई जाती है। इसके अन्तर्गत ग्राम की सम्पूर्ण भूमि को एक फार्म इकाई के रूप में मानकर कृषि योजना बनाना, सम्पूर्ण भूमि को इस प्रकार कृषि कार्यों के लिए संचालित करना ताकि ग्राम के पूर्ण समुदाय को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके तथा ग्राम के निवासियों को अधिकतम रोजगार भी उपलब्ध हो सके, आदि सम्मिलित होता है।

भूमि सुधार कार्यक्रमों की आलोचनात्मक समीक्षा

देश में भूमि सुधार के लिए स्वतन्त्रता के समय में ही प्रयास किये गए हैं जिसके कारण विभिन्न राज्य सरकारों ने मध्यस्थों की समाप्ति, कृषकों को भूमि पर स्थायी स्वामित्व दिलाने, भू-लगान की राशि कम करने, जोत की उच्चतम सीमा नियत करने, जोतों की चकबन्दी करने आदि कार्यों के लिए कानून पारित किये हैं। इन भूमि-सुधार कानूनों से प्राप्त लाभों के विषय में विशेषज्ञों में मतभेद हैं। भूमि-सुधार कार्यक्रमों की प्रगति भी विभिन्न राज्यों में समान नहीं है।

देश में भूमि-सुधार कार्यक्रमों के प्रभाव के अध्ययन पर अनेक विद्वानों के लेख प्रकाशित हुए हैं, जिनमें भूमि सुधारों के क्रिया-व्ययन सम्बन्धी दृष्टियों पर प्रकाश डाला गया है। भूमि सुधार कार्यक्रमों के दोषों पर वुल्फ लडी जिन्स्की¹³, कोटो-वस्की, राजकृष्ण, पी एस अप्पु¹⁴, पी. सी जोशी¹⁵, डेरी एच मीची¹⁶ और भूमि सुधार-पैनल की काश्तकार-समिति ने विशेष प्रकाश डाला है। उपर्युक्त विद्वानों का कथन है कि भूमि सुधार कार्यक्रमों का गरीब काश्तकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव भूमि-सुधार कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के कारण, बेदखल हुए काश्तकारों की संख्या की अधिकता से स्पष्ट है। देश में 1961 से 1971 की अवधि में कृषकों की संख्या 51 प्रतिशत से गिरकर 43 प्रतिशत हो गई जबकि कृषि श्रमिकों की संख्या बढ़कर 17 से 26 प्रतिशत हो गई। इसी अवधि में बड़े कृषकों की संख्या 23 मिलियन से बढ़कर 28 मिलियन हो गई। भूमि-सुधार कार्यक्रमों से मध्यस्थों को लाभ पहुँचा है, वे पहले से अधिक प्रभावशाली हो गए हैं। श्री पी एस अप्पु ने अपने कृषि भूमि सुधार प्रतिवेदन में भूमि-सुधार कार्यों से प्राप्त लाभ की व्यवस्था करते हुए लिखा है कि "Land Reform is Dead"। वुल्फ लेजिन्स्की ने अपने प्रतिवेदन में भूमि सुधार कार्यक्रमों की व्याख्या में वर्ष 1965 में कहा है कि, "भारत में कई अच्छे कृषि-सुधार कानून प्रारम्भ से ही मृत रहे हैं

- 13 (a) Wolf Ladejnsky: A study of Tenurial Conditions in Package Districts, Planning Commission, Government of India, New Delhi, 1955, p 41
- (b) do, The Green Revolution in Punjab Economic and Political Weekly, Vol IV No 26, 1969
- (c) do, Agrarian Reforms in Asia Foreign Affairs, April, 1964, p 456
- 14 P S Appu Report of Task Force on Agrarian Relations Economic and Political Weekly, Vol VIII, No 20, May 19, 1973, pp 854-95
- 15 P C Joshi Land Reforms in India and Pakistan, Economic and Political Weekly, Vol V, No 52, December 26, 1970
- 16, Barry H Michie, Variations in Economic Behaviour and the Green Revolution An Anthropological Perspective, Economic and Political Weekly, Vol VIII, No 26, 30 June, 1973, pp A 67-A, 75

(Many a good piece of agrarian reform legislation has arrived stillborn in India) " ।

विभिन्न विद्वानों द्वारा भूमि-सुधार कार्यक्रमों में व्याप्त दोषों का निम्न प्रकार से विवेचन किया गया है —

1 भूमि-सुधार अधिनियमों को पारित करने एवं उनके क्रियान्वयन में समय का बहुत अन्तर रहा है । भूमि-सुधार के लिए पारित अधिकांश अधिनियम विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा तुरन्त प्रभावशाली न किये जाकर बहुत समय उपरान्त लागू किये गये, जिसके कारण अनेक समृद्धिशाली कृषक एवं मध्यस्थ भूमि को इस काल में अपने परिवार के अन्य सदस्यों, रिश्तेदारों एवं मित्रों में वितरित करके कानून की सीमा में बचकर निकल गए । अतः पारित अधिनियमों में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई । भूमि-सुधार के क्षेत्र में कानून बनाने एवं उसे कार्यान्वित करने में जितना समयान्तर रहा है उतना अन्य किसी क्षेत्र में नहीं पाया गया ।

2 भूमि-सुधार कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार के द्वारा पूर्ण नियन्त्रण की आवश्यकता होती है, जिसका भी विभिन्न राज्य सरकारों के पास अभाव पाया गया है । अतः विभिन्न पारित अधिनियम पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं हो पाए, जिससे उनके उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी ।

3 देश के वर्तमान सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक ढाँचे में समृद्धिशाली व्यक्ति अपने प्रभाव के कारण अधिक लाभान्वित होते हैं । ऐसी स्थिति में गरीब कृषकों को भूमि सुधार कानूनों से विशेष लाभ प्राप्त होने की आशा नहीं है । कानून के निर्माण करने वाले, उन्हें कार्यान्वित करने वाले तथा अनेक स्थानों पर निष्ठाविक भी बड़े जमींदार एवं समृद्धिशाली व्यक्ति ही होते हैं ।

4 बहुत से राज्यों में भूमि-सुधार के लिए पारित अधिनियमों में अनेक कमियाँ रही हैं । उदाहरण के तौर पर व्यक्तिगत कृषि की भूमि से तात्पर्य यह होना चाहिए कि उस भूमि पर कृषि करने वाला व्यक्ति अथवा उसकी देख-रेख करने वाला व्यक्ति उसी भूमि के पास अथवा ग्राम में रहना चाहिए, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है । इसी प्रकार वर्तमान में भू-सीमा कानून स्वामित्व वाली भूमि पर तो लागू है, लेकिन बटाई पर लेकर भूमि के क्षेत्र में वृद्धि करने पर भू-सीमा कानून लागू नहीं है । अनेक राज्यों में अनुसूचित जाति/अनजाति के व्यक्तियों को अपनी भूमि को कृषित करने के लिए दूसरों को पट्टे पर देने की अनुमति है, जो अनेक दृष्टिकोणों से गलत है ।

5 वर्तमान में भूमि-सुधार कार्यक्रमों का नारा है कि 'भूमि काश्तकार की होनी चाहिए (Land of the tiller)' । लेकिन इसके स्थान पर यह होना चाहिए

कि भूमि का स्वामी वह होगा जो स्वयं उसके ऊपर विभिन्न कृषि कार्य जैसे हल चलाना, बुवाई करना, सिंचाई करना आदि कार्य करता है। इस परिवर्तन से देश में अनुपस्थित भू-स्वामी प्रथा समाप्त हो सकती है एवं भूमि वास्तविक कृषको के स्वामित्व में जा पाएगी। लेकिन देश के वर्तमान ढाँचे में ऐसा कानून बनाने एवं उसे कार्यान्वित करने की सम्भावना कम प्रतीत होती है।

6. भूमि-सुधार कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण भी कृषको को इनसे वांछित लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं। जो कार्यकर्त्ता भूमि-सुधार कार्यक्रमों को ईमानदारी से कार्यान्वित करना चाहते हैं, उन्हें सरकार अनेक प्रकार के दबाव के कारण अन्य स्थानों अथवा पदों पर स्थानान्तरित कर देती है जिसके कारण कार्यकर्त्ता कार्यक्रमों को पूर्ण-रूप से कार्यान्वित करने के प्रति उदासीन हो जाते हैं।

7. जोत चकबन्दी योजना को कार्यान्वित करने से अनेक काश्तकार एवं बटाईदार भूमि से वेदखल हो गए। चकबन्दी से पूर्व काश्तकारों के पास भूमि अनेक खण्डों में होने के कारण, वे अपने भू-खण्ड दूसरों को कृषित करने के लिए बटाई पर देते थे। वर्तमान में चकबन्दी के कारण उनकी जोत एक खण्ड में हो गई, जो वह स्वयं कृषित कर लेता है। इस प्रकार भू-सुधार योजना से अनेक काश्तकार वेदखल कर दिये गये।

8. बड़े एवं समृद्धिवासी कृषक, काश्तकारों को कृषि के लिये दी गई अपनी भूमि के सम्बन्ध में कोई लिखित अनुबन्ध नहीं करते हैं। जिसके कारण कृषक अपने अधिकार के लिये कोर्ट में नहीं जा पाते हैं। साथ ही गरीब काश्तकार घनाभाव के कारण अपना अधिकार साबित नहीं कर पाते हैं और उनका मानना है कि कोर्ट में विवाद का निर्णय बड़े जमींदार के पक्ष में होता है।

9. भूमिहीन श्रमिक, लघु एवं सीमान्त कृषक भूमि के पुनर्वितरण से प्राप्त भूमि को स्वयं कृषित नहीं करके उसे पट्टे पर दे देते हैं जिससे उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता नहीं मिलती है।

10. भूमि-सुधार के लिए पारित अधिनियमों को कृषक पूर्णतया समझ नहीं पाते। सरकार भू-स्वामी एवं काश्तकारों दोनों वर्गों को खुश करने की अपनी दोहरी नीति के कारण अस्पष्ट भाषा का प्रयोग करती है।

11. देश के कृषको को सरकार द्वारा भूमि-सुधार के लिए पारित अधिनियमों के विषय में जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था का अभाव होना भी इनका एक दोष है।

12 देश के कृषकों को अधिनियमों का ज्ञान होते हुए भी वे संगठन के अभाव में पारित अधिनियमों से पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। वे समझते हैं कि कानून से स्वतः ही उनकी रक्षा हो जायेगी।

श्री पी सी अण्णु की अध्यक्षता में नियुक्त भूमि-सुधारों के कार्यकारी दल (Task-Force on Agrarian Relations) ने भूमि-सुधार के व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए निम्न सुझाव दिये थे—

1. भूमि सुधार कानूनों में व्याप्त कमियों को दूर करना।

2. भू-सीमा के निर्धारण के लिए नया कानून बनाना एवं भू-सीमा निर्धारण से प्राप्त भूमि को भूमिहीन श्रमिकों में वितरित करना।

3. भूमि-सुधार कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए एक पृथक् प्रशासन-व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। इस प्रशासन को अधिनियमों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के कानूनी अधिकार प्राप्त होने चाहिए।

4. भूमि-सुधार कार्यक्रमों को पूर्णरूप से कार्यान्वित करने एवं राजनैतिक प्रभावों को समाप्त करने के लिये कृषकों में राजनीति का रंग चढ़ाना (politicalisation) चाहिए। कृषकों में यह राजनैतिक भावना विस्तृत पैमाने पर जाग्रत करना आवश्यक है।

धन

उत्पादन का दूसरा प्रमुख कारक धन है। धन से तात्पर्य शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार के धन से है जो धन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जे० बी० क्लार्क¹⁷ के शब्दों में “धन का मूलन करने वाला मानवी प्रयास धन कहलाता है।” जेवन्स के अनुसार “धन भस्तिष्क अथवा शरीर की वह चेष्टा है जो पूर्णतया या अंशतः कार्यजन्य सुख के अतिरिक्त किसी अधिक उद्देश्य से किया जाता है।” धन कारक की पूर्ति करने वाला मनुष्य धमिक कहलाता है। कृषि व्यवसाय में कार्य करने वाले श्रमिकों को कृषि धमिक कहते हैं।

कृषि धमिक—कृषि श्रमिकों की परिभाषा में बहुत विभिन्नता है। साधारण शब्दों में कृषि धमिकों से तात्पर्य उन श्रमिकों से है जो अपना धन कृषि फार्म पर कार्यों के बदले नकद या वस्तु के रूप में मजदूरी प्राप्त करके विक्रय करते हैं। जन-गणना आयोग एवं कृषि धन-जाँच समितियों ने कृषि धमिकों को विभिन्न-विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है।

प्रथम कृषि धन-जाँच समिति 1950-51 के अनुसार वे धमिक, जो वर्ष में कुल कार्यरत अवधि के आधे से अधिक समय कृषि-व्यवसाय (फसल उत्पादन

मात्र) में श्रम करके रोजगार प्राप्त करते हैं, कृषि श्रमिक कहलाते हैं। इसके अन्तर्गत कृषि से सम्बन्धित अन्य व्यवसाय, जैसे—पशु-पालन, दूध उद्योग, कुक्कुट-पालन बागवानी आदि में किया गया श्रम सम्मिलित नहीं किया गया है। उदाहरणतः, जैसे एक श्रमिक को वर्ष में 240 दिन रोजगार उपलब्ध होता है, उसमें से यदि उस श्रमिक को 120 दिन या इससे अधिक दिन कृषि व्यवसाय में कार्य करने से रोजगार प्राप्त होता है तो वह कृषि श्रमिक कहलाता है।

द्वितीय कृषि-श्रम-जाँच-समिति, 1956-57 के अनुसार वे श्रमिक, जो वर्ष में कुल कार्यरत अवधि के आधे से अधिक समय कृषि व्यवसाय, जैसे—फसल-उत्पादन, पशु पालन, दूध उद्योग, बागवानी, कुक्कुट पालन में कार्य करके रोजगार प्राप्त करते हैं, कृषि श्रमिक कहलाते हैं। द्वितीय कृषि-श्रमिक जाँच-समिति में फसल उत्पादन के अतिरिक्त अन्य कृषि कार्य, जैसे—पशु-पालन दूध उद्योग, बागवानी, कुक्कुट पालन में कार्य करने वाले श्रमिकों को भी कृषि श्रमिकों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।

जनगणना आयोग, 1961 के अनुसार “कृषि श्रमिक वे हैं जो दूसरों के फार्म पर कार्य करते हैं और कार्य के लिये नकद या वस्तु के रूप में मजदूरी प्राप्त करते हैं। श्रमिकों को फार्म पर उत्पादन प्रबन्ध, संचालन आदि के निर्णय लेने के अधिकार नहीं होते हैं और न ही उन्हें उस भूमि को जिस पर वे कार्य करते हैं, बन्धक रखने, विन्यस करने या पट्टे पर देने का अधिकार होता है। श्रमिक भूमि से प्राप्त लाभ अथवा हानि के लिए भी जिम्मेदार नहीं होते हैं। श्रमिकों को कृषि श्रमिकों की श्रेणी में आने के लिए उस मौसम या पिछले मौसम में कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करना आवश्यक होता है।”

कृषि श्रमिक परिवार—प्रथम कृषि-श्रम जाँच समिति, 1950-51 के अनुसार कृषि श्रमिक परिवार से तात्पर्य उस श्रमिक परिवार से है जिसमें परिवार का मुखिया अथवा परिवार के अधिकांश सदस्य वर्ष में कुल उपलब्ध श्रम दिवसों के 50 प्रतिशत या अधिक दिवस तक कृषि श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं। द्वितीय कृषि-श्रम जाँच समिति ने कृषि श्रमिक परिवार को परिभाषित करने में कार्य-दिवस को आधार न मानकर परिवार को प्राप्त होने वाली आय को आधार माना है। अतः वे श्रमिक परिवार जिनमें परिवार की कुल आय का आधा या आधे से अधिक भाग कृषि क्षेत्र में मजदूरी करने से प्राप्त होता है, कृषि श्रमिक परिवार कहलाते हैं।

कृषि श्रमिकों की विशेषताएँ—कृषि श्रमिकों की कुछ विशेषताओं के कारण वे औद्योगिक व्यवसायों में कार्यरत श्रमिकों से भिन्न होते हैं। कृषि श्रमिकों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. कृषि श्रमिक एक स्थान पर न होकर विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए होते हैं अर्थात् वे संगठित नहीं होते हैं जबकि औद्योगिक श्रमिक संगठित होते हैं।

2 कृषि श्रमिक प्रमुखतया बदक्ष श्रेणी के होते हैं जबकि अन्य व्यवसायों में कार्य करने वाले श्रमिक अपने कार्य में दक्ष हात हैं।

3 कृषि श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान मुद्रा एवं वस्तु (खाद्यान्न, तम्बाकू, नाशता आदि) दोनों ही रूप में किया जाता है, जबकि औद्योगिक श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान सिर्फ मुद्रा में किया जाता है।

4 कृषि श्रमिक कार्य उपलब्ध होने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, प्रवासन अस्थायी रूप से करते हैं, जबकि औद्योगिक श्रमिक स्थायी प्रवासन करते हैं।

5 कृषि श्रमिक फार्म पर कृषकों एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कार्य करते हैं। कृषि क्षेत्र में श्रमिकों को कार्य की अवधि में परिवार के सदस्यों के रूप में माना जाता है जबकि औद्योगिक श्रमिकों एवं उनके स्वामियों में इस प्रकार के सम्बन्ध नहीं होते हैं।

6 कृषि श्रमिकों की मजदूरी की दर कम होती है तथा प्राप्त रोजगार नियमित नहीं होता है जिसके कारण कृषि श्रमिकों को प्राप्त वार्षिक आय औद्योगिक श्रमिकों की अपेक्षा कम होती है।

भारत में कृषि श्रमिक—सारणी 4.5 भारत में कृषि श्रमिकों की संख्या एवं उनका कुल कार्यरत व्यक्तियों में प्रतिशत प्रदर्शित करती है।

सारणी 4.5

भारत में कृषि श्रमिकों की संख्या

(मिलियन में)

वर्ष	कृषि श्रमिक	कृषक	अन्य श्रमिक	कुल कार्यरत व्यक्ति	कृषि व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत
जनगणना 1951	27.5 (19.7)	69.8 (50.0)	42.2 (30.3)	139.5 (100)	28.26
जनगणना 1961	31.5 (16.7)	99.6 (52.8)	57.6 (30.5)	188.7 (100)	24.05
जनगणना 1971	47.5 (26.3)	78.3 (43.4)	54.7 (30.3)	180.5 (100)	37.54
जनगणना 1981	55.5 (24.9)	92.5 (41.6)	74.5 (33.5)	222.5 (100)	37.50
जनगणना 1991	74.6 (26.1)	110.6 (38.8)	100.2 (35.1)	285.4 (100)	40.30

Figures in brackets give percentage to total workers

स्रोत Agricultural statistics at a glance, Ministry of Agriculture, Government of India, New Delhi.

देश में कृषि श्रमिकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार देश में 27.5 मिलियन कृषि श्रमिक थे, जो बढ़कर वर्ष 1961 में 31.5 मिलियन, वर्ष 1971 में 47.5 मिलियन, वर्ष 1981 में 55.5 मिलियन एवं वर्ष 1991 में 74.6 मिलियन हो गए। इस प्रकार इनकी संख्या में पिछले 40 वर्षों में 170 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कृषि श्रमिकों का कुल कार्यरत व्यक्तियों में प्रतिशत 19.7 से बढ़कर 26.1 एवं कृषि व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत 28.26 से 40.30 हो गया। कृषि श्रमिकों के साथ साथ कृषकों एवं अन्य श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। विभिन्न जनगणना एवं कृषि श्रमिक जाच रिपोर्टों में कृषि श्रमिकों की संख्या ज्ञात करने की विधि में बहुत भिन्नता होती हुए भी स्पष्ट है कि देश में कृषि श्रमिकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 1961 से 1971 के काल में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि 4 प्रतिशत प्रति वर्ष वक्रवृद्धि दर से हुई है जबकि इस काल में ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि दर 2 प्रतिशत ही थी। कृषि श्रमिकों में इस प्रसाधारण वृद्धि के प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि, कृषि भूमि क्षेत्र विस्तार की कम सम्भावना का होना, बटाई पर कार्यरत कृषकों को सिंचाई एवं अन्य सुविधाओं के बढ़ने से भूमि से वेदलित करना एवं स्वतः कृषि करने की भावना में वृद्धि आदि कारण प्रमुख हैं।

सारणी 4.6 विभिन्न राज्यों में कृषि श्रमिकों का कृषि व्यवसाय में कार्यरत कुल व्यक्तियों में प्रतिशत प्रदर्शित करती है।

सारणी 4.6

राज्यवार कृषि श्रमिकों का कृषि व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत, 1981

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कुल जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों का वर्ष 1981 में प्रतिशत	कुल कार्यरत व्यक्तियों में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत	कृषि व्यवसाय में कार्यरत कुल व्यक्तियों में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत
1	2	3	4
1 मध्य प्रदेश	42.3	36.79	51.18
2 असम	28.4	NA	—
3 बिहार	29.7	35.50	44.44
4 गुजरात	32.2	22.66	36.22
5 हरियाणा—	28.4	16.11	26.12
6 हिमाचल प्रदेश	34.4	2.72	3.84

1	2	3	4
7 जम्मू एवं कश्मीर	30.4	3.49	5.83
8 कर्नाटक	36.8	26.78	38.88
9 केरल	26.7	28.23	55.69
10 मध्य प्रदेश	38.4	24.24	31.08
11 महाराष्ट्र	38.7	26.63	41.68
12 मणिपुर	40.3	4.99	7.36
13 मेघालय	43.3	9.98	13.78
14 नागालैण्ड	47.5	0.81	1.11
15 उड़ीसा	32.5	27.76	36.08
16 पंजाब	29.4	22.17	37.41
17 राजस्थान	30.5	7.32	26.15
18 सिक्किम	46.5	3.31	0.01
19 तमिलनाडु	39.3	31.73	49.95
20 त्रिपुरा	29.7	24.00	35.70
21 उत्तरप्रदेश	29.2	15.98	21.31
22 पश्चिम बंगाल	28.3	25.23	43.29
23 अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	33.3	3.73	16.67
24 अरुणाचल प्रदेश	49.5	2.49	3.46
25 चण्डीगढ़	34.7	0.55	33.33
26 दादरा एवं नागर हवेली	40.4	10.85	16.12
27 देहली	31.9	0.81	31.37
28 गोवा, दमन एवं दीव	30.5	9.74	33.68
29 लक्षद्वीप	20.0	—	—
30 मिजोरम	41.7	2.49	3.31
31 पाण्डिचेरी	28.6	31.47	77.46
भारत	32.5	24.9	36.27

Source (i) Indian Labour Year Book, 1985

(ii) Census of India, 1981.

कृषि श्रमिकों का राष्ट्रीय कृषि आय में योगदान

सारणी 47 कृषि श्रमिकों की कुल आय प्रति श्रमिक वार्षिक आय एवं कृषि श्रमिकों का राष्ट्रीय कृषि आय में योगदान प्रदर्शित करती है—

सारणी 47

कृषि श्रमिकों का राष्ट्रीय आय में योगदान

विवरण	1956-57	1961-62	1971-72	1981
कृषि श्रमिकों की प्रति व्यक्ति	200	274	552	1895
औसत वार्षिक आय (रु०)	(100)	(137)	(276)	(948)
कृषि श्रमिकों की कुल आय	568	862	2611	11706
(करोड़ रु०)	(100)	(152)	(460)	(2061)
राष्ट्रीय कृषि आय-प्रवर्धित	5870	6776	16850	40342
कीमत स्तर पर करोड़ रु०)	(100)	(115)	(287)	(687)
कृषि श्रमिकों की आय का राष्ट्रीय	10	14	15	29
कृषि आय में प्रतिशत	(100)	(140)	(150)	(290)

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े सूचकांक हैं।

स्रोत G C Mandal, Share of Agricultural Labour in National Agricultural Product—An Exercise, Economic and Political Weekly, Vol XVIII (52-53), December, 24-31, 1983, PA 154

कृषि श्रमिकों की वार्षिक आय में वर्ष 1956-57 से 1981 के काल में 848 प्रतिशत तथा कुल कृषि श्रमिक आय में 1961 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कृषि श्रमिकों का राष्ट्रीय कृषि आय में अंशदान जो वर्ष 1956 में मात्र 10 प्रतिशत था, बढ़कर वर्ष 1981 में 29 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार 1956-57 से 1981 के काल में राष्ट्रीय आय में कृषि श्रमिकों के अंशदान में 190 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

कृषि श्रमिकों का वर्गीकरण—कृषि श्रमिकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है—

I कृषि श्रम जाँच समिति के अनुसार—

(अ) स्थायी श्रमिक—वे श्रमिक जो नियत अवधि—एक फसल, मौसम, वर्ष या अधिक समय के लिए फार्म पर कार्य करने के लिये अनुवन्धित किये जाते हैं, स्थायी श्रमिक कहलाते हैं। स्थायी श्रमिक नियत अवधि की समाप्ति के पूर्व दूसरों

के फार्म पर कार्य नहीं कर सकते हैं और कृषक भी नियत समय से पूर्व उन्हें कार्य से पृथक् नहीं कर सकते हैं। इन श्रमिकों को मजदूरी का मुग्तान क्षेत्र में प्रचलित दर से मासिक अथवा वार्षिक आधार पर किया जाता है।

(ब) अस्थायी/द्राकस्मिक श्रमिक—वे श्रमिक जिनको फार्म पर आवश्यकता होने पर कार्य के लिए रख लिया जाता है और आवश्यकता नहीं होने पर कार्यमुक्त कर दिया जाता है। इनको रखने की अवधि नियत नहीं होती है। अस्थायी श्रमिकों को मजदूरी का मुग्तान दैनिक अथवा कार्य की मात्रा के अनुसार किया जाता है। इनकी मजदूरी की दर विभिन्न मौसमों में भिन्न-भिन्न होती है।

II कांग्रेस भूमि-सुधार समिति के अनुसार—

(अ) खेत में कार्य करने वाले श्रमिक—वे श्रमिक जो खेत पर हल चलाने, बुवाई करने, पौध लगाने, पौधों पर मिट्टी चढ़ाने आदि कार्यों के लिए रखे जाते हैं। उपर्युक्त कार्य करने के लिये श्रमिकों को कार्य का अनुभव होना आवश्यक होता है।

(ब) प्रदक्ष/साधारण श्रमिक—जो श्रमिक फार्म पर ऐसे कार्यों के करने के लिये रखे जाते हैं जिन्हें करने में अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है, प्रदक्ष श्रमिक कहलाते हैं। जैसे—गड्ढे खोदना, मेड़ बनाना, खाद फैलाना आदि। इन्हें मजदूरी का मुग्तान दैनिक अथवा कार्य की मात्रा के अनुसार किया जाता है।

(स) दक्ष श्रमिक—इस श्रेणी के अन्तर्गत वे श्रमिक आते हैं जो फार्म पर उन कार्यों को करने के लिये रखे जाते हैं जिनको करने के लिये अनुभव एवं दक्षता की आवश्यकता होती है, जैसे—बढ़ई, लुहार, ट्रैक्टर चालक, पम्प चालक आदि।

श्रमिकों की कार्यकुशलता

श्रमिकों की कार्यकुशलता से तात्पर्य श्रमिकों के श्रम से प्राप्त उत्पादन की मात्रा से लगाया जाता है। अर्थात् श्रमिकों की कार्यकुशलता श्रम के उपयोग से प्राप्त उत्पाद का अनुपात होती है। वे श्रमिक जो किसी दिये गये समय में अधिक उत्पाद की मात्रा उत्पादित करते हैं वे अन्य श्रमिकों की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल होते हैं।

श्रमिकों की कार्यकुशलता को प्रभावित करने वाले कारक :

श्रमिकों की कार्यकुशलता निम्न कारकों पर निर्भर होती है—

(1) व्यक्तिगत कारक—ये वे कारक हैं जो श्रमिकों में निहित होते हैं तथा जिनके कारण उत्पादन की मात्रा प्रभावित होती है। प्रमुख व्यक्तिगत कारक ये हैं—

(अ) जातीय तथा पितृक गुण,

(ब) नैतिक गुण,

(स) सामान्य बुद्धिमत्ता,

- (द) शिक्षा का स्तर,
- (य) रहन सहन का स्तर,
- (र) श्रमिकों की कार्य में रुचि, प्रशिक्षण एवं प्रवीणता ।

(2) कार्य करने की परिस्थितियाँ—श्रमिकों के कार्य करने की निम्न परिस्थितियाँ भी श्रमिकों की कार्यकुशलता को प्रभावित करती हैं—

- (घ) कार्य करने का मौसम,
- (ङ) सामाजिक तथा राजनैतिक स्थिति,
- (स) सामाजिक प्रथाएँ,
- (ङ) श्रम-संगठन,
- (य) पदोन्नति की आशा ।

(3) प्रबन्ध सम्बन्धी कारक—निम्न प्रबन्ध सम्बन्धी कारक भी श्रमिकों की कार्यकुशलता को प्रभावित करते हैं—

- (अ) कार्य करने के औजार,
- (ब) कार्य की अवधि एवं कार्य करने का समय,
- (स) पारित्यमिक की भुगतान राशि एवं शर्तें,
- (द) कार्य करने की स्वतन्त्रता ।

श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि के उपाय

श्रमिकों की कार्यकुशलता में निम्न उपायों द्वारा वृद्धि की जा सकती है—

(1) कार्य संगठन—कार्य संगठन के अन्तर्गत अगले दिन की कार्य-योजना तैयार करना, आवश्यक औजारों की व्यवस्था करना, कार्य समय में श्रमिकों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना प्रमुख हैं ।

(2) श्रमिकों की सुविधाएँ—आवश्यक सुविधाएँ, जैसे—आवास, दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं को सस्ती दर पर उपलब्ध कराना, मनोरंजन की व्यवस्था आदि के होने से श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है ।

(3) निरीक्षण एवं प्रशिक्षण—श्रमिकों की कार्यकुशलता में निरीक्षण एवं प्रशिक्षण व्यवस्था द्वारा सुधार किया जा सकता है । प्रशिक्षण से श्रमिकों के कार्य में प्रवीणता आती है । निरीक्षण से श्रमिकों के उत्पादन में वृद्धि होती है ।

कृषि श्रमिकों की समस्याएँ—कृषि श्रमिकों की प्रमुख समस्याएँ निम्न हैं—

(1) बेरोजगारी—कृषि श्रमिकों की प्रथम समस्या वर्ष में निरन्तर रोजगार उपलब्ध नहीं होना है । कृषि व्यवसाय में फसल की बुवाई, कटाई आदि के समय

श्रमिकों की माँग अधिक होती है तथा वर्ष के अन्य समय में उनकी माँग कम होती है। औसतन कृषि श्रमिकों को वर्ष में 7-8 माह रोजगार प्राप्त होता है और शेष 4-5 माह कार्य नहीं मिलने के कारण बेरोजगार रहते हैं। बेरोजगारी के कारण औसत आय कम हो जाती है जिससे उनका रहन-सहन का स्तर गिर जाता है।

(2) मजदूरी की दर कम होना—कृषि श्रमिकों की मजदूरी की दर भी कम होती है। इसका प्रमुख कारण कृषि श्रमिकों की अधिकता, उनमें संगठन का अभाव तथा कार्य के लिए दूसरे गाँव में जाने की इच्छा का न होना है।

(3) श्रमिकों पर ऋण का बोझ होना—अधिकांश श्रमिक ऋण के बोझ से बंधे हुए हैं। बेरोजगारी एवं उनमें व्याप्त फिजूल खर्चों की प्रवृत्ति के कारण वे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेते हैं। मजदूरी की दर कम होने के कारण श्रमिक प्राप्त ऋण राशि का मुग्तान नहीं कर पाते हैं और ऋण का बोझ पीढ़ी-दर-पीढ़ी बढ़ता ही रहता है, जिसके उनके रहन-रहन के स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

(4) कार्य करने का समय नियत नहीं होना—कृषि व्यवसाय में अन्य व्यवसायों की भाँति श्रमिकों का कार्य समय एवं अवधि नियत नहीं होती है। कृषि व्यवसाय में श्रमिकों को सुबह से शाम तक कार्य करना होता है। फसल की कटाई के समय तो श्रमिकों को रात्रि में देर तक कार्य करना होता है। इसी प्रकार विजली की कमी होने पर सर्दियों के मौसम में श्रमिकों को रात्रि में सिंचाई का कार्य करना होता है।

(5) कार्य करने की परिस्थितियों का अनुकूल न होना—कृषि श्रमिकों को वर्षा, तेज धूप एवं भयंकर सर्दियों में भी फार्म पर खुले में कार्य करना होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य करने के लिये भी श्रमिकों को अतिरिक्त मजदूरी का मुग्तान नहीं किया जाता है।

(6) कार्य के लिए अच्छे औजार उपलब्ध न होना—कृषि श्रमिकों को कार्य करने के लिये जो औजार दिये जाते हैं वे अच्छे नहीं होते हैं जिससे श्रमिकों को थकावट शीघ्रता से आती है तथा कार्य कम हो पाता है।

पि श्रमिकों में बेरोजगारी एवं अर्द्ध-बेकारी :

कृषि श्रमिकों में व्याप्त बेरोजगारी एवं अर्द्ध-बेकारी की समस्या के अध्ययन के पूर्व इन शब्दों की व्याख्या करना आवश्यक है, जो इस प्रकार है—

बेरोजगारी—बेरोजगारी से तात्पर्य व्यक्ति की उस स्थिति से है जहाँ उसमें कार्य करने की क्षमता के विद्यमान होते हुये भी वह कार्य की तलाश में रहता है, लेकिन उसे उस काल में कोई कार्य उपलब्ध नहीं होता है।

पूर्ण रोजगार—जब किसी व्यक्ति को पूर्ण समय के लिये कार्य उपलब्ध होता हो और उससे प्राप्त आय में कोई कार्य के अनुरूप हो तो उसे पूर्ण रोजगार की स्थिति कहते हैं।

जब किसी अर्थव्यवस्था में काम करने के इच्छुक तथा काम करने के योग्य सभी व्यक्तियों को प्रचलित मजदूरी पर काम मिल जाता है तो यह पूर्ण रोजगार की स्थिति कहलाती है। प्रो० पीगू के मतानुसार पूर्ण रोजगार वह अवस्था है जिसमें यदि व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करना चाहते हैं तो सभी स्वस्थ व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो जाता है। पूर्ण रोजगार की स्थिति में एक नौकरी छूटने के बाद दूसरी नौकरी मिलने में बहुत कम समय लगता है। पूर्ण रोजगार की धारणा विकसित अर्थव्यवस्था पर ही लागू होती है। भारत जैसे विकासोन्मुख देशों पर यह लागू नहीं होती है।

अर्द्ध-बेकारी—अर्द्ध-बेकारी से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें कार्य उपलब्ध होता है, लेकिन उपलब्ध कार्य श्रमिकों को कम समय या कम दक्षता तक ही कार्यरत रख पाता है। श्रमिक कार्यरत होते हुए भी और अधिक कार्य करने की तलाश में रहता है। अर्द्ध-बेकारी की स्थिति उपरोक्त दोनों अवस्थाओं के मध्य होती है।

कृषि श्रमिकों में व्याप्त बेरोजगारी एवं अर्द्ध-बेकारी दो प्रकार की होती है—

(अ) प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी (Disguised Under-employment)—प्रच्छन्न बेरोजगारी से तात्पर्य श्रमिकों की उस स्थिति से है जिसमें नाम-मात्र का रोजगार उपलब्ध होता है, लेकिन उपलब्ध रोजगार उत्पादकता की वृद्धि में सहायक नहीं होता है। इस अवस्था में फार्म पर किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यकता से अधिक सस्या में श्रमिक कार्यरत होते हैं। कार्यरत श्रमिकों की संख्या में कमी करने पर कार्य के पूरा करने में बचत उससे प्राप्त उत्पादन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं आता है। कृषि में यह स्थिति बहुत व्यापक है क्योंकि प्रत्येक फार्म पर उपलब्ध श्रमिकों की संख्या भूमि के अनुपात में अधिक होती है। श्रमिकों को अन्य कार्य उपलब्ध नहीं होने के कारण सभी श्रमिक फार्म पर कार्य करते हैं। उपलब्ध श्रमिकों में से कुछ कार्यरत होते हैं तो कुछ उस समय कार्य नहीं करते हैं। दूसरे समय में वे श्रमिक कार्य करते हैं और पहले वाले कार्यरत श्रमिक प्राराम करते हैं। प्रो० रेग्नार नर्कसे (Ragnar Nurkse) के शब्दों में इन श्रमिकों की सीमान्त उत्पादकता शून्य होती है।

(ब) संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural Potential Under-employment)—संरचनात्मक बेरोजगारी से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें फार्म पर तकनीकी परिवर्तन करने से श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। फार्म पर सिंचाई के लिए

विद्युत् पम्प लगाने, जुताई के लिए ट्रैक्टर का उपयोग करने, फसल की कटाई के लिए रोपर एव ब्रेसर का उपयोग करने से पहले की स्थिति (जिसमें सारा कार्य मानव शक्ति से होता था) की अपेक्षा बहुत से श्रमिक अब बेरोजगार हो जाते हैं, जिन्हें हटाया जा सकता है। कृषि के क्षेत्र में वर्तमान में सरचनात्मक बेरोजगारी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है क्योंकि इसमें तकनीकी ज्ञान के उपयोग का स्तर बहुत पिछड़ा हुआ है।

कृषि श्रमिकों में व्याप्त बेरोजगारी एवं अर्द्ध-बेकारी का आकलन :

श्रमिकों में व्याप्त बेरोजगारी का आकलन निम्न पहलुओं के समझने में सहायक होता है¹⁸ :

(1) बेरोजगारी के आँकड़ों से पता चलता है कि देश में प्रति वर्ष कितनी मात्रा में मानव-शक्ति का ह्रास हो रहा है।

(2) बेरोजगारी के आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि कितने प्रतिशत व्यक्तियों को कार्य के द्वारा आय प्राप्त करने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है।

(3) व्याप्त बेरोजगारी के आधार पर समाज में विद्यमान आर्थिक असमानता का विश्लेषण किया जा सकता है—

श्रमिकों में बेरोजगारी एवं अर्द्ध-बेकारी के आकलन के लिए चार प्रकार के माप दण्ड प्रयोग में लिये जा सकते हैं—

(1) समय के अनुसार—श्रमिकों को विभिन्न समय के लिए उपलब्ध श्रम की मात्रा के अनुसार रोजगार प्राप्त, बेरोजगार एवं अर्द्ध-बेकारी की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार 42 घण्टे प्रति सप्ताह से अधिक काम पाने वाले श्रमिकों को रोजगार प्राप्त श्रमिकों की श्रेणी में और 42 घण्टे प्रति सप्ताह से कम काम पाने वाले श्रमिकों को बेरोजगारी की श्रेणी में विभक्त किया गया है। देश में श्रमिकों के रोजगार एवं बेरोजगार के आकलन में समय-आधार का सर्वाधिक उपयोग किया गया है। विभिन्न समितियाँ, जनगणना, आयोग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के विभिन्न दौरों में एवं व्यक्तिगत अनुसन्धान-कर्त्ताओं द्वारा भी इसी आधार को उपयोग में लिया गया है।

(2) आय के अनुसार—श्रमिकों को वर्ष में प्राप्त आय के स्तर को आधार मानकर भी बेरोजगारी का आकलन किया जाता है। प्रो० दाढेकर एवं रघु द्वारा 'भारत में गरीबी' के अध्ययन में इसी आधार पर बेरोजगारी आकलित की गई है।

(3) कार्य करने की इच्छा—श्रमिकों को कार्य उपलब्ध होने के बाद भी उन्ही शर्तों पर क्या वे अधिक श्रम की तलाश में हैं या नहीं ? यह आधार भी कमी-कमी प्रयुक्त किया जाता है ।

(4) उत्पादकता—श्रमिक उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होते हैं अथवा नहीं ? यह आधार भी प्रयोग में लिया जा सकता है ।

देश में श्रमिकों में व्याप्त बेरोजगारी तथा भद्र-बेकारी की स्थिति के आकलन के लिए वर्ष 1950 से ही प्रयास किये जा रहे हैं । विभिन्न समितियों, जनगणना आयोग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण एवं प्राध्यापकों द्वारा किये गये अध्ययनों के परिणामों में बहुत असमानता है, क्योंकि इनके आकलन में विभिन्न पैमानों का प्रयोग किया गया है तथा शब्दों की परिभाषा में भी क्षिपमता रही है । प्रथम कृषि-श्रम जाँच समिति, 1950-51 के अनुसार देश में पुरुष कृषि श्रमिकों को वर्ष में 218 दिन एवं स्त्री कृषि श्रमिकों को 184 दिन मजदूरी पर कार्य उपलब्ध हुआ था । द्वितीय कृषि-श्रम जाँच समिति, 1956-57 के अनुसार मजदूरी पर उपलब्ध श्रमिक दिवसों की सकल वर्ष में पुरुष एवं स्त्री कृषि श्रमिकों के लिये क्रमशः 222 एवं 141 थी और शेष समय वे बेरोजगार थे ।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के विभिन्न दौरों में बेरोजगारी की जाँच के प्राप्त परिणाम निम्न हैं—

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण	परिणाम
1 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के ग्यारहवें एवं बारहवें दौर (1956-57)	भारत में श्रमिक वर्ष में औसतन 142 दिन बेरोजगार रहते हैं । यह बेरोजगारी सबसे कम असम एवं पंजाब राज्य में 93 दिन एवं सबसे अधिक केरल राज्य में 184 दिन थी ।
2 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के उन्नीसवें दौर (1964-65)	भारत में कृषि श्रमिक को वर्ष में 273 दिन पुरुषों, 183 दिन स्त्रियों एवं 280 दिन बच्चों का रोजगार उपलब्ध होता है । इस प्रकार वे क्रमशः 93, 182 दिन एवं 85 दिन बेरोजगार रहते हैं ।
3 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के विभिन्न दौरों में देश में श्रमिकों में व्याप्त बेरोजगारी का प्रतिष्ठित निम्नलिखित है—	

नवें दौर	(1954-55) के अनुसार 0.68 प्रतिशत
दसवें दौर	(1955-56) के अनुसार 2.17 प्रतिशत
ग्यारहवें एव बारहवें दौर	(1956-57) के अनुसार 2.17 प्रतिशत
चौदहवें दौर	(1958-59) के अनुसार 5.59 प्रतिशत
पन्द्रहवें दौर	(1959-60) के अनुसार 4.63 प्रतिशत
सोलहवें दौर	(1960-61) के अनुसार 4.85 प्रतिशत
सत्रहवें दौर	(1961-62) के अनुसार 5.12 प्रतिशत
उन्नीसवें दौर	(1964-65) के अनुसार 3.80 प्रतिशत
इक्कीसवें दौर	(1966-67) के अनुसार 3.66 प्रतिशत

- 4 राष्ट्रीय प्रतिदशं सर्वेक्षण के पच्चीसवें दौर (1970-71) के अनुसार (अ) लघु-कृषकों में बेरोजगारी का प्रतिशत पुरुषों में सबसे कम पंजाब राज्य में (0.7 प्रतिशत) एव सबसे अधिक तमिलनाडु राज्य में (9.5 प्रतिशत) पाया गया है।
- (ब) भूमिहीन श्रमिकों में बेरोजगारी सबसे अधिक तमिलनाडु में 14.7 प्रतिशत एव सबसे कम उड़ीसा में 1.1 प्रतिशत पाई गई।
- (स) समृद्ध राज्यों—तमिलनाडु गुजरात, महाराष्ट्र एव हरियाणा में बेरोजगारी पिछड़े राज्यों—उड़ीसा असम एव राजस्थान की अपेक्षा अधिक पाई गई।

श्रीमती शकुन्तला मेहरा¹⁹ ने वर्ष 1966 में देश में कुल उपलब्ध श्रम का 17.1 प्रतिशत श्रम अविशेष पाया। यह अविशेष श्रम असम राज्य में 39.7

19. Shakuntala Mehra, Surplus Labour in Indian Agriculture, Indian Economic Review, April, 1966.

प्रतिशत, बिहार में 36.6 प्रतिशत, राजस्थान में 35.7 प्रतिशत, उत्तरप्रदेश में 28.8 प्रतिशत था। डॉ. राजकृष्णा द्वारा 1971 के लिए आकलित बेरोजगारी के आंकड़े सारणी 4.8 में दिए गए हैं। डॉ. राजकृष्णा के अनुसार देश में 9.25 मिलियन व्यक्ति पूर्णतया बेरोजगार एवं 21.45 मिलियन व्यक्ति पूर्णतया बेरोजगार तथा बहुत कम राजगार पाने वाले श्रमिक हैं। यह कुल राष्ट्रीय श्रम-शक्ति का 9 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कुल श्रम-शक्ति का 9.7 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 5.8 प्रतिशत है।

सारणी 4.8

भारत में वर्ष 1971 में आकलित बेरोजगारी

(संख्या मिलियन में)

क्षेत्र	बेरोजगार व्यक्ति	बेरोजगार एवं कम रोजगार वाले व्यक्ति जो प्रतिरिक्त कार्य करने के लिए उपलब्ध हैं।	बेरोजगार एवं बहुत कम रोजगार पाने वाले व्यक्ति जो प्रतिरिक्त कार्य करने के लिए उपलब्ध हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में			
पुरुष	3 616	14 662	9,928
स्त्री	4 644	11 558	9,454
कुल	8,260	26 220	19 382
शहरी क्षेत्रों में			
पुरुष	0 758	—	—
स्त्री	0,233	—	—
कुल	0,991	3,073	2,172
कुल			
पुरुष	4 374	—	—
स्त्री	4 877	—	—
कुल	9 251	29 293	21 453

स्रोत: Rajkrishna, Unemployment in India, Economic and Political Weekly, Vol VIII, No 9, March 3, 1973, p. p 475-484

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के चौदहवें से सत्रहवें दौर के औसत मान के आधार पर वर्ष 1961 में 1590 करोड़ श्रमिका में से 221 करोड़ श्रमिकों बेरोजगार एवं अर्द्ध-बेकारी (076 करोड़ पूर्णतया बेरोजगार एवं 145 करोड़ अर्द्ध-बेकार) के श्रेणी में थे। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के सत्रहवें, उन्नीसवें एवं इक्कीसवें दौर के औसत मान के आधार पर वर्ष 1971 में 1987 करोड़ श्रमिकों में से 1183 करोड़ श्रमिक पूर्णतया बेरोजगार एवं 179 करोड़ अर्द्ध-बेकारी (2.62 करोड़ कुल) की श्रेणी में थे। प्रत्यक्ष स्पष्ट है कि उपर्युक्त दशकों में बेरोजगारी की संख्या 221 करोड़ से बढ़कर 262 करोड़ हो गई। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि देश में अर्द्ध-बेकारी की समस्या बेरोजगारी की समस्या से ज्यादा गम्भीर है।

स्वतन्त्र भारत की प्रथम जनगणना (1951) में बेरोजगारी के आंकड़े तीन राज्यों से ही प्राप्त किए गये थे। वर्ष 1961 की जनगणना के आधार पर भारत में कुल श्रम में बेरोजगारी का प्रतिशत 038 था। वर्ष 1971 की जनगणना में श्रमिकों में व्याप्त बेरोजगारी का आकलन नहीं किया गया था।

प्रो दांतवाला²⁰ ने बताया है कि बेरोजगारी के पूर्णतया सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। प्रत्यक्ष श्रमिका की संख्या में वृद्धि ही बढ़ती हुई बेरोजगारी की सूचक मानी जानी चाहिए। दश के ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिका की संख्या वर्ष 1961 में 138 मिलियन तथा वर्ष 1971 में 168 मिलियन थी। वर्ष 1981 के लिए बेरोजगारी का आकलन 215 मिलियन व्यक्तियों का लगाया गया है। प्रत्यक्ष बढ़ती हुई श्रम शक्ति बेरोजगारी में भी वृद्धि करती है।

कृषि-श्रमिकों में व्याप्त बेरोजगारी व अर्द्ध-बेकारी के लिए नियुक्त समितियाँ

भारत सरकार द्वारा कृषि श्रमिका में व्याप्त बेरोजगारी एवं अर्द्ध-बेकारी के आकलन एवं इसका कम करने के सुझाव देने के लिये निम्न दो समितियाँ नियुक्त की थीं—

(अ) दांतवाला समिति—यह समिति भारत सरकार द्वारा अगस्त, 1968 में प्रो० एम एल दांतवाला की अध्यक्षता में बेरोजगारी व आकलन के लिए नियुक्त की गई थी। समिति का प्रमुख कार्य योजना आयोग को दश में बेरोजगारी-आकलन से सम्बंधित प्रश्नों पर सलाह प्रदान करना था। समिति ने अगस्त, 1970 में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। समिति ने दश में श्रम-शक्ति, बेरोजगारी की स्थिति एवं पंचवर्षीय योजना काल में उपलब्ध होने वाले अतिरिक्त राजस्व का आकलन की विधि को अनुचित बताया है। समिति के सुझावों के अनुसार चतुर्थ

पंचर्षीय योजना में बेरोजगारी के आकलन करने की प्रथा समाप्त कर दी गई। समिति ने जनगणना, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, रोजगार नियोजन कार्यालय एवं अन्य संस्थाओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बेरोजगारी के आँकड़ों को एकत्रित करने के लिये अनेक सुझाव दिये।

(ब) भगवती समिति—यह समिति भारत सरकार द्वारा प्रो० बी सी भगवती की अध्यक्षता में दिसम्बर 1970 में देश में बेरोजगारी एवं अर्द्ध-बेकारी के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन व आवश्यक आकलन एवं इनमें सुधार की विधियों को प्रस्तावित करने के लिये नियुक्त की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1972 में सरकार को प्रस्तुत की। समिति के अनुसार देश में वर्ष 1972 में 18.7 मिलियन व्यक्ति बेरोजगार थे, जिनमें से 16.1 मिलियन (कुल श्रम शक्ति का 10.9 प्रतिशत) व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में एवं 2.6 मिलियन व्यक्ति शहरी क्षेत्रों में (कुल श्रम-शक्ति का 8.1 प्रतिशत) थे। समिति के अनुसार 9.0 मिलियन व्यक्ति पूर्ण बेरोजगार एवं 9.7 मिलियन व्यक्ति अल्प रोजगार/अर्द्धबेकारी की श्रेणी में थे। अतः देश में बेरोजगारी एवं अर्द्ध-बेकारी की समस्या समान मात्रा में विद्यमान है और दोनों को एक ही स्तर पर दूर करने की आवश्यकता है। भगवती समिति ने योजना आयोग द्वारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के शुरू में (अप्रैल 1969) में आकलित बेरोजगारी 9 से 10 मिलियन को कम बताये हुये उसका ऊपर की ओर सशोधन करने का सुझाव दिया था।²²

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के कारण—ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी के प्रमुख कारण निम्न हैं—

- (1) जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि।
- (2) ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों एवं सहायक उद्योगों के विकास की दर में कमी का होना।
- (3) कृषि उत्पादकता की दर का कम होना।
- (4) कृषि जोती का आकार कम होना एवं उनका वित्तीय रूप में होना, तथा
- (5) श्रमिकों में कार्य के लिये शहर में जाने के प्रति अरुचि का होना।

बेरोजगारी समस्या का निवारण—बेरोजगारी की समस्या देश में अग्रिमशाप है जिसका निवारण आवश्यक है। समय-समय पर बेरोजगारी की समस्या के

21. Report of the Committee of Experts on Unemployment Estimates Government of India, Planning Commission New Delhi 1970
22. Committee on Unemployment, Report of the Working Group on Agriculture, Government of India New Delhi, 1972 (Bhagwati Committee)

निवारण के लिए अनेक सुझाव दिये गये हैं एवं उनको कार्यान्वित करने का प्रयास भी किया गया है। भगवती समिति ने बेरोजगारी की समस्या के स्थायी निराकरण के लिये प्रतिवेदन में निम्न सुझाव दिये थे—

(1) देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम के द्वारा जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाकर बढ़ती हुई-शक्ति में कमी करना।

(2) उद्योगों में निम्न उपाय अपनाकर रोजगार वृद्धि की जानी चाहिये—

(अ) उद्योगों को उनकी पूर्ण क्षमता तक संचालित किया जाना चाहिये।

(ब) उद्योगों के लिये कच्चे माल की उपलब्धि की व्यवस्था निरंतर होनी चाहिये।

(स) उद्योगों का विस्तार सभी क्षेत्रों में किया जाना चाहिये।

(द) उद्योगों में स्वचालित एवं बड़ी मशीनों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिये।

(य) उद्योगों की सहायक इकाइयों का विकास किया जाना चाहिये।

(र) ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की कार्य-प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिये।

(ल) पिछड़े क्षेत्रों में आवश्यक आधारभूत ढाँचे की सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिये जिससे इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हो सकें।

(3) देश में कृषि कार्यक्रमों, जैसे—सिंचाई, भूसंरक्षण, भूमि-सुधार, सड़क निर्माण, नहर, बांध निर्माण आदि कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इन कार्यों में श्रमिकों को रोजगार अधिक उपलब्ध होता है। इसी प्रकार कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिये उपलब्ध पानी का संरक्षण, उत्तम फसल योजना तथा पशु पालन कार्यक्रम का विकास किया जाना चाहिये। विभिन्न क्षेत्र में उन फसलों का अधिकाधिक विकास किया जाना चाहिये, जिसमें अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हो सके।

भारतीय कृषि में श्रम-अवशोषण (Labour absorption) की मात्रा वर्तमान में 150 मानव-दिवस प्रति हैक्टर से कम है, जबकि जापान, चीन एवं ताइवान जैसे देशों में श्रम-अवशोषण की मात्रा कृषि क्षेत्रों में 500 मानव-दिवस प्रति हैक्टर से भी अधिक है।²³ भारतीय कृषि में बहुफलसीय कार्यक्रम अपनाकर, उत्पादन की उन्नत विधियों एवं आवश्यक मात्रा में उत्पादन साधनों का उपयोग

23 Vishnu Kumar, Increasing Employment in Agriculture Sector, Yojana XXV, No 7, 16—30 April 1981, p 18

करके श्रम-अवशोषण को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार कृषि-क्षेत्र देश में व्याप्त बेरोजगारी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बेरोजगारी को कम करने में सहायक होगा।

(4) देश में सड़क एवं भवन-निर्माण कार्य को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

देश में छठी पंचवर्षीय योजना में रोजगार वृद्धि पर विशेष बल दिया गया है। विभिन्न क्षेत्रों से जो रोजगार उपलब्ध हो सकेगा, उसके विश्लेषण से पता चलता है कि सबसे अधिक रोजगार के अवसर कृषि, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, निर्माण-कार्य एवं अन्य सेवाओं से उत्पन्न होते हैं। सातवीं योजना के अन्त तक विभिन्न क्षेत्रों से रोजगार उपलब्धि का आकलन 227 1 मिलियन मानक व्यक्ति वर्ष का लगाया गया है, इसमें से 114 1 मिलियन मानक व्यक्ति वर्ष (46 2 प्रतिशत) कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों से प्राप्त होने का आकलन है।

कृषि श्रमिकों की मजदूरी दर

कृषि श्रमिकों में व्याप्त बेरोजगारी के बाद दूसरी प्रमुख समस्या इनकी मजदूरी की दर का कम होना है। विभिन्न कृषि-जाँच समितियों के प्रतिवेदनो से यह स्पष्ट है कि कृषि-श्रमिकों की मजदूरी की दर अन्य क्षेत्र के मजदूरों की अपेक्षा बहुत कम है। भारत में विभिन्न कृषि-श्रम जाँच समितियों के प्रतिवेदन के अनुसार कृषि-श्रमिकों (पुरुष, स्त्रियों एवं बच्चों) को प्राप्त औसत मजदूरी सारणी 4 9 में प्रदर्शित है—

सारणी 4.9

विभिन्न कृषि-श्रम जाँच समितियों के अनुसार

कृषि-श्रमिकों को प्राप्त मजदूरी की दर

(रुपये प्रतिदिन)

	प्रथम कृषि- श्रम जाँच समिति	द्वितीय कृषि- श्रम जाँच समिति	ग्रामीण श्रम- जाँच समिति	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 25वें दौर	1981
	(1950-51)	(1956-57)	(1964-65)	(1970-71)	
पुरुष	1.09	0.96	1.43	3.03	6.94
स्त्री	0.68	0.59	0.95		
बच्चे	0.70	0.53	0.72		

विभिन्न राज्यों में कृषि श्रमिकों की मजदूरी की दर में बहुत भिन्नता पाई जाती है। सभी राज्यों में कृषि श्रमिकों को उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की अपेक्षा कम मजदूरी प्राप्त होती है। कृषि श्रमिकों को मजदूरी कम प्राप्त होने एवं वर्ष में काफी समय तक बेरोजगार रहने के कारण उनका रहन सहन का स्तर गिर जाता है और अधिकांश कृषि श्रमिक ऋणग्रस्त हो जाते हैं। कृषि श्रमिकों को कार्य के अनुसार मजदूरी दिलाने, उनमें व्याप्त ऋणग्रस्तता को कम करने तथा उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार लाने के लिये, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की नीति अपनाई गई है।

न्यूनतम मजदूरी से तात्पर्य—मजदूरी श्रम का वह मूल्य है जो श्रमिकों को कार्य करने के बदले में प्राप्त होता है। मजदूरी की दर श्रमिकों एवं उनके द्वारा किये गये कार्य की विभिन्नता के अनुसार विभिन्न होती है। न्यूनतम मजदूरी, मजदूरी की वह न्यूनतम दर है जो श्रमिकों को राजकीय नियमों के अनुसार दी जाती है। न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण सरकार उस स्तर पर करती है जिससे श्रमिकों अपने परिवार का पालन-पोषण सुगमता से कर सकें। उचित मजदूरी समिति ने न्यूनतम मजदूरी उसे कहा है जो श्रमिकों के जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं करती है, बल्कि श्रमिकों की कार्यकुशलता भी बनाये रखती है।²⁴ अतः न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय शिक्षा, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य सुविधाओं को भी ध्यान में रखना चाहिये।

कृषि श्रमिकों की मजदूरी नियत करने का कार्य सरकार की नीति का एक भाग है। इंग्लैण्ड में सर्वप्रथम वर्ष 1924 में कृषि श्रमिकों की मजदूरी एक कानून के तहत नियन्त्रित की गई थी। भारत सरकार ने श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी नियत करने के लिये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Minimum Wages Act, 1948) पारित किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य श्रमिकों की माय में वृद्धि करके उन्हें उचित जीवन-स्तर प्रदान करना था। इस अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों (कृषि श्रमिकों सहित) के लिये न्यूनतम मजदूरी की दर निश्चित की जाती है तथा रहन-सहन की लागत के सूचकांक में परिवर्तन के आधार पर न्यूनतम मजदूरी की दर में परिवर्तन किये जाते हैं। न्यूनतम मजदूरी नियम करने का कार्य भारत सरकार का श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय करता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में वर्ष 1951 एवं 1954 में संशोधन किये गये। संशोधित अधिनियम के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों को विभिन्न प्रकार के श्रमिकों (कृषि श्रमिकों सहित) के लिये न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का अधिकार

24 मोहनलाल जर्मा, न्यूनतम मजदूरी का प्रश्न, योजना, वर्ष XIII, अंक 3, मार्च 2, 1969 पृष्ठ 19-20.

प्रदान किया गया। न्यूनतम मजदूरी कानून, 1948 के अनुसार यदि किसी श्रमिक को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम दर का भुगतान किया जाता है तो वह अपने नियोजक पर कानूनी कार्यवाही करके क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त कर सकता है।

भारतीय श्रम सम्मेलन के पन्द्रहवें अधिवेशन में आवश्यकतानुसार मजदूरी को न्यूनतम मजदूरी के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्तमान में सभी राज्यों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हो चुके हैं और उनके अनुसार कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी नियत की गई है। जम्मू-कश्मीर, नागालैण्ड, सिक्किम, मिजोरम, लक्षद्वीप एवं अरुणाचल-प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी नियत नहीं की गई। न्यूनतम मजदूरी में वर्ष 1975 के बाद अनेक संशोधन किये गये एवं सरकार द्वारा उन्हें लागू करने के प्रयास पर भी विशेष रूप से बल दिया गया। केन्द्रीय सरकार भी प्रदर्शन फार्म, अनुसन्धान फार्म एवं सैनिक फार्म के लिए न्यूनतम मजदूरी नियत करती है।

प्रत्येक राज्य में न्यूनतम मजदूरी की दर में क्षेत्र में उपलब्ध सिंचाई एवं अन्य सुविधाओं के अनुसार बहुत भिन्नता पाई जाती है। पंजाब राज्य में कृषि श्रमिकों के लिये निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है।

कृषि के क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को पूर्णरूप से लागू करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही है। कृषि क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी लागू करने में प्रमुख बाधाएँ निम्न हैं—

(1) कृषि क्षेत्र की उत्पादकता एवं श्रमिकों की उत्पादकता का स्तर कम होना, जिससे नियोजक निर्धारित न्यूनतम मजदूरी देने में असमर्थ होते हैं।

(2) कृषि क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार की स्थिति में भिन्नता का होना।

(3) कृषि-क्षेत्र में श्रमिकों को रोजगार उद्योगों की भाँति एक स्थान पर उपलब्ध न होकर असंग-अलग स्थानों पर प्राप्त होना।

(4) कृषि में प्रकृति के प्रकोपों के कारण उत्पादन प्राप्ति की निश्चितता का न होना।

(5) कृषि-क्षेत्र में कार्यरत कृषकों एवं श्रमिकों में शिक्षा का अभाव होना।

(6) कृषि श्रमिकों में संगठन का अभाव होना।

(7) कृषि-क्षेत्र में मजदूरी का भुगतान नकद एवं खाद्यान्न, भोजन आदि के रूप में करने की प्रथा का प्रचलित होना।

(8) कृषि-क्षेत्र में श्रमिकों एवं नियोजक कृषकों द्वारा फार्म पर सम्मिलित रूप से एक साथ कार्य करना, जिससे उनमें एक-दूसरे के प्रति विश्वास की भावना जागृत हो जाती है।

(9) कृषि श्रमिकों एवं कृषकों को न्यूनतम मजदूरी कानून के बारे में ज्ञान नहीं होना ।

(10) कृषि व्यवसाय में कृषकों द्वारा श्रमिकों के रूप में अपनी जाति, रिश्तेदारों आदि को कार्य पर लगाया जाना है, जिन्हें श्रमिक न बताकर घर के सदस्य ही बताया जाता है ।

(11) सरकार भी कानून के पालन में पूर्ण इच्छा नहीं रखती है ।

(12) कृषि-श्रमिकों को नियम न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार उपलब्ध नहीं होना, जैसाकि पिछले पृष्ठों में स्पष्ट किया गया है कि कृषि-क्षेत्र में बेरोजगारी बहुत व्याप्त है । जब निर्धारित न्यूनतम मजदूरी पर श्रमिकों को कार्य उपलब्ध नहीं होता है तो वे नियम न्यूनतम मजदूरी से कम पर कार्य करने को तैयार हो जाते हैं और कानून के परिपालन की मात्र खानापूर्ति के लिए पूरी मजदूरी की प्राप्ति पर भ्रम हस्ताक्षर कर देते हैं । रोजगार उपलब्धि के समय की गारन्टी के बिना न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से श्रमिकों को विशेष लाभ नहीं हो सकता है । अतः देश में पिछले चार दशकों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के होने हुए भी कृषि श्रमिकों को इससे वाञ्छित लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं । इन कानून से केवल खाना वाले क्षेत्रों के कृषि श्रमिकों को विशेष लाभ प्राप्त हुए हैं ।

कृषि श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयास

कृषि श्रमिकों की समस्याओं पर कृषि रायल कमीशन व कांग्रेस भूमि-सुधार समिति ने लिखा है कि समाज के इस वर्ग की समस्याओं को हल करने में अब तक विशेष ध्यान नहीं दिया गया है । स्वतन्त्र भारत में इनकी ओर विशेष ध्यान दिया गया और अनेक कार्यक्रम सरकार ने चलाए । अब तक कृषि श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिये निम्न कार्यक्रम अपनाये गये हैं—

(1) भूमि-सुधार कार्यक्रम—देश में भूमि-सुधार कार्यक्रम को लागू किये जाने के फलस्वरूप आसामी कृषकों को भूमि पर स्थायी अधिकार प्राप्त हो गये हैं । भूमि-सुधार कार्यक्रमों के फलस्वरूप उन कृषकों की स्थिति में जो कृषि श्रमिकों से भिन्न नहीं थे, बहुत सुधार हुआ है ।

(2) देश में प्रचलित बेगार-प्रथा एवं कृषि दास-प्रथा को समाप्त कर दिया गया है । जमींदार एवं जागीरदार श्रमिकों से बेगार (Forced labour) लिया करते थे तथा कार्य के लिये किसी प्रकार की मजदूरी का मुगतान नहीं किया जाता था । यह प्रथा अब कानूनन समाप्त कर दी गई है ।

(3) कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी नियम कर दी गई है । अतः नियोजकों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम का मुगतान करना कानूनन अवरोध माना जाता है ।

(4) देश के विभिन्न राज्यों में व्याप्त बन्धक मजदूर प्रथा (Bonded labour system) भी सरकार द्वारा वर्ष 1975 में बन्धक मजदूर उन्मूलन अधिनियम पारित करके समाप्त कर दी गई है। इस प्रथा के अन्तर्गत भू स्वामी मजदूरों को पुराने कर्जों के भुगतान अथवा कुछ ऋण राशि देकर लम्बी अवधि के लिये बंधक बना लेते थे। इस कानून के तहत बन्धक मजदूर प्रथा को कानूनन अपराध घोषित कर दिया गया है।

(5) कृषि श्रमिकों के कार्य के घंटे नियन करने कार्य उलम्बि की गारण्टी देने एवं उनके कल्याण हेतु अनेक कार्यक्रम जैसे—सप्ताह में एक दिन का सर्वतनिक अवकाश दिलाने, सामाद प्रमोद के साधन जुटाने, कार्य के समय चोट लगने पर क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने के लिये भी अनेक राज्यों ने कानून पारित किये हैं। कृषि श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिये केरल राज्य द्वारा पारित 'केरल कृषि-श्रमिक कानून' 1974 अनुकरणीय है। अन्य राज्यों द्वारा भी केरल राज्य के समान कृषि-श्रमिकों की भलाई के लिये कानून पारित किया जाता चाहिये।

(6) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों की भलाई के लिये भी सरकार ने अनेक कार्यक्रम शुरू किये हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम क्षेत्र विशेष के श्रमिकों के लिये प्रारम्भ किये गये हैं तथा कुछ कार्यक्रम समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिये प्रारम्भ किये गये हैं। प्रमुख कार्यक्रम निम्न हैं—

(i) सूखा सम्भावना वाले क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम (Draught Prone Area Programme)—यह कार्यक्रम वर्ष 1970 में देश के उन क्षेत्रों में प्रारम्भ किया गया है जो वर्षा के नहीं होने अथवा कम होने के कारण सूखा से प्रभावित होते रहते हैं। इस कार्यक्रम में प्रमुखतया भू-संरक्षण एवं भूमि विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों पर धन दिया जाता है, जिससे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हो सके। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम का शत-प्रतिशत व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया गया था, लेकिन पांचवी योजना से इस कार्यक्रम पर किये जाने वाला व्यय केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 50 : 50 के अनुपात में किया जाता है। सातवी योजना में इस कार्यक्रम पर 46986 करोड़ रुपये व्यय किया गया है। वर्तमान में यह कार्यक्रम 13 राज्यों के 91 जिलों में 615 ब्लॉकों में कार्यान्वित है।

(ii) मरुस्थल विकास कार्यक्रम (Desert Development Programme)—यह कार्यक्रम उन राज्यों में प्रारम्भ किए गये हैं, जो मरुस्थल की श्रेणी में आते हैं और वहाँ पर फसलों का उत्पादन

करना सम्भव नहीं है। यह कार्यक्रम वर्ष 1977-78 में केन्द्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता से प्रारम्भ किया गया था और वर्ष 1979-80 में इस योजना का व्यय केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 50 : 50 के अनुपात में किया जाता है। वर्तमान में यह कार्यक्रम गुजरात, हरियाणा, हिमाचल-प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा राजस्थान राज्य के कुल 21 जिलों में कार्यान्वित है।

(iii) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Integrated Rural Development Programme)—इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को लाभान्वित करके ग्रामीण क्षेत्रों का एकीकृत विकास करना है। यह कार्यक्रम वर्ष 1978-79 में केन्द्रीय सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता से कार्यान्वित था। वर्ष 1979-80 से इस पर होने वाले व्यय की राशि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समान अनुपात में वहन की जाती है। इस कार्यक्रम से मार्च, 1991 तक 376 35 लाख परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही लाभान्वित परिवारों को सहकारी एवं वाणिज्यिक बैंकों से 9665 करोड़ रुपये के अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए जा चुके हैं।

(iv) सीमान्त कृषक एवं कृषि-श्रमिक अभिकरण—यह अभिकरण वर्ष 1971 में उन क्षेत्रों में प्रारम्भ की गई है जहाँ पर सीमान्त कृषक (एक हेक्टर से कम भूमि वाले) एवं कृषि-श्रमिकों की बाहुल्यता होती है। इनका प्रमुख उद्देश्य सीमान्त कृषकों एवं कृषि-श्रमिकों को वित्तीय सहायता एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करना है, जिससे इस वर्ग का भी आर्थिक विकास हो सके। विभिन्न कृषि कार्यक्रमों को अपनाने के लिए इन्हें एक तिहाई राशि सहायता के रूप में एवं दो-तिहाई राशि वाणिज्यिक बैंकों से कम व्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

(v) ग्रामीण रोजगार का क्रैश कार्यक्रम (Crash Scheme for Rural Employment)—इस कार्यक्रम में उक्त श्रेणियों में नहीं आने वाले क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए रोजगार उपलब्ध हेतु विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ करने हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम जैसे सड़क निर्माण, सिंचाई के साधन निर्माण, स्कूल भवन का निर्माण आदि से क्षेत्र में स्थायी सम्पत्ति के निर्माण के साथ साथ श्रमिकों को निरन्तर कार्य भी उपलब्ध होता है।

- (vi) काम के बदले अनाज योजना (Food for Work Programme)—कृषि में मौसमी बेरोजगारी को दृष्टि में रखते हुए एब सरकार के पास उपलब्ध अनाज के वितरण हेतु काम के बदले अनाज योजना अप्रैल, 1977 में प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत सायंजनिक निर्माण कार्यों के रख-रखाव तथा नए पूंजीगत निर्माण कार्यों (सिंचाई कार्य, मिट्टी तथा जल संरक्षण, वनरोपण, सड़क तथा स्कूल आदि के निर्माण) पर लगे मजदूरों को काम के बदले तकद भुगतान के साथ-साथ अनाज भी दिया जाता है। काम के बदले अनाज योजना में अप्रैल, 1977 से मार्च, 1980 तक 933.8 मिलियन दिवस रोजगार उपलब्ध हुआ है तथा 3 749 मिलियन टन अनाज श्रमिकों को उपलब्ध कराया गया है।
- (vii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (National Rural Employment Programme)—काम के बदले अनाज योजना का अक्टूबर, 1980 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम नाम दिया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना के काल में (1980-81 से 1984-85) इस कार्यक्रम के तहत 1775.13 मिलियन मानव दिवस का रोजगार श्रमिकों को उपलब्ध कराया गया है तथा श्रमिकों को 2 397 मिलियन टन खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। इस योजना को केन्द्र एब राज्य सरकार 50 : 50 के अनुपात में वित्तीय सहायता देते हैं।
- (viii) अन्त्योदया कार्यक्रम (Antyodaya Programme)—विकास का लाभ समाज के निम्नतम स्तर तक के व्यक्तियों तक पहुँचाने के उद्देश्य से समाज में पिछड़े वर्ग में सबसे पिछड़े व्यक्ति का चुनाव इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है और उन्हें आवश्यक वित्तीय सुविधा एब रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।
- (ix) ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के लिए रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (Rural Landless Employment Guarantee Programme or RLEGP)—यह कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में (अगस्त 1983) बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य गाँवों के भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार उपलब्धि के अवसर प्रदान करना है तथा प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्धि की गारन्टी प्रदान करना है। साथ ही कार्यक्रम से क्षेत्र में आवागारिक संरचनाओं का विकास करना है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास

हो सके। इस कार्यक्रम में उन कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जिन पर 50 प्रतिशत से अधिक व्यय थम पर होना है और शेष 50 प्रतिशत व्यय उस कार्य के लिए आवश्यक सामान जैसे पत्थर, चूना, सीमेन्ट आदि के तय पर होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के लिए रोजगार गारन्टी कार्यक्रम ने पिछले 4 वर्षों (1985-86 से 1988-89) में प्रतिवर्ष 635 मिलियन मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराया है, इस दर पर रोजगार उपलब्ध होने से सातवीं पञ्चवर्षीय योजना में 2450 मिलियन मानव दिवस रोजगार उपलब्ध होने का आकलन है। उपरोक्त दोनों कार्यक्रमों पर पिछले 4 वर्षों (1985-86 से 1988-89) में किया गया व्यय एवं उससे उत्पन्न रोजगार सारणी 4.10 में प्रदर्शित है।

सारणी 4.10

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के लिए रोजगार गारन्टी कार्यक्रम की प्रगति

वर्ष	उपलब्ध वित्तीय सुविधा (करोड़ रुपये)	व्यय राशि (करोड़ रुपये)	उत्पन्न रोजगार (मिलियन मानव दिवस)
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम			
1985-86	593.08	531.95	316.41
1986-87	765.13	717.77	395.39
1987-88	888.21	788.31	370.77
1988-89	845.68	901.84	394.96
ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के लिए रोजगार गारन्टी कार्यक्रम			
1985-86	580.35	453.17	247.58
1986-87	649.96	635.91	306.14
1987-88	648.41	653.53	304.11
1988-89	761.55	669.37	296.56

स्रोत : Eighth Five year Plan (1992-97), Planning Commission, Government of India, New Delhi.

- (x) ग्रामीण युवाओं के लिए स्वतः रोजगार प्रशिक्षण (Training of Rural Youth for Self Employment or TRYSEM) —यह कार्यक्रम ग्रामीण युवकों के लिए विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देने हेतु अगस्त, 1979 में शुरू किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षण द्वारा स्वतः रोजगार प्रारम्भ करने की प्रेरणा दिया जाना है, जिससे वे नौकरी की तलाश में नहीं भटके तथा गाँवों में प्राप्त प्रशिक्षण के अनुसार व्यवसाय प्रारम्भ कर सकें।
- (xi) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों के विकास के कार्यक्रम (Development of Women and Children in Rural Areas or DWCRA) —यह कार्यक्रम सितम्बर, 1982 में महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए प्रारम्भ किया गया है। इसमें महिलाओं एवं बच्चों के लिए रोजगार की शर्तों एवं कार्य स्थिति में सुधार करना प्रमुखतया सम्मिलित है।
- (xii) रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (Employment Guarantee Programme) —यह कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1971-72 में प्रारम्भ किया था। इस कार्यक्रम के तहत कार्य चाहने वाले श्रमिक को जिले के जिलाधीश को रोजगार चाहने हेतु प्रार्थना पत्र देना होता है। निर्धारित समयावधि में जिले का जिलाधीश उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करता है अन्यथा एक निश्चित राशि श्रमिक को प्रतिमाह देय होती है।
- (xiii) जवाहर रोजगार योजना (Jawahar Rozgar Yojana) —ग्रामीण बेरोजगारी पर सीधा एवं प्रत्यक्ष प्रहार करने के लिए रोजगार उपलब्धि की यह नवीन योजना जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी वर्ष (1989-90) में प्रारम्भ की गई है। इस योजना के प्रारम्भ की घोषणा 28 अप्रैल, 1989 को ससद में की गई। जवाहर रोजगार योजना पर इस वित्तीय वर्ष में 2600 करोड़ रु व्यय करने का प्रावधान है। योजना पर आने वाले कुल व्यय का 80 प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं 20 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी। योजना के द्वारा सम्पूर्ण भारत में 4-40 करोड़ निर्धनता रेखा के नीचे के परिवारों के कम से कम एक सदस्य को रोजगार दिया जावेगा। यह योजना देश के सभी गाँवों में कार्यरत है।

जवाहर रोजगार योजना की विशेषताएँ :

इस रोजगार योजना की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं—

- (1) जवाहर रोजगार योजना के क्रियान्वयन का दायित्व ग्राम पंचायतो का होगा। इससे आशा की जाती है कि ग्रामीण परिवारों को पूर्व में सरकार द्वारा चालू की गई अन्य रोजगार योजनाओं की अपेक्षा अधिक रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। योजना की कार्यान्विति के लिए तीन से चार हजार तक की जनसंख्या वाली एक ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष 80 हजार से एक लाख रुपये तक प्राप्त होंगे। यह योजना सभी ग्राम पंचायतों में लागू की जायेगी, जबकि पूर्व में चालू की गई ग्रामीण रोजगार योजनाएँ 55 प्रतिशत ग्राम पंचायत क्षेत्रों में ही लागू की जा सकी थी।
- (2) ग्रामीण रोजगार की वर्तमान में चल रही सभी योजनाओं एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों का विलय जवाहर योजना में स्वतः ही हो जायेगा। जन-जातियों के व्यक्तियों को रोजगार दिलाने वाली योजनाओं को भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया जायेगा। कुल स्वीकृत रोजगार अवसरों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत अवसर आरक्षित रहेंगे।
- (3) इस रोजगार योजना के द्वारा निर्धनता रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को उनके घर के निकट कार्यस्थल पर प्रतिवर्ष 50 से 100 दिन तक का रोजगार प्राप्त हो सकेगा।
- (4) कार्यक्रमों विशिष्ट भौगोलिक संरचना वाले क्षेत्रों, जैसे—पर्वतीय, महस्यलीय तथा द्वीप समूह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष ध्यान दिया जावेगा।
- (5) इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण सामान्वित परिवार यह जान सकेंगे कि अन्य व्यक्तियों को वर्ष में कितने दिन रोजगार उपलब्ध कराया गया है तथा कितनी राशि उन्हें भुगतान की गई है। रोजगार उपलब्ध दिवस एवं भुगतान राशि में विशेष असमानता के होने पर ग्रामीण अपनी धाराज पंचायत के सदस्यों के खिलाफ लड़ा सकेंगे तथा चुनाव के समय अपने मताधिकार से उन्हें सत्ता से पृथक भी कर सकेंगे।
- (6) धन राशि का आवंटन राज्यों को, उनमें निवास कर रही जनसंख्या की निर्धनता की सघनता के आधार पर किया जायेगा। राज्यों द्वारा प्राप्त धन को जिसो को आवंटित किया जायेगा। इसके लिए निम्न तीन मुख्य आधार होंगे।

नहीं है। अन्य व्यक्तियों का मत है कि कृषि में यन्त्रीकरण के अपनाने से भूमि की उत्पादकता, श्रम की मांग एवं रोजगार में वृद्धि होती है।

कृषि यन्त्रीकरण एवं हरित-क्रान्ति का कृषि-श्रम पर दो प्रकार का प्रभाव होता है—

(1) प्रत्यक्ष प्रभाव—कृषि यन्त्रीकरण के कारण कृषकों को फार्म पर प्रत्यक्ष रूप से अनेक कृषि कार्यों, जैसे—ट्रैक्टर द्वारा खेत की जुताई, रीपर द्वारा फसल की कटाई, ग्रैंसर द्वारा फसल की गहवाई, पम्पिंग सेंट द्वारा फसल की सिंचाई करने में प्रति इकाई भूमि पर श्रम की कम आवश्यकता होती है। दूसरी ओर फार्म पर कृषि यन्त्रीकरण को अपनाने में फसल गहनता में वृद्धि होती है। कृषि कार्य समय पर एवं उचित गहुराई तक हो पाने के कारण प्रति इकाई भूमि से उत्पादन की मात्रा अधिक प्राप्त होती है, जिसके लिए प्रति हेक्टर भूमि पर पहले से अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यन्त्रीकरण का कृषि श्रम पर होने वाला प्रभाव इन दोनों का योग होता है, जो घनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है।

कृषि यन्त्रीकरण एवं तकनीकी ज्ञान एवं उन्नत बीजों के प्रयोग का सम्मिलित प्रभाव कृषि-श्रम की आवश्यकता पर घनात्मक होता है, क्योंकि कम अवधि में पकने वाली किस्मों को अपनाने से कृषक भूमि के एक इकाई क्षेत्र से वर्ष 3-4 फसलें सुगमता से लेकर बहु-फसलीय कार्यक्रम अपना लेते हैं। इससे फार्म पर फसल-गहनता एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है।

कृषि यन्त्रीकरण एवं हरित-क्रान्ति का कृषि श्रम पर होने वाले उपर्युक्त प्रभावों को प्रत्यक्ष प्रभावों की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के प्रभावों का प्रति हेक्टर भूमि के क्षेत्र पर सुगमता से आकलन किया जा सकता है।

(2) अप्रत्यक्ष प्रभाव—कृषि यन्त्रीकरण एवं उन्नत बीजों को अपनाने से कृषि-श्रम पर आने वाले दूसरे प्रकार के प्रभाव अप्रत्यक्ष श्रेणी के होते हैं। कृषि-यन्त्रीकरण के उपयोग के लिए कृषि यन्त्रों—ट्रैक्टर, टिलर, रीपर, ग्रैंसर, पम्प आदि अधिक सहाय में निमित्त करने, विक्रय करने एवं उन्हें कार्यगत रखने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता में वृद्धि होती है। इसी प्रकार फार्म पर उन्नत बीजों के अधिक मात्रा में प्रयोग करने से सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशी दवाइयों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना होता है। अतः उत्पादन-साधनों की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति के लिए इनके उत्पादन, विपणन आदि कार्यों के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है जिससे श्रम की कुल आवश्यकता में वृद्धि होती है। इस प्रकार अतिरिक्त श्रम की मात्रा में जो वृद्धि होती है वह अप्रत्यक्ष प्रभाव की श्रेणी में आती है क्योंकि इसके आकलन का कार्य कठिन होता है।

कृषि यन्त्रीकरण एवं हरित-क्रान्ति के कारण कृषि-श्रम की कुल माँग की मात्रा में परिवर्तन के साथ साथ श्रम की विभिन्न समयों में होने वाली माँग में भी परिवर्तन होता है, जिसमें श्रम की कम माँग वाले मौसम एवं अधिक माँग वाले मौसम के रूख में भी परिवर्तन होता है। विभिन्न समय में श्रमिकों की माँग की असमानता भी कम हो जाती है।

कृषि यन्त्रीकरण का कृषि श्रमिकों की माँग पर प्रभाव

कृषि यन्त्रीकरण से कृषि श्रमिकों की माँग पर आने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों में अनेक अध्ययन किये गये हैं। सारणी 4 11 विभिन्न राज्यों में किये गए अध्ययनों के अनुसार कृषि यन्त्रीकरण के कृषि-श्रम पर आने वाले प्रभाव को प्रदर्शित करती है।

सारणी 4 11

कृषि यन्त्रीकरण का कृषि श्रम की माँग पर प्रभाव

(मानव-विवर)

अध्ययन क्षेत्र	प्रति एकड़ श्रम की माँग		श्रम की माँग में परिवर्तन	
	बैलो से कृषित फार्म	ट्रैक्टर से कृषित फार्म	मात्रात्मक	प्रतिशत
1 पंजाब	47 24	38 46	(-) 8 78	(-)18 59
2 दिल्ली	36 00	24 50	(-)11 50	(-)31 83
3 राजस्थान	82 90	52 40	(-)30 50	(-)36 80

- स्रोत (i) S S Grewal & A S Kahlon, Impact of Mechanization on Farm Employment in Punjab, Indian Journal of Agricultural Economics, Vol XXVIII, No 4, October-December, 1972, pp 214-218
- (ii) G Motilal, Economics of Tractor Utilization, Indian Journal of Agricultural Economics, Vol XXVIII No 1, January-March, 1973, pp 96-105
- (iii) S S Acharya, Green Revolution and Farm Employment, Indian Journal of Agricultural Economics, Vol XXVIII, No 3, July-September, 1973, pp 30-45

विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट है कि ट्रैक्टर से कृषित फार्म पर श्रम की माँग वेलो से कृषित फार्म की अपेक्षा कम होती है। कृषि यन्त्रीकरण से श्रम की माँग पंजाब में 19 प्रतिशत, दिल्ली में 32 प्रतिशत एवं राजस्थान में 37 प्रतिशत कम होती है। ट्रैक्टर से कृषित फार्म पर श्रम की माँग में भूमि की जुताई (88.14 प्रतिशत कमी), बुवाई (17.46 प्रतिशत कमी) फसल की गहाई (12.01 प्रतिशत कमी) एवं परिवहन (43.01 प्रतिशत कमी) आदि नियात्रों में कमी आती है। अतः स्पष्ट है कि फार्म पर कृषि यन्त्रीकरण को अपनाने से श्रम की माँग में कमी आती है। लेकिन फार्म पर कृषि यन्त्रीकरण के उपयोग के साथ-साथ बहुफसलीय कार्यक्रम अपनाया जाय तो श्रम की माँग पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है। कृषि में यन्त्रीकरण अपनाने से निम्न उद्योगों में श्रम की आवश्यकता में वृद्धि होती है। यह वृद्धि अधिक मरुया में मशीनों एवं औजारों के निर्माण की आवश्यकता के कारण उत्पन्न होती है। साथ ही इन औजारों एवं मशीनों की देख-रेख एवं मरम्मत के लिए वर्कशाप की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार कृषि में यन्त्रीकरण के फलस्वरूप कुल श्रम की माँग में वृद्धि होती है।

हरित-क्रान्ति का कृषि श्रम की माँग पर प्रभाव

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर अपने प्रतिवेदन में बताया है कि क्षेत्र में अधिक पैदावार देने वाली किस्मों को लेने से देशी किस्मों की अपेक्षा 30 मानव-दिवस प्रति एकड़ प्रति वर्ष श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। इसी प्रकार बहुफसलीय कार्यक्रम को एक एकड़ भूमि-क्षेत्र पर अपनाने से 26 मानव-दिवस श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। सारणी 4.12 विभिन्न अध्ययनों के अनुसार उन्नत बीजों को फार्म पर अपनाने से प्रति एकड़ श्रम की माँग में होने वाले प्रभाव को प्रदर्शित करती है।

उन्नत बीजों को फार्म पर अपनाने से श्रम की माँग में 10 से 40 प्रतिशत वृद्धि विभिन्न जगहों वाले फार्मों पर होती है। सभी जगहों के फार्मों पर उन्नत बीजों को अपनाने से औसतन 20 प्रतिशत कृषि श्रम की आवश्यकता में वृद्धि होती है।

सारणी 4.12

उन्नत बीजों के अपनाने से कृषि धम की माँग पर प्रभाव

(मानव दिवस में)

अध्ययन क्षेत्र	जात का प्रकार	प्रति कृषित एकड़ धम की माँग		धम की माँग में प्रतिशत वृद्धि
		देशी किस्म के बीजों के फार्म पर	उन्नत किस्म के बीजों के फार्म पर	
1	2	3	4	5
1 कोटा (राजस्थान)	लघु जौत	44 20	50 27 (+)	13 73
	मध्यम जौत	52 47	54 97 (+)	4 38
	दीर्घ जौत	39 32	56 60 (+)	43 94
	सभी जात	44 31	53 30 (+)	20 30
2 धमतूसर (पंजाब)	लघु जौत	28 03	33 00 (+)	16 06
	मध्यम जात	26 05	31 03 (+)	19 01
	दीर्घ जौत	26 09	29 08 (+)	10 08
3 कानपुर (उत्तरप्रदेश)	सभी जौत	69 00	85 00 (+)	22 25
4 उदयपुर (राजस्थान)	सभी जौत	60 08	82 09 (+)	36 03

- स्रोत (1) R A Yadava, Impact of High Yielding Varieties on Farm Incomes, Employment and Resources Productivity in Kota District (Rajasthan) Unpublished M Sc Ag (Agri Economics), Thesis, University of Udaipur, 1974
- (2) J S Chawla, S S Gill and R. P Singh, Green Revolution, Mechanization and Rural Employment-A Case Study in Amritsar, District, Indian Journal of Agricultural Economics, Vol XXVII, No 4, October-December, 1972
- (3) R I Singh, R Kunwar and Shri Ram, Impact of New Agricultural Technology and Mechanisation on Labour Employment, Indian Journal of Agricultural

(4) S S Acharya, Op cit

कृषि यन्त्रीकरण एवं हरित-क्रान्ति का कृषि श्रम पर सम्मिलित प्रभाव

कृषि यन्त्रीकरण एवं हरित-क्रान्ति के सम्मिलित रूप से कृषि-श्रम पर होने वाले प्रभाव को निश्चित रूप से कहना कठिन है। इसके कृषि-श्रम पर शुद्ध प्रभाव घनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों पाये गये हैं। पत्राव एवं हरियाणा प्रान्तों में किये गये अध्ययनों के परिणामों के अनुसार वर्ष 1968-69 में उन्नत बीजों को फार्म पर अपनाने से श्रम की माँग में 6 प्रतिशत वृद्धि तथा फार्म पर पम्पिंग सैंट, ट्रैक्टर एवं ट्रंकटर के उपयोग से श्रम की माँग में 13 प्रतिशत की कमी हुई है, लेकिन फार्म पर उन्नत बीजों एवं यन्त्रीकरण के सम्मिलित उपयोग से श्रम की माँग में 5.5 प्रतिशत कमी हुई है।

राजस्थान के उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में वर्ष 1971-72 में किये गये अध्ययन²⁵ के अनुसार यदि कृषक फार्म पर 35 प्रतिशत क्षेत्रफल उन्नत किस्म के बीजों के अन्तर्गत लेते हैं तो कृषि-श्रम की माँग में 36.3 प्रतिशत वृद्धि होती है। फार्म पर सिंचाई के लिए पम्पिंग सैंट लगाने से श्रम की माँग में 27.6 प्रतिशत कमी होती है। फार्म पर उन्नत बीजों एवं पम्पिंग सैंट को साथ-साथ लेने से कृषि-श्रम की माँग में 8.7 प्रतिशत वृद्धि होती है। चूँकि फार्म पर सिंचाई के लिये पम्प लगाने से फसल गहनता में वृद्धि होना स्वाभाविक है। अतः श्रम की माँग में 23.3 प्रतिशत की वृद्धि होती है। फार्म पर ट्रंकटर के उपयोग से कृषि-श्रम की माँग में 50.1 प्रतिशत की कमी होती है, लेकिन ट्रंकटर के उपयोग के साथ कृषि क्षेत्र का 50 प्रतिशत क्षेत्रफल उन्नत बीजों के अन्तर्गत लेने से श्रम की माँग में होने वाली कमी मात्र 13.4 प्रतिशत ही रह जाती है। फार्म पर फसल-गहनता में वृद्धि होने से कृषि-श्रम की शुद्ध माँग में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि होती है। अतः फार्म पर यन्त्रीकरण के अपनाने से श्रम की माँग पर विपरीत प्रभाव, उन्नत बीजों के उपयोग का घनात्मक प्रभाव तथा इन दोनों के साथ-साथ उपयोग एवं फसल गहनता में वृद्धि के होने से श्रम की माँग पर घनात्मक प्रभाव आता है।

देश में मात्र यन्त्रीकरण को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। यन्त्रीकरण के साथ-साथ उन्नत बीजों का उपयोग एवं फसल-गहनता में वृद्धि के उपाय भी अपनाये जाने चाहिए। इनके सम्मिलित उपयोग से श्रम की माँग में वृद्धि होगी और देश में व्याप्त बेरोजगारी कम होगी।

25 S S Acharya, Green Revolution and Farm Employment, Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. No XXVIII, No 3 July-September, 1973, pp 30-45

कृषि श्रमिकों का प्रवासन

(Migration of Agricultural Labourers)

कृषि श्रमिकों में प्रवासन से तात्पर्य व्याप्त बेरोजगारी काल में रोजगार प्राप्ति के लिए ग्राम से दूर स्थानों पर कार्य के लिए श्रमिकों के जाने से है। देश के अधिकांश कृषि मजदूर गरीबी, अशिक्षा, शहरों में कार्य एवं रहने महन में आने वाली कठिनाई आदि कारणों से मजदूरी प्राप्ति के लिए ग्राम से दूर स्थानों पर कार्य के लिए जाने को तैयार नहीं होते हैं। गाँवों में श्रमिक कार्य उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण वर्ष में काफी समय बेकार रहते हैं। श्रमिकों का शहर में उद्योगों एवं अन्य व्यवसायों में कार्य करने के लिए प्रवासन नहीं होने के कारण गाँवों में अधिक सहाय में श्रमिक पाये जाते हैं। श्रमिकों की माँग उनकी पूर्ति की प्रवृत्ति कम होती है जिसके कारण मजदूरी की दर भी कम होती है एवं रोजगार भी निरन्तर उपलब्ध नहीं होता है। इस प्रकार श्रमिकों में गरीबी बढ़ती जाती है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 25 वें दौर (1970-71)²⁶ में कृषि श्रमिकों के प्रवासन के अध्ययन से स्पष्ट है कि विभिन्न राज्यों में श्रमिकों को गाँव से दूर कार्य करने की इच्छा में बहुत भिन्नता पाई जाती है। उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक 60 प्रतिशत कृषि श्रमिक (पुरुष) एवं 42 प्रतिशत सधु-कृषक (पुरुष) कार्य करने के लिए दूसरे ग्राम अथवा नजदीक के शहर में जाने की इच्छुक है। असम, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में सबसे कम मात्रा में सधु कृषकों (12 से 13 प्रतिशत) एवं कृषि श्रमिकों (16 से 22 प्रतिशत) ने ग्राम से बाहर जाकर कार्य करने की इच्छा प्रकट की है। इसी प्रकार सभी श्रमिकों में सबसे अधिक राजस्थान राज्य (64 प्रतिशत) एवं सबसे कम असम, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश राज्य (2 से 4 प्रतिशत) के श्रमिकों ने बाहर जाकर कार्य करने की इच्छा प्रकट की है। अतः स्पष्ट है कि देश के श्रमिकों में कार्य के लिए प्रवासन की भावना कम पाई जाती है।

पूँजी

पूँजी भी उत्पादन का एक प्रमुख व सक्रिय साधन है। प्रत्येक व्यवसाय को सुचारु रूप से चलाने के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है। पूँजी से तात्पर्य सम्पत्ति के उस भाग से है जो उत्पादन वृद्धि के लिए उपयोग में लाया जाता है। मार्शल के शब्दों में "मनुष्य द्वारा उत्पादित वह सम्पत्ति जो धन को अधिक मात्रा में उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, पूँजी कहलाती है।" पूँजी के अन्तर्गत आने वाली सभी वस्तुएँ धन होती हैं किन्तु धन एवं पूँजी पर्यायवाची शब्द नहीं हैं क्योंकि समस्त उपलब्ध धन पूँजी नहीं होता है।

कृषि पूँजी से तात्पर्य उस सम्पत्ति में है जो कृषक द्वारा फार्म पर उत्पादन करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। जैसे ट्रैक्टर हल, बीज उर्वरक कीटनाशी दवाइयाँ मिचूँ के साधन फार्म, घर आदि। ये सब साधन कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं और इनके न्य पर धन खर्च होता है। कृषक की पूँजी में स्थावर सम्पदा (Real estate) जैसे भूमि बड़ी मशीनें पशु सम्मिलित होते हैं। अनेक अर्थशास्त्री भूमि को पूँजी में सम्मिलित नहीं करते क्योंकि उनका कहना है कि भूमि प्रकृति की देन है। व्यक्तिगत कृषक के लिए भूमि पूँजी होती है। वह उसे क्रय-विक्रय द्वारा कम या अधिक कर सकता है।

कृषि पूँजी अधिग्रहण के स्रोत—कृषकों के पूँजी अधिग्रहण के स्रोत निम्नलिखित हैं—

(1) वशागत कृषि पूँजी अधिग्रहण का प्रमुख स्रोत पूर्वजों की सम्पत्ति में से वशागत कानून के अनुसार हिस्सा प्राप्त करना है। भारतीय कृषि में पूँजी प्राप्त करने का यह प्रमुख स्रोत है। फार्म की अधिकांश पूँजी कृषक पूर्वजों से ही प्राप्त करते हैं।

(2) बचत—पूँजी अधिग्रहण का दूसरा प्रमुख स्रोत फार्म पर की गई बचत की राशि होता है। फार्म पर बचत की मात्रा उत्पाद के मूल्य, फार्म लागत एवं उपभोग खर्च की राशि पर निर्भर करती है। बचत कृषक की शुद्ध परिसम्पत्ति की राशि में वृद्धि करती है। बचत की राशि विभिन्न फार्मों पर विभिन्न मात्रा में होती है। प्रत्येक वर्ष में फार्म में प्राप्त बचत को एकत्रित करने से भारी राशि में पूँजी जमा हो जाती है। बचत के द्वारा फार्म पर आवश्यक राशि से पूँजी एकत्रित करने में बहुत समय लगता है।

(3) पारिवारिक सदस्यों के द्वारा—पूँजी अधिग्रहण की इस विधि में कृषक फार्म के लिए आवश्यक पूँजी परिवार के सदस्यों से ऋण अथवा सहायता के रूप में प्राप्त करते हैं।

(4) निगमोक्ति—पूँजी अधिग्रहण की इस विधि में कृषक आवश्यक राशि में पूँजी उनके द्वारा स्थापित निगम से प्राप्त करते हैं। ये निगम विभिन्न व्यक्तियों से पूँजी शेयर ऋण आदि के रूप में प्राप्त करके कृषकों को आवश्यक मात्रा में ऋण के रूप में प्रदान करते हैं।

(5) भूमि को पट्टे पर देकर—इस विधि में कृषक अपनी अथवा भूमि दूसरे कृषक को पट्टे पर देकर (Leasing of Land) उनसे पूँजी ऋण अथवा अग्रिम लगान के रूप में प्राप्त करते हैं। कुछ वर्षों में बचत द्वारा धन एकत्रित करके कृषक अपनी भूमि को वापिस प्राप्त कर लेते हैं।

(6) क्रय-विक्रय द्वारा—पूँजी अधिग्रहण की इस विधि में कृषक विभिन्न

उत्पादन-साधन के विक्रेताओं से क्रय के इकरार (Purchase Contract) करके पूँजी प्राप्त करते हैं। क्रय-इकरारों के अन्तर्गत कृषक उत्पादन साधन जैसे—हल, मशीन, ट्रैक्टर आदि की कीमत का एक भाग नकद भुगतान करते हैं और शेष राशि का किश्तों में भुगतान करने का वायदा करते हैं। उत्पादन-साधन कृषक के अधिपत्य में रहना है, लेकिन उस पर स्वामित्व विक्रेता व्यापारी का होता है। उत्पादन साधन की कीमत का पूर्ण भुगतान होने पर उसका स्वामित्व व्यापारी द्वारा कृषक के नाम स्थानान्तरित कर दिया जाता है। इस प्रकार कृषक अधिक कीमत वाले उत्पादन साधनों को क्रय करते हैं जो अन्यथा आवश्यक पूँजी के अभाव में एक साथ कीमत का भुगतान करके कृषक द्वारा क्रय कर पाना सम्भव नहीं होता है।

(7) ऋण प्राप्त करके—पूँजी अधिग्रहण की इस विधि में कृषक आवश्यक पूँजी ऋणदात्री संस्थाओं से ऋण के रूप में प्राप्त करते हैं और प्राप्त ऋण को धीरे-धीरे किश्तों में भुगतान करते हैं।

(8) फार्म उत्पादों के विक्रय-इकरारों द्वारा (Sale Contracts)—पूँजी अधिग्रहण की इस विधि में कृषक फार्म पर उत्पादित होने वाले विभिन्न उत्पादों की कटाई के पूर्व भावी सौदा करके उनकी कीमत का एक भाग अग्रिम राशि के रूप में प्राप्त करते हैं। फसल की कटाई होने पर माल व्यापारी का दे दिया जाता है और उससे शेष राशि प्राप्त करनी जाती है। पूँजी प्राप्त करने की यह विधि फलों के बागानों में अधिक प्रचलित है।

पूँजी-संचय—कृषकों द्वारा फार्म पर संचित पूँजी की राशि, फार्म से प्राप्त उत्पाद की कीमत एवं उन पर होने वाली उत्पादन लागत के अतिरिक्त निम्न कारकों पर निर्भर करती है—

(अ) कृषकों की पूँजी-संचय करने की शक्ति—कृषकों की संचित पूँजी एवं उनकी पूँजी-संचय शक्ति में सीधा सम्बन्ध होता है। कृषकों का धरेलू खर्च अधिक होने पर फार्म आय की अधिकता होते हुए भी उनकी पूँजी-संचय करने की शक्ति कम होती है। अतः उनके पास संचित-पूँजी की राशि कम होती है।

(ब) कृषकों में पूँजी-संचय करने की शक्ति—पूँजी-संचय की राशि को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख कारक कृषकों में पूँजी-संचय करने की इच्छा का होना है। विभिन्न व्यक्तियों में पूँजी संचय करने की इच्छा भिन्न-भिन्न होती है। कृषकों में पूँजी-संचय करने की इच्छा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्न हैं—

(i) दूरदर्शिता,

(ii) मितव्ययी स्वभाव,

- (iii) पारिवारिक स्नेह,
- (iv) अधिक प्रेरणा का होना,
- (v) सामाजिक सम्मान की इच्छा ।

(स) पूँजी-संचय करने की सुविधाओं की उपलब्धि—कृषकों में पूँजी संचय की राशि को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक पूँजी-संचय के लिए उपलब्ध सुविधाओं का होना है । क्षेत्र में पूँजी-संचय करने के लिए बैंक या पोस्ट-ऑफिस में जमा करने की सुविधा होने, व्याज की दर की अधिकता, शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था आदि के होने से पूँजी-संचय की राशि अधिक होती है ।

कृषि पूँजी के प्रकार—कृषि पूँजी को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है—

(1) उपयोग के समय के अनुसार—उपयोग के समय की दृष्टि से कृषि पूँजी दो प्रकार की होती है—

(अ) स्थायी/अल्प पूँजी—स्थायी या अल्प पूँजी वह है जो उत्पादन प्रक्रिया में निरन्तर उपयोग में आती रहती है और बहुत समय तक आय प्रदान करती है जैसे—ट्रैक्टर, पशु, फार्म पर त्रय की गई मशीनें, सिंचाई का पम्प, नालियाँ, मेढ आदि में निवेश की गई पूँजी ।

(ब) कार्यगत कार्यशील/चल पूँजी—कार्यशील पूँजी वह है जो उत्पादन प्रक्रिया में एक बार ही उपयोग आती है तथा उसके उपयोग से आय एक ही समय में प्राप्त होती है जैसे—खाद, उर्वरक, श्रमिकों की मजदूरी, बीज आदि में व्यय की गई पूँजी ।

(2) उत्पादकता के अनुसार—उत्पादकता के अनुसार कृषि पूँजी दो प्रकार की होती है—

(क) उत्पादन पूँजी—यह पूँजी का वह रूप है जिसके उपयोग से फार्म उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है, जैसे—बीज, खाद, उर्वरक, ट्रैक्टर बेल आदि में निवेश की गई पूँजी ।

(ख) उपभोग पूँजी—यह पूँजी का वह रूप है जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किया जाता है । उपभोग पूँजी उत्पादन में वृद्धि करने में सहायक नहीं होती है, जैसे—पुस्तकें, भवन, रेडियो, घड़ी एवं वस्त्रों में खर्च की गई पूँजी ।

(3, ब्रैडफोर्ड एवं जोनसन²⁷—ने पूँजी को पाँच श्रेणियों में विभक्त किया है—

(अ) श्रम-प्रतिस्थापन पूंजी (Labour displacing capital)—वह पूंजी जो फार्म पर उत्पादन कार्यों के लिये आवश्यक श्रम-शक्ति को प्रतिस्थापित करने में प्रयुक्त की जाती है, श्रम प्रतिस्थापन पूंजी कहलाती है, जैसे—ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीन, ग्रेसर, रोपर, कुट्टी काटने की मशीन, दूध निकालने की मशीन आदि में निवेश की गई पूंजी ।

(ब) उत्पाद सुधार पूंजी (Product improving capital)—वह पूंजी जो फार्म पर उत्पादित माल के गुणों में सुधार करने के लिये प्रयुक्त की जाती है, उत्पाद सुधार पूंजी कहलाती है, जैसे—घास सुखाने की मशीन (Hay-drier). पास्तुरीकरण मशीन (Pasteurization plant) आदि में निवेशित पूंजी ।

(स) उत्पादवर्द्धक पूंजी (Product increasing capital)—पूंजी का वह रूप जो फार्म पर उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करती है, उत्पादवर्द्धक पूंजी कहलाती है, जैसे—बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशी दवाइयों में खर्च की गई पूंजी ।

(द) उत्पाद परिवर्तक पूंजी (Product converting capital)—पूंजी का वह रूप जो उत्पाद के रूप को परिवर्तित करके नये रूप में बदल देती है, उत्पाद परिवर्तक पूंजी कहलाती है, जैसे—मक्खन निकालने की मशीन, गन्ना पेसने की मशीन, घाटा चक्की आदि में निवेश की गई पूंजी ।

(प) पारिवारिक या घरेलू आवश्यकता की पूंजी (Family or Home maintenance capital)—वह पूंजी जो घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने में प्रयुक्त की जाती है । जैसे—आवास के लिए भवन, मनोरंजन के लिये रेडियो, घड़ी, बर्तन, खाने की वस्तुएँ आदि पर किया गया खर्च ।

(4) अधिग्रहण के आधार पर—अधिग्रहण के आधार पर कृषि-पूंजी दो प्रकार की होती है ।

(अ) उत्पादक की पूंजी—यह वह पूंजी है जो फार्म पर उत्पन्न की जा सकती है, जैसे—पशु, खाद्यान्न आदि ।

(ब) अधिग्रहीत पूंजी—यह वह पूंजी है जो दूसरों से ऋण, लगान या किराये पर लेकर प्राप्त की जाती है । प्राप्त पूंजी के लिये उसके स्वामी को ब्याज, लगान आदि दिया जाता है ।

प्रबन्ध

उत्पादन का चतुर्थ कारक प्रबन्ध है । प्रबन्ध कारक उत्पादन का अमूर्त कारक (Intangible factor) कहलाता है । यह कारक उत्पादन के तीन मूर्त कारकों (Tangible factors) भूमि, श्रम एवं पूंजी को फार्म पर उचित अनुपात में नियोजित करने तथा उनसे उत्पादन की अधिकतम मात्रा प्राप्त करने की व्यवस्था करता है । प्रबन्ध-कार्य करने वाला व्यक्ति प्रबन्धक/व्यवस्थापक कहलाता है ।

कृषि व्यवसाय में कुशल प्रबन्धक की आवश्यकता—उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन कारको—भूमि, धन, पूँजी एवं प्रबन्ध का होना आवश्यक है। प्रत्येक व्यवसाय में उत्पादन की मात्रा मुख्यतया प्रबन्धक की योजना एवं कुशलता पर निर्भर होती है। योग्य प्रबन्धक उद्योग एवं व्यापार में अपनी कुशलता के कारण लाभ जमा लेते हैं। कृषि भी एक व्यवसाय है। कृषि क्षेत्र में भी कुशल प्रबन्धक का होना उद्योगों के समान ही आवश्यक है। कृषि व्यवसाय में अनिश्चिन्ता की अधिकता, कृषि में तकनीकी ज्ञान के प्रसार एवं निरुण्यों की शीघ्रता के कारण प्रबन्धक का महत्व अन्य व्यवसायों की अपेक्षा अधिक होता है। फार्म पर लिये जाने वाले सभी प्रकार के निरुण्य फार्म पर होने वाली लागत एवं प्राप्त आय में परिवर्तन लाते हैं। प्रबन्ध का महत्व लघु एवं बड़े पैमाने के व्यवसाय में समान होता है।

भारत में कृषि को व्यवसाय के रूप में लेकर जीवन-निर्वाह के रूप में लिया गया है। कृषि क्षेत्र में परम्परागत रिवाजों के कारण प्रबन्ध कारक की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन वर्तमान में कृषि जीवन-निर्वाह दृष्टिकोण में व्यापारिक दृष्टिकोण की ओर अग्रसर हो रही है। उत्पादन की विधि में भी परिवर्तन हो रहा है। कृषि में वर्तमान में भूमि एवं पूँजी की सीमितता की अवस्था में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कुशल प्रबन्धक का होना आवश्यक है।

कुशल कृषि प्रबन्धक व्यवस्थापक के कार्य—कुशल कृषि प्रबन्धक के निम्न कार्य होते हैं—

(1) फार्म पर सर्वाधिक लाभ प्रदान करने वाली फसलों का चुनाव करना। इसके लिए कुशल प्रबन्धक को क्षेत्र में उत्पन्न की जाने वाली विभिन्न फसलों के तुलनात्मक लाभ का ज्ञान होना अनिवार्य है।

(2) फार्म पर विभिन्न खण्डों/खेतों के लिए उचित फसल-चक्र का चुनाव करना।

(3) फार्म उत्पादन योजना में विभिन्न उत्पादों के अन्तर्गत क्षेत्रफल निर्धारित करना।

(4) भूमि की उत्पादन क्षमता को बनाये रखते हुए, भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र से अधिकतम उत्पादन की मात्रा प्राप्त करना।

(5) फार्म पर उपलब्ध उत्पादन-साधनों के इष्टतम उपयोग के लिए व्यवसाय की उत्पादन योजना बनाना एवं उसे कार्यान्वित करना।

(6) निर्मित उत्पादन योजना के लिए आवश्यक उत्पादन-साधनों, जैसे उर्वरक, उन्नत बीज, पूँजी, कृषि यन्त्र आदि की व्यवस्था करना, जिससे उत्पादन योजना का कार्यान्वयन किया जा सके।

(7) फार्म पर श्रमिकों की कुशलता एवं क्षमता में वृद्धि के उपाय अपनाना।

(8) उत्पादन क्रिया के लिए आवश्यक ऋण की कम व्याज-दर पर व्यवस्था करना ।

(9) उपज के विक्रय से अधिकतम कीमत की प्राप्ति के लिए विपणन सम्बन्धी निर्णय लेना ।

कुशल प्रबन्धक/व्यवस्थापक के गुण—समान उत्पादन-साधनों की मात्रा वाले विभिन्न फार्मों पर, जो प्रबन्धक फार्म से अधिकतम लाभ की राशि प्राप्त करता है, वह कुशल प्रबन्धक कहलाता है । फार्म पर प्राप्त कुल आय में से फार्म पर होने वाली विभिन्न प्रकार की लागत को घटाने पर जो राशि शेष रहती है, वह लाभ कहलाती है । लाभ की यह राशि प्रबन्धक को अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त होती है । एक कुशल प्रबन्धक में निम्न गुणों का होना आवश्यक है—

- (1) दूरदर्शिता,
- (2) अमिकों के मनोविज्ञान की जानकारी,
- (3) व्यवसाय का विशिष्ट ज्ञान,
- (4) व्यवसाय का अनुभव एवं प्राप्त प्रशिक्षण,
- (5) विश्वसनीयता एवं ईमानदारी,
- (6) समयनिष्ठता ।

शिक्षा प्रबन्धक के ज्ञान में वृद्धि करती है । अनुभव तथा शिक्षा के आधार पर निर्णय लेने में परिपक्वता आती है जो कृषक-प्रबन्धक को उत्पादन-साधनों से लाभ की अधिकतम राशि उपलब्ध कराती है ।

फार्म-प्रबन्ध—परिभाषा एवं क्षेत्र

फार्म-प्रबन्ध, फार्म एव प्रबन्ध शब्दों के समन्वय से बना है। अतः फार्म-प्रबन्ध शब्द को परिभाषित करने से पूर्व फार्म एव प्रबन्ध शब्दों को परिभाषित करना आवश्यक है।

फार्म

फार्म वह क्षेत्र अथवा भूमि का खण्ड है जो फसल उत्पादन अथवा पशुपालन के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिस पर एक कृषक अथवा अनेक कृषकों का सम्मिलित रूप से स्वामित्व होता है और जिसकी सीमा निश्चित होती है। विभिन्न विद्वेषज्ञों ने फार्म शब्द को विभिन्न शब्दों में परिभाषित किया है। उनमें से प्रमुख परिभाषाएँ निम्न हैं—

जॉनसन¹—फार्म से तात्पर्य उस स्थान से है जहाँ पर या तो कुछ एकर क्षेत्र में फसलें उगाई जाती हैं या कुछ पशु पाले जाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उस भूमि पर फसल उत्पादन अथवा पशुपालन करने वाला कृषक की श्रेणी में आता हो।

चौहान²—भूमि के एक या अनेक खण्ड जो कृषि उद्यम की एक इकाई के रूप में एक ही प्रबन्ध के अन्तर्गत संचालित किये जाते हों, फार्म कहलाते हैं।

1. "Almost any place that raises a few acres of crops or a few heads of livestock is commonly regarded as a farm, even though the person living there may not consider himself a farmer"

—Sherman E Johnson, Neil W Johnson, Martin R. Cooper, Orlin, J. Scoville, Samuel W Mendum, Managing A Farm, D Von Nostrand Company, INC, New York, 1946, P 15

2. "A piece or pieces of land operated as single unit of agriculture enterprise under one management"

—D, S Chauhan, Agricultural Economics, Lakshmi Narain Agarwal, Agra, P 57.

एडम्स³—वैधानिक रूप से फार्म से तात्पर्य उस भूमि के क्षेत्र से है जिसका स्वामित्व एक व्यक्ति के पास होता है और भूमि का वह क्षेत्र, फसलें उगाने या चरागाह के रूप में काम में लिया जाता है। इसके अन्तर्गत कई एकड़ क्षेत्र के एक या अनेक क्षेत्र भी हो सकते हैं।

एडम्स द्वारा फार्म की दी गई उपर्युक्त परिभाषा सभी रूपों (क्षेत्र, स्वामित्व एवं उपयोग) में पूर्ण होने के कारण वैधानिक परिभाषा के रूप में स्वीकार की जाती है।

पारिवारिक फार्म

फार्म एवं पारिवारिक फार्म में अन्तर होता है। पारिवारिक फार्म को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है

योजना आयोग⁴ ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में पारिवारिक फार्म को निम्न शब्दों में परिभाषित किया था—

‘पारिवारिक फार्म से संक्षेप में तात्पर्य भूमि के उस समतुल्य क्षेत्र से है जो स्थानीय परिस्थितियों एवं कृषि की वर्तमान प्रचलित विधियों के अनुसार एक हल की इकाई या ग्रासत परिवार के लिए कार्य इकाई के समान हो तथा उस फार्म पर आवश्यक कृषि कार्यों में दूसरों की सहायता न ली जा सकती हो।’

कांग्रेस कृषि सुधार समिति⁵ ने अपनी रिपोर्ट में वर्ष 1951 में पारिवारिक फार्म को परिभाषित करते हुए लिखा है कि वह क्षेत्र अथवा भूमि का खण्ड जो वृषको को 1,600 रु प्रतिवर्ष की समग्र आय अथवा 1,200 रु प्रतिवर्ष की शुद्ध आय प्रदान करता हो और उसका क्षेत्र एक हल की इकाई से कम नहीं हो।

पारिवारिक फार्म की उपर्युक्त परिभाषा वर्ष 1951 में दी गई थी। वर्तमान कीमतों के सूचकांक के आधार पर 1,200 रु प्रतिवर्ष की शुद्ध आय एक ग्रासत परिवार के जीवन निर्वाह के लिये पर्याप्त नहीं होती है। अतः आय की यह मात्रा स्थायी नहीं है, बल्कि इससे तात्पर्य है कि एक पारिवारिक फार्म, कृषक एवं उसके परिवार को आय की वह मात्रा प्राप्त कराना हो जिससे उसके रहन सहन का उचित स्तर बना रहे। आय की राशि कीमतों के सूचकांक में परिवर्तन के अनुसार

3 ‘Legally a farm generally means an area of land under single ownership and devoted to agriculture either to raising crops or for pasturage. It may consist of a number of acres of one field or many fields.’

—R. L. Adams Farm Management 1912, p 694

4 “A family farm may be defined briefly as being equivalent according to the local conditions and under the existing conditions of techniques, either to a plough unit or of a work unit for a family of average size working with such assistance as is customary in agricultural operation. First Five Year Plan Planning Commission, Government of India New Delhi, p 189

5 Congress Agrarian Reforms Committee, A. I. C. C 1951

परिवर्तित होती है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में परिवार के लिये उचित जीवन-स्तर प्रदान करने के लिये आवश्यक आय को राशि में भिन्नता होती है। अतः उचित जीवन स्तर के लिये आवश्यक आय की मात्रा में विभिन्नता के कारण पारिवारिक फार्म के क्षेत्र में काफी विभिन्नता पायी जाती है।

प्रबन्ध

प्रबन्ध से तात्पर्य किसी भी कार्य को करने अथवा प्रबन्ध करने की कला से है। प्रबन्ध की आवश्यकता सभी उद्योगों में समान रूप से होती है।

कृषि उत्पादन के लिये भूमि, श्रम, पूँजी एवं प्रबन्ध कारकों की आवश्यकता होती है। उत्पादन के प्रथम तीन कारकों को मूलतः कारक एवं चतुर्थ कारक प्रबन्ध को उत्पादन का अमूल्य कारक कहते हैं। फार्म पर मूलतः कारकों की बहुतायत होते हुए भी प्रबन्ध कारक के अभाव में उत्पादन कम प्राप्त होता है। फार्म से प्राप्त उत्पादन की मात्रा विभिन्न फार्मों पर अन्य उत्पादन साधनों से समान होने पर भी प्रबन्ध-क्षमता की विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न पाया जाता है। प्रबन्धकर्ता में पायी जाने वाली प्रबन्ध क्षमता की कला ईश्वरीय देन होती है। प्रशिक्षण द्वारा प्रबन्धकर्ता की इस क्षमता में वृद्धि की जा सकती है।

फार्म-प्रबन्ध

फार्म प्रबन्ध—कृषि अर्थशास्त्र विज्ञान का एक भाग है जिसमें उत्पादन के सीमित साधनों से अधिकतम लक्ष्यों की पूर्ति की विधि का समावेश होता है। कृषि के व्यावसायिक सिद्धान्तों एवं कृषि-कार्यों की पद्धतियों द्वारा फार्म इकाई से अधिकतम सम्भावित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से फार्म प्रबन्ध का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा फार्म-प्रबन्ध की दी गई परिभाषाओं में बहुत भिन्नता है। फार्म प्रबन्ध की प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा दी गई परिभाषाएँ निम्न हैं—

प्रे⁶—“फार्म प्रबन्ध से तात्पर्य फार्म का सुव्यवस्थित ढंग से प्रबन्ध करने से है जिसे लाभ की राशि के अनुसार आका जाता है।”

एफरसन⁷—“कार्यक्षमता को बनाये रखने एवं निरन्तर लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य से फार्म के संगठन एवं संचालन का विज्ञान फार्म प्रबन्ध कहलाता है।”

6 “The art of managing a farm successfully as measured by the test of profitableness is called farm management

—Gray L. C, Introduction to Agricultural Economics, Macmillan & Company Newyork, 1924 P 3

7 The science which considers the organization and operation of the farm from the point of view of efficiency and continuous profit,

—J. N Efferson, Principles of Farm Management, McGraw Hill Book Company INC, Newyork, 1953, P 5,

हुडलसन⁸—“कृषि प्रबन्ध या अन्य उद्योगों के प्रबन्ध का मुख्य तात्पर्य उचित समय पर सही निर्णय लेने तथा लिए गए निर्णयों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने से है।”

इलेक⁹—“फार्म प्रबन्ध में संगठन, संचालन, वय-वित्त एवं वित्तीय व्यवस्था सम्मिलित होती है।”

ब्रैंडफोर्ड एवं जॉनसन¹⁰—फार्म-प्रबन्ध, निम्न पाँच कार्यों के करने का विज्ञान है — (1) व्यवसायिक, (2) विश्लेषण, (3) निर्णय लेना, (4) लिये गये निर्णयों को कार्यान्वित करना, एवं (5) निर्णयों के परिणामों का दायित्व वहन करना।

हेडी एवं जैरसन¹¹—“फार्म-प्रबन्ध व्यवसाय के एक भाग के रूप में फार्म पर सीमित साधनों के आवंटन सम्बन्धी विकल्पों के निर्णयों का विज्ञान है।”

एडम्स¹²—“फार्म प्रबन्ध का तात्पर्य विषय के रूप में, व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक प्रवृत्तियों के परिणामों के ज्ञान को कृषि में निरन्तर अधिकतम लाभ की प्राप्ति के लिए उपयोग करना है तथा कार्यविधि के रूप में, फार्म प्रबन्ध से तात्पर्य अधिकतम सम्भावित लाभ की प्राप्ति के लिए फार्म पर उद्यमों के चुनाव, संगठन तथा संचालन में आर्थिक सिद्धान्तों के आचार पर निर्णय लेने से है।”

- 8 “Management in farming or any other business consists chiefly in making correct decisions at the right time and then seeing that these decisions are carried to successful completion.”

—R. H. Hudelson, Farm Management

- 9 “These questions can best be considered under the heads of organization, operation, buying & selling and financing to include all four of these.”

—J. D. Black, Farm Management, The Macmillan & Company, New York, 1947

- 10 L A Bradford & G L Johnson Farm Management Analysis John Wiley & Sons INC, New York, 1960, p 7

- 11 ‘Farm Management as the sub-division of economics which considers the allocation of limited resources within the individual farm is a science of choice and decision making’

—E O Heady & H R Jensen Farm Management Economics Prentice Hall of India (Private) Ltd, New Delhi, 1964 p 6

- 12 “Farm Management—The subject is the presentation of business and Scientific findings in their application to farming for the purpose of indicating the way to greatest continuous profit Farm Management—The method is the utilisation of sound principles in the selection, organisation and conduct of an individual farm business for the purpose of obtaining the greatest possible profit.

—R. L. Adams Farm Management, 1912

टण्डन एवं ठोंढियाल¹³—फार्म-प्रबन्ध कृषि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो कृषक द्वारा धनोपार्जन करने व धन के व्यय करने की प्रवृत्तियों का, फार्म की इकाई के संगठन व संचालन के साथ विपणन के सभी पहलुओं या कुछ कृषि-कार्यों का अध्ययन भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाये रखते हुए निरन्तर अधिकतम लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य से करती है।

फार्म-प्रबन्ध की उपर्युक्त परिभाषाओं में लेखकों ने विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया है। लेकिन शब्दों की विभिन्नता होते हुए भी उपर्युक्त परिभाषाओं में काफी समानता है। सभी लेखकों ने फार्म पर उपलब्ध सीमित साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करके फार्म से अधिकतम लाभ की निरन्तर प्राप्ति पर जोर दिया है।

फार्म-प्रबन्ध के उद्देश्य

फार्म-प्रबन्ध का मुख्य उद्देश्य फार्म पर लिए जाने वाले विभिन्न उद्यमों से कृषक को अधिकतम शुद्ध लाभ प्राप्त कराना है। कृषक का उद्देश्य फार्म पर लिए जाने वाले किसी एक उद्यम से अधिकतम लाभ प्राप्त करना न होकर, लिए जाने वाले सभी उद्यमों से अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है, क्योंकि फार्म विभिन्न उद्यमों का एक सामूहिक रूप होता है। उपर्युक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए फार्म पर विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय लिये जाने चाहिये। किसी भी निर्णय के गलत होने पर फार्म से प्राप्त कुल लाभ की मात्रा कम हो जाती है। फार्म से निरन्तर अधिकतम लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य के लिए फार्म-प्रबन्ध में निम्नांकित अध्ययन किया जाता है—

- (i) कृषि-क्षेत्र में उत्पादन के साधन एवं प्राप्त उत्पाद में पारस्परिक सम्बन्ध एवं विभिन्न उत्पादन-साधनों की अपेक्षित कार्यक्षमता बनाये रखने का अध्ययन।
- (ii) फार्म के लिए फसल-उत्पादन एवं पशुपालन की उत्तम विधि का चुनाव।
- (iii) विभिन्न उद्यमों की प्रति इकाई उत्पादन लागत का अध्ययन।
- (iv) विभिन्न उद्यमों से प्राप्त लाभ का तुलनात्मक अध्ययन।

13. "Farm Management is a branch of agricultural economics which deals with wealth getting and wealth spending activities of a farmer in relation to the organization and operation of the individual farm unit including some or all the functions of marketing for securing the maximum possible net income consistent with the maintenance of soil fertility"
—R. K. Tandon and S. P. Dhondyal, *Principles and Methods of Farm Management*, Achal Prakashan Mandir, Kanpur, 1964, p. 20.

(v) ज़ोन के आकार से भूमि उपयोग, फसल-क्रम योजना व पूँजी-निवेश का सम्बन्ध ।

(vi) तकनीकी ज्ञान का फार्म व्यवसाय एवं उत्पादन पर प्रभाव ।

(vii) उत्पादन साधनों एवं भूमि उपयोग का भूतयाकन ।

(viii) फार्म व्यवसाय की कार्य क्षमता में वृद्धि के उपाय ।

फार्म प्रबन्ध के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपर्युक्त अध्ययन कृषकों को निम्न निर्णय लेने में सहायता देते हैं

(i) फार्म पर अधिकतम उत्पादन कैसे प्राप्त करें ?

(ii) प्राप्त उत्पादन की अधिकतम कीमत कैसे प्राप्त करें ?

(iii) प्रति हैक्टर/क्विन्टल खाद्यान्न उत्पादन की लागत कैसे कम करें ?

(iv) सम्पूर्ण फार्म व्यवसाय से अधिकतम शुद्ध लाभ कैसे प्राप्त करें ?

अधिकतम लाभ की प्राप्ति कृषकों का महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हुए भी अन्तिम उद्देश्य नहीं होता है । कृषकों का अन्तिम उद्देश्य रहन-सहन के स्तर में वृद्धि एवं परिवार के सदस्यों को अधिकतम सन्तोष प्रदान करना होता है । रहन-सहन के स्तर में सुधार एवं सदस्यों को सन्तोष फार्म से अधिकतम लाभ करने पर ही प्राप्त हो सकता है । फार्म के सफल संचालन के लिए प्रबन्धक को फार्म प्रबन्ध का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है । फार्म के सफल संचालन से तात्पर्य फार्म से प्राप्त आमदनी से परिवार के सदस्यों को अधिकतम सन्तोष प्राप्त कराना है ।

अनिश्चितता के वातावरण में फार्म प्रबन्ध का योगदान

कृषि के क्षेत्र में प्रत्येक निर्णय जैसे उत्पादन, कीमतें आदि प्रायः अनिश्चित होते हैं । अनिश्चित कृषि-वातावरण की अवस्था में निरन्तर अधिकतम लाभ की प्राप्ति के लिए फार्म-प्रबन्ध का ज्ञान कृषकों को फार्म पर निम्न कार्यों के करने में सहायक होता है ।

1. कृषि उत्पादों के उत्पादन, उत्पादकता एवं कीमतों के भावी अनुमान लगाना—कृषक फार्म पर विभिन्न उद्यमों के अन्तर्गत क्षेत्रफल के निर्णय प्रचलित कीमतों के आधार पर लेते हैं, लेकिन उत्पादन से प्राप्त होने वाली आय, फसल की कटाई के समय प्रचलित कीमतों पर निर्भर करती है । फसल की कटाई के समय प्राप्त होने वाली कीमतों की सदैव अनिश्चितता बनी रहती है । अतः उत्पादन, उत्पादकता एवं कीमतों का सही आकलन करना आवश्यक होता है । फार्म-प्रबन्ध ज्ञान इनके आकलन करने में सहायक होता है ।

2 कृषि उत्पादों के अनुमानित उत्पादन, उत्पादकता व कीमतों को प्राप्त करने के लिए फार्म-योजना बनाना—फार्म-प्रबन्ध के दूसरे कार्य के अन्तर्गत फार्म-योजना तैयार करना जाना है ताकि निर्धारित लक्ष्य कृषकों को प्राप्त हो सके।

3. निमित्त फार्म-योजना को फार्म पर कार्यान्वित करना फार्म-योजना में प्राप्त होने वाले लाभ की राशि योजना को कार्यान्वित करने पर निर्भर करती है। फार्म-योजना को कार्यान्वित करने में फार्म-प्रबन्ध ज्ञान सहायक होना है।

4 फार्म-योजना को कार्यान्वित करने से होने वाले सम्भावित लाभ अथवा हानि को बहुत करना—सामान्यतः फार्म योजना को कार्यान्वित करने पर उपर्युक्त निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार लाभ प्राप्त होता है। मौसम अथवा कीमतों की प्रतिकूलता की अवस्था में फार्म-योजना से हानि भी हो सकती है। अतः फार्म-योजना को कार्यान्वित करने से होने वाले लाभ/हानि भी फार्म-प्रबन्धक को बहुत करना होता है।

फार्म-प्रबन्ध का कृषि-विज्ञान के अन्य विषयों में सम्बन्ध.

फार्म-प्रबन्ध विज्ञान, कृषि अर्थशास्त्र विज्ञान का एक भाग है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक फार्म पर किये जाने वाले सभी कृषि कार्यों को करने में आर्थिक दृष्टि से निर्णय लिए जाते हैं। कृषि विज्ञान के अन्य विषयों के अन्तर्गत भी विषय-सम्बन्धी समस्या का निर्णय लिया जाता है। फार्म-प्रबन्ध विज्ञान एवं कृषि-विज्ञान के अन्य विषयों में निम्न अन्तर होता है :

1 फार्म-प्रबन्ध-विज्ञान फार्म पर कृषि क्रियाओं को करने से प्राप्त होने वाले लाभ की राशि का ज्ञान प्रदान करता है जबकि कृषि विज्ञान के अन्य विषय फार्म पर क्रियाओं को करने का ज्ञान ही प्रदान करते हैं। जैसे फसल विज्ञान फार्म पर फसलों का चुनाव, पौधों की दूरी, फसल-चक्र आदि के निर्णय का ज्ञान, मृदा विज्ञान फसल के लिए आवश्यक उर्वरकों की मात्रा व प्रयोग की विधि का ज्ञान, पौध-व्याधि विज्ञान फसलों की बीमारियों की रोकथाम के लिए रोगनाशक दवाइयों की मात्रा व प्रयोग विधि का ज्ञान तथा कीट-विज्ञान फसलों पर लगने वाले कीड़े मकौड़ों की रोकथाम के लिए कीटनाशक दवाइयों की मात्रा व विधि का ज्ञान कृषकों को प्रदान करता है। कृषि-विज्ञान के उपर्युक्त विभिन्न विषय अशुभ विधि के फार्म पर प्रयोग से प्राप्त होने वाले लाभ की विस्तृत विवेचना नहीं करते हैं। फार्म-प्रबन्ध-विज्ञान फार्म पर लिए जाने वाले प्रत्येक निर्णय से होने वाले लाभ एवं उसकी लागत का ज्ञान प्रदान करता है।

2. फार्म-प्रबन्ध-विज्ञान के अन्तर्गत निर्णय लेने के लिए प्रत्येक कृषक के फार्म को एक पृथक् इकाई के रूप में मानते हैं जिससे विभिन्न कृषकों

के पास समान मात्रा में उत्पादन साधन होते हुए भी फार्म पर होने वाली समस्याओं के लिए एक ही निर्णय प्रस्तावित नहीं किया जाता है। कृषि विज्ञान के अन्य सभी विषयों में क्षेत्र के सभी कृषकों की समस्याओं के लिए एक ही निर्णय प्रस्तावित किया जाता है। उदाहरणतया फसल-वैज्ञानिक अमुक क्षेत्र में गेहूँ की हीरा किस्म उगाने, मृदा-वैज्ञानिक गेहूँ की फसल में अमुक क्षेत्र में 00 किलोग्राम नत्रजन उर्वरक डालने, पौध संरक्षण विशेषज्ञ बीमारियों एवं कीड़ों की रोकथाम के लिए अमुक कीटनाशी दवा के प्रयोग करने का अनुमोदन करता है, लेकिन फार्म-प्रबन्ध विशेषज्ञ प्रत्येक कृषक के फार्म के लिए पृथक् फार्म-योजना तैयार करता है।

- 3 फार्म-प्रबन्ध एक संयोजन करने वाला विज्ञान (Integrating Science) है जिसके अन्तर्गत प्रबन्धक फार्म को एक इकाई मान कर संचालन करता है। कृषि-विज्ञान के अन्य विषय अपनी समस्याओं के हल करने के निर्णय लेने तक ही सीमित होते हैं। जैसे पौध-व्याधिविज्ञान फसलों की बीमारियों की रोकथाम, कीट-विज्ञान फसलों की कीड़ों से रक्षा के उपाय, फसल विज्ञान फसलों की किस्म एवं उनके चुनाव का निर्णय देने तक सीमित रहते हैं। लेकिन फार्म-प्रबन्ध विज्ञान में कृषि के सभी विषयों के ज्ञान को सम्मिलित करके फार्म को एक इकाई मानते हुए निर्णय लिए जाते हैं जिससे सम्पूर्ण फार्म में अधिकतम लाभ की राशि प्राप्त हो सके। अतः फार्म-प्रबन्ध, कृषि-विज्ञान के विभिन्न विषयों के ज्ञान को फार्म पर एक साथ प्रयोगित करके अधिक लाभ की प्राप्ति की योजना बनाता है।
- 4 फार्म-प्रबन्ध एक प्रायोगिक अध्ययन है जिसके अन्तर्गत कृषकों को कृषि विधियों को अपनाने से होने वाली लागत एवं उससे प्राप्त सम्भावित लाभ की राशि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जबकि कृषि-विज्ञान के अन्य विषयों के अन्तर्गत विभिन्न कृषि-कार्यों को करने की विधि का ज्ञान ही प्रदान किया जाता है।

फार्म-प्रबन्ध एवं कृषि-अर्थशास्त्र में सम्बन्ध :

कृषि-अर्थशास्त्र, कृषि-विज्ञान की एक शाखा है जिसके अन्तर्गत कृषकों द्वारा धन-प्राप्ति एवं धन के व्यय की क्रियाओं के अध्ययन का समावेश होता है। फार्म-प्रबन्ध, कृषि-अर्थशास्त्र का एक भाग है जिसके अन्तर्गत अधिकतम लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य से फार्म के प्रबन्ध का ज्ञान सम्मिलित होता है। फार्म-प्रबन्ध एवं कृषि-अर्थशास्त्र के अध्ययन में निम्न स्तर पाये जाते हैं—

1. कृषि-अर्थशास्त्र, कृषि-विज्ञान की एक शाखा है जबकि फार्म-प्रबन्ध,

- कृषि-अर्थशास्त्र की अन्य शाखाओं जैसे उत्पादन-अर्थशास्त्र, कृषि-वित्त, कृषि-वित्त, ग्रामीण अर्थशास्त्र के समान एक शाखा है।
- 2 फार्म-प्रबन्ध के अध्ययन की इकाई एक फार्म होती है जबकि कृषि-अर्थशास्त्र के अध्ययन की इकाई कृषक समूह अथवा कृषक समाज होता है। कृषि-अर्थशास्त्र फसल-उत्पादन, पशुपालन, कृषि की उन्नत विधियों के ज्ञान के आधार पर देश या क्षेत्र के कृषकों के हितों की समग्र रूप में व्याख्या करता है। फार्म प्रबन्ध एक ही फार्म या कृषक के लिए उप-युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति की व्याख्या करता है।
 - 3 फार्म-प्रबन्ध का उद्देश्य प्रत्येक कृषक को अपने फार्म से अधिकतम निरन्तर लाभ की राशि प्राप्त कराना है जबकि कृषि-अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्षेत्र के कृषकों को अधिकतम लाभ की राशि प्राप्त कराते हुए उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार एवं कल्याण की मनोकामना करना है।
 - 4 अध्ययन की दृष्टि से कृषि-अर्थशास्त्र समष्टिमूलक तथा फार्म-प्रबन्ध व्यष्टिमूलक होता है।

फार्म-प्रबन्ध का क्षेत्र

फार्म-प्रबन्ध का क्षेत्र व्यापक है जिसमें निम्न ज्ञान सम्मिलित होता है —

- 1 फार्म प्रबन्ध का क्षेत्र व्यष्टिमूलक (Micro economic) होता है। इसमें प्रत्येक फार्म को पृथक् इकाई मानकर निम्न लिया जाता है। अतः फार्म पर लिए जाने वाले विभिन्न निर्णय जैसे फसलों का चुनाव, उर्वरकों का प्रयोग, कृषि यन्त्रों का उपयोग आदि क्रियाएँ फार्म-प्रबन्ध के क्षेत्र में सम्मिलित होती हैं।
2. फार्म-प्रबन्ध में अनुसन्धान, प्रशिक्षण एवं प्रसार नामक तीनों क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं। कृषकों की विभिन्न आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए अनुसन्धान करना होता है। आर्थिक अनुसन्धान के लिए आवश्यक आकड़े सर्वेक्षण-विधि द्वारा एकत्रित किये जाते हैं। एकत्रित आँकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त अनुसन्धान परिणाम प्रशिक्षण की सहायता से प्रसार-कार्यकर्त्ताओं तक पहुँचाए जाते हैं। प्रसार-कार्यकर्त्ता प्राप्त ज्ञान को प्रसार-विधियों के माध्यम में कृषकों तक पहुँचाते हैं। अतः अनुसन्धान प्रशिक्षण एवं प्रसार तीनों ही फार्म-प्रबन्ध के क्षेत्र में आते हैं।
- 3 फार्म योजना बनाने का कार्य फार्म-प्रबन्ध के क्षेत्र में सम्मिलित है। फार्म पर विभिन्न कृषि कार्यों को करने की फार्म-योजना बनाई जाती है। फार्म-योजना में फार्म पर किये जाने वाले सभी कार्यक्रमों की सूची तैयार की जाती है, जिससे सभी कार्य फार्म पर समय पर एवं बिना किसी

कठिनाई के हो जाते हैं। फार्म-योजना बनाने का ज्ञान फार्म-प्रबन्ध विषय से प्राप्त होता है।

अन उपर्युक्त नश्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि फार्म-प्रबन्ध का क्षेत्र काफी व्यापक होता है।

कृषि-व्यवसाय के सफलता के नियम :

प्रत्येक व्यवसाय की सफलता के लिए कुछ नियम होते हैं जिनके ज्ञान से व्यवसायी अधिकतम लाभ की राशि प्राप्त करता है एवं उसका व्यवसाय सफलीभूत होता है। कृषि भी एक व्यवसाय है, जिसकी सफलता के निम्न तीन नियम हैं, जिनके द्वारा कृषक फार्म से अधिकतम लाभ की राशि प्राप्त कर सकते हैं।¹⁵

1. क्षेत्र की कृषि-क्रियाओं, विधियों एवं कृषि-परिस्थितियों का ज्ञान :

कृषि-व्यवसाय की सफलता के लिए कृषिक-प्रबन्धक को क्षेत्र में विभिन्न फसलों को उत्पादित करने की प्रचलित विधियों एवं क्रियाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। विभिन्न क्षेत्रों में भूमि, जलवायु, आर्पिक एवं सामाजिक कारकों की विभिन्नता के कारण फसलों को उत्पादित करने की क्रियाओं एवं विधियों में बहुत भ्रममानता पायी जाती है। क्षेत्र में कृषि की प्रचलित विधियों के ज्ञान के बिना कृषक व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते हैं। प्रचलित कृषि विधियों एवं क्रियाओं का प्रायोगिक ज्ञान कृषक-प्रबन्धक क्षेत्र के प्रगतिशील कृषकों के फार्म पर देखकर प्राप्त कर सकते हैं। अतः कृषक-प्रबन्धक को कृषि-व्यवसाय की सफलता के लिए सर्वप्रथम क्षेत्र में उत्पन्न की जाने वाली विभिन्न फसलों का प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है।

2. फसल एवं पशुपालन उद्यमों के उत्पादन के वैज्ञानिक सिद्धान्तों का ज्ञान

कृषि व्यवसाय की सफलता का दूसरा नियम क्षेत्र में विभिन्न उद्यमों के उत्पादन से सम्बन्धित वैज्ञानिक, व्यावहारिक एवं तकनीकी ज्ञान का होना है। कृषि में अनुसन्धान के कारण उत्पादन विधियों, फसलों की किस्मों, नए उर्वरकों का उत्पादन, कीटनाशी दवाइयों का आविष्कार, पशु-प्रजनन विधि द्वारा नरल सुधार कार्यक्रम, पशुओं के लिए सन्तुलित आहार में उत्पादन की मात्रा में निरन्तर परिवर्तन हो रहा है। उपर्युक्त विधियों के ज्ञान में निरन्तर परिवर्तन के कारण फार्म से अधिकतम लाभ के लिए कृषकों को प्रचलित तकनीकी विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। कृषक-प्रबन्धक विभिन्न फसलों एवं पशुओं के विषय में वैज्ञानिक ज्ञान, विश्वविद्यालयों, कृषि एवं पशुपालन विभाग, किसान-विद्यापीठ में प्रशिक्षण प्राप्त करके, रेडियो एवं टेलीविजन से आभीष्ट कृषक-कार्यक्रम सुनकर, विभिन्न

पत्रिकाओं का अध्ययन करके एवं समीप के प्रसार-अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करके प्राप्त कर सकते हैं।

3 फार्म-प्रबन्ध से व्यावसायिक सिद्धान्तों का ज्ञान :

कृषि-व्यवसाय की सफलता का तीसरा नियम कृषक-प्रबन्धक को फार्म-प्रबन्ध के व्यावसायिक सिद्धान्तों के ज्ञान का होना है। प्राचीनकाल में प्रबन्ध के व्यावसायिक सिद्धान्तों के ज्ञान की कृषको को आवश्यकता प्रतीत नहीं होती थी, क्योंकि कृषक कृषि को व्यवसाय के रूप में न लेकर जीविका-निर्वाह के रूप में लेते थे, जिसके कारण वे व्यवसाय से प्राप्त लाभ की ओर विशेष ध्यान नहीं देते थे। वर्तमान में कृषक कृषि को व्यवसाय के रूप में लेते हैं। उत्पादन के लिए उत्पादन-साधनों की अधिकांश मात्रा बाजार से ज़रूरतें हैं। अतः वर्तमान में कृषि व्यवसाय से अधिकतम लाभ की प्राप्ति के लिये फार्म-प्रबन्ध के व्यावसायिक सिद्धान्तों का ज्ञान कृषको को होना आवश्यक है। व्यावसायिक सिद्धान्तों का ज्ञान कृषको को फार्म पर निम्न प्रकार के निर्णय लेने में सहायता करता है, जिनसे प्राप्त लाभ की राशि में वृद्धि होती है।

फार्म पर आवश्यक उत्पादन साधन— बीज, खाद, उर्वरक कीटनाशी दवाई आदि किस समय किस सस्था से क्रय करना चाहिए ?

फार्म में प्राप्त उत्पादों को किस समय एवं कौनसी सस्था के माध्यम से विक्रय करना चाहिए ?

फार्म पर उपलब्ध उत्पादन-साधनों का किन उद्देश्यों में उपयोग किया जाना चाहिए जिससे लाभ अधिकतम प्राप्त हो सके ?

उत्पादन की विभिन्न उपलब्ध विधियों में से कौनसी विधि फार्म पर अपनानी चाहिए ? विभिन्न उत्पादन-साधनों की कितनी मात्रा का प्रति हेक्टर भूमि के अनुसार प्रयोग करना चाहिए, जिससे सीमित उत्पादन-साधनों से अधिकतम लाभ की राशि प्राप्त हो सके ?

विभिन्न उद्यमों का, जो आपस में पूरक (complementary), सम्पूरक (supplementary) एवं प्रतिस्पर्धी (competitive) का सम्बन्ध रखते हैं, किस अनुपात में मयोग किया जाए जिससे फार्म से अधिकतम लाभ की राशि प्राप्त हो सके ?

कृषि व्यवसाय की सफलता के लिए व्यावसायिक सिद्धान्त :

कृषि व्यवसाय की सफलता के लिए प्रमुख व्यावसायिक सिद्धान्त निम्न हैं—

1 कीमतों का ज्ञान—कृषको को फार्म से प्राप्त होने वाली आय की राशि, उत्पाद की मात्रा एवं उनकी बाजार कीमत पर निर्भर होती है। कृषि उत्पादों की कीमतों में विभिन्न समयों एवं स्थानों पर बहुत विभिन्नता पाई जाती है। कृषको

को अधिकतम लाभ की प्राप्ति के लिए कीमतों की प्रवृत्ति का ज्ञान होना आवश्यक है। कृषि एक जैविक क्रिया है, जिसके कारण कीमतों में वृद्धि अथवा कमी होने से उत्पादन की मात्रा में सामंजस्य करना कृषको के नियन्त्रण में नहीं होता है। अतः कृषको को फसल के चुनाव एवं उनके अन्तर्गत क्षेत्रफल निर्धारित करते समय उत्पादन काल में कीमतों में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर उत्पादन-सम्बन्धी निर्णय लेने चाहिए।

2 फार्म पर उद्यमों का चुनाव—फार्म पर विभिन्न मौसम में विभिन्न फसल उत्पन्न की जा सकती हैं। प्रत्येक फसल के उत्पादन से विभिन्न राशि में लाभ प्राप्त होता है। अतः कृषको के समस्त समस्या होती है कि फार्म पर कौन-कौन से उद्यमों का चुनाव करे, जिससे लाभ की राशि अधिकतम प्राप्त हो सके। फार्म पर उद्यमों के चुनाव का निर्णय भूमि, जलवायु, उपलब्ध उत्पादन-साधनों की मात्रा, विपणन सुविधा एवं प्राप्त होने वाले शुद्ध लाभ की राशि के आधार पर लेना चाहिए।

3 उद्यमों का फार्म पर संयोग—उद्यमों के चुनाव के पश्चात् विभिन्न उद्यमों को फार्म पर इस प्रकार संयोजित करना चाहिये जिसमें फार्म से अधिकतम लाभ की राशि प्राप्त हो सके। विभिन्न उद्यमों के संयोग करने एवं क्षेत्रफल निर्धारित करने का निर्णय परिवार की छाछात्र आवश्यकता, पशुओं के लिए चारे की आवश्यकता, उद्यमों में आपसी सम्बन्ध—पूरकता, सम्पूरकता अथवा प्रतस्पर्धा आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। जिससे प्रस्तावित उद्यमों में संयोग से लाभ की अधिकतम राशि प्राप्त हो सके।

4 उत्पादन विधि का चुनाव—विभिन्न उद्यमों के उत्पादन अथवा विभिन्न क्रियाओं को करने की अनेक विधियाँ होती हैं। प्रत्येक विधि से कार्य करने पर लागत भिन्न भिन्न आती है। अतः चुने हुए उद्यमों की उत्पादन-लागत में कमी करने के लिए उत्पादन-विधि का चुनाव अधिक आधार पर करना चाहिए।

5 उत्पादन-साधनों का क्रय—कृषको को आवश्यक उत्पादन साधन जैसे—बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशी दवाईयाँ, उन्नत कृषि यन्त्र एवं औजार बाजार से क्रय करने होते हैं। उत्पादन-साधनों की कीमतों में स्थान, समय एवं विपणन संस्था के अनुसार विभिन्नता पाई जाती है। अतः कृषको को निर्णय लेना होता है कि फार्म पर आवश्यक उत्पादन-साधन किस समय, संस्था एवं स्थान से क्रय किया जावे, जिससे उनके क्रय पर कम से कम घन व्यय हो।

■ कृषि उत्पादों का विक्रय—कृषको को प्राप्त होने वाले लाभ की मात्रा फार्म से उत्पादित विभिन्न प्रकार के उत्पादों की मात्रा एवं उनके विक्रय से प्राप्त कीमत पर निर्भर होती है। कृषि उत्पादों की कीमतों के विवरण-मौसम में पूर्ति की अधिकतम एवं माँग की स्थिरता के कारण गिरावट होती है। विवरण-मौसम में विभिन्न मण्डियों में कीमतों में बहुत अन्तर पाया जाता है। विवरण-मौसम की समाप्ति के साथ कीमतों का बढ़ना शुरू होता है। इन सबके कारण विभिन्न समयों

में कृषि उत्पाद के विपणन से प्राप्त कीमतों एवं लाभ की राशि में बहुत अन्तर पाया जाता है। अतः कृषकों को उत्पादित माल के विक्रय से अधिकतम कीमत प्राप्त करने के लिए विपणन सम्बन्धी निर्णय पूरी तरह सोच समझ कर लेना चाहिये।

7 वित्तीय व्यवस्था करना—कृषि-व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है। कृषकों के पास आवश्यक राशि में पूँजी का साधारणतया अभाव होता है। कृषक कृषि कार्यों के लिये विभिन्न स्रोतों से पूँजी ऋण के रूप में उधार लेते हैं। प्रत्येक ऋणदात्री सस्या की ऋण स्वीकृति की शर्तें, व्याज-दर आदि में बहुत विभिन्नता होती है। अतः कम व्याज दर एवं आसान किस्तों पर ऋण की प्राप्ति के लिए कृषकों को उचित ऋणदात्री सस्या का चुनाव करना चाहिये।

8 फार्म से प्राप्त आय का कृषि-व्यवसाय में निवेश करना एवं उसे सुरक्षित रखना—फार्म से प्राप्त आय का कृषि-व्यवसाय में निवेश करने एवं निवेशित आय की सुरक्षा की व्यवस्था का भी कृषकों को ज्ञान होना आवश्यक है। इस ज्ञान के होने से कृषक फार्म से प्राप्त आय का ऐसे व्यवसायों में निवेश करेंगे, जिनसे प्रति रुपया आय अधिक प्राप्त होती है तथा निवेशित व्यवसाय में जोखिम कम होती है।

9 घरेलू आवश्यकता की वस्तुओं का फार्म पर उत्पादन कर। कृषकों को फार्म से लाभ की अधिकतम राशि प्राप्त करने के साथ साथ परिवार के सदस्यों के सन्तोष की ओर भी ध्यान देना होता है। अतः विपणन के लिये विभिन्न फसलों के उत्पादन के साथ साथ परिवार के लिए आवश्यक खाद्यान्न, सब्जी तथा दालों की फसलें भी फार्म पर उत्पादित करनी चाहिये जिससे कृषक के परिवार के सदस्यों को अधिकतम सन्तोष प्राप्त हो सके।

कृषि-व्यवसाय की सफलता के लिए व्यावसायिक सिद्धान्तों के अतिरिक्त फार्म-प्रबन्ध सिद्धान्त का ज्ञान होना भी आवश्यक है। फार्म प्रबन्ध सिद्धान्तों का विवेचन अगले अध्याय में किया गया है।

अध्याय 6

फार्म-प्रबन्ध के सिद्धान्त

फसल तथा पशु-पालन उत्पादन के वैज्ञानिक सिद्धान्तों एवं विधियों की पूर्ण जानकारी होने हुए भी फार्म में अनुकूलतम अथवा इष्टतम लाभ की राशि (Optimum profit) तक प्राप्त नहीं की जा सकती जब तक कृषको को फार्म-प्रबन्ध के सिद्धान्तों का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। फार्म-प्रबन्ध के सिद्धान्तों का ज्ञान कृषको को फार्म पर विभिन्न कृषि कार्यों को करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने में सहायता करता है। उदाहरणतया, फार्म पर विभिन्न फसलों के घन्तर्गत कितना क्षेत्रफल लेना चाहिए? विभिन्न फसलों को किस अनुपात में फार्म पर लेना चाहिए? फार्म पर कौन-कौन से उद्यम अथवा फसलों का चुनाव करना चाहिये? विभिन्न खेतों पर प्रति हेक्टर क्षेत्र में कितनी मात्रा में उर्वरक डालना चाहिये? विभिन्न उत्पादन-साधनों को कब व कितनी मात्रा में क्रय करना चाहिए? उत्पादन के विभिन्न साधनों को किस अनुपात में प्रतिस्थापित करना चाहिये, आदि? इन सब महत्वपूर्ण क्रियाओं के करने से फार्म पर लागत होती है। यदि इन कार्यों को करने में फार्म प्रबन्ध के सिद्धान्तों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाय, तो फार्म पर होने वाली लागत में कमी एवं फार्म से प्राप्त होने वाले लाभ की राशि में वृद्धि होती है। फार्म पर निर्णय फार्म-प्रबन्ध के सिद्धान्तों के ज्ञान के बिना भी लिए जा सकते हैं, परन्तु फार्म प्रबन्ध सिद्धान्तों के ज्ञान के आधार पर निर्णय शीघ्रतापूर्वक लिए जा सकते हैं तथा लिए गये निर्णय सही होते हैं।

फार्म प्रबन्ध के मुख्य सिद्धान्त निम्न हैं—

1. प्रतिफल का सिद्धान्त

(अ) परिवर्तनीय अनुपात का सिद्धान्त,

(ब) पैमाने के प्रतिफल का सिद्धान्त,

2. न्यूनतम लागत का सिद्धान्त अथवा साधनों एवं क्रियाओं के प्रतिस्थापन का सिद्धान्त,

- 3 सम-सीमान्त प्रतिफल का सिद्धान्त अथवा सीमित साधन एवं प्रवसर परिव्यय का सिद्धान्त,
- 4 लागत का सिद्धान्त,
- 5 उद्यमों के संयोग का सिद्धान्त अथवा उद्यमों के प्रतिस्थापन का सिद्धान्त,
- 6 तुलनात्मक समय का सिद्धान्त, एवं
- 7 तुलनात्मक लाभ का सिद्धान्त ।

फार्म पर एक हो निर्णय के लिए एक से अधिक फार्म-प्रबन्ध के सिद्धान्तों का भी प्रयोग किया जाता है । फार्म-प्रबन्ध के सिद्धान्तों का विस्तृत विवरण आगे दिया गया है ।

1. प्रतिफल का सिद्धान्त

प्रतिफल का सिद्धान्त दो प्रकार का होता है—

(अ) परिवर्तनीय अनुपात का सिद्धान्त—परिवर्तनीय अनुपात के सिद्धान्त में उत्पादन के लिए आवश्यक विभिन्न उत्पादन साधनों में से एक या एक से अधिक साधनों की मात्रा में परिवर्तन होता है, जबकि उत्पादन के लिए आवश्यक अन्य सभी साधनों की मात्रा स्थिर रहती है जैसे खरबक की मात्रा में परिवर्तन होता है तथा उत्पादन के लिए आवश्यक अन्य साधन—भूमि का क्षेत्र, सिंचाई की सुविधा, श्रम आदि की मात्रा स्थिर रहती है, अर्थात् इन साधनों की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है—

उत्पादन-साधनों के परिवर्तनीय अनुपात के सिद्धान्त में प्रतिफल तीन दर से प्राप्त होता है—

- (अ) ह्रासमान दर प्रतिफल,
- (ब) सामान दर प्रतिफल,
- (स) वृद्धमान दर प्रतिफल ।

प्रतिफल के सिद्धान्त की विस्तृत व्याख्या करने से पूर्व, सिद्धान्त की स्पष्टता के लिए निम्न शब्दों एवं उनमें आपस में पाए जाने वाले सम्बन्धों की व्याख्या करना आवश्यक है—

कुल उत्पाद—उत्पादन साधन की विभिन्न मात्रा का प्रयोग करने से जो उत्पाद की मात्रा प्राप्त होती है, उसे कुल उत्पाद (Total product) कहते हैं । उत्पादन-साधन की विभिन्न मात्राओं के उपयोग से प्राप्त कुल उत्पादन की मात्रा भी विभिन्न होती है ।

औसत उत्पाद—औसत उत्पाद (Average product) से तात्पर्य उत्पादन-

साधन की औसत उत्पादकता से है। औसत उत्पाद, कुल उत्पाद एवं प्रयुक्त उत्पादन-साधन की मात्रा का अनुपात होता है। उत्पादन साधन की विभिन्न मात्राओं के प्रयोग से प्राप्त होने वाले कुल उत्पाद की मात्रा में उत्पादन-साधन की मात्रा का भाग देने पर प्राप्त प्रतिफल औसत उत्पाद कहलाता है। उदाहरणार्थ यदि भूमि के एक इकाई क्षेत्र में 20 किलोग्राम नम्रजन उर्वरक के उपयोग से 8 क्विण्टल कुल उत्पाद प्राप्त होता है तो प्रति किलोग्राम नम्रजन उर्वरक से औसत उत्पाद $(8 \div 20) = 0.40$ क्विण्टल प्राप्त होता है। अतः सूत्र के अनुसार,

$$\text{औसत-उत्पाद} = \frac{\text{कुल उत्पाद की मात्रा } (Y_1)}{\text{उत्पादन-साधन की कुल मात्रा } (X_1)}$$

सीमान्त उत्पाद—एक इकाई अतिरिक्त उत्पादन-साधन की मात्रा के उपयोग से जो उत्पाद की मात्रा में अतिरिक्त वृद्धि होती है, उसे सीमान्त उत्पाद (Marginal Product) कहते हैं। परिवर्तनशील उत्पादन-साधन के किसी भी स्तर के लिए सीमान्त-उत्पाद, कुल उत्पाद की वृद्धि की मात्रा में, उत्पादन-साधन में की गई वृद्धि की मात्रा का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। सीमान्त उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र निम्न होता है—

$$\text{सीमान्त-उत्पाद} = \frac{\text{कुल उत्पाद की मात्रा में परिवर्तन } (\Delta Y)}{\text{उत्पादन-साधन की मात्रा में परिवर्तन } (\Delta X)}$$

उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि सीमान्त एवं औसत उत्पाद, कुल उत्पाद की मात्रा से ज्ञात किये जाते हैं। उत्पादन-साधन के विभिन्न मात्रा में उपयोग करने से प्राप्त कुल उत्पाद की मात्रा से औसत व सीमान्त-उत्पाद ज्ञात करने की विधि सारणी 6.1 में प्रदर्शित की गई है।

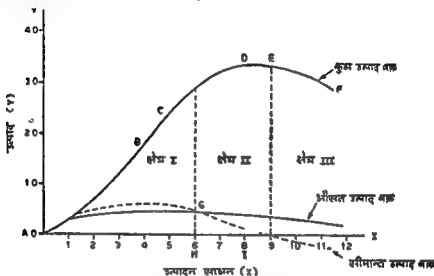
सारणी 61

कुल उत्पाद की मात्रा से सीमान्त एवं औसत उत्पाद
ज्ञात करना

उत्पादन-साधन (उर्वरक) की इकाइयाँ (X)	प्राप्त कुल उत्पाद की मात्रा (Y)	औसत-उत्पाद $\left(\frac{Y_1}{X_1}\right)$	सीमान्त उत्पाद $\left(\frac{\Delta Y}{\Delta X}\right)$	अन्य विवरण
0	0	0		
1	3	3	3	वर्द्धमान दर से उत्पादन में वृद्धि
2	7	3.50	4	
3	12	4.00	5	
4	18	4.50	6	समान दर से उत्पादन में वृद्धि
5	24	4.80	6	
6	29	4.83	5	ह्रासमान दर से उत्पादन में वृद्धि
7	32	4.57	3	
8	33	4.12	1	
9	33	3.66	0	
10	32	3.20	-1	कुल उत्पादन में कमी
11	30	2.72	-2	

उपयुक्त उदाहरण में एक उत्पादन-साधन (उर्वरक) की मात्रा में परिवर्तन होने से प्राप्त कुल उत्पाद, औसत उत्पाद एवं सीमान्त की मात्राएँ प्रदर्शित की गई हैं। इसमें यह मान्यता है कि उत्पादन वृद्धि के लिए आवश्यक अन्य सभी साधनों की मात्राओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

सारणी के आधार पर कुल उत्पाद, औसत उत्पाद एवं सीमान्त उत्पाद वक्र-रेखाएँ चित्र 6.1 में प्रदर्शित की गई हैं।



चित्र 6.1 कुल उत्पाद, सीमान्त उत्पाद एवं औसत उत्पाद में सम्बन्ध एवं उत्पादन फलन के विभिन्न क्षेत्र

कुल उत्पाद एवं सीमान्त उत्पाद में सम्बन्ध—सारणी 6.1 एवं चित्र 6.1 के आधार पर कुल उत्पाद एवं सीमान्त उत्पाद में निम्न सम्बन्ध पाए जाते हैं

- (i) कुल उत्पाद में वृद्धि की अवस्था में (A से D बिन्दु के मध्य) सीमान्त उत्पाद घनात्मक, कुल उत्पाद में कमी की अवस्था में (E से F बिन्दु के मध्य) सीमान्त उत्पाद ऋणात्मक एवं कुल उत्पाद की मात्रा में परिवर्तन नहीं होने की अवस्था में (E बिन्दु पर) सीमान्त उत्पाद की मात्रा शून्य होती है।
- (ii) सीमान्त उत्पाद में वृद्धि की अवस्था में कुल उत्पाद में बढ़ते-बढ़ते दर से वृद्धि (A से B बिन्दु के मध्य), सीमान्त उत्पाद की मात्रा के समान रहने पर कुल उत्पाद में समान दर से वृद्धि (B से C बिन्दु के मध्य), सीमान्त उत्पाद में कमी होने की अवस्था में कुल उत्पाद में ह्रासमान दर से वृद्धि (C से E बिन्दु के मध्य) एवं सीमान्त उत्पाद की मात्रा शून्य होने पर कुल उत्पाद स्थिर एवं सर्वाधिक (E बिन्दु पर) होता है। इस स्तर पर कुल उत्पाद वक्र रेखा सबसे अधिक ऊँचाई पर होती है।

सीमान्त उत्पाद एवं औसत उत्पाद में सम्बन्ध—सीमान्त उत्पाद एवं औसत उत्पाद में अप्राकृत सम्बन्ध पाये जाते हैं—

- (i) सीमान्त उत्पाद की मात्रा में वृद्धि होने पर औसत उत्पाद में वृद्धि होती है। सीमान्त उत्पाद वक्र रेखा (A से G बिन्दु तक) के औसत उत्पाद वक्र रेखा से ऊपर होने की अवस्था में औसत उत्पाद वक्र-रेखा ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। अर्थात् जब तक सीमान्त उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है औसत उत्पाद बढ़ता रहता है।
- (ii) सीमान्त उत्पाद के औसत उत्पाद से कम होने अथवा सीमान्त उत्पाद वक्र-रेखा के औसत उत्पाद वक्र-रेखा के नीचे आने पर (G से I एवं उसके आगे तक) औसत उत्पाद कम होता है। अर्थात् जब तक सीमान्त उत्पाद की मात्रा औसत उत्पाद की मात्रा से कम होती है, औसत उत्पाद कम होता जाता है।
- (iii) सीमान्त उत्पाद के औसत उत्पाद के समान होने के बिन्दु (G) पर औसत उत्पाद सर्वाधिक होता है। इसी बिन्दु से सीमान्त उत्पाद वक्र-रेखा औसत उत्पाद वक्र-रेखा से नीचे की ओर हो जाती है। सीमान्त उत्पाद वक्र-रेखा औसत उत्पाद वक्र रेखा को उसके अधिकतम बिन्दु (G) पर ऊपर से काटती है।

उत्पादन-फलन के क्षेत्र — उत्पादन-फलन को उत्पादन साधनों के इष्टतम उपयोग के निर्णय के आधार पर निम्न तीन क्षेत्रों/भागों में विभक्त किया जाता है।

(i) क्षेत्र I—उत्पादन फलन का प्रथम क्षेत्र उत्पादन के प्रारम्भ बिन्दु से उस बिन्दु तक होता है, जहाँ पर सीमान्त उत्पाद वक्र-रेखा, औसत उत्पाद वक्र-रेखा को काटती है (A से H उत्पाद-साधन के प्रयोग स्तर या 6 इकाई तक)। इस क्षेत्र में औसत-उत्पाद की मात्रा में निरन्तर वृद्धि होती रहती है। सीमान्त उत्पाद वक्र-रेखा, औसत उत्पाद वक्र-रेखा से ऊपर होती है। जिस स्थान पर सीमान्त उत्पाद, औसत उत्पाद की मात्रा के बराबर होता है, वह बिन्दु इस क्षेत्र का अन्तिम बिन्दु होता है।

उत्पादन-फलन का यह क्षेत्र विवेकशून्य क्षेत्र (Irrational Zone) कहलाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में उत्पादन करने पर उत्पादन साधन की मात्रा के बढ़ाने से प्राप्त लाभ की मात्रा भी बढ़ती जाती है। कृषक का उत्पादन करने का उद्देश्य लाभ कमाना ही नहीं होता, बल्कि लाभ को अधिकतम राशि प्राप्त करना होता है। इस क्षेत्र में औसत उत्पाद एवं सीमान्त उत्पाद की मात्रा में निरन्तर वृद्धि होती है जिसके कारण उत्पादन साधन की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई पहले से अधिक लाभ प्रदान करती है। अतः इस क्षेत्र में उत्पादन करने का निर्णय लेना उचित नहीं होता है।

(ii) क्षेत्र II—उत्पादन फलन का द्वितीय क्षेत्र उस बिन्दु से प्रारम्भ होता है, जहाँ पर सीमान्त उत्पाद वक्र-रेखा, औसत उत्पाद वक्र-रेखा को काटती है तथा

उस बिन्दु तक होता है जहाँ पर सीमान्त उत्पाद शून्य हो जाता है या सीमान्त उत्पाद वक्र-रेखा OX अक्ष को छूती है (चित्र 6 I में उत्पादन-साधन के प्रयोग स्तर II से 9 इकाई या H से I बिन्दु के मध्य में)। इस क्षेत्र में उत्पादन-साधन के प्रयोग में सीमान्त उत्पाद की मात्रा निरन्तर कम होनी जाती है तथा कुल उत्पाद में वृद्धि ह्रासमान दर से होती है।

उत्पादन-फलन का यह क्षेत्र विवेकसंगत क्षेत्र (Rational Zone) कहलाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में कृषको को उत्पादन करने के निर्णयों से सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में कृषको द्वारा अधिकतम लाभ की प्राप्ति के लिए अनुकूलतम उत्पादन-साधन की मात्रा ज्ञात करने की विधि का विवेचन अगले पृष्ठों में किया गया है।

(III) क्षेत्र III—उत्पादन-फलन का तृतीय क्षेत्र उस बिन्दु (उत्पादन-साधन के I बिन्दु अथवा 9 इकाई के घाते) से प्रारम्भ होता है जहाँ से सीमान्त उत्पाद की मात्रा शून्य से कम हो जाती है। इस पूरे क्षेत्र में सीमान्त उत्पाद की मात्रा ऋणात्मक होती है जिसके कारण कृषको को प्राप्त कुल उत्पाद की मात्रा उत्पादन-साधन की मात्रा में वृद्धि करने के साथ-साथ निरन्तर कम होती जाती है।

उत्पादन-फलन का यह क्षेत्र भी विवेकशून्य क्षेत्र (Irrational Zone) कहलाता है। इस क्षेत्र में उत्पादन करने के निर्णय लेने से कृषको को दो प्रकार की हानियाँ होती हैं—

(क) उत्पादन-साधन की अतिरिक्त प्रयुक्त मात्रा की लागत की हानि।

(ख) उत्पादन-साधन के प्रयोग से कुल उत्पाद में हुई कमी से हानि।

कृषको को उत्पादन-साधन यदि बिना किसी लागत के भी प्राप्त होता है तब भी इस क्षेत्र में उत्पादन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में उत्पादन करने से प्राप्त लाभ की राशि कम होती जाती है।

परिवर्तनीय अनुपात के सिद्धान्त में प्रतिफल

परिवर्तनीय अनुपात के सिद्धान्त में प्रतिफल तीन दर से होता है जिनका विस्तृत विवेचन नीचे दिया गया है—

(1) ह्रासमान प्रतिफल का सिद्धान्त :

कृषको के पास उत्पादन के लिए भूमि, पशु आदि स्थिर साधन एवं श्रम, पूँजी, बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशी दवाइयाँ, सिंचाई, चारा, दाना आदि परिवर्तनशील साधन होते हैं। ह्रासमान प्रतिफल का सिद्धान्त मुख्यतया उम्र समय प्रदर्शित होता है जब कृषक भूमि के एक इकाई क्षेत्र या एक पशु से अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। उत्पाद की अधिक मात्रा की प्राप्ति के लिए वे परिवर्तनशील साधनों के प्रयोग की मात्रा में निरन्तर वृद्धि करते हैं, लेकिन प्रकृति की देन के

कारण जैसे-जैसे परिवर्तनशील साधन की मात्रा में प्रति इकाई भूमि के क्षेत्र अथवा प्रति पशु वृद्धि की जाती है तो कुल उत्पाद की मात्रा में वृद्धि होती है किन्तु उत्पादन में वृद्धि की मात्रा क्रमशः पहले उत्पादन वृद्धि की मात्रा से बिरुद्ध कम होती जाती है। दूसरे शब्दों में, परिवर्तनशील साधनों की विभिन्न इकाइयों में जो उत्पादन-वृद्धि हासमान दर से होती है। इसे हासमान प्रतिफल का सिद्धान्त कहते हैं। प्रो मार्शल¹ ने हासमान प्रतिफल के सिद्धान्त को निम्न शब्दों में परिभाषित किया है—

“यदि साथ-साथ कृषि कला में उन्नति नहीं होती है तो भूमि पर नियोजित धन एवं पंजी की मात्रा में वृद्धि करने से सामान्यतः कुल उत्पाद में अनुपात से कम वृद्धि होती है।”

कृषि के क्षेत्र में प्रत्येक उत्पादन-साधन के प्रयोग के उदाहरण में हासमान प्रतिफल का सिद्धान्त पाया जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार यदि उत्पादन-साधन की प्रथम इकाई कुल उत्पाद की मात्रा में 25 इकाई वृद्धि करती है तो उत्पादन-साधन की दूसरी इकाई कुल उत्पाद में पहले से कम अर्थात् 20 इकाई की वृद्धि करेगी। इसी प्रकार उत्पादन-साधन की तीसरी इकाई उत्पादन में 15 इकाई की वृद्धि एवं चौथी उत्पादन-साधन की इकाई कुल उत्पाद की मात्रा में 10 इकाई वृद्धि करती है। चित्र 6.2 उत्पादन का हासमान प्रतिफल-सिद्धान्त प्रदर्शित करता है।

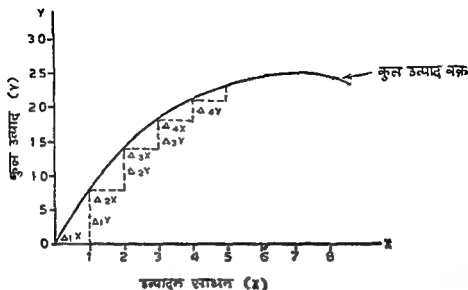
हासमान प्रतिफल के सिद्धान्त में प्राप्त कुल उत्पाद वक्र-रेखा उद्गम बिन्दु से अवतल (Concave to the Origin) होती है। हासमान प्रतिफल की अवस्था में निम्न सम्बन्ध पाये जाते हैं—

$$\frac{\Delta_1 Y}{\Delta_1 X} > \frac{\Delta_2 Y}{\Delta_2 X} > \frac{\Delta_3 Y}{\Delta_3 X} > \dots\dots\dots > \frac{\Delta_n Y}{\Delta_n X}$$

चूँकि $\Delta_1 X = \Delta_2 X = \Delta_3 X \dots = \Delta_n X$, अतः ΔY की मात्रा निरन्तर कम होती जाती है जिससे $\Delta Y / \Delta X$ का अनुपात उत्पादन-साधन की मात्रा के बढ़ने के साथ-साथ कम होता जाता है।

1. “An increase in the capital and labour applied in the cultivation of land causes in general a less than proportionate increase in the amount of produce raised unless it happens to coincide with an improvement in the art of agriculture

—A. Marshall, Principles of Economics. Macmillan and Company, London, 1956, P. 125



चित्र 6.2 ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था में कुल उत्पन्न वक्र

ह्रासमान प्रतिफल का सिद्धान्त कृषि क्षेत्र में सदैव लागू होता है, लेकिन निम्न स्थितियों में यह सिद्धान्त कृषि क्षेत्र में भी विलम्ब से लागू होता है—

- (1) कृषि उत्पादन की विधि में सुधार होने की स्थिति में ।
- (ii) उत्पादक-कृषक की निपुणता, कार्यकुशलता एवं दक्षता में वृद्धि होने की अवस्था में ।

(iii) परिवर्तनशील साधनों—श्रम, पूँजी, खाद, उर्वरक, चारा, दाना, सिंचाई के पानी आदि की इकाइयों का बहुत ही कम अथवा अल्प मात्रा में प्रयोग किये जाने की अवस्था में । परिवर्तनशील साधनों की प्रयुक्त की गई इकाइयों की मात्रा कम होने पर उत्पादन में ह्रासमान प्रतिफल के प्रारम्भ होने में विलम्ब होना स्वाभाविक होता है ।

कृषि के क्षेत्र में ह्रासमान प्रतिफल सिद्धान्त लागू होने के कारण कृषकों के सामने समस्या होती है कि फार्म पर उपलब्ध स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधन—श्रम, पूँजी, उर्वरक आदि उत्पादन साधनों की कितनी मात्रा उपयोग में लेनी चाहिए अथवा उत्पादन का कौन सा स्तर प्राप्त करना चाहिए जिससे प्रति हेक्टर भूमि या प्रति पशु सम्भावित लाभ की राशि अधिकतम प्राप्त हो सके ? उपर्युक्त निर्णयों में कृषकों का उद्देश्य स्थिर उत्पादन-साधनों से अधिकतम लाभ की

राशि प्राप्त करना होता है। फार्म-प्रबन्ध विज्ञान उपयुक्त निर्णय लेने में सहायक होता है। फार्म-प्रबन्ध विज्ञान का उद्देश्य उत्पादन की अधिकतम मौलिक मात्रा प्राप्त करना न होकर, अधिकतम लाभ की राशि प्राप्त करना होता है। कृषको द्वारा उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में ली गई मात्रा, उनकी लागत व उनसे प्राप्त अतिरिक्त उत्पाद के मूल्य के आधार पर ज्ञात किया जाता है।

ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था में निर्णय लेने का नियम—ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था में निर्णय लेने के नियम के अनुसार अधिकतम लाभ की प्राप्ति के लिए परिवर्तनशील उत्पादन साधन की मात्रा में उस स्तर तक वृद्धि करते रहना चाहिए जब तक कि सीमान्त आय की राशि (Marginal Revenue or MR), सीमान्त लागत की राशि (Marginal Cost or MC) से अधिक होती है। सीमान्त आय एवं सीमान्त लागत की राशि के बराबर हो जाने की स्थिति के उपरान्त परिवर्तनशील उत्पादन-साधन की मात्रा में वृद्धि नहीं करनी चाहिए। इस स्तर पर प्राप्त उत्पादन की मात्रा कृषक को अधिकतम लाभ प्रदान करती है। उत्पादन की मात्रा बढ़ावा परिवर्तनशील उत्पादन-साधन की मात्रा में इस स्तर से आगे वृद्धि करने के प्रयास करने पर कृषकों को प्राप्त होने वाले कुल लाभ की राशि में कमी होती है।

ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था में परिवर्तनशील उत्पादन-साधन की मात्रा का अनुकूलतम लाभ प्रदान करने वाला स्तर निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है—

$$\frac{\text{उत्पाद की अतिरिक्त मात्रा}}{\text{उत्पादन-साधन की अतिरिक्त मात्रा}} \text{ का अनुपात } = \frac{\text{उत्पादन-साधन की प्रति इकाई कीमत}}{\text{उत्पाद की प्रति इकाई कीमत}}$$

के अनुपात के बराबर होना चाहिए।

$$\text{अर्थात् } \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{P_x}{P_y}$$

$$\Rightarrow \Delta Y P_y = \Delta X P_x$$

जहाँ ΔY = उत्पाद की मात्रा में परिवर्तन,

ΔX = उत्पादन-साधन की मात्रा में परिवर्तन

P_x = उत्पादन-साधन की प्रति इकाई कीमत

P_y = उत्पाद की प्रति इकाई कीमत

$\Delta Y P_y$ = अतिरिक्त/सीमान्त आय

$\Delta X P_x$ = अतिरिक्त सीमान्त लागत

ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था में निर्योग लेने का उदाहरण— एक कृषक फार्म पर एक हैक्टर गेहूँ की फसल में नत्रजन उर्वरक की विभिन्न मात्राओं का उत्पादन-वृद्धि के लिये उपयोग करता है जिससे उत्पादन की सारणी 6.2 के अनुसार वृद्धि होती है। अधिकतम लाभ की प्राप्ति के लिये ज्ञात कीजिये की उत्पादन-साधन की कितनी मात्रा का निम्न कीमतों की अवस्था में कृषक के लिये उपयोग करना लाभकर होगा :

- (अ) नत्रजन उर्वरक 2 00 रु० प्रति किलोग्राम एवं गेहूँ 100 रु० प्रति क्विन्टल ।
 (ब) नत्रजन उर्वरक 1.75 रु० प्रति किलोग्राम एवं गेहूँ 75 रु० प्रति क्विन्टल ।

सारणी 6.2 में नत्रजन उर्वरक की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त प्रति हैक्टर गेहूँ का उत्पादन, उर्वरक उपयोग की अतिरिक्त लागत एवं प्राप्त अतिरिक्त आय प्रदर्शित की गई है ।

उपर्युक्त उदाहरण उत्पादन में ह्रासमान प्रतिफल के सिद्धान्त को प्रदर्शित करता है क्योंकि प्रथम 10 किलोग्राम नत्रजन उर्वरक से 20 क्विन्टल गेहूँ का उत्पादन होता है, द्वितीय 10 किलोग्राम नत्रजन उर्वरक के उपयोग से कुल उत्पादन 23 क्विन्टल प्राप्त होता है अर्थात् 10 किलोग्राम अतिरिक्त नत्रजन उर्वरक से 3 क्विन्टल गेहूँ का अतिरिक्त उत्पादन होता है। नत्रजन उर्वरक की मात्रा 30 किलोग्राम करने पर कुल उत्पादन 25 क्विन्टल प्राप्त होता है अर्थात् जैसे जैसे नत्रजन उर्वरक की मात्रा में वृद्धि की जाती है, वैसे-वैसे अतिरिक्त उत्पादन कमशः पहले की अपेक्षा कम होता जाता है ।

कीमतों के परिवर्तन से लाभप्रद उत्पादन के स्तर की मात्रा में घाने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिये सारणी में गेहूँ एवं नत्रजन उर्वरक की कीमतों के दो विभिन्न स्तर लिये गये हैं । नत्रजन-उर्वरक की कीमत 2 00 रु० प्रति किलोग्राम तथा गेहूँ की कीमत 100 रु० प्रति क्विन्टल होने की अवस्था में कृषक को अधिकतम लाभ 60 किलोग्राम नत्रजन उर्वरक के उपयोग से प्राप्त होता है । इस नत्रजन स्तर पर अतिरिक्त लागत 20 00 रु० और अतिरिक्त आय 25 00 रु० की होती है । अतिरिक्त आय, अतिरिक्त लागत से अधिक है । नत्रजन-उर्वरक का प्रयोग 70 किलोग्राम करने से कुल उत्पाद की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि कुल उत्पाद की मात्रा स्थिर रहती है, जिसके कारण अतिरिक्त लागत 20 रु० व अतिरिक्त आय शून्य होती है । कृषक द्वारा 70 किलोग्राम नत्रजन उर्वरक का प्रयोग करने से फार्म पर 60 किलोग्राम नत्रजन उर्वरक के उपयोग की अपेक्षा प्राप्त कुल

सारणी 6.2

नम्रजन उर्वरक की विभिन्न मात्राओं के उपयोग से प्राप्त गेहूँ के उत्पादन की अवस्था में निम्न लेना

(काल्पनिक आकड़े)

क्रम संख्या	नम्रजन उर्वरक की मात्रा (किया)	गेहूँ का प्रति हेक्टर कुल उत्पादन (क्विण्टल)	उर्वरक की सीमान्त मात्रा (किलोग्राम)	गेहूँ की सीमान्त मात्रा (क्विण्टल)	उर्वरक की अतिरिक्त/ सीमान्त लाभ		उत्पाद से प्राप्त अतिरिक्त सीमान्त आय	
					200 रु	175 रु	100 रु	7500 रु
	X	Y	ΔX	ΔY	MC	MC	MR	MR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	1600						
2	10	2000	10	400	2000	1750	400	300
3	20	2300	10	300	2000	1750	300	225
			10	200	2000	1750	200	150

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	30	25.00	10	1.00	20.00	17.50	100	75
5	40	26.00	10	0.50	20.00	17.50	50	37.50
6	50	26.50	10	0.25	20.00	17.50	25	18.75
7	60	26.75	10	0.00	20.00	17.50	0	0
8	70	26.75	10	—0.25	20.00	17.50	—25	—18.75
9	80	26.50						

लाम की राशि में $(10 \times 2) = 20$ रु० की कमी होती है। अतः उपर्युक्त कीमत स्तर पर 60 किलोग्राम नत्रजन उर्वरक ही कृषक को अधिकतम लाभ प्रदान करता है।

यदि गेहूँ की कीमत 75 रु० प्रति क्विण्टल एवं नत्रजन उर्वरक की कीमत 2 रु० प्रति किलोग्राम हो तो 50 किलोग्राम नत्रजन उर्वरक का उपयोग ही कृषक के लिए सबसे अधिक लाभकर होता है। नत्रजन उर्वरक का 60 किलोग्राम तक उपयोग करने से अतिरिक्त लागत 20 रु० आती है जबकि अतिरिक्त आय 18 75 रु० की ही प्राप्त होती है। इससे प्राप्त कुल लाभ की राशि में 1 25 रु० की कमी होती है। उर्वरक की कीमत 1 75 रु० प्रति किलोग्राम तथा गेहूँ की कीमत 100 रु० प्रति क्विण्टल होने पर 60 किलोग्राम नत्रजन उर्वरक का उपयोग कृषक के लिए सबसे अधिक लाभकर होता है। इस प्रकार उत्पादन-साधन व उत्पाद की कीमतों में परिवर्तन की अवस्था में उत्पादन साधन का अधिकतम लाभकारी स्तर ज्ञात किया जाता है। उत्पादन साधनों का अधिकतम लाभकारी स्तर विभिन्न कीमतों की अवस्था में विभिन्न होता है।

ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था में परिवर्तनशील उत्पादन साधन की मात्रा का अनुकूलतम लाभ प्रदान करने वाला स्तर, सीमांत आय एवं सीमांत लागत के आधार के सूत्र की सहायता से भी ज्ञात किया जा सकता है। सूत्र की सहायता से उत्पादन-साधन का अनुकूलतम लाभ प्रदान करने वाला स्तर ज्ञात करने में समय कम लगता है। सूत्र द्वारा विभिन्न कीमतों के स्तर पर उर्वरक की अनुकूलतम मात्रा ज्ञात करने की विधि सारणी 6 3 प्रदर्शित की गई है।

उर्वरक की कीमत 2 00 रु० प्रति किलोग्राम व गेहूँ की कीमत 100 रु० प्रति क्विण्टल होने की अवस्था में 60 किलोग्राम उर्वरक का उपयोग अधिकतम लाभ प्रदान करने वाला स्तर है क्योंकि इस स्तर पर अतिरिक्त उत्पाद एवं अतिरिक्त उत्पादन-साधन की मात्रा का अनुपात 0 025 है जबकि उनकी कीमतों का विलोम अनुपात 0 020 है। चूँकि यह अनुपात कीमतों के विलोम अनुपात से अधिक है तथा इसके बाद यह कम होता जाता है, अतः इन कीमतों के स्तर पर 60 किलोग्राम नत्रजन उर्वरक का उपयोग कृषक के लिए अनुकूलतम लाभ की राशि प्रदान करने वाला स्तर है। इसी उत्पादन-फलन में उर्वरक की कीमत 1 75 रु० प्रति किलोग्राम व गेहूँ की कीमत 100 रु० प्रति क्विण्टल तथा उर्वरक की कीमत 1 75 रु० प्रति किलोग्राम व गेहूँ की कीमत 75 रु० प्रति क्विण्टल होने की दोनों ही अवस्थाओं में 60 कि ग्रा नत्रजन उर्वरक के उपयोग-स्तर तक अतिरिक्त उत्पाद व अतिरिक्त उत्पादन साधन का अनुपात उनकी प्रति इकाई कीमतों के विलोम अनुपात से अधिक है। अतः उपर्युक्त कीमतों की अवस्था में भी 60 किलोग्राम नत्रजन उर्वरक के उपयोग से कृषक

को अधिकतम लाभ की राशि प्राप्त होती है। उपर्युक्त उत्पादन-फलन की अवस्था में उर्वरक की कीमत 200 रु प्रति किलोग्राम तथा गेहूँ की कीमत 75 रु प्रति क्विण्टल होने पर 50 किलोग्राम नत्रजन उर्वरक की मात्रा ही अधिकतम लाभ प्राप्त कराती है, क्योंकि 50 किलोग्राम नत्रजन उर्वरक के स्तर पर अतिरिक्त उत्पाद एवं अतिरिक्त उत्पादन-साधन का अनुपात, उनकी कीमतों के विलोम अनुपात से अधिक होता है। इस स्तर के उपरान्त उर्वरक की मात्रा में वृद्धि करने पर कीमतों का विलोम अनुपात, अतिरिक्त उत्पाद व अतिरिक्त उत्पादन-साधन के अनुपात से अधिक होता जाता है जो लाभ की प्राप्त राशि में कमी करता है।

इस प्रकार सीमान्त लागत एवं सीमान्त माय की राशि प्रत्येक सूत्र की सहायता से ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था में परिवर्तनशील साधनों की अनुकूलतम लाभ प्रदान करने वाली मात्रा ज्ञात की जाती है।

(II) समान प्रतिफल का सिद्धान्त

समान प्रतिफल के अन्तर्गत परिवर्तनशील उत्पादन साधन की प्रत्येक इकाई का जब स्थायी साधनों के साथ प्रयोग किया जाता है तो उसमें प्राप्त अतिरिक्त उत्पाद की मात्रा क्रमशः समान होती है, अर्थात् परिवर्तनशील उत्पादन साधन की प्रत्येक इकाई, उत्पाद के उत्पादन में समान मात्रा से वृद्धि करती है। कृषि क्षेत्र में समान प्रतिफल का सिद्धान्त बहुत ही कम पाया जाता है। समान प्रतिफल का सिद्धान्त कृषि क्षेत्र में निम्न दो अवस्थाओं में ही साधारणतया पाया जाता है—

- (1) उत्पादन के लिए आवश्यक किसी भी उत्पादन-साधन के स्थिर न होकर परिवर्तनशील होने की अवस्था में समान प्रतिफल का सिद्धान्त पाया जाता है। जैसे—एक एकड़ भूमि, 50 किलोग्राम नत्रजन उर्वरक, 8 बार सिंचाई एवं 30 मानव-श्रम दिवस से 20 क्विण्टल गेहूँ उत्पन्न होता है, तो दूसरी एक एकड़ भूमि, 50 किलोग्राम नत्रजन उर्वरक, 8 बार सिंचाई एवं 30 मानव-श्रम दिवस से भी 20 क्विण्टल गेहूँ उत्पन्न होगा।
- (2) उत्पादन में एक या एक से अधिक साधन स्थिर हों, लेकिन उनकी क्षमता का पूर्णरूप से उपयोग नहीं किया गया हो, अर्थात् उनकी क्षमता अधिशेष मात्रा में हो।

समान प्रतिफल के सिद्धान्त का वक्र सीधी रेखा के रूप में होता है तथा वक्र पर ढाल सभी स्थानों पर समान होता है। समान प्रतिफल की अवस्था में निम्न सम्बन्ध पाया जाता है—

$$\frac{\Delta_1 Y}{\Delta_1 X} = \frac{\Delta_2 Y}{\Delta_2 X} = \frac{\Delta_3 Y}{\Delta_3 X} = \dots \dots \dots = \frac{\Delta_n Y}{\Delta_n X}$$

सारणी 63

विभिन्न कीमतों के स्तर पर सूत्र द्वारा मजदूरन उर्बरक की अनुकूलतम साम प्रदान करने वाली मात्रा ज्ञात करना

मजदूरन उर्बरक की मात्रा	गेहूँ का प्रति हेक्टर कुल उत्पादन	उत्पाद एवं उत्पादन साधन की प्रतिरिक्त मात्रा का अनुपात $\left(\frac{\Delta Y_1}{\Delta X_1}\right)$	विभिन्न कीमतों की अवस्था में उत्पाद एवं उत्पादन- साधनों की कीमतों का विलोम अनुपात $P_x=200$ रु $P_X=175$ रु $PX=175$ रु $PX=200$ रु $P_y=100$ रु $PY=100$ रु $PY=75$ रु $PY=75$ रु	1	2	3	4	5	6	7
(किलोग्राम) (X)	(निष्पटल) (Y)									
0	16 00	0 40	0 02	0 0175	0 023	0 026				
10	20 00	0 30	0 02	0 0175	0 023	0 026				
20	23 00	0 20	0 02	0 0175	0 023	0 026				
30	25 00	0 10	0 02	0 0175	0 023	0 026				

1	2	3	4	5	6	7
40	26.00	0.05	0.02	0.0175	0.023	0.026
50	26.50	0.025	0.02	0.0175	0.023	0.026
60	26.75	0.00	0.02	0.0175	0.023	0.026
70	26.75	-0.025	0.02	0.0175	0.023	0.026
80	26.50					

सारणी 6.4 काल्पनिक झाँकड़ों के आधार पर समान प्रतिफल के सिद्धान्त एवं उनके अन्तर्गत निर्णय लेने की विधि को स्पष्ट करती है।

उदाहरण में प्रत्येक उत्पादन साधन की एक इकाई (10 किलोग्राम उर्वरक) से समान मात्रा (2 क्विण्टल) में अतिरिक्त उत्पाद प्राप्त होता है। उत्पादन-साधन की प्रत्येक इकाई के उपयोग में समान राशि में लाभ भी प्राप्त होता है, क्योंकि उत्पादन-साधन की एक इकाई का मूल्य उससे प्राप्त अतिरिक्त उत्पाद के मूल्य से कम है। समान प्रतिफल की अवस्था में उत्पादन वृद्धि करने से लाभ की राशि में निरन्तर वृद्धि होती है। अतः उपर्युक्त उदाहरण में 50 इकाई उत्पादन साधन के उपयोग से सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है।

समान प्रतिफल की अवस्था में निर्णय लेने का नियम—समान प्रतिफल की अवस्था में यदि उत्पादन-साधन की प्रथम इकाई का उपयोग लाभप्रद है तो आगे की सभी इकाइयाँ लाभप्रद होंगी। अतः जब तक समान दर से उत्पादन में वृद्धि होती रहती है, उत्पादन-साधन की इकाइयों में वृद्धि करते रहना चाहिए। यदि उत्पादन-साधन की प्रथम इकाई लाभप्रद नहीं है तो आगे की कोई भी इकाई लाभप्रद नहीं होती है। अतः ऐसी अवस्था में उत्पादन-साधन की किसी भी इकाई का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

समान प्रतिफल की अवस्था का रेखीय चित्र—समान प्रतिफल की अवस्था में प्राप्त कुल उत्पाद वक्र सीधी रेखा होती है जो चित्र 6.3 में प्रदर्शित है।

(iii) वर्द्धमान प्रतिफल का सिद्धान्त :

वर्द्धमान प्रतिफल के सिद्धान्त के अन्तर्गत परिवर्तनशील साधन की प्रत्येक इकाई का जब स्थिर साधनों के साथ उपयोग किया जाता है तो परिवर्तनशील साधन की प्रत्येक इकाई पहले वाली इकाई की अपेक्षा थोड़ा अधिक मात्रा में अतिरिक्त उत्पादन करती है अर्थात् कुल उत्पाद में वर्द्धमान दर से परिवर्तन होता है। कृषि क्षेत्र में वर्द्धमान प्रतिफल का सिद्धान्त बहुत कम पाया जाता है। कृषि क्षेत्र में सम्भवतः निम्न अवस्थाओं में वर्द्धमान प्रतिफल का सिद्धान्त पाया जाता है—

- (प्र) जब स्थिर उत्पादन-साधनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो रहा है अर्थात् उनमें उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता होती है।

सारणी 64 समान प्रतिकल का सिद्धान्त

उत्पादन- साधन की इकाइयाँ	कुल उत्पाद की मात्रा	उत्पादन- साधन की सीमान्त मात्रा	उत्पाद की सीमान्त मात्रा	उत्पाद व उत्पादन- साधन की सीमान्त मात्राओं का अनुपात	उत्पाद एवं उत्पादन साधन की कीमतों का विलोम अनुपात $P_X = ₹. 1.50$ $P_Y = ₹. 1.0$
(X)	(Y)	(ΔX)	(ΔY)	$\left(\frac{\Delta Y}{\Delta X}\right)$	$\left(\frac{P_X}{P_Y}\right)$
1	2	3	4	5	6
0	12				
		10	2	0.2	0.15
10	14	10	2	0.2	0.15
20	16	10	2	0.2	0.15
30	18	10	2	0.2	0.15
40	20	10	2	0.2	0.15
50	22	10	2	0.2	0.15

(ब) जब प्रारम्भ में परिवर्तनशील उत्पादन साधन की उपयोग की गई इकाई की मात्रा बहुत कम होती है।

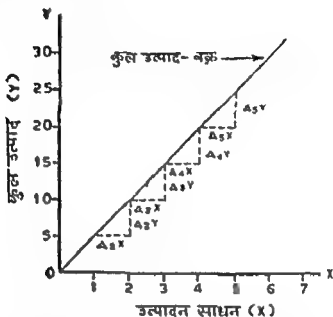
वर्द्धमान प्रतिकल की अवस्था में प्राप्त कुल उत्पाद वक्र का ढाल उद्गम से उत्तल (Convex to the Origin) होता है तथा प्राप्त सम्बन्ध निम्न प्रकार का होता है—

$$\frac{\Delta_1 Y}{\Delta_1 X} < \frac{\Delta_2 Y}{\Delta_2 X} < \frac{\Delta_3 Y}{\Delta_3 X} < \dots < \frac{\Delta_n Y}{\Delta_n X}$$

अर्थात् उत्पादन-साधन की इकाइयों में वृद्धि के साथ-साथ $\Delta Y/\Delta X$ का अनुपात क्रमशः बढ़ता जाता है।

वर्द्धमान प्रतिकल की अवस्था में निर्णय लेने का नियम—वर्द्धमान प्रतिकल की अवस्था में भी निर्णय का नियम ह्रासमान प्रतिकल के सिद्धान्त के समान ही

होता है। अर्थात् जब तक उत्पाद व उत्पादन साधन की सीमा-त-दर का अनुपात उनकी विलोम कीमतों के अनुपात से अधिक है, तब तक उत्पादन-साधन की मात्रा में वृद्धि करते रहना चाहिए।



चित्र 6.3 समान प्रतिकूल की अवस्था में कुल उत्पाद का वक्र

सारणी 6.5 वाल्पनिश भाँवड़ों के आधार पर वर्द्धमान प्रतिकूल सिद्धान्त एवं उसके प्रन्तर्गत निरालेय लेने की विधि स्पष्ट करती है। उदाहरण में उत्पादन-साधन की प्रथम इकाई का उपयोग लाभप्रद है। वर्द्धमान प्रतिकूल की अवस्था में प्रागे वाली सभी उत्पादन साधन की इकाइयाँ पहले वाली इकाई की अपेक्षा अधिक लाभप्रद होती हैं, जिससे उनके प्रयोग से लाभ की राशि में निरन्तर वृद्धि होती है। अतः वर्द्धमान प्रतिकूल के सिद्धान्त में यदि उत्पादन साधन की प्रथम इकाई लाभप्रद है तो प्रागे की सभी इकाइयाँ लाभप्रद होगी तथा प्रत्येक इकाई के उपयोग से लाभ की राशि क्रमशः पहले से अधिक होती है। अतः प्रस्तुत उदाहरण में उत्पादन-साधन की 60 इकाइयों के उपयोग से वृषन को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है।

वर्द्धमान प्रतिकूल की अवस्था का रेखीय चित्र—वर्द्धमान प्रतिकूल की अवस्था में प्राप्त कुल उत्पाद वक्र चित्र 6.4 में प्रदर्शित किया गया है।

(घ) पैमाने के प्रतिकूल का सिद्धान्त

पैमाने के प्रतिकूल के सिद्धान्त में उत्पादन के सभी आवश्यक साधन परिवर्तन-शील होते हैं अर्थात् कोई भी उत्पादन-साधन स्थिर मात्रा में नहीं होता है। पैमाने के

प्रतिफल के सिद्धान्त का अध्ययन कृषको, राजनैतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं कृषि-अर्थशास्त्रियों के लिए आवश्यक होता है। पैमाने के प्रतिफल का सिद्धान्त कृषको को बड़े अथवा लघु फार्म बनाने से सम्बन्धित समस्याओं के निर्णय लेने में सहायक होता है। पैमाने के प्रतिफल का सिद्धान्त राष्ट्रीय स्तर पर भी फार्म के आकार के निर्धारण में सहायक होता है।

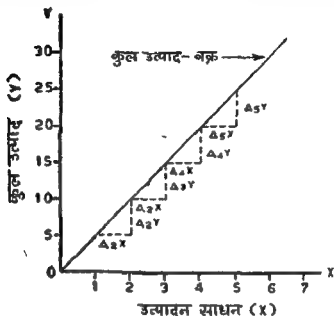
पैमाने के प्रतिफल के सिद्धान्त में उत्पादन-वृद्धि के लिए आवश्यक सभी उत्पादन-साधनों की मात्रा में वृद्धि की दर समान अथवा विभिन्न अनुपातों में हो सकती है। यदि उत्पादन वृद्धि के लिए आवश्यक सभी उत्पादन-साधनों की मात्रा में समान अनुपात में वृद्धि की जाती है तो उसे शुद्ध पैमाने का सम्बन्ध (Pure Scale Relationship) कहते हैं। जैसे यदि उत्पादन साधन X_1 की मात्रा में

सारणी 65.

वर्द्धमान प्रतिफल का सिद्धान्त

उत्पादन- साधन की इकाईयाँ	उत्पाद की कुल मात्रा	उत्पादन- साधन की सीमान्त मात्रा	उत्पाद की सीमान्त मात्रा	उत्पाद व उत्पादन-साधन की सीमान्त मात्रा का अनुपात	उत्पाद व उत्पादन साधन की कीमतों का बिलोम अनुपात
(X)	(Y)	(ΔX)	(ΔY)	$\left(\frac{\Delta Y}{\Delta X}\right)$	$\left(\frac{P_X}{P_Y}\right)$
				यदि $P_X = 1.50$ रु. $P_Y = 10$ रु	
10	10	10	2	0.2	0.15
20	17	10	3	0.3	0.15
30	15	10	4	0.4	0.15
40	19	10	5	0.5	0.15
50	24	10	6	0.6	0.15
60	30				

होता है। अर्थात् जब तक उत्पाद व उत्पादन साधन की सीमान्त-दर का अनुपात उनकी विलोम कीमतों के अनुपात से अधिक है, तब तक उत्पादन-साधन की मात्रा में वृद्धि करते रहना चाहिए।



चित्र 6.3 समान प्रतिफल की अवस्था में कुल उत्पाद का वक्र

सारणी 6.5 काल्पनिक आँकड़ों के आधार पर वर्द्धमान प्रतिफल सिद्धान्त एवं उसके अन्तर्गत निर्णय लेने की विधि स्पष्ट करती है। उदाहरण में उत्पादन-साधन की प्रथम इकाई का उपयोग लाभप्रद है। वर्द्धमान प्रतिफल की अवस्था में आगे वाली सभी उत्पादन-साधन की इकाइयाँ पहले वाली इकाई की अपेक्षा अधिक लाभप्रद होती हैं, जिससे उनके प्रयोग से लाभ की राशि में निरन्तर वृद्धि होती है। अतः वर्द्धमान प्रतिफल के सिद्धान्त में यदि उत्पादन-साधन की प्रथम इकाई लाभप्रद है तो आगे की सभी इकाइयाँ लाभप्रद होगी तथा प्रत्येक इकाई के उपयोग से लाभ की राशि क्रमशः पहले से अधिक होती है। अतः प्रस्तुत उदाहरण में उत्पादन-साधन की 60 इकाइयों के उपयोग से कृषक को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है।

वर्द्धमान प्रतिफल की अवस्था का रेखीय चित्र—वर्द्धमान प्रतिफल की अवस्था में प्राप्त कुल उत्पाद वक्र चित्र 6.4 में प्रदर्शित किया गया है।

(ब) पैमाने के प्रतिफल का सिद्धान्त

पैमाने के प्रतिफल के सिद्धान्त में उत्पादन के सभी आवश्यक साधन परिवर्तन-शील होते हैं अर्थात् कोई भी उत्पादन-साधन स्थिर मात्रा में नहीं होता है। पैमाने के

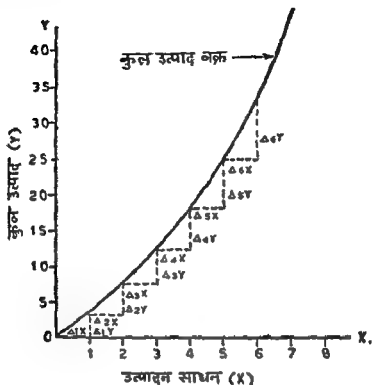
प्रतिफल के सिद्धान्त का अध्ययन कृषको, राजनैतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं कृषि-अर्थशास्त्रियों के लिए आवश्यक होता है। पैमाने के प्रतिफल का सिद्धान्त कृषको को बड़े प्रयत्न लघु फार्म बनाने से 'सम्बन्धित' समस्याओं के निर्णय लेने में सहायक होता है। पैमाने के प्रतिफल का सिद्धान्त राष्ट्रीय स्तर पर भी फार्म के प्रकार के निर्धारण में सहायक होता है।

पैमाने के प्रतिफल के सिद्धान्त में उत्पादन-वृद्धि के लिए आवश्यक सभी उत्पादन-साधनों की मात्रा में वृद्धि की दर समान प्रयत्न विभिन्न अनुपातों में हो सकती है। यदि उत्पादन वृद्धि के लिए आवश्यक सभी उत्पादन-साधनों की मात्रा में समान अनुपात में वृद्धि की जाती है तो उसे शुद्ध पैमाने का सम्बन्ध (Pure Scale Relationship) कहते हैं। जैसे यदि उत्पादन साधन X_1 की मात्रा में

सारणी 65

वर्द्धमान प्रतिफल का सिद्धान्त

उत्पादन- साधन की इकाइयाँ	उत्पाद की कुल मात्रा	उत्पादन- साधन की सीमान्त मात्रा	उत्पाद की सीमान्त मात्रा	उत्पाद व उत्पादन-साधन की सीमान्त मात्रा का अनुपात	उत्पाद व उत्पादन साधन की कीमतों का विलोम अनुपात
(किलोग्राम)	(क्विण्टल)	(किलोग्राम)	(क्विण्टल)	$\left(\frac{\Delta Y}{\Delta X}\right)$	$\left(\frac{P_X}{P_Y}\right)$
				यदि $PX = 1.50$ रु. $PY = 10$ रु	
10	10				
		10	2	0.2	0.15
20	17	10	3	0.3	0.15
30	15	10	4	0.4	0.15
40	19	10	5	0.5	0.15
50	24	10	6	0.6	0.15
60	30				



चित्र 6.4 बढ्दमान प्रतिफल की अवस्था में कुल उत्पाद का वक्र

100 प्रतिशत वृद्धि की जाती है तो उत्पादन के लिये आवश्यक अन्य सभी उत्पादन-साधनों की मात्रा में भी 100 प्रतिशत वृद्धि की जाती है। अतः जब सभी उत्पादन-साधनों की मात्रा में समान अनुपात में वृद्धि की जाती है तो उन्हें एक समुच्चय उत्पादन साधन के रूप में मानकर विश्लेषण किया जाता है। यदि विभिन्न उत्पादन-साधनों की वृद्धि की दर विभिन्न होती है तो उसे पैमाने का परिवर्तनीय अनुपात का सम्बन्ध (Variable Proportion Scale Relationship) कहते हैं। जैसे उत्पादन साधन X_1 की मात्रा में 100 प्रतिशत वृद्धि, उत्पादन-साधन X_2 की मात्रा में 50 प्रतिशत वृद्धि, उत्पादन साधन X_3 की मात्रा में 40 प्रतिशत वृद्धि, उत्पादन-साधन X_4 की मात्रा में 25 प्रतिशत वृद्धि आदि।

पैमाने के प्रतिफल के सिद्धान्त के अन्तर्गत सभी उत्पादन साधनों की मात्रा में समान अनुपात में वृद्धि करने की अवस्था में उत्पादन में वृद्धि समान, बढ्दमान एक ह्रासमान दर से हो सकती है, जिसके कारण पैमाने के प्रतिफल के सिद्धान्त में भी उत्पादन-वृद्धि की निम्न तीन दरें होती हैं—

(1) पैमाने के समान प्रतिफल का सिद्धान्त—इसके अन्तर्गत उत्पादन-

साधनों में एक इकाई मात्रा से क्रमिक वृद्धि करने पर प्राप्त अतिरिक्त उत्पाद की मात्रा क्रमशः समान रहती है।

(ii) पैमाने के बढ्ढमान प्रतिफल का सिद्धान्त—इसके अन्तर्गत उत्पादन-साधनों में एक इकाई मात्रा में क्रमिक वृद्धि करने पर प्राप्त अतिरिक्त उत्पाद की मात्रा क्रमशः पहले की अपेक्षा अधिक होती जाती है।

(iii) पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल का सिद्धान्त—इसके अन्तर्गत उत्पादन-साधनों में एक इकाई मात्रा से क्रमिक वृद्धि करने पर प्राप्त अतिरिक्त उत्पाद की मात्रा क्रमशः पहले की अपेक्षा कम होती जाती है।

1 परिवर्तनीय अनुपात प्रतिफल सिद्धान्त एवं पैमाने के प्रतिफल के सिद्धान्त में अन्तर :

परिवर्तनीय अनुपात के प्रतिफल सिद्धान्त एवं पैमाने के प्रतिफल सिद्धान्त में निम्न अन्तर होते हैं —

(i) परिवर्तनीय अनुपात के प्रतिफल सिद्धान्त में उत्पादन के लिए आवश्यक सभी उत्पादन साधनों में परिवर्तन नहीं होता है। इसके अन्तर्गत उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं और एक या अनेक साधनों की मात्रा में परिवर्तन होता है। जैसे उर्वरक की मात्रा में परिवर्तन होता है तथा उत्पादन के लिये आवश्यक अन्य सभी साधन स्थिर मात्रा में होते हैं। पैमाने के प्रतिफल में उत्पादन के लिये आवश्यक सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं अर्थात् कोई भी उत्पादन-साधन स्थिर मात्रा में नहीं होता है।

(ii) परिवर्तनीय अनुपात के प्रतिफल का सिद्धान्त साधारणतया एक उत्पादन-साधन की अनुकूलतम मात्रा अथवा परिवर्तनशील उत्पादन-साधन से अनुकूलतम उत्पादन-मात्रा ज्ञात करने के लिये प्रयुक्त किया जाता है, जबकि पैमाने के प्रतिफल के सिद्धान्त का उपयोग फार्म पर अधिकतम लाभ प्रदान करने वाले फार्म के आकार अथवा सभी उत्पादन साधनों का अनुकूलतम उपयोग करने वाले फार्म के आकार को ज्ञात करने में किया जाता है।

2. ग्नूरतम लागत का सिद्धान्त/साधनों या क्रियाओं के प्रतिस्थापन का सिद्धान्त :

फार्म पर विभिन्न परिवर्तनशील साधनों की अनुकूलतम मात्रा ज्ञात करने के अतिरिक्त कृषकों की अन्य समस्याएँ भी होती हैं, जैसे अमुक कार्य को करने के लिये विभिन्न उपलब्ध विधियों में से कौन-सी विधि उत्तम है। फसल की कटाई, खरपन-वार-नियन्त्रण, उर्वरक-उपयोग, पशुओं का दूध निकालना, पशुओं को खिलाने के लिये चारे व दाने की उपलब्धि आदि अनेक कार्य हैं। प्रत्येक साधन/नियम की लागत

विभिन्न आती है, जिसके कारण कार्य को करने में विभिन्न विधियाँ/साधनों में कुल लागत भी विभिन्न आती है। साथ ही उत्पादन साधनों को विभिन्न दरों से प्रतिस्थापित भी किया जा सकता है। अतः कृषकों की समस्या होती है कि प्रमुख कार्य को करने के लिये उत्पादन की कौन सी विधि या कौन से उत्पादन-साधन की कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाए, जिससे कार्य करने की लागत कम से कम आए। अर्थात् कृषक उत्पादन-साधनों/क्रियाओं के संयोग का वह स्तर ज्ञात करना चाहता है, जहाँ उस कार्य को करने की लागत न्यूनतम आती है।

उत्पादन-साधनों/विधियों/क्रियाओं को जो एक-दूसरे के लिये प्रतिस्थापित की जा सकती है, तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

- (i) वे उत्पादन साधन/विधियाँ/क्रियाएँ, जो एक-दूसरे के लिये समान दर से प्रतिस्थापित की जा सकती हैं और जिनके उपयोग से उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मानव-श्रम या दूध निकालने की मशीन द्वारा पशुओं का दूध निकालना, फसल की कटाई के लिये रीपर या मानव-श्रम का उपयोग करना; फसल की गहुराई के लिये प्रेसर या बैलों के श्रम का उपयोग करना, कुट्टी काटने के लिये कुट्टी की हाथ से चलने वाली मशीन अथवा ट्रैक्टर द्वारा कुट्टी कटवाना आदि।
- (ii) वे उत्पादन-साधन/विधियाँ/क्रियाएँ, जो एक-दूसरे के लिए विभिन्न दर से प्रतिस्थापित की जा सकती हैं और जिनके उपयोग से उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे—नत्रजन उर्वरक की पूर्ति के लिये उपलब्ध विभिन्न नत्रजन उर्वरक—यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट अथवा अन्य उर्वरकों को विभिन्न अनुपातों में मिलाना; सन्तुलित भोजन की पूर्ति के लिये विभिन्न चारे एवं दाने को विभिन्न मात्रा में मिलाना।
- (iii) वे उत्पादन-साधन/विधियाँ/क्रियाएँ, जो एक-दूसरे के लिये प्रतिस्थापित की जा सकती हैं और जिनके उपयोग से उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होता है। जैसे विभिन्न फसलों के देशी एवं सकर/बोने किस्म के बीजों का उपयोग—देशी मक्का एवं सकर मक्का के बीज, देशी किस्म एवं बोनी किस्म के गेहूँ के बीज आदि।

विभिन्न उपलब्ध विधियों या क्रियाओं में से एक विधि या क्रिया का चुनाव उत्पादन-साधनों की प्रतिस्थापन दर, विधि या क्रिया के उपयोग से होने वाली लागत व उनसे प्राप्त प्रतिफल की राशि पर निर्भर होता है। ऐसा माना जाता है कि उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न विधियों के प्रयोग से प्राप्त प्रतिफल

की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः प्रतिफल की मात्रा की समानता की अवस्था में न्यूनतम लागत के निर्णय, विधियों की लागत एवं उनकी प्रतिस्थापन दर के आधार पर ही लिये जाते हैं। प्रत्येक वृषक फार्म पर उत्पादन की न्यूनतम लागत लाने के लिये अधिक लागत वाले साधन/क्रिया के स्थान पर कम लागत वाले साधन/क्रिया का चुनाव करना है।

साधनों/विधियों/क्रियाओं की प्रतिस्थापन की समस्याओं को हल करने के लिये उनकी प्रतिस्थापन की दर व कीमतों का ज्ञान होना आवश्यक है। उत्पादन-साधनों के प्रतिस्थापन की दर व उनकी कीमतों का विलोम अनुपात निम्न प्रकार से ज्ञात किये जाते हैं—

उत्पादन साधनों की प्रतिस्थापन की दर

$$= \frac{\text{प्रतिस्थापित किये गये साधन/क्रिया की इकाइयाँ}}{\text{वृद्धि किये गये साधन/क्रिया की इकाइयाँ}} = \frac{-\Delta X_2}{\Delta X_1}$$

जबकि ΔX_0 = प्रतिस्थापित साधन/क्रिया में परिवर्तन की मात्रा

ΔX_1 = वृद्धि किये गये साधन/क्रिया में परिवर्तन की मात्रा

साधनों/क्रियाओं की प्रतिस्थापन दर $(\Delta X_2/\Delta X_1)$ का चिह्न ऋणात्मक होता है,² क्योंकि जब एक साधन/क्रिया की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो दूसरे साधन/क्रिया की मात्रा में कमी होती है।

कीमतों का विलोम अनुपात

$$= \frac{\text{वृद्धि किये गये साधन की प्रति इकाई कीमत}}{\text{प्रतिस्थापित किये गये साधन की प्रति इकाई कीमत}} = \frac{Px_1}{Px_2}$$

साधनों/क्रियाओं के प्रतिस्थापन की अवस्था में निर्णय लेने के नियम—
साधनों/क्रियाओं के प्रतिस्थापन की अवस्था में निर्णय लेने के निम्न तीन मुख्य नियम होते हैं—

(1) यदि साधनों/क्रियाओं की प्रतिस्थापन दर उनकी विलोम कीमतों के

अनुपात से अधिक $\left(\frac{-\Delta X_2}{\Delta X_1} > \frac{Px_1}{Px_2} \right)$ है तो क्रियाओं के

प्रतिस्थापन करने से फार्म पर लागत कम होती है। अतः उपर्युक्त अवस्था में साधनों/क्रियाओं का प्रतिस्थापन उस स्थिति तक करते रहना चाहिये, जब तक दोनों अनुपात परस्पर समान नहीं हो जाते हैं।

2. साधारणतया निम्न में ऋणात्मक चिह्न का प्रयोग नहीं किया जाता है।

(ii) यदि साधनो/क्रियाओं की प्रतिस्थापन दर, उनकी विलोम कीमतों के अनुपात से कम $\left(-\frac{\Delta X_2}{\Delta X_1} < \frac{P_{X_1}}{P_{X_2}} \right)$ है तो प्रतिस्थापन करने से फार्म पर लागत में वृद्धि होती है। अतः उपर्युक्त अवस्था में प्रतिस्थापन नहीं करना चाहिये।

(iii) यदि साधनो/क्रियाओं की प्रतिस्थापन दर उनकी विलोम कीमतों के अनुपात के बराबर $\left(-\frac{\Delta X_2}{\Delta X_1} = \frac{P_{X_1}}{P_{X_2}} \right)$ है तो वह स्तर उत्पादन साधन के संयोग का न्यूनतम लागत का स्तर कहलाता है।

विभिन्न साधनो/क्रियाओं/विधियों के प्रतिस्थापन के निम्न लेते समय मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिये कि जो उत्पादन-साधन/क्रिया प्रतिस्थापित की जाती है उसकी लागत जिस साधन/क्रिया द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है उससे अधिक होनी चाहिये। साधनो/क्रियाओं के प्रतिस्थापन का मुख्य उद्देश्य फार्म पर साधनो के लागत व्यय को कम करना होता है।

एक निश्चित उत्पत्ति की मात्रा के लिए साधनो/क्रियाओं का प्रतिस्थापन निम्न दरों से होता है —

(1) समान दर से उत्पादन साधनो में प्रतिस्थापन।

समान दर से उत्पादन-साधनो के प्रतिस्थापन की अवस्था में एक उत्पादन-साधन की प्रत्येक एक इकाई की वृद्धि दूसरे उत्पादन साधन की मात्रा में क्रमशः समान मात्रा में प्रतिस्थापन करती है, जैसे—दूध निकालने की मशीन एवं मानव-श्रम द्वारा पशुओं का दूध निकालना रीपर अथवा मानव श्रम द्वारा फसल की कटाई करना आदि। निम्न उदाहरण समान दर से उत्पादन साधनो के प्रतिस्थापन की अवस्था में निर्णय लेने की विधि को स्पष्ट करता है —

उदाहरण—एक फार्म पर 1000 लीटर दूध का उत्पादन होता है। फार्म पर मशीन एवं मानव-श्रम द्वारा पशुओं का दूध निकाला जा सकता है। निम्न आकड़ों के आधार पर न्यूनतम लागत स्तर ज्ञात कीजिये।

सारणी 66

समान दर से उत्पादन साधनों के प्रतिस्थापन की अवस्था में
न्यूनतम लागत स्तर ज्ञात करना

मशीन द्वारा दूध निकालना मशीनों की संख्या	मानव-श्रम द्वारा दूध निकालना श्रमिकों की संख्या	विधियों की प्रतिस्थापन दर	विधियों की विलोम कीमतों का अनुपात $X_1=24.00$ रु $X_2=3.00$ रु	एक हजार लीटर दूध निकालने की कुल लागत
(X_1)	(X_2)	$\left(\frac{\Delta X_2}{\Delta X_1}\right)$	$\left(\frac{Px_1}{Px_2}\right)$	(रु०)
0	50			150
		10	8	
1	40			144
		10	8	
2	30			138
		10	8	
3	20			132
		10	8	
4	10			126
		10	8	
5	0			120

सारणी में क्रियाओं की प्रतिस्थापन दर, उनकी विलोम कीमतों के अनुपात से अधिक है। साधन/क्रियाओं के संयोग के नियम के अनुसार मानव-श्रम के स्थान पर मशीन प्रतिस्थापित करने से लागत में कमी होती जाती है। इस उदाहरण में 1000 लीटर दूध निकालने की मशीन द्वारा कुल लागत 120 रु आती है जो मानव-श्रम द्वारा दूध निकालने अथवा मानव-श्रम एवं मशीन के संयोग के उपयोग से कम है। उपर्युक्त प्रतिस्थापन दर व कीमतों की अवस्था में मशीन द्वारा दूध निकालने में लागत कम आती है। साधारणतया समान-दर से उत्पादन-साधनों/क्रियाओं के प्रतिस्थापन की अवस्था में दोनों में से एक उत्पादन-साधन का उपयोग न्यूनतम लागत स्तर प्रदान करता है।

(ii) ह्रास-दर से उत्पादन-साधनों में प्रतिस्थापन

ह्रास-दर से उत्पादन-साधनों के प्रतिस्थापन की अवस्था में निश्चित उत्पत्ति के लिये एक उत्पादन-साधन की प्रत्येक एक इकाई की वृद्धि, दूसरे उत्पादन साधन की मात्रा में क्रमशः पहले की अपेक्षा कम मात्रा प्रतिस्थापित करती है। उदाहरण-तया, पशुओं को खिलाने के लिये विभिन्न चारे (सूखा एवं हरा चारा) एक-दूसरे को ह्रास-दर से प्रतिस्थापित करते हैं। निम्न उदाहरण ह्रास-दर से उत्पादन-साधनों की प्रतिस्थापन अवस्था में निर्णय लेने की विधि को स्पष्ट करता है।

उदाहरण— एक पशु से दैनिक 10 किलोग्राम दूध प्राप्त करने के लिये सूखा चारा 'क' एवं हरा चारा 'ख' के निम्न संयोग उपयोग में लाये जा सकते हैं। निम्न आकड़ों के आधार पर 10 किलोग्राम दूध दैनिक प्राप्त करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यूनतम लागत वाले चारे का संयोग ज्ञात कीजिये।

सारणी में सूखे चारे की प्रत्येक इकाई, हरे चारे की पहलू की अपेक्षा क्रमशः कम मात्रा प्रतिस्थापित करती है। सूखा चारा 'क' व हरा चारा 'ख' के उपर्युक्त किसी भी संयोग को खिलाने से पशु से दूध की समान मात्रा प्राप्त होती है। इस स्थिति में कृषक लागत कम करने के लिये न्यूनतम लागत वाले चारे का संयोग ज्ञात करना चाहता है। न्यूनतम लागत-संयोग वह है जहाँ पर साधनों की प्रतिस्थापन दर का अनुपात उनकी विलोम कीमतों के अनुपात के बराबर होता है।

सारणी में 16 किलोग्राम सूखा चारा 'क' व 12 किलोग्राम हरा चारा 'ख' के संयोग तक प्रतिस्थापन दर विलोम कीमतों के अनुपात से अधिक है और उसके पश्चात् चारे की प्रतिस्थापन दर का अनुपात उनकी विलोम कीमतों के अनुपात से कम होता जाता है। साधनों के प्रतिस्थापन नियम के अनुसार 16 किलोग्राम सूखा चारा व 12 किलोग्राम हरा चारा का संयोग ही न्यूनतम लागत-संयोग है। इस संयोग की कुल लागत 3 20 रु० होती है जो अन्य सभी संयोगों की लागत से कम है। अतः पशु से 10 किलोग्राम दूध प्राप्त करने के लिये 16 किलोग्राम सूखा चारा व 12 किलोग्राम हरा चारा खिलाना चाहिये, क्योंकि यह स्तर न्यूनतम लागत का संयोग है।

सारणी 67

ह्रास दर से उत्पादन-साधनों के प्रतिस्थापन में न्यूनतम लागत वाले चारे का संयोग ज्ञात करना

सूखा चारा 'क'	हरा चारा 'ख'	चारा 'क' की चारा 'ख' के लिए प्रतिस्थापन की दर	विलोम कीमतों का अनुपात चारा 'क' ₹ 14/क्वि. एवं चारा 'ख' ₹ 8/क्वि.	दस किलोग्राम दूध प्राप्त करने के लिए पशु को चारा खिलाने की कुल लागत
(किलोग्राम)	(किलोग्राम)	$\left(\frac{\Delta \text{ख}}{\Delta \text{क}}\right)$	$\left(\frac{P_{\text{क}}}{P_{\text{ख}}}\right)$	(₹०)
10	30			3.80
		4.0	1.75	
12	22	3.0	1.75	3.44
14	16	2.0	1.75	3.24
16	12	1.0	1.75	3.20
18	10	0.75	1.75	3.32
20	8.5	0.50	1.75	3.48
22	7.5	0.25	1.75	3.68
24	7.0			3.92

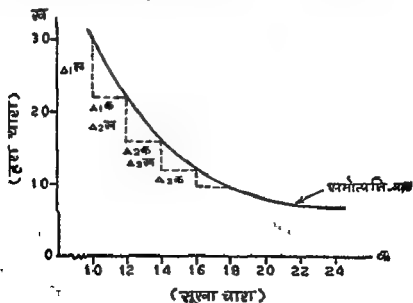
समोत्पत्ति-वक्र—समोत्पत्ति-वक्र की विधि भी उत्पादन साधनों के इष्टतम संयोग को ज्ञात करने में प्रयुक्त की जाती है। चूंकि दो उत्पादन-साधनों व एक उत्पाद के सम्बन्ध को ग्राफ की सहायता से स्पष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन समोत्पत्ति वक्र द्वारा उपर्युक्त सम्बन्ध को सरलतापूर्वक प्रदर्शित किया जा सकता है। समोत्पत्ति-वक्र भी उदासीनता-वक्र (Indifference Curve) की तरह एक सामान्य किस्म का वक्र होता है। उदासीनता-वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान संतोष प्रदान करते हैं। उसी प्रकार

समोत्पत्ति-वक्र भी दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनके उपयोग से उत्पाद की समान मात्रा प्राप्त होती है। समोत्पत्ति-वक्र पर प्रत्येक बिन्दु समान उत्पत्ति की मात्रा का चोतक होता है।

समोत्पत्ति-वक्र की भी सामान्य विशेषताएँ वे ही हैं जो उदासीनता-वक्र की होती हैं, जैसे—दो समोत्पत्ति-वक्र एक-दूसरे को नहीं काटते हैं तथा समोत्पत्ति-वक्र बायीं ओर नीचे की तरफ झुकता है। समोत्पत्ति-वक्र का नीचे की ओर ढाल एक साधन के लिये दूसरे साधन को प्रतिस्थापित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिये साधनों का जो संयोग आवश्यक होता है, वह एक साधन की मात्राओं को दूसरे साधन की मात्राओं से प्रतिस्थापित करके परिवर्तित किया जा सकता है। समोत्पत्ति-वक्र का ढलान सीमान्त उत्पत्ति की मात्राओं का अनुपात $\left(\frac{MPX_1}{MPX_2}\right)$ होता है।

पिछले पृष्ठों में उत्पादन-साधनों के प्रतिस्थापन के सिद्धान्त को स्पष्ट करते समय उत्पादन-साधनों की दो विभिन्न प्रतिस्थापन दरों के आधार पर साधनों का इष्टतम संयोग ज्ञात किया गया था। उपर्युक्त समस्या को समोत्पत्ति-वक्र एवं सम-लागत वक्र (Isocost Curve) द्वारा भी हल किया जा सकता है।

साधनों के ह्रासमान दर से प्रतिस्थापन की स्थिति में समोत्पत्ति-वक्र—साधनों के ह्रासमान दर से प्रतिस्थापन के उदाहरण में प्राप्त समोत्पत्ति-वक्र चित्र 6.5 में प्रदर्शित किया गया है।



चित्र 6.5- साधनों के ह्रासमान दर से प्रतिस्थापन की स्थिति में समोत्पत्ति-वक्र

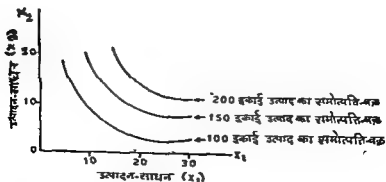
उपरोक्त चित्र में प्राप्त समोत्पत्ति-वक्र पर विभिन्न बिन्दु उत्पादन-साधन (क) और उत्पादन-साधन (ख) के उन संयोगों को प्रदर्शित करते हैं, जिनसे उत्पत्ति की 10 इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। ह्रासमान दर से प्रतिस्थापन की अवस्था में समोत्पत्ति-वक्र कम ढालू (Less steep) होता है। साधनों की प्रतिस्थापन दर निम्न प्रकार से होती है—

$$-\frac{\Delta_1 \text{ख}}{\Delta_1 \text{क}} > -\frac{\Delta_2 \text{ख}}{\Delta_2 \text{क}} > -\frac{\Delta_3 \text{ख}}{\Delta_3 \text{क}} > \dots > -\frac{\Delta_n \text{ख}}{\Delta_n \text{क}}$$

अर्थात् इसके अन्तर्गत उत्पादन-साधन 'क' की प्रत्येक इकाई उत्पादन-साधन 'ख' को उत्तरोत्तर कम मात्रा में प्रतिस्थापित करती है।

विभिन्न उत्पादन-स्तर की मात्राओं को भिन्न-भिन्न समोत्पत्ति-वक्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अधिक उत्पादन-स्तर वाला समोत्पत्ति-वक्र अपेक्षाकृत अधिक ऊँचाई पर होता है। इस प्रकार एक ही चित्र में विभिन्न उत्पादन की मात्राएँ प्रदान करने वाले समोत्पत्ति वक्रों को प्रदर्शित किया जा सकता है और प्राप्त चित्र को समोत्पत्ति वक्र का चित्र कहते हैं। विभिन्न समोत्पत्ति-वक्रों के लिए उत्पादन-साधनों के विभिन्न संयोगों की आवश्यकता होती है। चित्र 6.6 में प्रत्येक समोत्पत्ति-वक्र उत्पादन की एक निश्चित मात्रा प्रदर्शित करता है।

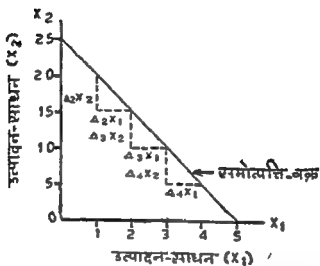
साधनों के समान-दर से प्रतिस्थापन की स्थिति में समोत्पत्ति-वक्र—उत्पादन साधनों के समान-दर से प्रतिस्थापन की अवस्था में प्राप्त समोत्पत्ति वक्र एक सीधी रेखा के रूप में होता है। इसमें एक उत्पादन-साधन दूसरे उत्पादन-साधन को उत्तरोत्तर समान-दर से प्रतिस्थापित करता है। समान-दर से साधनों के प्रतिस्थापन की अवस्था में समोत्पत्ति-वक्र का ढाल सभी बिन्दुओं पर समान होता है एवं साधनों की प्रतिस्थापन दर अप्रकट होती है—



चित्र 6.6 उत्पाद की विभिन्न मात्राओं के लिए समोत्पत्ति-वक्र

$$\frac{-\Delta_1 X_2}{\Delta_1 X_1} = \frac{-\Delta_2 X_2}{\Delta_2 X_1} = \dots = \frac{-\Delta_n X}{\Delta_n X}$$

इस अवस्था में प्राप्त समोत्पत्ति वक्र चित्र 6.7 में प्रदर्शित किया गया है।



चित्र 6.7 साधनों के समान-दर से प्रतिस्थापन की स्थिति में समोत्पत्ति-वक्र समोत्पत्ति-वक्र एवं समलागत वक्र द्वारा न्यूनतम लागत वाले साधनों का समीक्षा करना

समोत्पत्ति वक्र एवं समलागत-वक्र द्वारा न्यूनतम लागत वाले साधनों के समीक्षा को जान करन में पूर्व समलागत वक्र का अर्थ स्पष्ट करना आवश्यक है।

समलागत-वक्र से तात्पर्य—समलागत-वक्र साधनों के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिन्हें कृषक उसके द्वारा किये जाने वाले लागत परिव्यय और प्रत्येक उत्पादन साधन की प्रति इकाई कीमत ज्ञात होने पर खर्च कर सकता है। साधनों के प्रत्येक संयोग (जो लागत परिव्यय की राशि से खर्च किये जा सकते हैं) की कुल लागत समान होती है।

उदाहरणतया कृषक के फार्म पर दूध निकालने के दो साधन X_1 और X_2 हैं। उनकी कीमतें क्रमशः P_{X_1} और P_{X_2} हैं और कुल लागत परिव्यय की राशि C है। यदि

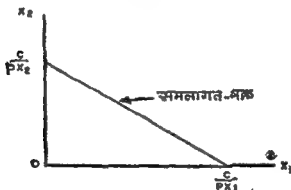
कृषक केवल X_1 साधन का उपयोग करना है तो वह उसकी $\frac{C}{P_{X_1}}$ इकाइयां खर्च

कर सकता है। यदि केवल x_2 साधन का उपयोग करता है तो इसको $\frac{C}{Px_2}$ इकाइयाँ

क्रय कर सकता है। x और y अक्षों पर अंकित दो बिन्दुओं को मिलाने वाली एक सरल रेखा x_1 और x_2 साधनों के उन समस्त संयोगों को प्रकट करती है, जिन्हें कृपक अर्पित दिये हुए लागत-परिव्यय से क्रय कर सकता है। यह रेखा समलागत-वक्र कहलाती है। समलागत वक्र का ढाल निम्न प्रकार का होता है—

$$\frac{\frac{C}{Px_2}}{\frac{C}{Px_1}} = \frac{C}{Px_2} \times \frac{Px_1}{C} = \frac{Px_1}{Px_2} \quad \begin{array}{l} \text{जहाँ } C = \text{कुल लागत परिव्यय} \\ P = \text{प्रति इकाई कीमत} \\ x_1 \text{ और } x_2 = \text{उत्पादन-साधन} \end{array}$$

समलागत वक्र चित्र 68 में प्रदर्शित किया गया है।



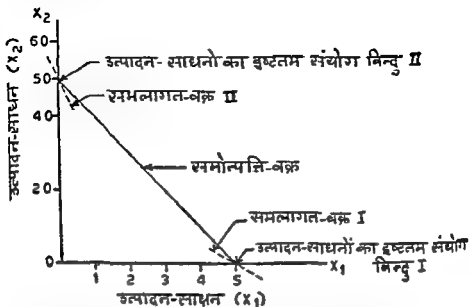
चित्र 68 समलागत-वक्र

चित्र 68 समलागत-वक्र

समोत्पत्ति-वक्र व समलागत-वक्र ज्ञात करने के पश्चात् साधनों के न्यूनतम लागत वाले संयोग को ज्ञात करने के लिए दोनों वक्रों को एक ही ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं। जिस बिन्दु पर समलागत-वक्र, समोत्पत्ति-वक्र का स्पर्शी (Tangent) होता है, वह बिन्दु उत्पादन-साधनों का न्यूनतम लागत का संयोग होता है। उत्पादन साधनों के न्यूनतम लागत संयोग-बिन्दु पर समोत्पत्ति-वक्र एवं समलागत वक्र का ढाल बराबर होता है। इस प्रकार इस साम्य बिन्दु पर

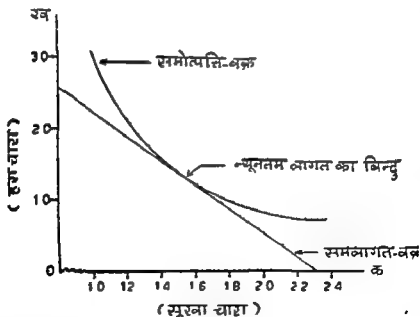
$$\frac{MPX_1}{MPX_2} = \frac{-\Delta X_2}{\Delta X_1} = \frac{Px_1}{Px_2} \text{ की स्थिति होती है।}$$

समान-दर से साधनों के प्रतिस्थापन में समोत्पत्ति-वक्र एवं समलागत-वक्र द्वारा साधनों के न्यूनतम लागत का संयोग बिन्दु ज्ञात करने की विधि चित्र 69 में प्रदर्शित की गई है।



चित्र 6.9 समान-दर से साधनों के प्रतिस्थापन में समोत्पत्ति-वक्र एवं समलागत-वक्र द्वारा उत्पादन-साधनों का न्यूनतम लागत संयोग बिन्दु ज्ञात करना।

ह्रासमान दर से साधनों के प्रतिस्थापन में समोत्पत्ति-वक्र व समलागत-वक्र द्वारा साधनों के संयोग का न्यूनतम लागत-बिन्दु ज्ञात करने की विधि चित्र 6.10 में प्रदर्शित की गई है।



चित्र 6.10 ह्रासमान-दर से साधनों के प्रतिस्थापन में समोत्पत्ति-वक्र एवं समलागत-वक्र द्वारा उत्पादन-साधनों का न्यूनतम लागत संयोग-बिन्दु ज्ञात करना।

दो से अधिक उत्पादन-साधनों के उपयोग की अवस्था में न्यूनतम लागत संयोग ज्ञात करता :

पिछले पृष्ठों में दो उत्पादन-साधनों के न्यूनतम लागत संयोग का विवेचन किया गया है। न्यूनतम लागत संयोग ज्ञात करने के निर्णय के लिये उत्पादन साधनों की प्रतिस्थापन दर के अनुपात को उनकी कीमतों के विलोम अनुपात के बराबर किया जाता है :

$$\frac{\Delta X_1}{\Delta X_2} = \frac{Px_2}{Px_1}$$

$$+ X_1 Px_1 = \Delta X_2 Px_2$$

प्रतिस्थापित साधन की लागत = वृद्धि किये गये साधन की लागत

उत्पादन-प्रक्रिया में दो से अधिक उत्पादन साधन विविधता भी प्रयुक्त की जाती है जैसे नत्रजन की पूर्ति के लिये यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक प्रयुक्त किये जा सकते हैं। न्यूनतम लागत के निर्णय के उपर्युक्त नियम का दो से अधिक उत्पादन साधन/क्रियाओं के लिये भी उपयोग किया जा सकता है। उत्पाद की निश्चित मात्रा की प्राप्ति के लिये तीन उत्पादन-साधनों की न्यूनतम लागत का संयोग निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है :

$$\frac{\Delta X_1}{\Delta X_2} = \frac{Px_2}{Px_1}$$

$$\frac{\Delta X_2}{\Delta X_3} = \frac{Px_3}{Px_2}$$

$$\frac{\Delta X_3}{\Delta X_1} = \frac{Px_1}{Px_3}$$

जबकि X_1 , X_2 एवं X_3 तीन उत्पादन-साधन हैं।

3. सम-सीमान्त प्रतिफल का सिद्धान्त अथवा सीमित-साधन और अवसर परिदृश्य (बैकल्पिक लागत) का सिद्धान्त :

कृषकों के पास असीमित मात्रा में उत्पादन-साधन होने की अवस्था में साधनों के आवंटन से सम्बन्धित समस्याएँ उत्पन्न नहीं होती हैं तथा वे विभिन्न उद्यमों को इच्छानुरूप स्तर में अपना सकते हैं। बहुधा कृषकों के पास भूँजी एवं उत्पादन के अन्य साधन—भूमि, उर्वरक, श्रम, सिंचाई के लिए पानी आदि सीमित मात्रा में होते हैं। उत्पादन-साधनों की सीमितता की अवस्था में कृषक विभिन्न उद्यमों/फसलों को इच्छित मात्रा में उत्पादित नहीं कर सकते हैं जिसके कारण कृषकों की समस्या होती है कि सीमित उत्पादन-साधनों को विभिन्न उद्यमों/फसलों में किस प्रकार आवंटित

करें ताकि उपलब्ध सीमित उत्पादन-साधनों से फार्म पर अधिकतम लाभ की राशि प्राप्त हो सके। उदाहरणतया क्षेत्रफल की सीमितता की अवस्था में एक फसल के अन्तर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि तभी सम्भव है जब दूसरी फसल के अन्तर्गत क्षेत्रफल कम किया जाए। इसी प्रकार उर्वरक के सीमित मात्रा में होने की स्थिति में कृषक के लिए समस्या उत्पन्न होती है कि उपलब्ध उर्वरक की मात्रा को विभिन्न फसलों में किस प्रकार आवंटित करें ताकि उर्वरक के उपयोग से फार्म पर अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। सम सीमान्त प्रतिफल का सिद्धान्त अथवा सीमित साधनों एवं अवसर परिव्यय का सिद्धान्त कृषकों के लिए उपलब्ध सीमित साधनों के समुचित आवंटन से सम्बन्धित समस्याओं को अधिकतम लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य के लिए हल करने में सहायक होता है।

अवसर परिव्यय या लागत (Opportunity Cost) से तात्पर्य फार्म पर चुने गए विकल्प के बाद दूसरे उत्तम विकल्प से प्राप्त होने वाले मूल्य से है जो फार्म पर नहीं चुना गया है। फार्म पर नहीं चुने गए उद्यम से प्राप्त आय, चुने गये उद्यम की लागत कहलाती है।

सम सीमान्त प्रतिफल के सिद्धान्त का नियम—अवसर लागत के सिद्धान्त के अनुसार फार्म पर अधिकतम लाभ की प्राप्ति के लिए सीमित साधनों की प्रत्येक इकाई का विभिन्न उद्यमों/फसलों में इस प्रकार उपयोग किया जाना चाहिये कि उत्पादन साधन की प्रत्येक इकाई से अधिकतम सीमान्त आय प्राप्त हो सके। कृषकों को अधिकतम लाभ, सीमान्त-आय के ज्ञान के आधार पर निर्णय लेने से प्राप्त होता है। सम-सीमान्त-प्रतिफल के सिद्धान्त के अनुसार निर्णय लेने के लिये कृषकों को निम्न भाँकड़ों की आवश्यकता होती है :

- (1) विभिन्न उद्यमों/वस्तुओं की कीमतें।
- (ii) विभिन्न उद्यमों/वस्तुओं की उत्पादन-लागत।
- (iii) एक वस्तु के उत्पादन से दूसरी वस्तु के प्रतिस्थापन द्वारा हुई उत्पत्ति की कम मात्रा।

उदाहरण, निम्न उदाहरण सम-सीमान्त प्रतिफल के सिद्धान्त द्वारा निर्णय लेने की विधि को स्पष्ट करता है :—

— एक कृषक के फार्म पर विभिन्न उद्यमों के उत्पादन के लिए 1000 रु० की सीमित पूँजी उपलब्ध है। कृषक उपलब्ध सीमित पूँजी में गेहूँ, चना, सरसो व दूध उत्पादन करना चाहता है। विभिन्न वस्तुओं में 200 रु० पूँजी की प्रत्येक इकाई निवेशित करने से निम्न प्रकार से सीमान्त आय (काल्पनिक भाँकड़े) प्राप्त होती है। ज्ञात कीजिए कि उपलब्ध सीमित पूँजी से अधिकतम आय की प्राप्ति के लिए विभिन्न उद्यमों में किननी पूँजी निवेश करना चाहिए ?

सारणी 68

फार्म पर विभिन्न उद्यमों में पूँजी की विभिन्न राशि निवेशित करने से प्राप्त सीमान्त आय

पूँजी निवेश की राशि (रु.)		विभिन्न उद्यमों से प्राप्त सीमान्त आय (रुपये)		
		गेहूँ	चना	दूध
प्रथम	200	500 IV	400	600 I 550 II
द्वितीय	200	450	300	500 III 475 V
तृतीय	200	400	275	450 400
चतुर्थ	200	300	250	400 300
पंचम	200	250	200	300 200
1000 रु की कुल पूँजी निवेश करने से प्राप्त कुल सीमान्त आय		1900	1425	2250 1925
प्रति रुपया निवेश से प्राप्त औसत आय		1.90	1.425	2.25 1.925

कृषक को सीमित पूँजी के उपयोग से विभिन्न उद्यमों में सबसे अधिक 2250 रु की आय सरसो की फसल उत्पन्न करने से प्राप्त होती है। इस फसल से प्रति रुपया औसत आय 2.25 रु प्राप्त होती है। लेकिन अबसर लागत का सिद्धान्त औसत आय के अनुसार निर्णय न लेकर सीमान्त आय के आधार पर निर्णय लेने की सलाह देता है। अबसर लागत के सिद्धान्त के अनुसार प्रथम 200 रु सरसो उद्यम में निवेश करना चाहिए क्योंकि सरसो उद्यम से अन्य उद्यमों की अपेक्षा आय अधिक होती है। द्वितीय 200 रु का दूध-उत्पादन उद्यम में निवेश किया जाना चाहिये क्योंकि दूध उद्यम से प्राप्त आय अन्य सभी उद्यमों की अपेक्षा अधिक होती है। इस प्रकार अबसर लागत के सिद्धान्त के अनुसार कृषक को अपनी सीमित पूँजी में से 400 रु सरसो उद्यम, 400 रु दूध उद्यम व शेष 200 रु गेहूँ उद्यम में निवेशित करना चाहिए। उपर्युक्त प्रकार से विभिन्न उद्यमों में पूँजी निवेश करने से कृषक को 2625 रु की आय प्राप्त होती है, जो फार्म पर विभिन्न उद्यमों को वैयक्तिक रूप में लेने या उद्यमों के अन्य संयोग पर पूँजी निवेश करने से प्राप्त आय से अधिक होती है। अतः अबसर लागत का सिद्धान्त फार्म पर कृषकों को प्राप्त होने वाली आय की राशि में वृद्धि करता है।

अवसर-लागत का सिद्धान्त कृषकों की अन्य समस्याओं, जैसे-फसल की कटाई, गापटा, मक्का छीलने की मशीन का प्रयुक्त करने अथवा उन्हें किराये पर लेने आदि के सम्बन्ध में निर्णय लेने में भी सहायक होता है।

4 लागत का सिद्धान्त

फार्म-प्रबन्ध का यह सिद्धान्त कृषकों को फार्म पर होने वाली विभिन्न प्रकार की लागतों के आधार पर निर्णय लेने में सहायता करता है। कृषि या अन्य उद्योगों में होने वाली लागतें दो प्रकार की होती हैं

(अ) स्थिर या बंधी लागत—फार्म पर होने वाली वह सभी लागत, जो उद्यमों के उत्पादन की मात्रा में किसी निश्चित योजनाकाल में परिवर्तन नहीं लाती है, स्थिर लागत कहलाती है। स्थिर लागत का उद्यम के उत्पादन की मात्रा से सम्बन्ध नहीं होता है। अधिक उत्पादन होने या उत्पादन न करने या उत्पादन कम होने की सभी स्थितियों में स्थिर लागत समान रहती है। भूमि का लगान, प्राप्त ऋण का व्याज, मशीनों का मूल्य-हास, कर, फसल बीमा की किश्त की राशि, बिजली के मीटर का किराया आदि फार्म पर स्थिर लागत कहलाती है।

(ब) परिवर्तनशील लागत—फार्म पर होने वाली वे सभी लागतें, जो उद्यमों के उत्पादन की मात्रा में अल्पावधि में परिवर्तन लाती है, परिवर्तनशील लागत कहलाती हैं। परिवर्तनशील लागत की राशि अधिक व कम करने पर उत्पादन की मात्रा में वृद्धि व कमी होती है। उत्पाद की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए परिवर्तनशील लागत की राशि अधिक आती है। उत्पादन नहीं करने की स्थिति में परिवर्तनशील लागत शून्य होती है। परिवर्तनशील लागत व उत्पाद की मात्रा में सीधा सम्बन्ध होता है। बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, श्रम, बिजली आदि की लागत परिवर्तनशील लागत कहलाती है। स्थिर और परिवर्तनशील लागत के योग को कुल लागत कहते हैं। कुल आय-राशि में से कुल लागत की राशि के घटाने पर जो राशि शेष रहती है, वह लाभ कहलाती है। अल्पावधि में फार्म पर निर्णय लेने में परिवर्तनशील लागत ही महत्वपूर्ण होती है, स्थिर लागत महत्वपूर्ण नहीं होती है।

लागत के सिद्धान्त के नियम—इस सिद्धान्त के अनुसार फार्म पर निर्णय निम्न आधार पर लेना चाहिए

- (1) यदि फार्म से प्राप्त कुल आय, कुल लागत से अधिक है, तो कृषक को उस समय तक कृषि करते रहना चाहिये जब तक कि फार्म से प्राप्त अतिरिक्त आय की राशि अतिरिक्त लागत की राशि से अधिक होती है। इस नियम के आधार पर निर्णय लेने से कृषकों को प्राप्त होने वाले लाभ की राशि में निरन्तर वृद्धि होती है।

- (ii) यदि फार्म से प्राप्त कुल आय, कुल लागत की राशि से कम है परन्तु प्राप्त आय परिवर्तनशील लागत की राशि से अधिक है तो कृषको को अन्त्यावधि में कृषि उस समय तक करते रहने का निर्णय लेना चाहिए जब तक कि प्राप्त अतिरिक्त आय की राशि, अतिरिक्त लागत की राशि से अधिक होती है। इस नियम के आधार पर निर्णय लेने से कृषको को होने वाली हानि की राशि में कमी होती है।
- (iii) यदि फार्म से प्राप्त कुल आय, परिवर्तनशील लागत की राशि से भी कम है तो कृषको को कृषि नहीं करने का निर्णय लेना चाहिए। कृषि करने से फार्म पर होने वाली हानि की राशि में निरन्तर वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में भूमि को या तो परती छोड़ देना चाहिए अथवा दूसरो को बटाई पर दे देना चाहिए।

लागत के सिद्धान्त का उदाहरण—निम्न उदाहरण लागत के सिद्धान्त एवं निर्णय लेने की विधि को स्पष्ट करता है—

उदाहरण 1 एक फार्म पर वर्ष में 56°0 रुपये की स्थिर व 10,000 रु की परिवर्तनशील लागत होती है। प्रतिवर्ष फार्म पर उपर्युक्त लागत करने से आगामी तीन वर्षों में निम्न प्रकार से आय प्राप्त होने का सम्भावना है। शायद कीजिये कि क्या कृषक को आगामी वर्षों में कृषि करनी चाहिए ?

प्रथम वर्ष—सम्भावित आय रु. 19,200

द्वितीय वर्ष—सम्भावित आय रु. 11,500

तृतीय वर्ष—सम्भावित आय रु. 4,500

लागत के सिद्धान्त के नियमों के अनुसार कृषक को कृषि करने सम्बन्धित निर्णय विभिन्न वर्षों में निम्न प्रकार से लेना चाहिए—

(अ) प्रथम वर्ष में कृषक को फार्म से 19,200 रु की कुल आय प्राप्त होने की सम्भावना है जबकि वर्ष में कुल लागत 15,600 रु की आती है। कृषि करने से कृषक को 3,600 रु (19,200 - 15,600 = 3,600 रु) का शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। अतः प्रथम वर्ष में कृषि करना लाभकर है।

(ब) द्वितीय वर्ष में कृषक को फार्म से 11,500 रु की कुल आय प्राप्त होने की सम्भावना है जबकि फार्म पर वर्ष में कुल लागत 15,600 रु की होती है। कृषि करने से कृषक 4,100 रु (15,600 - 11,500 = 4,100 रु) की शुद्ध हानि होती है। लेकिन प्राप्त कुल आय की राशि, परिवर्तनशील लागत की राशि (रु 10,000) से अधिक है। इस अवस्था में कृषक को कृषि नहीं करने से पूरी स्थिर लागत 5,600 रु की हानि होती है क्योंकि कृषि करने अथवा नहीं

करने की दोनों ही अवस्थाओं में स्थिर लागत समान रहती है। कृषक द्वारा कृषि करने की स्थिति में 4,100 रु की ही हानि होती है। कृषि करने से हानि की राशि में 1,500 रु की कमी होती है। अतः दूसरे वर्ष में भी कृषक को कृषि करने का निर्णय लेना चाहिए।

- (स) तृतीय वर्ष में कृषक को फार्म में 4,500 रु की कुल आय प्राप्त होने की सम्भावना है। सम्भावित कुल आय की राशि, फार्म पर कुल लागत तथा परिवर्तनशील लागत की राशि से बहुत कम है। अतः लागत के सिद्धान्त के नियम तीन के अनुसार तृतीय वर्ष में कृषि नहीं करने का निर्णय लेना चाहिए। इस वर्ष में कृषि करने से फार्म पर कुल स्थिर लागत (5,600 रु) व क्षेत्र परिवर्तनशील लागत 5,500 रु. ($10,000 - 4,500 = 5,500$ रु.) अर्थात् कुल 11,100 रु. की हानि होती है तथा कृषि नहीं करने की अवस्था में हानि मात्र स्थिर लागत 5,600 रु. की ही होती है।

उदाहरण 2. एक कृषक फार्म पर गेहूँ की फसल के उत्पादन में फसल की कटाई के पूर्व अर्थात् मार्च माह तक 2,750 रु प्रति हेक्टर की लागत कर चुका है। अप्रैल माह में मौसम की प्रतिकूलता के कारण गेहूँ की फसल से 1,500 रु प्रति हेक्टर की आय ही प्राप्त होने की सम्भावना रह जाती है। अप्रैल माह में फसल की कटाई, गायटा व सफाई की परिवर्तनशील लागत खर्च रह जाती है, जो 750 रु. प्रति हेक्टर है। क्या उपर्युक्त स्थिति में कृषक को गेहूँ की फसल की कटाई करने का निर्णय लेना चाहिए?

कृषक को फार्म से प्राप्त होने वाली सम्भावित कुल आय 1,500 रु. कुल लागत की राशि 3,500 रु ($2,750$ रु स्थिर + 750 रु परिवर्तनशील) से कम है; लेकिन सम्भावित आय, सम्भावित परिवर्तनशील लागत की राशि से अधिक है। लागत के सिद्धान्त के नियम दो के अनुसार कृषक को फसल की कटाई करने का निर्णय लेना चाहिए। फसल की कटाई का निर्णय लेने से कृषक को होने वाली हानि की राशि में 750 रु की कमी होती है। चूँकि गेहूँ की फसल की कटाई करने पर हानि 2,000 रु प्रति हेक्टर तथा कटाई नहीं करने पर हानि सपस्त स्थिर लागत 2,750 रु. की होती है। अतः कृषक को फसल की कटाई करने का निर्णय लेना चाहिए।

उदाहरण 3. एक फार्म पर एक एकड़ भूमि से उत्पन्न गेहूँ की मात्रा व उम्र पर होने वाली लागत के आँकड़े सारणी 6.9 में प्रदर्शित हैं। यदि गेहूँ की कीमत 200 रु. प्रति क्विन्टल हो तो ज्ञात कीजिए कि कृषक को अधिकतम लाभ के लिए कितनी मात्रा में गेहूँ का उत्पादन करना चाहिए?

सारणी 6.9

एक एकड़ भूमि से प्राप्त गेहूँ की मात्रा एवं उसकी विभिन्न लागतें

(रुपये में)

उत्पाद की मात्रा (क्वि)	कुल लागत	कुल आय	सीमान्त आय	सीमान्त लागत	श्रीसत लागत
10	1500	2000			150.00
11	1640	2200	200	140	149.09
12	1785	2400	200	145	148.75
13	1940	2600	200	155	149.23
14	2100	2800	200	160	150.00
15	2275	3000	200	175	151.66
16	2490	3200	200	215	155.62
17	2710	3400	200	220	159.41

उदाहरण से स्पष्ट है कि सभी उत्पादन स्तरों पर प्राप्त कुल आय, कुल लागत की राशि से अधिक है। लागत सिद्धान्त के नियम एक के अनुसार कृषक को उस स्तर तक उत्पादन वृद्धि करते रहना चाहिए, जब तक कि प्राप्त अतिरिक्त आय, अतिरिक्त लागत के बराबर न हो जाय। उपर्युक्त उदाहरण में कृषक को 15 क्विंटल प्रति एकड़ तक गेहूँ का उत्पादन करना चाहिए। उत्पादन के इस स्तर पर सीमान्त आय 200 रु व सीमान्त लागत 175 रु होती है। गेहूँ का उत्पादन 16 क्विंटल प्रति एकड़ करने की अवस्था में सीमान्त लागत 215 रु व सीमान्त आय 200 रु होती है अर्थात् लागत 15 रु आती है, जिससे प्राप्त लाभ की राशि में 15 रु की कमी होती है। अतः कृषक को अनुकूलतम लाभ 11 क्विंटल प्रति एकड़ गेहूँ उत्पादन करने की अवस्था में प्राप्त होता है।

कृषको को निर्णय सीमान्त आय व सीमान्त लागत के आधार पर ही लेना चाहिए। श्रीसत लागत के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिये। गेहूँ के उत्पादन की श्रीसत लागत 12 क्विंटल प्रति एकड़ की मात्रा तक गिरती है और इसके उपरान्त उत्पादन में वृद्धि होने पर श्रीसत उत्पादन-लागत में भी वृद्धि होती है।

औसत लागत के आधार पर निर्णय लेने में 12 क्विन्टल प्रति एकड़ तक ही गेहूँ का उत्पादन करना चाहिये। उत्पादन के इस स्तर पर कृषक को लाभ तो प्राप्त होता है लेकिन अनुकूलतम लाभ की राशि प्राप्त नहीं होती है।

5 उद्यमों के संयोग/प्रतिस्थापन का सिद्धान्त।

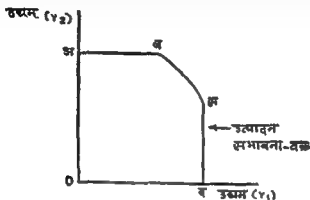
फार्म-प्रबन्ध का यह सिद्धान्त फार्म पर विभिन्न उद्यमों, — खाद्यान्न, दालों, कपास, गन्ना, तिलहन, पशु-पालन, कुक्कुट-पालन, फल एवं सब्जियों की फसलों के संयोग ज्ञात करने एवं विभिन्न उद्यमों के मध्य पाए जाने वाले सम्बन्धों का विश्लेषण करता है। इस सिद्धान्त का उद्देश्य कृषकों द्वारा फार्म पर लिए जाने वाले विभिन्न उद्यमों से अधिकतम लाभ की राशि प्राप्त करना है। उद्यमों के संयोग का सिद्धान्त, विभिन्न उद्यमों को फार्म पर किस अनुपात में मिलाया जाए, समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है, ताकि फार्म पर उपलब्ध उत्पादन साधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।

उद्यमों का संयोग, उद्यमों में पाए जाने वाले सम्बन्ध के ऊपर निर्भर होता है। विभिन्न उद्यमों में चार प्रकार के सम्बन्ध पाए जाते हैं।

(i) असम्बद्ध/स्वतन्त्र उद्यम—असम्बद्ध उद्यम वे हैं जिनमें आपस में कोई सम्बन्ध नहीं होता है। एक उद्यम के स्तर में वृद्धि करने से दूसरे उद्यम के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं आता है। अर्थात् दोनों उद्यम एक-दूसरे से न तो उत्पादन साधनों के लिए स्पर्धा रखते हैं और न ही वे एक-दूसरे उद्यम की उत्पादन वृद्धि में सहायक होते हैं। जब विभिन्न उद्यमों में कोई सम्बन्ध नहीं होता है तो दोनों उद्यमों को पृथक् रूप से फार्म पर उत्पन्न करने का निर्णय लेना चाहिये। जैसे—खरीफ के मौसम में बाजरा एवं रबी के मौसम में गेहूँ। उपर्युक्त उत्पादों में असम्बद्धता की स्थिति तब पायी जाती है, जब फार्म पर उपलब्ध उत्पादन साधन असंमित मात्रा में होते हैं।

(ii) सम्पूरक (Supplementary) उद्यम—जब विभिन्न उद्यम उत्पादन-साधनों के लिए न तो स्पर्धा करते हैं और न ही एक-दूसरे की उत्पादन वृद्धि में सहायक होते हैं, बल्कि उनका लेने से फार्म आय में वृद्धि होती है तो ऐसे उद्यमों को सम्पूरक उद्यम कहते हैं। सम्पूरक उद्यमों की अवस्था में एक उत्पाद की मात्रा में की गई वृद्धि अथवा कमी का दूसरे उत्पाद के उत्पादन स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरणतया खाद्यान्न उत्पादन के फार्म पर कुछ संख्या में कुक्कुट पालना, दूध के लिए एक या दो दुधारू पशु रखना, कुछ फल वाले वृक्ष लगाना मधुमक्खी पालन करना आदि सम्पूरक उद्यम कहनाते हैं, क्योंकि इनके साथ साथ करने से फार्म पर मुख्य फसल उद्यम के स्तर अथवा उत्पादन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही सम्पूरक उद्यम फार्म पर उपलब्ध बेकार अथवा अधिशेष उत्पादन-साधनों, जैसे—भूमि, मकान, चारा दाना आदि का सदुपयोग करके फार्म आय में वृद्धि करते हैं।

चित्र 6 11 उद्यमों में सम्पूरकता सम्बन्ध प्रदर्शित करता है। यह रेखाचित्र दो उत्पादों (Y_1 एवं Y_2) के उत्पादन-सम्भावना वक्र (Production possibility curve) को प्रदर्शित करते हैं, तथा इनके प्रत्येक बिन्दु पर उद्यमकर्त्ता समान कुल



चित्र 6 11 उद्यमों में सम्पूरकता का सम्बन्ध

लागत वहन करता है। अतः उत्पादन-सम्भावना वक्र के ढलाव को सीमान्त लागतों के अनुपात के रूप में (MC_{Y1}/MC_{Y2}) भी जानते हैं।

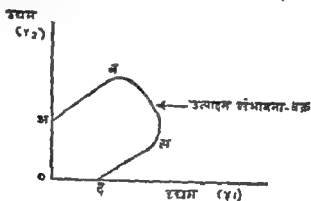
उद्यम Y_1 एवं Y_2 में अ से ब एवं द से स स्तर तक सम्पूरकता का सम्बन्ध विद्यमान है। उद्यमों में इस स्तर से आगे उत्पादन में वृद्धि करने पर वे मुख्य उद्यम से उत्पादन साधनों के लिए स्पर्धा करने लगते हैं। सम्पूरक उद्यम के क्षेत्रफल अथवा स्तर में वृद्धि करने के फलस्वरूप मुख्य उद्यम के क्षेत्रफल अथवा स्तर में कटौती करनी होती है।

कुछ उद्यम आपस में एक उत्पादन-साधन के लिए सम्पूरक होते हैं, लेकिन दूसरे उत्पादन-साधन के लिए स्पर्धा करते हैं, जैसे छोटे अनाज (Small Millets) एवं मक्का। ये उद्यम एक ही मौसम में बोये जाने के कारण भूमि के लिए आपस में स्पर्धा करते हैं जबकि थ्रिमिको एवं मशीनों के उपयोग के लिए ये सम्पूरक होते हैं, क्योंकि दोनों उद्यमों में कटाई, निराई गुड़ाई एवं अन्य कृषि कार्यों का समय मिला होता है।

विभिन्न उद्यमों में सम्पूरकता का सम्बन्ध पाए जाने की अवस्था में दोनों उद्यमों का उस स्तर तक उत्पादन करते रहना चाहिए, जब तक कि उनमें सम्पूरकता का सम्बन्ध विद्यमान रहता है एवं वैयक्तिक रूप से उनका उत्पादन लाभकर होता है। यदि सम्पूरक उद्यम से प्राप्त आय, उस पर होने वाली लागत की राशि से अधिक होती है तो सम्पूरक उद्यम को फार्म पर उत्पादन करना लाभप्रद होता है। ऐसी स्थिति में सम्पूरक उद्यम को उस स्तर तक बढ़ाना चाहिए जब तक कि वह मुख्य उद्यम से स्पर्धा नहीं करता है। विभिन्न उद्यमों में एक उत्पादन-साधन के लिए

स्पर्धा एवं अन्य उत्पादन साधनों के उपयोग में सम्पूर्णता का सम्बन्ध विद्यमान होने की स्थिति में निर्यात प्रतिस्पर्धा वाले उद्यमों के समान लेना चाहिये।

(iii) सहायक या पूरक (Complementary) उद्यम—पूरक उद्यम वे होते हैं जो दूसरे उद्यम की उत्पादन वृद्धि में सहायक हाथ हैं अर्थात् जब एक उद्यम की उत्पादन वृद्धि के लिये प्रयास किये जाते हैं, तो दूसरे उद्यम का उत्पादन स्वतः ही बढ़ जाता है। जैसे फलीदार फसलें (बरसीम, मटर आदि) एवं खाद्यान्न वाली फसलें। फलीदार फसलों की उत्पादन-वृद्धि के लिये किये गये प्रयासों से उस भूमि पर अगले मौसम में बोयी जाने वाली खाद्यान्न फसल का उत्पादन भूमि में मजजून की अधिक मात्रा में पूर्ति के कारण स्वतः ही बढ़ जाता है। उद्यमों में पाये जाने वाले पूरकता के सम्बन्ध को चित्र 6.12 में प्रदर्शित किया गया है।



चित्र 6.12 उद्यमों में पूरकता का सम्बन्ध

उपर्युक्त चित्र विभिन्न उत्पादों Y_1 एवं Y_2 में पूरकता का सम्बन्ध विद्यमान होने की अवस्था के उत्पादन सम्भावना-वक्र को प्रदर्शित करता है। चित्र में, A से B एवं B से C स्तर तक पूरकता का सम्बन्ध पाया जाता है। उसके उपरान्त उत्पाद की मात्रा में वृद्धि करने पर दोनों उद्यमों में प्रतिस्पर्धा का सम्बन्ध पाया जाता है। अतः उद्यमों के सभी संयोगों में पूरकता का सम्बन्ध विद्यमान नहीं होता। प्रारम्भ में उद्यमों में पूरकता का सम्बन्ध होता है तथा नियत स्तर से आगे उद्यमों के स्तर में वृद्धि करने पर उनमें विद्यमान पूरकता का सम्बन्ध समाप्त होकर वे एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं।

विभिन्न उद्यमों में पूरकता का सम्बन्ध होने की स्थिति में दोनों उद्यमों की फार्म पर उम स्तर तक लेते रहना चाहिये जब तक उनमें पूरकता का सम्बन्ध विद्यमान रहता है। लेकिन पूरक उद्यम में आवश्यकता से अधिक वृद्धि करने पर वह मुख्य उद्यम से उत्पादन-साधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगता है, जिसके

कारण मुख्य उद्यम के क्षेत्रफल अथवा स्तर में कमी करनी होती है। उद्यमों में पूरकता के सम्बन्ध की समाप्ति अथवा प्रतिस्पर्धा की अवस्था उत्पन्न होने पर उनके चुनाव एवं संयोग का निर्णय दोनों उद्यमों के उत्पादन में प्रतिस्थापन की दर एवं उनकी कीमतों के अनुपात के आधार पर लिया जाता है।

(iv) प्रतिस्पर्धात्मक उद्यम (Competition)—प्रतिस्पर्धात्मक उद्यम वे होते हैं जो फार्म पर उपलब्ध विभिन्न उत्पादन-साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूँजी, कृषि-यन्त्र आदि के लिये एक-दूसरे से स्पर्धा रखते हैं। प्रतिस्पर्धा की अवस्था में एक उद्यम के अन्तर्गत क्षेत्रफल अथवा उत्पादन-साधन की मात्रा में वृद्धि करने पर दूसरे उद्यम के अन्तर्गत क्षेत्रफल अथवा उत्पादन-साधन का उपयोग कम करना होता है। प्रतिस्पर्धा वाले उद्यमों के उदाहरण में गेहूँ एवं जौ, कपास एवं मूँगफली, चावल एवं जूट, बाजरा एवं मक्का प्रमुख हैं।

उपरोक्त वर्णन के आधार पर प्रतिस्थापन की सीमान्त दर के अनुसार उत्पादों के सम्बन्ध का संक्षिप्त विवरण निम्न है—

उत्पादों की सीमान्त प्रतिस्थापन दर	उद्यमों का सम्बन्ध
(i) $\Delta Y / \Delta Y_2$ or $\Delta Y_2 / \Delta Y_1 < \text{Zero}$	प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध
(ii) $\Delta Y_1 / \Delta Y_2$ or $\Delta Y_1 / \Delta Y_1 = \text{Zero}$	सम्पूरक सम्बन्ध
(iii) $\Delta Y_1 / \Delta Y_2$ or $\Delta Y_2 / \Delta Y_1 > \text{Zero}$	पूरक सम्बन्ध

प्रतिस्पर्धात्मक उद्यमों में वस्तुओं का अनुकूलतम लाभ प्रदान करने वाला संयोग ज्ञात करने के लिये कृषकों को निम्न ज्ञान होना आवश्यक होता है—

- (i) प्रतिस्पर्धा वाले उद्यमों की प्रतिस्थापन दर।
- (ii) प्रतिस्पर्धा वाले उद्यमों की कीमतों का ज्ञान।
- (iii) प्रतिस्पर्धा वाले उद्यमों की प्रति इकाई उत्पादन-लागत।

प्रतिस्पर्धा वाले उद्यमों की प्रति इकाई उत्पादन लागत की राशि समान होने की अवस्था में उद्यमों के संयोग/प्रतिस्थापन के निर्णय उद्यमों की प्रतिस्थापन दर एवं उनकी विलोम कीमतों के अनुपात के आधार पर ही लिये जाते हैं। उद्यमों की उत्पादन-लागत में भिन्नता की अवस्था में उत्पादों की कीमतों का अनुपात, शुद्ध कीमतों (बाजार कीमत-उत्पादन लागत) के अनुपात के रूप में ज्ञात किया जाता है और प्रत्यक्ष शुद्ध कीमतों के विलोम अनुपात को उत्पादों की प्रतिस्थापन-दर के बराबर करते हैं।

प्रतिस्पर्धा वाले उद्यमों में संयोग के नियम—प्रतिस्पर्धा वाले उद्यमों में उद्यमों के संयोग प्रतिस्थापन के निर्णय निम्न नियमों के आधार पर लिये जाते हैं—

- (i) यदि प्रतिस्पर्धा वाले उद्यमों की विलोम कीमतों का अनुपात $\left(\frac{\text{वृद्धि किये गये उद्यम की प्रति इकाई कीमत}}{\text{प्रतिस्थापित उद्यम की प्रति इकाई कीमत}} \text{ या } \frac{Py_1}{Py_2} \right)$ उनकी

प्रतिस्थापन दर $\left(\frac{\text{प्रतिस्थापित उद्यम में परिवर्तन की मात्रा}}{\text{वृद्धि किये गये उद्यम में परिवर्तन की मात्रा}} \text{ या } -\frac{\Delta Y_2}{\Delta Y_1} \right)$ से अधिक है तो उद्यमों का प्रतिस्थापन करना लाभकर होता है। अब उपर्युक्त अवस्था में उस स्तर तक उद्यमों में प्रतिस्थापन करते रहना चाहिये जब तक कि उपर्युक्त दोनों अनुपात $\left(-\frac{\Delta Y_2}{\Delta Y_1} = \frac{Py_1}{Py_2} \right)$ समतुल्य अवस्था में नहीं आ जाते हैं।

(ii) यदि प्रतिस्पर्धा वाले उद्यमों की विलोम कीमतों का अनुपात उनकी प्रतिस्थापन दर से कम $\left(\frac{Py_1}{Py_2} < -\frac{\Delta Y_2}{\Delta Y_1} \right)$ होता है तो उद्यमों का प्रतिस्थापन नहीं करना चाहिए। प्रतिस्थापन करने से फार्म पर प्राप्त आय में कमी होती है।

(iii) उद्यमों में प्रतिस्थापन की अवस्था में कृषकों को फार्म से अनुकूलतम अर्थात् अधिकतम लाभ दोनों अनुपात के समतुल्य $\left(-\frac{\Delta Y_2}{\Delta Y_1} = \frac{Py_1}{Py_2} \right)$ होने पर प्राप्त होता है।

प्रतिस्पर्धा वाले उद्यमों में प्रतिस्थापन-दर एक निर्णय लेना—प्रतिस्पर्धा वाले उद्यम एक-दूसरे को निम्न दो दरों से प्रतिस्थापित करते हैं—

(i) समान दर से उद्यमों का प्रतिस्थापन—एक उद्यम में की गई एक इकाई की वृद्धि यदि दूसरे उद्यम की मात्रा में उमोत्तर समान दर से बढ़ती करती है तो उन उद्यमों को समान दर से प्रतिस्थापित करने वाले उद्यम कहते हैं। जैसे-गेहूँ एवं जौ, मक्का एवं कपास आदि उद्यम एक-दूसरे के लिये भूमि को समान दर से प्रतिस्थापित करते हैं। समान दर से प्रतिस्थापन की अवस्था में उद्यमों में निम्न प्रकार का सम्बन्ध पाया जाता है—

$$\frac{-\Delta_1 Y_2}{\Delta_1 Y_1} = \frac{-\Delta_2 Y_2}{\Delta_2 Y_1} = \dots = \frac{-\Delta_n Y_2}{\Delta_n Y_1}$$

निम्न उदाहरण (काल्पनिक आंकड़े) एक 5 एकड़ के फार्म पर गेहूँ एवं जौ उद्यम में समान दर से प्रतिस्थापन की अवस्था में निर्णय लेने की विधि को स्पष्ट करता है।

सारणी 6.10

समान दर से उद्यमों के प्रतिस्थापन की अवस्था में उद्यमों
का अनुकूलतम लाभ वाला संयोग ज्ञात करना

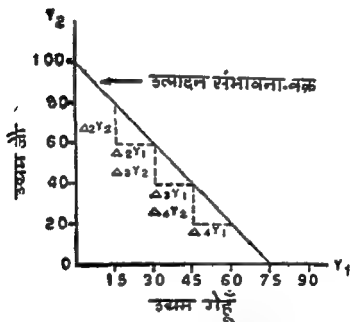
उत्पाद गेहूँ		उत्पाद जौ		उत्पादों की प्रतिस्थापन दर	उत्पादों की विलोम कीमतों का अनुपात	
क्षेत्रफल (एकड़)	उत्पादन (किग)	क्षेत्रफल (एकड़)	उत्पादन (किग)		गेहूँ=280 रु/क्विन्टल	गेहूँ=200 रु/क्विन्टल जौ=160 रु/क्विन्टल
0	0	5	100			
				1 33	1 75	1 25
1	15	4	80	1.33	1 75	1 25
2	30	3	60	1 33	1 75	1 25
3	45	2	40	1 33	1 75	1 25
4	60	1	20	1 33	1 75	1 25
5	75	0	0			

उपयुक्त उदाहरण में उत्पादों की प्रतिस्थापन-दर समान है। कीमतों के प्रथम स्तर (गेहूँ 280 रु प्रति क्विन्टल एवं जौ 160 रु प्रति क्विन्टल) की अवस्था में गेहूँ का उत्पादन लाभप्रद होता है। अतः जौ के अन्तर्गत क्षेत्रफल नहीं लेना चाहिए। कीमतों के द्वितीय स्तर की अवस्था (गेहूँ की कीमत 200 रु प्रति क्विन्टल एवं जौ की कीमत 160 रु प्रति क्विन्टल) में फार्म पर जौ का उत्पादन लाभप्रद होता है, क्योंकि उत्पादों की विलोम कीमतों का अनुपात उनके प्रतिस्थापन दर से कम है। अतः फार्म पर गेहूँ के अन्तर्गत क्षेत्रफल नहीं लेना चाहिए।

समान दर से उद्यमों के प्रतिस्थापन की अवस्था में साधारणतया सर्वाधिक लाभ फार्म पर एक उद्यम को लेने से प्राप्त होता है। वस्तुओं के विभिन्न संयोगों की अवस्था में प्राप्त लाभ की राशि समान रहती है। चित्र 6.13 उद्यमों के समान दर से प्रतिस्थापन को प्रदर्शित करता है।

(ii) **वर्द्धमान-दर से उद्यमों का प्रतिस्थापन**—एक उद्यम की मात्रा में की गई एक इकाई वृद्धि, यदि दूसरे उद्यम के अन्तर्गत उभोत्तर अधिक (बढ़ती हुई) मात्रा में कमी करती है तो दोनों उद्यमों के सम्बन्ध को वर्द्धमान दर से उद्यमों का प्रतिस्थापन कहते हैं। इसके अन्तर्गत एक उद्यम की मात्रा में प्रत्येक एक इकाई की वृद्धि दूसरे उद्यम की मात्रा में उभोत्तर पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में कमी करती है। वर्द्धमान-दर से उद्यमों के प्रतिस्थापन की अवस्था में पाया जाने वाला सम्बन्ध निम्न प्रकार का होता है—

$$\frac{-\Delta_1 Y_2}{\Delta_1 Y_1} < \frac{-\Delta_2 Y_2}{\Delta_2 Y_1} < \dots < \frac{-\Delta_n Y_2}{\Delta_n Y_1}$$



चित्र 6.13 समान दर से उद्यमों का प्रतिस्थापन

निम्न उदाहरण (काल्पनिक आँकड़े) वर्द्धमान-दर से उद्यमों के प्रतिस्थापन की प्रवस्था में अनुकूलतम लाभ स्तर प्राप्त करने की विधि को स्पष्ट करता है।

कीमतों के प्रथम विकल्प की अवस्था में प्रतिस्पर्धा वाले उद्यमों की विलोम कीमतों का अनुपात उद्यमों के प्रतिस्थापन के अनुपात से उत्पादों के संयोग क्रमांक 8 (49 इकाई उत्पाद अ तथा 70 इकाई उत्पाद ब) तक अधिक है। अतः उत्पादों के संयोग के नियम के अनुसार इस स्तर तक उद्यमों का प्रतिस्थापन करना लाभकर है। उत्पादों के इस संयोग स्तर के आगे, उद्यमों की विलोम कीमतों का अनुपात,

उद्यम की प्रतिस्थापन दर से कम है, जिसके कारण प्रतिस्थापन करने से लाभ की राशि कम होनी जाती है। अतः प्रतिस्थापन नहीं करना चाहिए।

कीमती के द्वितीय विकल्प की अवस्था में, उद्यमों की विलोम कीमतों का अनुपात उद्यमों की प्रतिस्थापन दर उत्पादों के संयोग क्रमांक 2 (133 इकाई उत्पाद अ तथा 10 इकाई उत्पाद ब) तक अधिक है। उत्पादों के संयोग के नियम के अनुसार उद्युक्त संयोग कृषकों को फार्म से अधिकतम लाभ प्राप्त करता है। इस संयोग के आगे उनकी विलोम कीमतों का अनुपात, प्रतिस्थापन दर से कम होता जाता है जिससे प्रतिस्थापन करने से लाभ की राशि में कमी होती है। अतः प्रतिस्थापन नहीं करना चाहिये।

सारणी 6 11

वर्तमान दर से उद्यमों के प्रतिस्थापन की अवस्था में अनुकूलतम
लाभ वाले उत्पादों का संयोग ज्ञात करना

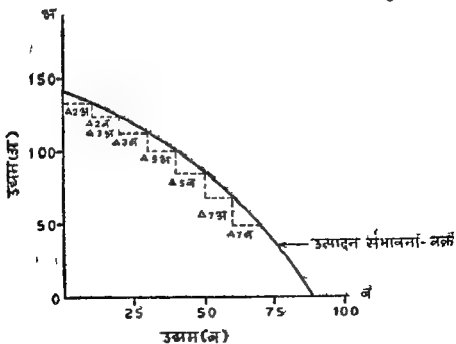
उत्पादों के संयोग का क्रमांक	उत्पादन साधनों की समान इकाइयों से विभिन्न उत्पादों के उत्पादन की सम्भावनाएँ		उत्पादों की प्रतिस्थापन दर	उत्पादों की विलोम कीमतों का अनुपात	
	उत्पाद अ	उत्पाद ब		प्रथम विकल्प अ=1 00 रु / इकाई तथा ब=2 00 रु / इकाई	द्वितीय विकल्प अ=1 00 रु / इकाई तथा ब=0 80 रु / इकाई
1	140	0	0 70	2 00	0 80
2	133	10	0 90	2 00	0 80
3	124	20	1 10	2 00	0 80
4	113	30	1 30	2 00	0 80
5	100	40	1 50	2 00	0 80
6	85	50	1 70	2 00	0 80

7	68	60	1.90	2 00	0 80
8	49	70	2.10	2 00	0 80
9	28	80			

वर्द्धमान-दर से उत्पादों के प्रतिस्थापन की अवस्था में दोनों उद्यमों के संयोग का वह स्तर जहाँ प्रतिस्थापन-दर उनकी विलोम कीमतों के समतुल्य होती है, अधिकतम लाभ की राशि प्रदान करता है। वर्द्धमान दर से उद्यमों के प्रतिस्थापन को चित्र 6.14 में प्रदर्शित किया गया है।

कृषिगत उत्पादों के उत्पादन में विशिष्टीकरण एवं विविधता

कृषकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों अथवा विभिन्न कृषकों द्वारा एक ही कृषि-क्षेत्र में उत्पादों के संयोग का चुनाव किया जाता है। कुछ कृषक फार्म पर एक ही फसल का चुनाव करके कृषि उत्पादन में विशिष्टीकरण करते हैं, जबकि अन्य कृषक कृषि की विविधता वाली पद्धति अपनाते हैं। कृषि के विशिष्टीकरण से तात्पर्य फार्म पर एक ही उद्यम को चुनने से है, जबकि विविधता के अन्तर्गत फार्म पर अनेक उद्यमों का चुनाव किया जाता है तथा चुना हुआ कोई भी उद्यम फार्म पर प्राप्त कुल आय का



चित्र 6.14 वर्द्धमान-दर से उद्यमों का प्रतिस्थापन

50 प्रतिशत अंश प्रदान नहीं करता है। कृषको द्वारा इस प्रकार की उत्पादन विधि का चुनाव करने के प्रमुख कारण निम्न हैं —

- (i) विभिन्न उत्पादों में सम्बन्ध—उत्पादों में पूरकता एवं सम्पूरकता के सम्बन्ध होने की अवस्था में उत्पादन में विविधता वाली पद्धति प्रचलित होती है। उत्पादों में प्रतिस्पर्धा का सम्बन्ध होने पर उनका विशिष्टीकरण अथवा विविधता, उत्पादों की प्रतिस्थापन की दर पर निर्भर करती है। उत्पादों में वर्तमान दर से प्रतिस्थापन की अवस्था में विविधता वाली कृषि-पद्धति एवं उत्पादों में समान दर से प्रतिस्थापन की अवस्था में विशिष्टीकरण वाली कृषि पद्धति अपनाई जाती है।
- (ii) भारत के अधिकतर क्षेत्रों में दो फसल मौसम होते हैं जबकि अनेक क्षेत्रों में एक फसल मौसम होता है। प्रत्येक मौसम में अनेक फसलें उत्पन्न की जा सकती हैं, जिसके कारण भारत में विविधता वाली कृषि अधिक प्रचलित है।
- (iii) कृषि में जोखिम एवं अनिश्चितता—भारतीय कृषि में जोखिम एवं अनिश्चितता के कारण विविधता वाला कृषि प्रणाली अधिक अपनाई जाती है।
- (iv) व्यापारिक योग्यता—वर्तमान में कृषि व्यवसाय में प्रत्येक उद्यम के लिए व्यापारिक योग्यता की आवश्यकता होती है। कृषक प्रत्येक फसल के लिए व्यापारिक योग्यता प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में कृषक विशिष्टीकरण की तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं।
- (v) कृषि में पूँजी की अधिक आवश्यकता के कारण कृषक एक ही फसल का उत्पादन अर्थात् विशिष्टीकरण वाली पद्धति अपनाने का अधिक प्रयास करते हैं।

6 तुलनात्मक समय का सिद्धान्त

तुलनात्मक समय सम्बन्धी निर्णय फार्म पर निम्न दो अवस्थाओं में कृषको को लेने होते हैं

- (i) जब फार्म पर लिये गये विभिन्न उद्यमों से लाभ एक समय में प्राप्त न होकर विभिन्न समयों में प्राप्त होता है।
- (ii) जब फार्म पर लिये गये विभिन्न उद्यमों में पूँजी निवेश एक समय में न होकर विभिन्न राशियों में विभिन्न समयों में होता है।

उपयुक्त परिस्थितियों में कृषको को निर्णय लेना होता है कि कौन सा उद्यम या उत्पादन विधि फार्म के लिये अधिक लाभकर है। विभिन्न समय पर लाभ प्राप्त

होने अथवा लागत होने की स्थिति में तुलनात्मक समय के सिद्धान्त के द्वारा उद्यमों/विधियों का चुनाव आर्थिक दृष्टिकोण से सरलता से किया जा सकता है। तुलनात्मक समय का सिद्धान्त कृषकों को निम्न प्रकार की समस्याओं की अवस्था में निर्णय लेने में सहायक होता है :

- (i) उपलब्ध सीमित पूँजी से कृषक चार दुयारू गायें या 1॥ बछड़ियाँ ख़र कर सकते हैं। उपयुक्त विकल्पों में प्रथम विकल्प से आय शीघ्र प्राप्त होती है, जबकि दूसरे विकल्प से आय कुछ वर्षों के बाद प्राप्त होना प्रारम्भ होती है।
- (ii) एक कृषक 10,000 रु की लागत से पशुओं के लिये 60 वर्ष की अवधि वाली पक्की पशुशाला या 6,000 रु की लागत से 30 वर्ष की अवधि वाली कच्ची पशुशाला का निर्माण करवा सकता है। प्रथम विकल्प में सम्पूर्ण लागत प्रारम्भ में लगानी होती है, जबकि दूसरे विकल्प में कुछ समय प्रारम्भ में लगानी होती है और 30 वर्ष पश्चात् पुन उतनी ही लागत लगानी होती है।
- (iii) कृषक 1,50,000 रु में 12 वर्ष तक कार्य देने वाला नया ट्रैक्टर अथवा 75,000 रु में 6 वर्ष तक कार्य देने वाला पुराना ट्रैक्टर ख़र कर सकता है और 6 वर्ष पश्चात् पुन उतनी ही लागत लगानी होती है।

इसी प्रकार के समय सम्बन्धी अन्य निर्णय, जिनमें विभिन्न विकल्पों से लाभ विभिन्न समयों में प्राप्त होता है अथवा इन विकल्पों पर लागत व्यय विभिन्न समयों में होता है, तुलनात्मक समय के सिद्धान्त द्वारा सुगमता से लिये जा सकते हैं।

उपयुक्त विकल्पों की स्थिति में भविष्य में प्राप्त होने वाले लाभ का वर्तमान मूल्य बट्टाविधि (Discounting) द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, तथा वर्तमान लागत का भविष्य मूल्य ज्ञात करने में चक्र-वृद्धि (Compounding) काम में ली जाती है। उपर्युक्त दोनों विधियों में वर्तमान या भविष्य मूल्य ज्ञात करने में ब्याज दर का प्रयोग किया जाता है। ब्याज दर विभिन्न पूँजी की राशि वाले कृषकों के लिये पृथक् होती है। असीमित मात्रा में पूँजी वाले कृषकों के लिये वर्तमान या भविष्य मूल्य ज्ञात करने के लिये ब्याज दर के स्थान पर प्रचलित बैंक ब्याज दर तथा सीमित पूँजी वाले कृषकों के लिये ब्याज की दर अन्य उद्यमों से प्राप्त होने वाली आय की दर अथवा अवसर-लागत दर प्रयुक्त की जाती है। अतः सीमित पूँजी वाले कृषकों के लिये ब्याज की दर, असीमित पूँजी वाले कृषकों की अपेक्षा अधिक होती है।

भविष्य में प्राप्त होने वाले लाभ का वर्तमान-मूल्य बट्टा-विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है जिसका सूत्र अग्रानुसार होता है।

$$\text{वर्तमान मूल्य} = \frac{\text{भविष्य में प्राप्त होने वाले लाभ की राशि}}{(1 + \text{प्रति रुपया व्याज दर})^n} \text{ वर्षों की संख्या}$$

$$\text{अथवा } PV = \frac{Q}{(1+r)^n} \quad \text{जबकि } PV = \text{वर्तमान-मूल्य}$$

$Q =$ भविष्य में प्राप्त होने वाले लाभ की राशि

$r =$ व्याज-दर प्रति रुपया

$n =$ वर्षों की संख्या

वर्तमान लागत की राशि का भविष्य-मूल्य ज्ञात करने के लिये चक्रवृद्धि विधि प्रयुक्त की जाती है। व्याज के कारण भविष्य की लागत-राशि बढ़ती जाती है जिसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है —

$$\text{भविष्य मूल्य} = \text{वर्तमान लागत राशि} (1 + \text{प्रति रुपया व्याज दर})^n \text{ वर्षों की संख्या}$$

$$\text{अथवा } Q = PV (1+r)^n$$

तुलनात्मक समय के सिद्धान्त का उदाहरण—निम्न उदाहरण तुलनात्मक समय के सिद्धान्त को स्पष्ट करता है —

एक कृषक पशुशाला का निर्माण करना चाहता है। पक्की पशुशाला जो 60 वर्ष तक उपयोग में आ सकती है, का निर्माण करने पर कुल लागत 5,000 रु आती है। कच्ची पशुशाला का निर्माण करने पर वर्तमान में 4,000 रु की लागत आती है, लेकिन वह 30 वर्ष तक ही उपयोग में ली जा सकती है। तीस वर्ष पश्चात् पुनः पशुशाला का निर्माण करना होता है जिस पर 4,000 रु फिर से लागत आती है। ज्ञात कीजिये कि उपर्युक्त विकल्पों में से सीमित एवं प्रसीमित पूँजी वाले कृषक के लिये कौनसा विकल्प का चुनाव (पक्की अथवा कच्ची पशुशाला) लाभकर है ?

प्रथम विकल्प—पक्की पशुशाला के निर्माण में कृषक को वर्तमान में 5,000 रु की लागत लगानी होती है जो 60 वर्ष तक उपयोग में ली जा सकती है।

द्वितीय विकल्प—कच्ची पशुशाला के निर्माण पर कृषक को वर्तमान में 4,000 रु की लागत लगानी होती है और 30 वर्ष पश्चात् पुनः नई पशुशाला के निर्माण पर 4,000 रु की लागत लगानी होती है, अतः कच्ची पशुशाला के निर्माण पर 60 वर्ष की अवधि में कुल लागत 8,000 रु की होती है, लेकिन यह लागत विभिन्न समयों में होती है। ऐसी स्थिति में लाभकर विकल्प का चुनाव करने के लिये कृषक द्वारा 30 वर्ष पश्चात् लगाई जाने वाली लागत की राशि 4,000 रु का वर्तमान लागत मूल्य ज्ञात करना होता है। सीमित एवं प्रसीमित पूँजी वाले कृषको

के लिये 30 वर्ष पश्चात् व्यय किये जाने वाले 4,000 रु. का वर्तमान मूल्य निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है :

सीमित पूँजी वाला कृषक—सीमित पूँजी वाला कृषक अपने धन को बैंक में जमा नहीं कराता है, बल्कि उस धन को विभिन्न उद्यमों में निवेश करता है जहाँ उसे बैंक ब्याज दर से अधिक आय प्राप्त होती है। अतः सीमित पूँजी वाले कृषकों के लिये ब्याज-दर उद्यमों से प्राप्त होने वाली आय की दर होती है। यदि सीमित पूँजी वाले कृषक को उद्यमों में पूँजी निवेश करने पर 15 प्रतिशत आय प्राप्त होती है तो मावी मूल्य-लागत से वर्तमान मूल्य-लागत ज्ञात करने में 15 प्रतिशत ब्याज-दर का प्रयोग किया जाता है।

तीस वर्ष उपरान्त कच्ची पशुशाला के निर्माण पर होने वाले 4,000 रु. की लागत का वर्तमान मूल्य $\frac{4000}{(1+15)^{30}} = 60.42$ रु. होता है। सीमित पूँजी वाला कृषक कच्ची पशुशाला के निर्माण पर 60 वर्ष की अवधि में कुल 4060.42 रु. (4000 + 60.42) रु. की लागत लगाता है। यह लागत पक्की पशुशाला के निर्माण की लागत 5,000 रु. से कम है। अतः सीमित पूँजी वाले कृषक के लिये जिसे उद्यमों में पूँजी-निवेश करने से 15 प्रतिशत की आय प्राप्त होती है, कच्ची पशुशाला का निर्माण करना लाभकर होता है।

असीमित पूँजी वाला कृषक—असीमित पूँजी वाला कृषक अपनी पूँजी बैंक में जमा कराता है जहाँ उसे 4 प्रतिशत ब्याज प्राप्त होता है। अतः असीमित पूँजी वाले कृषक के लिए 30 वर्ष उपरान्त पशुशाला के निर्माण पर किये जाने वाले 4,000 रु. की लागत का वर्तमान मूल्य 4 प्रतिशत ब्याज-दर पर

$$\left(\frac{4000}{(1+0.40)^{30}} \right) = 1235 \text{ रु.}$$

होता है। इस कृषक के लिए कच्ची पशुशाला के निर्माण पर कुल लागत 60 वर्ष की अवधि के लिए 5235 रु. (रु. 4000 + 1235) आती है, जो पक्की पशुशाला की वर्तमान लागत 5000 रु. से अधिक है। अतः असीमित पूँजी वाले कृषक के लिये पक्की पशुशाला का निर्माण करना लाभकर है।

उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि सीमित एवं असीमित पूँजी वाले कृषकों के लिये एक ही निर्णायक उपयुक्त नहीं होता है। इसी प्रकार समय सम्बन्धी अन्य समस्याएँ भी तुलनात्मक समय के सिद्धान्त द्वारा हल की जा सकती हैं।

7 तुलनात्मक लाभ का सिद्धान्त :

यह सिद्धान्त फार्म स्तर पर प्रयोगित नहीं होकर क्षेत्र स्तर पर प्रयोगित होता है।

विभिन्न क्षेत्रों में भौतिक व आर्थिक तत्त्वों की विभिन्नता के कारण विभिन्न फसलें उत्पन्न की जाती हैं और ये फसलें एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र की अपेक्षा अधिक लाभ प्रदान करती हैं। तुलनात्मक-लाभ का सिद्धान्त विभिन्न क्षेत्र के कृषकों को अधिकतम लाभ की प्राप्ति के लिए फसलों के चुनाव में सहायक होता है। विभिन्न फसलों से प्राप्त लाभ दो प्रकार के होते हैं—

(अ) निरपेक्ष लाभ (Absolute Margin)—निरपेक्ष लाभ से तात्पर्य प्राप्त शुद्ध लाभ की राशि से होता है। यह लाभ उत्पादन-साधनों के उपयोग में होने वाली भाय व लागत की राशि का शुद्ध अन्तर होता है। यदि किसी क्षेत्र में एक फसल के लिए यह लाभ दूसरे क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होता है, तो प्रथम क्षेत्र उस फसल को उत्पन्न करने में निरपेक्ष लाभ प्रदान करता है।

(ब) सापेक्ष/तुलनात्मक लाभ (Relative/Comparative Margin)—सापेक्ष लाभ के अन्तर्गत विभिन्न उद्यमों/फसलों में उत्पादन-साधनों के उपयोग से विभिन्न क्षेत्रों में प्रति रुपया लागत पर लाभ या प्रतिशत लाभ का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और प्रति रुपया लागत के आधार पर प्राप्त लाभ अथवा प्रतिशत लाभ के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।

तुलनात्मक लाभ के सिद्धान्त का उदाहरण—विभिन्न उदाहरण तुलनात्मक लाभ के सिद्धान्त को स्पष्ट करता है—

गेहूँ व मक्का की फसल क्षेत्र 'अ' एवं क्षेत्र 'ब' में भौतिक कारकों के अनुसार उत्पादित की जा सकती है। विभिन्न क्षेत्रों में इन फसलों के उत्पादन से प्राप्त शुद्ध लाभ व प्रति रुपया सकल लाभ सारणी 6 12 में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 6 12

तुलनात्मक लाभ के सिद्धान्त के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में फसलों का चुनाव

(रुपये प्रति एकड़)

विवरण	क्षेत्र 'अ'		क्षेत्र 'ब'	
	गेहूँ	मक्का	गेहूँ	मक्का
प्राप्त कुल भाय	500	450	450	400
कुल लागत	300	300	300	260
शुद्ध लाभ	200	150	150	140
प्रति रुपया सकल लाभ	1.67	1.50	1.50	1.54

सारणी से स्पष्ट है कि क्षेत्र 'अ' में क्षेत्र 'ब' की अपेक्षा गेहूँ एवं मक्का दोनों ही फसलों का उत्पादन करने से प्रति एकड़ शुद्ध लाभ अधिक प्राप्त होता है। क्षेत्र अ के कृषक गेहूँ व मक्का दोनों ही फसलों को उत्पादित करके क्षेत्र ब की अपेक्षा अधिक लाभ कमा सकते हैं। क्षेत्र ब के कृषकों को दोनों ही फसलों से निरपेक्ष लाभ अधिक प्राप्त होता है। कृषकों का उद्देश्य अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक लाभ कमाने के प्रतिरिक्त, अपने क्षेत्र में उत्पादित की जाने वाली विभिन्न फसलों से भी अधिकतम लाभ कमाना होता है। अधिकतम लाभ प्राप्त करना सभी सम्भव है जब कृषक फार्म पर अधिक से अधिक क्षेत्रफल उस फसल के अन्तर्गत लेते हैं, जो उस क्षेत्र में उत्पादित की जाने वाली फसलों में पूँजी के निवेश से प्रति रुपया अधिकतम लाभ प्राप्त कराती है। सारणी से स्पष्ट है कि क्षेत्र अ के कृषकों को गेहूँ की फसल से सापेक्ष लाभ एवं क्षेत्र ब के कृषकों को मक्का की फसल से सापेक्ष लाभ अधिक प्राप्त होता है। अतः क्षेत्र अ के कृषकों को गेहूँ व क्षेत्र ब के कृषकों को मक्का की फसल उत्पन्न करने से लाभ की अधिकतम राशि प्राप्त होती है।

तुलनात्मक लाभ का सिद्धान्त कृषकों को अधिकतम लाभ की प्राप्ति के लिए उन्हीं फसलों के उत्पादन की सलाह देता है, जिनसे अपेक्षाकृत लाभ अधिक प्राप्त होता है। विभिन्न फसलों में उत्पादन सम्बन्धी निर्णय लेने में निरपेक्ष लाभ को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। तुलनात्मक लाभ के सिद्धान्त के आधार पर ही बड़े शहरी के समीप के क्षेत्रों में सब्जी व फल की खेती, चीनी मिलों के समीप के क्षेत्रों में गन्ने की खेती, निचली व नम भूमि में धान की खेती विशिष्ट रूप से की जाती है। फार्म पर विशिष्ट या विविधीकृत कृषि अपनाने से सम्बन्धित निर्णय भी तुलनात्मक लाभ के सिद्धान्त के आधार पर लिए जाते हैं।

फार्म-प्रबन्ध के उपर्युक्त सिद्धान्त कृषकों को फार्म पर कृषि-क्रियाओं एवं उत्पादन-साधनों में सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के मुलभूत में सहायक होते हैं। उपर्युक्त सिद्धान्तों के आधार पर निर्णय लेने से कृषकों को प्राप्त होने वाले लाभ की राशि में वृद्धि होती है, निर्णय लेने में समय कम लगता है एवं लिए गए निर्णय सही होते हैं।

फार्म-योजना एवं बजट

प्रत्येक व्यवसायी कार्य शुरू करने के पूर्व कार्य करने की क्रिया, लागत एवं लाभ के विषय में विचार करता है। कुछ व्यवसायी इन कार्यों को लिखित रूप में देते हैं। उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार एक ठेकेदार भवन निर्माण में पूर्व, भवन के मालिक द्वारा चाही गई सभी आवश्यकताओं को अंकित करके भवन का नक्शा तैयार करता है, जिससे भवन मुख्यस्थित ढंग से सुन्दर, सस्ता एवं समय पर तैयार हो सके तथा भवन निर्माण के समय होने वाली त्रुटियों से बचाव हो सके। नक्शे के द्वारा ठेकेदार भवन-निर्माण के लिए आवश्यक सामान की सूची तैयार कर लेता है, जिसके आधार पर भवन की सम्भावित लागत ज्ञात हो जाती है। इसी प्रकार फार्म योजना एवं फार्म-बजट, फार्म पर होने वाली प्रस्तावित लागत एवं प्राप्त होने वाली आय का ज्ञान कृषक को प्रदान करते हैं और कृषक कृषि में होने वाली त्रुटियों से बच जाता है।

फार्म योजना—फार्म योजना, कृषक द्वारा फार्म पर किये जाने वाले कृषि-कार्यों की सूची होती है, जिसमें फार्म पर आगामी वर्ष या मौसम में उत्पन्न की जाने वाली फसलों, उनके अन्तर्गत क्षेत्रफल, उपयोग किये जाने वाले उत्पादन-साधनों जैसे बीज, खाद, उर्वरक, सिंचाई आदि की पूर्ण जानकारी होनी है। फार्म के लिए उपयुक्त कार्यक्रम बनाने की क्रिया को फार्म योजना कहते हैं। दूसरे शब्दों में फार्म-योजना बनाने से तात्पर्य वर्तमान फार्म-व्यवस्था में त्रुटियों एवं उन्हें सुधारने के तरीकों का पता लगाने से है, जिससे फार्म की भावी योजना अधिकतम लाभ प्रदान करने वाली हो सके।

फार्म योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य कृषक को फार्म से प्राप्त होने वाली आय को अधिकाधिक बढ़ाना होता है। कृषक फार्म की योजना एक मौसम, वर्ष या अधिक समय के लिए तैयार कर सकते हैं। साधारणतया फार्म-योजना एक से अधिक वर्षों के लिए तैयार नहीं की जाती, क्योंकि उत्पादन की विधियों, उत्पादन-साधनों तथा कृषिगत वस्तुओं की कीमतों में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण निमित्त योजना में उपयुक्त परिवर्तनों के साथ-साथ परिवर्तन करना होता है।

फार्म बजट—फार्म-बजट, फार्म-योजना के विश्लेषण की विधि है, जिसके अन्तर्गत फार्म-योजना की सभी क्रियाओं को मुद्रा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। फार्म-बजट, फार्म-योजना से प्राप्त होने वाली कुल आय, लागत एवं लाभ ज्ञात करने की विधि है। फार्म बजट से कृषकों को पता हो जाता है कि फार्म पर कौनसी फसल या उद्यम को अपनाने से, उत्पादन की कौनसी विधि अपनाने से एवं उत्पादन साधन की कितनी मात्रा के प्रयोग से लाभ अधिक प्राप्त होता है। फार्म-बजट, फार्म-योजना के अनुसार भविष्य में मुद्रा व्यय करने एवं प्राप्त होने वाली आय की योजना को सूचित करता है।

फार्म-योजना एवं फार्म बजट की आवश्यकता

कृषकों के लिए फार्म योजना एवं फार्म-बजट बनाना उतना ही आवश्यक है जितना एक मकान-निर्माण के ठेकेदार के लिए मकान के ब्लूप्रिन्ट का बनवाना आवश्यक होता है। फार्म-योजना कृषक को क्रमबद्ध विधि से फार्म पर कार्य करने की सलाह देती है, जिससे कार्य करने में त्रुटि नहीं होती है एवं कार्य की लागत भी कम आती है।

पूर्व में कृषक कृषि की व्यवसाय के रूप में न लेकर, जीविकोपार्जन के साधन के रूप में लेते थे। अतः उस काल में कृषक कृषि-व्यवसाय की सफलता के लिए अधिक चिन्तित नहीं थे। वर्तमान में कृषि ने व्यवसाय का रूप ले लिया है। कृषि की सफलता के लिए व्यवसाय पर होने वाली लागत, आय व शुद्ध लाभ का ज्ञान होना आवश्यक है। यह ज्ञान कृषकों को सभी प्राप्त हो सकता है जब वे फार्म-व्यवसाय की नियमित योजना बनाएँ और प्रत्येक कार्य का पूरा लेखा जोखा रखें। अतः कृषि-व्यवसाय की सफलता के लिए फार्म-योजना बनाना आवश्यक है।

मौसम व कीमतों की अनिश्चितता की स्थिति में भी फार्म योजना का बनाना आवश्यक होता है। एक बार की तैयारी की हुई फार्म योजना, मौसम एवं कीमतों की अनिश्चितता की अवस्था में आगामी वर्षों में लागू नहीं हो सकती। अमुक सफल जो वर्तमान कीमतों के स्तर पर लाभप्रद है, वह उत्पाद या उत्पादन साधन की कीमतों में परिवर्तन के कारण भविष्य में कम लाभप्रद या नुकसानदेह भी हो सकती है। अतः प्रत्येक मौसम व वर्ष में फार्म-योजना बनाना व उसका पुनरावलोकन करना आवश्यक होता है।

फार्म योजना बनाना वर्तमान में कृषि के क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान के प्रसार एवं कृषकों द्वारा तकनीकी ज्ञान के अधिक प्रयोग के कारण भी आवश्यक हो गया है। तकनीकी ज्ञान के प्रयोग से फार्म-व्यवसाय की आय एवं लागत पर प्रभाव पड़ता है। अतः तकनीकी ज्ञान के प्रसार की अवस्था में फार्म से अधिकतम लाभ की प्राप्ति के लिए कृषकों द्वारा फार्म-योजना एवं बजट बनाना आवश्यक होता है।

उपयुक्त स्थितियों के अनिर्दिष्ट, कृषकों के पास व्यवसाय में निवेश करने के लिए अधिक पूँजी होने, कृषक द्वारा अधिक भूमि पट्टेदारी पर लेने अथवा

पुरानी फार्म-योजना में परिवर्तन करने की इच्छा होने पर भी फार्म-योजना का बनाना आवश्यक है।

फार्म योजना एवं फार्म बजट के प्रकार :

फार्म योजना एवं बजट दो प्रकार के होते हैं :

1. **सम्पूर्ण फार्म-योजना एवं बजट**—सम्पूर्ण फार्म-योजना एवं बजट के अन्तर्गत पूरे फार्म के लिए आगामी वर्ष या वर्षों के लिए नई योजना तैयार की जाती है। सम्पूर्ण फार्म-योजना, फार्म से प्राप्त होने वाली कुल आय, लागत एवं शुद्ध लाभ की राशि का ज्ञान प्रदान करती है। सम्पूर्ण फार्म-योजना एवं बजट बनाने समय, उन सभी क्रियाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है जिनको अपनाने से फार्म पर होने वाली लागत अथवा प्राप्त होने वाली आय में अन्तर आता है। निम्न परिस्थितियों में सम्पूर्ण फार्म योजना एवं बजट बनाना आवश्यक होता है :

- (i) जब कृषक कृषि के लिए अतिरिक्त भूमि ख़य करता है या बटाई पर लेता है।
- (ii) जब कृषक फार्म पर शक्ति के साधन में परिवर्तन करता है, जैसे बैटो के स्थान पर ट्रैक्टर का उपयोग।
- (iii) जब कृषक फार्म पर सिंचाई के पानी की मात्रा में वृद्धि करता है, जैसे फार्म पर नए कुओं का निर्माण पुराने कुओं को गहरा करना, नलकूप लगाना आदि।
- (iv) जब कृषक फार्म पर लिए जाने वाले उद्यमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन करना चाहता है, जैसे खाद्यान्न के स्थान पर सब्जी, फल, पशुपालन आदि का चुनाव।

2. **आंशिक फार्म-योजना एवं बजट**—आंशिक फार्म-योजना एवं बजट के अन्तर्गत पूरे फार्म की फार्म-योजना न बनाकर, फार्म पर किसी एक उद्यम अथवा उसकी उत्पादन विधि अथवा उत्पादन साधनों की मात्रा का प्रयोग करने से जो परिवर्तन आता है, उसकी योजना बनाई जाती है। आंशिक फार्म-योजना एवं बजट से ज्ञात होता है कि कौनसी फसल, उत्पादन-विधि या उत्पादन साधन की कितनी मात्रा का उपयोग कृषकी के लिए लाभकर होता है। आंशिक फार्म-योजना एवं बजट निम्न परिस्थितियों में बनाना आवश्यक होता है :

- (i) दूध उत्पादन के लिए फार्म पर गाय के स्थान पर भैंस पालना।
- (ii) सिंचाई के लिए डीजल पम्प के स्थान पर बिजुत् पम्प का उपयोग अथवा रूट्टे के स्थान पर पम्पिंग सेट का उपयोग करना।
- (iii) निराई के लिए अमिको के स्थान पर खरपतवारनाशी दवाइयों का उपयोग।

- (iv) फसल की कटाई के लिए श्रमिकों के स्थान पर रीपर का उपयोग ।
- (v) फसलों के गायटा के लिए बैलों के स्थान पर ट्रैक्टर का उपयोग ।
- (vi) नम्रजन उर्वरक की पूर्ति के लिए मूरिया के स्थान पर कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट या अन्य नम्रजन उर्वरक का उपयोग ।
- (vii) दशो किस्म के बीजा के स्थान पर सुकर या बीन किस्म के बीजों का उपयोग ।
- (viii) देर से पकने वाली किस्म के स्थान पर जल्दी पकने वाली किस्म का चुनाव ।

निम्न उदाहरण आशिक बजट बनाने की विधि प्रदर्शित करते हैं :

उदाहरण 1 वर्तमान में कृषक फसलों में होने वाली खरपतवार को निपट-गुड़ाई द्वारा दूर कर रहे हैं जिससे मानव-श्रम की अधिक आवश्यकता होती है । खरपतवार को नष्ट करने के लिए खरपतवारनाशी दवाइयों का भी उपयोग किया जा सकता है । दोनों विधियों की आर्थिक दृष्टि से तुलना आशिक बजट द्वारा की जा सकती है ।

सारणी 7.1 में किए गए विश्लेषण में स्पष्ट है कि फार्म पर निपट-गुड़ाई के लिए श्रमिकों के स्थान पर खरपतवारनाशी दवाई का उपयोग किया जाए तो कृषकों को एक एकड़ क्षेत्र से 48 रु की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी है ।

उदाहरण 2. वर्तमान में कृषक खेत की जुताई बैलों द्वारा वेशी हल की सहायता से करते हैं । कृषक खेत की जुताई ट्रैक्टर की सहायता से भी कर सकते हैं । ट्रैक्टर द्वारा खेत की जुताई समय पर तथा उचित गहराई तक की जाने के कारण गेहूँ का उत्पादन बेना द्वारा जुताई किए जाने की अपेक्षा 0.25 क्विन्टल प्रति हैक्टर अधिक होता है । भूमि की जुताई की दोनों विधियों की आर्थिक दृष्टि से तुलना आशिक बजट बना करके की जा सकती है ।

सारणी 7.2 में दिए गए आशिक बजट से स्पष्ट है कि बैलों द्वारा जुताई करने के स्थान पर ट्रैक्टर द्वारा जुताई करने से कृषकों की आय में 52.50 रु प्रति हैक्टर की अतिरिक्त वृद्धि होती है ।

सारणी 71

खरपतवार नष्ट करने के लिए मानव-धन एवं खरपतवारनाशी दवाइयों के उपयोग का आंशिक बजट

व्यय	आय
(अ) खरपतवारनाशी दवाई के उपयोग से प्रति एकड़ लागत में वृद्धि	(घ) खरपतवारनाशी दवाई के उपयोग से प्रति एकड़ लागत में होने वाली कमी
(i) खरपतवारनाशी दवाई की लागत रु 40 00	एक एकड़ क्षेत्र की खरपतवार को मानव-धन के स्थान पर दवाई से नष्ट करने पर धन की बचत = $56-16=40$ घटे @ रु 2 50 प्रति घटे = रु 100 00
(ii) दवा छिड़कने के यन्त्र की घिसावट एवं मर्याद की लागत रु 2 00	
(ब) दवा छिड़कने से उत्पादन/आय में प्रति एकड़ होने वाली कमी-कुछ नहीं	(ब) दवाई के उपयोग से उत्पादन आय में होने वाली प्रति एकड़ वृद्धि-कुछ नहीं
खरपतवारनाशी दवाई के उपयोग से होने वाली अतिरिक्त लागत एवं आय में कमी की कुल राशि रु 52 00	खरपतवारनाशी दवाई के उपयोग से लागत में कमी तथा आय में वृद्धि की कुल राशि रु 100 00
	आय में शुद्ध अन्तर (लाभ) = रु 48 00

फार्म योजना की विशेषताएँ—एक अच्छी फार्म-योजना में निम्न विशेषताएँ होनी चाहिए :

- (i) निमित्त फार्म-योजना में फार्म पर उपलब्ध सभी उत्पादन-साधनों का पूर्ण एवं इष्टतम उपयोग होना चाहिए ।
- (ii) निमित्त फार्म-योजना कृषक को अधिकतम आय की राशि प्रदान करने वाली होनी चाहिए ।
- (iii) निमित्त फार्म-योजना में फार्म पर उत्पादों का अनुकूलतम सयोग होना चाहिए जिससे कृषको को आवश्यकता के सभी साधन, दालें, तिलहन, चारा आदि आवश्यक मात्रा में फार्म से उपलब्ध हो सकें एवं भूमि की उर्वरा-शक्ति में किसी प्रकार का ह्रास नहीं होने पाए ।

- (iv) निर्मित फार्म-योजना में कृषि की उन्नत एवं आधुनिकतम विधियों का अधिकतम समावेश होना चाहिए।
- (v) निर्मित फार्म-योजना में, कृषि की परिवर्तनशील परिस्थितियों के कारण हेरफेर करने की सुविधा होनी चाहिए।
- (vi) निर्मित फार्म-योजना कृषक के लिए कम जोखिम वाली होनी चाहिए।
- (vii) निर्मित फार्म-योजना में उत्पादन-प्रणाली के अतिरिक्त उत्पाद के विपणन, फार्म के लिए ऋण-प्राप्ति एवं मुग्तान की योजना भी सम्मिलित होनी चाहिए।

सारणी 72

खेत की जुताई करने के लिए बंलो के भ्रम एवं ट्रैक्टर के उपयोग का आंशिक बचत

व्यय	आय
(अ) ट्रैक्टर द्वारा जुताई करने से प्रति हैक्टर लागत में वृद्धि	(अ) ट्रैक्टर द्वारा एक हैक्टर क्षेत्र में एक जुताई किए जाने पर प्रति हैक्टर लागत में कमी
ट्रैक्टर द्वारा एक हैक्टर क्षेत्र में जुताई किए जाने की लागत रु 160 00	(i) मानव श्रम में कमी 20 घंटे @ रु 2 50 प्रति घंटे = रु 50 00
	(ii) बंलो के भ्रम की बचत 20 घंटे @ रु 3 75 प्रति घंटे = रु 75 00
(ब) ट्रैक्टर द्वारा जुताई करने पर प्रति हैक्टर उत्पादन/आय में कमी-कुछ नहीं	(ब) ट्रैक्टर द्वारा जुताई करने से प्रति हैक्टर उत्पादन/आय में वृद्धि, 0 25 किब गेहूँ @ रु 3 50/किब = रु 87 50
ट्रैक्टर के उपयोग से होने वाली प्रति हैक्टर अतिरिक्त लागत एवं आय में कमी की कुल राशि = रु 60 00	ट्रैक्टर द्वारा जुताई करने पर प्रति हैक्टर लागत में कमी तथा आय में वृद्धि = रु 212 50
ट्रैक्टर द्वारा जुताई करने से प्रति रु 52 50।	हैक्टर आय में शुद्ध अन्तर (लाभ) =

फार्म-योजना एवं बजट बनाना :

फार्म-योजना एवं बजट कृषक स्वयं अथवा फार्म-प्रबन्ध विशेषज्ञ अथवा कृषि विस्तार-अधिकारी की सहायता से बना सकते हैं। फार्म-योजना बनाने की विधि सरल है, लेकिन निर्मित योजना के विश्लेषण की विधि थोड़ी जटिल होती है। अतः योजना के परिणाम योजना बनाने वाले पर निर्भर करते हैं। प्राप्त परिणामों का दायित्व कृषक को वहन करना होता है। फार्म-योजना एवं बजट बनाने समय कृषक अथवा विशेषज्ञ की निम्न बातों का ज्ञान होना आवश्यक है :—

(i) कृषकों के उद्देश्य—फार्म-योजना बनाने के उद्देश्य विभिन्न कृषकों के लिये विभिन्न होते हैं। कुछ कृषकों का फार्म-योजना बनाने में उद्देश्य अधिक आय की राशि प्राप्त करना होता है जबकि दूसरे कृषकों का उद्देश्य कम पूँजी-निवेश करना अथवा कम जोखिम वहन करना होता है। उपर्युक्त सभी उद्देश्यों को एक ही फार्म-योजना में सम्मिलित कर पाना सम्भव नहीं होता है।

(ii) कृषक के पास उपलब्ध उत्पादन-साधनों की मात्रा—विभिन्न कृषकों के पास उपलब्ध उत्पादन-साधन—भूमि, सिंचाई की सुविधा, श्रम, पूँजी तथा प्रबन्ध क्षमता में विभिन्नता के कारण, प्रत्येक कृषक के लिये पृथक् रूप में फार्म-योजना निर्मित करनी होती है।

(iii) तकनीकी ज्ञान का स्तर—कृषकों में कृषि से सम्बन्धित तकनीकी ज्ञान के उपयोग स्तर में परस्पर विभिन्नता पाई जाती है जिसके कारण कुछ कृषक नयी विधियों अथवा उद्यमों को फार्म पर अपनाने को तत्पर होते हैं, जबकि अन्य कृषक ज्ञान के अभाव में उन्हें फार्म पर अपनाना नहीं चाहते हैं।

(iv) कृषकों की फार्म-प्रबन्ध क्षमता एवं जोखिम-वहन शक्ति का ज्ञान।

(v) कृषकों के योजना क्षितिजों (Planning-Horizons) की विभिन्नता का ज्ञान। विभिन्न कृषकों के योजना-क्षितिज में भी विभिन्नता पायी जाती है, जैसे कुछ कृषक आगामी एक या दो वर्षों में फार्म से अधिक आय प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि अधिकांश कृषक फार्म से भविष्य में निरन्तर अधिक आय प्राप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार भू-स्वामियों एवं आसामियों के योजना-क्षितिज में भी अन्तर होता है। अतः विभिन्न योजना-क्षितिज वाले कृषकों के लिये पृथक् रूप से फार्म-योजना तैयार की जाती है।

(vi) उत्पादन-साधनों एवं प्रचलित बाजार कीमतों का ज्ञान।

फार्म-योजना एवं बजट बनाने की विधि :

फार्म-योजना एवं बजट बनाने में कृषक अथवा विशेषज्ञ को अग्रगृही के अनुसार कार्य करना होता है—

(1) फार्म पर उपलब्ध उत्पादन-साधनों की सूची तैयार करना—फार्म-योजना बनाने का कार्य शुरू करने से पूर्व सर्वप्रथम कृषक के पास उपलब्ध साधनों की सूची तैयार करना आवश्यक होता है। उपलब्ध उत्पादन-साधनों की मात्रा के आधार पर ही कृषक के फार्म की भावी योजना तैयार की जाती है। उत्पादन-साधनों की सूची में भूमि की किस्म के अनुसार फार्म का क्षेत्रफल, उपलब्ध पूंजी की मात्रा, थम की उपलब्धि, सिंचाई के पानी की व्यवस्था, बैल एवं यान्त्रिक शक्ति की उपलब्धि, फार्म पर उपलब्ध यन्त्र एवं मशीनें आदि सम्मिलित होती है। फार्म पर उपलब्ध उत्पादन-साधनों की सूची तैयार करते समय फार्म का नक्शा भी तैयार किया जाता है, जिससे फार्म के विभिन्न खण्डों की भूमि की किस्म, उनकी समतलता, उर्वरता, सिंचाई के साधन की स्थिति आदि अंकित होती है।

उत्पादन-साधनों की सूची के आधार पर फार्म की भावी योजना तैयार की जाती है। निमित्त योजना की सफलता के लिये फार्म पर आवश्यक मात्रा में उत्पादन-साधनों का होना आवश्यक है। उत्पादन-साधनों के अभाव में फार्म पर निमित्त योजना कार्यान्वित नहीं हो सकती है। फार्म पर उत्पादन के सभी साधन आवश्यक मात्रा में उपलब्ध होने की अवस्था में ही कृषक फार्म-योजना को कार्यान्वित करके लाभ की अधिकतम राशि प्राप्त कर सकते हैं। फार्म पर सभी उत्पादन-साधनों का बाहुल्य होते हुये भी फार्म-योजना से प्राप्त होने वाले लाभ की राशि, फार्म पर सीमित उत्पादन-साधन की उपलब्ध मात्रा पर निर्भर करती है।

(2) फार्म की वर्तमान योजना का अध्ययन एवं विश्लेषण करना—फार्म पर उपलब्ध उत्पादन-साधनों की विस्तृत सूची तैयार करने के पश्चात् योजना-विशेषज्ञ का दूसरा कार्य कृषक द्वारा ली जाने वाली वर्तमान फसल-योजना, उत्पादन विधियों एवं उत्पादन-साधनों की विभिन्न फसलों में प्रयुक्त की जाने वाली मात्रा का अध्ययन करना है। फार्म की वर्तमान फार्म-योजना के अध्ययन एवं विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य फार्म पर पायी जाने वाली कमियों को ज्ञात करना है, जिनके कारण कृषक की वर्तमान में अनुकूलतम लाभ की राशि प्राप्त नहीं हो रही है। फार्म की भावी योजना बनाते समय इन कमियों को दूर करने की कोशिश की जाती है, जिससे कृषक निमित्त भावी फार्म-योजना से अधिकतम लाभ की राशि प्राप्त कर सकें।

(3) फार्म-योजना के लिये उद्यमों का चुनाव एवं उनके बजट तैयार करना—कृषक की वर्तमान फार्म-योजना का विश्लेषण करने के उपरान्त, फार्म की भावी योजना बनाने का कार्य शुरू किया जाता है। फार्म की भावी योजना बनाने में सर्वप्रथम फार्म के लिये उद्यमों का चुनाव करना होता है। उद्यमों का चुनाव करते समय कृषक द्वारा वर्तमान में अपनाये जाने वाले उद्यमों एवं अन्य उद्यम, जो उस क्षेत्र में लिये जा सकते हैं, को ध्यान में रखा जाता है। फार्म पर विभिन्न उद्यमों का चुनाव अग्र कारको पर निर्भर करता है—

- (i) क्षेत्र की जलवायु एवं मिट्टी की किस्म ।
- (ii) विभिन्न उद्यमों के उत्पादन में कृषक का अनुभव एवं दक्षता ।
- (iii) कृषक परिवार के लिये साद्यान्न, तिलहन, दालें, सब्जी की आवश्यक मात्रा ।
- (iv) पशुओं के लिये चारे की आवश्यक मात्रा ।
- (v) विभिन्न फसलों के लिये आवश्यक उत्पादन-साधनों, जैसे—सिंचाई के लिये पानी, पूँजी, श्रम आदि की मात्रा का ज्ञान ।
- (vi) क्षेत्र विशेष में उद्यमों के उत्पादन पर सरकारी प्रतिबन्ध ।
- (vii) विभिन्न उद्यमों से प्राप्त होने वाले प्रति हैक्टर आकलित लाभ की राशि ।
- (viii) भूमि की उर्वरा-शक्ति को बनाये रखने वाले उद्यमों का ज्ञान ।
- (ix) उद्यमों की विपणन सम्भावना एवं फार्म की बाजार से दूरी ।
- (x) विभिन्न उद्यमों के चुनाव में सामाजिक एवं धार्मिक बन्धन ।

उपर्युक्त कारकों के आधार पर फार्म के लिये उद्यमों/फसलों का चुनाव करने के उपरान्त, उनके बजट तैयार किये जाते हैं। उद्यमों/फसलों के बजट में तात्पर्य विभिन्न उद्यमों/फसलों पर प्रति हैक्टर होने वाली सम्भावित लागत, सम्भावित आय एवं शुद्ध लाभ की राशि ज्ञात करने से होता है। विभिन्न फसलों को कृषित करने की प्रति हैक्टर लागत ज्ञात करते समय बाजार से त्रय किये गये उत्पादन-साधन एवं कृषक द्वारा अपने फार्म एवं घर से पूर्ति किये गये उत्पादन-साधनों की लागत सम्मिलित की जाती है। साधारणतया कृषक फार्म एवं घर से पूर्ति किये गये उत्पादन-साधनों की लागत को फसल की प्रति हैक्टर लागत ज्ञात करने में सम्मिलित नहीं करते हैं तथा बाजार से त्रय किये गये साधनों की लागत का ही लेखा रखते हैं। प्रति हैक्टर कुल कृषित लागत ज्ञात करते समय व्यवस्थापन एवं जोखिम की लागत सम्मिलित नहीं की जाती है। फसल से प्राप्त होने वाली प्रति हैक्टर कुल आय, प्राप्त मुख्य उत्पाद एवं उपोत्पाद की मात्रा को उनकी विपणन मौसम में प्रबलित कीमत से गुणा करके ज्ञात की जाती है।

फसलों के बजट द्वारा विभिन्न फसलों की प्रति क्विण्टल उत्पादन-लागत भी ज्ञात की जा सकती है। विभिन्न फसलों की प्रति क्विण्टल उत्पादन लागत के आँकड़ों के आधार पर सरकार बफर स्टॉक निर्माण हेतु उनकी वसूली कीमत निर्धारित करती है। मुख्य उत्पाद की प्रति क्विण्टल उत्पादन लागत निम्न दो विधियों से ज्ञात की जाती है—

- (1) उपोत्पाद को सम्मिलित नहीं करते हुये—इस विधि में उपोत्पाद पर हुई लागत व उससे प्राप्त आय को मुख्य उत्पाद के साथ सम्मिलित

नहीं किया जाता है। मुख्य उत्पाद की प्रति विवण्टल उत्पादन-लागत शात करने का सूत्र निम्न है—

$$\text{उत्पाद की प्रति विवण्टल उत्पादन-लागत} = \frac{\text{प्रति हेक्टर कुल कृषि लागत}}{\text{मुख्य उत्पाद की प्रति हेक्टर प्राप्त मात्रा (विवण्टल में)}}$$

- (ii) उपोत्पाद को सम्मिलित करते हुये इस विधि में उपोत्पाद से प्राप्त धाय की प्रति हेक्टर कुल की गई लागत में से घटाने पर प्राप्त शेष लागत में मुख्य उत्पाद की मात्रा का भाग दिया जाता है। सूत्र के अनुसार—

$$\text{उत्पाद की प्रति विवण्टल उत्पादन-लागत} = \frac{\text{प्रति हेक्टर कुल कृषि लागत} - \text{उपोत्पाद से प्राप्त धाय}}{\text{मुख्य उत्पाद की प्रति हेक्टर प्राप्त मात्रा (विवण्टल में)}}$$

फसलों के बजट बनाने का प्रोफार्मा धागे दिया जा रहा है। फसलों के समान ही पशुओं के बजट तैयार किये जाते हैं।

फसलों के बजट बनाने का प्रोफार्मा

फसल का नाम..... किस्म वर्ष क्षेत्र

विवरण	मात्रा (प्रति हेक्टर)	कीमत (रु प्रति इकाई)	कुल मूल्य रु
-------	--------------------------	----------------------------	-----------------

1. कुल कृषि लागत
 - (i) भूमि की तैयारी
 - (ii) बुवाई से पूर्व सिंचाई
 - (iii) खाद एवं उर्वरक की लागत
 - गोबर की खाद
 - नेत्रजन उर्वरक
 - फासफोरस उर्वरक
 - पोटास उर्वरक
 - (iv) बीज एवं बीज उपचार
 - (v) सिंचाई
 - (vi) अन्तः कृषि कार्य, जैसे—
 - निराई, गुड़ाई आदि।

- (vii) कौटनाशक दवाइयों का उपयोग
- (viii) कटाई, गायटा एवं भौसाई
- (ix) विद्युत डीजल तेल का उपयोग
- (x) श्रम की आवश्यकता
- (xi) विविध लागत
- (xii) कार्यशील पूँजी का फसल के मौसम
समय से आधे समय का व्याज
कुल कृषित लागत

2 कुल आय

- (i) मुख्य उत्पाद (ii) उपोत्पाद
- कुल आय

3. शुद्ध लाभ/स्वायी फार्म उत्पादन-
साधनों का प्रतिफल

4 प्रति विन्डल उत्पादन लागत

विभिन्न फसलों के बजट प्रचलित कृषि-उत्पादन विधियों के अनिश्चित कृषि विभाग एवं कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश किए गए तकनीकी ज्ञान के स्तर पर भी बनाए जाते हैं। प्रस्तावित तकनीकी ज्ञान में प्रयुक्त उत्पादन-साधनों एवं प्राप्त होने वाली उत्पत्ति के गुणांक (Input-Output-Coefficients) क्षेत्र के अनुसन्धान एवं प्रदर्शन फार्म, प्रगतिशील कृषक, क्षेत्र के कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विभाग से प्राप्त किए जा सकते हैं।

(4) फार्म के लिए फसल-योजना तैयार करना—फार्म के लिए उद्यमों/फसलों के चुनाव एवं उनके बजट बनाने के पश्चात् चुनी हुई फसलों को फसल-चक्र में लगाना एवं विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल निर्धारित करना होता है। फसल-चक्र द्वारा फसलों का क्रम निर्धारित किया जाता है। फार्म पर विभिन्न फसलों के अन्तर्गत लिया जाने वाला क्षेत्रफल निम्न कारकों पर निर्भर करता है—

- (i) फार्म पर सीमित उत्पादन-साधनों की उपलब्ध मात्रा।
- (ii) विभिन्न फसलों से प्राप्त प्रति हेक्टर लाभ की राशि।
- (iii) पशुओं के लिए चारे की आवश्यक मात्रा।
- (iv) परिवार के सदस्यों के उपयोग के लिए खाद्यान्न, तिलहन, दालों की आवश्यक मात्रा।
- (v) कृषकों की जोखिम वहन क्षमता।

(vi) कृषको द्वारा चाही गई फसल-गहनता (Cropping intensity) ।

(vii) फसल-चक्र के नियम ।

(viii) भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने वाली फसलों का समावेश ।

उपर्युक्त कारकों के आधार पर फार्म के लिए दो या तीन फसल-चक्र योजनाएँ तैयार की जाती हैं । विभिन्न फसल चक्र योजनाओं में फसलों के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रफल होता है । एक फार्म के लिए दो या तीन योजनाएँ बनाना इसलिए आवश्यक है कि प्रस्तावित एक फसल-क्रम योजना के लिए आवश्यक उत्पादन-साधनों के पूर्ण मात्रा में फार्म पर उपलब्ध नहीं होने की अवस्था में फार्म-योजना बनाने का कार्य फिर से प्रारम्भ नहीं करना पड़े ।

(5) प्रस्तावित फसल-क्रम योजनाओं के जाँच पत्र तैयार करना—फार्म-योजना बनाने के इस क्रम में प्रस्तावित फसल-क्रम योजनाओं में से फार्म के लिए एक योजना का चुनाव किया जाता है । विभिन्न प्रस्तावित योजनाओं में से एक योजना का चुनाव उनके लिए आवश्यक उत्पादन-साधनों की मात्रा एवं फार्म पर उपलब्ध साधनों के जाँच-पत्र के आधार पर किया जाता है । यह जाँच-पत्र सिंचाई, धूम, पूंजी आदि उत्पादन-साधनों के लिए तैयार किये जाते हैं । अन्त में एक फार्म योजना का, जो जाँच-पत्रों के आधार पर पूरांतया अपनायी जा सकती है, चुनाव किया जाता है ।

(6) प्रस्तावित फार्म-योजना का विश्लेषण करना—निर्मित फार्म-योजना के फार्म पर कार्यान्वित करने के पूर्व कृषक की जिज्ञासा होती है कि चुनी हुई योजना को फार्म पर कार्यान्वित करने से वर्तमान फार्म-योजना की अपेक्षा कितना अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा । अतः फार्म-योजना से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त लाभ की राशि ज्ञात करने के लिए फार्म-योजना का आर्थिक विश्लेषण करना होता है । प्रस्तावित फार्म-योजना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभ प्रदान करने वाली होने की अवस्था में ही कृषको द्वारा फार्म पर कार्यान्वित की जाती है ।

वर्तमान फार्म-योजना एवं प्रस्तावित फार्म-योजना का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए दोनों योजनाओं के फार्म कार्यकुशलता के उपाय (Farm efficiency measures) ज्ञात किये जाते हैं । विभिन्न उत्पादन-साधनों के फार्म कार्यकुशलता उपाय ज्ञात करने के सूत्र अग्रांकित दिए गए हैं—

(i) भूमि-साधन की कार्यकुशलता या दक्षता करने के उपाय

$$(अ) \text{ फसल-गहनता} = \frac{\text{कुल फसल क्षेत्रफल}}{\text{कुल कृषित क्षेत्र}} \times 100$$

$$(ब) \text{ प्रति हेक्टर शुद्ध फार्म आय} = \frac{\text{कुल शुद्ध फार्म आय}}{\text{फार्म पर कुल भूमि क्षेत्र (हेक्टर)}}$$

$$(स) \text{ प्रति हेक्टर शुद्ध फार्म अर्जन} = \frac{\text{कुल शुद्ध फार्म अर्जन}}{\text{फार्म पर कुल भूमि क्षेत्र (हेक्टर)}}$$

(ii) श्रम साधन की कार्यकुशलता ज्ञात करने के उपाय

$$(अ) \text{ प्रति श्रमिक समग्र आय} = \frac{\text{फार्म से प्राप्त कुल आय}}{\text{फार्म पर कुल श्रमिकों की संख्या}}$$

(ब) प्रति मानव उत्पादित मानव कार्य इकाई

$$= \frac{\text{कुल उत्पादित मानव कार्य इकाईयाँ}}{\text{कुल श्रमिक (मानव इकाई के समतुल्य)}}$$

$$(स) \text{ प्रति श्रमिक फसल-क्षेत्रफल} = \frac{\text{फार्म पर कुल फसल-क्षेत्रफल}}{\text{कुल श्रमिक संख्या}}$$

(द) श्रम अर्जन = शुद्ध फार्म अर्जन — निवेश की गई पूँजी का व्याज

(iii) पूँजी-साधन की कार्यकुशलता ज्ञात करने के उपाय

(अ) स्थायी फार्म साधनों का प्रतिफल = फार्म से प्राप्त कुल आय — फार्म की कुल परिवर्तनशील लागत

(ब) उत्पादन से प्राप्त शुद्ध आय = उत्पादन से प्राप्त कुल नकद आय — कुल कार्यशील नकद उत्पादन-लागत

(स) शुद्ध फार्म आय = उत्पादन से प्राप्त शुद्ध नकद आय \pm फार्म सम्पत्ति में परिवर्तन की राशि \pm मूल्य-ह्रास की राशि

(द) शुद्ध फार्म अर्जन = शुद्ध फार्म आय \div फार्म से प्राप्त उत्पादों के घर पर उपयोग का मूल्य

(य) पूँजी-निवेश प्रतिफल = शुद्ध फार्म अर्जन — प्रबन्ध लागत

(र) औसत पूँजी-निवेश

$$= \frac{\text{वर्ष के शुरू में कुल सम्पत्ति} + \text{वर्ष के अन्त में कुल सम्पत्ति}}{2}$$

(ल) पूँजी-उत्पादन अनुपात

$$= \frac{\text{समग्र आय}}{\text{फार्म पर पूँजी-निवेश की औसत राशि}} \times 100$$

(iv) प्रबन्ध-साधन की कार्यकुशलता ज्ञात करने के उपाय

प्रबन्ध-प्रतिफल = शुद्ध फार्म अर्जन — परिवार के सदस्यों द्वारा किये गए श्रम का मूल्य — निवेश की गई पूँजी का व्याज

(v) फसल उत्पादकता सूचकांक (Crop Yield Index) :

यह सूचकांक फार्म पर सभी फसलों की उत्पादकता का सम्मिलित सूचकांक होता है जो फार्म पर फसल योजना की दक्षता ज्ञात करने में प्रयुक्त किया जाता है। यदि किसी फार्म पर फसल-उत्पादकता सूचकांक 100 से अधिक होता है तो उससे तात्पर्य है कि वह फार्म क्षेत्र के औसत फार्मों की अपेक्षा अधिक दक्ष है। इसे मात करने की विधि सारणी 7.3 में दी गई है—

(7) प्रस्तावित फार्म-योजना को कार्यान्वित करना—फार्म-योजना के आर्थिक विश्लेषण के पश्चात् प्रस्तावित फार्म-योजना को कार्यान्वित करना होना है। फार्म-योजना से प्रस्तावित लाभ की राशि तभी प्राप्त हो सकती है जब प्रस्तावित फार्म-योजना फार्म पर कार्यान्वित की जाती है। बहुधा कृषक फार्म-योजना तो तैयार करते हैं, लेकिन कार्यान्वित करने में आने वाली कठिनाइयों के कारण उसे फार्म पर पूर्णतया अपना नहीं पाते हैं। प्रत्येक नए व्यवसाय को शुरू करने में कठिनाइयाँ होती हैं। अन्य व्यवसायों की भाँति कृषकों को भी फार्म-योजना को कार्यान्वित करने में कठिनाइयों का होना स्वभाविक है। फार्म व्यवसाय से अधिकतम लाभ की प्राप्ति के लिए निम्नित योजना को सभी कठिनाइयों की अवस्था में कृषकों द्वारा कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

उपयुक्त विधि से कृषकों को प्रतिवर्ष अपने फार्म के लिए फार्म-योजना एवं बजट बनाना चाहिए। फार्म-योजना एवं बजट बनाने में कृषकों का समय अवश्य लगता है, लेकिन फार्म-योजना के अनुसार कार्य करने पर कृषकों को योजना रहित कार्य करने की अपेक्षा लाभ अधिक प्राप्त होता है।

रेखीय प्रोग्रामिंग

फार्म-योजना विश्लेषण की दूसरी प्रयुक्त गणितीय-विधि रेखीय प्रोग्रामिंग है जो द्वितीय महायुद्ध के समय प्रचलित हुई थी। इस विधि के अन्तर्गत कृषकों को फार्म से अधिकतम भाय प्राप्त कराने के लिए उद्यमों का चुनाव, उद्यमों के अन्तर्गत क्षेत्रफल तथा उत्पादन-साधनों के उपयोग की मात्रा का ज्ञान फार्म-बजट द्वारा ज्ञात न करके मैट्रिक्स बीजगणित (Matrix algebra) की सहायता से ज्ञात किया जाता है।

रेखीय प्रोग्रामिंग वह विधि है जिसके द्वारा फार्म पर अधिकतमकरण व न्यूनतमकरण की समस्याओं का हल उपलब्ध उत्पादन-साधनों की परिसीमितता की स्थिति में ज्ञात किया जाता है। रेखीय प्रोग्रामिंग विधि द्वारा प्राप्त परिणाम पूर्ण होते हैं

फार्म की फसल-उत्पादकता सूचकांक ज्ञात करना

फसल	क्षेत्रफल (हेक्टर)	फार्म पर औसत उत्पादकता (क्विन्टल/हेक्टर)	फार्म पर प्राप्त कुल उत्पादन (क्विन्टल)	क्षेत्र में औसत उत्पादकता (क्विन्टल हेक्टर)	फार्म पर प्राप्त कुल उत्पादन की प्राप्ति के लिए क्षेत्र की औसत उत्पादकता के अनुसार आवश्यक क्षेत्रफल (हेक्टर में)
गेहूँ	10	30	300	20	15
जौ	5	16	80	10	8
चना	5	10	50	12.5	4
बाजरा	15	4	60	5	12
मूँग	5	3	15	2.50	6
योग	40				45

$$\text{फार्म पर फसल-उत्पादकता सूचकांक} = \frac{45}{40} \times 100 = 112.5 \text{ प्रतिशत}$$

यद्यपि इस विधि द्वारा प्राप्त उद्यमों के समान उन्मादन-साधनों के उपयोग से अनुकूलतम लाभ की राशि प्राप्त होती है। उद्यमों का अन्य उपयोग अथवा उत्पादन-साधनों का अन्य उपयोग रेखीय प्रोग्रामिंग विधि से प्राप्त लाभ से कम लाभ की राशि प्रदान करता है।

रेखीय प्रोग्रामिंग विधि में गणित का अधिक प्रयोग होने के कारण इस विधि के उपयोग में आकलन मशीनों (Calculating machines) के आने से विस्तार हुआ है। मशीनों की सहायता के बिना रेखीय प्रोग्रामिंग विधि का उपयोग अनुकूलतम फार्म-योजना बनाने के लिए सम्भव नहीं हो पाता है। अधिकांश दृष्टकों, विस्तार सस्याओं एवं विशेषज्ञों के पास ये मशीनें उपलब्ध नहीं हैं एवं वे इस विधि से भी अनभिज्ञ होते हैं। अतः देश में अनुकूलतम फार्म-योजना बनाने के लिए फार्म-बजट विधि ही अधिक प्रचलित है। फार्म-योजना के विस्तरेण की दोनों ही विधियों-फार्म-बजट एवं रेखीय प्रोग्रामिंग के लिए आवश्यक सूचनाएँ एवं आँकड़े समान होते हैं। रेखीय प्रोग्रामिंग विधि किसी भी आर्थिक समस्या का हल ज्ञान करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसका उद्देश्य आय में वृद्धि अथवा लागत में कमी करना होता है।

रेखीय प्रोग्रामिंग विधि की सूचनूत मान्यताएँ

रेखीय प्रोग्रामिंग विधि निम्न सूचनूत मान्यताओं पर आधारित है—

(i) **रेखीयता**—रेखीय प्रोग्रामिंग विधि की प्रथम मान्यता है कि इन्पुट-आउटपुट एवं कीमतों के सम्बन्ध रेखीय होते हैं अर्थात् उत्पादन-साधन की प्रत्येक इकाई, उत्पत्ति में समान मात्रा में वृद्धि करती है। इन्पुट-आउटपुट में $y = bx$ का सम्बन्ध होता है।

(ii) **इन्पुट-आउटपुट गुणांक** की कीमतों में एकाकीयता होना—रेखीय प्रोग्रामिंग विधि की दूसरी मान्यता है कि उत्पादन-साधनों की मात्रा, इन्पुट-आउटपुट गुणांक एवं कीमतें निश्चित रूप से ज्ञात होती हैं। जहाँ पर इनमें अनिश्चितता होती है अथवा इनमें परिवर्तन होने की आशंका होती है, वहाँ पर रेखीय प्रोग्रामिंग विधि उपयोग में नहीं आ सकती है। उत्पादन की मात्रा कम होने अथवा अधिक होने, फार्म पर उत्पादन-साधनों की मात्रा अधिक अथवा कम उपयोग करने की दोनों ही अवस्थाओं में उत्पाद एवं उत्पादन-साधनों की कीमतें समान रहती हैं।

(iii) **विभाज्यता**—इस मान्यता से तात्पर्य है कि उत्पादन-साधन एवं क्रियाओं को छोटी-छोटी इकाइयों में विभक्त किया जा सकता है जैसे—भूमि के क्षेत्र को छोटे-छोटे खण्डों में, पूंजी को रुपये एवं पैसों में, श्रम को दिन व घण्टों में विभक्त किया जा सकता है।

(iv) **योगात्मक**—यह मान्यता विभाज्यता की विलोम है। इससे अन्तर्गत

विभिन्न उत्पादन-साधनों एवं क्रियाओं के योग से प्राप्त उत्पाद का, उस इकाई के पृथक् रूप से प्रयोग से प्राप्त उत्पाद की मात्रा के समतुल्य होना आवश्यक होता है।

(v) सीमितता—इस मान्यता से तात्पर्य है कि उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन-साधनों की संख्या, उत्पादन विधियों/क्रियाओं की संख्या, उन पर प्रतिबन्धों की संख्या सीमित होती है। साधनों, क्रियाओं एवं प्रतिबन्धों की संख्या सीमित नहीं होने की प्रवृत्ति में यह विधि प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है।

रेखीय प्रोग्रामिंग विधि का उदाहरण :

इस अनुभाग में रेखीय प्रोग्रामिंग विधि द्वारा अनुकूलतम फार्म-योजना बनाने की विधि का विवेचन किया गया है। अनुकूलतम फार्म-योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य लाभ की अधिकतम राशि प्राप्त करने से है। यहाँ अधिकतमकरण की दो समस्याएँ प्रस्तुत की गई हैं। सर्वप्रथम दो उत्पादों के उत्पादन में चार उत्पादन-साधनों के अनुकूलतम उपयोग एवं तत्पश्चात् अनेक उत्पादन-साधनों से अनेक उत्पादों के अनुकूलतम उत्पाद संयोग ज्ञात करने की विधि का विवेचन किया गया है।

(i) दो उत्पाद एवं अनेक उत्पादन-साधन

इस समस्या में कृषक के कुल लाभ की राशि को उस स्थिति में अधिकतम करना है जबकि फार्म पर अनेक कृषिगत पदार्थ उत्पन्न किये जा सकते हैं और उनके उत्पादन के लिए कई सीमित साधन प्रयुक्त किये जाते हैं। सुविधा के लिए यहाँ दो उत्पाद एवं चार उत्पादन-साधन लिए गये हैं। प्रत्येक उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रक्रियाएँ निर्धारित की जाती हैं। उत्पादन साधनों के प्रतिबन्धों के सहित यह समस्या विभिन्न उत्पादों के सम्भाव्य क्षेत्र को निर्धारित करती है। प्रत्येक उत्पाद के द्वारा प्रदान किये जाने वाले लाभ की राशि के ज्ञात होने पर, विभिन्न उत्पादों की मात्राओं के लिए समआय रेखाएँ (Iso-Revenue Lines) स्थापित की जाती हैं। समस्या का श्रेष्ठतम हल वह है जहाँ पर सम्भाव्य हलों का क्षेत्र सर्वोच्च-सम्भव सम-आय रेखा को केवल मात्र छूता है। यह बिन्दु सामान्यतः सम्भाव्य हलों के क्षेत्र के कोने (Corner) पर होता है।

उदाहरण के रूप में एक कृषक अपने सीमित उत्पादन-साधनों—भूमि, पूंजी, बुवाई के लिए उपलब्ध श्रम एवं कटाई के लिए उपलब्ध श्रम से गेहूँ एवं जौ उत्पाद उत्पन्न करना चाहता है। प्रत्येक उत्पादन-साधन की क्षमता निश्चित होती है। विभिन्न उत्पादों की एक इकाई से प्राप्त लाभ, प्रत्येक उत्पाद की प्राप्त कीमत व उसकी औसत परिवर्तनशील लागत पर निर्भर करता है। यहाँ यह मान्यता है कि विभिन्न उत्पादों की औसत परिवर्तनशील लागत एवं लाभ की राशि स्थिर होती है। सारणी 7 4 में विभिन्न उत्पादन-साधनों की कुल उपलब्ध मात्रा एवं प्रत्येक उत्पादन-

साधन का वह माप जो गेहूँ एवं जौ उत्पाद की एक इकाई के उत्पादन में आवश्यक होता है, प्रदर्शित किये गए हैं—

सारणी 74

कार्ग पर उपलब्ध उत्पादन-साधनों की मात्रा एवं विभिन्न उत्पादों की एक इकाई उत्पादन के लिए आवश्यक साधनों की मात्राएँ

उत्पादन-साधन	उत्पादन-साधन की कुल उपलब्ध मात्रा	प्रति इकाई (क्विन्टल) उत्पाद के लिए आवश्यक उत्पादन-साधनों की मात्रा	
		गेहूँ (X)	जौ (Y)
1 भूमि (हेक्टर)	80	0.033	0.05
2 पूंजी (रुपय)	10,000	50	40
3 बुवाई के लिए उपलब्ध श्रम (मानव दिवस)	200	0.67	0.5
4 कटाई के लिए उपलब्ध श्रम (मानव-दिवस)	150	0.67	0.5

सारणी में दो उत्पादों के उत्पादन की प्रक्रियाएँ प्रदर्शित की गई हैं। गेहूँ के उत्पादन में एक प्रक्रिया व जौ के उत्पादन में भी एक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त सारणी के आधार पर विभिन्न उत्पादन-साधनों की सहायता से गेहूँ एवं जौ की अधिकतम मात्रा उत्पन्न की जा सकती है, वह बात की जाती है। उदाहरणतया 0.033 हेक्टर भूमि क्षेत्र गेहूँ की एक इकाई उत्पादन के लिए और 0.05 हेक्टर क्षेत्र जौ की एक इकाई उत्पादन के लिए आवश्यक होना है। अतः यदि गेहूँ की मात्रा शून्य हो तो उपलब्ध भूमि के क्षेत्र (80 हेक्टर) से 160 इकाइयाँ जौ की उत्पन्न की जा सकती हैं। यदि जौ की मात्रा शून्य हो तो भूमि के 8 हेक्टर क्षेत्र से गेहूँ की 240 इकाइयाँ उत्पन्न की जा सकती हैं। इसी प्रकार अन्य उत्पादन-साधनों की उपलब्ध सीमित मात्रा से गेहूँ एवं जौ की जा अधिकतम इकाइयाँ उत्पन्न की जा सकती हैं वह बात की जाती है। सारणी 75 में विभिन्न उपलब्ध उत्पादन-साधनों से गेहूँ एवं जौ की जा अधिकतम मात्रा उत्पन्न की जा सकती है, वह प्रदर्शित की गई है—

सारणी 75

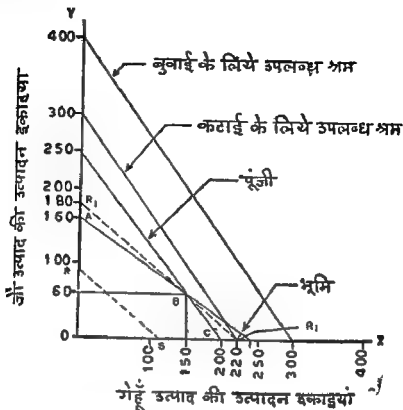
विभिन्न उत्पादों की अधिकतम उत्पादन की मात्राएँ

उत्पादन-साधन	उत्पाद की अधिकतम मात्रा जो उत्पन्न की जा सकती है	
	गेहूँ (X) (क्विण्टल)	जौ (Y) (क्विण्टल)
1 भूमि	240	160
2 पूँजी	200	250
3 बुवाई के लिये उपलब्ध मानव-श्रम	300	400
4 कटाई के लिये उपलब्ध मानव श्रम	225	300

दोनों उत्पादों के अधिकतम उत्पादन-बिन्दुओं को रेखाचित्र 7.1 में प्रदर्शित किया गया है। विभिन्न उत्पादन साधनों की उपलब्धि सीमित मात्रा से अधिकतम उत्पाद के बिन्दुओं को मिलाने वाली सरल रेखा, उत्पादों का उत्पादन-सम्भावना वक्र कहलाती है। चित्र में भूमि, पूँजी, बुवाई के लिये उपलब्ध मानव-श्रम एवं कटाई के लिये उपलब्ध मानव-श्रम से उत्पादन सम्भावना रेखाचित्रोप रूप दर्शाती है। प्रत्येक वक्र उत्पादन-साधन के सम्पूर्ण उपयोग को प्रदर्शित करता है, लेकिन प्रत्येक उत्पादन साधन का सम्पूर्ण उपयोग तभी सम्भव है जब उत्पादन के अन्य साधन फार्म पर प्रसीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। उत्पादन-साधनों की सीमितता की प्रवस्था में प्राप्त उत्पादन सम्भाव्य क्षेत्र ABC होता है। भूमि एवं पूँजी सबसे अधिक सीमित मात्रा में फार्म पर उपलब्ध होते हैं।

कृषक की समस्या का श्रेष्ठतम हल उत्तरोत्तर ऊँचे समन्वय-वक्रों पर जाकर रेखाचित्रोप विधि से निकाला जा सकता है और यह उस स्थान पर होता है जहाँ ऐसा समन्वय-वक्र आ जाता है जिसे सम्भाव्य हलों का क्षेत्र (Production feasible zone) केवल मात्र छूता है।

यदि गेहूँ एवं जौ के उत्पादन से लाभ की राशि क्रमशः 45 रु. व 55 रु. प्रति इकाई प्राप्त होती है तो कृषक को अधिकतम लाभ प्रदान करने वाला लक्ष्य-समीकरण (Objective equation) $45 \text{ गेहूँ} + 55 \text{ जौ} = W$ होता है। प्रति इकाई गेहूँ की मात्रा से प्राप्त लाभ को गेहूँ उत्पादन की कुल मात्रा से गुणा करने पर प्राप्त राशि गेहूँ के उत्पादन से प्राप्त कुल लाभ की राशि होती है। प्रति इकाई जौ की मात्रा से प्राप्त लाभ को जौ उत्पादन की कुल मात्रा से गुणा करने पर प्राप्त राशि जौ के उत्पादन से प्राप्त कुल लाभ की राशि होती है। दोनों उत्पादों के



चित्र 7.1 रेखीय प्रोग्रामिंग विधि द्वारा उत्पादों की उत्पादन सम्भाव्य मात्रा

उत्पादन से प्राप्त कुल लाभ की राशि का योग W कहलाता है, जो कृषक को फार्म से प्राप्त होने वाला कुल लाभ होता है।

चित्र 7.1 में RS रेखा कृषक के 4950 रु. कुल लाभ (W) के लिये सम-आय वक्र है। यह वक्र गेहूँ एवं जौ के उन समस्त संयोगों को दर्शाता है जो इस राशि के समान लाभ प्रदान करते हैं। फार्म से अधिक लाभ (W की अपेक्षा अधिक लाभ) के लिये सम-आय वक्र, पहले वाले वक्र के दाहिनी तरफ कुछ दूरी पर होता है, लेकिन सभी सम-आय वक्रों का ढाल समान होता है। इसी प्रकार फार्म से कम लाभ अर्थात् W की अपेक्षा कम लाभ के लिये सम-आय वक्र पहले वाले वक्र के बायीं तरफ कुछ दूरी पर होता है। चित्र में सम-आय वक्र का ढाल $= P \text{ गेहूँ} / P \text{ जौ}$ अर्थात् $45/55$ है।

सम-आय वक्र R_1R_2 उपर्युक्त चित्र में सम्भाव्य हलों के क्षेत्र में B बिन्दु पर छूता है। सम्भाव्य हलों के क्षेत्र की सीमा पर अथवा इसके अन्दर कोई भी दूसरा बिन्दु R_1R_2 सम-आय वक्र को नहीं छू पाता है। अर्थात् R_1R_2 सम-आय वक्र पर B बिन्दु के अतिरिक्त अन्य सभी बिन्दु सम्भाव्य हलों के क्षेत्र के बाहर पड़ते

है। कृषक उपलब्ध उत्पादन साधनों से 150 इकाई गेहूँ एवं 60 इकाई जौ का उत्पादन करेगा। उपर्युक्त उत्पादों के उत्पादन से कृषक को 10,050 रु का कुल लाभ (150 इकाई गेहूँ \times 45 रु + 60 इकाई जौ 55 रु) प्राप्त होता है। लाभ की यह राशि सर्वाधिक होती है।

(II) अनेक उत्पाद एवं अनेक उत्पादन साधन

फार्म पर साधारणतया दो से अधिक उत्पाद उत्पन्न किये जाते हैं। अतः दो से अधिक उत्पाद एवं अनेक उत्पादन साधनों की अवस्था में अधिकतम लाभ प्रदान करने वाले उत्पादों का संयोग ज्ञात करने का कार्य रखाचित्र की सहायता से कर पाना सम्भव नहीं होता है। यह कार्य मैट्रिक्स बीजगणित की सहायता से सुगमता से हो सकता है। निम्न उदाहरण में फार्म पर 4 सीमित उत्पादन साधनों से 6 उत्पादों के उत्पादन में अधिकतम लाभ की राशि प्रदान करने वाले संयोग ज्ञात करने की विधि मैट्रिक्स बीजगणित की सहायता से प्रस्तुत की गई है। मैट्रिक्स बीजगणित की सहायता से उत्पादों के संयोग की विभिन्न पुरस्तियाँ (Iterations) ज्ञात की जाती हैं। प्रत्येक पुनरुक्ति फार्म की एक दैकल्पिक योजना है जिसको अपनाते से प्राप्त लाभ की राशि सारणी के B कॉलम में ज्ञात हो जाता है।

कृषक फार्म पर चार सीमित उत्पाद साधनों की सहायता से गन्धक/फसलें—गेहूँ, जौ, चना, बाजरा मूग एवं ग्वार का वह संयोग उत्पन्न करना चाहता है जिसको अपनाने से उसे अधिकतम लाभ की राशि प्राप्त हो सके। उपलब्ध सीमित उत्पादन साधन निम्न हैं—

(i) खरीफ की भूमि—70 एकड़

(ii) रबी की भूमि—55 एकड़

(iii) सिचाई का अधिकतम क्षेत्र—45 एकड़

(iv) श्रम उपलब्ध (अक्टूबर—नवम्बर)—1528 घंटे।

सर्वप्रथम फार्म से प्राप्त आंकड़ों की सहायता से विभिन्न फसलों के बजट तैयार किये जाते हैं जो विभिन्न फसलों से प्रस्तावित प्रति एकड़ लाभ की राशि प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद उपर्युक्त सभी आंकड़ों को मैट्रिक्स सारणी रूप में नियत किया जाता है। सारणी 7.6 में प्राप्त आंकड़ों को मैट्रिक्स विधि में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 7.7 में प्रस्तावित योजना फार्म पर अपनाने से कृषकों को 2250 रु का लाभ प्राप्त होता है। यह योजना अनुकूलतम फार्म योजना कहलाती है क्योंकि इस योजना में यदि कुछ भी परिवर्तन किया जाता है तो फार्म से प्राप्त होने वाले लाभ की राशि बढ़ने के स्थान पर कम हो जाती है। प्राप्त परिणामों के अनुसार कृषक को फार्म पर 7 एकड़ क्षेत्र में खरीफ के मौसम में मूग की फसल एवं रबी के मौसम में एक एकड़ क्षेत्र में चना एवं 45 एकड़ क्षेत्र में गेहूँ की फसल लेनी

सारणी 7.6

मैट्रिक्स सारणी

Z	सीमित उत्पादन-साधन	C _j →	Disposal प्रक्रियाएँ										R			
			Real प्रक्रियाएँ													
			A ₇	A ₈	A ₉	A ₁₀	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A ₆				
0	खरीफ भूमि (A ₇)	70 एकड़	1	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1
0	रबी भूमि (A ₈)	5.5 एकड़	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	5.5
0	सिचाई का अधिकतम															
0	क्षेत्र (A ₉)	4.5 एकड़	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	4.5
0	उपलब्ध मानव श्रम (अक्टूबर-नवम्बर) (A ₁₀)	1528 घंटे	0	0	0	1	114	90	50	40	0	0	0	0	0	13.89
	Z ₁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Z ₁ -C ₁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

सारणी में C_j = विभिन्न फसलों के प्रति एकड़ भूमि क्षेत्र से प्राप्त लाभ की राशि-रूपों में

A₁, A₂...A₆ विभिन्न फसलें—गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, मूंग एवं ग्वार

A₇, A₈... A₁₀ सीमित उत्पादन-साधन जैसे—खरीफ भूमि, रबी भूमि, सिंचित क्षेत्र एवं उपलब्ध मानव-श्रम

उपयुक्त सारणी की सिम्प्लेक्स विधि¹ (Simplex Technique) द्वारा हल करके प्रत्युत्तम योजना की पुनर्रक्षितियाँ निकालते रहते हैं जब तक कि $Z_j - C_j$ पंक्ति में सभी संख्याएँ धनात्मक नहीं हो जाती हैं। प्राप्त परिणाम (अन्तिम पुनर्रक्षित) सारणी 7.7 में प्रदर्शित है।

सारणी 7.7

प्राप्त अन्तिम पुनर्रक्षित

सीमित	Cj →	0	0	0	0	300	270	200	125	100	90
Z उत्पादन-साधन	B	A ₇	A ₈	A ₉	A ₁₀	A ₁	A ₇	A ₃	A ₄	A ₅	A ₆
100 मूंग (A ₈)	7.0 एकड़	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
200 चना (A ₉)	1.0 एकड़	0	1	-1	0	0	0	1	-1	0	0
300 गेहूँ (A ₁)	4.5 एकड़	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
0 धम (A ₁₀)	808 मानव घंटे	0	-160	1	-50	-70	-70	50	-120	0	0
Z _j	2250	100	200	100	0	300	300	200	200	100	100
Z _j - C _j	2250	100	200	100	0	0	30	0	75	0	10

1. E. O. Heady & W. Candler, Linear Programming Methods, The Iowa State University Press, Ames, Iowa, 1958.

चाहिये। उपर्युक्त फसलों को लेने के उपरान्त कृषक के पास 808 मानव श्रम घंटे अधिशेष रह जाते हैं। अतः कृषक को इन अधिशेष मानव-घंटों में दूसरों के फार्म पर कार्य करके अपनी आय में वृद्धि करनी चाहिये।

अनुकूलतम फसल-योजना

अनुकूलतम फसल योजना से तात्पर्य फार्म की उस युक्ति-संगत उत्पादन-योजना से है जो कृषको को फार्म पर उपलब्ध उत्पादन-साधनों की सीमितता एवं उत्पादन सम्भावनाओं के ढाँचे में अधिकतम शुद्ध लाभ की राशि प्राप्त कराती है। कृषको को प्राप्त होने वाला अधिकतम लाभ एक वर्ष के लिए अधिक न होकर सन्ने वाले वर्षों में अधिक प्राप्त होना चाहिए।

प्रत्येक जौत के लिए उत्पादन-साधनों की विविधता के कारण अनुकूलतम फसल-योजना विभिन्न होती है। अतः देश की अनेक जौतों के लिए एक ही अनुकूलतम योजना प्रस्तावित नहीं की जा सकती है। अनुकूलतम फसल योजना वर्तमान तकनीकी ज्ञान स्तर एवं उन्नत तकनीकी ज्ञान-स्तर पर तथा साधनों की प्रस्तावित उपलब्ध मात्रा के अनुसार उपर्युक्त दोनों विधियों—फार्म योजना एवं बजट तथा रेखीय प्रोग्रामिंग—द्वारा बनाई जा सकती है।

लागत-संकल्पना (Cost Concepts)

विभिन्न फार्म व्यवस्थापन अध्ययनों में उत्पादन की लागत ज्ञात करने में निम्न चार लागत-संकल्पनाएँ प्रयुक्त की गई हैं। इन्हीं लागतों के आधार पर विभिन्न उत्पादन कारकों की प्राप्त होने वाली आय की परिकल्पना की गई है। इन लागतों की संक्षिप्त व्याख्या निम्न है।

(i) लागत A_1 (Cost A_1)

इस लागत में वे सभी खर्च सम्मिलित होते हैं जो कृषक द्वारा नकद या वस्तु के रूप में भुगतान किए जाते हैं। इसमें सम्मिलित लागत के अन्वय निम्न हैं।

- (i) स्थायी एवं अस्थायी धर्मिकों की लागत।
- (ii) स्वयं एवं किराये पर लिए गए बैलों के श्रम की लागत।
- (iii) स्वयं एवं किराये पर ली गई मशीनों की लागत।
- (iv) उर्वरक की लागत।
- (v) खाद की लागत (स्वयं एवं क्रय किए गए)।
- (vi) बीज की लागत (फार्म पर उत्पादित एवं क्रय किये गये)।
- (vii) कीटनाशी दवाइयों की लागत।
- (viii) सिंचाई की लागत।
- (ix) नहर के पानी की दी गई लागत राशि।
- (x) मूल-राजस्व, अधिभार एवं अन्य भुगतान किए गए करों की राशि।

(xi) फार्म भवन, मशीनो, सिंचाई साधनो एवं फार्म औजारो की घिसावट की लागत ।

(xii) अन्य लागत जैसे-छोटे औजारो के रख-रखाव की लागत एवं अन्य कार्यों की लागत ।

(xiii) फार्मशोल पूँजी का व्याज ।

(ii) लागत A_2 (Cost A_2)

लागत A_1 में बटाई पर ली गई भूमि की देय लगान राशि सम्मिलित करने पर जो लागत आती है, वह लागत A_2 कहलाती है । दूसरे शब्दों में एक आसामी कृषक (Tenant farmer) द्वारा दिए गए सभी व्यय लागत A_2 कहलाती है ।

लागत A_2 = लागत A_1 + बटाई पर ली गई भूमि की देय लगान की राशि ।

(iii) लागत 'ब' (Cost B)

लागत A_2 में स्वय की भूमि की आरोप्य लगान राशि (Imputed rental value) एवं स्वय की स्थायी निवेश पूँजी (भूमि के प्रतिरिक्त) का व्याज सम्मिलित करने से प्राप्त लागत को लागत ब कहते हैं ।

लागत ब = लागत A_2 + स्वय की भूमि की आरोप्य लगान राशि + स्वय की स्थायी निवेश पूँजी (भूमि के प्रतिरिक्त) का व्याज ।

(iv) लागत 'स' (Cost C) :

लागत 'ब' में पारिवारिक श्रम की आरोप्य राशि (Imputed value of family labour) सम्मिलित करने पर प्राप्त राशि लागत 'स' कहलाती है । यह लागत फार्म पर होने वाली कुल लागत भी कहलाती है ।

लागत 'स' = लागत 'ब' + पारिवारिक श्रम की आरोप्य राशि ।

भारत सरकार ने वर्ष 1979 में डा एस आर सेन की अध्यक्षता में एक विशेष विशेषज्ञ समिति, कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत ज्ञात करने की विधि में सुझाव देने हेतु नियुक्त की थी । इस समिति ने अन्य सुझावों के प्रतिरिक्त, लागत सकल्पना को निम्न 6 श्रेणियों में वर्गीकृत करने की सिफारिश की है—

(1) लागत A_1 (Cost A_1)—इसमें स्वामित्व भूमि वाले कृषक द्वारा फार्म पर किए गए सभी नकद एवं वस्तु के रूप में वास्तविक व्यय सम्मिलित होता है ।

(2) लागत A_2 (Cost A_2)=लागत A_1 + बटाई पर ली गई भूमि का दिये गये लगान की राशि ।

(3) लागत B_1 (Cost B_1)=लागत A_1 + स्वय की पूँजी राशि (भूमि के प्रतिरिक्त) पर देय व्याज की राशि ।

(4) लागत B_2 (Cost B_2)=लागत B_1 + स्वय की भूमि का आरोप्य लगान राशि (सरकार को दिए गए राजस्व राशि को शेष निकालकर) + बटाई पर प्राप्त भूमि की देय लगान राशि ।

(5) लागत s_1 (Cost C_1) = लागत b_1 + पारिवारिक श्रम की आरोप्य राशि ।

(6) लागत s_2 (Cost C_2) = लागत b_2 + पारिवारिक श्रम की आरोप्य राशि ।

उपयुक्त लागत सकल्पना के आधार पर फार्म पर विभिन्न उत्पादन-साधनों को प्राप्त होने वाली आय ज्ञात हो जाती है जो अनेक प्रकार के निर्णय लेने में सहायक होते हैं ।

(i) लागत 'स'

इस लागत में सभी प्रकार के फार्म पर होने वाले व्यय सम्मिलित होते हैं । फार्म से प्राप्त उत्पादों से होने वाली आय में से लागत 'म' राशि देय निकालने पर जो राशि शेष रहती है, वह फार्म व्यवसाय की सफलता का सूचक होती है । इस राशि की मात्रा फार्म दक्षता का सर्वोत्तम मापदण्ड होता है । इस लागत के आधार पर फार्म पर शुद्ध लाभ या व्यवस्थापन साधन का प्रतिफल ज्ञात हो जाता है ।

शुद्ध लाभ का व्यवस्थापन साधन = फार्म पर उत्पादों से —लागत 'स'
का प्रतिफल = प्राप्त आय

(ii) लागत 'ब'

फार्म पर प्राप्त उत्पादों से होने वाली आय में से लागत 'ब' राशि शेष निकालने पर प्राप्त राशि पारिवारिक श्रम एवं व्यवस्थापन साधन का प्रतिफल (Reward for Family Labour and Management) अथवा पारिवारिक श्रम की आय (Family Labour Income) कहलाती है ।

पारिवारिक श्रम की प्राप्त आय = फार्म पर उत्पादों से प्राप्त आय — लागत 'ब'

(iii) लागत m_2

फार्म पर उत्पादों से प्राप्त आय की राशि में लागत m_2 राशि शेष निकालने पर प्राप्त राशि को फार्म व्यवसाय से प्राप्त आय (Farm Business Income) कहते हैं । दूसरे शब्दों में यह राशि स्वयं पारिवारिक श्रम, भूमि का प्रबन्ध एवं स्थायी पूंजी निवेश राशि के लिए प्राप्त प्रतिफल है ।

फार्म व्यवसाय से प्राप्त आय = फार्म पर उत्पादों से प्राप्त आय — लागत m_2

(iv) लागत अ

फार्म पर उत्पादों से प्राप्त आय की राशि में से लागत अ, की राशि देय निकालने पर प्राप्त आय शुद्ध फार्म आय (Net-farm Income) कहलाती है । साधारणतया कृषक अपने फार्म पर पूंजी निवेश करने के उपरान्त फार्म से अधिकधिक शुद्ध फार्म आय प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं ।

शुद्ध फार्म आय = फार्म पर उत्पादों से प्राप्त आय — लागत अ,

कृषि के विभिन्न रूप एवं प्रणालियाँ

देश के विभिन्न राज्यों, जिलों एवं क्षेत्रों में प्राकृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कारकों की विभिन्नता के कारण कृषि के विभिन्न रूप एवं प्रणालियाँ पाई जाती हैं। कृषि के विभिन्न रूपों एवं प्रणालियों का विस्तृत अध्ययन करने से पूर्व इनके अभिप्राय का ज्ञान होना आवश्यक है।

कृषि के रूप—कृषि के रूपों से तात्पर्य कृषि की भूमि की उपयोगिता, पशु तथा फसल उत्पादन एवं प्रयुक्त फार्म क्रियाओं के आधार पर वर्गीकरण करने से है जैसे—विशिष्ट कृषि, विविधीकृत कृषि (Diversified farming), मिश्रित कृषि, शुष्क कृषि, यान्त्रिक कृषि आदि। जॉनसन¹ ने कृषि के रूपों की निम्न परिभाषा दी है—

“जब क्षेत्र में बहुत से फार्म, फसलों एवं पशुओं के उत्पादन के अनुपात व उत्पादन में प्रयोग की गई विधियों एवं प्रणालियों में बिल्कुल समान होते हैं तो उन फार्मों को कृषि के रूपों के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है।”

कृषि प्रणालियाँ—कृषि-प्रणालियों से तात्पर्य कृषि का सामाजिक एवं आर्थिक प्रबन्ध के आधार पर वर्गीकरण करने से है जैसे—व्यक्तिगत कृषि, राजकीय कृषि, पूँजी-प्रधान कृषि, सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि आदि। जॉनसन² ने कृषि-प्रणालियों की निम्न परिभाषा दी है—

- 1 “When farms in a group are quite similar in the kinds and proportions of the crops and livestock that are produced and in the methods and practices followed in production, that group is described as a type of farming”

—Sherman E. Johnson, Neil W. Johnson, Martin, R. Cooper, Orlin, J. Secville, and Samuel W. Mendum, *Managing A Farm*, D. Von Nostrand, Company, INC., New-york, 1946 P. 27.

- 2 “The Combination of production on a given farm and the Methods or practices that are used in the production of those products is known as the system of farming that is followed on that farm”

—Sherman E. Johnson, et al, *Ibid*, 1946, p. 27

जब क्षेत्र में फार्म, उत्पादित वस्तुओं के संयोजन एवं उन वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त विधि या क्रिया में समान होते हैं तो फार्मों को कृषि-प्रणालियों के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है।

कृषि के रूप निर्धारित करने वाले कारक

कृषि के रूप निर्धारण करने वाले प्रमुख कारक निम्नांकित हैं—

(1) प्राकृतिक कारक—क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक कारक कृषि के रूप के निर्धारक होते हैं। ये निम्नलिखित होते हैं—

(अ) भूमि—भूमि के अन्तर्गत भूमि की उपजाऊ, क्षारीयता, बनावट, पानी रोकने की शक्ति, जल निकास आदि सम्मिलित होते हैं। विभिन्न फसलों के उत्पादन के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है जैसे—कपास के लिए काली, गेहूँ के लिए दमट मिट्टी, आदि। अतः विभिन्न क्षेत्रों में भूमि की भिन्नता के कारण कृषि के रूप में भी भिन्नता होती है।

(ब) भूमि का घरातल—भूमि के घरातल के अन्तर्गत भूमि की सतह, ढाल आदि सम्मिलित होते हैं। निचली भूमि पर जहाँ पानी के निकास की उचित व्यवस्था नहीं होती है वहाँ चावल व जूट की खेती अच्छी नहीं होती है। असम व बंगाल में चाय, काफी के बागान भूमि के घरातल के कारण ही पाये जाते हैं।

(स) जलवायु—जलवायु में वर्षा, नमी, तापक्रम सम्मिलित होते हैं। जलवायु भी क्षेत्र में कृषि के प्रकार में परिवर्तन लाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल, गन्ना, जूट की खेती अच्छी होती है। नमी वाले क्षेत्रों में कपास एवं सूखे क्षेत्रों में बाजड़ा, ग्वार, मोठ, मूंग अधिक होते हैं। जलवायु की अनुकूलता के कारण ही कुल्लू व कश्मीर में सेब के बाग अधिक पाये जाते हैं।

(2) आर्थिक कारक—आर्थिक कारकों के होने से एक क्षेत्र में फसल का उत्पादन दूसरे क्षेत्र की अपेक्षा अधिक लाभकर होता है। निम्न आर्थिक कारक कृषि के रूप में परिवर्तन लाते हैं—

(अ) वस्तुओं की विपणन लागत—वस्तुओं की प्रति इकाई विपणन लागत की अधिकता व कमी कृषि के रूप में परिवर्तन लाती है। प्रति इकाई पर उत्पाद की विपणन लागत की कमी के कारण ही गन्ने की खेती चीनी मिलों तथा सब्जी, फल, दूध का उत्पादन शहरों के नजदीक अधिक होता है। उत्पादन व उपभोग स्थान में दूरी के बढ़ने से अम्बार जाती एवं शीघ्रनाशी वस्तुओं की परिवहन लागत में वृद्धि होती है। फलतः ऐसी वस्तुओं का उत्पादन उपभोग स्थान से दूर करने पर विपणन लागत अधिक आती है जिससे उस क्षेत्र में उस वस्तु का उत्पादन करना कम लाभ-प्रद होता है।

(ब) श्रम व पूँजी की उपलब्धि—क्षेत्र में श्रम व पूँजी की बहुलता एवं कमी भी कृषि के रूप में परिवर्तन लाती है। गन्ना, कपास एवं आलू की फसल श्रम

माहृत्य क्षेत्रों में ही अधिक उत्पादित की जाती है। थम व पूँजी के कम मात्रा में उपलब्ध होने वाले क्षेत्रों में उपयुक्त फसलों को लेना आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं होता है।

(स) भूमि की कीमत—शहरों के नजदीक भूमि की मांग की अधिकता के कारण कीमत अधिक होती है जिसके कारण इन क्षेत्रों की भूमि में अधिक आय देने वाली फसलें जैसे—सब्जी, फल, फूल आदि का उत्पादन ही लाभप्रद होता है। शहर से दूरी बढ़ने पर भूमि की प्रति इकाई कीमत कम होती जाती है जिसके कारण इन क्षेत्रों में खाद्यान्नों का उत्पादन अधिक होता है।

(द) उद्योगों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा—कृषकों के पास उत्पादन-साधन सीमित मात्रा में होते हैं। विभिन्न उद्योगों में उत्पादन-साधनों के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा के कारण कृषक उत्पादन-साधनों का उपयोग क्षेत्र में अधिकतम लाभ प्रदान करने वाली फसल के अन्तर्गत करते हैं, जिसके कारण क्षेत्र में कुछ फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल अधिक होता है तथा दूसरी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल कम होता है। इससे कृषि के रूप में परिवर्तन आता है।

(य) बीमारियों एवं कीड़ों का प्रकोप—क्षेत्र विशेष में कुछ फसलों में बीमारी एवं कीड़ों का प्रकोप दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। अतः कृषक उस क्षेत्र में ऐसी फसलों का उत्पादन करते हैं जिन पर बीमारियों एवं कीड़ों का आक्रमण नहीं होता है। इससे भी कृषि के रूप में परिवर्तन आता है।

(र) कृषि-उत्पादों की कीमतों में परिवर्तन—कृषि-उत्पादों की कीमतों में निरन्तर परिवर्तन के कारण भी क्षेत्र में कृषि के रूप में परिवर्तन आता है। गेहूँ की कीमत में अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक वृद्धि होने पर क्षेत्र के कृषक गेहूँ के अन्तर्गत अधिक क्षेत्रफल लेते हैं जिससे अन्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल में कमी होती है।

(ल) जोत का आकार—जिन क्षेत्रों में जोत का औसत आकार कम होता है वहाँ पर यान्त्रिक साधनों से जोती करना लाभकर नहीं होता है, जबकि अधिक जोत आकार वाले क्षेत्रों में यान्त्रिक सेती अपनाई जा सकती है।

(व) सिंचाई की सुविधा—सिंचाई की पर्याप्त सुविधा वाले क्षेत्रों में वे सभी फसलें, जिन्हें अधिक मात्रा में पानी की निरन्तर आवश्यकता होती है, उगाई जा सकती हैं जैसे—सब्जियाँ, गेहूँ, रिजका आदि। अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है, वहाँ पर वे फसलें उगाई जा सकती हैं जिन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है जैसे—बाजरा, ग्वार, मूँग, मोठ आदि।

(3) सामाजिक कारक—कृषि के रूप में परिवर्तन लाने वाले प्रमुख सामाजिक कारक भ्रष्टाचार होते हैं—

(प्र) व्यक्तिगत रुचि—कृषक साधारणतया वे ही फसलें उत्पन्न करने पसन्द करते हैं जिनके उत्पादन में उनकी व्यक्तिगत रुचि होती है। फसल का लेना आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होते हुए भी कृषक उनको तब तक उत्पन्न नहीं करते हैं जब तक कि उनकी व्यक्तिगत रुचि उस फसल को लेने की नहीं होती है। कृषको की व्यक्तिगत रुचि फसल के उत्पादन में उनके अनुभव, प्रशिक्षण आदि पर निर्भर होती है।

(ख) सामाजिक रिवाज—सामाजिक रिवाज भी कृषि के रूप में परिवर्तन लाते हैं जैसे—सिख-समुदाय के कृषक तम्बाकू की फसल उत्पन्न नहीं करते हैं।

(स) समुदाय-प्रभाव—कृषक क्षेत्र में वे ही फसलें अधिक उत्पन्न करते हैं जो समुदाय के अन्य कृषको द्वारा उस क्षेत्र में उत्पन्न की जाती हैं। वे नये उद्यम या फसलों को फार्म पर उत्पन्न करने के कम इच्छुक होते हैं।

कृषि के विभिन्न रूपों का वर्गीकरण :

निम्न आधारों के अनुसार कृषि के रूपों का वर्गीकरण किया जा सकता है—

1 उत्पादों से प्राप्त आय के अनुपात के आधार पर

- (प्र) विशिष्ट कृषि
- (ब) विविधीकृत कृषि
- (स) मिश्रित कृषि

2 उत्पादों की प्रकृति के आधार पर

- (प्र) खाद्यान्नों की कृषि
- (ब) सब्जी की कृषि
- (स) फलों के बाग
- (द) डेयरी फार्म
- (य) कुक्कट पालन फार्म
- (र) पशुओं की चराई/रैचिंग

3 भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर

- (अ) छोटे पैमाने पर कृषि
- (ब) बड़े पैमाने पर कृषि

4 व्यावसायिक उद्यमों के आधार पर

- (अ) पारिवारिक कृषि
- (ब) व्यापारिक कृषि
- (स) अर्ध-कालीन कृषि

5 सिंचाई की सुविधा के आधार पर

(अ) सिंचित कृषि

(ब) शुष्क कृषि

6 यान्त्रिक साधनों के उपयोग के आधार पर

(अ) प्रचलित कृषि

(ब) यान्त्रिक कृषि

7. श्रम उपलब्धि के आधार पर

(अ) पारिवारिक सदस्यों के श्रम द्वारा कृषि

(ब) श्रमिकों के श्रम द्वारा कृषि

■ उत्पादन साधनों के उपयोग के अनुपात के आधार पर

(अ) सघन कृषि/पूँजी तथा श्रम प्रधान कृषि

(ब) विस्तृत कृषि/भूमि-प्रधान कृषि

कृषि की प्रणालियों का वर्गीकरण :

कृषि की प्रणालियों को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जाता है—

1. फार्म संचालन एवं प्रबन्ध के आधार पर

(अ) व्यक्तिगत कृषि

(ब) पूँजी प्रधान कृषि

(स) राजकीय कृषि

(द) सहकारी कृषि

(य) सामूहिक कृषि

(र) निगमित कृषि

2 भू-धृति के आधार पर

(अ) पैतृक भू-धारण कृषि

(ब) काश्तकार कृषि

(स) ऐच्छिक भू-धारण कृषि

(द) पट्ट पर प्राप्त भूमि पर कृषि ।

कृषि के प्रमुख रूपों एवं प्रणालियों का विस्तृत विवेचन नीचे किया जा रहा है—

कृषि के रूप

1 फार्म पर उत्पादित उत्पादों से प्राप्त आय के अनुपात के आधार पर :

(अ) विशिष्ट कृषि

फार्म पर प्राप्त कुल आय का 50 प्रतिशत या अधिक भाग एक ही उद्यम या फसल से प्राप्त होता है तो ऐसे फार्म को उस उद्यम या फसल के उत्पादन का विशिष्ट फार्म तथा इस प्रकार की कृषि को विशिष्ट कृषि कहते हैं । हॉपकिन्स के अनुसार विशिष्ट कृषि से तात्पर्य “फार्म पर विपणन के लिए एक ही वस्तु के

उत्पादन करने से है।" देश के कुछ राज्यों में चाय, काफी, पटसन, एम्बाबू, कपास, गन्ना, सब्जियों के विशिष्ट फार्म हैं।

विशिष्ट कृषि से लाभ—विशिष्ट कृषि अपनाते से कृषकों को निम्न लाभ प्राप्त होते हैं—

1. भूमि का उत्तम उपयोग—जिम फसल के लिये भूमि उपयुक्त होती है उस फसल की विशिष्ट कृषि करने से भूमि का उत्तम उपयोग होता है तथा प्रति हैक्टर उत्पादन की मात्रा अधिक प्राप्त होती है।
2. उत्तम प्रबन्ध—फार्म पर फसलों की सीमित सहाय के कारण फर्म प्रबन्धक फार्म के प्रबन्ध में दक्षता प्राप्त कर लेता है, जिससे फार्म का प्रबन्ध उत्तम होता है।
3. श्रमिकों को कार्यकुशलता एवं दक्षता में वृद्धि—फार्म पर निरन्तर एक ही फसल या उद्यम के उत्पादन से श्रमिक फसल की प्रत्येक उत्पादन-क्रिया में दक्षता प्राप्त कर लेते हैं, जिससे उनकी कार्य-कुशलता व दक्षता में वृद्धि होती है।
4. विपणन दक्षता—विशिष्ट कृषि के कारण फार्म पर उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। उत्पादन की अधिकता के कारण, उस वस्तु को विप्रेय अधिक मात्रा में अधिक होती है। वस्तुओं का अधिक मात्रा में एक साथ विक्रय करने से विपणन लागत कम आती है एवं विपणन प्रक्रिया में दक्षता आती है।
5. फार्म पर उन्नत यन्त्र एवं मशीनों का प्रयोजन करना—विशिष्ट कृषि में फसलों के लिए आवश्यक उन्नत औजारों एवं कीमती मशीनों का प्रयोजन करके उपयोग किया जा सकता है। विशिष्ट फार्म पर रीपर ब्रँसर आदि मशीनों का प्रयोजन एवं उपयोग आर्थिक दृष्टि से लाभकर होता है।
6. समय की बचत—विशिष्ट कृषि के अन्तर्गत मशीनों के उपयोग से फार्म पर विभिन्न कार्य करने में समय की बचत होती है, जिसके कारण कृषकों को दूसरे कार्य करने के लिए अधिक समय मिल जाता है।

विशिष्ट कृषि से हानियाँ—विशिष्ट कृषि अपनाने से कृषकों को निम्न हानियाँ होती हैं—

1. जोखिम की अधिकता—मौसम की अनिश्चितता अथवा उत्पाद की कीमत में गिरावट से कृषकों की विशिष्ट कृषि की स्थिति में हानि अधिक होती है क्योंकि आय के स्रोत सीमित होते हैं।

- 2 भूमि की उर्वरा-शक्ति में ह्रास-भूमि पर निरन्तर एक ही फसल के उत्पादन करने तथा उचित फसल-चक्र के अभाव में भूमि की उर्वरा-शक्ति में ह्रास होता है जिससे भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है।
3. विशिष्ट कृषि में फार्म पर उपलब्ध उत्पादन साधनों—भूमि, श्रम, पूँजी आदि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है जिससे काफी मात्रा में उत्पादन-साधन बेकार रहते हैं।
- 4 विशिष्ट कृषि के अन्तर्गत कृषक को वर्ष में एक या दो बार ही भाय प्राप्त होती है जबकि विभिन्न कृषि कार्यों के करने के लिए निरन्तर पूँजी की आवश्यकता होती है।
- 5 विशिष्ट कृषि में फार्म पर उपोत्पादों का अधिक मात्रा में उत्पादन होने के कारण उनका उचित एवं पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है।
- 6 विशिष्ट कृषि अपनाने से कृषको को खाद्यान्नों की घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी दूसरे कृषको पर निर्भर रहना होता है।
- 7 विशिष्ट कृषि में कृषको को एक या दो फसलों के उत्पादन में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाता है लेकिन वे अन्य फसलों के उत्पादन ज्ञान से पूर्णतया अनभिज्ञ होते हैं।

(ब) विविधीकृत कृषि 'सामान्य कृषि'

विविधीकृत कृषि के अन्तर्गत कृषक फार्म पर वर्ष में अनेक उत्पाद उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार की कृषि के अन्तर्गत कृषक को फार्म से प्राप्त आय का 50 प्रतिशत या अधिक भाग किसी भी एक फसल या उद्यम के उत्पादन के प्राप्त नहीं होता है। विविधीकृत कृषि वाले फार्म को 'विविध व्यवसाय-फार्म' भी कहते हैं। ऐसे फार्म पर शाद्यान्न, सब्जी, पशुपालन, कुक्कुट-पालन आदि सभी उद्यम लिए जाते हैं।

विविधीकृत कृषि से लाभ—फार्म पर विविधीकृत कृषि अपनाने से कृषको को निम्न लाभ प्राप्त होते हैं—

(1) जोखिम का कम होना—इस प्रकार की कृषि में मौसम की प्रतिकूलता एवं उत्पादों की कीमतों के गिरने की स्थिति में हानि, विशिष्ट कृषि की अपेक्षा कम होती है। मौसम की प्रतिकूलता का प्रभाव विभिन्न फसलों पर विभिन्न मात्रा में होता है। इसी प्रकार कीमतों में उतार चढ़ाव भी विभिन्न फसलों में समान न होकर विभिन्न मात्रा में होते हैं।

(2) उत्पादन-साधनों का पूर्ण एवं उचित उपयोग—विविधीकृत कृषि के अन्तर्गत फार्म पर उपलब्ध उत्पादन-साधनों—भूमि, श्रम, पूँजी आदि का पूर्ण एवं उचित उपयोग होता है क्योंकि विभिन्न उद्यमों के उत्पादन के लिए उत्पादन साधनों की आवश्यकता विभिन्न मात्रा में होती है। कुछ उद्यम पूँजी अधिक चाहते हैं, जबकि दूसरे उद्यम श्रम अधिक चाहते हैं।

(3) इस तरह की कृषि में वृषको को वर्ष भर घास प्राप्त होती रहती है, जिससे कृषको को घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति एवं फार्म के लिए उत्पादन साधनों में क्रय करने में परेशानी नहीं होती है।

(4) इस प्रकार कृषि में फार्म पर उत्पादित विभिन्न उपोत्पाद कम मात्रा में होने के कारण इनका पूर्ण एवं उचित उपयोग होता है।

(5) फार्म पर उचित फसल चक्र अपनाने में भूमि की उर्वरा-शक्ति में ह्रास नहीं होता है और उचित उर्वरता-स्तर बना रहता है।

(6) कृषको को खाद्यान्न एवं सब्जी की घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरे कृषको पर निर्भर नहीं रहना होता है।

विविधीकृत कृषि से हानियाँ—विविधीकृत कृषि के अपनाने से कृषको को निम्न हानियाँ होती हैं—

(1) फार्म संचालन एवं प्रबन्ध में असुविधा—फार्म पर विभिन्न उद्यमों के होने से वर्ष भर कृषको को विभिन्न कार्य करने होते हैं। कार्य की विविधता के कारण फार्म प्रबन्ध में असुविधा होती है एवं दक्षता नहीं आ पाती है।

(2) प्रति इकाई विपणन लागत की अधिकता—इस प्रकार की कृषि के अन्तर्गत फार्म पर विभिन्न फसलों के विक्रेय अधिशेष की मात्रा कम होती है। अतः उत्पादों का विक्रय करने में प्रति इकाई विपणन लागत अधिक आती है एवं कृषको को उत्पाद की शुद्ध कीमत कम प्राप्त होती है।

(3) फार्म पर उन्नत औजारों एवं मशीनों का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से लाभकर नहीं होता है। मशीनें वर्ष में अधिक समय बेकार पड़ी रहती हैं जिससे स्थायी लागत अधिक आती है।

(4) भूमि की उपयुक्तता एक फसल के लिए होते हुए भी उस पर अनेक फसलें उत्पादित की जाती हैं जिससे भूमि का उचित उपयोग नहीं हो पाता है।

(5) कार्य की विविधता के कारण अधिक भी कार्य में दक्षता प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

विशिष्ट एवं विविधीकृत कृषि के लाभ व हानियों को दृष्टिगत रखते हुए भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए, जिसमें मौसम की अनिश्चितता कृषि का वर्षा पर निर्भर होना, विशिष्ट उत्पादों की मण्डियों का अभाव, कृषको के पास उत्पादन-साधनों की सीमितता एवं कृषको की जोखिम बहन क्षमता कम होने के कारण, विविधीकृत कृषि ही अधिक उपयुक्त है।

(स) मिश्रित कृषि

मिश्रित कृषि से तात्पर्य फार्म पर कृषि-उत्पादन के साथ साथ पशुपालन उद्यम या दूध उत्पादन व्यवसाय को लेने से है। मिश्रित कृषि में फार्म से प्राप्त कुल

आय में फसलों के अतिरिक्त पशुपालन व्यवसाय भी आय का प्रमुख स्रोत होता है। मिश्रित कृषि में पशुपालन एवं फसल उत्पादन उद्यम एक-दूसरे के सहायक उद्यम होते हैं। भारतीय कृषि अर्थशास्त्र सस्था ने मिश्रित कृषि को निम्न शब्दों में परिभाषित किया है—

“किसी भी फार्म को मिश्रित श्रेणी में होने के लिए फार्म से प्राप्त कुल आय का कम से कम 10 प्रतिशत व अधिकतम 49 प्रतिशत आय पशुपालन उद्यम से प्राप्त होना आवश्यक है। पशुपालन में गाय एवं भैंस ही सम्मिलित किए जाते हैं। भेड़, बकरी, कुक्कुट आदि पशुपालन उद्योग में शामिल नहीं किये जाते हैं।”³ उदाहरणतया यदि किसी फार्म पर प्राप्त कुल आय का 10 प्रतिशत से अधिक भाग गाय एवं भैंस उद्यम से प्राप्त होता है तो वह फार्म ‘मिश्रित फार्म’ कहलाता है। इसी प्रकार यदि फार्म से प्राप्त कुल आय का 10 प्रतिशत से अधिक भाग सभी प्रकार के पशुओं से सम्मिलित रूप में प्राप्त होता है तो वह फार्म विविधीकृत फार्म कहलाएगा।

मिश्रित कृषि देश में लघु कृषकों, मौसम की अनिश्चितता वाले क्षेत्रों, कम नमी या सूखा वाले क्षेत्रों के लिए अधिक लाभकारी होती है। फसल उद्यम, पशुपालन उद्यम के लिए सहायक उद्यम होने के कारण मिश्रित कृषि अन्य प्रकार की कृषि का अपेक्षा अधिक लाभकारी होती है। राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में किए गए अध्ययन से स्पष्ट है⁴ कि फार्म पर मिश्रित कृषि अपनाने से लघु, मध्यम व बड़े फार्मों पर 20 29,63 28 एवं 52.15 प्रतिशत लाभ विविधीकृत फार्म की अपेक्षा अधिक प्राप्त होता है। मिश्रित कृषि अपनाने से उसी भूमि के क्षेत्र से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होता है तथा फार्म आय में स्थिरता आती है।

विभिन्न देशों में मिश्रित कृषि से तात्पर्य विभिन्न उद्यमों के संयोजन से होता है, जैसे—भारत में फसल उत्पादन के साथ दूध-उत्पादन, अमेरिका में फसल उत्पादन के साथ मांस उत्पादन, इंग्लैंड में खाद्यान्न-उत्पादन के साथ घास उत्पादन आदि।

मिश्रित कृषि से लाभ :

- 1 मिश्रित कृषि में पशुपालन उद्यम के होने से कृषि के लिए आवश्यक अच्छे बैल, कृषक फार्म पर ही तैयार कर लेते हैं, जिससे बैलों की लागत कम आती है।

3 Indian Journal of Agricultural, Economics, Vol XVI, No 1, January-March, 1961.

4 Dr L. Agarwal, Possibilities of Increasing Farm Income through optimum combination of Crops and Livestock Enterprise in Jaipur District, Rajasthan, M Sc. Ag. Thesis, Punjab Agricultural University, Ludhiana, 1966, p. 55

- 2 मिश्रित कृषि में पशुओं से प्राप्त गोबर भूमि की उर्वरता-शक्ति को बनाए रखने में सहायक होता है ।
- 3 मिश्रित कृषि में कृषक एवं परिवार के अन्य सदस्यों को नियमित रूप से वर्ष भर रोजगार उपलब्ध होता है ।
- 4 मिश्रित कृषि के अपनाने से फार्म पर प्रति हेक्टर लाभ विविधीकृत कृषि की अपेक्षा अधिक प्राप्त होता है तथा फसलों की प्रति इकाई उत्पादन लागत भी कम आती है ।
- 5 मिश्रित कृषि में फसलों से प्राप्त उपोत्पाद—भूसा, कड़वी एवं अन्य प्रकार के चारे का पशुओं द्वारा उचित उपयोग हो जाता है ।
- 6 मिश्रित कृषि में कृषकों को वर्ष भर निरन्तर आय प्राप्त होती रहती है ।
- 7 मिश्रित कृषि को अपनाने से उपलब्ध पशु स्रोत प्रोटीन की मात्रा में भी वृद्धि होती है । वर्तमान में पशु-प्रोटीन की खपत भारत में मात्र 6 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, जबकि अमेरिका में 65 ग्राम, आस्ट्रेलिया में 61 ग्राम, न्यूजीलैंड एवं इंग्लैंड में 52 ग्राम है ।⁵ पशु प्रोटीन के कम उपलब्ध होने से भारत के निवासियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव आता है । पशु-प्रोटीन स्रोत—मांस, शू बे, दूध एवं दुग्ध पदार्थ एवं मछली की कीमतेँ निरन्तर बढ़ती जा रही हैं जो एक साधारण व्यक्ति के लिए कय कर पाना सम्भव नहीं है ।
- 8 मिश्रित कृषि के अपनाने से पशुओं से प्राप्त गोबर से गोबर गैस प्लांट लगाया जा सकता है और घरेलू आवश्यकता की विद्युत्-ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है ।

2 उत्पाद की प्रकृति के आधार पर

(अ) खाद्यान्नों की कृषि—वे फार्म, जिन पर मुख्यतया खाद्यान्न वाली फसलें जैसे—गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का आदि उत्पन्न किये जाते हैं, खाद्यान्नों के फार्म कहलाते हैं ।

(ब) सब्जों की कृषि—वे फार्म, जिन पर मुख्यतया सब्जी जैसे—गोभी, टमाटर, बैंगन, मटर, भूचो, शलजम आदि उत्पन्न की जाती हैं, सब्जों के फार्म कहलाते हैं ।

(स) फलों के बाग—वे फार्म, जिन पर आम, पपीता, सेब, अमरुद, सन्तरे आदि के बाग लगाए जाते हैं ।

(द) दूध उत्पादन के फार्म/डरी फार्म—वे फार्म, जिन पर दूध उत्पादन के लिए गाय या भैंस पाली जाती हैं।

(घ) कुक्कुट पालन फार्म—वे फार्म, जिन पर अण्डे उत्पादन के लिए कुक्कुट पाले जाते हैं।

(र) पशुओं की चराई/रैचिंग—इसके अन्तर्गत पशु भूमि पर होने वाली प्राकृतिक वनस्पति को चराई करते हैं। भूमि पर किसी प्रकार की जुताई नहीं की जाती और न ही बीज बोए जाते हैं। स्वतः उत्पन्न वनस्पति को चरने के लिए पशुओं को छोड़ दिया जाता है। उपर्युक्त प्रकार के चरागाहों पर व्यक्ति विशेष का स्वामित्व न होकर सभी ग्राम वालों का सामूहिक स्वामित्व होता है। रैचिंग कृषि अमेरिका, आस्ट्रेलिया, तिब्बत व भारत के रगिस्तानी इलाकों में अधिक प्रचलित है।

3 उत्पादन-साधनों के उपयोग के अनुपात के आधार पर

(प्र) विस्तृत कृषि भूमि प्रधान कृषि—जब फार्म पर कृषि उत्पादन के लिए भूमि-साधन का श्रम व पूँजी की अपेक्षा अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है तो उस फार्म को 'विस्तृत कृषि फार्म' एवं कृषि को 'विस्तृत कृषि' कहते हैं। जनसंख्या के कम घनत्व वाले क्षेत्रों में साधारणतया विस्तृत कृषि अपनाई जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भूमि आसानी से व कम लगान राशि पर उपलब्ध हो जाती है। उत्पादन के अन्य साधन श्रम व पूँजी या तो कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं अथवा उनकी लागत अधिक होती है।

(ब) सघन कृषि/श्रम तथा पूँजी प्रधान कृषि—जब फार्म पर कृषि उत्पादन के लिए श्रम तथा पूँजी उत्पादन साधनों का भूमि की अपेक्षा अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है तो उस कृषि को सघन कृषि कहते हैं। जनसंख्या के अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में सघन कृषि अपनाई जाती है। उत्पादन वृद्धि के लिए उपलब्ध सीमित भूमि के क्षेत्रफल पर श्रम तथा पूँजी की अधिक इकाइयाँ प्रयुक्त की जाती हैं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पश्चात् कृषि क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि करने के लिए सघन-कृषि अपनायी गयी है। सघन-कृषि योजना की सफलता के लिए पँकेज प्रोग्राम सघन कृषि विस्तार क्षेत्र योजना सकार एवं उन्नत किस्म के बीजों का आविष्कार, उर्वरक एवं कीटनाशी दवाइयाँ का अधिक मात्रा में प्रयोग, बिजली की अधिक उपलब्धि एवं उपयोग आदि कार्यक्रम मुख्य हैं।

4 सिंचाई की सुविधा के आधार पर

(अ) सिंचित कृषि—जिन क्षेत्रों में सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएँ होती हैं उन क्षेत्रों में वे फसलें उत्पादित की जाती हैं जिन्हें पानी की अधिक मात्रा में निरन्तर आवश्यकता होती है। ऐसी कृषि को सिंचित कृषि कहते हैं।

(ब) शुष्क कृषि—शुष्क व अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में जहाँ वार्षिक औसत वर्षा 20 इंच या 50 से मी से कम होती है तथा सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं होती है, ऐसे क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को शुष्क कृषि कहते हैं। शुष्क क्षेत्रों में फसलें मुख्यतया वर्षा पर ही निर्भर होती हैं। देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन का 42 प्रतिशत भाग शुष्क क्षेत्रों से प्राप्त होता है।

देश की कुल कृषित भूमि का 60 प्रतिशत भाग असिंचित है एवं कृषित क्षेत्र का 36 प्रतिशत क्षेत्र शुष्क क्षेत्र की श्रेणी में आता है। देश के 128 जिलों में न्यूनतम से मध्यम श्रेणी की वर्षा होती है। राजस्थान का उत्तरी-पश्चिमी भाग, दक्षिणी-पूर्वी पंजाब, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश के कुछ भाग जो शुष्क क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं, उनमें शुष्क कृषि अपनाई जाती है।

शुष्क क्षेत्रों में फसलें उत्पादित करने के लिए भूमि में नमी की मात्रा को बनाए रखने की समस्या प्रमुख होती है। शुष्क क्षेत्रों का नमी संरक्षण विधियों द्वारा अल्पकालीन विकास किया जा सकता है। भूमि में नमी की मात्रा का निम्न उपायों द्वारा संरक्षण किया जा सकता है—

1. शुष्क क्षेत्रों में कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें जैसे—बाजरा, ज्वार (मी एस एच 1 व 2), अरुण्ड (अरुण्ड), अरहर (पूसा अगेती एस 5 व एस 8) आदि जो शुष्कता सहन कर सकें, उगायी चाहिए।
2. शुष्क क्षेत्रों में जीवांस खाद का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिये जिससे भूमि की जलधारण शक्ति में वृद्धि हो सके।
3. शुष्क क्षेत्रों में भूमि की जुताई उचित समय पर की जानी चाहिये, जिससे वर्षा का जल अधिक से अधिक मात्रा में भूमि सोख सके एवं जल बहकर बेकार नहीं जा पाए।
4. भूमि की जुताई व अन्य कार्यों के लिए उचित कृषि यन्त्रों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे भूमि में नमी अधिक संरक्षित रह सके। देशी हल से निरन्तर जुताई करने पर भूमि के अन्दर जो कड़ी परत बन जाती है उसे सबमोडलर या मिट्टी पलटने वाले हल द्वारा दूसरे या तीसरे वर्ष अवश्य तोड़ना चाहिये। ढालू भूमि को बक स्क्रैपर एवं करहा द्वारा समतल करना चाहिए, जिससे पानी बहकर दूसरे खेतों में नहीं जाने पाए।
5. ढालू खेतों की जुताई हैरो चलाकर तथा बुवाई समोच्च रेखा के समानान्तर करना चाहिए।
6. शुष्क क्षेत्रों में पट्टीदार कृषि (Strip Cropping) की जानी चाहिए तथा भू-संरक्षण सहायक फसलें व अवरोधक फसलें एक के बाद दूसरी पट्टियों में उगाई जानी चाहिए।

वर्तमान में 40 प्रतिशत क्षेत्र से कम क्षेत्र में ही सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अतः देश की बढ़ती हुई खाद्यान्न माँग को पूरा करने के लिए शुष्क

क्षेत्रों का विकास करना अति आवश्यक है। शुष्क क्षेत्रों के विकास के बिना देश का खाद्यान्न उत्पादन में पूर्णतः आत्म-निर्भर हो पाना सम्भव नहीं प्रतीत होता है। देश में शुष्क व अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों के विकास के लिए वर्तमान में कई योजनाएँ बनाई गई हैं तथा तकनीकी ज्ञान के प्रसार के आधार पर कृषि की नई विधियाँ भी निकाली गई हैं। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में शुष्क कृषि के विकास के लिए बहुत धन व्यय किया गया है। जून, 1970 में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने शुष्क कृषि के विकास के लिए अखिल भारतीय शुष्क भूमि कृषि समन्वय अनुसन्धान प्रोजेक्ट (All India Co-ordinated Research Project on Dry-land Agriculture) स्थापित किया है, जिसके विभिन्न प्रकार की भूमि एवं जलवायु वाले क्षेत्रों में 23 केन्द्र हैं।

विभिन्न केन्द्रों से प्राप्त अनुसन्धान परिणामों से स्पष्ट है कि शुष्क भूमि वाले क्षेत्रों में ली जाने वाली फसलों की उत्पादकता में फसलों एवं उनकी किस्मों के सही चुनाव, फसलों के उचित प्रतिस्थापन, अन्तःसह्य, उचित समय पर बुवाई एवं निराई-गुड़ाई तथा उचित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करके न्यूनतम 100 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। यह भी स्पष्ट है कि नई फसलों की किस्मों से शुष्क भूमि वाले क्षेत्रों में प्रचलित फसलों की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त हुआ है। शुष्क क्षेत्रों की महत्ता एवं अखिल भारतीय शुष्क भूमि समन्वय अनुसन्धान केन्द्रों के अच्छे परिणामों से प्रभावित होकर भारत सरकार ने शुष्क कृषि का केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान (Central Research Institute for Dry land Agriculture) हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश) में स्थापित किया है। शुष्क भूमि से विभिन्न योजनाओं के काल में हुई फसलों की उत्पादकता वृद्धि को सारणी 8.1 में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 8.1

शुष्क क्षेत्रों में विभिन्न फसलों की औसत उत्पादकता

(किलोग्राम प्रति हेक्टर)

फसल	औसत उत्पादकता			
	आधार वर्ष	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	पंचम पंचवर्षीय योजना	छठी पंचवर्षीय योजना
	(1950-51)	(1969-74)	(1974-79)	(1980-85)
ज्वार	353	488	670	695
बाजरा	288	476	448	483
मक्का	547	1052	1068	1158
दालें	441	491	502	480
तिलहन	481	541	580	603

स्रोत : S S Khanna and M P Gupta, Using Improved Technology for Dry-land Farming, Yojana, Vol 32 (24), January 1-15, 1989, p. 7

5 यान्त्रिक साधनों के उपयोग के आधार पर :

(अ) प्रचलित कृषि—इसके अन्तर्गत फार्म पर कृषि कार्यों को करने के लिए देशी औजार व हल प्रयुक्त किये जाते हैं। देशी हल व औजारों से खेती करने पर लागत अधिक आती है, कार्य करने में समय अधिक लगता है और जुताई भी उचित गहराई तक नहीं हो पाती है। इन कारणों से कृषकों को इस कृषि विधि में लाभ कम प्राप्त होता है।

(ब) यान्त्रिक कृषि—यान्त्रिक कृषि से तात्पर्य उस कृषि के प्रकार से है जिसके अन्तर्गत फार्म पर किये जाने वाले सभी या आंशिक कृषि-कार्य पशु एवं मानव-श्रम के स्थान पर यन्त्रों की सहायता से किये जाने हैं। यान्त्रिक कृषि में श्रम की अपेक्षा पूँजी का अधिक उपयोग होता है। फार्म पर यान्त्रिक कृषि का पूर्णतः व अंशतः होना क्षेत्र में यन्त्रों की उपलब्धि, कृषि में निवेश की जाने वाली पूँजी की राशि, श्रम उपलब्धि एवं मजदूरी की दर, जल का आकार, कृषकों का मशीनों के प्रायोगिक ज्ञान के स्तर, कृषकों का उपलब्ध ऋण सुविधा आदि पर निर्भर करता है। कृषि कार्यों में प्रायोगिक यान्त्रिक शक्ति के आधार पर यन्त्रीकरण दो प्रकार का होता है—

(1) गतिशील यन्त्रीकरण—गतिशील यन्त्रीकरण (Mobile Mechanization) से तात्पर्य उस यन्त्रीकरण से है जिसमें फार्म पर कृषि कार्यों को करने में गतिशील यन्त्रों का उपयोग किया जाता है। इसमें शक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गतिमान होना आवश्यक होता है। जैसे—ट्रैक्टर एवं उसके साथ के यन्त्र—हैरो, कल्टीवेटर, बीज बोने की मशीन, बटाई की मशीन आदि।

(ii) स्थायी यन्त्रीकरण - स्थायी यन्त्रीकरण (Stationary Mechanization) से तात्पर्य उस यन्त्रीकरण से है जिसमें फार्म पर कृषि कार्यों को करने में ऐसे यन्त्रों का उपयोग किया जाता है जो एक स्थान पर स्थिर रहते हुए शक्ति उत्पन्न करते हैं और उस शक्ति से विभिन्न कृषि कार्य सम्पन्न किये जाते हैं, जैसे—बुझों से पानी निकालने के लिए मोटर एवं पम्प, बूट्टी काटने की मशीन, गन्ने पेरने का कोल्हू, गहराई के लिए ग्रैंसर आदि यन्त्रों का उपयोग।

भारत में कृषि यन्त्रीकरण के क्षेत्र में हुई प्रगति

कृषि यन्त्रीकरण के क्षेत्र में हुई प्रगति का आकलन देश में ट्रैक्टर, पावर टिलर, ग्रैंसर एवं सिंचाई के लिए पम्पिंग सेटों के उपयोग आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। कृषि यन्त्रीकरण की प्रगति का सर्वप्रथम चोटक ट्रैक्टरों की संख्या है। भारत में वर्ष 1951 में 8,635 ट्रैक्टर, वर्ष 1961 में 31,016 ट्रैक्टर, वर्ष

1971 में 1,43,000 ट्रैक्टर, वर्ष 1981 में 5,72,973 ट्रैक्टर एवं वर्ष 1991 में 14 68 लाख ट्रैक्टर थे। कृषि यन्त्रीकरण की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए देश में उपलब्ध ट्रैक्टरों की संख्या बहुत कम है। भारत में वर्ष 1984-85 में प्रति एक लाख हैक्टर भूमि क्षेत्र के लिए 450 ट्रैक्टर ही उपलब्ध थे। भारत के विभिन्न राज्यों में ट्रैक्टर उपलब्धि में बहुत विभिन्नता है। सर्वाधिक ट्रैक्टर पंजाब एवं हरियाणा राज्य में हैं।

देश में वर्ष 1960 के पूर्व ट्रैक्टर का उत्पादन नहीं होता था। अतः ट्रैक्टरों की उपलब्धि आयात पर ही निर्भर थी। भारत में ट्रैक्टरों का उत्पादन सर्वप्रथम वर्ष 1961-62 में प्रारम्भ हुआ। उस समय देश में 880 ट्रैक्टरों का उत्पादन प्रति वर्ष किया जाता था। वर्तमान में देश में 15 ट्रैक्टर बनाने की इकाईयाँ कार्यरत हैं, जिनमें प्रतिवर्ष 1 40 लाख ट्रैक्टर का उत्पादन होता है। ट्रैक्टरों का आयात वर्ष 1976-77 तक हुआ है। वर्तमान में देश की ट्रैक्टरों की आवश्यकता देश में उत्पादन किए गए ट्रैक्टरों से ही की जाती है।

कृषि यन्त्रीकरण हेतु पावर टिलर का उपयोग भी वर्ष 1961-62 के बाद निरन्तर बढ़ा है। देश में पावर टिलर का उत्पादन वर्ष 1965-66 में मात्र 329 था, जो बढ़कर 1981-82 में 2352 व 1990-91 में 6228 हो गया। पावर टिलर के उत्पादन में वृद्धि के लिए अनेक कारखाने स्थापित किए गए। वर्ष 1971-72 में सर्वाधिक 1,583 पावर टिलर का आयात देश में किया गया। वर्ष 1974-75 के पश्चात् इनका आयात भी बन्द कर दिया गया। ग्रैंसर का उपयोग भी हरित क्रांति के उपरान्त के 20-25 वर्षों में निरन्तर बढ़ा है। ग्रैंसर के उपयोग से कृषक फसल की समय पर गहवाई करके, मण्डी में खानेवाले का सही समय पर विप्रेषण करके अच्छी कीमत प्राप्त कर पाने में सक्षम हो सके हैं। कम्बाइन्ड हार्वेस्टर का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। वर्ष 1987-88 में इनकी उत्पादन संख्या 149 थी, जो बढ़कर वर्ष 1990-91 में 337 प्रति वर्ष हो गई।

कृषि में सिंचाई की समय पर एवं बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरी करने के लिए डीजल चालित एवं विद्युत् चालित पम्पिंग सेटों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इनके अपनाने से सिंचाई की लागत में कमी हो पाई है, साथ ही कम समय में कृषक अधिक क्षेत्र में सिंचाई कर पाते हैं। वर्ष 1950-51 में मात्र 87 हजार पम्पसेट कार्यरत थे जो बढ़कर वर्ष 1960-61 में 4 28 लाख, 1968-69 में 18 10 लाख, 1979-80 में 61 02 लाख एवं 1990-91 में 133 47 लाख हो गए।

कृषि यन्त्रीकरण के लिए प्रयोगित विभिन्न यन्त्रों की प्रगति को सारणी 8 2 में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 82

कृषि में यन्त्रोपकरण के लिए आवश्यक यन्त्रों की प्रगति

वर्ष	ट्रेंडर		पावर ट्रिलर उत्पादन प्रति वर्ष	पम्प सेट	
	उत्पादन प्रति वर्ष	आयात प्रति वर्ष	कुल संख्या	रीजल चलित (कुल)	विद्युत् चलित (कुल)
1950-51	—	—	—	66,000	21,000
1960-61	—	—	—	230,000	198,000
1961-62	880	2,997	3,877	—	—
1968-69	15,437	12,397	27,834	721,000	1089,000
1979-89	62,756	Nil	62,756	2553,000	3449,000
1986-87	80,369	Nil	80,369	3553,000	6732,000
1990-91	139,826	Nil	139,826	4355,000	8992,000
					कुल पम्पिंग सेट
					87,000
					428,000
					1810,000
					6102,000
					10285,000
					13347,000

यान्त्रिक कृषि से लाभ *

- 1 फार्म पर यान्त्रिक साधनों से कृषि करने पर श्रमिकों की कार्य-कुशलता एक क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे प्रति श्रमिक उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है।
- 2 कृषि में यान्त्रिक साधनों के उपयोग से कृषि कार्य उचित समय पर एवं शीघ्रता से पूरे किये जा सकते हैं, जिससे कृषक अधिक क्षेत्र में कृषि कर सकने में सक्षम होते हैं।
- 3 यन्त्रों की सहायता से बड़े पैमाने पर भूमि को समतल करना, फसल की बुवाई, पौध संरक्षण आदि कार्य कम लागत पर किये जा सकते हैं।
- 4 यन्त्रों की सहायता से कृषि कार्य करने में, मानव एवं बैलों के श्रम की अपेक्षा प्रति इकाई क्षेत्र पर लागत कम आती है एवं प्रति हेक्टर लाभ अधिक प्राप्त होता है।
- 5 गहरी जुताई करने, भू-संरक्षण, भूमि-सुधार गहरे पानी वाले क्षेत्रों से पानी उठाने के कार्य यन्त्रों की सहायता से सरलतापूर्वक किये जा सकते हैं।
- 6 यान्त्रिक कृषि अपनाने से कृषकों की आय में वृद्धि होती है।
- 7 यन्त्रों की सहायता से फार्म पर किये जाने वाले कृषि-कार्यों में समानता आती है।
- 8 श्रमिकों को कम उपलब्धि वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कृषि, यन्त्रों की सहायता से सुगमतापूर्वक की जा सकती है।

यान्त्रिक कृषि से हानियाँ *

- 1 यान्त्रिक कृषि देश में बेरोजगारी की समस्या को बढ़ाने में सहायक होती है। जो भूमि पहले कृषकों को कृषि करने के लिए दी जाती थी, यान्त्रिक कृषि के अपनाने से वह भूमि भू-स्वामियों द्वारा स्वयं कृषि की जाती है।
- 2 यन्त्रों की सहायता से कार्य करने पर श्रमिकों को लगानगर एक ही कार्य करना होता है। जिससे उनके जीवन में नीरसता आ जाती है।
- 3 यान्त्रिक साधनों को जुटाने के लिए अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है, जिसे जुटा पाना अधिकांश कृषकों के लिए सम्भव नहीं होता है।

- 4 कृषकों की जोत छोटी एवं विसंछिन्न होने के कारण, बड़े कृषि यन्त्र वर्ष में बहुत समय तक बेकार पड़े रहते हैं जिससे फार्म पर स्थायी लागत-व्याज, मूल्य-ह्रास आदि अधिक आती है।
- 5 यान्त्रिक साधनों के उपयोग के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान का कृषकों में अभाव होने के कारण, उन्हें छोटी-छोटी कमियों को दूर कराने के लिए मस्तिष्क पर निर्भर रहना होता है, जिससे दूसरों पर निर्भरता बढ़ती है और कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाता है।
6. यान्त्रिक कृषि के अपनाने से समृद्ध कृषक, लघु कृषकों की भूमि अधिक कीमत का मुग़तान करके बिक्री कर लते हैं जिससे भूमिहीन श्रमिकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है।
- 7 गाँवों में वर्कशॉप के अभाव में कृषि यन्त्रों एवं मशीनों को सुधारवाने के लिए शहर में ले जाना होता है जिससे लागत अधिक आती है एवं कृषकों का बहुत समय खराब हो जाता है।

कृषि क्षेत्र में यन्त्रीकरण अपनाने में कठिनाइयाँ

निम्न कठिनाइयों के कारण देश में कृषि क्षेत्र में यन्त्रीकरण का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है—

- 1 जोत का औसत आकार कम होना एवं जोत विसंछिन्न होना—भारत में जोत का औसत आकार कम है। साथ ही जोतें अपसंछिन्न रूप में पायी जाती हैं।
- 2 बेरोजगारी के बढ़ने की सम्भावना—यान्त्रिक साधनों के उपयोग से श्रमिकों में बेरोजगारी के अधिक बढ़ने की सम्भावना के कारण भी कृषि के यन्त्रीकरण के क्षेत्र में प्रगति नहीं हो पा रही है।
- 3 पशुओं के देकार होने की समस्या—यान्त्रिक साधनों के कृषि में उपयोग से वर्तमान में कृषि कार्य में आ रहे पशुओं को काय लिए बिना ही चारा दाना खिलाना होगा। अतः फार्म पर लागत से अनावश्यक वृद्धि होगी।
- 4 कृषकों के पास पूँजी का अभाव—भारत में अधिकांश कृषक गरीब हैं। यान्त्रिक साधनों को खरीदने के लिए उनके पास पर्याप्त धन का अभाव होता है। अतः पूँजी के अभाव में यान्त्रिक कृषि लाभप्रद होत हुए भी कृषक उसे अपनाने में असमर्थ होते हैं।
- 5 आवश्यक तेल/विद्युत का अभाव—यन्त्रों को चलाने के लिए आवश्यक तेल/विद्युत भी समय एवं उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं होते हैं।

कीमत की अधिकता के साथ-साथ उनके समय पर उपलब्ध नहीं होने की अवस्था में यन्त्र-मशीनें बेकार पड़ी रहती हैं।

- 6 कुशल प्रशिक्षित चालकों का अभाव होना।
- 7 ग्रामीण क्षेत्रों में यन्त्रों की मरम्मत के लिए वर्कशॉप का न होना एवं आवश्यक पुर्जों समय पर उपलब्ध न होना।
8. कृषकों के फार्म तक मशीनें एवं तेल पहुँचाने के लिए सड़की एवं आवश्यक परिवहन सुविधाओं का अभाव होना।
- 9 देश में कृषकों की ज़ोत के आकार के अनुसार कम शक्ति वाले एवं छोटे यन्त्रों का उपलब्ध नहीं होना।

उपर्युक्त कठिनाइयों के कारण देश में यान्त्रिक कृषि के विकास की गति बहुत मन्द रही है। यान्त्रिक कृषि की सफलता के लिए उपर्युक्त कठिनाइयों को दूर करना आवश्यक है। यान्त्रिक कृषि के प्रोत्साहन के लिए सरकार ने निम्न कदम उठाये हैं—

- 1 सरकार ने कृषकों को कृषि में काम आने वाले यन्त्रों के उपयोग का प्रशिक्षण देने के लिए मध्यप्रदेश राज्य के बुंदेली एवं हरियाणा राज्य के हिसार जिलों में ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं। इन केन्द्रों पर 500 कृषकों को प्रति वर्ष प्रशिक्षण देने की सुविधा उपलब्ध है।
- 2 गाँव के कारीगरों को यन्त्रों के सुधार की प्रशिक्षण-सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने ग्राम-सेवक प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ साथ वर्कशॉप भी खोले हैं जहाँ पर कारीगरों को प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है।
- 3 सरकार ने विभिन्न राज्यों में कृषि-औद्योगिक निगमों (Agro-Industries Corporations) की स्थापना की है। ये निगम आमतौर पर ट्रैक्टर, पावर टिलर, पम्पसेट और अन्य कृषि यन्त्रों को मकदमूल्यों या किशतों पर कृषकों को देने की व्यवस्था करते हैं। कृषि-औद्योगिक निगमों ने कृषि यन्त्रों की मरम्मत के लिए वर्कशॉप भी चालू किये हैं जहाँ उचित मूल्य पर मशीनों की मरम्मत की जाती है तथा निर्धारित मूल्य पर पुर्जे उपलब्ध कराये जाते हैं।

6 मूल्य के क्षेत्रफल के आधार पर

(अ) छोटे पैमाने पर कृषि—इसमें फार्म का आकार कम होता है, जिससे कृषि कार्यों के करने में यान्त्रिक साधनों का उपयोग करना सम्भव नहीं होता है।

(ब) बड़े पैमाने पर कृषि—इसमें फार्म का आकार अधिक होता है। फार्म पर कृषि कार्यों को करने के लिए ट्रैक्टर एवं अन्य बड़े फार्म यन्त्र काम में लिए जाते हैं।

7. व्यावसायिक उद्यमों के आधार पर :

(अ) पारिवारिक कृषि—वे फार्म जो परिवार के सदस्यों की सहायता से कृषि किए जाते हैं तथा उनसे प्राप्त आय परिवार के जीवनयापन के लिए पर्याप्त होती है।

(ब) व्यापारिक कृषि—वे फार्म जो पूँजीपतियों एवं अन्य समृद्ध शील व्यक्तियों द्वारा कृषि किए जाते हैं। इन पर कृषि की उन्नत विधियाँ तथा कृषि-यन्त्र उपयोग में लिए जाते हैं। इन फार्मों का मुख्य उद्देश्य कृषि को व्यवसाय मानते हुए अधिक धन कमाना होता है।

(स) अश-कालीन कृषि—वे फार्म जो समृद्ध व्यक्तियों द्वारा अपने अन्य कार्यों के साथ-साथ कृषि कराये जाते हैं। फार्म का स्वामी आय के लिए इन फार्मों पर पूर्णतया निर्भर नहीं होते हैं। उन्हें आय अपने अन्य व्यवसाय या नौकरी से भी साथ-साथ होती रहती है।

8. श्रम उपलब्ध के आधार पर :

(अ) पारिवारिक सदस्यों के श्रम द्वारा कृषि—वे फार्म जो परिवार के सदस्यों द्वारा उपलब्ध श्रम द्वारा कृषि कराए जाते हैं। इन फार्मों पर बुवाई एवं कटाई मौसम में विशेष आवश्यकता के होने पर श्रमिक भी लगाए जाते हैं।

(ब) श्रमिकों के श्रम द्वारा कृषि—वे फार्म जो पूर्णतया श्रमिकों के श्रम द्वारा ही कृषि किए जाते हैं, जैसे—सरकारी फार्म, व्यापारिक फार्म। इन फार्मों पर कृषि कार्यों के करने के लिए स्थायी एवं अस्थायी श्रमिक लगाए जाते हैं, जिन्हें निर्धारित दर से मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

कृषि-प्रणालियाँ

1. फार्म संचालक एवं प्रबन्ध के आधार पर :

(अ) व्यक्तिगत कृषि—व्यक्तिगत कृषि से तात्पर्य कृषि की उस प्रणाली से है जिसमें कृषक को फार्म पर कृषि-कार्य करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। कृषक स्वयं भूमि का स्वामी, प्रबन्धक व श्रमिक होता है। कृषक अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से फार्म पर सभी कृषक कार्य सम्पन्न करता है। फसल की बुवाई व कटाई के समय आवश्यकता होने पर फार्म पर दैनिक मजदूरी पर श्रमिक लगाते हैं। व्यक्तिगत कृषि में सरकार का कृषक से सीधा सम्पर्क होता है। कृषक

भूमि का लगान सरकार को स्वयं जमा कराते हैं। भारत में अधिकांश कृषक व्यक्तिगत कृषि करते हैं। व्यक्तिगत कृषि करने वाले कृषकों के पास विभिन्न आकार में जोत एवं उत्पादन-साधन होते हैं। व्यक्तिगत फार्मों पर उत्पादन एवं तकनीकी ज्ञान के उपयोग स्तर में अन्तर पाया जाता है। बड़े कृषक पूँजी की बहुलता के कारण तकनीकी ज्ञान का अधिक उपयोग करते हैं।

(ब) पूँजी प्रधान कृषि—पूँजी-प्रधान कृषि पूँजीवाद पर आधारित होती है जिसमें भूमि का स्वामित्व एवं उत्पादन के अन्य साधनों पर पूँजीपतियों का स्वामित्व होता है। पूँजी-प्रधान कृषि अधिकतर अमेरिका व इंग्लैण्ड आदि देशों में पाई जाती है। भारतवर्ष में चीनी मिट्टी मालिकों के गन्ने के खेत, रबर, काफी, चाय, फल आदि के बागों के रूप में पूँजी-प्रधान फार्म पाये जाते हैं। ऐसे फार्मों पर कृषि की उन्नत विधियाँ, उन्नत बीज, उन्नत तरीके अपनाये जाते हैं। पूँजीवादी कृषि में पूँजी का निवेश अन्य उत्पादन साधनों की अपेक्षा अधिक मात्रा में होता है। पूँजी-प्रधान कृषि के अन्तर्गत श्रमिकों को कार्य के फलस्वरूप मजदूरी का मुगलान किया जाता है। पूँजीवादी फार्मों पर भूमि व पूँजी, पूँजीपति की होती है लेकिन श्रम व प्रबन्ध श्रमिकों का होता है। पूँजीवादी कृषि में उत्पादन वृद्धि के सभी नये तरीके अपनाये जाते हैं जिसके कारण भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र से उत्पादन अन्य फार्मों की अपेक्षा अधिक होता है। पूँजीवादी कृषि का मुख्य दोष श्रमिकों का शोषण होता है।

(स) राजकीय कृषि—राजकीय कृषि में भूमि एवं उत्पादन-साधनों का प्रबन्ध सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। राजकीय फार्मों की भूमि एवं पूँजी पर सरकार का स्वामित्व होता है। श्रम के लिए फार्म पर स्थायी एवं अस्थायी श्रमिक नियुक्त किये जाते हैं। फार्म का प्रबन्ध एवं योजनाएँ बनाने का कार्य फार्म प्रबन्धक करता है। कार्य सम्बन्धी निर्णय फार्म प्रबन्धक विभिन्न विशेषज्ञों की सहायता से लेता है। राजकीय फार्म निम्न प्रकार के होते हैं—

- (1) बीजवर्धन फार्म,
- (2) पशुपालन फार्म,
- (3) व्यापारिक फार्म,
- (4) अनुसन्धान फार्म,
- (5) प्रदर्शन फार्म।

राजकीय फार्मों की जोत का आकार साधारणतया अधिक होता है। राजकीय फार्मों पर कृषि उत्पादन की सभी नई विधियों एवं तकनीकी ज्ञान, उन्नत यन्त्र आदि का उपयोग उत्पादन वृद्धि के लिए किया जाता है। राजकीय फार्मों पर कार्य करने वाले श्रमिकों की फार्म प्रबन्ध में रम नहीं ली जाती है, जिससे श्रमिकों में कार्य में विशेष रुचि नहीं लेते हैं।

(ब) सहकारी कृषि—सहकारी कृषि कृषकों की पारस्परिक सहायता के सिद्धान्त पर आधारित है। कृषक अपने सहयोगियों की सहायता से फार्म पर उत्पादन में वृद्धि करते हैं। कृषि के वर्तमान टांचे में दग के लघु एवं सीमान्त कृषक उत्पादन-साधनों की सीमितता के कारण बड़े कृषकों के समान लाभ नहीं उठा पाते हैं। सहकारी कृषि द्वारा लघु कृषक भी धनी एवं दही जोत दले कृषकों के समान लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अतः सहकारी कृषि का मुख्य उद्देश्य लघु कृषकों को बड़े कृषकों के समान लाभ की राशि प्राप्त कराना है।

सहकारी कृषि से तात्पर्य कृषि की उस प्रणाली से है जिसमें कृषकों द्वारा स्वेच्छापूर्वक फार्म पर सभी या कुछ कृषि-क्रियाएँ सदुक्त रूप में की जाती हैं। कृषक-उत्पन्न-उत्पादन-साधनों—भूमि, श्रम, पूँजी, मशीन आदि का प्रयोग सामूहिक रूप में करते हैं किन्तु साधनों पर स्वामित्व कृषकों का पृथक् रूप में होता है। सहकारी कृषि प्रणाली में विभिन्न कृषकों की भूमि को एक इकाई मानकर सदुक्त रूप से खेती की जाती है। प्राप्त लाभ को कृषकों में भूमि एवं अन्य उत्पादन-साधनों की मात्रा के अनुपात में वितरित कर दिया जाता है।

सहकारी कृषि के विभिन्न रूप—सहकारी नियोजन समिति ने वर्ष 1946 में सर्वप्रथम सहकारी समितियों को चार वर्गों में विभाजित किया था

- (1) सहकारी उन्नत कृषि।
- (2) सहकारी समुक्त कृषि।
- (3) सहकारी कारखाने कृषि।
- (4) सहकारी सामूहिक कृषि।

सहकारी कृषि के कार्यकारी दल के प्रतिवेदन (Report of the Working Group on Co-operative Farming 1959) में दिए गए मुद्दों के अनुसार सहकारी कृषि समितियों को 1960 में दो श्रेणियों में ही वर्गीकृत किया गया था—

- (1) सहकारी उन्नत कृषि,
- (2) सहकारी सामूहिक कृषि।

1959 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने नागपुर में हुए अपने 64 वें अधिवेशन में सहकारी समितियों के लिए प्रस्तावित किया कि भविष्य में कृषि की विधि समुक्त कृषि होनी चाहिये, जिसमें कृषकों की भूमि एवं श्रम की जाए, कृषकों की अपनी भूमि पर स्वामित्व अधिकार प्राप्त हो, श्रमिकों एवं कृषकों को फार्म पर किए गए श्रम की मात्रा के अनुसार मजदूरी का मुकतान किया जाए तथा प्राप्त क्षेत्र लाभ सदस्यों में भूमि के अनुपात के अनुसार वितरित किया जाए। विभिन्न प्रकार की सहकारी कृषि का संक्षिप्त विवेचन निम्न है—

1 सहकारी उन्नत कृषि—सहकारी उन्नत कृषि में भूस्वामित्व एवं कृषि का प्रबन्ध वैयक्तिक होता है। इस विधि में कृषकों की भूमि को सम्मिलित रूप में

कृषित नहीं किया जाता है। प्रत्येक कृषक को अपनी भूमि के क्षेत्र पर स्वतन्त्र रूप से कृषि करने का अधिकार होता है। सहकारी समिति कृषको को समयानुसार उचित व उन्नत विधियों को अपनाने का परामर्श देती है तथा उनके लिए उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक, उन्नत कृषि यन्त्र, कीटनाशी दवाइयों को उपलब्ध कराने तथा बड़ी मशीनों जैसे ट्रैक्टर आदि का संयुक्त उपयोग करने हेतु प्रबन्ध करती है। सहकारी समिति कृषको के उत्पाद की उचित कीमत कर सामूहिक रूप से सहकारी-विपणन-समिति या अन्य संस्थाओं के माध्यम से विनय करवाने का प्रबन्ध भी करती है। प्रत्येक कृषक को सहकारी समिति से प्राप्त सेवाओं के अनुसार लागत राशि का भुगतान करना होता है। समिति प्राप्त धन्य में से लागत व्यय निकालने के बाद शेष लाभ को सदस्यों में उनके द्वारा ली गई सेवाओं के अनुसार वितरित कर देती है। सहकारी उन्नत कृषि समितियों के गठन में सदस्य कृषको को किसी प्रकार का विरोध नहीं होता है।

2. सहकारी संयुक्त कृषि - सहकारी संयुक्त कृषि में भूस्वामित्व वैयक्तिक तथा कृषि का प्रबन्ध संयुक्त होता है। सहकारी संयुक्त कृषि में सभी कृषको की भूमि को एक इकाई के रूप में तथा उनके पशु, औजार आदि उत्पादन साधनों को सम्मिलित करके लेती की जाती है। इस विधि में प्रत्येक कृषक का अपनी-अपनी भूमि पर स्वामित्व होता है। समिति का प्रत्येक सदस्य कार्यकारिणी समिति की देखरेख में कार्य करता है और किये गये कार्य के लिए मजदूरी प्राप्त करता है। उत्पादित उत्पाद को संयुक्त रूप से विनय किया जाता है। समिति को प्राप्त शुद्ध लाभों की राशि में से प्रत्येक कृषक को भूमि के क्षेत्र के अनुपात में लाभों वितरित किया जाता है। प्रत्येक सदस्य को स्वेच्छा से समिति छोड़ने का अधिकार होता है। समिति छोड़ने पर सदस्यों को उनकी भूमि वापिस लौटा दी जाती है, लेकिन उपर्युक्त समय में कृषक की भूमि पर यदि कोई सुधार कार्य किया गया है तो कृषक को उसकी लागत देनी होती है।

कृषको में अज्ञानता, अज्ञानता, रुढ़िवादिता, भूमि का स्वामित्व छिन जाने की-आशंका व भूमि के प्रति लगाव होने के कारण सहकारी संयुक्त कृषि का विकास द्रुत गति से नहीं हुआ है। संयुक्त कृषि प्रणाली के अन्तर्गत कृषको को कृषि कार्य एवं प्रबन्ध के विषय में निर्णय लेने की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नहीं होती है जिसके फल-स्वरूप कृषक कार्य के प्रति उदासीन रहते हैं।

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषको की जोन का आकार कम एवं जोतो के विखंडित होने की अवस्था में सहकारी संयुक्त कृषि लाभप्रद है। सहकारी संयुक्त कृषि में कृषको की भूमि के प्रति भावनात्मक आसक्ति (Sent mental attachment to land) बनी रहती है। सहकारी संयुक्त कृषि में स्वामित्व इकाइयाँ छोटी होते हुए भी प्रबन्धित इकाई बड़ी हो जाती है। प्रबन्ध की इकाई के आकार में वृद्धि

होने से बड़े यन्त्रों एवं मशीनों का उपयोग सरलता में हो सकता है तथा प्रति इकाई क्षेत्र पर उत्पादन लागत कम आती है।

3 सहकारी वास्तवकारी कृषि—सहकारी वास्तवकारी कृषि में भूमि पर स्वामित्व समिति का होता है। समिति भूमि को छोट-छोटे खेतों में विभक्त करके सदस्यों में कृषि करने के लिए वितरित कर देती है। प्रत्येक सदस्य को जोती गई भूमि का लगान, समिति को देना होता है। समिति कृषकों के लिए उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशी दवाइयाँ, उन्नत यन्त्र आदि का प्रबन्ध करती है। समिति कृषकों के फार्म की फार्म-याजना बनाने में भी सहायता करती है। कृषकों को निमित्त फार्म-योजना का पालन करने एवं फार्म से प्राप्त उत्पाद का इच्छानुसार विनियम करने की स्वतन्त्रता होती है। प्राप्त शुद्ध लाभ को समिति के सदस्यों में उनके द्वारा दिये गये भूमि के लगान की राशि के अनुसार वितरित किया जाता है। सहकारी वास्तवकारी समितियाँ साधारणतया उन क्षेत्रों में गठित की गई हैं जहाँ बंजर भूमि का मुआवजा करके, तराई क्षेत्रों का विकास करके एवं नहरों के पास वास्तवकारों को विस्थापित करके नई भूमि को कृषि-योग्य बनाया गया है।

4 सरकारी सामूहिक कृषि—सहकारी सामूहिक कृषि में भूमि पर स्वामित्व एवं कृषि का प्रबन्ध समिति का होता है। समिति यह भूमि नये करके अथवा नियत अवधि के पट्टे पर सरकार से प्राप्त करती है। सहकारी सामूहिक कृषि में कार्य-विधि सहकारी संयुक्त कृषि के समान ही होती है, लेकिन भूमि पर स्वामित्व व्यक्तिगत न होकर समिति का सामूहिक होता है। समिति का प्राप्त लाभ की राशि में से एक हिस्सा सुरक्षित काय में जमा रखने के पश्चात् सदस्यों में बाँट दिया एवं निवेश की गई पूँजी की राशि के अनुपात में शेष लाभ का वितरित किया जाता है। सदस्यों को समिति छोड़ने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। सहकारी सामूहिक समितियाँ बनाने का उद्देश्य बड़े पैमाने पर की जान वाली कृषि के समान लघु कृषकों का लाभ प्राप्त कराना होता है।

सहकारी कृषि की दिशा में प्रयत्न—सर्वप्रथम वर्ष 1944 में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की सलाहकार समिति ने कृषि उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं का सहकारीकरण करने का सुझाव दिया था। इसी वर्ष बम्बई-अभिलेखन में भी सहकारी कृषि पर चर्चा की गई। सहकारी नियोजन समिति ने 1946 में सहकारी कृषि की चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया। इसी वर्ष फिलिप्पीन में सहकारी कृषि के अध्ययन के लिए भेजे गए प्रतिनिधि मण्डल ने भी भारत में सहकारी कृषि उपनाने का सुझाव दिया था। वर्ष 1947 में राज्यों के राजस्व मन्त्रियों के सम्मेलन में भी गई सफा-रिशों के अनुसार लघु जोत वाले कृषकों को मिलाकर सहकारी आधार पर कृषि करने का सुझाव दिया गया। कांग्रेस कृषि सुधार समिति ने 1949 में बहुउद्देशीय

सहकारी समितियाँ गठित करने तथा सहकारी कृषि की दिशा में प्रयास करने के लिए सुझाव दिए।

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में संयुक्त ग्राम प्रबन्ध एवं सहकारी कृषि पद्धति को स्वीकार किया गया तथा सहकारी कृषि समितियों के लिए आवश्यक नियम बनाए गए। प्रथम भारतीय सहकारी कांग्रेस ने फरवरी 1952 में, बम्बई अधिवेशन में, देश में सहकारी कृषि समितियाँ निर्माण करने का प्रस्ताव पारित किया। कृषि एवं सहकारिता मन्त्रियों ने 1952 में इसकी पुष्टि की। योजना आयोग ने भी देश में सहकारी कृषि के विचार के लिए सहमति प्रकट की। फोर्ड संस्थान दल ने सहकारी संयुक्त कृषि अपनाने के लिए सेवा समितियाँ गठित करने का सुझाव दिया।

सितम्बर 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में देश में 30,000 सहकारी कृषि समितियाँ गठित की जानी चाहिए। देश में सहकारी कृषि कार्यक्रमों को बनाने एवं कार्यान्वित करने के लिए सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय ने "राष्ट्रीय सहकारी कृषि परामर्श मण्डल" की स्थापना की। चीन देश में भेजे गए पाटिल एवं कृष्णाप्पा दल ने भी सहकारी कृषि अपनाने के सुझाव दिए। वर्ष 1959 में भारतीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भारतीय कृषि के लिए सहकारी संयुक्त कृषि अपनाने पर जोर दिया गया।

सहकारी कृषि के विपक्ष में तर्क

- 1 लघु कृषकों के फार्म पर बड़े कृषकों के फार्म की अपेक्षा भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादन अधिक होता है। अतः ऐसी धारणा है कि सहकारी कृषि अपनाने से उत्पादन कम हो जाएगा।
- 2 भारतीय कृषक व्यवसाय में व्यक्तिवादी होते हैं, अतः जब वे सामूहिक रूप से कार्य करते हैं तो कार्य के प्रति उदासीन हो जाते हैं।
- 3 सहकारी फार्मों पर बड़ी मशीनों एवं उन्नत औजारों के उपयोग से देश में बेरोजगारी की समस्या को बढ़ावा मिलेगा।
- 4 सहकारी कृषि में कृषकों की प्रबन्ध एवं उद्यमों के चुनाव की वैयक्तिक स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है।
- 5 कृषकों को भूमि का स्वामित्व छिन जाने की आशंका बनी रहती है।

सहकारी कृषि के विकास के लिए सुझाव

- 1 कृषकों में सहकारिता की भावना जागृत करने के लिये सर्वप्रथम उन्हें सहकारी उन्नत कृषि अपनाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, जिससे उनमें व्याप्त भूमि के स्वामित्व के छिन जाने की आशंका समाप्त हो सके।

- 2 सहकारी कृषि से प्राप्त होने वाले लाभों से कृषकों को अवगत कराने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी प्रदर्शन फार्म स्थापित किये जाने चाहिये ।
- 3 सहकारी कृषि के विकास के लिए देश में सहकार शिक्षा का विस्तार करना चाहिये ।
- 4, कृषकों में भूमि के प्रति लगाव की भावना के व्याप्त होने के कारण सर्व-प्रथम नई भूमि पर ही सहकारी कृषि की जानी चाहिए । धीरे-धीरे उनकी भूमि को सहकारी कृषि में लेना चाहिए ।

(घ) सामूहिक कृषि सामूहिक कृषि से सात्पर्य कृषि की उस प्रणाली से है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर समिति का नियन्त्रण होता है । सामूहिक कृषि की सदस्यता स्वीकार करने पर कृषकों के पास उपलब्ध उत्पादन के सभी साधन—भूमि, पशु, यन्त्र, पूँजी आदि समिति को देने होते हैं । समिति उत्पादन-साधनों को सामूहिक रूप से कृषि में उपयोग करती है । सदस्य निर्वाचित समिति के आदेशानुसार फार्म पर मिलजुल कर कार्य करते हैं । फार्म पर विभिन्न कृषि-कार्यों को करने, कृषि उत्पादों का विपणन, सामाजिक वितरण आदि के नियंत्रण लेने का अधिकार निर्वाचित समिति को होता है । सामूहिक फार्म पर सुचारु रूप से कार्य संचालन करने के लिए सदस्यों को ब्रिगेड्स में विभाजित कर देते हैं । प्रत्येक ब्रिगेड का एक मुखिया होता है जो ब्रिगेड के कार्य की देख-रेख व प्रबन्ध करता है । फार्म पर कार्य करने वाले प्रत्येक सदस्य को उनके द्वारा किये गये कार्य के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है । सामूहिक फार्मों के सदस्य निम्न दो प्रकार से आय प्राप्त करते हैं—

1. सामूहिक फार्म पर उत्पादित उपज के विक्रय से प्राप्त शुद्ध लाभ में उत्पादन-साधनों की मात्रा के अनुसार हिस्सा प्राप्त करके ।
2. व्यक्तिगत सम्पत्ति से—सामूहिक फार्म पर कृषकों को दुधारू पशु एवं सब्जी व फलों के उत्पादन के लिए कुछ भूमि रखने का प्रबंधन होता है । अतः उनसे प्राप्त आय पर कृषक का व्यक्तिगत अधिकार होता है ।

सामूहिक फार्म मुख्यतया रूस, चीन, इजरायल तथा पूर्वी यूरोप के कुछ साम्यवादी देशों में अधिक प्रचलित हैं । विभिन्न देशों में प्रचलित सामूहिक फार्मों का संक्षिप्त विवरण निम्न है—

कम्यून (Communes)—कम्यून सामूहिक फार्म चीन में पाये जाते हैं । चीन में प्रथम कम्यून अप्रैल 1958 में स्थापित किया गया था, जिसका नाम स्पुतनिक (Sputnik) रखा गया । कम्यून सामूहिक फार्मों के अन्तर्गत सदस्यों की भूमि एवं उत्पादन के अन्य साधनों को एक इकाई के रूप में एकत्रित करके उनका सामूहिक

रूप से उपयोग किया जाता है। कम्यूनस फार्म के सदस्यों की व्यक्तिगत कोई सम्पत्ति नहीं होती है। इनके सदस्यों एवं उनके परिवार के लोगों को भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक वस्तुएँ कम्यूनस द्वारा ही प्राप्त होती हैं। कम्यूनस सामूहिक फार्म की निर्वाचन प्रबन्धकारिणी समिति, सदस्यों के परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं आवास का प्रबन्ध करती है। कम्यूनस फार्मों पर सदस्यों का व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नहीं होती है।

कोलखोज (Kolkhoz)—कोलखोज सामूहिक फार्म इस में पाये जाते हैं। कोलखोज सामूहिक फार्मों के अन्तर्गत कृषक सदस्यों की भूमि कृषि यंत्र एवं उत्पादन के अन्य साधनों पर सदस्यों का स्वामित्व होता है, लेकिन प्रबंध का कार्य एक समिति करती है। सदस्यों को फार्म पर कार्य करने एवं संचालन के वैयक्तिक अधिकार नहीं होते हैं। कोलखोज फार्म के सदस्य पृथक् रूप में अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं। सदस्यों को घरेलू आवश्यकता हेतु दूध उत्पादन के लिए एक या दो पशु अण्डों के लिये कुछ पालन एवं फलों के लिये बगीचा लगाने की स्वतन्त्रता होती है। कोलखोज फार्म पर उत्पादित उपज का एक भाग सरकार को देना होता है और शेष उत्पाद को सदस्यों में उनके द्वारा दिये गये उत्पाद साधनों की मात्रा के अनुसार वितरित किया जाता है। सदस्यों को फार्म पर किये गये कार्य के लिए सजदूरी का भुगतान किया जाता है।

किब्बुत (Kibbutz)—इजरायल में पाये जाने वाले सामूहिक फार्म किब्बुत कहलाते हैं। किब्बुत फार्म पर सभी कृषि कार्य सामूहिक रूप से सदस्यों द्वारा किये जाते हैं। सदस्यों को रहने के लिये मकान दिये जाते हैं और उन्हें भोजन सामूहिक फार्म पर चलाये गये भोजनालय में प्राप्त होता है। बच्चों की शिक्षा एवं पालन पोषण का कार्य सामूहिक फार्मों के द्वारा चलाये गये स्कूल, नर्सरी एवं शयन-शालाओं में किया जाता है। सदस्यों को अन्य आवश्यक सभी वस्तुएँ किब्बुत फार्म के स्टोर से प्राप्त होती हैं। सदस्यों को व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने की छूट नहीं होती है। प्रत्येक सदस्य को किब्बुत सामूहिक फार्म छोड़ने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है लेकिन सदस्यता छोड़ते समय उन्हें किसी प्रकार की सम्पत्ति नहीं दी जाती है।

भारत में प्रजातान्त्रिक प्रणाली के कारण सामूहिक फार्म पद्धति उचित नहीं है। सामूहिक फार्म साम्यवादी देशों में ही प्रचलित हैं।

(२) निगमित कृषि—निगमित कृषि के अन्तर्गत वे फार्म आते हैं जिनका स्वामित्व वैयक्तिक अथवा सरकारी नहीं होकर शेयर जेताओं का होता है। ऐसे निगम अर्द्ध-सरकारी रूप के होते हैं। निगमित कृषि वाणिज्यिक कृषि की विधि पर आधारित होती है। फार्म पर आवश्यक पूँजी की पूर्ति शेयर जेता करते हैं। निगमित फार्मों का प्रबन्ध वेतन भोगी कर्मचारी करते हैं। निगमित फार्मों पर पूँजी की बहुलता

के कारण कृषि की उन्नत विधियाँ, उन्नत औजार आदि का उपयोग किया जाता है, जिससे उत्पादन अधिक प्राप्त होता है। निगमित फार्मों से प्राप्त लाभ का मुख्य अंश शेयर-क्रेताओं में शेयर सख्या के अनुपात में वितरित किया जाता है।

2 मू-धृति के आधार पर .

(अ) पैतृक मू-धारण कृषि—पैतृक मू-धारण कृषि के अन्तर्गत भूमि का स्वामित्व काश्तकार को पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्राप्त होता रहता है। कृषक की मृत्यु के उपरान्त भूमि का स्वामित्व उसके उत्तराधिकारियों को स्वतः ही स्थानान्तरित हो जाता है।

(ब) काश्तकार कृषि—कृषि की इस प्रणाली के अन्तर्गत काश्तकार, जमींदार (मू स्वामी) से कृषि करने के लिये भूमि प्राप्त करता है। अधिकांश जमींदार स्वयं भूमि को कृषित नहीं करके, भासामियों को कृषि करने के लिए बटाई पर दे देते हैं। भासामी कृषक भूमि पर खेती करता है और प्राप्त भूमि के लिए जमींदार को लगान नकद या उत्पाद के रूप में भुगतान करता है। काश्तकारी भूमि में साझे की कृषि या बटाई (Share cropping) की प्रणाली भी प्रचलित है। बटाई विधि में जमींदार काश्तकार को बीज, खाद उर्वरक आदि की लागत में से एक हिस्से का भुगतान करता है। ऐसी स्थिति में जमींदार काश्तकार से लगान के अतिरिक्त उपज में से निर्धारित हिस्सा भी प्राप्त करता है।

(ग) ऐच्छिक मू धारण कृषि—ऐच्छिक मू-धारण कृषि के अन्तर्गत काश्तकार की भूमि पर कृषि करने की अवधि जमींदार की इच्छा पर निर्भर होती है। जमींदार अपनी इच्छा से काश्तकार को कभी भी भूमि से बेदखल कर सकता है। इस विधि में कृषि करने के समय की अनिश्चितता के कारण, कृषक भूमि के ऊपर स्थायी सुधार करने के इच्छुक नहीं होते हैं, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होती जाती है।

(द) पट्टे पर प्राप्त भूमि पर कृषि—कृषि की इस विधि में जमींदार काश्तकार को एक निर्धारित समयावधि के लिए भूमि कृषि करने के लिए देता है। भूमि को कृषित करने की यह अवधि जमींदार एवं काश्तकार के मध्य में पहले ही निश्चित हो जाती है। समय की अवधि पूर्व नियत हो जाने से कृषक भूमि पर स्थायी सुधार करने अथवा भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करने की कोशिश करते हैं। पट्टे पर प्राप्त भूमि पर कृषि (Lease farming) के लिए भूमि का लगान एक वर्ष/मौसम या पट्टे की पूर्ण अवधि के लिए नियत कर दिया जाता है।

अध्याय 9

कृषि-वित्त

प्रत्येक व्यवसाय को सुचारु रूप से चलाने के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है। कृषि भी एक व्यवसाय है, जिसमें पूँजी की आवश्यकता अन्य उद्योगों की अपेक्षा अधिक होती है। कृषि-व्यवसाय में स्थायी लागत के लिए पूँजी अधिक राशि में निवेश करनी होती है। कृषि में तकनीकी ज्ञान के प्रसार, उन्नत किस्म के बीजों के आबिष्कार, उर्वरक एवं कीटनाशी दवाइयों का कृषि में अधिक उपयोग, कृषि में यन्त्रीकरण, सिंचाई के लिए विद्युत का उपयोग आदि के कारण कृषि में पूँजी की आवश्यकता पहले की अपेक्षा कई गुना अधिक हो गई है। फसलों की उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण फार्म पर पूँजी की आवश्यक राशि में भी वृद्धि हुई है। कृषि-व्यवसाय में बचत की राशि कम होने के कारण कृषकों के पास उपलब्ध पूँजी आवश्यकता से बहुत कम होती है, जिसे वे दूसरों से ऋण लेकर पूरा करते हैं।

कृषि वित्त के दो दृष्टिकोण हैं—प्रथम, पूँजी अधिग्रहण (Acquisition of capital) एवं द्वितीय, प्राप्त पूँजी का कृषि में उचित उपयोग। प्रथम दृष्टिकोण में उन सभी समस्याओं के अध्ययन का समावेश होता है जो कृषकों को धन की पूर्ति के लिए ऋण प्रदान करती हैं। द्वितीय दृष्टिकोण में कृषकों के स्वयं के धन एवं प्राप्त ऋण का कृषि-व्यवसाय में उचित लाभ की प्राप्ति के लिए उपयोग का अध्ययन किया जाता है।

वर्तमान में कृषकों को फार्म से प्राप्त बचत के कम होने तथा कृषि में तकनीकी ज्ञान के विकास के कारण स्वयं का उपलब्ध धन कृषि-व्यवसाय के लिए पर्याप्त नहीं होता है। अतः आवश्यक पूँजी की राशि कृषक दूसरों से ऋण लेकर प्राप्त करते हैं। जो धन दूसरों से प्राप्त किया जाता है उसे ऋण कहते हैं। ऋण शब्द का उद्गम लैटिन शब्द क्रेडो (Credo) से हुआ है जिसका अर्थ विश्वास से है। ऋण-स्वीकृति प्रक्रिया में ऋणदाता का ऋणी में विश्वास होता है कि वह प्राप्त ऋण को भविष्य में निश्चित समय पर व्याज सहित भुगतान कर देगा। इसी आधार पर ऋणदात्री समस्याओं द्वारा कृषकों को ऋण स्वीकृत किया जाता है।

कृषि-ऋण से तात्पर्य निवेश किये जाने वाले धन की उस राशि से है जो फार्म विकास एवं उत्पादकता वृद्धि में सहायक होता है।¹ कृषि ऋण में उत्पादकता वृद्धि के लिए प्राप्त किया गया ऋण एवं उपभोग ऋण जो कृषकों की दक्षता में वृद्धि करने में सहायक होता है, शामिल होते हैं।

कृषकों के लिए ऋण की आवश्यकता :

कृषक मुख्य रूप से निम्न दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न सस्थाओं से ऋण प्राप्त करते हैं—

(1) कृषि व्यवसाय के लिए—कृषकों द्वारा ऋण प्राप्त का प्रथम उद्देश्य कृषि व्यवसाय को सुचारु रूप से चलाने के लिए आवश्यक धन की पूर्ति करना होता है। कृषकों द्वारा भूमि क्रय करने, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए तकनीकी विधियों को फार्म पर अपनाने, नए कुएँ का निर्माण तथा पुराने कुएँ की मरम्मत कराने, सिंचाई के लिए पम्प लगाने, भूमि समतल करने, उन्नत कृषि यन्त्र एवं मशीनों का क्रय करने, बीज, उर्वरक, कीटनाशी दवाइयाँ क्रय करने, आदि कार्यों के लिए ऋण प्राप्त किया जाता है। यह ऋण उत्पादन-ऋण कहलाता है क्योंकि इस ऋण-राशि के उपयोग करने से फार्म पर उत्पादन में वृद्धि होती है और प्राप्त ऋण का व्याज सहित भुगतान करना सरल होता है।

(2) घरेलू उपभोग के लिए—कृषकों द्वारा ऋण प्राप्त करने का दूसरा उद्देश्य घरेलू आवश्यकताओं, जैसे—खाद्यान्न, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के क्रय, भवन निर्माण, विवाह, मृत्युभोज एवं अन्य सामाजिक उत्सवों के लिए धन प्राप्त करना होता है। घरेलू उपभोग के लिए प्राप्त ऋण को उपभोग ऋण कहते हैं। इस ऋण राशि के उपयोग से कृषकों की आय में वृद्धि नहीं होती है जिससे उपभोग-ऋण का समय पर भुगतान करना कठिन होता है।

इस अध्याय में कृषि व्यवसाय के लिए प्राप्त उत्पादन ऋण का ही विवेचन किया गया है क्योंकि ऋण-प्रबन्ध के सिद्धान्त उपभोग ऋण पर लागू नहीं होते हैं।

कृषि-ऋण का वर्गीकरण

कृषि-ऋण निम्न आधारों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है—

1. ऋण-प्राप्ति के उद्देश्य के अनुसार—ऋण-प्राप्ति के उद्देश्यों के अनुसार ऋण दो प्रकार का होता है—

1 "Agricultural credit may be defined as the amount of investible funds made available for the purpose of development and sustenance of farm productivity"

—V. Rajagopalan, Farm Liquidity and Institutional Financing for Agricultural Development, Indian Journal of Agricultural Economics, Vol XXIII, No 4, October-December, 1968, p 26

(i) उत्पादन-ऋण—उत्पादन-ऋण फार्म पर कृषि-उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए प्राप्त किया जाता है। इस ऋण के फार्म पर उपयोग करने से उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है। उत्पादन-ऋण दो प्रकार के होते हैं—

(अ) प्रत्यक्ष उत्पादन-ऋण—प्रत्यक्ष उत्पादन-ऋण फार्म पर उत्पादन-साधनो—बीज, खाद, उर्वरक, औजार, पम्प सैंट आदि त्रय करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, जिनके प्रयोग से कृषि उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि होती है। इन साधनो का अधिक उपयोग करने से उत्पादन की अधिक मात्रा प्राप्त होती है।

(ब) अप्रत्यक्ष उत्पादन ऋण—अप्रत्यक्ष उत्पादन-ऋण वह है जिसके फार्म पर उपयोग करने से उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि नहीं होकर अप्रत्यक्ष रूप में वृद्धि होती है, जैसे—शिक्षा के लिए प्राप्त ऋण। शिक्षा से तकनीकी ज्ञान के उपयोग में वृद्धि होती है एवं उत्पादन बढ़ता है। प्रबन्धक की दक्षता में वृद्धि के लिए फार्म पर सार्किल क्रय करना, कृषि साहित्य त्रय करना आदि अप्रत्यक्ष उत्पादन-ऋण की श्रेणी में आते हैं।

(ii) अनुत्पादक ऋण—अनुत्पादक ऋण वह है जो कृषको द्वारा घरेलू उपयोग की आवश्यक वस्तुओं के त्रय करने, सामाजिक उत्सवो, जैसे—विवाह, मृत्यु-भोज, जन्मोत्सव आदि पर खर्च करने, मकान बनाने आदि कार्यों के लिए प्राप्त किया जाता है। अनुत्पादक ऋण के उपयोग से फार्म पर उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। अनुत्पादक ऋण का भुगतान कठिन होने के कारण कृषक पर ऋण का बोझ निरन्तर बढ़ता जाता है।

2. ऋण प्राप्ति के समय के अनुसार—ऋण प्राप्ति के समय के अनुसार कृषि-ऋण को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है—

(i) अल्पकालीन ऋण—अल्पकालीन ऋण वह है जो कृषको को मौसमी लागत को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है। अल्पकालीन ऋण फार्म पर बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशी दवाइयाँ आदि त्रय करने, धमिको को मजदूरी का भुगतान करने, भूमि का रागस्व जभा कराने, पशुओं के लिए चारा एवं दाना खरीदने आदि कार्यों के लिए दिया जाता है। अल्पकालीन ऋण एक वर्ष की अवधि में परिपक्व हो जाता है, लेकिन अल्पकालीन ऋण के भुगतान की अधिकतम अवधि 15 माह होती है।

(ii) मध्यकालीन ऋण—मध्यकालीन ऋण वह है जो कृषको को फार्म पर औजार, बैल, दुग्ध पशु खरीदने, कुर्जा गहरा करने, भूमि-सुधार, कुओं पर मोटर लगाने, बाड़ लगाने आदि कार्यों के लिए स्वीकृत किया जाता है। मध्यकालीन ऋण एक से अधिक वर्ष की अवधि में परिपक्व होता है और ऋण का भुगतान दो या दो

से अधिक मौसमों में किसानों में किया जाता है। मध्यकालीन ऋण के भुगतान की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होती है।

(iii) दीर्घकालीन ऋण—दीर्घकालीन ऋण वह है जो कृषकों को भूमि त्रय करने, भूमि पर स्थायी सुधार करने, ट्रैक्टर व अन्य मशीनों के त्रय करने, फार्म पर खाद्यान्न सप्लाय के लिए गोदाम, पशुशाला भवन का निर्माण करने, कुआँ बनवाने, फार्म पर बिजली लगाने आदि कार्यों के लिए स्वीकृत किया जाता है। इन कार्यों में पूँजी के निवेश से कृषकों को आय अनेक वर्षों तक निरन्तर प्राप्त होती रहती है जिसमें ऋण का भुगतान दीर्घावधि में हो पाता है। दीर्घकालीन ऋण के भुगतान की अवधि साधारणतया 5 से 20 वर्ष होती है।

3 प्रतिभूति के अनुसार—प्रतिभूति के अनुसार ऋण दो प्रकार के होते हैं—

(1) रक्षित ऋण—रक्षित ऋण कृषकों को चल व अचल सम्पत्ति अथवा व्यक्तिगत प्रतिभूति के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। रक्षित ऋण देने में ऋणदात्री सस्था को जोखिम नहीं होती है। रक्षित ऋण पर साधारणतया ब्याज की दर कम होती है। रक्षित ऋण चार प्रकार के होते हैं—

(अ) व्यक्तिगत प्रतिभूति ऋण—इस प्रकार के रक्षित ऋण में ऋणदात्री सस्था, ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य जिम्मेदार व्यक्ति की प्रतिभूति के आधार पर ऋण स्वीकृत करती है। ऋणी द्वारा प्राप्त ऋण का समय पर भुगतान नहीं किये जाने की प्रवस्था में प्रतिभूति देने वाला व्यक्ति ऋण भुगतान की जिम्मेदारी वहन करता है।

(ब) स्यावर सम्बन्ध की प्रतिभूति—इस प्रकार के रक्षित ऋण में ऋणदात्री सस्था, ऋणी की अचल सम्पत्ति—भूमि, मकान आदि बन्धक रखकर ऋण स्वीकृत करती है। सम्पत्ति ऋणी के पास ही रहती है, लेकिन उस पर स्वामित्व ऋणदात्री सस्था का होता है। ऋण के भुगतान से पूर्व ऋणी सम्पत्ति को अन्य व्यक्ति को विक्रय या बन्धक नहीं रख सकता है।

(स) चल सम्पत्ति की प्रतिभूति—इस प्रकार के रक्षित ऋण में ऋणदात्री सस्था ऋणी की चल सम्पत्ति—पशु, खाद्यान्न, मशीनें एवं औजार, जेवर आदि को बन्धक रखकर ऋण स्वीकृत करती है। ऋणी द्वारा नियत समय पर ऋण का भुगतान नहीं करने की प्रवस्था में ऋणदात्री सस्था चल सम्पत्ति को विक्रय करके ऋण वसूल कर लेती है।

(द) संपाश्विक प्रतिभूति (Collateral Security)—इस प्रकार के रक्षित ऋण में ऋणदात्री सस्था ऋणी के नाम के जेवर प्रमाण पत्र, बॉण्ड्स, बीमा पॉलिसी एवं नियत अवधि वाली बैंक की जमा रसीदों को

बन्धक रखकर ऋण स्वीकृत करती है। ऋणी द्वारा ऋण का भुगतान करके अपनी संपादित सम्पत्ति वापिस प्राप्त की जाती है।

(ii) अरक्षित ऋण—ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा बिना किसी प्रकार की प्रतिभूति के जो ऋण स्वीकृत किया जाता है उसे अरक्षित ऋण कहते हैं। अरक्षित ऋण में ऋणदात्री संस्था को जोखिम अधिक होती है जिसके कारण ऋण-दात्री संस्था ऋणी से व्याज अधिक दर से लेती है।

अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण रक्षित एवं अरक्षित दोनों ही प्रकार के स्वीकृत किये जाते हैं लेकिन दीर्घकालीन ऋण मुख्यतः रक्षित ही स्वीकृत किया जाता है।

4 ऋणदात्री संस्थाओं के अनुसार—ऋणदात्री संस्थाओं के अनुसार ऋण दो प्रकार का होता है—

(i) संस्थागत अभिकरण या एजेंसियों से प्राप्त ऋण—संस्थागत अभिकरणों से तात्पर्य उन ऋण संस्थाओं से है जिन पर व्यक्ति विशेष का स्वामित्व न होकर, अनेक व्यक्तियों का सामूहिक स्वामित्व होता है, जैसे सरकार, सहकारी समितियाँ, बाणिज्यिक बैंक, निगम आदि। इन संस्थाओं से प्राप्त ऋण को संस्थागत अभिकरण से प्राप्त ऋण कहते हैं।

(ii) गैर-संस्थागत या निजी अभिकरण स्रोत से प्राप्त ऋण—गैर-संस्थागत अभिकरणों से तात्पर्य उन ऋण संस्थाओं से है जिन पर एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है, जैसे—साहूकार, व्यापारी, भाडतिया, जमींदार आदि। इनसे प्राप्त ऋण को गैर-संस्थागत अभिकरण से प्राप्त ऋण कहते हैं।

5 ऋणी कृषक के अनुसार—ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों के अनुसार ऋण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है—

- (अ) खानान्न उत्पादन करने वाले ऋणी कृषक,
- (ब) सब्जी उत्पादन करने वाले ऋणी कृषक,
- (स) फल उत्पादन करने वाले ऋणी कृषक,
- (द) दूध उत्पादन करने वाले ऋणी कृषक,
- (य) कुक्कुट पालन करने वाले ऋणी कृषक।

सुदृढ़/ठोस ऋण व्यवस्था के आवश्यक गुण

सुदृढ़ ऋण व्यवस्था में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है—

- 1 कृषकों को फार्म पर आवश्यक कार्यों के लिए उचित भवधि के लिए ऋण स्वीकृत करना चाहिए। ऋण को चुकाने की भवधि के कम होने पर प्राप्त ऋण का समय पर भुगतान पर पाना कृषक के लिए सम्भव नहीं होता है।

- 2 कृषको को ऋण स्वीकृत करने वाली संस्था, कृषको के विकास में इच्छुक तथा उन्हें तकनीकी ज्ञान प्रदान करने की क्षमता रखने वाली होनी चाहिए ।
- 3 कृषको को ऋण न्यूनतम व्याज दर पर उपलब्ध होना चाहिये ।
- 4 कृषको को ऋण की राशि उनकी वित्तीय स्थिति के अनुसार स्वीकृत करनी चाहिए, जिससे आर्थिक मन्दी काल में भी कृषको में ऋण-भुगतान की सामर्थ्य बनी रहे ।
- 5 कृषको को ऋण स्वीकृति के समय उनकी वित्तीय स्थिति के प्रतिरिक्त बाजार ऋण साख, कार्यक्षमता, फार्म से प्राकृतिक लाभ की राशि एवं नैतिक स्तर भी रक्षित में रखने चाहिए ।
- 6 कृषको को ऋण स्वीकृति की शर्तें, ऋण-भुगतान/अदायगी का समय व्याज की राशि ज्ञात करने की विधि आदि की जानकारी ऋण स्वीकृत करते समय ही देनी चाहिये ।
- 7 कृषको को उत्पादन-ऋण के साथ-साथ उपभोग-ऋण भी स्वीकृत करना चाहिए । उपभोग ऋण कम से कम राशि में लेने के लिए उन्हें सहमत करना चाहिये ।
- 8 कृषको को आवश्यक स्वीकृत ऋण की कुल राशि एक विश्व में नहीं देकर, आवश्यकतानुसार राशि में समय-समय पर देना चाहिए । स्वीकृत ऋण राशि को एक साथ प्राप्त करने से कृषको को व्याज की राशि अधिक देनी होती है तथा उनके पास अनावश्यक राशि में पूँजी होने से फिजूल खर्ची की प्रवृत्ति बढ़ती है ।

कृषि-ऋण की समस्याएँ

कृषि ऋण, अन्य उद्यमों के लिए प्राप्त ऋण से भिन्न होता है । इसका प्रमुख कारण कृषि उद्यम की कुछ विशेषताओं का होना है, जिनमें कृषि ऋण की समस्याएँ अन्य व्यवसायों की ऋण समस्याओं से भिन्न होती हैं । कृषि ऋण की प्रमुख समस्याएँ निम्न हैं —

- 1 कृषि उत्पादन पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर होता है । कृषि में मौसम की प्रतिकूलता के कारण अनिश्चितता बनी रहती है जिसके कारण ऋणदात्री संस्थाएँ कृषको को ऋण स्वीकृति में प्राथमिकता नहीं देती हैं ।
- 2 कृषि-क्षेत्र में उत्पादन कार्यों के लिए पूँजी निवेश करने के समय एवं पूँजी से प्राप्त आय के समय में विशेष समयान्तर होना है, जैसे—खाद्यान्न में 5—6 माह, पशुओं में 4 से 5 वर्ष, फलों में 5 से 10 वर्ष आदि । अतः स्वीकृत ऋण राशि दीर्घावधि में बसूल हो पाती है,

जिसके कारण भी ऋणदात्री सस्याएँ कृषि-व्यवसायकर्ताओं को ऋण स्वीकृत करने को तैयार नहीं होती है।

- 3 कृषि व्यवसाय में छोटी छोटी जोत के असह्य कृषक होते हैं। प्रत्येक कृषक को ऋण आवश्यकता की पूर्ति करने एवं उनसे वसूली करने का कार्य कठिन होता है। ऋण-वसूली में लागत भी अधिक आती है।
- 4 कृषि व्यवसाय में पूँजी की आवश्यकता वर्ष भर निरन्तर नहीं होकर मौसम विशेष में होती है। अतः मौसम विशेष में ऋण की आवश्यक राशि की अधिकता के कारण ब्याज-दर अधिक होती है।
- 5 कृषकों के पास ऋण की प्रतिभूति के लिए आवश्यक मात्रा में चल व अचल सम्पत्ति का अभाव होता है जिसके कारण भी कृषक आवश्यक राशि में ऋण प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
- 6 विभिन्न कृषकों की आवश्यक ऋण राशि एवं उनकी मुग्तान क्षमता के निर्धारण का कार्य भी कठिन होता है।
- 7 कृषि, व्यवसाय के साथ-साथ जीविका-निर्वाह का साधन भी है। अतः कृषि व्यवसाय में उत्पादन व उपभोग ऋण में अन्तर करना कठिन होता है।

कृषि में पूँजी एवं ऋण की आवश्यकता

प्रत्येक व्यवसाय की सफलता के लिए धन की आवश्यकता होती है। कृषि भी एक व्यवसाय है। कृषि व्यवसाय में पूँजी की आवश्यकता निम्न प्रचलित कहा-वत से स्पष्ट है। 'Capital is ammunition in the farming battle' अर्थात् जिस प्रकार युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए गोला-बारूद की आवश्यकता होती है उसी प्रकार कृषि व्यवसाय में सफलता अर्थात् अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है। पूँजी कृषि उत्पादन में अपरिहार्य (Indispensable) कारक है। प्राचीन काल में कृषि व्यवसाय के लिए पूँजी की आवश्यकता बहुत कम थी, क्योंकि उस समय कृषक कृषि की व्यवसाय के रूप में न लेकर जीविकोपार्जन के रूप में अपनाते थे। साथ ही कृषि में उत्पादन के लिए आवश्यक उत्पादन-साधन कृषक बाहर से क्रय नहीं करते थे, बल्कि अपने पास से ही पूर्ति करते थे। सिंचाई भी कुओं से चरस द्वारा करते थे। कृषि में तकनीकी ज्ञान का विकास भी नहीं हुआ था।

वर्तमान में कृषक कृषि को एक व्यवसाय के रूप में लेते हैं। उत्पादन के सभी आवश्यक साधनों का प्रचुर मात्रा में उपयोग करते हैं। तकनीकी ज्ञान के विकास के कारण नए-नए उत्पादन साधनों का आविष्कार हो रहा है जिन्हें वे अन्य सस्थाओं से न्य लेते हैं। जैसे उर्वरक, कीटनाशी दवाइयाँ, औजार, मशीन, उन्नत बीज, सिंचाई के लिए बिजली। इन सब कारणों से कृषि-व्यवसाय में पूँजी की

आवश्यकता प्रति इकाई क्षेत्र पर पहले की अपेक्षा कई गुना अधिक हो गई है। साथ ही कृषि व्यवसाय में अन्य उद्योगों की अपेक्षा स्थायी पूँजी की आवश्यकता अधिक होती है। स्थायी पूँजी की कृषि में आवश्यकता भूमि को ध्रुव करने, भूमि को कृषि योग्य बनाने, सिंचाई के साधनों का विकास करने, फार्म पर आवश्यक भवन जैसे— पशुगृह, भण्डार-गृह आदि का निर्माण करने, कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टर, हारवेस्टर, प्रैसर, सीडड्रिल, सिंचाई के लिए विद्युत् चालित मोटर आदि को ध्रुव करने के लिए अधिक होती है। कृषि व्यवसाय में स्थायी पूँजी की अधिक आवश्यकता के कारण पूँजी-आवर्त अनुपात (Capital turnover ratio) अन्य व्यवसायों की अपेक्षा कम होता है। अतः कृषि व्यवसाय में पूँजी एक बार लगाने के बाद जल्दी-जल्दी प्राप्त नहीं होती है।

विभिन्न फार्मों पर पूँजी की आवश्यकता में बहुत भिन्नता पाई जाती है।

निम्न कारक फार्म पर पूँजी की आवश्यक राशि में परिवर्तन लाते हैं —

- (i) क्षेत्र में भूमि की कीमत एवं फार्म का आकार।
- (ii) फार्म पर भूमि को समतल करना, बाड़ लगाना, सिंचाई के साधनों एवं मशीनों की आवश्यकता।
- (iii) फार्म पर उत्पादित किये जाने वाले उद्यमों की प्रकृति एवं उनके अन्तर्गत क्षेत्रफल। खाद्यान्नों की अपेक्षा सब्जी, फल, तिलहन, फसलों को उत्पादित करने के लिए पूँजी की आवश्यकता अधिक होती है।
- (iv) फार्म पर सघन अथवा विस्तृत कृषि की अपनाई जाने वाली प्रणाली।
- (v) फार्म पर तकनीकी ज्ञान के प्रयोग का स्तर।
- (vi) फार्म पर यन्त्रीकरण के प्रयोग का स्तर।
- (vii) फार्म पर आवश्यक उत्पादन-साधनों जैसे सफ़त बीज, खाद, उर्वरक, अम्लिक, कीटनाशी दवाइयों की लागत राशि, आदि।

कृषि-व्यवसाय में प्राप्त होने वाली शुद्ध आय की राशि बहुत कम होती है, जिसके कारण बचत की राशि कम होती है। अतः कृषकों के पास उपलब्ध पूँजी, कृषि व्यवसाय के लिए आवश्यक पूँजी से बहुत कम राशि में होती है। कृषक पूँजी को इस आवश्यक राशि को सस्याओं एवं गैर-सस्याओं से ऋण लेकर पूरी करते हैं।

कृषि व्यवसाय में पूँजी एवं ऋण की आवश्यकता के आकलन—देश में कृषि-जोत के आकार में विभिन्नता, प्रयुक्त तकनीकी ज्ञान-स्तर एवं फार्म पर लिए जाने वाले उद्यमों की विभिन्नता के कारण कृषि-क्षेत्र में पूँजी एवं ऋण की कुल आवश्यकता के आकलन का कार्य कठिन एवं पेचीदा है। विभिन्न सस्याओं ने विभिन्न वर्षों में कृषि-ऋण की आवश्यकता के आकलन किये हैं। देश में विभिन्न सस्याओं/समितियों/अर्थशास्त्रियों द्वारा कृषि-व्यवसाय के लिए पूँजी/ऋण की आवश्यकता के सम्बन्ध में किए गए आकलन अशक्ति हैं—

- (1) केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति ने वर्ष 1949 में कृषि के लिए 300 से 400 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण एवं 500 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता का आकलन किया था।
- (2) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा वर्ष 1950-51 में नियुक्त अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने कृषकों की अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण की वार्षिक आवश्यकता के रूप में 750 करोड़ रुपये के आकलन दिये थे।
- (3) अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण प्रस्तुता एवं निवेश सर्वेक्षण, 1961-62 के अनुसार कृषि-व्यवसाय में कुल पूँजीगत व्यय 626 करोड़ रुपये का था, जिसमें से 33 प्रतिशत ऋण के रूप में प्राप्त किया गया था।
- (4) केन्द्रीय कृषि-मन्त्रालय ने वर्ष 1966-67 के लिए कृषि में 1003 करोड़ रुपये की आवश्यकता का आकलन प्रस्तुत किया था, जिसमें से 735 करोड़ रुपये अल्पकालीन ऋण, 90 करोड़ रुपये मध्यकालीन ऋण एवं 28 करोड़ रुपये दीर्घकालीन ऋण के थे।
- (5) श्री पी सी बंसिल² ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए कृषि में 1677 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता के आकलन प्रस्तुत किये थे। इनमें से 819 करोड़ रुपये फार्म व्यवसाय के लिए एवं 858 करोड़ रुपये घरेलू आवश्यकता के लिये थे।
- (6) भारत सरकार के कृषि उत्पादन-मण्डल (Agricultural Production Board) द्वारा वर्ष 1965 में नियुक्त कार्यकारी दल ने प्रस्तावित चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1966-1971) के लिये कृषि में 4470 करोड़ रुपये की पूँजी तथा 2412 करोड़ रुपये के कृषि ऋण की आवश्यकता का आकलन किया था।
- (7) भारत सरकार ने प्रो एम एल दातवाला की अध्यक्षता में नियुक्त कृषि अर्थशास्त्रियों के पैनल ने कृषि-परिवारों के लिए अल्पकालीन ऋण के सम्बन्ध में वर्ष 1970-71 के लिए 1228 करोड़ रुपये व 1341 करोड़ के आकलन दिये थे।

अर्थशास्त्रियों के पैनल द्वारा दिए गए अल्पकालीन ऋण के आकलन एवं कार्यकारी दल के द्वारा दिए गए आकलनों में अन्तर है जिसका प्रमुख कारण आकलन विधि में अन्तर का होना है। कार्यकारी दल के द्वारा दिए गए मध्य एवं दीर्घकालीन ऋण के आकलनों को कृषि-अर्थशास्त्रियों के पैनल ने उचित बताया था।

2 P C Bansil, Short Term Credit Requirements at the end of the Fourth-Five Year Plan, 1973-74, Indian Journal of Agricultural Economics, Vol XXVI, No 4, October-December, 1971, p 467-73

- (8) अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनर्निरीक्षण समिति ने सशोधित चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) के लिए 2000 करोड़ रुपये अल्पकालीन ऋण, 500 करोड़ रुपये मध्यकालीन ऋण एवं 1500 करोड़ रुपये दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता का आकलन किया था।
- (9) श्री पी वी शिनोय³ ने कृषि क्षेत्र में उन्नत कृषि के बीजों के अधिक उपयोग एवं कृषि में यन्त्रीकरण की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए पाचवी पंचवर्षीय योजना (1974-79) के लिए कृषि-ऋण की आवश्यकता 5000 करोड़ रुपये होने का आकलन किया था।
- (10) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कृषि एवं सहायक उद्योगों के लिए आवश्यक सम्भावित पूँजी के आकलन में बतलाया है कि यदि देश में निर्धारित सभी योजनाओं को पूर्णरूप से कार्यान्वित किया जाता है तो वर्ष 1985 के अन्त तक 16,549 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, जिसका विवरण सारणी 9 I में दिया गया है।

सारणी 9 I

देश में कृषि क्षेत्र में सभी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 1985 के अन्त तक पूँजी की आवश्यकता

(करोड़ रुपये)

पूँजी का विवरण	सीमान्त एवं लघु कृषक	मध्य एवं दीर्घ जोत कृषक	कुल
1 अल्पकालीन पूँजी	2193	5691	7884
2 मध्य एवं दीर्घकालीन पूँजी	2497	5786	8265
3 कृषि यन्त्रों एवं मशीनों के लिए	—	—	—
कुल पूँजी	—	—	16549

स्रोत Report of National Commission on Agriculture, Vol XII, Ministry of Agriculture and Irrigation, Government of India, New Delhi, 1976, p 57

3 P V Shenoi, Agricultural Development in India, Vikas Publishing House, New Delhi, 1975, p 280

(11) कृषि क्षेत्र में अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता के विभिन्न वर्षों के लिए डॉ. डी के देसाई द्वारा दिए गए आकलन सारणी 92 में प्रदर्शित हैं।

सारणी 92

अल्पकालीन ऋण आवश्यकता के विभिन्न जोत कृषकों के लिए
वर्ष 1984-85 से 2000 तक के आकलन

(करोड़ रुपये)

वर्ष		लघु एवं सीमान्त कृषक	मध्य जोत कृषक	दीर्घ जोत कृषक	कुल
1984-85	A ₁	7,740	15,003	6,721	29,464
	A ₂	9,460	18,337	8,214	36,011
1990	A ₁	9,492	18,071	6,593	34,156
	A ₂	12,090	21,721	7,936	41,747
1995	A ₁	11,748	21,287	7,712	40,567
	A ₂	14,359	25,798	9,426	49,582
2000	A ₁	14,293	25,680	9,383	49,356
	A ₂	17,470	31,368	11,468	60,324

A₁ = All farmers would get credit on the basis of cash and kind expenditure for production of all crops

A₂ = All farmers would get credit on the basis of cash and kind expenditure plus the imputed value of family labour for production of all crops.

स्रोत D K Desai, Institutional Credit Requirements for Agricultural Production—2000 AD, Indian Journal of Agricultural Economics, Vol XL III, No. 3, July-September, 1988, p 341

सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2000 तक कुल अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता विकल्प प्रथम के अनुसार 49,356 करोड़ रुपये एवं विकल्प द्वितीय के अनुसार 60,324 करोड़ रुपये होने का आकलन है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि कृषि के क्षेत्र में पूँजी/ऋण की आवश्यकता में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। भविष्य में कृषि में तकनीकी ज्ञान के अधिक विस्तार के साथ-साथ कृषि ऋण की आवश्यकता में अधिक वृद्धि होने की सम्भावना है।

कृषि-ऋण की आवश्यकता के फार्म स्तर पर भी विभिन्न क्षेत्रों में आकलन के लिए अध्ययन किये गये हैं, जो क्षेत्र एवं फार्म पर ली जाने वाली फसलों तथा उनके अन्तर्गत क्षेत्रफल के अनुसार प्रति फार्म एवं प्रति हेक्टर पूँजी एवं ऋण की आवश्यकता के आँकड़े प्रदर्शित करते हैं।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता

ऋणग्रस्तता से तात्पर्य उस ऋण राशि से है जिसका ऋणी द्वारा ऋणदात्री संस्थाओं को भुगतान करना है, अर्थात् ऋणग्रस्तता ऋणदात्री संस्थाओं की कृषकों पर बकाया राशि का द्योतक होता है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या है। कृषि देश का प्रमुख व्यवसाय होते हुए भी भारतीय कृषक ऋण के भारी बोझ से दबे हुए हैं, जिसके कारण कृषक कृषि में उन्नत तरीकों को अपनाने के लिए आवश्यक राशि में पूँजी के निवेश करने में असमर्थ होते हैं। कृषकों की ऋणग्रस्तता भारतीय कृषि के लिए अभिशाप है। कृषि रायल कमीशन ने 1928 में अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि "भारतीय कृषक ऋण का बोझ कंधे पर लेकर जन्म लेता है, ऋणग्रस्तता में पूरा जीवन व्यतीत करता है ऋण में ही उसका अन्त हो जाता है और वह अपनी सन्तान के लिए भी ऋण का बोझ छोड़ जाता है।" इस प्रकार कृषकों पर ऋण पीढ़ी-दर-पीढ़ी चसता रहता है।

कृषकों की ऋणग्रस्तता का प्रमुख कारण कृषकों द्वारा सामाजिक उत्सवों—शादी, मृत्युभोज आदि कार्यों पर अधिक धनराशि का व्यय करना है। सामाजिक उत्सवों पर व्यय करने के लिए प्राप्त ऋण उत्पादक नहीं होता है जिससे प्राप्त ऋण का बोझ कृषकों पर निरन्तर बढ़ता ही जाता है। निर्धनता एवं ऋणग्रस्तता भारतीय कृषक के जीवन के अविभाज्य अंग बन गये हैं।

भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता का आकलन—देश में कृषकों पर ऋणग्रस्तता का आकलन करने के लिए समय-समय पर विभिन्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों ने अपने प्रतिवेदनों में इनकी राशि का वर्णन किया है। अकाल-आयोग ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 में अपने प्रतिवेदन में बताया कि 80 प्रतिशत कृषक देश में ऋणग्रस्त हैं। सर एडवर्ड मैकलेगन (1911) के अनुसार देश में ग्रामीण ऋणग्रस्तता की राशि 300 करोड़ रुपये, सर एम. एल डारलिंग (1925) के अनुसार 600 करोड़ रुपये, केन्द्रीय बैंकिंग जाच समिति (1931) के अनुसार 900 करोड़ रुपये, डॉ. राधाकमल मुखर्जी एवं डॉ. पी. जे. शॉमस (1935) के अनुसार 1200 करोड़ रुपये एवं

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के कृषि-ऋण-विभाग (1937) के अनुसार 1800 करोड़ रुपये प्राकलित किये गए हैं। प्राप्त आकलनों से स्पष्ट है कि देश में ग्रामीण-ऋणग्रस्तता की राशि निरन्तर बढ़ रही है।

ग्रामीण-ऋण के सम्बन्ध में किये गये दो विस्तृत सर्वेक्षणों—अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण, 1951-52 एवं अखिल भारतीय ग्रामीण कर्ज एवं विनियोग सर्वेक्षण, 1961-62 में ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्राप्त परिणाम सारणी 9.3 में प्रस्तुत किये गये हैं।

सारणी 9.3

ग्रामीण-ऋणग्रस्तता का 1951-52 से 1960-61 के
दशक में तुलनात्मक अध्ययन

विवरण	1951-52	1961-62	परिवर्तन
(1) ऋणग्रस्त परिवारों का प्रतिशत			
(अ) कुल परिवार	58.6	52.0	(-) 6.6
(ब) अ-कुल परिवार	38.6	40.0	(+) 1.4
(स) सभी ग्रामीण परिवार	51.7	48.8	(-) 2.9
(2) प्रति परिवार ऋण का बोझ (रु०)			
(अ) कुल परिवार	209.5	205.4	(-) 4.1
(ब) अ-कुल परिवार	66.1	111.8	(+) 45.7
(स) सभी ग्रामीण परिवार	159.9	NA	NA
(3) प्राप्त कुल ऋण की राशि (करोड़ रु०)	750	1034	(+) 284
(4) ऋणी कुल का प्रतिशत	69.2	66.7	(-) 2.5
(5) प्रति ऋणी कुल का ऋण का बोझ (रु०)	526	708	(+) 182

स्रोत : 1. All India Rural Credit Survey, 1951-52, Reserve Bank of India, Bombay

2. All India Rural Debt and Investment Survey, 1961-62, Reserve Bank of India, Bombay.

वर्ष 1951-52 से 1961-62 के दशक में कुल ऋण की राशि में 284 करोड़ रुपये अर्थात् 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लेकिन ऋणप्रस्त कृषक परिवारों एवं प्रति कृषक परिवार पर ऋण के बोझ में उपर्युक्त काल में कमी हुई है।

सारणी 9.4 कृषकों द्वारा वर्ष 1951-52 व 1961-62 में प्राप्त ऋण का कुल ऋण में विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार प्रतिशत प्रदर्शित करती है। प्राप्त ऋण का लगभग आधा भाग (47 प्रतिशत) कृषकों द्वारा परिवार की उपभोग-आवश्यकताओं में व्यय किया गया है। उपर्युक्त काल में घरेलू उपभोग व्यय के प्रतिशत में परिवर्तन नहीं आया है। ऋण प्राप्ति का दूसरा प्रमुख उद्देश्य कृषि-व्यवसाय में पूंजी निवेश करना है। वर्ष 1951-52 में कृषि-व्यवसाय में पूंजी निवेश करने एवं चालू-व्यय का पूरा करने के लिए 42.1 प्रतिशत ऋण प्राप्त किया गया था, जो कम होकर वर्ष 1961-62 में 35.6 प्रतिशत हो रहा गया।

सारणी 9.4

कृषकों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार प्राप्त ऋण

ऋण प्राप्ति का उद्देश्य	प्राप्त कुल ऋण का प्रतिशत	
	1951-52	1961-62
1. फार्म व्यवसाय में पूंजी निवेश करने	31.5	22.1
2. फार्म व्यवसाय में चालू व्यय करने	10.6	13.5
3. फार्म व्यवसाय के अतिरिक्त कार्यों में व्यय करने	4.5	6.7
4. घरेलू उपभोग व्यय करने	46.9	46.6
5. अन्य व्यय हेतु	6.5	11.1
कुल	100.0	100.0

ग्रामीण श्रम-जाँच समिति, 1964-65 के अनुसार कृषि श्रमिक परिवार एवं सभी ग्रामीण श्रमिक परिवारों पर औसतन ऋण की राशि इस प्रकार थी—

सारणी 95

कृषि-श्रमिक परिवारों पर ऋण का बोझ

(रुपये)

परिवार	प्रति परिवार ऋण का औसत बोझ	ऋणग्रस्त परिवारों पर ऋण का औसत बोझ
1. कृषि-श्रमिक परिवार	147.89	243 87
2. सभी ग्राम्य श्रमिक परिवार	148 42	250 70

स्रोत Rural Labour Enquiry, Summary Report, 1964-65

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण ऋणग्रस्तता की राशि वर्ष 1962 में 2789 करोड़ रुपये एवं जून 1971 में 3921 करोड़ रुपये होने का आकलन है। मखिल भारतीय स्तर पर रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित ग्रामीण ऋण एवं विनियोग सर्वेक्षणों को आधार मानते हुए प्रति कुपक परिवार ऋण का बोझ निरन्तर बढ़ता जा रहा है। प्रति कुपक परिवार ऋण का बोझ वर्ष 1951-52 में 526 रुपये का था, जो बढ़कर 1961-62 में 708 रुपये एवं 1971-72 में 812 रुपये का हो गया, जबकि प्रति ग्रामीण परिवार पर ऋण का बोझ 1971-72 में 303 रुपये का, प्रति गैर कुपक परिवार पर 219 रुपये का, प्रति खेतिहर मजदूर परिवार पर 162 रुपये एवं प्रति गैर कृषि मजदूर परिवार पर 261 रुपये का हो था।

स्पष्ट है कि कृषि-श्रमिक परिवारों पर ममी श्रमिक परिवारों की अपेक्षा ऋण का भार कम है।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारण—ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्रमुख कारण निम्न हैं—

(1) पैतृक ऋण—भारत में ग्रामीण परिवारों की ऋणग्रस्तता का प्रमुख कारण परिवार के मुखिया की मृत्यु के उपरान्त पैतृक ऋण का उत्तराधिकारी पर हस्तान्तरण होना है, जिसके कारण ऋण का बोझ परम्परागत रूप में चलता रहता है।

(2) कृषि में प्राकृतिक प्रकोपों का होना—भारतीय कृषि प्रकृति पर निर्भर है। प्रति वर्ष ओला, सूखा, अतिवृष्टि आदि के कारण देश के किसी न किसी भाग में फसल के खराब होने के कारण कृषकों को प्राप्त होने वाली आय कम हो जाती है जिससे वे ऋण का समय पर मुगनान नहीं कर पाते हैं।

(3) ग्रामीण परिवारों द्वारा अनुत्पादक कार्यों के लिए अधिक राशि व्यय करना—देश के कुपक विवाह, मृत्युभोज, जन्मोत्सव एवं अन्य सामाजिक उत्सवों पर अधिक राशि में धन व्यय करते हैं। इसका प्रमुख कारण देश में सामाजिक

कुरीतियों का होना है। अनुत्पादक वायों के लिए प्राप्त ऋण से कृषकों की आय में वृद्धि नहीं होती, बल्कि उन पर ऋण का बोझ बढ़ाने में सहायक होता है।

(4) जोत उप-विभाजन एवं अपखण्डन—भारत में वशागत कानून के कारण जोत उप-विभाजन एवं अपखण्डन में जोतें अस्तामकर होती जा रही हैं। अस्तामकर जोत के कारण कृषकों को बचत की राशि कम प्राप्त होती है। ऋण का मुगतान भी समय पर नहीं हो पाता है और ऋण का बोझ बढ़ता जाता है।

(5) कृषकों की निरक्षरता निरक्षरता के कारण कृषक ऋण प्राप्ति के लिए सही सस्या का चुनाव नहीं कर पाते हैं तथा अज्ञानता के कारण प्राप्त ऋण पर अधिक व्याज राशि एवं अन्य लागतें देनी होती हैं।

(6) ग्राम्य क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों का अभाव—गाँवों में कृषि-व्यवसाय के अतिरिक्त लघु एवं कुटीर उद्योगों के अभाव के कारण, वर्ष में बहुत समय तक कृषक बेकार रहते हैं। कृषि-व्यवसाय से मौसमी रोजगार ही उपलब्ध होता है। अतः रोजगार आवश्यक मात्रा में वर्ष भर उपलब्ध नहीं होने के कारण कृषकों की वार्षिक आय कम हो जाती है जिससे प्राप्त ऋण को चुकाना सम्भव नहीं होता है।

(7) ऋण पर व्याज की दर अधिक होना—गाँवों में सस्थागत अभिकरणों के अभाव में कृषक असस्थागत अभिकरणों से ऋण प्राप्त करते हैं। असस्थागत अभिकरण स्वीकृत ऋण पर व्याज अधिक दर से लेते हैं। व्याज के अतिरिक्त अनेक कटौतियाँ भी काटते हैं जिससे भी ऋण का बोझ बढ़ता है।

(8) निर्धनता—निर्धनता, स्वास्थ्य-स्तर अच्छा नहीं होना एवं बचत का स्तर कम होने से कृषकों की कार्यक्षमता में कमी होती है और प्राप्त धन आवश्यकताओं के लिए पूरा नहीं पड़ता है।

(9) सरकार की राजस्व वसूली नीति—राजस्व वसूली की नीति में कठोरता होने से कृषकों को राजस्व मुगतान के लिए अन्य सस्थाओं से ऋण लेना होता है। कृषकों की ऋण आवश्यकता की मजबूरी का फायदा उठाते हुए साहूकार अधिक व्याज वसूल करते हैं।

(10) फसल के विक्रय से उचित मूल्य प्राप्त न होना—देश में पर्याप्त नियन्त्रित मण्डियों के अभाव के कारण कृषकों को साद्यान्तों की विक्री अपने गाँव में ही व्यापारी को करनी होती है। प्रतिस्पर्धा के अभाव में कृषकों को गाँव में साद्यान्तों की उचित कीमत प्राप्त नहीं होती है तथा विपणन लागत भी अधिक देनी होती है जिससे प्राप्त लाभ की राशि में कमी होती है।

(11) कृषकों द्वारा कृषि उत्पादन की उन्नत विधियों को न अपनाकर पुरानी विधियों से खेती करना भी ऋणग्रस्तता का एक कारण है।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता के दुष्परिणाम— ग्रामीण ऋणग्रस्तता के मुख्य दुष्परिणाम निम्न है—

(1) आर्थिक दुष्परिणाम—कृषको पर ऋण के बढ़ते हुए बोझ के कारण निम्न आर्थिक दुष्परिणाम होते हैं—

- (अ) कृषको को ऋण मुक्तान के लिए साहूकारों एवं जमींदारों के खेतों पर अनिवार्यतया कम मजदूरी पर कार्य करना होता है।
- (ब) कृषको द्वारा फार्म पर उत्पादित फसल, सब्जों, ईंधन, चारा, दूध एवं अन्य वस्तुएँ साहूकारों तथा जमींदारों को समय समय पर उपहार में देनी होती हैं।
- (स) कृषको को ऋणग्रस्तता के कारण उत्पाद गांव के साहूकार या व्यापारी के माध्यम से बेचने के लिए बाध्य होना होता है, जिससे फसल की उचित कीमत प्राप्त नहीं होती है।
- (द) कृषको द्वारा प्राप्त ऋण को समय पर मुक्तान नहीं करने की स्थिति में सौकर एवं जमींदार भूमि पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे कृषक भूमिहीन श्रमिकों की श्रेणी में आ जाते हैं।

(2) सामाजिक दुष्परिणाम—ऋणग्रस्तता के कारण समाज घनी एवं निर्धन वर्गों में विभक्त हो जाता है जिससे समाज में सामाजिक वैषम्यता बढ़ती है।

(3) नैतिक दुष्परिणाम—ऋण के बोझ से लदे हुए कृषक समाज में अन्य व्यक्तियों के समान अस्तित्व नहीं रख पाते हैं जिससे उनका नैतिक पतन होता है।

ऋणग्रस्तता की समस्या का निवारण—ऋणग्रस्तता की व्याप्त समस्या के निवारण के लिए उपलब्ध उपायों को निम्न तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है—

1 पुराने ऋण का निपटारा—कृषको की ऋणग्रस्तता के निवारण के लिए सर्वप्रथम उन पर वर्तमान ऋण राशि को कम करना आवश्यक है। इसके लिए सरकार ने समय-समय पर विभिन्न कानून पारित किये हैं। इन सब कानूनों का मुख्य उद्देश्य ऋणदात्री संस्थानों पर पाबन्दी लगाते हुए कृषको के वर्तमान ऋण की राशि को कम करना है। इसके लिए पारित प्रमुख अधिनियम निम्नलिखित हैं—

- (अ) दक्षिण कृषक सहायता अधिनियम, 1879 (The Deccan Agriculturists Relief Act)—इस अधिनियम की मुख्य विशेषता ऋण के इतिहास की जाँच करके मूलधन एवं व्याज का अनुपात नियत करना तथा साहूकारों की कुचालों पर नियन्त्रण लगाना है।
- (ब) समझौता कानून, 1899 (The Control Act)—इसके अन्तर्गत साहूकारों द्वारा ऋण की राशि में अनुचित विधि से की गई वृद्धि में छूट देने का प्रावधान है।

- (स) अधिक ब्याज से मुक्ति दिलाने का कानून, 1918 (The Usurious Loans Act)—इस कानून के अन्तर्गत ऋणी को ब्याज की राशि मूलधन की राशि से अधिक होने पर छूट देने का प्रावधान है।
- (द) हिसाब नियन्त्रण कानून (Regulation of Accounts)—हिसाब नियन्त्रण कानून बंगाल में वर्ष 1933, असम एवं मध्यप्रदेश में 1934, बिहार में 1938 एवं उड़ीसा व बम्बई में 1939 में पारित किए गए। इनके अन्तर्गत साहूकारों को लेने-देने का पूर्ण हिसाब रखना होता है और आवश्यकता होने पर सरकार को पेश करना होता है।
- (य) साहूकारों के पंजीकरण एवं अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने का कानून—इसके अन्तर्गत साहूकारों को ऋण देने के लिए अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करना होता है। ये कानून 1930 के पश्चात् राज्यों में पारित किए गए हैं।
- (र) ऋण समझौता कानून (Debt Conciliation Act)

2 भविष्य के लिए ऋण पर ब्याज की दर निर्धारित करना—ऋणग्रस्तता कम करने का दूसरा उपाय भविष्य में दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर में कमी करना है। इसके लिए विभिन्न राज्यों में रक्षित एवं अरक्षित ऋण के लिए अधिकतम ब्याज दर निर्धारित करने के कानून पारित किए गए हैं।

3 नए ऋणों की स्वीकृति पर पाबन्दी—इसके अन्तर्गत ऋणदात्री संस्था पर अधिक राशि में अनुत्पादक ऋण स्वीकृत करने पर पाबन्दी लगाई गई है, जिससे कृषकों में फिजूलखर्ची की प्रवृत्ति कम हो सके।

कृषकों की ऋणग्रस्तता को कम करने के लिए देश के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में भी इसे प्राथमिकता दी गई है जिसके अनुसार अनेक राज्यों ने असत्यागत अभिकरणों के ऋण के बोझ से कृषकों को मुक्त कर दिया है तथा कुछ राज्यों ने ऋण वसूली पर एक से दो वर्ष के लिए पाबन्दी लगाई है। वर्तमान में अनेक राज्य सरकारों ने सत्यागत ऋण के बोझ से भी कृषकों को राहत दी है।

कृषि ऋण के स्रोत

कृषि-ऋण प्राप्ति के प्रमुख स्रोत-संस्थागत एवं गैर संस्थागत या निजी अभिकरण होते हैं। इन समस्याओं का विस्तृत वर्गीकरण व विवरण इस अध्याय में दिया जा रहा है।

1 संस्थागत अभिकरण—संस्थागत अभिकरण में निम्न संस्थाएँ सम्मिलित होती हैं -

- (अ) सरकार
- (ब) सहकारी समितियाँ
- (स) वाणिज्यिक बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- (द) निगम—(i) कृषि पुनर्वित्त निगम
(ii) कृषि वित्त निगम
(iii) कृषि ऋण निगम
(iv) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम

2. गैर संस्थागत या निजी अभिकरण—इसमें निम्न सम्मिलित होते हैं—

- (अ) साहूकार—(i) पेशेवर साहूकार
(ii) कुपक साहूकार
- (ब) व्यापारी एवं आडतिया
- (स) जमींदार
- (द) सम्बन्धी
- (प) विविध स्रोत

सारणी 10.1 कुपक परिवारों पर बकाया ऋण राशि में संस्थागत एवं गैर संस्थागत अभिकरणों द्वारा प्रदत्त ऋण का अंश प्रदर्शित करती है।

सारणी 10 1

संस्थागत एवं गैर संस्थागत अभिकरणों का कृषकों पर
बकाया ऋण में अंशदान

(प्रतिशत)

वर्ष	संस्थागत अभिकरण	गैर संस्थागत अभिकरण	कुल ऋण
1951-52	12 3	87 7	100
1961-62	18 4	81 6	100
1971-72	31 7	68 3	100
1981-82	63 3	36 7	100

स्रोत : (i) All India Rural Credit Survey, Vol I, Part II, Reserve Bank of India, Bombay, 1957

(ii) All India Rural Debt and Investment Survey, 1961-62, 1971-72 and 1981-82, Reserve Bank of India, Bombay 1966 1977 & 1986-

सारणी से स्पष्ट है कि संस्थागत अभिकरणों का कृषकों पर बकाया ऋण में प्रतिशत अंश में निरन्तर वृद्धि हुई है। उनका ऋण में अंशदान 12 3 प्रतिशत से बढ़कर 63 3 प्रतिशत तक पहुँच गया है। गैर संस्थागत अभिकरणों का कृषक परिवारों के ऋण में अंशदान निरन्तर कम होता जा रहा है।

सारणी 10 2 विभिन्न ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा कृषकों को वर्ष 1951-52 से 1981-82 के काल में प्राप्त कुल ऋण में प्रतिशत अंश प्रदर्शित करती है।

सारणी 10 2

कृषकों को प्राप्त ऋण में विभिन्न ऋणदात्री संस्थाओं का अंश

ऋणदात्री संस्था	कृषकों को कुल प्राप्त ऋण में संस्था का अंश			
	1951-52	1961-62	1971-72	1981-82
1	2	3	4	5
1 संस्थागत अभिकरण				
(i) सरकार	3 3	2 6	6 9	4 6
(ii) सहकारी समितियाँ	3 1	15 5	20 1	28 6
(iii) वाणिज्यिक बैंक	0 9	0 6	2 2	28 0
योग	7 3	18 7	29 2	61 2

1	2	3	4	5
2 गैर सस्थागत अभिकरणा				
(i) साहूकार—	69.7	49.2	36.9	16.9
(अ) कृषक साहूकार	2.9	36.0	23.1	8.6
(ब) पेशेवर साहूकार	44.8	13.2	13.8	8.3
(ii) जमींदार एवं भू स्वामी	1.5	0.6	8.6	4.0
(iii) व्यापारी एवं आदितिया	5.5	8.8	8.7	3.4
(iv) सम्बन्धी, मित्र एवं विविध स्रोत	16.0	22.7	16.8	14.5
योग	92.7	81.3	70.8	38.8
कुल	100	100	100	100

स्रोत (i) Reserve Bank of India, All India Rural Credit Survey, Vol I, Part 2, Bombay, 1957

(ii) Reserve Bank of India All India Rural Debt and Investment Survey, 1971-72, Bombay, 1977

(iii) Reserve Bank of India All India Debt and Investment Survey 1981-82 Bombay 1986

सारणी से स्पष्ट है कि उपरोक्त काल (1951-52 से 1981-82) में कृषकों को प्राप्त कुल ऋण में सस्थागत अभिकरणा से प्राप्त ऋण का प्रतिशत में वृद्धि एवं गैर सस्थागत अभिकरणों से प्राप्त ऋण के प्रतिशत में कमी आई है। वर्ष 1951-52 में सस्थागत अभिकरणों के कृषकों को प्राप्त कुल ऋण का 73 प्रतिशत अंश ही प्राप्त हुआ था जो बढ़कर वर्ष 1971-72 में 29.2 प्रतिशत एवं वर्ष 1981-82 में 61.2 प्रतिशत हो गया। सस्थागत अभिकरणा में वाणिज्यिक बैंक एवं सहकारी समितियों के प्रतिशत अंश में वृद्धि की गति अधिक रही है। गैर सस्थागत अभिकरणों द्वारा प्रदत्त ऋण के प्रतिशत अंश में निरन्तर कमी आई है। वर्ष 1951-52 में इनका कुल ऋण में प्रतिशत अंश 92.7 था, आबम होकर वर्ष 1981-82 में 38.8 ही रह गया। यह कमी साहूकारों द्वारा प्रदत्त ऋण की प्रतिशतता में निरन्तर कमी के कारण आ पाई है। साहूकारों द्वारा दिए गए ऋण की प्रतिशतता 69.7 स बम होकर मात्र 16.9 ही रह गई। अतः स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में वाणिज्यिक बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सहकारी समितियों की प्रगति भी उल्लेखनीय है। वर्तमान में कृषि क्षेत्र का प्राप्त ऋण में से लगभग दो तिहाई अंशदान सस्थागत अभिकरण प्रदान करते हैं।

सस्यागत अभिकरण

कृषि ऋण के क्षेत्र में सस्यागत अभिकरण दीर्घकाल से विद्यमान है। पूर्व में कृषि क्षेत्र में इनकी महत्ता कम थी, क्योंकि कृषि क्षेत्र को यह बहुत ही कम राशि में ऋण सुविधा उपलब्ध कराते थे। सरकार द्वारा किये गए प्रयासों के फलस्वरूप यह क्षेत्र भी कृषि क्षेत्र को निरन्तर अधिक राशि में ऋण सुविधा उपलब्ध करा रहा है, जिससे इनकी महत्ता में निरन्तर वृद्धि हुई है। पूर्व में कृषकों को जब सस्यागत अभिकरण आवश्यक मात्रा में ऋण उपलब्ध नहीं कराते थे, तो कृषक गैर सस्यागत अभिकरणों से अधिक ध्याज दर पर ऋण प्राप्त करते थे। सहकारी समितियों के विकास एवं वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रवेश करने के उपरान्त सस्यागत अभिकरणों का कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। सस्यागत अभिकरणों में सरकार द्वारा दिये जाने वाले कृषि ऋण नगण्य हैं। अतः इसमें सहकारी समितियाँ एवं वाणिज्यिक बैंक ही प्रमुख हैं।

सारणी 103 सहकारी समितियों एवं वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सम्मिलित रूप से दिये गये ऋण में से प्रत्येक का अंशदान एवं महत्ता प्रदर्शित करती है।

सारणी 103

सहकारी समितियों एवं वाणिज्यिक बैंकों का प्रदत्त ऋण में अंशदान
(प्रतिशत)

सस्या	1974-75		1980-81		1984-85	
	अल्पकालीन मध्य		अल्पकालीन मध्य		अल्पकालीन मध्य	
	ऋण	एवं दीर्घ- कालीन ऋण	ऋण	एवं दीर्घ- कालीन ऋण	ऋण	एवं दीर्घ- कालीन ऋण
सहकारी समितियाँ	83.69	69.27	68.69	43.59	64.15	29.68
वाणिज्यिक बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	16.31	30.73	31.31	54.41	35.85	70.32
कुल	100	100	100	100	100	100

स्रोत : D K Desai, Institutional Credit Requirements for Agricultural Production—2000 A D, Indian Journal of Agricultural Economics, Vol XLIII, No. 3, July-September, 1988, pp 326-355.

सारणी 10 4 देश में सस्थागत स्रोतों से कृषि क्षेत्र को उपलब्ध ऋण राशि प्रदर्शित करती है—

सारणी 10 4

सस्थागत स्रोतों से कृषि क्षेत्र को उपलब्ध ऋण राशि

(करोड़ रुपये)

वर्ष	सहकारी बैंक		वाणिज्यिक बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		कुल ऋण राशि
	ग्रहण	मध्यकालीन दीर्घकालीन ऋण	अल्पकालीन ऋण	योग	
1950-51	22 90	—	1 33	24 23	24 23
1960-61	182 82	19 93	11 60	214 35	214 35
1970-71	519 34	58 54	100 91	678 79	206 37
1980-81	1526.32	237 27	362 72	2126 31	745 83
1985-86	2746 87	393 00	542 76	3682 63	1424 16
1986-87	2833	529	540	3902	NA
1987-88	3116	613	599	4328	NA
1988-89	3513	381	719	4613	NA
1989-90	3654	416	744	4814	NA
1990-91	2066	317	804	3187	NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA
					NA

Source Economic Survey Ministry of Finance, Government of India, New Delhi.

अल्पसंख्यक ऋण के क्षेत्र में सहकारी समितियाँ प्रमुख स्रोत थी, जिन्होंने वर्ष 1974-75 में 83 69 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया था। वर्ष 1984-85 में इन्होंने मात्र 64 15 प्रतिशत ऋण की पूर्ति की है। दूसरी तरफ वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका में वृद्धि हुई है। इस प्रकार मध्य एवं दीर्घकालीन ऋण पूर्ति में सहकारी समितियों के अण्ड में कमी एवं वाणिज्यिक बैंकों के अण्ड में वृद्धि हुई है।

सारणी 10 4 में स्पष्ट है कि संस्थागत स्रोतों में कृषि क्षेत्र की उपलब्ध ऋण की राशि में निरन्तर वृद्धि हुई है। इन स्रोतों में वर्ष 1950-51 में कृषि क्षेत्र को मात्र 24 23 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया था, जो बढ़कर वर्ष 1990-91 में 10 368 करोड़ रुपये हो गया। सहकारी ऋण समितियों एवं वाणिज्यिक बैंकों का अण्ड 30 एवं 70 प्रतिशत है। वाणिज्यिक बैंकों राष्ट्रीयकरण के उपरान्त कृषि क्षेत्र का ऋण उपलब्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

कृषि ऋण के प्रमुख संस्थागत अभिकरण निम्न हैं -

(अ) सरकार

संस्थामय अभिकरणों में कृषि ऋण प्राप्ति का प्रमुख स्रोत सरकार है। सरकार द्वारा कृषकों को कृषि ऋण का ऋण दिया जाता है जिससे ऋण का तत्कालीन ऋण (Tactical loan) कहते हैं। तत्कालीन ऋण उस दिवस दिये गये ऋण से है जो सरकार द्वारा कृषकों को ऋण की बुवाई के समय दिया जाता है और फसल की कटाई के समय वसूल किया जाता है। इसका राष्ट्रीय कृषि आयोग ने उचित बतलाते हुए लिखा है कि साधारण उत्पादन वाले वर्ष में कृषकों की ऋण की आवश्यकता प्राचीन साहकारों से पूरी हो जाती है, लेकिन सूखा अथवा अन्य प्राकृतिक प्रकोपों के समय उनके पास उपलब्ध वित्त आवश्यकता से कम राशि में होता है। अतः कृषकों को सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। सरकार कृषकों को तत्कालीन ऋण निम्न दो अधिनियमों के अन्तर्गत प्रदान करती है जो कि अन्तर्गत आयोग 1880 के मुद्दों पर सरकार ने पारित किये थे¹—

- (1) भूमि सुधार अधिनियम 1883 (Land Improvement Loan Act)—इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार कृषकों को भूमि पर स्थायी सुधार—बुआ का निर्माण मेढर-दी भूमि को समतल करने सिंचाई के नियम नालियाँ बनाने भू संरक्षण आदि कार्यों के लिए दीर्घकालीन ऋण स्वीकृत करती है। उपर्युक्त प्रकार के ऋण स्वीकृत करने का प्रमुख उद्देश्य भूमि की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना है,

जिससे देश में खाद्यान्न-उत्पादन में वृद्धि हो सके। सरकार कृषकों को दीर्घकालीन ऋण भूमि की प्रतिभूति के आधार पर 25 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत करती है।

- (ii) कृषक ऋण अधिनियम, 1884—कृषक ऋण अधिनियम (The Agriculturists Loan Act, 1884) के अन्तर्गत सरकार कृषकों को बीज, खाद, उर्वरक, कृषि यन्त्र, पशु नय करने के लिए अल्प-कालीन ऋण स्वीकृत करती है। अल्पकालीन ऋण फसल की कटाई के उपरान्त तथा मध्यकालीन ऋण 4 से 5 वर्षों की अवधि में किरतो में देय होते हैं।

तत्कालीन ऋण कृषक को बीज, खाद, उर्वरक एवं पशुओं को क्रय करने, भूमि को समतल करने एवं भेड़ बनाने, भू संरक्षण कार्य करने, कुआ खोदने एवं मरम्मत करने, पम्पिंग सैंट अथवा रहट लगाने, सिंचाई की नालियाँ बनाने, बेकार भूमि को ठीक करने, कृषि यन्त्र एवं मशीनों को क्रय करने, उन्नत कृषि विधियों को अपनाने, पौध संरक्षण कार्य करने, बाग लगाने, पशुओं के लिए चारा खरीदने एवं बाड़ से हुए भवनों के नुकसान की मरम्मत करने आदि कार्यों के लिए स्वीकृत किये जाते हैं।²

तत्कालीन ऋण की प्रगति—सरकार ने वर्ष 1951-52 में कृषकों को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कुल ऋण का 33 प्रतिशत, 1961-62 में 26 प्रतिशत, 1971-72 में 69 प्रतिशत व 1981-82 में 48 प्रतिशत ऋण तत्कालीन ऋण के रूप में प्रदान किया था। तत्कालीन ऋण राज्य सरकारें अपनी-अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार स्वीकृत करती हैं। सारणी 10.5 में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में स्वीकृत तत्कालीन ऋण की राशि प्रदर्शित करती है।

सारणी 10.5

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में स्वीकृत तत्कालीन ऋण राशि

पंचवर्षीय योजना	स्वीकृत तत्कालीन ऋण (करोड़ ₹)
प्रथम पंचवर्षीय योजना	18.5
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	41.0
तृतीय पंचवर्षीय योजना	55.0
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	62.5

स्रोत : V V Desai, Agricultural Credit, Eastern Economist, Vol 67, No 2, July, 1976, p 86

2 Report of the Committee on Taccavi Loans and Co-operative Credit, Government of India, New Delhi, 1962, pp 12 II

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के काल में तकावी ऋण की स्वीकृत राशि में निरन्तर वृद्धि हुई है, लेकिन कुल स्वीकृत ऋण में तकावी ऋण का प्रतिशत बहुत कम है। इसके लिये प्रथम तो सरकार उत्सुक नहीं है, क्योंकि सरकार तकावी ऋण प्रसामान्य ढर्रे में ही अधिक स्वीकृत करती है। साथ ही कृषकों की ऋण की आवश्यकता को पूरा करने का सरकार का दायित्व भी नहीं है। कृषक भी तकावी ऋण रकम में विशेष इच्छुक नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें समय पर यह ऋण उपलब्ध नहीं होता है और प्राप्त ऋण की राशि स्वीकृत उद्देश्य के लिए अपर्याप्त होती है।

तकावी ऋण की प्रगति के आँकड़ा के विश्लेषण के आधार पर अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति इस परिणाम पर पहुँची थी कि तकावी ऋण का इतिहास कमियों का इतिहास है।³ सरकार के पास पर्याप्त धन न होना, वितरण में असमानता एवं समय पर ऋण उपलब्ध न होना इसकी प्रमुख कमियाँ हैं। समिति ने तकावी ऋण के लिए निम्न सिफारिशों की हैं—

- 1 तकावी ऋण कृषकों का मौज्जिम राशि में देना चाहिए।
- 2 तकावी ऋण आपातकालीन स्थिति जैसे—बाढ़, सूखा या अन्य आपत्ति के समय में ही स्वीकृत करना चाहिए।
- 3 तकावी ऋण एवं सहकारी ऋण में समन्वय होना चाहिए।
- 4 तकावी ऋण एवं सहकारी ऋण पर व्याज की दर समान होनी चाहिए।
- 5 देश में विषम आपातकालीन स्थिति के होने पर सहकारी समितियों के सदस्यों को ऋण-स्वीकृति में प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए।

सरकार ने वर्ष 1958 में निर्णय लिया कि देश में विषम आपातकालीन ऋणों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के ऋण कृषकों को सहकारी समितियों से उपलब्ध कराये जाने चाहिए। सहकारी ऋण समिति, 1960 ने भी सिफारिश की कि सरकार के पास उपलब्ध तकावी ऋण राशि सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिसमें सहकारी समितियाँ आवश्यक राशि में कृषकों को ऋण उपलब्ध करा सकें। सहकारी ऋण समिति के इस सुझाव की कार्यान्वित करने में होने वाली कठिनाई का अध्ययन करने के लिए जुलाई, 1961 में थो वी पी पटेल की अध्यक्षता में नियुक्त तकावी कर्ज एवं सहकारी ऋण समिति (Taccavi Loan and Co-operative Credit) ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं—

1. देश में आपातकालीन स्थिति में कृषकों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा तकावी ऋण स्वीकृत किया जाना चाहिए।

- 2 सहकारिता में पिछड़े हुए राज्यों—बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल में सहकारी विकास के लिए चुने गए जिलों में भूमि सुधार, कृषि उत्पादन आदि कार्यों के लिए तकावी ऋण बन्द कर देना चाहिए। धीरे-धीरे यह योजना दूसरे जिलों में लागू की जानी चाहिए, जिससे सहकारिता का विकास हो सके।
- 3 सरकार द्वारा कृषकों को भूमि सुधार एवं उत्पादन के लिए दी जाने वाली तकावी ऋण की जिम्मेदारी धीरे-धीरे सहकारी समितियों को सौंपी जानी चाहिए।
- 4 जब सहकारी समितियाँ कृषकों को भूमि सुधार एवं उत्पादन कार्यों के लिए दिए जाने वाले ऋण में प्रमुख समस्याएँ बन जायें, तब सरकार की तकावी ऋण की राशि को सहकारी समितियों को उपलब्ध करा देनी चाहिए।

तकावी ऋण में व्याप्त कमियाँ—तकावी ऋण में अनेक कमियों के कारण इसकी महत्ता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तकावी ऋण में प्रमुख कमियाँ ये हैं—

- 1 ऋण-राशि की अपर्याप्तता—सरकार विभिन्न उद्देश्यों के लिए बहुत कम राशि तकावी के रूप में स्वीकृत करती है। अतः तकावी ऋण-राशि प्राप्त उद्देश्य के लिए अपर्याप्त होती है।
- 2 ऋण स्वीकृत में अनावश्यक देरी—कृषकों को तकावी ऋण प्राप्त करने के लिए काफी समय तक इन्तजार करना होता है। कभी-कभी तो ऋण स्वीकृति में 3 से 6 माह का समय लग जाता है जिसके कारण कृषक स्वीकृत ऋण को प्राप्त उद्देश्य के लिए उपयोग में लाने में असमर्थ होते हैं।
3. कृषकों द्वारा स्वीकृत ऋण का प्राप्त उद्देश्यों के प्रतिरिक्त अन्य कार्यों में उपयोग कर लेना, जिससे उनकी भाय में आकलन के अनुसार वृद्धि नहीं होती है।
- 4 तकावी ऋण की वसूली का प्रतिशत कम होना—तकावी ऋण की राशि अनेक कारणों से समय पर वसूल नहीं हो पाती है, जिससे बकाया ऋण राशि निरन्तर बढ़ती जाती है तथा सरकार के पास भविष्य में ऋण स्वीकृति के लिए उपलब्ध राशि कम हो जाती है।
- 5 अन्य कारण जैसे—ऋण स्वीकृति एवं वितरण में विशेष समयान्तर होना, ऋण भुगतान का समय उत्पाद के विपणन के समयानुसार निर्धारित नहीं करना आदि भी इसकी प्रमुख कमी है।

अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण-जाँच समिति, 1969 ने अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया कि तकावी ऋण कृषकों को विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ कृषि कार्यों के लिए ऋण-उपलब्धि की पूर्ण व्यवस्था नहीं हो पाई है, उपलब्ध कराते रहना चाहिए। समिति के अन्य प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं—

- (i) तकावी ऋण उन्ही कार्यों के लिए स्वीकृत करना चाहिए जिनसे कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है तथा उन्ही क्षेत्रों में स्वीकृत करना चाहिए जहाँ पर या तो सहकारी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है अथवा वह कमजोर स्थिति में है।
- (ii) तकावी ऋण कृषकों को नकद राशि के रूप में नहीं दिया जाकर उत्पादन साधनों जैसे—बीज, उर्वरक, कृषि यन्त्र, कीटनाशी दवाइयों के रूप में दिया जाना चाहिए।
- (iii) सहकारी समितियों के सदस्यों एवं बकाया ऋण राशि वाले कृषकों को तकावी ऋण स्वीकृत नहीं करना चाहिए।
- (iv) तकावी ऋण पर ब्याज की दर, सहकारी समितियों के ऋण पर ब्याज की दर की अपेक्षा अधिक होनी चाहिए क्योंकि तकावी ऋण के लिए कृषकों को शेयर पूँजी जमा नहीं करानी होती है।
- (v) तकावी ऋण समय पर ऋण भुगतान करने वाले कृषकों को ही स्वीकृत करना चाहिए। जिन कृषकों पर पिछला ऋण बाकी है उन्हें नया तकावी ऋण स्वीकृत नहीं करना चाहिए।
- (vi) तकावी ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों को स्पष्ट कर देना चाहिए कि तकावी ऋण योजना एक या दो वर्ष के लिए है। अतः उन्हें सहकारी समितियों के सदस्य बनने को प्रेरित करना चाहिए।

(ख) सहकारी समितियाँ

संस्थागत ऋण अभिकरणों में दूसरी प्रमुख संस्था सहकारी समितियाँ हैं। वर्ष 1904 में सहकारी समितियाँ कानून पारित होने के पश्चात् कृषि ऋण के क्षेत्र में सहकारी समितियों का महत्व बढ़ता जा रहा है। देश में सहकारी समितियाँ स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य साहूकारों को ऋण व्यवसाय के क्षेत्र से प्रतिस्थापित करना रहा है। साहूकार कृषकों को अधिक ब्याज दर पर ऋण देते थे और ब्याज के अतिरिक्त अनेक प्रकार की कटौतियाँ भी काटते थे। सहकारी समितियाँ कृषकों को अल्प, मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋण देती हैं। समय के आधार पर स्वीकृत ऋण के अनुसार सहकारी समितियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है—

अल्प एवं मध्यकालीन ऋण—कृषकों को अल्प एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान करने वाली सहकारी ऋण समितियों का ढाँचा तीन स्तरीय होता है—

- (i) ग्राम स्तर पर—प्राथमिक सहकारी कृषि ऋण समितियाँ।

(II) जिला स्तर पर—जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक ।

(III) राज्य स्तर पर—राज्य/शेखर सहकारी बैंक ।

दोषकालीन ऋण—कृषकों को दोषकालीन ऋण भूमि विकास बैंक (पूर्व में भूमि-बन्धक बैंक) द्वारा प्रदान किया जाता है । भूमि विकास बैंक दो स्तर पर होते हैं—

(i) प्राथमिक भूमि विकास बैंक ।

(ii) केन्द्रीय भूमि विकास बैंक ।

सहकारी समितियों ने कृषकों को 1951-52 में कुल प्राप्त ऋण का 31 प्रतिशत अंश प्रदान किया था, जो 1961-62 में बढ़कर 15.5 प्रतिशत तथा 1981-82 में 28.6 प्रतिशत हो गया । वर्तमान में सहकारी ऋण समितियाँ कृषकों को कुल प्राप्त ऋण का 35 प्रतिशत अंश प्रदान कर रही हैं । इस प्रकार उपर्युक्त 40 वर्षों में सहकारी समितियों के द्वारा कृषकों का उपलब्ध कराए गए ऋण में 11 गुना वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी सहकारी समितियाँ निर्धारित उद्देश्य—सहकारियों को कृषि ऋण के क्षेत्र में से पूर्णरूप से प्रतिस्थापित करने में सफल नहीं हुई हैं ।

सहकारी ऋण की प्रगति—सहकारी ऋण की प्रगति सारणी 10.6 एवं 10.7 में प्रदर्शित की गई है ।

प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियाँ—देश में प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों की संख्या वर्ष 1950-51 में 1.04 लाख एवं 1960-61 में 2.12 लाख थी, जो बाद में उनके पुनर्गठन के फलस्वरूप कम होकर 1985-86 में मात्र 0.92 लाख हो गई । इन समितियों की सदस्य संख्या 44 लाख से बढ़कर उपर्युक्त काल में 722 लाख अर्थात् 16 गुना हो गई । सहकारी ऋण अभियान पूरी तरह गाँवों में प्रवेश कर गया है । वर्ष 1985-86 तक 99 प्रतिशत गाँव इस अभियान में सम्मिलित हो चुके हैं । समितियों की जमा धनराशि एवं कायशील पूँजी में भी द्रुतगति से वृद्धि हुई है । समितियों ने वर्ष 1950-51 में मात्र 22.90 करोड़ रुपये की ऋण राशि स्वीकृत की थी, जो बढ़कर 1981-82 में 1940 करोड़ रुपये तक पहुँच गई । समितियों की बकाया ऋण राशि वर्ष 1985-86 में 4323 करोड़ रुपये थी जो इनकी प्रगति में बाधक है ।

केन्द्रीय सहकारी बैंक—देश में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की संख्या वर्ष 1951-52 में 109 एवं उनकी शाखाएँ 779 थी । बैंकों के पुनर्गठन के कारण केन्द्रीय सहकारी बैंकों की संख्या वर्ष 1981-82 में 338 रह गई, लेकिन उनकी शाखाएँ 5598 हो गई । केन्द्रीय सहकारी बैंकों ने 1951-52 में 106 करोड़ रुपये की ऋण-राशि स्वीकृत की थी, जो बढ़कर 1985-86 में 7333 करोड़ रुपये हो गई । प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों की तरह इन बैंकों की बकाया ऋण राशि भी बहुत अधिक है । वर्ष 1985-86 में इनकी बकाया ऋण राशि 5444 करोड़ रुपये थी ।

सारणी 10 6

भारत में प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों की प्रगति

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	सहकारी वर्ष (जुलाई से जून)				
	1950-51	1960-61	1970-71	1981-82	1982-86
1 समितियों की संख्या (लाखों में)	1 05	2 12	1 61	0 95	0 924
2 समितियों के सदस्य संख्या (लाखों में)	44 08	170 41	309 63	607 11	721 77
3 समितियों में सम्मि- लित गाँव (प्रतिशत)	NA	75	95	97	99
4 समितियों के अन्तर्गत ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत	9	30	NA	47	60
5 प्रति समिति सदस्य संख्या	45	80	193	638	781
6 समितियों की जमा हिस्सा पूँजी	7.61	57 75	205 74	803	832
7 समितियों की जमा राशि	4 28	14 59	69 46	317	572
8 समितियों की कार्य- शील पूँजी	37 25	273 92	1153 40	NA	6548
9 समितियों द्वारा वर्ष में स्वीकृत ऋण राशि	22 90	202 75	577 88	1940	NA
10 समितियों की बकाया ऋण राशि	NA	NA	NA	2762	4323

स्रोत : (i) Indian Agriculture in Brief, 17th Edition, Directorate of Economics and Statistics, Ministry of Agriculture, Government of India, New Delhi, 1978, pp 226-227.

(ii) Reserve Bank of India—Report on Trend and Progress of Banking in India, 1982-83

(iii) Yojana, Vol. 32, No 13, 16-31 July 1988, p. 14

सारणी 10 7

भारत में सहकारी बैंकों की प्रगति

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	सहकारी वर्ष (जुलाई से जून)				
	1951-52	1960-61	1971-72	1981-82	1985-86
I केन्द्रीय सहकारी बैंक					
(1) सहायता	509	380	341	338	352
(2) शाखाएँ	779	1445	4317	5598	NA
(3) स्वयं की पूँजी	10	38	225	733	1007
(4) जमा पूँजी	38	111	509	2768	4932
(5) कार्यशील पूँजी	56	300	NA	5327	8663
(6) स्वीकृत ऋण राशि	106	351	NA	4059	7333
(7) बकाया ऋण राशि	36	218	889	3683	5444
II राज्य सहकारी बैंक					
(1) सहायता	16	21	26	27	29
(2) स्वयं की पूँजी	4	24	103	396	616
(3) जमा पूँजी	21	72	330	1888	3385
(4) कार्यशील पूँजी	NA	NA	NA	3275	5547
(5) स्वीकृत ऋण राशि	55	258	748	3541	5514
(6) बकाया ऋण राशि	20	NA	553	2430	3853

स्रोत . (i) S. S. M. Desai, Rural Banking in India, Himalaya Publishing House, Bombay, 1979

(ii) Reserve Bank of India-Report on Trend and Progress of Banking in India, 1982-83

(iii) Yojana, Vol 32, No 13, 16-31 July, 1988, p. 14

राज्य सहकारी बैंक—देश में वर्तमान में 29 राज्य सहकारी बैंक हैं जिनकी कार्यशील पूँजी 5547 करोड़ रुपये है। इन बैंकों ने वर्ष 1985-86 में 5514 करोड़ रुपये की ऋण राशि स्वीकृत की है। वर्ष 1985-86 तक राज्य सहकारी बैंकों की बकाया ऋण राशि 3853 करोड़ रुपये थी।

पाचवी पंचवर्षीय योजना में सहकारी ऋण समितियों के लिए 1300 करोड़ के मत्पकालीन ऋण, 325 करोड़ के मध्यकालीन ऋण एवं 1500 करोड़ के दीर्घ-कालीन ऋण स्वीकृति के लक्ष्य रखे थे, जिनमें से इन्होंने कमश 1164 करोड़,

208 करोड़ एवं 803 करोड़ रुपये के लक्ष्य प्राप्त किए। सहकारी ऋण समितियों ने अपने स्वीकृत ऋण में से 40 प्रतिशत ऋण लघु एवं सीमान्त कृषक एवं ग्रामीण कारीगरों को उपलब्ध कराया है।

जून 1979 के अन्त में सहकारी ऋण समितियों के पास 3064 करोड़ (1206 राज्य + 1654 केन्द्रीय + 204 प्राथमिक) रुपये की कुल जमा पूँजी थी जबकि इसी समय वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा पूँजी 30,000 करोड़ रुपये के लगभग थी। सहकारी ऋण समितियों की बकाया ऋण राशि के अधिक होने से इनके कार्य की गति में तीव्रता नहीं आ पा रही है। वर्ष 1985-86 में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की बकाया ऋण राशि कुल दिए गए ऋण की 37.8 प्रतिशत एवं प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों की 40.96 प्रतिशत थी जो बहुत ज्यादा है। वाणिज्यिक बैंकों की बकाया ऋण राशि भी वर्तमान में 45 प्रतिशत के लगभग है।

सभी राज्यों में सहकारी ऋण समितियों की प्रगति की गति समान नहीं है एवं उनमें बहुत क्षेत्रीय विषमता है। सहकारी ऋण की प्रगति के विभिन्न आँकड़ों के आधार पर राज्यों की तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—

- (i) सहकारी ऋण के क्षेत्र में विशेष प्रगति करने वाले राज्य—गुजरात, महाराष्ट्र एवं पंजाब।
- (ii) सहकारी ऋण के क्षेत्र में मध्यम प्रगति वाले राज्य—ग्राम्प्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु।
- (iii) सहकारी ऋण के क्षेत्र में पिछड़े राज्य—असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान तथा जम्मू एवं कश्मीर।

सहकारी समितियों ने अन्य प्रयास भी किये हैं जो इनकी प्रगति के सूचक हैं। सहकारी समितियों द्वारा उठाए गए विशेष कदम निम्न हैं—

- (अ) सहकारी ऋण के विकास एवं उत्पादन के आधार पर ऋण स्वीकृत करने के लिए फसल ऋण योजना निर्धारित की गई एवं कार्यान्वित की गई।
- (ब) लघु कृषकों को सहकारी समितियों के द्वारा ऋण स्वीकृति में प्राथमिकता देने के लिए कदम उठाए गए।
- (स) सहकारी समितियों के माध्यम से सदस्यों में बचत करने की भावना जागृत करने की कोशिश की गई है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक धन एकत्रित हो सके।
- (द) सहकारी आधार पर उद्योगों में विशेषतः चीनी उद्योग के क्षेत्र में उत्प्रेरणीय प्रगति हुई है।

ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति के अनुसार सहकारी समितियाँ निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही हैं, लेकिन राष्ट्र के विकास के लिए सहकारिता को बढ़ावा देना आवश्यक है। सर्वेक्षण समिति ने अपने प्रतिवेदन में सहकारी समितियों की विफलता के निम्न कारण बतलाये हैं—

- (I) सहकारिता के ढाँचे एवं प्रशासन में कमियों का होना।
- (II) सहकारिता के विकास के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओं का अभाव होना।
- (III) कृषकों में शिक्षा का अभाव होना।
- (IV) सहकारी समितियों की साहूकारों से प्रतिस्पर्धा तथा उनसे विरोध।
- (V) सहकारी समितियों के पास सभी कृषकों की ऋण आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त धनराशि का न होना।
- (VI) कृषकों एवं कार्यकर्त्ताओं का सहकारिता में विश्वास न होना।
- (VII) सहकारी समितियों के कार्यकर्त्ताओं द्वारा ऋण स्वीकृति में लघु कृषकों की उपेक्षा करना।

उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त निम्न अपर्याप्तताएँ भी सहकारी ऋण के क्षेत्र में बाधक रही हैं—

- (I) अनेक प्राथमिक सहकारी ऋण समितियाँ वर्तमान में सबल व सक्षम नहीं हैं और वर्तमान कार्य क्षेत्र को देखते हुए उनके सक्षम होने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है।
- (II) सहकारी समितियाँ कृषकों को समय पर ऋण-सुविधा उपलब्ध कराने में भी असफल रही हैं।
- (III) सहकारी समितियों द्वारा स्वीकृत उत्पादन ऋण, आवश्यकता से कम राशि में होता है।
- (IV) कृषकों पर ऋण की बढ़ती राशि के निरन्तर बढ़ने से अनेक राज्य में सहकारी ऋण समितियों के पास ऋण-स्वीकृति के लिए उपलब्ध धनराशि बहुत कम रह गई है।
- (V) सहकारी ऋण समितियों एवं उत्पादन-साधनों की पूर्ति करने वाली संस्थाओं में समन्वय नहीं होना भी इनकी प्रगति में बाधक है।

अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण जाँच-समिति, 1969 ने देश में सहकारी ऋण के विकास के लिए निम्न उपायों को अपनाने के सुझाव दिये थे—

1 जिन क्षेत्रों में सहकारी विकास की गति धीमी रही है, उन क्षेत्रों में सहकारी विकास के लिए विशेष प्रयास किये जाने चाहिए।

इस विषय पर समय-समय पर अनेक समितियों ने भी इसके पूर्व सुझाव दिये थे। कृषि ऋण के सत्सागत व्यवस्था पर अनौपचारिक दल, 1962-63 (The

Informal Group on Institutional Arrangement for Agricultural Credit) ने सहकारिता में पिछड़े राज्यों—विशेषकर राजस्थान, असम, उड़ीसा, बिहार एवं पश्चिमी बंगाल में सहकारी समितियों के विकास के लिए विशेष कदम उठाए जाने के सुझाव दिये थे। इनमें से एक सुझाव राज्यों में कृषि ऋण निगम स्थापित करने का था, जिसे कृषकों को फसल उत्पादन के लिए ऋण स्वीकृत करने के साथ-साथ राज्यों में सहकारिता के विकास के लिए प्रयास भी करना था। राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा सितम्बर 1968 में आयोजित सेमिनार के परिणामों के अनुसार कृषि-ऋण निगम बनाने से सहकारी ऋण के क्षेत्र में कोई विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि सहकारी समितियों एवं कृषि ऋण-निगमों के कार्य क्षेत्र में विशेष अंतर नहीं है। सहकारिता के विकास के लिए सहकारिता के ढाँचे में सुधार करने की आवश्यकता है, जिसके लिए सेमिनार में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये गये—

- (i) सहकारी समितियों द्वारा दिए जाने वाले ऋण में व्याप्त अपर्याप्तता के दोष को दूर करने के लिए उनके वित्तीय साधनों में वृद्धि एवं बकाया ऋण की वसूली के प्रयास किये जाने चाहिए।
- (ii) कमजोर वित्तीय स्थिति एवं प्रबन्ध वाले केन्द्रीय सहकारी बैंक जो कृषकों के ऋण पूर्ति के दायित्व को पूर्ण रूप से निभा नहीं पा रहे हैं उनका पुनर्गठन करके आवश्यक वित्त सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
- (iii) केन्द्रीय बैंक, जो बकाया ऋण राशि के कारण कृषकों की ऋण पूर्ति में सफल नहीं हो सके हैं उनको सरकार द्वारा दीर्घकाल के लिए जमा राशि प्रदान की जानी चाहिए।
- (iv) सहकारी समितियों के प्रबन्ध में सुधार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सहकारी बैंक के अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।
- (v) सहकारी समितियों/बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण की वसूली एवं उनकी काय प्रणाली में सुधार करने के प्रयास किए जाने चाहिये।

2 असरय छोटी छोटी समितियाँ जो आर्थिक दृष्टिकोण से सक्षम नहीं हैं, उनके पुनर्गठन द्वारा एक बड़ी सहकारी समिति का निर्माण किया जाना चाहिए। एक सक्षम समिति वह है जो प्राप्त आय से कार्यकर्ताओं को वेतन भुगतान, भवन किराया एवं अन्य लागत का भुगतान करके, शिक्षा एवं अन्य सामाजिक उद्देश्यों के लिए सहायता प्रदान करने, रिजर्व कोष में एक निश्चित राशि जमा करने के पश्चात् सदस्यों को उनकी हिस्सा पूँजी पर उचित लाभ की रशि प्रदान करने में सक्षम होती है। इसके लिए आवश्यक है कि विभिन्न राज्यों में सहकारी समितियों की

सवलता के लिए व्याप्त आचारों में समानता हो। सर्वेक्षण द्वारा जो समितियाँ समय नहीं हैं उनका पता लगाया जाये तथा उनको सबल व समर्थ बनाने के लिए कार्यक्रम किये जाएँ।

3 सहकारी समितियों की ऋण नीति एवं कार्य प्रणाली में परिवर्तन करना

सहकारी समितियों की ऋण नीति एवं कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए जाँच समिति ने निम्न प्रमुख सुझाव दिए हैं।

- (i) कृषकों को ऋण उनकी आवश्यकता एवं भुगतान-क्षमता के अनुसार स्वीकृत करना चाहिए। सघु कृषकों को ऋण स्वीकृति में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऋण राशि के अनुसार व्याज-दर में भिन्नता होनी चाहिए।
- (ii) कृषकों को स्वीकृत ऋण का अधिक भाग नकद राशि के रूप में नहीं दिया जाकर उत्पादन-साधनों के रूप में दिया जाना चाहिए।
- (iii) कृषकों को ऋण फसल की बुवाई के पूर्व उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- (iv) ऋण उपलब्ध कराने की विधि को सरल बनाना चाहिए, जिससे ऋण प्राप्ति में कृषकों को कठिनाई महसूस नहीं हो।
- (v) भूमि बन्धक में आने वाली कठिनाइयों के कारण कृषकों का अल्प-कालीन ऋण उनके द्वारा ली गई फसल की प्रतिभूति के आधार पर दिया जाना चाहिए।

4 कृषकों पर बढ़ती हुई बकाया ऋण राशि की बसूली के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। समिति ने बकाया ऋण राशि की बसूली के लिए निम्नांकित सुझाव दिये थे—

- (i) कृषकों में शिक्षा द्वारा भावना जागृत करनी चाहिये कि वे प्राप्त ऋण का स्वीकृत उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में उपयोग नहीं करें।
- (ii) सहकारी ऋण एवं विपणन में सामाजिक स्थापित करना चाहिए।
- (iii) कृषकों में समय पर ऋण भुगतान करने की आदत डालनी चाहिए तथा समय पर ऋण भुगतान करने वालों को व्याज एवं अन्य प्रकार की छूट देनी चाहिए।
- (iv) सहकारी समितियों के कार्यकर्त्ताओं द्वारा ऋण बसूली के लिए अधिक प्रयास किये जाने चाहिए।

ग्राम विकास बैंक

सहकारी समितियों के पञ्जीयक अधिकारियों के सम्मेलन, 1926, कृषि रॉयल कमीशन, 1928 एवं केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति के मुताबिक के अनुसार देश

में भूमि विकास बैंको की स्थापना की गई। पहले ये भूमि बन्धक बैंक कहलाते थे। इन बैंको की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य कृषकों को भूमि विकास कार्यों जैसे—फार्म पर सिंचाई के लिए कुओं के निर्माण, फार्म पर नालियाँ एवं पम्प घर निर्माण, पम्पिंग सेट लगवाने, ट्रैक्टर, पावर-टिलस, स्प्रेयर्स, डस्टर्स, कम्बाईन्स, ग्रैंसर आदि मशीनों के त्रय के लिए दीर्घकालीन ऋण स्वीकृत करना है। भूमि विकास बैंक कृषकों को पुराने कर्जों से मुक्ति भी दिलाते हैं। भूमि विकास बैंक कृषकों की भूमि को बन्धक रखकर दीर्घकालीन ऋण स्वीकृत करते हैं। कुछ राज्यों में भूमि विकास बैंक कृषकों की भूमि के अतिरिक्त अन्य स्थायी सम्पत्ति जैसे मकान बन्धक रखकर भी ऋण स्वीकृत करते हैं। वर्तमान में ये बैंक कृषकों द्वारा त्रय किये गये यन्त्र, जैसे—ट्रैक्टर, ग्रैंसर, पावर टिलर आदि को बन्धक रखकर भी ऋण स्वीकृत करते हैं।

भूमि विकास बैंको का ढाँचा सभी राज्यों में समान नहीं है। कुछ राज्यों में इन बैंको का ढाँचा राष्ट्रीय स्तर का है अर्थात् राज्य-स्तर पर केन्द्रीय भूमि-विकास बैंक तथा जिले एवं उसके नीचे के स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक होते हैं। अन्य राज्यों में इनका ढाँचा एकात्मक होता है अर्थात् भूमि विकास बैंक केन्द्रीय स्तर पर होते हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों में उनकी शाखाएँ होती हैं।

भूमि विकास बैंको से ऋण प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम कृषकों को प्रार्थना-पत्र मय आवश्यक दस्तावेजों जैसे—भूमि पर स्वामित्व का प्रमाण-पत्र, भूमि का मान-चित्र, भूमि का ऋण मार से मुक्ति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है। प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की जाँच करके भूमि विकास बैंक ऋण स्वीकृत करते हैं। बन्धक की गई सम्पत्ति की 50 प्रतिशत कीमत राशि ऋण के रूप में स्वीकृत की जाती है। ऋण स्वीकृति की अधिकतम अवधि 20 वर्ष होती है। भूमि विकास बैंक स्वीकृत ऋण पर कृषकों से, ऋण-पत्रों पर दी गई व्याज की दर से एक प्रतिशत अधिक वसूल करते हैं।

भारत में भूमि विकास बैंको की प्रगति सारणी 10 8 में प्रदर्शित है।

सारणी 10 8

भारत में भूमि विकास बैंकों की प्रगति

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सन्कारी वर्ष (जुलाई से जून)					
	1951—	1961—	1968—	1975—	1981—	1985—
	52	62	69	76	82	86
I प्राथमिक भूमि विकास बैंक						
1 बैंकों की संख्या	289	536	740	890	NA	1800
2 सदस्य संख्या (लाखों में)	214	852	2800	2622	NA	3468

3 शेयर पूँजी	0 58	2 83	25.26	631 16	NA
4. उधार प्राप्त पूँजी	6.84	34 29	277 90	569 28	NA
5 कार्यशील पूँजी	7.59	38 51	309 76	704 22	NA
6 स्वीकृत ऋण राशि वर्ष में	1 30	12 59	103 76	136 09	NA
7. बकाया ऋण राशि	6 96	38 28	285 56	576 70	NA
II राज्य/केन्द्रीय भूमि विकास बैंक					
1 बैंको की सहायता	8	17	19	19	19
2 सदस्य सहायता (लाखों में)	0 34	2 99	11 71	NA	NA
3 शेयर पूँजी	0.44	5 37	30 90	164 00	326
4 ऋण-पत्र बकाया (Debenture outstanding)	7.83	47 74	426 11	1591	2135
5. कार्यशील पूँजी	NA	NA	NA	1918	2637
6 स्वीकृत ऋण राशि वर्ष में	2.51	14 75	143 62	249	369
7 बकाया ऋण राशि	8 05	47 90	395 06	1211	1855

स्रोत : (i) S.S.M. Desai, Rural Banking in India, Himalaya Publishing House, Bombay, 1979

(ii) Reserve Bank of India—Report on Trend and Progress of Banking in India, 1982-83.

भूमि विकास बैंक वर्ष 1961-62 तक पिछड़ी अवस्था में थे। उसके बाद उनकी प्रगति विशेष रूप से उल्लेखनीय रहती है। देश में प्राथमिक भूमि विकास बैंको की सहायता वर्ष 1951-52 में 289 थी, वह बढ़कर 1985-86 में 1800 हो गई। वर्तमान में भूमि विकास बैंक 2100 शाखाओं के माध्यम से (जो खण्ड/तहसील एवं तालुका

स्तर पर है) कृषकों को दीर्घकालीन ऋण-सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। अब तक भूमि विकास बैंको द्वारा कृषकों को 3000 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये जा चुके हैं। स्वीकृत ऋण में से 70 प्रतिशत लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिए एव शेष 30 प्रतिशत अन्य कार्य जैसे—भूमि समतल करने, बाड़ लगाने एवं भूमि को बन्धनों से मुक्त कराने के लिए स्वीकृत किये गये है।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा मार्च, 1973 में श्री के माधवदास की अध्यक्षता में नियुक्त समिति का सुझाव था कि प्रत्येक राज्य में भूमि विकास बैंको का विकास किया जाना चाहिए। इसके लिये प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से वचत का इनमें संचालन करने का सुझाव भी दिया था। समितियों ने यह भी सुझाव दिया कि भूमि बन्धक रखने के स्थान पर उद्देश्य की सफलता के आधार पर ऋण स्वीकृत किया जाना चाहिये।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, देश में कार्यरत भूमि विकास बैंकों के कार्य में सुधार लाने के लिये निरन्तर प्रत्यनशील है जिससे ये बैंक विकास कार्यों हेतु ऋण प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका दक्षतापूर्वक निभा सकें। अतः राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने इनके कार्यरत ढाँचे में वित्तीय एवं कानूनन परेशानियों को दूर करने की आवश्यकता महसूस की तथा इनके अध्ययन हेतु एक उच्चस्तरीय कार्यदल का गठन 2 जनवरी, 1985 का किया है। इस कार्यकारी दल के प्रमुख कार्य निम्न हैं—

- (i) इस बात का पता लगाना है कि क्या भूमि विकास बैंक अपने निहित कार्यों को सक्षमतापूर्वक पूरा कर रहे हैं अथवा उनकी कार्य-विधि में क्या परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता है ?
- (ii) उनके वर्तमान संगठन, ढाँचे, वित्तीय साधनों एवं कानूनन पहलुओं का अध्ययन करते हुए, उनके अधिक सक्षमतापूर्वक कार्य करने हेतु सुझाव देना।
- (iii) भूमि विकास बैंकों को ऋण वसूल करने, ऋण की देखभाल, वित्तीय साधन जुटाने एवं ऋण योजनाओं की जाँच हेतु आवश्यक कानूनन सुझाव देना, जिससे वे निर्धारित कार्यों के लिए अधिक ऋण सुविधा उपलब्ध करा सके।
- (iv) राज्य के भूमि विकास बैंको एवं अन्य सहकारी ऋण संस्थानों के कार्य में समन्वय स्थापित करने हेतु सुझाव देना।

(v) राज्य स्तरीय भूमि विकास बैंक एवं प्राथमिक स्तर के भूमि विकास बैंको की वर्तमान व्याज दर, सीमान्त राशि की जाँच करना एवं उसमें उनके कार्य को देखते हुये परिवर्तन करने के सुझाव देना।

(स) वाणिज्यिक बैंक :

कृषको को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने वाले सस्थागत अभिकरणों में तृतीय सस्था वाणिज्यिक बैंक हैं। बैंको ने कृषि व्यवसाय के लिये ऋण प्रदान करने में निरन्तर उपेक्षा बरती है। कृषको को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कुल ऋण में से वर्ष 1951-52 में 0.9 प्रतिशत अंश वाणिज्यिक बैंको से प्राप्त हुआ था। यह अंश वर्ष 1961-62 में कम होकर मात्र 0.6 प्रतिशत रह गया। वर्ष 1971-72 में वाणिज्यिक बैंको ने कृषको को प्राप्त कुल ऋण में से 22 प्रतिशत अंश प्रदान किया है। तत्पश्चात् वाणिज्यिक बैंको की प्रगति सराहनीय रही है।

वाणिज्यिक बैंको द्वारा प्रदत्त कुल ऋण का 2.5 प्रतिशत से कम अंश कृषि क्षेत्र को बैंक राष्ट्रीयकरण के पूर्व प्राप्त हुआ है, जबकि उद्योग एवं व्यापार को उपर्युक्त काल में 84 से 90 प्रतिशत अंश प्राप्त हुआ है।⁶ कृषि क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंको द्वारा प्रदत्त ऋण का अधिकांश भाग चाय, काफी, रबर के बागान वाले कृषको को प्राप्त हुआ है। वाणिज्यिक बैंको द्वारा कृषि क्षेत्र में ऋण स्वीकृति के लिए तत्पर नहीं होने के प्रमुख कारणों में कृषि व्यवसाय का मौसम पर निर्भर होना, देश में अस्खल लघु कृषको का होना, कृषको द्वारा ऋण प्राप्ति के लिये उचित प्रतिभूति नहीं दे पाना, क्षेत्र में ऋण सुविधा उपलब्ध कराने वाली सस्थाओं में सहयोग की भावना नहीं होना, बैंको के कार्यकर्त्ताओं की कृषि व्यवसाय के प्रति अज्ञानता एवं बैंको के प्रबन्धक व्यवसाय एवं उद्योगों से सम्बन्धित होने के कारण व्यवसायियों को प्राथमिकता देना है।

वाणिज्यिक बैंको द्वारा कृषि क्षेत्र की ऋण स्वीकृति में उपेक्षा बरती जाने एवं देश में कृषि व्यवसाय की बढ़ती हुई महत्ता के कारण सरकार ने वर्ष 1968 में बैंक सामाजिक नियन्त्रण कानून पारित किया। बैंक सामाजिक नियन्त्रण कानून निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हो सका। अतः सरकार ने 19 जुलाई, 1969 को देश के चौदह बड़े बैंको के राष्ट्रीयकरण के लिये अध्यादेश जारी किया। इस अध्यादेश का प्रमुख उद्देश्य कृषि, लघु उद्योगों एवं अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को वाणिज्यिक बैंको से अधिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराना था, जिससे ये क्षेत्र भी अन्य क्षेत्रों के समान विकसित हो सकें। इसके अतिरिक्त अप्रलिखित कारणों से भी वर्तमान में वाणिज्यिक बैंको का कृषि-व्यवसाय के क्षेत्र में प्रवेश आवश्यक हो गया था—

1. कृषि क्षेत्र में ऋण प्रदान करने वाले सस्थागत अभिकरणों में सहकारी समितियों के पास धन की अपर्याप्तता के कारण वे कृषकों की ऋण की आवश्यकता को पूरी कर पाने में सक्षम नहीं हैं। सरकार तत्कालीन ऋण पर प्रायः पाबन्दी लगा देती है। अतः सस्थागत अभिकरणों में कृषकों की ऋण आवश्यकता की पूर्ति के लिये वाणिज्यिक बैंक ही शेष रहते हैं। इनके पास पर्याप्त राशि में धन होने के कारण, ये कृषकों की ऋण की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम हैं।
2. कृषि में हरित-क्रान्ति के कारण कृषकों की उन्नत बीज, उर्वरक, उन्नत औजार, सिंचाई के लिये पम्पिंग सेट, कीटनाशी दवाइयाँ आदि के क्रय के लिये धन की आवश्यकता पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ गई है। ऋण की बढ़ती हुई आवश्यकता को सहकारी समितियों द्वारा पूरा कर पाना सम्भव नहीं है। अतः हरित-क्रान्ति की सफलता के लिये ऋण की पूर्ति हेतु कृषि क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों का प्रवेश आवश्यक हो गया है।
3. सहकारी समितियों ने बड़े कृषकों को ही ऋण-सुविधा अधिक उपलब्ध कराई है। लघु कृषक बहुत ही कम राशि में सहकारी समितियों से ऋण-सुविधा प्राप्त कर पाये हैं। अतः देश के अधिकांश लघु कृषकों को पर्याप्त राशि में समय पर ऋण-सुविधा उपलब्ध कराने के लिये भी वाणिज्यिक बैंकों का कृषि क्षेत्र में प्रवेश करना आवश्यक है।
4. कृषि व्यवसाय के कुछ उद्योगों में जैसे—पशु-पालन, दूध उद्योग, चाय, काफ़ी, रबर, काजू, नारियल, अमूर आदि के बाग लगाने के लिये पूँजी की अधिक आवश्यकता होती है और साथ ही इन उद्योगों में निवेश की गई पूँजी से आय बहुत वर्षों के पश्चात् प्राप्त होना शुरू होती है। अतः ऐसे उद्योगों को पर्याप्त ऋण-सुविधा उपलब्ध कराने के लिये वाणिज्यिक बैंक एक मात्र स्रोत माने गये हैं।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को प्रदान किये जाने वाले ऋण दो प्रकार के होते हैं—

- (अ) प्रत्यक्ष ऋण-सुविधा—इसके अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंक कृषकों को कृषि कार्यों के लिये अल्पकालीन तथा कृषि में पूँजी निवेश कार्यों के लिये मध्य एवं दीर्घकालीन ऋण स्वीकृत करते हैं।
- (ब) अप्रत्यक्ष ऋण-सुविधा—इसके अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंक कृषकों को सीधे रूप में ऋण स्वीकृत नहीं करते हैं, बल्कि वे कृषि उद्योग निगम, राज्य विद्युत् मण्डल, कृषि यन्त्र सेवा-केन्द्र आदि को ऋण उपलब्ध कराते हैं, जो कृषकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान करते हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा कृषि क्षेत्र को अधिक ऋण-सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए किये गये प्रयास :

भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंको द्वारा कृषि क्षेत्र को अधिकाधिक ऋण-सुविधा उपलब्ध कराने के लिये अनेक उपाय अपनाये गये हैं जिनमें से प्रमुख निम्न हैं—

1 बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण (Social Control Over Banks) :

भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था में समाजवादी समाज की रचना (Socialistic Pattern of Society) के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समाज आधारभूत एवं सेवा उद्योगों का संचालन एवं नियन्त्रण सरकार के हाथ में होना आवश्यक है। बैंक भी जनोपयोगी उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। अतः इस तथ्य को दृष्टिकोण में रखते हुए दिसम्बर, 1968 में बैंको पर सामाजिक नियन्त्रण स्थापित करने का विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया। बैंको पर सामाजिक नियन्त्रण से अभिप्राय सरकार द्वारा बैंको पर अतिरिक्त प्रतिबन्ध लगाने से है जिससे बैंक अधिक से अधिक सामाजिक हित में कार्य करे। इसके अन्तर्गत बैंकों की नीति को सरकार की नीति के अनुकूल किया जाता है, जिसमें रिजर्व बैंक अपने नियन्त्रण के अधिकारों का अधिक उपयोग कर सके।

सामाजिक नियन्त्रण का उद्देश्य बैंको द्वारा ऋण प्रदान करने की नीति में परिपर्तन करना है। बैंको पर सामाजिक नियन्त्रण द्वारा उन क्षेत्रों को अधिक ऋण-सेवा उपलब्ध कराना है जिनकी अब तक उपेक्षा की गई थी जैसे—कृषि, लघु-उद्योग, कुटीर-उद्योग आदि। इस नीति का उद्देश्य देश के सभी उद्योगों को समान रूप से विकसित करना था। वर्तमान में कृषि उद्योग को ऋण-सुविधा उपलब्ध कराने में वाणिज्यिक बैंकों ने कोई प्रयास नहीं किया है। कृषि देश का प्रमुख उद्योग है, जिसका विकास करना आवश्यक है।

बैंको पर सामाजिक नियन्त्रण से लाभ :

- 1 देश के सभी उद्योगों को समान रूप से ऋण-सुविधा उपलब्ध कराना, जिससे देश का सन्तुलित विकास हो सके।
- 2 देश की मौद्रिक नीति पर नियन्त्रण करना।
- 3 भुद्रा-स्फीति पर नियन्त्रण करना।
- 4 सदृशाजी के कार्यों के लिए बैंको द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर पाबन्दी लगाना। आवश्यक वस्तुओं की कमी होने पर उनकी प्रति-भूति पर ऋण स्वीकृत नहीं करना।

2. बैंक राष्ट्रीयकरण (Nationalization of Banks) :

सरकार द्वारा बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण करने के उपरान्त भी वाणिज्यिक बैंको ने कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए ऋण स्वीकृति में

प्राथमिकता नहीं दी। इसका प्रमुख कारण वाणिज्यिक बैंको का परम्परागत उद्योग-पतियो एवं व्यापारियों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध का होना है। बैंको का सामाजिक नियन्त्रण विधेयक अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हुआ। अतः सरकार ने कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योगों की ऋण की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बैंको के राष्ट्रीयकरण का कदम उठाया। बैंक राष्ट्रीयकरण देश को समाजवाद की ओर अग्रसर करने का एक कदम माना गया है।

बैंको के राष्ट्रीयकरण से तात्पर्य बैंको पर किसी व्यक्ति विशेष का नियन्त्रण न रखकर सरकार के सीधे नियन्त्रण में रखने तथा बैंको का कार्य-संचालन सरकार की नीति के अनुसार करने से है। बैंक राष्ट्रीयकरण के अन्तर्गत बैंकिंग कंपनियों के संचालकों को उनके हिस्से पूँजी के मूल्य मुग्तान करके सरकार बैंको पर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करती है। बैंको के राष्ट्रीयकरण की नीति का मुख्य उद्देश्य निम्न वर्ग के व्यक्तियों (लघु कृषक, सीमान्त कृषक, मजदूर, कारीगर) की सहायता करना है जिससे ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में सुधार हो सके एवं कुटीर उद्योगों का विकास हो सके। इससे आर्थिक प्रगति एवं सामाजिक न्याय प्राप्त हो सकेगा।

देश के चौदह बड़े वाणिज्यिक बैंको के राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा 19 जुलाई, 1969 को राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा की गई। इस अध्यादेश ने 9 अगस्त, 1969 को कानून का रूप धारण किया। इस अध्यादेश द्वारा देश के उन चौदह बड़े बैंको का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी 31 दिसम्बर, 1968 को जमा राशि 50 करोड़ रुपये से अधिक थी। इन राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंको के पास समूचे बैंकिंग क्षेत्र की 58 प्रतिशत जमा-राशि थी। स्टेट बैंक एवं उसके सहायक बैंको की जमा-राशि को सम्मिलित करते हुए भारतीय बैंक व्यवस्था की 85 प्रतिशत जमा-राशि पर राष्ट्रीयकरण से सरकार का सीधा नियन्त्रण हो गया। सरकार ने उपर्युक्त अध्यादेश में विदेशी बैंको को सम्मिलित नहीं किया क्योंकि विदेशों से व्यापार करने के लिए दूसरे देशों में भारतीय बैंको की शाखाओं का पर्याप्त रूप से विस्तार नहीं था।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1969 को 10 फरवरी, 1970 को अवैध घोषित कर दिये जाने के कारण, राष्ट्रपति ने 14 फरवरी, 1970 को देश के चौदह बड़े बैंको का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई, 1969 से पुनः घोषित करने का अध्यादेश जारी किया। राष्ट्रीयकरण किये गए चौदह वाणिज्यिक बैंक—सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, कनारा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया, देना बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, इसाहाबाद बैंक, सिड्डीकेट बैंक, इण्डियन प्रोविडेंट बैंक, इण्डियन बैंक, एवं बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैं। इनमें 31 दिसम्बर, 1968 को

सर्वाधिक जमा-राशि सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की 433 करोड़ रुपये व सबसे कम जमा-राशि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 73 करोड़ रुपये थी। सर्वाधिक बैंक शाखाओं में पंजाब नेशनल बैंक अग्रणी था। स्थापन वर्ष की दृष्टि से सबसे पुराना राष्ट्रीयकृत बैंक इलाहाबाद बैंक है जिसकी स्थापना 1865 में हुई थी।

सरकार ने 15 अप्रैल, 1980 को 6 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। हाल में राष्ट्रीयकरण किये गये 6 बैंक—विजया बैंक, ग्रामिणा बैंक, ओरियन्टल कामर्सियल बैंक, पंजाब एव सिन्ध बैंक, कोरपोरेशन बैंक एव न्यू बैंक ऑफ इण्डिया हैं। इस प्रकार अब राष्ट्रीयकरण किये गए बैंकों की सख्या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एव उसके सहायक बैंकों के अतिरिक्त 20 हो गई है। सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एव उसके सहायक बैंक सम्मिलित रूप से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का 82.6 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र में आ गया है। इसी प्रकार वर्ष 1978 के अन्त तक 91 प्रतिशत जमा एव स्वीकृत राशि सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत आ गई थी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रगति

राष्ट्रीयकरण के उपरान्त आभीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं में विस्तार, जमा राशि में वृद्धि, कृषि एव प्राथमिक क्षेत्रों को अधिक राशि में ऋण उपलब्ध कराने से बैंकों की गति में तीव्रता आई है। बैंकों की प्रगति का संक्षिप्त विवरण निम्न है—

(अ) बैंक शाखाओं का विस्तार—सारणी 10.9 वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का विस्तार शहरीकरण के आधार पर प्रदर्शित करती है—

सारणी 109
वाणिज्यिक क्षेत्रों की भाषाओं का विस्तार

शहरीकरण के आधार पर क्षेत्र	राष्ट्रीयकरण से पूर्व जून 1969	जून, 1979	जून, 1988	माघ, 1992	जून 1969 से माघ 1988 के मध्य में विस्तार
1. ग्रामीण क्षेत्र (दम हज़ार जगहों पर)	1,833 (22.2)	13,337 (44.2)	31,114 (56.1)	35,218 (58.0)	33,385 (63.68)
2. घट्टे शहरी क्षेत्र (दम हज़ार में एक लाख जगहों पर रातो क्षेत्र)	3,342 (40.4)	7,889 (26.1)	11,132 (20.1)	11,397 (18.8)	8,055 (15.36)
3. शहरी क्षेत्र (एक से दस लाख जनसंख्या वाले)	1,584 (19.1)	5,039 (16.7)	7,322 (13.2)	14,077 (23.2)	10,990 (20.96)
4. राजधानी क्षेत्र (दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले)	1,503 (18.2)	3,939 (13.0)	5,842 (10.6)		
कुल	8,262 (100)	30,202 (100)	55,410 (100)	60,692 (100)	52,430 (100)

नोट: 1. दम हज़ार क्षेत्रों में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों का प्रतिफल है।

स्रोत : Pigmy Economic Review, Vol 38 (No 2, 4 & 5), September 1992 and November-December 1992.

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पूर्व देश में जून, 1969 में मात्र 8,262 बैंक शाखाएँ थी, जो बढ़कर मार्च 1992 में 60,692 हो गई। राष्ट्रीयकरण के उपरान्त वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं में तीव्र गति से विस्तार हुआ है। यह विस्तार ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक हुआ है। राष्ट्रीयकरण से पूर्व कुल बैंक शाखाओं में ग्रामीण क्षेत्र का शाखाओं का प्रतिशत मात्र 22.2 था जो बढ़कर मार्च, 1992 में 58.0 प्रतिशत हो गया। ग्रामीण-शहरी, शहरी एवं राजधानी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की संख्या में तो विस्तार हुआ है लेकिन उनका कुल बैंक शाखाओं की प्रतिशतता में निरन्तर कमी हुई है। राष्ट्रीयकरण के उपरान्त जून, 1969 से मार्च, 1992 के मध्य में खोली गई 52430 शाखाओं में से 33,385 बैंक शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्र में खोली गई हैं, जो कुल खोली गई शाखाओं का 63.68 प्रतिशत है। पिछले 23 वर्षों में 2280 बैंक शाखाएँ प्रति वर्ष की दर से बढ़ोत्तरी हुई हैं, जो स्वयं में एक कीर्तिमान है।

बैंक शाखाओं का विस्तार उन राज्यों में अधिक हुआ है जो बैंकिंग दृष्टि से पिछड़े हुए थे जैसे—असम, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर मध्य प्रदेश उड़ीसा राज्य।

जनसंख्या की दृष्टि से राष्ट्रीयकरण के पूर्व जून, 1969 में औसतन 64 हजार जनसंख्या के लिए एक बैंक शाखा थी। शाखाओं के विस्तार के कारण मार्च, 1992 में 10 हजार जनसंख्या पर ही एक बैंक शाखा हो गई है। बैंकों की शाखाओं के विस्तार की गति विभिन्न राज्यों में समान नहीं है। अतः विभिन्न राज्यों में प्रति बैंक शाखा जनसंख्या में बहुत विभिन्नता है। मार्च 1988 में मनीपुर में 22 हजार जनसंख्या पर एक बैंक शाखा व बिहार एवं सिक्किम राज्यों में 16 हजार जनसंख्या पर एक बैंक शाखा थी, जबकि हिमाचल प्रदेश पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में 6 से 9 हजार जनसंख्या पर ही एक बैंक शाखा थी। अन्य राज्यों में प्रति बैंक शाखा जनसंख्या 10 से 12 हजार है।

(ब) बैंकों के जमा एवं ऋण राशि में विस्तार—बैंक राष्ट्रीयकरण के पूर्व जून, 1969 में बैंकों की कुल जमा राशि 4,646 करोड़ रुपये एवं स्वीकृत ऋण राशि 3,599 करोड़ रुपये थी। ऋण जमा राशि का अनुपात जून, 1969 में 77.5 प्रतिशत था। राष्ट्रीयकरण के उपरान्त बैंकों की जमा-राशि एवं ऋण राशि में बहुत विस्तार हुआ है। दो दशक के उपरान्त मार्च, 1989 में कुल जमा-राशि बढ़कर 146,890 करोड़ रुपये तथा कुल स्वीकृत ऋण राशि 96,808 करोड़ रुपये हो गई। इस प्रकार 20 वर्षों में जमा राशि में 32 गुना एवं स्वीकृत ऋण राशि में 27 गुना वृद्धि हुई है जिससे स्वीकृत ऋण एवं जमा राशि का अनुपात 66.4 हो गया।

शहरीकरण के अनुसार जमा-राशि एवं स्वीकृत ऋण राशि में सर्वाधिक वृद्धि ग्रामीण क्षेत्र में ग्रन्थ क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक हुई है। प्रति बैंक शाखा जमा-

राशि एवं स्वीकृत ऋण राशि में भी तीव्र गति से वृद्धि हुई है। प्रति बैंक शाखा जमा-राशि जून, 1969 में 56 लाख रुपये थी, जो बढ़कर मार्च, 1989 में 258 लाख रुपये हो गई। इसी प्रकार प्रति बैंक शाखा स्वीकृत ऋण राशि उपरोक्त काल में 44 लाख रुपये से 169 लाख रुपये हो गई।

सारणी 10 10 में विभिन्न समय काल में बैंको की जमा एवं ऋण राशि में विस्तार को प्रदर्शित किया गया है ---

सारणी 10 10

बैंको की जमा एवं ऋण राशि में विस्तार

विवरण	जून 1969	जून 1979	जून 1985	मार्च 1989
बैंको की कुल जमा राशि (करोड़ रुपये)	4,646	28,671	77,075	146,890
बैंको द्वारा स्वीकृत कुल ऋण राशि (करोड़ रुपये)	3,599	19,116	50,921	96,008
ऋण-जमा राशि का अनुपात	77.5	66.7	66.1	65.4
प्रति बैंक शाखा जमा राशि (लाख रुपये)	56	95	150	258
प्रति बैंक शाखा स्वीकृत ऋण (लाख रुपये)	44	63	99	169

स्रोत Pigmy Economic Review, Vol 38 (2), September, 1992

राष्ट्रीयकरण के समय ग्रामीण क्षेत्रों को कुल स्वीकृत ऋण का मात्र 1.49 प्रतिशत अंश ही ऋण के रूप में उपलब्ध हुआ था। यह अंशदान बढ़कर दिसम्बर, 1987 में 15.3 प्रतिशत हो गया। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रीयकरण के उपरान्त वाणिज्यिक बैंको ने ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराई है। लेकिन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को सुचारु रूप से कार्यान्वित करने के लिए इसमें और बढ़ोतरी होना आवश्यक है।

(स) ऋण प्राप्तकर्ता एवं धन अभावकर्ताओं को सहाय्य में विस्तार—राष्ट्रीयकरण के उपरान्त वाणिज्यिक बैंको की शाखाओं, जमा एवं ऋण राशि में विस्तार

के साथ साथ ऋण प्राप्त करने वाले व घन जमाकर्त्ताओं की संख्या में भी विस्तार हुआ है। राष्ट्रीयकरण के पूर्व जून, 1969 में वाणिज्यिक बैंको से ऋण प्राप्तकर्त्ताओं की संख्या मात्र एक मिलियन एवं घन जमाकर्त्ताओं की संख्या 10 मिलियन थी। पिछले 20 वर्षों में इनकी संख्या में 10 से 15 गुना वृद्धि हुई है।

(द) प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्रदत्त ऋण सुविधा—प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु सरकार द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र घोषित किए और सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा इन्हें अधिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर इनके लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य निर्धारित किया। वाणिज्यिक बैंको ने राष्ट्रीयकरण के उपरान्त अपनी स्वीकृत ऋण-नीति में आवश्यक परिवर्तन करके, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अधिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराई है। यह प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण स्वीकृति के क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंको द्वारा अब तक उपेक्षित थे। बैंक राष्ट्रीयकरण करने का सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य देश के सुनियोजित विकास के लिए निर्धारित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को अधिकाधिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराना था।

सारणी 10 11 कृषि एवं अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को बैंको द्वारा स्वीकृत ऋण राशि प्रदर्शित करती है।

सारणी 10 11

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को स्वीकृत ऋण

वर्ष	प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्रदत्त ऋण राशि (करोड़ रुपये)	कुल ऋण राशि में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्रदत्त ऋण राशि का प्रतिशत
जून, 1969	5,04	14 0
जून, 1979	5,906	30 91
जून, 1985	19,829	39 00
मार्च, 1987	25,050	40 00
मार्च 1989	34,207	43 00

स्रोत Pigmy Economic Review, Vol. 38 (2), September, 1992, p 5

बैंको ने राष्ट्रीयकरण के पूर्व जून, 1969 में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को 504 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया था, जो कुल स्वीकृत ऋण राशि का

मात्र 140 प्रतिशत था। यह ऋण राशि बढ़कर मार्च, 1989 में 34,207 करोड़ रुपये हो गई। इस प्रकार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का कुल स्वीकृत ऋण में अग्रदान बढ़कर 430 प्रतिशत हो गया। अतः स्पष्ट है कि बैंको ने इन क्षेत्रों के व्यक्तियों को अधिक ऋण स्वीकृत करने में रुचि ली है।

राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कुल स्वीकृत ऋण राशि में से मार्च, 1985 तक 40 प्रतिशत स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा गया था। बैंक सुपरोक्त लक्ष्य से अधिक राशि में, (मार्च, 1989 में 43 प्रतिशत) ऋण सुविधा इन क्षेत्रों को उपलब्ध करा रहे हैं। इसी प्रकार सरकार द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र को 17 प्रतिशत प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि वर्तमान में यह प्रतिशत 17.6 है जो लक्ष्य से अधिक है।

भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा जारी मार्गदर्शन के अनुसार निजी क्षेत्र के वारिण्डिक बैंको द्वारा भी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों एवं कृषि के विशेष कार्यक्रमों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराया जाना है। अतः निजी वारिण्डिक बैंको द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को जून, 1987 में कुल स्वीकृत ऋण का 38.5 प्रतिशत अग्र प्रदान किया है। वर्ष 1988-89 में विदेशी बैंको को भी कुल स्वीकृत ऋण में से 10 प्रतिशत ऋण राशि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने सुझाव दिया है।

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अधिक प्रतिशत ऋण राशि उपलब्ध कराने में हरियाणा, मनीपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, मेघालय एवं बिहार राज्यों का स्थान अन्य राज्यों की अपेक्षा ऊपर है जबकि महाराष्ट्र एवं पश्चिमी बंगाल राज्यों का स्थान सबसे नीचे है।

राष्ट्रीयकृत बैंक कृषकों को आवश्यकतानुसार अल्पावधि ऋण—बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशी दवाइयाँ, मजदूरी का भुगतान करने, मध्यावधि ऋण—सिंचाई के लिए कुआँ पर मोटर लगाने, पशु क्रय करने, कृषि यन्त्र एवं छाटी मशीनों का क्रय करने के लिए तथा दीर्घावधि ऋण—भूमि सुधार कार्यक्रम, ट्रैक्टर एवं बड़ी मशीनों का क्रय आदि के लिए कम व्याज दर पर उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र को अधिकाधिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वारिण्डिक बैंको ने अनेक योजनाएँ भी बनाई हैं, जैसे—फसल ऋण योजना, अग्रणी बैंक योजना, रियायती व्याज दर योजना आदि।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को कृषि ऋण के विस्तार में आ रही समस्याएँ :

वारिण्डिक बैंको ने राष्ट्रीयकरण के बाद के वर्षों में कृषि ऋण प्रदान करने, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंको की शाखाएँ खोलने, कृषि ऋण की नई योजनाएँ शुरू करने

में विशेष प्रगति की है, लेकिन ग्रामीण ऋण विस्तार में बैंको को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बैंको के समक्ष ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण विस्तार में आने वाली प्रमुख समस्याएँ निम्न हैं—

(1) कृषिगत ऋण विस्तार के लिए क्षेत्र एवं परियोजनाओं के चुनाव से सम्बन्धित समस्याएँ—ऋण विस्तार में सर्वप्रथम समस्या ऋण प्रदान करने के लिए क्षेत्र एवं परियोजनाओं के चुनाव की होनी है। किस क्षेत्र में ऋण की अधिक आवश्यकता है और कौनसी योजनाओं को ऋण की स्वीकृति में प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए, जैसे उत्पादन कार्य, कृषि विकास हेतु पूँजी निवेश की योजनाओं या आधारभूत संरचना के विकास की योजनाएँ आदि।

(2) बैंकों के पास कृषि ऋण-विस्तार के लिए आवश्यक वित्त की कमी—राष्ट्रीयकृत बैंको के सामने कृषि ऋण विस्तार में दूसरी समस्या कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक वित्त राशि का घटगव होना है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। प्रथम तो राष्ट्रीयकृत बैंक कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण की राशि में कमी नहीं करना चाहते हैं, दूसरी ओर कृषि-क्षेत्र में हरित-क्रान्ति एवं तकनीकी ज्ञान विकास के कारण ऋण की आवश्यकता में कई गुना वृद्धि हो गई है जिसे बैंक अपनी वर्तमान वित्त-राशि में पूरा करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। अतः बैंको की जमा-राशि में वृद्धि करना आवश्यक है।

(3) कृषको को ऋण-स्वीकृति में आने वाली समस्याएँ—राष्ट्रीयकरण के पूर्व वाणिज्यिक बैंक उद्योगों को ही प्रमुखतया ऋण स्वीकृत करते थे, जिसके कारण वाणिज्यिक बैंको के कार्यक्षमता कृषि क्षेत्र में ऋण स्वीकृत करने में आने वाली समस्याओं से अनभिज्ञ थे। कृषि-क्षेत्र में आने वाली समस्याएँ उद्योगों के लिए ऋण-स्वीकृति में आने वाली समस्याओं से भिन्न होती हैं। राष्ट्रीयकरण के उपरान्त ऋण-स्वीकृति में प्राथमिकता प्रदान करने की नीति में परिवर्तन के कारण, वाणिज्यिक बैंको को कृषि के क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा तथा साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-ऋण प्रदान करने के लिए शाखाओं का विस्तार करना पड़ा। इन सब कार्यों में बैंको को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिसके कारण प्रगति की रफ्तार में गति नहीं आ सकी—

(अ) कृषि-ऋण की स्वीकृति के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओं का अभाव—वाणिज्यिक बैंकों के पास कृषि ऋण स्वीकृत करने के पूर्व ऋणी द्वारा दी गई परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता (Technical feasibility) एवं आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन करने एवं ऋण-प्रार्थना-पत्रों की जाँच करने के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओं (वाणिज्यिक बैंको के सिद्धान्तों एवं कृषि की समस्याओं के ज्ञाता) का अभाव था, जिसके कारण ऋण-प्रार्थना-पत्रों की जाँच में काफी समय लगता था।

- (ब) बैंक कार्यकर्त्ताओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई शाखाओं में कार्य करने में रुचि नहीं लेना जिससे शाखाओं के विस्तार में तेज गति से वृद्धि नहीं हो पाई।
- (स) कृषकों के भूमि पर स्वामित्व के सही अभिलेख उपलब्ध नहीं होना—वाणिज्यिक बैंक भूमि की प्रतिभूति पर अधिकांश ऋण स्वीकृत करते हैं। कृषकों के ऋण प्रार्थना-पत्र पर भूमि के स्वामित्व को सत्यापित करने में राजस्व अधिकारी अधिक समय लेते हैं जिसके कारण ऋण स्वीकृति में देर हो जाती है।
- (द) प्रतिभूति के लिए भूमि बन्धक रखने में समय लगना—ऋण-प्राप्ति के लिए कृषकों को भूमि बन्धक करके बैंक के नाम से पंजीकृत करनी होनी है जिसमें राजस्व अधिकारी अधिक समय लगाते हैं और कृषकों को समय पर ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है। साथ ही भूमि को बैंक के नाम पंजीकृत करने में कृषकों को पंजीकरण फीस देनी होती है जिसके कारण लागत अधिक जाती है।
- (प) कानूनी परेशानियाँ—बैंकों द्वारा कृषकों को कुछ राज्यों में कानूनी श्रद्धांशों का सामना करना पड़ता है, जैसे—भूमि को सत्या के नाम हस्तान्तरण करने पर रोक होना, पुराने ऋण की वसूली से छुटकारा दिलाने के नियमों में साहूकारों एवं वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण में अन्तर नहीं होना, कृषकों पर ऋण-वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही करने पर प्रतिबन्ध होना आदि। इन सब कानूनों में बैंकों को साहूकारों के समान रखा गया है, जिसके कारण बैंक कृषकों को ऋण स्वीकृत करने में विशेष रुचि नहीं ले पाए हैं।

(4) ऋण वसूली की समस्याएँ—वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में ऋण-स्वीकृति में आने वाली यह भी प्रमुख समस्या है जिसके कारण बैंक कृषि क्षेत्र में विशेष प्रगति नहीं कर पाए हैं। समय पर ऋण वसूल नहीं हो पाने के कारण ऋण की बढ़ती राशि कृषकों पर बढ़ती जाती है और बैंकों के पास उपलब्ध विन कर्म होना जाता है जिसके कारण वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि के क्षेत्र में ऋण स्वीकार करने की नीति पर विपरीत प्रभाव आता है। कृषि-ऋण की वसूली का प्रतिशत कम होने के प्रमुख कारण अग्रलिखित हैं—

- (अ) अस्वस्थ ऋण-नीति—कृषि ऋण की वसूली का प्रतिशत कम होने का प्रथम कारण ठीक कृषि नीति का न होना है। आवश्यकता से अधिक राशि में ऋण स्वीकृत करना, गलत समय पर ऋण स्वीकृत करना, आवश्यकता से कम राशि में ऋण स्वीकृत करना तथा उत्पादन

कार्यों के लिए आवश्यक राशि में ऋण स्वीकार नहीं करने के कारण कृषको को दिये गये ऋण में सम्भाविन आय प्राप्त नहीं होती है, जिससे ऋण की वसूली में वाणिज्यिक बैंको को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

(घ) निरीक्षण का अभाव—स्वीकृत ऋण की वसूली का प्रतिशत कम होने का दूसरा प्रमुख कारण स्वीकृत ऋण के उपयोग एवं वसूली पर बैंक का पर्यवेक्षण पर्याप्त नहीं होना है, जिसके कारण कृषक प्राप्त ऋण का स्वीकृत उद्देश्य के लिए उपयोग न करके अनुत्पादक कार्यों में उपयोग कर लेते हैं। समय पर ऋण-वसूली की कार्यवाही नहीं करने पर उत्पाद के विन्य से प्राप्त आय को कृषक अन्य कार्यों अथवा पुराने कर्ज चुकाने में उपयोग कर लेते हैं, जिससे बैंक का ऋण समय पर वसूल नहीं हो पाता है। इन सबका कारण वाणिज्यिक बैंको के पास पर्याप्त कार्यक्षमताओं का नहीं होना तथा उनकी कार्य के प्रति रुचि नहीं होना है।

(ङ) फसल उत्पादन कम होना—कृषि में प्राकृतिक प्रकोप निरन्तर आते रहते हैं। सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़, तूफान, ओले, कीड़े, टिड्डो, बीमारियाँ आदि के कारण या तो फसल पूर्णतया नष्ट हो जाती है अथवा उत्पादन कम प्राप्त होता है जिससे कृषको की ऋण भुगतान-क्षमता कम हो जाती है और ऋण वसूली का प्रतिशत कम हो जाता है।

(च) राजनैतिक हस्तक्षेप—राजनैतिक हस्तक्षेप भी ऋण की समय पर वसूली में बाधक होते हैं। ऋण की राशि बड़े कृषको पर तबु कृषको की अपेक्षा अधिक बकाया होती है।

(5) वाणिज्यिक बैंकों का अन्य समस्याओं से सम्बन्ध नहीं होना—वाणिज्यिक बैंको के समस्त कृषि ऋण विस्तार में आने वाली अन्य समस्या ऋणदात्री एवं गैर ऋणदात्री समस्याओं जैसे—सरकार वाणिज्यिक बैंक एवं साहकार उत्पादन-साधनों की पूर्ति करने वाली समस्याओं जैसे—डब्लरक नियम, राष्ट्रीय बीज नियम, प्रोनेसिंग समस्याओं में पूर्ण सम्बन्ध नहीं होना है। उपर्युक्त समस्याओं का वाणिज्यिक बैंको से सम्बन्ध ऋण विस्तार के लिए आवश्यक है। जैसे—सरकार वाणिज्यिक बैंको के ऋण विस्तार के लिए क्षेत्र का चुनाव करके, बैंको को ऋण योजनाएँ बनाने के लिए तकनीकी कार्यकर्ताओं की सेवाएँ प्रदानियुक्ति पर देकर ऋण विस्तार में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। इसी प्रकार विस्तार-समस्याएँ वाणिज्यिक बैंको के लिए कृषको का सही चुनाव, ऋण वसूली, ऋण की आवश्यक राशि प्राप्त करने में

सहायक होती है। विपणन, प्रोसेसिंग एवं उत्पादन साधनों की पूर्ति करने वाली संस्थाओं से भी वाणिज्यिक बैंको का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि कृषकों को जब तक इन संस्थाओं की सेवाएँ समय पर उपलब्ध नहीं होगी तब तक कृषक प्राप्त ऋण का पूर्ण उपयोग नहीं कर पायेंगे, ऋण में आय में वृद्धि नहीं होगी और ऋण-वसूली में वाणिज्यिक बैंको को परेशानी होगी। इसी प्रकार विभिन्न ऋणदात्री संस्थाओं में भी आपस में समन्वय होना आवश्यक है, विशेषकर वाणिज्यिक बैंको का दूसरे बैंको तथा सहकारी ऋण-संस्थाओं से समन्वय होना आवश्यक है। इनमें समन्वय नहीं होने से कृषक विभिन्न संस्थाओं से एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऋण प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार विभिन्न ऋणदात्री संस्थाओं को ऋण की वसूली में परेशानियाँ उठानी होती हैं।

(6) अन्य कारण—शिक्षा के कारण वाणिज्यिक बैंको द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऋणों के विषय में कृषकों की अज्ञानता, विस्तार कार्यक्रमों को वाणिज्यिक बैंको द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का पर्याप्त ज्ञान न होना, कृषकों द्वारा तकनीकी ज्ञान का उपयोग नहीं किया जाना, कृषकों का गाँव के साहूकार का ऋणी होने के कारण बैंक से ऋण प्राप्त करने की इच्छा न होना, गाँवों में सड़कों के अभाव के कारण वाणिज्यिक बैंको के अधिकारियों द्वारा समय पर निरीक्षण नहीं कर पाना, सहकारी बैंको द्वारा कम व्याज पर ऋण स्वीकृत करना आदि कारक भी वाणिज्यिक बैंको के कृषि-ऋण विस्तार कार्यक्रम में बाधक होते हैं।

3. फसल-ऋण-प्रणाली (Crop-Loan-System)

ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की एक प्रमुख सिफारिश के अनुसार कृषकों को अल्पकालीन ऋण फसल-ऋण-प्रणाली के अनुसार दिया जाना चाहिए, जिससे कृषक प्राप्त ऋण का उत्पादन वृद्धि के कार्यों के लिए ही उपयोग करें और कृषकों को फार्म पर ली जाने वाली फसलों के लिए आवश्यकतानुसार राशि ऋण के रूप में प्राप्त हो सके। साथ ही कृषकों को स्वीकृत ऋण का अधिकांश भाग तत्काल रूप में नहीं दिया जाकर उत्पादन साधनों के रूप में दिया जाए तथा ऋण की वसूली फसल के विक्रय से प्राप्त आय में से की जाए। फसल-ऋण-प्रणाली के उपर्युक्त सिद्धान्तों को सहकारिता राज्य-मन्त्रियों के सम्मेलन (अप्रैल, 1955) में सैद्धान्तिक रूप में स्वीकार कर लिया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रिजर्व बैंक की सिफारिश के अनुसार सभी राज्यों ने उत्पादन के आधार पर ऋण स्वीकृत करने अर्थात् फसल-ऋण-प्रणाली को अपनाने का श्रीगणेश किया।

फसल-ऋण-प्रणाली के अन्तर्गत कृषकों की उत्पादन-क्षमता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अन्तर्गत विभिन्न फसलों को उगाने के लिए आवश्यक ऋण

फसलो की आवश्यकतानुसार ज्ञात किया जाता है। प्रत्येक कृषक के लिए पृथक् रूप से ऋण की सीमा निर्धारित की जाती है। फसल ऋण प्रणाली में कृषको को ऋण मोतिक प्रतिभूति के अभाव में उत्पादित की जाने वाली फसलो की प्रतिभूति के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

फसल ऋण प्रणाली के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण-राशि के कृषको द्वारा स्वीकृत उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में किये जाने वाले उपभोग को रोकने के लिए स्वीकृत ऋण के अधिकांश भाग को नकद न दिया जाकर उत्पादन-साधनों—बीज, उर्वरक, कीटनाशी दवाइयाँ, उन्नत औजार आदि के रूप में दिया जाता है और शेष राशि का नकद मुग्तान किया जाता है। इस प्रकार स्वीकृत ऋण तीन भागों में दिया जाता है—

- (अ) प्रचलित कृषि विधियों को अपनाने के लिए नकद राशि का मुग्तान।
- साधारणतया यह राशि कुल उत्पादन लागत के एक-तिहाई भाग से अधिक नहीं होती है।
- (ब) उत्पादन-साधनों के रूप में ऋण का एक भाग। साधारणतया यह राशि उत्पादन-साधनों में प्रयुक्त की जाने वाली राशि के समतुल्य होती है।
- (स) उपर्युक्त (ब) भाग के अन्तर्गत स्वीकृत राशि की 50 प्रतिशत राशि नकद रूप में। इस राशि को स्वीकृत करने का प्रमुख उद्देश्य आधुनिक उत्पादन-साधनों के उपयोग में होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करना है।

कृषको द्वारा प्राप्त ऋण के मुग्तान हेतु सहकारी-विपणन-समितियों के माध्यम से उत्पाद के विक्रय का प्रबन्ध होता है तब कृषक विपणन समिति के माध्यम से उत्पाद विक्रय करके प्राप्त राशि से ऋण का ब्याज सहित मुग्तान कर सकें।

फसल ऋण प्रणाली कृषको के लिए ऋण-उपलब्धि के क्षेत्र में प्रगतिशील कदम होते हुए भी इसको कार्यान्वित करने में ऋणदात्री संस्थाओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना होता है, जैसे—विभिन्न फसलो की उत्पादन-लागत के सही आँकड़ों का उपलब्ध न होना, सहकारी समितियों के पास पर्याप्त राशि में ऋण प्रदान करने के लिए धन न होना, सभी क्षेत्रों में सहकारी-विपणन समितियों का न होना, सहकारी पर्यवेक्षकों की कमी आदि। अतः फसल ऋण-प्रणाली के विकास के लिए आवश्यक सेवाओं का, जो इसकी प्रगति में बाधक है, विकास करना आवश्यक है।

4 अग्रणी बैंक योजना (Lead Bank Scheme) :

वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उपरान्त बैंकों को कृषि के क्षेत्र में प्रयत्न करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त नरीमन समिति के सुझाव पर दिसम्बर, 1969 में अग्रणी बैंक योजना या 'लीड बैंक योजना' निर्मित की गई। लीड बैंक योजना में देश के चौदह बड़े राष्ट्रीयकृत बैंक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं उसके सहायक बैंक तथा बैंक ऑफ राजस्थान एवं आन्ध्र बैंक सम्मिलित हैं। इस योजना के अनुसार प्रत्येक बैंक के लिए कृषि ऋण योजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक राज्य में जिले निर्धारित किये गये हैं जिससे वे उन जिलों के सभी कृषकों की ऋण आवश्यकता को पूर्ण कर सकें। साथ ही बैंकों को विभिन्न क्षेत्रों में ऋण स्वीकृत करने में शुरू में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनसे वे बच सकें। देश के अग्रणी बैंक योजना शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य देश के ग्रामीण निवासियों को अधिक ऋण सेवा उपलब्ध कराना एवं जिले के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन देना है।

अग्रणी/लीड बैंकों के कार्य—लीड बैंकों के प्रमुख कार्य निम्न हैं—

- (1) जिले में बैंकिंग विकास के लिए उपलब्ध सुविधाओं और साधनों का सर्वेक्षण करना।
- (2) जिले की औद्योगिक संस्थाओं, कृषकों एवं अन्य व्यापारिक संस्थाओं का सर्वेक्षण करना, जो बैंकों से ऋण सुविधा प्राप्त न करके साहूकारों पर ऋण के लिए निर्भर हैं।
- (3) जिले की प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं की सहायता करना।
- (4) जिले के कृषकों को ऋण-सुविधा एवं अन्य सलाह प्रदान करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करना एवं प्रशिक्षण देना।
- (5) जिले में कृषि उत्पाद के विपणन संग्रहण आदि सुविधाओं के सर्वेक्षण के आधार पर ऋण की विपणन से जोड़ना तथा उत्पादन माधनों की समय पर उपलब्धि के लिए विपणन संस्थाओं को ऋण सुविधा प्रदान करना।
- (6) जिले के निवासियों को अतिरिक्त वचत की राशि जमा कराने की सुविधा प्रदान करना।

अग्रणी बैंक योजना के अन्तर्गत लीड बैंक के क्षेत्र निर्धारण के उपरान्त सेवा-योजना के लिए अपने अनुभव के आधार पर ऋण स्वीकृति की विधि में परिवर्तन की सुविधा प्रदान की गई है। इन लीड बैंक की योजना में एक और ग्रामीण कृषकों को ऋण की सुविधा की व्यवस्था की जाती है, वहाँ दूसरी और ग्रामीण वचतों को बैंकों द्वारा आकर्षित करके जमा राशियों को बढ़ाया जाता है, ताकि उनका उत्पादन कार्यों में उपयोग किया जा सके।

अग्रणी बैंक योजना की कार्यप्रणाली की समीक्षा हेतु नवम्बर, 1981 में एक कार्य दल का गठन किया गया था। इस गठित कार्यदल की प्रस्तुत सिफारिशों को

कुछ संशोधन करके भारतीय रिजर्व बैंक ने मान ली है। प्रस्तुत सिफारिशों में अग्रणी बैंको में प्रमुखता कहा गया है कि जिला परामर्शदात्री समितियों तथा स्थायी समितियों का पुनर्गठन करे, ताकि वे प्रभावशाली कार्य कर सकें, अग्रणी बैंक अधिकारी का पद भूमिका एवं कार्य तय करे तथा गैर-अग्रणी जिलों में प्रत्येक जिला समन्वयकर्ताओं की नियुक्ति करे। दिसम्बर, 1988 तक इस योजना में 440 जिले सम्मिलित किये जा चुके हैं।

5. ग्राम अभिग्रहण योजना (Village Adoption Scheme) :

वाणिज्यिक बैंको ने 'ग्राम अभिग्रहण योजना' शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का क्रमागत विकास करना है। अतः योजना के तहत गोद लिए गए गांव के सभी व्यक्तियों को उनकी आवश्यकतानुसार प्रदान किए गए कार्य के लिए ऋण-सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके तहत बैंक एक ही चुने हुए गांव में सभी सम्भावित उद्यमियों को ऋण-सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जिससे बैंक को पृथक्-पृथक् स्थान पर स्वीकृत ऋण से होने वाली परेशानी कम होती है।

जून, 1983 तक 70,000 गांव राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा 27 राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में अभिग्रहण किए जा चुके हैं, जिससे गांवों का एकीकृत विकास हो सके। चुने गए गांवों में सर्वांगीण विकास के आकलन से स्पष्ट है कि यह योजना अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हुई है। इसकी सफलता में बाधक प्रमुख कारण निम्न हैं—

- (1) ग्राम स्तर पर विभिन्न वाणिज्यिक बैंको में समन्वय नहीं होता, जिससे एक ही ग्राम को अलग-अलग बैंको द्वारा चुन लिया जाता है।
- (2) गांव के कार्रगारों पर ऋण की बढ़ती बकाया राशि।
- (3) लघु एवं विखण्डित ओत कृषकों को ऋण स्वीकृति में होने वाली समस्याएँ।

इन समस्याओं के होते हुए भी आवश्यक है कि वाणिज्यिक बैंक इनका समाधान निकालते हुए चुने गए गांवों के सर्वांगीण विकास का निर्धारित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रयास करें।

6 भारतीय ऋण प्रतिभूति निगम

(Credit Guarantee Corporation of India) :

भारत सरकार ने थ्री एस० एस० सीरलकर की अध्यक्षता में नियुक्त अध्यक्ष इन के सुझाव के अनुसार वाणिज्यिक बैंको को कृषि क्षेत्र में ऋण स्वीकृति में होने वाली हानि से रक्षा करने के लिए भारतीय ऋण प्रतिभूति निगम स्थापित किया है, जिसका प्रमुख कार्य वाणिज्यिक बैंको को होने वाली जोखिम को पूरा

करना है। इस योजना के अनुसार कृषको एवं प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिए जाने वाले सभी ऋणों पर निगम प्रतिभूति देता है। इस कार्य के लिए निगम बकाया ऋण राशि पर 0.5 प्रतिशत प्रतिभूति शुल्क वसूल करता है।

7 बहु-अभिकरण दृष्टिकोण (Multi Agency Approach) :

वर्ष 1968 तक कृषि ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकारी नीति के अन्तर्गत सहकारी ऋण समितियों को एक मात्र सस्था के रूप में अपनाया था। लेकिन कृषि में ऋण की बढ़ती आवश्यकताएँ एवं सहकारी ऋण समितियों के वित्तीय, प्रशासकीय एवं प्रबन्धकीय टाचे में कमी के कारण सरकार ने स्वीकार किया कि इस परिस्थिति में एक सस्था से पूर्ण विकास सम्भव नहीं है। अतः कृषि ऋण के क्षेत्र के बहु-अभिकरण दृष्टिकोण की महत्ता स्वीकृत की गई है। सरकार के इस दृष्टिकोण के कारण कृषकों को अधिक वित्त सुविधा उपलब्ध होने के साथ-साथ कृषि ऋण के क्षेत्र में अनेक ऋणदात्री नस्थाओं के होने से विभिन्न सस्थाओं में समन्वय के अभाव में अनेक समस्याएँ भी उत्पन्न होनी शुरू हुईं, जिनमें से प्रमुख यह थी कि कुछ कृषक अनेक सस्थाओं से ऋण प्राप्त करने लग गए। अतः सरकार ने अगस्त, 1976 में कामध्व कार्यकारी ढल एवं जून, 1977 में दाठवाला समिति को बहु-अभिकरण दृष्टिकोण में होने वाली कठिनाइयों के लिए मुभाव देने हेतु नियुक्त किया। इन दोनों समितियों ने अपने प्रतिवेदन में अनेक मुभाव दिए हैं।

8. विभेदक व्याज दर योजना (Differential Rates of Interest Scheme)

समाज के गरीब-वर्ग के हिनों का ध्यान में रखते हुए एक मुख्य प्रश्न उठता है कि क्या सभी वर्ग के कृषकों एवं कृषि श्रमिकों से स्वीकृत ऋण पर समान दर से व्याज वसूल किया जाना चाहिए? इस प्रश्न के समाधान के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने डॉ॰ आर॰ के॰ हजारती की अध्यक्षता में सितम्बर, 1970 में एक समिति का गठन किया था। समिति ने मई 1971 में प्रस्तुत प्रतिवेदन में विभिन्न स्तर के ऋण प्राप्तकर्ताओं के लिए विभेदक व्याज दर योजना प्रस्तावित की थी। समिति ने सिफारिश की थी कि विभेदक व्याज दर $\frac{1}{2}$ से 10 प्रतिशत होनी चाहिए तथा गरीब ऋण प्राप्तकर्ताओं में होने वाले प्राथमिक व्यय जैसे प्रतिभूति फीस आदि बैंक द्वारा वहन किये जाने चाहिए। साथ ही गरीब ऋण-प्राप्तकर्ताओं से रक्षित एवं अरक्षित ऋण पर समान व्याज दर ली जानी चाहिए। समिति का मत था कि अधिकांश लघु कृषकों एवं कुटीर उद्योगों के व्यवसायियों को बड़े एवं समृद्ध कृषकों एवं उद्यमियों के समान लाभ प्राप्त नहीं होता है। इन वर्ग के कृषकों एवं उद्यमियों को कम व्याज-दर पर ऋण उपलब्ध होना न केवल व्यवसाय में अधिक पूँजी निवेश करने का प्रयास करेंगे और अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। सरकार ने मार्च 1972 में हजारती समिति की रिपोर्ट स्वीकार की थी।

विभेदक ब्याज-दर की इस योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको द्वारा अपनी पिछले वर्ष की बकाया राशि का न्यूनतम एक प्रतिशत राशि कमजोर वर्ग को उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है। कमजोर वर्ग से तात्पर्य इस योजना हेतु ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की वार्षिक आय 6,400 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 7,200 रुपये निर्धारित की गई है। कृषको की श्रेणी में लघु एवं सीमान्त कृषक (एक हैक्टर से कम सिंचित भूमि या दो हैक्टर से कम असिंचित भूमि) सम्मिलित किए गए हैं। शुरू में यह योजना चुने गए पिछड़े क्षेत्रों, जनजाति क्षेत्र, लघु एवं सीमान्त कृषकों की बाहुल्यता वाले क्षेत्रों में शुरू की गई थी, जिसे वर्तमान में देश के सभी क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के अतिरिक्त अग्रणी बैंक का कार्य करने वाले निजी क्षेत्र के बैंक भी विभेदक ब्याज दर पर ऋण स्वीकृत करते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंको द्वारा विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण राशि सारणी 10.12 में प्रदर्शित है—

सारणी 10.12

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको द्वारा विभेदक ब्याज दर योजना
के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण राशि

वर्ष के अन्त में	सातो की सहाय (लाखों में)	बकाया ऋण राशि (करोड़ रुपयों में)	कुल स्वीकृत ऋण में विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण का प्रतिशत
1972	0 26	0 87	0 02
1975	4 65	20 99	0 31
1980	25 10	193 50	1 04
1985	43 18	462 70	1 10
1988	46 19	646 58	1 00

स्रोत V V Bhat, Trends in Banking Since Nationalisation,
Yojana, Vol 33 No 13, July 16-31, 1989, p 12

प्रारम्भ वर्ष 1972 के अन्त में 26 2 हजार ऋण प्राप्तकर्ताओं को 87 3 लाख रुपये (कुल ऋण राशि का 0 02 प्रतिशत) का ऋण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको ने इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराया था, जो बढ़कर वर्ष 1988 के अन्त में

646 58 करोड़ रुपये अर्थात् कुल स्वीकृत ऋण का 10 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक निर्धारित लक्ष्य एक प्रतिशत ऋण इस योजना के अन्तर्गत प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार लक्ष्य के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कुल ऋण की 40 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाना है। वर्तमान में (दिसम्बर, 1988) में कुल स्वीकृत ऋण में से 331 25 करोड़ रुपये अर्थात् 51 21 प्रतिशत ऋण इन जातियों के ऋण प्राप्तकर्ताओं को उपलब्ध कराकर विभेदक व्याज दर योजना का यह लक्ष्य भी बैंक प्राप्त कर चुके हैं।

9 कृषक सेवा समितियाँ (Farmer's Service Societies) *

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अपने अन्तरिम प्रतिवेदन, 1971 में देश में कृषि-ऋण की सुविधा के लिए कृषक सेवा समितियाँ स्थापित करने का सुझाव दिया था। आयोग ने एकीकृत कृषि-ऋण के निम्न तीन अवयवों की बात कही थी—

- (1) तहसील या पंचायत समिति स्तर पर सेवा समितियाँ स्थापित की जानी चाहिए। समितियाँ ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त, कृषकों के लिए आवश्यक उत्पादन-साधन एवं सेवाएँ भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगी।
- (2) जिला स्तर पर कृषक सेवा समितियों का एक सच होना चाहिए।
- (3) प्रत्येक जिले का लीड बैंक इन समितियों के प्रबन्ध का मार्ग-दर्शक होगा।

राष्ट्रीय कृषि आयोग की यह सिफारिश सरकार ने मान ली एवं वर्ष 1973-74 से देश में कृषक सेवा समितियाँ स्थापित होना प्रारम्भ हो गईं। मार्च, 1977 तक देश में 346 कृषक सेवा समितियाँ स्थापित हो चुकी थी। इनमें से सर्वाधिक समितियाँ कर्नाटक राज्य में थी। ये समितियाँ वाणिज्यिक बैंकों तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा स्थापित की गई हैं।

कृषक सेवा समितियों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लघु कृषकों को सभी आवश्यक उत्पादन-साधन एवं सेवाएँ तथा तकनीकी परामर्श प्रदान करना है जिससे कृषक समाज के कमजोर वर्ग के हित में वातावरण बन सके एवं कृषक सेवा समितियों के संचालक मण्डल में उन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। कृषक सेवा समितियाँ मदस्य-कृषकों को ऋण एवं उत्पादन-साधनों की पूर्ति हेतु विभिन्न समस्याओं जैसे-ऋण के लिए वाणिज्यिक बैंक एवं सहकारी बैंक, उत्पादन-साधनों की पूर्ति करने वाली संस्थाएँ, सरकारी कार्यालय, कृषि विस्तार सेवाएँ, विपणन संस्थाएँ, भूमि विकास बैंक भारतीय खाद्य निगम आदि से सम्पर्क स्थापित करती है।

क्षेत्रीय/प्राचलिक ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks) :

श्री आर जी सरैया की अध्यक्षता में 1972 में नियुक्त बैंकिंग आयोग ने सिफारिश की थी कि वारिण्डिक बैंको की शाखाओं के विस्तार के साथ-साथ देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी स्थापित किये जाने चाहिए, जिससे लघु एवं सीमान्त कृषकों की ऋण समस्याओं को ज्यादा अच्छी तरह से हल किया जा सके। आयोग ने पाया कि वारिण्डिक बैंको को ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण-सुविधा उपलब्ध कराने में दो मुख्य परेशानियाँ होती हैं :

- (i) ग्रामीण क्षेत्रों में वारिण्डिक बैंको की शाखाओं के विस्तार पर व्यय बहुत आता है।
- (ii) वारिण्डिक बैंको के पास ग्रामीण कर्तृकारों की वित्तीय समस्याओं के समझने एवं उनके अनुसार कार्य करने के लिए आवश्यक कार्य-कर्त्ताओं का अभाव है।

तत्पश्चात् भारत सरकार ने श्री एम नरसिंहम की अध्यक्षता में एक कार्य-कारी दल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के कार्य प्रणाली को समझने हेतु नियुक्त किया और उसके फलस्वरूप 26 सितम्बर, 1975 को देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने हेतु एक अध्यादेश जारी किया गया।

उद्देश्य क्षेत्रीय बैंकों का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं सीमान्त कृषक, कृषि श्रमिक, कारीगर एवं छोटे उद्यमियों का ऋण एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। ये बैंक मुख्यतया पिछड़े एवं जन जाति क्षेत्रों में स्थापित किए जायेंगे, जहाँ वारिण्डिक एवं सहकारी बैंको की शाखाओं का विस्तार कम है।

कार्य-क्षेत्र प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने नियत क्षेत्र में कार्य करेगा। इसके लिए वह आवश्यकतानुसार क्षेत्र में शाखाएँ स्थापित करेगा। बैंक में कार्य हेतु कार्यकर्त्ताओं का चयन क्षेत्र के व्यक्तियों में से किया जावेगा, जिससे उन्हें भाषा सम्बन्धी एवं क्षेत्रीय समस्याओं को समझने में आसानी होती है। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक समर्थक बैंक (Sponsor bank) की देख-रेख में कार्य करेगा। समर्थक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को अनेक प्रकार के कार्यों, जैसे शेयर पूँजी ऋण करना एवं उसकी स्थापना में सहयोग देना, इसके कार्यकर्त्ताओं का चयन करना एवं उनकी ट्रेनिंग में सहयोग देना, प्रबन्धकीय एवं वित्तीय सहायता देना आदि में सहयोग देगा।

पूँजी प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अधिकतम जमा पूँजी एक करोड़ रुपये होगी। यह अधिकृत जमा पूँजी केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक एवं

समर्थक बैंक की राय से कम की जा सकती है, लेकिन 25 लाख से कम नहीं होगी। प्रत्येक बैंक की निर्भर पूंजी 25 लाख रुपये होगी, जिसमें से 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार, 15 प्रतिशत राज्य सरकार एवं 35 प्रतिशत समर्थक बैंक प्रदान करेगा।

प्रबन्ध : बैंक का प्रबन्ध एवं कार्य संचालक-मण्डल की देख-रेख में होगा। संचालक मण्डल में अध्यक्ष के अलावा 3 निदेशक केन्द्रीय सरकार द्वारा, 2 निदेशक राज्य सरकार द्वारा एवं 3 निदेशक समर्थक बैंक द्वारा मनोनीत होते हैं। बैंक का अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है जो पूर्ण समय कार्य की देख-रेख करता है।

प्रगति : सर्वप्रथम 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 2 अक्टूबर, 1975 को मुरादाबाद एवं गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), मिर्जाना (हरियाणा), जयपुर (राजस्थान) एवं नालन्दा (पश्चिमी बंगाल) में स्थापित किए गए थे। इनकी प्रगति सारणी 10 13 में प्रदर्शित की गई है।

सारणी 10 13

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रगति

विवरण	मार्च 1978	जून 1981	जून 1984	जून 1987	मार्च 1992
1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की संख्या	48	102	162	196	196
2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की शाखाएँ	1405	3784	8727	13076	14574
3 सम्मिलित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की संख्या	NA	18	23	23	23
4 सम्मिलित जिलों की संख्या	NA	167	286	362	—
5 कुल जमा राशि (करोड़ रुपये)	37 11	252 83	774 34	1909 68	5559 36

6 कुल स्वीकृत ऋण					
राशि (करोड़ रुपये)	48 39	302 45	859 97	1933 53	4027 45
7 स्वीकृत ऋण एवं					
जमा राशि का					
अनुपात (प्रतिशत)	130 4	119 6	111 1	101 3	72 44

स्रोत : (1) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन ।

(ii) Yojana, Vol 32 (13), 16-13 June, 1988, p 8

(iii) Pigmy Economic Review, Vol 38 (2), September, 1992

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की सख्या, शाखाओं, सम्मिलित जिलों की सख्या, जमा-राशि एवं स्वीकृत ऋण-राशि में इनके स्थापना वर्ष (अक्टूबर, 1975) के उपरान्त निरन्तर वृद्धि हुई है। स्थापना वर्ष (1975) में देश में मात्र 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही कार्यरत थे, इनकी सख्या बढ़कर जून, 1987 में 196 हो गई। मार्च, 1992 के अन्त में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की 14574 शाखाओं में कुल जमा राशि 5559.36 करोड़ रुपये एवं उनके द्वारा स्वीकृत ऋण राशि 4027 45 करोड़ रुपये थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको ने 90 प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण एवं बैंक रहित क्षेत्रों में खोलकर, ग्रामीण क्षेत्रों के समुदायों को ऋण एवं बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करके तथा प्रयुक्त स्रोतों से जमा-राशि एकत्रित करके सराहनीय कार्य किया है। साथ ही इन्होंने राष्ट्रीय नीति के अनुरूप कमजोर वर्गों एवं ग्रामीण निर्धनों को आर्थिक उत्थान के लिए ऋण प्रदान करके राष्ट्रीय विकास में सहयोग दिया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना था, अतः इन बैंको ने मार्च, 1992 तक 4027 45 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई है। अतः स्पष्ट है कि इन बैंकों ने प्राप्त जमा राशि में 111 अधिक राशि की ऋण सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों को उपलब्ध कराई है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का राज्यवार विवरण दर्शाता है कि अब तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको ने 23 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में 196 बैंक 362 जिलों में स्थापित किए हैं। इस प्रकार इन्होंने 20 मिलियन परिवारों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई है। सर्वाधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उत्तरप्रदेश राज्य में हैं। मध्यप्रदेश एवं बिहार राज्य दूसरे एवं तीसरे स्थान पर हैं। शाखाओं की दृष्टि से उत्तरप्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर, कर्नाटक दूसरे स्थान पर एवं बिहार तीसरे स्थान पर है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के कार्य की प्रगति की समीक्षा करने एवं उनके कार्य-विधि में सुधार लाने के लिए एक समिति प्रो. एम. एन. वातवाला की अध्यक्षता में

वर्ष 1977 में नियुक्त की गई थी। समिति ने 1978 में प्रस्तुत वृत्तान्त में इन बैंकों के दो वर्षों के कार्य एवं प्रगति पर सन्तोष व्यक्त किया है। समिति ने महसूस किया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण ऋण के ढाँचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अतः इनके विकास के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए। समिति ने सुझाव दिया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के क्षेत्र में कार्यरत सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धीरे-धीरे अपना सभी व्यापार इन बैंकों को इनकी क्षमता के आधार पर स्थानान्तरण कर देना चाहिए। इस प्रकार वाणिज्यिक बैंकों की गाँवों में कार्यरत शाखाओं को ग्रामों वाले घरों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर देना चाहिए। दातवाला समिति ने इन बैंकों की व्यवहार्यता की जाँच हेतु सुझाव दिया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी लाभकर हो सकता है जब इनकी 70 शाखाएँ हों, 8 करोड़ का ऋण व्यवसाय करे एवं 5 प्रतिशत व्याज की दर में अन्तर होवे।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वर्ष 1976 से 1986 के व्यवसाय के विश्लेषण से स्पष्ट है कि इनकी प्रगति में विरोधाभास है। इनकी शाखाओं के विस्तार में 26 गुना, जमा राशि में 222 गुना एवं ऋण स्वीकृति में 254 गुना वृद्धि हुई है। दूसरी ओर 196 में से 149 बैंकों को हानि हुई है। मात्र 47 बैंक ही लाभ कमाते हैं। चूँकि ये बैंक एक सीमित स्तर पर कार्यरत हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्गों को कम व्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। अतः इन बैंकों का आर्थिक स्तर पर व्यवहार्य होना सम्भव नहीं है।

वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में ऋण वसुली के क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रगति अच्छी है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने कार्य क्षेत्र विशेषकर कार्य की लागत एवं उद्योगों की समस्याओं को समझने में अनेक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इनका संगठनात्मक ढाँचा भी कमजोर है। अतः विकास के वर्तमान बदलते हुए ढाँचे के अनुसार इन्हें कार्य करने में अनेक परेशानियाँ हो रही हैं। सरकार द्वारा श्री बी के धर, अतिरिक्त सचिव बैंकिंग विभाग, वित्त मन्त्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य इन बैंकों के संगठनात्मक ढाँचे को सुदृढ़ बनाना तथा इनके कार्यक्षेत्र में विकास लाना है। इस कार्यकारी दल के कार्य करने एवं सुझाव देने के प्रमुख पहलू निम्न हैं—

- (i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नियत कार्य करने की दृष्टि से उनके वर्तमान संगठन, क्षेत्र एवं कार्य-प्रणाली की जाँच करना।
- (ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आकार, क्षेत्र, एवं दिए जाने वाले ऋणी व्यक्तियों को दृष्टिगत रखते हुए, इनको आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने

हेतु सुझाव देना और इनको होने वाली हानि की राशि को कम करने हेतु उपायों का पता लगाना ।

- (iii) बैंको में कार्य करने हेतु आवश्यक मानव शक्ति का धुनाव करना एवं उनमें कार्य को पूरा करने की क्षमता का बढ़ाना ।
- (iv) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के समर्थक बैंकों के अल्पकालीन व दीर्घकालीन उत्तरदायित्व को स्पष्ट करना ।
- (v) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्य-क्षमता में वृद्धि लाने सम्बन्धी ग्रन्थ पहालुओं पर सुझाव देना ।

11 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) :

भारत में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पहले से अनेक वित्तीय संस्थाएँ जैसे—सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वारिएजियक बैंक, कृषि पुन वित्त एवं विकास निगम, रिजर्व बैंक का कृषि ऋण विभाग आदि के होते हुए भी भारत सरकार ने कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए 12 जुलाई 1982 को एक पृथक् राष्ट्रीय बैंक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, (National Bank for Agriculture and Rural Development), (नाबाई) की स्थापना की है। इसकी स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा तथा समन्वित ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सकेगी ।

देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली वित्तीय संस्था की कमी सर्वप्रथम भारतीय सहकारित कांग्रेस ने अनुभव की एवं कृषि विकास बैंक अथवा राष्ट्रीय सहकारी बैंक अथवा कृषि एवं सहकारिता के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना के लिए प्रस्ताव किया । मार्च, 1979 में रिजर्व बैंक द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सन्धानत ऋण पर विचारार्थ शिवरमन समिति की नियुक्ति की गई और समिति की सिफारिशों के आधार पर अप्रैल, 1981 में केन्द्रीय सरकार ने नाबाई की स्थापना का निणय लिया ।

नाबाई पूर्व में जो कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का कृषि ऋण विभाग एवं कृषि पुन वित्त एवं विकास निगम कर रहा था, उन्हें सम्पूर्ण रूप से करेगा । इसकी स्थापना के साथ ही रिजर्व बैंक का कृषि ऋण विभाग तथा ग्रामीण नियोजन एवं ऋण प्रकोष्ठ, कृषि पुन वित्त एवं विकास निगम को नाबाई में सम्मिलित कर दिया गया है । नाबाई अब रिजर्व बैंक द्वारा कृषि एवं सहकारिता हेतु प्राविधित दोनों कोषों—राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन) कोष तथा राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) कोष की व्यवस्था भी करेगा तथा इन कोषों का परिवर्तित नाम क्रमशः राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन) कोष [National Rural Credit (Long-Term) Fund] तथा राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) कोष [National Rural Credit (Stabilization) Fund] होगा ।

वित्तीय व्यवस्था—नाबाडों की प्रारम्भिक पूंजी 100 करोड़ रुपये रखी गई है, जिसका आधा भाग रिजर्व बैंक तथा आधा भाग भारत सरकार द्वारा दिया गया है। यह पूंजी 500 करोड़ रुपये तक बढ़ायी जा सकती है। नाबाडों अपनी अल्पकालीन आवश्यकताओं के लिए रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है। दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं के लिए केन्द्रीय सरकार से ऋण प्राप्त करने के साथ-साथ खुले बाजार से भी बॉण्ड निर्गमित कर सकता है। नाबाडों आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण कोषों से भी राशि ले सकता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, वाणिज्यिक बैंकों से भी एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जमा भी प्राप्त कर सकता है।

संगठन—नाबाडों का प्रधान कार्यालय बम्बई में तथा देश भर में इसके 16 क्षेत्रीय केन्द्र हैं। बैंक के प्रबन्ध के लिए अध्यक्ष एवं प्रबन्ध सचालक के अतिरिक्त 12 सचालकों का सचालक मण्डल होता है। सचालक मण्डल में 4 ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं ग्रामीण विकास के विशेषज्ञ, 3 सचालक रिजर्व बैंक के सचालकों में से, 3 सचालक भारत सरकार के अधिकारियों में से एवं 2 सचालक राज्य सरकारों के अधिकारियों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक की सलाह से नियुक्त किये जाते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध सचालक का कार्यकाल 5 वर्ष एवं अन्य सचालकों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है। नाबाडों के सचालक मण्डल द्वारा एक सलाहकार परिषद की नियुक्ति भी की जायेगी, जिसमें कृषि, कृषि ऋण, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग से सम्बन्धित विशेषज्ञ होंगे।

कार्य—

- (i) कृषि, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, हस्तकला इत्यादी के लिए पुनः वित्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु नाबाडों अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन एवं मिश्रित ऋण की सुविधा वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय बैंकों को प्रदान करेगा।
- (ii) नाबाडों अपने कार्यकर्ताओं द्वारा शोध एवं विकास कार्य भी करायेगा, जिससे कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में शोध एवं अनुसन्धान को प्रोत्साहित किया जा सके।
- (iii) नाबाडों द्वारा ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में सस्यागत व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा तथा ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न समस्याओं जैसे— वाणिज्यिक बैंक एवं सहकारी समितियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करेगा।
- (iv) नाबाडों कृषि एवं ग्रामीण विकास सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन हेतु विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन करायेगा तथा अध्ययन के आधार पर केन्द्र व राज्य सरकारों व रिजर्व बैंक को आवश्यक सलाह देगा।

सारणी 10.14

भाषाई द्वारा उद्देश्य अनुसार वितरित ऋण राशि

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	लाघु सिधार्ह	भूमि विकास	कार्म यन्त्रीकरण	फल एवं वागान् बाली फसलें	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	अन्य	कुल ऋण
1981-82	251	11	128	33	98	79	600
1982-83	244	21	147	27	185	79	703
1983-84	312	29	204	38	233	76	892
1984-85	335	43	170	47	354	112	1061
1985-86	385	27	200	63	376	141	1192
1986-87	460	6	192	68	379	229	1334

स्रोत : Annual Report of National Bank for Agriculture and Rural Development.

लिये स्वतः रोजगार उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई थी, जिसके अन्तर्गत वर्ष 1987-88 में 101 लाख लगभग निवृत्त युवकों को 207.93 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया।

- (स) शहरी गरीबों के लिये स्वतः रोजगार कार्यक्रम (Self Employment Programme for Urban Poor-SEPUR)—यह कार्यक्रम सितम्बर, 1986 में शहरी गरीबों के लिये शुरू किया गया है जो सम्बन्धित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में नहीं आते हैं। इसमें भी उनके द्वारा स्वतः रोजगार प्राप्ति के लिये बैंक ऋण-सुविधा उपलब्ध कराते हैं। वर्ष 1987-88 में 30 63 करोड़ सामान्तिजों को 131 74 करोड़ रुपये का ऋण इस योजना में उपलब्ध कराया जा चुका है।
- (ख) सेवा-निवृत्त व्यक्तियों को स्वतः रोजगार उपलब्ध कराने का कार्यक्रम (Financial Assistance to Ex-servicemen for Self Employment-PEXSEM)—यह योजना देश के चुने हुए 18 जिलों में सेवा-निवृत्त व्यक्तियों को स्वतः रोजगार प्राप्त कराने के लिये वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्यान्वित है।
- (घ) अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्गों के बाहुल्यता वाले क्षेत्रों को विशेष ऋण-सुविधा भी बैंक उपलब्ध करा रहे हैं।
- (ग) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—खाद्यान्न उत्पादन में विशेष वृद्धि के लिये 14 राज्यों में से 169 चुने हुए जिलों में खाद्यान्न उत्पादन के लिये आवश्यक ऋण-सुविधा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम भी इन बैंकों द्वारा संचालित है।

(ब) निगम :

कृषकों को ऋण-सुविधा उपलब्ध कराने के क्षेत्र में चतुर्थ सस्थागत अभि-करण निगम होते हैं। निम्न निगम कृषि क्षेत्र की प्रत्यक्ष प्रथम परोक्ष रूप से ऋण-सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं—

(1) कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम—कृषकों को मध्यकालीन एवं दीर्घ-कालीन ऋण की पर्याप्त सुविधा के लिये सस्थागत अभिकरणों के विवक्षित नहीं होने, साहकारों द्वारा प्रदत्त ऋण पर व्याज की दर अधिक होने एवं उनके द्वारा प्रत्येक कटौतियाँ किये जाने के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषकों को कम व्याज दर पर ऋण-सुविधा उपलब्ध कराने एवं वर्तमान सस्थाओं को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये एक राष्ट्रीय स्तर की सस्था—वित्त निगम स्थापित करने की

व्यवस्था की गई। संसद ने 14 मार्च, 1963 को कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के द्वारा रिजर्व बैंक एवं केन्द्रीय सरकार की सहायता से 25 करोड़ रु० की अधिकृत शेयर पूंजी से एक जुलाई, 1963 को कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना बम्बई में की गई। इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुहम्मदाबाद, बंगलूर, भोपाल, भुवनेश्वर, कलकत्ता, चण्डीगढ़, गौहाटी, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, मद्रास, नई दिल्ली, पटना एवं त्रिवेन्द्रम में स्थापित किये गये।

कार्य—इसके प्रमुख कार्य निम्न हैं

(1) कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम का प्रथम कार्य प्रारम्भिक ऋणदात्री संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि ये संस्थाएँ कृषि विकास के लिए आवश्यक राशि में कृषकों को दीर्घकालीन ऋण स्वीकृत कर सकें। वर्तमान में सरकार, भूमि विकास बैंक एवं सहकारी समितियों के लिए कृषि-उद्योग को आवश्यक राशि में ऋण-सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है, विशेषतः उन कृषि उद्योगों को, जिनमें पूँजी का अधिक राशि में निवेश होता है तथा पूँजी के निवेश से फायदे के प्राप्त होने में काफी समयान्तर होता है जैसे—चाय, कॉफी, रबर, फलों के बाग। अतः कृषि पुनर्वित्त निगम, राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, अनुसूचित वारिष्ठ बैंक एवं पञ्जीकृत सहकारी समितियों को पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करता है। वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी निगम से पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम निम्न कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है—

- (अ) भूमि सुधार एवं भूमि को समतल करने के कार्यों के लिए—जिससे उपलब्ध सिंचाई सुविधा का पूर्ण उपयोग हो सके।
- (ब) विशेष फसलों—सुपारी, चाय, कॉफी, नारियल, काजू, इलायची, रबर, मसूर के बगीचे एवं फलों के बाग लगाने के लिए।
- (स) यान्त्रिक खेती, फार्म पर बिजुलीकरण, सिंचाई के लिए पम्पिंग स्टैंड लगाने, पौध-संरक्षण के लिए दवा छिड़कने वाले एवं प्रकीर्णक यन्त्र क्रय करने।
- (द) पशुपालन, दूध उत्पादन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि उद्योगों के विकास करने के लिए।
- (ध) सिंचाई के लिए नये कुओं का निर्माण, पुराने कुओं की मरम्मत, सिंचाई की नालियाँ बनाने।
- (र) साधारण को संग्रह करने के लिए गोदामों का निर्माण करने एवं चारे के लिए साइलोघर बनाने।

(2) के द्रीय भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एवं सहकारी समितियों द्वारा जारी किये गये ऋण पत्र (Debentures) क्रय करना जिसमें उनके वित्तीय साधनों में वृद्धि हो सके।

पूँजी-निगम की पूँजी के प्रमुख स्रोत निम्न हैं

(1) निगम की अधिकृत पूँजी 25 करोड़ रुपये है जो 25,000 शेयरों में विभाजित है। प्रत्येक शेयर 10,000 रुपये का होता है। ये शेयर रिजर्व बैंक, भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक जीवन बीमा निगम व अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा क्रय किये जाते हैं। केन्द्रीय सरकार निगम के शेयर के मूलधन व न्यूनतम लामाश (4 25 प्रतिशत) के भुगतान की प्रतिभूति देती है।

(2) निगम को वित्तीय साधनों में वृद्धि करने के लिए एक वर्ष की अवधि की नियत जमा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एवं स्वायत्त संस्थाओं द्वारा प्राप्त करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है।

(3) भारत सरकार ने कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम को 15 करोड़ रुपये का व्याज मुक्त ऋण भी स्वीकृत किया है। इस ऋण का भुगतान 5 वर्ष परचाद शुरू होकर 15 वर्ष में वार्षिक किश्तों में देय होगा।

प्रबन्ध—निगम का प्रबन्ध संचालक बोर्ड द्वारा किया जाता है। संचालक बोर्ड में 9 निदेशक होते हैं जो विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का उप-मैनेजर, कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम का अध्यक्ष होता है। उसके अतिरिक्त एक-एक प्रतिनिधि रिजर्व बैंक, राज्य सहकारी बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एवं जीवन बीमा निगम से तथा तीन प्रतिनिधि भारत सरकार के होते हैं। कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम के दैनिक कार्य का संचालन बोर्ड द्वारा नियुक्त कार्यकारिणी समिति करती है।

प्रगति—कृषि पुनर्वित्त व विकास निगम की वित्तीय सहायता राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक एवं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से आवश्यक लाभकर्ताओं तक उपलब्ध कराई जाती है। कृषि पुनर्वित्त व विकास निगम ने 1965 में 36 योजनाएँ स्वीकृत की थी, जिनके लिए स्वीकृत राशि 27 84 करोड़ रुपये थी। इन योजनाओं की सख्या बढ़कर दिसम्बर, 1980 में 3717 एवं उनके लिए कुल स्वीकृत ऋण राशि 1,715 करोड़ रुपये की थी। दिसम्बर, 1980 तक कृषि पुनर्वित्त व विकास निगम द्वारा दिए गए वित्त में से 54 प्रतिशत वित्त राज्य भूमि विकास बैंक के माध्यम से, 2 प्रतिशत राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से एवं 44 प्रतिशत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से वितरित किया गया था। वर्ष 1975-76 तक राज्य भूमि विकास बैंक ही मुख्य संस्था थी, जिसके माध्यम से 80 प्रतिशत वित्त का प्रवाह होता था। वर्ष 1975-76 के उपरान्त

बैंको द्वारा अनेक कार्यक्रम शुरू करने के कारण उनके माध्यम से प्रवाह करने वाले वित्त की प्रतिशतता में आशातीत परिवर्तन हुआ है। दिनांक 12 जुलाई, 1982 को कृषि क्षेत्र के लिए एक पृथक् बैंक नावाडें की स्थापना के साथ ही इस निगम को समाप्त करके नावाडें में सम्मिलित कर दिया गया है।

(11) कृषि वित्त निगम—कृषि ऋण की बढ़ती हुई आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, कृषि व्यवसाय की अल्प, मध्य एवं दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकताओं की वाणिज्यिक बैंको द्वारा पूर्ति करने के लिए 10 अप्रैल, 1968 को कृषि वित्त निगम की स्थापना की गई। कृषि वित्त निगम कम्पनीज कानून 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है। कृषि वित्त निगम की अधिकृत पूंजी 100 करोड़ रुपये तथा जमा पूंजी 5 करोड़ रुपये है। वर्ष 1978 में 35 वाणिज्यिक बैंक इसके सदस्य थे, जिनमें से 14 राष्ट्रीयकृत बैंक, 14 गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक एवं 7 विदेशी बैंक हैं।

प्रबन्ध—निगम का प्रबन्ध संचालक बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष एवं संचालक निदेशक होते हैं, जो राष्ट्रीयकृत बैंक, गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्त मन्त्रालय, कृषि एवं सिंचाई मन्त्रालय, कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम के प्रतिनिधि एवं कृषि अर्थशास्त्री होते हैं। कृषि वित्त निगम का पंजीकृत कार्यालय बम्बई तथा दो क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता (पूर्वी क्षेत्रों के लिए) एवं लखनऊ (उत्तरी क्षेत्रों के लिए) तथा प्रोजेक्ट कार्यालय पटना, कोटा, शिलांग एवं सूरत में हैं।

कार्य—कृषि वित्त निगम, वाणिज्यिक बैंको के माध्यम से ऋण विस्तार करके कृषि विकास के लिये राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। कृषि वित्त निगम के प्रमुख कार्य निम्न हैं—

- (1) कृषि वित्त निगम वाणिज्यिक बैंको को कृषि विकास कार्यक्रमों में अधिक भाग लेने हेतु सहायता प्रदान करता है।
- (2) कृषि वित्त निगम पिछड़े क्षेत्रों में बैंको द्वारा दिये जाने वाले ऋण हेतु प्रोजेक्ट तैयार करना एवं उसकी जाँच करके वाणिज्यिक बैंको को उनके लिये ऋण स्वीकृत करने के लिए आमन्त्रित करता है ताकि इन क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंक अधिकाधिक ऋण सुविधा उपलब्ध करा सकें।
- (3) कृषि वित्त निगम सदस्य बैंकों केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों, निगम एवं निजी उद्यमियों को तकनीकी सलाह प्रदान करता है। इसके लिए योजनाओं की तकनीकी सुगमता एवं वित्तीय आवश्यकताओं की जाँच भी करता है। ऋण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए भी वित्त उपलब्ध कराता है।

कृषि वित्त निगम ने मुख्यतया लघु सिंचाई योजना, कमाण्ड क्षेत्र विकास, समन्वित क्षेत्र विकास, फल विकास, मत्स्य विकास, डेयरी विकास, नियन्त्रित मण्डियों के लिए यार्ड एव गोदामों के निर्माण की योजनाएँ बनाई हैं साथ ही फसल ऋण, मुर्गी-पालन, भेड़ विकास, कुओं पर विद्युतीकरण, कृषि आधारित उद्योग, वन विकास, बागान वाली फसलों की विकास योजनाएँ भी इसके कार्यक्षेत्र में आती हैं। आधारभूत सुविधाओं का विकास, कृषि सेवा केन्द्र, सूखाग्रस्त क्षेत्रीय कार्यक्रम, विस्तृत क्षेत्र विकास कार्यक्रम, समन्वित जन-जाति विकास कार्यक्रम, बीज विकास कार्यक्रम एव कृषि क्षेत्र में ऋण सम्बन्धी अनुसन्धान भी इसकी योजनाओं में सम्मिलित हैं।

(4) कृषि वित्त निगम ऐसे कार्यक्रम भी सेता है जिससे कृषि क्षेत्र में अधिक ऋणों का उपयोग करने की क्षमता में वृद्धि हो सके जैसे-वाणिज्यिक बैंको, सरकार, योजना आयोग, राज्य सरकार, रिजर्व बैंक आदि इण्डिया एव अन्य संस्थाओं से सम्बन्ध बनाये रखना, ऋण के प्रपत्र में सरलीकरण करना एव सभी बैंकों को एक से ही प्रपत्र काम में लेने हेतु तैयार करना आदि।

(5) कृषि वित्त निगम वाणिज्यिक बैंकों की कृषि क्षेत्र में ऋण सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करके उनको हल करने के लिए सुझाव देता है।

(6) कृषि वित्त निगम वाणिज्यिक बैंकों के संगठन (Consortium) के कारक प्रादेशिक, राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की समितियों, बैंकों एव ऋण मण्डलों में प्रतिनिधित्व करता है।

(iii) कृषि-ऋण निगम—प्रो० डी० आर० गाडगिल की अध्यक्षता में नियुक्त कृषि वित्त उप-समिति ने 1944 में विभिन्न राज्यों में कृषि ऋण निगम स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम सुझाव दिया था। श्री आर० जी० सरैया की अध्यक्षता में 1946 में नियुक्त सहकारी नियोजन समिति एव ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने भी कृषि-ऋण निगम स्थापित करने का विचार प्रकट किया तथा राज्यों में सहकारी संस्थाओं के विकास पर अधिक बल देने का सुझाव दिया। रिजर्व बैंक के कृषि-ऋण संस्थागत अभिकरण के अनीपचारिक दल ने भी 1964 में सहकारी आन्दोलन में पिछड़े हुए राज्य—असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान एव केन्द्र शासित प्रान्तों—मणिपुर एव त्रिपुरा में कृषि-ऋण-निगम स्थापित करने का सुझाव दिया। रिजर्व बैंक का यह सुझाव 1966 में दिल्ली में आयोजित मुख्य-मन्त्रियों के सम्मेलन में स्वीकृत किया गया।

कृषि-ऋण-निगम स्थापित करने के लिए एक नवम्बर, 1968 को ससद द्वारा विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक के अनुसार सहकारी आन्दोलन में

असन्तोषजनक प्रगति वाले राज्य एवं अन्य इच्छित राज्य केन्द्र सरकार की अनुमति से कृषि-ऋण निगम स्थापित कर सकते हैं। फलस्वरूप असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल मणिपुर एवं त्रिपुरा में कृषि ऋण-निगम स्थापित किये गये। ये निगम प्रारम्भ में 5 वर्ष के लिए स्थापित किये गये थे तथा राज्यों में सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ होने पर कृषि ऋण निगम अपना कार्य सहकारी समितियों को सौंप देंगे, लेकिन इनकी महत्ता के कारण आज भी कार्यरत हैं।

कार्य—कृषि-ऋण-निगम का प्रमुख कार्य कृषकों को अल्प एवं मध्यकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। कृषि ऋण-निगम फसल-ऋण-पद्धति के आधार पर निम्न श्रेणियों के कृषकों को अल्पकालीन ऋण स्वीकार करते हैं।

(अ) वे कृषक, जो गेहूँ एवं चावल का उत्पादन करना चाहते हैं तथा उत्पादित वस्तुओं को भारतीय खाद्य निगम या उनके एजेंट के द्वारा विपणन करना स्वीकार करते हैं।

(ब) वे कृषक, जो गन्ना, जूट, तम्बाकू उत्पादन करना चाहते हैं तथा उत्पादित उत्पाद को राज्य-व्यापार-निगम, चीनी मिलों अथवा विपणन समितियों (जो राज्य व्यापार निगम के लिये कार्य करती हैं) द्वारा विपणन करना स्वीकार करते हैं।

निगम बड़े कृषकों को प्रत्यक्ष रूप से तथा लघु कृषकों को सामूहिक रूप से सामूहिक प्रतिभूति के आधार पर ऋण स्वीकृत करता है। कृषि ऋण निगम कृषकों की संस्था न होकर केन्द्र सरकार एवं रिजर्व बैंक की संस्था है।

पूँजी—कृषि-ऋण-निगम की अधिकृत पूँजी विभिन्न राज्यों में आवश्यकता-नुसार एक से 5 करोड़ रुपये रखी गई है। कृषि-ऋण-निगम केन्द्रीय सरकार, भारतीय खाद्य निगम, रिजर्व बैंक एवं राज्य सरकार को शेषर विपणन करके, स्टेट बैंक एवं रिजर्व बैंक से ऋण लेकर एवं प्राथमिक सहकारी समितियों से नियत अवधि की जमा स्वीकृत करके पूँजी एकत्रित करता है।

प्रबन्ध—निगम का प्रबन्ध, केन्द्र सरकार एवं रिजर्व बैंक से प्रतिनियुक्ति पर भ्राए अधिकारियों द्वारा किया जाता है। निगम की नीति-निर्धारण एवं संचालन का कार्य रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार होता है।

(14) ग्रामीण विद्युत्तीकरण निगम—ग्रामीण विद्युत्तीकरण निगम भी कृषि के क्षेत्र में ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्तमान में कृषि के लिए फार्म पर विद्युत् आवश्यक है। विद्युत् शक्ति के उपयोग से फार्म पर सिंचाई की लागत में कमी ही नहीं होती है, अपितु फार्म पर सघन कृषि, बहुफसलीय योजना एवं फसल-उत्पादन योजना में परिवर्तन करके अधिक लाभ कमा पाना भी सम्भव हो गया है।

कृषकों को ऋण प्रदान करने वाले साहूकार दो प्रकार के होते हैं :

- (i) पेशेवर साहूकार—पेशेवर साहूकार कृषकों को ऋण स्वीकृत करने के प्रतिरिक्त कृषि वस्तुओं में व्यापार भी करते हैं। ये कृषकों के प्रतिरिक्त अन्य उद्योगों वाले व्यवसायियों को भी ऋण प्रदान कराते हैं। इन्होंने वर्ष 1951-52 में कृषकों को विभिन्न अभिकरणों से प्राप्त कुल ऋण का 44.8 प्रतिशत अंश प्रदान किया था। वर्ष 1961-62 में यह अंश कम होकर 13.2 प्रतिशत व 1981-82 में 8.3 प्रतिशत ही रह गया। इन साहूकारों को कृषकों को ऋण स्वीकृति के क्षेत्र में उड़ीसा राज्य में प्रथम, बिहार, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त है।
- (ii) कृषक साहूकार—कृषक साहूकार कृषि कार्यों के लिए ऋण स्वीकृत करने के प्रतिरिक्त स्वयं कृषि भी करते हैं। कृषक साहूकार ने वर्ष 1951-52 में कृषकों को विभिन्न अभिकरणों से प्राप्त कुल ऋण का 24.9 प्रतिशत अंश प्रदान किया था, जो वर्ष 1961-62 में बढ़कर 36 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1971-72 में इनके द्वारा स्वीकृत ऋण का कुल ऋण में अंश 23.1 प्रतिशत ही रह गया। कृषक, साहूकारों से ऋण प्राप्ति में पेशेवर साहूकारों के स्थान पर कृषक साहूकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं। कृषक साहूकार, कृषकों को ऋण स्वीकृति में उड़ीसा राज्य में चौथे स्थान पर, महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल में वृत्तरे स्थान पर व शेष राज्यों में प्रथम स्थान पर हैं।

कृषि-ऋण में साहूकारों की प्रमुखता के कारण—कृषकों को ऋण-स्वीकृति के क्षेत्र में साहूकार विशेष स्थान रखते हैं जिसके प्रमुख कारण निम्न हैं—

- (1) ऋण स्वीकृति विधि की सरलता एवं सुगमता।
- (2) साहूकारों द्वारा कृषकों को सभी कार्यों के लिए अल्प, मध्य एवं दीर्घ-कालीन ऋण स्वीकृत करना।
- (3) साहूकारों द्वारा उत्पादन एवं उपभोग दोनों ही प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण स्वीकृत करना।
- (4) साहूकारों द्वारा कृषकों को रक्षित ऋण के अतिरिक्त अरक्षित ऋण भी आवश्यक राशि में स्वीकृत करना।
- (5) साहूकारों का ऋण-स्वीकृति का निश्चित समय न होकर किसी भी समय पहुँचने की छूट होना।
- (6) ऋण-स्वीकृति-अवधि में आवश्यकता होने पर ऋणी की सुविधानुसार समय में वृद्धि कर देना।

- (7) ऋण चुकाने के लिए व्याज एवं मूलधन का सम्मिलित भुगतान करने एवं पृथक् रूप में आंशिक राशि का भुगतान करने की कृपको को छूट होना ।
- (8) साहूकारों का कृपको से व्यक्तिगत सम्बन्ध होना ।
- (9) साहूकारों को कृपको की वित्तीय स्थिति का ज्ञान होना ।
- (10) साहूकारों द्वारा कृपको की ऋण-सम्बन्धी जानकारी को गोपनीय रखना ।
- (11) साहूकारों द्वारा कृपको की विभिन्न मुसीबतों में सहायता करना ।

साहूकारों से ऋण-प्राप्ति में कृपको को उपर्युक्त सुविधाओं के होते हुए भी, साहूकारों द्वारा कृषि-ऋण में अनेक कुचालों के उपयोग के कारण ऋण की लागत अधिक प्राप्ती है । साहूकारों की ऋण के क्षेत्र में प्रयुक्त कुचालें निम्न हैं—

- 1 स्वीकृत ऋण पर व्याज की दर अधिक लेना । साहूकार कृपको से स्वीकृत ऋण पर 18 से 40 प्रतिशत व्याज वसूल करते हैं, जो सस्पागत अभिकरणों से प्राप्त ऋण के व्याज-दर की अपेक्षा कई गुना अधिक होती है ।
- 2 ऋण चुकाने की अवधि का व्याज ऋण स्वीकृत करते समय अग्रिम रूप से काट लेना, जिसके कारण कृपको को स्वीकृत ऋण राशि से कम धन प्राप्त होता है और वास्तविक व्याज की दर अधिक होती है ।
- 3 ऋण स्वीकृत करते समय साहूकारों द्वारा स्वीकृत राशि में से अनेक प्रकार की कटौतियाँ काट लेना, जैसे—काटा, धर्मादा मुनीमी, लिखाई, गिरह खुलाई आदि ।
- 4 स्वीकृत ऋण राशि से अधिक राशि का ऋण-पत्र लिखवा लेना और कृपको की अज्ञानता का लाभ उठाते हुए अधिक मूलधन वसूल करना ।
- 5 ऋण वसूल करते समय कृपको से व्याज निर्धारित दर से अधिक जोड़ लेना और ऋण भुगतान की रसीद नहीं देना ।
- 6 ऋण स्वीकृत करते समय ऋणों की शर्तों में भ्रू-सम्पत्ति का प्रतिबन्ध सहित विनयनामा लिखवा लेना जिससे कृपको द्वारा समय पर ऋण भुगतान नहीं किए जाने की अवस्था में भ्रू-सम्पत्ति पर कब्जा कर लेना ।
- 7 कृपको से खाली कागज पर झूठा या हस्ताक्षर करवा लेना, तत्पश्चात् इच्छित ऋण राशि एवं शर्तों को उसमें लिख लेना ।

साहूकारों की उपर्युक्त कुचालों पर नियन्त्रण लगाने के लिए सरकार ने समय-समय पर विभिन्न कानून पारित किये हैं । पारित किये गये कानूनों का

मुख्य उद्देश्य ऋण के क्षेत्र में प्रचलित कुचालों से कृषकों की रक्षा करना है। इसके लिए सरकार ने व्याज दर कानून, हिसाब नियन्त्रण कानून, साहूकारों का पंजीकरण करना, अनावश्यक कटौतियों पर प्रतिबन्ध, व्याज की अधिकतम भुगतान राशि आदि के सम्बन्ध में कानून पारित किये हैं, जिनके होने से ऋणी कृषक साहूकार की कुचालों से रक्षा के लिए कानून की सहायता ले सकते हैं।

(ब) व्यापारीक व आढतियाँ

कृषकों के लिए ऋण प्राप्त करने का गैर-संस्थागत अभिकरणों में दूसरा प्रमुख स्रोत व्यापारी एवं आढतियाँ हैं। व्यापारी एवं आढतियाँ मुख्यतया अल्प-कालीन ऋण स्वीकृत करते हैं और फसल के विपणन से कृषकों को प्राप्त राशि में से अपना ऋण वसूल करते हैं। व्यापारी एवं आढतियों से ऋण प्राप्त करने के कारण कृषकों के लिए इन संस्थाओं के माध्यम से फार्म से प्राप्त उत्पाद का विक्रय करना आवश्यक होता है। व्यापारी कृषकों की मजबूरी का लाभ उठाते हुए खाद्यान्नों की बिक्री से प्राप्त आय में से कई प्रकार की कटौतियाँ करते हैं, जिससे कृषकों को खाद्यान्न की उचित कीमत प्राप्त नहीं होती है। व्यापारी एवं आढतियों ने वर्ष 1951-52 में कृषकों को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कुल ऋण का 55 प्रतिशत अंश ऋण के रूप में प्रदान किया था, जो वर्ष 1961-62 में 88 प्रतिशत एवं 1981-82 में 34 प्रतिशत हो रहा गया। ऋण के क्षेत्र में व्यापारी एवं आढतियों की महत्ता कम हुई है। विभिन्न राज्यों में कृषकों को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ऋण की राशि के आधार पर व्यापारियों को उड़ीसा व जम्मू एवं कश्मीर में द्वितीय स्थान, आन्ध्रप्रदेश में तृतीय स्थान एवं असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल में चतुर्थ स्थान प्राप्त है।

(स) सम्बन्धी, मित्र एवं विविध स्रोत

गैर-संस्थागत अभिकरणों में कृषकों के लिए ऋण का तीसरा स्रोत 'सम्बन्धी', मित्र एवं विविध स्रोत हैं। उत्पादन एवं उपभोग कार्यों के लिए आवश्यक ऋण कृषक अपने सम्बन्धियों एवं मित्रों से प्राप्त करते हैं। कृषकों को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कुल ऋण का वर्ष 1951-52 में 16.0 प्रतिशत, 1961-62 में 22.7 प्रतिशत व 1971-72 में 16.6 प्रतिशत ऋण सम्बन्धियों से प्राप्त हुआ था। असम, गुजरात, बिहार, केरल महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल में सम्बन्धियों ने अन्य राज्यों की अपेक्षा कृषकों को अधिक ऋण सुविधा उपलब्ध करायी है।

(द) जमींदार एवं भू स्वामी :

जमींदार एवं भू स्वामी भी कृषकों को भूमि जोतने, उत्पादन-साधनों के प्रयोजन आदि कार्यों के लिए ऋण-सुविधा प्राप्त कराते हैं। जमींदारों एवं भू-स्वामियों ने वर्ष 1951-52 में कृषकों को विभिन्न अभिकरणों से प्राप्त कुल ऋण का 1.5

प्रतिशत अंश प्रदान किया था। यह अंश वर्ष 1961-62 में कम होकर मात्र 0.6 प्रतिशत ही रह गया। इसका प्रमुख कारण देश में जमींदारी प्रथा की समाप्ति के साथ-साथ देश में जमींदारों की सहायता का कम होना था। वर्ष 1971-72 में भू-स्वामियों ने कृषकों को प्राप्त कुल ऋण का 8.6 प्रतिशत ऋण-सुविधा उपलब्ध कराई थी।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया

रिजर्व बैंक कानून, 1934 के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना एक घण्टी, 1935 को हुई थी। एक जनवरी, 1944 से इसे केन्द्रीय बैंक बना दिया गया। रिजर्व बैंक कानून की धारा 54 के अन्तर्गत रिजर्व बैंक में कृषि ऋण विभाग की स्थापना की गई। ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने सुझाव दिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय कोष स्थापित किया जाए, इसके द्वारा दिये जाने वाले मध्यकालीन ऋणों पर से प्रतिबन्ध हटाये जायें तथा कृषि-ऋण विभाग का विस्तार किया जाये। तत्पश्चात् रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया कानून में वर्ष 1955 में संशोधन किया गया। रिजर्व बैंक, बैंकिंग ससार के भिन्न, पथ-प्रदर्शक एवं हितैषी के रूप में कार्य करता है। रिजर्व बैंक के कृषि-ऋण-विभाग के प्रमुख कार्य ये हैं—

- (i) कृषि-ऋण से सम्बन्धित समस्याओं के अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति करना।
- (ii) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा सहकारी संस्थाओं को कृषि-ऋण के विषय में तकनीकी सलाह प्रदान करना।
- (iii) कृषि कार्यों के लिए राज्य सहकारी बैंक के द्वारा वित्त प्रदान करना।
- (iv) रिजर्व बैंक के कृषि-ऋण कार्यों एवं कृषि के क्षेत्र में ऋण प्रदान करने वाले बैंकों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना।

रिजर्व बैंक कृषकों को सीधे रूप से ऋण-सुविधा उपलब्ध नहीं कराता, बल्कि राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक एवं प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है। रिजर्व बैंक सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंकों को ऋण-सुविधा प्रचलित ब्याज दर से 2 प्रतिशत कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराता है।

रिजर्व बैंक के कार्य—(1) रिजर्व बैंक कानून की अश्वकित धाराओं के अन्तर्गत अल्प-कालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है—

अल्पकालीन ऋण—रिजर्व बैंक धारा 17 (2) (ब) एवं 17 (4) (स) के अन्तर्गत राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को कृषि-कार्यों एवं विपणन के लिए 12 से 15 माह की अवधि में परिपक्व होने वाले अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक कानून की धारा 17 (4) (घ) के अन्तर्गत

भूमि-विकास बैंक द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रों की प्रतिभूति पर भी मध्यकालीन ऋण प्रदान करता है ।

मध्यकालीन ऋण—रिजर्व बैंक धारा 17 (4) (घ) के अन्तर्गत राज्य सहकारी बैंक को सरकार की प्रतिभूति पर 15 माह से 5 वर्ष की अवधि के लिए मध्यकालीन ऋण प्रदान करता है । रिजर्व बैंक द्वारा 1956 में स्थापित राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन) कोष एवं राष्ट्रीय कृषि-ऋण (स्थिरीकरण) कोष के द्वारा भी मध्यकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है ।

दीर्घकालीन ऋण—रिजर्व बैंक ने श्री ए डी गोरवाला की अध्यक्षता में नियुक्त ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति, 1954 के सुझाव के अनुसार दीर्घकालीन ऋण की सुविधा के लिए राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन) कोष [National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund] की स्थापना करवरी, 1956 में की । इस कोष की स्थापना 10 करोड़ रुपये से की गई थी और यह प्रावधान रखा गया था कि इस कोष में आगामी 5 वर्षों में प्रतिवर्ष कम से कम 5 करोड़ रुपये दिये जायेंगे । इस कोष की राशि से सहकारी ऋण सस्यामों की पूंजी में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों को 20 वर्ष की अवधि के लिए ऋण स्वीकृत एवं केन्द्रीय भूमि विकास बैंक के 20 वर्षीय अवधि के ऋण-पत्रों का क्रय किया जायेगा । एक जुलाई, 1960 को इस कोष में 40 करोड़ रुपये की धनराशि थी, जो बढ़कर 12 जुलाई, 1982 को 1,205 करोड़ रुपये हो गई । इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) कोष में रिजर्व बैंक की जमा धन-राशि एक जुलाई, 1960 को 5 करोड़ रुपये थी, जो 12 जुलाई, 1982 को 440 करोड़ रुपये हो गई । नाबार्ड की स्थापना हो जाने पर 12 जुलाई, 1982 को यह दोनों कोष रिजर्व बैंक से नाबार्ड का स्थानान्तरित कर दिये गये ।

- (2) रिजर्व बैंक सहकारी ऋण के विकास के लिए परामर्श देता है । इसके लिए रिजर्व बैंक ने स्थायी रूप से ग्रामीण सहकारी ऋण सलाहकार समिति (Standing Advisory Committee on Rural Cooperative Credit) की नियुक्ति वर्ष 1951 में की थी ।
- (3) रिजर्व बैंक 1951 से जिला एवं राज्य सहकारी बैंकों का निरीक्षण का कार्य भी करता है ।
- (4) रिजर्व बैंक समय-समय पर विभिन्न राज्यों व जिलों में ऋण सर्वेक्षण करके प्रतिवेदन प्रकाशित करता है । रिजर्व बैंक के प्रकाशित प्रतिवेदनो में अखिल भारतीय ऋण सर्वेक्षण समिति का प्रतिवेदन 1951-52, अखिल भारतीय ऋण एवं विनियोग सर्वेक्षण रिपोर्ट 1961-62 एवं अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट 1969

प्रमुख है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक एक मामिक पत्रिका रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन भी प्रकाशित करता है।

- (5) रिजर्व बैंक सहकारी प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रशिक्षण विद्यालयों में उच्च-स्तरीय एवं मध्यम श्रेणी के कार्यकर्त्ताओं के लिए खोले गये प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करता है।

कृषि-ऋण की विपणन से सम्बद्धता

ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति, 1951-52 द्वारा सुझाई गई कृषि ऋण की एकीकृत योजना (Integrated Scheme of Rural Credit) का एक मुख्य भाग सहकारी समितियों द्वारा स्वीकृत कृषि ऋण की राशि का विपणन से सम्बन्ध होना था। इसके अन्तर्गत प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों के सदस्यों को उत्पादित वस्तुओं का विपणन, विपणन समितियों के माध्यम से करना एवं उनके विक्रय से प्राप्त आय में से दिया गया उत्पादन-ऋण वसूल करना सम्मिलित है। समय समय पर अन्य समितियों ने भी कृषि ऋण एवं विपणन से सम्बद्धता के सुझाव दिये। वर्तमान में यह अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है क्योंकि प्रथम तो कृषकों की उत्पादन-ऋण की आवश्यकता में काफी वृद्धि हो गई है तथा दूसरी ओर सहकारी समितियों की बकाया राशि पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ गई है। अतः यदि कृषकों से ऋण-वसूली के लिए शीघ्र कदम नहीं उठाये गये तो देश में सहकारी ऋण का ठीका अस्त-व्यस्त हो जायेगा।

भारत सरकार ने अगस्त, 1962 में कृषि-ऋण का विपणन से सक्षम सम्बद्धता के लिए निम्न सिफारिशों की थी—

- (1) प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा कृषकों को उत्पादन हेतु ऋण स्वीकृत करते समय अनुबन्ध पत्र लिखवाना चाहिए कि वे ऋण मुगनान राशि के मूल्य का उत्पादित मास विपणन सस्था के माध्यम से विक्रय करेंगे। साथ ही विपणन-समिति को उसके द्वारा बचे गये खाद्यान्नों की कोमत राशि में से, प्राथमिक सहकारी ऋण समिति से प्राप्त ऋण की राशि को काटने का अधिकार होगा।
- (2) विपणन-संस्थाओं एवं प्राथमिक कृषि-सहकारी ऋण समितियों के मध्य पूर्ण सम्बन्ध होना चाहिये।
- (3) फसल की कटाई के पूर्व प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति द्वारा, विपणन समिति को कृषक-सदस्यों की वसूली की राशि की पूर्ण सूची भिजवा देनी चाहिये।
- (4) प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति के कार्यकर्त्ताओं द्वारा सदस्यों की फसल की कटाई पर पूर्ण निगरानी रखनी चाहिए तथा उनके

द्वारा कोशिश की जानी चाहिए कि सदस्य किये गये बायदो को पूर्ण रूप से निभाएँ ।

- (5) विपणन समिति द्वारा कृषको को बेचे गये उत्पाद की कीमत का मुग्तान, प्राथमिक कृषि-ऋण सहकारी समिति को ऋण को राशि मय व्याज के काटने के बाद ही करना चाहिए ।
- (6) केन्द्रीय सहकारी बैंको के अधिकारियों द्वारा प्राथमिक कृषि-ऋण सहकारी समितियों की ऋण-राशि की बसूली में सहायता करनी चाहिए ।
- (7) उत्पादन-ऋण के मुग्तान का समय, फसल की कटाई के समयानुसार नियत किया जाना चाहिए ।
- (8) इस योजना द्वारा उत्पाद-विक्रय करने वाले कृषको को व्याज की दर में कुछ छूट देनी चाहिए तथा आवश्यकता होने पर उन्हें उपभोग-ऋण भी स्वीकृत करना चाहिए ।



ऋण-प्रबन्ध के सिद्धान्त

कृपको, ऋणदात्री सन्स्थाओं एवं प्रसार-कार्यकर्ताओं के लिए ऋण के सिद्धान्तों का ज्ञान होना आवश्यक है। ऋण-प्रबन्ध के तीन मुख्य सिद्धान्त हैं जिन्हें ऋण के तीन 'भार' (3 'R's of Credit) कहते हैं।

- (1) ऋण के उपयोग से प्राप्त आय की राशि (Returns),
- (11) ऋणों की ऋण-प्रदायगी क्षमता (Repayment Capacity),
- (111) ऋणों की जोखिम-बहन-योग्यता (Risk Bearing Ability),

ऋणदात्री सन्स्था द्वारा ऋण स्वीकृत करने से पूर्व ऋण के उपर्युक्त तीनों 'भार' पक्ष में होने चाहिए, अन्यथा ऋण स्वीकृति में जोखिम अधिक होती है। इसी प्रकार ऋण के उपर्युक्त तीनों 'भार' पक्ष में होने पर ही कृपको को ऋण लेना चाहिए। ऋण के उपर्युक्त तीनों सिद्धान्तों में से किसी भी एक सिद्धान्त के पक्ष में न होने की स्थिति में कृपक के लिए समय पर ऋण का चुका पाना तथा ऋणदात्री सन्स्था द्वारा समय पर ऋण वसूल कर पाना सम्भव नहीं होता है। अतः ऋण के विभिन्न 'भार' लागू न होने की अवस्था में कृपको के लिए ऋण-प्राप्ति व ऋणदात्री सन्स्थाओं के लिए ऋण स्वीकृति नुकसानदेह होता है। ऋण प्रबन्ध के तीनों 'भार' सिद्धान्तों का विश्लेषण करने के उपरान्त, ऋण प्रबन्ध के अन्य सिद्धान्त, जिन्हें ऋण के चार 'सी' (4 C's of Credit) एवं ऋण के पांच 'पी' (5 P's of Credit) कहते हैं, का विश्लेषण भी करना चाहिए। ऋण के चार 'सी'—गुण (Character), क्षमता (Capacity) पूंजी (Capital) एवं शर्तें (Conditions) हैं। ऋण के पांच 'पी' उद्देश्य (Purpose), व्यक्ति (Person), उत्पादकता योजना (Productivity Planning) किश्त का भुगतान (Payment of instalment) एवं सरक्षण प्रतिभूति (Protection Security) है।

ऋण प्रबन्ध के उपरोक्त तीनों प्रकार के सिद्धान्त—तीन 'भार', चार 'सी' एवं पांच 'पी' आपस में सम्बन्धित हैं। ऋण का तीसरा 'भार' सिद्धान्त ऋणों की

जोखिम बहन योग्यता, प्रथम एवं चतुर्थ 'सी' गुण एवं शर्तें तथा द्वितीय एवं पाँचवा 'पी' व्यक्ति तथा सरक्षण प्रतिभूति कृषको की जोखिम बहन योग्यता के द्योतक हैं। इसी प्रकार ऋण प्रबन्ध का द्वितीय 'आर' ऋण अदायगी क्षमता, द्वितीय 'सी' क्षमता एवं चतुर्थ 'पी' किश्त का भुगतान भी सम्बन्धित है जो ऋणी की ऋण अदायगी क्षमता के द्योतक है।

ऋण-प्रबन्ध के 'आर' सिद्धान्त

1. ऋण के कृषि में निवेश करने से प्राप्त आय की राशि :

ऋण-प्रबन्ध का प्रथम सिद्धान्त है कि कृषि में निवेशित राशि से जो अतिरिक्त आय प्राप्त होती है क्या वह ऋण एवं व्याज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है ? यदि ऋण से प्राप्त अतिरिक्त आय, ऋण एवं व्याज की सम्मिलित राशि से अधिक है तो कृषको को ऋण प्राप्त करना चाहिए एवं ऋणदात्री संस्था को ऋण स्वीकृत करना चाहिए। यदि ऋण के उपयोग से प्राप्त अतिरिक्त आय, ऋण एवं व्याज की सम्मिलित राशि से कम है तो कृषको को उस कार्य के लिए ऋण प्राप्त नहीं करना चाहिए एवं ऋणदात्री संस्था को ऋण स्वीकृत नहीं करना चाहिए। प्राप्त अतिरिक्त आय, ऋण एवं व्याज की सम्मिलित राशि से अधिक होने पर ही, ऋण स्वीकृति के लिए ऋण-प्रबन्ध के दूसरे सिद्धान्त-ऋण-अदायगी क्षमता की जाँच करनी चाहिए।

2. कृषको की ऋण-अदायगी-क्षमता :

ऋण-प्रबन्ध के दूसरे सिद्धान्त के अनुसार यह देखा जाता है कि क्या कृषक के पास ऋण को निश्चित समय पर निर्धारित किश्तों में चुकाने की क्षमता है ? अर्थात् क्या कृषक को प्राप्त अतिरिक्त आय, ऋण अदायगी की निर्धारित किश्तों के समयानुसार प्राप्त होती है ? उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक होने पर ही ऋण-दात्री संस्था द्वारा कृषको को ऋण स्वीकृत किया जाना चाहिए और नकारात्मक उत्तर प्राप्त होने की स्थिति में ऋणदात्री संस्था द्वारा निर्धारित शर्तों पर ऋण स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

ऋण-प्रबन्ध के प्रथम एवं द्वितीय सिद्धान्त का उत्तर पक्ष में होने अर्थात् कृषक के पास पर्याप्त अतिरिक्त आय एवं ऋण अदायगी क्षमता के होने पर ऋण स्वीकृति के तीसरे सिद्धान्त जोखिम बहन योग्यता की जाँच करनी चाहिए।

3. कृषकों की जोखिम-बहन योग्यता :

ऋण प्रबन्ध के तीसरे सिद्धान्त के अनुसार ऋणदात्री संस्था को यह निश्चित करना होता है कि क्या कृषको के पास याकलित उत्पादन की मात्रा प्राप्त नहीं होने की स्थिति में ऋण चुकाने की क्षमता है ? कृषि व्यवसाय प्रकृति पर निर्भर होता है, एवं इसमें ग्रन्थ उद्योगों की अपेक्षा जोखिम अधिक होती है। इस सिद्धान्त में कृषको

की सम्पत्ति की पर्याप्तता की जाँच करते हैं जिससे मौसम की प्रतिकूलता—ओले, अतिवर्षा, सूखा आदि की स्थिति में फार्म पर उत्पादन कम होने अथवा नहीं होने की स्थिति में सम्पत्ति विक्रय करके ऋण का भुगतान कर सके। यदि कृषक के पास ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त सम्पत्ति है, तो उसे ऋण स्वीकृत करना चाहिए। कृषको के पास पर्याप्त मात्रा में सम्पत्ति नहीं होने की अवस्था में ऋण स्वीकृत नहीं करना चाहिए। कृषको के पास उपलब्ध सम्पत्ति उनके जोखिम बहुत योग्यता की छोटक होती है।

ऋण-प्रबन्ध के उपर्युक्त तीनों सिद्धान्तों की जाँच के आधार पर स्वीकृत ऋण का भुगतान सुगमता में होता है तथा ऋणदात्री संस्था को ऋण-बचूली में परेशानी नहीं होती है। कृषको पर ऋण बकाया भी नहीं रहता है।

ऋण-प्रबन्ध के 'भार' सिद्धान्तों की जाँच करने की विधि :

ऋण-प्रबन्ध के 'भार' सिद्धान्तों की जाँच करने की विधि का विस्तृत विवरण नीचे दिया जा रहा है—

1. ऋण के कृषि में निवेश करने से प्राप्त आय की राशि •

कृषक प्राप्त ऋण को कृषि में निवेश करने से होने वाली अतिरिक्त आय की राशि का ज्ञान फार्म-योजना बनाकर कर सकते हैं। ऋण-प्राप्ति से पूर्व की फार्म-योजना से प्राप्त आय एवं ऋण-प्राप्ति के उतराना बनाई गई फार्म-योजना से प्राप्त आय का अन्तर, ऋण के उपयोग से प्राप्त अतिरिक्त आय की राशि को प्रदर्शित करता है। फार्म-योजना कृषक, ऋणदात्री संस्था, प्रसार अधिकारी या फार्म-प्रबन्ध विशेषज्ञों के द्वारा बनाई जा सकती है। ऋण के उपयोग से होने वाली अतिरिक्त आय की राशि ज्ञात करने के लिए बनायी जाने वाली फार्म-योजना में निम्नांकित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है—

1. फार्म-योजना से प्राप्त आय की राशि का ज्ञान प्रस्तावित ऋण से ऋय किये जाने वाले उत्पादन साधनों के उपयोग के आधार पर करना चाहिए।
2. फार्म योजना से प्राप्त आय का निर्धारण सीमान्त लागत व सीमान्त आय के आधार पर किया जाना चाहिए।
3. फार्म में अधिकतम आय की प्राप्ति के लिए सीमान्त ऋण राशि का उपयोग सीमान्त लागत व सीमान्त आय के सिद्धान्त के अनुरिक्त, सम-सीमान्त-प्रतिफल के सिद्धान्त के आधार पर करना चाहिए।
4. प्रस्तावित ऋण के आधार पर फार्म-योजना बनाते समय उत्पादन के अन्य साधन जैसे—भूमि, श्रम, सिंचाई आदि की उपलब्ध मात्रा को

भी ध्यान में रखना चाहिए। फार्म से प्राप्त होने वाली आय सीमित उत्पादन-साधन की मात्रा पर निर्भर करती है।

- 5 फार्म-योजना बनाते समय कृषकों को उत्पादन कार्यों के लिए ऋण की आवश्यकता के साथ-साथ उपभोग ऋण की आवश्यक राशि की भी पूर्ति करनी चाहिए, अन्यथा कृषक उत्पादन-कार्यों के लिए प्राप्त ऋण का उपभोग कार्यों में उपयोग करेंगे, जिससे फार्म पर प्राकृतिक आय प्राप्त नहीं होगी।

अतः कृषक को वर्तमान में फार्म से प्राप्त आय व ऋण प्राप्ति के उपरान्त फार्म से प्राप्त होने वाली आय का अन्तर ऋण के उपयोग से होने वाली अतिरिक्त आय होती है। यह अतिरिक्त आय ही ऋण चुकाने के लिए उपलब्ध होती है।

2. कृषकों की ऋण-अदायगी-क्षमता :

ऋण के उपयोग से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय की राशि, ऋण एवं ब्याज की सम्मिलित राशि से अधिक होने पर भी आवश्यक नहीं है कि कृषक प्राप्त ऋण का समय पर निर्धारित किश्तों में भुगतान कर सकेगा। अतः ऋण का समय पर भुगतान कर पाने के लिए कृषक की ऋण-अदायगी-क्षमता की जाँच करना आवश्यक होता है।

ऋण के फार्म पर उपयोग करने से आय में वृद्धि होती है, लेकिन आय में वृद्धि विभिन्न उद्यमों से विभिन्न समय पर होती है। उदाहरणतया, यदि प्राप्त ऋण का भुगतान प्रत्येक तीसरे महीने किश्तों में करना है और ऋण को कृषि उद्यम में निवेश करने से आय वर्ष में दो बार अर्थात् खरीफ एवं रबी की फसल की फटाई के पश्चात् प्राप्त होती है, तो कृषक के लिए कृषि उद्यम से पर्याप्त आय प्राप्त होते हुए भी समय पर ऋण भुगतान करना सम्भव नहीं होता है। अतः कृषकों की ऋण से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय के साथ-साथ ऋण-अदायगी-क्षमता भी जात करना चाहिए।

ऋण अदायगी-क्षमता से तात्पर्य उस अतिरिक्त आय की राशि से है जो प्राप्त आय में से उत्पादन-लागत व उपभोग खर्च घटाने के बाद शेष रहती है और जो ऋण चुकाने लिए उपलब्ध होती है। ऋण-अदायगी-क्षमता जात करते समय कृषकों की सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय सम्मिलित करनी चाहिए। कृषकों की ऋण-अदायगी-क्षमता निम्नांकित विधियों द्वारा जात की जाती है—

- (1) भूमि के लगान की राशि का 30 गुना एवं कृषि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों में प्राप्त आय का 25 प्रतिशत-दस विधि द्वारा ऋण की अधिकतम सीमा (Maximum Credit Limit), कृषकों द्वारा भूमि के लगान की दी जाने वाली राशि को 30 गुना एवं कृषि के अतिरिक्त अन्य

स्रोतों से प्राप्त आय की 25 प्रतिशत राशि के समतुल्य आकलित की जाती है। ऋण की अधिकतम सीमा के आकलन की यह विधि दिसम्बर, 1958 के पूर्व तक प्रचलित थी। इस विधि के अन्तर्गत ऋण की अधिकतम सीमा भूमि के लगान की राशि का 30 गुना आकलित करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।

- (11) प्राप्त आय का एक-तिहाई भाग ऋण-अदायगी-क्षमता होना-कृषकों की ऋण-अदायगी-क्षमता का आकलन करने की यह विधि सहकारी समितियों द्वारा दिसम्बर, 1958 के उपरान्त प्रयुक्त की गई थी। इस विधि में कृषकों की फार्म एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त कुल आय का एक-तिहाई भाग ऋण-अदायगी-क्षमता मानी जाती है और आय का शेष दो-तिहाई भाग फार्म पर फसलों की उत्पादन-लागत एवं घरेलू आवश्यक वस्तुओं को खर्च करने में खर्च करने के लिए आवश्यक होती है। ऋण-अदायगी क्षमता ज्ञात करने की इस विधि के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं, जिनके कारण वर्तमान में यह विधि प्रचलित नहीं है—
- (अ) कृषकों की फार्म से प्राप्त होने वाली आय का आकलन फार्म पर पिछले वर्षों में प्राप्त औसत उत्पादन की मात्रा के आधार पर किया जाता है। औसत उत्पादन की मात्रा वर्तमान एवं भावी उत्पादन की मात्रा का सही प्रतीक नहीं होती है।
- (ब) विभिन्न फसलों की प्रति हैक्टर उत्पादकता विभिन्न क्षेत्रों, फसल-चक्र, भूमि-प्रबंध एवं जोत के आकार के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। उपर्युक्त विधि के द्वारा ऋण-अदायगी-क्षमता ज्ञात करने में एक ही माप दण्ड का उपयोग किया जाता है जो विभिन्न वर्गों के कृषकों की वास्तविक स्थिति का प्रतीक नहीं होता है।
- (स) इस विधि के द्वारा ऋण-अदायगी क्षमता ज्ञात करने में पिछले वर्षों की औसत कीमतों को औसत उत्पादन की मात्रा से गुणा करते हैं। कृषि उत्पादों की कीमतों में निरन्तर उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। अतः फार्म उत्पाद की पिछली औसत कीमत वर्तमान कीमत का प्रतीक होना आवश्यक नहीं है, जिसके कारण भी कृषकों की सही ऋण-अदायगी-क्षमता ज्ञात नहीं हो पाती है।
- (द) विभिन्न फार्मों पर उत्पादन-साधनों की उपयोग की मात्रा में भिन्नता के कारण उत्पादन-लागत की राशि में भी भिन्नता होती है। विभिन्न कृषकों का घरेलू उपयोग खर्च भी विभिन्न होता है। अतः सभी फार्मों पर एक ही आधार पर उत्पादन-क्षमता का आकलन करना सही नहीं है।
- (य) इस विधि द्वारा ऋण की ऋण-अदायगी-क्षमता का निर्धारण करते

समय फार्म-प्रबन्धक की योग्यता एवं दक्षता को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जो फार्म आय में परिवर्तन लाने का प्रमुख कारक होता है।

- (र) कृषकों द्वारा फार्म पर उपभोग हेतु किए गए विभिन्न प्रकार के ऋणों जैसे स्वतः परिसंसाधन ऋण, आश्रित परिसंसाधन ऋण व अपरिसंसाधन ऋण से प्राप्त होने वाली आय में निम्नता होती है, लेकिन ऋणों को ऋण-प्रदायगी क्षमता प्राप्त करने की इस विधि में ऋणों के उन्मुख रूपों को ध्यान में नहीं रखा जाता है।

- 3 फार्म उत्पादन योजना के आधार पर ऋण-प्रदायगी-क्षमता प्राप्त करना—इस विधि में कृषकों को ऋण-प्रदायगी-क्षमता फार्म से प्राप्त होने वाली आय की राशि के आधार पर प्राप्त की जाती है। फार्म से प्राप्त होने वाली आय का निर्धारण फार्म-योजना के आधार पर किया जाता है। फार्म-योजना के द्वारा फार्म से प्राप्त होने वाली प्रतिरिक्त आय की राशि प्राप्त करने के पश्चात् विभिन्न प्रकार के प्राप्त ऋणों के निम्न मूकों द्वारा ऋण प्रदायगी-क्षमता प्राप्त की जाती है।

- (घ) स्वतः परिसंसाधन—वे ऋण जिनके द्वारा क्रय किए गए उत्पादन-साधन उत्पादन-विधि में पूर्ण रूप से काम में आ जाते हैं, स्वतः परिसंसाधन ऋण कहलाते हैं। जैसे—बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशी दवाइयाँ आदि के लिए प्राप्त ऋण। उन्मुख कार्यों के लिए प्राप्त ऋण फार्म की कार्यशील लागत में सम्मिलित हो जाते हैं और प्राप्त ऋण से क्रय किये गये उत्पादन-साधनों के उपयोग से आय मुह्यतया उसी वर्ष प्राप्त होती है। स्वतः परिसंसाधन ऋण की अवस्था में ऋण शुक्राने की क्षमता प्राप्त करने का मूल निम्न है—

ऋण-प्रदायगी-क्षमता = फार्म से प्राप्त कुल नकद आय - (इसमें उपभोग खर्च + फार्म की कार्यशील लागत, जिसमें प्रस्तावित ऋण सम्मिलित नहीं होता है + कर + अन्य ऋण जो चुकाने के लिए हैं)।

- (ब) अपरिसंसाधन ऋण या आश्रित परिसंसाधन ऋण—वे ऋण जिनके द्वारा क्रय किए गए उत्पादन-साधन परीक्षित रूप से उत्पादन-विधि में काम में नहीं जाते हैं बल्कि क्रय किए गए उत्पादन-साधनों की वैधायी ही फार्म पर उपभोग में आती है, आश्रित परिसंसाधन ऋण कहलाते हैं। जैसे—ट्रैक्टर, पम्पिंग सेट, उन्नत औजार, कुत्तों वगैरह आदि कार्यों के लिए प्राप्त ऋण। उन्मुख ऋण कार्यशील लागत में सम्मिलित नहीं होता है एवं इस ऋण के निवेश से आय अनेक वर्षों

तक प्राप्त होती है। इस प्रकार के ऋण की ऋण-प्रदायगी-क्षमता शत करने का मूल निम्न है—

ऋण प्रदायगी-क्षमता = फार्म से प्राप्त कुल नकद आय—(कार्यशील लागत, मौसमी ऋण को सम्मिलित करते हुए + धरेलू उपभोग खर्च + कर + अन्य ऋण जो भुगतान करने हैं।)

ऋण-प्रदायगी-क्षमता में वृद्धि के उपाय—कृषकों की ऋण-प्रदायगी-क्षमता में निम्न उपाय अपनाकर वृद्धि की जा सकती है—

1. बचत की राशि में वृद्धि करना एवं प्राप्त बचत का कृषि में निवेश करना—फार्म से प्राप्त आय में वृद्धि करके अथवा फार्म लागत में कमी करके कृषि बचत की राशि में वृद्धि कर सकते हैं। फार्म आय में वृद्धि फार्म पर फसलों का सही चुनाव, तकनीकी ज्ञान के प्रसार, प्रबन्ध क्षमता में वृद्धि तथा विपणन के लिए उचित सस्था एवं समय का चुनाव करके कर सकते हैं। फार्म पर होने वाली लागत को उत्पादन-साधनों एवं विधियों में प्रतिस्थापन के सिद्धान्त का उपयोग करके कम किया जा सकता है। उपर्युक्त उपायों के अपनाने से बचत की राशि में वृद्धि होती है। प्राप्त बचत की राशि को कृषि में निवेश करने से आय में वृद्धि होती है जिससे ऋण-प्रदायगी-क्षमता में वृद्धि होगी।
2. फार्म पर विभिन्न उत्पादन-साधनों की प्रयुक्त मात्रा में सन्तुलन रखना—फार्म से प्राप्त होने वाली आय, फार्म पर उपलब्ध विभिन्न उत्पादन-साधनों में से न्यूनतम मात्रा में उपलब्ध उत्पादन-साधन की मात्रा पर निर्भर होती है। फार्म पर अनेक उत्पादन-साधन बहुतायत में उपलब्ध होते हुए भी, एक उत्पादन-साधन के कम मात्रा में उपलब्ध होने पर फार्म योजना न्यूनतम उपलब्ध उत्पादन-साधन के अनुसार बनाई जाती है जिससे बहुतायत में उपलब्ध उत्पादन-साधन बेकार रहते हैं। अतः फार्म से अधिकतम आय की प्राप्ति के लिए न्यूनतम मात्रा में फार्म पर उपलब्ध उत्पादन-साधन की मात्रा में आवश्यक वृद्धि करके उत्पादन साधनों के असन्तुलन को समाप्त करना चाहिये।
3. ऋण चुकाने की अवधि में वृद्धि करना—ऋण भुगतान अवधि में वृद्धि करने से ऋण की किश्तों की संख्या में वृद्धि हो जाती है और प्रति किश्त ऋण चुकाने की राशि कम हो जाती है, जिससे कृषक आसानी से प्राप्त ऋण का भुगतान कर सकता है।

- 4 उत्पादन साधनों का अनुकूलतम उपयोग—फार्म पर उपलब्ध सीमित उत्पादन साधनों की उत्पादकता में उनके अनुकूलतम उपयोग से वृद्धि की जा सकती है। सीमित उत्पादन-साधनों से अधिक आय की प्राप्ति के लिए उनका उपयोग सम-सीमान्त प्रतिफल के सिद्धान्त के अनुसार करना चाहिए।
- 5 फार्म पर तकनीकी ज्ञान का उपयोग—तकनीकी ज्ञान के उपयोग से वर्तमान में भूमि की प्रति इकाई उत्पादकता में पिछले दशक में विशेष वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके उपयोग से उत्पादकता में वृद्धि होने की सम्भावना है। अतः अधिक आय के लिए फार्म पर सकर व बौने किस्म के बीज उर्वरक, उन्नत विधियों द्वारा खेती तथा कीटनाशो दवाइयों का अधिक उपयोग करना चाहिये।
- 6 विपणन-प्रणाली में सुधार करना—फार्म से प्राप्त आय की राशि उत्पादकता में वृद्धि के प्रतिरिक्त, उत्पादों की कीमतों पर भी निर्भर होती है। अधिक आय की प्राप्ति के लिए उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ कृषकों को उत्पाद के विपणन पर भी ध्यान देना चाहिए। उत्पादों के विपणन के लिए सही संस्था, समय एवं स्थान का चुनाव करने से वस्तुओं के प्रति इकाई पर विपणन लागत में कमी होती है तथा उत्पादों की कीमत अधिक प्राप्त होती है। नियन्त्रित मण्डियों में अनियन्त्रित मण्डियों की अपेक्षा प्रति इकाई विपणन लागत कम होती है तथा उनमें प्रतिस्पर्धा के कारण कीमत भी अधिक प्राप्त होती है।
- 7 कृषकों की प्रबन्ध-योग्यता में वृद्धि करना—कृषकों की प्रबन्ध योग्यता में विभिन्नता के कारण भी फार्म पर लागत एवं आय में विभिन्नता होती है। तकनीकी ज्ञान के आविष्कार से प्रबन्ध-योग्यता की महत्ता पहले से अधिक बढ़ गई है। कृषकों की प्रबन्ध-योग्यता में सुधार के लिए उन्हें प्रशिक्षण की सुविधा अधिकाधिक उपलब्ध कराना चाहिए। प्रशिक्षण से कृषकों की निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है।
8. उचित ऋण-अदायगी योजना बनाकर—कृषकों के पास ऋण चुकाने के लिये आवश्यक आय होते हुए भी ऋण अदायगी योजना के सही नहीं होने पर कृषक ऋण का समय पर भुगतान नहीं कर पाते हैं। ऋण-अदायगी योजना प्राप्त आय की राशि व समय के अनुसार तैयार की जानी चाहिये। यदि कृषकों को आय वर्ष में एक बार प्राप्त होती है, तो ऋण चुकाने की योजना वार्षिक बनानी चाहिये। उपर्युक्त अवस्था में ऋण चुकाने की योजना अर्द्ध-वार्षिकी या मासिक किश्तों

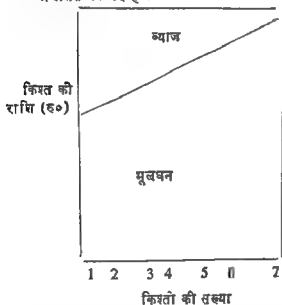
में होने पर कृपक के लिए ऋण की किस्त का समय पर भुगतान कर पाना सम्भव नहीं होता है।

9. कृपकों द्वारा अधिक राशि में स्वतः परिसमापन ऋण ही लेना चाहिए, क्योंकि इस ऋण का अन्य ऋणों की अपेक्षा भुगतान सरल होता है।

ऋण-अदायगी-योजना के रूप—ऋण-अदायगी-योजना चार प्रकार की होती है—

1. **एक मुस्त अदायगी योजना (Lump sum Repayment plan or straight end repayment plan)**—ऋण भुगतान की इस योजना में कृपकों द्वारा प्राप्त ऋण राशि निश्चित समय की समाप्ति पर एक साथ एक मुस्त में भुगतान करना होता है। ऋण भुगतान की यह योजना अपनाते से कृपक व्यवसाय से प्राप्त धन को पुनः कृषि व्यवसाय में निवेश कर सकता है बमर्ते कि पूँजी निवेश से सीमान्त उत्पादकता अधिक प्राप्त होती है। इस योजना के अपनाते में यह मान्यता होती है कि कृषि क्षेत्र में जोखिम के होने से एक वर्ष में हुई हानि, दूसरे वर्ष में प्राप्त लाभ से मन्तुलित हो जावेगी और समय पर कृपकों की ऋण राशि के भुगतान की क्षमता होगी। कभी-कभी यह भी होता है कि लम्बे समय के बाद कृपकों के पास ऋण राशि के भुगतान के लिये पर्याप्त धन नहीं होता है जिससे वे ऋण का समय पर भुगतान नहीं कर पाते हैं। घटः ऋण भुगतान की यह योजना कृपकों द्वारा उस स्थिति में अपनाई जानी चाहिये, जब उन्हें फार्म से ऋण राशि के समतुल्य प्रायः एक साथ प्राप्त होने की सम्भावना होवे। इस विधि में साधारणतया प्राप्त ऋण राशि पर ब्याज की राशि का भुगतान भी नियत समय की समाप्ति पर एक साथ ऋण राशि के साथ ही किया जाता है। कभी-कभी ऋण-राशि पर होने वाले ब्याज की राशि का भुगतान प्रतिवर्ष भी किया जाता है।
2. **समान किस्त परिशोधन अदायगी योजना (Amortised even Repayment plan)**—परिशोधन ऋण (amortised loan) वह है जो मूलधन एवं ब्याज सहित निर्धारित समय में किस्तों में भुगतान किया जाता है। परिशोधन योजना से उत्पन्न निर्धारित समय में प्राप्त मूलधन एवं उस पर होने वाले ब्याज की राशि का भुगतान किस्तों में समान राशि या ह्रासमान दर से किया जाने से है। समान किस्त परिशोधन अदायगी योजना में कुल ऋण एवं भुगतान धर्माधिक के ब्याज की राशि को सम्मिलित करके उसे समान रूप से

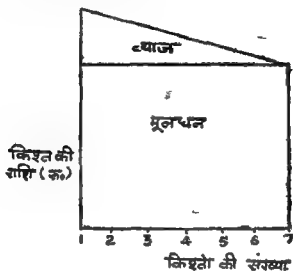
किश्तों में विभक्त कर सकते हैं। कृषको को प्रति किश्त समान राशि में धन का भुगतान करना होता है। इस योजना के प्रथम वर्षों में मूलधन की राशि कम व ब्याज की राशि अधिक होती है। धीरे-धीरे मूलधन की राशि बढ़ती जाती है और ब्याज की राशि कम होती जाती है। यह योजना कृषको द्वारा उस स्थिति में अपनायी जानी चाहिये जब उन्हें फार्म से प्रतिवर्ष समान आय होने की सम्भावना होवे। चित्र 11 I में समान किश्त परिशोधन अदायगी योजना के अन्तर्गत विभिन्न वर्षों में दिये जाने वाले मूलधन एवं ब्याज की राशि प्रदर्शित की गई है।



चित्र 11 I समान किश्त परिशोधन अदायगी योजना

3. **ह्रासमान-किश्त परिशोधन अदायगी योजना (Amortised Decreasing Repayment Plan)**—इस योजना में ऋण चुकाने की राशि प्रति किश्त निरन्तर कम होती जाती है। इस योजना में मूलधन की राशि भुगतान अवधि में प्रत्येक किश्त में समान रहती है। प्राप्त मूलधन राशि में किश्तों की संख्या का भाग देकर प्रति किश्त मूलधन की राशि ज्ञात कर ली जाती है। ब्याज की राशि प्रथम वर्ष में अधिक व उसके बाद वर्षों में मूलधन के कम होने से निरन्तर कम होती जाती है। अतः भुगतान राशि की किश्त प्रथम वर्ष में अधिक व उसके बाद निरन्तर कम होती जाती है। यह योजना कृषको द्वारा उस स्थिति में अपनायी जानी चाहिए जब उन्हें फार्म से प्रतिवर्ष समान आय प्राप्त

नहीं होकर प्रथम वर्ष में अधिक व उसके बाद निरन्तर कम प्राप्त होने की भांशका होवे। चित्र 11.2 में ह्रासमान-किश्त परिशोधन अदायगी योजना के अन्तर्गत विभिन्न वर्षों में देय मूलधन एवं ब्याज की राशि प्रदर्शित की गई है।



चित्र 11.2 ह्रासमान-किश्त परिशोधन अदायगी योजना

- 4 परिवर्ती या धामास परिवर्ती परिशोधन योजना—इस योजना में ऋण भुगतान की कोई निश्चित योजना नहीं होती है। कृषको को ऋण-भुगतान के लिए जमा कराने की राशि में पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। अधिक आय प्राप्त होने वाले वर्ष में, कृषक ऋण की अधिक राशि का भुगतान कर सकते हैं तथा कम आय प्राप्त होने वाले वर्ष में उन्हें ऋण की राशि का कम भुगतान करने अथवा बिल्कुल नहीं करने की छूट होती है। गावों में कृषको द्वारा साहूकारों से प्राप्त ऋण के लिए यही भुगतान-योजना अपनायी जाती है।

ऋण-परिशोधन अदायगी योजना में ऋण चुकाने को किश्त की राशि ज्ञात करना

ऋण-परिशोधन अदायगी योजना की दोनों विधियों में ऋण अदायगी किश्त की राशि निम्न प्रकार से ज्ञात की जाती है—

उदाहरण—1 एक कृषक फार्म पर ट्रैक्टर ख़रीदने के लिए 20,000 रु का ऋण वाणिज्यिक बैंक से प्रतिशत ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए प्राप्त करता है। कृषक ऋण का भुगतान वार्षिक किश्तों में करना चाहता है। परिशोधन की

उपयुक्त दोनों योजनाओं में कृषक द्वारा प्रतिवर्ष भुगतान की जाने वाली किश्त की राशि (मूलधन + ब्याज) ज्ञात कीजिए।

ह्रासमान-किश्त-परिशोधन अदायगी योजना—इस योजना में विभिन्न वर्षों में भुगतान किये जाने वाले ऋण की वार्षिक किश्त की राशि सारणी 11.1 में प्रदर्शित की गई है।

सारणी 11.1

ह्रासमान-किश्त परिशोधन-अदायगी योजना वार्षिक किश्तों की देय राशि
(रुपये में)

वर्ष	मूलधन राशि	ब्याज राशि	किश्त की राशि	वर्ष के अन्त में देय ऋण- राशि
1	2,000	1,600	3,600	18,000
2	2,000	1,440	3,440	16,000
3	2,000	1,280	3,280	14,000
4	2,000	1,120	3,120	12,000
5	2,000	960	2,960	10,000
6	2,000	800	2,800	8,000
7	2,000	640	2,640	6,000
8	2,000	480	2,480	4,000
9	2,000	320	2,320	2,000
10	2,000	160	2,160	—
कुल राशि	20,000	8,800	28,800	—

समान-किश्त परिशोधन अदायगी योजना—इस विधि में ऋण की वार्षिक किश्त निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात की जाती है²—

$$P = B \frac{1}{a} \frac{1}{1 - \frac{1}{n}}$$

जबकि P = वार्षिक किश्त की राशि

B = प्राप्त ऋण राशि

n = ऋण स्वीकृति की अवधि (वर्षों में)

i = वार्षिक ब्याज दर

2. A. G. Nelson & W. G. Murray, Agricultural Finance, Iowa State University Press, Ames, Iowa, 5th Edition, 1968, pp. 168-69.

$$\left. \begin{array}{c} a \\ n \end{array} \right\} = \text{वार्षिकी}$$

OR

$$P = B \frac{1}{1 - (1+i)^{-n}}$$

इस सूत्र को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है

$$P = B \frac{1}{1 - \frac{1}{(1+i)^n}}$$

प्रस्तुत उदाहरण में ऋण पर ब्याज की दर (i) 8 प्रतिशत एवं ऋण अवधि (n) 10 वर्ष होने पर

$$P = B \frac{0.08}{1 - \frac{1}{(1+0.08)^{10}}}$$

$$= B \frac{0.08}{1 - \frac{1}{(1.08)^{10}}}$$

$$= B \frac{0.08}{1 - \frac{1}{2.1589247}}$$

$$= B \frac{0.08}{1 - 0.4631935}$$

$$= B \frac{0.08}{0.5368065}$$

$$= B \times 0.14902949$$

ऋण की राशि 20,000 रुपये होने पर ऋण भुगतान की वार्षिक प्रति किस्त राशि $20,000 \times 0.14902949 = 2980.59$ रु होती है।

वार्षिकी $\frac{1}{a \overline{a}|n}$ की मात्रा विभिन्न ब्याज दर एवं ऋण अवधि के लिए

सारणी से भी ज्ञात की जाती है। ऋण अवधि 10 वर्ष एवं ऋण पर 8 प्रतिशत ब्याज की दर होने पर $\frac{1}{a \overline{a}|n}$ की मात्रा 0.14902949 होती है। अतः उपर्युक्त

उदाहरण में ऋण भुगतान की वार्षिक प्रति किस्त राशि

$$P = B \frac{1}{a \overline{a}|n} = 20,000 \times 0.14902949 = 2980.59 \text{ रु. होती है।}$$

अतः इस अदायगी योजना में विभिन्न वर्षों में कृषक द्वारा देय मूलधन ब्याज एवं वार्षिक किस्त की राशि सारणी 11.2 में प्रदर्शित की गई है।

सारणी 11.2

समान किस्त परिशोधन अदायगी योजना के विभिन्न वर्षों में
मूलधन ब्याज एवं किस्त की राशि

(रुपयों में)

वर्ष	मूलधन राशि	ब्याज राशि	प्रति किस्त भुगतान राशि	वर्ष के अन्त में देय ऋण राशि
1	1380.59	1600.00	2980.59	18619.41
2	1491.04	1489.55	2980.59	17128.37
3	1610.32	1370.27	2980.59	15518.05
4	1739.15	1241.44	2980.59	13778.90
5	1878.28	1102.31	2980.59	11900.62
6	2028.54	952.05	2980.59	9872.08
7	2190.82	789.77	2980.59	7681.26
8	2366.09	614.50	2980.50	5315.17
9	2555.38	425.21	2980.50	2959.79
10	2759.79	220.80	2980.50	—
कुल	20000.00	9805.90	29,805.90	—

यदि ऋण भुगतान वार्षिक किश्तों के स्थान पर अर्द्ध-वार्षिक, त्रै-मासिक या मासिक किश्तों में किया जाता है तो प्रति किश्त की राशि ज्ञात करने का सूत्र निम्न होता है :

$$\frac{P}{m} = B \frac{1}{a \frac{1}{nm} \left| \frac{1}{m} \right|}$$

जबकि m = वर्ष में भुगतान किश्तों की संख्या

उदाहरण—2. एक कृषक फार्म पर सिंचाई के लिए कुएँ पर पम्प लगाने के लिए बैंक से 4000 रु० का ऋण 7 प्रतिशत व्याज दर पर प्राप्त करता है। कृषक ऋण का भुगतान 4 वर्ष की अवधि में अर्द्ध-वार्षिक किश्तों में करना चाहता है। ह्रासमान एवं समान किश्त परिशोधन अदायगी योजना में प्रति किश्त ऋण की राशि ज्ञात कीजिए।

ह्रासमान किश्त परिशोधन अदायगी योजना—इस योजना के विभिन्न वर्षों में ऋण भुगतान की किश्त राशि सारणी 113 में प्रदर्शित की गई है।

सारणी 113

ह्रासमान-किश्त परिशोधन-अदायगी योजना में विभिन्न वर्षों में
देय किश्तों की राशि

(रुपयों में)

अर्द्ध वार्षिक किश्त संख्या	मूलधन- राशि	व्याज- राशि	प्रति किश्त भुगतान राशि	किश्त के भुगतान के अन्त में देय ऋण राशि
1	500	280	780	3500
2	500	245	745	3000
3	500	210	710	2500
4	500	175	675	2000
5	500	140	640	1500
6	500	105	605	1000
7	500	70	570	500
8	500	35	535	—
कुल	4000	1260	5260	—

समान-किश्त परिशोधन अदायगी योजना—इसमें ऋण की प्रति किश्त राशि

$$\frac{P}{m} = B \frac{1}{a \frac{1}{nm} \left| \frac{1}{m} \right.} = \frac{P}{2} = 4000 \frac{1}{a \frac{1}{4 \times 2} \left| \frac{0.07}{2} \right.}$$

$$= 4,000 \times 0.14547665 = 581.91 \text{ रु. होती है।}$$

समान किश्त परिशोधन अदायगी योजना के विभिन्न वर्षों में देय भ्रष्ट-वार्षिक किश्त की राशि तथा उसमें मूलधन एवं ब्याज की राशि सारणी 11.4 में प्रदर्शित की गई है।

सारणी 11.4

समान किश्त परिशोधन अदायगी योजना में विभिन्न भ्रष्ट-वार्षिक किश्तों की देय राशि, मूलधन एवं ब्याज की राशि

(रुपये में)

भ्रष्ट-वार्षिक किश्त संख्या	मूलधन राशि	ब्याज राशि	प्रति किश्त मुगतान राशि	किश्त के मुगतान के अन्त में देय ऋण राशि
1	441.91	140.00	581.91	3558.09
2	457.38	124.53	581.91	3100.71
3	473.39	108.52	581.91	2627.32
4	489.95	91.96	581.91	2137.37
5	507.10	74.81	581.91	1630.27
6	524.85	57.06	581.91	1105.42
7	543.22	38.69	581.91	562.20
8	562.20	19.71	581.91	—
कुल	4000.00	655.28	4655.28	—

3 कृषको की जोखिम वहन योग्यता

ऋण-स्वीकृति से पूर्व, ऋण के उपयोग से प्राप्त आय एवं ऋण मुगतान क्षमता के प्रतिरिक्त प्रतिकूल मौसम में कृषको की ऋण मुगतान कर पाने की सामर्थ्य का ज्ञान होना भी आवश्यक है। प्रतिकूल मौसम वाले वर्ष में ऋण का मुगतान

कृषको की जोखिम बहन करने की योग्यता पर निर्भर करता है। कृषको की जोखिम बहन करने की योग्यता का ज्ञान निम्नलिखित कारखो से आवश्यक होता है—

(1) कृषि-व्यवसाय की सफलता प्रकृति पर निर्भर होती है। मौसम की प्रतिकूलता—ओसे, अतिवर्षा, सूखा, बीमारियो आदि के होने पर उत्पादन कम प्राप्त होता है। अतः प्रतिकूल मौसम के काल मे ऋण-मुगतान की सामर्थ्य की जाँच के लिए कृषको की जोखिम बहन करने की योग्यता का ज्ञान होना आवश्यक होता है।

(2) कृषको की आय का आकलन पिछले वर्षों की औसत उत्पादकता एवं कीमतों के आधार पर किया जाता है। आकलित कीमतें व उत्पादकता अन्तिम बिन्दु तक सही नहीं होती है। कीमतें व उत्पादकता के आकालत स्तर से नीचे गिर जाने की व्यवस्था मे प्राप्त ऋण के मुगतान की सामर्थ्य के लिए कृषको मे जोखिम-बहन योग्यता का होना आवश्यक है।

जोखिम-बहन-योग्यता ज्ञात करने की विधि—कृषको की जोखिम-बहन-योग्यता ज्ञात करने के लिए कृषको को प्राप्त होने वाली आय एवं मुगतान-क्षमता की राशि को क्षेत्र के विचरण गुणांक (Variability Coefficient) की राशि तक कम करते हैं, जिससे कृषको की वास्तविक आय व मुगतान-क्षमता ज्ञात हो जाती है। यदि उत्पादन व कीमतों मे गिरावट नहीं आती है तो कृषको की यह राशि अतिरिक्त बचत होती है। प्रत्येक कृषक के लिए पृथक् रूप से विचरण गुणांक ज्ञात करने का कार्य कठिन होता है। अत विभिन्न क्षेत्रों के लिए पृथक् रूप से विचरण गुणांक ज्ञात किया जाता है। कुल विचरण प्रतिफल ज्ञात करने का सूत्र निम्न है :

$$\text{कुल विचरण गुणांक} = \frac{\text{कुल विचरण}}{\text{कुल प्रतिफल}} \times 100$$

कृषकों की जोखिम-बहन-योग्यता मे परिवर्तन लाते वाले कारक—निम्न कारक कृषको को जोखिम-बहन योग्यता मे परिवर्तन लाते हैं :

1 कृषको के घरेलू उपभोग पर खर्च करने की प्रवृत्ति एवं बचत करने की शक्ति—घरेलू उपभोग पर कम खर्च करने वाले कृषको की बचत अधिक होती है, जिससे उनकी जोखिम-बहन-योग्यता अधिक होती है।

2 कृषकों की आपातकालीन समय मे ऋण प्राप्त करने की क्षमता—कुछ कृषक अपनी बाजार साख के कारण प्रतिकूल मौसम वाले वर्ष मे भी आवश्यक ऋण राशि प्राप्त कर सकते हैं और विपत्ति का सामना करते हैं, जबकि अन्य कृषक ऐसे समय मे घबरा उठते हैं। अत उनमे जोखिम-बहन-योग्यता कम होती है।

3 कृषको की ईश्वरों या शुद्ध परिसम्पत्ति की राशि—जिन कृषको के

पास सम्पत्ति अधिक होती है उनमें जोखिम-बढ़न-योग्यता अन्य कृषकों की अपेक्षा अधिक होती है।

4. कृषकों की वैयक्तिक प्रवृत्ति पर भी जोखिम-बढ़न-क्षमता निर्भर करती है।

कृषकों की जोखिम-बढ़न-योग्यता में वृद्धि करने के उपाय—निम्न उपाय अपनाकर कृषकों की जोखिम-बढ़न-योग्यता में वृद्धि की जा सकती है—

- 1 फार्म पर कम जोखिम वाले उद्यमों का चुनाव करना एवं उनके अन्तर्गत अधिक क्षेत्रफल लेना।
- 2 फार्म पर विविष्ट कृषि के स्वाम पर विविधीकृत कृषि अपनाना।
3. फार्म पर कृषि की उन्नत विधियों का अपनाना।
- 4 फार्म पर फसल बीमा प्रवृत्ति अपनाना।
5. कीमतों के अत्यधिक उतार-चढ़ाव से रक्षा करने के लिए उत्पादों के क्रय-विक्रय का अग्रिम सौदा करना।
- 6 उपभोग एवं उत्पादन-लागत को कम करने के प्रयास करना।
- 7 फार्म से प्राप्त बचत राशि को कृषि व्यवसाय में पुन निवेश करना।
8. आर्थिक संकट काल में कृषकों द्वारा बाजार साख को बनाये रखकर भी जोखिम-बढ़न-योग्यता में वृद्धि की जा सकती है।

ऋण-प्रबन्ध के 'सी' सिद्धान्त

ऋण-प्रबन्ध के दूसरे सिद्धान्त ऋण के 'सी' (C's) कहलाते हैं। ऋण-प्रबन्ध के 'प्रार' सिद्धान्तों का उत्तर ऋणदात्री संस्था एवं कृषकों को सकारात्मक प्राप्त होने के पश्चात् ऋण के दूसरे सिद्धान्त अर्थात् ऋण के 'सी' सिद्धान्तों की जाँच करनी चाहिए। ऋण के 'सी' सिद्धान्त ऋण अदायगी क्षमता के द्योतक होते हैं। ऋण-प्रबन्ध के प्रमुख 'सी' सिद्धान्त निम्न हैं—

1 गुण (Character)—गुण से तात्पर्य यहाँ व्यक्ति के साधारण चाल-चलन से नहीं है, बल्कि ऋणी कृषक में ऋण चुकाने में ईमानदारी, सच्चाई, औचित्य, जिम्मेदारी, विश्वसनीयता तथा उसमें उद्यमशीलता या परिश्रमी होना आदि के गुण सम्मिलित होते हैं। ऋणी-कृषक में उपर्युक्त गुण विद्यमान होने से तात्पर्य है कि उस व्यक्ति में ऋण-भुगतान की क्षमता है। जोखिम-बढ़न शक्ति एवं ऋणी के उपर्युक्त गुणों में गहन सम्बन्ध होता है। उपर्युक्त गुणों वाला कृषक जोखिम बढ़न शक्ति के कम होते हुए भी ऋण अधिक राशि में प्राप्त कर सकता है एवं ऋण का समय पर भुगतान कर सकता है।

गैर-सम्पागत ऋण अधिकरण गाँवों में कृषकों को ऋण मुख्यतया उनमें पाये जाने वाले उपर्युक्त गुणों के आधार पर स्वीकृत करते हैं। साहूकारों, व्यापारियों एवं आदतियों को कृषकों में विद्यमान उपर्युक्त गुणों की जानकारी होती है, जिसके

कारण उन्हें स्वीकृत गुणों की बमूली में परेशानी नहीं होती है। बैंक एवं सस्थागत अभिकरणों को कृषकों में विद्यमान उपर्युक्त गुणों की जानकारी नहीं होने से ऋण-बमूली में परेशानी होती है एवं ऋण की अधिक राशि कृषकों पर बकाया रह जाती है।

2 क्षमता (Capacity)—क्षमता गुण से तात्पर्य कृषकों में नियत समय पर ऋण चुकाने की क्षमता के होने से है। क्षमता गुण मुख्यतया ऋण-अदायगी क्षमता का प्रतीक होता है। अतः कृषकों को ऋण स्वीकृत करते समय उनकी क्षमता की जाँच भी करनी चाहिए।

3 पूँजी (Capital)—पूँजी गुण से तात्पर्य ऋणी-कृषक की ईन्विटी या शुद्ध सम्पत्ति की राशि से है। पर्याप्त सम्पत्ति या ईन्विटी वाला कृषक मौसम की प्रतिकूलता की अवस्था में सम्पत्ति को विक्रय अथवा बन्धक रख कर प्राप्त ऋण का भुगतान कर सकता है। अतः ऋण स्वीकृत करते समय ऋणी कृषक की ईन्विटी की जाँच भी करनी चाहिए।

4 ऋण की शर्तें (Conditions)—ऋण की शर्तें—जैसे—ब्याज-दर, भुगतान की शर्तों आदि का ज्ञान भी ऋणी कृषक को ऋण स्वीकृति में पूर्व ही दे देना चाहिए। कृषक को ऋण-शर्तें स्वीकृत होने पर ही ऋण प्रदान करना चाहिए।



कृषि-विपणन

प्राचीन काल में कृषक जीवन-निर्वाह के लिए कृषि करते थे। पारिवारिक आवश्यकता की सभी वस्तुएँ—खाद्यान्न, दालें, कपास, तिलहन, सब्जी आदि अपने फार्म पर उत्पादित करते थे। पारिवारिक आवश्यकता की वस्तुओं के कम उत्पन्न होने या उत्पन्न न होने की स्थिति में, वे दूसरे कृषको से वस्तु-विनिमय करके कमी की पूर्ति करते थे। उस काल में कृषको के सामने वस्तुओं के विपणन की समस्याएँ नहीं थी। कृषि-विपणन व्यवसाय वर्तमान की भाँति विकसित नहीं था, तकनीकी विकास के कारण कृषि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने तथा शहरीकरण के कारण खाद्यान्नों के क्रेताओं की संख्या में वृद्धि होने से खाद्यान्नों के विपणन में अनेक समस्याएँ उत्पन्न होनी शुरू हुईं, जिनमें से कृषको के सामने अधिशेष पैदावार के बिक्रय एवं उपभोक्ताओं के सामने आवश्यक खाद्यान्न की मात्रा के सही कीमत पर क्रय की समस्याएँ प्रमुख थी। इन समस्याओं ने कृषि-विपणन को जन्म दिया। कृषि-व्यवसाय ने जीविका-निर्वाह के स्थान पर व्यापारिक रूप ग्रहण किया। कृषि उत्पादन में विशिष्टीकरण एवं व्यवसाय के व्यापारीकरण के कारण कृषक फार्म पर उत्पादित एक या दो उत्पादों को पूर्णतया बाजार में बिक्रय के लिए ही उत्पादित करने लगे, जिससे कृषि-विपणन के क्षेत्र में समस्याएँ अधिक जटिल होती गईं। अतः कृषि विपणन के अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत हुई।

कृषि-विपणन की परिभाषा—विपणन शब्द की परिभाषा पर्याप्त व्यापक एवं जटिल है। कृषि-वस्तुओं का उत्पादन असंख्य कृषको के फार्म पर विभिन्न आकार की जोतों पर होता है तथा उत्पादित कृषि-वस्तुओं के गुणों में विभिन्नता पाई जाती है। समाज के विभिन्न व्यक्ति विपणन शब्द के विभिन्न अर्थ लगाते हैं। उदाहरणतया, गृह-स्वामिनी विपणन शब्द से अग्निप्रायः घर के लिए आवश्यक वस्तुओं के त्रय करने से तथा कृषक फार्म से प्राप्त पैदावार के बिक्रय से लगाता है। इसी प्रकार व्यापारी विपणन शब्द के अर्थ वस्तुओं के त्रय-विनय से लेते हैं।

सामान्य तौर पर विपणन शब्द में तात्पर्य उन सभी विपणन कार्यों एवं सेवाओं के करने से है जिनके द्वारा वस्तुएँ उत्पादक से अन्तिम उपभोक्ता तक पहुँचती हैं। इसके अन्तर्गत विपणन की सभी सहयोगी प्रक्रियाएँ—एकत्रीकरण, पैकेजिंग, परिवहन, सग्रहण, श्रेणी-चयन एवं मानकीकरण, वित्त, जोखिम प्रबन्ध, विज्ञापन, आदि सम्मिलित होती हैं। उत्पादन को उपभोग से जोड़ने वाली श्रृंखला की समस्त कड़ियाँ विपणन में समाविष्ट होती हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने कृषि-विपणन शब्द की परिभाषा विभिन्न शब्दों में की है जिनमें से प्रमुख निम्नांकित हैं—

थॉमसन¹—कृषि-विपणन के अध्ययन में वे सभी कार्य एवं सस्थाएँ सम्मिलित होती हैं जिनके द्वारा कृषकों के फार्म पर उत्पादित खाद्यान्न, कच्चा माल एवं उनसे निर्मित माल का फार्म से अन्तिम उपभोक्ता तक संचालन होता है। विपणन क्रियाओं का कृषकों, मध्यस्थों एवं उपभोक्ताओं पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन भी कृषि विपणन के अन्तर्गत आता है।

कोल्स एवं उल्ल²—खाद्य विपणन से तात्पर्य उन सभी व्यापारिक क्रियाओं को सम्पन्न करने से है, जिनके द्वारा खाद्य वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह प्रारम्भिक कृषि उत्पादन स्थान (कृषक के फार्म) से उपभोक्ताओं तक होता है।

मूर, जोहल एवं खुसरो³—खाद्यान्न विपणन के अन्तर्गत वे सभी व्यापारिक क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं जो खाद्यान्न को उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए समय (सग्रहण), स्थान (परिवहन), रूप (परिवर्तन) एवं स्वामित्व परि-

- 1 The study of agricultural marketing comprises of all the operations and the agencies conducting them, involved in the movement of farm produced foods and raw materials and their derivatives such as textiles from the farms to the final consumers and the effects of such operations on farmers, middlemen and consumers

—F L Thomsen, Agricultural Marketing, Mc-Graw Hill Book Company, INC, Newyork, 1951, p 1

- 2 Food marketing [as the performance of all business activities involved in the flow of food products and services from the point of initial agricultural production until they are in the hands of consumers

—R L Kohls and J N. Uhl, Marketing of Agricultural Products, Macmillan Publishing Co, INC, Newyork, 1980, P 8

- 3 Foodgrain marketing includes all the business activities involved in moving foodgrains from producers to consumers through time (Storage), space (transport), from (processing) and transferring ownership at the various stages in the marketing channels. In a free enterprise system, the process is guided by prices

—J. M. Moore, S S Johl and A. M. Khuro, Indian Foodgrain Marketing, Prentice Hall India Private Limited, New Delhi, 1973, p 1.

वर्तन विपणन माध्यमों के द्वारा विपणन क्रिया में विभिन्न समय पर की जाती है। स्वतन्त्र व्यावसायिक पद्धति में ये क्रियाएँ कीमतों द्वारा निर्देशित होती हैं।

कनवर्ज हुगे, एव मिचेल⁴—विपणन में वे सभी क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं जिनके द्वारा वस्तु में स्थान, समय एवं स्वामित्व उपयोगिता उत्पन्न होती है। मैकलीन ने विपणन की परिभाषा में इन तीनों उपयोगिताओं के अतिरिक्त रूप उपयोगिताओं को भी सम्मिलित किया है ?

कृषि-विपणन की आधुनिक परिभाषा में कृषि उपकरणों एवं साधनों की उपलब्धि को भी सम्मिलित किया जाता है। अबोट और स्पिक्स ने कृषि विपणन को परिभाषित करने में उपयुक्त तथ्यों की पुष्टि की है। अबोट⁵ ने कृषि-विपणन की परिभाषा में कहा है कि “कृषि-विपणन में वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जिनके द्वारा खाद्य वस्तुएँ एवं कच्चा-माल फार्म से उपभोक्ता तक पहुँचता है। स्पिक्स⁶ के अनुसार कृषि-विपणन में उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त परिष्करण (प्रोसेसिंग), उद्योगों को कच्चे माल की पूर्ति, परिष्करण से उत्पादित वस्तुओं के विपणन, उनकी माँग का आकलन एवं उनकी नीति से सम्बन्धित पहलू भी सम्मिलित होते हैं।

कृषि-विपणन के उद्देश्य—समाज के विभिन्न वर्गों—उत्पादक, उपभोक्ता, मध्यस्थ एवं सरकार के लिए विपणन-अध्ययन के उद्देश्य विभिन्न होते हैं। साथ ही प्रत्येक वर्ग के विपणन-उद्देश्य दूसरे वर्ग के विपणन उद्देश्यों से मेल नहीं खाते हैं। उदाहरणतया उत्पादक-कृषकों का विपणन से मुख्य उद्देश्य फार्म पर उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से अधिक कीमत प्राप्त करके अधिकतम आय प्राप्त करना होता है, जबकि उपभोक्ताओं का विपणन से प्रमुख उद्देश्य वस्तुओं की आवश्यक मात्रा कम से कम कीमत पर प्राप्त करना होता है। उपयुक्त दोनों वर्गों के हित एक-दूसरे के विपरीत होते हैं। समाज का तीसरा वर्ग विपणन-मध्यस्थ-विपणन क्रिया से अधिकाधिक लाभ कमाना चाहता है। सरकार की दृष्टि में विपणन के उद्देश्य उत्पादकों को उत्पाद के उचित विक्रय प्रबन्ध द्वारा लाभप्रद कीमत प्राप्त कराना, उपभोक्ताओं को वस्तुएँ आवश्यक मात्रा में उचित कीमत पर उपलब्ध कराना एवं विपणन-मध्यस्थों को सेवाओं की उचित कीमत प्राप्त कराना होता है ताकि समाज के सभी वर्ग साथ-साथ पनप सकें। उत्पादक कृषक, उपभोक्ता, विपणन-मध्यस्थ एवं सरकार के विपणन उद्देश्यों का विस्तृत विवेचन नीचे दिया गया है —

- 4 P D Converse, H W, Huegey and Mitchell, The Elements of Marketing, Prentice Hall, Englewood cliffs, New Jersey, 1946, P 1
- 5 J C Abbott, Marketing Problems and Improvement Programmes, FAO, Rome 1958, p 1
- 6 R. Spinks, "Myths about Agricultural Marketing," A/D/C Teaching Forum, No 15, March, 1972 p 1

उत्पादक-कृषकों के विपणन-उद्देश्य—उत्पादक कृषकों के लिए समुचित एवं सुव्यवस्थित विपणन-विधि यह है जो फार्म पर उत्पादित माल के विक्रय से यथासम्भव अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करा सके। कृषकों को फार्म से प्राप्त लाभ की राशि वस्तु की उत्पादित मात्रा एवं कीमत पर निर्भर होती है। फार्म से प्राप्त आय की राशि कृषकों की उत्पादन नीति एवं उत्पादन-क्षमता को प्रभावित करती है। एक अच्छी विपणन विधि के होने से कृषकों को उत्पाद के विक्रय से उचित कीमत प्राप्त होती है जिससे कृषक उस वस्तु का उत्पादन बढ़ाने को प्रेरित होते हैं। अतः, अच्छी विपणन-विधि देश में वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करती है, जो देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्म-निर्भर बनाने के लिए आवश्यक मानी जाती है।

उपभोक्ता के विपणन-उद्देश्य—देश के उपभोक्ता उस विपणन-व्यवस्था की आकांक्षा करते हैं जो उन्हें आवश्यक वस्तुएँ जैसे—खाद्यान्न, तिलहन, दालें एवं अन्य वस्तुओं की उचित किस्म, आवश्यक मात्रा में न्यूनतम कीमत पर उपलब्ध करा सके। उपभोक्ता सीमित आय से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं। कुशल विपणन-व्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों का कम होना उचित माना जाता है।

विपणन-मध्यस्थों के विपणन उद्देश्य—विपणन-कार्य में लगे हुए मध्यस्थ उस विपणन-व्यवस्था की आशा रखते हैं जो उनको विपणन-प्रक्रिया में किए गए विपणन-कार्य एवं सेवाओं के लिए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करा सके। विपणन-प्रक्रिया में विपणन-मध्यस्थों का होना आवश्यक है, क्योंकि देश के असह्य उत्पादकों से वस्तुओं का उपभोक्ताओं तक संचालन विपणन-मध्यस्थों के द्वारा ही होता है। विपणन-क्रिया में विपणन-मध्यस्थ तब तक रहते हैं, जब तक कि उन्हें अपनी सेवाओं की उचित कीमत प्राप्त होती रहती है। विपणन प्रक्रिया में उचित लाभ की राशि प्राप्त नहीं होने पर विपणन मध्यस्थ अपने व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करने की कोशिश करते हैं, जिससे देश की विपणन-व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है, जो उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों के ही हित में नुकसानदेह होती है। कुछ विपणन-मध्यस्थ अल्पकाल में अधिकतम लाभ की अपेक्षा नहीं रखते हैं, बल्कि वे दीर्घकाल में निरन्तर निश्चित लाभ की राशि प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं।

सरकार के लिए विपणन उद्देश्य—सरकार के लिए अच्छी विपणन-व्यवस्था से तात्पर्य उस विपणन-व्यवस्था से है जो उपभोक्ताओं को कम से कम कीमत पर उचित किस्म की आवश्यक मात्रा में वस्तुएँ उपलब्ध कराएँ, उत्पादकों को उत्पाद की उचित कीमत दिलाते हुए उत्पादन-वृद्धि की प्रेरणा दें तथा विपणन मध्यस्थों को उनके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए उचित राशि प्राप्त कराएँ, जिससे समाज के तीनो वर्ग एक साथ पनप सकें।

विपणन उत्पादक क्रिया

विपणन-प्रक्रिया से वस्तुओं की लागत में वृद्धि होती है। अतः प्रश्न है कि क्या विपणन उत्पादक क्रिया है? उत्पादन से तात्पर्य किसी वस्तु को उसके रूप में परिवर्तन करके उसको उपभोग स्थिति में लाने, उपभोग के लिए सही समय एवं स्थान पर उपलब्ध कराने अथवा उन व्यक्तियों के स्वामित्व में परिवर्तन करने से है जो उसका उपयोग कर सकें। संक्षेप में, अर्थशास्त्रियों ने वस्तुओं में उपयोगिता उत्पन्न करने की विधि को उत्पादन कहा है। वस्तुओं की विपणन-विधि में निम्न चार प्रकार की उपयोगिताएँ उत्पन्न होती हैं —

1. **रूप-उपयोगिता**— विपणन-प्रक्रिया में विभिन्न सस्थाएँ वस्तुओं के रूप में परिष्करण क्रिया द्वारा परिवर्तन करके रूप उपयोगिता उत्पन्न करती हैं। वस्तुओं में रूप-उपयोगिता उत्पन्न होने से उपभोक्ता वस्तुओं का पहले की अपेक्षा शीघ्र उपयोग कर सकते हैं। परिष्करणकर्ता गेहूँ को भ्राटा, भ्राटे को बिस्कुट, दूध को मक्खन व घी, कपास को कपड़े, तिलहन को तेल, गन्ने को चीनी व गुड़ के रूप में परिवर्तित करके रूप-उपयोगिता उत्पन्न करते हैं। परिष्करण-क्रिया विपणन-प्रक्रिया का एक भाग है।
2. **स्थान-उपयोगिता**— वस्तुओं को अधिक पूर्ति वाले स्थानों से कमी वाले स्थानों पर परिवहन करके इनमें स्थान उपयोगिता उत्पन्न की जाती है, क्योंकि कमी वाले क्षेत्रों में वस्तुओं की उपयोगिता अधिक पूर्ति वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होती है। स्थान-उपयोगिता वस्तुओं में परिवहन साधनों द्वारा उत्पन्न की जाती है। परिवहन साधन वस्तुओं को देश के एक कोने से दूसरे कोने में पहुँचाकर स्थान उपयोगिता उत्पन्न करते हैं। परिवहन-क्रिया विपणन-प्रक्रिया का एक भाग है।
3. **समय-उपयोगिता**— अधिक उत्पादन वाले मौसम से उत्पादन नहीं होने वाले मौसम में वस्तुएँ उपलब्ध कराने से समय-उपयोगिता उत्पन्न होती है। उत्पादन की मौसम में वस्तुओं की पूर्ति अधिक होने से उपयोगिता कम होती है, जबकि दूसरे मौसम में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होने के कारण उपयोगिता बढ़ जाती है। समय-उपयोगिता वस्तुओं में संग्रहण एवं भण्डारण विधि द्वारा उत्पन्न की जाती है। संग्रहण एवं भण्डारण भी विपणन-प्रक्रिया का भाग है। उदाहरणार्थ आलू के मौसम में आलू का अधिक उत्पादन होने से उपयोगिता कम होती है जबकि दूसरे मौसम में आलू की कमी के कारण उपयोगिता अधिक होती है। अतः अधिक उत्पादन वाले मौसम में आलू को शीत

संग्रहागारों में सुरक्षित रखकर समय-उपयोगिता उत्पन्न की जाती है।

4. **स्वामित्व (स्वत्व) उपयोगिता**—वस्तु की उपयोगिता विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न होती है। जिस व्यक्ति के पास अधिक वस्तु अधिक मात्रा में होती है उसके लिए उस वस्तु की उपयोगिता दूसरे व्यक्ति जिसके पास वह कम मात्रा में उपलब्ध होती है उसकी अपेक्षा कम होती है। अतः वस्तु की बहुतायत वाले व्यक्ति से वस्तु की आवश्यकता वाले व्यक्ति के पास हस्तान्तरित करने से वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि होती है। स्वामित्व-उपयोगिता वस्तुओं में क्रय-विक्रय-क्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। क्रय-विक्रय विपणन-प्रक्रिया का प्रमुख भाग है।

उपयुक्त विपणन से स्पष्ट है कि विपणन-प्रक्रिया से वस्तुओं में उपयोगिता उत्पन्न होती है। अतः विपणन एक उत्पादक क्रिया है।

अच्छी विपणन-पद्धति की विशेषताएँ :

एक अच्छी विपणन-पद्धति में निम्न विशेषताएँ होनी चाहिए—

- 1 विपणन पद्धति के अन्तर्गत वस्तुओं के क्रय-विक्रय में सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए अर्थात् वस्तुओं का क्रय विक्रय स्वतन्त्र रूप से होना चाहिए।
- 2 विपणन-पद्धति के अन्तर्गत समाज के विभिन्न वर्गों, प्रमुखतया निर्धन वर्ग को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए।
- 3 विपणन-पद्धति, क्षेत्र की विपणन-व्यवस्था को विकसित की ओर अग्रसर करने वाली होनी चाहिए।
- 4 विपणन-व्यवस्था क्षेत्र में वस्तुओं की माँग एवं पूर्ति में समायोजन स्थापित करने वाली होनी चाहिए।
- 5 विपणन-व्यवस्था समाज में रोजगार में वृद्धि करने में भी सहायक होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि उपभोक्ता अधिक से अधिक उन वस्तुओं को क्रय करने को तत्पर हो जिनकी प्रोत्तिहीन होती है।

कृषि-विपणन का आर्थिक विकास में महत्त्व

देश के आर्थिक विकास में कृषि-विपणन का महत्त्वपूर्ण स्थान है जो निम्न-तथ्यों से स्पष्ट है—

- 1 तकनीकी ज्ञान के उपयोग से देश में कृषि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हुई है, लेकिन कृषकों को उत्पादन वृद्धि से अनुकूलनमय आय नहीं प्राप्त हो सकती है जब उत्पादित वस्तुओं के विक्रय की दृष्टि से सुव्यवस्थित विपणन-प्रणाली हो। उत्पादन की अधिक मात्रा प्राप्त होने से ही कृषकों को अधिक मेहनत करने की प्रेरणा मिले, यह आवश्यक नहीं

- है। देश में उचित विपणन-व्यवस्था के होने से कृषकों की उत्पादन की उचित कीमत प्राप्त होती है, विपणन-लागत कम देनी होती है और उन्हें उत्पादन में वृद्धि करने की प्रेरणा मिलती है। कृषकों की आय में वृद्धि होने में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तथा देश में विकास कार्यों पर व्यय करने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध हो सकेगी।
- 2 कृषि-विपणन द्वारा देश में उपलब्ध खाद्यान्न एवं अन्य कृषि वस्तुएँ असह्य उपभोक्ताओं तक पहुँच पाती हैं और उनकी आवश्यकताएँ पूरी होती हैं। उचित विपणन-व्यवस्था के अभाव में देश में आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध होते हुए भी वे उपभोक्ताओं तक उचित समय एवं उचित कीमत पर पहुँच नहीं पाते हैं। विपणन-प्रक्रिया में लागत भी अधिक आती है। अतः वस्तुओं की अधिक कीमतें, समय पर उनके आवश्यक मात्रा में उपलब्ध न होने तथा विपणन-लागत की अधिकता देश के आर्थिक विकास में बाधक होती है।
 - 3 देश के आर्थिक विकास की योजनाओं की सफलता भी कृषि विपणन पर निर्भर करती है। कृषि पर आधारित जनसंख्या की गरीबी को कम करने, आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने, अधिक विदेशी मुद्रा कमाने आदि योजनाओं के लिए देश में कृषि-वस्तुओं की कुशल विपणन-व्यवस्था का होना आवश्यक है।
 - 4 देश के आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक विकास भी आवश्यक है। देश के प्रमुख उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा-माल जैसे—गन्ना, कपास, जूट आदि कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। उत्पादित माल की लागत में कमी एवं उनका विदेशों को निर्यात बढ़ा करके अधिक विदेशी मुद्रा कमाने में विपणन ज्ञान सहायक होता है। कृषि-विपणन वस्तुओं को उपभोक्ताओं की आवश्यकतानुसार उत्पादित करने एवं उनके रूप में परिवर्तन करने का ज्ञान भी प्रदान करता है।
 - 5 कृषि विपणन देश के असह्य निवासियों (उत्पादकों, विपणन-मध्यस्थों, परिष्करण में सलग्न व्यक्तियों आदि) को उचित जीवन-स्तर बनाये रखने के लिए आय प्राप्त कराने में सहायक होता है। अधिक आय प्राप्त होने से देश के निवासी अधिक मात्रा में औद्योगिक वस्तुओं का क्रय करते हैं जिससे उद्योगों का विकास होता है, जो देश के आर्थिक विकास में सहायक होता है।
 - 6 देश में कृषि उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी उत्पादन-साधनों जैसे—उर्वरक, कीटनाशी दवाइयाँ, कृषि-यन्त्र आदि का समय एवं उचित कीमत पर उपलब्ध होना आवश्यक है। यह

तभी सम्भव हो पाता है जब देश में विपणन की उचित व्यवस्था होती है। उचित विपणन-व्यवस्था का अभाव देश के आर्थिक विकास में बाधक होता है।

बाजार मण्डी

प्राचीन काल में देश में वस्तुओं का लेन-देन वस्तु-विनिमय प्रथा द्वारा होता था, जिसके कारण वर्तमान की भाँति मण्डियाँ/बाजार नहीं थे। वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा में वृद्धि, उत्पादन में विशिष्टीकरण एवं वस्तु-विनिमय के स्थान पर मुद्रा द्वारा विनिमय होने के कारण देश में मण्डियों का विकास होना शुरू हुआ। शुरू में यह बाजार धार्मिक मेलों के स्थान पर लगने लगे, उसके पश्चात् प्रति सप्ताह हटवाड़े लगने लगे, आवश्यकताओं के बढ़ने के साथ बाजार नियमित रूप से लगने लग गये। बाजार शब्द के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न पर्यायवाची शब्द हैं जैसे—मण्डी, हाट, सण्डीज, पैथम आदि। मार्केट (बाजार) शब्द का उद्गम लेटिन शब्द मार्केटस् (Marcatus) से हुआ है जिससे तात्पर्य वस्तुओं के क्रय-विक्रय के स्थान से होता है।

बाजार की परिभाषा—विभिन्न व्यक्ति बाजार शब्द से विभिन्न अर्थ लगाते हैं। साधारणतया बाजार शब्द से तात्पर्य उस स्थान से है जहाँ क्रैता एवं विक्रेता एकत्रित होकर वस्तुओं का लेन-देन करते हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने बाजार शब्द को विभिन्न शब्दों में परिभाषित किया है लेकिन उनमें आपस में बहुत समानता है। प्रमुख परिभाषाएँ ये हैं—

कूनो⁷—“अर्थशास्त्रियों का बाजार शब्द से तात्पर्य किसी विशिष्ट स्थान, जहाँ पर वस्तुओं का त्रय विषय होता है, से नहीं होकर, उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें क्रैताओं एवं विक्रेताओं के मध्य वस्तुओं के त्रय-विक्रय की पूर्ण स्पर्धा होती है, तथा एक ही वस्तुओं की कीमतें सुगमता व शीघ्रतापूर्वक समानता की स्थिति में आ जाती हैं।”

हियार्ड⁸—बाजार वह क्षेत्र है जिसके अन्तर्गत कीमत-निर्धारण की शक्तियाँ कार्य करती हैं।

7 Economists understand by the term markets not any particular market place in which things are bought and sold, but the whole of any region in which buyers and sellers are in such free intercourse with one another that the prices of the same goods tend to equality easily & quickly
—Cournot Recherches sur les Principes Mathematiques de la Theorie des Richesses Chap IV

8 B. H. Hibbard, Marketing Agricultural Products, D Appleton & Company, INC, Newyork 1921, pp. 13-15

चंपमैन—आर्थिक दृष्टिकोण से बाजार शब्द का तात्पर्य किसी स्थान से नहीं है बल्कि उन वस्तुओं से है जिनके क्रेता एवं विक्रेता क्रय-विक्रय के लिए एक-दूसरे से सीधे स्पर्धा में होते हैं।

समाजशास्त्र ज्ञानकोष के अनुसार⁹—बाजार शब्द से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसके अन्तर्गत माँग एवं पूर्ति की शक्तियाँ किसी वस्तु की एक ही कीमत निर्धारित करने में सफल होती हैं।

बाजार के लिए आवश्यकताएँ—किसी भी क्षेत्र को बाजार शब्द की परिभाषा में सम्मिलित करने के लिए कुछ विशेषताओं का उस क्षेत्र में होना आवश्यक है। आवश्यक विशेषताओं के नहीं होने पर, क्षेत्र को बाजार की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया जाता है। बाजार शब्द के लिए प्रमुख आवश्यकताएँ निम्न हैं—

- 1 बाजार में क्रय-विक्रय के लिए वस्तुओं का होना आवश्यक है।
- 2 बाजार में वस्तुओं के क्रय-विक्रय के लिए क्रेताओं एवं विक्रेताओं का होना आवश्यक है।
- 3 बाजार के लिए स्थान एवं क्षेत्र का निर्धारण आवश्यक है।
- 4 क्षेत्र के क्रेता एवं विक्रेताओं के मध्य स्वतन्त्र व्यापारिक सम्बन्ध का होना आवश्यक है।

किसी क्षेत्र को बाजार की परिभाषा में होने के लिए आवश्यक नहीं है कि बाजार के समस्त क्षेत्र में वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित हो एवं बाजार में पूर्ण स्पर्धा की स्थिति विद्यमान हो।

विकसित बाजार की विशेषताएँ—विकसित बाजार में निम्न विशेषताएँ होनी आवश्यक हैं—

- 1 बाजार में उपभोक्ताओं द्वारा चाही गई सभी वस्तुएँ, जिन्हें वे क्रय कर सकें, उपलब्ध होनी चाहिये।
- 2 उपभोक्ताओं के द्वारा वस्तुओं के चयन हेतु विभिन्न किस्म की वस्तुएँ उपलब्ध होनी चाहिये।
- 3 बाजार में नुकसानदेह वस्तुएँ विपणन के लिये नहीं होनी चाहिये।
- 4 बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं की सूचना एवं उनके गुणों की जानकारी देने की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये।
- 5 बाजार में क्रेताओं पर वस्तुओं के क्रय के लिये किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिये।
- 6 बाजार में वस्तुओं की उचित कीमत प्रचलित होनी चाहिये।
- 7 बाजार में वस्तुओं के सुदरा-विक्रय की व्यवस्था होनी चाहिये।

बाजारों का वर्गीकरण—निम्न आधारों के अनुसार बाजारों का वर्गीकरण किया जाता है—

1. क्षेत्रफल के अनुसार—इस आधार के अन्तर्गत बाजारों का वर्गीकरण उनके फैलाव अथवा उनमें आने वाले क्रेताओं एवं विक्रेताओं के स्थान से बाजार की दूरी के अनुसार किया जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर बाजार निम्न प्रकार के होते हैं—

(अ) स्थानीय बाजार—स्थानीय बाजार में क्रेता एवं विक्रेता अधिक दूरी से न आकर मुख्यतया उसी गाँव या कस्बे के होते हैं। स्थानीय बाजार मुख्यतया शीघ्रमासी वस्तुओं जैसे—दूध, सब्जी आदि के विपणन के लिये होते हैं। इन्हें ग्रामीण बाजार भी कहते हैं।

(ब) क्षेत्रीय बाजार—इन बाजारों का क्षेत्र स्थानीय बाजारों की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। इनमें क्रेता एवं विक्रेता मजदीक के ग्रामों अथवा क्षेत्र से क्रय-विक्रय के लिये आते हैं जैसे—खाद्यान्न के बाजार।

(स) राष्ट्रीय बाजार—इन बाजारों में क्रेता एवं विक्रेता देश के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं अर्थात् वस्तुओं का क्रय-विक्रय सम्पूर्ण देश के निवासियों के मध्य होता है। राष्ट्रीय बाजार में उन सभी वस्तुओं का विपणन होता है जो अधिक समय तक सहेजती जा सकती हैं जैसे—चाय, जूट आदि।

(द) अन्तर्राष्ट्रीय/विश्व बाजार—इन बाजारों में क्रेता एवं विक्रेता विभिन्न देशों के होते हैं। क्षेत्र की दृष्टि से ये सबसे बड़े बाजार हैं। इन बाजारों में उन वस्तुओं का क्रय-विक्रय होता है जो लम्बी अवधि तक खराब नहीं होती हैं जैसे—चीनी, चाय, मशीनें, सोना चाँदी आदि।

2 स्थान स्थिति के अनुसार—स्थान स्थिति के अनुसार बाजार निम्न प्रकार के होते हैं—

(अ) स्थानीय/ग्रामीण बाजार—ये बाजार ग्रामों में स्थित होते हैं और इनमें अधिकांश क्रेता एवं विक्रेता उसी ग्राम के होते हैं।

(ब) प्राथमिक थोक बाजार—ये बाजार उत्पादन स्थानों के नजदीक बड़े कस्बों में लगते हैं। इनमें वस्तुएँ अधिकांश मात्रा में विक्रय के लिये उत्पादकों द्वारा लायी जाती हैं। देश के अधिकांश कृषक उत्पादित खाद्यान्नों को विक्रय के लिये इन्हीं बाजारों में लाते हैं।

(स) माध्यमिक थोक बाजार—ये बाजार बड़े कस्बों, शहरों एवं रेल्वे जंक्शनों के समीप लगते हैं। इनमें खाद्यान्नों का क्रय-विक्रय थोक में होता है। माध्यमिक थोक बाजारों में वस्तुओं का क्रय विक्रय ग्रामीण व्यापारियों एवं थोक व्यापारियों के मध्य में होता है। छुट्टा व्यापारी वस्तुएँ इन्हीं बाजारों से क्रय करके विक्रय हेतु ले जाते हैं।

(द) छुट्टा बाजार—इन बाजारों में खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं की बित्री थोड़ी-थोड़ी मात्रा में उपभोक्ताओं एवं छोटे व्यापारियों के बीच होती है। विक्रेता

छोटे दुकानदार होते हैं जो माध्यमिक थोक बाजार ने वस्तुएँ ख़रीद करके इन बाजारों में विक्रय करने हैं। मुद्रा बाजार देश के सभी स्थानों पर पाये जाते हैं।

(य) बन्दरगाहों के समीप बाजार—ये बाजार मुख्यतः उन वस्तुओं के क्रय-विक्रय के लिए होते हैं जो आयात अथवा निर्यात की जाती हैं। अतः ऐसे बाजार बन्दरगाहों के समीप होते हैं, जैसे—कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कादला बन्दरगाहों के समीप के बाजार।

(र) अन्तिम बाजार अन्तिम बाजार (Terminal Market) वे हैं जहाँ से वस्तु पुनः उस रूप में बाजार में विक्रय के लिये नहीं आती है। इन बाजारों से वस्तुएँ उपभोक्ताओं अथवा दूसरे देशों को निर्यात करने वाले व्यक्तियों को विक्रय की जाती हैं।

3 समय के अनुसार—समय के अनुसार बाजार निम्न प्रकार के होते हैं—

(अ) अल्पकालीन बाजार—ये बाजार वस्तुओं में भीषणता की गुण होने के कारण अल्पकाल के लिये ही लग पाते हैं। इन बाजारों में वस्तुओं की कीमतों पर पूर्ति की अपेक्षा माँग का प्रभाव अधिक होता है। अतः वस्तुओं की कीमतें माँग की प्रबलता के अनुसार निर्धारित होती हैं क्योंकि अल्पकाल में वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि करना सम्भव नहीं होता है, जैसे—सब्जी बाजार, मछली बाजार आदि।

(ब) दीर्घकालीन बाजार—ये बाजार उन वस्तुओं के लिये लगते हैं जो भीषणता नहीं होती हैं, जैसे—खाद्यान्न, तिलहन आदि। दीर्घकालीन बाजार में माँग में परिवर्तन के अनुसार पूर्ति में परिवर्तन के लिये समय मिल जाता है जिससे वस्तुओं की कीमत पर माँग की अपेक्षा पूर्ति का प्रभाव अधिक होता है।

(स) सुदीर्घकालीन बाजार—ये बाजार उन वस्तुओं के क्रय-विक्रय के लिये होते हैं जो बहुत समय तक खराब नहीं होती हैं, जैसे—मशीनें, निर्मित वस्तुएँ आदि। इन बाजारों में माँग में परिवर्तन के अनुसार पूर्ति में परिवर्तन के लिये पर्याप्त समय मिल जाता है, जिसके कारण वस्तुओं की कीमत पर पूर्ति का प्रभाव दीर्घकालीन बाजार की अपेक्षा अधिक होता है।

4 क्रय-विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की सख्या के अनुसार :

(अ) साधारण मिश्रित बाजार—इन बाजारों में अनेक वस्तुओं, जैसे—खाद्यान्न, दालें, तिलहन, कपास, गूद आदि का क्रय-विक्रय होता है। इस प्रकार के बाजार देश के प्रत्येक ग्राम, कस्बे एवं शहर में होते हैं।

(ब) विशिष्ट बाजार—इन बाजारों में एक या दो वस्तुओं का ही क्रय-विक्रय होता है। विभिन्न वस्तुओं के क्रय-विक्रय के लिये पृथक् विशिष्ट बाजार होते हैं, जैसे—खाद्यान्न-मण्डी, सब्जी-मण्डी, फल-मण्डी, कपास-मण्डी, जूत मण्डी आदि।

(स) नमूने के द्वारा विक्रय बाजार—इन बाजारों में वस्तुओं का क्रय-विक्रय

वस्तु की पूरी मात्रा के स्थान पर उसके नमूने के आधार पर होता है। विक्रेता वस्तु का नमूना क्रेता को दिखाकर सौदा करते हैं। वस्तु की पूरी मात्रा का मण्डी में होना आवश्यक नहीं है।

(द) श्रेणी के अनुसार विक्रय बाजार—इन बाजारों में वस्तुओं का क्रय-विक्रय वस्तु की निर्धारित श्रेणी के आधार पर होता है। इन श्रेणियों से क्रेता एवं विक्रेता पूर्ण परिचित होते हैं। वस्तुओं की श्रेणी के अनुसार कीमतें निर्धारण होती हैं।

5 स्पर्धा के अनुसार—क्रय-विक्रय में होने वाली स्पर्धा के अनुसार बाजार निम्न प्रकार के होते हैं—

(अ) पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार—वे बाजार जिनमें क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य वस्तुओं के क्रय-विक्रय के लिये पूर्ण स्पर्धा की स्थिति होती है। इन बाजारों में क्रेता एवं विक्रेता काफी संख्या में होते हैं। इन बाजारों के सभी क्षेत्रों में वस्तु की कीमत का समान होना आवश्यक होता है। वास्तव में पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार काल्पनिक होते हैं क्योंकि उपर्युक्त शर्तें पूर्ण रूप से बाजार में नहीं पायी जाती हैं।

(ब) अपूर्ण स्पर्धा वाले बाजार—वे बाजार जिनमें क्रेताओं एवं विक्रेताओं के मध्य पूर्ण स्पर्धा की स्थिति का अभाव होता है। इन बाजारों में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या पर्याप्त नहीं होने के कारण पूर्ण स्पर्धा नहीं होती है तथा विक्रेता विभिन्न कीमतों पर क्रेताओं को वस्तुएँ विक्रय करते हैं। अपूर्ण स्पर्धा वाले बाजार निम्न प्रकार के होते हैं—

(i) एकाधिकार बाजार—इन बाजारों में वस्तु का एक ही विक्रेता होता है जिसके कारण वह क्रेताओं से अपनी इच्छानुसार कीमत वसूल करता है। इन बाजारों में कीमती स्पर्धा के अभाव के कारण साधारणतया अन्य बाजारों की अपेक्षा अधिक होती है। जब बाजार में वस्तु का एक ही क्रेता होता है तो उस बाजार को एक-क्रेताधिकार बाजार (Monopsony Market) कहते हैं।

(ii) द्वयाधिकार बाजार—इन बाजारों में वस्तुओं के दो ही विक्रेता होते हैं। दोनों विक्रेता आपस में समझौता कर लेते हैं और क्रेताओं से अधिक कीमत वसूल करते हैं। बाजार में वस्तुओं के दो ही क्रेता होने की स्थिति में बाजार को द्वि-क्रेताधिकार बाजार (Duopsony Market) कहते हैं।

(iii) अल्पाधिकार बाजार—इन बाजारों में वस्तुओं के विक्रेता दो से अधिक होते हैं, लेकिन उनकी संख्या अधिक नहीं होती है। अतः पूर्ण स्पर्धा का अभाव होता है। क्रेताओं की संख्या दो से अधिक, लेकिन ज्यादा नहीं होने की स्थिति में बाजार को अल्प-क्रेताधिकार बाजार (Oligopsony Market) कहते हैं।

(iv) एकाधिकारात्मक बाजार—एकाधिकारात्मक बाजार (Monopolistic Market) में क्रेता एवं विक्रेता अधिक संख्या में होते हैं। इन बाजारों में वस्तुओं की किस्म में विभिन्नता होती है। वस्तुओं की किस्म में विभिन्नता,

विक्रेताओं द्वारा वस्तुओं पर विभिन्न ट्रेडमार्क देकर की जाती है, जिसके कारण उनकी कीमतों में भी निम्नता पायी जाती है।

6 नियन्त्रण के अनुसार—नियन्त्रण के अनुसार बाजार दो प्रकार के होते हैं :

(प्र) नियन्त्रित बाजार—ये बाजार जो कृषि-उपज मंडी समिति द्वारा नियन्त्रित किए जाते हैं। इन बाजारों में विपणन पद्धतियों एवं व्यापारियों की कुचालों को कानून द्वारा नियन्त्रित किया जाता है, जिसमें वस्तुओं की प्रति इकाई विपणन-लागत कम आती है और उत्पाद की कीमत अच्छी प्राप्त होती है।

(ब) अनियन्त्रित बाजार—इन बाजारों में व्यापारी इच्छानुसार कार्य करते हैं। इन बाजारों में विपणन की दोषयुक्त प्रणाली पायी जाती है, जिससे विपणन-लागत अधिक आती है। इन बाजारों में विपणन के नियम व्यापारियों द्वारा बनाए जाते हैं, जिनमें कृषकों के हितों की रक्षा करने के उपाय सम्मिलित नहीं होते हैं।

7 वस्तुओं के आदान-प्रदान के समयानुसार .

(प्र) हाजिर बाजार—हाजिर बाजार में वस्तुओं का लेन-देन एवं आदान-प्रदान विक्रय के तुरन्त पश्चात् होता है। वस्तुओं की कीमत का सीधे मुग्तान करके क्रेता वस्तुओं को ले जाते हैं।

(ब) वायदा बाजार—वायदा बाजार में वस्तुओं का क्रय-विक्रय वर्तमान में होता है, लेकिन उनका आदान-प्रदान भविष्य में निश्चित किए गए दिनांक को होता है। साधारणतया वायदा बाजारों में वस्तुओं का वास्तविक आदान-प्रदान नहीं होता है, बल्कि क्रेताओं एवं विक्रेताओं में विक्रय से होने वाले लाभ अथवा हानि की राशि का ही मुग्तान होता है।

8 वस्तुओं की मात्रा के अनुसार .

(प्र) थोक बाजार—थोक बाजार में वस्तुओं का क्रय-विक्रय अधिक मात्रा में एक साथ होता है। अधिक मात्रा में क्रय-विक्रय साधारणतया व्यापारियों के मध्य होते हैं।

(ब) खुदरा बाजार—इन बाजारों में वस्तुओं का क्रय-विक्रय थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खुदरा विक्रेताओं एवं उपभोक्ताओं के मध्य होता है। थोक एवं खुदरा विक्रय के लिए वस्तु की मात्रा वस्तु की किस्म के अनुसार परिवर्तित होती है।

9 वस्तुओं की प्रकृति के अनुसार :

(प्र) वस्तुओं का बाजार—इन बाजारों में विभिन्न उत्पादित वस्तुओं (कृषि उत्पादों, निर्मित वस्तुओं एवं उत्पादन साधनों) का क्रय-विक्रय होता है।

(ब) मुद्रा बाजार—इन बाजारों में वस्तुओं का लेन-देन न होकर मुद्रा, शेयर, बॉन्ड आदि का क्रय-विक्रय होता है।

मण्डियों का विकास :

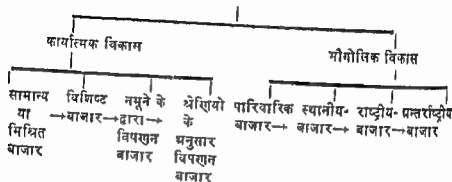
प्राचीनकाल में देश में वर्तमान की भांति मण्डियाँ विकसित नहीं थी, क्योंकि इस काल में वस्तुओं का लेन-देन रूपों के आधार पर नहीं होकर, वस्तु-विनिमय विधि द्वारा होता था। वर्तमान में मुद्रा का प्रसार, कोमतों का ज्ञान, कृषि में विशिष्टीकरण की प्रवृत्ति के कारण वस्तुओं का लेन-देन, घास-पास के क्रेताओं एवं विक्रेताओं तक ही सीमित नहीं रह कर, देश-विदेश के क्रेताओं एवं विक्रेताओं के मध्य होने लग गया है, जिससे देश में मण्डियों का विकास हुआ है और मण्डियाँ वर्तमान स्थिति में आ गयी हैं। मण्डियों के विकास का निम्न दृष्टिकोण से अध्ययन किया जा सकता है—

1 कार्यात्मक विकास—इस दृष्टिकोण में मण्डियों में किये जाने वाले कार्य मुख्य आधार होते हैं। देश में सर्वप्रथम सामान्य/मिश्रित बाजारों का जन्म हुआ था। इन बाजारों में अनेक वस्तुओं में लेन-देन होता था। उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं में वृद्धि, वस्तुओं के प्रचार, उत्पादन में विशिष्टीकरण आदि के कारण सामान्य बाजार धीरे-धीरे विशिष्ट बाजारों के रूप में परिवर्तित होने शुरू हुये। विशिष्ट बाजारों में एक या दो वस्तुओं में ही क्रेताओं एवं विक्रेताओं के मध्य लेन-देन होता है। व्यवसाय बढ़ने के साथ विपणन के क्षेत्र में अधिक प्रगति हुई और वस्तुओं का क्रय-विक्रय पूरे माल की देखने के स्थान पर नमूने के आधार पर होना शुरू हुआ। तत्पश्चात् कृषि-उपज के श्रेणी चयन एवं मानकीकरण के कारण वस्तुओं का व्यापार निर्धारित श्रेणियों के अनुसार होने लग गया, जिससे वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में सहयोग मिला। इस प्रकार मण्डियों का कार्यात्मक विकास होकर मण्डियाँ वर्तमान स्थिति में आ गई।

2 भौगोलिक विकास—मण्डियों के विकास के अध्ययन का दूसरा दृष्टिकोण भौगोलिक विकास है, जिसके अनुसार सर्वप्रथम वस्तुओं का क्रय-विक्रय पारिवारिक बाजार अर्थात् क्रय विक्रय परिवार एवं ग्राम के सदस्यों तक ही सीमित होता था। उत्पादन में विशिष्टीकरण एवं उपभोक्ताओं की आवश्यकता में वृद्धि के कारण पारिवारिक बाजार स्थानीय बाजार के रूप में विकसित हुए अर्थात् वस्तुओं का क्रय-विक्रय घास-पास के गाँवों के क्रेताओं एवं विक्रेताओं के मध्य होने लग गया। वस्तुओं की माँग देश के सभी कोनों से होने तथा परिवहन एवं संचार सुविधाओं के विकास के कारण राष्ट्रीय बाजारों का विकास हुआ। देश-विदेश के ज्ञान एवं व्यवहार के बढ़ने तथा देश की मुद्रा के विभिन्न देशों की मुद्राओं में विनिमय की सुविधा के कारण वस्तुओं में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की शुरुआत हुई। वस्तुएँ एक देश से दूसरे देश को आयात-निर्यात की जाने लगी। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों का विकास हुआ।

मण्डियों के उपर्युक्त विकास को निम्न प्रकार से अधिक स्पष्ट किया जा सकता है—

मण्डियों का विकास



मण्डियों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक—निम्न कारक मण्डियों के विकास को प्रभावित करते हैं—

(1) वस्तुओं की प्रकृति—शीघ्रनाशी वस्तुओं का बाजार अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कम विकसित हो पाता है, क्योंकि उन्हें अधिक समय तक संचयित नहीं किया जा सकता है।

(2) वस्तुओं की मांग—स्थायी मांग वाली वस्तुएँ जैसे—खाद्यान्न का बाजार अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक विकसित होता है।

(3) परिवहन एवं संचार व्यवस्था—जिन क्षेत्रों में परिवहन एवं संचार की सुविधाएँ अधिक होती हैं, उन क्षेत्रों में मण्डियों का विकास अधिक होता है।

(4) क्षेत्र में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था—शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था वाले क्षेत्रों में मण्डियों का विकास अधिक होता है। सुरक्षा-व्यवस्था के खराब होने पर मण्डियों के विकास में बाधा पहुँचती है।

(5) सरकार की नीति—सरकार की नीति के कारण वस्तुओं के आयात-निर्यात पर पाबन्दी वाले क्षेत्रों में मण्डियों का विकास अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम हो पाता है।

(6) ऋण-उपलब्धि—पर्याप्त ऋण-सुविधा वाले क्षेत्रों में मण्डियों का विकास अधिक होता है।

(7) मुद्रा का विकास—जिस देश की मुद्रा की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी मांग होती है, उस देश में मण्डियों का विकास अधिक होता है क्योंकि उस देश के साथ अन्य देश व्यापार करने में प्राथमिकता देते हैं।

(8) वस्तुओं के श्रेणीचयन की सुविधा—जिन वस्तुओं में श्रेणीचयन सुगमता से किया जा सकता है, उन वस्तुओं का बाजार अश्रेणीकृत वस्तुओं की अपेक्षा अधिक विकसित होता है।

(9) वस्तुओं की पूर्ति की मात्रा - जिन वस्तुओं का उत्पादन वर्ष भर तथा काफी मात्रा में होता है, उन वस्तुओं का बाजार अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक विकसित होता है।

बायदा बाजार (Forward Market)

बायदा बाजार से तात्पर्य उस बाजार से है जिसमें वस्तुओं का क्रय-विक्रय वर्तमान में होता है, लेकिन उनका वास्तविक आदान-प्रदान भविष्य में निश्चित किए गए दिनांक को होता है। बायदा बाजार को अग्रिम बाजार भी कहते हैं। साधारणतया बायदा बाजार में वस्तुओं का वास्तविक आदान-प्रदान नहीं होता है, बल्कि क्रेतार्थों एवं विक्रेतार्थों में विषय से होने वाले लाभ अथवा हानि की राशि का ही भुगतान होता है। बायदा बाजार में वस्तुओं के लेन-देन में दो प्रकार के व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। विपणन भाषा में तेजडिये (Bulls) एवं मन्दडिये (Bears) कहते हैं। वे व्यक्ति जो यह महसूस करते हैं कि निकट भविष्य में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी, तेजडिये कहलाते हैं तथा वे व्यक्ति जो यह महसूस करते हैं कि निकट भविष्य में वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आवेगी, मन्दडिये कहलाते हैं। बायदा बाजार इन्हीं दोनों वर्गों के व्यक्तियों में आपसी निर्णयों के आधार पर चलता है। एक वर्ग कीमतों के बढ़ने की आशा में वस्तुओं का क्रय करना है, जबकि दूसरा वर्ग कीमतों के गिरने की आशा में विषय करता है।

बायदा बाजार से लाभ—दण के आर्थिक ढाँचे में बायदा बाजार निम्न में बाएँ प्रदान करता है—

- 1 बायदा बाजार वस्तुओं की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को कम करने में सहायक होता है, जिससे व्यापारी, संप्रभुकर्ता, परिष्करण में लगे व्यक्तियों की कीमतों के प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली हानि कम हो जाती है।
- 2 बायदा बाजार के होने से वस्तुओं के व्यापार में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति के कारण कीमतों में उतार-चढ़ाव सामान्य गति से होता है। वस्तुओं का संचयन निरन्तर बना रहता है, जिसके कारण उत्पादन मौसम में कीमतों में अत्यधिक वृद्धि वाली स्थिति उत्पन्न नहीं होती है।
- 3 बायदा बाजार विभिन्न समयों में वस्तुओं की कीमतों के ढाँचे में एकीकरण बनाए रखता है, जिस प्रकार परिवहन एवं संचार कार्य बाजार के विभिन्न स्थानों पर कीमतों के ढाँचे में एकीकरण बनाए रखता है।

4. बायदा-बाजार के कारण वस्तुओं का कम-बिनाय उत्पादन के पूर्व धनवा पंदावार के मण्डी में आन के पूर्व ही विनय हो पाता सम्भव होता है ।

5 बायदा-बाजार के होने से वर्तमान एव भावी कीमतों में समन्वय स्थापित हो पाता है ।

बायदा-बाजार से हानि—बायदा-बाजार से निम्न हानियाँ होने की आशका बनी रहती है—

(1) बायदा-बाजार के कारण विपणन प्रक्रिया में ऐसे व्यक्ति कमी-कमी लेन-देन में सम्मिलित हो जाते हैं, जिनके पास पर्याप्त धनाभाव, साधन, मूचन एव अनुभव नहीं होने के कारण विपणन प्रक्रिया में किये गये बायदे पूरा करना उनके लिये सम्भव नहीं होता है । इस प्रकार की परिस्थिति से बायदा-बाजार के नैतिक स्तर पर विपरीत प्रभाव आता है ।

(2) बायदा-बाजार के कारण सट्टे की प्रवृत्ति वाले विपणन-मध्यस्थ, विपणन-प्रक्रिया में प्रवेश कर जाते हैं, जिन्हें वस्तु की पूर्ति एव माँग में कोई दिलचस्पी नहीं होती है । वे वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा का गुप्त संचय करके बाजार में कृत्रिम कमी की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, जिससे कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव होते हैं जो अर्थव्यवस्था के लिये नुकसानदेह होते हैं ।

अतः बायदा-बाजार के कारण अर्थव्यवस्था पर घाने वाले प्रभावों के विषय में विभिन्न व्यक्तियों में मतभेद पाया जाता है । प्रथम वर्ग के व्यक्ति यह मानते हैं कि बायदा-बाजार वस्तुओं की कीमतों में होने वाले अत्यधिक उतार-चढ़ावों को कम करने एव कीमतों में स्थिरीकरण की स्थिति उत्पन्न करते हैं । दूसरे वर्ग का मत है कि बायदा बाजार के कारण कीमतों में होने वाले उतार चढ़ावों के अन्तर एव क्रम में वृद्धि होती है, जिससे कीमतों में असाधारण दर से परिवर्तन होता है । तीसरे वर्ग का मानना है कि बायदा-बाजार के होने से वस्तुओं की कीमतों के परिवर्तन में दोनों ही प्रकार के प्रभाव होते हैं ।

कृषि कीमतों में होने वाले अत्यधिक व हानिकारक सट्टे की प्रथा को नियन्त्रित करने के लिए सरकार ने बायदा सविदा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1952 [Forward Contracts (Regulation) Act] पारित किया है । इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य बायदा-बाजार में होने वाले लेन-देन को नियन्त्रित करना, वस्तुओं के विकल्प (Option) की प्रथा पर रोक लगाना एव अन्य सम्बन्धित निर्णय लेने से है । ये कार्य बायदा-बाजार आयोग की सहायता से किये जाते हैं । इस अधिनियम के अन्तर्गत समय-समय पर सरकार वस्तुओं की कीमतों में होने

वाले सट्टे की प्रवृत्ति को देखते हुए विभिन्न वस्तुओं के बायदा-बाजार पर पाबन्दी लगाती है। आवश्यकतानुसार कानून में व्याप्त कमियों को दूर करने एवं अनेक वस्तुओं के बायदा बाजार को नियन्त्रण में लाने के लिए अधिनियम में संशोधन भी ये भये हैं।

यदा बाजार के होने के लिए वस्तुओं में गुणों की आवश्यकता -

किसी भी वस्तु के बायदा बाजार हेतु सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने के लिए वस्तुओं में निम्न गुण होने चाहिए—

- (1) वस्तु की पूर्ति बाजार में पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिये। कम पूर्ति वाली वस्तुओं में बायदा-बाजार की स्वीकृति सरकार नहीं देती है।
- (2) वस्तुओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में होने के साथ-साथ वस्तु के पूतिकर्ता एक न होकर अनेक होने चाहिए।
- (3) वस्तुओं में शीघ्रनाशी का गुण नहीं होना चाहिए।
- (4) वस्तुओं में श्रेणीकरण किए जाने का गुण होना चाहिए, जिससे मन्त्रिम्य में वस्तुओं की बिना किसी गुणात्मक समस्या के पूर्ति की जा सके।
- (5) वस्तु की माँग पर्याप्त मात्रा में हानी चाहिए एवं उनके क्रेता भी अधिक संख्या में होने चाहिए।
- (6) वस्तु की कीमत में निरन्तर परिवर्तन होने का गुण होना चाहिए।

वस्तुओं के बायदा बाजार 19वीं शताब्दी के अन्त से ही प्रचलित हैं। सर्व-प्रथम कपास के लिये बायदा बाजार वर्ष 1885 में बम्बई में स्थापित किया गया था। उसके पश्चात् तिलहन के लिए बम्बई में वर्ष 1900 में, गेहूँ के लिये हापुड में वर्ष 1913 में, कच्चे जूट एवं निर्मित जूट की वस्तुओं के लिये कलकत्ता में वर्ष 1912 में एवं सोने-चाँदी के लिये बम्बई में वर्ष 1920 में बायदा-बाजार स्थापित किये गये। तत्पश्चात् अन्य वस्तुओं के बायदा-बाजार भी अनेक स्थानों पर स्थापित किये जा चुके हैं।

विपणन अध्ययन के दृष्टिकोण (Approaches for Studying Marketing)

विपणन-प्रक्रिया एवं समस्याओं के अध्ययन के प्रमुख दृष्टिकोण निम्न हैं—

(1) कार्यात्मक दृष्टिकोण—विपणन प्रक्रिया के अध्ययन के इस दृष्टिकोण में विभिन्न समस्याओं द्वारा किये जाने वाले विपणन कार्यों का समावेश होता है। प्रत्येक वस्तु के विपणन के लिये विभिन्न विपणन-कार्य आवश्यक रूप से करने होते हैं। विपणन-कार्यों को समाप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि विपणन कार्यों को करने वाली समस्याओं में परिवर्तन किया जा सकता है। विपणन कार्यों के अभाव में वस्तुओं की विपणन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। विपणन कार्यों का अध्ययन वस्तुओं के विपणन में होने वाली लागत की भिन्नता, विभिन्न विपणन मध्यस्था का प्राप्त होने वाले लाभ की राशि एवं विपणन-तन्त्र के अध्ययन में सहायक होता है।

वस्तुओं के विपणन में किये जाने वाले विपणन कार्यों का विस्तृत विवरण अध्याय 13 में दिया गया है।

(2) सस्थागत दृष्टिकोण—विपणन-प्रक्रिया के अध्ययन के दूसरे दृष्टिकोण के अन्तर्गत विपणन कार्य करने वाली संस्थाओं का समागत अध्ययन किया जाता है। विपणन कार्य में लगी हुई विपणन-संस्थाएँ एक या अनेक विपणन-कार्य सम्पन्न करती हैं और अपनी सेवाओं के लिये लागत/लाभ की राशि प्राप्त करती हैं।

(3) वस्तुगत दृष्टिकोण—इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत बाजार संरचना के अध्ययन के लिये विभिन्न वस्तुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। वस्तुओं के गुणों में भिन्नता के कारण सभी वस्तुओं का एक साथ अध्ययन नहीं किया जा सकता। वस्तुगत दृष्टिकोण में बाजार संरचना के अध्ययन के लिए कार्यात्मक एवं संस्थागत दोनों ही दृष्टिकोण काम में लाये जाते हैं।

(4) व्यवहार विधि दृष्टिकोण—विपणन अध्ययन के इस दृष्टिकोण में विभिन्न विपणन संस्थाओं के व्यवहार का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। विपणन संस्थाओं का व्यवहार निरन्तर परिवर्तित होता रहता है। इस दृष्टिकोण में विभिन्न विपणन संस्थाओं एवं उनके समूह का एक व्यवहार-विधि के रूप में अध्ययन किया जाता है।

साधानों के विपणन में पाये जाने वाले विपणन-मध्यस्थ

साधानों के विपणन में पाये जाने वाले विपणन-मध्यस्थों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है—

(1) सौदागर मध्यस्थ—ये मध्यस्थ साधानों का क्रय-विक्रय लाभ की प्राप्ति के लिये करते हैं और क्रय-विक्रय की कीमतों के अन्तर से लाभ कमाते हैं। सौदागर मध्यस्थ दो प्रकार के होते हैं—

(अ) थोक व्यापारी—ये व्यापारी वस्तुओं का थ्रू विक्रय बहुत मात्रा में एक साथ करते हैं। इन्हें वस्तु की प्रति इकाई मात्रा पर लाभ कम प्राप्त होते हुए भी कुल लाभ अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि एक साथ वस्तु की काफी मात्रा का क्रय करते हैं।

(ब) खुदरा व्यापारी—खुदरा व्यापारी मण्डियों से सस्ते भाँसे अधिक मात्रा में क्रय करके उपभोक्ताओं को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में विक्रय करते हैं और विक्रय कीमत एवं क्रय-कीमत के अन्तर में अपना निर्वाह करते हैं।

(2) एजेंट/प्रमोकर मध्यस्थ—ये विपणन-मध्यस्थ कृषकों अथवा विपणन करने वाले व्यापारियों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। एजेंट मध्यस्थ स्वयं वस्तुओं का क्रय विषय लाभ कमाने के लिये नहीं करते हैं बल्कि वे अपने कार्य के लिये कृषकों या व्यापारियों से कमीशन/आडव प्राप्त करते हैं। प्रमोकर मध्यस्थ दो प्रकार के होते हैं—

(अ) **आढतिया**—ये कृषको एव व्यापारियों द्वारा लाये गये खाद्यान्नों का विक्रय करने हैं और प्राप्त विक्रय राशि में से अपना कमीशन काटकर शेष राशि का कृषक/व्यापारी को मुणतान करते हैं। आढतियों की बाजार में स्थायी दुकान होती है और आवश्यकता पड़ने पर ये कृषको को ऋण भी प्रदान करते हैं। आढतियों को कृषको द्वारा लाये गये खाद्यान्नों को विक्रय करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं।

(ब) **दलाल**—इनका प्रमुख कार्य वस्तुओं के क्रेताओं एव विक्रेताओं को क्रय-विक्रय के लिये एक स्थान पर मिलाना होता है। अपनी सेवाओं के लिये वे क्रेताओं, विक्रेताओं अथवा दोनों से ही बाजार प्रथा के अनुसार दलाली प्राप्त करते हैं। दलालों को क्रेताओं एव विक्रेताओं के लिये वस्तुओं के क्रय-विक्रय करने का अधिकार सामान्यतः प्राप्त नहीं होता है। इनकी मण्डी में दुकान साधारणतया नहीं होती है।

(3) **सट्टा मध्यस्थ**—सट्टा मध्यस्थों का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ावों के अन्तर से लाभ कमाना होता है। ये मध्यस्थ कीमतों के बढ़ने की सम्भावना में वस्तुओं को क्रय करते हैं और कुछ समय उपरान्त कीमतों के बढ़ने पर वस्तुओं का विक्रय करते हैं। सट्टा मध्यस्थों में साधारणतया वस्तुओं का भावान-प्रदान नहीं होता है बल्कि लाभ अथवा हानि की राशि का ही भाग में मुणतान होता है।

(4) **परिष्करण में सलग्न मध्यस्थ**—ये मध्यस्थ वस्तुओं के रूप में परिवर्तन करते हैं। जैसे—दाल मिल या तेल मिल का स्वामी आदि। ये स्वयं वस्तुओं को क्रय करके अथवा निर्धारित मजदूरी पर वस्तुओं के रूप में परिवर्तन करते हैं।

(5) **ग्रामीण व्यापारी**—ये व्यापारी गांवों में कृषकों से खाद्यान्न क्रय करके एकत्रित खाद्यान्नों को एक साथ मण्डी तक पहुँचाते हैं और क्रय-विक्रय कीमत के अन्तर से लाभ कमाते हैं। ग्रामीण व्यापारी कृषकों को फसल उत्पादन के लिये ऋण भी देते हैं और उत्पादित फसल की मात्रा को उनके माध्यम से बेचने को विवश करते हैं।

(6) **घुमक्कड़ सौदागर**—ये मध्यस्थ गाँव-गाँव में घूमते रहते हैं और खाद्यान्न क्रय करते हैं। एकत्रित खाद्यान्नों को मण्डी में ल जाकर विक्रय करके कीमतों के अन्तर से लाभ कमाते हैं।

(7) **तौलारा**—विपणन-प्रक्रिया में ये वस्तुओं का सही तौलने का कार्य करते हैं और सेवाओं के लिये तुलार्ड प्राप्त करते हैं।

(8) **पत्तेदार/हुमाल**—ये व्यक्ति वस्तुओं का परिवहन साधनों से उतारने, चढ़ाने, गोदाम तक पहुँचाने आदि में होने का कार्य करते हैं और सेवाओं के लिये मजदूरी प्राप्त करते हैं।

(9) **अन्य कार्यकर्ता**—मुनीम, चौकीदार, सफाई करने वाले कर्मचारी आदि।

कृषकों का उत्पादन अधिशेष

फार्म पर उत्पादित खाद्यान्न एवं अन्य फसलों की सम्पूर्ण मात्रा कृषकों द्वारा विक्रय नहीं की जाती है। कृषक किसी भी वस्तु की उत्पादित मात्रा में घरेलू आवश्यकता की मात्रा रखने के बाद शेष बची हुई मात्रा को विक्रय करते हैं। कृषकों का उत्पादन-अधिशेष दो प्रकार का होता है—

(1) विक्रय (विक्री योग्य) अधिशेष (Marketable Surplus)—विक्रय अधिशेष वह मात्रा है, जिसे कृषकों द्वारा कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है। कुल उत्पादन की मात्रा में से विभिन्न आवश्यकताएँ जैसे—परिवार के उपभोग, बीज, पशुओं के लिए दाना, अमिकों को मजदूरी का वस्तु के रूप में भुगतान की मात्रा को घटाने पर जो मात्रा शेष रहती है, वह उस वस्तु की विक्रय अधिशेष की मात्रा कहलाती है। सूत्र के अनुसार विक्रय अधिशेष = उत्पादन की कुल मात्रा - विभिन्न आवश्यकताओं के लिए आवश्यक मात्रा।

अतः कृषकों के विक्रय-अधिशेष की मात्रा, परिवार के लिए उपभोग, बीज, पशुओं के लिए दाना आदि की आवश्यकता पर निर्भर करती है। उपर्युक्त कार्यों के लिए आवश्यकता के अधिक होने पर विक्रय-अधिशेष की मात्रा कम होती है तथा इनकी आवश्यकता कम होने पर विक्रय अधिशेष की मात्रा अधिक होती है। विक्रय-अधिशेष एक सैद्धान्तिक धारणा है क्योंकि कृषकों द्वारा वस्तु की बाजार में विक्रय की जाने वाली मात्रा साधारणतया इससे अधिक भवना कम होती है।

(2) विक्रीत अधिशेष (Marketed Surplus)—विक्रीत अधिशेष वस्तुओं की वह मात्रा है जो कृषकों द्वारा उपभोक्ताओं को सीधे रूप में अथवा व्यापारियों को अथवा दोनों को वास्तव में विक्रय किया जाता है। विक्रीत अधिशेष की मात्रा, उत्पादक कृषकों के स्वयं के परिवार, पशुओं के लिए दाना, बुवाई के लिए बीज, अमिकों को मजदूरी भुगतान करने के लिए वस्तु की आवश्यक मात्रा के अतिरिक्त वस्तु की प्रचलित कीमत, प्रतिस्पर्धा वाली वस्तुओं की कीमतों, कृषकों को वित्त की आवश्यकता एवं भावी कीमतों की स्थिति आदि पर निर्भर होती है। उपभोक्ताओं की दृष्टि से वस्तु की विक्रीत अधिशेष की मात्रा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि विक्रीत अधिशेष की मात्रा ही उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए घन उपलब्ध कराने में सक्षम होती है।

कृषकों की किसी भी वस्तु की विक्रीत अधिशेष की मात्रा विक्रय अधिशेष की मात्रा से अधिक, कम व उसके समतुल्य हो सकती है। कृषकों की विक्रीत अधिशेष की मात्रा विक्रय अधिशेष की मात्रा से अधिक उस अवस्था में होती है जब कृषक वित्तीय आवश्यकताओं के कारण उपलब्ध विक्रय अधिशेष की मात्रा से अधिक मात्रा में वस्तुओं का विक्रय करते हैं। इस स्थिति के अन्तर्गत कृषक, परिवार एवं

फार्म के लिए आवश्यक मात्रा से कम मात्रा में वस्तुओं को अपने पास रखते हैं तथा आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ समय उपरान्त ऋण प्राप्त करके ग्रथवा उधार में वस्तुओं को बाजार से स्वयं क्रय करते हैं। लघु कृषकों के यहाँ ऐसा मुख्यतया होता है विक्रीत अधिशेष की मात्रा विक्रेय अधिशेष की मात्रा में कम उस अवस्था में होती है जब कृषक बाजार में वस्तु की प्रचलित कीमत कम होने के कारण, वस्तु को विक्रय नहीं करके संग्रहण करते हैं। साधारणतया बड़ी जोत वाले कृषकों ग्रथवा समृद्धिवाली कृषकों के यहाँ विक्रीत अधिशेष की मात्रा विनैग अधिशेष की मात्रा से कम होती है। शीघ्रनाशी वस्तुओं में विक्रीत अधिशेष एवं विक्रेय अधिशेष की मात्रा समान होती है। विभिन्न कृषकों के यहाँ मिश्र मिश्र खाद्यान्नों की विक्रीत अधिशेष की मात्रा एवं कृषकों के जोत के आकार में घनात्मक सम्बन्ध होता है। कृषि जोत के आकार के बढ़ने के साथ-साथ कृषकों के विक्रेय-अधिशेष की मात्रा में वृद्धि होती है।

श्री एच एल चावला की अध्यक्षता में बनी उप-समिति¹⁰ की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1981-82 के संशोधित आकड़ों के अनुसार कुल उत्पादित मात्रा में से विक्रेय अधिशेष/विक्रीत अधिशेष की मात्रा धान में 42.71 प्रतिशत, गेहूँ में 52.44 प्रतिशत, ज्वार में 32.85 प्रतिशत, बाजरे में 33.29 प्रतिशत, मक्का में 27.19 प्रतिशत, चने में 40.30 प्रतिशत, अरहर में 50.83 प्रतिशत, सरसों में 92.70 प्रतिशत, कपास में 95.50 प्रतिशत एवं गन्ने में 88.00 प्रतिशत होता है। इस मात्रा का धान में 45 प्रतिशत, ज्वार में 30 प्रतिशत, बाजरे में 40 प्रतिशत, मक्का में 47 प्रतिशत, गेहूँ में 64 प्रतिशत, जौ में 61 प्रतिशत एवं चना में 48 प्रतिशत उत्पाद विक्रय हेतु कटाई के उपरान्त की प्रथम तिमाही में ही मंडी में पहुँचा जाता है। दूसरी, तीसरी एवं चौथी तिमाही में खाद्यान्नों की बहुत ही कम मात्रा विक्रय के लिए मंडी में आती है एवं उसमें कार्तकारों का भण बहुत ही कम होता है।

विभिन्न राज्यों में मक्का, बाजरा, धान, गेहूँ, भूँसफली, चना एवं सरसों की फसलों के लिए किये गए विपणन अध्ययनों के अनुसार विभिन्न जोत आकार के कृषकों के यहाँ कुल उत्पादन में विक्रेय-अधिशेष एवं विक्रीत अधिशेष की पायी गई प्रतिशत मात्रा सारणी 12.1 में प्रदर्शित की गई है।

10 Centre for monitoring Indian Economy (CMIE), Government of India, New Delhi

सारणी 12 1

विभिन्न कृषि उत्पादों का विक्रीय एवं विक्रीत अधिशेष

(कुल उत्पादन का प्रतिशत)

उत्पाद/अधिशेष	लघु जोत	मध्यम जोत	दीर्घ जोत	सभी बाजार की जोतो का औसत
(1) मक्का (राजस्थान)				
विक्रीय-अधिशेष	17 27	57 78	71 96	52 90
विक्रीत-अधिशेष	23 34	53 21	69 71	52 10
(2) बाजरा (राजस्थान)				
विक्रीय-अधिशेष	40 58	49 67	63 74	51 29
(3) घान (आन्ध्रप्रदेश)				
विक्रीय-अधिशेष	47 10	58 20	68 10	—
विक्रीत-अधिशेष	46 30	56 40	63 70	—
(4) गेहूँ (राजस्थान)				
विक्रीत अधिशेष	33 20	44 80	57 40	50 30
विक्रीय-अधिशेष	3 0	43 70	55 70	49 40
(5) मूँगफली (गुजरात)				
विक्रीत-अधिशेष	70 35	78 47	80 01	78 56
(6) चना (राजस्थान)				
विक्रीय-अधिशेष	71 10	75 70	79 70	76 6
विक्रीत अधिशेष	78 70	81 20	86.30	83 6
(7) सरसो (राजस्थान)				
विक्रीत-अधिशेष	91 88	93 29	93 89	92 88

स्रोत (i) Department of Agricultural Economics, Rajasthan Agricultural University, Udaipur Campus, Research Report

(ii) Kamalakar, M M Marketed Surplus and Price-Margin of Paddy and Groundnut in Nelloor District, Andhra Pradesh, Thesis, Andhra Pradesh Agricultural University, Hyderabad, 1973

- (iii) Acharya, S.S., Agricultural Production, Marketing and Price Policy in India, Mittal Publications Delhi, 1988, p 268
- (iv) Patel, G.N., Price Behaviour and Marketing of Groundnut in Gujarat, Ph D. Thesis, Rajasthan Agricultural University, Bikaner, 1991
- (v) Hariom, Marketing of Rapessed and Mustard in Bharatpur District of Rajasthan, M Sc Ag Thesis, Rajasthan Agricultural University, Bikaner, 1988

उपरोक्त अध्ययनों से प्राप्त परिणामों से स्पष्ट है कि कृषकों के यहाँ, औसतन गेहूँ, मक्का एवं बाजरे में 50 प्रतिशत, धान में 60 प्रतिशत, चना-एव मूँगफली में 80 प्रतिशत एवं सरसों में 93 प्रतिशत विक्रीत अधिशेष/विक्रय अधिशेष की मात्रा होती है। विक्रय अधिशेष की मात्रा खाद्यान्नों में तिलहन, रेशे वाली फसलों एवं व्यापारिक फसलों की अपेक्षा कम होती है क्योंकि कृषक खाद्यान्नों की उत्पादित मात्रा का एक बड़ा भाग अपनी घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए रख लेते हैं। विक्रीत/विक्रय अधिशेष की मात्रा एवं कृषकों की जोत के आकार में घनात्मक सम्बन्ध होता है अर्थात् जोत के आकार के बढ़ने के साथ साथ विक्रीत/विक्रय अधिशेष की मात्रा में भी वृद्धि होती है। वर्तमान में विनय अधिशेष एवं विक्रीत अधिशेष की मात्रा में भी विशेष अन्तर नहीं पाया गया।

विपणन-माध्यम

विपणन-माध्यम से तात्पर्य वस्तुओं के उत्पादन कृषकों से उपभोक्ताओं तक कार्यरत विभिन्न मध्यस्थों एवं उनके द्वारा प्रवाह की निर्देशित दिशा की सूची से है। विपणन माध्यम का ज्ञान वस्तुओं के उत्पादक कृषकों से उपभोक्ताओं तक पहुँचने में होने वाले स्वामित्व परिवर्तनों को स्पष्ट करते हैं। कुछ वस्तुएँ उत्पादक से उपभोक्ता तक सीधे रूप में पहुँचती हैं अर्थात् उनके संचालन में कोई मध्यस्थ नहीं होता है, जबकि अन्य वस्तु या उसी वस्तु के लिए दूसरी मण्डी में उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुँचाने में अनेक विपणन-मध्यस्थ सहायता करते हैं।

विपणन-मध्यस्थों की अधिकता, विपणन माध्यमों की श्रृंखला को लम्बा बना देती है, जिससे वस्तुओं की विपणन-लागत में वृद्धि होती है। वस्तु के विपणन में पाये जाने वाले विपणन-मध्यस्थों की संख्या एवं उनकी विपणन-लागत में घनात्मक सम्बन्ध होता है। विभिन्न वस्तुओं के लिए विपणन-माध्यम की श्रृंखला की लम्बाई

वस्तु की प्रकृति, विपणन की गति, विपणन स्थान एवं क्रय-विक्रय के उद्देश्य पर विचार करने से है।

उत्पादन शक्ति में बढ़ते, बाजार एवं मण्डों के अध्ययन में निम्नलिखित विपणन-नाम्यम पाए गए हैं¹¹

पहले—उत्पादक में उपभोक्ता तक निम्न विपणन-नाम्यमों के द्वारा बढ़ते का सुबोधन होता है :

- (i) उत्पादक—उपभोक्ता,
- (ii) उत्पादक—मुद्रण विक्रेता—उपभोक्ता,
- (iii) उत्पादक—बोर्ड विक्रेता—मुद्रण विक्रेता—उपभोक्ता,
- (iv) उत्पादक—सहकारी विपणन मण्डल—मुद्रण विक्रेता—उपभोक्ता,
- (v) उत्पादक—समाधानकर्ता—मुद्रण विक्रेता—उपभोक्ता,
- (vi) उत्पादक—स्थानीय विक्रेता—बोर्ड विक्रेता—मुद्रण विक्रेता—उपभोक्ता।

बादवा—बाजार के विपणन में निम्न विपणन-नाम्यम पाये गये हैं :

- (i) उत्पादक—मुद्रण विक्रेता—उपभोक्ता,
- (ii) उत्पादक—आयोजना—उपभोक्ता,
- (iii) उत्पादक—बोर्ड विक्रेता—मुद्रण विक्रेता—उपभोक्ता।

अन्तरे—मण्डों के विपणन में निम्न विपणन-नाम्यम पाये गये हैं :

- (i) उत्पादक—उपभोक्ता,
- (ii) उत्पादक—मुद्रण विक्रेता—उपभोक्ता,
- (iii) उत्पादक—सहकारी विपणन मण्डल—बोर्ड विक्रेता, सम्बन्ध—उपभोक्ता
- (iv) उत्पादक—सहकारी विपणन मण्डल—बोर्ड विक्रेता, देहली—उपभोक्ता
- (v) उत्पादक—बड़े शहर का बोर्ड विक्रेता—मुद्रण विक्रेता—उपभोक्ता,
- (vi) उत्पादक—बोर्ड विक्रेता—स्थानीय उपभोक्ता।

कृषि उत्पादकों के वैज्ञानिक विपणन के नियम

(Commandments of Scientific Marketing) :

कृषक उत्पादित उपज के विपणन में निम्न नियम अपनाकर अच्छी धारा प्राप्त कर सकते हैं :

- (1) उत्पाद की सुझाई करने के परभाव ही मण्डों में विक्रय हेतु जाना चाहिए।
- (2) वस्तु की विभिन्न किस्मों को पृथक् रूप से विक्रय हेतु जाना चाहिए। इनको मिश्रित करके नहीं जाना चाहिए।

11. Agricultural Research—A Review, Department of Agricultural Economics, S. K. N. College of Agriculture, JOBNER (Rajasthan).

- (3) कृषि उत्पादों को श्रेणीकरण करने के पश्चात् ही विक्रय करना चाहिए, इससे उन्हें उत्पाद की अच्छी कीमत प्राप्त हो सकेगी।
- (4) कृषकों को अपने उत्पाद को विक्रय करने से पूर्व मंडियों में प्रचलित कीमत ज्ञान सूचना से पूर्णतया जानकारी रखना चाहिए, जिससे वे सही मंडी एवं समय का चुनाव कर सकें।
- (5) कृषि उत्पादों को तोलकर निश्चित मात्रा के थैले या बोरियों में ही उत्पाद को मंडी में ले जाना चाहिए।
- (6) कृषकों को अपने उत्पाद को विक्रय के लिए फसल कटाई के शीघ्र उपरान्त नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि उस समय पूर्ति की अधिकता के कारण कीमतों के कम मिलने के साथ-साथ विपणन में समय भी अधिक लगता है।
- (7) कृषकों को उत्पाद के विक्रय के लिए सहकारी विपणन समितियों की सेवामें का उपयोग करना चाहिए।
- (8) कृषकों को अपना उत्पाद अपने निकटतम नियंत्रित मण्डी में ले-जाकर विक्रय करना चाहिए।

□□□

विपणन-कार्य

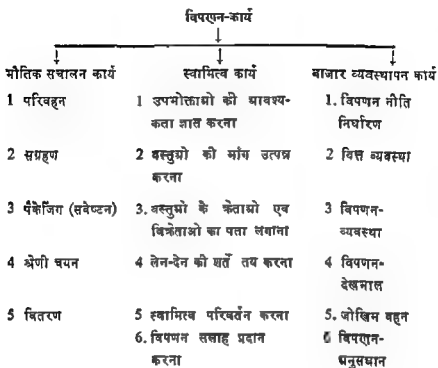
उत्पादक कृषक से अन्तिम उपभोक्ता तक वस्तुओं को पहुँचाने के लिये विभिन्न विपणन-कार्य करने होते हैं। ये विपणन-कार्य, विभिन्न विपणन संस्थाओं एवं व्यक्तियों द्वारा किये जाते हैं। प्रत्येक विपणन-कार्य को करने में लागत आती है, जिससे वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है। विपणन-कार्य अनिवार्य होते हैं। विभिन्न संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले विपणन कार्यों की संख्या में कमी एवं विपणन-कार्यों को करने वाली संस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन विपणन-कार्यों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। विपणन संस्थाओं को किये गये विपणन-कार्य के लिये लागत राशि के अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त होता है। अतः विपणन-कार्य, वस्तुओं की विपणन-विधि की प्रमुख आर्थिक-क्रिया है। कोल्स एवं उल्ल¹ के शब्दों में, विपणन-कार्यों से तात्पर्य उन प्रमुख विशेष क्रियाओं के करने से है जो विपणन-विधि को पूरा करने के लिये आवश्यक होती हैं। गुप्ता² के शब्दों में विपणन-कार्य से तात्पर्य उन कार्यों, क्रियाओं एवं सेवाओं को करने से है जिनके द्वारा प्राथमिक उत्पादक एवं अन्तिम उपभोक्ता में वस्तुओं के लेन-देन के सम्बन्ध स्थापित होते हैं।

विपणन कार्यों का वर्गीकरण :

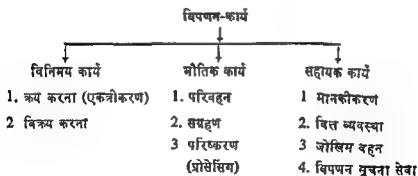
विभिन्न लेखकों ने विपणन-कार्यों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है जो अग्रलिखित प्रकार से हैं—

1. A marketing function may be defined as a major specialized activity performed in accomplishing the marketing process
—R. L. Kohls and J. N. Uhl Marketing of Agricultural Products, Macmillan Publishing Co., INC, Newyork, 1980. p. 23.
2. A marketing function is an act, operation or service by which the original producer and the final consumer are linked together.
—A. P. Gupta, Marketing of Agricultural Produce in India, Vora & Co Publishers Pvt. Ltd., Bombay, 1975, p. 5.

1 कनयर्ज, ह्यूगे एव मिचेल³ द्वारा दिया गया वर्गीकरण :



2. कोल्स एव उल्ल⁴ द्वारा दिया गया वर्गीकरण :

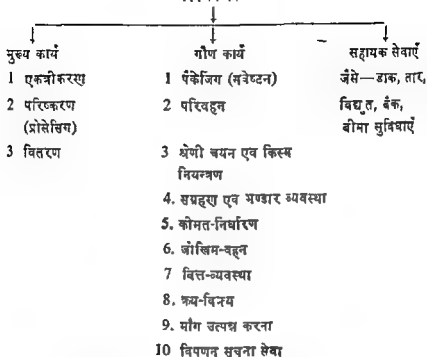


3. P. D Converse, H. W. Huegy and Mitchell; The Elements of Marketing, Prentice Hall Englewood cliffs, New Jersey, 1946, p. 56

4. R. L. Kohls and J. N. Uhl ; op. cit, p.24.

3 थॉमसन⁵ द्वारा दिया गया वर्गीकरण :

विपणन-कार्य



उपर्युक्त लेखकों द्वारा दिये गये विपणन कार्यों के वर्गीकरण में बहुत समानता है। प्रमुख विपणन कार्यों का विस्तृत विवरण नीचे दिया जा रहा है—

(1) पैकेजिंग/सवेष्टन—सवेष्टन से तात्पर्य वस्तुओं को आवरण में बन्ध करके सुरक्षित रखने से है। सवेष्टन प्रायः सभी कृषि-वस्तुओं में करना आवश्यक होता है। कृषि-वस्तुओं में सवेष्टन निम्न तीन स्तरों पर होता है—

- (1) फार्म से गोदाम अथवा बाजार में विपणन के लिये ले जाने के लिये।
- (2) गोदाम/बाजार से दूसरे बाजार में परिवहन द्वारा ले जाने के लिये।
- (3) बाजार से उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिये।

उपर्युक्त तीनों अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के आवरण पैकेजिंग के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं। पैकेजिंग के लिये आवरण, वस्तुओं की किस्म के अनुसार विभिन्न होते हैं। जैसे—दूध के लिये फार्म से गोदाम या निकटतम स्थान तक ड्रमों, एक मण्डी से दूसरी मण्डी तक ले जाने के लिये रेल या ट्रक के प्रशीतन-यानों तथा

बाजार से उपभोक्ताओं तक ले जाने के लिये काच या प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार खाद्यान्नों के परिवहन के लिये जूट की बोरीयाँ, फलों के लिये टोकरी अथवा लकड़ी के बक्से उपयोग में लाये जाते हैं। पैकेजिंग सही ढंग से ही करना चाहिये तथा पैकेजिंग लागत में कमी करने के लिये सस्ते आवरण का उपयोग करना चाहिये।

पैकेजिंग से लाभ—वस्तुओं का पैकेजिंग करने से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं—

- (1) पैकेजिंग करने से वस्तुओं का अम्बार कम हो जाता है, जिससे वस्तु की अधिक मात्रा का परिवहन साधन द्वारा परिवहन किया जा सकता है, जैसे—कपास, ऊन आदि।
- (2) पैकेजिंग करने से वस्तुओं के प्रबन्ध एवं संचालन में आसानी होती है जैसे—फल एवं अण्डों के आवरणबन्ध डिब्बों को परिवहन साधन में चढ़ाने एवं उतारने में समय कम लगता है।
- (3) पैकेजिंग से वस्तुओं में किस्म व गुण की खराबी, सफाई आदि नुकसान कम हो जाते हैं, जैसे—डिब्बों में बन्द फलों का रस, अचार, मुरब्बा आदि।
- (4) पैकेजिंग से वस्तुओं की किस्म पहचानने में आसानी रहती है, क्योंकि वस्तु का विस्तृत विवरण डिब्बे, बोरी, लकड़ों के बक्से, बोतल पर अंकित किया जा सकता है।
- (5) पैकेजिंग से वस्तुओं के विनाश करने में आसानी होती है। जैसे—अमूल मखन, हीमा मटर, इफको उर्वरक।
- (6) पैकेजिंग से मिलावट की सम्भावना कम हो जाती है।
- (7) पैकेजिंग से परिवहन, विपणन आदि विपणन कार्यों की लागत राशि में कमी होती है।
- (8) पैकेजिंग से वस्तु में स्वच्छता बनी रहती है।
- (9) पैकेजिंग करने से वस्तु की बनावट, उनमें पाये जाने वाले अवयवों का प्रतिफल एवं विक्रय की शक्ति आसानी से आवरण पर अंकित की जा सकती है। पैकेजिंग रहित वस्तुओं पर उपर्युक्त विवरण अंकित करना सम्भव नहीं होता है।

(2) परिवहन—विपणन-प्रक्रिया में दूसरा प्रमुख कार्य वस्तुओं का परिवहन है। परिवहन कार्य वस्तुओं को उत्पादन से उपभोग स्थान तक पहुँचाने में सहायता करता है, जिससे वस्तुओं में स्थान-उपयोगिता उत्पन्न होती है। वस्तुओं की कुल

विपणन-लागत में परिवहन कार्य की लागत का प्रतिशत अन्य विपणन कार्यों की लागतों की अपेक्षा साधारणतया अधिक होता है।

परिवहन साधन—वस्तुओं के परिवहन के लिए उपलब्ध परिवहन साधन तीन प्रकार के होते हैं—

- (i) पल परिवहन—पल परिवहन साधनों में मानव, पालतू पशु, बैल एवं ऊँट गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, ट्रक एवं रेल प्रमुख हैं। इनमें से कृषक सर्वाधिक साधारण की मात्रा बैलगाड़ियों से डोते हैं।
- (ii) जल परिवहन—जल परिवहन के धन्यगत वस्तुएँ नदियों, नहरों एवं समुद्र के माध्यम से परिवहन की जाती हैं।
- (iii) नम परिवहन—हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर भी देश में अति आवश्यक स्थिति होने अथवा दूसरे देशों को वस्तुएँ पहुँचाने के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं।

वस्तुओं की परिवहन लागत में विनिश्चयता—वस्तुओं की परिवहन लागत में निम्न कारणों से विनिश्चयता होती है—

1. दूरी—परिवहन की दूरी के बढ़ने पर वस्तुओं की परिवहन लागत में वृद्धि होती है।
2. परिवहन-साधन—रेल अथवा ट्रक द्वारा वस्तुओं के परिवहन पर बैल एवं ऊँट गाड़ियों की अपेक्षा परिवहन लागत कम आती है।
3. परिवहन की जाने वाली वस्तुओं का अम्बार—अम्बार 'वाली वस्तुएँ जैसे—कपास, जूट, मिर्च, जूट आदि परिवहन-साधन में स्थान अधिक घेरती हैं। अतः ऐसी वस्तुओं की प्रति इकाई भार पर परिवहन-लागत अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक होती है।
4. सड़क की स्थिति—परिवहन किये जाने वाले स्थान तक पक्की एवं मैटल सड़क होने पर वस्तुओं की परिवहन-लागत कच्चे रास्तों की अपेक्षा कम होती है।
5. वस्तुओं में सीधेनाली गुरु का होना सीधेनाली वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी पहुँचाने की आवश्यकता के कारण उनकी परिवहन-लागत अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक होती है।
6. मौसम—वर्षा के मौसम में सड़क की दुर्दशा एवं अन्य कारणों से परिवहन में अधिक समय लगने के कारण वस्तुओं की परिवहन-लागत अधिक होती है।
7. परिवहन की जाने वाली वस्तु की मात्रा—परिवहन के लिए पूरे ट्रक के लिए आवश्यक मात्रा उपलब्ध होने पर वस्तुओं की प्रति इकाई

- परिवहन-लागत कम आती है। इसके विपरीत वस्तुओं के कम मात्रा में उपलब्ध होने पर प्रति इकाई परिवहन-लागत अधिक आती है।
- 8 परिवहन साधनों में स्पर्धा—क्षेत्र में परिवहन-साधनों की बहुतायत होने की स्थिति में परिवहन के क्षेत्र में स्पर्धा उत्पन्न होती है, जिससे वस्तुओं की प्रति इकाई परिवहन-लागत में कमी होती है।
 - 9 परिवहन-साधनों का लौटते समय परिवहन के लिए वस्तुओं के उपलब्ध होने की सम्भावना—परिवहन साधनों को लौटते समय परिवहन के लिए वस्तुओं की उपलब्धि की सम्भावना होने पर परिवहन-लागत कम होती है। लौटते समय वस्तुओं की उपलब्धि की सम्भावना नहीं होने पर परिवहन-साधन को खाली लौटना होता है, जिससे वस्तु की प्रति इकाई परिवहन-लागत अधिक आती है।
 - 10 जोखिम—वस्तुओं के परिवहन में जोखिम बहन की जिम्मेदारी परिवहन-साधन के स्वामी की होने पर परिवहन-लागत अधिक होती है।
 - 11 परिवहन के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता—पशुओं तथा शीघ्रनाशी वस्तुओं के परिवहन के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है। जैसे—विशेष किस्म के डिब्बे, शीत-संग्रहण-युक्त डिब्बे। इससे परिवहन-लागत अधिक आती है।

कृषि वस्तुओं में परिवहन की प्रमुख समस्याएँ—कृषि वस्तुओं में परिवहन सम्बन्धी प्रमुख समस्याएँ निम्न हैं—

- 1 कृषिगत वस्तुओं में शीघ्रनाशी गुण के कारण उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक द्रुतगति में भेजना होता है। अतः परिवहन के क्षेत्र में प्रथम समस्या उपलब्ध वर्तमान परिवहन-साधनों की गति में वृद्धि करना है।
2. कृषिगत वस्तुओं की परिवहन काल में होने वाली किस्म की हानि की माया।
- 3 कृषिगत वस्तुओं की प्रति इकाई भार अथवा कीमत पर होने वाली परिवहन लागत की अधिकता।
- 4 अधिक दूरी तक परिवहन करने के लिए विभिन्न परिवहन-साधनों जैसे—ट्रक एवं रेल में समन्वय नहीं होना।

कृषि वस्तुओं की परिवहन लागत को कम करने के लिए सुझाव—कृषि-वस्तुओं के परिवहन में निर्मित व अन्य उत्पादित वस्तुओं की अपेक्षा परिवहन-लागत

अधिक आती है। इसका प्रमुख कारण कृषि-क्षेत्र में अम्बार वाली वस्तुओं का पाया जाना है। इसके अलावा उनमें शीघ्रनाशी होने का गुण पाये जाने से परिवहन के दौरान उनकी किस्म में हानि होती है एवं उनका प्रति इकाई भार के अनुसार मूल्य निर्मित वस्तुओं की अपेक्षा कम होता है। निम्न उपायों द्वारा कृषि-वस्तुओं की परिवहन-लागत को कम किया जा सकता है—

- 1 दूरी के अनुसार विभिन्न परिवहन-साधनों की परिवहन लागत का कानूनन निर्धारण करना।
- 2 विभिन्न कृषकों की विक्रय हेतु उपलब्ध वस्तुओं को एक साथ एकत्रित करके उनका सामूहिक रूप से परिवहन करना।
- 3 परिवहन काल में मौसम एवं अन्य कारणों से होने वाले किस्म व भार के नुकसानों को अच्छे पैकेजिंग, शीघ्र परिवहन-साधनों एवं अन्य विधियों द्वारा कम करना।
- 4 परिष्करण (प्रोसेसिंग) विधि का उपयोग करके वस्तुओं के अम्बार एवं शीघ्रनाशी होने के गुण को कम करना।
- 5 देश में सड़को एवं परिवहन-साधनों का विकास करना, जिससे परिवहन-साधनों में स्वर्द्धा उत्पन्न होंगे।
- 6 विभिन्न वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय संचालन में होने वाले नियन्त्रण के अवरोधकों को समाप्त करना, जिससे समय एवं धन की लागत में घटत होती है।

(3) श्रेणीबन्धन (श्रेणीकरण), मानकीकरण एवं किस्म नियन्त्रण :

विपणन-प्रक्रिया में तीसरा प्रमुख विपणन-कार्य वस्तुओं के श्रेणीबन्धन मानकीकरण एवं किस्म नियन्त्रण का है। वस्तुओं के श्रेणीबन्धन से तात्पर्य वस्तुओं के विभिन्न गुणों-वजन, आकार, रंग, स्वाद, सुगन्ध, बनावट, पकावट, कोमलता, रेशे की लम्बाई आदि के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करने से होता है। इसके लिए विभिन्न वस्तुओं में भिन्न-भिन्न गुणों को आधार माना जाता है। श्रेणियों में विभक्त करने के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले गुणों को श्रेणी-निर्देश (Grade specification) कहते हैं, जैसे—मण्डों के लिए भार, कपास व ऊन के लिए रेशे की लम्बाई, सन्तरो के लिए आकार आदि। विभिन्न वस्तुओं के लिए निर्धारित श्रेणी-निर्देशों को सभी स्थानों एवं समयों में समान करने की विधि को मानकीकरण कहते हैं। वस्तुओं के मानकीकरण करने से सभी व्यक्ति वस्तु की श्रेणी का समान अर्थ लगाते हैं, जिससे वस्तुओं के श्रेणीबन्धन में विभिन्न स्थानों पर पायी जाने वाली विभिन्नता समाप्त हो जाती है।

श्रेणीचयन एवं मानकीकरण से लाभ—वस्तुओं को श्रेणीचयन एवं मानकीकरण करके विक्रय करने से उत्पादको, उपभोक्ताओं एवं विपणन मध्यस्थों को निम्न लाभ प्राप्त होते हैं—

- (1) वस्तुओं को श्रेणीचयन करके विक्रय करने से उत्पादक कृषको को उत्पाद के विक्रय से अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि अच्छी किस्म के उत्पाद के लिए उपभोक्ता अधिक कीमत देने को तैयार होते हैं।
- (2) विभिन्न भाग वाले उपभोक्ता विभिन्न श्रेणी की वस्तुओं की मांग करते हैं। वस्तुओं के श्रेणीचयन द्वारा सभी उपभोक्ता-वर्ग की आवश्यकताओं को सुगमता में पूरा किया जा सकता है।
- (3) वस्तुओं में श्रेणीचयन-विधि अपनाने से विक्रेता को पूरे माल का बाजार में ढेर एवं क्रेताओं को नमूना दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। वस्तुओं का क्रय-विक्रय श्रेणी के आधार पर सीधे रूप से होता है, जिससे वस्तुओं की प्रति इकाई विपणन लागत में कमी होती है।
- (4) वस्तुओं के श्रेणीचयन से उत्पादको को माल की विक्री में कुल लाभ की राशि अधिक प्राप्त होती है। लाभ की अधिकता से कृषको को अच्छी किस्म की वस्तुओं के उत्पादन की प्रेरणा मिलती है।
- (5) श्रेणीचयन करने से वस्तुओं की किस्म में सुधार होता है क्योंकि श्रेणीचयन विधि में खराब किस्म के माल को पृथक् कर दिया जाता है। जैसे-दाग लगे हुए फल, टूटे हुए घण्डे आदि।
- (6) उत्पादको, उपभोक्ताओं तथा व्यापारियों के मध्य नमूने के अनुसार वस्तुओं के नहीं होने से उत्पन्न होने वाले झगड़े, वस्तुओं में श्रेणीचयन विधि अपनाने पर उत्पन्न नहीं होते हैं।
- (7) श्रेणीचयन-विधि को अपनाने से विभिन्न किस्म की वस्तुओं की कीमत-सम्बन्धी सूचना के प्रसारण में आसानी होती है।
- (8) श्रेणीकृत वस्तुओं को भण्डार-गृह में संग्रह करके उस माल के आधार पर उचित राशि में ऋण प्राप्त करने में आसानी होती है। भण्डार-गृह-मैनेजर वस्तु की निर्धारित किस्म भण्डार गृह रसीद में अंकित कर देते हैं, जिससे वस्तु की सही कीमत आंकी जा सकती है।
- (9) श्रेणीचयन एवं मानकीकरण प्रक्रिया, कृषको एवं उपभोक्ताओं में वस्तुओं की उचित श्रेणी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करती है।
- (10) वस्तुओं को श्रेणीकृत करने से विभिन्न कृषका द्वारा लाए गए खाद्यान्नों को विभिन्न श्रेणियों के अनुसार मिश्रित किया जा सकता है, जिससे संग्रहण एवं विक्रय में आसानी रहती है।

श्रेणीचयन के प्रकार—श्रेणीचयन दो प्रकार का होता है •

1 अधिदेश श्रेणीचयन—इस विधि के अन्तर्गत वस्तुओं का श्रेणीचयन करने में इच्छुक व्यक्ति को भारत सरकार के कृषि विपणन-सलाहकार द्वारा निर्धारित श्रेणी निर्देश के अनुसार वस्तु को श्रेणीकृत करना होता है। वस्तुओं को विभिन्न श्रेणियों में इच्छानुसार विभक्त करने की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नहीं होती है। श्रेणीचयन करने वाली संस्था को भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा पारित नियमों एवं उपनियमों का पालन करना अनिवार्य होता है।

2 अनुज्ञात या ऐच्छिक श्रेणीचयन—श्रेणीचयन की इस विधि के अन्तर्गत कृषकों, व्यापारियों एवं श्रेणीचयन करने के अन्य इच्छुक व्यक्तियों को इच्छानुसार वस्तुओं को श्रेणियों में विभक्त करने की स्वतन्त्रता होती है। अतः विभिन्न संस्थाएँ वस्तुओं को भिन्न-भिन्न प्रकार से श्रेणियों में वर्गीकृत करती हैं।

देश में कृषि-वस्तुओं का श्रेणीचयन वर्तमान में निम्न उद्देश्यों के लिये किया जाता है :

(1) निर्यात के लिए—वस्तुओं के निर्यात की मात्रा में निरन्तर वृद्धि करने के लिए निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के गुणों में समता बनाये रखना आवश्यक है। अतः देश से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को भारतीय कृषि विपणन सलाहकार द्वारा निर्धारित श्रेणी निर्देशों के अनुसार श्रेणीचयन करना अनिवार्य है। श्रेणीचयन के बिना वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण नियेध होता है। देश में निर्यात के लिये श्रेणीचयन सर्वप्रथम पटसन के लिए 1942 में शुरू किया गया था। वर्ष 1945 में कपास, 1954 में बाल, 1955 में ऊन, 1956 में नीम्बू, घासतेल तथा 1957 में चन्दन तेल के लिए श्रेणीकरण शुरू किया गया। वर्तमान में तम्बाकू, ऊन, बकरी के बाल, काली भिच, तेन्दू की पत्तियाँ, अदरक, चन्दन तेल, नीम्बू, घासतेल, इलायची, काजू, अखरोट, पटसन, आम के लिए निर्यात से पूर्व श्रेणीचयन करना आवश्यक है। निर्यात हेतु निर्धारित श्रेणियों में वर्गीकृत की गई वस्तुओं का विभिन्न स्थातों, जैसे—निर्मित किये जाने वाले स्थान, बन्दरगाह आदि स्थानों पर निरीक्षण किया जाता है, जिससे व्यापारी वर्ग निर्धारित श्रेणी से न्यूनतम स्तर की वस्तुओं को निर्यात नहीं कर सकें। न्यूनतम स्तर की वस्तुओं के निर्यात से भारतीय माल की साख में गिरावट आती है।

(2) आन्तरिक व्यापार एवं उपभोग के लिए—इसके अन्तर्गत भी कृषि वस्तुओं का श्रेणीचयन भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार द्वारा निर्धारित गुणों के आधार पर किया जाता है। आन्तरिक व्यापार एवं उपभोग के लिये निर्धारित श्रेणीचयन के आधार निर्यात के स्तर से भिन्न होते हैं। भारत में आन्तरिक व्यापार एवं उपभोग के लिये सर्वप्रथम घी में 1938 में श्रेणीचयन शुरू किया गया

था। उसके पश्चात् खाद्य तेलो में 1939, मक्खन के लिए 1941, गुड़, अण्डे, सन्तरे एवं मौसमी फल के लिए 1949, आलू में 1950 एवं चावल में 1954 से श्रेणी-चयन का कार्य शुरू किया गया। वर्तमान में देश में आन्तरिक व्यापार एवं उपभोग के लिए श्रेणीचयन की सुविधा अनेक वस्तुओं के लिए उपलब्ध है, जिनमें से प्रमुख कपास, ऊन, घी, मक्खन, चावल, गुड़, अण्डे, गेहूँ का आटा, सुपारी, आलू, खाद्य तेल, पिसे हुए मसाले, शहद, आम, सेब, सन्तरे, अमूर व इलायची हैं।

देश के उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं में श्रेणीचयन अपनाने में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सरकार द्वारा देश की अनेक मण्डियों में श्रेणीचयन-सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इकाइयाँ स्थापित की जा चुकी हैं। कृषि-वस्तुओं के श्रेणी-चयन के लिए भारत सरकार ने सर्वप्रथम कृषि-उपज (श्रेणीचयन एवं विपणन) अधिनियम, 1937 [The Agriculture Produce (Grading and Marketing) Act, 1937] पारित किया। शुरू में 19 कृषि वस्तुओं के श्रेणीचयन के लिए श्रेणियाँ निर्धारित की गई थी। वर्ष 1943 में उपर्युक्त अधि-यम में संशोधन किया गया, जिसने अन्य कृषि वस्तुएँ भी इसमें सम्मिलित की जा सकें। वर्तमान में 142 कृषि वस्तुओं के श्रेणीचयन के लिए श्रेणी निर्देश बनाये जा चुके हैं।

य-वस्तुओं के श्रेणीचयन के लिए प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की विधि :

कृषि-वस्तुओं के श्रेणीचयन के इच्छुक व्यक्ति को सर्वप्रथम श्रेणीचयन की जाने वाली वस्तु, स्थान एवं वस्तु की मात्रा का विवरण देते हुए प्रार्थना-पत्र कृषि-विपणन सलाहकार, भारत सरकार, फरीदाबाद, हरियाणा को भेजना होता है। कृषि-विपणन सलाहकार, प्रार्थना-पत्र को सम्बन्धित राज्य के कृषि विपणन-अधिकारी के पास जाँच एवं सिफारिश के लिए भिजवाता है। राज्य-कृषि विपणन-अधिकारी प्रार्थी के स्थान का निरीक्षण करता है और दी गई सूचनाओं की जाँच करता है। राज्य कृषि विपणन-अधिकारी अपनी सिफारिशों सहित उक्त प्रार्थना पत्र को कृषि-विपणन-सलाहकार, भारत सरकार को भिजवाता है। कृषि-विपणन सलाहकार प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी को श्रेणीचयन करने की स्वीकृति का प्रमाण-पत्र प्रदान करता है। प्रमाण-पत्र अहस्तान्तर्य होता है। प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रार्थी श्रेणीचयन का कार्य शुरू कर सकता है।

भारत सरकार के कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के अनुसार श्रेणी-कृत वस्तुओं के बक्खो, टोकरियों, टीन अथवा ड्रमों पर एममार्क (ACMARK) लेबल अंकित किया जाता है। एममार्क लेबल के रंग विशिष्ट श्रेणी की वस्तुओं के लिए सफेद, 'ए' श्रेणी की वस्तुओं के लिए लाल, 'बी' श्रेणी के लिए नीला, 'सी' श्रेणी के लिए पीला एवं 'डी' श्रेणी के लिए हरे रंग का एममार्क लेबल अंकित किया जाता है। कृषि वस्तुओं पर लगाये जाने वाले ये एममार्क लेबल भारत सरकार

द्वारा विशेष कामज पर अंकित किये जाते हैं। प्रत्येक एगमार्क लेबल पर क्रमांक अंकित होता है।

विभिन्न कृषि वस्तुओं के श्रेणीचयन के लिए श्रेणी निर्देश :

भारत सरकार के कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय ने अब तक 142 प्रमुख कृषि एवं सम्बन्धित वस्तुओं के श्रेणीचयन के लिए श्रेणी निर्देश निर्धारित किये हैं। कुछ कृषि-वस्तुओं जैसे—अण्डे, सन्तरे, आम आदि के श्रेणीचयन के लिए निर्धारित श्रेणी-निर्देश यहाँ दिये गये हैं।⁶ निर्यात के लिए 41 वस्तुओं के श्रेणीचयन के लिए श्रेणी-निर्देश निर्धारित किये गये हैं।

(अ) अण्डों का श्रेणीचयन

श्रेणी	एगमार्क लेबल का रंग	मुर्गी के अण्डों का न्यूनतम भार (ग्राम)	अन्य शर्तें
विशिष्ट	सफ़ेद	2.00	1 अण्डे किसी भी विधि द्वारा परिरक्षा किये हुए नहीं होने चाहिए।
'ए'	लाल	1.75	2 अण्डे चम्बे एवं राग-रहित होने चाहिए।
'बी'	नीला	1.50	3. अण्डों का योक्त मध्य में होता चाहिए।
'सी'	पीला	1.25	4 अण्डे ठोस होने चाहिए। 5. अण्डे पारदर्शी होने चाहिए। 6. अण्डों में हवा का घेरा $\frac{3}{8}$ " से कम होना चाहिए।

(ब) सन्तरो का श्रेणीचयन

श्रेणी	एगमार्क लेबल का रंग	न्यूनतम आकार (इन्चों में)	अन्य शर्तें
विशिष्ट	सफेद	3 50	1 सन्तरे अच्छे पके हुए होने चाहिए जिससे वे परिवहन में खराब न होने पाएँ।
I	लाल	3 00	2 सन्तरो का रंग किस्म के अनुसार होना चाहिए, लेकिन हरा रंग नहीं होना चाहिए।
II	नीला	2 75	3 सन्तरा के ऊपर भुरियाँ पड़ी हुई नहीं होनी चाहिए।
III	पीला	2 50	4 सन्तरे कटाव, कीड़े व बीमारी लगे हुए नहीं होने चाहिए।
IV	हरा	2 25	5 सन्तरो के वर्गीकरण में 10 प्रतिशत तक उस श्रेणी से नीचे की श्रेणी के सन्तरे होने की छूट होती है।

(स) एलफन्सी किस्म के आम का श्रेणीचयन (निर्यात के लिए)

श्रेणी	भारत में		अन्य विशेषताएँ
	न्यूनतम	अधिकतम	
I	280	338	1 आम ठोस तथा कटाव, घब्बे एवं दाग-रहित होने चाहिए।
II	222	280	2. आम की बनावट एवं आकार किस्म के अनुसार होना चाहिए।
III	163	222	3 आम हरे रंग के होने चाहिए। उनमें पीला रंग नहीं होना चाहिए।

निरीक्षण—श्रेणीचयन का कार्य मुख्यतया उत्पादकों एवं व्यापारियों के द्वारा किया जाता है। श्रेणीचयन करने वालों द्वारा श्रेणीचयन में की जाने वाली वेईमानी को रोकने के लिए वस्तुओं का विभिन्न समय एवं स्थानों पर निरीक्षण करना अनिवार्य होता है। निरीक्षक का कार्य विपणन-विभाग के निरीक्षकों द्वारा किया जाता है। निरीक्षक वस्तु की जाँच करते हैं। वे वस्तुओं का निरीक्षण सारणतया निम्न समय में करते हैं—

- (i) परिष्करण या प्रोसेसिंग के समय।
- (ii) संग्रहण-काल में श्रेणीचयनकर्त्ता के गोदाम अथवा थोक व खुदरा व्यापारियों के यहाँ पर।
- (iii) निर्यात से पूर्व बन्दरगाह पर।

वस्तुओं को निर्धारित श्रेणियों के अनुसार नहीं पाये जाने की अवस्था में निरीक्षक, श्रेणीचयनकर्त्ता का श्रेणीचयन करने का प्रमाण-पत्र रद्द कर देने की सिफारिश कृषि-विपणन सलाहकार को कर देता है। प्रमाण-पत्र रद्द होने पर श्रेणीचयनकर्त्ता को शेष एगमार्क लेबल एवं श्रेणीचयन सम्बन्धित सामान, कृषि-विपणन सलाहकार को वापिस लौटाना होता है। निरीक्षक वस्तु की किस्म में सन्देह होने पर वस्तुओं के नमूने जाँच के लिए केन्द्रीय प्रयोगशाला में भिजवाता है। केन्द्रीय प्रयोगशाला से प्राप्त जाँच का परिणाम निरीक्षक एवं श्रेणीचयन करने वाले व्यापारी/उत्पादक को मान्य होता है।

भारत में श्रेणीचयन की प्रगति

भारत में श्रेणी चयन तीन स्तर पर किया जाता है। कृषि वस्तुओं के विदेशों में निर्यात हेतु अधिशेष श्रेणी चयन, देश में ही व्यापार हेतु ऐच्छिक श्रेणी चयन एवं उत्पादक स्तर पर मंडी में विपणन हेतु किया जाता है। विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए उपरोक्त तीनों ही प्रकार के श्रेणीकृत वस्तुओं के व्यापार राशि में वृद्धि हुई है। वर्ष 1938 में जहाँ 0.15 करोड़ रुपये मूल्य की कृषि वस्तुओं का श्रेणी चयन होता था। वह बढ़कर वर्ष 1960-61 में 69.38 करोड़ रुपये, वर्ष 1970-71 में 436.80 करोड़ रुपये, वर्ष 1980-81 में 1248.61 करोड़ रुपये एवं वर्ष 1989-90 में 4190.26 करोड़ रुपये हो गई। मार्च 1990 में देश में 1040 श्रेणी चयन की इकाईयाँ एवं 566 श्रेणी चयन प्रयोगशालाएँ कार्यरत थी। श्रेणीचयन एवं मानकीकरण के क्षेत्र में श्रेणीचयनकर्त्ताओं को आने वाली परेशानियाँ

कृषि-वस्तुओं के श्रेणीचयन में निम्नलिखित परेशानियाँ होने से उत्पादक कृषक, व्यापारी एवं परिष्करण में लगे व्यक्ति (परिष्कर्त्ता) वस्तुओं के श्रेणीचयन करने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं और वस्तुओं को श्रेणियों में विभक्त नहीं करते हैं—

- (1) उत्पादित कृषि-वस्तुएँ गुणों में समान नहीं होती हैं। उनके गुणों में बहुत विभिन्नता होती है, जिससे श्रेणीचयन-विधि में अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- (2) विभिन्न उपभोक्ता कृषि-वस्तुओं में विभिन्न गुण चाहते हैं। कुछ उपभोक्ता उनमें पकने के गुण देखते हैं जबकि दूसरे स्वाद, पौष्टिकता अथवा बाहरी बनावट एवं सवेष्टन देखते हैं। अतः सभी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को एक श्रेणी में निर्धारित करने का कार्य कठिन होता है।
- (3) विभिन्न कृषि-वस्तुओं के श्रेणीचयन के लिए विभिन्न आधार प्रयुक्त किये जाते हैं जैसे—रासायनिक जाँच, भौतिक गुण, संवेदक (Sensory) आदि। संवेदक गुणों के आधार पर श्रेणीचयन में वस्तुओं के गुणों में बहुत विभिन्नता पायी जाती है, जिससे श्रेणीचयन के निर्धारित उद्देश्य प्राप्त नहीं होते हैं।
- (4) कृषि-वस्तुएँ विनाशशील किस्म की होती हैं। अतः श्रेणीचयन करने के उपरान्त उनके विरुद्ध-समय में उनके गुणों में ह्रास होता है, जिससे वस्तुओं में विपणन के समय एवं श्रेणीचयन समय के गुणों में समानता नहीं पायी जाती है।
- (5) श्रेणीचयन के लिए निर्धारित न्यूनतम व उच्चतम स्तर में बहुत भ्रंतर होना है, जिसके कारण एक ही श्रेणी की वस्तुओं के गुणों में भ्रंतर पाया जाता है।
- (6) वस्तुओं की श्रेणी एवं कीमत में उचित सम्बन्ध का अभाव होना है, जिसके कारण श्रेणीचयन-वर्ताओं को वस्तुओं की मछली श्रेणी से अधिक कीमत प्राप्त नहीं होती है।

उपभोक्ताओं द्वारा श्रेणीचयन की गई वस्तुओं को क्य में प्राथमिकता नहीं देता :

उपभोक्ताओं को तब करते समय श्रेणीचयन की गई वस्तुओं को निम्न कारणों को प्राथमिकता नहीं देते हैं—

- (1) निर्धारित श्रेणियों को उपभोक्ता समझ नहीं पाते हैं।
- (2) एगमार्क लेबल वस्तु पर अंकित नहीं करके, वस्तु के आवरण पर अंकित किया जाता है जिससे उपभोक्ता को वस्तु के निर्धारित श्रेणी के अनुसार होने का विश्वास नहीं होता है।
- (3) उपभोग की वस्तुओं पर 'सी' अथवा 'डी' श्रेणी अंकित होने से उपभोक्ताओं में यह धारणा बन जाती है कि वस्तु उपभोग के लिए उचित नहीं है।

- (4) कृषि वस्तुओं में विनाशशीलता के गुण होने से, वस्तुएँ जाँच के समय निर्धारित स्तर के अनुसार नहीं पाई जाती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को श्रेणीचयन में पूर्ण विश्वास उत्पन्न नहीं होता है।
- (5) बहुत-सी कृषि-वस्तुओं पर जिनका सबेष्टन-रहित ही विन्य होता है, का विवरण देना सम्भव नहीं होता, जैसे—मास।
- (6) साधारणतया वस्तुओं के श्रेणीचयन के लिए श्रेणी-निर्देश थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के उपयोग के लिए ही निर्धारित किये जाते हैं। ये श्रेणी-निर्देश उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार ही बनाये जाते हैं।

राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा श्रेणीचयन के लिये दिये गये सुझाव

वर्तमान में देश की लगभग 13 प्रतिशत नियन्त्रित मण्डियों में ही उत्पादक स्तर पर श्रेणीकरण की सुविधाएँ उपलब्ध हैं एवं शेष नियन्त्रित मण्डियों में माल का विन्य श्रेणीकरण के बिना ही होना है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने स्वीकार किया कि सभी प्राथमिक स्तर की मण्डियों में श्रेणीकरण एवं मानकीकरण की सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए। श्रेणीकरण की विधि सरल होनी चाहिए। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में श्रेणीकरण के विकास के लिए निम्न सुझाव दिए हैं।⁷

- (1) श्रेणीकरण एवं मानकीकरण वस्तुओं के ऋय-विन्य में अनिवार्य रूप में कृषक स्तर, आन्तरिक व्यापार, अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं निर्यात के लिए होना चाहिए। श्रेणीकरण के अनुसार वर्गीकृत वस्तुओं के नमूने मण्डी में प्रदर्शित करने चाहिए।
- (2) श्रेणीकरण एवं मानकीकरण सभी कृषि-वस्तुओं में लागू किये जाने चाहिए।
- (3) श्रेणीकरण से सम्बन्धित विभिन्न विभागों, जैसे—कृषि विपणन निदेशालय, भारतीय मानक सस्था, स्वास्थ्य विभाग, भारतीय खाद्य निगम मूहकारी विपणन समितियाँ एवं राज्य मण्डार व्यवस्था निगम द्वारा वस्तुओं के श्रेणीकरण में एक ही आधार अपनाया जाना चाहिए। वर्तमान में प्रत्येक सस्था विभिन्न आधार के अनुसार श्रेणीकरण करती है।
- (4) श्रेणीकरण व्यवस्था के लिए श्रेणीकर्ता अपने कार्य में दक्ष होने चाहिये तथा वे विपणन निदेशालय या राज्य विपणन विभाग के कर्मचारी होने चाहिए।

⁷ Report of the National Commission on Agriculture, Ministry of Agriculture and Irrigation, Government of India, Vol XII, 1976, p p. 135-36.

(5) श्रेणीकरण करने की जिम्मेदारी अन्तरज्तीय व्यापार एवं निर्यात के लिए विपणन निदेशालय तथा उत्पादकता स्तर एवं आन्तरिक व्यापार के लिए राज्य विपणन निदेशालय की होनी चाहिए ।

(4) सग्रहण एवं भण्डार व्यवस्था—विपणन-प्रक्रिया का चतुर्थ कार्य वस्तुओं के सग्रहण एवं भण्डार की व्यवस्था करना है । सग्रहण कार्य का मुख्य उद्देश्य अधिशेष पूर्ति की मात्रा को उत्पादन काल से उपभोग काल तक सुरक्षित रखना होता है । सग्रहण कार्य द्वारा वस्तुओं में समय उपयोगिता उत्पन्न होती है । सग्रहण-कार्य विपणन-व्यवस्था को वर्ष भर कार्यरत बनाये रखता है एवं बाजार-विकास में सहायक होता है । विगिष्ट एवं वैज्ञानिक ढंग से सग्रहण करने की क्रिया को भण्डार व्यवस्था कहते हैं ।

कृषि-वस्तुओं के सग्रहण की आवश्यकता—निम्न कारणों से कृषि-वस्तुओं का सग्रहण करना आवश्यक है—

(1) कृषि वस्तुओं का उत्पादन मौसम विशेष में होता है लेकिन उनकी मांग वर्ष भर निरन्तर रहती है । अतः उपभोक्ताओं का निरन्तर उत्पन्न होने वाली मांग की पूर्ति के लिए वस्तुओं का सग्रहण करना आवश्यक होता है, जैसे—आलू, सादाभा, दालें, तिलहन ।

(2) कुछ कृषि-वस्तुओं की मांग का विशेष मौसम अथवा समय होता है । मौसम विशेष की अत्यधिक मांग की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उत्पादन वर्ष भर निरन्तर करना होता है । अतः उत्पादन समय से उपभोग समय तक वस्तुओं का सग्रहण करना होता है, जैसे—ऊन ।

(3) वस्तुओं की किस्म में सुधार करने के लिए सग्रहण करना आवश्यक होता है, जैसे—पनीर, चावल, तम्बाकू, अचार ।

(4) कच्चे फलों को पकाने एवं उपभोग योग्य बनाने के लिए सग्रहण करना आवश्यक होता है, जैसे—केले, आम ।

(5) विपणन कार्यों जैसे—परिवहन, सवेट्टन परिष्करण (प्रोससिंग), तुलाई, क्रय-विक्रय यादि कार्य करने के लिए कृषि वस्तुओं का सग्रहण करना होता है, क्योंकि प्रत्येक विपणन कार्य को करने में समय लगता है ।

(6) उत्पादन मौसम में कृषि-वस्तुओं की अधिक पूर्ति के कारण कीमतों की गिरावट से होने वाली हानि को कम करने के लिए भी सग्रहण करना आवश्यक है । उत्पादन मौसम के कुछ समय उपरान्त विनय करने से उत्पादक कृषकों को उत्पाद की अधिक कीमत प्राप्त होती है ।

(7) वर्तमान में वस्तुओं का उत्पादन अधिक में उत्पन्न होने वाली मांग के आधार पर किया जाता है। अतः उपभोक्ताओं की मांग उत्पन्न होने के फलतः उन वस्तुओं का संग्रहण करना आवश्यक है।

(8) वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति में समन्वय स्थापित करने के लिए भी संग्रहण करना आवश्यक है।

भण्डार-गृह-व्यवस्था—भण्डार-गृह-व्यवस्था से तात्पर्य वस्तुओं के संग्रहण की विशेष व्यवस्था करने से है। कृषि-विपणन के सन्दर्भ में भण्डार-गृह-व्यवस्था से तात्पर्य कृषकों के उत्पाद को सुरक्षित रूप से संग्रहण करना एवं संग्रहीत माल की प्रतिभूति के आधार पर ऋण-सेवा उपलब्ध कराना है, जिससे कृषकों को बाजारों से दूर रहने की शक्ति उत्पन्न हो सके। वर्तमान में दृष्ट दानाभाज के कारण फसल की कटाई के पुराने पक्काई विषय के लिए बाजारों में लाते हैं जिससे उन्हें विनीत उत्पाद की उचित कीमत प्राप्त नहीं होती है। भण्डार-गृह-व्यवस्था से कृषकों में उत्पाद का सीधे विनिमय करने की प्रथा समाप्त होती है और कृषकों को अधिक लाभ प्राप्त होता है।

कृषि रॉयल कमीशन 1928, केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति 1930 एवं रिजर्व बैंक ने वर्ष 1944 में भण्डार-गृहों की आवश्यकता अनुभव करते हुए, देश में दलकों बनाने के सुझाव दिए, लेकिन इनके निष्पत्ति के ये प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं हो सके। ग्रामीण साहस-संरक्षण समिति ने भी वर्ष 1954 में अपने प्रतिवेदन में कृषि-साहस की एकीकृत योजना (Integrated Scheme of Rural Credit) के अन्तर्गत भी भण्डार गृह-निगम की स्थापना की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार ने देश में भण्डार-गृहों की स्थापना एवं संचालन के लिए जून, 1956 में कृषि उपज (विकास एवं भण्डार व्यवस्था) निगम अधिनियम [The Agricultural Produce (Development and Warehousing) Corporation Act, 1956], राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भण्डार गृह बोर्ड (National Co-operative Development and Warehousing Board), केन्द्रीय भण्डार-गृह-निगम एवं राज्य भण्डार-गृह-निगम स्थापित करने के लिए पारित किया।

उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भण्डार-गृह बोर्ड की स्थापना 1 मितम्बर, 1956, केन्द्रीय भण्डार-गृह-निगम की स्थापना 2 मार्च, 1957 तथा बिहार राज्य में प्रथम राज्य भण्डार-गृह-निगम की स्थापना 1956-57 में की गई। 1969-70 तक सभी राज्यों में भण्डार गृह-निगम स्थापित किये जा चुके थे। वर्ष 1962 में उपरोक्त अधिनियम को भण्डार-व्यवस्था निगम अधिनियम, 1962 (The Warehousing Corporation Act, 1962) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। मार्च, 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भण्डार-गृह बोर्ड को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम में परिवर्तित कर दिया गया।

इन मण्डार-गृहों में सभी प्रकार के खाद्यान्न, तिलहन, कपास, चीनी, उर्वरक आदि वस्तुओं के संग्रहण करने का प्रावधान होता है। मण्डार-गृहों में संग्रहण सेवा के लिए विभिन्न वस्तुओं के लिए पृथक् दर से प्रतिमाह द्रव्यवा प्रति सप्ताह की दर से शुल्क देय होता है। मण्डार-व्यवस्था-निगम अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति, संस्था, कम्पनी को मण्डार-गृह स्थापित करने के लिए लाइसेन्स लेना अनिवार्य होता है। लाइसेन्स प्राप्त होने के पश्चात् ही मण्डार-गृह के स्वामी, मण्डारण के लिए वस्तुओं को ले सकते हैं। सरकार मण्डार गृह के लिए लाइसेन्स प्रदान करने के पूर्व निम्न बातों की जाँच करती है—

- (i) क्या निर्मित मण्डार-गृह वस्तुओं के संग्रहण के लिए उचित है ?
- (ii) क्या मण्डार-गृह स्वामी की वित्तीय स्थिति ठीक है ?
- (iii) क्या मण्डार-गृह स्थापित करने की फीस सरकार को जमा करा दी गई है ?

केन्द्रीय मण्डार-गृह-निगम—केन्द्रीय मण्डार-गृह-निगम 20 करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी से स्थापित किया गया है। केन्द्रीय मण्डार-गृह-निगम के प्रमुख कार्य निम्न हैं—

- (i) विभिन्न स्थानों, जैसे—बन्दरगाह, रेन्व स्टेसन तथा बड़े शहरों में मण्डार-गृहों का निर्माण करना।
- (ii) कृषि-वस्तुओं के संग्रहण के लिए स्थापित विभिन्न मण्डार-गृहों का संचालन करना।
- (iii) राज्य मण्डार गृह नियमों के शेरर त्रय करना।
- (iv) सरकार के लिए कृषि वस्तुओं के संग्रहण, विपणन एवं क्रय-विक्रय के लिए एजेंट का कार्य करना।

राज्य मण्डार-गृह-निगम—ये केन्द्रीय मण्डार गृह-निगम की सहयोगी संस्थाएँ हैं। वर्तमान में 16 राज्यों में मण्डार गृह-निगम स्थापित हो चुके हैं। राज्य मण्डार-गृह-निगमों की अधिकृत पूँजी 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होती है। अधिकृत पूँजी में से 50 प्रतिशत पूँजी के शेरर केन्द्रीय-मण्डार-गृह-निगम त्रय करता है। ये मण्डार-गृह-निगम राज्यों में मण्डारण के लिए गोदामों का निर्माण करते हैं एवं मण्डारण सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं।

मण्डार-गृह निगम खाद्यान्नों को संग्रहण करने के पूर्व अच्छी, उचित एवं शीतल श्रेणियों में विभक्त करते हैं। शीतल श्रेणी से नीचे की श्रेणी की वस्तुओं का मण्डार-गृहों में संग्रहण नहीं किया जाता है। विभिन्न व्यक्तियों की वस्तुओं को पृथक् संग्रहीत किया जाता है। वस्तुओं का संग्रहण करने पर मण्डार-गृह से प्राप्त रसीद को राष्ट्रीयकृत बैंक में गिरवी रखकर ऋण प्राप्त किया जा सकता है।

मण्डार गृहों के प्रबन्ध के लिए प्रशिक्षित व प्राविधिक व्यक्ति रखे जाते हैं। प्रत्येक मण्डार में प्रबन्धक के अतिरिक्त एक प्राविधिक सहायक भी होता है जिसका कार्य खाद्यान्नों की बीमारियों एवं कीड़ों से रक्षा करना होता है। मण्डार-गृहों को कुशलतापूर्वक चलाने में सहायता देने के लिए प्रत्येक मण्डार गृह के लिए सलाहकार समिति होती है, जिसमें विभिन्न अभिकरणा, जैसे—बैंक, सहकारी समितियों, व्यापारियों, कृषक एवं सरकार के प्रतिनिधि होते हैं।

मण्डार-गृह निर्माण के उद्देश्य—निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मण्डार-गृह निर्मित किये जाते हैं—

- (1) कृषकों, व्यापारियों, उपभोक्ताओं एवं अन्य व्यक्तियों को वस्तुओं के संग्रहण की सुविधा उपलब्ध कराना।
- (2) खाद्यान्नों की पूर्ति की अधिकता एवं अन्य कारणों से कीमतों में होने वाली गिरावट को कम करना।
- (3) आग, चोरी एवं अन्य कारणों से होने वाले नुकसानों से संग्रहण-कर्ता की रक्षा करना।
- (4) वैज्ञानिक ढंग से वस्तुओं का संग्रहण करना, जिससे संग्रहण काल में वस्तुओं का गुण एवं मात्रा नष्ट नहीं होने पाएँ।
- (5) वस्तुओं के संग्रहण कर्ताओं को जमा उत्पाद की कीमत का 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में बैंकों से उपलब्ध कराना।

मण्डार गृहों का वर्गीकरण—मण्डार-गृहों को निम्न दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है—

- 1 सगृहीत की जाने वाली वस्तुओं के अनुसार—सगृहीत की जाने वाली वस्तुओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के मण्डारगृह निर्मित किये जाते हैं। जैसे—ठोस वस्तुओं (खाद्यान्न, चीनी) के मण्डारगृह, तरल वस्तुओं के संग्रहण के लिए मण्डारगृह एवं शीघ्रनाशी वस्तुओं के संग्रहण के लिए शीत संग्रहागार। शीत संग्रहागार मण्डारों में तापक्रम नियन्त्रण की व्यवस्था होती है।
- 2 स्वामित्व के अनुसार—स्वामित्व के अनुसार मण्डारगृह निम्न प्रकार के होते हैं—

(अ) व्यक्तिगत मण्डारगृह—थोक व्यापारी, आदतिया, परिष्कर्ता वस्तुओं के संग्रहण के लिए मण्डारगृह निर्माण कराते हैं और स्वयं की अथवा विनय के लिए आई हुई वस्तुओं को सगृहीत करते हैं। मण्डारगृह में स्थान होने पर वे अन्य व्यक्तियों को किराये पर भी उठाते हैं।

(ब) सहकारी मण्डारगृह—इन पर सहकारी नमितिया का स्वामित्व होता है। सहकारी मण्डारगृह में मण्डारण के लिए समितिया क सदस्यों की वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाती है।

(त) सरकारी मण्डारगृह—इन पर स्वामित्व सरकार का होता है जिनमें उत्पादक, व्यापारी एवं उपभोक्ता निर्धारित शु. क का भुगतान करके वस्तुओं को संग्रहीत कर सकते हैं।

(द) धरेलू मण्डारगृह—यह उपभोक्ताओं के स्वयं क होता है जिनमें धरेलू वस्तुओं का संग्रहण किया जाता है।

(घ) अनुवृद्ध मण्डारगृह—अनुवृद्ध मण्डारगृह विद्यों में आगतिन वस्तुओं को शुल्क भुगतान के समय तक क लिए सुरक्षित रूप स संग्रहीत किये जाने के लिए हवाई अड्डों एवं बन्दरगाहों के मनीष निर्मित किये जाने हैं। वस्तुओं के भ्रम त करने वाले को संग्रहण-काल के लिए किराना देना होता है।

भारत में मण्डारण एवं मण्डारण सुविधा का विकास :

संग्रहण एवं मण्डारण सुविधाओं का विकास तीनो ही क्षेत्रों—सार्वजनिक (भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय मण्डार निगम एवं राज्य मण्डारगृह निगम), सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में हो रहा है। सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रों द्वारा निर्मित यह सुविधा मार्च 1974 में 11.87 मिलियन टन क्षमता की थी, जो बढ़कर मार्च, 1990 में 32.80 मिलियन टन हो गई। इस सुविधा का अधिकांश भाग खाद्यान्नों के संग्रहण में उपयोग में आता है।

केन्द्रीय एवं राज्य मण्डारगृहों का वर्तमान में देश में जात कीट भगा है। इनकी संख्या एवं संग्रहण क्षमता में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इतनी संग्रहण क्षमता वर्ष 1960-61 में मात्र 1.57 लाख टन थी, जो बढ़कर 1991-92 में 160.0 लाख टन हो गई। देश में खाद्यान्नों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित बातों को देखते हुए उपलब्ध संग्रहण क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए—

एव 1980 में 2,795 हो गई। इसी प्रकार इनकी क्षमता जो वर्ष 1964 में 3 05 लाख टन थी, जो बढ़कर वर्ष 1990 में 68 15 लाख टन हो गई। वर्तमान में 85 प्रतिशत इकाईयाँ जिनकी कुल स्थापित क्षमता 91 24 प्रतिशत है, निजी क्षेत्र में है और शेष 15 प्रतिशत शीन-गृह सार्वजनिक तथा सहकारी क्षेत्र में हैं, जिनकी कुल क्षमता मात्र 8 76 प्रतिशत ही है। कुल उपलब्ध शीत संग्रहण क्षमता का लगभग 80 प्रतिशत भाग चार राज्यों—उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं पंजाब में है। देश के शीत संग्रहण-गृह, शीत संग्रहण आदेश, 1964 द्वारा नियमित होते हैं। इस आदेश में वर्ष 1980 में परिवर्तन करके इसे व्यापक आदेश का रूप दे दिया गया है।

संग्रहण एवं भण्डारण लागत—वस्तुओं की संग्रहण एवं भण्डारण लागत ज्ञात करते समय, लागत के निम्न मद शामिल करने चाहिएँ—

(अ) भण्डारगृहों में भौतिक सुविधाओं को बनाये रखने में घाने वाली लागत जैसे—भण्डारगृह की मरम्मत एवं टूट फूट की लागत, मशीनों एवं भवन का मूल्य-ह्रास, बीमा की किस्त, ब्याज आदि।

(ब) उत्पादन-स्थान अथवा बाजार से संग्रहण स्थान तक वस्तुओं का परिवहन करने की लागत।

(स) संग्रहीत वस्तुओं के मूल्य पर संग्रहण समय का ब्याज।

(द) संग्रहण-काल में वस्तुओं के सूखने, खराब होने, संकुचन आदि कारणों से होने वाली मात्रा एवं किस्म ह्रास का मूल्य।

(य) संग्रहीत काल में वस्तुओं की कीमतों में गिरावट होने से हानि की राशि।

(र) संग्रहीत वस्तुओं एवं ताजा वस्तुओं की कीमतों में पाये जाने वाले अन्तर की राशि।

खाद्यान्नों की संग्रहण एवं भण्डारण लागत को कम करने की विधियाँ—निम्न विधियों को अपनाकर खाद्यान्नों की संग्रहण लागत को कम किया जा सकता है—

- 1 वस्तुओं के संग्रहण एवं भण्डारण काल में होने वाली मात्रा एवं किस्म के ह्रास में कमी करके—कीटनाशक दवाइयों के उपयोग, तापक्रम में होने वाले परिवर्तनों को कम करके तथा आर्द्रता नियन्त्रण द्वारा वस्तुओं की मात्रा एवं किस्म में होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। भारतीय खाद्यान्न संग्रहण संस्था (Indian Foodgrains Storage Institute) हापुड निरन्तर अनुसन्धान द्वारा संग्रहण विधियों में सुधार ला रही है ताकि खाद्यान्नों के संग्रहण-काल में कम से कम क्षति होवे।

- 2 धमिको की कार्य-कुशलता में वृद्धि करके संग्रहण लागत को कम किया जा सकता है ।
- 3 शिक्षा के प्रसार द्वारा संग्रहीत वस्तुओं के प्रति उपभोक्ताओं के विरोध को कम करना, जिससे संग्रहीत ताजा वस्तुओं की कीमतों में प्रन्तर नहीं होवे ।
- 4 संग्रहण-काल में वस्तुओं की कीमतों में होने वाली गिरावट की हानि को सट्टा एवं सुरक्षण विधि द्वारा कम करना ।
- 5 मण्डार गृहों की सुविधा मण्डियों एवं गाँवों में उपलब्ध कराना, ताकि उत्पादन स्थान से मण्डार गृह तक वस्तुओं को पहुँचाने में होने वाली परिवहन-लागत में कमी होवे ।
- 6 मण्डार-गृहों में खाद्यान्न-संग्रहण के लिए कृषकों को संग्रहण शुल्क में विशेष छूट देना, जिससे वे उपलब्ध मण्डारण सुविधाओं के उपयोग के लिए प्रेरित हो सकें ।

उपलब्ध संग्रहण एवं मण्डारण सुविधाओं का कृषकों द्वारा उपयोग नहीं कर पाना .

उपलब्ध मण्डार गृह क्षमता का सर्वाधिक उपयोग सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएँ जैसे—भारतीय खाद्य निगम एवं राष्ट्रीय बीज निगम करते हैं । कृषक उपलब्ध राज्य मण्डारगृहों की क्षमता का 2 प्रतिशत से कम उपयोग करते हैं । निम्न कारणों से वर्तमान में उपलब्ध संग्रहण एवं मण्डारण सुविधाओं का कृषक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं—

- 1 कृषकों को मण्डारगृहों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का ज्ञान न होना ।
- 2 अनेक मण्डियों एवं गाँवों में मण्डारगृह-सुविधा उपलब्ध न होना, जिससे कृषकों को शहर के मण्डारगृहों तक खाद्यान्न ले जाने में परेशानी होती है एवं अनावश्यक परिवहन लागत देनी पड़ती है ।
- 3 खाद्यान्नों को मण्डारगृहों में जमा कराने एवं वापस प्राप्त करने में होने वाली असुविधाएँ ।
- 4 मण्डारगृहों में सभी वस्तुओं के लिए संग्रहण सुविधा का समभाव होना ।
- 5 मण्डारगृहों से प्राप्त रसीद के आधार पर ऋण प्राप्ति की सुविधा राष्ट्रीयकृत बैंकों तक ही सीमित होना । अनेक स्थानों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के नहीं होने में कृषकों को ऋण-प्राप्ति से परेशानी होती है । मण्डारगृहों की रसीदों का प्रतिभूति के आधार पर अनुमूचित बैंक एवं सहकारी बैंक ऋण स्वीकार नहीं करते हैं ।

6 भण्डारशुद्धी में संग्रहण-लागत का अधिक होना ।

7. लघु जोत के कृषकों के पास विक्रेय-अधिशेष की मात्रा संग्रहण के लिए होना ।

(5) वित्त-व्यवस्था—विपणन-प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है । प्रत्येक विपणन-कार्य के लिए वित्त की आवश्यकता होती है । पाइल⁸ के अनुसार भुद्धा या ऋण विपणन-प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसी प्रकार से आवश्यक है जिस प्रकार मशीनों व यन्त्रों को चलाने के लिए स्निग्ध पदार्थ आवश्यक होते हैं । वित्त की आवश्यकता सभी उत्पादक कृषकों, व्यापारियों एवं अन्य विपणन-मध्यस्थों को होती है । प्रत्येक विपणन-मध्यस्थ की वित्त की आवश्यकता विभिन्न होती है । निम्नलिखित कारक विपणन के लिए वित्त की आवश्यक राशि में परिवर्तन लाते हैं—

- (1) व्यापार की प्रकृति—विभिन्न वस्तुओं के व्यापार के लिए वित्त की आवश्यकता भिन्न-भिन्न होती है ।
- (2) व्यापार का प्रकार—थोक व्यापार के लिए खुदरा व्यापार की अपेक्षा वित्त की आवश्यकता अधिक होती है ।
- (3) व्यापार के लिए वस्तुओं की संग्रहीत की जाने वाली मात्रा ।
- (4) वस्तुओं के उत्पादन एवं विपणन काल में समयांतर ।
- (5) वस्तुओं के क्रय-विक्रय एवं कीमत भुगतान की शर्तें ।
- (6) वस्तुओं के विपणन-कार्यों की लागत-राशि, जैसे—परिवहन लागत, सवैष्टन लागत, श्रेणीकरण लागत आदि ।
- (7) वस्तुओं में परिष्करण की आवश्यकता ।
- (8) व्यापार का स्थायी अथवा अस्थायी होना ।

विपणन-व्यवसाय के लिये वित्त प्राप्त करने के अनेक स्रोत हैं जिनमें से प्रामाण्य व्यापारी, भू-स्वामी, आदितिया, व्यापारिक बैंक एवं सहकारी समितियाँ प्रमुख हैं ।

(6) परिष्करण (रीफ़िनिंग)—परिष्करण से तात्पर्य उन क्रियाओं को करने से है जिनके द्वारा वस्तुओं के मूल रूप को परिवर्तित करके उनको उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए पहले से अधिक उपयोगी बनाया जाता है । विल्सन⁹ के अनुसार वे कार्य, जो कच्चे माल को निर्मित वस्तुओं के रूप में परिवर्तित करते हैं, परिष्करण के कार्य कहलाते हैं । इनमें वे सभी क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं जो वस्तु के रूप-परिवर्तन में सहायक होती हैं । इस क्रिया के द्वारा वस्तुओं में रूप-उपयोगिता उत्पन्न

8. "Money or Credit is the lubricant that facilitates the operation of the marketing machine."

-Pyle.

9. Wilson Gee, The Social Economics of Agriculture, 1942 p. 273.

होती है, जैसे—धान से चावल, गन्ने से गुड़, शक्कर व चीनी, फलों से शर्बत, मुरब्बा, जैम, जेली, म्चर, दूध से घी, मक्खन, खोआ, पनीर, गेहूँ से आटा, तिहहन से तेल आदि ।

कृषि-वस्तुओं की विपणन-प्रक्रिया में परिष्करण भी प्रमुख कार्य होता है, क्योंकि अनेक वस्तुओं का उत्पादन उस रूप में नहीं होता है, जिस रूप में उपभोक्ता उनका उपयोग करते हैं । कुछ कृषि वस्तुएँ, जैसे—धान, गन्ना, तिलहन आदि का परिष्करण उपयोग के पहले अति आवश्यक होता है, लेकिन फल, सब्जी एवं अन्य वस्तुओं को परिष्करण द्वारा अधिक उपयोगी बना सकते हैं एवं एक मौसम के अधिशेष उत्पाद को दूसरे मौसम अथवा समय में उपयोग के लिए सुरक्षित रख सकते हैं । अतः वस्तुओं को उपभोग-योग्य बनाने एवं उन्हें अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए परिष्करण करना होता है । इस क्रिया द्वारा वस्तुओं के संगृहीत किये जाने के काल में भी वृद्धि होती है, जैसे—फलों से जैम, जेली, शर्बत तथा सब्जियों को म्चर, डिब्बा-बन्दी एवं भुखाकर अधिक समय तक खराब होने से बचा लिया जाता है । उत्पादन मौसम के अतिरिक्त अन्य काल (Off-season) में भी उनकी माँग पूरी की जा सकती है । प्रोसेसिंग द्वारा वस्तुओं का बाजार भी विस्तृत होता है ।

परिष्करण से वस्तुओं की विपणन लागत में वृद्धि होती है, जिससे उत्पादकों को उपभोक्ता द्वारा दी जाने वाली कीमत में से प्राप्त प्रतिशत भाग कम होता जाता है । इस क्रिया द्वारा वस्तुओं के फार्म पर उत्पादित मूल्य में 7 प्रतिशत (चावल में) से 86 प्रतिशत (चाय) तक वृद्धि हो जाती है । वाणिज्यिक फसलों में यह वृद्धि खाद्यान्नों वाली फसलों की अपेक्षा अधिक होती है ।¹⁰

विभिन्न कृषि-वस्तुओं के लिए विभिन्न प्रकार के एवं विभिन्न स्तर तक परिष्करण कार्य करने होते हैं । इस सम्बन्ध में खाद्यान्न, तिलहन, दालों वाली फसलों, फलों एवं सब्जियों में किये जाने वाले कार्यों में बहुत भिन्नता होती है । परिष्करण कार्य की महत्ता के कारण वर्तमान में विभिन्न वस्तुओं के परिष्करण उद्योगों का विकास तीव्र गति से हुआ है । प्रत्येक वस्तु की परिष्करण प्रक्रिया में हो रहे निरन्तर अनुसंधान से वस्तुएँ अधिक उपयोगी होनी जा रही हैं ।

(7) क्रय-विक्रय—विपणन-कार्य की सम्पन्नता के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय होना आवश्यक है । वस्तुओं का क्रय विक्रय जेनाओं एवं विज्रंताओं के मध्य कीमत भुगतान के आधार पर होता है । इस कार्य द्वारा वस्तुओं में स्वामित्व-उपयोगिता उत्पन्न होती है ।

10 National Sample Survey, Report on the Sample Survey of the Manufacturing Industries, Report No. 23, Government of India, New Delhi, 1960.

वस्तुओं के क्रय से तात्पर्य, वस्तुओं का स्वामित्व क्रेता को प्राप्त होने से है। वस्तुओं के क्रय में क्रेताओं को निम्न सहायक कार्य करने होते हैं—

- (i) उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं के लिए विभिन्न वस्तुओं की मात्रा एवं किस्म की आवश्यकता का निर्धारण करना।
- (ii) वस्तुओं की पूर्ति के स्रोतों का पता लगाना।
- (iii) वस्तुओं का एकत्रीकरण करना, जिससे व्यापार हो सके।
- (iv) विक्रेता से क्रय की शर्तें तय करना।
- (v) वस्तुओं के क्रय के लिए सहमति देना एवं उनके स्वामित्व में परिवर्तन करना।

वस्तुओं के विनय से तात्पर्य विक्रेता से उपभोक्ताओं को वस्तुओं का स्वामित्व प्राप्त कराने से है। वस्तुओं के विक्रय में विक्रेताओं को निम्नांकित सहायक कार्य करने होते हैं—

- (i) वस्तुओं का आवश्यक मात्रा में उत्पादन करना, जिससे उपभोक्ताओं की आवश्यकताएँ पूरी हो सकें।
- (ii) क्रेताओं की तलाश करना एवं उनसे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना।
- (iii) उपभोक्ताओं में वस्तुओं की माँग उत्पन्न करना।
- (iv) वस्तुओं के विनय की शर्तें निर्धारित करना।
- (v) वस्तुओं के विनय के लिए सहमत होना एवं वस्तुओं के स्वामित्व में परिवर्तन करना।

वस्तुओं के विवरण के लिये विक्रय विधियाँ—बाजार में वस्तुओं के विक्रय की निम्न विधियाँ प्रचलित हैं—

- (1) कपड़े की छाड़ (आवरण) में गुप्त सकेतों द्वारा विक्रय—विक्रय की इस विधि के अन्तर्गत आढतियाँ एवं क्रेता व्यापारी कपड़े से अपने हाथ ढक लेते हैं तथा कपड़े की छाड़ में हाथ की अंगुलियों के गुप्त सकेतों द्वारा कीमत निर्धारित करते हैं। आढतियाँ एवं क्रेता द्वारा निश्चित की गई कीमत का विक्रेता-कृपक को ज्ञान नहीं होना है। निर्धारित की गई कीमत पर साधारण क्रेताओं को विनय कर दिया जाता है। विक्रय के पश्चात् आढतियाँ विक्रेता कृपक को साधारण की कीमत का भुगतान करता है। विनय की इस विधि में कृपकों की कीमतों के ज्ञान की अज्ञानता का अनेक आढतियाँ लाभ उठाते हुए कृपकों को निर्धारित कीमत से कम कीमत भुगतान करते हैं। अतः उपर्युक्त दोष के होने से सरकार ने विक्रय की इस विधि का कानूनन निषेध कर दिया है।

(ii) खुली नीलामी द्वारा विक्रय—विक्रय की इस विधि के अन्तर्गत उत्पादक-कृपको द्वारा लाये गये खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं का खुली नीलामी द्वारा बाजार में विक्रय किया जाता है। वस्तुओं की नीलामी में जान सेने की प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रता होती है। कृपको को क्रेताओं द्वारा नीलामी के समय दी जाने वाली कीमत का पूर्ण ज्ञान होता है, जिससे आदतियों के लिए नीलामी द्वारा निर्धारित कीमत में कम कीमत का कृपको को नुगतान कर पाना सम्भव नहीं होता है। वस्तुओं की खुली नीलामी के निम्न तरीके प्रचलित हैं—

(अ) फड नीलामी विधि—नीलामी की इस विधि के अन्तर्गत विभिन्न कृपको द्वारा बाजार में लाये गये विभिन्न किस्म के माल को एक ही बार में नीलाम किया जाता है। वस्तुओं की नीलामी वस्तु की किस्म के अनुसार नहीं की जाती, जिससे विक्रेताओं को अच्छे एवं औसत किस्म के उत्पाद के लिए समान कीमत प्राप्त होती है। बाजार में नीलामी की उपर्युक्त विधि के होने से उत्पादक कृपको में अच्छी किस्म के उत्पाद के उत्पादन की प्रेरणा का हास होता है।

(ब) प्राबुद्धिक नीलामी विधि—नीलामी की इस विधि के अन्तर्गत आदतिया वस्तुओं की नीलामी के लिए कुछ आदतियों को बाजार से बुलाता है और वस्तुओं की खुली नीलामी करता है। आदतियों द्वारा बाजार में खरीदने वालों को नीलामी की सूचना नहीं देने से विक्रय में स्पर्धा कम होती है और कृपको को खाद्यान्नों की सही कीमत प्राप्त नहीं होती है।

(स) तालिकाबद्ध नीलामी पद्धति—इस विधि के अन्तर्गत बाजार में प्रतिदिन निश्चित समय एवं स्थान से नीलामी शुरू होती है। विभिन्न कृपको द्वारा लाये गये माल को किस्म के अनुसार पृथक् रूप से नीलाम किया जाता है। एक आदतिया के यहाँ आई हुई विभिन्न वस्तुओं की नीलामी समाप्त होने पर, दूसरे आदतिया के यहाँ पर वस्तुओं की नीलामी शुरू होती है। वस्तुओं की नीलामी की यह नियमित विधि है। बाजार के खरीदने वाले को नीलामी की सूचना होती है। अतः विक्रय में स्पर्धा अधिक होती है जिससे कृपको को खाद्यान्न की उचित कीमत प्राप्त होती है।

(iii) आपसी समझौते के अनुसार विक्रय—इस विधि के अन्तर्गत वस्तुओं का विक्रय क्रेताओं एवं विक्रेताओं में परस्पर बार्ता के आधार पर होता है। वेदा वस्तुओं के नमूने के अनुसार कीमत तय होते हैं और विक्रेताओं की कीमत स्वीकार होने पर माल क्रेताओं को विक्रय कर दिया जाता है। वस्तुओं का क्रय-विक्रय, विक्रेताओं के फार्म पत्रवा क्रेताओं के व्यवसाय स्थान पर होता है।

(14) नमूने के द्वारा विक्रय—इस विधि के अन्तर्गत उत्पादक कृषको द्वारा लाये गये खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं का सर्वप्रथम घाड़तिया नमूना लेते हैं और वे नमूने को सम्भावित क्रेताओं के पास ले जाते हैं। जो क्रेता सबसे अधिक कीमत देने को तैयार होता है, घाड़तिया उस वस्तु को उसे विक्रय कर देता है। विनय की इस विधि में भी घाड़तिए वही वही वस्तु की निर्धारित कीमत से कम कीमत कृषको को भुगतान करते हैं और कीमतों के अन्तर को स्वयं हड़प जाते हैं।

(15) दड़ा विक्रय—विनय की इस विधि के अन्तर्गत विभिन्न किस्म की वस्तुओं को एक साथ मिश्रित करके दड़ा कर लिया जाता है और दड़े की सम्मिलित रूप से नीलाम किया जाता है। इस विधि से कम समय में अधिक मात्रा में वस्तुओं का विक्रय हो जाता है, जिसमें बाजार में माया हुआ सभी माल उसी दिन विनय हो जाता है।

(16) बन्द निविदा पद्धति से विक्रय—विनय की इस विधि के अन्तर्गत विभिन्न कृषको द्वारा लाये गये खाद्यान्नों को घाड़तियों की दुकान के सामने ढेर करके नम्बर अंकित कर दिया जाता है। वस्तुओं के क्रेता बाजार में घाड़तियों की दुकान पर आते हैं और वस्तु पसन्द होने पर वस्तु की न्य कीमत नीलाम पत्रों में अंकित करके घाड़तिया की दुकान पर रखे डिब्बे में डाल देते हैं। वस्तुओं के विक्रय के लिए निर्धारित समय की समाप्ति पर नीलाम पत्रियों को खाद्यान्न के ढेर की सहा के अनुसार कीमतों के बढ़ने हुए क्रम के अनुसार राग लिया जाता है। वस्तु के ढेर के लिए सबसे अधिक कीमत देने वाले क्रेता को बुलाकर वस्तु विक्रय की जाती है। विक्रय की इस विधि में कृषको को खाद्यान्न की उचित कीमत प्राप्त होने की सम्भावना अधिक होती है।

(17) मोगम विक्रय विधि (Moghum Sale)—मोगम-विक्रय विधि में कृषको द्वारा क्रेताओं को वस्तुओं की विक्री कीमत निर्धारित किए बिना ही की जाती है। विक्रेता कृषको को नेता-व्यापारियों पर पूर्ण विश्वास होता है कि वे बाजार में प्रचलित कीमत के अनुसार ही उन्हें खाद्यान्नों की कीमत भुगतान करेंगे। यह विधि मुख्यतया गाँवों में पायी जाती है, क्योंकि विक्रेता कृषक व्यापारियों के श्रेणी होते हैं।

कृषि वस्तुओं के विक्रय के माध्यम—उत्पादक कृषक कृषि-उत्पादों को निम्न माध्यम के द्वारा विक्रय करते हैं—

(1) उत्पादकों द्वारा उपभोक्ताओं एवं परिष्कर्ताओं को सीधे रूप में विनय :

(क) उपभोक्ताओं को सीधे रूप से विक्रय—विनय के इस माध्यम में उत्पादक-कृषक एवं उपभोक्ताओं के मध्य में कोई मध्यस्थ नहीं होता है। खाद्यान्न सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय किये जाते हैं, जिसके कारण विपणन-लागत बहुत कम आती है।

(ख) परिष्कर्ताओं को सीधे रूप से विक्रय—विक्रय के इस माध्यम में उत्पादक कृपको द्वारा साक्षात् परिष्कर्ताओं को बिना किसी विपणन-मध्यस्थ की सहायता से विक्रय किया जाता है ।

- (11) विपणन-मध्यस्थों के माध्यम से विक्रय—रूपि-उत्पाद के विक्रय का दूसरा माध्यम विपणन मध्यस्था, जैसे—भादतिया, दलाल, सहकारी विपणन संस्थाओं की सहायता से विक्रय करना है । विपणन-मध्यस्थों को किए गए कार्यों के लिए विपणन-भागत प्राप्त होती है ।

वस्तुओं के विक्रय में विक्रय शर्तें—वस्तुओं के विक्रय में विक्रय शर्तों को स्पष्ट करना आवश्यक है अन्यथा मण्डी में क्रेताओं एवं विक्रेताओं के मध्य में विवाद एवं झगड़े उत्पन्न होते हैं । विक्रय के समय निम्न शर्तों को स्पष्ट करना आवश्यक है—

- (1) वस्तुओं की किस्म—वस्तुओं की किस्म के नमूने, वस्तु का विस्तृत विवरण, ट्रेडमार्क अथवा श्रेणी का स्पष्ट किया जाना आवश्यक है ।
- (11) वस्तु की मात्रा—क्रय-विक्रय के पूर्व क्रेताओं एवं विक्रेताओं के मध्य में लेन-देन की जाने वाली वस्तु की मात्रा भी निश्चित की जानी आवश्यक है, जिससे कीमतों में परिवर्तन होने की स्थिति में विवाद उत्पन्न नहीं होवे ।
- (111) विक्रय राशि के भुगतान की शर्तें—उक्त विक्रय के समय क्रेता एवं विक्रेता के मध्य में राशि भुगतान समय की स्पष्टता भी आवश्यक है । विभिन्न मण्डियों में राशि भुगतान के विभिन्न नियम होते हैं । कुछ मण्डियों में भुगतान साक्षात् विक्रय के शीघ्र पश्चात् करना होता है जबकि अन्य मण्डियों में भुगतान के लिए कुछ अवधि नियत होती है ।
- (iv) सवेष्टन की शर्तें—वस्तुओं के विक्रय के समय क्रेताओं एवं विक्रेताओं के मध्य सवेष्टन की शर्तें स्पष्ट होनी चाहिये । जैसे कीमत में सवेष्टन में उपयोग की गई वस्तु सम्मिलित है या नहीं । कुछ मण्डियों में साक्षात् विक्रय में जूट की बोरी सम्मिलित होती है जबकि अन्य मण्डियों में बोरी को सम्मिलित नहीं करते हुए साक्षान्तों का विक्रय होता है ।
- (v) माल के आदान प्रदान का समय—क्रय-विक्रय के समय वस्तु के आदान प्रदान के समय की स्पष्टता भी आवश्यक है । कमी-कमी क्रय विक्रय वनमान में होता है, लेकिन वस्तु का वास्तविक आदान-प्रदान मविध्य के निश्चिन दिनांक को होता है ।

वस्तुओं की माँग उत्पन्न करना—वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए उपभोक्ताओं

की वस्तु के प्रति माँग का होना आवश्यक है। वस्तुओं की माँग उत्पन्न करने से तात्पर्य उपभोक्ताओं को वस्तु का ज्ञान प्रदान करते हुए उसकी आवश्यकता उत्पन्न करने से है। विप्रेता वस्तुओं की माँग में वृद्धि, विज्ञापन एवं अन्य विषय-विधियों द्वारा उपभोक्ताओं का वस्तु के गुण, लाभ, कीमत एवं अन्य जानकारी का विस्तृत ज्ञान प्रदान करके करते हैं जिससे उपभोक्ता उस वस्तु को ख़रीदने को तैयार हो सकें।

वर्तमान में प्रत्येक वस्तु की माँग उत्पन्न करना आवश्यक है क्योंकि उत्पादन-कर्त्ता वस्तुओं का उत्पादन भविष्य में माँग के उत्पन्न होने की आकांक्षा से करते हैं। विज्ञापन एवं माँग उत्पन्न करने की अन्य विधियों से वस्तुओं की विपणन-लागत में वृद्धि होती है। विज्ञापन द्वारा वस्तुओं की कुल बिक्री की मात्रा में वृद्धि होती है जिससे प्रति इकाई विपणन-लागत में कमी होती है। विक्रेता वस्तुओं का विज्ञापन समाचार-पत्र एवं पत्रिकाओं में सूचना प्रकाशित करके, रेडियो, टेलीविजन द्वारा सूचना-प्रसारण करके सिनेमा में स्टाइड दिखाकर, कलेण्डर, डायरियाँ एवं अन्य माध्यमों द्वारा करते हैं। विभिन्न विक्रेता वस्तुओं के विपणन के लिए विभिन्न विधियों को प्रयोग में लेते हैं। विज्ञापन मुख्यतया परिष्कर्त्ताओं एवं अन्य मध्यस्थ विक्रेताओं, जैसे—थोक विक्रेता आदि द्वारा किया जाता है।

(8) जोखिम वहन—वस्तुओं की विपणन-प्रक्रिया के विभिन्न विपणन-कार्यों जैसे—परिवहन, परिष्करण, संग्रहण एवं भण्डारण, कीमतों के पता लगाने आदि में वस्तु की मात्रा के कम होने अथवा किस्म का ह्रास अथवा कीमतों में गिरावट होने से जोखिम होती है। विपणन-प्रक्रिया में जोखिम के होने से विपणन सस्थाओं को हानि होने की निरन्तर घाशका बनी रहती है। विपणन-प्रक्रिया में होने वाली जोखिम दो प्रकार की होती है—

(अ) भौतिक जोखिम—भौतिक जोखिम वस्तु की मात्रा में कमी होने अथवा उसके गुणों में ह्रास, आग, वर्षा, दुर्घटना, कीड़े-मकोड़े, बीमारियाँ, अत्यधिक नमी, तापक्रम में परिवर्तन आदि कारणों से होती है। भौतिक जोखिम परिवहन, परिष्करण एवं संग्रहण-काल में प्रमुख रूप से होती है। भौतिक जोखिम, संग्रहण की उचित वैज्ञानिक विधि अपनाकर, वस्तुओं की आग, बाढ़ एवं अन्य दुर्घटना से होने वाली हानि का बीमा कराकर, परिवहन के उचित साधन अपनाकर कम की जा सकती है।

(ब) कीमत-जोखिम—विपणन-प्रक्रिया में दूसरी जोखिम वस्तुओं की कीमतों में गिरावट से उत्पन्न होती है। वस्तुओं की कीमतों में गिरावट, वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि, वस्तु की माँग में कमी आदि कारणों से

होती है। कीमतों में गिरावट के कारण होने वाली जोखिम को निम्न प्रकार से कम किया जा सकता है—

- (i) कीमतों से सम्बन्धित आवश्यक ज्ञान कृषकों को समय समय पर प्रदान करके।
- (ii) कीमतों में होने वाले अत्यधिक उतार-चढ़ावों को सरकार द्वारा न्यूनतम एवं अधिकतम कीमतों की निर्धारित सीमा में नियन्त्रित करके।
- (iii) कीमतों को वैज्ञानिक विधि द्वारा पूर्वानुमानित करते हुए कृषकों को सूचना प्रदान करके।
- (iv) कीमतों में गिरावट से रक्षा के लिए सट्टा एवं सरक्षण विधि अपनाकर।

सरक्षण विधि में व्यापारी वस्तुओं का हाजिर बाजार में क्रय करते हैं और कीमतों में गिरावट के कारण होने वाले नुकसान से रक्षा करने के लिए भावी बाजार में वस्तु की उतनी ही मात्रा का विक्रय करते हैं। सरक्षणकर्त्ताओं में व्यवसाय से होने वाले लाभ अथवा हानि की राशि का ही भुगतान होता है। वस्तुओं की मात्रा का वास्तविक लेन-देन साधारणतया नहीं होता है। वस्तुओं में सट्टे के कारण कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव की गति धीमी होती है एवं वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति में साम्यावस्था आसानी से स्थापित हो जाती है। विभिन्न मण्डलों में प्रचलित कीमतों के विशेष अन्तर की राशि को भी सट्टा एवं सरक्षण विधि द्वारा कम किया जा सकता है।

सरक्षण विधि का प्रमुख उद्देश्य व्यापारी की भावी समय में वस्तुओं की कीमतों के गिरने में होने वाली हानि से रक्षा करना है। इस विधि के अन्तर्गत व्यापारी वस्तुओं का क्रय-विक्रय जितनी मात्रा में हाजिर बाजार में करते हैं, उतनी ही मात्रा के लिए विपरीत क्रिया अर्थात् विक्रय अथवा क्रय भावी बाजार में करते हैं।¹¹ व्यापारी को हाजिर बाजार में कीमतों के गिरने से जो हानि होती है उसकी पूर्ति भावी बाजार में उसी अनुपात में कीमतों में गिरावट होने से प्राप्त होने वाले लाभ द्वारा हो जाती है। इस प्रकार सरक्षण विधि द्वारा व्यवसाय में होने वाली सम्भावित हानि से व्यापारी की रक्षा होती है। सट्टा विधि के अन्तर्गत भी व्यापारी वस्तुओं का क्रय विक्रय हाजिर बाजार एवं भावी बाजार में करते हैं। इसके अन्तर्गत हाजिर एवं भावी बाजार में बी गई क्रियाएँ पूर्णतया एक-दूसरे के विपरीत होना आवश्यक नहीं है और न ही वस्तुओं का हाजिर एवं भावी बाजार में क्रय विक्रय समान मात्रा में होना आवश्यक है। क्रय-विक्रय वस्तुओं में लाभ कमाने की आशा

से किए जाते हैं। सट्टा विधि में व्यापारियों को होने वाले लाभ अथवा हानि उनके द्वारा की गई नियाजों के सम्बन्ध में लिये गये उचित निर्णयों पर निर्भर होती है। सट्टा विधि के अन्तर्गत व्यापारी वस्तुओं की कीमतों के बढ़ने की आशा में क्रय करके स्टॉक कर लेते हैं और उनको आशानुसार कीमतों के बढ़ने पर विक्रय करके लाभ कमाते हैं।

सरक्षण विधि का उदाहरण

हाजिर बाजार में वस्तुओं का क्रय-विक्रय	भावी बाजार में वस्तुओं का क्रय-विक्रय
दिसम्बर 1, 1992 100 क्विन्टल गेहूँ 300 रु प्रति क्विन्टल की दर से क्रय किया गया।	दिसम्बर 1, 1992 100 क्विन्टल गेहूँ, अप्रैल 15, 1993 के सौदे पर 310 रु प्रति क्विन्टल की दर से विक्रय किया गया।
दिसम्बर 15, 1992 100 क्विन्टल गेहूँ 295 रु प्रति क्विन्टल की दर से विक्रय किया गया।	दिसम्बर, 15, 1992 100 क्विन्टल गेहूँ अप्रैल 15, 1993 के सौदे पर 305 रु प्रति क्विन्टल से क्रय किया गया।
हाजिर बाजार में खाद्यान्न के क्रय विक्रय में प्रति क्विन्टल हानि 5 00 रु	भावी बाजार में खाद्यान्न के क्रय-विक्रय में प्रति क्विन्टल लाभ 5 00 रु

सरक्षण एवं सट्टा विधि उन सभी कृषि वस्तुओं में अपनाई जा सकती हैं जिन्हें आसानी से श्रेणीचयन एवं सङ्गृहीत किया जा सकता है। सरकार विभिन्न वस्तुओं पर समय-समय पर सरक्षण अथवा सट्टे के लिए प्रतिबन्ध लगाती है और गैर-कानूनी सट्टे पर रोक लगाती है। वस्तुओं के अग्रिम बाजार में होने वाले लेन-देन सरकार वायदा सविदा (नियन्त्रण) अधिनियम [The Forward Contracts (Regulation) Act, 1952] के तहत नियन्त्रण करती है।

सरक्षण विधि की प्रमुख धारणा यह है कि हाजिर बाजार एवं भावी बाजार में वस्तुओं की कीमत में गिरावट अथवा वृद्धि का स्तर समान होता है। कभी-कभी हाजिर बाजार एवं भावी बाजार में कीमतों में वृद्धि अथवा गिरावट का स्तर समान नहीं होता है। दोनों बाजारों की कीमतों में गिरावट अथवा वृद्धि के अन्तर से व्यापारियों को लाभ अथवा हानि होती है जिससे व्यवसाय चलता है। अतः सरक्षण विधि कीमतों में उतार चढ़ाव से होने वाली हानि से व्यापारियों को पूर्ण रूप से रक्षा नहीं करती है।

9 कीमत-निर्धारण एवं कीमतों का पता लगाना—विभिन्न वस्तुओं की कीमत निर्धारण एवं कीमतों का पता लगाने का कार्य भी विपणन-प्रक्रिया का प्रमुख

भाग है। कीमतों के आकार पर ही वस्तुओं का ज़ेताओं एवं विक्रेताओं में आदान-प्रदान होता है। विभिन्न वस्तुओं की उचित कीमत का निर्धारण आवश्यक है। वस्तु की उचित कीमत होने पर ही विक्रेता वस्तु को बेचने एवं ज़ेता खरीदने को तैयार होते हैं। कीमतों का निर्धारण वस्तु की मांग एवं पूर्ति नामक शक्तियों पर निर्भर होता है। विपणन-मध्यस्थ विभिन्न वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण देश की मण्डियों में वस्तु की आपूर्ति एवं आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए करते हैं। निर्धारण-कीमत विपणन-प्रक्रिया में निम्न प्रकार से सहायक होती है—

- (i) कीमतें विपणन-क्रिया के संचालन को निर्देशित करती हैं।
- (ii) कीमतें वस्तु की मांग एवं पूर्ति की मात्रा में सन्तुलन स्थापित करती हैं जिससे विक्रेताओं द्वारा लाया गया माल पूर्णरूप से विक्रय हो जाता है तथा ज़ेताओं की आवश्यकताएँ पूर्ण हो जाती हैं।
- (iii) कीमतें उपभोक्ताओं की मांग को निर्धारित करती हैं।
- (iv) कीमतें उत्पादकों को फार्म पर विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल निर्धारण करने में प्रथम-प्रदर्शक का कार्य करती हैं एवं उत्पादकों को उत्पादन-वृद्धि की प्रेरणा देती हैं।

निर्धारित कीमतों की विशेषताएँ :

- (i) निर्धारित कीमत पर बाजार में विक्रय के लिए लाये गये खाद्यान्नों की सम्पूर्ण मात्रा की बिक्री हो जानी चाहिए।
- (ii) निर्धारित कीमत कृषकों को उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा देने वाली होनी चाहिए।
- (iii) निर्धारित कीमत विपणन में कार्य करने वाले विपणन-मध्यस्थों को उचित लाभ की राशि प्रदान करने वाली होने चाहिए जिससे विपणन मध्यस्थ विपणन-कार्य करते रहे।

ज़ेताओं एवं विक्रेताओं द्वारा कीमतों का निर्धारण बाजार में आपूर्ति में बातचीत के द्वारा होता है। ज़ेता साधारणतया वस्तु की वास्तविक ज़रूरत कीमत से कम कीमत लगाना है जबकि विक्रेता वास्तविक विजय-कीमत से अधिक कीमत माँगता है। अन्त में कीमतें दोनों स्तरों के बीच में निर्धारित होती हैं। कीमतों का यह स्तर ज़ेता की वस्तु की आवश्यकता, विक्रेता को घन की आवश्यकता, वस्तु की बाजार में उपलब्धि की मात्रा, वस्तुओं की स्थानीय एवं विदेशी बाजार में सम्भावित मांग, अगले मौसम में उत्पादन की सम्भावित मात्रा आदि कारकों पर निर्भर होता है।

(10) विपणन-सूचना सेवा—विपणन प्रक्रिया में विपणन-सूचना सेवा भी आवश्यक विपणन कार्य है। विपणन में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं को विपणन सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने पर विपणन-प्रक्रिया सुगमता एवं सरलता से संचालित होती है। विपणन सूचना-सेवा के अन्तर्गत मण्डियों में प्रचलित कीमत, विजय के

लिए बाजार में वस्तु की आवक मात्रा, सम्भावित कीमतों आदि का ज्ञान सम्मिलित होता है जो क्रेताओं एवं विक्रेताओं को क्रय-विक्रय के निर्णय लेने के लिए आवश्यक होता है। विपणन-सूचना दो प्रकार की होती है।

(i) बाजार-दृष्टिकोण-सूचना-सेवा—बाजार-दृष्टिकोण-सूचना सेवा के अन्तर्गत कृषकों को वस्तुओं की सम्भावित मांग एवं पूर्ति की मात्रा एवं कीमतों के विषय में सूचना प्रदान की जाती है, ताकि कृषक अगले वर्ष के लिए फार्म पर विभिन्न फसलों एवं उनके अन्तर्गत क्षेत्रफल का निर्धारण कर सकें। उपर्युक्त सूचना सेवा प्रदान करने की व्यवस्था का वर्तमान में देश में बहुत अभाव है। इस सूचना सेवा के प्रभाव में कृषक फार्म पर विभिन्न उद्यमों का चुनाव एवं निर्णय बिना किसी वैज्ञानिक आधार के लेते हैं, जिससे फार्म से प्राप्त होने वाला सम्भावित लाभ कम होता है। हरित-क्रान्ति के कारण कृषकों को अधिक लाभ के लिए बाजार दृष्टिकोण-सूचना-सेवा की आवश्यकता अधिक होती है।

(ii) बाजार समाचार सेवा—बाजार-समाचार-सेवा के अन्तर्गत विभिन्न मण्डियों में प्रचलित कीमतों के समाचार कृषकों, मध्यस्थों एवं उपभोक्ताओं को देने की व्यवस्था होती है। बाजार-समाचार सेवा वस्तुओं के क्रय-विक्रय के लिए आवश्यक होती है। विभिन्न मण्डियों से कीमतों के समाचार प्राप्त होने पर कृषक उत्पाद के विक्रय के लिए उचित मण्डी, सही समय एवं विपणन-संस्था का चुनाव करके उत्पाद के विक्रय से अधिक लाभ कमा सकते हैं।

बाजार दृष्टिकोण सूचना-सेवा पूर्वानुमान है, जबकि बाजार समाचार-सेवा प्रसारण है। कृषकों, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं को बाजार सूचना वर्तमान में समाचार-पत्र, रेडियो, पत्रिकाओं एवं आदतियों के पत्रों के माध्यमों से प्रतिदिन प्राप्त होती है। कीमत सूचना हेतु भारत सरकार ने आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय में मूल्य सूचना विभाग (Price Intelligence Section) स्थापित किया है। यह विभाग प्रत्येक राज्य की प्रमुख मण्डियों से खाद्यान्नों एवं अन्य कृषि-वस्तुओं के धोक एवं खुदरा कीमतों में दैनिक एवं साप्ताहिक आंकड़े इकट्ठा करता है और उन्हें प्रतिदिन रेडियो एवं पत्रिकाओं से प्रसारण करता है।

वर्तमान में देश के असंख्य कृषक अशिक्षा, कृषि की व्यवसाय के रूप में नहीं लेने, मण्डियों में होने वाली असुविधाओं, स्थानीय व्यापारियों के चूल्हों होने, विक्रेय-अधिशेष की मात्रा के कम होने आदि कारणों से उपलब्ध विपणन समाचार-सेवा से पूर्ण लाभ नहीं उठा रहे हैं। देश के उत्पादक कृषकों को विपणन-कीमत-सूचना-सेवा से अधिक लाभ की प्राप्ति के लिए निम्न सुझाव प्रेषित है—

- 1 कृषि-वस्तुओं की कीमतों की सूचना का प्रतिदिन 3 से 4 बार रेडियो एवं टेलीविजन द्वारा प्रसारण किया जाना चाहिए।

- 2 कृपि वस्तुओ की कीमतो की सूचना का प्रसारण करने मे स्थानीय मण्डियो की कीमतो को प्राथमिकता देनी चाहिए ।
- 3 वर्तमान मे प्रचलित कीमतो के प्रसारण के साथ-साथ भावी कीमतो के पूर्वानुमान भी प्रसारित किये जाने चाहिए ।
- 4 कीमत-सम्बन्धी विपणन-सूचना-सेवा प्रसारण करने वाले समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ आदि हिन्दी एव स्थानीय भाषा मे होने चाहिए, जिन्हें कृषक यासानी से समझ सकें ।
- 5 कीमतो की सूचना-सेवा के साथ-साथ बाजार मे वस्तु की सम्भावित माँग के झँकडे देने की व्यवस्था भी की जानी चाहिये, जिससे कृषक विपणन-सम्बन्धी निर्णय सुगमता से से सकें ।



विपणन-लागत, विपणन-लाभ एवं विपणन-दक्षता

इस अध्याय में वृषि वस्तुओं के उद्य-विक्रय में विभिन्न विपणन-कार्यों की होने वाली लागत, विपणन मध्यस्थों को प्राप्त होने वाले लाभ एवं विपणन-दक्षता का विवेचन किया गया है।

विपणन-लागत

विपणन-लागत से तात्पर्य—विपणन-लागत में वास्तविक वस्तुओं को उत्पादन स्थान से अन्तिम उपभोक्ता तक पहुँचाने में वृषकों एवं विपणन मध्यस्थों द्वारा किये जाने वाले व्यय की कुल राशि से होता है। विभिन्न वस्तुओं के विपणन में होने वाली विपणन-लागत की गति विभिन्न होती है। विपणन-लागत ज्ञात करते समय वृषकों के द्वारा की जाने वाली लागत के अतिरिक्त विभिन्न विपणन मध्यस्थों की लागत भी सम्मिलित की जानी है। विपणन-प्रक्रिया में वृषि वस्तुओं पर होने वाली कुल विपणन-लागत ज्ञात करने का सूत्र निम्न है—

कुल विपणन-लागत = उत्पादक वृषक की लागत + प्रथम विपणन-लागत + द्वितीय + अन्य विपणन-लागत

मध्यस्थ की विपणन मध्यस्थों की विपणन-लागत मध्यस्थ विपणन-लागत की विपणन-लागत

विपणन-प्रक्रिया के सभी कार्यों वस्तुओं की विपणन-लागत में वृद्धि करते हैं। वस्तुओं के विक्रय के लिए विपणन कार्यों का करना अनिवार्य है। विभिन्न वस्तुओं के लिए विपणन-लागत की निम्न विपणन मध्यस्थों की संख्या, विपणन में परिष्करण (प्रोसेसिंग) की आवश्यकता, परिवहन स्थान की दूरी, संचरण की आवश्यकता एवं अवधि, वस्तुओं के पैकेजिंग में प्रयुक्त आवरण की लागत आदि कारकों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है।

विपणन-लागत के अध्ययन का महत्त्व—विपणन-लागत का अध्ययन विपणन-प्रक्रिया में प्रयुक्त स्थान रखता है। विपणन-लागत की अधिकता की अवस्था में

उत्पादको को फार्म से प्राप्त उत्पाद के विक्रय मूल्य में से कम अंश प्राप्त होता है तथा उपभोक्ताओं को अधिक कीमत देनी होती है। कृषकों को उपभोक्ता द्वारा दिये गये मूल्य में से कम अंश की प्राप्ति, विपणन-दक्षता के कम होने का प्रतीक है, जिससे तात्पर्य है कि वस्तुओं के विपणन की उचित व्यवस्था नहीं है तथा विपणन-विधि में अनेक त्रुटियाँ हैं।

विपणन-प्रक्रिया में होने वाली विपणन-लागत का अध्ययन विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न वस्तुओं एवं बाजारों के अध्ययन के लिए आवश्यक है। विभिन्न बाजारों में वस्तु की विपणन लागत में भिन्नता, उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाली सुविधाओं अथवा बाजार में पायी जाने वाली विपणन कुरीतियों का ग्रामास कराती है जिससे विपणन विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने में सहायता मिलती है।

विपणन-लागत के मुख्य अवयव — विभिन्न वस्तुओं के विपणन में होने वाली विपणन-लागत के मुख्य अवयव निम्न हैं—

(1) परिवहन लागत—कृषि वस्तुओं का उत्पादन कृषकों के फार्म पर होता है जबकि उनका उपभोग विभिन्न दूरी पर स्थित शहरों, कस्बों एवं गांवों में होता है। अतः वस्तुओं को उत्पादन से उपभोग स्थान तक ले जाना होता है। उत्पादित उपज को फार्म से घर अथवा निकटतम मण्डी में लाने, एक मण्डी से दूसरी मण्डी तक ले जाने मण्डी में खुदरा विक्रेताओं के विक्रय स्थल तक ले जाने, संग्रहण के लिए गोदाम तक ले जाने एवं मण्डी में उपभोक्ता के घर तक पहुँचाने के लिए उनका परिवहन करना होता है। वस्तुओं के परिवहन करने पर लागत धाती है।

(2) संवेष्टन पैकेजिंग लागत—विभिन्न वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए विभिन्न पैकेजिंग की वस्तुएँ प्रयोग में ली जाती हैं, जैसे- फलों के लिए टोकरीयाँ एवं लकड़ी के बक्से, दूध के लिए काच व प्लास्टिक की बोतलें, खाद्यान्नों के लिए जूट की बोरीयाँ आदि। संवेष्टन में प्रयुक्त वस्तु की भिन्नता के कारण संवेष्टन लागत में भिन्नता होती है।

(3) श्रमिक लागत—वस्तुओं को गोदाम से परिवहन साधनों में षटाने एवं उतारने, माल की सफाई, तुलाई के लिए काटे पर लगाने आदि कार्यों के लिए पल्लेदारों एवं अन्य श्रमिकों की मेवाएँ काम में ली जाती हैं, जिनके लिए दी जाने वाली लागत को पल्लेदारी अथवा हमाली कहते हैं।

(4) तुलाई—अग्र-विक्रय में वस्तुओं को तोलने की लागत भी तुलारा को देनी होती है, जिसे तुलाई कहते हैं।

(5) चुगी—शहर एवं कस्बों की मण्डियों में प्रवेश के पूर्व वस्तुओं पर चुगी कर भी देय होता है। यह कर क्षेत्र की नगरपालिका अथवा ग्राम पंचायत को देय होता है।

(6) बिक्री-कर—कुछ वस्तुओं के त्रय-विनय में सरकार को बिक्री-कर देना होता है। केना द्वारा बिक्री कर सरकार को विक्रेता के माध्यम से दिया जाता है।

(7) आड़त—मण्डियों में उत्पाद के विनय के लिए आड़तियों की सेवाओं के लिए आड़त देनी होनी है। आड़त की दर विभिन्न वस्तुओं के लिए भिन्न-भिन्न होती है।

(8) दलाली—वस्तुओं के त्रय-विनय में कभी-कभी दलालों की सेवाएँ भी काम में ली जाती हैं, जिसके लिए दी जाने वाली लागत को दलाली कहते हैं।

(9) करदा एवं घलता—वस्तुओं में अशुद्धता के लिए अतिरिक्त मात्रा के रूप में करदा दिया जाता है जो सामान्यतः वस्तु के रूप में दिया जाता है। वस्तुओं में नमी के कारण मात्रात्मक ह्रास की पूर्ति के लिए वस्तु की दी जाने वाली अतिरिक्त मात्रा घलता कहलाती है। विभिन्न मण्डियों में विभिन्न वस्तुओं पर पृथक् दर से करदा एवं घलता दिया जाता है।

(10) सग्रहण लागत—वस्तुओं का शीघ्र विनय नहीं हो पाने के कारण उन्हें कुछ समय के लिए सग्रहीत भी किया जाता है। सग्रहण के लिए दी जाने वाली लागत को सग्रहण लागत कहते हैं।

(11) कटौती/मुद्दत—वस्तुओं की कीमत को विनय के तुरन्त बाद मुग्तान करने के लिए दी जाने वाली लागत को कटौती/मुद्दत कहते हैं।

(12) विविध लागत—वस्तुओं के विपणन में प्रयुक्त श्रृंखला पर ब्याज, विपणन मूचना के लिए डाक खर्च, जोखिम के लिए बीमा किस्त, धर्मादा, गौशाला, प्याऊ खर्च एवं अन्य खर्च भी देने होते हैं। विविध खर्च विभिन्न मण्डियों में भिन्न-भिन्न होते हैं।

विपणन लागत में परिवर्तन लाने वाले कारक—विभिन्न वस्तुओं की विपणन-लागत में परिवर्तन लाने वाले प्रमुख कारक निम्न हैं—

(1) वस्तुओं में शीघ्रनाशी होने का गुण—वस्तुओं के शीघ्रनाशी होने के गुण एवं उनकी विपणन-लागत में घनात्मक सम्बन्ध होता है। शीघ्रनाशी वस्तुओं की प्रति इकाई विपणन-लागत अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक होती है क्योंकि इनके परिवहन कार्य में प्रशीतन-युक्त मशीनरी एवं द्रुतगामी परिवहन साधन प्रयुक्त करने होते हैं।

(2) विपणन-प्रक्रिया में वस्तुओं की टूट-फूट, संकुचन, गलने एवं सड़ने की लागत—उपर्युक्त प्रकार के नुकसान जिन वस्तुओं में अधिक मात्रा में होते हैं, उन वस्तुओं में विपणन-लागत अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक आती है।

(3) संवेष्टन में प्रयुक्त वस्तु की लागत—वस्तुओं के संवेष्टन में अर्द्धवस्तु का उपयोग करने पर विपणन-लागत अधिक आती है। वर्तमान में उपभोगकर्ताओं

को वस्तु के प्रति आकर्षित करने के लिए अन्धे किस्म के सबेष्टनों का उपयोग किया जाता है।

(4) परिवहन लागत—परिवहन लागत वस्तुओं की किस्म, परिवहन दूरी, सड़क की स्थिति एवं परिवहन साधनों पर निर्भर करती है जिससे विपणन लागत में परिवर्तन आता है।

(5) सग्रहण लागत—विभिन्न वस्तुओं के लिए सग्रहण की आवश्यकता में होने वाली भिन्नता के कारण सग्रहण लागत में परिवर्तन होता रहता है।

(6) वस्तुओं का भ्रम्भार—भ्रम्भार वाली वस्तुओं, जैसे—कपास, ऊन, मिर्च आदि द्वारा स्थान अधिक घेरे जाने के कारण उनकी परिवहन, सग्रहण एवं अन्य लागतें अधिक आती हैं।

(7) वस्तुओं के विक्रय के लिए विज्ञापन की आवश्यकता—विज्ञापन की अधिक आवश्यकता वाली वस्तुओं की विपणन-लागत अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक होती है।

(8) विपणन-प्रक्रिया में पाये जाने वाली कुरीतियाँ—विपणन में पायी जाने वाली कुरीतियाँ, जैसे—नमूने के रूप में विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न ले जाना, तोलने में अप्रमाणीकृत बाटो का प्रयोग, हिमाब में भूल आदि के कारण विपणन-लागत अधिक आती है।

(9) विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सुविधाएँ—उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सुविधाएँ, जैसे—माल पसन्द नहीं आने पर वापस लौटाने की सुविधा, भुगतान करने के समय में छूट, उपभोक्ता के घर तक निःशुल्क पहुँचाने आदि के कारण भी विपणन-लागत में वृद्धि होती है।

(10) वस्तुओं की माँग की प्रकृति—स्थायी माँग वाली वस्तुओं का व्यापार निरन्तर होने के कारण उनकी प्रति इकाई विपणन-लागत अस्थायी माँग वाली वस्तुओं की अपेक्षा कम आती है।

कृषि वस्तुओं में विपणन लागत की अधिकता के कारण—कृषि वस्तुओं में प्रति इकाई भार पर विपणन-लागत, औद्योगिक एवं निर्मित वस्तुओं की अपेक्षा अधिक आती है जिसके कारण निम्न हैं—

- (1) अधिकांश कृषि वस्तुएँ शीघ्रनाशी गुण वाली होती हैं जिसके कारण परिवहन एवं सग्रहण की लागत अधिक होती है।
- (2) कृषि वस्तुएँ भ्रम्भार वाली होती हैं जिससे प्रति इकाई भार पर परिवहन लागत अधिक आती है।
- (3) कृषि-वस्तुओं की किस्म में विभिन्नता के कारण वस्तुओं के श्रेणीकरण की लागत अधिक आती है।

- (4) कृषि-वस्तुओं के उत्पादन का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण, 'वस्तुओं के एकत्रीकरण की लागत अधिक आती है।
- (5) कृषि-वस्तुओं के उत्पादन एवं उपभोग-काल में विशेष समयान्तर होने से वस्तुओं का संग्रहण करना होता है। वैज्ञानिक विधि की संग्रहण सुविधाओं के अभाव में संग्रहण समय में कीड़े, चूहे, गमी आदि के कारण वस्तुओं की मात्रा एवं किस्म में बहुत हानि होती है, जिससे संग्रहण लागत में वृद्धि होती है।
- (6) कृषि वस्तुएँ गाँवों में उत्पन्न होती हैं। गाँवों में सड़कों के अभाव में वस्तुओं के परिवहन में समय एवं लागत अधिक होती है।
- (7) कृषि-वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव, विपणन में जोखिम की अधिकता आदि के कारण विपणन-मध्यस्थ कृषि वस्तुओं की विपणन प्रक्रिया से अधिक लाभ कमाने की इच्छा करते हैं जिससे विपणन-लागत में वृद्धि होती है।
- (8) लघु जोत के कारण कुबकों के यहाँ विक्रेय अधिशेष की मात्रा कम होती है। कृषि वस्तुओं का न्य विक्रय थोड़ी-थोड़ी मात्रा में होता है जिससे प्रति इकाई भार पर विपणन-लागत अधिक आती है।
- (9) उत्पादन-स्थानों एवं गाँवों में कृषि वस्तुओं के श्रेणीकरण की सुविधा के अभाव में वस्तुओं का श्रेणीकरण मण्डी में किया जाता है। मण्डियों में श्रेणीकरण करने पर लागत अधिक आती है। साथ ही खराब वस्तु को बेकार ही फेंकना होता है जबकि गाँव में यह पशुओं को लिलाने के काम में लायी जा सकती है।
- (10) कृषि-वस्तुओं का उत्पादन मौसमी होता है जिसके कारण विपणन-मध्यस्थों को दूसरे मौसम में स्थापन लागत बिना कार्य के ही करनी पड़ती है जो वस्तुओं की कुल लागत में वृद्धि करती है।

विपणन-लाभ

विपणन लाभ से तात्पर्य—वस्तु की निश्चित मात्रा के लिए उपभोक्ता द्वारा दी गई कीमत एवं उपादक कुबक द्वारा प्राप्त कीमत का अन्तर विपणन-लाभ कहलाता है, अर्थात् विपणन कार्यों में लगी हुई विभिन्न विपणन सस्थाओं की न्य-विक्रय-कीमत का अन्तर ही विपणन लाभ कहलाता है। विपणन-लाभ के अन्तर्गत वस्तुओं के उत्पादन स्थान से उपभोग स्थान तक संचलन में होने वाली सभी लागत जैसे—परिवहन, संग्रहण, परिष्करण, आहत मजदूरी आदि तथा विभिन्न विपणन सस्थाओं को प्राप्त होने वाले लाभ की राशि सम्मिलित होती है।

विपणन-लाभ के अध्ययन की उपयोगिता—विपणन-व्यवस्था की कार्यक्षमता के अध्ययन के लिए विभिन्न वस्तुओं की एक इकाई मात्रा के विक्रय पर होने वाली

लागत एवं विभिन्न विपणन-मध्यस्थों को प्राप्त होने वाले लाभ की राशि का ज्ञान होना आवश्यक है। मण्डियों की विपणन-दक्षता का मापदण्ड विपणन-लाभ की राशि होती है। विपणन-संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सेवाओं के समान-स्तर पर होते हुए यदि किसी मण्डी अथवा विपणन व्यवस्था में विपणन-लाभ की राशि दूसरी मण्डी अथवा विपणन व्यवस्था की अपेक्षा अधिक है तो इससे तात्पर्य है कि प्रथम मण्डी विपणन में कम दक्ष है अर्थात् प्रथम मण्डी की विपणन-व्यवस्था में अनेक कुरीतियाँ हैं, जिनके कारण मण्डी में प्रति इकाई विपणन-लागत अधिक आती है। अतः प्रथम मण्डी के क्षेत्र के कृषकों को उचित लाभ की राशि प्रदान करने के लिए वहाँ की विपणन-व्यवस्था में सुधार लाना आवश्यक है। विपणन-लाभ के अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि विभिन्न विपणन-संस्थाओं में से कौनसी विपणन-संस्था प्रति इकाई उत्पाद से अधिक लाभ प्राप्त कर रही है तथा विपणन-संस्था को प्राप्त हो रहे प्रतिरिक्त लाभ को किस प्रकार कम किया जाये, जिससे उत्पादक-कृषक को मेहनत की पूरी कमाई प्राप्त हो सके।

सरकार की विपणन-सम्बन्धी विभिन्न नीतियों जैसे—मण्डियों को नियन्त्रित करना विभिन्न वस्तुओं के लिए विपणन लागत की दर निर्धारित करना, सरकार द्वारा खाद्यान्न का ध्यावर हाथ में लेना आदि निर्णय लेने में भी विपणन लाभ का ज्ञान सहायक होता है।

विपणन लाभ ज्ञात करने के तरीके—कृषि वस्तुओं के विक्रय में प्राप्त होने वाले विपणन-लाभ की राशि ज्ञात करने की प्रमुख विधियाँ निम्न हैं—

(1) उत्पाद की प्रमुख ढेरी, बैलगाड़ी अथवा ट्रक का चुनाव करना—विपणन-लाभ ज्ञात करने की इस विधि में सर्वप्रथम मण्डी में विक्रय के लिए लाये हुए विभिन्न खाद्यान्नों में से एक ढेरी, बैलगाड़ी अथवा ट्रक का यादृच्छिक प्रतिचयन कर लिया जाता है। चुने हुए उत्पाद की ढेरी का अन्तिम उपभोक्ता तक पहुँचाने में क्रय विक्रय पर विभिन्न मध्यस्थों द्वारा की गई लागत एवं प्राप्त लाभ की राशि के आकड़े एकत्रित किये जाते हैं। तत्पश्चात् प्राप्त आकड़ों के आधार पर प्रति इकाई उत्पाद की मात्रा के लिए विपणन-लाभ ज्ञात किया जाता है।

विपणन-लाभ ज्ञात करने की इस विधि में प्रतिचयन की हुई खाद्यान्नों की ढेरी अथवा बैलगाड़ी के अन्तिम उपभोक्ता तक पहुँचाने के अध्ययन में आकड़े एकत्रित करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना होता है, जैसे—प्रतिचयन की हुई ढेरी के खाद्यान्न को मध्यस्थों द्वारा त्रय किये गये अन्य खाद्यान्न के साथ मिश्रित कर देना, चुनी हुई ढेरी के खाद्यान्न को विपणन-मध्यस्थों द्वारा विमिश्रित करके विक्रय के लिए पृथक् स्थानों पर भिजवाना, चुनी हुई ढेरी का अनेक मध्यस्थों के द्वारा संचालन करना आदि। उपर्युक्त कठिनाइयों के होने से साधारणतया विपणन-लाभ ज्ञात करने की यह विधि कम उपयोग में लाई जाती है।

(2) विभिन्न विपणन-मध्यस्थों को उत्पाद की प्रति इकाई मात्रा के क्रय-विक्रय से प्राप्त लाभ के योग द्वारा—विपणन-लाभ ज्ञात करने की इस विधि के अन्तर्गत विभिन्न विपणन-मध्यस्थों को उत्पाद की प्रति इकाई मात्रा के क्रय-विक्रय से प्राप्त होने वाले लाभ की राशि का योग किया जाता है। विपणन-मध्यस्थों की क्रय-विक्रय कीमत का अन्तर उन्हें प्राप्त होने वाले विपणन-लाभ की राशि का प्रतीक होता है, जो निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है—

$$\text{वस्तु की प्रति इकाई मात्रा पर} = \frac{\text{वस्तु की विक्रय-कीमत} - \text{वस्तु की क्रय-कीमत}}{\text{विपणन-लाभ की राशि}} \quad \text{वस्तु की विक्रीत मात्रा}$$

उपर्युक्त सूत्र द्वारा विपणन-कार्य में लगी हुई विभिन्न-संस्थाओं का प्रति इकाई उत्पाद की मात्रा के लिए प्राप्त औसत लाभ ज्ञात कर लिया जाता है। सभी विपणन-संस्थाओं को प्राप्त प्रति इकाई लाभ की राशि को सम्मिलित करने पर उत्पाद के उत्पादक से अन्तिम उपभोक्ता तक पहुँचाने में प्राप्त होने वाले कुल विपणन-लाभ की राशि ज्ञात हो जाती है। विपणन-लाभ ज्ञात करने की इस विधि में प्रमुख कठिनाई वस्तुओं की क्रय-विक्रय कीमत के सही आकड़े प्राप्त नहीं होने की है। विपणन-मध्यस्थ साधारणतया सूचना देने को तैयार नहीं होते हैं। अतः आवश्यक प्राकड़ों के अभाव में हम विधि में विभिन्न वस्तुओं के विक्रय में होने वाले लाभ की राशि के सही ज्ञान का कार्य कठिन होता है।

(3) विभिन्न विपणन-संस्थाओं के स्तर पर उत्पाद की कीमतों का तुलनात्मक अध्ययन करके—विपणन-लाभ ज्ञात करने की इस विधि में विपणन कार्य में लगी हुई विभिन्न विपणन संस्थाओं के स्तर पर एक इकाई उत्पाद की मात्रा के लिए दी जाने वाली कीमतों का अन्तर ज्ञात किया जाता है, जैसे—उत्पादक व थोक विप्रेता के स्तर पर कीमतों का अन्तर, थोक व्यापारी एवं खुदरा व्यापारी के स्तर पर कीमतों का अन्तर, खुदरा व्यापारी एवं उपभोक्ता के स्तर पर कीमतों का अन्तर आदि। इस प्रकार विभिन्न विपणन-संस्थाओं के स्तर पर कीमतों में पाये जाने वाले अन्तर का योग, उस वस्तु के विक्रय में होने वाले विपणन-लाभ की राशि को प्रदर्शित करता है। विपणन-लाभ ज्ञात करने की यह विधि साधारणतया अधिक उपयोग में लाई जाती है क्योंकि इस विधि के लिए आवश्यक आकड़े मण्डी से एकत्रित करने का कार्य सरल होता है।

विपणन-मध्यस्थों की लागत एवं उसका माँग की लोच से सम्बन्ध—वस्तुओं की माँग की लोच में विभिन्नता के कारण फार्म पर उत्पन्न उत्पाद के विप्रेत से प्राप्त कृषकों की आय पर प्रभाव पड़ता है। किसी वस्तु की माँग की लोच के कम होने अथवा निरपेक्ष होने की अवस्था में यदि वस्तु के उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है, तो वस्तु की बाजार कीमत/खुदरा कीमत में गिरावट आती है जिससे कृषकों को प्राप्त कीमत (फार्म-कीमत) में भी गिरावट आती है। लेकिन, फार्म-कीमत में

गिरावट, बाजार-कीमत में आने वाली गिरावट की अपेक्षा अधिक होती है। इसी प्रकार वस्तु की माग के निरपेक्ष होने की अवस्था में यदि उत्पादन की मात्रा कम प्राप्त होती है तो बाजार-कीमत में वृद्धि होने के साथ-साथ फार्म-कीमत में वृद्धि बाजार-कीमत की अपेक्षा अधिक होती है। इसका प्रमुख कारण विपणन-मध्यस्थों की लागत की राशि का समान रहना है।

बाजार कीमत में होने वाली कीमतों में गिरावट अथवा वृद्धि का प्रभाव विपणन-मध्यस्थों एवं कृषकों में समान राशि अथवा समान अनुपात में वितरित नहीं होता है। कीमतों में वृद्धि अथवा कमी की दोनों ही अवस्थाओं में विपणन-लागत की राशि लगभग स्थायी रहती है। उपरोक्त-कीमत में विपणन-मध्यस्थों की प्रतिशतता का भ्रम कीमतों में कम होने पर बढ़ जाता है। विपणन-मध्यस्थों की लागत की राशि के स्थायी होने के कारण वस्तुओं की माग की लोच फार्म स्तर पर खुदरा बाजार कीमत स्तर की अपेक्षा कम होती है। उपर्युक्त सम्बन्ध निम्न उदाहरण की सहायता से अधिक स्पष्ट हो जाता है—

उदाहरण के तौर पर यदि वर्तमान में वस्तु की बाजार में प्रचलित कीमत 1 00 रु० प्रति इकाई तथा प्राप्त कीमत में 50 प्रतिशत उत्पादक को एवं शेष 50 प्रतिशत विपणन-मध्यस्थों को प्राप्त होता है। वस्तु की बाजार कीमत में 20 प्रतिशत की कमी तथा विपणन मध्यस्थों की लागत की राशि समान रहने की स्थिति में फार्म कीमत में गिरावट का प्रतिशत सारणी 14.1 में प्रदर्शित है।

सारणी 14.1

बाजार कीमत में कमी का फार्म कीमत पर प्रभाव

	वर्तमान प्रचलित कीमत		बाजार कीमत में 20 प्रतिशत कमी		कीमतों में प्रतिशत कमी
	रु०	बाजार कीमत का प्रतिशत	प्रचलित कीमत (रु०)	बाजार कीमत का प्रतिशत	
फार्म-कीमत	0.50	50	0.30	37.50	-40
विपणन					
लागत	0.50	50	0.50	62.50	—
बाजार कीमत	1.00	100	0.80	100.00	-20

यदि वस्तु की प्रचलित बाजार कीमत में 20 प्रतिशत की कमी होती है तो फार्म कीमत में कमी, बाजार कीमत की अपेक्षा अधिक अर्थात् 40 प्रतिशत की होती है। बाजार कीमत में फार्म कीमत का भ्रमदान 50 प्रतिशत से गिरकर 37.50 प्रतिशत ही रह जाता है। बाजार कीमत में गिरावट की स्थिति में भी विपणन-

मध्यस्थों की लागत राशि रूपों के रूप में समान रहती है, लेकिन बाजार-कीमत में विपणन-मध्यस्थों की लागत का अंशदान 50 प्रतिशत से बढ़कर 62.50 प्रतिशत हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि बाजार कीमत में परिवर्तन का प्रभाव उत्पादक एवं विपणन-मध्यस्थों की लागत के ऊपर समान राशि अथवा अनुपात में नहीं होता है जिसका कारण फार्म एवं खुदरा बाजार में वस्तुओं की भाग की लोच का समान नहीं होना है। विपणन प्रक्रिया में विपणन-लागत के स्थायी रहने के प्रमुख कारण निम्न हैं—

1. अनेक विपणन लागतें, जैसे—परिवहन, संग्रहण, प्रोसेसिंग, चुंबी, मजदूरी आदि वस्तु की भौतिक मात्रा के आधार पर देय होती है। इन लागतों का वस्तु के मूल्य से सम्बन्ध नहीं होता है, जिसके कारण कीमतों में वृद्धि अथवा गिरावट का विपणन-मध्यस्थों की लागत पर प्रभाव नहीं आता है।
2. विपणन-मध्यस्थों की लागत के स्थायी रहने का दूसरा कारण विपणन-प्रक्रिया में कार्य करने वाले विपणन-मध्यस्थों का एकाधिकार अर्थात् उनमें परस्पर एकता का पाया जाना है।

विपणन-लाभ के प्रकार—विपणन-लाभ दो प्रकार के होते हैं :

(1) **समवर्ती विपणन-लाभ (Concurrent Marketing Margin)**—समवर्ती विपणन-लाभ एक निश्चित दिनांक के लिए ज्ञात किया जाता है जो विभिन्न विपणन-मध्यस्थों के स्तर पर एक निश्चित दिनांक के लिए प्रचलित कीमतों का अन्तर होता है। समवर्ती विपणन-लाभ में वस्तुओं के क्रय-विक्रय में समय के अन्तर को जो संग्रहण, परिवहन या अन्य कारणों से होता है, सम्मिलित नहीं किया जाता है। विपणन-लाभ की राशि निश्चित समय-बिन्दु को प्राप्त होने वाले लाभ का घातक होती है।

(2) **पश्चाद्य विपणन-लाभ (Lagged Marketing Margin)**—पश्चाद्य विपणन-लाभ से तात्पर्य उस लाभ की राशि से है जो विपणन की दो विभिन्न अवस्थाओं में उत्पाद की कीमतों के अन्तर से प्राप्त होता है। इस विपणन-लाभ में विभिन्न विपणन-प्रक्रिया में समयान्तर के कारण कीमतों में परिवर्तन होने से प्राप्त होने वाला लाभ भी सम्मिलित होता है। यह विपणन-लाभ की राशि औसत विपणन समय में प्राप्त होने वाले लाभ की प्रतीक होती है।

क्रय-विक्रय में समयान्तर वाली वस्तुओं का विपणन-लाभ ज्ञात करने के लिए पश्चाद्य विपणन-लाभ विधि सर्वोत्तम होती है, लेकिन समयान्तर-काल पर विपणन-प्रक्रिया के तुलनात्मक आकड़े प्राप्त करने का कार्य कठिन होता है। अतः समवर्ती विपणन-लाभ ही अधिकतर ज्ञात किया जाता है।

विपणन-लाभ से सम्बन्धित शब्द—विपणन-लाभ से सम्बन्धित प्रमुख शब्दों की परिभाषा निम्नलिखित है—

1. उत्पादक कीमत—कृषको को मण्डी में खाद्यपदार्थों के विक्रय से प्राप्त होने वाली कीमत में से उनके द्वारा व्यय की गई विपणन-लागत की राशि घटाने पर जो कीमत शेष रहती है, वह उत्पादक कृषक को वस्तु की एक इकाई मात्रा के विक्रय से प्राप्त शुद्ध कीमत अर्थात् उत्पादक कीमत (*Producer's price*) कहलाती है। सूत्र के अनुसार—

$$P_o = P_s - C_o \quad \text{जबकि } P_o = \text{उत्पादक कीमत}$$

$$P_s = \text{कृषको को मण्डी में प्राप्त कीमत}$$

$$C_o = \text{कृषको की विपणन-लागत, जैसे—परिवहन, ग्राहक, कर, बुर्गी, फलेदारी, तुलाई आदि की लागत।}$$

2. उपभोक्ता द्वारा दिये गये रुपये में से उत्पादक कृषक को प्राप्त भाग—उपभोक्ता द्वारा वस्तु के लिए दिये गये रुपये में से कृषको को प्राप्त होने वाला भाग, उपभोक्ता के रुपये में उत्पादक का भाग (*Producer's share in the Consumer's rupee*) कहलाता है। यह साधारणतया प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है। इसको ज्ञात करने के लिए उत्पादक को वस्तु की एक इकाई मात्रा के लिए प्राप्त कीमत में, वस्तु की उसी इकाई मात्रा के लिए उपभोक्ता द्वारा दी गई कीमत का भाग देते हैं और प्राप्त अनुपात को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है। सूत्र के अनुसार—

$$\frac{P_o}{P_c} \times 100 \quad \text{जबकि } P_o = \text{वस्तु की एक इकाई के लिए उत्पादक कृषक को प्राप्त कीमत।}$$

$$P_c = \text{वस्तु की एक इकाई के लिए उपभोक्ता द्वारा दी गई कीमत।}$$

3. निरपेक्ष लाभ—विपणन-मध्यस्थों को विपणन-प्रक्रिया में प्राप्त होने वाले शुद्ध लाभ की राशि को निरपेक्ष लाभ (*Absolute margin*) कहते हैं। वस्तु की एक निश्चित मात्रा की विक्रय-कीमत में से उसकी क्रय-कीमत एवं मध्यस्थ द्वारा की गई विपणन लागत की राशि बाकी निकालने पर जो कीमत शेष रहती है वह विपणन-मध्यस्थ को प्राप्त होने वाला निरपेक्ष लाभ कहलाता है। यह लाभ की राशि प्रति क्विन्टल मात्रा पर रुपये में प्रदर्शित की जाती है। सूत्र के अनुसार—

$$\text{निरपेक्ष लाभ} = P_s - (P_b + C_m) \quad \text{जबकि } P_s = \text{वस्तु की विक्रय-कीमत}$$

$$P_b = \text{वस्तु की क्रय-कीमत}$$

$$C_m = \text{वस्तु की विपणन-लागत}$$

4. प्रतिशत लाभ—विपणन-मध्यस्थों को प्राप्त होने वाले निरपेक्ष लाभ की राशि में वस्तु की विक्रय-कीमत का भाग देने पर प्राप्त अनुपात को प्रतिशत में

प्रदर्शित करने पर जो सख्या आती है, वह विपणन-म-स्थ को प्राप्त होने वाला प्रतिशत लाभ (Percentage margin) कहलाता है। विभिन्न वस्तुओं के विपणन में विपणन-मध्यस्थों को प्राप्त होने वाले लाभ के तुलनात्मक अध्ययन के लिए प्रतिशत लाभ का उपयोग किया जाता है। सूत्र के अनुसार—

$$\begin{aligned}\text{प्रतिशत लाभ} &= \frac{\text{निरपेक्ष लाभ की राशि}}{\text{वस्तु की विक्रय कीमत}} \times 100 \\ &= \left[\frac{P_s - (P_b + C_m)}{P_s} \times 100 \right]\end{aligned}$$

5. वद्धित मूल्य—विपणन मध्यस्थों को प्राप्त होने वाले निरपेक्ष लाभ की राशि में वस्तु की क्रय-कीमत का भाग देने पर प्राप्त अनुपात को प्रतिशत में प्रदर्शित करने पर जो सख्या आती है वह विपणन-मध्यस्थ को प्राप्त होने वाला वद्धित-मूल्य (Mark-up) कहलाता है। सूत्र के अनुसार—

$$\begin{aligned}\text{वद्धित मूल्य} &= \frac{\text{निरपेक्ष लाभ की राशि}}{\text{वस्तु की क्रय-कीमत}} \times 100 \\ &= \left[\frac{P_s - (P_b + C_m)}{P_b} \times 100 \right]\end{aligned}$$

वद्धित मूल्य माद्वारणतया अखाद्य वस्तुओं के व्यापार में लाभ ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निम्न उदाहरण निरपेक्ष लाभ, प्रतिशत लाभ एवं वद्धित मूल्य ज्ञात करने की विधि स्पष्ट करते हैं।

उदाहरण—एक खुदरा व्यापारी मण्डी में 280.00 प्रति क्विन्टल की दर से गेहूँ क्रय करता है और गेहूँ के क्रय में 10.00 रु. प्रति क्विन्टल लागत आती है। वह 300.00 रु. प्रति क्विन्टल की दर से उपभोक्ताओं को गेहूँ विक्रय करता है। खुदरा विक्रेता का निरपेक्ष लाभ, प्रतिशत लाभ एवं वद्धित मूल्य ज्ञात कीजिये।

$$\begin{aligned}\text{निरपेक्ष लाभ} &= \text{विक्रय कीमत} - (\text{क्रय-कीमत} + \text{विपणन लागत}) \\ &= 300 - (280 + 10) \\ &= 10.00 \text{ रु० प्रति क्विन्टल}\end{aligned}$$

$$\text{प्रतिशत लाभ} = \frac{\text{निरपेक्ष लाभ की राशि}}{\text{विक्रय कीमत}} \times 100 = \frac{10}{300} \times 100 = 3.33$$

प्रतिशत।

$$\text{वद्धित मूल्य} = \frac{\text{निरपेक्ष लाभ की राशि}}{\text{क्रय-कीमत}} \times 100 = \frac{10}{280} \times 100$$

$$= 3.57 \text{ प्रतिशत}$$

वद्धित मूल्य, प्रतिशत लाभ की अपेक्षा अधिक होता है।

6 कीमत-विस्तार—उपभोक्ता द्वारा दिये गये रुपये में से विभिन्न विपणन-संस्थाओं को प्राप्त होने वाली राशि का विश्लेषण कीमत-विस्तार (Price-spread) कहलाता है। उदाहरणतया यदि उपभोक्ता वस्तु की एक इकाई मात्रा के लिए 2.00 रु० कीमत भुगतान करता है तथा उपभोक्ता द्वारा दी गई कीमत में से खुदरा विक्रेता को 30 पैसे, थोक विक्रेता को 10 पैसे, परिवहन संस्था को 10 पैसे, आडिनिये को 20 पैसे और शेष 1 30 रुपया कृपक का प्राप्त होता है, तो कीमत विस्तार निम्न होता है—

संस्था	उपभोक्ता द्वारा दी गई कीमत में से कृपक एवं विभिन्न मध्यस्थों को प्राप्त अंश (रु०)	कृपक एवं विभिन्न मध्य- स्थों की उपभोक्ता कीमत में प्राप्त प्रतिशत अंश
खुदरा विक्रेता	0.30	15
थोक विक्रेता	0.10	5
परिवहन संस्था	0.10	5
आडिनिया	0.20	10
कृपक	1.30	65
कुल	2.00	100

विभिन्न वस्तुओं के विषय में होने वाली विपणन लागत एवं लाभ—विभिन्न कृषि-वस्तुओं के विषय में होने वाली विपणन-लागत एवं लाभ की राशि विभिन्न कारकों के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। विपणन-लागत एवं लाभ की राशि बढ़ने तथा घटने के साथ उत्पादक को प्राप्त कीमत का प्रतिशत भी कम या अधिक होता जाता है। सारणी 14 2 में विभिन्न कृषि-वस्तुओं (गेहूँ, अण्डे एवं सेब) के विपणन में उत्पादक कृपकों को प्राप्त हिस्सा, विपणन-लागत एवं विपणन-लाभ का प्रतिशत विभिन्न विपणन-माध्यमों के अनुसार संचित विधि में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 14.2

विभिन्न कृषि-वस्तुओं के विपणन में उत्पादक कीमत, विपणन-लागत व
विपणन-लाभ का प्रतिशत

विपणन-माध्यम	उत्पादक कीमत	विपणन लागत	विपणन लाभ	विपणन लागत व एव लाभ का योग	उपभोक्ता द्वारा दी गई कीमत
		गेहूँ			
1. उत्पादक-उपभोक्ता	94.8	5.2	—	5.2	100.0
2. उत्पादक-खुदरा विक्रेता-उपभोक्ता	89.7	6.0	4.3	10.3	100.0
3. उत्पादक-सहकारी विपणन संस्था- खुदरा विक्रेता- उपभोक्ता	87.3	6.2	6.5	12.7	100.0
4. उत्पादक-थोक विक्रेता-खुदरा विक्रेता-उपभोक्ता	86.6	7.6	5.8	13.4	100.0
5. उत्पादक-ग्रामीण व्यापारी-थोक- विक्रेता-खुदरा विक्रेता-उपभोक्ता	85.5	7.3	7.2	14.5	100.0
		मूँडे			
1. उत्पादक-उपभोक्ता	98.96	1.04	—	1.04	100.0
2. उत्पादक-खुदरा विक्रेता-उपभोक्ता	81.81	4.65	13.54	18.19	100.0
3. उत्पादक-सहकारी विपणन संस्था- थोक विक्रेता दिल्ली-उपभोक्ता	66.66	19.91	13.43	33.34	100.0

4 उत्पादक-सहकारी विपणन संस्था- थोक विक्रेता बम्बई-उपभोक्ता	60 25	24 65	15 10	39 75	100 11
5 उत्पादक-बड़े शहर का थोक विक्रेता-खुदरा विक्रेता-उपभोक्ता	84 07	7 83	8 10	15 93	100 0
6 उत्पादक थोक एवं खुदरा विक्रेता-उपभोक्ता	81 81	7 33	10.86	18 19	100 0
		सेब			
1 शिमला (हिमाचल प्रदेश) मण्डी में विक्रय करने पर	49 80	27 36	22 84	50 20	100 0
2 दिल्ली मण्डी में विक्रय करने पर	49 75	29 93	20 32	50 25	100 0
3 कलकत्ता मण्डी में विक्रय करने पर	45 92	30 76	23 32	54 08	100 0
4 मद्रास मण्डी में विक्रय करने पर	43 00	31 33	25 67	57 00	100 0
5 बम्बई मण्डी में विक्रय करने पर	44 15	29 29	26 56	55 85	100 0

स्रोत (1) Agricultural Research—A Review . op cit, pp 8-9

(2) D S Thakur Pricing Efficiency of the Indian Apple Market, Indian Journal of Agricultural Economics, Vol XXVIII, No 1, January-March, 1973, pp 105-111

गेहूँ राजस्थान में गेहूँ के विपणन अध्ययन के अनुसार, गेहूँ का उत्पादक से उपभोक्ता तक संचलन या प्रवाह पाँच विपणन-मध्यस्थों के द्वारा होता है। उत्पादक कृषकों द्वारा उपभोक्ताओं को सीधे रूप में गेहूँ विक्रय करने पर उपभोक्ता कीमतों में उन्हें सबसे अधिक भ्रष्ट प्राप्त होता है। विपणन के इस माध्यम में मध्यस्थ नहीं होने के कारण विपणन लाभ की राशि शून्य होती है। उत्पादक कृषक को सबसे कम भ्रष्ट पाचवें विपणन माध्यम में प्राप्त होता है क्योंकि इसमें तीन विपणन-मध्यस्थ—ग्रामीण व्यापारी, थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता होते हैं, जिनके कारण

विपणन-लाभ एवं लागत की राशि अधिक आती है। अतः गेहूँ के विपणन में उत्पादक कृषक को उपभोक्ता द्वारा दी गई कीमत का 86 से 95 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है और शेष 5 से 14 प्रतिशत भाग विपणन लागत एवं लाभ होता है।

ग्रण्ड राजस्थान के अजमेर जिले में ग्रण्डों के विपणन में 6 विपणन-मा पर राय गये हैं। उत्पादकों द्वारा ग्रण्डों को उपभोक्ताओं को सीधे विक्रय करने पर उपभोक्तों द्वारा दी गई कीमत का 99 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। थोक एवं खुदरा विक्रेता के माध्यम (विपणन-माध्यम 2, 5, 6) से विक्रय करने पर उत्पादकों को 82 से 84 प्रतिशत अंश ही प्राप्त होता है। ग्रण्डों को अजमेर से दिल्ली एवं बम्बई के शहरों में भेजकर विक्रय करने पर उत्पादकों को उपभोक्ता कीमत का लगभग दो तिहाई भाग ही प्राप्त होता है। अतः विपणन-माध्यमों में वृद्धि एवं दूर के शहरों में विपणन के लिए ग्रण्डों की मितरान में विपणन-लागत एवं लाभ की राशि में वृद्धि होती है और उत्पादक का उपभोक्ता की कीमत में से अंश कम होता जाता है।

मेव, हिमाचल प्रदेश में किये गये अध्ययन के अनुसार सेव के विक्रय में 50 से 57 प्रतिशत विपणन-लागत एवं लाभ की राशि होती है और उत्पादकों को उपभोक्ता कीमत में से आधे से भी कम भाग प्राप्त होता है। सेव के विक्रय में लगभग 30 प्रतिशत विपणन-लागत एवं 20 से 27 प्रतिशत विपणन-माध्यमों का लाभ होता है। अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि दूर की मण्डियों में स्थानीय मण्डियों की अपेक्षा अधिक कीमत प्राप्त होती है। शीघ्र तराब होने वाली वस्तुओं में विपणन-लागत एवं लाभ की अधिकता के कारण उत्पादक को उपभोक्ता की कीमत में प्राप्त प्रतिशत अंश कम होता है।

कृषि वस्तुओं के विपणन में होने वाली विपणन लागत व प्राप्त विपणन-लाभ को कम करने के उपाय—कृषि वस्तुओं के विपणन में औद्योगिक वस्तुओं की प्रवेक्षा प्रति इकाई विपणन-लाभ एवं लागत की राशि अधिक आती है जिससे विपणन-क्षमता कम हो जाती है। निम्न उपायों द्वारा कृषि-वस्तुओं के विपणन में होने वाले विपणन-लाभ एवं लागत की राशि को कम किया जा सकता है—

(1) विपणन संस्थानों को प्राप्त होने वाले लाभ की राशि को कम करना—कृषि-वस्तुओं के व्यवसाय में विपणन-संस्थानों को औद्योगिक वस्तुओं की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त होता है, जिसे निम्न प्रकार से कम किया जा सकता है—

(अ) विपणन-प्रक्रिया की जोखिम कम करके—कृषि-वस्तुओं की विपणन-प्रक्रिया में जोखिम की अधिकता के कारण विपणन-संस्थाएँ लाभ अधिक प्राप्त करती हैं। अतः विपणन-संस्थाओं को प्राप्त होने वाले लाभ की राशि को कम करने के लिए सर्वप्रथम विपणन-प्रक्रिया में होने वाली जोखिम को कम करना आवश्यक है जो अग्राजित प्रियियों द्वारा की जा सकती है—

- (i) सरलण विधि द्वारा ।
- (ii) मण्डो में समय-समय पर निरीक्षण एवं निम्न-मूल्य के उपाय अपना कर ।
- (iii) विपणन-मूचना सेवा के विस्तार द्वारा ।
- (iv) वस्तुओं के श्रेणीबद्धन एवं मानकीकरण सेवा का विस्तार करके ।
- (v) व्यवसाय प्रबन्ध क्षमता में वृद्धि करके ।

(ब) बाजार में नये विक्रय के लिए पूर्ण स्पर्धा की स्थिति उत्पन्न करना— वस्तुओं के क्रय-विक्रय में पूर्ण प्रतिस्पर्धा के नहीं होने पर व्यापारी न्यूनतम कीमतों पर क्रय करके एवं अधिकतम कीमतों पर विक्रय करके अधिक लाभ कमाता है। अतः विपणन संस्थाओं को प्राप्त होने वाले प्रतिरिक्त लाभ की राशि को कम करने के लिए बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा का होना आवश्यक है। बाजार में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के लिए एकाधिकार पद्धति की समाप्ति, के।एम। एवं विक्रेताओं को आवश्यक मूचना प्रदान करना एवं मण्डो में क्रेताओं एवं विक्रेताओं पर किसी प्रकार की पाबन्दी का होना आवश्यक है।

(स) विपणन-संस्थाओं की तकनीकी दक्षता में वृद्धि करके—विपणन-प्रक्रिया की विधियों में तकनीकी सुधार करके भी विपणन-लागत को कम किया जा सकता है। जैसे—शीघ्रताशी वस्तुओं के मण्डल के लिए प्रशीतन-सुविधा, प्रोमिसिंग विधि में तकनीकी आविष्कार, मण्डल में सहज एवं प्रसूत्र आवरण की खोज, तुलार्ई में यन्त्रीकृत काटे का प्रयोग, द्रुतगामी परिवहन साधनों के विकास द्वारा परिवहन-सागत में कमी करना आदि। विपणन-सागत की राशि के कम होने पर विपणन-लाभ की राशि स्वतः ही कम हो जाती है।

(2) विपणन-मध्यस्थों के एकीकरण द्वारा—कृपि वस्तुओं की विपणन-प्रक्रिया में विपणन-मध्यस्थों की अधिकता के कारण भी विपणन-लाभ एवं सागत अधिक होती है जिसे विपणन-मध्यस्थों के एकीकरण द्वारा कम किया जा सकता है। विपणन के क्षेत्र में एकीकरण दो प्रकार का होता है—

(अ) उदग्र एकीकरण—वस्तुओं के उत्पादक से उपभोक्ता तक संचालन प्रक्रिया में पाये जाने वाले विपणन-मध्यस्थों की संख्या को कम करने को उदग्र एकीकरण (Vertical integration) कहते हैं। सुपर बाजार, सहकारी-विपणन-संस्थाएँ एवं छाद्य-निगम स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य विपणन के क्षेत्र में पाये जाने वाले मध्यस्थों की संख्या को कम करना है। ये विपणन-संस्थाएँ उत्पादक से वस्तुओं को क्रय करके सीधे रूप में या उचित कीमत की दुकानों के द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुँचाती हैं जिससे विपणन-प्रक्रिया में विपणन-मध्यस्थों की संख्या में कमी होती

है। विपणन-मध्यस्थों की सख्या के कम होने पर वस्तुओं की विपणन-लागत एवं लाभ की राशि कम हो जाती है।

(व) क्षैतिज एकीकरण—क्षैतिज एकीकरण (Horizontal Integration) के अन्तर्गत विभिन्न छोटे छोटे विपणन-मध्यस्थ सम्मिलित होकर एक बड़ी विपणन-संस्था बनाते हैं। सभी मध्यस्थ एक प्रबन्ध के अन्तर्गत कार्य करते हैं और व्यवसाय के लिए विभिन्न स्थानों पर शाखाएँ स्थापित करते हैं। इस प्रकार उपलब्ध साधनों से पहुँच की अपेक्षा अधिक मात्रा में वस्तुओं का त्रय विक्रय किया जा सकता है। वस्तुओं के व्यवसाय के बढ़ने से प्रति इकाई विपणन-लागत कम हो जाती है।

(3) विपणन-प्रक्रिया में मध्यस्थों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में कमी करके—वस्तुओं के विपणन में होने वाली विपणन-लागत को कम करने का अन्य उपाय विपणन-मध्यस्थों द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाले सुविधाओं को कम करना है। विपणन में दी जाने वाली कुछ सेवाओं को घासानी से कम किया जा सकता है जैसे—उपभोक्ताओं को सामान पसन्द नहीं आने पर लौटाने की सुविधा, विक्रेताओं की सख्या में कमी, वस्तुओं की उधार-विक्रय पद्धति की समाप्ति, वस्तुओं की विज्ञापन लागत में कमी, संवेष्टन में सस्ते धावरण का उपयोग, वस्तुओं को उपभोक्ताओं के घर तक पहुँचाने की सुविधा समाप्त करके, विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को ठण्डे पेय आदि पर किये जाने वाले व्यय आदि।

(4) मण्डियों को नियन्त्रित करना एवं नियन्त्रित मण्डियों में विभिन्न विपणन-सेवाओं के लिए विपणन-लागत की दर निर्धारित करना।

(5) स्थान-स्थान पर उपभोक्ता मण्डल स्थापित करना, जहाँ से उपभोक्ताओं को निर्धारित दर पर वस्तुएँ उपलब्ध हो सकें।

(6) सरकार द्वारा विपणन-कार्य में हस्तक्षेप करना—आवश्यकता होने पर विक्रय-पद्धति पर नियन्त्रण लगाने, वस्तुओं की अधिकतम व न्यूनतम कीमतें निर्धारित करने, निर्धारित कानूनों का उल्लंघन करने वालों को कानूनन दण्ड देने की व्यवस्था करने से भी वस्तुओं के जमाखोरी द्वारा प्राप्त अधिक लाभ की राशि को कम किया जा सकता है।

विपणन-दक्षता

वस्तुओं को उत्पादक कृषकों से उपभोक्ताओं तक अधिकतम विपणन सेवाओं को प्राप्त कराते हुए कम से कम विपणन-लागत पर पहुँचाने की विधि को विपणन-

दक्षता कहते हैं। श्रीनारी जसदानवाला¹ के अनुसार विपणन-दक्षता से तात्पर्य किसी विपणन-संरचना द्वारा निर्धारित कार्यों को दक्षता पूर्ण करना है। क्लार्क एवं वेल्ड² ने विपणन दक्षता में निम्नांकित तीन अवयवों का होना आवश्यक बताया है—

- (i) दक्षता, जिससे विपणन सेवाएँ पूरी की जाती हैं।
- (ii) विपणन सेवाएँ न्यूनतम लागत पर प्रदान करना।
- (iii) विपणन सेवाएँ प्रदान करने एवं विपणन-चामत का उत्पादन एवं उपभोग पर होने वाला प्रभाव।

अनन्तनारायणन³ के शब्दों में विपणन दक्षता से तात्पर्य कृषि-वस्तुओं का कम से कम लागत पर विपणन करने से है जिससे उत्पादक कृषकों को उपभोक्ता के रुपये में से अधिकतम भाग प्राप्त हो सके। कोल्स एवं उल्स⁴ के शब्दों में विपणन-दक्षता से तात्पर्य प्रयुक्त उत्पादन-साधन एवं प्राप्त उत्पाद के अनुपात को अधिकतम करने से होता है। विपणन के क्षेत्र में उत्पादन-साधनों से तात्पर्य विपणन संस्थाओं द्वारा व्यवसाय में काम में ली गई पूँजी, श्रम एवं प्रबन्ध की लागत से तथा उत्पाद से तात्पर्य वस्तुओं एवं सेवाओं से उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाले सन्तोष से है। अतः विपणन-दक्षता के अध्ययन के लिए विपणन-लागत एवं वस्तुओं से प्राप्त सन्तोष का ज्ञान होना आवश्यक है। विपणन-लागत राशि को ज्ञात करना सरल है, लेकिन उत्पाद से प्राप्त सन्तोष को मुद्रा के रूप में प्रकट करने का कार्य कठिन एवं प्रायोगिक नहीं है क्योंकि सन्तोष एक संज्ञानिक धारणा है। अतः विपणन-दक्षता को सही रूप से ज्ञात करने का कार्य कठिन है।

- 1 Marketing efficiency may be defined broadly as the effectiveness or competence with which a marketing structure performs its designed functions.

—Z. Y. Zeddanwalla, *Marketing Efficiency in Indian Agriculture*, Allied Publishers Pvt Ltd, Bombay, 1966 p 3

- 2 F. B. Clark and L. D. H. Weld, *Marketing of Agricultural Products in the United States*, The Macmillan Company, New York, 1950.

- 3 Marketing efficiency can be defined as marketing of agricultural produce with minimum cost ensuring the maximum share for the producers in the consumers rupee.

—V. P. Anantanarayana, *Reduction of Marketing Cost and Increasing Efficiency with Special Reference to Grading at Producer's Level*, Seminar on Emerging Problems of Marketing of Agricultural Commodities, Indian Society of Agricultural Economics, Bombay, 1972, p 110.

4. Marketing efficiency in the Maximization of input-output ratio

—R. L. Kohls & J. N. Uhl, op. cit.,

विपणन-लागत के अध्ययन के आधार पर ही विपणन-दक्षता का आकलन उचित नहीं है। कृषको द्वारा फार्म पर वस्तुओं को ग्रामीण व्यापारी को विक्रय करने पर विपणन-लागत सबसे कम आती है। इस विपणन-क्रिया को दक्ष विपणन क्रिया नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फार्म पर उत्पाद के विचय से प्रतिस्पर्धा के अभाव में कृषको को उचित कीमत प्राप्त नहीं होती है, जिसके कारण सन्तोष कम प्राप्त होता है। विपणन-दक्षता के लिए विभिन्न मण्डियों में प्रचलित कीमतों एवं विपणन-लागत के ज्ञान के अतिरिक्त उपभोक्ताओं की मण्डियों में दी जाने वाली सेवाओं का ज्ञान भी होना आवश्यक है। विपणन सेवाओं के समान स्तर पर उपलब्ध होते हुए, विपणन-लागत में कमी, विपणन-दक्षता की द्योतक होती है। उदाहरण के लिए भारत में गेहूँ के विपणन में प्रति इकाई विपणन-लागत अमेरिका एवं अन्य देशों से कम आती है। इससे यह तात्पर्य नहीं है कि भारत में मण्डियाँ गेहूँ के विक्रय में अमेरिका की मण्डियों की अपेक्षा अधिक दक्ष हैं, बल्कि इसका कारण भारत में गेहूँ का विपणन उत्पादित रूप में ही अधिक होता है जबकि अमेरिका में गेहूँ का विपणन परिष्कृत (Processed) अर्थात् आटा, बिस्कुट, डबल रोटी आदि के रूप में अधिक होता है।

विपणन-दक्षता के प्रकार— विपणन दक्षता दो प्रकार की होती है :

(i) तकनीकी/कार्यात्मक दक्षता—उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली विपणन सेवाओं की विधियों में तकनीकी ज्ञान की सहायता से विपणन-लागत को कम करने की विधि तकनीकी दक्षता या कार्यात्मक दक्षता कहलाती है, जैसे—परिवहन के लिए बैलगाड़ियों के स्थान पर ट्रक अथवा ट्रैक्टर का उपयोग, जुताई के लिए हाथ के कांटे के स्थान पर स्वचालित तोलने की मशीन का उपयोग आदि। तकनीकी दक्षता से विपणन-लागत की राशि में कमी होती है।

(ii) कीमत/आर्थिक दक्षता—कीमत-दक्षता से तात्पर्य विपणन की उन विधियों में सुधार करने से है जिनके द्वारा उत्पाद की अधिकतम कीमत प्राप्त होवे या उसी उत्पादन स्तर को प्राप्त करने में लागत कम आवे। आर्थिक दक्षता, विपणन-सूचना-सेवा, श्रेणीचयन, विक्रय में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करके तथा उचित समय तक वस्तुओं को सशुद्धीत करके प्राप्त की जा सकती है। आर्थिक दक्षता भी कृषको को उपभोक्ता द्वारा दिये गये रुपये में से प्राप्त भाग की वृद्धि करने में सहायक होती है।

विपणन-दक्षता ज्ञात करने की विधियाँ—विपणन-दक्षता ज्ञात करने की निम्न तीन विधियाँ हैं⁵—

(1) प्रथम विधि में विपणन-दक्षता ज्ञात करने का सूत्र अग्रलिखित है—

$$\text{विपणन-दक्षता (प्रतिशत)} = \frac{\text{वस्तुओं के विपणन की कुल लागत}}{\text{विक्रय की गई वस्तुओं का कुल मूल्य}} \times 100$$

इस सूत्र की सहायता से विभिन्न मण्डियों की विपणन-दक्षता ज्ञात की जाती है। जिस मण्डी की विपणन-दक्षता का प्रतिशत अधिक होता है, वह मण्डी वस्तु के विक्रय के लिए दूसरी मण्डी की अपेक्षा अदक्ष कहलाती है। उपर्युक्त सूत्र के अनुसार विपणन-लागत में वृद्धि अथवा वस्तुओं के कुल मूल्य में कमी होने पर विपणन-दक्षता कम हो जाती है। वस्तुओं की सेवाओं में वृद्धि के कारण विपणन-लागत में वृद्धि अथवा कीमतों में गिरावट के कारण वस्तुओं के कुल मूल्य में कमी होना विपणन-पद्धति की अदक्षता का चोटक नहीं होता है।

(2) दूसरी विधि में विपणन-दक्षता ज्ञात करने का सूत्र निम्न है :

विपणन-दक्षता (प्रतिशत)

$$= \frac{\text{विपणन प्रक्रिया द्वारा वस्तुओं के मूल्य में हुई वृद्धि की राशि}}{\text{विपणन सेवाओं की कुल लागत}} \times 100$$

इस सूत्र के अनुसार जिस मण्डी की प्रतिशत विपणन दक्षता अधिक होती है, वह मण्डी दूसरी मण्डी की अपेक्षा दक्ष होती है। कुल विपणन-लागत ज्ञात करते समय सभी विपणन-संस्थाओं की लागत सम्मिलित की जाती है।

उदाहरण—प्राप्त विपणन सम्बन्धी निम्न आंकड़ों से 'अ' व 'ब' मण्डियों की विपणन-दक्षता ज्ञात कीजिए।

विवरण	मण्डी 'अ'	मण्डी 'ब'
विभिन्न विपणन-संस्थाओं की कुल		
विपणन लागत (रु०)	6,000	8,000
विपणन-प्रक्रिया द्वारा वस्तुओं के		
मूल्य में हुई वृद्धि की राशि (रु०)	15,000	16,000
विपणन दक्षता (प्रतिशत)	250	200

अतः स्पष्ट है कि मण्डी 'अ' वस्तुओं के विपणन में मण्डी 'ब' की अपेक्षा अधिक दक्ष है।

(3) तीसरी विधि में बाजार संरचना, बाजार व्यवहार (Market conduct) एवं बाजार निष्पादन/कार्य (Market performance) के विश्लेषण

के आधार पर विपणन-बाजार की दक्षता ज्ञात की जाती है। यह विधि अमेरिका में विकसित की गई थी। शुरू में यह विधि औद्योगिक क्षेत्रों के बाजारों की दक्षता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की गई थी। धीरे-धीरे इसे कृषि-क्षेत्र में भी प्रयुक्त किया गया।

विपणन-दक्षता में वृद्धि करने के उपाय—मण्डी में उपलब्ध विपणन-मेवाओं के समान स्तर पर होते हुए मण्डी की विपणन-दक्षता में वृद्धि, विपणन-लागत में कमी करके अथवा विक्रय से प्राप्त होने वाली कीमत में वृद्धि करके कर सकते हैं। विपणन-सेवाओं को कम करते हुए विपणन-लागत में कमी करने के उपाय विपणन-दक्षता में वृद्धि के उपायों में सम्मिलित नहीं होते हैं। निम्न उपायों को अपनाकर विपणन-दक्षता में वृद्धि की जा सकती है—

1 उत्पाद के विक्रय से प्राप्त होने वाली कीमत में वृद्धि करके—निम्न उपायों द्वारा उत्पाद के विक्रय से अधिक कीमत प्राप्त की जा सकती है—

(प्र) विपणन सूचना सेवा को विकसित करके—विपणन सूचना सेवा कृषकों को उत्पाद के विक्रय के लिए समय, स्थान एवं संस्था का उचित चुनाव करने में सहायक होती है जिससे कृषकों को उत्पाद की कीमत अधिक प्राप्त होती है।

(ब) नियन्त्रित मण्डियों का विकास करके—नियन्त्रित मण्डियों में विपणन-लागत अनियन्त्रित मण्डियों की अपेक्षा कम होती है तथा कृषकों को वस्तुओं की कीमत प्रतिस्पर्धा के कारण अधिक प्राप्त होती है जो विपणन-दक्षता की वृद्धि में सहायक होती है।

(स) सग्रहण के लिए मण्डार-गृहों की सुविधा उपलब्ध कराना—सग्रहण के लिए मण्डार-गृहों की सुविधा उपलब्ध होने पर कृषक खाद्यान्नों का विक्रय कटोई के शौभ्र उपरान्त नहीं करके, कीमतों के अधिक होने पर करेंगे, जिससे उत्पाद की कीमत अधिक प्राप्त होगी एवं विपणन-दक्षता में वृद्धि होगी।

(द) कृषकों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना—कृषकों को आवश्यक वित्त सुविधा उपलब्ध होने पर वे फसल की बिनी गाँव में साहूकारों एवं व्यापारियों को नहीं करेंगे तथा उनकी खाद्यान्न रोके रखने की शक्ति में वृद्धि होगी और मण्डी में ले जाकर खाद्यान्न विक्रय करने से कीमत अधिक प्राप्त होगी।

2 विपणन-लागत में कमी करने—वस्तुओं के विक्रय में होने वाली विपणन-लागत की राशि को भी परिवहन-सुविधाओं का विकास करके, घाटत, तुलाई एवं अन्य विपणन कार्यों की दर निश्चित करके, उपभोक्ताओं की दी जाने

वाली अनावश्यक सेवाओं—उधार विक्रय सुविधा, पसन्द नहीं आने पर लौटाने की सुविधा—को कम करके किया जा सकता है।

3. बाजार संरचना का विकास करके—निम्न उपायों द्वारा बाजार संरचना का विकास करके भी विपणन-दक्षता में वृद्धि की जा सकती है—

- (अ) कृषकों की गाँव के साहूकार की ऋणश्रस्तता को कम करना।
- (ब) कृषकों द्वारा फसल काटने के शीघ्र पश्चात् विक्रय करने की प्रवृत्ति को समाप्त करना।
- (स) कृषकों द्वारा विपणन-निर्णय जैसे—सनय, स्थान एवं सत्त्वा के चुनाव के निर्णय आर्थिक पहलुओं के आधार पर लेने चाहिए। निर्णय लेने में वैयक्तिक व सामाजिक तत्त्व शामिल नहीं करने चाहिए। आर्थिक पहलुओं के आधार पर निर्णय लेने से कृषकों को वस्तुओं के विपणन से अधिक लाभ प्राप्त होता है एवं बाजार संरचना का विकास होता है।

4 विपणन-प्रक्रिया की जोखिम को कम करके—विपणन-प्रक्रिया में होने वाली जोखिम को कम करके भी विपणन-दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। विपणन-जोखिम के कम होने पर विपणन-मध्यस्थ कम लाभ चाहते हैं। विपणन-जोखिम को संरक्षण, एकीकरण एवं बीमा विधि द्वारा कम किया जा सकता है।

□□□

भारत में कृषि विपणन-व्यवस्था

इस अध्याय में वर्तमान कृषि-विपणन-व्यवस्था के दोष एवं उनके निवारण के उपाय जैसे—नियन्त्रित मण्डियाँ, सहकारी विपणन समितियाँ, खाद्यान्न के थोक व्यापार का सरकार द्वारा अधिग्रहण का विवेचन किया गया है। भारतीय मानक सस्था एवं भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय का विवेचन भी इस अध्याय में किया गया है।

वर्तमान कृषि-विपणन-व्यवस्था के दोष

वर्तमान कृषि-विपणन-व्यवस्था में उत्पादक कृषको को उपभोक्ता द्वारा दिये गये कृषि-वस्तुओं के मूल्य में से बहुत कम भ्रश प्राप्त होता है। उपभोक्ता-कीमत में से अधिकांश भ्रश विपणन-मध्यस्थों को प्राप्त होता है। सब्जी, फल, फूल, दूध, घण्डे आदि शीघ्रनाशी वस्तुओं में उत्पादक कृषको को उपभोक्ता-कीमत में बाधे से भी कम भाग प्राप्त होता है। उत्पादक कृषको को उपभोक्ता के रुपये में से कम भाग प्राप्त होने का प्रमुख कारण वर्तमान विपणन-व्यवस्था का दोषयुक्त होना है। वर्तमान कृषि-विपणन-व्यवस्था में पाये जाने वाले प्रमुख दोष निम्न हैं—

(1) कृषको द्वारा उपज का अधिकांश भाग गाँव में विक्रय करना—कृषक उत्पादित कृषि-वस्तुओं की अधिकांश मात्रा का विक्रय साहूकारों, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं को गाँव में ही करते हैं जिसके कारण कृषको को उत्पाद के विक्रय से उचित कीमत प्राप्त नहीं होती है। गाँवों में मण्डियों की अपेक्षा उत्पादों की कीमतें कम होती हैं जिससे उन्हें गाँव में विक्रय करने से बहुत हानि होती है। कृषि-वस्तुओं की अधिकांश मात्रा की बिक्री कृषको द्वारा गाँवों में किये जाने के प्रमुख कारण ये हैं—

(i) गाँवों से शहर की मण्डियों तक कृषि-वस्तुओं को ले जाने के लिए सड़कों एवं पर्याप्त परिवहन सुविधाओं का न होना।

(ii) कृषक गाँव के साहूकारों के ऋण-ग्रस्त होते हैं, जिसके कारण वे साहूकारों के माध्यम से खाद्यान्न विक्रय करने के लिए बाबन्द होते हैं।

(iii) मण्डियों में प्रचलित कीमतों को सूचना कृषकों की प्राप्त नहीं होती है। मण्डियों में प्रचलित कीमतों के ज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण वे खाद्यान्न गांव में कम कीमत पर विक्रय करते हैं।

(iv) कृषकों में घनाभाव एवं अन्य कारणों से खाद्यान्न रोके रखने की शक्ति का अभाव होता है। अतः वे उत्पादित उपज शीघ्र विक्रय करके धन प्राप्त करना चाहते हैं। मण्डियों में ल जाकर विक्रय करके मूल्य प्राप्ति में समय लगता है।

(v) परिवहन-मुविधा उपलब्ध होने तक के समय के लिए खाद्यान्न-संग्रहण के लिए स्थान एवं सुविधाओं के अभाव की स्थिति में कृषक, खाद्यान्नों का विक्रय गांव में ही करने को तैयार हो जाते हैं।

(vi) लघु जोत के कृषकों के यहाँ विक्रय-प्रविशेष की मात्रा कम होती है, जिससे मण्डी में वस्तुओं को विक्रय के लिए ले जाने में प्रति इकाई विपणन-लागत अधिक पड़ती है। देश के 75 प्रतिशत कृषक लघु कृषकों की श्रेणी में हैं।

(vii) मण्डी में ठहरने की अनुविधा, विपणन कुरीतियों के होने, मध्यस्थों की अधिकता, भाषा की अनभिज्ञता आदि कारणों से भी कृषक खाद्यान्नों का विक्रय मण्डी में करना पसन्द नहीं करते हैं।

(2) कृषकों द्वारा फसल कटाई के शीघ्र बाद कृषि उत्पादों की अधिकांश मात्रा विक्रय करना—वर्तमान कृषि-विपणन-व्यवस्था का दूसरा दोष कृषकों द्वारा खाद्यान्नों की बिक्री फसल कटाई के तुरन्त बाद किया जाना है। फसल-कटाई के बाद वस्तुओं की पूर्ति मांग से अपेक्षाकृत अधिक होती है और कीमतें न्यूनतम स्तर पर होती हैं जिसके कारण कृषकों को उत्पाद के विक्रय से उचित कीमत प्राप्त नहीं होती है। कृषकों द्वारा औसतन 50 से 60 प्रतिशत खाद्यान्न फसल-कटाई के बाद अर्थात् प्रथम तीन महीने में विक्रय किये जाते हैं। फसल-कटाई के कुछ समय बाद वस्तुओं की पूर्ति में कमी होने से कीमतों में वृद्धि होती शुरू होती है। बढ़ती हुई कीमतों से व्यापारी-बर्ग लाभ उठाने हैं। फसल कटाई के बाद खाद्यान्नों का विक्रय कृषकों द्वारा निम्न कारणों से किया जाता है—

- (i) धन की अति आवश्यकता होने के कारण खाद्यान्न रोके रखने की शक्ति का कृषकों में अभाव होना।
- (ii) खाद्यान्न-संग्रहण के लिए कृषकों के यहाँ स्थान एवं सुविधाओं का अभाव होना।
- (iii) साहूकारों का शीघ्र ऋण-मुक्तान के लिए कृषकों पर दबाव होना।
- (iv) कृषकों में व्यापारिक दक्षता विकसित नहीं होना।
- (v) संग्रहण के लिए मण्डार-गृहों की आवश्यक सुविधा गांवों में उपलब्ध नहीं होना।

(3) कृषकों द्वारा विक्रय किये जाने वाले उत्पाद की मात्रा का कम होना—विविधीकृत (diversified) खेती अपनाने, जोत का आकार कम होने एवं खाद्यान्नों की विभिन्न किस्मों की खेती के कारण कृषकों के यहाँ वस्तुओं के विक्रेय-अधिशेष की मात्रा बहुत कम होनी है, जिससे वस्तुओं के विपणन में प्रति इकाई विपणन-लागत अधिक होती है।

(4) मण्डियों में विपणन कुरीतियों का पाया जाना—विपणन के क्षेत्र में मण्डियों में अनेक कुरीतियाँ जैसे—अनाधिकृत तौल एवं नाप के पैमानों का उपयोग, केना व्यापारियों द्वारा नमून के रूप में खाद्यान्नों की मात्रा से जाना, विक्रय-विविध का शोषयुक्त होना, कृषकों को कीमतों का ज्ञान न होना, आदतियों द्वारा विक्रय मूल्य में कम कीमत का भुगतान करना, करदा एवं अन्य अनावश्यक लागत वसूल करना, दलालों एवं आदतियों का नेताओं की ओर अधिक झुकाव आदि पाई जाती हैं, जिनके कारण कृषकों को खाद्यान्नों की विक्री से उचित कीमत प्राप्त नहीं होती है।

(5) विपणन-लागत की अधिकता—देश में पर्याप्त संख्या तथा सभी स्थानों पर नियन्त्रित मण्डियों के नहीं होने के कारण कृषक खाद्यान्न का विक्रय अनियन्त्रित मण्डियों में करते हैं। अनियन्त्रित मण्डियों में विभिन्न विपणन लागतों का भुगतान करना होता है। अनेक विपणन लागतों का कृषकों के विक्रय से कोई सम्बन्ध नहीं होता है जैसे—मुनीमी, धर्मादा, चुंगी, गौशाला आदि लागत।

(6) विपणन-प्रक्रिया में मध्यस्थों की अधिकता—मण्डियों में कृषकों एवं उपभोक्ताओं के बीच मध्यस्थों की एक लम्बी शृंखला पाई जाती है। प्रत्येक विपणन मध्यस्थ विपणन-कार्यों से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। विपणन-मध्यस्थों की अधिकता के कारण उत्पादक कृषक का उपभोक्ता के रुपये में से प्राप्त भाग कम हो जाता है।

(7) विपणन सूचना सेवा का अभाव—विभिन्न मण्डियों में प्रचलित कीमतों की सूचना समय पर प्राप्त नहीं होने से कृषक खाद्यान्न का विक्रय कम कीमतों पर कर देते हैं। विपणन-मध्यस्थों के पास विभिन्न मण्डियों में प्रचलित कीमतों की पूर्ण सूचना होती है, जिससे विपणन-मध्यस्थ कृषकों की कीमतों की जानकारी के अभाव का लाभ उठाते हुए उनसे खाद्यान्न कम कीमत पर खरीद लेते हैं।

(8) मण्डियों में श्रेणीकरण एवं मानकीकरण सुविधा का उपलब्ध न होना—श्रेणीकरण एवं मानकीकरण की आवश्यक सुविधाओं के उपलब्ध नहीं होने से कृषक वस्तुओं को श्रेणीकरण के बिना ही विक्रय करते हैं जिससे कृषकों को उत्पाद की किस्म के अनुसार कीमत प्राप्त नहीं होती है।

(9) कृषकों में संगठन का अभाव—कृषिगत वस्तुओं का उत्पादन, असंख्य कृषकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। कृषक संगठित नहीं होते हैं। संगठित

नहीं होने के कारण कृषक खाद्यान्न के क्रय-विक्रय में अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं और व्यापारी-वर्ग समर्थित होने के कारण कृषकों का शोषण करते हैं।

कृषि-विपणन-व्यवस्था के दोष-निवारण के उपाय

कृषि-वस्तुओं की विपणन-व्यवस्था में पाये जाने वाले उपर्युक्त दोषों के कारण कृषकों को खाद्यान्न की उचित कीमत प्राप्त नहीं होती है, जिससे उनमें उत्पादन वृद्धि की प्रेरणा का ह्रास होता है साथ ही कृषि आधारित उद्योगों को आवश्यक मात्रा में कच्चा माल प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः कृषि एवं उस पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए विपणन-व्यवस्था के दोषों का निवारण करना आवश्यक है। कृषि-विपणन-व्यवस्था के पाये जाने वाले दोषों का निवारण निम्न उपायों द्वारा किया जा सकता है—

1 मण्डियों को नियन्त्रित करना—विपणन व्यवस्था में पाये जाने वाले अनावश्यक मध्यस्थों, विपणन प्रथा में पायी जाने वाली नुस्तीशों एवं विपणन-लागत की अधिकता आदि दोषों को कृषि उपज-विपणन अधिनियम के अन्तर्गत नियन्त्रित मण्डियों की स्थापना करके दूर किया जा सकता है। नियन्त्रित मण्डियों का संचालन कृषि उपज मण्डी समितियों के द्वारा होता है जिसमें कृषकों, व्यापारियों, सरकार, बैंक एवं स्वायत्त संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं। मण्डी समिति विभिन्न वस्तुओं के विक्रय के लिए विभिन्न कार्यों की विपणन-लागत की दर निर्धारित करती है तथा अनावश्यक एवं अनधिकृत विपणन-लागत में कमी करती है। मण्डी में विक्रय की नीलामी पद्धति होने से उपज की कीमत भी अधिक प्राप्त होती है।

2 कृषि-वस्तुओं के लिए श्रेणीकरण एवं मानकीकरण-सुविधाओं का देश में विकास करना, जिससे उत्पादकों को वस्तु को श्रेणियों के अनुसार कीमत प्राप्त हो सके।

3 स्थान-स्थान पर आवश्यकतानुसार मण्डार-गृह सुविधाओं का विकास करना, जिससे कृषक खाद्यान्न का मण्डारण कर सकें और उत्पाद को कटाई के बाद शीघ्र विक्रय नहीं करें।

4 मण्डी में वस्तुओं का भार करने के लिए यान्त्रिक-तुल एवं मानकीकृत मीट्रिक तौल के बाटों का ही प्रयोग करने के कानून को पूर्णरूप से कार्यान्वित करना।

5 विपणन-सूचना-सेवा में श्रद्धा करना जिससे कृषक विक्रय के लिए स्थान एवं समय के चुनाव का निर्णय आर्थिक आधार पर ले सकें।

6 परिवहन-साधनों एवं सड़कों का विकास करना, जिससे परिवहन लागत में कमी होवे। विशेषकर गांवों में मण्डियों को जोड़ने के लिए सम्पर्क-सड़कों (Link-roads) का विकास प्रति आवश्यक है।

7 मण्डियों में कृषकों को ठहरने, पशुओं एवं गाड़ियों को खड़ी करने की सुविधाएँ प्रदान करना, जिससे कृषक मण्डी में होने वाली असुविधाओं के कारण गाँवों में विक्रय पद्धति का त्याग कर सकें।

8 सहकारी-विपणन समितियों के निर्माण की ओर विशेष ध्यान देना जिससे विशेषकर लघु कृषक वस्तुओं के विक्रेय-अधिशेष का विक्रय सहकारी-विपणन-समितियों को करके उचित कीमत प्राप्त कर सकें।

9 कृषकों को सस्ते व्याज दर पर आवश्यक राशि में ऋण-सुविधा उपलब्ध कराना जिससे उनकी स्वायत्तता रोके रखने की शक्ति में वृद्धि होवे।

10 कृषकों द्वारा विशिष्ट खेती-पद्धति को अपनाना, जिससे वस्तुओं के विक्रय-अधिशेष की मात्रा में वृद्धि होवे और प्रति इकाई विपणन लागत में कमी हो सके।

11. विपणन-प्रक्रिया में पायी जाने वाली विभिन्न कुरीतियों की समाप्ति के लिए कानूनन रोक लगाना, जिसमें व्यापारी-वर्ग कृषकों का शोषण नहीं कर सकें।

नियन्त्रित मण्डियाँ

पूर्व में कृषि-वस्तुओं की विपणन-व्यवस्था में मण्डियों में व्यापारियों के एकाधिपत्य के कारण अनेक प्रकार से उत्पादक-कृषकों को हानि उठानी पड़ी थी। विपणन में स्पर्धा के अभाव, अनेक प्रकार की विपणन-लागत की कटौतियों, विपणन की कुरीतियों आदि के कारण उत्पादक कृषकों को उत्पाद के विक्रय से सही कीमत प्राप्त नहीं होती थी। इन सबका लाभ मध्यस्थ वर्ग उठाता था। उत्पादक-कृषक मण्डियों में अपने उत्पाद के विक्रय के समय भूक-दशक की भाँति देखते थे। इन सबका प्रमुख कारण मण्डियों पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं होना था। मण्डियों का संचालन व्यापारियों द्वारा अपने हितों की सर्वोपरि रक्षा हेतु बनाये गये नियमों के अनुसार होता था। मण्डी नियमन में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की उपेक्षा की जाती थी।

एक दक्ष विपणन-व्यवस्था हेतु मण्डी में विपणन की समुचित व्यवस्था का होना आवश्यक है। कृषि उत्पादों के विपणन में पाये जाने वाले उपर्युक्त दोष देश में नियन्त्रित मण्डियों की स्थापना करके दूर किए जा सकते हैं।

नियन्त्रित मण्डी से तात्पर्य—नियन्त्रित मण्डी में तात्पर्य उस मण्डी से है जो राज्य सरकार द्वारा पारित कानून के तहत व्यापार के संचालन के लिए स्थापित की जाती है। इनकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य विपणन व्यवस्था में पाये जाने वाली कुरीतियों को दूर करना, विपणन लागत को कम करना एवं उत्पादक-कृषकों को विपणन काल में सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना होता है। ये मण्डियाँ पारित अधिनियम के अनुसार कार्य करती हैं।

नियन्त्रित मण्डियों के उद्देश्य — नियन्त्रित मण्डियों की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं—

- (1) कृषकों की विपणन प्रक्रिया में होने वाली मजबूरियों को दूर करके उनकी मध्यस्थों द्वारा किए जाने वाले शोषण से रक्षा करना ।
- (2) विपणन व्यवस्था को दक्ष बनाना जिससे कृषकों को उत्पाद की सही कीमत एवं उपभोक्ताओं को आवश्यक मात्रा में कम कीमत पर वस्तुएँ उपलब्ध हो सकें ।
- (3) कृषकों को उत्पादन की अधिक मात्रा एवं अच्छी किस्म के उत्पाद का उत्पादन करने की प्रेरणा देना ।
- (4) विपणन व्यवस्था के सुधार के लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना, जिससे मण्डियों में व्यापार की एक ठोस एवं सुदृढ़ व्यवस्था कायम हो सके ।

नियन्त्रित मण्डियों की स्थापना—देश में नियन्त्रित मण्डियों की स्थापना की आवश्यकता सर्वप्रथम ब्रिटिश शासनकाल में इंग्लैण्ड की बयडा मिलों को उचित कीमत पर कपास की पूर्ति हेतु महसूस हुई । वर्ष 1986 में प्रथम नियन्त्रित 'कर-जीया कपास मंडी' की स्थापना की गई । सर्वप्रथम अधिनियम "कॉटन एण्ड ग्रेन मार्केट ला" 1897 तत्कालीन बरार प्रदेश में नियन्त्रित मण्डियों की स्थापना हेतु पारित किया गया । यह अधिनियम बाद में अन्य राज्यों में नियन्त्रित मण्डियों की स्थापना हेतु आधार कानून माना गया । भारत सरकार द्वारा 1917 में स्थापित 'इण्डियन कॉटन कमिटी' ने भी बरार अधिनियम के अनुसार कपास मण्डियों को नियन्त्रित करने का मुझाव दिया । वर्ष 1927 में बम्बई सरकार ने बम्बई कॉटन मार्केट ला लागू किया । यह प्रथम विस्तृत अधिनियम था जो देश में स्वस्थ मंडी-प्रणाली की स्थापना की दृष्टि से बनाया गया था । इसका प्रमुख उद्देश्य उत्पादक व उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना था ।

वर्ष 1928 में ब्रिटिश सरकार के तत्कालीन वायसरॉय लार्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में नियुक्त कृषि रायल कमीशन ने भी कृषि विपणन में व्याप्त प्रच्यवस्थित परिस्थितियों के कारण भारत में नियन्त्रित मण्डियों की स्थापना की सिफारिश की थी । केन्द्रीय बैंकिंग आंच समिति, 1931 ने कृषि रायल कमीशन की सिफारिश का अनुमोदन किया । भारत सरकार ने 1935 में कृषि-विपणन समस्याओं को हल करने के लिए विपणन एवं निरोक्षस निदेशालय की स्थापना की । इस निदेशालय ने राज्य सरकारों को उत्पादक-कृषकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से राज्यों में नियन्त्रित मण्डियों की स्थापना की सिफारिश की थी । निदेशालय ने वर्ष 1938 में राज्यों में नियन्त्रित मण्डियों की स्थापना के लिए एक आधार बिल तैयार किया, जिसके आधार पर अनेक राज्यों ने मण्डियों के नियमन हेतु कानून पारित किये ।

विभिन्न राज्यों में मण्डियों को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से समय-समय पर अधिनियम पारित किए गए हैं, जैसे हैदराबाद कृषि विपणन अधिनियम, 1930, मद्रास वाणिज्यिक फसल विपणन अधिनियम, 1935, बम्बई कृषि उपज विपणन अधिनियम, 1939, पंजाब कृषि उपज विपणन अधिनियम, 1939, मैसूर कृषि उपज विपणन अधिनियम, 1939, केरल कृषि उपज विपणन अधिनियम, 1957, राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम 1961। आन्ध्रप्रदेश में मद्रास राज्य के विपणन अधिनियम तथा गुजरात एवं महाराष्ट्र ने बम्बई प्रान्त के अधिनियम को लागू किया। विभिन्न राज्यों ने पारित कृषि उपज विपणन अधिनियमों में समय-समय पर संशोधन किए हैं। संशोधित अधिनियमों में अनेक राज्यों ने मण्डियों के विकास एवं नियमन कार्य की प्रगति हेतु कृषि विपणन बोर्ड गठन करने का निर्णय लिया है। फलस्वरूप अनेक राज्यों—पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश आदि में कृषि विपणन बोर्ड स्थापित किये जा चुके हैं। मण्डी नियमन के लिए पारित अधिनियम कृषक विप्रेताग्रा के लिए रक्षा का कवच है जो उनकी मेहनत की कमाई में मध्यस्था द्वारा की जाने वाली अनाधिकृत कटौतियाँ को रोकने में सहायक होते हैं।

नियन्त्रित मण्डियों के विकास का कार्य वर्ष 1950 तक मथर गति में हुआ। नवम्बर, 1955 में विपणन और सहकारिता पर हुए सम्मेलन ने इनकी प्रगति की रफ्तार को बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया। सम्मेलन में सिफारिश की गई है कि जिन राज्यों में मण्डी नियमन कानून पारित नहीं किया है, वे शीघ्र कानून पारित करके नियमन पारित राज्यों की श्रेणी में आ जाएँ।

नियन्त्रित मण्डियों से कृषकों को लाभ—कृषकों को नियन्त्रित मण्डियों में कृषि-उत्पाद विक्रय करने से निम्न लाभ प्राप्त होते हैं—

1. नियन्त्रित मण्डी में उत्पादक कृषकों की व्यापारियों द्वारा किए जाने वाले शोषण से रक्षा होती है, क्योंकि मण्डी के व्यापारों मण्डी समिति के निर्देशन में कार्य करते हैं।
2. नियन्त्रित मण्डी में उत्पादक-कृषकों को वर्तमान में उत्पाद के विक्रय पर किसी प्रकार की विपणन-लागत नहीं देनी होती है। वर्तमान में सभी प्रकार की विपणन लागतें नेताओं से वसूल की जाती हैं।
3. नियन्त्रित मण्डियों में वस्तुओं का तौल मण्डी समिति से प्राप्त अनुज्ञापत्रधारी तुलारों द्वारा किया जाता है। तौल में काटे एवं मीट्रिक बाटों का ही उपयोग होता है। अतः कृषक तौल की बेईमानी से बच जाते हैं।
4. व्यापारियों एवं कृषकों के मध्य में नमूने, कीमत, हिसाब सम्बन्धित झगड़े मण्डी समिति की उप-समिति द्वारा निपटाये जाते हैं जिससे विवादों पर होने वाली लागत में बचत होती है।

5. नियन्त्रित मण्डी में वस्तुओं की खुली नीलामी पद्धति द्वारा विक्रय एवं पूर्ण स्पर्धा की स्थिति के कारण कृषकों को उत्पाद की उचित कीमत प्राप्त होती है ।
6. कृषकों को बेचे गये माल की कीमत का शीघ्र भुगतान प्राप्त होता है । भुगतान के लिए कटौती नहीं देनी होती है । रुपयों की प्राप्ति के लिए कृषकों को मण्डी में कई बार नहीं आना पड़ता है ।
7. कृषकों को कृषि उत्पादों की कीमतों को निरन्तर सूचना प्रदान करने की व्यवस्था नियन्त्रित मण्डी करती है, जिससे कृषकों का विपणन के लिए सही समय एवं स्थान के चुनाव में सुगमता होती है ।
8. नियन्त्रित मण्डियों में उत्पाद के विक्रय में पाई जाने वाली अनेक प्रकार की कुरीतियाँ जैसे--खाणास की यादी-योदी माना नमूने के रूप में केनाथों द्वारा ल जाना, विक्रय पथों नहीं देना, करदा एवं घलता अनावश्यक होते हुए भी काट लेना आदि समाप्त हो गई है । इससे भी कृषकों का लाभ पहुँचा है ।
9. मण्डी में रात्रि में ठहरने, पशुओं एवं बैलगाड़ियों की दख्खाल सपों की सुरक्षा के लिए बैक, पानी की व्यवस्था, माल की चौकीदारी एवं रात्रि में रोशनी की नि शुल्क व्यवस्था कृषकों को उपलब्ध कराई जाती है ।
10. मण्डी के प्रबन्ध में कृषक स्वयं भागीदार होते हैं जिससे उन्हें मण्डी नियमन की पूर्ण जानकारी होती है ।

नियन्त्रित मण्डियों से उपभोक्ताओं को लाभ—नियन्त्रित मण्डी में उपभोक्ताओं द्वारा खाद्यान्नों के क्रय करने से निम्न लाभ प्राप्त होते हैं —

1. नियन्त्रित मण्डी में विक्रय की सही प्रणाली के कारण उपभोक्ताओं को कृषि उत्पाद उचित कीमत पर उपलब्ध होते हैं ।
2. वस्तुओं की किस्म में मिलावट, कम तौलने की कुरियाँ आदि से होने वाली हानि में उपभोक्ताओं की रक्षा होती है ।
3. वस्तुओं के श्रेणीकरण एवं मानकीकरण व्यवस्था के होने से उपभोक्ताओं को आवश्यक श्रेणी की वस्तुएँ आसानी से उपलब्ध होती हैं ।

नियन्त्रित मण्डियों की कार्य-प्रणाली—सर्वप्रथम सरकार किसी भी क्षेत्र में मण्डी नियमन हेतु मण्डी का क्षेत्र, मुख्य मण्डी, गौण मण्डियाँ एवं मण्डी यादें निर्धारित करती है । तत्पश्चात् मण्डी में नियमन कार्य प्रारम्भ होता है । नियन्त्रित मण्डियों की कार्य-प्रणाली संक्षेप में निम्न प्रकार की होती है—

- (1) वस्तुओं की क्रय-विक्रय विधि—मण्डी में वस्तुओं का क्रय-विक्रय खुली नीलामी अथवा बन्द निविदा विधि द्वारा होने का प्रावधान है। अधिकांश मण्डियों में उत्पादों का क्रय विक्रय खुली नीलामी विधि द्वारा मण्डी समिति के कार्यकर्ता की उपस्थिति में निर्धारित समय में ही होता है।
- (2) तुलाई—वस्तुओं की तुलाई अनुज्ञा-पत्रधारी तुलारे के द्वारा मीट्रिक बाटो के उपयोग द्वारा की जाती है।
- (3) श्रेणीचयन—वस्तुओं के विक्रय से पूर्व उनका श्रेणीचयन करना आवश्यक है लेकिन अधिकांश मण्डियों में श्रेणीचयन के लिए आवश्यक उपकरण, स्थान एवं सुविधाओं के नहीं होने से कृषि उत्पादों का विक्रय श्रेणीचयन किये बिना ही होता है।
- (4) मण्डी सूचना सेवा—नियन्त्रित मण्डियों में कृषकों को प्रचलित मण्डी कीमतों की सूचना देने की पर्याप्त व्यवस्था होती है।
- (5) विपणन लागत—वर्तमान में उत्पादक-कृषकों को नियन्त्रित मण्डी में अपने उत्पादों के विक्रय पर किसी प्रकार की विपणन लागत नहीं देनी होती है। उन्हें मण्डी में विक्रय से पूर्व की लागत जैसे—परिवहन लागत, चुगी एवं मजदूरी ही देनी होती है।
- (6) उत्पादों की कीमत का भुगतान—उत्पाद की नीलामी के बाद तुलाई होते ही कीमत का भुगतान कृषकों को किया जाता है। इसके लिए उनसे किसी प्रकार की कटौती देय नहीं होती है।
- (7) विपणन-मध्यस्थों को अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करना—मण्डी में कार्य करने के प्रत्येक इच्छुक मध्यस्थ को निर्धारित मण्डी शुल्क का भुगतान करके अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करना होता है। साथ ही उन्हें मण्डी समिति द्वारा समय-समय पर पारित नियम एवं उपनियमों का पालन करना होता है।
- (8) विवादों का निपटारा—कृषकों एवं व्यापारियों के मध्य में होने वाले विवादों का निपटारा मण्डी समिति की उप समिति के द्वारा शीघ्रता से किया जाता है, जिन पर कोई व्यय नहीं होता है।
- (9) मण्डी में विपणन के लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना—नियन्त्रित मण्डी अपनी आय में से मण्डी क्षेत्र में आवश्यक विपणन सुविधाएँ भी उपलब्ध कराती हैं, जिससे कृषक अधिकाधिक सख्या में उत्पाद के विक्रय के लिए मण्डियों में आयेँ एवं गाँव में ही कृषि उत्पाद के विक्रय करने की प्रथा समाप्त हो सके। नियन्त्रित मण्डियाँ

अपने क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों का निर्माण, मण्डी क्षेत्र में सुव्यवस्थित याई, मण्डी-याई में कृषक-विधामगृह, पशुशाला, गाड़ी खड़ी करने का स्थान, बैंक, पशु चिकित्सालय, प्याऊ आदि का निर्माण कार्य भी कराती हैं।

- (10) नियन्त्रित मण्डियों का संचालन—प्रत्येक नियन्त्रित मण्डी के सुचारु रूप से संचालन के लिए मण्डी समिति होती है। मण्डी समिति में क्रय-विप्रेय से सम्बन्धित सभी वर्गों के प्रतिनिधि होते हैं। विभिन्न राज्यों की मण्डी समितियों में सदस्यों की संख्या भिन्न-भिन्न होती है। पंजाब में 10 एवं 17 सदस्यों की मण्डी समिति होती है जबकि तमिलनाडु की मण्डी समिति में 18, गुजरात में मण्डी समिति में 17 सदस्य एवं राजस्थान में 15 सदस्य होते हैं। राजस्थान राज्य में मण्डी समितियों के 15 सदस्यों में से 7 कृषक वर्ग, 2 व्यापारी वर्ग, 2 क्षेत्र की सहकारी विपणन समिति, एक सहकारी बैंक के प्रतिनिधि, एक सदस्य क्षेत्र की पंचायत समिति से, एक सदस्य क्षेत्र की नगरपालिका से एवं दो सदस्य राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। ये सदस्य अपने-अपने से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। शुरू में मण्डी समितियों के सदस्यों को दो वर्ष के लिए राज्य सरकार मनोनीत करती है। तत्पश्चात् मण्डी समितियों का निर्वाचन चुनाव द्वारा तीन वर्ष के लिए सरकार कराती है। मण्डी समितियों के सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं। उन्हें किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता है।

मण्डी समितियों के कार्य—मण्डी समितियों में प्रमुख कार्य निम्न होते हैं।

- (1) मुख्य एवं गौण मण्डी का प्रबन्ध करना।
- (2) मण्डी में विभिन्न विपणन सेवाओं के लिए लागत दर नियत करना।
- (3) मण्डी में प्रवेश करने वाले मध्यस्थों की संख्या एवं उनके व्यवहार को नियन्त्रित करना।
- (4) कृषि वस्तुओं में होने वाले धपमिश्रण को रोकने की व्यवस्था करना।
- (5) कृषि वस्तुओं के थणीकरण एवं मानकीकरण की मण्डी में व्यवस्था करना।
- (6) कृषकों एवं मध्यस्थों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की उप-समिति के माध्यम से निपटारा करना।
- (7) मण्डी में कार्य करने के इच्छुक मध्यस्थों को अनुज्ञापत्र जारी करना।
- (8) मण्डी में प्रचलित कृषि वस्तुओं की कीमतों की सूचना के प्रसारण की व्यवस्था करना।

- (9) कृषि वस्तुओं के संग्रहण के लिए मण्डी में मण्डार-गृहों का निर्माण करना ।
- (10) मण्डी में कार्यरत व्यक्तियों को नियम पालने की सलाह देना एवं उल्लंघन करने वालों को दण्ड देने की व्यवस्था करना ।
- (11) कृषि उत्पादों के विपणन की सही पद्धति अपनाना एवं विपणन के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति उत्पन्न करना ।
- (12) मण्डी के कृषकों को ठहराने, भोजन, पानी, पशुओं के लिए पशुशाला, बैंक, पशु चिकित्सालय, राशनी, सफाई, चौकीदारी की व्यवस्था करना ।

मण्डी समिति की धार्य—उपर्युक्त कार्यों को करने के लिए मण्डी समिति को धन की आवश्यकता होती है । मण्डी समितियाँ आवश्यक धन निम्न स्रोतों से प्राप्त करती हैं—

- (i) मण्डी में कार्यरत विभिन्न विपणन-मध्यस्थों से अनुज्ञा-पत्र शुल्क वसूल करके आय प्राप्त करना ।
- (ii) मण्डी में विक्रीत विभिन्न कृषि उत्पादों पर मण्डी शुल्क प्राप्त करना । वर्तमान में राजस्थान की मण्डियों में कृषि वस्तुओं के विपणन पर एक प्रतिशत मण्डी-शुल्क वसूल किया जाता है । प्राप्त मण्डी शुल्क में से 10 प्रतिशत राशि मण्डियों द्वारा राज्य कृषि विपणन बोर्ड को जमा करानी होती है ।
- (iii) राज्य सरकार द्वारा मण्डियों में अनेक सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु एवं अनार्षिक मण्डियों को कार्यक्षम बनाने हेतु प्रारम्भ में वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है ।

मण्डी समितियाँ प्राप्त आय में से कार्यरत कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करके शेष राशि को मण्डी के विकास पर व्यय करती हैं । देश में अनेक स्थानों पर विस्तृत क्षेत्र पर सभी सुविधाओं से युक्त नियन्त्रित मण्डियों का निर्माण हो चुका है एवं अनेक स्थानों पर वे निर्माणाधीन हैं ।

नियन्त्रित मण्डियों की प्रगति :

देश में नियन्त्रित मण्डियों की स्थापना का कार्य 1930 के काल में प्रारम्भ हुआ था, लेकिन इनकी संख्या में स्वतन्त्रता के पश्चात् विशेष प्रगति हुई है । सन् 1951 में विभिन्न काल में स्थापित नियन्त्रित मण्डियों की संख्या दर्शाई गई है । प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ (अप्रैल, 1951) में नियन्त्रित मण्डियों की संख्या मात्र 236 थी, जो बढ़कर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ (अप्रैल, 1956) में

470, तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ (अप्रैल, 1961) में 715, अप्रैल, 1966 में 1012, अप्रैल, 1976 में 3528 एवं अप्रैल, 1990 में 6217 हो गई। वर्तमान में देश के 94 प्रतिशत थोक बाजार नियन्त्रित हो चुके हैं। अभी भी देश के 22,000 ग्रामीण बाजार स्वायत्त संस्थाओं द्वारा प्रबन्धित हो रहे हैं। इन बाजारों में क्रय-विक्रय व्यापारियों द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार ही होता है। अतः देश के सभी कृषकों को समान रूप से लाभ पहुँचाने के लिए इन ग्रामीण बाजारों को भी नियन्त्रित करना आवश्यक है।

सारणी 15 1

भारत में नियन्त्रित मण्डियों की प्रगति

वर्ष	नियन्त्रित मण्डियों की संख्या	थोक मण्डियों की संख्या का प्रतिशत (6632)
मार्च 1951	236	3.56
मार्च 1956	470	7.09
मार्च 1961	715	10.78
मार्च 1966	1012	15.26
अक्टूबर 1973	2754	41.53
मार्च 1976	3528	53.20
मार्च 1980	4446	67.04
मार्च 1984	5579	84.12
मार्च 1986	5766	86.94
मार्च 1988	6062	91.25
मार्च 1990	6217	93.74

स्रोत Government of India, Indian Agriculture in Brief, Ministry of Agriculture, New Delhi

राज्यवार कुल थोक मण्डियों एवं नियन्त्रित मण्डियों की प्रगति सारणी 15 2 में प्रदर्शित की गई है। वर्तमान में 24 राज्यों में से 6 राज्यों (जम्मू एवं कश्मीर, केरल, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एवं सिक्किम) एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में से चार (मण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली एवं लक्षद्वीप) केन्द्रशासित प्रदेशों ने नियन्त्रित मण्डियों की स्थापना हेतु कानून पारित

नहीं किया है। केरल राज्य ने चार नियन्त्रित मण्डियाँ हैं, जो मत्ताकार क्षेत्र में हैं। यह मण्डियाँ भूतपूर्व मद्रास राज्य वाणिज्यिक फसलें अधिनियम, 1933 द्वारा नियमित हो रही हैं। केरल राज्य ने नियन्त्रित मण्डियों की स्थापना हेतु कानून पारित नहीं है। सभी राज्यों में नियन्त्रित मण्डियों की प्रगति समान नहीं है। आन्ध्रप्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा पंजाब, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्यों ने नियन्त्रित मण्डियों की प्रगति प्रशंसनीय है। असम, नगौरपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा राज्यों में नियन्त्रित मण्डियों की प्रगति नगण्य है।

नियन्त्रित मण्डियों की कार्य-प्रणाली में सुधार हेतु राष्ट्रीय कृषि मायोग की सिफारिशों—

राष्ट्रीय कृषि मायोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है¹ कि देश में नियन्त्रित मण्डियों की संख्या में वृद्धि तो संजोवजनक है, लेकिन कार्य-प्रणाली में दक्ष विवरण के लिए सुधार लाना आवश्यक है। अतः राष्ट्रीय कृषि मायोग ने नियन्त्रित मण्डियों की कार्य-प्रणाली में सुधार लाने के लिए निम्न सिफारिशें की हैं—

- (1) कृषकों को मण्डी समिति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मण्डी समिति का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कृषक वर्ग से होना चाहिए।
- (2) नियन्त्रित मण्डियों में निम्नरूप हेतु खाद्यान्नों के अतिरिक्त अन्य कृषि वस्तुएँ, जैसे—वाणिज्यिक फसलें, फल एवं सब्जियाँ, पशुओं से प्राप्त उत्पाद एवं वना से प्राप्त उत्पाद भी सम्मिलित किये जाने चाहिए।
- (3) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मण्डी-मुक्त को स्थानान्तरण दर क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाएँ एवं सम्भावित विकास कार्यक्रमों के अनुसार निम्न को जानी चाहिए।

1. Report of the National Commission on Agriculture, Ministry of Agriculture and Irrigation, Government of India, New Delhi, Vol. XII, 1976, pp. 117-119.

सारणी 152

भारत के विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में नियन्त्रित
भण्डियों की प्रगति

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	योग भण्डियों की संख्या	नियन्त्रित भण्डियों की संख्या			
		31 दिसम्बर 1968	31 मार्च 197	31 मार्च 1986	31 मार्च 1990
1	2	3	4	5	6
1 आन्ध्र प्रदेश	568	123	379	564	568
2 असम	172	—	4	22	32
3 बिहार	443	60	314	765	798
4 गुजरात	341	203	267	312	341
5 गोवा	11	—	—	—	5
6 हरियाणा	257	59	135	240	257
7. हिमाचल प्रदेश	29	—	27	44	52
8 कर्नाटक	397	155	236	337	397
9 केरल*	348	5	4	4	4
10. मध्य प्रदेश	633	164	297	436	532
11 महाराष्ट्र	799	301	416	671	773
12 मणिपुर	20	—	—	—	—
13 मेघालय	101	—	—	—	—
14. उड़ीसा	163	40	58	103	130

1	2	3	4	5	6
15 पंजाब	662	87	346	649	662
16. राजस्थान	379	88	185	379	379
17 उदितनाडु	300	93	157	270	276
18 त्रिपुरा	84	—	1	4	21
19. उत्तर प्रदेश	635	46	596	628	635
20 पश्चिम बंगाल	214	—	112	321	337
21 चंडीगढ़	3	—	—	3	3
22. देहली	25	6	8	9	13
23 पश्चिम बंगाल	2	—	—	1	2
24. मद्रास प्रदेस*	31	—	—	—	—
25. जम्मू एण्ड कश्मीर*	26	—	—	—	—
26. मिजोरम*	—	—	—	—	—
27 नागालैण्ड*	10	—	—	—	—
28 सिक्किम*	10	—	—	—	—
29. मण्डमान एव निकोबार द्वीप समूह*	—	—	—	—	—
30. दादर एव नागर हवेली*	—	—	—	—	—
31. दमन एव दीप*	—	—	—	—	—
32. लक्षद्वीप*	—	—	—	—	—
कुल	6632	1430	3528	5756	6217

* कानून पारित नहीं किया गया ।

- टिप्पणी** 1. केरल राज्य में पुराने मद्रास राज्य के मलाबार क्षेत्र में नियन्त्रित मण्डियाँ मद्रास वाणिज्यिक फसलें बाजार कानून 1933 के तहत स्थापित हैं।
- 2 कुछ राज्यों में नियन्त्रित मण्डियों की संख्या, थोक मण्डियों की संख्या में अधिक है क्योंकि उन राज्यों की गौण मण्डियों में ग्रामीण मण्डियाँ या जीत सग्रहागार भी सम्मिलित हैं।

- स्रोत** (1) *Indian Agriculture in Brief-Various Issues*, Directorate of Economics and Statistics, Ministry of Agriculture, Government of India, New Delhi
- (ii) *Agricultural Marketing Vol. 33(a)*, October-December, 1990, p 49
- (4) प्रशासनिक दृष्टि से नियन्त्रित मण्डी का क्षेत्र एक तहसील होना चाहिए।
- (5) प्रत्येक नियन्त्रित मण्डी के पास पर्याप्त क्षेत्र का मण्डी यार्ड एंव उसमें आवश्यक सभी सुविधाएँ—कार्यालय, शराकर, बैंक, विपणन स्थल, श्रेणीकरण एंव सग्रहण हेतु सुविधा होनी चाहिए।
- (6) नियन्त्रित मण्डियों में सभी क्रय-विक्रय निर्धारित मण्डी क्षेत्र में ही होना चाहिए और मण्डी क्षेत्र के बाहर होने वाले क्रय विक्रय को रोकने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- (7) नियन्त्रित मण्डियों के कार्य-संचालन के लिए आवश्यक कार्यकर्ता—सचिव, मण्डी पर्यवेक्षक, विपणन निरीक्षक, श्रेणीकरण पर्यवेक्षक एंव नीलामीकर्ता, राज्य विपणन विभाग द्वारा नियुक्त किये जाने चाहिए।
- (8) कृषि वस्तुओं का क्रय विक्रय खुली नीलामी पद्धति प्रथम बन्द निविदा विधि से निर्धारित स्थान पर ही किया जाना चाहिए।
- (9) सभी राज्यों द्वारा मण्डी विकास कोष की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे ऐसी मण्डियाँ को वित्तीय सहायता दी जा सके जो वर्तमान में अपने स्तर पर विकास कार्य करने में सक्षम नहीं हैं। वर्तमान में 'मण्डी विकास कोष' की स्थापना आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात एंव महाराष्ट्र राज्यों में की जा चुकी है।

शोध विनाशशील कृषि वस्तुओं के समुचित विपणन के लिए सुझाव

भारत सरकार द्वारा डॉ एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 29 जनवरी, 1981 को नियुक्त शोध विनाशशील कृषि वस्तुओं के दल ने शोध विनाशशील कृषि वस्तुओं के लिए मंडी विकास एंव मंडी सूचना सेवा में सुधार लाने के लिए निम्न सिफारिशों की हैं—

- (i) मड़ी नियन्त्रण का लाभ फलो एवं सब्जियों के उत्पादकों को दिलाने हेतु सभी फल एवं सब्जियों का विपणन नियन्त्रित मड़ियों में होना आवश्यक है। वर्तमान में बहुत कम फल एवं सब्जियों का विक्रय नियन्त्रित मड़ियों में होता है।
- (ii) वर्तमान में बहुत ही कम फल एवं सब्जियों की मड़ियों में नियन्त्रण के लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अधिकांश मड़ियाँ खाद्यान्नों के लिए ही आवश्यक सुविधाएँ जुटा रही हैं। अतः वाणिज्यिक फसलों के साथ-साथ फल एवं सब्जियों की मड़ियों का भी विकास होना आवश्यक है। इसके लिए उन्हें पर्याप्त वित्त सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए।
- (iii) विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय का बाजार योजना एवं अभिकल्पना केन्द्र (Market Planning and Design Centre) को फलो एवं सब्जियों के लिए मड़ी क्षेत्र का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहिये।
- (iv) सभी मड़ियों में शीघ्र विनाशशील कृषि जिनसों के श्रेणीकरण, तुलाई, संप्रहण, पकाने हेतु कक्ष एवं पैकेजिंग की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये।
- (v) बड़ी मड़ियों के समीप रेल्वे का साइडिंग बनाना चाहिए, जिससे उनके संचालन में गति भावे एवं कम से कम मात्रा का नुकसान होवे।
- (vi) शीघ्र विनाशशील कृषि जिनसों की आन्तरिक एवं बाहर की आवश्यकता को मद्दे नज़र रखते हुए दक्ष एवं सुष्ठु विपणन सूचना-सेवा का होना भी आवश्यक है।
- (vii) आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को ध्याज एवं भालू के अतिरिक्त अन्य फलों एवं सब्जियों की सूचना भी एकत्रित करनी चाहिए। इसके लिए निदेशालय में आवश्यक सुविधाओं में भी वृद्धि की जानी चाहिए।
- (viii) विभिन्न मड़ियों में फलो एवं सब्जियों की भावक एवं कीमतों की सूचना रेडियो एवं टेलीविजन द्वारा देने का प्रबन्ध भी किया जाना चाहिए।

सहकारी-विपणन-समितियाँ

कृषि-विपणन पद्धति में पाये जाने वाले विपणन दोषों के निवारण का दूसरा उपाय सहकारी-विपणन समितियों की स्थापना करना है। सहकारी विपणन समितियों का मुख्य उद्देश्य कृषकों की उपज को सामूहिक रूप से विपणन करके

उनको उपज का उचित मूल्य प्रदान कराना है। बेकन एवं सहस्र² के शब्दों में सहकारी-विपणन-समितियाँ कृषको द्वारा उत्पादित उपज के सामूहिक रूप में विक्रय के लिए स्थापित ऐच्छिक संस्थाएँ हैं। समितियों का संचालन प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों के आधार पर होता है और प्राप्त शुद्ध लाभ कृषको में खाद्यान्नों की विक्रीत मात्रा के अनुसार वितरित किया जाना है। सदस्य ही, समितियों के स्वामी संचालक; वस्तुओं की पूर्ति करने वाले एवं लाभ के प्राप्तकर्त्ता होते हैं। सहकारी-विपणन-समितियों में किसी प्रकार के मध्यस्थ नहीं होते हैं।

सहकारी-विपणन-समितियों के कार्य—सहकारी-विपणन-समितियों के प्रमुख कार्य निम्न हैं—

1. सदस्यों के उत्पादित माल को उचित कीमत पर विक्रय करना।
2. सदस्यों को उत्पाद की प्रतिभूति के आधार पर ऋण-सुविधा उपलब्ध कराना।
3. सदस्यों को उत्पाद के विक्रय के पूर्व सग्रह की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।
4. उत्पाद के श्रेणीकरण की व्यवस्था करना, जिससे उत्पादक-कृषकों को अच्छी किस्म के उत्पाद की अधिक कीमत प्राप्त हो सके।
5. सदस्यों के खाद्यान्नों को एकत्रित करना, जिससे लघु कृषकों की उत्पाद को परिवहन लागत कम होने के साथ-साथ सहकारी विपणन समितियों के व्यवसाय में वृद्धि हो सके।
6. खाद्यान्नों के निर्यात की व्यवस्था करना, जिससे कृषको को अधिक आय प्राप्त हो सके।
7. सरकार की खाद्यान्न-वसूली एवं कीमत समर्थन नीति को कार्यान्वित करने के लिए एजेंट के रूप में कार्य करना।
8. कृषको के लिए आवश्यक उत्पादन-साधनों—उर्वरकों, कीटनाशी दवाइयों, कृषि यन्त्रों की पूर्ति की समय पर व्यवस्था करना।

A Co-operative sales association is a voluntary business organization established by its member patrons, markets farm products collectively for their direct benefits. It is governed according to democratic principles and savings are apportioned to the members on the basis of their patronage. Members are owners, operators and contributors of the commodities and are the direct beneficiaries to the savings that accrues to the society. No intermediary stands to profit or loss at the expense of the other members.

—H. H. Bakken and M. A. Schaars, *Economics of Co-operative Marketing*, Mc Graw Hill Book Co., New York, 1937.

सहकारी विपणन-समितियों की व्यापार-पद्धति—सहकारी-विपणन-समितियों का व्यापार पद्धति तीन प्रकार की होती है—

(1) सहकारी विपणन-समितियों द्वारा आदतियों के रूप में (Commission agency system) कार्य करना एवं कृषकों द्वारा लाए गए उत्पाद को अधिक कीमत देने वाले व्यापारी को बेचकर आदन प्राप्त करना ।

(2) सहकारी विपणन-समितियों द्वारा छायाओं के संग्रहण, परिवहन, श्रेणीकरण, श्रेणी तथा निर्यात को सुविधा उपलब्ध कराना एवं प्रदान की गई सेवाओं के लिए लागत एवं लाभ प्राप्त करना ।

(3) समितियों द्वारा स्वयं छायाएँ क्रय करना (Outright purchases) एवं क्रय किये गये उत्पाद को उचित कीमत के आने पर विक्रय करके लाभ कमाना ।

सदस्यता—सहकारी-विपणन-समितियों के सदस्य दो प्रकार के होते हैं :

1 व्यक्तिगत कृषक, सहकारी कृषि-समितियाँ, सहकारी-सेवा समितियाँ, जिन्हें सहकारी विपणन-समितियों की कार्य प्रणाली में भाग लेने के सभी अधिकार प्राप्त होते हैं ।

2 व्यापारी वर्ग, सहकारी-विपणन-समितियों के नाम मात्र के सदस्य (Nominal members) बन सकते हैं, इन्हें विपणन-समितियों की कार्य प्रणाली में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है ।

सहकारी-विपणन-समितियों की पूँजी—सहकारी-विपणन-समितियों के वित्त-स्रोत निम्न हैं—

1. हिस्सा पूँजी—सहकारी-विपणन-समिति सदस्यों को समिति के द्वारे विक्रय करके पूँजी एकत्रित करती है ।

2. केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया से ऋण प्राप्त करके भी सहकारी विपणन-समितियाँ आवश्यक पूँजी राशि एकत्रित करती हैं ।

3. सहकारी-विपणन-समितियाँ सरकार से प्रथम तीन वर्षों में धनोपकरण की मशीन लगाने, परिवहन साधनों के क्रय करने आदि कार्यों के लिए अतिरिक्त सागत राशि को पूरा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करके भी पूँजी एकत्रित करती हैं ।

सहकारी-विपणन-समितियों का ढाँचा—सहकारी-विपणन-समितियों का ढाँचा स्तूपीकार (Pyramidal) अर्थात् तीन स्तरीय (Three tier) होता है ।

1 ग्राम/तहसील स्तर पर—ग्राम या तहसील स्तर पर सहकारी विपणन-समितियाँ प्राथमिक सहकारी विपणन-समितियों के रूप में कृषि-वस्तुओं के क्रय-विक्रय का कार्य करती हैं । इनके सदस्य उस क्षेत्र में रहने वाले कृषक होते हैं तथा

समितियाँ एक या अनेक वस्तुओं में क्रय-विक्रय का कार्य करती हैं। प्राथमिक सहकारी-विपणन-समितियाँ दो प्रकार की होती हैं—सामान्य एवं विशिष्ट वस्तु सहकारी विपणन समितियाँ, सामान्य कृषि सहकारी विपणन समितियाँ सभी प्रकार की वस्तुओं में व्यापार करती हैं जबकि विशिष्ट समितियाँ क्षेत्र के अनुसार विशिष्ट वस्तुओं, जैसे—गन्ना, कपास, दूध का व्यापार करती हैं।

2. जिला स्तर पर—जिला स्तर पर केन्द्रीय विपणन-समितियाँ अथवा सघ होते हैं जिनका प्रमुख कार्य प्राथमिक सहकारी-विपणन समितियों के द्वारा लाए गए खाद्यान्न विक्रय करना एवं उन्हें ऋण-सुविधा उपलब्ध कराना होता है। इन समितियों के सदस्य जिले के कृषक एवं प्राथमिक सहकारी विपणन-समितियाँ होती हैं।

3. राज्य स्तर पर—राज्य स्तर पर होने वाली शिखर सहकारी-विपणन-समितियाँ (Apex Co-operative Marketing Societies) जिला स्तर की विपणन समितियों एवं प्राथमिक सहकारी-विपणन-समितियों के द्वारा लाये गये खाद्यान्न को विक्रय करने एवं आवश्यक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करती हैं। प्राथमिक एवं जिला स्तर की विपणन समितियों के अतिरिक्त, राज्य के कृषक भी इनके सदस्य होते हैं।

उपयुक्त स्तरों पर पाई जाने वाली समितियाँ, क्रय-विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की सख्या के अनुसार एक वस्तु समिति एवं बहु-वस्तु समिति में वर्गीकृत की जा सकती हैं। बहु-वस्तु सहकारी-समितियाँ देश में अधिक सख्या में पाई जाती हैं।

सहकारी विपणन समितियों से कृषकों को लाभ—सहकारी विपणन-समितियाँ कृषकों को निम्न लाभ पहुँचाती हैं—

1. कृषि उत्पादों की प्रति इकाई भार पर विपणन लागत में कटौती करती हैं, जिससे उत्पादक-कृषकों को वस्तुओं के विक्रय से उन्नोक्ता द्वारा दिये गये रुपये में से अधिक ग्रन्थ प्राप्त होता है।
2. कृषकों को माल के सग्रहण के लिये भण्डार-गृह सुविधा उपलब्ध कराती है। अतः कृषक कीमती के उचित स्तर पर आने तक उत्पाद को कम लागत पर सग्रहीत कर सकत हैं।
3. कृषकों में सहकारिता की भावना उत्पन्न करती है जो आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सहायक सिद्ध होती है।
4. कृषकों को वस्तुओं के श्रेणीकरण, सवेष्टन एवं परिवहन सेवा सस्ती दर पर उपलब्ध कराती है।
5. सहकारी विपणन समितियाँ कृषकों को सस्ती दर पर आवश्यक राशि में ऋण-सेवा उपलब्ध कराती है।

6. कृषकों को आवश्यक उत्पादन-साधन, जैसे-उर्वरक, बीज, कीटनाशी दवाइयाँ नियत कीमतों एवं समय पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराती है।
7. सहकारी विपणन-समितियाँ कृषकों को विपणन सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने के लिये आवश्यक सुझाव देती हैं जिससे कृषक लाभान्वित होते हैं।
- सहकारी-विपणन-समितियों के माध्यम से वस्तुओं के क्रय-विक्रय करने से कृषकों की क्रय-शक्ति में सुधार होता है।
9. विपणन-पद्धति में पाई जाने वाली अनेक कुरीतियों के शिकार होने से कृषक बच जाते हैं।

सहकारी-विपणन-समितियों की प्रगति :

देश में वर्ष 1960-61 में 3108 प्राथमिक कृषि सहकारी विपणन समितियाँ कार्यरत थी, जो बढ़कर 1970-71 में 3222, 1980-81 में 3789 एवं 1987-88 में 6980 हो गई। इनमें से लगभग 500 प्राथमिक कृषि सहकारी विपणन समितियाँ विशेष वस्तुओं में ही व्यापार करती हैं। राज्य-स्तर पर 29 विपणन सघ कार्य कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त राज्य स्तर पर दो फल एवं सब्जी विपणन सघ (गुजरात एवं देहली में), एक गन्ना पूति विपणन समिति एवं तीन विशेष कृषि वस्तुओं की विपणन समितियाँ राज्य स्तर पर कार्यरत हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन सघ कार्यरत है।

सारणी 15.3 सहकारी विपणन समितियों द्वारा विभिन्न वर्षों में किया गया व्यापार दर्शाती है।

सारणी 153

भारत में सहकारी विपणन एवं सहायन समितियों की प्रगति

विवरण	1960-61	1970-71	1980-81	1985-86	1989-90
1. प्राथमिक कृषि सहकारी विपणन समितियाँ					
(अ) समितियों की संख्या	3108	3222	3789	6356	6980*
(ब) सदस्य संख्या (लाख)	13.93	26.71	34.51	47.51	48.27*
2. सहकारी विपणन समितियों द्वारा विभिन्न कृषि उत्पाद का मूल्य (करोड़ रुपये)	179	649	1950	4193	6274
3. सहकारी विपणन समितियों द्वारा विभिन्न कृषि-सागत का मूल्य (करोड़ रुपये)	36	317	1114	1510	2117
4. पंजीकृत सहकारी बोली बारखाने (संख्या)	56	123	179		222
5. बगल (Ginning) एवं सहायन समितियाँ (संख्या)	155	234	327		NA

* Figures pertain to 1987-88.

Source : Compiled from Indian Agriculture in Brief 23rd Edition and Annual Report 1990-91
Department of Agriculture and Cooperation, Government of India, New Delhi.

सहकारी विपणन समितियों ने व्यापार के क्षेत्र में निरन्तर अच्छी प्रगति की है। यह समितियाँ कृषकों के उत्पाद के विक्रय के अतिरिक्त उन्हें आवश्यक उत्पादन साधन प्रमुखतया उर्वरक तथा उपभोक्ता वस्तुओं के पूर्ति का कार्य भी करती है। वर्ष 1960 में इन समितियों ने 179 करोड़ रुपये के कृषि उत्पाद विक्रित किये थे, जो बढ़कर वर्ष 1989-90 में 6,274 करोड़ रुपये के स्तर तक पहुँच गए। कृषि उत्पादों में विक्रित मुख्य फसलें खाद्यान्न, गन्ना, कपास, तिलहन, बागान वाली फसलें एवं फल व सब्जो है।

सहकारी विपणन समितियाँ कृषि उत्पादों के व्यापार के अतिरिक्त कृषि उत्पादन साधनों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण का कार्य भी करती है। इन समितियों ने वर्ष 1960-61 में 36 करोड़ रुपये मूल्य के उत्पादन साधन कृषकों को उपलब्ध कराये थे, जो बढ़कर 1989-90 वर्ष में 2117 करोड़ रुपये मूल्य स्तर तक पहुँच गए। सहकारी क्षेत्रों में पंजीकृत चीनी कारखानों एवं कपास संसाधन समितियों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि प्राथमिक सहकारी विपणन समितियाँ जो मुख्यतया तालुका स्तर पर हैं, कृषकों के उत्पादों के विक्रय तथा संग्रहण के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं। वर्तमान में इनकी शाखाएँ प्राथमिक मंडियों तथा गौण मंडियों में नहीं होने के कारण इन क्षेत्रों के कृषकों के उत्पादों के विक्रय में इनका सीधा सम्पर्क नहीं है। अतः राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सिफारिश की है कि कृषक सेवा समितियाँ (Farmers Service Societies) इन क्षेत्रों में विपणन समितियों का कार्य करें।

कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, भारत सरकार के सर्वेक्षण परिणामों से स्पष्ट है कि कृषकों द्वारा विक्रित माल का 75.3 प्रतिशत घान एवं 81.3 प्रतिशत गेहूँ व्यापारियों के माध्यम से विक्रय किया जाता है। सहकारी समितियों के माध्यम से 4 प्रतिशत घान एवं 5 प्रतिशत गेहूँ का विक्रय ही होता है (सारणी 15.4)।

सारणी 154

विभिन्न सस्थाओं के माध्यम से धान एवं गेहूँ का विक्रय

विपणन माध्यम	धान 1972-73			गेहूँ 1974-75		
	गाँवों में	गाँवों के बाहर	कुल विक्रय	गाँवों में	गाँवों के बाहर	कुल विक्रय
1. व्यापारी	71.23	80.48	75.27	63.1	90.5	81.3
2. सहकारी विपणन समितियाँ	4.69	2.96	3.93	4.5	5.4	5.1
3. उपभोक्ता	17.23	—	9.70	25.2	—	8.4
4. भारतीय खाद्य निगम	2.89	7.09	4.37	2.7	3.1	3.0
5. अन्य माध्यम	3.96	9.47	6.73	4.5	1.0	2.2
कुल	100.00	100.00	100.00	100.0	100.0	100.0

स्रोत . Directorate of Marketing and Inspection, Government of India, Faridabad

सहकारी विपणन समितियों की प्रगति सभी राज्यों में समान नहीं है। पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश एवं तामिलनाडु राज्यों में 75 प्रतिशत खाद्यान्न सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से विक्रय किये जाते हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र एवं उत्तरप्रदेश में 75 प्रतिशत मक्का, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य में 75 प्रतिशत कपास एवं कर्नाटक राज्य में 84 प्रतिशत बागान वाली फसलों का विपणन सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से होता है।

सहकारी विपणन समितियों की प्रगति में बाधक कारक—सहकारी-विपणन समितियों के द्वारा कृषकों को अनेक लाभ प्राप्त होते हुए भी देश में सहकारी विपणन-समितियों की आघाती प्रगति नहीं हुई है। अनेक राज्यों में सहकारिता के क्षेत्र में प्रगति बहुत कम हुई है। सहकारिता के क्षेत्र में बाधक कारकों को निम्न दो वर्गों में विभक्त किया जाता है—

(1) कृषकों की ओर से बाधक कारक—ये कारक निम्न हैं .

1. कृषक वित्तीय आवश्यकताओं के कारण खाद्यान्नों का बिनाय शोधन करना चाहते हैं। गाँव से सहकारी विपणन समिति तक खाद्यान्नों को पहुँचाने एवं उनके द्वारा विक्रय करने में समय अधिक लगता है। विपणन में

लगने वाले अधिक समय का कृषक इन्तजार करने में असमर्थ होते हैं जिसके कारण कृषक विपणन-समितियों के माध्यम से खाद्यान्न विक्रय न करके गाँव में साहूकारों/भाड़ातियों के द्वारा ही विक्रय करते हैं।

- 2 परिवहन सुविधाओं की अपर्याप्तता के कारण कृषक उत्पादित उपज को विपणन-समितियों तक ले जाने में असमर्थ होते हैं।
3. सदस्य कृषकों में सहकारी-विपणन-समितियों के प्रति रुचि नहीं होने के कारण वे सहकारी विपणन-समितियों के सदस्य होते हुए भी उनके माध्यम से कृषि उत्पादों के विपणन में उत्सुक नहीं होते हैं।
- 4 सदस्य-कृषकों में आपसी वैमनस्यता होने से वे समिति के प्रति उदासीन होते हैं।
5. सदस्यों का सहकारी क्षेत्र के उद्यमों में विश्वास नहीं होता है क्योंकि अधिकतर सहकारी उद्योगों में हानि होती है। इसका प्रमुख कारण कार्यकर्ताओं द्वारा कार्य सुचारु रूप से नहीं करना एवं अनेक प्रकार से बेईमानी करना होता है।
- 6 कृषक व्यापारियों के ऋण-ग्रस्त होते हैं। साथ ही उनके साहूकारों से व्यक्तिगत सम्बन्ध भी होते हैं जिनके कारण खाद्यान्नों के विक्रय में साहूकारों को प्राथमिकता देते हैं।
7. विविधीकृत कृषि प्रणाली को अपनाये जाने के कारण वस्तुओं के विविध-अधिशेष की मात्रा कृषकों के यहाँ कम होती है, जिसके कारण भी वे उत्पाद को विपणन-समितियों के माध्यम से विक्रय करने में इच्छुक नहीं होते हैं।

(II) समितियों की ओर से बाधक कारक—ये कारक निम्न हैं :

1. विपणन-समिति के कर्मचारियों में व्यावसायिक योग्यता का अभाव एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षित नहीं होना, जिनके कारण वे विपणन कार्य को सुचारु रूप से नहीं कर पाते हैं।
- 2 विपणन-समितियों के पास खाद्यान्न-संग्रहण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण वे कृषकों के खाद्यान्नों को शीघ्र विक्रय करते हैं। ऐसा करने से पूर्ति की अधिकता की अवस्था में उचित कीमत प्राप्त नहीं होती है।
- 3 सहकारी विपणन-समितियों के पास कृषकों द्वारा लाए गए मात्र की सम्पूर्ण मात्रा को क्रय करने के लिए पूँजी का अभाव होता है। अतः बहुत से कृषकों को निराश लौटना होता है।
- 4 सहकारी विपणन-समितियों के कार्यालय मण्डी क्षेत्र एवं कृषकों के गाँवों से दूर होते हैं, जिससे कृषकों को परेशानियाँ होती हैं।

5 विपणन-समितियों के कार्यकर्त्ताओं का व्यापारियों की ओर कृषकों की अपेक्षा अधिक भुकाव होता है। अतः कृषक सहकारी विपणन-समितियों के प्रति उदासीन रहते हैं।

6 सहकारी विपणन समितियाँ, व्यापारियों से स्पर्धा करने में सक्षम नहीं होती हैं।

7. सहकारी-विपणन एवं सहकारी ऋण-समितियों में समन्वय नहीं होने से कृषकों को अनेक परेशानियाँ होती हैं।

सहकारी विपणन-समितियों के विकास के लिए सुझाव—सहकारी-विपणन-समितियों के विकास के लिए निम्न सुझाव प्रेषित हैं—

1. सहकारी विपणन समितियों के सदस्यों में आंतरिक प्रेरणा के साथ कार्य करने की भावना जागृत करना।
2. समिति के सदस्यों में जागरूकता लाने एवं सदस्यों में आपस में सहयोग बनाए रखने के लिए गोष्ठियों का आयोजन करना एवं सहकारिता के लाभों से सम्बन्धित साहित्यों में वितरण करना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता के वातावरण में परिपक्वता लाने के लिए धार्मिक मतभेद, वैर-जिम्मेदाराना व्यवहार आदि नस्लों को समाप्त करना।
4. सहकारी-विपणन समितियों के प्रबन्ध एवं व्यवस्था में उचित निरीक्षण के द्वारा सुधार लाना।
5. सहकारिता के विभिन्न पहलू—सहकारी विपणन एवं सहकारी ऋण में परस्पर समन्वय स्थापित करना, जिससे वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त मूल्य राशि से ऋण का सीधा मुगतान किया जा सके।
6. सहकारी-विपणन-समितियों द्वारा गाँव अथवा शहर की मण्डियों में संग्रहण के लिए भोदामो का निर्माण करवाना।
7. सहकारी-विपणन-समितियों द्वारा कृषकों के माल को क्रय करने में प्राथमिकता प्रदान करना।
8. सहकारी-विपणन-समितियों के कार्यकर्त्ताओं को समय-समय पर आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करके उनके कार्यगत अनुभव में सुधार लाना एवं अच्छे कार्य के लिए पारितोषिक प्रदान करने की व्यवस्था करना।

राष्ट्रीय कृषि सहकारी-विपणन संघ/नाफेड

(National Agricultural Cooperative Marketing Federation) :

राज्य-स्तरीय सहकारी-विपणन संघों ने मिसकर अक्टूबर, 1958 में राष्ट्रीय

स्तर पर इस सघ की स्थापना की गयी, जिसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में तथा अनेक राज्यों में इसके कार्यालय हैं। वर्तमान में 29 राज्य-स्तरीय विपणन सघ, 7 राज्य-स्तरीय उत्पाद विपणन सघ एवं 123 प्राथमिक विपणन एवं ससाधन समितियाँ इसके सदस्य हैं।

नाफेड के प्रमुख कार्य निम्न हैं—

- (1) अन्त प्रदेशीय बाजार—नाफेड का प्रथम कार्य विभिन्न कृषि वस्तुओं में अन्त प्रदेशीय व्यापार करना है। नाफेड यह कार्य प्रमुखतया खाद्यान्न, दालें, तिलहन, मसाले, फल, सब्जी, अण्डे, कृषि मशीनें एवं औजार, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों में करता है। नाफेड कृषि वस्तुओं का ऋय कृषि-विपणन सहकारी समितियों के द्वारा करता है। विपणन में भी सहकारी संस्थाएँ, सार्वजनिक संस्थाएँ एवं राज्य सरकार को प्राथमिकता देता है।
- (2) विदेशी व्यापार—नाफेड विभिन्न वस्तुओं के आयात-निर्यात का कार्य भी करता है। नाफेड निर्यात प्रमुखतया प्याज, आलू, भदरक, लहसुन, तिल, गीद, मोटे अनाज, मूँगफली, विनोला एवं सोयाबीन की छेल रहित खली, मसाले, फल एवं सब्जी, इलायची, जूट के बँले, चावल आदि वस्तुओं का करता है। इसी प्रकार नाफेड दालों, मूखे एवं अन्य फल, जायफल एवं जावत्री का आयात भी करता है।
- (3) नाफेड कृषकों के लिए आवश्यक उत्पादन साधनों, जैसे—कृषि-यन्त्र एवं मशीनरी, उर्वरक आदि का आयात करता है एवं समय पर उन्हें कृषकों को उपलब्ध कराता है।
- (4) प्रोत्साहन कार्य—नाफेड तकनीकी विशेषज्ञ भी रखता है जो विपणन में सर्वेक्षण का कार्य करके प्राप्त परिणामों की आवश्यक जानकारी भी देता है। नाफेड सब्जी तथा फलों की ससाधन इकाइयों की स्थापना में भी तकनीकी सलाह प्रदान करता है। नाफेड विपणन सलाह सेवा सुविधा भी प्रदान करता है तथा जनजाति क्षेत्रों में उत्पादित उत्पादों के विपणन के लिए सहकारी विपणन-समितियाँ बनाने में भी मदद देता है।
- (5) नाफेड सरकार के लिए तिलहन, दलहन एवं मोटे अनाज को न्यूनतम समर्थित कीमतों पर ऋय का कार्य भी करता है। नाफेड यह कार्य तिलहन फसलों के लिए वर्ष 1976-77 से, दलहन फसलों के लिए वर्ष 1978-79 से एवं मोटे अनाजों के लिए वर्ष 1985-86 से कर रहा है।

नाफेड कृषको को प्याज, भानू गुड, अदरक आदि कृषि वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मक कीमत भी दिला रहा है। इन कृषि उत्पादों की सरकार वर्तमान में न्यूनतम सन्धिजन कीमतों की घोषणा नहीं करती है। इसके अलावा नाफेड भालू, प्याज एवं निलहन का व्यापार भी करता है। इन्हें नाफेड उत्पादन मौसम में क्रय करके भण्डार करता है और उच्च कीमत आने पर दूसरे मौसम में विक्रय करता है और लाभ कमाता है।

विदेशों में सहकारी विपणन संस्थाएँ—जापान, इजरायल एवं ताइवान देशों में सहकारी-विपणन-समितियों का उच्च भारत के डाँचे से बहुत ममाना रहना है। यहाँ पर जापान एवं इजरायल देशों में कृषि-वस्तुओं की सहकारी विपणन-प्रतिष्ठा का संक्षेप में विवेचन किया गया है।

जापान—जापान देश में कृषि-वस्तुओं के विपणन का कार्य कृषि सहकारी सघ (Agricultural Co-operative Associations) करते हैं। कृषि-सहकारी सघ बहुउद्देशीय कार्य करते हैं, जैसे—कृषकों को ऋण प्रदान करना, वस्तुओं का विपणन करना, कृषकों को बैंक सुविधा उपलब्ध कराना, आवश्यक फार्म एवं घरेलू वस्तुओं की पूर्ति करना आदि। उपर्युक्त कार्यों में ये सहकारी सघों का मुख्य कार्य उत्पादित चावल एवं अन्य खाद्यान्न, भालू, फल, रेशम का कोर या कोकन (Cocoon), दूध एवं अन्य वस्तुओं के विपणन का कार्य करना है। कृषि सहकारी सघ जापान में कृषकों द्वारा विक्रीत अधिकतम 60 से 70 प्रतिशत भाग विक्रय करते हैं और शेष 30 से 40 प्रतिशत भाग अन्य विपणन माध्यमों के द्वारा विक्रीत होता है। अतः जापान में सहकारी सघ कृषि-वस्तुओं के विपणन में विशेष महत्त्व रखते हैं।

सहकारी सघ कृषकों को उत्पादन के लिए आवश्यक सभी साधन जैसे—उर्वरक, कीटनाशी दवाइयाँ, कृषि-यन्त्र, मशीनें आदि उनकी आवश्यकतानुसार कारखानों से सीधे क्रय करके पूर्ति करते हैं। उत्पादन-साधनों की पूर्ति के अनतिरिक्त कृषि सहकारी सघ देश में कृषकों को चन्न किसिम के बीज, उर्वरक, फसला का चुनाव, कीटनाशी दवाइयों के उपयोग की तकनीकी सलाह भी देते हैं, जिससे कृषक प्राप्त उत्पादन-साधनों से अधिकतम उत्पादन की मात्रा प्राप्त कर सकें। जापान में सहकारी समितियों की प्रमुख विशेषता ऋण का उत्पादन एवं विपणन से पूर्ण सामंजस्य करना है। ऋण के उत्पादन एवं विपणन में सामंजस्य के कारण सहकारी समितियों ने जापान में विशेष प्रगति की है। ऋण का उत्पादन एवं विपणन से पूर्ण सामंजस्य नहीं होने के कारण भारत में सहकारी समितियों को विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है।

इजरायल—इजरायल में कृषि वस्तुओं के विपणन के लिए सहकारी विपणन

मध होते है जिन्हे TNUVA कहने है। ये सहकारी-विपणन सह इजरायल देश की कुन उदज का 75 प्रतिशत घासाघ्न, 80 प्रतिशत दूध एवं दूध-वदार्थ तथा 90 प्रतिशत नीबू-वज के फलो का मचालन करते है। देश म किन्बुत फार्म पर उत्पादित कृषि-वस्तुओं, पशु-उत्पादो एवं फलो का इन्ही विपणन सस्थाओं के माध्यम से विनय होता है। सहकारी विपणन मध के अपने कारखाने भी होत है।

भारतीय मानक सस्था

विदेशो मे वस्तुओं के निर्यात के स्तर को बनाये रखने के लिए वर्ष 1947 मे देश मे भारतीय मानक सस्था (Indian Standard Institution) की स्थापना की गई। यह सस्था विभिन्न वस्तुओं के गुणो और किस्म का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके उनके लिए मानक तैयार करती है और निर्धारित मानक के अनुसार वस्तुओ स निमित होने पर मानकीकरण का प्रमाण-पत्र प्रदान करती है, जो उप-भोक्ताओ मे वस्तु के प्रति विश्वास उत्पन्न करता है।

भारतीय मानक सस्था के कार्य—भारतीय मानक सस्था के प्रमुख कार्य निम्न है—

- (1) विभिन्न वस्तुओं के लिए मानक तैयार करना।
- (2) वस्तुओं के उत्पादन एवं ससाधन मे कम लागत वाली विधि का आविष्कार करना एवं उसका निर्माताओ को उपयोग करने के लिए सुझाव देना।
- (3) निर्मित वस्तुओं का प्रयोगशाला मे जांच करके उन पर मानक का प्रमाण अंकित करना।
- (4) विदेशों से आयातित वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के सफल परीक्षण द्वारा उपभोक्ताओ मे विश्वास उत्पन्न करना एवं देश मे आयातित वस्तुओं की मात्रा कम करना।
- (5) मानक निर्धारित करने वाले विदेशी समठनो से सम्पर्क स्थापित करना एवं निर्धारित मानको मे समन्वय स्थापित करना।
- (6) मानक-निर्धारण के लिए कर्मचारियो को प्रशिक्षण देना।
- (7) मानक सस्था द्वारा निर्दिष्ट एवं स्वीकृत मानको वाली वस्तुओ को समय-समय पर विशेषज्ञो द्वारा जांच करना एवं निर्धारित मानक के अनुसार वस्तु के नही होने पर मानकीकरण का अनुज्ञा-पत्र रद्द करना।

भारतीय मानक-संस्था का कार्य-संचालन—भारतीय मानक सस्था नौ परिपदो के माध्यम से उपयुक्त कार्य सम्पन्न करती है।³ ये परिपदें कृषि तथा

खाद्यान्न-उत्पादन, रसायन, सिविल इंजीनियरी, उपभोक्ता तथा चिकित्सा उपकरण, इलेक्ट्रो तकनीकी, मैकेनिकल इंजीनियरी तथा सवेष्टन आदि विषयों से सम्बन्धित वस्तुओं के लिए मानक तैयार करने के कार्य की देखभाल करती है। मानक सस्था का कार्य तकनीकी समितियों उप समितियों तथा पैनल के द्वारा होता है। मानकीकृत वस्तुओं पर ISI का मार्का अंकित किया जाता है। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सस्थाएँ एवं उपभोक्ता वस्तुओं को क्रय करने में मानक सस्था द्वारा प्रमाणित वस्तुओं को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि इन वस्तुओं की बनावट, इनमें अवयवों की मात्रा आदि भारतीय मानक सस्था द्वारा निर्मित मानक के अनुसार होती है। भारतीय मानक सस्था ने सितम्बर, 1977 तक 9251 मानक तैयार किए हैं जिनमें से 8408 (92 प्रतिशत) मानक विभिन्न सस्थाओं ने अपना लिए हैं।

एक अप्रैल, 1987 से इसका नाम भारतीय मानक ब्यूरो कर दिया गया है जिससे इसके कार्य क्षेत्र में पहले की अपेक्षा विस्तार हुआ है।

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

कृषि रॉयल कमीशन (1928) एवं केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति, 1931 की सिफारिशों के अनुसार कृषि वस्तुओं के विपणन एवं विपणन-ज्ञान के प्रसार के लिए भारत सरकार ने विपणन निदेशालय की स्थापना करने का निर्णय लिया। तत्पश्चात् एक जनवरी, 1935 को कृषि-वस्तुओं के विपणन से सम्बन्धित ज्ञान प्रदान करने के लिए कृषि-विपणन सलाहकार का कार्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया। शुरू में कृषि विपणन सलाहकार का कार्यालय 5 वर्ष के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन महत्त्व को देखते हुए इनको स्थायी रूप दे दिया गया। विपणन-निदेशालय के प्रमुख कार्य निम्न हैं—

- (1) प्रमुख कृषि वस्तुओं के विपणन की वर्तमान प्रणाली का सर्वेक्षण करना एवं उनमें व्याप्त दोषों के सम्बन्ध में सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
- (2) कृषि-वस्तुओं के श्रेणीकरण एवं मानकीकरण के लिए श्रृंखला निर्धारित करना एवं निर्धारित श्रेणियों को विपणन प्रक्रिया में कार्यान्वित करना।
- (3) कृषि विपणन अधिकारियों एवं नण्डी सचिवों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- (4) वस्तुओं की विपणन प्रक्रिया में सुधार के लिए निम्न कार्यों को करना—

(अ) कृषि-वस्तुओं की मांग का आकलन करना एवं प्रस्तावित मांग व पूर्ति के आधार पर सरकार को न्यूनतम कीमत निर्धारण के लिए सलाह देना।

- (ब) खाद्यान्नों की कमी, सूखा या अन्य स्थिति का मुकाबला करने के लिए खाद्यान्नों के सुरक्षित भण्डार की आवश्यकता का आकलन करना एवं भण्डार-गृहों के निर्माण के लिए सुझाव देना ।
- (स) कृषि-उत्पादों के उत्पादकों को उचित कीमत प्राप्त कराने एवं उपभोक्ताओं को सही कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए विपणन-सूचना-सेवा का प्रसारण करना ।
- (द) मण्डियों को नियन्त्रित करने के लिए सरकार को समय-समय पर सलाह देना ।
- (य) आवश्यकता होने पर विभिन्न खाद्यान्नों के अन्तर्गत क्षेत्रफल निर्धारित करने के लिए सरकार को सलाह देना, जिससे देश में खाद्यान्न उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो सके ।

वर्ष 1947 में विपणन-निदेशालय का नाम विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय कर दिया गया तथा 1958 में विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के कार्यालय को दिल्ली से नागपुर (महाराष्ट्र) में स्थानान्तरित किया गया । वर्ष 1970 में केन्द्रीय सरकार ने कृषि-विपणन सलाहकार की सेवाओं की समय समय पर परामर्श के लिए आवश्यकता के कारण उसके कार्यालय को फरीदाबाद (हरियाणा) में स्थानान्तरित कर दिया । मुख्य कार्यालय अभी भी नागपुर में है ।

विपणन एवं निरीक्षण-निदेशालय की प्रगति .

- (1) निदेशालय ने विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में मार्च, 1990 तक 6217 मण्डियों को नियन्त्रित किया है । केरल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, सिक्किम तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्यों के अतिरिक्त सभी राज्यों में मण्डी नियमन कानून पारित होने से नियन्त्रित मण्डियाँ स्थापित हो चुकी हैं ।
- (2) निदेशालय ने कृषि पशुपालन एवं वन-पदार्थों के सर्वेक्षण के आधार पर 140 वस्तुओं के विपणन की रिपोर्टें प्रकाशित की हैं । वस्तुओं के विपणन की रिपोर्टों के अतिरिक्त निदेशालय ने शीत सग्रहणालय, मण्डी नियमन, सहकारी विपणन पर भी रिपोर्टें प्रकाशित की हैं ।
- (3) निदेशालय ने 143 कृषि-वस्तुओं के श्रेणीकरण एवं मानकीकरण के लिए श्रेणियाँ निर्धारित की हैं तथा इसके लिए व्यापारियों एवं सहायन में लगे व्यक्तियों की अनुज्ञापत्र जारी किये हैं । विदेशी व्यापार हेतु 42 कृषि वस्तुओं में अतिरिक्त श्रेणीकरण कार्यान्वित है ।

- (4) निदेशालय ने नागपुर, हैदराबाद, चंडीगढ़ एवं लखनऊ में विपणन अधिकारी, मंडियों के सचिवों एवं थ्रेणीचयन कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किये हैं, जहाँ पर निदेशालय विभिन्न व्यवधि की प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराता है।
- (5) वस्तुओं की किस्म, गुण एवं शुद्धता की जाँच के लिए निदेशालय ने एगमार्क प्रयोगशालाएँ—बम्बई, बलरत्ता, मद्रास, कोचीन, गुंटूर, कानपुर, जाम नगर, राजकोट, पटना, बगलौर एवं साहिबाबाद (दिल्ली) में स्थापित की हैं। नागपुर स्थित केन्द्रीय प्रयोगशाला इनके कार्य की देखभाल के अतिरिक्त वस्तुओं में मिलावट की जाँच भी करती है।
- (6) निदेशालय विपणन-विस्तार-सेवा के माध्यम से विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों को आवश्यक विपणन सूचना भी उपलब्ध कराता है। इसके लिए निदेशालय स्थान-स्थान पर प्रदर्शनियाँ लगाता है।
- (7) निदेशालय कृषि-विपणन पर एक पत्रिका प्रकाशित करता है जिसके द्वारा विपणन के क्षेत्र में किये गये विभिन्न लेखकों के सर्वेक्षण व अनुसंधान के परिणाम विभिन्न वर्गों तक पहुँचाये जाते हैं।

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय का ढाँचा—विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय का प्रमुख प्रभारी कृषि-विपणन सलाहकार होता है। कृषि विपणन सलाहकार के अतिरिक्त निदेशालय में समुक्त कृषि-विपणन सलाहकार, उप-कृषि विपणन सलाहकार, वरिष्ठ विपणन अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। निदेशालय के प्रमुख कार्यालय के अतिरिक्त चारों क्षेत्रों—उत्तरी पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्षिणी—में क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनका मुख्य अधिकारी वरिष्ठ विपणन अधिकारी होता है। उप-वरिष्ठ विपणन अधिकारी, विपणन अधिकारी, सहायक विपणन अधिकारी, वरिष्ठ निरीक्षणकर्ता के तत्वावधान में उप-कार्यालय कार्य करते हैं। यह उप-कार्यालय विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले प्रमुख कृषि-उत्पादनों के विपणन-सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्ट तैयार करते हैं।

सभी राज्यों एवं केन्द्र-शासित प्रदेशों में राज्य विपणन विभाग होते हैं। राज्य विपणन विभाग राज्य में विपणन, नियमन, सर्वेक्षण करके रिपोर्ट तैयार करने का कार्य करते हैं। राज्य विपणन विभाग, विपणन अधिकारी अथवा कृषि-निदेशक के तत्वावधान में कार्य करते हैं। वर्तमान में अनेक राज्यों में कृषि-विपणन बोर्ड भी बन गये हैं।

कृषि-विपणन के क्षेत्र में पारित प्रमुख अधिनियम

कृषि-विपणन में सुधार हेतु पारित प्रमुख अधिनियम निम्न हैं :

- 1 कृषि-उत्पाद (थ्रेणीकरण एवं विपणन) अधिनियम, 1937—इस

अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कृषि-वस्तुओं के लिए थ्रेणियों का निर्धारण करना, थ्रेणीकृत करने के इच्छुक व्यक्तियों को अनुज्ञा-पत्र प्रदान करना एवं निर्धारित थ्रेणियों का समय-समय पर निरीक्षण करना है। थ्रेणीकृत किये गये कृषि-उत्पादों पर 'एगमाक' लेबल अंकित किया जाता है।

2. कृषि उत्पाद (विकास एवं भंडारण) निगम अधिनियम, 1956—इस अधिनियम के द्वारा देश के उत्पादकों एवं व्यापारियों को खाद्यान्न संग्रहण के लिए उचित भंडारण सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराना है। यह अधिनियम 1962 में सहकारिता के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम एवं भंडार-गृह सुविधा के लिये राष्ट्रीय भंडारण अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। शीत संग्रह के लिये शीत संग्रहण आदेश, 1964 व 1980 पारित किया गया है।

3. फल-उत्पाद नियन्त्रण अधिनियम, 1948 व 1955—इस अधिनियम के अन्तर्गत फलों से शर्बत, रस व अन्य उत्पाद बनाने के नियमन एवं नियन्त्रण की व्यवस्था की जाती है।

4. बाण्डा सचिदा (नियमन) अधिनियम, 1952—इस अधिनियम का उद्देश्य देश में विभिन्न वस्तुओं के बाण्डा-बाजार का नियमन करना है जिससे बाजार में वस्तुओं की अनाधिकृत सट्टेबाजी नहीं होने पाये।

5. भार एवं पैमाना मानकीकरण अधिनियम, 1958—इस अधिनियम के द्वारा विपणन में मानकीकृत बाट एवं पैमाना का उपयोग करना है। सरकार ने 1960 से देश में मीट्रिक बाट एवं 1963 से मीट्रिक पैमानों का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है।

6. कृषि उपज विपणन अधिनियम—विभिन्न राज्यों में मण्डियों को नियन्त्रित करने हेतु समय-समय पर अनेक अधिनियम पारित किये गये हैं।

7. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं 1976—इस अधिनियम का उद्देश्य अपमिश्रण करके एवं भ्रामक नाम में खाद्य पदार्थों के विपणन पर कानूनन नियन्त्रण करना है।

8. मानक माप-वोल (डिब्बा बन्द वस्तुएँ) अधिनियम, 1977—इस अधिनियम का उद्देश्य डिब्बा बन्द वस्तुओं के सही तोल, बन्द वस्तु के गुणों के बारे में सूचना, सही कीमत का उपभोक्ता को अवगमन कराना है।

9. निर्यात विस्म नियन्त्रण एवं जाँच अधिनियम, 1963—इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के गुणों का नियन्त्रण करने से है, जिससे विदेशी बाजार में वस्तुओं की मांग बनी रहे।

10 राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्नों के व्यापारियों के लिए जारी अनुज्ञा-पत्र नियम—इन नियमों का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा खाद्यान्न व्यापारियों को नियन्त्रण में रखने से है, जिससे वे अपने स्टॉक एवं कीमतों की घोषणा करें।

खाद्यान्नों के थोक व्यापार का सरकार द्वारा अधिग्रहण

खाद्यान्नों के थोक व्यापार का सरकार द्वारा अधिग्रहण से तात्पर्य देश में खाद्यान्न (प्रमुखतया गेहूँ एवं चावल) के थोक व्यापार को निजी क्षेत्र में करने पर प्रतिबन्ध लगाने से है। खाद्यान्न के थोक व्यापार अधिग्रहण के अन्तर्गत वर्षों 1973 से गेहूँ एवं खरीफ 1974 से चावल का व्यापार सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया गया। गेहूँ एवं चावल भारत के प्रमुख खाद्यान्न हैं जो देश के कुल खाद्यान्न-उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत होते हैं।

खाद्यान्नों के थोक व्यापार अधिग्रहण के अनुसार, गेहूँ एवं चावल एक राज्य में दूसरे राज्य में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, भारतीय खाद्य निगम, राज्य सहकारी विपणन सघ, खाद्य एवं पूर्ति विभाग एवं अन्य सरकारी स्थापनों के माध्यम के बिना नहीं ले जाया जा सकता है। व्यापारी उपर्युक्त दोनों खाद्यान्नों का क्रय-विक्रय नहीं कर सकते हैं। मुदरा व्यापारी लाइसेंस प्राप्त करके सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर गेहूँ एवं चावल क्रय-विक्रय कर सकते हैं।

खाद्यान्न के थोक व्यापार अधिग्रहण के उद्देश्य—खाद्यान्नों के थोक व्यापार के सरकार द्वारा अधिग्रहण के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे—

1 गेहूँ एवं चावल के विक्रय-अधिशेष की मात्रा को नियन्त्रित करना, जिससे उनमें होने वाली सट्टेबाजी तथा कृत्रिम कमी को समाप्त करके कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके।

2 उत्पादक कृषकों से लाभप्रद कीमतों पर खाद्यान्न क्रय करना, जिससे कृषकों को खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने की प्रेरणा मिले।

3 उपभोक्ताओं (विशेषकर कमजोर वर्ग) को उचित कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध करना।

4 उत्पादक कृषक एवं उपभोक्ता के मध्य पाये जाने वाले बिचौलियों को समाप्त करना, जिससे विपणन लागत में कमी हो सके।

खाद्यान्न के थोक व्यापार अधिग्रहण की आवश्यकता—निम्न परिस्थितियों के कारण सरकार को देश में खाद्यान्नों के थोक व्यापार का अधिग्रहण करने की आवश्यकता महसूस हुई—

1 सरकार की मान्यता है कि उत्पादक कृषकों को, वर्तमान विपणन-प्रणाली में खाद्यान्न के विक्रय से उचित कीमत प्राप्त नहीं होती है। कृषकों के पास

संग्रहण की उचित सुविधा एवं क्षमता नहीं होने से फसल कटाई के तुरन्त बाद उन्हें उत्पाद बेचना होता है। उस समय बाजार में खाद्यान्नों की पूर्ति की अधिकता व मांग के पूर्ति की अपेक्षा कम होने के कारण, कीमतें अत्यधिक नीचे गिर जाती हैं। समृद्धि-शाली व्यापारी एवं बिचौलिये न्यूनतम कीमतों पर खाद्यान्न क्रय करके लाभ उठाते हैं। अतः सरकार द्वारा निर्धारित समाजवादी लक्ष्य की प्राप्ति, कृषकों को श्रम का उचित मूल्य दिलाने एवं उनके शोषण को समाप्त करने के लिए खाद्यान्नों के थोक व्यापार के अधिसंग्रहण की आवश्यकता प्रतीत हुई।

2 वर्तमान विपणन व्यवस्था में जमाखोरी व मुनाफाखोरी चरम सीमा पर है। बिचौलिए वस्तु की जमाखोरी व मुनाफाखोरी द्वारा वस्तुओं की कृत्रिम कमी उत्पन्न करके कीमतों में वृद्धि करने में सफल होते हैं। सरकार का एक उद्देश्य इस वर्ग को प्राप्त हो रहे अधिक लाभ की राशि पर नियन्त्रण करना है। अतः खाद्यान्नों के थोक व्यापार अधिसंग्रहण की आवश्यकता प्रतीत हुई।

3 वर्तमान विपणन व्यवस्था में समाज के गरीब उपभोक्ता वर्ग को उचित कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। सरकार गरीब वर्ग को उचित कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए भी वर्तमान विपणन व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहती है।

4 देश के सूखे एवं अकालग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्नों की उपलब्धि की समुचित व्यवस्था करना, जिससे भुखमरी पर नियन्त्रण किया जा सके। इसके लिए भी खाद्यान्नों के व्यापार का सरकार द्वारा अधिसंग्रहण करना आवश्यक है।

5 कीमतों में असाधारण वृद्धि होने पर जनता का सरकार में विश्वास समाप्त हो जाता है, जिससे समाज की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव आता है। अतः देश के विकास एवं सफलभूत योजना के लिए कीमत स्थिरीकरण करना आवश्यक है। कीमत स्थिरीकरण के उद्देश्य हेतु भी सरकार व्यापार का अधिसंग्रहण करती है।

खाद्यान्नों के थोक व्यापार में आने वाली प्रमुख कठिनाइयाँ—खाद्यान्नों के थोक व्यापार की योजना को सुचारु रूप से कार्यान्वित करने में सरकार को निम्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जिससे खाद्यान्न अधिसंग्रहण के निर्धारित उद्देश्य प्राप्त करने में सरकार पूर्णतः सफल नहीं हो पाई है—

- (1) सरकार के पास देश के विभिन्न जिलों, तहसीलों एवं ग्रामों के स्तर पर खाद्यान्न संग्रहण के लिए आवश्यक संस्था एवं क्षमता के गोदामों का अभाव होना।

- (2) देश के 2,699 शहरो तथा 5,66,878 ग्रामो से खाद्यान्न क्रय करके देश में चारो ओर फैले हुए उपभोक्ताओ को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व सक्षम व्यवस्था का अभाव होना ।
- (3) खाद्यान्न के व्यापार में लगे हुए 17 लाख व्यक्तियों के रोजगार छिन जाने से देश में बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि होने की आशंका में असन्तोष की लहर का फैलना ।
- (4) सरकार के पास आवश्यक वित्तीय साधनों का अभाव होना । खाद्यान्न के मस्रदेण, गोदामों के निर्माण, खाद्यान्न के धन्य के लिए कार्यशील पूंजी, कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए वित्त की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाना भी बहुत बड़ा कठिनाई है ।
- (5) निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यापारी वर्ग से प्रतिस्पर्धा, सरकार के एक मात्र नेता होने से एकाधिकार क्रय-पद्धति के दोष, सरकारी कार्य-कलापों के व्यवहार में क्लृप्त एव मष्टाचार का व्याप्त होना ।

समाजवादी कदम की सफलता के लिए सरकार को जनता का पूर्ण सहयोग मिलना आवश्यक है । जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने पर ही सरकार निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेगी तथा उत्पादको एव उपभोक्ताओ को लाभ प्राप्त हो सकेगा । इस योजना में सरकार को जनता का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ । अतः सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन को खरीफ 1974 में स्थगित कर दिया ।

कृषि-कीमतें एवं उनमें उतार-चढ़ाव

प्रत्येक व्यवसाय की सफलता का मापदण्ड व्यवसाय में प्राप्त लाभ की राशि होती है। कृषि एक व्यवसाय है। इसकी सफलता का मापदण्ड भी इस व्यवसाय से प्राप्त लाभ ही होता है। कृषि-व्यवसाय में प्राप्त होने वाले लाभ की राशि, उत्पादित कृषि-उत्पादों की मात्रा एवं उनकी बाजार कीमत पर निर्भर करती है। कृषि-व्यवसाय से अधिकतम लाभ की प्राप्ति के लिए कृषकों को उत्पादन वृद्धि के नये तकनीकी ज्ञान के उपयोग के साथ-साथ उत्पाद के विपणन से अधिकतम कीमत प्राप्त करने की विधियाँ भी अपनानी चाहियें। विपणन के सम्बन्ध में उचित निर्णय नहीं लेने की स्थिति में कृषकों को उत्पादित उत्पाद की मात्रा की अधिगन्तम कीमत प्राप्त नहीं हो पाती है। अतः कृषि-व्यवसाय की सफलता के लिए कीमतों का ज्ञान महत्वपूर्ण होता है।

कृषि कीमतों से तात्पर्य .

किसी वस्तु या सेवा के विनिमय-मूल्य को मुद्रा के रूप में प्रकट करने को उस वस्तु या सेवा की कीमत कहते हैं। प्रो० वेट एव ट्रेसोगन के शब्दों में कीमत, मुद्रा की इकाइयों के रूप में अभिव्यक्त मूल्य होती है। कीमतों के उपर्युक्त अन्विष्टों को कृषि-वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किये जाने पर कृषि-कीमत शब्द का उपयोग किया जाता है।

कृषि कीमतों के कार्य

कृषि-कीमतें अनेक कार्य सम्पन्न करती हैं जिनमें से कुछ देश के आर्थिक विकास में विशेष महत्व रखते हैं। कृषि-कीमतों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

- (1) कृषि-कीमतें विभिन्न वस्तुओं के विनिमय मूल्य एवं उनमें पारस्परिक सम्बन्ध को प्रदर्शित करती हैं। स्वतन्त्र उद्यम वाली अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का मूल्य उनकी कीमतों के द्वारा आँका जाता है और यही मूल्यांकन विधि उपभोक्ताओं की आय को तथा व्यय करने की प्रवृत्ति को संचालित करती है।
- (2) कृषि-कीमतें, कृषि-वस्तुओं की माँग एवं पूर्ति की शक्तियों में साम्यावस्था/सन्तुलन स्थापित करती हैं। कीमतों के बढ़ने पर

सामान्यतया वस्तुओं की मांग कम हो जाती है तथा कीमतों के कम होने पर उनकी मांग बढ़ जाती है। कीमतों के आधार पर ही मण्डी में एकत्रित खान्दाओं का क्रय-विक्रय होता है।

- (3) कीमतें विभिन्न कृषि वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करती हैं। सीमित उत्पादन साधनों का उपयोग उन फसलों के उत्पादन में किया जाता है जिनकी प्रति इकाई कीमत अधिक होती है। साथ ही विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का निर्धारण अन्य कारकों के प्रतिरिक्त उनकी कीमतों पर प्रमुखतया निर्भर करता है। अतः कृषि कीमतें फार्म पर अनुकूलतम लाभ की प्राप्ति के लिए विभिन्न उद्यमों के अन्तर्गत उत्पादन-साधनों के आवंटन कार्य में सहायक होती हैं।
- (4) कीमतें कृषि वस्तुओं के उपभोग की मात्रा का निर्धारण करने में सहायक होती हैं। कीमतों के द्वारा ही वस्तु की उपलब्ध मात्रा का विभिन्न उपभोक्ताओं में आवंटन होता है। वस्तुओं की कमी की अवस्था में कीमतें बढ़ जाती हैं और उपभोक्ता क्रय की मात्रा कम कर देते हैं। इसके विपरीत वस्तु की पूर्ति की अधिकता की अवस्था में कीमतें गिर जाती हैं और उपभोक्ता क्रय की मात्रा में वृद्धि करते हैं।
- (5) कृषि कीमतें कृषि-व्यवसाय में पूंजी निवेश की राशि को प्रभावित करती हैं। कृषि कीमतों के अधिक स्तर पर निर्धारित होने पर कृषि-व्यवसाय में पूंजी निवेश की राशि में वृद्धि होती है।
- (6) कीमतें औद्योगिक संस्थाओं, विभिन्न व्यवसायों एवं फार्म पर विभिन्न उद्यमों के अन्तर्गत साधन आवंटन का कार्य सम्पन्न करती हैं। उत्पादन-साधन निरन्तर कम लाभ वाले उपयोगों से अधिक लाभ वाले उपयोगों की ओर गतिशील होते हैं। इसी आधार पर विभिन्न व्यवसायों में सीमित उत्पादन-साधनों का आवंटन होता है।
- (7) कीमतें विपणन एवं स्वामित्व सम्बन्धी समस्याओं को सुविधाजनक तरीकों से हल करने के निर्णय लेने में सहायक होती हैं।
- (8) कीमतें विभिन्न कृषि वस्तुओं के संग्रहण एवं विभिन्न स्थानों पर परिवहन सम्बन्धी निर्णय लेने में सहायक होती हैं। कीमतों में होने वाले परिवर्तनों के कारण ही वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन एवं एक मौसम से दूसरे मौसम तक संग्रहण होता है।
- (9) कृषि-कीमतें विभिन्न वर्गों एवं ग्रंथ-अवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आय-वितरण को प्रभावित करती हैं।

(10) कीमते मौसममापी यन्त्र की भाति भावी आर्थिक परिस्थितियों का ज्ञान प्रदान करती है।

कृषि-कीमतों के अध्ययन की आवश्यकता

समाज के सभी वर्गों—कृषको उत्पात्ताओं उद्योगपतियों एवं व्यवसायियों तथा सरकार के लिए कृषि कीमतों का अध्ययन आवश्यक होता है। कीमतों के अध्ययन का ज्ञान कृषका को व्यवसाय सुचारु रूप में चलाने, उत्पात्ताओं की रहस्य-सहन का उचित स्तर बनाकर रखने उद्योगपतियों का उत्पादन की नीति निर्धारण करने एवं सरकार को राष्ट्रीय योजनाओं के निर्माण एवं उह कार्यान्वित करने में सहायक होना है। समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कृषि कामों के अध्ययन की महत्ता का विवेचन यहाँ किया गया है—

कृषकों के लिए कृषि कीमतों की आवश्यकता कृषकों के लिए फार्म में प्राप्त आय उत्पाद की उत्पादित मात्रा एवं उनकी बाजार कीमत पर निर्भर करती है। मण्डी कीमत के ज्ञान के अभाव में कृषक फार्म से अधिकतम लाभ की राशि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कृषि-कीमतों का ज्ञान कृषकों को फार्म पर निम्न निरूप्य लेने में सहायक होता है। ये निरूप्य फार्म पर होने वाली लागत में कमी अथवा प्राप्त होने वाले लाभ की राशि में वृद्धि करते हैं—

- (i) कृषकों को फार्म पर विभिन्न उद्यमों के चयन एवं उत्पादन सम्बन्धी निर्णय लेने में कीमतों का ज्ञान सहायक होता है।
- (ii) चुन हुए उद्यमों में अधिकतम लाभ की प्राप्ति के लिए उनके प्रबन्ध सम्बन्धी निर्णय लेने जैसे—प्रति इकाई भूमि के क्षेत्र में विभिन्न फसलों में कितना उर्वरक उपयोग करना चाहिए, विभिन्न उर्वरकों में से कौनसे उर्वरक का उपयोग करना चाहिए, उर्वरक का किस विधि में उपयोग करना चाहिए, सिंचाई कब एवं किन्नी मर्यादा में देनी चाहिए आदि।
- (iii) सीमित उत्पादन साधना का किस उद्योग के उत्पादन में उपयोग किया जाये जिससे लाभ की अधिकतम राशि प्राप्त हो सके।
- (iv) कृषि उत्पादों के विक्रय एवं उत्पादन साधना के क्रय के लिए समय स्थान एवं विपणन माध्यम के चयन का निर्णय करने में कीमतों का ज्ञान कृषकों के लिए आवश्यक होता है।
- (v) कृषि कीमतों कृषका को फार्म-योजना बनाने में सहायक होती है।

प्राचीन काल में कृषि कीमतों का ज्ञान कृषकों के लिए वर्तमान की भांति आवश्यक नहीं था। उस काल में कृषक कृषि को व्यवसाय के रूप में नहीं अपनाकर जोड़कोराजन के रूप में अस्तित्व में थे। फार्म पर धरे हुए आवश्यकता के नतीजा उत्पाद उत्पन्न करने में जिसमें उनका पास विक्रय के लिए उत्पाद की मात्रा बहुत कम होती

यी। वर्तमान में कृषकों द्वारा विशिष्टीकरण कृषि पद्धति के अपनाये जाने के कारण फार्म पर एक या दो फसलें उत्पन्न की जाती हैं जो प्रमुखतया मण्डी में विक्रय के लिए ही होती हैं। कृषि में तकनीकी ज्ञान के आविष्कार एवं उपयोग के कारण विभिन्न वस्तुओं की उत्पादकता एवं विक्रेय-अधिशेष की मात्रा में वर्तमान में अधिक वृद्धि हुई है, जिसके कारण वे अधिक मात्रा में कृषि वस्तुओं का विक्रय करते हैं। अतः उत्पाद के विक्रय से अधिकतम कीमत प्राप्त करने के लिए कृषकों को विभिन्न मण्डियों में प्रचलित कीमतों का ज्ञान होना आवश्यक है।

प्राचीन काल में कृषि-वस्तुओं के विक्रय के लिए वर्तमान की भांति विकसित मण्डियाँ, विपणन-माध्यम एवं विपणन-माध्यम भी नहीं थे। वस्तुओं का विक्रय वस्तु-विनिमय प्रथा द्वारा होता था, जिसमें एक कृषक अपने अधिशेष उत्पाद की मात्रा को दूसरे व्यक्ति की अधिशेष उत्पाद की मात्रा से विनिमय कर लेता था। वर्तमान में विपणन कीमतों के आधार पर होता है। अतः कृषकों के लिए कीमतों का ज्ञान वर्तमान में अत्यावश्यक है।

II उपभोक्ताओं के लिए कृषि-कीमत ज्ञान की आवश्यकता—कृषि-कीमतों का ज्ञान देश के उपभोक्ताओं को भी उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुओं के चुनाव, उनकी मात्रा का निर्धारण एवं क्रय करने के निर्णय लेने में सहायक होता है। उपभोक्ताओं की प्रायः का अधिकांश भाग कृषि-वस्तुओं जैसे खाद्यान्न, दालें, तिलहन, फल, सब्जी, दूध, अण्डे आदि के क्रय पर व्यय होता है। कृषि-वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने से, उपभोक्ता अपनी सीमित आय में पहले की अपेक्षा कम मात्रा में वस्तुएँ क्रय कर पाते हैं, जिससे उनके रहन-सहन के स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः प्रायः वाले उपभोक्ताओं का तो जीवन-निर्वाह करना कठिन हो जाता है। अतः कीमतों का ज्ञान उपभोक्ताओं को सीमित आय में अनुकूलतम स्तर का जीवन-यापन करने हेतु विभिन्न निर्णय जैसे—वस्तुओं के क्रय के लिए मण्डी, समय एवं विपणन-माध्यम का चुनाव करने, विभिन्न वस्तुओं का चुनाव एवं उनकी क्रय की मात्रा निर्धारण करने में सहायक होता है।

III उद्योगपतियों एवं व्यवसायियों के लिए कृषि-कीमतों के ज्ञान की आवश्यकता—उद्योगपतियों एवं व्यवसायियों के अधिकांश उद्योग जैसे—घीनी, जूट, चाय, केरडा, तिलहन आदि की उत्पादन, विस्तार एवं कीमत-नीति, कृषि-कीमतों पर निर्भर करती है, क्योंकि कृषि-क्षेत्र ही इन उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल प्रदान करता है। कच्चे माल का उत्पादन कम होने एवं उनके उत्पादन की लागत के बढ़ने से उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है जिससे उनकी उत्पादन एवं विस्तार नीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कृषि-कीमतों का ज्ञान उद्योगपतियों एवं व्यवसायियों को निम्न निर्णय लेने में सहायक होता है—

- (1) विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल क्रय करने के लिए समय एवं मण्डी का चुनाव एवं क्रय की मात्रा का निर्णय लेना।

- (ii) विभिन्न उद्योगों से निर्मित वस्तुओं के ऋय से अधिकतम लाभ की प्राप्ति के लिए समय मण्डी, विपणन-माध्यम एवं विपणन विधि के चुनाव के सम्बन्ध में निर्णय लेना ।
- (iii) विभिन्न उद्योगों को स्थापित करने के लिए स्थान के चुनाव, क्षमता आदि के निर्णय लेना ।
- (iv) उद्योगों द्वारा निर्मित माल की उत्पादन-सागत को कम करने के लिए तकनीकी ज्ञान के स्तर का उपयोग, विभिन्न उत्पादन विधियों एवं नियायों के प्रतिस्थापन आदि के सम्बन्ध में निर्णय लेना ।

IV सरकारी सस्याओं के लिए कृषि-कीमत ज्ञान की आवश्यकता—सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी सस्याओं, प्रशासका एवं नीति निर्धारका के लिए कृषि-कीमतों का ज्ञान कृषि विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में निर्णय लेने में सहायक होता है । कीमता के ज्ञान के आधार पर लिये गये निर्णय सही एवं उचित होते हैं तथा देश के विकास में सहायक होते हैं । कृषि-कीमतों का ज्ञान विभिन्न सस्याओं को निम्न निर्णय लेने में सहायक होता है—

- (i) कृषि विकास कार्यक्रमों को सुचारु रूप से कार्यान्वित करना ।
- (ii) कृषि-विकास कार्यक्रमों के परिणामों का मूल्यांकन करना ।
- (iii) कृषि-विकास के लिए आवश्यक पूरक सस्याएँ जैसे—कृषि-सूचना-सेवा, सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, परिवहन सुविधाओं का विकास आदि से सम्बन्धित निर्णय लेना ।
- (iv) देश में सघन कृषि-योजना, उन्नत किस्मा के बीजों का अधिकाधिक उपयोग, बहुफलसीय कार्यक्रम, लघु कृषक विकास योजना, नियन्त्रित मण्डियों के विकास से सम्बन्धित निर्णय लेना ।

कृषि कीमतों में उतार-चढ़ाव

कृषि-कीमतों में प्रतिवर्ष, मौसम, माह, दिन व एक ही दिन में विभिन्न समयों में परिवर्तन अर्थात् उतार-चढ़ाव पाये जाते हैं । वैसे तो सभी वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव पाये जाते हैं लेकिन कृषि-वस्तुओं की कीमतों में औद्योगिक एवं निर्मित वस्तुओं की अपेक्षा उतार-चढ़ाव अधिक होता है । कृषि-वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव अधिक होने से कृषकों की आय में अनिश्चिन्ता, उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में परिवर्तन तथा कृषि-आधारित उद्योगों की उत्पादन नीति में अस्थिरता बनी रहती है । कृषि-कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से समाज के विभिन्न वर्गों निम्न-निम्न प्रकार से प्रभावित होते हैं । सामान्यतया कृषि-कीमतों के अत्यधिक परिवर्तन से उत्पादक एवं उपभोक्ता वर्गों का विशेष हानि होती है । कीमतों के उतार-चढ़ाव का मुख्य लाभ समाज का समृद्ध वर्ग उठाता है ।

भारत में कृषि-कीमतों में उतार-चढ़ाव सर्वप्रथम वर्ष 1914-1920

की अवधि में पाये गये। इस काल में कीमत वृद्धि के प्रमुख कारण प्रथम महायुद्ध (1914-18) का होना, कृषि-पदार्थों की आन्तरिक मांग एवं मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होना था। वर्ष 1920 के बाद कीमतों में गिरावट आई। वर्ष 1929-30 में विश्व-व्यापी आर्थिक मन्दी के कारण कीमतों में अत्यन्त गिरावट हुई, जिससे कृषकों की आर्थिक दशा बहुत दयनीय हो गई। सितम्बर, 1939 में द्वितीय-महायुद्ध के प्रारम्भ होने से 1939 में कीमतों में पुनः वृद्धि प्रारम्भ हुई। कीमत वृद्धि वर्ष 1950-51 तक निरन्तर होती रही। इस दशक में कीमतों में तीव्र गति से वृद्धि होने के कारणों में सरकार द्वारा सैनिक सुविधाओं के विकास पर व्यय राशि में वृद्धि, मौसम की प्रतिकूलता के कारण उत्पादन में कमी, देश का विभाजन, विस्थापितों के पुनर्वास पर भारी राशि में व्यय प्रमुख हैं।

विभिन्न समयों में प्रचलित कीमतों के स्तर को कीमत सूचकांक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विभिन्न वस्तुओं के समूहों एवं विभिन्न कृषि-पदार्थों की धाक कीमतों के सूचकांक भारत सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी सलाहकार द्वारा जनवरी 1942 में प्रकाशित किये जा रहे हैं। कीमत सूचकांक ज्ञात करने में विभिन्न समयों में विभिन्न आधार वर्ष लिए गए हैं। साथ ही सूचकांक ज्ञात करने में वस्तुओं की संख्या एवं उनके भार में भी समय समय पर परिवर्तन किए गये हैं। इन सूचकांकों में होने वाले परिवर्तन इनकी कीमतों में वृद्धि अथवा कमी का सूचक होते हैं। सारणी 16 में वर्ष 1950-51 से 1968-69 के काल में 1952-53 के आधार पर विभिन्न वस्तुओं के समूहों के थोक कीमत सूचकांक एवं विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में थोक कीमत सूचकांक में हुए प्रतिशत परिवर्तन प्रदर्शित करती है।

सारणी 16 1

विभिन्न वस्तुओं के समूहों की थोक कीमतों के सूचकांक एवं विभिन्न पंचवर्षीय योजना काल में हुए प्रतिशत परिवर्तन

(आधार वर्ष 1952-53=100)

वर्ष	सभी वस्तुएँ	खाद्य पदार्थ	मादक द्रव्य एवं तम्बाकू	इधन विजली, प्रकाश व स्निग्ध पदार्थ	औद्योगिक कच्चा माल	निमित्त माल
1	2	3	4	5	6	7
1950-51	111.8	112.5	98.4	92.6	130.9	101.8
1951-52	118.0	111.0	121.9	96.5	141.5	100.7
1952-53	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1953-54	104.6	106.7	98.7	99.2	107.4	100.1
1954-55	97.4	94.6	90.6	97.1	94.6	99.6
1955-56	92.5	86.6	81.0	95.2	99.0	99.7

१०४/भारतीय कृषि का अर्थतन्त्र

प्रथम पञ्चवर्षीय

योजनाकाल में -17.27 -23.03 -17.69 -2.80 -3.49 -24.37
प्रतिशत परिवर्तन

१९५०-५१	105.3	102.3	84.4	104.2	116.0	106.3
1957-58	108.4	106.4	94.0	113.5	116.5	108.1
१९५८-५९	112.9	112.2	95.4	115.4	115.6	108.4
१९५९-६०	117.1	119.0	99.5	116.5	123.7	111.7
१९६०-६१	124.9	120.0	109.9	120.0	145.4	123.9

द्वितीय पञ्चवर्षीय

योजनाकाल में -35.02 -38.56 -35.67 -26.05 -24.27 -46.86
प्रतिशत परिवर्तन

१९६१-६२	125.1	120.1	100.3	122.1	142.6	126.6
१९६२-६३	127.9	126.1	100.9	124.4	136.5	128.5
1963-64	135.3	136.8	119.6	139.4	139.5	131.1
१९६४-६५	152.7	159.9	131.2	144.9	162.7	137.3
१९६५-६६	165.1	168.9	136.6	153.0	159.1	149.3

तृतीय पञ्चवर्षीय

योजना काल

में +32.18 +40.75 +24.29 +25.00 +20.33 +30.05
प्रतिशत

परिवर्तन

1966-67	191.3	199.9	130.3	169.7	228.7	160.0
1967-68	212.4	242.2	136.6	184.1	219.1	165.5
1968-69	210.2	231.3	212.1	192.5	222.7	168.6

चौथा वार्षिक

योजनाकाल में -9.88 -15.70 -38.58 +13.43 -2.63 +3.43
प्रतिशत परिवर्तन

स्रोत निम्नलिखित हैं: भारत इन्स्टीट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक्स, बॉम्बे, खण्ड XXIII, पृष्ठ 11, नवम्बर १९६९, इच्छा 1855.

सारणी 162

प्रमुख वस्तुओं के समूहों के थोक कीमत सूचकांक (वार्षिक औसत)
(आधार वर्ष 1961-62=100)

वर्ष	सभी वस्तुएँ	साथ पदार्थ	मादक द्रव्य एवं तम्बाकू	इंधन बिजली एवं स्निग्ध पदार्थ	औद्योगिक ंकड़ा माल	रसायन	मशीनें एवं परिवहन उपकरण	निमित्त वस्तुएँ
1961-62	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1962-63	1049	1048	1215	1168	970	1136	1065	1031
1963-64	1133	1198	1235	1194	1054	1177	1094	1061
1964-65	1223	1323	1333	1216	1164	1195	1140	1122
1965-66	1375	1503	1331	1307	1436	1330	1204	1235
1966-67	1589	1879	1326	1356	1656	1509	1302	1303
1967-68	1603	1943	1667	1467	1414	1618	1321	1303
1968-69	1651	1865	2155	1529	1716	1772	1332	1381
1969-70	1757	1998	1882	1601	1858	1934	1402	1489
1970-71	1806	1998	1849	1627	1910	1895	1515	1604
1971-72	1923	2165	2091	1781	1785	1988	1628	1734
1972-73	2185	2501	2491	1876	2364	2084	1716	1834
1973-74	2845	3217	2722	2929	3227	2708	2157	2342
1974-75	3071	3570	3111	3244	2867	3288	2646	2523
1975-76	2829	3052	3121	3668	2419	3131	2606	2539

स्रोत रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन, सण्ड XXIII, 12, दिसम्बर, 1969 एवं सण्ड XXX, सख्या 8, अगस्त, 1976

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कीमतों के सूचकांक में हुए प्रतिशत परिवर्तन के अवलोकन में स्पष्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में सभी वस्तुओं के समूहों की कीमतों के सूचकांक में कमी हुई है। इस योजनाकाल में कीमतों में सर्वाधिक कमी निमित्त मानव खाद्य पदार्थों में हुई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के शुरु से ही कीमतों में निरन्तर वृद्धि हुई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में खाद्य पदार्थों की थोक कीमतों के सूचकांक में 39 प्रतिशत, निमित्त माल में 47 प्रतिशत एवं सभी वस्तुओं में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में खाद्य पदार्थों की थोक कीमतों के सूचकांक में 41 प्रतिशत, निमित्त माल में 30 प्रतिशत एवं सभी वस्तुओं में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तीनों वार्षिक योजनाओं में औद्योगिक कच्चे माल के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं के समूहों की कीमतों में वृद्धि हुई है। तीन पंचवर्षीय योजनाओं एवं तीन वार्षिक योजनाओं में हुए प्रतिशत परिवर्तन के अवलोकन में स्पष्ट है कि औद्योगिक एवं निमित्त वस्तुओं की अपेक्षा खाद्य पदार्थों की कीमतों में प्रशिक्षण परिवर्तन अधिक हुआ है।

कीमतों के सूचकांक की उपर्युक्त सीरीज सितम्बर, 1969 में बन्द कर दी गई और नई सीरीज आचार वर्ष 1961-62 के अनुसार प्रारम्भ हुई। वर्ष 1961-62 से 1975-76 तक विभिन्न वस्तुओं के समूहों के थोक कीमत सूचकांक सारणी 162 में प्रदर्शित हैं। वर्ष 1961-62 से 1975-76 के काल में सभी वस्तुओं के समूहों की कीमतों के सूचकांक में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि सभी वस्तुओं में सम्मिलित रूप से 183 प्रतिशत की हुई। कीमतों में सर्वाधिक वृद्धि खाद्य पदार्थ, मादक-द्रव्य तथा ईंधन, बिजली एवं स्निग्ध पदार्थ के समूहों में व सबसे कम वृद्धि निमित्त वस्तुओं के समूह में हुई है। कीमतों के सूचकांक में वृद्धि की दर 1973-74 में अन्य वर्षों की अपेक्षा अधिक थी। कीमतों के सूचकांक में 1961-62 से 1974-75 तक निरन्तर वृद्धि हुई है, लेकिन अप्रैल, 1975 के पश्चात् कीमतों के थोक सूचकांक में गिरावट आई है।

थोक कीमत सूचकांक ज्ञात करने के आचार वर्ष 1961-62 को बन्द करके, सरकार ने वर्ष 1970-71 को आचार वर्ष मानकर कीमत सूचकांक आकलन अप्रैल, 1971 से प्रारम्भ किया है। सूचकांक आकलन करने की इस नई सीरीज में विभिन्न वस्तुओं के समूहों में वस्तुओं की संख्या एवं उनके महत्ता के लिए दिए गए भार (Weight) में भी परिवर्तन किया है, जिसके कारण पिछले आकड़े तुलनात्मक नहीं हैं। वर्ष 1970-71 के आचार वर्ष पर विभिन्न वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक 1970-71 से 1987-88 तक के सारणी 163 में दिए गए हैं।

सारणी 163

विविध वस्तुओं के समूहों के बीच कीमत सूचकांक (वार्षिक औसत)

आधार वर्ष 1970-71=100

वर्ष	प्राथमिक वस्तुएं			इधन, ऊर्जा, विजली		
	समी वस्तुएं (1000)	सभी (416 67)	साथ वस्तुएं (297 99)	महाद्य वस्तुएं (118 68)	एव स्निग्ध पदार्थ (84 59)	निर्मित माल (498 74)
1970-71	100 0	100 0	100 0	100 0	100 0	100 0
1971-72	105 6	109 9	101 1	98 6	105 9	109 5
1972-73	116 2	110 7	111 3	107 5	110 1	121 9
1973-74	139 7	141 8	136 6	146 6	130 6	139 5
1974-75	174 9	177 5	172 1	163 7	198 3	168 8
1975-76	173 0	165 8	163 6	139 8	219 2	171 2
1976-77	176 6	167 2	155 3	167 0	230 8	175 2
1977-78	185 8	183 8	173 6	178 0	234 2	179 2
1978-79	185 8	181 4	172 4	170 4	244 7	179 5
1979-80	217 6	206 5	186 6	194 6	283 1	215 8
1980-81	257 3	237 5	207 9	217 7	354 3	257 3
1981-82	281 3	264 4	235 1	240 5	427 5	270 6
1982-83	288 6	273 9	249 6	244 6	458 7	272 1
1983-84	316 0	304 0	283 1	281 6	494 8	295 8
1984-85	338 4	324 4	297 4	319 6	518 4	319 5
1985-86	357 8	331 0	317 7	286 8	579 9	342 6
1986-87	376 8	349 0	339 0	305 0	619 0	359 0
1987-88	405 4	383 0	367 0	386 0	642 0	384 0

टिप्पणी वीछक से दिए मूल्य वस्तुओं के मार प्रदर्शित करते हैं।

स्रोत Reserve Bank of India Bulletin—Various Issues, Reserve Bank of India, Bombay

वर्ष 1970-71 से 1987-88 के काल में भी कीमतों में निरन्तर वृद्धि हुई है। कीमतों में निरन्तर वृद्धि के कारण सभी वस्तुओं का थोक कीमत सूचकांक 405.4 एवं प्राथमिक वस्तुओं का सूचकांक 383.0 हो गया। इस काल में सर्वाधिक कीमत वृद्धि ई धन, ऊँचा, विजली एवं स्निग्ध पदार्थों के सूचकांक में एवं सबसे कम कीमतों में वृद्धि खाद्य वस्तुओं के समूह में पाई गई। वर्ष 1975-76 में प्राथमिक वस्तुओं के कीमत सूचकांक में प्रथम बार कमी हुई थी, जिसके कारण अन्य वस्तुओं के थोक कीमत सूचकांक में भी कमी हुई थी।

थोक कीमत सूचकांक ज्ञात करने के आधार वर्ष 1970-71 को बन्द करके सरकार ने वर्ष 1981-82 को आधार वर्ष मानकर कीमत सूचकांक आकलन वर्ष 1981-82 से प्रारम्भ किया है। सूचकांक आकलन करने की इस नई सीरीज में विभिन्न वस्तुओं के समूहों में वस्तुओं की मर्यादा एवं उनके महत्वता को दिए गए भार (Weight) में भी परिवर्तन किया है। अतः पिछले आधार वर्ष के आधार पर दिए गए कीमत सूचकांक आंकड़े वर्तमान आधार वर्ष के आंकड़ों से तुलनात्मक नहीं हैं। वर्ष 1981-82 के आधार वर्ष पर विभिन्न वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 1981-82 से 1991-92 तक के सारणी 16.4 में दिए गए हैं। सारणी से स्पष्ट है कि पिछले 10 वर्षों में सभी वस्तुओं की कीमतों में लगभग 100 प्रतिशत से अधिक (घातु के अतिरिक्त) की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि खाद्य वस्तुओं की कीमतों में हुई है। खाद्यान्नों की कीमतों में उतार-चढ़ाव।

सारणी 16.5 विभिन्न खाद्यान्नों की कीमतों के सूचकांक वर्ष 1970-71 के आधार पर प्रदर्शित करती है।

वर्ष 1961-62 से 1987-88 की अवधि में सभी खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि हुई है। कीमतों में वृद्धि की गति वर्ष 1972-73 के बाद में असामान्य थी। खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि की दृष्टि से वर्ष 1974-75 विशेष उल्लेखनीय है। सरकार ने खाद्यान्नों की कीमतों में हुई असामान्य वृद्धि को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें से मुद्रा-स्फीति को नियन्त्रित करने हेतु पारित अधिनियम प्रमुख हैं। इनके फलस्वरूप वर्ष 1975-76 एवं 1976-77 में खाद्यान्नों की कीमतों में गिरावट आई। आधार वर्ष 1981-82 के अनुसार प्रमुख कृषि उत्पादों के थोक कीमत सूचकांक वर्ष 1982-83 से 1990-91 है। सारणी 16.4 में दिए गए हैं।

सारणी 164

विभिन्न वस्तुओं के समूहों के चोक कीमत सूचकांक (वार्षिक औसत)
(आधार वर्ष 1981-82 = 100)

वर्ष	प्राथमिक वस्तुएं				द्वितीय, ऊर्जा, विजली		
	सभी वस्तुएं (100 00)	सभी (32 295)	खाद्य वस्तुएं (17 386)	अखाद्य वस्तुएं (10 081)	घातु (4 828)	एव स्निग्ध पदार्थ (10 663)	निर्मित माल (57 042)
1981-82	100 0	100 0	100 0	100 0	100 0	100 0	100 0
1982-83	104 9	106 7	111 1	100 8	103 3	106 5	103 5
1983-84	112 8	118 2	126 5	112 4	100 4	112 5	109 8
1984-85	120 1	125 5	131 8	124 6	105 1	117 3	117 5
1985-86	125 4	125 7	134 1	120 4	106 5	129 8	124 5
1986-87	132 7	137 1	147 8	134 1	104 2	138 6	129 2
1987-88	143 5	152 6	161 1	163 0	100 5	143 3	138 5
1988-89	154 2	160 1	177 1	160 2	98 5	151 2	151 5
1989-90	165 7	163 6	179 3	166 0	102 2	156 6	168 6
1990-91	182 5	184 9	200 5	194 3	109 0	175 8	182 8
1991-92	207 8	218 3	241 1	229 2	113 5	199 0	203 4

टिप्पणी कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वस्तुओं के भार प्रदर्शित करते हैं।

स्रोत : Reserve Bank of India Bulletin—Various Issues, Reserve Bank of India, Bombay

सारणी 165

प्रमुख कृषि उत्पादों के धोक कीमत सूचकांक (वार्षिक औसत)

(1970-71=100)

[illegible]

1971-72	103 0	109 9	97 0	100 8	99 5	95 0	102 8	101 9	110 7	103 4	99 3
1972-73	116 0	126 0	140 9	125 0	106 5	133 6	131 4	115 8	137 9	119 5	109 3
1973-74	140 2	151 2	165 5	174 2	108 2	190 3	201 3	134 8	176 9	141 9	139 7
1974-75	183 2	203 2	242 0	242 9	183 1	243 0	246 3	191 8	215 7	195 8	174 8
1975-76	178 8	175 6	196 7	173 5	159 6	147 4	201 8	172 6	181 6	174 1	155 0
1976-77	156 9	163 6	146 3	145 4	152 0	174 7	134 5	154 1	145 7	152 7	156 1
1977-78	162 0	157 4	169 1	177 9	156 5	179 3	198 6	161 3	215 2	170 4	174 8
1978-79	161 0				154 0	157 6	247 1	247 0	173 0		
1979-80	184 0				161 0	173 5	244 2	244 0	185 0		
1980-81	206 0				176 0			323 0	217 0		
1981-82	226 0				192 0			339 0	237 0		
1982-83	257 0				214 0			302 0	249 0		
1983-84	292 0				218 0		259 0	347 0	274 0		
1984-85	273 0				210 0		245 0	431 0	276 0		
1985-86	284 0				226 0		262 0	463 0	296 0		
1986-87	302 0				239 0			408 0	299 0		
1987-88	326 0				259 0			494 0	332 0		

स्रोत (i) H L Chandok Wholesale Price Statistics Vol I, India 1947-1978 Economic and Scientific Research Foundation New Delhi 1978

(ii) Economic Survey 1988-89, Ministry of Finance, Government of India New Delhi 1989, P 5-59

सारणी 166

प्रमुख कृषि उत्पादों के थोक कीमत सूचकांक (वार्षिक औसत)

(1981-82=100)

कृषि उत्पाद	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
चावल	1150	1293	1214	1269	1342	1458	1612	1687	1781
गेहूँ	1112	1136	1108	1190	1271	1345	1542	1482	1717
ज्वार	920	994	982	1014	1085	1129	1265	1508	1315
बाजरा	971	1003	935	1189	1233	1338	1350	1264	1375
मक्का	1090	1147	953	1227	1303	1376	1529	1469	1535
जौ	1104	1184	1209	1400	1216	1517	1698	1681	2023
भनाज	1115	1209	1149	1223	1296	1394	1557	1590	1713
चना	781	842	1264	1449	1079	1233	1963	1983	2106
मसूर	1102	1351	1208	1095	1387	1941	1950	1968	2494
दालें	942	1100	1308	1380	1283	1534	1997	2057	2275
खाद्यान्न	1091	1194	1171	1245	1294	1413	1618	1654	1790
फल एवं सब्जियाँ	1105	1364	1452	1353	1694	1802	1851	1705	2040
दूध	1106	1216	1326	1404	1474	1623	1848	2011	2092
सभी खाद्य वस्तुएँ	1111	1265	1318	1341	1478	1611	1771	1793	2005

Index Numbers of wholesale Prices in India, Monthly Bulletin office of the Economic Adviser, Ministry of Industry, Government of India (Various Issues)

कृषि कीमतों के उतार चढ़ाव के रूप •

कृषि वस्तुओं की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ावों को समय के अनुसार मुख्यतः निम्न 6 भागों में विभक्त किया जाता है—

(1) **अल्पकालीन कीमत उतार चढ़ाव**—कृषि-वस्तुओं की कीमतों में होने वाले वे उतार-चढ़ाव जो कुछ समय के लिए ही प्रभावशाली होते हैं, अल्पकालीन उतार-चढ़ाव कहलाते हैं। कीमतों के नियमित उतार-चढ़ावों के कारकों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं होता है। अल्पकालीन उतार चढ़ाव कृषि-वस्तुओं की माग एवं पूर्ति में अचानक परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होते हैं। मौसम में परिवर्तन होना, शादियों का होना, उपभोक्ताओं की आय में अचानक वृद्धि, वर्षा या अन्य कारणों से परिवहन साधनों का समय पर उपलब्ध नहीं होना, बजट में कर लगने की आशंका आदि कारणों से वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को अल्पकालीन उतार-चढ़ाव की श्रेणी में विभक्त किया जाता है। जैसे—मंडी में गेहूँ की प्रति सप्ताह, दिन एवं एक ही दिन में विभिन्न समयों पर विभिन्न कीमतों का होना। कृषि-कीमतों में अल्पकालीन उतार-चढ़ाव निम्न कारणों से होते रहते हैं—

- (अ) कृषि-वस्तुओं की पूर्ति की मात्रा में विस्तृत परिवर्तन होते रहना—कृषि वस्तुओं का उत्पादन मौसम की अनुकूलता पर निर्भर होने एवं उनमें क्षीघ्रनाशी होने का गुण विद्यमान होने के कारण मण्डी में कृषि-वस्तुओं की पूर्ति की मात्रा सदैव नियमित नहीं होती है।
- (ब) कृषि-वस्तुओं की मांग में भी अस्थायी परिवर्तन होते रहते हैं। मांग में परिवर्तन उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि, मौसम के परिवर्तन, शादियों आदि कारणों से होते रहते हैं।
- (स) कृषि-वस्तुओं की माग एवं पूर्ति की मात्रा के आधार पर कीमत-निर्धारण की प्रायोगिक विधि में भी समय लगता है। अतः इस काल में कीमतों में अल्पकालीन उतार चढ़ाव होते हैं।

(2) **मौसमी कीमत उतार-चढ़ाव**—कृषि-वस्तुओं के उत्पादन व उपभोग में मौसम का प्रभाव होने से उनमें मौसमी उतार चढ़ाव पाये जाते हैं। प्रायः सभी कृषि-वस्तुओं के उत्पादन का विशेष मौसम होता है। मौसम-विशेष में पूर्ति की अधिकता के कारण कीमतें गिर जाती हैं और बाद में कीमतें बढ़नी शुरू होती हैं। कुछ कृषि-वस्तुओं का मौसम विशेष में उपभोग अधिक होने के कारण भी कीमतों में मौसमी उतार-चढ़ाव पाये जाते हैं जैसे—अण्डा, मक्का, बाजरा आदि का उपभोग सर्दी की मौसम में अधिक एवं गर्मी की मौसम में कम होता है। कीमतों के मौसमी उतार चढ़ाव उन कृषि वस्तुओं में अधिक पाये जाते हैं जो क्षीघ्रनाशी होती हैं और

... के सम्बन्ध करके नियमित नहीं किया जा सकता है, जैसे—सब्जी, फल,

दूध आदि। कृषि-वस्तुओं की कीमतों के भीमभी उतार-चढ़ाव का ज्ञान कृषकों के लिए विभिन्न उत्पादों के विपणन मन्य के निर्णय लेने में सहायक होता है।

(3) वार्षिक कीमत उतार-चढ़ाव—कृषि-वस्तुओं के उत्पादन एवं पूर्ण की मात्रा में उनके अन्तर्गत क्षेत्रफल, उत्पादकता, बीमारी आदि कारणों से प्रतिवर्ष निरन्तर परिवर्तन होता रहना है, जिसके कारण उनकी विभिन्न वर्षों की कीमतों में भिन्नता होती है। कृषि-वस्तुओं की कीमतों में होने वाले वार्षिक उतार-चढ़ाव में कोई निश्चित नियमितता नहीं पाई जाती है।

(4) चक्रीय कीमत उतार-चढ़ाव—कुछ कृषि-वस्तुओं के उत्पादन एवं कीमतों में चक्रीय गति के विद्यमान होने के कारण उनकी कीमतों में चक्रीय उतार-चढ़ाव अर्थात् उतार-चढ़ाव नियमित समयान्तर पर पाये जाते हैं। चक्र से तात्पर्य नियमित आवर्ती परिवर्तन से है। कुछ कृषि-वस्तुओं के उत्पादन एवं कीमतों का प्रभाव एक वर्ष में प्रदर्शित नहीं होकर अनेक वर्षों, जैसे 3-4 वर्ष के अन्तर से प्रदर्शित होता है। उत्पादन चक्रीय गति के कारण किसी वर्ष उत्पादन के अधिक होने से कीमतें गिर जाती हैं तथा अन्य वर्षों में उत्पादन कम होने से कीमतों में वृद्धि होती है। चक्रीय उतार-चढ़ाव वाली विभिन्न कृषि-वस्तुओं की अवधि विभिन्न समयों की होती है। कीमतों के इन चक्रों में अनेक कारणों से विघ्न उत्पन्न होते रहते हैं जिससे इनकी अवधि कम अथवा अधिक हो जाती है।

(5) सुदीर्घकालीन कीमत उतार-चढ़ाव—एक लम्बे समयकाल तक कृषि-वस्तुओं की कीमतों में निरन्तर वृद्धि अथवा कमी को सुदीर्घकालीन कीमत उतार-चढ़ाव कहते हैं। सुदीर्घकालीन कीमत उतार-चढ़ाव जनसंख्या में वृद्धि, नागरिकों की आय में स्थायी वृद्धि, उत्पादन लागत एवं रीति-रिवाजों के परिवर्तन के कारण होते हैं। कीमतों में सुदीर्घकालीन परिवर्तन ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों ही प्रकार के होते हैं।

(6) अनियमित कीमत उतार-चढ़ाव—कृषि-वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव ऐसे कारणों से भी होते हैं जिनके विषय में कोई निश्चितता नहीं होती है, जैसे—युद्ध, सूखा, बाढ़ आदि। कीमत में परिवर्तन के कारण कभी-कभी गुप्त भी होते हैं।

कृषि-कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ावों का प्रभाव :

कृषि-वस्तुओं की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ावों से समाज के विभिन्न वर्ग समान रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। इनसे समाज के एक वर्ग को हानि होती है, लेकिन दूसरे वर्ग को लाभ प्राप्त होता है। कृषि-वस्तुओं की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ावों से समाज के विभिन्न वर्ग एवं व्यवसाय निम्न प्रकार से प्रभावित होते हैं—

(1) उत्पादक (कृषक) वर्ग—कृषि वस्तुओं की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ावों के कारण देश के उत्पादक कृषकों को हानि होती है। इनके कारण कृषकों की आय में अनिश्चितता बनी रहती है, जिससे वे उत्पादन योजना के लिए विवेकपूर्ण नीति नहीं अपना पाते हैं। सामान्यतया फसल की कटाई के समय पूँति की अधिकता के कारण कीमतें गिर जाती हैं। अधिकांश कृषक अपनी पैदावार की अधिकतम मात्रा को फसल-कटाई के बाद विक्रय करते हैं जिसमें उन्हें विनीत माल की कीमत कम प्राप्त होती है। कभी-कभी तो फसल-कटाई के तुरन्त बाद कीमतें इतनी नीची गिर जाती हैं कि कृषकों को प्राप्त उत्पाद के विक्रय से उत्पादन लागत की राशि भी प्राप्त नहीं होती है। फसल की कटाई के कुछ समय बाद पूँति के कम होने से कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं जिसका लाभ समृद्ध मध्यम वर्ग उठाता है।

(2) उपभोक्ता वर्ग—कीमतों के उतार-चढ़ाव से उपभोक्ता वर्ग को मुख्यतः हानि होती है। उपभोक्ताओं की आय सीमित होती है तथा सीमित आय से वर्ष भर के लिए वस्तुओं की आवश्यक मात्रा का एक साथ क्रय कर पाने में उपभोक्ता सक्षम नहीं होते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं को प्रति माह आवश्यकतानुसार क्रय करते हैं जिससे वे फसल कटाई के बाद कीमतों में होने वाली गिरावट से लाभ नहीं उठा पाते हैं। कीमतों में वृद्धि से उनकी वास्तविक आय कम हो जाती है तथा रहन-सहन के स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कीमतों की वृद्धि में उपभोक्ता वर्ग में सर्वाधिक हानि बेतनमोगो एवं मध्यम आय वाले परिवारों को होती है।

कीमतों में निरन्तर वृद्धि होने के कारण रुपये की वस्तुओं के रूप में क्रय-शक्ति निरन्तर कम होती जा रही है। वर्ष 1960 की कीमतों पर रुपये की क्रय-शक्ति कम होकर 1970 में 54.3 पैसा, 1980 में 25.0 पैसा एवं जून, 1987 में मात्र 14 पैसे ही रह गई है। अर्थात् 100 रुपये से वस्तुओं की जितनी मात्रा वर्ष 1960 में क्रय की जा सकती थी, आज उतनी ही मात्रा के क्रय करने के लिए 715 रुपये की आवश्यकता होती है।

(3) ऋणदात्री संस्थाएँ—कृषि वस्तुओं की कीमतों में घट्यधिक गिरावट आने से कृषकों के लिए ऋणदात्री संस्थाओं से प्राप्त ऋण का समय पर भुगतान कर पाना सम्भव नहीं होता है, क्योंकि प्राप्त आय कृषकों के जीवन-निर्वाह के लिए ही पर्याप्त नहीं होती है। ऋण बमूल नहीं होने से ऋणदात्री संस्था के व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

(4) विदेशी व्यापार—कृषि-वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव से उनके व्यापार पर भी प्रभाव पड़ता है। कीमतों में वृद्धि होने से प्रायः वस्तुओं का निर्यात कम हो जाता है और देश के व्यापार का मन्तुलन खराब हो जाता है। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता होने पर कृषकों में उनके उत्पादन में वृद्धि करने की प्रेरणा का हास होता है।

(5) पूंजी-निवेश—कृषि-व्यवसाय में अन्य व्यवसायों की अपेक्षा जोखिम अधिक होती है। साथ ही कृषि-उत्पादों की कीमत में उतार-चढ़ाव अधिक होते हैं। इन कारणों से कृषक कृषि-व्यवसाय में पूंजी निवेश करने में हिचकते हैं। कृषि व्यवसाय में पूंजी-निवेश की दर कम होने पर तकनीकी ज्ञान का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाता है, फलस्वरूप उत्पादकता कम होती है।

(6) सट्टा एवं जमाखोरी की प्रवृत्ति—कृषि-वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव होने के कारण व्यापारी एवं अन्य समृद्धशाली वर्ग वस्तुओं का गुप्त सचय करते हैं और उनकी कृत्रिम कमी उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। इससे कीमतों में वृद्धि होती है और मध्यस्थ वर्ग सामान्वित होता है। इस वर्ष अधिक लाभ की राशि प्राप्त होने से व्यापारी अगले वर्ष अधिक मात्रा में गुप्त सचय करते हैं। अतः कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव सट्टा एवं जमाखोरी की प्रवृत्ति को बढ़ाने में सहायक होते हैं।

(7) देश में आर्थिक नियोजन एवं विकास कार्यक्रम—कृषि-कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव होने से देश में आर्थिक नियोजन एवं विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में अनेक बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। इससे सरकार की आय में अनिश्चितता होती है और सरकार निर्धारित योजना के अनुसार धन व्यय करने में सक्षम नहीं हो पाती है। अतः कीमतों में अत्यधिक परिवर्तनों से योजना के निर्धारित लक्ष्य समय पर प्राप्त नहीं हो पाते हैं।

(8) देश में अशान्ति एवं भुखमरी की प्रवृत्ति को बढ़ावा—कृषि-वस्तुएँ जीवन की प्रमुख आवश्यकता की वस्तुएँ होती हैं। इन पर उपभोक्ताओं की आय का अधिक प्रतिशत व्यय होता है। कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने से सीमित आय वाले नागरिकों के लिए जीवन-निर्वाह करना कठिन हो जाता है, जिससे देश में अशान्ति, भुखमरी, चोरी, डकैती एवं रिश्वतखोरी को बढ़ावा मिलता है।

(9) रोजगार उपलब्धि—कृषि वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव का देश में रोजगार उपलब्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। कीमतों में अत्यधिक गिरावट होने में बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है तथा कीमतों में वृद्धि से कृषि-व्यवसाय में रोजगार अधिक उपलब्ध होता है।

विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था वाले देश में कीमतों में मन्द गति से वृद्धि एक स्वस्थ प्रक्रिया मानी जाती है। कीमतों में मन्द गति से वृद्धि होने से कृषकों को लाभ अधिक प्राप्त होता है, उत्पादन वृद्धि करने की प्रेरणा मिलती है और कृषि व्यवसाय में पूंजी-निवेश अधिक होता है। कीमतों में वृद्धि के साथ-साथ यदि उत्पादन में भी वृद्धि होती है तो देश में आर्थिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए कीमतों में तीव्र गति से वृद्धि लाभकारी नहीं होती है।

कृषि कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण :

कृषि-वस्तुओं की कीमतों में अन्य वस्तुओं की अपेक्षा उतार-चढ़ाव अधिक होने के प्रमुख कारण निम्नांकित हैं—

(1) कृषि-वस्तुओं की माँग एवं पूर्ति की मात्रा में असन्तुलन होना — कृषि-वस्तुओं की माँग एवं पूर्ति की मात्रा में निरन्तर असन्तुलन बना रहता है। कृषि-वस्तुओं की पूर्ति, माँग की मात्रा के अनुरूप नहीं होने से उनकी कीमतों में वृद्धि होती है। कृषि-वस्तुओं की माँग एवं पूर्ति में असन्तुलन निम्न कारणों से बना रहता है—

(अ) कृषि वस्तुओं का उत्पादन प्रकृति की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता पर निर्भर होता है। अनुकूल मौसम वाले वर्ष में उत्पादन अधिक एवं प्रतिकूल मौसम वाले वर्ष में उत्पादन कम होता है, जिससे उनकी पूर्ति की मात्रा में अनिश्चितता बनी रहती है। सामान्यतया अनुकूल मौसम वाले वर्ष में उत्पादन की अधिकता से कीमतें गिर जाती हैं और प्रतिकूल मौसम वाले वर्ष में उत्पादन कम होने से कीमतें बढ़ जाती हैं। औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन पर मौसम का प्रभाव कृषि-वस्तुओं के समान नहीं होता है।

(ब) कृषि एक जैविक क्रिया है, जिसके कारण कृषि वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा को कृषि-कीमतों में परिवर्तन के साथ-साथ समायोजित नहीं किया जा सकता है। उत्पादन की मात्रा की कीमतों के अनुसार समायोजित करने में अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय अधिक लगता है। अतः माग की मात्रा में परिवर्तन के साथ-साथ पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन नहीं हो पाने से कीमतों में उतार-चढ़ाव होते रहते हैं।

(स) कृषि वस्तुओं के उत्पादन का निश्चित मौसम होता है, जबकि औद्योगिक एवं निमित्त वस्तुओं का उत्पादन वर्ष भर होता रहता है। अतः उत्पादन मौसम में कृषि-वस्तुओं की पूर्ति अधिक होती है एवं वर्ष के अन्य मौसम में पूर्ति कम होती है, जिसके कारण उत्पादन मौसम में कीमतों में गिरावट होती है और उसके बाद कीमतों में वृद्धि होना प्रारम्भ होता है।

(द) कृषि-वस्तुओं में शोधनाशी होने का गुण विद्यमान होने के कारण उन्हें अधिक समय तक संग्रहीत नहीं किया जा सकता है, जिससे उनकी पूर्ति की मात्रा सभी समयों में समान नहीं होती है और कीमतों में उतार-चढ़ाव होते हैं।

(य) कृषि वस्तुएँ जीवन की प्रमुख आवश्यकता की वस्तुएँ होती हैं, जिसके कारण उनकी माँग निरपेक्ष होती है। अतः पूर्ति की अनिश्चितता

तथा माँग के निरपेक्ष होने के कारण कृषि-वस्तुओं की कीम उतार-चढ़ाव होते रहना स्वाभाविक है।

(2) जनसंख्या में वृद्धि—कृषि-वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का दूसरा प्रमुख कारण देश में जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना है। जनसंख्या वृद्धि से खाद्यान्नों की माँग में वृद्धि होती है। कृषि-वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि की गति के समतुल्य नहीं हो रही है। अतः कृषि-वस्तुओं की माँग के बढ़ने तथा उनकी पूर्ति में उसी अनुपात से वृद्धि नहीं होने के कारण कीमतों में निरन्तर वृद्धि होती रही है।

(3) सरकार की मौद्रिक नीति—कृषि-वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का एक कारण सरकार की मौद्रिक नीति है। सरकार की मौद्रिक नीति से तात्पर्य मुद्रा-संचालन एवं रिजर्व बैंक की ऋण विस्तार नीति से है।

(प्र) देश में मुद्रा-संचालन की राशि में वृद्धि अथवा कमी कृषि-वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन लाती है। अधिक मुद्रा-संचालन से मुद्रा-स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है, रुपये का मूल्य गिर जाता है तथा कीमतों में वृद्धि होती है। इसके विपरीत मुद्रा-संचालन में कमी होने पर कीमतों में गिरावट होती है। मुद्रा-संचालन का अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कृषि-वस्तुओं की कीमतों पर अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे आवश्यकता की प्रमुख वस्तुएँ होती हैं। योजना काल के प्रारम्भ से ही देश में मुद्रा-संचालन में वृद्धि हो रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मुद्रा-संचालन में वृद्धि की गति, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की गति से अधिक रही है जिसके कारण कीमतों में असाधारण गति से वृद्धि हुई है। देश में मार्च, 1951 में 2,016 करोड़ रुपये की मुद्रा-पूर्ति थी, जो बढ़कर 1961 में 2,869 करोड़ रुपये, 1971 में 7,373 करोड़ रुपये एवं 1978 में 18,083 करोड़ रुपये हो गई।

(ब) रिजर्व बैंक की ऋण विस्तार नीति भी कीमतों को प्रभावित करती है। रिजर्व बैंक द्वारा ऋण-स्वीकृति की नीति में ढिलाई देने एवं व्याज की प्रतिशत दर में कमी करने से व्यापारी वर्ग अधिक मात्रा में खाद्यान्नों का सग्रहण करने में सक्षम होते हैं जिससे खाद्यान्नों की कृत्रिम कमी उत्पन्न होती है और कीमते बढ़ जाती हैं। इसके विपरीत रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारियों को सट्टा, जमाखोरी आदि के लिए ऋण-विस्तार पर नियन्त्रण लगाने एवं व्याज की दर में वृद्धि करने पर मुद्रा-संचालन की राशि में कमी होती है। व्यापारी वर्ग वित्त के अभाव में वस्तुओं के सग्रहण एवं जमाखोरी करने में सक्षम नहीं होते हैं जिससे खाद्यान्नों की पूर्ति में वृद्धि होती है और कीमते गिर जाती हैं। अतः रिजर्व बैंक की ऋण-विस्तार नीति में परिवर्तन होने से कृषि वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है। रिजर्व बैंक की इस नीति का कृषि वस्तुओं की कीमतों पर अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि कृषि एवं कृषि आधारित वस्तुएँ वित्त आवश्यकता की दृष्टि से प्रमुख वस्तुएँ होती हैं।

(4) सरकार की राजकोषीय नीति—सरकार की राजकोषीय नीति के निम्नांकित पहलू कृषि-वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन लाते हैं—

- (अ) घाटे की वित्त व्यवस्था—घाटे की वित्त-व्यवस्था से तात्पर्य सरकार द्वारा आय से अधिक धन व्यय करने की व्यवस्था को बजट में प्रदर्शित करने से है। इससे देश में मुद्रा-संचलन अधिक होता है, मुद्रा-स्फीति उत्पन्न होती है और कीमतों में वृद्धि होती है। घाटे की वित्त व्यवस्था की राशि की अधिकता से कीमतों में वृद्धि अधिक होती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से ही देश में घाट की वित्त-व्यवस्था की राशि में निरन्तर वृद्धि हुई है।
- (ब) विकास कार्यक्रमों पर सरकार के व्यय करने की प्रवृत्ति—सरकार की विभिन्न समयावधि के विकास-कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने एवं उन पर किये जाने वाले व्यय की राशि भी कृषि वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन लाती है। प्रत्येकालीन विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाने पर कृषि-वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव की गति धीमी होती है, क्योंकि इनसे उत्पादन में वृद्धि शीघ्रता से होती है। दीर्घ-कालीन विकास कार्यक्रमों पर अधिक धन व्यय करने से कीमतों में उतार-चढ़ाव की गति तेज होती है, क्योंकि इन पर किये गये व्यय से उत्पादन वृद्धि देर से प्रारम्भ होती है, जबकि नागरिकों की आय में वृद्धि शीघ्रता से होती है।
- (स) कर-नीति—सरकार को कर-नीति के कारण भी कीमतें प्रभावित होती हैं। सरकार द्वारा करो में वृद्धि करने पर नागरिकों की वास्तविक आय कम हो जाती है, मुद्रा-संचलन कम होता है और कीमतें गिर जाती हैं। साथ ही सरकार द्वारा जिस वस्तु पर कर की दर में वृद्धि अधिक की जाती है, उस वस्तु की कीमत में वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक होती है। कर-नीति में सरकार प्रति वर्ष परिवर्तन करती है।
- (द) प्रतिरक्षा पर व्यय नीति—सुरक्षा-व्यवस्था पर सरकार द्वारा अधिक धन व्यय करने की स्थिति में, विकास कार्यक्रमों एवं अन्य क्षेत्रों में व्यय की जाने वाली राशि में कटौती होती है। इससे विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन स्तर गिर जाता है और कीमतों में वृद्धि होती है।
- (प) प्रशासन-व्यय के सम्बन्ध में नीति—कर्मचारियों के वेतन एवं मंहगाई भत्ते में वृद्धि तथा नये विभागों के प्रारम्भ एवं विस्तार से सरकार का प्रशासनिक व्यय बढ़ जाता है। इस व्यय के बढ़ने से सरकार के पास विकास कार्यक्रमों पर व्यय करने के लिए उपलब्ध वित्त कम हो

जाता है। साथ ही प्रशासनिक व्यय में वृद्धि से नागरिकों की आय में वृद्धि तथा वस्तुओं की माँग की मात्रा में वृद्धि होती है जिससे कीमतें बढ़ती हैं।

(4) सरकार की व्यापार एवं प्रशुल्क नीति—सरकार की व्यापार एवं प्रशुल्क नीति जैसे—आयात-निर्यात नीति, लगाये गये प्रशुल्क आदि भी कृषि-वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन लाते हैं। वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध होने तथा आयातित वस्तुओं की प्रशुल्क दर अधिक होने से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। आयातित वस्तुओं पर प्रशुल्क-दर के कम होने पर उनकी कीमतों में गिरावट आती है।

(6) देश में आर्थिक एवं राजनैतिक घटनाओं का होना—देश की आर्थिक घटनाएँ जैसे—रुपये का अवमूल्यन, आर्थिक मन्दी तथा राजनैतिक घटनाएँ जैसे—युद्ध का होना, शरणाधियों का आना आदि से भी कीमतों में उतार-चढ़ाव आते हैं। वर्ष 1962 में चीन के आक्रमण, 1965 में पाकिस्तान के आक्रमण व 1971 में बंगला-देश युद्ध के फलस्वरूप देश में कृषि-वस्तुओं की कीमतों में काफी वृद्धि हुई। इसी प्रकार सितम्बर, 1949 व जून, 1966 में रुपये के अवमूल्यन के कारण भी कृषि-वस्तुओं की कीमतों पर प्रभाव पड़ा है। उपर्युक्त घटनाओं के फलस्वरूप अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कृषि-वस्तुओं के उत्पादन पर विशेष प्रभाव पड़ता है।

(7) कृषि-विपणन सुविधाओं का अभाव—विपणन के लिए परिवहन, सग्रहण एवं दक्ष नियन्त्रित मण्डियों का अभाव भी कृषि-वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव में सहायक होता है। परिवहन-सुविधाओं के अभाव में खाद्यान्नों का संचलन रुक जाता है एवं बिक्री गाँव में ही अधिक होती है। सग्रहण-सुविधाओं के अभाव में कृषकों द्वारा खाद्यान्न फसल कटाई के शीघ्र पश्चात् अधिक मात्रा में विक्रीत कर दिये जाते हैं। इस समय मण्डी में वस्तुओं की पूर्ति की अधिकता के कारण कीमतें गिर जाती हैं। देश में नियन्त्रित मण्डियों की अपर्याप्तता के कारण कृषकों को खाद्यान्न, अनियन्त्रित मण्डियों में विक्रय करना होता है। अनियन्त्रित मण्डियों में मध्यस्थों की लम्बी शृंखला एवं उनके द्वारा अपनायी जाने वाली कुचालों के कारण उत्पादक-कृषकों की उपभोक्ता द्वारा दी गई कीमत में से कम भाग प्राप्त होता है। साथ ही प्रतिस्पर्धा के अभाव में अनियन्त्रित मण्डियों में कीमत भिन्नता अधिक होती है। इन सबके परिणामस्वरूप कृषि-वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव अधिक होते हैं।

(8) उचित कृषि-कीमत नीति का अभाव—सरकार की कृषि कीमत नीति के विभिन्न पहलुओं जैसे—बफर स्टॉक-निर्माण नीति, खाद्यान्नों की वसूली कीमत एवं वसूली नीति, आयात-निर्यात नीति, कीमत निर्धारण नीति, अन्तर्राज्यीय-संचालन नीति, क्षेत्र-निर्माण नीति आदि के सम्बन्ध में सरकार को ठोस एवं उचित नीति के

अभाव में उनकी कीमतों में उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। देश के उत्पादक एवं उपभोक्ता कृषि कीमत नीति के उपर्युक्त पहलुओं के विकास में सशय में रहते हैं। कृषि-कीमत नीति के विभिन्न पहलुओं में एकरूपता तथा सबति के अभाव के कारण कीमतों में उतार-चढ़ाव होते रहते हैं।

(9) व्यापारियों एवं समाज विरोधी तत्त्वों द्वारा खाद्यान्नों की अमावस्यी एवं कालाबाजारी करना—समाज विरोधी तत्त्वों द्वारा खाद्यान्नों में सट्टेबाजी, जमा-खोरी एवं कालाबाजारी की प्रवृत्ति अपनाने से भी कीमतों में वृद्धि होती है।

(10) विविध कारण—कृषि-वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव लाने वाले उपर्युक्त प्रमुख कारणों के अतिरिक्त विविध कारण जैसे—परिवहन साधनों के किराये में वृद्धि, औद्योगिक अशान्ति, अमिको द्वारा हड़ताल, भ्रष्टाचार, सरकार के प्रशासन में ढिलाई आदि कारणों से भी कृषि-वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव होते रहते हैं।

कीमत-स्फीति

कीमत-स्फीति से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें वस्तुओं की कीमतों में सामान्य कीमत स्तर में अत्यधिक तीव्र गति से वृद्धि होती है। स्फीति की स्थिति में वस्तुओं की समग्र भांग उनकी समग्र पूर्ति की मात्रा में अधिक होती है, जिसके कारण कीमतों में असामान्य एवं अनावश्यक वृद्धि होती है। कीमतों में असामान्य वृद्धि से तात्पर्य प्रतिवर्ष कीमतों के सूचकांक में 3 से 6 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने से है। कीमत स्फीति शब्द का सर्वप्रथम उपयोग रैंडवलीफ रिपोर्ट में वर्ष 1931 में किया गया था।

भारत में द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में कृषि-वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की गति सामान्य दर (5 से 6 प्रतिशत) से थी। बाष्पिक योजनाओं के काल में कीमत वृद्धि की गति अप्रामाण्य हो गई। वर्ष 1966-67 में कीमतों में वृद्धि 14 प्रतिशत एवं 1967-68 में 13 प्रतिशत की दर से हुई। तत्पश्चात् चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के वर्ष 1972-73 एवं 1973-74 में पुनः कीमतों में वृद्धि अप्रसाधारण दर से हुई। कीमतों में वृद्धि की दर 1972-73 में 12.3 प्रतिशत एवं 1973-74 में 21.8 प्रतिशत थी। सरकार द्वारा अपनाये गये उपायों के फलस्वरूप पाचवी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (1979-80) के अतिरिक्त अन्य वर्षों में कीमतों की वृद्धि अप्रसाधारण थी। इस योजना के अन्तिम वर्ष में कीमतों में वृद्धि 22.5 प्रतिशत दर से हुई। छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष (1980-81) में भी कीमतों में वृद्धि 16.7 प्रतिशत की दर से हुई। इस प्रकार कीमतों में वृद्धि अप्रसाधारण गति से होने को कीमत स्फीति शब्द से सम्बोधित किया गया है। कीमत-स्फीति के कारण उत्पादक कृषकों एवं उपभोक्ताओं को हानि अधिक होती है। अतः कीमत स्फीति पर नियन्त्रण करना आवश्यक हो गया है।

कीमत स्फीति के प्रकार :

कीमत स्फीति अनेक प्रकार की होती है, जिसको निम्न आधारों के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है—

1. स्फीति उत्पन्न होने के कारणों के आधार :

(अ) मांगजन्य-स्फीति—वस्तुओं की मांग में वृद्धि, पूर्ति में वृद्धि की अपेक्षा अधिक दर से होने को मांगजन्य स्फीति कहते हैं। वस्तुओं की मांग में यह अत्यधिक वृद्धि उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि अथवा सरकार द्वारा लम्बी अवधि के विकास कार्यक्रमों पर अधिक धन व्यय करने की स्थिति में होती है।

(ब) लागतजन्य स्फीति—यह स्फीति-वस्तुओं की उत्पादन-लागत में अत्यधिक वृद्धि होने से उत्पन्न होती है। आवश्यक उत्पादन-साधनों—उर्वरक, डीजल, तेल, बीज, कीटनाशी दवाइयाँ एवं श्रम की लागत में वृद्धि होने पर लागतजन्य स्फीति उत्पन्न होती है।

2. कीमत वृद्धि के लिए नियन्त्रण के उपाय अपनाने के आधार पर :

(अ) अनियन्त्रित स्फीति—कीमत स्फीति की वह स्थिति जिसमें कीमतों में वृद्धि बिना किसी नियन्त्रण के उपाय अपनाये होती रहती है। कीमतों में वृद्धि होते रहने पर अन्त में यह स्फीति अतिस्फीति का रूप लेती है।

(ब) दबी हुई स्फीति—कीमतों में वृद्धि की स्थिति विद्यमान होते हुए भी कीमत नियन्त्रण के उपाय अपनाये जाने के कारण स्फीति की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती है, लेकिन कीमत नियन्त्रण के उपायों में ढिलाई देने पर कीमतों में प्रसामान्य दर से वृद्धि होती है। इस प्रकार की कीमत स्फीति को दबी हुई स्फीति कहते हैं।

3. कीमतों में वृद्धि की गति के आधार पर :

(अ) क्रमिक स्फीति/मन्द स्फीति (Creeping Inflation) - स्फीति उत्पन्न होने की प्रथम अवस्था, जिसमें कीमतों में धीमी गति से वृद्धि होती है, मन्द स्फीति कहलाती है।

(ब) द्रुत-स्फीति (Running Inflation)—कीमतों में तीव्र दर से वृद्धि होने को द्रुत स्फीति कहते हैं। स्फीति की यह अवस्था खतरे का सूचक होती है।

(ग) अति स्फीति (Gallopig Inflation)—कीमतों में अत्यधिक तेज गति से वृद्धि को अति स्फीति कहते हैं। कीमत-स्फीति की यह अवस्था नागरिकों में सरकार के प्रति अविश्वास एवं आन्तरिक उत्पन्न करती है, जो बाद में आन्दोलन एवं अशान्ति में परिणत हो जाती है। इस अवस्था के उत्पन्न होने के पूर्व ही कीमत स्फीति पर नियन्त्रण करना आवश्यक होता है।

कृषि-कीमत स्थिरीकरण एवं कृषि-कीमत नीति

कृषि के प्रकृति पर निर्भरता के कारण कृषि वस्तुओं के उत्पादन में तथा उसके फलस्वरूप कृषि-कीमतों में उतार-चढ़ाव होना स्वाभाविक है। प्रत्येक कृषि-उत्पाद को कीमतों में उतार-चढ़ावों से होने वाली हानि से रक्षा करने हेतु कीमत स्थिरीकरण आवश्यक होता है। फार्म व्यवसाय से प्राप्त होने वाली आय की स्थिरता की दृष्टि से भी कीमत स्थिरीकरण महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में कृषि-उत्पादों की कीमतों में होने वाले अत्यधिक उतार-चढ़ावों को कम करने के उपाय एवं सरकार द्वारा कृषि-उत्पाद-कीमत नीति के लिए किए गए प्रयासों का संक्षिप्त विवेचन किया गया है।

कृषि-कीमत स्थिरीकरण से तात्पर्य :

कृषि-कीमत स्थिरीकरण से तात्पर्य कीमतों में होने वाले अत्यधिक उतार-चढ़ाव को कम करने अथवा कीमतों को निर्धारित सीमा के अन्तर्गत नियमित करने से है, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों की कीमतों के उतार-चढ़ाव से होने वाली हानि से रक्षा की जा सके। अमरीकी कृषि व्यावसायिकों के आयोग के अनुसार स्थिरीकरण से वास्तविक तात्पर्य कीमतों के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को समाप्त करना नहीं है, बल्कि कीमतों के उच्च-स्तरीय शिखरों को कम करने एवं कीमतों की न्यूनतम गहराई वाली खाई को भरने में मदद देने से है।¹ प्रथम पंच-वर्षीय योजना के अनुसार कीमत स्थिरीकरण से तात्पर्य उच्चतम एवं न्यूनतम कीमतों के स्तर को दृष्टि में रखने से है।² कीमत स्थिरीकरण से तात्पर्य कीमतों को स्थायी अथवा अपरिवर्तनशील करने से नहीं होता है, बल्कि इससे तात्पर्य है कि कीमतें एक निर्धारित सीमा के अन्तर्गत ही नियमित होती रहें जिससे समाज के विभिन्न वर्गों को आवश्यक रूप से प्रभावित न हो।

1. Businessman's Commission on Agriculture in USA, 1927.

2. First Five Year Plan Draft, Planning Commission, Government of India.
New Delhi

कृषि-कीमत स्थिरीकरण के उद्देश्य :

कृषि-उत्पादों की कीमत-स्थिरीकरण के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं :

- (1) कृषकों को फार्म पर उत्पादित विभिन्न उत्पादों की उचित कीमत प्राप्त कराना जिससे उनके पास उत्पादन लागत का भुगतान करने के उपरान्त पर्याप्त आय छेप रहे। शुद्ध आय की अधिकता से कृषकों में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने की प्रेरणा बनी रहती है जो देश का खाद्यान्न उत्पादन में स्वावलम्बी बनाने में सहायक होती है।
- (2) देश के उपभोक्ताओं को आवश्यक मात्रा में उचित कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, जिससे वे अपनी सीमित आय से निश्चित उपभोग-स्तर प्राप्त कर सकें।
- (3) उत्पाद-कृषकों को उपभोक्ताओं द्वारा दी गई कीमत में से अधिकाधिक भाग प्राप्त कराना, जिससे विपणन में दक्षता आये। साथ ही विपणन-मध्यस्थों को प्राप्त होने वाले लाभ की राशि को कम करना भी स्थिरीकरण का उद्देश्य है।
- (4) कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र की वस्तुओं तथा कृषि क्षेत्र में विभिन्न फसलों के मूहों की कीमतों में उचित समता सम्बन्ध बनाये रखना, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के व्यापार पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े।
- (5) मुद्रा-स्थिति पर नियन्त्रण बनाये रखना।
- (6) देश में उत्पादित की जाने वाली विभिन्न फसलों के निर्धारित उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करना।
- (7) औद्योगिक क्षेत्र की वस्तुओं का उत्पादन स्तर बनाये रखना, क्योंकि कृषि-क्षेत्र विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति करता है तथा औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं का कृषि-क्षेत्र में उपयोग होता है।
- (8) कृषकों द्वारा त्रय किये जाने वाले उत्पादन-साधनों एवं उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों की कीमतों में उचित सम्बन्ध बनाये रखना, जिससे कृषकों में उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा बनी रहे।
- (9) देश में नियोजित आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को सुचारु रूप से कार्यान्वित करना।

कृषि-कीमत स्थिरीकरण के उपाय :

कृषि-उत्पादों की कीमतों में होने वाले अत्यधिक उतार-चढ़ावों को निम्न उपाय अपनाकर कम किया जा सकता है और कीमत-स्थिरीकरण के उपर्युक्त उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं—

- (1) कृषि-उत्पादों की मांग एवं पूर्ति में सन्तुलन स्थापित करना—कृषि-

उत्पादों की कीमतों में होने वाले अत्यधिक उतार-चढ़ावों को स्थायी रूप से कम करने के लिए उनकी मांग एवं पूर्ति में सन्तुलन स्थापित करना आवश्यक है। वर्तमान में कीमतों में अत्यधिक वृद्धि उनकी पूर्ति की मात्रा मांग के अनुरूप नहीं होने से हुई है। अतः मांग एवं पूर्ति की मात्रा में सन्तुलन स्थापित करने का तरीका, कृषि-कीमत-स्थिरीकरण की स्थायी एवं सर्वोत्तम विधि है। कृषि-उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए स्वतन्त्रता के बाद निरन्तर प्रयास किया गया है, जिससे उनकी पूर्ति की मात्रा में वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी उनकी पूर्ति की मात्रा मांग के अनुरूप नहीं हो पाई है। उत्पादन में वृद्धि कृषि-योग्य परती भूमि को कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त करके, कृषि में तकनीकी ज्ञान का अधिकाधिक उपयोग करके, उर्वरक एवं उन्नत बीजों का उपयोग करके, बहुफसलीय उत्पादन कार्यक्रम अपनाकर तथा सग्रहण काल में होने वाली हानि से रक्षा करके की जा सकती है।

(2) कृषि-वस्तुओं की अधिकतम एवं न्यूनतम कीमतें नियत करना—कृषि कीमतों के स्थिरीकरण का दूसरा उपाय कृषि वस्तुओं की अधिकतम एवं न्यूनतम कीमत नियत करना है। इनके नियतन का मुख्य उद्देश्य कृषि-कीमतों को उपयुक्त नियत सीमा में ही परिवर्तित होते रहने देने से है। कीमतों के निर्धारित न्यूनतम स्तर से नीचे गिरने अथवा अधिकतम स्तर से ऊपर बढ़ने पर सरकार उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाती है। कीमतों के न्यूनतम नियत स्तर से नीचे गिरने पर उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए खाद्यान्नों को निर्धारित न्यूनतम कीमतों पर श्रय करने की सरकार व्यवस्था करती है। कीमतों के अधिकतम नियत स्तर से ऊपर बढ़ने पर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से सरकार सङ्गृहीत स्टॉक में से नियत अधिकतम कीमत पर खाद्यान्नों के विपणन का प्रबन्ध करती है। इस प्रकार सरकार कृषि-वस्तुओं की अधिकतम एवं न्यूनतम कीमत नियत करके एवं आवश्यकतानुसार भ्रम अथवा विपणन करके कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ावों को कम करने का प्रयास करती है। वर्ष 1964-65 से प्रमुख कृषि उत्पादों की न्यूनतम समर्थित कीमत सरकार नियत कर रही है, जो सारणी 17.1 एवं 17.2 में दी गई है।

(3) खाद्यान्नों के संचलन पर नियन्त्रण लगाना एवं खाद्य-क्षेत्रों का निर्माण करना—देश के विभिन्न राज्यों, जिलों एवं क्षेत्रों में कृषि-वस्तुओं की कीमतों में पाई जाने वाली विभिन्नता एवं होने वाले उतार-चढ़ावों को कम करने के लिए सरकार कमो वाले क्षेत्रों से खाद्यान्नों की निकासी पर प्रतिबन्ध तथा अधिकसे अधिक पूर्ति वाले क्षेत्रों से कमो वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न के आयात करने का प्रबन्ध करती है। इन उपायों द्वारा कमो एवं अधिकसे अधिक दोनों प्रकार के क्षेत्रों में कीमतों के उतार-चढ़ावों को कम करने के प्रयास किए जाते हैं। खाद्यान्नों की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न

राज्यों को मिलाकर खाद्य-क्षेत्रों का निर्माण भी किया जाता है। खाद्य क्षेत्रों के निर्माण करते समय सरकार खाद्यान्नों में कमी एवं अधिशेष वाले क्षेत्रों/राज्यों को सम्मिलित करती है, जिससे दोनों क्षेत्रों में सम्मिलित रूप से माँग एवं पूर्ति में संतुलन स्थापित हो सके एवं खाद्यान्नों का अनावश्यक संचलन नहीं होवे।

(4) कृषि-वस्तुओं के व्यापार का सरकार द्वारा अधिग्रहण—देश में विपणन-मध्यस्थों द्वारा अधिक लाभ कमाने के लिए कृषि-वस्तुओं का सट्टा, गुप्त-सचय एवं अन्य विधियों द्वारा उनको कृत्रिम कमी उत्पन्न करके कीमतों में होने वाले प्रत्यधिक उतार-चढ़ाव का नियन्त्रण सरकार द्वारा कृषि-वस्तुओं के व्यापार को निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में संचालित करके किया जा सकता है। खाद्यान्नों के व्यापार को सार्वजनिक क्षेत्र में संचालित करके विपणन मध्यस्थों की कुचाओं एवं उनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली कृत्रिम कमी एवं विपणन कुरीतियों पर सुगमता से नियन्त्रण किया जा सकता है और बढ़ती हुई कीमतों को रोका जा सकता है। वर्ष 1973-74 में खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमतों पर नियन्त्रण पाने के लिए सरकार ने गेहूँ के थोक व्यापार का अधिग्रहण किया और व्यापारियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये। अनेक कारणों से सरकार की यह योजना सफल नहीं हो सकी और इसे शीघ्र ही स्थगित कर दी।

(5) खाद्यान्नों का राशनिंग—देश, राज्य प्रथवा क्षेत्र-विशेष में खाद्यान्नों एवं अन्य कृषि-वस्तुओं की अत्यधिक कमी उत्पन्न होने पर उनकी कीमतों को तेजी से बढ़ने से रोकने के लिए सरकार उपभोक्ताओं की माँग पर नियन्त्रण लगाती है। सरकार द्वारा कृषि-वस्तुओं का राशनिंग करने का प्रमुख उद्देश्य समाज के—विशेषकर निचले वर्ग को नियत मात्रा में उचित कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, क्योंकि बढ़ती हुई कीमत पर समाज का यह वर्ग आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न क्रय कर पाने में सक्षम नहीं होता है। राशनिंग में सरकार प्रति परिवार/व्यक्ति खाद्यान्नों की निश्चित मात्रा नियत कीमत पर प्रतिमाह उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराती है। राशनिंग एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। खाद्यान्नों के वितरण का यह कार्य कीमत-विभेद कार्यक्रम भी कहलाता है।

(6) लेवी द्वारा खाद्यान्नों की बसूली एवं बफर स्टॉक का निर्माण—कृषि-वस्तुओं की कीमतों में होने वाले अत्यधिक उतार चढ़ाव को कम करने एवं खाद्यान्न-वितरण की निर्धारित नीति को कार्यान्वित करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों का संगृहीत भण्डार होना आवश्यक है। बढ़ती हुई कीमतों की अवस्था में सरकार के लिए खाद्यान्नों की आवश्यक मात्रा को बाजार से तय करके संग्रहण करना कठिन होता है।

सरकार खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का निर्माण कृषकों अथवा व्यापारियों पर लेवी लगाकर करती है। लेवी के अन्तर्गत सरकार कृषकों से क्षेत्रफल प्रथवा उपज

सारणी 17.1
साक्षात्सों एवं वाणिज्यिक फसलों को घोषित न्यूनतम समर्थित कीमते

(₹० प्रति क्विन्टल)

विपणन वर्ष	जो	चन्ना	बलहून फसले		मूग एवं उदद	वाणिज्यिक फसले		कपास
			अरहर	4		जूट	मन्ना	
I	2	3	4	5	(W-5 किस्म TD-5)	6	7	8
1968-69	—	46	—	—	—	—	—	—
1969-70	—	—	—	—	—	—	—	—
1970-71	—	—	—	—	—	—	—	—
1971-72	—	—	—	—	—	113	—	—
1972-73	—	—	—	—	—	115	—	—
1973-74	—	—	NA	NA	—	125	8 00	—
1974-75	—	—	NA	NA	—	125	8 50	—
1975-76	—	—	NA	NA	—	135	8 50	210
1976-77	65	90	NA	NA	—	136	8 50	NA
1977-78	65	95	NA	NA	—	141	8 50	255
1978-79	67	125	155	165	—	150	10 00	255
1979-80	NA	140	165	175	—	155	12 50	275
1980-81	NA	145	190	200	—	160	13 00	304
1981-82	105	NA	NA	NA	—	175	13 00	NA
1982-83	122	NA	215	230 उदद 240 मूग	—	175	13 00	380

1	2	3	4	5	6	7	8
1983-84	122	235	245	245 रुदद 250 मंग	185	13 50	400+ 527*
1984 85	124	240	275	275	195	14 00	410+ 535*
1985-86	130	NA	300	300	215	16 50	425+ 535*
1986-87	132	260	320	320	225	17 00	430+ 540*
1987-88	135	280	325	325	240	18 50	440+ 550*
1988-89	135	290	360	360	250	19 50	500+ 600*
1989-90	145	325	425	425	295	22 00	570+ 690*
1990-91	180	420	480	480	320	23 00	620+ 750*
1991-92	200	450	545	545	375	26 00	695+ 840*
1992-93	210	500	640	640	400	27 00	800+ 950*
1993-94	260	600					

NA=Not Announced

+ =for F 414, H 777 and 320 F variety of Cotton.

* =for H 4 long staple Good quality Cotton

} =upto 1988-89 W-5 variety in Assam and later for TD-5 variety in Assam

° =These are statutory minimum prices

Note—Crop year and marketing year are same in Arhar, Moong, Urad, Cotton and Jute For Barley and Gram, for the crop year 67-68 the marketing year is 1968-69 and so on. The Marketing year is April to March for Barley and Gram, November to October for Arhar, Moong and Urad, July to June for Jute and September to August for Cotton

Source : Publications of Directorate of Economics and Statistics, Ministry of Agriculture, Government of India, New Delhi

सारणी 17.2

तिलहन फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थित कीमतें

(रुपये प्रति क्विन्टल)

विपणन वर्ष	सरसो (घोसत किस्म)	मूंगफली (छिलके सहित)	सोयाबीन काली	सोयाबीन पीली	सूरजमुखी के बीज	कुसुम के बीज	खोपरा
1968-69	—	—	—	—	—	—	—
1969-70	—	—	—	—	—	—	—
1970-71	—	—	—	—	—	—	—
1971-72	—	—	—	—	—	—	—
1972-73	—	—	85	—	—	—	—
1973-74	—	—	85	—	—	—	—
1974-75	—	—	NA	—	—	—	—
1975-76	—	—	NA	—	—	—	—
1976-77	—	140	NA	—	150	—	—
1977-78	—	160	145	—	165	—	—
1978-79	225	175	175	—	175	—	—
1979-80	245	190	175	—	175	—	—
1980-81	NA	206	183	198	183	—	—
1981-82	NA	270	210	230	250	—	—
1982-83	NA	295	220	245	250	—	—
1983-84	355	315	230	255	275	—	—
1984-85	360	340	240	265	325	—	—
1985-86	385	350	250	275	335	—	—
1986-87	400	370	255	290	350	400	—
1987-88	415	390	260	300	390	415	—
1988-89	430	430	275	320	450	415	—
1989-90	460	500	325	370	530	440	1500
1990-91	575	580	350	400	600	550	1600
1991-92	600	645	395	445	670	575	1700
1992-93	670	750	475	525	800	640	—
1993-94	760	—	—	—	—	—	—

NA=Not announced.

Note : Crop year and marketing year are same in Soyabean, Groundnut and Sunflower while in Mustard and Safflower the marketing year is next of crop year for example for 1972-73 crop year the marketing year is 1973-74 and so on.

The marketing year is April to March for Mustard and November to October for Kharif Season crops.

Source : Publications of Directorate of Economics and Statistics, Ministry of Agriculture, Government of India, New Delhi.

की मात्रा के अनुसार, उपज का एक भाग निर्धारित वसूली-कीमत पर धनिवार्य रूप में लेती है। सरकार कभी-कभी व्यापारियों से उनके द्वारा व्यापार की गई मात्रा के अनुरूप अथवा सहायकताओं से उनके द्वारा सहायित की गई मात्रा के अनुसार लेवी वसूल करती है। लेवी की दर विभिन्न राज्यों एवं उत्पादों के लिए भिन्न-भिन्न होती है। संगृहीत खाद्यान्नों की उचित कीमत की दुकानों के माध्यम से सरकार विक्रय करती है और कीमतों को नियन्त्रण में लाने की कोशिश करती है। प्रमुख खाद्यान्नों की वसूली हेतु सरकार प्रतिवर्ष उनकी वसूली कीमतें घोषित करती है। सरकार द्वारा घोषित खाद्यान्नों की वसूली कीमतें सारणी 17.3 में दी गई हैं।

सारणी 17.3

खाद्यान्नों की वसूली/न्यूनतम समर्थित कीमतें

(रुपये/क्विन्टल)

विपणन वर्ष	गेहूँ	धान	मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा, मक्का एवं रागी)
1	2	3	4
1968-69	65-86	—	47-55
1969-70	66-76	45-56.25	52
1970-71	71-76	46-58	55
1971-72	71-76	47-58	55
1972-73	71-76	49-58	57-60
1973-74	71-82	70	70-72
1974-75	105	74	74

1	2	3	4
1975-76	105	74	74
1976-77	105	74	74
1977-78	110	77	74
1978-79	112 50	85	85
1979-80	115	95	95
1980-81	117	105-113	105
1981-82	130	115-123	116
1982-83	142	122-130	118
1983-84	151	132-140	124
1984-85	152	137-145	130
1985-86	157	142-150	130
1986-87	162	146-154	132
1987-88	166	150-170	135
1988-89	173	160-180	145
1989-90	183	185-205	165
1990-91	215	205-225	180
1991-92	225	230-250	205*
1992-93	250**	270-290	240
1993-94	305**		

Note— Crop year and marketing year are one and the same in paddy and coarse cereals while in wheat for the crop year 1967-68, the marketing year is 1968-69 and so on.

*=For maize it is Rs 210.

**=Central Government Bonus of Rs. 25 per quintal is extra for all those farmers selling before 30th June of the year.

Source : Publications of Directorate of Economics and Statistics,
Ministry of Agriculture, Government of India, New Delhi.

मुद्रा-संचलन को रोकने के लिए 16 जनवरी, 1978 को सरकार ने एक हजार व उससे बड़े नोटों का विमुद्रीकरण अधिनियम पारित किया था।

(10) विविध उपाय — निम्न विविध उपाय अपनाकर भी कृषि-कीमतों में पाये जाने वाले अत्यधिक उतार-चढ़ावों को कम किया जा सकता है—

- (i) देश में जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण करके कृषि-वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग को कम करना।
- (ii) उत्पादन वृद्धि के प्रयासों के साथ-साथ हड़ताल एवं तालाबन्दी पर रोक लगाना।
- (iii) वस्तुओं को जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करके वस्तुओं की कृत्रिम कमी को कम करना।
- (iv) नागरिकों का नैतिक उत्थान करना एवं उनमें राष्ट्रीय भावना जागृत करना, जिससे देश में समाज-विरोधी तत्त्व पनपने नहीं पायें।

उपयुक्त उपायों को सम्मिलित रूप से अपनाकर कृषि-वस्तुओं की कीमतों में होने वाले अत्यधिक उतार-चढ़ावों को एक निर्धारित सीमा में रखा जा सकता है, लेकिन ये सभी उपाय एक ही स्थिति में काम में नहीं लाये जा सकते हैं। इन उपायों का चुनाव, कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारणों के विश्लेषण के आधार पर किया जाना चाहिए।

कृषि-कीमतों के स्थिरीकरण में कठिनाइयाँ .

कृषि-कीमतों के स्थिरीकरण की उपर्युक्त विधियों को कार्यान्वित करने में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं जिनके कारण कीमत स्थिरीकरण के उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होते हैं और कीमतों में निरन्तर उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। अतः कीमत स्थिरीकरण के विभिन्न उपायों की सफलता निम्न कठिनाइयों को दूर करने पर निर्भर करती है। कृषि कीमतों के स्थिरीकरण में आने वाली कठिनाइयाँ निम्न हैं—

- (1) कृषि के प्रकृति पर निर्भरता के कारण उत्पादन पूर्णतः मौसम की अनुकूलता एवं प्रतिकूलता पर निर्भर करता है। अतः उत्पादन कम प्राप्त होने पर कृषि-कीमत स्थिरीकरण के उपर्युक्त उपायों द्वारा कीमतों के उतार-चढ़ाव को कम करना सम्भव नहीं है।
- (2) कृषि-वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के लिए विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल नियत करने के निर्णय सेने में कृषक आर्थिक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों एवं धरेलू आवश्यकता को अधिक महत्त्व देते हैं, जिससे कृषि-वस्तुओं के कुछ उत्पादन की प्राप्ति होने वाली मात्रा में अनिश्चितता बनी रहती है।

- (3) कृषि-वस्तुओं की प्रति इकाई उत्पादन लागत में क्षेत्र, जोत के आकार, उत्पादन-साधनों की प्रयुक्त मात्रा एवं प्रबन्ध कारक की विभिन्नता के कारण बहुत भिन्नता पाई जाती है, जिससे निर्धारित न्यूनतम कीमत से विभिन्न कृषकों को प्राप्त होने वाले लाभ की राशि में बहुत अन्तर होता है। अधिकांश कृषक न्यूनतम कीमत पर कृषि-वस्तुओं को विक्रय करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें इस कीमत पर उत्पादन-लागत की राशि भी प्राप्त नहीं होती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि कीमत निर्धारण के लिए विभिन्न स्थितियों में उत्पादन-लागत के सही एवं विश्वसनीय आँकड़े सरकार को उपलब्ध नहीं होना है।
- (4) कृषि-वस्तुओं के व्यापार के लिए सरकार के पास संग्रहण के लिए पर्याप्त क्षमता वाले भण्डारगृहों का उचित स्थानों पर अभाव, खाद्यान्नों के संचालन के लिए परिवहन सुविधाओं की अपर्याप्तता, प्रशिक्षित एवं अनुभवी कार्यकर्ताओं का अभाव एवं सरकारी नौकरी में लाल-फीताशाही भी कृषि कीमतों की स्थिरीकरण नीति को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने में बाधक होती है।
- (5) कृषि-वस्तुओं की विपणन की नीति-निर्धारण में राजनैतिक हस्तक्षेप होना, जिससे निर्धारित नीति पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं हो पाती है।
- (6) व्यापारियों एवं विपणन-मध्यस्थों द्वारा कीमत स्थिरीकरण नीति के लिए सरकार द्वारा अपनाये गये उपायों का विरोध करना एवं निर्धारित नीति को असफल बनाने की निरन्तर कोशिश करना।
- (7) खाद्यान्नों के क्रय-विक्रय के लिए ग्राभीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों एवं उचित कीमत की दुकानों की अपर्याप्तता एवं उनके द्वारा खाद्यान्नों के वितरण में अनेक अनियमितताओं के व्याप्त होने से कीमत-स्थिरीकरण की नीति अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाती है।

कृषि कीमत स्थिरीकरण नीति के विभिन्न उपायों के अपनाने एवं निर्धारित नीति के अनुसार कार्य करने में उपर्युक्त कठिनाइयों के होते हुए भी देश की अर्थ-व्यवस्था के विकास एवं समाज के विभिन्न वर्गों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य हेतु कृषि-कीमतों का स्थिरीकरण करना आवश्यक है। अतः सरकार को उपर्युक्त कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास करने चाहिए, जिससे कृषि उत्पादों की कीमत-स्थिरीकरण के उद्देश्य प्राप्त हो सकें।

कृषि-कीमत-नीति

समाज के विभिन्न वर्गों—उत्पादकों, उपभोक्ताओं, श्रमदात्री समस्याओं, विप-
रान मध्यस्थों एवं निर्यातकों के हितों की रक्षा करने एवं देश की अर्थव्यवस्था के
विकास हेतु, एक आदर्श कृषि-कीमत-नीति का होना आवश्यक है। कृषि वस्तुओं से
सम्बन्धित कीमत नीति इस प्रकार से निर्धारित की जानी चाहिए जिससे कृषि-क्षेत्र
में बढ़ते हुए उत्पाद से आवश्यकता की पूर्ति हो सके। यह प्रयास होना चाहिए कि
कीमतें कृषकों के लिए कृषि-व्यवसाय में अधिक पूँजी-निवेश को प्रेरणा देने वाली हो
तथा वे उपभोक्ताओं के लिए भी अधिक न हों।

एक सफल एवं आदर्श कृषि-कीमत-नीति से सात्पर्य देश के कृषकों को पैदा-
वार की उचित कीमत दिलाने, उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर आवश्यक मात्रा
में खाद्यान्न उपलब्ध कराने एवं देश की अर्थव्यवस्था को विकास की ओर अग्रसर
करने वाली नीति से है। साथ ही यह नीति उत्पादन एवं बाजार-प्रधान भी होनी
चाहिए।

एक सफल एवं आदर्श कृषि-कीमत-नीति के निम्न उद्देश्य होते हैं³—

- (1) कृषि-उत्पाद एवं निर्मित औद्योगिक माल की कीमतों में उचित
सम्बन्ध बनाये रखना, जिससे दोनों क्षेत्रों के व्यापार का विकास
हो।
- (2) विभिन्न कृषि-उत्पादों की कीमतों में परस्पर उचित सम्बन्ध बनाये
रखना, जिससे नियोजित अर्थव्यवस्था में विभिन्न कृषि उत्पादों के
निर्धारित उत्पादन लक्ष्य प्राप्त हो सकें।
- (3) कृषि-वस्तुओं के लिए उपभोक्ता द्वारा दिये गये मूल्य एवं कृषक को
उसी इकाई के लिए प्राप्त मूल्य के अन्तर को न्यूनतम करना, जिससे
समाज के दोनों वर्गों के हितों की रक्षा हो सके एवं विपणन-मध्यस्थों
द्वारा लिये जाने वाले अत्यधिक लाभ को कम किया जा सके।
- (4) कृषकों को कृषि-उत्पादों की उचित कीमत दिलाकर उत्पादन बढ़ाने
को प्रेरणा देना, जिससे कृषि-आधारित उद्योगों को आवश्यक मात्रा
में नियमित रूप से कच्चा माल उपलब्ध होता रहे।
- (5) कृषि-वस्तुओं की कीमतों में होने वाले उन्नीय एवं मौसमी उतार-
चढ़ाव कम करना।

3. नन्दलाल घग्गल, कृषि मूल्य नीति, याचना. वर्ष 15, पृष्ठ 23 व 24, दिसम्बर 19,
1971, पृष्ठ 29-30,

- (6) कृषि-उत्पादों की कीमतों में स्थिरता लाना, जिससे कृषक कृषि-विकास में अधिक से अधिक धन लगाने को उत्प्रेरित रहे ।
- (7) विभिन्न क्षेत्रों में कृषि-वस्तुओं की कीमतों में पायी जाने वाली असमानता को कम करना, जिससे खाद्यान्नों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनावश्यक संचलन नहीं होवे ।
- (8) कृषि-उत्पादों एवं कृषि के लिए आवश्यक उत्पादन-साधनों की कीमतों में उचित समता (Parity) बनाये रखना, ताकि कृषकों में उत्पादन वृद्धि की प्रेरणा बनी रहे ।
- (9) उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, जिससे वे सीमित आय से उचित जीवन-स्तर प्राप्त कर सकें ।
- (10) कृषि-वस्तुओं की माँग एवं पूर्ति में समन्वय स्थापित करना, जिससे कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव कम हों ।

कृषि-कीमत नीति के उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीति-निर्धारण के साथ-साथ निर्धारित नीति को कार्यान्वित करना भी आवश्यक है । कार्यान्वयन में ढील देने अथवा उसमें गड़बड़ होने से निर्धारित कृषि-कीमत-नीति के उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति सम्भव नहीं होती है । वर्तमान में सरकार का नीति-निर्धारण का पक्ष मजबूत रहा है, लेकिन उसको कार्यान्वित करने का पक्ष कमजोर रहा है, जिससे समाज के दोनों वर्गों—उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को सम्भावित लाभ प्राप्त नहीं हो पाये हैं । कृषि-कीमत-नीति की सफलता का ज्ञान निर्धारित नीति को कार्यान्वित करने के पश्चात् ही प्राप्त होता है । अतः कृषि-कीमत-नीति के निर्धारण के साथ-साथ उसे कार्यान्वित करने के पहलू में भी सुधार लाना आवश्यक है ।

कृषि-कीमत-नीति के निर्धारण के लिए नियुक्त समितियाँ एवं उनके सुझाव :

कृषि-कीमत-नीति के निर्धारण के लिए सरकार ने समय-समय पर विभिन्न समितियाँ नियुक्त की हैं, जिन्होंने कृषि-वस्तुओं की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ावों को कम करने एवं खाद्यान्नों की कमी की समस्या को हल करने के लिए अनेक सुझाव दिये हैं । सरकार द्वारा नियुक्त प्रमुख समितियाँ ये हैं—

(1) खाद्यान्न नीति समिति—यह समिति सर चियोडोर ग्रेगोरी की अध्यक्षता में वर्ष 1943 में नियुक्त की गई थी । समिति ने प्रतिवेदन में कृषि-वस्तुओं की कीमतों के स्थिरीकरण, कीमतों के नियतन में समता सूच के उपयोग एवं कृषि-कीमतों से सम्बन्धित विभिन्न आँकड़ों एकत्रित करने की विधि के लिए सुझाव प्रेषित किये थे ।

(2) कीमत उप-समिति—यह समिति वर्ष 1944 में श्री कृष्णमाचारी की

अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी, जिसने कृषि कीमतों के स्थिरीकरण के लिए निम्न सुझाव दिये थे—

- (i) कृषि-वस्तुओं की कीमतों का पूर्वानुमान फसल की बुवाई के पूर्व तथा पूर्वानुमानित कीमत पर खाद्यान्नों के क्रय करने को कृषकों को आश्वासन दिया जाना चाहिए।
- (ii) कीमतों के निर्धारण में उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा का उद्देश्य भी होना चाहिए।
- (iii) बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए सरकार को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का निर्माण करना चाहिए।
- (iv) निर्धारित नीति को कार्यान्वित करने के लिए, सरकार द्वारा प्रखिल भारतीय कृषि परिषद् का गठन करना चाहिए।
- (v) देश में खाद्यान्नों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा विभिन्न खाद्यान्नों के अन्तर्गत क्षेत्रफल नियत किया जाना चाहिए।

(3) कृषि-कीमत जाँच समिति—इस समिति की नियुक्ति वर्ष 1953 में कृषकों को लाभप्रद सूचना देने, विपणन के आँकड़े एकत्रित करके उनके विश्लेषण के आधार पर सरकार को उत्पादन नीति के विषय में सलाह देने के उद्देश्य से की गई थी।

(4) कृषि-कीमत परिवर्तन जाँच समिति—इस समिति का गठन 1955 में श्री एम० बी० कुब्जाप्पा की अध्यक्षता में अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्देशीय कीमतों की असमानता एवं मौसमी कीमतों के उतार-चढ़ावों को कम करने के लिए आवश्यक सुझाव देने हेतु किया गया था।

(5) खाद्यान्न जाँच समिति—यह समिति वर्ष 1957 में श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमतों की जाँच करने एवं उनके स्थिरीकरण के लिए सुझाव देने हेतु गठित की गई थी। इस समिति ने देश में खाद्य समस्या को हल करने के लिए नवम्बर, 1957 में प्रस्तुत रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव दिये थे—

- (i) कीमत-स्थिरीकरण के विभिन्न पहलुओं पर सरकार को सलाह देने के लिए कीमत स्थिरीकरण परिषद् की स्थापना की जानी चाहिए।
- (ii) कीमतों के सम्बन्ध में सूचना संचार करने के लिए केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर कीमत-सूचना विभाग की स्थापना की जानी चाहिए।

- (iii) खाद्यान्नों की न्यूनतम कीमत का निर्धारण प्रति वर्ष मॉग एंव पूर्ति की स्थिति के अनुसार किया जाना चाहिए।
- (iv) सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों का बफर स्टॉक किया जाना चाहिए।
- (v) खाद्यान्नों की बढ़ती हुई अल्पकालीन कीमतों को रोकने के लिए व्यापारियों को अनुज्ञा-पत्र देने, विभिन्न क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए खाद्य-क्षेत्रों का निर्माण करके, लेवो द्वारा खाद्यान्नों की अतिवायं बनूली एवं उचित कीमत की दुकानों द्वारा उनके वितरण की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- (vi) कीमतों में वृद्धि रोकने के उपर्युक्त उपायों को अपनाने के अतिरिक्त उत्पादन-वृद्धि की कोशिश भी की जानी चाहिए। उत्पादन-वृद्धि के लिए उन्नत बीजा के आविष्कार, उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग, कृषकों को कृषि की उन्नत विधियों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए अनुदान तथा कृषि-मृत्तु की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

(6) फोडं सस्थान दल—भारतीय खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए फोडं सस्थान दल ने वर्ष 1959 में निम्न सुझाव दिये—

- (i) विभिन्न खाद्यान्नों की न्यूनतम कीमत सरकार द्वारा फसल की बुवाई के पूर्व घोषित की जानी चाहिए, जिससे घोषित कीमतों से कृषक उत्पादन-योजना बनाते समय लाभान्वित हो सकें।
- (ii) निर्धारित कीमत-नीति को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा स्थायी संगठन का निर्माण किया जाना चाहिए।
- (iii) खाद्यान्नों की कीमतों का निर्धारण आयातित खाद्यान्नों की प्रवेष्टा 10 से 15 प्रतिशत कम स्तर पर किया जाना चाहिए।

(7) खाद्यान्न-नीति समिति—सरकार ने वर्ष 1966 में श्री बी० बैकटपेंड्या की अध्यक्षता में कीमतों में होने वाले अत्यधिक उतार-चढ़ावों को कम करने हेतु आवश्यक सुझाव देने के लिए खाद्यान्न-नीति समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव दिये थे—

- (i) खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने एवं कीमत-स्थिरीकरण के लिए राष्ट्रीय खाद्य-बजट का निर्माण किया जाना चाहिए।
- (ii) कीमतों के मौसमी उतार-चढ़ावों को कम करने के लिए सरकार को खाद्यान्नों के पर्याप्त मात्रा में भण्डारण का प्रबन्ध करना चाहिए।

- (iii) खाद्यान्नों की वस्तुओं एवं वितरण का कार्य खाद्य निगम की प्रादेशिक शाखाओं के द्वारा करवाया जाना चाहिए, जिससे क्षेत्र में होने वाली व्यापारिक कुरीतियों को रोका जा सके।
- (iv) प्रति वर्ष सरकार द्वारा खाद्यान्नों की न्यूनतम एवं वस्तुली कीमत नियत की जानी चाहिए।
- (v) ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्नों की समुचित वितरण व्यवस्था के लिए उचित कीमत की दुकानों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए।
- (vi) अधिक उत्पादन वाले क्षेत्रों के कृषकों से उत्पादन की प्राप्त मात्रा अथवा क्षेत्रफल के अनुसार श्रेणीकृत सेवा विधि द्वारा खाद्यान्नों की वस्तुली की जानी चाहिए।
- (vii) खाद्यान्नों के विरखन में होने वाली विपणन-लागत को कम करने के लिए समिति ने देश की मण्डियों को नियन्त्रित करने, व्यापारियों को अनुज्ञा-पत्र देने एवं उनके हिसाब की समय-समय पर जांच करने की सिफारिश की है।
- (viii) सरकार द्वारा कृषकों को उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। कृषकों को उत्पादन वृद्धि की प्रेरणा देने के लिए उत्पादन-साधन, जैसे—उर्वरक, कीटनाशी दवाइयाँ, विद्युत् आदि के ऋय पर धार्मिक सहायता दी जानी चाहिए, जिससे कृषक इनका अनुकूलतम मात्रा में उपयोग करके खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि कर सकें।

(8) कृषि लागत एवं कीमत आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices) —कृषि वस्तुओं की कीमत-नीति के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए भारत सरकार ने जनवरी, 1965 में प्रो एम. एल. बानर्जी की अध्यक्षता में कृषि-कीमत आयोग (Agricultural Prices Commission) की स्थापना की थी। प्रारम्भ में यह आयोग तीन वर्ष की अवधि के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन नीति निर्धारण में इसकी महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए इसे स्थायी रूप दे दिया गया है। कृषि कीमत आयोग की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य ये हैं—

- (i) प्रमुख कृषि-उत्पाद—गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट, मन्च दालें एवं मोटे अनाज वाली फसलों के सन्तुलित एवं एकीकृत कीमतों के ढाँचे का निर्माण करने एवं उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सरकार को समय-समय पर आवश्यक सुझाव देना।
- (ii) विभिन्न कृषि उपादों की कीमतों में होने वा उतार-चढ़ावों की

समीक्षा करना एवं उनको कम करने के लिए सरकार को समय-समय पर आवश्यक सुझाव देना, जैसे खाद्यान्नों की वसूली के लिए लेवी लगाना, वेंफर स्टॉक निर्माण, खाद्य-क्षेत्रों का निर्माण, खाद्यान्नों का वितरण आदि ।

- (iii) कृषि-उत्पादन के क्षेत्र में बाधक तत्वों—उत्पादन-साधनों की कमी, उनका समय पर उपलब्ध नहीं होना, कीमतों की अधिकता की समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार को आवश्यक सुझाव देना ।
- (iv) कृषि-उत्पादों के विपणन में होने वाली विपणन-लागत एवं मध्यस्थों को प्राप्त होने वाले लाभ का अध्ययन करना एवं उनको कम करने के उपायों की सरकार को सलाह देना, जिससे कृषकों को उपभोक्ता-मूल्य में से अधिक भ्रश प्राप्त हो सके ।
- (v) कृषकों को उत्पादन वृद्धि की प्रेरणा देने के लिए सरकार को आवश्यक सुझाव देना, जैसे—विभिन्न खाद्यान्नों की न्यूनतम समर्थित कीमत घोषित करना, खाद्यान्नों की वसूली के लक्ष्य एवं कीमतें नियन करना आदि ।

कृषि-कीमत आयोग प्रत्येक वर्ष खरीफ एवं रबी की मौसम के प्रमुख कृषि-उत्पादों की न्यूनतम समर्थित कीमत एवं वसूली कीमत नियत करने की सिकारिश अपनी रिपोर्ट में सरकार को करता है । सरकार आयोग द्वारा सुझाई गई कीमतों पर विचार करके एवं उनमें आवश्यकतानुसार संशोधन करके कीमतें घोषित करती है । वर्तमान में सरकार ने इसका नाम कृषि-लागत एवं कीमत आयोग करके इसके कार्य-क्षेत्र में विस्तार किया है ।

कृषि-लागत एवं कीमत आयोग द्वारा कीमतों का निर्धारण—कृषि-कीमत आयोग अपने स्थापना वर्ष 1965 से ही कृषि-उत्पादों की तर्क-संगत योजना के आधार पर कीमत-निर्धारण का कार्य कर रहा है । कृषि लागत एवं कीमत आयोग निम्न दो प्रकार की कीमतें प्रस्तावित कर रहा है—

(अ) न्यूनतम-समर्थित कीमत—कृषि-लागत एवं कीमत आयोग विभिन्न कृषि-उत्पादों की कीमतों में प्रतिवर्ष होने वाली मिरावट से कृषकों की रक्षा करने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थित कीमत नियत करने का सुझाव सरकार को देता है । यह न्यूनतम समर्थित कीमत कृषकों की उत्पादन-लागत के आधार पर निर्धारित की जाती है । न्यूनतम समर्थित कीमत कृषकों के लिए बीमा कीमत के रूप में होती है । यह कीमत उन्हें विश्वास दिलाती है कि बाजार में कृषि-उत्पादों की प्रचलित कीमत के कम होने अथवा उत्पादन अधिक मात्रा में होने की दोनों ही अवस्थाओं में सरकार कृषकों से नियत की गई न्यूनतम समर्थित कीमतों पर कृषि-उत्पाद न्य करेगी ।

कृषि-लागत एवं कीमत आयोग विभिन्न कृषि उत्पादों की न्यूनतम समर्थित कीमत की सिफारिश सरकार को फसल की बुवाई के समय से पूर्व ही कर देना है, जिससे सरकार फसल की बुवाई से पूर्व ही कृषकों के लिए इन कीमतों को घोषित कर सके। इन कीमतों को फसल की बुवाई से पूर्व घोषित कर देने से कृषकों को फार्म की उत्पादन-योजना बनाने से सम्बन्धित निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

(ब) वसूली/अधिप्राप्ति कीमत—कृषि-लागत एवं कीमत आयोग न्यूनतम समर्थित कीमत के साथ-साथ प्रमुख खाद्यान्नों के लिए वसूली कीमतें भी प्रस्तावित करता है। वसूली कीमत वह है जिस पर सरकार आवश्यकता होने पर कृषकों, व्यापारियों एवं मिल-मालिकों से कृषि-उत्पाद कय करती है। सरकार कमजोर वर्षों को उचित कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए बचनबद्ध होती है। अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वसूली कीमत का निर्धारण आवश्यक है। कृषि-लागत एवं कीमत आयोग खाद्यान्नों के लिए वसूली कीमत का निर्धारण फसल के कटाई के पूर्व कृषकों की उत्पादन-लागत एवं प्राप्त उत्पादन की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए करता है।

कृषि-लागत एवं कीमत आयोग द्वारा प्रस्तावित कीमतों पर सरकार राज्यों के मुख्यमन्त्रियों एवं कृषि-मन्त्रियों से मन्त्रणा के पश्चात् निर्णय लेकर कीमतों की घोषणा करती है। सरकार कृषि लागत एवं कीमत आयोग द्वारा प्रस्तावित कीमत में संशोधन कर सकती है। वर्ष 1975-76 के अतिरिक्त सभी वर्षों में कृषि-लागत एवं कीमत आयोग द्वारा प्रस्तावित वसूली-कीमतों में सरकार ने संशोधन किया है। राजनैतिक एवं अन्य कारणों से सरकार ने खाद्यान्नों की वसूली कीमत, कृषि-लागत एवं कीमत आयोग द्वारा प्रस्तावित कीमत से अधिक स्तर पर ही निर्धारित की है। वर्ष 1975-76 में कृषि-लागत एवं कीमत आयोग द्वारा गेहूँ की प्रस्तावित वसूली कीमत को सरकार ने मान लिया था। अतः कृषि-लागत एवं कीमत आयोग द्वारा प्रस्तावित कीमत एक सिफारिश मात्र है जिसे स्वीकार करना अथवा नहीं करना सरकार के अधिकार में होता है।

कृषि-लागत एवं कीमत आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थित कीमत 'तब प्रभाव में आती है जब कृषक निर्धारित न्यूनतम कीमत पर खाद्यान्न सरकार को विक्रय करना चाहते हैं, अर्थात् बाजार में प्रचलित कीमत, न्यूनतम समर्थित कीमत से कम होती है। ऐसी कृषि-लागत एवं कीमत आयोग की स्थापना के पश्चात् एक बार वर्ष 1970-71 में गेहूँ के उत्पादन में विशेष वृद्धि होने के कारण पंजाब व हरियाणा राज्यों में हुआ था, जब मण्डियों में गेहूँ की कीमत निर्धारित न्यूनतम समर्थित कीमत से भी नीचे स्तर पर आ गई थी। सरकार के पास खाद्यान्नों के क्रय संग्रहण, वित्त आदि की कार्य-कुशल व्यवस्था नहीं होने के कारण सरकार बाजार में, उपलब्ध गेहूँ की मात्रा को निर्धारित न्यूनतम समर्थित कीमत पर क्रय नहीं कर सकी, जिसके कारण कृषकों को न्यूनतम नियत कीमत से नीचे के स्तर पर गेहूँ विक्रय करके हानि उठानी पड़ी। सरकार के पास खाद्यान्नों के क्रय, संग्रहण आदि की उचित व

पर्याप्त मात्रा के उत्पाद में न्यूनतम समर्थित कीमतों की घोषणा से कृषकों को लाभ नहीं हो पाता है। वर्ष 1970-71 के बाद खाद्यान्नों की कीमतों में निवारित न्यूनतम स्तर से नीचे गिरावट नहीं आई। अतः कृषि-साग्न एवं कीमत आयोग द्वारा निवारित न्यूनतम समर्थित कीमतों की घोषणा एक औपचारिकता मात्र ही रही है।

कृषि-साग्न एवं कीमत आयोग वनूली-कीमतों का निर्धारण कृषकों को होने वाली साग्न के स्तर से ऊँचे स्तर पर करता है, जिससे कृषकों को उत्पादन-साग्न की प्राप्ति के साथ-साथ लाभ का भण्डो राशि भी प्राप्त हो और उन्हें उत्पादन वृद्धि की प्रेरणा मिले। वे केवल वनूली-कीमतों का निर्धारण बाजार में प्रचलित कीमतों से नीचे स्तर पर किया जाता है, जिससे देश के गरीब वर्ग के उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर सरकार द्वारा उपलब्ध करा सके। देश में खाद्यान्नों की बाजार कीमत एवं सरकार द्वारा नियत वनूली-कीमत में काफी अन्तर होने पर, कृषक, व्यापारी एवं मिल-मालिक सरकार को निर्धारित वनूली कीमत पर स्वेच्छा से खालान्न विक्रय करना नहीं चाहते हैं और ऐसा न करने के लिये अनेक प्रकार की धनौलें पेश करते हैं। उनके द्वारा दी गई दलीलों में प्रमुख उत्पादन-साग्न की राशि पूरी प्राप्त नहीं होना, विक्रय के लिए उनके पास खालान्न का अविशेष नहीं होना, व्यापारियों एवं मिल-मालिकों द्वारा खरीद के इन्तज नहीं किया जाना, आदि हैं।

कृषि-साग्न एवं कीमत आयोग द्वारा प्रस्तावित वनूली-कीमत का अधिकार राज्यों के मुख्य मन्त्रियों एवं कृषि मन्त्रियों द्वारा विरोध प्रकट किया जाता है तथा दलील दी जाती है कि प्रस्तावित वनूली-कीमत ने वृद्धि की जाती चाहिये, क्योंकि इन पर राज्य के अनेक कृषकों का उत्पादन-साग्न की राशि एवं कृषकों को खालान्न के उत्पादन में अन्य क्षेत्रों में कार्यरत ध्यक्तियों के समान लाभ की उम्मीद नहीं होती है। कृषि-साग्न एवं कीमत आयोग द्वारा गृह के लिये प्रस्तावित वनूली-कीमत का गेहूँ के प्रमुख उत्पादन वाले राज्यों—पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान द्वारा विरोध किया जाता रहा है, जिसके कारण सरकार को प्रतिद्वेष वनूली-कीमत की घोषणा कृषि-साग्न एवं कीमत आयोग द्वारा प्रस्तावित कीमतों से ऊँचे स्तर पर करनी पड़ती है।

कृषि-कीमत-नीति के कार्यान्वयन में मुषार के उपाय

कृषि-कीमत-नीति के कार्यान्वयन में मुषार के लिए निम्न उपाय अन्तर्गत होने चाहिये—

- (1) कृषि-उत्पादों के सम्बन्ध में उनके अनावश्यक उपभवन को कम करने के लिए विभिन्न स्थानों—गाँवों, शहरों, मण्डियों एवं रेल्व स्टेशनों के नजदीक वैज्ञानिक विधि के आधार पर याज्ञना का निदान करना चाहिए। वर्तमान में देश के विभिन्न क्षेत्रों में गोदाओं की स्थिति,

सस्या एवं सग्रहण-क्षमता संतोषजनक नहीं है। कृषि-कीमत नीति की सफलता के लिए इनकी महत्ता काफी अधिक है। उचित स्थानों पर गोदानों के निर्माण में परिवहन-लागत में कमी होती है।

- (2) निर्धारित बफर स्टॉक के निर्माण के लिए खाद्यान्नों के क्रय का कार्य व्यापारियों एवं मध्यस्थों को नहीं देना चाहिए। खाद्यान्नों के क्रय का कार्य सहकारी-विपणन समितियों, भारतीय खाद्य निगम अथवा राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के माध्यम से कराना चाहिए, जिससे उप-भोक्ताओं में अनावश्यक भ्रांतियाँ नहीं फैले।
- (3) व्यापारियों को कुचालों एवं उनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली कृत्रिम कमी पर नियन्त्रण पाने के लिए व्यापारियों को अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने चाहिए। उनके द्वारा सग्रहण की जाने वाली मात्रा का नियतन एवं उनके स्टॉक के प्रदर्शन की व्यवस्था भी होनी चाहिए।
- (4) निर्धारित कीमत-नीति में सरकार को परिवर्तन कम से कम करना चाहिए तथा किये गये परिवर्तनों की सूचना समय पर समाज के सभी वर्गों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- (5) कीमत-नीति का उत्सर्जन करने पर सभी वर्गों के नागरिकों के लिए समान जुमनि का प्रावधान होना चाहिए, जिससे नागरिकों की कीमत-नीति के प्रति दृढ़ भावना जागृत हो सके।
- (6) सरकार द्वारा विभिन्न खाद्यान्नों की न्यूनतम-समर्थित कीमतों का नियतन एवं उनकी घोषणा का कार्य फसल की बुवाई के पूर्व हो जाना चाहिए, जिससे कृषक फसलों का चुनाव एवं उनके अन्तर्गत क्षेत्रफल-निर्धारण का सही निर्णय ले सकें।
- (7) कीमतों के नियत न्यूनतम स्तर से नीचे गिरने की स्थिति में सरकार को खाद्यान्नों के क्रय की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक वित्त, सग्रहण एवं कार्यकर्ताओं की व्यवस्था समय से पूर्व ही कर लेनी चाहिए, जिससे आवश्यकता होने पर उनका शीघ्रता से उपयोग किया जा सके।
- (8) कीमतों के बढ़ते हुए स्तर को रोकने के लिए कृषकों को आवश्यक मात्रा में एवं सस्ती दर पर उत्पादन-साधन—बीज, उर्वरक, कीटनाशक वगैरह, कृषि-यन्त्र उपलब्ध कराने के लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए, जिससे खाद्यान्नों की उत्पादन-लागत में कमी हो सके।

- (9) सरकार द्वारा घोषित कृषि-नीति की सफलता के लिए आवश्यक सुविधाओं (Infrastructure) का विकास करना आवश्यक है, जैसे—
देश में परिवहन सुविधा के लिए सड़कों का निर्माण, विभिन्न मण्डलों का विकास, सहकारी विपणन समितियों की स्थापना, आदि।
- (10) गाँवों में खाद्यान्नों की उचित वितरण व्यवस्था के लिए उचित कृषि की दुकानों की सहायता में वृद्धि तथा सहकारी विपणन समितियों के निर्माण के लिए कृषकों में जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए।
- (11) कृषि में वृद्धि होने की स्थिति में सरकार द्वारा खाद्यान्नों के व्यापार को पूर्णतः अपने हाथ में ले लेना चाहिए तथा विपणन-नियमों को बनाए रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए।



कृषि उत्पादों की कीमत-निर्धारण

वस्तुओं के क्रय-विन्य के लिए कीमतों का निर्धारण आवश्यक होता है। कीमतों का निर्धारण मण्डी में वस्तुओं के क्रेताओं एवं विक्रेताओं के परस्पर सम्पर्क द्वारा होता है। कमी-कमी निर्धारित कीमतें व्यापारियों के प्रभाव के कारण अपने निर्धारित उद्देश्य—कृषकों को उत्पाद की लाभप्रद कीमत दिलाने तथा उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सफल नहीं होती है। अतः समाज के दोनों वर्गों को होने वाली हानि से रक्षा करने हेतु सरकार कीमत-निर्धारण का कार्य करती है।

कीमत-निर्धारण में वस्तुओं के अधिकतम एवं न्यूनतम दोनों ही स्तर निर्धारित किये जाते हैं। न्यूनतम कीमत का निर्धारण कृषकों को उत्पादन की उत्पादन-लाभ एवं उचित लाभ की राशि प्राप्त कराने तथा अधिकतम कीमत का निर्धारण उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु किया जाता है, जिससे उपभोक्ता अपनी सीमित आय से उचित जीवन-स्तर बनाये रख सकें। कृषि-वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण करने में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के उद्देश्य के प्रति-रिक्त निम्न सावधानियाँ भी ध्यान में रखनी चाहिए—

- (i) देश के विभिन्न क्षेत्रों में कीमत निर्धारण नीति में समानता बनाये रखने के लिए यह कार्य राज्य सरकारों की सलाह के अनुसार किया जाना चाहिए।
- (ii) कृषि वस्तुओं की कीमतों के निर्धारण में उन सभी उत्पादों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, जो एक दूसरे से सम्बन्धित हैं एवं एक उत्पाद की कीमत-निर्धारण से दूसरे उत्पाद की कीमत प्रभावित होती है।
- (iii) कृषि उत्पादों की कीमतों के निर्धारण में विभिन्न राज्यों में उत्पादों के उत्पादन-लाभ के अंकड़ा को दृष्टिगत रखना चाहिए, क्योंकि इनमें विभिन्न राज्यों में बहुत भिन्नता पायी जाती है।
- (iv) कृषि-उत्पादन के लिए सभी वष सामान्य नहीं होते हैं। अतः कृषि व्यवसाय में होने वाली जोखिमा को कीमतों के निश्चित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

- (v) निर्धारित कीमतें कृषकों को उत्पादन वृद्धि की प्रेरणा देने वाली होनी चाहिए, जिससे देश खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता की ओर अग्रसर हो सके।
- (vi) वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए पृथक् कीमतें नियत की जानी चाहिए, जिससे देश में अच्छी किस्म की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हो सके।

कृषि कीमतों के निर्धारण के आधार .

कृषि-कीमतों के निर्धारण के निम्न आधार होते हैं जिनका उपयोग सरकार कीमतें निश्चित करत समय विभिन्न परिस्थितियों में करती है—

(1) औसत उत्पादन लागत का आधार—कृषि-कीमतों के निर्धारण का प्रथम आधार वस्तुओं के उत्पादन में आने वाली औसत लागत है। विभिन्न वस्तुओं की प्रति इकाई मार के उत्पादन पर खेन को तैयारी में उनकी बिपणन प्रक्रिया तक होने वाली लागत को उस वस्तु की उत्पादन-लागत कहते हैं। विभिन्न कृषि वस्तुओं की प्रति इकाई उत्पादन लागत की राशि भूमि की किस्म, जलवायु एवं तकनीकी ज्ञान के स्तर के अनुसार परिवर्तित होती है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र विशेष में उपर्युक्त कारकों के समान होत हुए, कृषकों की प्रबन्ध क्षमता, उत्पादन साधनों की उपलब्धि एवं उपयोगित मात्रा में भिन्नता, व्यवसाय में पूँजी निवेश की राशि, फार्म पर कृषि-यन्त्रीकरण का स्तर आदि कारकों के अनुसार उत्पादन-लागत में बहुत अन्तर पाया जाता है। अतः विभिन्न कृषकों की उत्पादन-लागत में अधिक भिन्नता पायी जाने के कारण, उनकी औसत लागत ज्ञात की जाती है। कृषि-उत्पादों की औसत उत्पादन-लागत की राशि में कृषकों को दिये जाने वाले लाभ की राशि को सम्मिलित करके उनकी न्यूनतम कीमतें सरकार द्वारा नियत की जाती हैं।

वस्तुओं की औसत उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए विभिन्न मनों पर हुई लागत के आँकड़े लागत-लेखा-विधि अथवा सर्वेक्षण-विधि द्वारा प्राप्त किये जाते हैं। लागत-लेखा-विधि में नियुक्त क्षेत्रिक, कृषकों द्वारा फार्म पर उत्पादित की गई विभिन्न फसलों के उत्पादन पर किये गये व्यय का मद के अनुसार दैनिक लेखा रखते हैं। सर्वेक्षण-विधि के अन्तर्गत विभिन्न फसलों के उत्पादन-लागत के आँकड़े क्षेत्र के कृषकों में साक्षात्कार के द्वारा प्राप्त किये जाते हैं। सर्वेक्षण-विधि द्वारा प्राप्त उत्पादन-लागत के आँकड़ों का सही अनुमान कृषकों की स्मरण-शक्ति एवं उनके द्वारा दी गई सूचना की सत्यता पर निर्भर करता है, जबकि लागत-लेखा-विधि के आँकड़े अधिक विश्वसनीय होते हैं। उत्पादन-लागत के आँकड़े लागत-लेखा-विधि द्वारा एकत्रित करने में समय एवं व्यय की अधिकता के कारण सर्वेक्षण विधि अधिक प्रयुक्त की जाती है।

औसत उत्पादन-लागत विधि द्वारा कीमतों के निर्धारण में निम्न दोष विद्यमान होते हैं—

(1) विभिन्न कृषकों द्वारा फार्म पर प्रयुक्त श्रम एवं प्रबन्ध के मूल्यांकन की विधि, उत्पादन-साधनों की प्रयुक्त मात्रा, उत्पादन-साधनों की क्रय-कीमत में भिन्नता होने के कारण कृषकों की प्रति विबन्धन उत्पादन-लागत में बहुत भिन्नता होती है, जिसके कारण औसत उत्पादन लागत की राशि अनेक कृषकों की प्रतिनिधि उत्पादन-लागत नहीं होती है। अनेक कृषकों को इसके आधार पर निर्धारित कीमत से उत्पादन-लागत की राशि भी प्राप्त नहीं हो पाती है। उदाहरण के लिए, नहरों से सिंचाई करने वाले कृषकों की विभिन्न फसलों की उत्पादन-लागत चरस मृदावा पम्प से सिंचाई करने वाले कृषकों की अपेक्षा बहुत कम आती है। अतः निर्धारित कीमत से नहरों क्षेत्र के कृषकों को प्रति इकाई उत्पादन की मात्रा में लाभ अधिक प्राप्त होता है, जबकि चरस में सिंचाई करने वाले कृषकों को ध्वय की गई राशि भी पूरी प्राप्त नहीं हो पाती है। २

(II) औसत उत्पादन-लागत विधि के आधार पर कीमतों के निर्धारण से कृषकों द्वारा प्रयुक्त उर्वरक की मात्रा के कम होने की सम्भावना हो जाती है। वर्तमान में कृषक उर्वरक एवं अन्य उत्पादन-साधनों का उपयोग उस स्तर तक करते हैं जहाँ उनके उपयोग किये गये उर्वरक की सीमान्त-लागत व उससे प्राप्त सीमान्त-लाभ की राशि बराबर होती है। इस स्तर तक उर्वरक के उपयोग से फसल की प्रति इकाई भार पर औसत उत्पादन-लागत बढ़ जाती है, जिसमें उन्हें प्रति इकाई उत्पादन की मात्रा पर लाभ कम प्राप्त होता है और वे अगले वर्ष उत्पादन-साधनों की कम मात्रा का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं।

(III) इस विधि के द्वारा कीमत-निर्धारण में अर्थ-व्यवस्था के एक ही पहलू अर्थात् पूर्ति को ही ध्यान में रखा जाता है। कीमत-निर्धारण के दूसरे पहलू माँग को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। कीमत-निर्धारण में माँग एवं पूर्ति दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं।

विभिन्न फसलों के उत्पादन-लागत के सही आँकड़े ज्ञात करने के लिए भारत सरकार के कृषि मन्त्रालय के आर्थिक एवं सांख्यिकी सलाहकार के तत्वावधान में अनेक राज्यों में उत्पादन-लागत ज्ञात करने के लिए एक विस्तृत योजना (Comprehensive Scheme for Studying Cost of Cultivation of Principal Crops) वर्ष 1970-71 से शुरु की गई है, जिसके द्वारा भूमि एवं जलवायु की भिन्नता के अनुसार क्षेत्र की प्रमुख फसलों की औसत उत्पादन-लागत के आँकड़े एकत्रित किये जाते हैं। इन आँकड़ों के आधार पर कृषि-लागत एवं कीमत आयोग न्यूनतम एवं वसूली कीमत नियत करने की सरकार को सिफारिश करता है।

(2) बहुसंख्यक-उत्पादन-लागत विधि—एक ही क्षेत्र में लघु एवं दीर्घ जोत कृषकों, पूँजीपति एवं गरीब कृषकों तथा विद्युत् पम्प एवं चरस से सिंचाई करने वाले कृषकों के फार्म पर उत्पादों की प्रति इकाई भार पर आने वाली उत्पादन-

लागत में बहुत भिन्नता होती है। अने विभिन्न कृषकों की उत्पादन-लागत के आधार पर ज्ञान की गई औसत उत्पादन-लागत देश के अधिकांश कृषकों की प्रतिनिधि उत्पादन-लागत नहीं होती है। इस दोष को दूर करने के लिए कीमत निर्धारण की दूसरी विधि बहुसंख्यक उत्पादन-लागत विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में 80 से 85 प्रतिशत उत्पादन खाद्यान्नों की मात्रा प्रति इकाई उत्पादन-लागत के आंकड़ों को ही कीमत निर्धारण में प्रयुक्त किया जाता है और शेष 15 से 20 प्रतिशत उत्पादन की मात्रा जो असंख्य कृषकों द्वारा उत्पादित की जाती है और जो कृषि को व्यवसाय के रूप में नहीं लेकर जीविकोपार्जन के रूप में लेते हैं, उनकी उत्पादन-लागत की कीमत-निर्धारण के लिए सम्मिलित नहीं किया जाता है। बहुसंख्यक उत्पादन-लागत विधि के आधार पर भी कीमतों के निर्धारण में अर्थ-व्यवस्था के एक ही पहलू अर्थात् पूर्ति को ही ध्यान में रखा जाता है। अर्थ-व्यवस्था के दूसरे पहलू मांग को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता है। अर्थात् यह विधि भी दोष रहित नहीं है।

(3) प्रचलित कीमत-विधि—इस विधि में कीमते, वस्तु के पिछले वर्षों की औसत कीमत, वर्तमान प्रचलित कीमत, उनकी आकस्मिक मांग एवं पूर्ति की मात्रा एवं उनमें परिवर्तन लाने वाले विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित आंकड़ों के आधार पर नियत की जाती है। वस्तुओं की कीमतों में मौसमी, क्षेत्रीय एवं अनियमित उतार-चढ़ावों के कारण, नियत कीमत मण्डी में प्रचलित वास्तविक कीमत की प्रतीक नहीं होती है। किसी वर्ष में नियत कीमत मण्डी-कीमत से बहुत अधिक तथा अन्य वर्ष बहुत कम होती है। इस प्रकार कीमत-निर्धारण की यह विधि भी कृषकों को सही कीमत दिलाने में सफल नहीं होती है।

(4) समता कीमत-सूत्र विधि—समता-कीमत कृषि एवं कृषितर क्षेत्र की वस्तुओं की कीमतों, अमुक खाद्यान्न एवं सभी कृषि-वस्तुओं की कीमतों, कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं उनके द्वारा क्रय किये जाने वाले उत्पादन-साधनों की कीमतों में आधार वर्ष के अनुसार पाये जाने वाले सम्बन्ध की खोज होती है। कृषि कीमतों को नियत करने के लिए कृषकों द्वारा उत्पादित उत्पाद एवं उनके उत्पादन के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले उत्पादन-साधनों की कीमतों में समता ज्ञात की जाती है। समता-कीमत के आधार पर कृषि-कीमतें नियत करने का मुख्य उद्देश्य कृषि-क्षेत्र में कार्यरत कृषकों को उसी अनुपात में लाभ प्राप्त करना है, जिस अनुपात में यह लाभ औद्योगिक एवं अन्य क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को प्राप्त होता है। इस पद्धति के पक्ष में 1943 में खाद्यान्न नीति समिति एवं 1944 में कीमत उप-समिति ने अपनी संहति प्रकट की थी।

कृषि-क्षेत्र में समता-अनुपात एवं समता-कीमत ज्ञात करने का सूत्र अग्रलिखित प्रकार से है—

$$\text{समता-अनुपात} = \frac{\text{कृषकों द्वारा विक्रय की गई वस्तुओं की कीमतों का आधार-वर्ष के अनुसार प्रचलित कीमत सूचकांक}}{\text{कृषकों द्वारा त्रय की गई वस्तुओं की कीमतों का आधार-वर्ष के अनुसार प्रचलित कीमत सूचकांक}} \times 100$$

$$\text{समता-कीमत} = \frac{\text{आधार-वर्ष का विक्रय कीमत सूचकांक} + \text{प्रचलित त्रय कीमत सूचकांक}}{\text{आधार-वर्ष का त्रय-कीमत सूचकांक}}$$

समता-कीमत विधि के आधार पर कीमत नियत करने के लिए कृषि-उत्पादों की प्रति इकाई उत्पादन-लागत के आँकड़े एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही यह विधि समाज के विभिन्न वर्गों में पायी जाने वाली आय असमानता को कम करने में भी सहायक होती है। समता-कीमत विधि के अनुसार कीमत नियत करने में वस्तुओं की उपलब्धि एवं आवश्यकता की मात्रा को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जिसके कारण बड़े कृषकों के पास विक्रय-अधिशेष की मात्रा की अधिकता के कारण उन्हें लघु कृषकों की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त होता है।

(5) वायदा-कीमत विधि—कृषि-वस्तुओं की वायदा-कीमत सरकार द्वारा उनकी माँग, पूर्ति एवं उत्पादन-लागत के आधार पर फसल की बुवाई के पूर्व घोषित की जाती है। यह कीमत कृषकों को आश्वासन देती है कि उन्हें फसल की कटाई के उपरान्त विपणन मौसम में नियत वायदा-कीमत प्राप्त होगी। मण्डी में प्रचलित कीमत के कम होने पर सरकार घोषित कीमत पर कृषि-उत्पाद नय करती है। इस प्रकार वायदा-कीमत कृषकों को फार्म की उत्पादन योजना बनाने एवं उसे कार्यान्वित करने में सहायक होती है, लेकिन वायदा-कीमत के निर्धारण के लिए आवश्यक आँकड़े, जैसे—कृषि-वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा, उपभोक्ताओं की माँग की मात्रा एवं उसे प्रभावित करने वाले कारकों से सम्बन्धित विश्वसनीय सूचना प्राप्त नहीं हो पाती है तथा नियत वायदा-कीमत, आवश्यक सग्रहण सुविधा के अभाव, सरकार के पास कार्य-कुशल शासन-व्यवस्था के न होने, सरकार की कीमत-नीति की अस्थिरता आदि कारणों से पूर्ण रूप में कार्यान्वित नहीं हो पाती है। इन कारणों से देश में वायदा-कीमत विधि भी सफल नहीं हो पायी है।

कृषि-वस्तुओं के कीमत-निर्धारण के लिए विभिन्न समयों में विभिन्न आधार प्रयुक्त किये गये हैं।

कीमत-निर्धारण की विधियाँ

कीमत निर्धारण की निम्न दो विधियाँ होती हैं—

(1) समूह समग्र कीमत निर्धारण अथवा समष्टिमूलक कीमत निर्धारण विधि—इस विधि द्वारा कृषि उत्पादों की कीमतों के निर्धारण में सर्वप्रथम उत्पादों के समूहों की कीमतों तथा उसके पश्चात् समूह के विभिन्न अवयवों की कीमतों का विवेचन किया जाता है। कीमत निर्धारण की इस विधि का सिद्धान्त सरल है, लेकिन कीमत निर्धारण का वास्तविक कार्य कठिन होता है, क्योंकि कीमत निर्धारण के लिए राष्ट्रीय स्तर के सही आँकड़ उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। कीमतों के निर्धारण के लिए आवश्यक सही आँकड़े उपलब्ध नहीं हो पाने की अवस्था में जो कीमतें निर्धारित होती हैं वे प्रचलित कीमतों की प्रतीक नहीं होती हैं।

(2) प्रति इकाई कीमत निर्धारण अथवा व्यष्टिमूलक कीमत निर्धारण विधि—इस विधि में विभिन्न वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति की मात्रा के आधार पर कीमतें निर्धारित की जाती हैं। कीमतों का निर्धारण मांग एवं पूर्ति के सन्तुलन बिन्दु पर होता है। विभिन्न वस्तुओं की कीमतों के निर्धारण के लिए वस्तु की मांग, क्षेत्र के उत्पादकों द्वारा उत्पादित मात्रा एवं बाजार में वस्तु की पूर्ति की मात्रा का अध्ययन किया जाता है। कीमत निर्धारण की इस विधि को व्यष्टिमूलक विधि कहते हैं क्योंकि इस विधि में कीमत संरचना के एक मुख्य भाग पर ही ध्यान केन्द्रित किया जाता है। कीमत निर्धारण की यह विधि प्रयोग में अधिक ली जाती है। मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के द्वारा कीमत निर्धारण की इस विधि का विस्तृत विवेचन नीचे किया गया है—

मांग—कीमत निर्धारण की प्रथम शक्ति वस्तु की मांग होती है। वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता दी हुई कीमतों पर विशिष्ट समय एवं बाजार में क्रय करने को तत्पर होते हैं, मांग कहलाती है। उपभोक्ताओं को किसी वस्तु की मांग की मात्रा, उसकी कीमत, उपभोक्ताओं की आय उपभोक्ताओं की मर्यादा सम्बन्धित वस्तुओं की कीमतों मौसम परिवर्तन एवं उपभोक्ताओं की रसि में परिवर्तन से प्रभावित होती रहती है।

मांग और कीमत के सम्बन्ध के विवरण को मांग का नियम कहते हैं। मांग का नियम हासमान उपयोगिता के नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब वस्तु अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है तो वस्तु की उपयोगिता कम हो जाती है जिससे उपभोक्ता उसकी पहले के समान कीमत देने को तत्पर नहीं होते हैं और कीमतें गिर जाती हैं। मांग के नियम के अनुसार अन्य कारकों के समान रहते हुए किसी वस्तु की कीमत के कम हो जाने पर उसकी मांग की मात्रा में वृद्धि तथा कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग की मात्रा कम हो जाती है। अतः वस्तु की कीमत एवं मांग में सामान्यतः विलोम सम्बन्ध होता है। मांग का यह

नियम प्रायः सभी वस्तुओं में लागू होता है तथा इनके सम्बन्ध से प्राप्त माँग-वक्र अधोमुखी होता है। यह वक्र बायें से दायें नीचे की तरफ ढलता है।

पूर्ति—कीमत-निर्धारण की दूसरी शक्ति वस्तु की पूर्ति होती है। वस्तु की वह मात्रा जो दी हुई कीमतों पर विशिष्ट समय एवं बाजार में वित्रय हेतु उपलब्ध होती है पूर्ति कहलाती है। पूर्ति और कीमत के सम्बन्ध के विवेचन को पूर्ति का नियम कहते हैं। पूर्ति के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है तथा कीमत के कम होने पर पूर्ति की मात्रा कम हो जाती है। वस्तु की कीमत एवं पूर्ति में सामान्यतः घनात्मक सम्बन्ध होता है। पूर्ति और कीमत के सम्बन्ध से प्राप्त वक्र पूर्ति-वक्र कहलाता है जो बायें से दायें ऊपर की तरफ बढ़ता है।

माँग व पूर्ति के द्वारा कीमत-निर्धारण का सिद्धान्त—कीमत निर्धारण के लिए समय-समय पर प्रतिपादित विभिन्न सिद्धान्तों—उत्पादन-लागत का सिद्धान्त, धर्म का सिद्धान्त, सीमान्त उपयोगिता का सिद्धान्त, मार्शल का सिद्धान्त—में से प्रो० मार्शल के सिद्धान्त का वर्तमान में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। प्रो० मार्शल द्वारा प्रतिपादित कीमत-निर्धारण का सिद्धान्त माँग व पूर्ति का सिद्धान्त कहलाता है क्योंकि उसके अनुसार वस्तुओं की कीमतें माँग एवं पूर्ति नामक शक्तियों पर समान रूप से निर्भर होती हैं। माँग पर सीमान्त उपयोगिता एवं पूर्ति पर वस्तु की उत्पादन-लागत का प्रभाव पड़ता है। प्रो० मार्शल के इस सिद्धान्त को कीमत-निर्धारण का आधुनिक सिद्धान्त भी कहते हैं, क्योंकि यह सिद्धान्त वैज्ञानिक, पूर्ण एवं सर्वमान्य होने के कारण सर्वाधिक प्रचलित है।

प्रो० मार्शल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की कीमतें, उनकी माँग एवं पूर्ति की शक्तियों के पारस्परिक प्रभाव अथवा दोनों शक्तियों के सन्तुलन-बिन्दु पर निर्धारित होती हैं। वस्तुओं की माँग के आधार पर वस्तुओं की अधिकतम-कीमत नियत होती है और क्रेता (उपभोक्ता) इस अधिकतम-नियत कीमत से कम कीमत पर वस्तु प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इसके विपरीत वस्तुओं के विक्रेता (वृषक) वस्तुओं की उत्पादन लागत के आधार पर वस्तुओं के विक्रय की न्यूनतम कीमत नियत करते हैं तथा वस्तुओं के विक्रय से वे न्यूनतम-नियत कीमत से अधिक कीमत प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। वस्तुओं की कीमत इन्हीं दोनों सीमाओं—अधिकतम एवं न्यूनतम कीमतों के मध्य निर्धारित होती है। क्रेतों का वस्तुओं के क्रय करने के लिए अधिक उत्सुक होने पर कीमतें अधिकतम-कीमत के समीप तथा विक्रेताओं द्वारा वस्तुओं के विक्रय करने को अधिक उत्सुक होने पर कीमतें न्यूनतम-कीमत के समीप निर्धारित होती हैं। इस प्रकार क्रेतों एवं विक्रेताओं की प्रतिस्पर्धा से कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहता है। अन्त में कीमतें माँग एवं पूर्ति के सन्तुलन-बिन्दु अर्थात् दोनों के समान स्तर पर होने पर निर्धारित होती

हैं। माँग एवं पूर्ति के सन्तुलन स्तर पर होने वाली कीमत वस्तु की सन्तुलन-कीमत कहलाती है।

कीमत-निर्धारण के सिद्धान्त की स्पष्टता के लिए माँग एवं पूर्ति अनुगूची तथा माँग एवं पूर्ति-वक्र का अध्ययन आवश्यक है। सारणी 18 1 मण्डी में विभिन्न कीमतों पर गेहूँ की माँग एवं पूर्ति की मात्रा प्रदर्शित करती है।

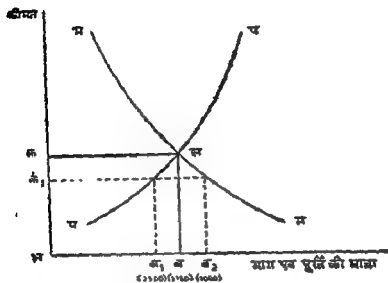
सारणी 18 1

गेहूँ की माँग एवं पूर्ति अनुगूची

मण्डी में गेहूँ की कीमत (रु० प्रति क्विन्टल)	गेहूँ की माँग (लाख क्विन्टल में)	गेहूँ की पूर्ति (लाख क्विन्टल में)
325	2000	3500
315	2200	3400
305	2500	3100
295	2750	2750
285	3000	2500
275	3300	2200

स्पष्ट है कि मण्डी में गेहूँ की कीमत 295 रु० प्रति क्विन्टल होने पर माँग एवं पूर्ति की मात्रा में साम्यावस्था होती है। अतः कीमत-निर्धारण के सिद्धान्त के अनुसार प्रतिस्पर्धा की अवस्था में मण्डी में गेहूँ की 295 रु० प्रति क्विन्टल कीमत निर्धारित होती है। सन्तुलन-कीमत 295 रु० प्रति क्विन्टल होने की स्थिति में मण्डी में विक्रय के लिए उपलब्ध गेहूँ की पूर्ण मात्रा का विक्रय एवं मण्डी में आये सभी क्रेताओं की माँग पूरी हो जाती है। मण्डी में गेहूँ की 295 रु० प्रति क्विन्टल के अतिरिक्त अन्य सभी कीमतों पर सन्तुलन स्थापित नहीं हो पाता है। सन्तुलन-कीमत से ऊपर कीमत होने पर, उसकी माँग की मात्रा कम होती जाती है, लेकिन पूर्ति की मात्रा बढ़ती जाती है। इसके विपरीत गेहूँ की मण्डी में कीमत 295 रु० प्रति क्विन्टल से कम होने पर माँग की मात्रा में वृद्धि होती है, लेकिन पूर्ति की मात्रा कम होती जाती है। अतः मण्डी में गेहूँ की कीमत, सन्तुलन-कीमत से ऊपर अथवा नीचे होने की दोनों ही अवस्थाओं में सन्तुलन स्तर बिगड़ जाता है। माँग एवं पूर्ति की मात्रा में सन्तुलन बिगड़ जाने पर मण्डी में आये सभी क्रेताओं की आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं हो पाती हैं अथवा विक्रेताओं द्वारा विक्रय करने हेतु लायी गयी गेहूँ की पूर्ण मात्रा विक्रय नहीं होती है। फलस्वरूप कीमतों में पुनः वृद्धि अथवा कमी होने की प्रारम्भ हो जाती है, जो कीमतों में सन्तुलन स्थापित होने तक होती रहती है। कीमतें माँग एवं पूर्ति से सन्तुलन स्तर पर आकर स्थिर हो जाती हैं।

मांग एवं पूर्ति वक्र द्वारा गेहूँ की कीमत-निर्धारण के सिद्धान्त को चित्र 18.1 में दर्शाया गया है।



चित्र 18.1 मांग एवं पूर्ति-वक्र द्वारा कीमत-निर्धारण

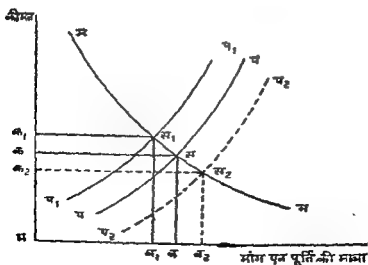
चित्र में मांग वक्र (म म) पूर्ति-वक्र (प प) को स बिन्दु पर काटती है। अर्थात् स बिन्दु मांग एवं पूर्ति का सन्तुलन-बिन्दु है। यह सन्तुलन 'क' कीमत स्तर (295 रु प्रति क्विन्टल) पर होता है। इस कीमत पर गेहूँ की अ व मात्रा (2750 क्विन्टल) का क्रय विक्रय होता है। गेहूँ की कीमत सन्तुलन कीमत 'क' से ऊपर अथवा नीचे होने पर मांग एवं पूर्ति का सन्तुलन स्तर बिगड़ जाता है। गेहूँ की कीमत 295 रु प्रति क्विन्टल अर्थात् 'क' कीमत से कम होने से बाजार में गेहूँ की मांग में वृद्धि होती है, लेकिन पूर्ति कम हो जाती है। उपर्युक्त चित्र में 295 रु प्रति क्विन्टल अर्थात् 'क' स्तर से कम कीमत होने पर गेहूँ की मांग अथवा मात्रा (3000 क्विन्टल) तथा पूर्ति अथवा मात्रा (2500 क्विन्टल) होती है। इस कीमत पर मण्डी में गेहूँ की मांग पूर्ति की अपेक्षा अधिक होती है। सभी उपभोक्ताओं को इस कीमत पर आवश्यक मात्रा में गेहूँ उपलब्ध नहीं होता है। अतः उपभोक्ता अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए गेहूँ की कीमत अधिक देने को तैयार होते हैं, जिससे गेहूँ की कीमत में वृद्धि होनी शुरू होती है। कीमत में यह वृद्धि तब तक होती रहती है जब तक मांग एवं पूर्ति में सन्तुलन स्थापित नहीं हो जाता है अर्थात् सभी

उपभोक्ताओं को आवश्यक मात्रा में गेहूँ उपलब्ध नहीं हो जाता है। इसके विपरीत गेहूँ की कीमत 295 रु प्रति बिन्टल अर्थात् 'क' स्तर से ऊपर बढ़ने पर गेहूँ की कुल मांग की मात्रा कम हो जाती है और पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है। इस कीमत पर विक्रेताओं द्वारा लायी गयी गेहूँ की पूर्ण मात्रा विन्य नहीं हो पाती है। बढी हुई कीमत पर सभी विक्रेता गेहूँ विक्रय करना चाहते हैं। प्रतिस्पर्धा के कारण विक्रेता कीमत कम करते हैं और कीमत उस स्तर तक गिरती है जब तक सभी विक्रेताओं द्वारा लाया गया गेहूँ विन्य नहीं हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि गेहूँ की कीमत 'क' स्तर से ऊपर अथवा नीचे होने की दोनों ही अवस्थाओं में मांग एवं पूर्ति में सन्तुलन स्थापित नहीं हो पाता है।

कृषि-वस्तुओं की पूर्ति में कमी अथवा वृद्धि का कीमतों पर प्रभाव

कृषि-वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति में अनेक कारणों से निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं। कृषि-वस्तुओं की पूर्ति में परिवर्तन मांग की अपेक्षा अधिक होते हैं। उनकी मांग की मात्रा प्रायः स्थिर रहती है लेकिन पूर्ति की मात्रा मुख्यतया मौसम की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता पर निर्भर करती है। अतः मांग-वक्र के समान स्थिति में रहने तथा पूर्ति में हुए परिवर्तन (वृद्धि अथवा कमी) के कारण कृषि वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होता है। कृषि-वस्तुओं के मांग वक्र के समान स्थिति में होने तथा उनकी पूर्ति में परिवर्तन (कमी एवं वृद्धि) से उनकी कीमतों पर आने वाले प्रभाव को चित्र 18.2 में दर्शाया गया है।

चित्र में म म कृषि-वस्तुओं का स्थिर मांग-वक्र एवं प प पूर्ति-वक्र हैं।



चित्र 18.2 कृषि-वस्तुओं की पूर्ति में होने वाले परिवर्तन का कीमतों पर प्रभाव

वस्तुओं की पूर्ति के कम होने से नया पूर्ति-वक्र (p_1, p_2) पहले वाले पूर्ति-वक्र के बायीं तरफ स्थानान्तरित हो जाता है। माग वक्र के समान स्तर पर होने तथा पूर्ति-वक्र के बायीं तरफ स्थानान्तरित हो जाने से कीमत k से k_1 हो जाती है। इस बढी हुई कीमत पर उपभोक्ताओं की मांग कम होकर a व से a_1 हो रही जाती है। अतः कृषि वस्तुओं की पूर्ति में कमी होने तथा माग के स्थिर रहने की स्थिति में उनकी कीमतों में वृद्धि होती है लेकिन विक्रय की मात्रा कम हो जाती है।

अनुकूल मौसम वाले वर्ष में कृषि वस्तुओं की पूर्ति के बढने से नया पूर्ति-वक्र (p_2, p_3) पहले वाले पूर्ति वक्र (p, p) के बाहिनी तरफ स्थानान्तरित हो जाता है। माग के समान स्तर पर होने तथा पूर्ति के बढने से कृषि वस्तुओं की कीमत k से k_2 बिन्दु तक गिर जाती है तथा उपभोक्ताओं की माग a व से a_2 हो जाती है। अतः कृषि वस्तुओं की पूर्ति के बढने तथा माग के स्थिर रहने पर कीमतें गिर जाती हैं और क्रय की मात्रा बढ़ जाती है।

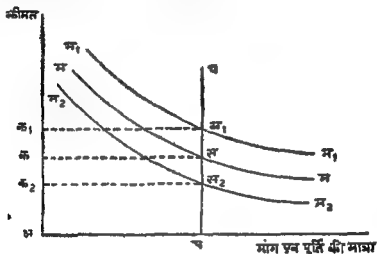
कृषि वस्तुओं की कीमतों के निर्धारण में समय का महत्त्व

कीमत निर्धारण में समय तत्त्व महत्त्वपूर्ण होता है। समय की अधिकता एवं कमी का वस्तुओं की पूर्ति की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। समय अधिक होने पर वस्तु की कीमत पर पूर्ति का प्रभाव अधिक होता है तथा समय कम होने पर माग का कीमत पर प्रभाव अधिक जाता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में समय की दृष्टि से कीमतों का विश्लेषण अति-अल्पकाल, अल्पकाल एवं दीर्घकाल में विभाजन करके किया जाता है। इन समय कालों में निर्धारित कीमतों को अति अल्पकालीन, अल्प-कालीन एवं दीर्घकालीन कीमत कहते हैं।

(1) अति अल्पकालीन कीमत—अति अल्पकालीन में तात्पर्य उस समय से है जो कुछ घण्टे या दिनों का होता है। अति अल्पकाल में वस्तुओं की पूर्ति की मात्रा उनकी बाजार में उपलब्ध मात्रा पर निर्भर करती है। अल्पकाल में वस्तुओं का उत्पादन करके पूर्ति में वृद्धि कर पाना सम्भव नहीं होता है। उत्पादक उपलब्ध मात्रा से अधिक मात्रा में वस्तुएँ नहीं बेच सकते हैं। अति अल्पकाल का समय विभिन्न वस्तुओं के लिए विभिन्न होता है जैसे—मछली एवं दूध के लिए कुछ घण्टे तथा अन्य वस्तुओं के लिए कुछ दिनों का। अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र शीघ्रनाशी वस्तुएँ (जिन्हें संगृहीत नहीं किया जा सकता) तथा नाशवान वस्तुएँ (जिन्हें कुछ समय के लिए संगृहीत करके पूर्ति की मात्रा में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है) में विभिन्न प्रकार का होता है जिसका विवेचन नीचे दिया जा रहा है—

(अ) शीघ्रनाशी कृषि वस्तुओं में अति अल्पकालीन कीमत ज्ञात करना—शीघ्रनाशी कृषि वस्तुओं की पूर्ति उस दिन या उसी समय बाजार में उपलब्ध मात्रा होती है। उपलब्ध मात्रा को बाजार में प्रचलित कीमत पर विक्रय करना होता है

क्योंकि उसे सृष्टहीन नहीं किया जा सकता है। अतः इन वस्तुओं की कीमतें प्रमुखतया उपभोक्ताओं की माग पर ही निर्भर करती है। मांग के अधिक होने पर कीमतें बढ़ जाती हैं तथा माग के कम होने पर कीमतें कम हो जाती हैं। इस अवस्था में प्राप्त सन्तुलन अस्थायी होता है, क्योंकि मविष्य में वस्तुओं की पूर्ति की मात्रा को परिवर्तित किया जा सकता है। शीघ्रनाशी कृषि-वस्तुओं में अति अल्पकालीन कीमत निर्धारण की विधि चित्र 18.3 में प्रदर्शित की गई है—

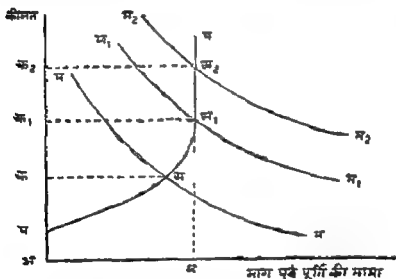


चित्र 18.3 शीघ्रनाशी कृषि-वस्तुओं में अति अल्पकालीन कीमत श्रात करना

चित्र में प-प पूर्णतया बेलोच पूर्ति-वक्र है। अति अल्पकाल में शीघ्रनाशी कृषि-वस्तुओं का पूर्ति-वक्र उदग्र/लम्बवत् तथा कीमत रेखा के समानान्तर होता है। माग-वक्र (म-म) पूर्ति-वक्र (प-प) को स बिन्दु पर काटता है और क कीमत निर्धारित होती है। इस कीमत पर वस्तुओं की माग एवं पूर्ति की मात्रा समान होती है। किन्हीं कारणों से कृषि-वस्तु की माग में वृद्धि होने से नया माग-वक्र (M_1 M_1) दाहिनी ओर स्थानान्तरित हो जाता है। बाजार में पूर्ति की मात्रा स्थिर रहती है। अतः पूर्ति की मात्रा समान रहने एवं माग में वृद्धि होने से कीमत में वृद्धि होती है और सन्तुलन K_1 कीमत स्तर पर होता है। इसके विपरीत मांग के कम होने पर नया माग-वक्र (M_2 M_2) पहले वाले माग-वक्र के बायीं तरफ स्थानान्तरित हो जाता है और कीमत कम होकर K_2 निर्धारित होती है। कीमतों में इस गिरावट का प्रमुख कारण वस्तुओं में शीघ्रनाशी होने का गुण होता है जिसके कारण कीमत कम होते हुए भी वस्तु का विक्रय करना होता है। अतः स्पष्ट है कि शीघ्रनाशी वस्तुओं में कीमतों का निर्धारण पूर्णतया माग की मात्रा पर ही निर्भर

करता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत का कीमत निर्धारण में कोई महत्त्व नहीं होता है।

(ब) नाशवान कृषि-वस्तुओं में प्रति अल्पकालीन कीमतें ज्ञात करना—
नाशवान कृषि वस्तुओं में पूर्ति-वक्र पूर्णतया बेलोचदार नहीं होकर चित्र 18.4 में प्रदर्शित रूप में होता है। इन वस्तुओं को कुछ काल के लिए संचयीत किया जा सकता है, जिसके कारण उत्पादन की लागत से कम कीमत प्राप्त होने पर उत्पादक उन्हें विक्रय नहीं करते हैं। कीमतों में वृद्धि होने पर उनकी पूर्ति की मात्रा में वृद्धि संचयीत स्टॉक को विन्यस्त हेतु लाये जाने के कारण ही होती है। संचयीत स्टॉक समाप्त होने के पश्चात् पूर्ति की मात्रा स्थिर हो जाती है, जो चित्र 18.4 नीचे कीमत रेखा द्वारा प्रदर्शित है—

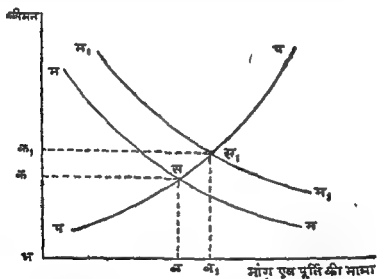


चित्र 18.4 नाशवान कृषि-वस्तुओं में प्रति अल्पकालीन कीमत ज्ञात करना

प प पूर्ति-वक्र है। वस्तु की कुल उपलब्ध मात्रा अ ब है। कृषकों की आरक्षित कीमत प है। मण्डी में इससे कम कीमत होने पर कृषक वस्तु की मात्रा को विन्यस्त नहीं करते हैं। आरक्षित कीमत प्राप्त होने के पश्चात् कीमत में वृद्धि होने के साथ-साथ वस्तु की पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होती है। मांग-वक्र म म, पूर्ति-वक्र प प को स बिन्दु पर काटता है और क कीमत निर्धारित होती है। मांग के बढ़ने पर नया मांग-वक्र म₁ म₂ पूर्ति-वक्र प प को स₁ बिन्दु पर काटता है और क₁ कीमत निर्धारित होती है। इस कीमत स्तर पर वस्तु की मण्डी में उपलब्ध पूरी मात्रा अ ब विक्रय हो जाती है। इस स्तर से आगे वस्तु की मांग के बढ़ने पर मांग-वक्र दाहिनी

और स्थानान्तरित हो जाता है। पूर्ति-वक्र लम्बवत् होने के कारण कीमत में तो वृद्धि होती है, लेकिन पूर्ति की मात्रा यथावत् अब ही रहती है। इस स्तर पर कीमत क₂ होती है। इसके विपरीत कीमत के कम होने पर वस्तु की अतिरिक्त मात्रा सृजित कर ली जाती है।

(2) अल्पकालीन कीमतें—अल्पकाल से तात्पर्य उस समय से है जिसमें वस्तुओं की पूर्ति की मात्रा में उपलब्ध उत्पादन साधनों की क्षमता तक वृद्धि की जा सकती है, लेकिन अल्पकाल में वस्तुओं के उत्पादन मापदण्ड में परिवर्तन करना सम्भव नहीं होता है। वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि सृजित वस्तुओं की मात्रा को विक्रय करके अथवा वस्तुओं को अन्य स्थानों से क्रय करके किया जा सकता है। चित्र 18.5 में कृषि-वस्तुओं की अल्पकालीन कीमत ज्ञात करने की विधि दर्शायी गई है—



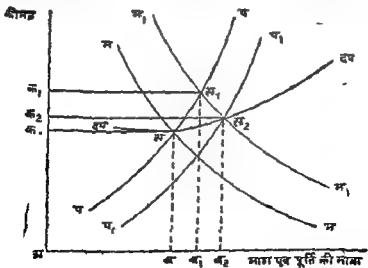
चित्र 18.5 माग एवं पूर्ति-वक्र द्वारा अल्पकालीन कीमत ज्ञात करना

प प अल्पकालीन पूर्ति-वक्र एवं म म माग-वक्र है जो एक दूसरे को स बिन्दु पर काटते हैं। इस बिन्दु पर विक्रेता वस्तु की अब मात्रा विक्रय करते हैं। क्रेताओं की माग इस बिन्दु पर अब मात्रा ही होती है। सन्तुलन स्थापित हो जाता है। किन्हीं कारणों से उपभोक्ताओं की माग में वृद्धि होने पर वस्तुओं का नया माग-वक्र (M_1 M_1) पहले वाले माग-वक्र के दाहिनी तरफ आ जाता है। अल्पकाल में वस्तुओं की पूर्ति की मात्रा अधिक बढ़ पाती है। उनको पूर्ति में वृद्धि सृजित की गई मात्रा तक ही की जा सकती है। माग में वृद्धि हो जाने के कारण क कीमत पर वस्तु का अभाव उत्पन्न हो जाता है और सन्तुलन बिन्दु स स्थान से हटकर S_1 स्थान पर पहुँच

जाता है, जो कि पहले वाले संतुलन बिन्दु से ऊपर की ओर होता है। कीमतों में क से K_1 स्तर तक वृद्धि होती है। नये संतुलन पर उत्पादक एवं उपभोक्ता श्र B_1 मात्रा का त्रय-विचय करते हैं। ठीक इसके विपरीत मांग में कमी होने पर वस्तुओं का नया मांग-वक्र वास्तविक स्थिति में बायीं ओर आ जाता है और संतुलन बिन्दु नीचे की ओर आ जाता है तथा कीमत कम हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि अल्पकालीन कीमतों में पूर्ति की अपेक्षा मांग की मात्रा से अधिक प्रभावित होती है, लेकिन मांग की मात्रा का कीमत पर प्रभाव अति अल्पकालीन कीमत के प्रभाव से कम होता है।

अल्पकाल में समय कम होने के कारण उत्पादन मापदण्ड में परिवर्तन करके पूर्ति में वृद्धि कर पाना सम्भव नहीं होता है, क्योंकि कृषि-वस्तुओं के उत्पादन का निश्चित मौसम होता है और निश्चित मौसम में भी उत्पादन करने में नियत समय लगता है जिसे कम नहीं किया जा सकता है।

(3) दीर्घकालीन कीमत सामान्य कीमत—दीर्घकाल से तात्पर्य उस समय से है जिसमें वस्तुओं के उत्पादन स्तर में परिवर्तन करके उत्पादन में वृद्धि अथवा कमी की जा सकती है। दीर्घकाल में उत्पादन सयन्त्र की विद्यमान क्षमता के उपयोग में परिवर्तन करने के साथ-साथ उत्पादकों को अपने उत्पादन के पैमाने में वृद्धि अथवा कमी करने का समय भी मिल जाता है। फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि अथवा कमी, उत्पादन वृद्धि के लिए तकनीकी ज्ञान का उपयोग आदि निर्णय लेने से पूर्ति में परिवर्तन काफी समय पश्चात् होता है। उपर्युक्त सम्भावनाओं के कारण



चित्र 18.6. मांग एवं पूर्ति-वक्र द्वारा दीर्घकालीन कीमत ज्ञात करना

दीर्घकालीन पूति-वक्र की लोच अल्पकालीन पूति-वक्र की अपेक्षा अधिक होती है। दीर्घकालीन-कीमत निर्धारण में वस्तु की मांग की अपेक्षा पूति अधिक प्रभाव डालती है। दीर्घकालीन कीमतों के निर्धारण की विधि चित्र 18.6 में दर्शायी गई है—

अल्पकालीन पूति-वक्र P P मांग वक्र M M को S बिन्दु पर काटता है, जिससे K कीमत पर सन्तुलन स्थापित होता है। किन्हीं कारणों से वस्तु की मांग में वृद्धि होने से नया मांग-वक्र M_1 M_1 पहले वाले मांग-वक्र के दाहिनी ओर आ जाता है। मांग में वृद्धि एवं पूति के उसी स्तर पर रहने से नया सन्तुलन S_1 बिन्दु पर स्थापित होता है और कीमत K से K_1 हो जाती है। उत्पादक वस्तु की मात्रा Q Q से Q_1 स्तर तक वृद्धि करते हैं जिससे उन्हें लाभ प्राप्त होता है।

समय की अधिकता के कारण व्यवसाय के स्तर में परिवर्तन तथा नये उत्पादकों के व्यवसाय में प्रवेश करने से वस्तु की पूति बढ़ जाती है और अल्पकालीन पूति-वक्र दाहिनी ओर आ जाता है। वस्तुओं की पूति की मात्रा में होने वाली वृद्धि के अनुसार पूति-वक्र दाहिनी ओर आ जाता है। इस प्रकार दीर्घकालीन पूति-वक्र P P बनता है, जो अल्पकालीन पूति-वक्र की अपेक्षा कम दस्तान वाला होता है। दीर्घकालीन पूति-वक्र P P , नये मांग वक्र M_1 M_1 को S_1 बिन्दु पर काटता है जिससे वस्तु की कीमत K_1 निर्धारित होती है। इस प्रकार दीर्घकालीन कीमत K_1 , अल्पकाल में निर्धारित कीमत K से नीचे की ओर होती है। वस्तुओं की निर्धारित दीर्घकालीन कीमत K_1 , प्रारम्भिक अल्पकालीन कीमत K से अधिक तथा अल्पकालीन कीमत K से कम अर्थात् K और K_1 के मध्य में निर्धारित होती है। दीर्घकालीन कीमत वस्तु की औसत उत्पादन लागत की राशि के समान होती है। इस कीमत पर Q Q मात्रा का उत्पादन होता है। अतः दीर्घकाल में कृषि-वस्तुओं की कीमत पर पूति का प्रभाव मांग की अपेक्षा अधिक होता है। दीर्घकाल में वस्तुओं के उत्पादन-स्तर में परिवर्तन हो पाने के कारण दीर्घकालीन कीमत, अल्पकालीन कीमत की अपेक्षा नीचे स्तर पर निर्धारित होती है।

दीर्घकालीन कीमत का उत्पादन लागत से सम्बन्ध - वस्तुओं की दीर्घकालीन कीमत एवं उनकी उत्पादन-लागत में महत्वा सम्बन्ध होता है। दीर्घकाल में वस्तुओं की प्रचलित कीमत उत्पादन-लागत से कम होने की अवस्था में उत्पादक वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा कम कर देते हैं, जिससे पूति कम हो जाती है और कीमतों का बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार वस्तुओं की मांग के अधिक होने पर, उत्पादक वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा में उस स्तर तक वृद्धि करते हैं जब तक कि उत्पादित की जाने वाली वस्तु की अतिरिक्त इकाई की उत्पादन-लागत, उसकी कीमत के समान नहीं हो जाती है। साथ ही वस्तुओं की मांग के अधिक होने पर दीर्घकाल में

नये उत्पादक भी वस्तुओं के उत्पादन हेतु क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जिससे भी उत्पादन-मात्रा में वृद्धि होती है। इन सबके फलस्वरूप कीमतों के स्तर में गिरावट होती है और अन्त में कीमतों का यह स्तर उत्पादन-लागत के समीप आ जाता है। इसके विपरीत वस्तुओं की माँग कम होने पर कीमतों में गिरावट से यदि उत्पादकों को उत्पादन-लागत (परिवर्तनशील लागत) की राशि भी पूरी प्राप्त नहीं होती है तो वे उस वस्तु का उत्पादन करना बन्द कर देते हैं। यदि उत्पादकों को वस्तुओं के विपणन में परिवर्तनशील लागत की राशि तो पूरी प्राप्त होती है, लेकिन स्थायी लागत की राशि प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसी अवस्था में उत्पादक उत्पादन की मात्रा को उस स्तर तक गिरा देते हैं, जिस स्तर पर उनकी होने वाली हानि कम से कम होती है।

दीर्घकाल में वस्तुओं की कीमतें कम होने पर उत्पादक उस व्यवसाय को बन्द कर देते हैं अथवा वस्तु का उत्पादन कम करते हैं या मशीनों एवं तकनीकी ज्ञान में परिवर्तन करके लागत कम करने के प्रयास करते हैं। उत्पादन-लागत की राशि से वस्तुओं की कीमतें अधिक होने पर नये उत्पादक व्यवसाय में प्रवेश करते हैं एवं वर्तमान में उत्पादन में लगे कृषक भी अपने उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करते हैं। ऐसा करने से उत्पादन की कुल मात्रा में वृद्धि होती है तथा कीमतों में गिरावट आती है जिससे व्यावसायिक कृषकों को प्राप्त होने वाले लाभ की राशि में कमी होती है। अतः दीर्घकाल में उत्पादन का स्तर, वस्तुओं की औसत कीमत एवं औसत उत्पादन-लागत के स्तर पर होता है, अर्थात् दीर्घकाल में सामान्य कीमतें ही प्रचलित होती हैं।

उपयुक्त तथ्यों को एक फलों के उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, ग्राम के बाग के मालिक को अपने उत्पादित आम प्रचलित कीमत पर विन्य करने होते हैं। बाजार में आम की माँग अधिक होने पर उत्पादकों को अधिक लाभ एवं माँग के कम होने पर लाभ कम अथवा हानि होती है। हानि होने अथवा लाभ कम प्राप्त होने की दोनों ही स्थितियों में उत्पादक अपने वर्तमान उत्पादन निर्णय में परिवर्तन नहीं कर सकना है। साथ ही ग्राम के अनेक उत्पादक होने के कारण, एक उत्पादक द्वारा आम विक्रय नहीं करने के निर्णय लेने से आम की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं आता है। वर्तमान में कीमत के उत्पादन-लागत से कम होने एवं भविष्य में कीमतों के बढ़ने की आशा नहीं होने की स्थिति में कृषक आम के बाग को पूर्णतया नष्ट करने का निर्णय लेता है और उस भूमि के क्षेत्र को अन्य फसलों के उत्पादन में लगाता है। इसी प्रकार यदि उसे प्रचलित कीमतों पर लाभ अधिक प्राप्त होता है तो वह आम की फसल के अन्तर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि करके एवं तकनीकी ज्ञान के उपयोग से आम के उत्पादन में वृद्धि करने का निर्णय लेता है। इस क्रिया में अन्य उत्पादक भी आम लेते हैं। नये उत्पादक आम के बाग स्थापित करते

है। इन प्रयासों के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है और कीमतें गिर जाती हैं। दीर्घकाल में पूर्ण साम्यावस्था-बिन्दु आने पर उत्पादन में वृद्धि अथवा कमी नहीं होती है।

विभिन्न उद्यमों में दीर्घावधि का समय विभिन्न होता है। यह समय खाद्यान्नों एवं दालों की फसलों में एक वर्ष, दूध उत्पादन में 4 से 5 वर्ष एवं फलों के उत्पादन में 6 से 10 वर्ष का होता है। अल्पकाल में वस्तुओं की बाजार में प्रचलित कीमत उनकी उत्पादन-लागत से कम अथवा अधिक होती है। वस्तुओं की माग अधिक होने पर अधिक कीमत तथा मांग कम होने पर कम कीमत होती है। अतः अल्पकाल में कीमतों का वस्तुओं की उत्पादन-लागत से सम्बन्ध नहीं होता है।



कृषि-कराधान

योजना-बद्ध, विकासशील अर्थ-व्यवस्था के लिए देश में सार्वजनिक कार्य, जैसे—सड़क निर्माण, बिजुत् उत्पादन एवं उसका प्रसार, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नहरों एवं बांधों का निर्माण, आधारभारिक संरचना (Infra-structures) का विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य आदि पर होने वाले व्यय की राशि में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है, जिसके कारण देश में आय के स्रोतों में वृद्धि करना आवश्यक है। आय एवं व्यय के इस अन्तर को सरकार कर लगाकर पूरा करती है। सरकार प्रतिवर्ष कुछ नये कर लगाती है एवं प्रचलित करों की दरों में संशोधन करती है। सरकार के कोष में करोड़ों द्वारा जितनी अधिक राशि एकत्रित होगी, देश में सार्वजनिक विकास कार्य उतने ही अधिक हो सकेंगे और उसी अनुपात में साधारण व्यक्ति का जीवन स्तर ऊँचा होगा। प्रत्येक देश की सरकार के पास आर्थिक प्रगति, विकास एवं अन्य सेवाओं को बनाये रखने एवं प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए कर ही प्रमुख वित्तीय स्रोत होते हैं।

कर अनिवार्य शुल्क हैं जिनका भुगतान नागरिकों द्वारा सरकार को सामान्य हित के कार्यों को करने के लिए किया जाता है। कर भुगतान के बदले में करदाता को कोई विशेष-सुविधा मिलना आवश्यक नहीं है।¹ प्रत्येक नागरिक को, जो करदाता की श्रेणी में आता है, कर का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होता है।

कराधान के अभिनियम—कराधान के प्रमुख अभिनियम निम्न होते हैं—

- (1) समानता का अभिनियम (Canon of Equity),
- (2) निश्चितता का अभिनियम (Canon of Certainty),
- (3) सुविधा का अभिनियम (Canon of Convenience),
- (4) मितव्ययिता का अभिनियम (Canon of Economy),
- (5) उत्पादकता का अभिनियम (Canon of Productivity),

1- Philip E. Taylor, The Economics of Public Finance, The Macmillan Company, New York, 1961, P. 282

- (6) लोच का अभिनियम (Canon of Elasticity),
- (7) सरलता का अभिनियम (Canon of Simplicity),
- (8) विविधता का अभिनियम (Canon of Variety) ।

उपर्युक्त प्रथम चार अभिनियम प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित किये गये थे ।

सरकार वित्तीय आवश्यकताओं के कारण नागरिकों पर विभिन्न प्रकार के कर लगानी है, जैसे भू-राजस्व आयकर, बिजली-कर, सम्पत्ति कर, मनोरंजन कर, आयात-कर, यात्री-कर आदि । इस अध्याय का प्रमुख उद्देश्य कृषि-क्षेत्र में लगने वाले करो अर्थात् कृषि-करो का विस्तृत अध्ययन करना है ।

कृषको द्वारा कृषक-उपभोक्ताओं, कृषक-सम्पत्तिधारियों आदि के रूप में कृषको द्वारा भुगतान किये जाने वाले कर, कृषि कर की श्रेणी में आते हैं । कृषि कर देश के आर्थिक विकास में निम्न प्रकार से सहायक होते हैं ।

- (i) कृषि-कर सरकार को देश के विकास कार्यक्रमों पर व्यय करने के लिए वित्त प्रदान करते हैं ।
- (ii) कृषि क्षेत्र में कर होने से, कर भुगतान राशि की प्राप्ति के लिए वस्तुओं की मात्रा के विक्रय करने से मजि में पूर्ति बढ़ जाती है जो कीमत स्थिराकरण में सहायक होती है ।
- (iii) कृषि-करो के भुगतान के लिए कृषको को आवश्यक रूप से बचत करनी होती है । इससे कृषको में बचत करने की भावना को बढ़ावा मिलता है जो अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक है ।

कृषि-करो का वर्गीकरण :

कृषि-क्षेत्र में लगाये गये करों को मुख्यतः दो वर्गों में विभक्त किया जाता है :

- (i) प्रत्यक्ष कृषि-कर—वे कर जो प्रत्येक कृषक करदाता के लिए पूंजी रूप से निर्धारित किए जाते हैं तथा उनके द्वारा ही सीधे सरकार को भुगतान किये जाते हैं, जैसे-भू-राजस्व, कृषि-आयकर, कृषि-सम्पत्ति कर, सिंचाई-कर, सुधार-लेवी आदि ।
- (ii) अप्रत्यक्ष कृषि-कर—ये कर कृषको द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय/उपयोग के लिए देय होते हैं तथा कृषको द्वारा सरकार को सीधे भुगतान नहीं किये जाते हैं । ये कर व्यापारियों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा कृषको से वसूल किये जाते हैं और वे ही सरकार को एकत्रित किये गये कर राशि का भुगतान करते हैं । अप्रत्यक्ष कृषि-करो का भार तो कृषको पर होता है, लेकिन इनके भुगतान का दायित्व कृषको पर न होकर अन्य व्यक्तियों पर होता है । अप्रत्यक्ष कृषि-करो में बिजली-कर, विद्युत-कर प्रमुख हैं ।

कृषि-क्षेत्र में लगने वाले प्रमुख प्रत्यक्ष करों का संक्षिप्त विवेचन निम्न है—

(1) भू-राजस्व :

भू-राजस्व की राशि प्रत्येक कृषक के लिए उसकी भूमि के क्षेत्र एवं किस्म के अनुसार पृथक् रूप से निर्धारित की जाती है। सरकार भू-राजस्व कृषकों से सीधे रूप में वसूल करती है। भू-राजस्व कर, कृषकों को भूमि से प्राप्त होने वाली आय के कारण देय होता है। इसके भुगतान का निम्न कार्यों से कोई सम्बन्ध नहीं होता है—

- (i) कृषकों द्वारा कृषि कार्यों को करने अथवा भूमि को अपने अधिकार में रखने।
- (ii) सरकार द्वारा कोई विशेष सेवा कृषकों को प्राप्त कराने, जैसे बाध, सड़क, नहर आदि का निर्माण।
- (iii) कृषकों द्वारा कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाने।

भू-राजस्व की विशेषताएँ—भू-राजस्व की निम्न विशेषताएँ होनी चाहिए—

1. भू-राजस्व उन कृषकों से वसूल किया जाना चाहिए, जिन्हें भूमि को कृषि करने से शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। लघु, सीमांत एवं मलाम-कर लोगों पर इसका भार नहीं पड़ना चाहिए।
2. भू-राजस्व में आरोहीपन (Progressiveness) का गुण होना चाहिए अर्थात् यह उत्पादकता से सम्बन्धित होना चाहिए।
3. भू-राजस्व में लचीलेपन का गुण होना चाहिए अर्थात् यह परिवर्तनशील आर्थिक कारकों के अनुसार परिवर्तित होना चाहिए।
4. भू-राजस्व का भार राज्य में एक-सी परिस्थितियों के कृषकों पर समान होना चाहिए।

भू-राजस्व के गुण—इसमें निम्न गुण विद्यमान हैं

1. भू-राजस्व सरकार की आय का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी राशि निश्चित होती है तथा इसकी वसूली में खर्च कम आता है।
2. भू-राजस्व फसल की कटाई के उपरान्त वसूल किया जाता है जिसके कारण यह कर कृषकों के लिए भुगतान की दृष्टि से सुविधाजनक होता है।
3. भू-राजस्व की भुगतान की जाने वाली राशि का कृषकों को पूर्ण ज्ञान पहले से ही होता है।
4. भू-राजस्व का निर्धारण भूमि की किस्म, उर्वरता आदि गुणों के मापदण्ड पर किया जाता है, जिससे अच्छी किस्म की भूमि वाले कृषकों को प्रति इकाई भूमि के क्षेत्र के लिए अधिक भू-राजस्व देना होता है।

- 5 मौसम की प्रतिकूलता के कारण फसल उत्पादन कम होने अथवा फसल के पूर्णतया नष्ट होने की स्थिति में भू-राजस्व की राशि में छूट देने अथवा उसके भुगतान को स्थगित करने का प्रावधान होता है।
- 6 भू-राजस्व में एक उत्तम कर-प्रणाली के सभी गुण, जैसे-निश्चितता, सरलता, उत्पादकता, मितव्ययिता, सुविधा आदि विद्यमान होते हैं।

भू-राजस्व में व्याप्त दोष—भू-राजस्व में व्याप्त प्रमुख दोष निम्न हैं :

- 1 भू-राजस्व एक निरपेक्ष कर है, क्योंकि भू-राजस्व की राशि एव भूमि से प्राप्त पैदावार के मूल्य में उचित सम्बन्ध नहीं होता है।
- 2 भू-राजस्व में सभी वर्गों के कृषकों पर समान भार होने के सिद्धान्त का अभाव होता है। साधारणतया भू-राजस्व का भार लघु कृषकों पर बड़े कृषकों की अपेक्षा अधिक आता है।
- 3 भू-राजस्व एक लम्बी अवधि के लिए नियत किया जाता है। कीमतों में परिवर्तन के कारण भूमि से प्राप्त उत्पाद के मूल्य में होने वाले परिवर्तन तथा भू-राजस्व की राशि में सामंजस्य नहीं होता है।
- 4 फसल की कटाई देर में होने तथा फसल विपणन से आय देर में प्राप्त होने की अवस्था में भू-राजस्व के भुगतान करने में असुविधा होती है तथा इसके समय पर भुगतान करने के लिए कृषकों को गैर-सम्पागत अभिकरणों से अधिक ब्याज-दर पर ऋण लेना होता है।
- 5 भू-राजस्व के निर्धारण का कार्य बहुत खर्चीला होता है तथा इसके निर्धारण में समय अधिक लगता है।
- 6 भू-राजस्व की राशि राज्य सरकारों द्वारा नियत की जाती है, जिसके कारण विभिन्न राज्यों में भू-राजस्व की दरों में असमानता होती है।

भू-राजस्व से प्राप्त आय :

सारणी 19.1 भारत में वर्ष 1951-52 से 1988-89 तक भू-राजस्व, कृषि-आयकर एवं कृषि-करो से प्राप्त राशि प्रदर्शित करती है।

सारणी 19 1

भारत में कृषि करो से प्राप्त राशि

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	भू-राजस्व	कृषि आय कर	कृषि क्षेत्र से प्राप्त कर	राज्यो एव केन्द्र की प्राप्त कुल कर राजस्व राशि	कृषि क्षेत्र से प्राप्त कर का कुल कर राजस्व राशि में अंशदान
1951-52	48	4	52	741	7.0
1961-62	95	9	104	1,537	6.8
1971-72	101	13	114	5,568	2.0
1975-76	230	29	259	11,155	2.3
1980-81	146	46	192	19,844	1.0
1981-82	205	38	243	24,067	1.0
1985-86	353	127	480	43,267	1.1
1986-87	382	104	486	49,540	1.0
1987-88	415	71	486	56,949	0.9
1988-89 (B E)	536	100	636	64,147	1.0

Source Basic statistics Relating to Indian Economy, vol I, All India, August 1989, Centre for monitoring Indian Economy

भारत में कर-राजस्व राशि वर्ष 1951-52 में 741 करोड़ रुपये थी, जो बढ़ कर वर्ष 1988-89 में 64,147 करोड़ रुपये हो गई। इस काल में कुल कर-राजस्व राशि में 86 गुना वृद्धि हुई है, जबकि कृषि क्षेत्र से प्राप्त करो की राशि में 12 गुना ही वृद्धि हुई है।

कृषि क्षेत्र में प्रमुखतया भू-राजस्व एवं कृषि आयकर दो प्रमुख कर हैं। भू-राजस्व की राशि वर्ष 1951-52 में 48 करोड़ रुपये थी, जो बढ़ कर वर्ष 1988-89 में 536 करोड़ रुपये अर्थात् 12 गुना वृद्धि हुई है लेकिन भू-राजस्व का कुल राजस्व में प्रतिशतता जो वर्ष 1951-52 में 6.5 थी, वह घटकर एक प्रतिशत से भी कम रह गई। इसी प्रकार कृषि आयकर की राशि में भी उपरोक्त काल में 25

गुना वृद्धि हुई है लेकिन कुल राजस्व कर में इसकी प्रतिनतता नगण्य है। अब स्पष्ट है कि उपर्युक्त अवधि में कृषि क्षेत्र से प्राप्त करो की राशि में वृद्धि की गति मन्व क्षेत्र के करो में हुई वृद्धि की अपेक्षा बहुत कम रही है।

भू-राजस्व की कुल राशि प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में 237.1 करोड़ रुपये, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 464.6 करोड़ रुपये, तृतीय पंचवर्षीय योजना में 570.3 करोड़ रुपये एवं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 539.5 करोड़ रुपये थी। भू-राजस्व की प्राप्त राशि में द्वितीय योजना-काल में प्रथम योजना की अपेक्षा 42.3 प्रतिशत की वृद्धि तृतीय योजना-काल में द्वितीय योजना की अपेक्षा 22.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भू-राजस्व की राशि में तृतीय योजना की अपेक्षा गिरावट आई है। द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में भू-राजस्व की राशि में वृद्धि वर्ष 1957-58 में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के नागन में विलय होने के कारण क्षेत्रफल में वृद्धि, जागीरदारी एवं जमींदारी-प्रदा की समाप्ति, इनाम एवं धानिक सम्पत्तियों की भूमि पर भू-राजस्व के मुग्तान में दी गई छूट की समाप्ति करन एवं अनक राज्यों में भू-राजस्व पर अधिभार लगान के कारण हुई थी। विभिन्न राज्यों में भू-राजस्व की राशि एवं करो से प्राप्त कुल राजस्व में उनके प्रतिशत अंशदान में बहुत निरता पाई जाती है। विकसित राज्यों में कुल कर-राजस्व में भू-राजस्व का प्रतिशत अंशदान कम है।

भू-राजस्व की समाप्ति के पक्ष एवं विपक्ष में दिये गये तर्क -

भू-राजस्व की समाप्ति के पक्ष एवं विपक्ष में विभिन्न अर्थशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकों ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न तर्क दिए हैं। उनमें से प्रमुख तर्क निम्न हैं—

भू-राजस्व की समाप्ति के पक्ष में दिये गये तर्क

1. भू-राजस्व एक निम्नपन्न कर है क्योंकि इसका भूमि से प्राप्त उत्पाद के मूल्य में कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता है।
2. भू-राजस्व का भार विभिन्न राज्यों के कृषकों पर समान नहीं है।
3. भू-राजस्व का भार विभिन्न जात वर्गों के कृषकों पर भी समान नहीं है। अब इसमें कराधान के समानता अनिवार्यता का पालन नहीं होता है।
4. भू-राजस्व अवराही (Regressive) होता है। अब इसमें कराधान के अवराही-अनिवार्यता का अभाव पाया जाता है।
5. भू-राजस्व के निवारण का कोई निश्चित आधार नहीं होता है।
6. भू-राजस्व वसूली के समय में छूट नहीं होता है।

भू-राजस्व की समाप्ति के विपक्ष में दिये गये तर्क :

1. भू-राजस्व राज्य सरकारों की आय का प्रमुख स्रोत है। भू-राजस्व की समाप्ति से राज्यों की आय में कमी होगी, जिससे राज्य सरकारों के पास विकास कार्यों पर व्यय करने के लिए धन की कमी से विकास की गति रुक जाएगी।
2. भू-राजस्व सरस एवं सुविधाजनक कर है। इसका भुगतान करने में कृषकों को विशेष भार महसूस नहीं होता है। भू-राजस्व का भार प्रति इकाई भूमि के क्षेत्र से प्राप्त उत्पाद के मूल्य की तुलना में नगण्य होता है। साथ ही कृषक इस कर का काफी लम्बी अवधि से भुगतान करते आ रहे हैं।
3. सरकार भू-राजस्व राशि वसूल करके भूमि पर अधिकार अस्थायी रूप से कृषकों को प्रदान करती है।
4. वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों पर सहरी क्षेत्र के नागरिकों की अपेक्षा कर का भार कम है। भू-राजस्व की समाप्ति से ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों पर करा का भार पहले से और कम हो जायेगा। अतः समाज के विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों पर कर का भार समान बनाये रखने के लिए भू-राजस्व की समाप्ति उचित नहीं है।
5. विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में विकास कार्यों के लिए कुल व्यय का काफी अधिक प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर व्यय किया गया है। जैसे—सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, भू-संरक्षण आदि कार्यों पर। अतः कृषकों से भू-राजस्व वसूल किया जाना चाहिए।
6. कृषि क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान के प्रयोग से कृषकों की आय में वृद्धि हुई है। आय के बढ़ने से उन पर भू-राजस्व का भार पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गया है। अतः बढ़ती हुई आय में से एक भाग सरकार को विकास कार्यों के लिए भू-राजस्व के रूप में मिलना चाहिए। वर्तमान में कृषक सरकार को भू-राजस्व की राशि का भुगतान खेत से प्राप्त लूंग, पाला, मूज आदि वस्तुओं को विक्रय करके ही कर पाने में सक्षम होते हैं।
7. भू-राजस्व के भुगतान दायित्व से बचना कृषकों के लिए अग्रसान नहीं है। इसका उन्हें अवश्य ही भुगतान करना होता है, जबकि वे अन्य प्रकार के करों के भुगतान से अपेक्षाकृत अधिक भुगतान से बच जाते हैं।

भू-राजस्व की समाप्ति के पक्ष एवं विपक्ष में दिये गये तर्कों से स्पष्ट है कि वर्तमान परिस्थितियों में इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसमें सुधार किया जाना चाहिए। भू-राजस्व में विद्यमान अवरोहीपन (Regressiveness) के गुण को समाप्त करके इसका लोचदार बनाने की आवश्यकता है। भू-राजस्व में सुधार के लिए निम्न सुझाव प्रेषित हैं—

1. देश की ग्रामीण विकास योजनाओं एवं हरित-क्रान्ति का मुख्य लाभ बड़े एवं सम्पन्न कृषकों को अपेक्षाकृत अधिक प्राप्त हुआ है। लघु एवं सीमान्त वर्ग के कृषकों, बड़े कृषकों के समान उत्पादन साधनों के प्रभाव में लाभान्वित नहीं हो पाये हैं। अतः बड़े एवं मध्यम जोत वाले कृषकों पर भू-राजस्व के भार में वृद्धि की जानी चाहिए तथा लघु एवं अनाधिक जोतों पर लगने वाले भू-राजस्व को स्थायी रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। ऐसा करने से राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति के साथ-साथ, लघु कृषकों की देश में बहुलता होने के कारण भू-राजस्व की वसूली की लागत में भी कमी होगी। इस नीति से सरकार को प्राप्त होने वाले कुल राजस्व राशि में विशेष अन्तर नहीं आयेगा।
2. भू-राजस्व में विद्यमान अवरोहीपन के गुण को समाप्त करने के लिए इस पर बढ़ती हुई दर (50 से 200 प्रतिशत तक) से अधिभार लगाना चाहिए।
3. भू-राजस्व के भार को विभिन्न राज्यों में समान करने के लिए भू-राजस्व में आवश्यक सशोधन किये जाने चाहिये।
4. भू-राजस्व का नियतन 5 से 10 वर्षों की अवधि के लिए ही किया जाना चाहिए। तत्पश्चात् भूमि की उत्पादकता, कीमती एवं उत्पादन-लागत में परिवर्तन के अनुसार भू-राजस्व में परिवर्तन किया जाना चाहिए। इस प्रकार भू-राजस्व से प्राप्त आय की राशि में वृद्धि होगी एवं इसमें लोचपन का गुण आयेगा।
5. वाणिज्यिक फसलों से छायाओं की अपेक्षा प्रति इकाई भूमि के क्षेत्र से अधिक लाभ प्राप्त होता है। अतः वाणिज्यिक फसलों पर भू-राजस्व के अतिरिक्त विशेष कर भी लगाया जाना चाहिए।

(2) कृषि आयकर .

कृषि-क्षेत्र में दूसरा प्रमुख प्रत्यक्ष कर कृषि-आयकर है। यह कर कृषकों की कृषि-व्यवसाय से प्राप्त आय पर देय होता है। कृषि आय से तात्पर्य उस आय से है जो कृषकों को भूमि पर उत्पादित कृषि-उत्पादों से प्राप्त होती है। कृषि-आयकर

कृषको को वर्ष में प्राप्त शुद्ध कृषि आय पर देय होता है। कृषको को एक वर्ष में प्राप्त समग्र आय की राशि में से कानून के अन्तर्गत दी जाने वाली अनुमेय कटौतियों को निकासने पर जो आय शेष रहती है, वह उनकी शुद्ध कर-योग्य आय कहलाती है। कृषि-आयकर कानून के अन्तर्गत दी जाने वाली कटौतियों में प्रमुख अनुमेय कटौतियाँ निम्न हैं—

- (i) भू राजस्व, जगान, सिंचाई कर आदि की देय राशियाँ।
- (ii) कृषि कार्यों के लिए प्राप्त ऋण पर दिये गये व्याज की राशि।
- (iii) सिंचाई के साधनों एवं अन्य कार्यों पर की गई मरम्मत की लागत।
- (iv) कृषि सम्पदा—मवन, पशुआला, सग्रहघर, ट्रैक्टर एवं अन्य मशीनों की घिसावट एवं मूल्य ह्रास लागत।
- (v) मशीनों एवं औजारों के अप्रयोज्य (Obsolete) होने से सम्भाव्य मूल्य ह्रास की राशि।
- (vi) कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त उत्पादन साधनों, जैसे—बीज, खाद, उर्वरक, श्रम आदि की लागत।
- (vii) कृषि बीमा की भुगतान किश्त की राशि।
- (viii) कृषि उत्पादन एवं विपणन पर सरकार को दिए गये करों की राशि।
- (ix) अन्य कटौतियाँ जैसे—धार्मिक संस्थाओं को दी गई सहायता, अनुसंधान पर किया गया व्यय आदि।

भारत में सर्वप्रथम आयकर ब्रिटिश शासन-काल में वर्ष 1860 में लागू किया गया था। इसमें कृषि स्रोत से प्राप्त आय भी आयकर में सम्मिलित थी। आयकर कानून, 1886 में कृषि क्षेत्र से प्राप्त आय को आयकर कानून से मुक्त कर दिया गया। कृषि-आय पर यह छूट वर्ष 1935 तक बनी रही। देश में कृषि आय वर्ष 1935 के पूर्व (1860 से 1865 एवं 1869 से 1873 के नौ वर्षों के अतिरिक्त) आयकर से मुक्त रही थी। वर्ष 1935 में भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र से प्राप्त आय पर आयकर लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया, जिसे भारतीय संविधान ने 1950 में अपना लिया। भारतीय संविधान में कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों पर आयकर लगाने का अधिकार केन्द्र सरकार का एवं कृषि क्षेत्र से प्राप्त आय पर आयकर लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को प्राप्त है। वर्ष 1935 के उपरान्त अनेक राज्यों में कृषि आयकर लागू करके कुछ समय परचाढ़ समाप्त कर दिया तथा अनेक राज्यों ने लागू ही नहीं किया। अतः कृषि आयकर के होने तथा नहीं होने की दृष्टि से विभिन्न राज्यों को निम्न तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है—

(i) वे राज्य, जहाँ कृषि आय पर वर्तमान में कृषि-आयकर लागू है :

इस श्रेणी में बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश राज्य हैं। इन राज्यों में सर्वप्रथम बिहार राज्य ने 1938, असम ने 1939, उड़ीसा ने 1947, केरल ने 1949, मध्यप्रदेश ने 1952 एवं तमिलनाडु व कर्नाटक ने 1955 में कृषि-आयकर लागू करने के कानून पारित किये। इन राज्यों में आयकर लगाने की विधि एवं उसमें दी जाने वाली छूट में बहुत भिन्नता है। दक्षिण क्षेत्र के राज्यों में कृषि-आयकर प्रमुखतया बागान वाली फसलों पर लगाया गया है।

(ii) वे राज्य, जहाँ कृषि-आयकर कुछ समय के लिए लागू हुआ, लेकिन बाद में समाप्त कर दिया गया :

इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश, आन्ध्रप्रदेश एवं राजस्थान राज्य आते हैं। उत्तर-प्रदेश राज्य में 1948 में आयकर लागू किया गया था, जिसे 1957 में दीर्घ भूमि फ़ोट कर द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। हैदराबाद में लागू कृषि-आयकर को 1956 में राज्य का पुनर्गठन होने पर आन्ध्रप्रदेश सरकार ने भू-राजस्व (अधिनियम) कानून द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया। राजस्थान राज्य ने अप्रैल, 1966 से कृषि-आयकर समाप्त कर दिया तथा राज्य में यह कर लगान पर अधिनियम के रूप में वसूल किया जाता है।

(iii) वे राज्य, जहाँ अभी तक कृषि-आयकर लागू नहीं किया गया है :

इस श्रेणी में पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्यप्रदेश (मोपल एवं विन्ध्य-प्रदेश के प्रतिरिक्त), हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय एवं नागालैंड राज्य हैं। पंजाब एवं हरियाणा राज्य की सरकारें कृषि-आयकर लगाने के पक्ष में नहीं हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि देश का 55 प्रतिशत कृषि-क्षेत्र कृषि-आयकर से मुक्त है।² विभिन्न राज्यों में कृषि आय पर दी गई छूट की विषमता के साथ-साथ, राज्यों में कृषि-आयकर की दरों में भी बहुत भिन्नता पायी जाती है, जिसके कारण विभिन्न राज्यों में कृषि-आयकर का भार भिन्न-भिन्न है।

कृषि-आयकर से प्राप्त आय—कृषि-आयकर से देश को वर्ष 1951-52 में 43 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई थी। यह आय बढ़कर 1978-79 में 8036 करोड़ रुपये हो गई (सारणी 19.1)। वर्ष 1951-52 की अपेक्षा 1988-89 में कृषि-आयकर की राशि में 25 गुना वृद्धि हुई है, लेकिन देश के कुल कर-राजस्व की राशि में कृषि-आयकर के प्रतिशत अंश में उपर्युक्त काल में बिराबट आई है।

सारणी 19.2

विभिन्न वर्षों में कृषि धायकर से राजस्व प्राप्त आय की रक्ति

(करोड रुपयो में)

राज्य	1950-51	1960-61	1966-67	1972-73	1978-79	1979-80	1980-81
आन्ध्रप्रदेश	—	0 03	—	—	—	—	—
असम	0 79	2 75	4 84	3 11	35 04	17 53	17 00
बिहार	0 69	0 51	0 30	0 44	0 08	—	0 01
केरल	0 50	2 35	2 40	3 52	11 14	10 57	11 50
कर्नाटक	—	0 74	1 33	1 95	14 37	15 60	11 00
महाराष्ट्र	—	—	0 40	0 38	0 50	0 45	0 35
उड़ीसा	0 10	0 04	0 05	—	0 01	0 02	—
राजस्थान	—	0 03	0 01	—	—	—	—
तमिलनाडु	—	1 35	1 26	1 95	10 32	6 82	5 98
उत्तरप्रदेश	1 38	0 83	0 22	0 08	—	—	—
पश्चिमी बंगाल	0 63	0 85	0 77	0 98	8.81	7 28	4 25
त्रिपुरा	—	—	—	—	0 09	0 08	0 04
भारत में कुल	4 09	9 48	11 58	12 41	80 36	58 35	50 13
कृषि-धायकर							

स्रोत : Reserve Bank of India Bulletins—Various Issues

हथि-आयकर से प्राप्त आय को राजि ने विभिन्न वृद्धि नहीं होने के प्रमुख कारण निम्न हैं—

- (i) प्रत्येक राज्यों में हथि-आय पर दो गटे दूट को सीना की अनिवार्यता के कारण, अविक्रय हथि आयकर मुग्तान की श्रेणी में नहीं आते हैं, जैन-महाराष्ट्र में 36,000 रु. वार्षिक आय, मध्यम बगान में 100 नानक बीना तक हथि नूनि, कनाटक में 100 एकड़ जंगल क्षेत्रों की नूनि या उससे कम नूनि अन्य श्रेणी की नूनि का क्षेत्र, मध्यप्रदेश के सीमांत एवं विन्ध्यप्रदेश में 50 एकड़ तक टुकट्टर द्वारा हथि नूनि अथवा 100 एकड़ तक अन्य प्रकार से हथि नूनि, हथि-आयकर से मुक्त हैं।
- (ii) जनोदधार एवं आर्थोदधार प्रथा की अनुमति, नूनीना नियतन आदि के कारण, बड़ी हथि जाते छोटी जातों में विभक्त हो गई हैं, जिसके कारण नई आयकर मुग्तान की श्रेणी में आने वाले हथि की संख्या कम हो गई है।
- (iii) हथि-उत्पादन का प्रवृत्ति पर निर्भरता के कारण, हथि की आय में अनिश्चितता बनी रहती है, जिससे नई आयकर की राजि कम प्राप्त होती है।
- (iv) अविक्रय हथि हथि-व्यवसाय का नेत्रा-श्रोत्रा नहीं रखते हैं बल्कि हथि से प्राप्त आय के नहीं आकर उभयव्य नहीं होते हैं और नए हथि आय-कर मुग्तान से बच जाते हैं।
- (v) हथि-आयकर की समुदाय में राजनैतिक हस्तक्षेप भी एक बाधा है।

विभिन्न राज्यों में हथि-आयकर से प्राप्त आय की राजि में बहुत भिन्नता है। असम, केरल, कनाटक एवं तमिलनाडु राज्यों में हथि-आयकर से प्राप्त आय की राजि में हथि-आयकर से प्राप्त कुल आय के 80 प्रतिशत से अधिक है। इन राज्यों में हथि आयकर से अधिक आय की राजि का प्रमुख कारण बागान बानी फलों के प्रसंग अथवा क्षेत्रफल का होना है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल-प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड राज्यों में हथि आय पर आयकर नहीं लगाया गया है। मध्यप्रदेश में हथि-आयकर की अनुमति के कारण वर्ष 1972-73 में बार्ड प्राप्त नहीं हो रही है।

हथि-आयकर के पक्ष एवं विपक्ष में दिये गये तर्क -

हथि-आयकर एक वाद विवाद का प्रश्न बना हुआ है जिसके पक्ष एवं विपक्ष में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। हथि-आयकर के पक्ष में दिए जाने वाले प्रमुख तर्क प्रस्तुत हैं—

- (1) शहरी क्षेत्र के निवासी ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों की अपेक्षा प्रति व्यक्ति अधिक कर-राशि का भुगतान कर रहे हैं। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद्³ के अध्ययन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र से 5 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र से 22 प्रतिशत कर प्राप्त होता है। अतः कर में भार की भेद भाव की समाप्ति के लिए कृषि क्षेत्र में प्राप्त आय पर आयकर होना आवश्यक है।
- (2) सरकार द्वारा ग्रामीण विकास-कार्यक्रमों पर अधिक राशि में धन व्यय करने के कारण कृषि-क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों की आय में निरन्तर वृद्धि हुई है। अतः कृषकों की बढ़ती हुई आय पर, आयकर का होना अनिवार्य है, अन्यथा बढ़ती हुई आय देश में मुद्रास्फीति उत्पन्न करने में सहायक होगी।
- (3) वर्तमान में कृषि-क्षेत्र में भू-राजस्व के अतिरिक्त अन्य कोई प्रत्यक्ष कर नहीं है। भू-राजस्व अवरोही कर है जिसका भार बड़े कृषकों की अपेक्षा लघु कृषकों पर अधिक आता है। अतः बड़े एवं लघु कृषकों की आय में व्याप्त असमानता का समाप्त करने एवं करोड़ों भार में समानता बनाये रखने के लिए बड़ी जोत वाले कृषकों पर कृषि-आयकर का होना आवश्यक है।
- (4) देश के सचिवान में ग्रामीण एवं शहरी-व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त है। अतः कर भार में पाये जाने वाले भेदभाव की नीति की समाप्ति के लिए कृषि आयकर का लगाया जाना आवश्यक है।

कृषि-आयकर की समाप्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिये गये तर्क निम्न हैं—

- (1) भू-राजस्व के साथ-साथ कृषि आय पर आयकर के होने से कृषकों को भूमि से प्राप्त आय पर दो करो का भुगतान करना होता है। कृषक भू-राजस्व बहुत पहले से देते आ रहे हैं। अतः कृषि-आय पर जो भूमि से ही प्राप्त होती है, आयकर का होना उचित नहीं है।
- (2) कृषि-क्षेत्र से प्राप्त आय पर आयकर होने से कृषकों को उत्पादन बढ़ाने की पर्याप्त प्रेरणा नहीं मिलती है।
- (3) देश के अधिकांश कृषक लघु जोत वाले एवं गरीब हैं तथा वे कृषि-व्यवसाय से प्राप्त आय एवं उसमें होने वाली लागत का लेखा-जोखा नहीं रखते हैं। अतः कृषि-आयकर के निर्धारण में सरकार को अनेक

परेशानियों का सामना करना होगा एवं अनेक कृषकों को भी अनावश्यक रूप में परेशान होना पड़ेगा।

(4) कृषि-आयकर के होने से सरकार की प्रशासनिक कठिनाइयाँ एवं व्यय की राशि में वृद्धि होगी।

कृषि-आयकर के पक्ष एवं विपक्ष में दिये गये तर्कों के आधार पर कहा जा सकता है कि कृषि-आयकर लगाये जाने के पक्ष में दिये गये तर्क अधिक सुदृढ़ हैं। अन्न कृषि क्षेत्र से प्राप्त आय पर आय कर होना चाहिये, लेकिन आयकर लगाने की विधि से राजस्व-राशि अधिक प्राप्त करने के लिये आवश्यक समीक्षण किये जाने चाहिये। कृषि आय पर आयकर लगाने के लिये समय-समय पर अनेक समितियों एवं व्यक्तियों ने सुझाव दिये हैं। उनमें से प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं—

- 1 जिन राज्यों ने कृषि आयकर लागू नहीं किया है, उन राज्यों द्वारा भी कृषि-आयकर लगाया जाना चाहिये।
- 2 सभी राज्यों में कृषि आयकर की दरों में समानता होनी चाहिये।
- 3 साधारण आयकर एवं कृषि-आयकर के लिये दी जाने वाली छूट की राशि में समानता होनी चाहिये, जिससे नागरिक एक क्षेत्र से प्राप्त आय को दूसरे क्षेत्र से प्राप्त आय में प्रदर्शित करके आयकर भुगतान में बच नहीं पाये।
- 4 कृषि-आयकर, कृषकों की समग्र आय के स्थान पर शुद्ध आय के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिये।
- 5 कृषि-आयकर, साधारण आयकर के समान प्रगामी दर से होना चाहिये।
- 6 कृषि-आयकर की दर में आवश्यकतानुसार समय-समय पर परिवर्तन किये जाने चाहिये, जिससे देश के विकास के लिये आवश्यक वित्त जुटाया जा सके।

कृषि-आयकर के लिए नियुक्त राज-समिति—प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल से ही सरकार का ध्यान कृषि-क्षेत्र से प्राप्त आय पर आयकर लगाने की ओर आकर्षित हुआ था। सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियों ने भी कृषि आय पर आयकर लगाने का सुझाव दिया था। डॉ० जान मयाई की अध्यक्षता में नियुक्त कराधान, जाँच आयोग, 1953-54 ने कृषि-आयकर लगाने का सुझाव दिया था। अनेक राज्य सरकारों ने कृषि-आयकर लगाने के लिये कानून पारित किये और उन्हें क्रियान्वित किया। न्यायाधीश श्री के. एन. वांचू ने 21 मार्च, 1972 को आय कर व कानून की समस्या-सम्बन्धी रिपोर्ट में कृषि आय पर केन्द्रीय सरकार के आयकर कानून को लागू करने का सुझाव दिया था। कृषि केन्द्रीय विषय-सूची में न

होकर राज्यों की विषय-सूची में होने की सर्वैधानिक अड़चन के कारण आयकर लगाने का उपयुक्त सुझाव कार्यान्वित नहीं हो सका। कृषि-आय पर कर लगाने की बढ़ती हुई आवश्यकता तथा अर्थशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकों के विचारों में मतभेद होने के कारण सरकार ने 24 फरवरी, 1972 को कृषि-सम्पत्ति व आय पर कर लगाने के लिए आवश्यक सुझाव देने हेतु एक समिति डॉ॰ के.एन. राज की अध्यक्षता में नियुक्त की। राज-समिति नियुक्त करने के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे—

- (i) कृषि-आय एवं सम्पत्ति पर कर लगाने की विधि का सुझाव देना, जिससे देश के विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त धन जुटाया जा सके।
- (ii) देश में व्याप्त अर्थिक असमानता को कम करना एवं उत्पादन-साधनों का वक्षतापूर्ण उपयोग करने के लिए सुझाव देना।

राज-समिति ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1972 को वित्त मन्त्रालय को प्रस्तुत की। राज-समिति ने कृषि आय पर कर लगाने में आने वाली सभी प्रशासनिक एवं सर्वैधानिक समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए कृषि आय पर कर लगाने के लिए निम्न सिफारिशों की हैं—

- (1) जिन कृषकों के यहाँ कृषि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आय नहीं है, उनके यहाँ भू-राजस्व के स्थान पर कृषि जोतकर (Agricultural Holding Tax) लागू किया जाना चाहिए।
- (2) जिन कृषकों के यहाँ कृषि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी आय प्राप्त होती है, उनके यहाँ कृषि से प्राप्त आय को कृषि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त आय में सम्मिलित करके आयकर की दर निर्धारित की जानी चाहिए। प्रस्तावित आयकर की दर से आयकर कृषि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त आय पर ही वसूल किया जाना चाहिए।
- (3) पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गीपालन एवं दुग्ध उत्पादन से प्राप्त आय पर कर लगाना चाहिए।
- (4) कृषि-सम्पत्ति को अन्य सम्पत्ति में सम्मिलित करके समन्वित सम्पत्ति पर प्रारम्भ किया जाना चाहिए।
- (5) कृषि-भूमि के विक्रय से प्राप्त लाभ की राशि को सम्पत्ति लाभ की श्रेणी में मानते हुए उस पर कर लगाना चाहिए।

उपयुक्त सिफारिशों का विवरण नीचे दिया गया है—

(1) कृषि-जोतकर—राज-समिति की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा कृषि जोत के आकार तथा उत्पादन के अनुसार “कृषि-जोत कर” लागू किया

जाना चाहिए। कृषि जोत कर भू-राजस्व पद्धति की एक मुश्किल हुई विधि है, जिसके अन्तर्गत भूमि के क्षेत्रफल के साथ-साथ भूमि की उत्पादकता एवं प्राप्त उत्पाद की कीमतों को भी दृष्टिगत रखा जाता है। समिति ने कृषि-जोत कर निर्धारण करने के लिए "अखिल भारतीय कृषि-जोत कर स्थायी समिति" स्थापित करने की सिफारिश की थी। समिति के अनुसार 5000 रु० या इसमें अधिक कर योग्य आय की सभी जोतों पर भू-राजस्व के स्थान पर कृषि-जोत कर लगाने से 200 करोड़ रु० प्रति वर्ष की आय प्राप्त होगी, जबकि वर्तमान में भू-राजस्व से 50 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होती है। इसी प्रकार 2500 रुपये तक की कर योग्य आय की जोत पर कृषि-जोत कर लागू करने से 150 करोड़ रुपये की प्रतिरिक्त आय प्राप्त होगी।

कृषि-जोत कर के निर्धारण की विधि—कृषि-जोत कर के निर्धारण की विधि निम्न है—

- (1) समिति ने कृषि-जोत कर कृषकों की कृषि जोत के आधार पर लागू करने का सुझाव दिया है। कृषि जोत ज्ञात करने का सूत्र निम्न है :

$$\text{कृषि जोत} = \frac{\text{स्वयं के स्वामित्व में दूसरे कृषकों से कृषि करने के लिए प्राप्त बंटाई पर दिया गया भूमि क्षेत्र}}{\text{दूसरे कृषकों का भूमि क्षेत्र}}$$
- (2) समिति ने कर-निर्धारण वर्ष एक जुलाई से 30 जून तक रखन का अनुमोदन किया है।
- (3) समिति के अनुसार पारिवारिक इकाई में पति, पत्नी तथा नाबालिग बच्चों को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- (4) पति एवं पत्नी की सम्मिलित आय के योग की राशि पर आय-कर निर्धारण करना चाहिए।
- (5) कृषि-जोत-कर की राशि का निर्धारण करने के लिए देश की भूमि, जलवायु एवं उत्पादकता की समानता के आधार पर विभिन्न सम-जातीय जिलों या क्षेत्रों में विभक्त करना चाहिए।
- (6) विभिन्न जिलों व क्षेत्रों के लिए विभिन्न फसलों का प्रतिवर्ष प्रति हेक्टर उत्पादन की मात्रा का स्तर निर्धारित किया जाना चाहिए। उत्पादन की मात्रा का निर्धारण पिछले 10 वर्षों की औसत उत्पादकता के आधार पर ज्ञात किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, 1980-81 के लिए किसी क्षेत्र में गेहूँ का उत्पादन स्तर, उस क्षेत्र में गेहूँ के 1970-71 से 1979-80 तक के औसत उत्पादन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। औसत उत्पादन के आधार पर ज्ञात किये गये उत्पादन स्तर में मौसम की प्रतिकूलता के कारण उत्पादन स्तर

के बहुत कम प्राप्त होने वाले वर्ष में पूर्ण व आंशिक छूट देने का प्रावधान होता है।

- (7) विभिन्न फसलों से प्रति हेक्टर प्राप्त आय की राशि, औसत उत्पादन-स्तर की माना को पिछले तीन वर्षों की कटाई मौसम की औसत कीमत से गुणा करके ज्ञात किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, वर्ष 1980-81 की गेहूँ की कीमत ज्ञात करने के लिए उस क्षेत्र या जिले की 1977-78 से 1979-80 की कीमतों का औसत लिया जाता है।
- (8) विभिन्न फसलों से प्रति हेक्टर प्राप्त आय में से, फसल-उत्पादन कार्यों के लिए दी गई लागत (Paid-out-costs) एवं सम्पत्ति पर मूल्य-ह्रास की राशि को घटाकर, उस क्षेत्र के लिए उस फसल की प्रति हेक्टर कर-योग्य आय की राशि (Rateable Value) ज्ञात कर ली जाती है। राज समिति के अनुसार अतिरिक्त क्षेत्रों में उत्पादन-सागत कुल आय में 40 से 50 प्रतिशत व सिंचित क्षेत्रों में 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (9) विभिन्न फसलों के लिए प्राप्त प्रति हेक्टर कर-योग्य आय की राशि को फार्म पर विभिन्न फसलों के अन्तर्गत लिये गये क्षेत्रफल से गुणा करके फार्म की कुल कर-योग्य आय ज्ञात कर ली जाती है।
- (10) फार्म पर प्राप्त कुल कर-योग्य आय (Total Rateable Value) की राशि में से विकास-छूट (Development Allowance) की राशि घटाने से फार्म की शुद्ध कर योग्य आय ज्ञात हो जाती है। फार्म पर विकास-छूट की राशि कुल कर-योग्य आय राशि के 20 प्रतिशत की दर से ज्ञात की जाती है, लेकिन विकास-छूट की कुल राशि 1,000 रुपये प्रति फार्म से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (11) कृषि-जोत कर की प्रतिशत दर निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है—

$$\text{कृषि-जोत कर की प्रतिशत दर} = \frac{\text{फार्म की कुल कर-योग्य आय} - \text{विकास-छूट की राशि}}{\text{घाय (हजार रुपये में)}} \times 100 \quad (\text{हजार रुपये में})$$

उदाहरण के लिए यदि किसी फार्म की शुद्ध कर-योग्य आय 25,000 रु० और विकास छूट राशि 1,000 रुपये है तो उस फार्म पर कृषि-जोतकर की प्रतिशत दर $\left(\frac{25,000 - 1,000}{2} \right) = 12$ होती है।

- (12) उपर्युक्त प्रतिशत दर के अनुसार शुद्ध कर-योग्य आय पर कृषि-जोतकर की राशि ज्ञात की जाती है। फार्म पर कृषि-जोतकर की राशि, कर-योग्य आय की राशि के अनुसार बढ़ती एवं घटती है। कर योग्य आय की राशि में वृद्धि होने से कृषि-जोतकर की दर में वृद्धि एवं कर योग्य आय कम होने पर कृषि-जोतकर की दर में कमी होती है।

(2) कृषि व कृषि अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त आय को सम्मिलित करते हुए आयकर की दर निर्धारित करना

राज-समिति ने दूसरा प्रमुख सुझाव कृषि एवं कृषि अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त आय को सम्मिलित करके प्राप्त कुल आय पर लागू होने वाली आयकर की दर से कृषि अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त आय पर आयकर लगाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस प्रकार आयकर की दर निर्धारित करने से कृषि-अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त आय पर लगने वाले आयकर की दर में वृद्धि होगी और सरकार को आयकर से प्राप्त राजस्व की राशि में वृद्धि होगी। समिति ने दोनों क्षेत्रों की आय को सिर्फ आयकर की दर निर्धारित करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सम्मिलित करने का सुझाव दिया है। इस विधि से आयकर-निर्धारण करने के लिए सविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है और न ही इस प्रस्ताव से राज्य सरकारों के अधिकारों का हनन होता है, क्योंकि प्रस्ताव में केन्द्र सरकार को प्राप्त अतिरिक्त आय, सम्बन्धित राज्य सरकारों को वितरित करने का प्रावधान है।

राज-समिति का अनुमान है कि वे व्यक्ति जो कृषि क्षेत्र में आयकर नहीं होने के कारण अन्य स्रोतों से प्राप्त आय को कृषि क्षेत्र से प्राप्त आय प्रदर्शित करके आयकर भुगतान से बच जाते हैं, वे इस प्रस्ताव के लागू होने के पश्चात् आयकर की वास्तविक भुगतान राशि से बच नहीं सकेंगे और न ही एक क्षेत्र से प्राप्त आय को दूसरे क्षेत्र में दिखा सकेंगे। इस प्रकार इससे राष्ट्रीय आय के विभिन्न क्षेत्रों के सही आँकड़े प्राप्त होंगे। इस विधि के अन्तर्गत आयकर की दर ज्ञात करने की विधि इस प्रकार है—

- (i) कृषि-अतिरिक्त अन्य स्रोतों में प्राप्त आय की राशि में से छूट की सीमा की राशि (वर्तमान में 28,000 रु) घटाकर शेष राशि में कृषि-क्षेत्र से प्राप्त आय की राशि सम्मिलित की जाती है।
- (ii) दोनों स्रोतों से प्राप्त सम्मिलित राशि पर लगने वाले आयकर की दर से कृषि-अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त आय पर आयकर की राशि ज्ञात की जाती है। इस प्रकार आयकर की दर साधारण आयकर की अपेक्षा अधिक निर्धारित होती है, जिससे सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा।

वित्त मन्त्री ने वर्ष 1973-74 का वार्षिक बजट 28 फरवरी, 1973 को लोकसभा में पेश करते हुए राज-समिति द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार कृषि व कृषि-अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त आय को सम्मिलित करते हुए, आयकर की दर निर्धारण करने की विधि को स्वीकार करते हुए उसे वित्त वर्ष 1973-74 में लागू करने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया था। जिसे सदन ने स्वीकृति प्रदान कर दी थी।

(3) कृषि-सम्पत्ति कर (Agricultural Wealth Tax)

कृषि-सम्पत्ति कर से तात्पर्य कृषकों की सम्पत्ति-भूमि, पशु, भवन, मशीनों, आदि पर कर लगाने से है। कृषि-क्षेत्र में सम्पत्ति-कर लगाने का प्रमुख उद्देश्य वास्तविक कृषकों के अतिरिक्त कृषि-क्षेत्र में प्रवेश करने वाले पूँजीपतियों पर, जो कृषि-व्यवसाय में अधिक धन-निवेश करते हैं, कर लगाकर राजस्व प्राप्त करना है। पूँजीपति एवं व्यवसायी औद्योगिक क्षेत्र में सम्पत्ति कर के होने तथा कृषि-क्षेत्र में सम्पत्ति-कर के नहीं होने से कृषि-क्षेत्र में अधिक धनराशि निवेश करके सम्पत्ति-कर के भुगतान से बच जाते हैं। अतः इस प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए कृषि-क्षेत्र में सम्पत्ति-कर का होना आवश्यक है।

कृषि-क्षेत्र में सम्पत्ति-कर लगाने में परेशानियाँ :

- (1) देश के अधिकांश कृषक अनशिक्षित होने के कारण कृषि-सम्पत्ति का लेखा-जोखा नहीं रखते हैं, अतः उसके अभाव में कृषकों के लिए सम्पत्ति-कर का प्रतिवर्ष सही हिसाब प्रस्तुत करने का कार्य कठिन होता है।
- (2) कृषि-सम्पत्ति में भूमि की किस्म एवं उपजाऊ शक्ति में भिन्नता तथा भूमि एवं भवन पर बने हुए विभिन्न भवनों के मूल्यों के निर्धारण का कार्य कठिन होता है। अतः कर निर्धारण अधिकारी इच्छानुसार भूमि की कीमत निर्धारित करके कृषकों को आवश्यक रूप से परेशान करने की कोशिश करेंगे।
- (3) कृषकों की आय मौसम की अनुकूलता पर निर्भर रहती है। प्रतिकूल मौसम वाले वर्ष में कृषकों के लिए सम्पत्ति-कर का भुगतान करना सम्भव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में कृषक सम्पत्ति-कर के भुगतान के लिए सम्पत्ति का विक्रय करेंगे, जो कृषि-विकास में घातक होगा।
- (4) कृषि-सम्पत्ति-कर के द्वारा सरकार को शुद्ध आय बहुत कम प्राप्त होने की सम्भावना है क्योंकि देश में कृषकों की संख्या की अधिकता के कारण सम्पत्ति-कर के आकलन में व्यव अधिक होगा।

- (5) कृषि-क्षेत्र में सम्पत्ति-कर के होने से कृषको में उत्पादन-वृद्धि की प्रेरणा का ह्रास होगा। तकनीकी ज्ञान के उपयोग से कृषि-क्षेत्र में पूंजी-निवेश की राशि में वृद्धि होने से देय सम्पत्ति-कर की राशि में वृद्धि होती है। सम्पत्ति-कर की देय राशि में वृद्धि होने से कृषक उत्पादन-वृद्धि में अधिक इच्छुक नहीं होंगे।
- (6) कृषि-सम्पत्ति पर कर लगाने से कृषक पूंजी का निवेश कृषि-उपकरणों के स्थान पर सोना, चाँदी के जेवर, शेयर एवं अन्य सामान के रूप में करेंगे। कृषि-क्षेत्र में पूंजी-निवेश नहीं होने से कृषि-उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पायेगी।

कृषि सम्पत्ति-कर के लिए राज-समिति के सुझाव :

कृषि-सम्पत्ति-कर के लिए राज-समिति द्वारा प्रस्तावित सुझाव निम्नांकित हैं—

- (1) सम्पत्ति-कर परिवार के आधार पर नियत किया जाना चाहिए। सम्पत्ति-कर के निर्धारण में दी जाने वाली अनेक छूटों को समाप्त किया जाना चाहिए।
- (2) धार्मिक संस्थानों को सम्पत्ति-कर के भुगतान के लिए दी गई छूट को समाप्त किया जाना चाहिए।
- (3) सम्पत्ति का मूल्य ज्ञात करते समय परिवार के सदस्यों द्वारा विभिन्न सहकारी समितियों एवं कम्पनियों के द्रव किये गये शेयरों का वर्तमान मूल्य उनकी सम्पत्ति में शामिल करना चाहिए।
- (4) सम्पत्ति के लेन-देन से होने वाली वृद्धि को आय में सम्मिलित करते हुए कर-निर्धारण करना चाहिए।
- (5) कृषि-सम्पत्ति पर कर-निर्धारण करने के लिए भूमि का मूल्य, आय-पूंजीकृत विधि (Income Capitalization Method) द्वारा ज्ञात करना चाहिए।
- (6) हिन्दू अविभाज्य परिवार को कर इकाई (Tax entity) के रूप में दी गई छूट को समाप्त करना चाहिए।

(4) सुधार-कर (Betterment Levy)

सरकार द्वारा क्षेत्र-विशेष में विकास कार्यक्रमों जैसे—सिंचाई की सुविधाओं का विकास, नहरों एवं बाँधों का निर्माण, बाढ़ से रक्षा, भूमि का धारोपन दूर करना आदि के क्रियान्वयन से क्षेत्र-विशेष के कृषकों को अन्य क्षेत्र के कृषकों की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार की सुविधाओं से कृषकों की उत्पादन लागत में कमी (नहरों द्वारा सिंचाई से) एवं भूमि के मूल्य में वृद्धि होती है। अतः ऐसे क्षेत्रों के कृषकों पर सरकार अतिरिक्त कर लगाती है जिसे सुधार-कर कहते

हैं। विकास योजनाओं में लगाये गये घन के व्याज, मूल्य-ह्रास, मरम्मत एवं उन्हे कार्यन्त रखने के लिए होने वाले खर्च की वसूली हेतु सुधार-कर लगाया जाता है। सुधार-कर के लगाने में सरकार को वित्त प्राप्त होता है तथा दूसरे क्षेत्र के कृषकों को, क्षेत्र विशेष के कृषकों को प्राप्त हो रहे अतिरिक्त लाभ में ईप्स्य नहीं होती है। सुधार-कर क्षेत्र-विशेष में लाभान्वित कृषकों से ही वसूल किया जाता है। नानावती एवं ग्रन्जारिया के शब्दों में "सुधार-कर कृषकों की भूमि के मूल्य में वृद्धि के लिए दिया जाने वाला कर है। कृषकों की भूमि का मूल्य सिंचाई सुविधाओं के बढ़ने, क्षेत्र में नहर व बाँध के बनाने अथवा क्षेत्र की वाढ़ में रक्षा करने से बढ़ता है।"

(5) विशेष-कर :

देश के कई राज्यों ने विभिन्न फसलों पर विशेष-कर भी लगाये हैं। विशेष-कर लगाने से प्रमुख तात्पर्य यह है कि कृषकों को विशेष फसल के फार्म पर उत्पादन करने से साक्षान्तों की अपेक्षा अधिक व अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, उसमें से एक भाग सरकार विशेष-कर के रूप में प्राप्त करती है। विशेष-कर प्रमुखतया वाणिज्यिक फसलों पर लगाये गये हैं। जैसे—आन्ध्रप्रदेश राज्य ने तम्बाकू, गन्ना, मिर्च, कपास व मूँगफली पर तथा पंजाब राज्य ने मूँगफली एवं मूँग की फसलों पर विशेष-कर लगाये हैं।

(6) सिंचाई-कर

विभिन्न क्षेत्रों के कृषकों को, उपलब्ध सिंचाई-सुविधाओं के उपयोग के लिए सरकार जो राशि प्राप्त करती है, उसे सिंचाई कर कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कृषि एवं आर्थिक विकास के लिए सरकार प्रतिवर्ष नहरों एवं बाँधों का निर्माण कराती है, जिस पर करोड़ों रुपये व्यय होते हैं। उपलब्ध सिंचाई सुविधाओं को बनाये रखने तथा प्रशासनिक व्यय की पूर्ति के लिए सरकार कृषकों से सिंचाई-कर के रूप में राजस्व प्राप्त करती है। सिंचाई की दरें दो प्रकार की होती हैं—

(अ) ऐच्छिक—ऐच्छिक सिंचाई-दर कृषि सिंचाई विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है। जो कृषक सिंचाई के लिए पानी का उपयोग करना चाहते हैं वे निर्धारित दर के मुग्तान पर सिंचाई सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

(ब) अनिवार्य—अनिवार्य सिंचाई-दर के अन्तर्गत सिंचाई योजनाओं के क्षेत्र में आने वाले सभी कृषकों को सिंचाई दर कर मुग्तान करना होता है। प्रत्येक कृषक निर्धारित मात्रा में सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर सकता है। निर्धारित मात्रा से अधिक सिंचाई की सुविधा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त दर देना होता है।

सिंचाई-दर निर्धारित करने की पद्धतियाँ—सिंचाई-दर निर्धारित करने की प्रमुख पद्धतियाँ निम्न हैं—

(1) पानी की मात्रा के अनुसार—प्रत्येक कृषक को उपयोग किये गये पानी की मात्रा के अनुसार सिंचाई की दर देय होती है। कृषकों द्वारा

उपयोग किये गये पानी की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए जल-मापक यन्त्र लगाये जाते हैं। इस विधि में पानी का अपव्यय नहीं होता है।

- (2) भू-राजस्व राशि के भुगतान के आधार पर—इस विधि में सिंचाई की दर कृषको से भू-राजस्व राशि के आधार पर अनिवार्य रूप से वसूल की जाती है।
- (3) भूमि की उत्पादकता के अनुसार—इस विधि में सिंचाई की दर भूमि की उत्पादकता के अनुसार वसूल की जाती है।
- (4) समझौते के अनुसार—इस विधि में सिंचाई की दर सरकार एवं कृषको में आपसी समझौते के अनुसार नियत की जाती है।
- (5) फसलों के अनुसार—इस विधि में विभिन्न फसलों के लिए पानी की आवश्यक मात्रा के अनुसार सिंचाई की दर नियत की जाती है। इस विधि में प्रमुख फसल के लिए कम एवं अधिक पानी का उपयोग करने वाले कृषको को समान दर से सिंचाई-कर का भुगतान करना होता है, जिसके कारण पानी का अपव्यय होता है।

□□□

पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि

देश के नियोजित आर्थिक विकास के लिए वर्ष 1951 से पंचवर्षीय योजनाएँ प्रारम्भ की गई हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य उपलब्ध उत्पादन-साधनों का सन्तुलित एवं उचित उपयोग करके देश के निवासियों के जीवन-स्तर को निर्धारित समय में ऊँचा उठाना है। इस कार्य के लिए 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं¹—

- (1) देश में सीमित उत्पादन-साधन, जैसे—पूँजी, मानव-श्रम आदि की उपलब्धि का आकलन करना एवं उनकी पूर्ति बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना।
- (2) देश में उपलब्ध सीमित साधनों के अनुकूलतम एवं सन्तुलित उपयोग की योजना तैयार करना।
- (3) देश में विभिन्न कार्य की योजनाओं की प्राथमिकता के अनुसार पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्पादन-साधनों का आवंटन करना, जिससे निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो सकें।
- (4) देश के आर्थिक विकास में बाधक कारकों का पता लगाना एवं उन्हें दूर करने की योजना बनाना।
- (5) विभिन्न योजनाओं को विभिन्न चरणों में कार्यान्वित करने का कार्य-कुशल तन्त्र तैयार करना।
- (6) योजनाओं की प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन करना एवं निर्धारित नीति में आवश्यक परिवर्तन करने की सिफारिश करना।
- (7) आवश्यकता होने पर जन-साधारण से सम्बन्धित नीति के विषय में सरकार को अन्तरिम सिफारिशें करना।

योजना आयोग एक सलाहकार समिति है जिसका मुख्य कार्य केन्द्रीय सरकार

को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना है। योजना आयोग विभिन्न विकास कार्यक्रमों के विषय में सिफारिशें करने के पूर्व केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों से आवश्यक परामर्श करता है, क्योंकि निर्मित योजनाओं को कार्यान्वित करने का दायित्व राज्य एवं केन्द्र सरकार पर होता है। प्रजातान्त्रिक शासन-प्रणाली में योजना बनाकर आर्थिक विकास करने का श्रेय सर्वप्रथम भारत सरकार को प्राप्त हुआ है।

विभिन्न पञ्चवर्षीय योजनाएँ

विभिन्न पञ्चवर्षीय योजनाओं का संक्षिप्त विवेचन निम्नलिखित है।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (अप्रैल 1951 से मार्च 1956) :

देश में प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अप्रैल, 1951 से लागू की गई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य देश के निवासियों के रहन सहन के स्तर को ऊँचा उठाना, समाज के सभी वर्गों के लिए समान सुविधाएँ उपलब्ध कराना एवं विभिन्न वर्गों में व्याप्त आर्थिक विषमता को समाप्त करना था। इस योजना के कुल व्यय की राशि में से कृषि, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण पर सर्वाधिक राशि व्यय की गई। योजना आयोग द्वारा इस योजना-काल में कृषि-क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता प्रदान करने में मुख्य मान्यता यह थी कि कृषि उत्पादन में वृद्धि के बिना औद्योगिक विकास प्राप्त करना सम्भव नहीं है। अतः देश की आधारभूत कृषि-अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना अति-आवश्यक माना गया था।

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना (अप्रैल, 1956 से मार्च, 1961) :

॥ द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य देश में समाजवादी स्तर का समाज (Socialistic Pattern of Society) की स्थापना करना था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित थे—

- (i) राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना जिससे देश के निवासियों का जीवन स्तर ऊँचा उठ सके।
- (ii) देश के औद्योगीकरण के लिए प्रमुखतया भारी एवं आधारभूत उद्योगों का विकास करना।
- (iii) योजना-काल में देश के निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराना।
- (iv) समाज में व्याप्त आय की असमानता को कम करना एवं आर्थिक साधनों का समानता के आधार पर वितरण करना।

इस योजना में औद्योगीकरण एवं खनिज विकास कार्यों को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया। यह महसूस किया गया कि उद्योग एवं खनिज विकास के बिना राष्ट्रीय आय में निर्धारित स्तर तक वृद्धि करना तथा बेरोजगारी की समस्या को हल करना सम्भव नहीं है। योजना-काल में औद्योगीकरण के साथ-साथ कृषि, परिवहन एवं सामाजिक सेवाओं के विकास पर भी ध्यान दिया गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (अप्रैल, 1961 से मार्च, 1966) :

तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे—

- (i) राष्ट्रीय आय में 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से निरन्तर वृद्धि करना ।
- (ii) खाद्यान्न उत्पादन में देश को आत्म-निर्भरता प्राप्त कराना तथा उनके निर्यात की मात्रा में वृद्धि करना ।
- (iii) देश के प्रमुख उद्योगों जैसे—लोहा, ईंधन, रसायन, ऊर्जा, मशीनरी एवं औजारों के निर्माण को प्रोत्साहन देना ।
- (iv) देश में उपलब्ध श्रम-शक्ति के पूर्ण उपयोग के लिए योजना बनाना ।
- (v) देश में आय एवं धन की विभिन्न वर्गों में पायी जाने वाली असमानता को कम करना एवं आर्थिक साधनों का समानता के आधार पर बँटवारा करना ।
- (vi) देश में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना ।

वार्षिक योजनाएँ (अप्रैल, 1966 से मार्च, 1969)

तृतीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के उपरान्त जून, 1966 में रुपये के अवमूल्यन, कीमतों में वृद्धि एवं वर्ष 1965-66 तथा 1966-67 में देश के कई राज्यों में विषम मूँछा पड़ने के कारण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अप्रैल, 1966 से प्रारम्भ नहीं हो सकी । उपर्युक्त कारणों से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप एवं पूँजीगत व्यय की राशि में आवश्यक संशोधन किये जाने के कारण चतुर्थ योजना एक अप्रैल, 1969 से प्रारम्भ हो पायी । तृतीय योजना की समाप्ति एवं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के शुरू होने के तीन वर्षों में तीन वार्षिक योजनाएँ बनाकर योजना की प्रक्रिया को जारी रखा गया । इन तीनों वार्षिक योजनाओं के काल में भी कृषि एवं सम्बन्धित कार्यक्रम, सिंचाई एवं ऊर्जा के विकास पर विशेष ध्यान का प्रावधान किया गया ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (अप्रैल, 1969 से मार्च, 1974) :

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना था । योजना के अन्य उद्देश्य निम्नलिखित थे—

- (i) राष्ट्रीय आय में 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से निरन्तर वृद्धि करना ।
- (ii) कृषि उत्पादन में 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से निरन्तर वृद्धि के लिए आवश्यक साधन जुटाते हुए उत्पादन-वृद्धि करना ।
- (iii) देश में खाद्यान्नों के आयात को समाप्त करना ।
- (iv) निर्यात की दर में 7 प्रतिशत तक वृद्धि करना ।
- (v) देश के विभिन्न क्षेत्रों का सन्तुलित विकास करना ।

- (vi) सहकारी समितियों (विशेषकर कृषि एवं उपभोक्ता समितियों) के विकास पर बल देना ।
- (vii) लघु कृषकों एवं सूखे क्षेत्रों के कृषकों को विकास कार्यों में भाग ले सकने और उनसे लाभान्वित हो सकने में सक्षम बनाना ।
- (viii) खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता बनाये रखना ।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना (अप्रैल, 1974 से मार्च, 1979) :

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य निर्धनता-उन्मूलन एवं आत्म-निर्भरता प्राप्त करना था । समग्र घरेलू उत्पाद की मात्रा में प्रतिवर्ष 5.5 प्रतिशत की दर से प्रौद्योगिकी वृद्धि करके देश में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना एवं आर्थिक एवं सामाजिक असमानता को दूर करके देश के निम्न आय स्तर के व्यक्तियों के रहन-सहन के स्तर में सुधार लाना था । विलासिता एवं सुख-साधन की वस्तुओं के उपभोग पर सख्ती से नियन्त्रण एवं सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों का विस्तार करना भी इस योजना के उद्देश्यों में शामिल था । पाँचवी योजना की समाप्ति से उपरान्त एक वर्ष की वार्षिक योजना (1979-80) कार्यान्वित की गई ।

छठी पंचवर्षीय योजना (अप्रैल, 1980 से मार्च, 1985) :

छठी पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के विशेष महत्वपूर्ण क्षेत्रों के समन्वित और बहुमुखी विकास पर बल दिया गया है । योजना की विकास कार्यनीति में गरीबी को हटाने, लाभदायक रोजगार पैदा करने, प्रौद्योगिकी और आर्थिक क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने तथा कृषि और उद्योग का आधार मजबूत करने की दिशा में तेजी से प्रगति करने की बात कही गई है । सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप राष्ट्रीय आय, उपभोग तथा जन सेवाओं के उपयोग में गरीब वर्ग के हिस्से को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास भी किये जायेंगे । छठी योजना के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं—

- (i) देश के समग्र घरेलू उत्पाद में 5.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है जिससे प्रति व्यक्ति समग्र घरेलू उत्पाद में 3.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो सके । योजना के अन्त में प्रति व्यक्ति आय 1979-80 की कीमतों के आधार पर 1,484 रुपये से बढ़कर 1,744 रुपये होने का अनुमान है ।
- (ii) प्रति व्यक्ति वार्षिक उपभोग जो 1979-80 में 95 रुपये का था, वह बढ़ाकर 1984-85 में (1979-80 की कीमतों पर) 110 रुपये का करना ।

- (iii) गरीबी को रखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 48.44 से घटाकर 30 प्रतिशत करना।
- (iv) रोजगार में 3.40 करोड़ मानक व्यक्ति वर्ष की वृद्धि करना जिससे योजना के अन्त तक यह 18.50 करोड़ मानक व्यक्ति-वर्ष हो जायेगा।
- (v) योजना अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति अनाज की खपत में 2 प्रतिशत, चीनी की खपत में 3 प्रतिशत और कपड़े की खपत में 2 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि करना।
- (vi) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता देना।

सातवें पंचवर्षीय योजना (अप्रैल, 1985 से मार्च, 1990)

सातवीं पंचवर्षीय योजना में औसतन 5.0 से 5.5 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना काल में निम्न क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी जावेगी—

- (i) देश के मुख्य आधार-क्षेत्र (Core-sector) जैसे—शक्ति, कोयला, स्टील, रेल्वे, संचार, उर्वरक, सिंचाई एवं सीमेन्ट में व्याप्त कमी को दूर करना। इस योजना-काल में ऊर्जा क्षेत्र पर कुल परिश्रम का सर्वाधिक अंश 30.45 प्रतिशत व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है।
- (ii) दूसरी प्राथमिकता कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र को दी जावेगी। कृषि विकास पर ही उद्योगों का विकास निर्भर करता है। अतः कृषि विकास हेतु तीन स्तरीय नीति अपनाने का कार्यक्रम है—
 - (अ) अनुसन्धान एवं तकनीकी ज्ञान के द्वारा दलहन, निलहन एवं शुष्क कृषि क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि करना। इसके लिए इन क्षेत्रों में अधिक पूंजी निवेश करने का भी कार्यक्रम है।
 - (ब) कृषि विकास के लिए आवश्यक संरचनात्मक सुविधाओं का बढ़ाना जैसे—सिंचाई तकनीकी ज्ञान का विस्तार जोत चक-बन्दी करना।
 - (स) उचित कीमत पर कृषकों को आवश्यक कृषि निषिष्ट जैसे—उर्वरक, उन्नत बीज, विद्युत् सुविधा उपलब्ध कराना।
- (iii) ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम शुरू करना, जिससे रोजगार उपलब्धि में वृद्धि होवे।
- (iv) गरीबी के स्तर पर जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी करना। अनुमान के अनुसार गरीबी के स्तर पर वर्तमान में

कार्यरत जनसंख्या 273 मिलियन से वर्ष 1989-90 तक 211 मिलियन लाना अर्थात् प्रतिशतता में 36.9 से कमी करके 25.8 प्रतिशत ही रहना ।

योजना आयोग ने सातवी योजना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में 1,80,000 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित किया है । यह राशि छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित व्यय राशि से 85 प्रतिशत अधिक है । कुल परिव्यय राशि में 95,534 करोड़ रुपये (53 प्रतिशत) केन्द्र सरकार एवं 80,698 करोड़ रुपये राज्य सरकारों तथा 3,768 करोड़ रुपये सघ-शासित प्रदेशों (राज्यों एवं सघ-शासित प्रदेशों को 47 प्रतिशत) को आवंटन किया गया है । सातवी योजना में केन्द्रीय सरकार का प्रशदान पिछली पंचवर्षीय योजनाओं की तुलना में काफी बड़ा दिया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य ऊर्जा, सिंचाई एवं कृषि में अधिक व्यय करने हेतु किया गया है ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (अप्रैल, 1992 से मार्च, 1997) :

आठवी पंचवर्षीय योजना को अप्रैल, 1990 के स्थान पर अप्रैल, 1992 से प्रारम्भ की जा सके । इसके पूर्व के दो वर्ष दो वार्षिक योजनाएँ (1990 से 1992) के रूप में अपनाई गईं । आठवी पंचवर्षीय योजना में 5.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है । इस योजना में चार पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाना है :

- (i) विभिन्न क्षेत्रों/कार्यक्रमों में सघन पूँजी निवेश को प्राथमिकता देना जिससे राजकोपीय, व्यापार एवं औद्योगिक क्षेत्र की नीति को कार्यान्वित किया जा सके ।
- (ii) प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए साधन सुविधा उपलब्ध कराना एवं उनकी दक्षता से उपयोग करने की योजना बनाना ।
- (iii) देश में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए रोजगार उपलब्धि, स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि एवं शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देना ।
- (iv) आवश्यक आधारभारिक संस्थाओं का विकास करना, जिससे पूँजी निवेश से प्राप्त लाभ देश के सभी व्यक्तियों तक पहुँच सके ।

उपरोक्त पहलुओं के सन्दर्भ में आठवी योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं :

- (1) आवश्यक रोजगार सुविधा उत्पन्न करना, जिससे इस शताब्दी के अन्त तक लगभग पूर्ण रोजगार की स्थिति देश में बने ।
- (2) देश में जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाता । यह व्यक्तियों के सहयोग तथा उन्हें प्रेरणाजनक योजनाओं को अपनाकर किया जाना है ।

- (3) देश में प्राथमिक शिक्षा सभी को उपलब्ध कराना जिससे देश के 15 से 35 वर्ष के उम्र समूह के व्यक्तियों में से अशिक्षा को पूर्णतया समाप्त किया जा सके ।
- (4) देश के सभी गाँवों एवं जनसंख्या को पीने का स्वच्छ जल एवं आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना ।
- (5) कृषि का विकास एवं विविधिकरण करना जिससे देश में सभी वस्तुओं में स्वावलम्बिता प्राप्त की जा सके तथा निर्यात के लिए अविशेष वस्तुओं का उत्पन्न करना ।
- (6) आधारभारिक सुविधाओं—परिवहन संचार सिंचाई का विकास करना जिससे विकास की दर में वृद्धि हो सके ।

सारणी 20 1 व 20 2 देश में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सावजनिक क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में की गई परिणय राशि प्रदर्शित करती है ।

सारणी 20 3 विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में प्राप्त उपलब्धियाँ एवं घाटवी योजना के लक्ष्य प्रदर्शित करती है । देश में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के काल में सभी क्षेत्रों का विकास हुआ है । योजना काल में पूर्व देश में खाद्यान्नों का उत्पादन-स्तर 50 मिलियन टन ही था जो बढ़कर 1989-90 में 170.4 मिलियन टन हो गया । इस प्रकार योजना काल के 40 वर्षों में खाद्यान्नों के उत्पादन स्तर में 3.5 गुना के लगभग वृद्धि हुई है । उन्नत किस्मों के बीजों का आविष्कार देश में सर्वप्रथम 1966-67 में हुआ था जो विस्तार होकर आज 61.3 मिलियन हेक्टर क्षेत्र में कृषित किये जा रहे हैं । स्वतन्त्रता के समय देश में ट्रैक्टर निर्माण का एक भी कारखाना नहीं होने के कारण इनका आयात किया जाता था । वर्तमान में देश में ट्रैक्टरों के 15 कारखानों से आवश्यक संख्या में ट्रैक्टर निर्मित किये जा रहे हैं । इसी प्रकार उर्वरकों के उत्पादन के लिए भी अनेक कारखाने स्थापित हो चुके हैं ।

सारणी 20 I

भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्धन राशि

(करोड़ रुपये में)

योजना/क्षेत्र	कृषि एवं उससे सम्बन्धित कार्यक्रम	सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं ऊर्जा	उद्योग एवं खनिज	परिवहन एवं संचार सेवा	सामाजिक सेवाएँ एवं विविध	कुल परिवर्धन राशि
प्रथम योजना (1951-56)	290@ (14 80)	583 (29 74)	97 (4 95)	518 (26 43)	472 (24 08)	1960 (100)
द्वितीय योजना (1956-61)	549@ (11 75)	882 (18 88)	1025 (24 08)	1261 (26 99)	855 (18 30)	4672 (100)
तृतीय योजना (1961-66)	1089 (12 70)	1917 (22 35)	1967 (22 93)	2112 (24 62)	1492 (17 40)	8577 (100)
वार्षिक योजनाएँ (1966-69)	1107 (16 71)	1684 (25 42)	1636 (24 69)	1222 (18 45)	976 (14 73)	6625 (100)
चतुर्थ योजना (1969-74)	2320 (14 70)	4286 (27 16)	3107 (19 69)	3080 (19 52)	2986 (18 93)	15779 (100)

पाँचवी योजना (1974-79)	4865 (12 34)	11276 (28 60)	9581 (24 30)	6870 (17 43)	6834 (17 33)	39426 (100)
वार्षिक योजना (1979-80)	1997 (16 4)	3528 (29 0)	2639 (21 7)	2045 (16 8)	1968 (16 1)	12177 (100)
छठी योजना (1980-85)	15201 (13 9)	41681 (38 1)	16948 (15 5)	17678 (16 2)	17784 (16 3)	109292 (100)
सातवी योजना (1985-90) का प्रस्तावित	22793 (12 6)	71801 (39 9)	22461 (12 5)	29443 (16 4)	33503 (18 6)	180000 (100)
1985-86 वास्तविक	4499 (13 6)	12471 (37 8)	5437 (16 5)	5014 (15 1)	5649 (17 0)	33060 (100)
1986-87 वास्तविक	5511 (14 1)	14680 (37 5)	5564 (14 2)	6287 (16 1)	7107 (18 2)	39149 (100)

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े कुल परिव्यय के प्रतिशत हैं। (ग) कृषि एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम।

स्रोत : 1 Reserve Bank of India Bulletin, December, 1984

2 Financial Survey, 1988-89, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi, 1989, pp 5-40-42

आठवी पंचवर्षीय योजना में 798,000 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है, जिसमें 3,61,000 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र (45.24 प्रतिशत) एवं 4,37,000 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र (54.76 प्रतिशत) से परिव्यय का लक्ष्य है। इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्ता में कमी की गई है। सातवी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का अंशदान 51.72 प्रतिशत था। आठवी योजना में क्षेत्रवार किए जाने वाले परिव्यय की सारणी 20.2 में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 20.2

आठवी योजना में विभिन्न क्षेत्रों में परिव्यय राशि

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय	निजी क्षेत्र परिव्यय	कुल परिव्यय	प्रतिशत
1 कृषि	52,000	96,800	148,800	18.65
2 खनिज	28,500	11,100	39,600	4.96
3 निर्मित क्षेत्र	71,300	14,100	188,400	23.61
4 ऊर्जा	92,000	10,120	102,120	12.80
5 निर्माण	3,300	17,240	20,540	2.57
6 परिवहन	49,200	38,710	87,910	11.02
7 संचार सेवा	25,000	1,000	26,000	3.26
8 सेवाएँ	63,900	120,730	184,630	23.13
कुल	361,000	437,000	798,000	100

विविन्न पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में प्राप्त उपलब्धियाँ

विवरण	इकाई	योजना-काल में 1950-51	प्रथम योजना के अवधि में 1951-56	द्वितीय योजना के अवधि में 1956-61	तृतीय योजना के अवधि में 1961-66	चौथी योजना के अवधि में 1966-69	पाँचवी योजना के अवधि में 1969-74	पाँचवी योजना के अवधि में 1974-79	छठी योजना के अवधि में 1980-85	सातवी योजना के अवधि में 1985-90	आठवी योजना के अवधि में 1992-97
1 साक्षात् उत्पादन	मि टन	5501	669	820	723	940	1047	1264	1455	16992	21000
2 तिसहन उत्पादन	मि टन	510	57	70	64	68	89	97	130	1680	23.00
3. गन्ना (गुड़ के रूप में) उत्पादन	मि टन	56	61	110	128	128	144	177	170	NA	NA
4 कपास उत्पादन	मि गांठें	29	40	53	46	51	63	72	85	1050	1400
5 जूट उत्पादन	मि गांठें	33	42	4.1	45	—	62	65	65	785	NA
6 दूध उत्पादन	मि. टन	1741	1972	2038	200	212	232	291	423	51.45	70 00
7 ऊन उत्पादन	मि किता.	25.6	NA	NA	3566	376	301	330	39.8	41.70	50

8 ग्रह उत्पादन	मिलियन	1832	NA	NA	4100	5300	7700	11,285	14,500	20204	30,000
9 कुल कृषि क्षेत्र	मि हेक्टर	131 9	147 3	152 8	155 3	159 5	169 9	175 20	176 4	182 50	190 6
10 कुल सिंचित क्षेत्र	मि हेक्टर	22 6	25 0	28 0	30 9	35 9	43 4	48 20	60 5	75 70	89 3
11. उन्नत किसानों के मन्तर्गत क्षेत्र	मि हेक्टर	—	—	—	—	9 2	26 4	40 13	54 14	61 30	78 00
12 उर्वरक उत्पादन	हजार टन	64	109	154	355	588	1383	2638	5181	8543	12,800
13 उर्वरक उपयोग	हजार टन	—	—	—	785	1761	2839	5117	8210	11,695	18,300
14 कृषि उत्पादन चक्रवृद्धि दर से वृद्धि प्रतिशत	—	—	43	41	10	69	31	46	60	—	—
15 औद्योगिक उत्पादन में चक्रवृद्धि दर से वृद्धि प्रतिशत	—	—	74	66	90	26	37	62	55	—	—

सारणी 20.4 प्रमुख कृषि उत्पादों का पिछले 40 वर्ष (सात पंचवर्षीय योजना काल) में हुए उत्पादन वृद्धि एवं आठवी योजना के लक्ष्य प्रदर्शित करती है।

सारणी 20.4

प्रमुख कृषि उत्पादों का योजना काल के 40 वर्षों में प्राप्त उत्पादन वृद्धि

कृषि उत्पाद	इकाई	योजना काल से पूर्व 1949-50	सातवी योजना के अन्त में 1989-90	प्रतिशत वृद्धि	आठवी योजना के लक्ष्य 1992-97
1 चावल	मिलियन टन	23.54	74.06	214.61	88.00
2. गेहूँ	" "	6.39	49.65	677.00	66.00
3. मोटे अनाज	" "	16.83	34.31	103.86	39.00
4 दलहन	" "	8.16	12.61	54.53	17.00
5 कुल खाद्यान्न	" "	54.92	107.63	210.69	210.00
6 तिलहन	" "	5.23	16.80	221.22	23.00
7. गन्ना	" "	50.17	222.6	343.69	275.00
8. कपास रेशा	मिलियन गार्डें	2.75	10.50	281.82	140.00
9 जूट एवं मेस्टा	" "	3.31	7.85	137.16	9.50
10 दूध	मि. टन	17.41	51.45	195.52	70.00
11. ऊन	मि. किग्रा.	25.6	41.70	62.89	50.00

स्रोत : (i) Yojana, Vol 24(14 & 15), August, 1980, p. 82

(ii) Economic Survey, Ministry of Finance, Government of India New Delhi

कृषि में तकनीकी ज्ञान का विकास

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् खाद्यान्न-उत्पादन में वृद्धि एवं देश के आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय-योजनाएँ शुरू की गईं। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि-विकास को प्राथमिकता प्रदान की गई है। कृषि-क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया, जिससे कृषि उत्पादन एवं कृषकों की आय में वृद्धि हुई है। कृषि-उत्पादन में वृद्धि के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से विशेष प्रयास किए गए हैं। कृषि विकास की नई नीति के अनुसार चुने हुये जिलों में कृषि के नये तरीकों का उपयोग करके उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की गई। कृषि अनुसंधान को भी पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष महत्ता दी गई। इन योजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना था। कृषि में तकनीकी ज्ञान विकास के लिए समय समय पर अनेक कार्यक्रम अपनाये गये। इन कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है—

अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम (Grow More Food Campaign) :

वर्ष 1942 में बंगाल अकाल के फलस्वरूप कृषि-उत्पादन में वृद्धि के लिए “अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम” शुरू किया गया। अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्न उपाय अपनाये गये—

- (i) नई भूमि को कृषि योग्य बनाकर दो या अधिक फसलें प्रतिवर्ष उत्पन्न करना।
- (ii) नहरों, बाँधों एवं नये कुओं का निर्माण करके सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि करना।
- (iii) उर्वरकों के उपयोग की मात्रा में वृद्धि करना।
- (iv) उन्नत बीजों की पूर्ति एवं उपयोग में वृद्धि करना।

अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम निर्धारित कृषि-उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति में पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ, जिसके कारण कार्यक्रम के उद्देश्यों में समय-समय पर आवश्यक परिवर्तन किए गए। फरवरी, 1952 में भारत सरकार ने अधिक अन्न

उपजाओ कार्यक्रम की जाँच के लिए एक समिति नियुक्त की। समिति के प्रमुख सुभाष निम्न थे—

(i) देश में प्रसार-सेवा सुविधा का सुव्यवस्थित प्रबंध करना।

(ii) लघु-सिंचाई कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

(iii) आवश्यक ऋण-सुविधा की व्यवस्था करना।

अधिक मात्र उपजाओ जाँच समिति की उपरोक्त सिफारिशों को प्रथम पंच-वर्षीय योजना में कृषि-विकास कार्यक्रम में सम्मिलित कर ली गई। प्रसार-सेवा सुविधाओं के विकास के लिए देश में वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास खण्ड एवं वर्ष 1953 में राष्ट्रीय-विस्तार-सेवाएँ प्रारम्भ की गईं।

फोर्ड संस्थान दल

वर्ष 1957-58 में खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट के कारण देश में गम्भीर खाद्य-समस्या का समाधान सुझाने के लिए भारत सरकार ने फोर्ड-संस्थान के कृषि विशेषज्ञों के एक दल को भारत आमन्त्रित किया। इसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय विशेषज्ञों के सहयोग से कृषि स्थिति का अध्ययन करना एवं खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के लिए सुझाव देना था। फोर्ड-संस्थान दल ने वर्ष 1959 में भारत-भ्रमण के पश्चात् 'भारतीय खाद्य समस्या एवं उसे दूर करने के उपाय' नामक प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया। फोर्ड-संस्थान दल ने प्रतिवेदन में चुनी हुई फसलों एवं चुने हुए क्षेत्रों में सघन कृषि-विकास कार्यक्रम (पैकेज कार्यक्रम) अपनाने का सुझाव दिया।

फोर्ड-संस्थान के कृषि उत्पादन दल की सिफारिशों को लागू करने के लिए, फोर्ड-संस्थान के कृषि विशेषज्ञों के दूसरे दल ने, अक्टूबर, 1959 में भारत का पुनः दौरा किया और चुने हुये क्षेत्रों में खाद्यान्न-उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्नांकित दस-सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया—

- (1) उत्पादन-योजना के आधार पर कृषकों को आवश्यक कृषि-श्रृण सुविधा सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराना।
- (2) कृषकों को उर्वरक, कीटनाशी दवाइयाँ, उन्नत बीज, कृषि औजार एवं अन्य साधनों की सुगमता से उपलब्धि के लिए सहकारी सेवा समितियों का विकास करना।
- (3) गेहूँ, चावल एवं छोटे भनाजों की न्यूनतम समर्थित कीमत द्वारा कृषकों को उत्पादन वृद्धि की प्रेरणा देना।
- (4) विभिन्न फसलों के विषय अधिशेष के विपणन से उचित कीमत की प्राप्ति के लिए सुव्यवस्थित विपणन-व्यवस्था का विकास करना।
- (5) कृषकों को गाँवों में तकनीकी शिक्षा एवं फार्म-प्रबन्धक की सुविधा प्रदान करने के लिए खण्ड-स्तर पर प्रसार-शिक्षा की व्यवस्था करना।

- (6) कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों को फार्म-योजना बनाने को प्रोत्साहित करना ।
- (7) कृषि एवं पशुपासन सुधार के लिए गाँवों में विभिन्न आवश्यक सस्याओं का विकास करना एवं विकास के लिए आवश्यक नेतृत्व प्रदान करना ।
- (8) देश में कृषि-उत्पादन में वृद्धि के लिए बाँध निर्माण, सड़क निर्माण, भू-संरक्षण, सघु सिंचाई परियोजनाओं पर अधिक ध्यान देना ।
- (9) गाँव, सण्ड, राज्य एवं केन्द्रीय स्तर पर उपलब्ध उत्पादन-साधनों के उपयोग से कार्यक्रमों के विकास की योजना बनाना ।
- (10) कार्यक्रम की प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन करना ।

फोर्ड संस्थान दल के प्रतिवेदन के अनुसार देश में आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन करने के लिए उपलब्ध उत्पादन-साधन सीमित मात्रा में थे और सीमित उत्पादन-साधनों का सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र में अनुकूलतम उत्पादन की मात्रा प्राप्त करने के लिए उपयोग कर पाना सम्भव नहीं था। दल की धारणा थी कि सीमित उत्पादन-साधनों का चुने हुए क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार प्रस्तावित मात्रा में उपयोग करने से उत्पादन में अधिक वृद्धि की जा सकती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए फोर्ड संस्थान दल ने भारत के लिए सघन-कृषि कार्यक्रम योजना प्रस्तावने की सिफारिश की। भारत सरकार ने फोर्ड संस्थान दल के उपर्युक्त सुझावों को स्वीकार करते हुए वर्ष 1960 में सघन कृषि-जिला कार्यक्रम शुरू किया।

सघन-कृषि जिला-कार्यक्रम/पैकेज कार्यक्रम (Intensive Agricultural District Programme or Package Programme) -

भारत सरकार ने फोर्ड संस्थान दल की सिफारिश के अनुसार पैकेज कार्यक्रम सर्वप्रथम देश के सात जिलों में शुरू किया। ये जिले लुधियाना (पंजाब), पाली (राजस्थान), प्रलीगढ़ (उत्तरप्रदेश), पश्चिमी गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश), शाहाबाद (बिहार), रायपुर (मध्यप्रदेश) एवं तंजौर (तमिलनाडु) थे। लुधियाना एवं प्रलीगढ़ जिलों में गेहूँ के लिए वर्ष 1961-62 में, पाली जिले में मोटे अनाज के लिए खरीफ 1961-62 में व अन्य जिलों में चावल के लिए वर्ष 1960-61 एवं खरीफ वर्ष 1961-62 में कार्यक्रम शुरू किए गये। इसकी सफलता को देखते हुए वर्ष 1962-63 व 1963-64 में यह कार्यक्रम देश के 8 अन्य जिलों में भी शुरू किया गया। इस कार्यक्रम को दिल्ली क्षेत्र में वर्ष 1964-65 व करनाल (हरियाणा) में वर्ष 1966-67 में शुरू किया गया।

योजनाबद्ध, सुचारु रूप से आवश्यकताओं एवं साधनों की प्राप्ति तथा क्षमता के मापदण्ड पर निर्मित तथा सही रूप से कार्यान्वित योजना को सघन कृषि-कार्यक्रम या पैकेज कार्यक्रम कहते हैं। पैकेज कार्यक्रम की सफलता का मुख्य आधार कृषकों

की प्रगति के लिए उन्मुक्तता तथा उसे प्राप्त करने के प्रयास में निःसकोच व उत्साह-पूर्वक परिश्रम करना है ।

पैकेज कार्यक्रम के उद्देश्य पैकेज कार्यक्रम शुरू करने के मुख्य उद्देश्य निम्न-लिखित हैं—

- (1) पैकेज कार्यक्रम देश में उत्पादन-वृद्धि के तरीके अपनाने की एक पथ-प्रदर्शन परियोजना है, जिसके माध्यम पर एक क्षेत्र में खाद्यान्न-उत्पादन में वृद्धि के सफलभूत तरीकों को देश के अन्य क्षेत्रों में प्रयुक्त करने अथवा उन विधियों में आवश्यक संशोधन करने का मार्ग प्रशस्त होता है ।
- (2) कृषकों की आय में वृद्धि करना, जिससे उन्हें अच्छा जीवन-स्तर प्राप्त हो सके ।
- (3) देश में उपलब्ध-साधनों की उत्पादकता में वृद्धि करना ।
- (4) देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए आधारभूत कृषि-संरचनाओं का विकास करना ।

पैकेज-कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ—पैकेज-कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं—

- (1) स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक फसल के लिए पैकेज तरीकों, जैसे — उन्नत बीज, उर्वरक, कृषि-यन्त्रों एवं कृषि-विधियों के अपनाने की सिफारिश करना एवं सिंचाई की सुविधाओं का विकास करना ।
- (2) पैकेज कार्यक्रम को फार्म पर अपनाने के लिए आवश्यक उत्पादन-साधनों के प्रवन्ध करने में कृषकों की सहायता करना एवं प्राप्त उत्पादों के विपणन के लिए उचित विपणन-सुविधा उपलब्ध कराना ।
- (3) अनुकूलतम लाभ प्रदान करने वाली फार्म-योजना बनाने में कृषकों की सहायता करना, जिससे कृषक प्रस्तावित फार्म-योजना को लागू करने के लिए आवश्यक उत्पादन-साधनों को समय से पूर्व जुटा सकें ।
- (4) फार्म प्रदर्शनों द्वारा कृषकों को सुधरे हुए तरीकों से खेती करने की शिक्षा प्रदान करना । फार्म प्रदर्शन, पैकेज कार्यक्रम की मूलभूत प्रेरणा-दायक विशेषता है ।

सघन-कृषि-क्षेत्र कार्यक्रम (Intensive Agricultural Area Programme) :

तृतीय पंचवर्षीय योजना की अन्तरिम मूल्यांकन रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि जिन क्षेत्रों में कृषि-उत्पादन में वृद्धि की सम्भावना अधिक है, उन क्षेत्रों में कृषि-विकास की आधुनिक विधियाँ अपनाई जानी चाहिए । कृषि-उत्पादन दल ने भी इस

पर अपनी सहमति जनवरी, 1964 में प्रदान की, जिसके कारण देश में सघन-कृषि-क्षेत्र कार्यक्रम मार्च, 1964 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भी क्षेत्र-विशेष में कृषि विकास के लिए सघन-कृषि-योजना अपनाई गई। सघन-कृषि-क्षेत्र कार्यक्रम एवं सघन-कृषि-जिला कार्यक्रम में प्रमुख अन्तर अपनाये जाने वाले क्षेत्र का है। प्रथम में कार्यक्रम खण्ड अथवा पंचायत-समिति स्तर पर अपनाया जाता है, जबकि दूसरे कार्यक्रम में जिला-स्तर पर कृषि की उन्नत विधियाँ अपनाई जाती हैं। सघन-कृषि-क्षेत्र कार्यक्रम 7 प्रमुख आधार निम्न हैं—

- (1) समुचित मिचाई व्यवस्था वाले क्षेत्रों में 20 से 25 प्रतिशत कृषित क्षेत्र में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए विकास योजना शुरू करना।
- (2) चुने हुए 140 जिलों से तकनीकी ज्ञान का अधिकाधिक उपयोग करते हुए फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना।

कृषि-क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान विकास :

कृषि क्षेत्र के विकास के लिए तकनीकी ज्ञान में निम्न कार्यक्रम सम्मिलित हैं—

- (1) अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का उपयोग बढ़ाना।
- (2) बहुफसलीय कार्यक्रम का विस्तार करना।
- (3) कृषकों को प्रेरणादायक कीमतेँ दिलाना।
- (4) कृषि-विकास के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना, जैसे—श्रृंखला, विपणन, संग्रहण, अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण, विद्युत् परिवहन, संचार एवं प्रशासनिक सुविधाओं का विकास करना।
- (5) सिंचाई सुविधाओं का विकास करना।
- (6) आवश्यक उत्पादन-साधनों, जैसे—बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों की समय पर उपलब्धि का प्रबन्ध करना।
- (7) फसल-संरक्षण के उपायों को अपनाते के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करना।
- (8) विद्युतीकरण का विकास।
- (9) लघु कृषकों के विकास के लिए योजना शुरू करना।
- (10) शुष्क क्षेत्रों में भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करना।
- (11) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम।

उपयुक्त कार्यक्रमों में से प्रथम आठ कार्यक्रम भूमि की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निश्चित समयावधि में उत्पादकता में वृद्धि करते हैं, जबकि अन्तिम तीन कार्यक्रम लघु कृषकों एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पाई जाने वाली आय की असमानता को समाप्त करने एवं ग्रामीण विकास के उद्देश्य से सरकार द्वारा कार्यान्वित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का सक्षिप्त विवेचन निम्न है—

1 अधिक उपज देने एवं उत्पादधि में तेजार होने वाले संकर एवं बीजों किस्म के बीजों का आविष्कार— देश में कृषि-योग्य भू-क्षेत्रफल की सीमितता के

कारण खाद्यान्न-उत्पादन में वृद्धि के लिए अल्पावधि में तैयार होने वाले एवं अधिक उपज देने वाले बीजों का आविष्कार नए तकनीकी ज्ञान एवं हरित क्रांति का प्रथम चरण है। देश के कृषि वैज्ञानिकों ने अनुसन्धानों द्वारा कृषि-उत्पादन में वृद्धि के लिए विभिन्न फसलों के अधिक उपज देने वाले सकर (Hybrid) एवं बौनी (Dwarf) किस्म के बीजों का आविष्कार किया है। इन बीजों के उपयोग में खाद्यान्नों का उत्पादन देशी किस्म के बीजों की अपेक्षा कई गुना अधिक होता है। ये किस्में उर्वरक एवं सिंचाई की मात्रा अधिक चाहती हैं तथा पकने में भी कम समय लेती हैं, जिससे भूमि के क्षेत्र में वर्ष में 3 से 4 फसलों को लेना सम्भव हो गया है। इसके लिए निरन्तर बीज सुधार कार्यक्रम अपनाया जा रहा है। बीज-सुधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत किए जा रहे अनुसन्धानों के मुख्य उद्देश्य निम्नांकित हैं—

- (i) विभिन्न फसलों की उत्पादकता में वृद्धि के लिए उन्नत बीजों का आविष्कार करना।
- (ii) बीमारियों के प्रभाव से मुक्त किस्म के बीजों का आविष्कार करना।
- (iii) प्रस्तावित नई किस्म के बीजों में प्रोटीन एवं खनिज की मात्रा में वृद्धि करना।
- (iv) अल्पकाल में पकने वाली किस्म के बीजों का आविष्कार करना, जिससे भूमि पर वर्ष में अधिक से अधिक फसलें उगाई जा सकें।
- (v) देश में भूमि एवं जलवायु की विभिन्नता के अनुसार विभिन्न किस्म के बीजों का आविष्कार करना।

उपयुक्त उद्देश्यों के अनुसार विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय तथा राज्य कृषि विभाग के फार्मों पर किये गये अनुसन्धानों के परिणामस्वरूप विभिन्न फसलों की अनेक सकर एवं बौनी किस्मों का आविष्कार हुआ है। देश में खाद्यान्नों की अधिक उपज देने वाली सकर एवं बौनी किस्मों के बीजों के अन्वयन प्रयुक्त क्षेत्र का धारणी 211 में प्रदर्शित है।

सारणी 21.1

भारत में प्रमुख खाद्यान्नों फसलों की उन्नत किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

(लाख हेक्टर)

फसल/विवरण	1966- 67	1970- 71	1980- 81	1989- 90	1990- 91
1 धान					
कुल क्षेत्र	353	376	402	422	426
उन्नत किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्रफल प्रतिशत	9	56	182	262	281
	2.5	14.9	45.3	62.1	66.0
2 गेहूँ					
कुल क्षेत्र	128	182	223	235	240
उन्नत किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र प्रतिशत	5	65	161	203	204
	3.9	35.7	72.2	86.4	84.6
3 ज्वार					
कुल क्षेत्र	181	174	158	149	145
उन्नत किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र प्रतिशत	2	8	35	69	67
	1.1	4.6	22.2	46.3	46.2
4. बाजरा					
कुल क्षेत्र	122	129	117	109	104
उन्नत किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र प्रतिशत	1	2	36	56	51
	0.8	1.6	30.8	51.4	49.0
5 मक्का					
कुल क्षेत्र	51	59	60	59	59
उन्नत किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र प्रतिशत	2	5	16	23	26
	3.9	8.5	26.7	39.0	44.1
पाँचों खाद्यान्नों के अन्तर्गत क्षेत्र	835	920	960	974	974
पाँचों खाद्यान्नों के अन्तर्गत उन्नत किस्मों का क्षेत्रफल प्रतिशत	19	136	430	613	629
	2.3	14.8	44.8	62.9	64.6

Source . (i) Indian Agriculture in Brief, 23rd Edition, Direc-

torate of Economics and Statistics, Ministry of Agriculture, Government of India, New Delhi

(ii) Economic Survey, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi

देश में खाद्यान्नों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का उपयोग सर्वप्रथम वर्ष 1965-66 में शुरू हुआ था। इसके पश्चात् इनके उपयोग के क्षेत्रफल में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 1966-67 में पाँचों खाद्यान्नों की उन्नत किस्मों के अन्तर्गत 1.9 मिलियन हेक्टर क्षेत्र ही था, यह बढ़कर वर्ष 1970-71 में 13.6 मिलियन हेक्टर, 1980-81 में 43.0 मिलियन हेक्टर तथा वर्ष 1990-91 में 62.9 मिलियन हेक्टर हो गया। पाँचों खाद्यान्नों के अन्तर्गत कुल क्षेत्र का उन्नत किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्रफल वर्ष 1966-67 में मात्र 2.3 प्रतिशत ही था, जो बढ़कर वर्ष 1990-91 में 64.6 प्रतिशत हो गया। अतः उन्नत किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्रफल में निरन्तर वृद्धि हुई है, लेकिन यह वृद्धि सभी खाद्यान्नों में समान नहीं है। वर्तमान में धान के कुल क्षेत्र का 66 प्रतिशत क्षेत्र में उन्नत किस्मों के बीज कृषित किए जाते हैं। यहाँ में यह प्रतिशतता 84.6 है। मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा एवं मक्का में यह प्रतिशतता 44 से 49 है। मोटे अनाजों के अन्तर्गत उन्नत किस्मों के क्षेत्रफल में गेहूँ एवं धान के समान वृद्धि नहीं होने का प्रमुख कारण, इन फसलों का उन क्षेत्रों में लिया जाना है, जहाँ सिंचाई की पर्याप्त सुविधा का नहीं होना है।

उन्नत किस्मों के बीजों के उपयोग से देशी किस्म के बीजों की अपेक्षा कई गुना अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। यहाँ की उन्नत किस्मों से प्रति हेक्टर उत्पादन 40 से 60 क्विन्टल प्राप्त होता है, जो देशी किस्मों के बीजों के उपयोग से प्राप्त उत्पादन की अपेक्षा 2 से 2½ गुना अधिक है। इसी प्रकार चावल की उन्नत किस्मों के उपयोग से प्रति हेक्टर 70 से 80 क्विन्टल धान प्राप्त होता है, जबकि देशी किस्मों से 15 से 20 क्विन्टल ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार ज्वार, बाजरा एवं मक्का की उन्नत किस्मों से उनकी देशी किस्मों की अपेक्षा कई गुना अधिक उत्पादन प्राप्त होता है।

सारणी 21.2 विभिन्न खाद्यान्नों की फसलों की उन्नत एवं देशी किस्म के बीजों के उपयोग से प्राप्त प्रति हेक्टर उत्पादन की मात्रा, लाभ की राशि एवं उन पर होने वाले उत्पादन-लागत की राशि प्रदर्शित करती है।

सारणी 21.2

उन्नत एवं देशी किस्म के बीजों के उपयोग से प्रति हेक्टर प्राप्त साम एवं प्रति क्विन्टल उत्पादन-सागत

अध्ययन क्षेत्र एवं वर्ष	उन्नत किस्म		देशी किस्म			
	उत्पादन प्रति हेक्टर (क्विन्टल)	साम प्रति हेक्टर (रु)	उत्पादन-सागत प्रति (प्रति क्विन्टल) (रु)	उत्पादन प्रति हेक्टर (क्विन्टल)	साम प्रति हेक्टर (रु)	उत्पादन सागत प्रति क्विन्टल (रु)
1 -	2	3	4	5	6	7
भलीगढ (उत्तर प्रदेश)		मेहू				
1967-68 a	26.52	903.67	36.83	12.56	459.95	59.43
दिल्ली 1968-69 b	36.77	1355.58	49.12	21.45	630.26	71.65
उदयपुर (राजस्थान)						
1968-69 c	29.15	1746.27	—	16.80	1185.35	—
कोटा (राजस्थान)						
1972-73 d	40.10	2039.00	31.40	22.75	1238.80	42.67
कानपुर (उत्तर-प्रदेश)			चावल			
1966-67 e	31.71	1931.79	17.89	6.61	285.96	35.66
तंजावर (तमिलनाडु)						
1967-68 d	34.85	1368.12	—	22.15	943.50	—
कोटा (राजस्थान) f						
1972-73 d	41.82	1728.00	37.66	20.00	622.00	58.90

1	2	3	4	5	6	7
कानपुर (उत्तर प्रदेश) 1966-67 ■	29.53	1993.46	20.26	9.13	334.89	44.20
मन्सीगढ़ (उत्तर प्रदेश) 1967-68 ■	41.75	678.64	35.96	18.40	183.64	48.56
मन्सीगढ़ (उत्तर-प्रदेश) 1967-68 a	29.42	1006.16	27.08	15.08	270.45	47.72
कोटा (राजस्थान) 1972-73 d	29.10	1216.75	—	16.25	789.55	—

स्रोत . (a) G S Lavania & R S Dixit, Economics of High, Yielding Varieties in Package District Aligarh, I J A E, Vol XXIII No 4, October-December, 1968, pp 93-103.

(b) B M Sharma, S K Goel & R K Patel 'Economic Aspect of Dwarf Wheat, Agricultural Economics Research Bulletin No 1, January-June 1973, Division of Agricultural Economics, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi

(c) S S Acharya, Comparative Study of HYVP-Case Study of Udaipur District, Economic & Political Weekly, November, 1969

(d) R A. Yadav, Impact of High, Yielding Varieties on Farm Incomes, Employment and Resource Use Efficiency in Kota District Rajasthan, M. Sc Ag. Economics Thesis, University of Udaipur, 1974.

(e) S. P. Dhondyal, 'Cost and Effectiveness of Modern Technology in Farm Production and Farm Income,' I J A E Vol XXIII, No. 2, April-June, 1968, pp 61-62

उन्नत किस्म के बीजा के उपयोग से सभी खाद्यान्ना—गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा एवं ज्वार में दसों किस्मा की अपेक्षा प्रति हेक्टर उत्पादन की मात्रा 100 से 500 प्रतिशत अधिक होती है। उन्नत किस्म के बीजा का उपयोग से फार्म पर प्रति हेक्टर लागत भी अधिक होती है। यह अनिश्चित लागत बीज की अधिक कीमत, उर्वरक का अधिक मात्रा में उपयोग, सिंचाई का अधिक आवश्यकता एवं अन्य की अनिश्चित आवश्यकता के कारण होती है। उन्नत किस्म के बीजा के उपयोग से कृषक का प्रति हेक्टर शुद्ध लाभ, दसों किस्म के बीजा की अपेक्षा 50 से 200 प्रतिशत अधिक प्राप्त होता है। उन्नत किस्म के बीजा के उपयोग से उत्पादन की अधिकता के कारण, खाद्यान्ना की प्रति क्विन्टन उत्पादन-लागत कम हो जाती है। यह उपर्युक्त प्रत्यक्षता के परिणाम से स्पष्ट है कि दसों किस्म के बीजा के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजा का उपयोग आवश्यक मात्रा में उत्पादन-लाघवों के साथ करने से कृषकों का प्रति हेक्टर क्षेत्र से अधिक उत्पादन एवं शुद्ध लाभ प्राप्त होता है।

(2) बहुकसलीय कार्यक्रम—बहुकसलीय कार्यक्रम से तात्पर्य भूमि के क्षेत्र से प्रति वर्ष दो या दो से अधिक फसलें उत्पन्न करने से है अर्थात् भूमि की उर्वरता-शक्ति का नष्ट किए बिना, भूमि के एक इकाई क्षेत्र से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना ही बहुकसलीय कार्यक्रम कहलाता है। वर्तमान में देश के अधिकांश क्षेत्रों में वर्ष में एक ही फसल उत्पन्न की जाती है। मि. चत क्षेत्र में वर्ष में भूमि पर दो फसलें भी उत्पन्न की जाती हैं। राजस्थान के सूखा क्षेत्रों में 3-4 वर्षों में एक फसल ही उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार देश में फसल-पहनता बहुत कम है, इसमें वृद्धि करने के लिए बहुकसलीय-कार्यक्रम शुरू किया गया है।

बहुकसलीय कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न फसलों की अत्यावधि में पकन वाली किस्मा का अधिकधिक अपनाना जाता है, जिसमें कृषक उपलब्ध सीमित भूमि के क्षेत्र से वर्ष में अधिक से अधिक संख्या में फसलें उत्पन्न कर पाते हैं। बहुकसलीय कार्यक्रम को अपनाने से जोत का क्षेत्र सीमित होत हुए भी, कुल कृषित क्षेत्र में वृद्धि होती है। अत्यावधि में पकन वाली किस्म साधारणतया अधिक उत्पादन देने वाली होती हैं, जिससे फार्म पर कुल उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है। अत्यावधि में पकन वाली उन्नत किस्मा के आविष्कार के कारण कृषक, वर्ष में एक या दो फसल को उगाने के स्थान पर अपना सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्र में नीचे में खार में कल सिंचाई वाले क्षेत्रों में दो फसलें प्रति वर्ष लेने लग गये हैं अत्यावधि में पकन वाली उन्नत किस्मा का अपनाने निश्चित मौसम के अनिश्चित अन्न मौसम में भी उत्पन्न किया जा सकता है। इस कार्यक्रम से भूमि वर्ष में किसी भी समय खाली नहीं रहती है एवं कृषक का अधिक समय तक रोजगार निरन्तर है।

कृषि वैज्ञानिकों ने विभिन्न राज्यों में भूमि व जलवायु की विभिन्नता के परीक्षणों द्वारा सिद्ध कर दिया है कि जहाँ सिंचाई की सुविधा पूरे वर्ष उपलब्ध है, वहाँ पर कृषक वर्ष में चार फसलें सुगमता से उगा सकते हैं तथा प्रति हेक्टर कई गुना अधिक उाज प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, सिंचित क्षेत्रों में गेहूँ, मूँग, मक्का फसल-चक्र वर्ष में आसानी से लिया जा सकता है। इस फसल-चक्र के द्वारा प्रति हेक्टर प्रति वर्ष 14-15 टन खाद्य-पदार्थ उत्पन्न किये जा सकते हैं। खाद्य-पदार्थ उत्पादन का यह स्तर मक्का-गेहूँ फसल-चक्र द्वारा वर्ष 1950 में प्राप्त उत्पादन स्तर का लगभग 5 गुना है। बहुफसलीय कार्यक्रम के प्रसारण हेतु देश में स्थान-स्थान पर प्रदर्शन लगाये जाते हैं।

बहुफसलीय कार्यक्रम के लाभ—बहुफसलीय कार्यक्रम को अपनाने से कृषकों को निम्न लाभ प्राप्त होते हैं—

- (i) भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक उत्पादन प्राप्त होता है।
- (ii) भूमि पर निरन्तर फसलों के होने से खरपतवार कम होती है।
- (iii) भूमि पर निरन्तर फसलों के होने से भूमि का कटाव कम होता है।
- (iv) कृषकों को वर्ष भर कार्य उपलब्ध होता है जिससे उनमें व्याप्त बेरोजगारी के समय में कमी होती है।
- (v) लघु कृषकों के फार्म पर मुख्यतया बैलों का श्रम, जो अधिकांश समय बेकार रहता था, उसका पूर्ण रूप से उपयोग होता है।

बहुफसलीय कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक तत्व—बहुफसलीय कार्यक्रम की सफलता के लिए निम्न तत्व आवश्यक हैं—

- (i) बहुफसलीय कार्यक्रम के लिए चुने हुए क्षेत्र में सिंचित एवं जल-निकासी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
- (ii) बहुफसलीय कार्यक्रम की सफलता के लिए सेवा-संस्थाएँ जैसे—वाणिज्यिक बैंक, सहकारी समितियाँ एवं उत्पादन-साधनों की पूर्ति के लिए क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में दुकानें होनी चाहिए।
- (iii) बहुफसलीय कार्यक्रम की सफलता के लिए क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएँ जैसे—विपणन संग्रहण, परिष्करण आदि की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

3. प्रेरणादायक कीमत—प्रेरणादायक कीमत से तात्पर्य उस कीमत से है जो कृषकों को उत्पादन-लागत की प्राप्ति के अतिरिक्त पर्याप्त लाभ प्रदान करके उत्पादन-वृद्धि की आवश्यक प्रेरणा प्रदान करती है। कृषकों को यह प्रेरणा या तो उत्पाद की अधिक कीमत के रूप में अथवा नियत कीमत अथवा दोनों रूपों में प्रदान की जा

सकती है। कृषकों को प्रेरणादायक कीमत प्राप्त कराने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त समितियों ने आवश्यक मुद्दाव दिए हैं तथा कृषि-लागत एवं कीमत आयोग की स्थायी तौर पर देश में स्थापना की गई है। विभिन्न कृषि-उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थित कीमत से कार प्रतिवर्ष निर्धारित करती है जो उन्हें उत्पादन वृद्धि की प्रेरणा देती है।

(4) आधारभूत संरचना का विकास (Development of Infrastructural Facilities)—कृषि-विकास के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना सुविधाओं जैसे—कृषि-ऋण उपलब्धि, समुचित कृषि-विपणन व्यवस्था, संग्रहण एवं भण्डारण सुविधाओं का विकास, विद्युत् सुविधा का विस्तार, सड़क एवं परिवहन सुविधाओं का विकास, कृषि शिक्षा, अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण आदि का विकास भी अत्यन्त आवश्यक है। इन सुविधाओं के होने से कृषि में तकनीकी ज्ञान के अपनाने की गति की तीव्रता मिलती है। जिन क्षेत्रों में इन सुविधाओं का विकास अधिक हुआ है, वहाँ पर कृषि विकास की दर अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है। इन सुविधाओं के होने से कृषकों को अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे-उत्पादन-लागत में कमी होना, प्राप्त उत्पाद की अधिक कीमत प्राप्त होना, कृषि में प्राविष्टिकारित तकनीकी ज्ञान को सीधे से अपनाना आदि।

(5) सिंचाई सुविधाओं का विकास—कृषि-उत्पादन में वृद्धि के लिए उन्नत किस्मों के बीजों के अपनाने के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था का होना भी आवश्यक है। उन्नत किस्मों के बीजों का उपयोग एवं उत्पादन वृद्धि के लिए अनुकूलतम माया में उर्वरकों का उपयोग उन्हीं क्षेत्रों में सम्भव है, जहाँ सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। योजना-काल के प्रारम्भ से ही देश में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए सरकार प्रयास कर रही है तथा इसके लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में काफी धन व्यय किया जाता है।

योजना-काल के पूर्व (1950-51) देश में मात्र 22 60 मिलियन हेक्टर क्षेत्रफल (कुल कृषि क्षेत्रफल का 17.4 प्रतिशत) में सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई सुविधा के विकास के लिए अनेक लघु एवं मध्यम व बड़ी सिंचाई योजनाएँ शुरू की गई हैं। इनके फलस्वरूप वर्ष 1989-90 तक 80.4 मिलियन हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकी है, जो कुल कृषि क्षेत्र का 36.5 प्रतिशत है।

सारणी 21.3 में देश में विभिन्न पंचवर्षीय योजना-काल में विकसित सिंचाई क्षेत्रफल एवं बड़ी योजनाओं पर सरकार द्वारा व्यय की गई राशि प्रदर्शित है—

सारणी 213

देश में सिंचाई सुविधाओं का विकास

योजना-काल	उपलब्ध सिंचित क्षेत्र (मिलियन हेक्टर)	बड़ी सिंचाई योजनाओं पर किया गया व्यय राशि (करोड़ रुपये)
योजनाकाल से पूर्व (1950-51)	22.60	—
प्रथम योजना (1951-56)	26.26	313
द्वितीय योजना (1956-61)	29.08	428
तृतीय योजना (1961-66)	33.61	665
वार्षिक योजनाएँ (1966-69)	37.10	457
चतुर्थ योजना (1969-74)	44.20	1354
पाँचवी योजना (1974-79)	52.02	3434
छठी योजना (1980-85)	67.50	8448
सातवी योजना (1985-90)	80.44	11556

सातवी योजना के अन्त तक 80 मिलियन हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। अतः तकनीकी ज्ञान विकास का लाभ इन्हीं क्षेत्रों के कृषकों को प्रमुखतया प्राप्त हुआ है। सिंचाई सुविधाओं का विकास हरित क्रान्ति में गति साने के लिए आवश्यक है।

(6) उर्वरकों का उपयोग—कृषि में तकनीकी ज्ञान के प्रसार के लिए उर्वरकों के उत्पादन एवं उपयोग में वृद्धि करना भी आवश्यक है। उन्नत किस्मों के बीजों के उपयोग द्वारा फसलों की अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए उर्वरकों का सन्तुलित मात्रा में सही समय पर उपयोग करना होता है। बहुफलमयी कार्यक्रम के अन्तर्गत उर्वरकों की आवश्यकता में पहले की अपेक्षा वृद्धि हुई है। सारणी 21.4 देश में उर्वरक उत्पादन, आयात एवं उपयोग की मात्रा प्रदर्शित करती है।

उर्वरकों का उत्पादन स्वतन्त्रता के समय बहुत कम था। अतः उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए स्वतन्त्रता के उपरान्त देश में अनेक उर्वरक कारखाने सार्वजनिक, सहकारी एवं निजी क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। देश में उर्वरकों का उत्पादन जो वर्ष 1951-52 में मात्र 0.273 लाख टन था, वह बढ़कर 1990 में 90.40 लाख टन हो गया। उर्वरकों का आयात भी काफी मात्रा में है।

उर्वरक के आयात में वर्ष 1985-86 तक निरन्तर वृद्धि हुई है। तत्परन्तु उसमें कमी आई है और पिछले 3 वर्षों से इनकी मात्रा में पुनः वृद्धि हुई है। वर्ष 1910 तक देश की उर्वरक आवश्यकता का लगभग 50 प्रतिशत भाग आयात से ही पूरा होता था। आज भी पोटाश उर्वरक की पूर्ण पूर्णतया आयात की मात्रा से ही होती है। उर्वरक उपयोग में भी इस काल में द्रुत गति से वृद्धि हुई है। वर्ष 1951-52 में उर्वरक उपयोग मात्र 0.218 लाख टन था, जो 1990-91 में 126.77 लाख टन हो गया। उर्वरक उपयोग में तीव्र गति से वृद्धि होने के उपरान्त भी प्रति हेक्टर कृषि भूमि क्षेत्र पर उर्वरक उपयोग देने में विकसित देशों की अपेक्षा कम है। भारत में उर्वरक उपयोग वर्ष 1951-52 में 0.6 किलोग्राम प्रति हेक्टर हो था, जो बढ़कर वर्ष 1989-90 में 68.7 किलोग्राम प्रति हेक्टर हो गया। विभिन्न राज्यों में भी उर्वरक उपयोग में बहुत असमानता व्याप्त है।

सारणी 21.4

भारत में उर्वरक उत्पादन, आयात एवं उपयोग

वर्ष	उत्पादन	आयात	उपयोग
1951-52	0.273	0.380	0.218*
1956-57	1.003	0.564	1.526**
1961-62	2.242	1.739	3.382
1965-66	3.550	4.159	7.750
1970-71	10.590	6.295	21.770
1975-76	24.850	15.507	28.940
1980-81	30.050	27.590	55.160
1985-86	57.560	33.990	84.740
1986-87	70.700	23.100	86.450
1987-88	71.310	9.840	87.840
1988-89	89.640	16.080	110.360
1989-90	85.430	31.140	116.950
1990-91	90.440	27.580	126.770
1991-92	100.00	27.930	136.000

* = Excluding Nitrogen

** = Excluding K_2O

स्रोत : Economic Survey, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi—Various Issues.

7. पौध संरक्षण सुविधा—कृषि में तकनीकी ज्ञान के प्रसार के लिए पौध संरक्षण सुविधा का विकास भी महत्वपूर्ण है। उन्नत किस्म के बीज, बीमारियों एवं कीड़े मकोड़ों से अधिक प्रभावित होते हैं। वर्ष 1950-51 में कुल कीटनाशी दवाईयों का उपभोग मात्र 2 35 हजार टन था, जो बढ़कर वर्ष 1960-61 में 8.62 हजार टन, वर्ष 1970-71 में 24 31 हजार टन, वर्ष 1980-81 में 45 हजार टन एवं वर्ष 1984-85 में 56 हजार टन हो गया। वर्ष 1990-91 में इनके उपभोग का स्तर 80 हजार टन होने का आकलन है। कीटनाशी दवाईयों के उपभोग में इस दर से वृद्धि के बावजूद भी प्रति हेक्टर उपभोग का स्तर विकसित देशों से बहुत कम है। कीटनाशी दवाईयों का उपभोग स्तर वर्ष 1955-56 में 16 ग्राम प्रति हेक्टर था, जो बढ़कर 1970-71 में 147 ग्राम व 1984-85 में 317 ग्राम प्रति हेक्टर हो गया। अमेरिका में कीटनाशी दवाईयों का उपभोग स्तर 1490 ग्राम प्रति हेक्टर तथा जापान में 10,790 ग्राम प्रति हेक्टर है। भूत देश में उन्नत किस्मों के बीजों के क्षेत्र में वृद्धि के साथ-साथ पौध संरक्षण उपायों के उपभोग स्तर में वृद्धि होना भी आवश्यक है।

(8) विद्युतीकरण का प्रसार—कृषि में उपलब्ध तकनीकी ज्ञान के प्रसार के लिए गांवों तक विद्युतीकरण करना भी अति आवश्यक है। कृषि क्षेत्र में विद्युतीकरण का उपयोग सिंचाई हेतु कुम्भों से जल निकालने, ग्रंसर चलाने, कुट्टी काटने की मशीन चलाने, गन्ना पेलने के कोल्हू चलाने आदि कार्यों में किया जाता है। विद्युत् उपलब्ध होने पर विभिन्न कृषि-कार्य जैसे सिंचाई, फसल की गहवाई, आदि समय पर एवं उचित दक्षता से कम खर्च पर सम्पन्न होते हैं।

कृषि क्षेत्र विद्युत् उपभोग का एक प्रमुख स्रोत है। इस क्षेत्र में विद्युत् उपभोग निरन्तर बढ़ता जा रहा है। कृषि क्षेत्र में विद्युत् उपभोग वर्ष 1950-51 में मात्र 20 3 मिलियन किलोवाट था, जो बढ़कर वर्ष 1965-66 में 1892 मिलियन किलोवाट तथा 1984-85 में 20,500 मिलियन किलोवाट हो गया। उपलब्ध विद्युत् शक्ति का कृषि क्षेत्र में उपभोग का स्तर 1950-51 में 3 9 प्रतिशत था जो बढ़कर 1960-61 में 6 1 प्रतिशत, 1970-71 में 10 2 प्रतिशत, 1980-81 में 17.6 प्रतिशत एवं 1990-91 में 26 0 प्रतिशत हो गया। विभिन्न राज्यों में विद्युत् उपभोग स्तर में बहुत भिन्नता है, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान एवं उत्तरप्रदेश राज्यों में पूर्वी क्षेत्र के राज्यों की अपेक्षा विद्युत् उपभोग का स्तर अधिक है।

गांवों एवं कृषि क्षेत्र के विकास में विद्युतीकरण की महत्ता के कारण इसके प्रसार के लिए सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है। वर्ष 1960 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की पृथक् रूप में स्थापना की है, जिसका प्रमुख उद्देश्य विद्युतीकरण द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देना है। ग्रामीण विद्युतीकरण

निगम की स्थापना के पश्चात् गाँवों में विद्युतीकरण पहुँचाने एवं विद्युत् चलित सिंचाई के पम्पसेटों की संख्या में बहुमुखी प्रगति हुई है। ग्रामीण विद्युतीकरण के कारण देश में सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि, कृषकों के फार्मों पर कृषित क्षेत्र में वृद्धि, फसलों से अधिक उत्पादन एवं कृषि क्षेत्र से प्राप्त लाभ की राशि में वृद्धि हुई है। सारणी 21.5 में विद्युत् उपलब्ध गाँवों की संख्या एवं विद्युत् चलित पम्पसेटों की संख्या दर्शाती है।

सारणी 21.5

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् उपलब्धता

वर्ष	विद्युत् उपलब्ध गाँवों की प्रणामी संख्या	कुल गाँवों का प्रतिशत	विद्युत् चलित पम्प सेटों की प्रणामी संख्या (लाख)
अप्रैल, 1, 1951	3,061	0.53	0.21
अप्रैल, 1, 1961	21,754	3.78	1.98
अप्रैल, 1, 1969	73,939	12.84	10.89
अप्रैल, 1, 1980	249,799	43.76	34.49
जुलाई, 1, 1987	413,754	71.80	67.32
अगस्त, 1, 1991	481,956	83.20	89.92

Source Indian Agriculture in Brief—various Issues, Directorate of Economics and Statistics, Ministry of Agriculture, Government of India, New Delhi.

वर्तमान में देश में 4.82 लाख गाँवों (83.20 प्रतिशत) एवं 89.92 लाख पम्पसेट पर विद्युत् सुविधा उपलब्ध है। वर्ष 1995 तक देश के सभी गाँवों तक विद्युत् सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। विद्युत् चलित पम्पसेटों की संख्या में भी द्रुतगति से वृद्धि हुई है। बीजल तेल से चलित पम्पसेटों के संचालन में लागत की अधिकता एवं बीजल उपलब्ध नहीं होने के कारण भी विद्युत् चलित पम्प सेटों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

(9) मशीनीकरण—कृषि में मशीनीकरण का होना भी तकनीकी ज्ञान के प्रसार के लिए अति आवश्यक है। कृषि में मशीनों के उपयोग से कृषि कार्य उचित समय पर, उचित दक्षता तक न्यूनतम लागत पर कर पाना संभव हो गया

है। कृषि-क्षेत्र में प्रमुखतया ट्रैक्टर, पम्पसेट, ग्रैंसर, पावर टिलर एवं स्प्रेयर तथा डस्टर उपयोग में लिए जाते हैं।

सिंचाई की आवश्यकता में वृद्धि के साथ-साथ डीजल चलित एवं विद्युत् चलित पम्पसेटों की संख्या में वृद्धि हुई है। पूर्व में कृषक अपने कुओं से पानी निकालने का काम चरसे द्वारा किया करते थे, जिसमें समय अधिक लगने के कारण बहुत कम क्षेत्र में सिंचाई प्रति दिन हो पाती थी। वर्ष 1950-51 में मात्र 87 हजार पम्पसेट कार्यरत थे, जो बढ़कर 1960-61 में 4.28 लाख, 1968-69 में 18.10 लाख, 1979-80 में 61.02 लाख एवं 1990-91 में 133.47 लाख हो गए।

कृषि भूमि के बढ़ते क्षेत्र को उचित गहराई तक जोतने में ट्रैक्टरों की भी प्रमुख भूमिका है। पूर्व में यह कार्य बैलों की शक्ति से किए जाते थे जिनमें समय एवं धन अधिक व्यय होना था। ट्रैक्टर भूमि को कृषि करने के प्रतिरिक्त, माल ढोने तथा अन्य मशीनों जैसे ग्रैंसर चलाने, कुट्टी काटने, स्प्रेयर चलाने तथा सिंचाई के पम्पसेट चलाने में भी काम आते हैं। वर्ष 1960 के पूर्व ट्रैक्टर का उत्पादन देश में नहीं होता था, अतः आयात ही किए जाते थे। ट्रैक्टर का देश में उत्पादन वर्ष 1960 में प्रारम्भ हुआ था। वर्तमान में 1.40 लाख ट्रैक्टर का उत्पादन देश में 15 इकाईयों द्वारा प्रति वर्ष होता है। देश में वर्ष 1951 में कुल 8,635 ट्रैक्टर उपयोग में थे, जो बढ़कर 1961 में 31,016, 1971 में 1,43,000, 1981 में 5,72,973 एवं 1991 में 14.68 लाख हो गए। ट्रैक्टर के उपयोग साथ-साथ पावर टिलर का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। वर्ष 1970-71 में जहाँ पावर टिलर का उत्पादन 1387 ही था, जो बढ़कर 1990-91 में 6228 पहुँच गया। अधिक उत्पादन का समय पर कटाई एवं गहवाई हेतु कम्बाइन्ड हारवेस्टर का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। वर्ष 1987-88 में इनका उत्पादन 149 का था जो 1990-91 में 337 प्रति वर्ष हो गया। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में विभिन्न फार्म मशीनरी का उपयोग भी बढ़ा है। इनके होने में कृषक बहुफसली कार्यक्रम आसानी से अपनाकर, उत्पादित उत्पादों को समय पर बाजार में विपणन हेतु लाने में सक्षम हो पाये हैं।

नए तकनीकी ज्ञान विकास के उपरोक्त अवयवों के सम्मिलित प्रभाव के कारण देश में खाद्यान्न उत्पादन में हुई वृद्धि को सारणी 21.6 में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 21.6

सहजीवी क्षान विकास व विभिन्न व्ययवर्गों का साक्षात् उत्साहले पर प्रभाव

वर्ष	साक्षात् उत्साह (मि टन)	कृषि वृषित क्षेत्र (मि हेक्टर)	कृषि उत्पादित क्षेत्र (मि हेक्टर)	उत्पादित (मि टन)	उत्पादित (मि टन)	उत्पादित (मि टन)	उत्पादित (मि टन)	उत्पादित (मि टन)	उत्पादित (मि टन)
1961-62		156 21	28 46	—	2 00				
1962-63	80 33	156 76	29 45	—	452	NA			
1965-66	72 35	155 28	30 90	—	785	14 63			
1966-67	74 23	157 35	32 68	1 89	1101	NA			
1970-71	108 42	165 80	38 09	13 70	2177	24 31			
1975-76	121 03	171 30	43 38	31 89	2894	NA			
1980-81	129 90	173 10	49 88	43 07	5516	45 00			
1981-82	133 00	177 04	51 55	46 05	6067	NA			
1982-83	129 52	173 34	52 12	47 48	6390	NA			
1983-84	152 37	180 36	53 94	53 74	7710	NA			
1984-85	145 54	176 42	54 08	54 14	8210	56 00			
1985-86	150 44	178 83	54 65	55 42	8470	NA			
1986-87	143 42	176 92	55 64	56 12	8645	NA			
1987-88	140 350	NA	59 33	51 23	8784	49 00			
1988-89	170 250	180 10	58 50	62 60	11,036	84 70			
1989-90	169 92	182 5	NA	61 30	11 695				
1990-91	176 50			62 90	12,677				
1991-92	169 20								

हरित क्रान्ति (Green Revolution)

हरित क्रान्ति, हरित एव क्रान्ति शब्द के मिलने से बना है। क्रान्ति से तात्पर्य किसी घटना में द्रुतगति से परिवर्तन होने तथा उन परिवर्तनों का प्रभाव आने वाले लम्बे समय तक रहने से है। हरित शब्द कृषि फसलों का सूचक है। अतः हरित क्रान्ति से तात्पर्य कृषि-उत्पादन में अल्पकाल में विशेष गति से वृद्धि का होना तथा उत्पादन की वह वृद्धि-दर आने वाले लम्बे समय तक बनाये रखने से है।

दूसरे शब्दों में हरित क्रान्ति से अग्निप्राय देश के सिंचित एवं अर्धसिंचित कृषि-क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले सकर एवं बीनी किस्म के बीजों के उपयोग द्वारा कृषि-उत्पादन में द्रुतगति से वृद्धि करना है। अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के बीजों द्वारा कृषि-उत्पादन में वृद्धि करना अथवा कृषि विकास के क्षेत्र में अपनाये जा रहे नये तकनीकी ज्ञान को ही "हरित क्रान्ति" का नाम दिया गया है।

हरित क्रान्ति का प्रादुर्भाव—देश में कृषि-क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान का आविष्कार एवं उसका वृहत स्तर पर उपयोग, उन्नत एवं अधिक उत्पादन देने वाले सकर एवं बीने किस्म के बीजों का आविष्कार, विभिन्न उर्वरकों का अधिक मात्रा में उत्पादन एवं उनका सन्तुलित मात्रा में उपयोग, सिंचाई सुविधाओं का विकास, कीटनाशी दवाइयों का उपयोग, कृषि क्षेत्र में उन्नत मशीन एवं मशीनों का अधिकाधिक उपयोग, कृषि में विद्युतीकरण, कृषि क्षेत्र में ऋण का विस्तार, कृषि-शिक्षा एवं विस्तार कार्यक्रमों के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 1966-67 के उपरान्त काल में उत्पादन में तीव्रगति से वृद्धि हुई है। उत्पादन वृद्धि की इस असाधारण गति दर को देश के कृषि वैज्ञानिकों ने हरित-क्रान्ति का नाम दिया है। अतः हरित क्रान्ति का देश में प्रादुर्भाव वर्ष 1966-67 के उपरान्त काल में हुआ है। हरित-क्रान्ति के जन्मदाता का श्रेय नोबल पुरस्कार विजेता प्रो० नोरमन बोरलोग को है।

हरित क्रान्ति के प्रादुर्भाव के पूर्व, कृषक फार्म पर उत्पादन बढ़ाने के लिए पुरानी विधियों, फार्म पर उत्पादित वीज एवं खाद तथा उत्पादन वृद्धि के लिए आवश्यक अन्य उत्पादन साधन, जैसे—कृषि ऋण कीटनाशी दवाइयाँ आदि का कम मात्रा में उपयोग करते थे, जिसके कारण उन्हें भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र से उत्पादन की मात्रा कम प्राप्त होती थी। हरित क्रान्ति के कारण कृषक प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक उत्पादन की मात्रा प्राप्त कर रहे हैं और वे अब निश्चलता (Stagnation) की स्थिति से बाहर आकर गतिशीलता के क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं।

कृषि-उत्पादन में वृद्धि की यह असाधारण गति कृषि में तकनीकी ज्ञान विकास के विभिन्न अवयवों के सम्मिलित प्रयास का ही प्रतिफल है। इन सब उपायों

को सम्मिलित या पेंकेज रूप में अपनाने से ही कृषि-उत्पादन में यह उत्पादन वृद्धि-दर प्राप्त हो पाई है। अतः हरित क्रान्ति के प्रमुख अवयवों में वे सभी पहलू सम्मिलित होते हैं जो तकनीकी ज्ञान विकास के होते हैं।

हरित क्रान्ति का कृषि-क्षेत्र पर प्रभाव—हरित क्रान्ति के कारण देश के सभी जोत एवं क्षेत्र के कृषकों को लाभ प्राप्त हुआ है। यह लाभ कृषकों को फार्म पर प्रति इकाई भूमि के क्षेत्र से उत्पादकता एवं आय में वृद्धि के कारण प्राप्त होता है। कृषकों को लाभ की राशि उनके द्वारा प्रायोगिक ज्ञान स्तर की विभिन्नता के कारण समान राशि में प्राप्त नहीं होकर उनके द्वारा अपनाए गए तकनीकी ज्ञान स्तर की विभिन्नता के कारण विभिन्न राशि में प्राप्त होता है। अतः हरित क्रान्ति के कारण दीर्घ जोत कृषकों एवं समृद्ध कृषकों को लघु जोत कृषकों की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त हुआ है। हरित क्रान्ति के प्रति अधिक एवं कम राशि में लाभ प्राप्त करने वाले सभी कृषक जागरूक हैं, लेकिन प्राप्त आय की असमानता ने उनके मध्य सामाजिक विषमताओं को भी जन्म दिया है। अतः हरित क्रान्ति का कृषि-क्षेत्र में आने वाले प्रभावों को आर्थिक प्रभाव (Economic impact) एवं सामाजिक प्रभाव (Sociological impact) की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

हरित क्रान्ति का आर्थिक प्रभाव—हरित क्रान्ति द्वारा कृषि-क्षेत्र में आए आर्थिक प्रभाव दो प्रकार के हैं :

- (i) कृषि-उत्पादों की प्रति इकाई भूमि-क्षेत्र से उत्पादकता में वृद्धि, एवं
- (ii) कृषि-उत्पादन की मात्रा में वृद्धि।

उपरोक्त दोनों ही प्रकार के प्रभावों से कृषि-क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि के कारण फार्म पर उत्पादित उत्पादों की प्रति इकाई मात्रा पर उत्पादन-लागत में कमी आई है। कृषकों को अपने फार्म-क्षेत्र से पूर्व की अपेक्षा अधिक शुद्ध लाभ की राशि प्राप्त होने लगी है, जिससे उनके आर्थिक स्तर में सुधार हुआ है।

कृषि-उत्पादों की उत्पादकता में वैसे तो स्वतन्त्रता के उपरान्त निरन्तर वृद्धि हुई है, लेकिन उत्पादकता में वृद्धि की दर वर्ष 1965-66 के उपरान्त विशेष दर में हुई है। कृषि-उत्पादों में यह वृद्धि खाद्यान्नों में सर्वाधिक तथा खाद्यान्न समूह में गेहूँ एवं चावल में सर्वाधिक पाई गई है। गेहूँ की प्रति हेक्टर उत्पादकता का स्तर वर्ष 1969-70 में 1209 किलोग्राम एवं चावल का 1073 किलोग्राम था, जो बढ़कर वर्ष 1989-90 में क्रमशः 2117 किलोग्राम एवं 1756 किलोग्राम हो गया। इसी प्रकार ज्वार, बाजरा एवं मक्का खाद्यान्नों की उत्पादकता में भी 15 से 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

हरित क्रान्ति के आर्थिक प्रभाव का दूसरा पहलू देश में कृषि-उत्पादन की कुल मात्रा में वृद्धि होना है। हरित क्रान्ति के प्रादुर्भाव के पश्चात् कृषि-उत्पादन एवं विशेषकर खाद्यान्नों के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। हरित क्रान्ति के

पूर्व वर्ष 1965-66 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 72.347 मिलियन टन था, जो बढ़कर वर्ष 1970-71 में 108 422 मिलियन टन, वर्ष 1980-81 में 129 590 मिलियन टन तथा वर्ष 1983-84 में 152 37 मिलियन टन हो गया। मूला के कारण वर्ष 1986-87 व 1987-88 में उत्पादन में गिरावट आई है। वर्ष 1990-91 में 176.50 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। इस प्रकार हरित क्रान्ति के प्रादुर्भाव के पश्चात् पिछले 25 वर्षों में खाद्यान्नों के उत्पादन स्तर में 100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। खाद्यान्नों में सर्वाधिक उत्पादन वृद्धि गेहूँ में हुई है।

वर्ष 1965-66 में देश में गेहूँ का कुल उत्पादन मात्र 10 3॥ मिलियन टन था, जो बढ़कर वर्ष 1990-91 में 54 6 मिलियन टन अर्थात् 5 गुना से अधिक हो गया। ऐसा सप्ताह के इतिहास में अद्वितीय है। उपरोक्त काल में घावल के उत्पादन में 90 प्रतिशत वृद्धि अर्थात् उत्पादन-स्तर 40 मिलियन टन से 75 मिलियन टन पहुँच गया। उत्पादन में वृद्धि से कृषकों के आय-स्तर में वृद्धि हुई है। गेहूँ के उत्पादन-क्षेत्रों के कृषकों की आय में अन्य क्षेत्र के कृषकों की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई है, जिससे कृषकों के रहन-रहन स्तर में बहुत परिवर्तन आया है।

हरित क्रान्ति का सामाजिक प्रभाव :

हरित क्रान्ति के उपरोक्त प्राथमिक प्रभावों के फलस्वरूप सामाजिक विषमताएँ भी उत्पन्न हो गई हैं। विभिन्न जोत स्तर के कृषकों एवं विभिन्न क्षेत्रों के कृषकों की प्राप्त आय में विषमता में वृद्धि के कारण वैमनस्यता की भावना को जाग्रत कर दिया है। हरित क्रान्ति के कारण सामाजिक क्षेत्र में उत्पन्न प्रभाव निम्न दो प्रकार के हैं—

(i) कृषकों की व्यक्तिगत आय असमानता में वृद्धि—हरित क्रान्ति के फल-स्वरूप धनी अथवा दीर्घ जोत कृषक पूर्व की अपेक्षा अधिक धनी हो गए हैं तथा गरीब अथवा लघु कृषकों की आय के स्तर में विशेष वृद्धि नहीं होने से वे दूसरे कृषकों की तुलना में गरीब होते जा रहे हैं। इस प्रकार दोनों वर्गों के मध्य पाई जाने वाली आय के अन्तर में वृद्धि हुई है।

वैज्ञानिकों का मानना है कि नया तकनीकी ज्ञान स्तर अथवा हरित क्रान्ति उत्पादन के पैमाने के प्रति उदासीन (Neutral to Scale) होता है। अर्थात् सभी जोत स्तर के कृषक तकनीकी ज्ञान के उपयोग से समान उत्पादकता स्तर एवं लाभ की राशि प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकी दृष्टिकोण से वैज्ञानिकों का यह दृष्टिकोण सही है, लेकिन सस्यागत कारणों से दीर्घ जोत अथवा धनी कृषक हरित क्रान्ति से लघु जोत कृषकों की अपेक्षा वास्तविक परिस्थिति में अधिक लाभ प्राप्त कर पाने में सक्षम होते हैं।

इस प्रकार विभिन्न दर पर लाभ प्राप्त होने का प्रमुख कारण नये तकनीकी ज्ञान के उपयोग स्तर में छन्नर का होना है। नये तकनीकी ज्ञान स्तर के अपनाने में विभिन्नता का कारण आवश्यक राशि में पूँजी का उपलब्ध नहीं होना है। नया तकनीकी ज्ञान अर्थात् उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशी दवाइयाँ, रिचार्ज के लिए विद्युत्। डीजल तेल का उपयोग, उन्नत कृषि-यन्त्रों के प्रयत्न करने आदि-के अपनाने से फसलों के कृषि करने पर प्रति हेक्टर व्यय राशि अधिक आती है। उत्पादन में वृद्धि के लिए नये तकनीकी ज्ञान स्तर के विभिन्न पहलू अर्थात् कृषि निविष्टों को सम्मिलित या पैकेज रूप में उपयोग करने से ही निर्धारित उत्पादन स्तर या आय प्राप्त हो सकती है। इसके लिए कृषक को पहले की अपेक्षा अधिक राशि में पूँजी की आवश्यकता होती है। पूँजी का इतनी अधिक मात्रा में लघु एवं मध्यम जोत अथवा निर्धन कृषकों के लिए निवेश कर पाना सम्भव नहीं होता है, क्योंकि उनके पास सधन की गई धन राशि का अभाव होता है। साथ ही इन कृषकों को मत्पायत अभिकरणों से प्रतिभूति के अभाव में आवश्यक राशि में ऋण सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पाती है।

अतः आवश्यक राशि में धन के अभाव में कृषक विभिन्न कृषि निविष्टों को सिफारिश मात्रा में उपयोग नहीं कर पाते हैं जिससे लघु एवं सीमान्त कृषकों अथवा निर्धन कृषकों को हरित क्रान्ति का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। दूसरी ओर दीर्घ जोत या समृद्ध कृषक विभिन्न कृषि निविष्टों का उपयोग सिफारिश मात्रा में कर पाते हैं। उनके पास धन का अभाव नहीं होता है। स्वयं की पर्याप्त वसत राशि के अतिरिक्त वे सत्पायत अभिकरणों से भी पर्याप्त राशि में ऋण प्राप्त कर पाने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार हरित क्रान्ति के कारण वास्तविक परिस्थिति में विभिन्न स्तर के कृषकों को प्रति इकाई भूमि के क्षेत्र अथवा फार्म से प्राप्त लाभ की कुल राशि में बहुत अन्तर पाया जाता है। अतः धनी कृषक पूर्व की अपेक्षा अधिक धनी हो गये हैं। इससे दोनों वर्गों के कृषकों के मध्य पायी जाने वाली आय के अन्तर में निरन्तर वृद्धि होने से कृषक समाज धनी एवं निर्धन वर्ग में विभक्त होता जा रहा है। इस आय-असमानता की बढ़ती हुई खाई ने उनमें आपस में वैमनस्यता की भावना जागृत कर दी है।

नये तकनीकी ज्ञान स्तर के उपयोग में जोखिम की अधिकता के कारण लघु एवं निर्धन वर्ग के कृषक जोखिम वहन क्षमता के कम होने के कारण इस ज्ञान को देर से फार्म पर अपनाते हैं, जबकि दीर्घ जोत कृषक तकनीकी ज्ञान को शीघ्र अपनाते हैं। इससे दीर्घ जोत कृषकों को तकनीकी ज्ञान के अपनाने के प्रारम्भिक वर्षों में अधिक लाभ की राशि प्राप्त होती है। धीरे-धीरे अन्य कृषक जब उस ज्ञान-स्तर को अपनाते हैं तो प्रतिस्पर्धा के बढ़ने से लाभ की राशि कम होती जाती है। अतः लघु एवं निर्धन कृषकों को नये तकनीकी ज्ञान से लाभ की राशि ही कम प्राप्त

नहीं होती है बल्कि उन्हें यह लाभ देर में भी प्राप्त होता है। इस प्रकार इससे भी आय-असमानता की विषमता के बढ़ने में सहयोग मिलता है।

(iv) विभिन्न क्षेत्र के कृषकों की आय-असमानता में वृद्धि होना (Increased income disparities among the regions)—हरित क्रान्ति का दूसरा सामाजिक प्रभाव देश के विभिन्न राज्यों एवं एक ही राज्य के विभिन्न क्षेत्र के कृषकों की आय-असमानता में विषमता का होना है। हरित क्रान्ति का लाभ उन्हीं क्षेत्रों के कृषकों को अधिक प्राप्त हुआ है जिन क्षेत्रों में पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। पर्याप्त सिंचाई सुविधा नहीं होने वाले क्षेत्रों में अथवा भूखे क्षेत्रों में उन्नत एवं सफल किस्म के बीज, उर्वरक आदि कृषि निविष्टों का उपयोग सम्भव नहीं होता है। सिंचाई की सुविधा देश के सभी राज्यों एवं राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में समान नहीं है।

वर्तमान में देश के 36 प्रतिशत क्षेत्र में ही सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है एवं शेष 64 प्रतिशत क्षेत्र कृषि उत्पादन के लिए वर्षा पर निर्भर है। पंजाब एवं हरियाणा राज्य में सिंचाई की सुविधा अन्य राज्यों की अपेक्षाकृत अधिक है। राजस्थान राज्य के गंगानगर एवं कोटा जिलों में सिंचाई की सुविधा नहरों के विस्तार के कारण अन्य जिलों की अपेक्षा अधिक है। इस कारण इन राज्यों एवं क्षेत्रों के कृषकों का पर्याप्त सिंचाई सुविधा की उपलब्धि के कारण हरित क्रान्ति का लाभ अधिक प्राप्त हुआ है तथा अन्य क्षेत्रों के कृषकों को लाभ कम प्राप्त हुआ है। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध सिंचाई सुविधा के कारण क्षेत्रिक आय-असमानता में वृद्धि हुई है। जो क्षेत्र पहले समृद्धशाली थे, वे हरित क्रान्ति के कारण अधिक समृद्धशाली हो गये हैं और पिछड़े राज्य क्षेत्र अधिक पिछड़ गए हैं। इस प्रकार विभिन्न राज्यों एवं क्षेत्रों के विकास में विषमता के कारण, उनकी समृद्धि में अंतर उत्पन्न हो गया है।

(9) लघु कृषकों का विकास—स्वतन्त्रता के पश्चात् देश में अपनाए गए विभिन्न विकास कार्यक्रमों से जो लाभ कृषक-वर्ग को प्राप्त हुआ है, उसमें विभिन्न जोतों के कृषकों को प्राप्त लाभ की राशि में बहुत विषमता है। इस बात पर सभी एक मत हैं कि देश के लघु कृषकों को उनकी कुल सख्या के अनुपात में विभिन्न विकास कार्यक्रमों से दीर्घ एवं मध्यम जोत वाले कृषकों के समान लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

देश के कृषकों को विभिन्न श्रेणी में विभक्त करने के लिए विभिन्न मापदण्ड जैसे—जोत का आकार, तकनीकी ज्ञान का उपयोग स्तर, फार्म-सम्पत्ति की राशि, कृषि-व्यवसाय से प्राप्त आय की राशि आदि को आधार माना जाता रहा है, लेकिन उपर्युक्त पैमानों में जोत का आकार मुख्य रूप से कृषकों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाता है। साधारणतः 5 एकड़ अथवा

2 हेक्टर से कम भूमि क्षेत्र के कृषकों को लघु कृषकों की श्रेणी में विभक्त किया जाता है। टुपि-समय 1970-71 के अनुसार देश में लघु जोतों का प्रतिशत 69.7, 1980-81 के अनुसार 74.6 प्रतिशत एवं 1985-86 में 76.4 प्रतिशत है। लघु टुपों की प्रतिशतता अधिक होते हुए भी उनके पास कुल भूमि का क्षेत्र मात्र 28.8 प्रतिशत ही है।

लघु-कृषकों की समस्याएँ—लघु-कृषकों की प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं—

- (i) जोत का आकार कम होना एवं जोत के विभिन्न खण्डों के विभिन्न स्थानों पर होना।
- (ii) आवश्यक मात्रा में उत्पादन-साधन समय पर उपलब्ध नहीं होना।
- (iii) लघु जोत वाले टुपों को टुपि की उन्नत विधियों की जानकारी नहीं होना।
- (iv) उचित समय एवं कम ब्याज दर पर आवश्यक राशि में ऋण-सुविधा उपलब्ध नहीं होना।
- (v) वर्ष में अधिक समय तक काम उपलब्ध नहीं होने से बेरोजगार रहना।
- (vi) काम पर विनयेय-अधिकेय की मात्रा के कम होने के कारण उत्पादों के विपणन पर प्रति इकाई विपणन-लागत अधिक होना।
- (vii) टुपि कार्यों के लिए यांत्रिक सुविधा का उपयोग नहीं हो पाने के कारण प्रति इकाई उत्पादन-लागत अधिक होना।

उपरोक्त समस्याओं के कारण देश के लघु एवं दीर्घ जोत के कृषकों की आय में विषमता बढ़ती जा रही है। सरकार लघु कृषकों की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रयत्नशील है। लघु कृषकों को राहत पहुँचाने के लिए सरकार ने निम्न योजनाएँ शुरू की हैं—

- (i) सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छोटी-छोटी सिंचाई की योजनाएँ गाँवों में शुरू की गई हैं।
- (ii) बेरोजगारी को दूर करने के लिए गाँवों में सरकार ने रोजगार उपलब्ध के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं।
- (iii) लघु कृषकों को कम ब्याज की दर एवं उचित समय पर ऋण-सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यांत्रिक बैंकों के द्वारा विशेष सुविधाएँ प्रदान करने की व्यवस्था की गई है जैसे—रियायती ब्याज दर पर ऋण सेवा, भूमि को बन्धक रखे बिना ऋण प्रदान करना, उत्पादन के साथ-साथ उपभोग ऋण-सुविधा प्रदान करना, गाँवों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाओं का विस्तार करना आदि।

- (iv) सरकार ने लघु कृषकों के विकास के लिए लघु-कृषक विकास संस्थाएँ स्थापित की हैं।

लघु-कृषक विकास संस्थाएँ :

लघु-कृषक विकास संस्थाएँ देश में उन गरीब कृषकों की समस्याओं को दूर करने के लिए स्थापित की गई हैं, जिन्हें देश में कार्यरत विकास योजनाओं से आवश्यक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। ये योजनाएँ श्री बी वेकटर्पैया की अध्यक्षता में नियुक्त अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण जाँच समिति, 1969 के सुझावों के आधार पर शुरू की गई हैं। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि सहकारी समितियाँ, वाणिज्यिक बैंक तथा विकास की अन्य संस्थाओं ने लघु एवं सीमान्त कृषकों की समस्याओं के समाधान के लिए वर्तमान में ध्यान नहीं दिया है। देश के विकास के लिए लघु कृषकों का विकास भी अति आवश्यक है। भारत सरकार ने श्री बी वेकटर्पैया समिति की सिफारिश पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 46 बुने हुए जिलों में लघु कृषकों के विकास के लिए विशेष योजनाएँ धालू की थी, जिन पर केन्द्रीय बजट में 67 ½ करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान था। इन संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य उन क्षेत्रों के 50,000 लघु कृषक परिवारों को लाभान्वित करना था।

लघु-कृषक विकास संस्था के कार्य—लघु-कृषक विकास संस्था के प्रमुख कार्य निम्न हैं—

- (i) लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा खेतिहर मजदूरों की समस्याओं का सर्वेक्षण द्वारा पता लगाना एवं उन्हें आवश्यक मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक कार्यक्रम तैयार करना।
- (ii) विभिन्न ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए प्रयत्न करना।
- (iii) लघु कृषकों को उत्पाद के संग्रहण एवं विपणन की उचित सुविधा प्रदान करना।
- (iv) क्षेत्र-विशेष की क्षमताओं पर आधारित योजना निर्मित करना एवं कार्यान्वित योजना का समय समय पर मूल्यांकन करना।
- (v) लघु एवं सीमान्त कृषकों का सहकारी संस्थाओं, तकनीकी एवं प्रशासकीय व्यक्तियों की सेवा उपलब्ध कराना एवं उन्हें सहायता देने के लिए विभिन्न संस्थाओं को प्रेरित करना।
- (vi) लघु कृषकों एवं खेतिहर मजदूरों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- (vii) लघु कृषकों को आवश्यक उत्पादन-साधन उपलब्ध कराने में सहायता करना।

(viii) लघु कृषकों की आय में वृद्धि करने के लिए पशु-पालन, कुक्कुट-पालन, भेड़-पालन, आदि योजनाओं को अपनाने में कृषकों की सहायता करना।

लघु कृषक विकास सस्थाओं का प्रबन्ध—लघु-कृषक विकास सस्थाओं का अध्यक्ष क्षेत्र का सम्बन्धित विकास आयुक्त अथवा कृषि-उत्पादन आयुक्त अथवा जिलाधीश होता है। इन सस्थाओं में प्रबन्ध हेतु सरकार एवं स्वायत्त सस्थाओं के प्रतिनिधि जैसे—केन्द्रीय सरकार से दो, राज्य सरकार से तीन, भूमि विकास बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं विपणन समिति से एक-एक प्रतिनिधि, वाणिज्यिक बैंकों से आवश्यकतानुसार, जिला परिषद् का अध्यक्ष एवं राज्य सरकार की सलाह से नियुक्त दो गैर-सरकारी प्रतिनिधि होते हैं। परियोजना अधिकारी सस्था का मदस्य-सचिव होता है। लघु-कृषक विकास सस्थाएँ स्वायत्त सस्थाएँ होती हैं। समिति पञ्जीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पञ्जीकृत होती है। इन सस्थाओं के लिए आवश्यक वित्त केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होता है। लघु-कृषक-विकास सस्था के अन्य कार्यकर्ता राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर लिए जाते हैं।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक लघु-कृषक-विकास समिकरण के लिए 1.5 करोड़ रुपये स्वीकार किये गये हैं। इस राशि में से 5 प्रतिशत प्रशासन पर और शेष 0.5 प्रतिशत प्रत्येक सस्था द्वारा सहायता के रूप में व्यय करने के लिए रखा गया था। यह सहायता कृषकों को उत्पादन-साधनों के न्यय करने, सहकारी समितियों को लघु कृषकों को ऋण देने में होने वाली जोखिम को पूरा करने तथा कृषि-सेवा केन्द्रों को यान्त्रिक सेवा उपलब्ध हेतु केन्द्र स्थापित करने के लिए रखी गई थी।

देश में मार्च, 1974 तक लघु कृषक विकास सस्थाएँ तथा 41 सीमान्त कृषक एवं श्रमिक सस्थाएँ स्थापित हो चुकी थी। राष्ट्रीय कृषि-आयोग ने 16 अगस्त, 1973 को लघु-कृषक विकास सस्थाओं तथा सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक सस्थाओं के पुनर्गठन कार्यक्रम के लिए सरकार को प्रस्तुत प्रतिवेदन में सुझाव दिया कि दोनों सस्थाओं के अन्तर को समाप्त करके, दोनों सस्थाएँ सम्मिलित रूप से एक ही क्षेत्र का चुनाव करें तथा उस क्षेत्र के लघु, सीमान्त एवं कृषि-श्रमिकों के विकास के लिए कार्य करें, जिससे लघु एवं सीमान्त कृषकों एवं कृषि-श्रमिकों की दशा में सुधार हो सके। राष्ट्रीय कृषि-आयोग की सिफारिश पर वर्तमान में इनकी संख्या 168 हो गई है। लघु कृषक विकास सस्थाओं से मार्च, 1980 तक 79.65 कृषक परिवार लाभान्वित हो चुके हैं।

(10) शुष्क भूमि कृषि—भारत का कुल कृषि योग्य क्षेत्र का 63 प्रतिशत क्षेत्र शुष्क है। देश के 128 जिले वर्षा के बहुत कम अथवा मध्यम स्तर के होने तथा सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध न होने से शुष्क क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। इन जिलों की कुल भूमि 77 मिलियन हेक्टर है जो शुद्ध कृषित क्षेत्र का लगभग आधा भाग है। भूले क्षेत्रों से भूमि की उत्पादकता बहुत कम प्राप्त होती है। शुष्क भूमि-क्षेत्र विशेष तौर से तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं

राजस्थान राज्य में हैं। ऐसे क्षेत्रों में मुख्य समस्या जल को संगृहीत करके बेकार जाने से रोकना एवं फसल उत्पादन के लिए कम जल की मात्रा चाहने वाली फसलों का चुनाव करना है।

कृषि में नये तकनीकी ज्ञान विकास के अन्तर्गत शुष्क क्षेत्रों में भी भूमि की प्रति इकाई क्षेत्र से अधिकतम उत्पादन की मात्रा प्राप्त करने का लक्ष्य होता है। सूखे क्षेत्रों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1970-71 में "शुष्क भूमि कृषि-विकास" योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत 12 राज्यों में 24 परियोजनाएँ कार्य कर रही हैं। शुष्क क्षेत्रों में विकास के लिए उपलब्ध तकनीकी ज्ञान के मुख्य प्रयोजन निम्न हैं—

- (i) भूमि प्रबन्ध—सारीय भूमि को ठीक करना एवं उत्पादकता वृद्धि में सुधार के विभिन्न उपाय अपनाना।
- (ii) वाटर हारवेस्टिंग विधि अपनाना।
- (iii) कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए शुष्क क्षेत्रों के उपयुक्त नई विधियों का आविष्कार करना, जैसे—उर्वरकों का पतियों पर छिड़काव आदि।
- (iv) शुष्क क्षेत्रों में उत्पादन के लिए शीघ्र पकने वाली एवं कम जल चाहने वाली किस्मों का आविष्कार करना।

वर्तमान में देश में उत्पादित खाद्यान्नों का 42 प्रतिशत भाग शुष्क क्षेत्रों में प्राप्त होता है। तिलहन, दलहन एवं मोटे अनाज मुख्यतया शुष्क भूमि क्षेत्र पर उत्पादित किए जाते हैं।

(11) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम—योजना आयोग ने छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में पूर्ण पिछले कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करने के उपरान्त महसूस किया कि देश में व्याप्त गरीबी का उन्मूलन करने एवं ग्रामीण विकास हेतु विकास खण्ड स्तर पर एक ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता है, जो उनके लिए उत्पादन साधन बनाते हुए उन्हें स्वतः रोजगार उपलब्ध करा सके। इसी उद्देश्य से एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Integrated Rural Development Programme or I. R. D. P) अप्रैल, 1978 से देश के 2300 विकास खण्डों में प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता देश के ग्रामीण निचले वर्ग (मुख्यतया लघु एवं सीमान्त कृषक, कृषि-श्रमिक व दस्तकार) को स्वतः रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाना है तथा उनके पास आवश्यक उत्पादन साधनों के जुटाने से है, जिनका कि प्रायः उनके पास अभाव होता है। उत्पादन के प्रमुख साधन—सिंचाई सुविधाओं का विकास, औजार, बैल, दुग्ध उत्पादन के लिए पशुपालन उपलब्ध कराना प्रमुख है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विस्तार करके 2 अक्टूबर, 1980 से इसके अन्तर्गत देश के सभी 5011 विकास खण्डों को सम्मिलित किया गया है। इस योजना में सम्मिलित परिवारों को ऋण एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1979-80 से इस कार्यक्रम पर होने वाली व्यय-राशि केन्द्र एवं राज्य सरकारों में 50 : 50 के अनुपात में की जाती है।

सारणी 21 6 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रगति प्रदर्शित करती है ।

सारणी 21 6
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रगति

वर्ष	लक्षान्वित कुल परिवार (लाख)	परिवार संख्या अनुमोचित जाति एवं जनजाति परिवारों की संख्या (लाख)	कुल व्यय राशि (करोड़ ₹)	कुल स्वीकृत ऋण राशि (करोड़ ₹)	कुल पूँजी निवेश राशि (करोड़ ₹)
छठी पंचवर्षीय योजना					
1980-81	27.3	7.8	158	289	447
1981-82	27.1	10.0	265	468	733
1982-83	34.6	14.0	360	714	1074
1983-84	36.8	15.4	406	774	1180
1984-85	39.8	17.4	472	857	1329
योग	165.60	64.60	1661	3102	4763
सातवीं पंचवर्षीय योजना					
1985-86	30.60	13.23	441	730	1171
1986-87	37.47	16.80	613	1015	1628
1987-88	42.47	18.99	728	1175	1903
1988-89	37.71	17.50	770	1239	2009
1989-90	33.52	15.45	764	1214	1978
योग	181.77	81.97	3316	5373	8689
वार्षिक योजना					
1990-91	28.98	14.46	810	1190	2000

- स्रोत (i) The Seven h and Eighth Five Year Plans Planning Commission Government of India New Delhi
(ii) Inderjit Khanna, Rural Employment and Subsidiary Occupation A perspective for the year 2000 Taken from Yojana vol 35 (8), May 1991, p 15

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु कृषकों को सम्पत्ति साधनों के क्रय पर 25 प्रतिशत एव सीमान्त कृषक एव कृषि श्रमिक परिवार को 33.3 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है, जो एक परिवार के लिए अधिकतम रु. 3000 की होनी है। सूखा प्रवण क्षेत्रों एव जनजाति क्षेत्रों में यह सहायता राशि 4000 रु. एव 5000 रु. की क्रमशः होती है। इस प्रोग्राम में उन काश्तकारों को वित्तीय सहायता दी जानी है जिनकी वार्षिक आय 4800 रु. तक होती है।

वर्ष 1980-81 से 1990-91 के 11 वर्षों में 376.35 लाख परिवार इस कार्यक्रम में लाभान्वित हो चुके हैं। इनमें से 161.03 लाख परिवार (42.79 प्रतिशत) अनुसूचित जाति एव जनजाति के थे। कार्यक्रम की नीति में 30 प्रतिशत लाभान्वित परिवार अनुसूचित जाति एव जनजाति से होने चाहिए। वर्ष 1990-91 से इनकी सहायता में वृद्धि करके 50 प्रतिशत कर दी गई है। लाभान्वित परिवारों को बैंकों से 9665 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया, 5787 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस प्रकार लाभान्वित परिवारों ने 15,452 करोड़ रुपये का कुल पूंजी निवेश किया है। इस कार्यक्रम के प्रमुख अवयव स्वतः रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण (Trysem) एव ग्रामीण क्षेत्रों के स्त्री एव बच्चों का विकास (Dwcra) है।

कृषि-बीमा

कृषि विभिन्न प्रकार से प्राकृतिक प्रकोपो जैसे—भूतिवृष्टि, घनावृष्टि, ओलावृष्टि, अग्नि तूफान, बीमारियों एवं कीड़ों आदि से प्रभावित होती रहती है। इन प्राकृतिक आपदाओं से कृषको को होने वाली सम्भावित हानि से एक सीमा तक रक्षा करने की विधि को कृषि बीमा कहते हैं। जिस प्रकार जीवन बीमा की एक साधारण-सी किश्त की राशि धाम आदमी के जीवन को अधिक सुरक्षित बनाती है, ठीक उसी तरह कृषि-बीमा के तहत कृषको द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की प्रीमियम राशि प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसकी फसल के चौपट हो जाने अथवा पशुओं के मर जाने से उत्पन्न भारी ऋण प्रस्तता एवं बर्बादी से रक्षा करती है।

कृषि-बीमा दो प्रकार का होता है

- (1) फसल-बीमा (Crop Insurance)
- (2) पशु बीमा (Livestock Insurance)

फसल-बीमा

फसल-बीमा कृषको को प्राकृतिक प्रकोपो के कारण फसलों को होने वाली हानि से रक्षा के लिए प्रीमियम की राशि का भुगतान करके जोखिम को बीमा कम्पनी पर स्थानान्तरित करने की विधि है। फसलों का बीमा कराने के उपरान्त प्राकृतिक प्रकोपो से यदि फसलों को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो उसकी पूर्ति कृषको को बीमा कम्पनी करती है। बीमा कम्पनी द्वारा बीमा की प्रीमियम की राशि का निर्धारण क्षेत्र में होने वाले प्राकृतिक प्रकोपो की सम्भावना एवं फसलों की उत्पादकता के आधार पर किया जाता है।

भारतीय कृषि-उत्पादन में प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप निरन्तर बना रहता है, जिसके कारण कृषि-व्यवसाय अनिश्चितता के वातावरण से ग्रस्त रहता है। पिछले वर्षों के कृषि-उत्पादन के आँकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि भारतीय कृषि में एक चार वर्षीय चक्र पाया जाता है जिसमें औसतन दो वर्ष बहुत अच्छे उत्पादन के, एक वर्ष औसत उत्पादन का एवं एक वर्ष कम उत्पादन वाला होता है। कम उत्पादन वाले वर्ष में कृषको को अनेक बार उत्पादन-साधनों पर की गई लागत

राशि भी प्राप्त नहीं होती है। प्राकृतिक आपदा वाले वर्ष में घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति तथा अगले वर्ष के लिए उत्पादन-साधनों के त्रय के लिए आवश्यक वित्तीय राशि कृषक साधारणतया गैर-संस्थायित ऋणदात्री संस्थाओं से प्राप्त करते हैं। ऋणदात्री संस्थाएँ मजबूर कृषकों से अधिक व्याज की दर वसूल करती हैं और होने वाली पैदावार को उनके माध्यम से विक्रय करने को प्रबन्ध कर देती हैं। इस प्रकार कृषक ऋणग्रस्तता के शिकार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में फसल बीमा आवश्यक है। फसल-बीमा का महत्व लघु एवं सीमाग्न कृषकों के लिए अधिक होता है, क्योंकि साधारण उत्पादन वाले वर्ष में भी उनके यहाँ बचत की मात्रा नगण्य होती है। फसल-बीमा पद्धति के कारण दूसरे देशों में जहाँ जनसंख्या का दबाव भारत की अपेक्षा कई गुना अधिक है, कृषि उत्पादकता का स्तर अधिक पाया जाता है।

फसल-बीमा से लाभ—फसल-बीमा के लागू होने पर कृषकों को निम्न लाभ प्राप्त होना आवश्यकतापूरक है—

- (1) प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप कृषकों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से बच जाती है। उत्पादन कम होने से हुई हानि की पूर्ति बीमा कम्पनी से प्राप्त क्षति-राशि से हो जाती है।
- (2) फसल-बीमा कृषकों को नये तकनीकी ज्ञान के उपयोग के लिए प्रेरणा देती है और उनमें जोखिम-बहन करने की शक्ति बढ़ाती है।
- (3) फसल-बीमा अधिक हानि की सम्भावना वाली भूमि पर भी कृषि करने का साहस कृषकों को देती है। इस प्रकार देश में कृषित क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, जो अन्यथा सम्भव नहीं है।
- (4) फसल-बीमा कृषकों को उत्पादन नहीं होने पर भी एक निश्चित राशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करती है। इससे कृषकों की आमदनी में स्थिरता आती है एवं परोक्ष रूप में कृषि-उत्पादन में सुधार होता है।
- (5) विषम परिस्थितियों में भी फसल-बीमा कृषकों के मनोबल को ऊँचा रखती है, जिससे वे जिम्मेदारी एवं साहस के साथ फार्म पर निरंतर ले पाते हैं।
- (6) फसल-बीमा पद्धति के होने पर आपदाओं व दुर्घटनाओं वाले वर्ष में भी कृषक ऋणदात्री संस्थाओं से प्राप्त ऋण की किश्त का समय पर भुगतान करने में सक्षम होते हैं।
- (7) फसल-बीमा कृषकों की ऋणग्रस्तता की समस्या को कम करने में सहायक होता है।

- (8) फसल-बीमा कृषको में वचत की प्रवृत्ति ढालने में सहायक होता है जिससे कृषि क्षेत्र में पूँजी-निवेश की राशि एवं कृषि क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि की दर में वदोत्तरी होती है।
- (9) फसल-बीमा के होने पर सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं वाले वर्षों में राहत कार्यों पर बिये जाने वाले व्यय की राशि में भारी कटौती होती है, जिससे सरकार उस धन का अन्य विकास कार्यक्रमों में व्यय करने अर्थव्यवस्था को विकास की ओर अग्रसर करने में सक्षम होती है।

भारत में फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन—भारत में फसल एवं पशु-बीमा योजना लागू करने का सुझाव सर्वप्रथम वर्ष 1939 में राष्ट्रीय नियोजन समिति द्वारा बनाई गई भूमि-नीति, कृषि-धर्म एवं बीमा उप-समिति ने दिया था। फसल-बीमा योजना लागू करने का प्रथम प्रयोग मध्यप्रदेश के देवास ग्राम निगम द्वारा अनिवार्य रूप में किया गया था, जो कुछ माह उपरान्त अनेक कारणों से स्थगित कर दिया गया। वर्ष 1946 में श्री नारायणस्वामी नायडू की अध्यक्षता में गठित ग्रामीण ऋण जीवन समिति द्वारा फसल-बीमा को अमेरिका की फेडरल फसल-बीमा पद्धति पर चलाये जाने का सुझाव दिया, जिससे कृषको की आय में स्थिरता बनी रहे। तत्पश्चात् सहकारी नियोजन समिति ने राज्य स्तर पर फसल एवं पशु बीमा को प्रयोगात्मक रूप से संचालित करने की सिफारिश की, जिसे 1947 में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों के सम्मेलन में अनुमोदित किया गया।

इनके परिणामस्वरूप कृषि एवं खाद्य मन्त्रालय ने वर्ष 1948 में डॉ जी. एस प्रियोत्कर की नियुक्ति चुने हुए क्षेत्रों में फसल एवं पशु-बीमा लागू करने में आने वाली समस्याओं के अध्ययन हेतु की गई। डॉ प्रियोत्कर ने चयनित फसलों (तमिलनाडु में धान एवं कपास, महाराष्ट्र में कपास, मध्यप्रदेश में गेहूँ एवं चावल तथा उत्तरप्रदेश में चावल, गेहूँ एवं मक्का) में फसल-बीमा की एक अग्रणी योजना के कार्यान्वयन का सुझाव दिया। इस सुझाव पर विशेषज्ञों की सहमति ली गई और उन्होंने फसल-बीमा का 50 प्रतिशत व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किए जाने की सिफारिश की। इस शर्त पर राज्य सरकारों ने फसल-बीमा योजना लागू करने में रुचि नहीं ली जिससे फसल-बीमा योजना कार्यान्वित नहीं हो पाई। बीमा सलाहकार समिति ने शीघ्र ही फसल-बीमा योजना प्रारम्भ करने की सिफारिश की थी। वर्ष 1947 में दिल्ली में हुए एशियन क्षेत्रिक सम्मेलन ने सिफारिश की कि सरकार को पूरे देश में अथवा उन क्षेत्रों में जहाँ फसल बीमा योजना लागू करने की सम्भावना अच्छी है, वहाँ फसल-बीमा शीघ्र लागू करने का निर्णय लेना चाहिए। खाद्य एवं कृषि संगठन संस्था की कार्यकारी समिति ने भी अपनी बैंक बँठक, 1956 में फसल-बीमा योजना को कार्यान्वित करने का सुझाव दिया था। तृतीय

पंचवर्षीय योजना के कृषि-कार्यकारी दल ने भी फसल एवं पशु-बीमा की समस्याओं पर विचार किया था। इन सबके बावजूद इसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में देश में प्रगति नहीं हो सकी।

वर्ष 1960 से 1965 के काल में प्राकृतिक विपदाओं के कारण फसलों का निरन्तर उत्पादन कम होने के फलस्वरूप फसल-बीमा का महत्व स्पष्ट हो पाया। वर्ष 1966 में केन्द्रीय खाद्य एवं कृषि मन्त्रालय में फसल-बीमा हेतु एक बिल तैयार करने की घोषणा की, जिसे 1968 में अनिवार्य फसल-बीमा की अग्रणी योजना के रूप में राज्य सरकारों को भिजवाया गया और उनसे कहा गया कि वे अपने राज्यों में उन क्षेत्रों में उन फसलों में फसल-बीमा योजना लागू करें, जो प्राकृतिक विपदाओं में अधिक प्रस्त होती हैं। चूँकि कृषि राज्य सरकार का विषय है, अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित बिल पर राज्य सरकारों से सुझाव आमन्त्रित किए गए। प्राप्त सुझावों से यह स्पष्ट था कि किसी भी राज्य सरकार की फसल एवं पशु बीमा योजना को लागू करने में रुचि नहीं है। केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित फसल एवं पशु-बीमा योजना बिल तथा स्कीम की पुनर्जाँच हेतु जुलाई, 1970 में डॉ० धर्मेन्द्रा रायण की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने फसल-बीमा योजना के प्राथमिक एवं प्रशासनिक पहलुओं पर अपनी राय देने के साथ-साथ अनिवार्य फसल-बीमा योजना कानूनन लागू करने पर आने वाली प्रमुख कठिनाइयों (राज्य सरकारों की अक्षमता तथा प्रीमियम राशि का निर्धारण) के फलस्वरूप इसे स्वेच्छा के आधार पर प्रयोग हेतु जनवरी, 1971 में सरकार को अपन प्रतिवेदन में आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किये। जुलाई, 1971 में केन्द्रीय कृषि मन्त्री द्वारा फसल-बीमा योजना पर लोकसभा में हुई बहस के दौरान सदस्यों को विभिन्न राज्यों की प्रतिक्रिया से अवगत कराया गया। साथ ही फसल बीमा बिल में से फल, फूल एवं सब्जियों की फसलों को वृक्ष कर दिया गया क्योंकि इनमें अनिश्चितता अन्य कृषि-फसलों की अपेक्षा अधिक होती है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भी फसल एवं पशु-बीमा योजना के कार्यान्वयन की सिफारिश अपने प्रतिवेदन में की है।

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली अनिश्चितता के कारण फसल एवं पशु-बीमा के लिए सभी सहमत हैं, लेकिन इसके कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के कारण आज भी यह योजना विभिन्न फसलों के लिए प्रायोगिक स्तर पर ही अनेक राज्यों में लागू है।

फसल-बीमा योजना के कार्यान्वयन से प्राप्त परिणाम

फसल-बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए अनेक प्रयोग किए गए हैं। जनवरी, 1973 के पूर्व एक फसल-बीमा योजना गुजरात राज्य में जीवन बीमा नियम द्वारा कपास की सबर किस्म-4 के लिए चलाई गई थी। वर्ष 1974-75 में

भारतीय सामान्य बीमा निगम (General Insurance Corporation of India) ने 10 प्रायोगिक फसल बीमा योजनाएँ ग्रान्ध्रप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्यों में कपास, गेहूँ व मूँगफली की फसलों के लिए प्रारम्भ की थी। इन योजनाओं में सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं (चोरी एवं युद्ध के कारण होने वाली जोखिमों के अतिरिक्त) से सुरक्षा की व्यवस्था थी। भारतीय सामान्य बीमा निगम ने फसल-बीमा की उपयुक्त योजनाएँ राज्यों में अनेक सस्थाओं जैसे—भारतीय उर्वरक निगम, राज्य उर्वरक निगम आदि के सहयोग से कार्यान्वित की थी। भारतीय सामान्य बीमा निगम को वर्ष 1973 से 1976 के काल में कार्यान्वित प्रायोगिक फसल-बीमा योजनाओं से मात्र 3 38 लाख रुपये की प्रीमियम राशि प्राप्त हुई, जबकि निगम द्वारा इस काल में 36 06 लाख रुपये की क्षति-पूर्ति राशि का भुगतान किया गया। अतः योजना से प्राप्त परिणाम उत्साहवर्द्धक नहीं है।

भारतीय सामान्य बीमा निगम ने राज्य सरकारों के सहयोग से पायलट फसल-बीमा योजना (Pilot Crop Insurance Scheme) वर्ष 1979 से परिचालित की है। यह योजना वर्ष 1982-83 की खरीफ मौसम में 9 राज्यों में—ग्रान्ध्रप्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्यप्रदेश—कार्यान्वित थी। सामान्य बीमा निगम ने इन राज्यों में खरीफ 1982-83 के वर्ष में 4 करोड़ रुपये की बीमा अभिरक्षा धन, ज्वार, मूँगफली, कपास और मक्का के उत्पादक कृषकों को प्रदान की। बीमे की प्रति किसान अधिकतम सीमा 2,000 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 5,000 रुपये व कम जोखिम वाले क्षेत्रों के अतिरिक्त मध्यम जोखिम वाले क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए, योजना में संशोधन किया, ताकि योजना किसानों में अधिक लोकप्रिय हो सके। सम्पूर्ण देश के लिए बीमाकृत राशि 6.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष कर दी गई। वर्ष 1981-82 तक समाप्त तीन वर्षों के दौरान प्राप्त प्रीमियम राशि 20 लाख रु० थी जबकि इस काल में निपटाए गए दावों की राशि 16 लाख रुपये थी।¹ अतः यह बीमा योजना अभी तक सीमित रूप में ही सफल रही है।

कृषकों को विभिन्न प्रतिकूल अवस्थाओं में होने वाले नुकसान एवं सस्थागत अभिकरणों से प्राप्त ऋण का समय पर भुगतान करने की सामर्थ्यता बनाये रखने की दृष्टि से खरीफ 1985 से भारत सरकार ने सम्पूर्ण देश के स्तर पर एक व्यापक फसल बीमा योजना (Comprehensive Crop Insurance Scheme) बनाई है। यह व्यापक फसल बीमा योजना भारतीय सामान्य बीमा निगम

1- Reserve Bank of India—Report on the Trend and Progress of Banking in India—1982-83, 1983, P, 157.

द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित की जावेगी। प्रस्तावित योजना सहकारी संस्थाओं, वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से प्राप्त ऋण से सम्बन्धित होगी। प्रारम्भ में यह योजना चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, तिलहन एवं दालों की फसलों के लिए बीमा सुविधा प्रदान करेगी। बीमा लागत की राशि किए गए बीमा राशि का चावल, गेहूँ एवं मोटे अनाज में दो प्रतिशत एवं तिलहन एवं दालों में एक प्रतिशत होगी। प्रति कृषक-बीमा की राशि उपर्युक्त फसलों के लिए प्राप्त संस्थागत फसल ऋण-राशि का 150 प्रतिशत होगी। यह बीमा योजना देश के उन सभी क्षेत्रों में क्रियान्वित की जावेगी, जिनके पिछले 5 वर्ष के फसल उत्पादकता के आँकड़े उपलब्ध हैं। कार्यान्वयन की दृष्टि से योजना खण्ड-स्तर पर लागू की जावेगी। इस फसल बीमा योजना में यदि बीमा किए गए क्षेत्र में कृषकों को प्रति हेक्टर उत्पादन, निर्धारित उत्पादकता स्तर से कम प्राप्त होता है तो उस क्षेत्र के सभी कृषकों को हुई हानि की राशि का समान दर से भुगतान किया जावेगा। अतः इस योजना में सभी कृषकों के उत्पादन के आँकड़े प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है।

फसल-बीमा योजना का लाभ सघु एवं सीमान्त कृषकों तक पहुँचाने के लिए उनके द्वारा देय प्रीमियम राशि का 50 प्रतिशत सहायता के रूप में राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा समान अनुपात में दिया जावेगा, जिससे यह वर्ष भी फसल-बीमा योजना में भाग लेने के लिए उत्सुक होंगे। प्रीमियम की राशि ऋण दात्री संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृत करते समय ही वसूल कर ली जावेगी। ऋणदात्री संस्था प्राप्त प्रीमियम राशि को पूर्ण विवरण सहित भारतीय सामान्य बीमा निगम को भेजेगा एवं भारतीय सामान्य बीमा निगम एक विस्तृत पानिसी ऋणदात्री संस्था के नाम से जारी करेगा।

भारत सरकार ने राज्य सरकारों से प्राप्त हुए सुझावों को ध्यान में रखकर इस व्यापक फसल-बीमा योजना को किसानों के लिए अधिक आकर्षक और लाभकारी बनाने की दृष्टि से इसमें निम्नांकित संशोधन किए हैं²—

- (1) उपज में होने वाली घट-बढ़ के गुणांक के आधार पर गेहूँ एवं धान के लिए क्षतिपूरक सीमाओं की तीन दरें—80 प्रतिशत, 85 प्रतिशत एवं 90 प्रतिशत होगी। प्रारम्भ की उपजों का निर्धारण पिछले तीन वर्षों की उपज के पारवर्तनशोल औसत के आधार पर किया जावेगा। गेहूँ एवं धान की क्षतिपूरक सीमाओं की इन विभेदक दरों को वर्ष 1986-87 की रबी की फसल से लागू किया गया है। अतः उपज में घट-बढ़ का गुणांक जहाँ कम है, वहाँ क्षतिपूरक सीमा ज्यादा होगी

और जहाँ उपज में घट-बढ़ का गुणांक ज्यादा है, वहाँ क्षतिपूर्क सीमा कम होगी। उपज में घट-बढ़ का गुणांक और विभिन्न इकाई क्षेत्रों की प्रारम्भिक उपज का निर्धारण भारतीय कृषि सांख्यिकीय अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा किया जावेगा।

- (ii) राज्यों की सरकारों को योजना के कार्यान्वयन के लिए किसी जिले/जिलों को चुनने का विकल्प होगा और इस प्रकार चुने हुए जिले/जिलों को तीन वर्षों की अवधि के लिए योजना से पूरा नहीं किया जा सकेगा।

किसी भी वित्तीय संस्था भयावह सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक भयावह क्षेत्रीय-ग्रामीण बैंक से योजना में सम्मिलित फसलों के लिए ऋण प्राप्त करने वाले सभी ऋणकर्ता किसानों को इसमें अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना होगा।

- (iii) योजना की कार्यान्वयन इकाई खण्ड-स्तर पर होगी तथा इससे छोटे स्तर की इकाई तक पहुँचने के लिए भी प्रयत्न किए जाने चाहिए। राज्य सरकार अपनी "फसल कटिंग मशीनरी" को मजबूत बनाकर इस योजना को ग्राम-स्तर भयावह गाँवों के छोटे समूह के स्तर तक लागू कर सकती है।

- (iv) जिन क्षेत्रों में विशेष-कृषि परियोजनाएँ, जैसे—राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना, विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम चल रहे हैं, यथासम्भव ऐसे जिलों को इस व्यापक फसल-बीमा योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

व्यापक फसल-बीमा योजना की प्रगति :

व्यापक फसल-बीमा योजना अप्रैल, 1988 (खरीफ 1985) में प्रारम्भ की गई। इस योजना को अप्रैल, 1988 में कुछ समय के लिए निलम्बित कर दिया गया था और सितम्बर, 1988 में पुनः प्रारम्भ किया गया। पुनः प्रारम्भ करने में दो मुख्य संशोधन किए गये—

- (अ) प्रति कृषक बीमा की अधिकतम राशि 10,000 रुपये होगी, चाहे कृषक ने कितनी ही राशि में ऋण प्राप्त किया हो।
- (ब) बीमा की राशि प्राप्त ऋण-राशि का 100 प्रतिशत होगी जबकि पूर्व में यह राशि 150 प्रतिशत थी।

वर्ष 1985-86 से 1990-91 की अवधि में इस बीमा योजना की प्रगति के विभिन्न पहलू सारणी 22.1 में प्रस्तुत हैं—

सारणी 22 1

व्यापक फसल बीमा योजना की प्रगति

मौसम/वर्ष	योजना में सम्मिलित राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश	योजना में सम्मिलित कृषक (लाख)	योजना में सम्मिलित क्षेत्रफल (लाख हेक्टर)	किए गए बीमा बीमों की राशि (करोड़ रुपये)	बीमा किस्त से प्राप्त राशि (करोड़ रुपये)	बीमा क्षतिपूर्ति की गई राशि (करोड़ रुपये)
खरीफ 1985	11+2	26 36	53 74	542 73	9 41	84 12
रबी 1986	14+2	12 12	23 18	238 41	4 47	3 11
खरीफ 1986	15+3	39 55	77 40	856 20	14 99	169 16
रबी 1987	15+2	11 28	20 99	242 37	4 51	4 58
खरीफ 1987	18+3	46 32	84 10	1140 68	19 10	277 24
रबी 1988	17+2	21 28	32 36	475 44	8.84	12 07
खरीफ 1988	13+0	29 64	52 35	547 88	8 82	29 18
रबी 1989	9+0	8 73	10 12	164 10	3 12	3 87
खरीफ 1989	15+2	42 76	66 45	873 89	14 48	34 36
रबी 1990	16+1	6 59	9 58	151 56	2 76	3 06
खरीफ 1990	17+1	19 42	34 09	515 15	7 66	NA
कुल					98 16	620 75

स्रोत Reserve Bank of India, Report on Currency and Finance, 1990-91 (Vol I) p 211

(Taken from Economic and Political Weekly, September, 26, 1992, P A -124)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि व्यापक फसल बीमा योजना की प्रगति सम्मिलित कृषकों की संख्या एवं सम्मिलित क्षेत्रफल की दृष्टि से अच्छी रही है। सर्वाधिक कृषक एवं कृषि क्षेत्रफल खरीफ 1987 में इस योजना में सम्मिलित किया गया। पिछले 5½ वर्षों में इस योजना के तहत 98 16 करोड़ रुपये बीमा किस्त राशि से प्राप्त हुए तथा 620 75 करोड़ रुपये बीमा क्षति पूर्ति राशि मुगतान की

गई। वर्ष 1986-87 एवं 1987-88 में देश के अधिकांश भागों में सूखा एवं बाढ़ की स्थिति होने के कारण गरीब 1987 में ही 277 करोड़ रुपये बीमा क्षति पूर्ति के भुगतान किए गए। स्पष्ट है कि कृषि में जोखिम अधिक होने से बीमा क्षति पूर्ति राशि का भुगतान प्राप्त बीमा किस्त राशि में कई गुना अधिक करना पड़ा है। अतः व्यापक फसल बीमा योजना की प्रगति भी उत्साहवर्द्धक नहीं है।

फसल-बीमा योजना के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयाँ—फसल-बीमा योजना के कार्यान्वयन में प्रमुख रूप से निम्न कठिनाइयाँ आती हैं—

1. विभिन्न फसलों के उत्पादन में होने वाली क्षति की मात्रा एवं उसकी आवृत्ति के सही दोनवार आँकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रीमियम की सही राशि के निर्धारण का कार्य कठिन होता है।
2. देश में लघु एवं सीमांत कृषकों की अधिकता, जोत का छोटे-छोटे खण्डों में विभक्त होना तथा विभिन्न कृषकों द्वारा निम्न-मिश्र फसल-चक्र लागू किये जाने के कारण भी बीमा-किस्त की सही राशि के निर्धारण का कार्य कठिन होता है।
3. भू-स्वामित्व के सही प्रमाणित प्राप्त नहीं होना भी फसल-बीमा योजना लागू करने में प्रमुख समस्या है।
4. सरकार के पास फसल-बीमा योजना को कार्यान्वित करने के लिए दक्ष कार्यकर्ताओं का अभाव होना।
5. अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण कृषकों द्वारा फसल-बीमा के महत्व को समझ नहीं पाना।
6. कृषकों का कृषि-व्यवसाय से वृद्धि की राशि कम प्राप्त होना तथा बीमा की किस्त राशि को उनके द्वारा अतिरिक्त-कर के रूप में मानना।
7. सरकार के पास बीमा कंपनियों को प्रारम्भ में फसल एवं पशु-बीमा लागू करने से होने वाली क्षति को पूरा करने के लिए धन की कमी का होना।
8. बीमा कंपनियों द्वारा फसल-बीमा का लागू करने से उत्पन्न परेशानियों के कारण इसका किसी-न-किसी माध्यम पर विरोध करना।

फसल-बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय कृषि-आयोग के सुझाव :

राष्ट्रीय-कृषि-आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भविष्य में फसल-बीमा योजना का विस्तार वर्तमान में कार्यान्वित अग्रणी योजनाओं के परिणामों पर निर्भर करेगा। फसल-बीमा योजना भारतीय कृषि के लिए आवश्यक ही नहीं प्रभितु

अपरिहार्य है। फसल-बीमा योजना के मावी विस्तार के लिए राष्ट्रीय-कृषि-आयोग ने सुझाव दिए हैं—

1. पायलट योजनाएँ (Pilot Schemes) सभी कृषि-वस्तुओं एवं प्रमुख खाद्यान्नों के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में शुरू की जानी चाहिए, जिससे सभी क्षेत्रों एवं विभिन्न फसलों में फसल बीमा के कार्यान्वयन की पूरी तस्वीर सामने आ सके।
2. देश के उन क्षेत्रों में जहाँ अनिश्चितता की अधिकता के कारण कृषक बीमा-किश्त (प्रीमियम) का भुगतान करने में समर्थ नहीं हैं, वहाँ किश्त का निर्धारण न्यूनतम स्तर पर किया जाना चाहिये। यह समाज कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जा सकता है।
3. पूंजी सम्पदा की बीमा योजना लागू किये जाने की सिफारिश भी आयोग ने की है। आयोग का मानना है कि पूंजी-सम्पदा का बीमा न्यूनतम किश्त की राशि पर किया जा सकता है। आयोग के मतानुसार सम्पदा-बीमा का महत्व फसल-बीमा की अपेक्षा कृषकों के लिए अधिक है।

पशु बीमा

भारतीय कृषि में पशु-बीमा भी फसल-बीमा के समान ही महत्वपूर्ण है। इसका महत्व लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए फसल-बीमा की अपेक्षा अधिक होता है। भारतीय कृषि में पशु रीढ़ की हड्डी के समान माने जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक कृषि-कार्य के करने में पशु प्रमुख हथ से काम में लिए जाते हैं। अतः पशुओं के प्राकृतिक प्रकांषों के फलस्वरूप मरने के कारण होने वाली जोखिम का बीमा कृषकों के लिए आवश्यक होता है।

फसल-बीमा के समान पशु-बीमा का इतिहास भी पुराना है। स्वतन्त्रता से पूर्व देश में अनेक पशु-बीमा समितियाँ थी, जो सहकारिता के आधार पर कार्यरत थी। धीरे-धीरे ये समितियाँ समाप्त हो गईं। श्री जी०सी० प्रियोल्कर ने 1948 में फसल-बीमा के साथ-साथ पशु-बीमा योजना भी बनाई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में पशु-बीमा योजना की अग्रगामी योजनाएँ शुरू करने के सुझाव भी दिए गए थे।

पशु-बीमा योजना के कार्यान्वयन में भी अनेक परेशानियाँ होने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। पशु-बीमा में होने वाली परेशानियाँ फसल-बीमा में होने वाली परेशानियों से भिन्न होती हैं। भारत में पशु बीमा योजना के कार्यान्वयन में प्रमुख कठिनाइयाँ अग्रलिखित हैं—

- (1) भारत में पशु अधिक संख्या में पाले जाते हैं। पाले जाने वाले पशुओं में अधिकतर पशु आर्थिक नहीं होते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पशुपालक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पशुओं को चारे की तलाश में ले जाते हैं। अतः सभी पशुओं का बीमा करवाना सम्भव नहीं होता है।
- (2) पशुओं में होने वाली मृत्यु-दर (Mortality Rate) के सही आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यह सभी मानते हैं कि पशुओं में मृत्यु-दर अधिक होती है। अतः इस धारणा के कारण बीमा की किंमत राशि अधिक होती है।
- (3) पशुओं का बीमा प्राकृतिक कारणों से हुई मौत के लिए किया जाता है। अनेक बार पशु की मृत्यु पशुपालक की लापरवाही के कारण होती है, जिसका पता लगाने का कार्य कठिन होता है।
- (4) पशु-बीमा के कार्यान्वयन में ग्राम्य परेशानी मृतक पशु के पहचानने की होती है। क्या मृतक पशु वही है जो बीमा कम्पनी से बीमा हेतु पंजीकृत किया गया है?
- (5) पशुओं का बीमा किसी निर्धारित मूल्य के लिये किया जाता है। पशुओं के मूल्य में उध के साथ साथ निरन्तर कमी तथा वृद्धि होती रहती है।
- (6) देश में पशु चिकित्सा की व्यवस्था भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होने के कारण अनेक बार पशुओं में संक्रामक बीमारी के कारण काफी पशुओं की मृत्यु चिकित्सा सुविधा बाहर के जुटाने से पूर्व ही हो जाती है। अतः बीमा कम्पनी को बहुत हानि उठानी पड़ती है।
- (7) पशु-बीमा योजना के कार्यान्वयन में प्रबन्ध की लागत अधिक आती है, क्योंकि बीमाशुदा पशुओं का निरन्तर निरीक्षण आवश्यक होता है।

पशु बीमा के क्षेत्र में उपर्युक्त परेशानियों के होते हुए भी, यह आवश्यक है कि देश में कृषकों को पशुओं की असामयिक मृत्यु से होने वाली जोखिम वहन करने की शक्ति उत्पन्न करने हेतु पशुओं के बीमा की व्यवस्था लागू की जाए। अनेक कृषकों के यहाँ पर बैल के मरने पर दूसरा बैल खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध की व्यवस्था न होने से कृषि-व्यवसाय या तो चौपट हो जाता है, अथवा गैर सस्थागत ऋणदात्री संस्था से ऋण लेने को कृषक मजबूर होते हैं, जिसके फलस्वरूप वे ऋणप्रस्तता के

स्थायी शिकार हो जाते हैं। पशु-बीमा के महत्त्व को मद्देनजर रखते हुए इसकी पायलट योजना लागू करते समय निम्न सुझाव ध्यान में रखने आवश्यक हैं—

- (1) पशु का बीमा पूरी कीमत पर नहीं करके उसकी दो-तिहाई कीमत का ही किया जाना चाहिए, जिससे पशुपालक पशु की देखभाल में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करते।
- (2) पशु-बीमा सभी पशुओं का नहीं किया जाकर कुछ चुने हुए अच्छे पशुओं का ही किया जाना चाहिए।
- (3) समय पर पशु-चिकित्सा की व्यवस्था एवं बीमाशुदा पशुओं की निरन्तर देखभाल की जानी चाहिए।

पशु बीमा योजना की प्रगति :

वर्ष 1974 में जब पशु-बीमा योजना प्रारम्भ की गई थी, मात्र 29,570 पशु ही बीमाशुदा थे। बीमाशुदा पशुओं की संख्या 1983 में 1.06 करोड़ हो गई। अतः पिछले दशक में इस क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है। वर्तमान में सरकार नस्ल के जानवरों के लिए पशु-बीमा सुविधा सभी स्थानों पर उपलब्ध है।

□□□

भारत में सहकारिता

सहकारिता आर्थिक संगठन का एक रूप है। सहकारी आन्दोलन भारत में नया नहीं है। भारत के ग्रामीण समुदायों का संगठन—समुक्त परिवार प्रणाली सहकारिता के सिद्धान्तों पर ही आधारित है। पश्चिमी सभ्यता के प्रादुर्भाव के कारण देश में सहकारिता के स्थान पर व्यक्तिवाद का उदय हुआ, जिससे सहयोग के स्थान पर प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ी। कृषि की दुर्दशा, ग्रामीण उद्योगों का पतन, जमींदारों, व्यापारियों एवं साहूकारों द्वारा किसानों के शोषण के कारण कृषकों की स्थिति दयनीय हुई। कृषकों में श्रद्धाघस्तता के बटन, उत्पादों के विक्रय से उचित कीमत प्राप्त नहीं होने एवं लघु कृषकों को पूँजीवादी कृषकों के समान स्थान नहीं प्राप्त होने के कारण, इस वर्ग की उन्नति के लिए जमीनी की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में अपनाये गये सहकारी आन्दोलन के आधार पर भारत में सहकारिता के उपयोग करने का विचार ब्रिटिश शासन-काल में किया गया। परिणामस्वरूप बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत में सहकारिता आन्दोलन प्रारम्भ हुआ।

विभिन्न आर्थिक प्रणालियों—व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में पाये जाने वाले दोषों को निवारण करने का उपाय सहकारिता ही है। यह इन दोनों के बीच की स्थिति है।

सहकारिता से तात्पर्य—सहकारिता से तात्पर्य परस्पर सहयोग से अथवा मिल-जुलकर काम करने से है। अर्थशास्त्र में सहकारिता से तात्पर्य स्वच्छा से बन हुए व्यक्तियों के संगठन से है जिसका उद्देश्य आर्थिक एवं/अथवा सामाजिक होता है। इसमें सम्मिलित सभी व्यक्तियों को समान स्तर पर समझा जाता है। संक्षेप में सहकारिता से तात्पर्य स्वयं की सहायता एक संगठन के माध्यम से प्राप्त करने से है।

कलबट्ट के अनुसार सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें व्यक्ति मानवता की भावना से समानता के आधार पर स्व-अपूर्वक सम्मिलित होते हैं तथा परस्पर सहायता न सक्ती आर्थिक उन्नति के लिए प्रयत्न करते हैं। स्ट्रीकलैण्ड के अनुसार सहकारिता का तात्पर्य व्यक्तियों के उस समूह से है जो सबके अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यापक किया जाता है।

मैकलेगन समिति के अनुसार, सहकारिता का सिद्धान्त संक्षेप में यह दर्शाता है कि एक प्रकेला एवं साधन-रहित व्यक्ति भी अपने स्वर के व्यक्तियों का संगठन बनाकर, एक-दूसरे के सहयोग से एवं नैतिक विकास व पारस्परिक समर्थन से अपनी कार्य-क्षमता के अनुसार, धनवान, ज्ञातिशाली व साधन-सम्पन्न व्यक्तियों को उपसब्ध सारे भौतिक लाभ प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार साधन-रहित व्यक्ति अपना विकास सहकारिता के माध्यम से कर सकता है।

सहकारिता नियोजन समिति के अनुसार, सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से समानता के आधार पर अपने अधिक हितों को प्राप्ति के लिए सम्मिलित होते हैं।

सहकारी के सिद्धान्त—सहकारिता के प्रमुख सिद्धान्त निम्न हैं—

1. स्वेच्छापूर्वक (Voluntary)—सहकारिता में सम्मिलित होने की प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रता होती है। वे स्वेच्छा से सदस्य बनते हैं। सदस्य बनने हेतु उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता है।
2. लोकतान्त्रिक (Democratic)—इसमें सम्मिलित सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रत्येक सदस्य को, चाहे उसने समिति के कितने ही शेयर खरीदे हों, एक ही वोट देने का अधिकार होता है। सहकारिता में 'एक व्यक्ति-एक मत' का सिद्धान्त अपनाया जाता है। इसका प्रबन्ध भी लोकतन्त्र पर आधारित होता है।
3. आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक उत्थान—सहकारिता में सभी सदस्यों का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक उत्थान प्राप्त करना होता है।
4. तटस्थता—सहकारिता में सम्मिलित सदस्यों का धर्म, जाति, राष्ट्रीयता एवं राजनीतिक दलों के प्रभाव से कोई सम्बन्ध नहीं होता है।
5. सहकारिता में व्यक्ति को प्रधानता दी जाती है, न कि उसकी सम्पत्ति को।
6. स्वावलम्बन एवं परस्पर सहयोग—सहकारिता मुख्यतया निबंलों का संगठन है जिसमें वे स्वावलम्बन तथा परस्पर सहयोग से अपनी निबंलता को संगठित शक्ति में बदल देते हैं। 'एक व्यक्ति सबके लिए व सब व्यक्ति एक के लिए' सहकारिता का मूलमन्त्र है।
7. सेवा भावना—सहकारी संगठन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होकर सदस्यों को अधिकतम सुविधाएँ प्राप्त कराना होता है।

सहकारिता में सम्मिलित व्यक्तियों में गुण—सहकारिता में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों में निम्न गुण होने चाहिए। इनके होने पर सहकारिता का विकास होगा तथा इन गुणों के नहीं होने पर सहकारिता की प्रगति में रुकावट आयेगी।

स्तर	ग्राम्य एवं मध्यकालीन ऋण के लिए सरकारी ऋण समितियाँ	दीर्घकालीन ऋण के लिए भूमि विकास बैंक	कृषि-उत्पादों के विपणन के लिए सहकारी विपणन समितियाँ
(प्र) प्राथमिक स्तर (गाँव या ग्रास-पास के गावों के समूह के लिए)	प्राथमिक कृषि-सहकारी ऋण समितियाँ	प्राथमिक भूमि विकास बैंक	प्राथमिक सहकारी कृषि-विपणन समिति
(ब) जिला-स्तर	केन्द्रीय सहकारी बैंक	जिला भूमि विकास बैंक	जिला सहकारी विपणन समिति
(स) राज्य-स्तर	राज्य/शीर्ष सहकारी बैंक	राज्य भूमि विकास बैंक	राज्य सहकारी विपणन संघ

भारत में सहकारिता का इतिहास

भारत में सहकारिता बहुत समय से प्रचलित है। पूर्व में सहकारिता वर्तमान रूप में नहीं होकर अन्य रूपों, जैसे—संयुक्त परिवार प्रणाली, पंचायत, चिट फण्ड्स, निधि आदि रूपों में प्रचलित थी। भारत में सहकारी आन्दोलन का प्रारम्भ वर्तमान रूप में मुख्यतया कृषकों को साहूकारों के शोषण से बचाने के लिए किया गया। प्रकाल आयोग, 1901 ने कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए दिए गए सुझाव पर सरकार ने एडवर्ड सॉ की अध्यक्षता में नियुक्त समिति को राय दी। इस समिति ने सन् 1901 में सहकारी समितियाँ स्थापित करने का सुझाव दिया एवं एक विधेयक बनाया जो 25 मार्च, 1904 को सहकारी ऋण समिति कानून के रूप में पारित किया गया। इस प्रकार आधुनिक काल में सहकारिता का जन्म भारत में वर्ष 1904 में हुआ। इस कानून का प्रमुख उद्देश्य लघु कृषकों को आवश्यक मात्रा में ऋण-सुविधा उपलब्ध कराना था। भारत में सहकारी ऋण समितियों का संगठन हुआ। इस कानून में व्याप्त कमियाँ, जैसे—विपणन, परिष्करण, कृषि आदि कार्यों के लिए गैर-ऋण सहकारी समितियों के संगठन की व्यवस्था के न होने, जिला एवं राज्य स्तर पर सहकारी बैंकों के नहीं होने आदि की स्थिति को दूर करने हेतु वर्ष 1912 में बृहद् सहकारी समिति कानून पारित किया गया। इस कानून के अनुसार सभी उद्देश्यों के लिए सहकारी समितियों की स्थापना की व्यवस्था की गई। इससे सहकारिता के विकास की गति में तीव्रता आई।

2 / भारतीय कृषि का अर्थतन्त्र

1. सदस्यों को सहकारिता के उद्देश्य लाभ आदि का ज्ञान होना चाहिए।
2. सदस्यों को सहकारिता का ज्ञान होना चाहिए।
3. सदस्यों में ईमानदारी की भावना होनी चाहिए।
4. सदस्य सहकारिता के प्रति वफादार होने चाहिए।
5. सदस्यों में सहकारिता के प्रति विश्वास होना चाहिए।
6. सदस्यों द्वारा सहकारिता के कार्य में रुचि होनी चाहिए।

सहकारिता से लाभ :

सहकारिता में सम्मिलित व्यक्तियों को निम्न लाभ प्राप्त होते हैं—

- (1) आर्थिक लाभ—सहकारिता के प्रत्येक क्षेत्र—ऋण, विपणन, कृषि परि-करण आदि में सम्मिलित होने पर सदस्यों को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। ऋण के क्षेत्र में कम व्याज दर पर ऋण-सुविधा प्राप्त होती है, जबकि विपणन के क्षेत्र में कम विपणन-लागत देनी होती है एवं उचित कीमत प्राप्त होती है। यह आर्थिक लाभ बाजार में प्रति-स्पर्धात्मक स्थिति के कारण प्राप्त होता है।
- (2) नैतिक लाभ—सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण सदस्यों का नैतिक उत्थान होता है। सदस्यों में बचत करने की भावना जागृत होती है। तथा असामाजिक आदतें, जैसे—सट्टा, शराब पीने की आदत आदि में कमी होती है।
- (3) सामाजिक लाभ—सहकारिता से समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, जैसे—मृत्यु-भोज, बाल-विवाह एवं अन्य सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने, ग्राम सुधार के लिए जल-प्रबन्ध, जल-निकासी व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए सदस्यों को प्रेरित किया जाता है।
- (4) शैक्षिक लाभ—सहकारिता में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को समान स्तर पर समझा जाता है। सदस्यों में शिक्षा का प्रसार किया जाता है।

सहकारी संस्थाओं का ढाँचा :

भारत में विभिन्न सहकारी समितियों का ढाँचा तीन स्तरीय या स्तूपकार (Pyramidal) होता है। ये तीन स्तर इस प्रकार होते हैं : गाँव या गाँवों का समूह, जिला एवं राज्य स्तर। इनकी संस्था ग्राम स्तर पर अधिक, जिला स्तर पर उससे कम एवं राज्य स्तर पर एक होने से स्तूपकार आकार का निर्माण होता है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए गठित समितियों का स्तर अग्रांकित प्रकार का होता है—

स्तर	ग्रन्थ एवं मध्यकालीन ऋण के लिए सरकारी ऋण समितियाँ	दीर्घकालीन ऋण के लिए भूमि विकास बैंक	कृषि-उत्पादों के विपणन के लिए सहकारी विपणन समितियाँ
(घ) प्राथमिक स्तर (गाँव या गाँव- पास के गाँवों के समूह के लिए)	प्राथमिक कृषि-सहकारी ऋण समितियाँ	प्राथमिक भूमि विकास बैंक	प्राथमिक सहकारी कृषि-विपणन समिति
(ङ) जिला-स्तर	केन्द्रीय सहकारी बैंक	जिला भूमि विकास बैंक	जिला सहकारी विपणन समिति
(च) राज्य-स्तर	राज्य/शीर्ष सहकारी बैंक	राज्य भूमि विकास बैंक	राज्य सहकारी विपणन संघ

भारत में सहकारिता का इतिहास .

भारत में सहकारिता बहुत समय से प्रचलित है । पूर्व में सहकारिता वर्तमान रूप में नहीं होकर अन्य रूपों, जैसे—समुक्त परिवार प्रणाली, पंचायत, चिट फण्ड्स, निधि आदि रूपों में प्रचलित थी । भारत में सहकारी आन्दोलन का प्रारम्भ वर्तमान रूप में मुख्यतया कृषकों को सहकारी के धोखे से बचाने के लिए किया गया । अकाल आयोग, 1901 ने कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए दिए गए सुझाव पर सरकार ने एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में नियुक्त समिति की राय ली । इस समिति ने सन् 1901 में सहकारी समितियाँ स्थापित करने का सुझाव दिया एवं एक विधेयक बनाया जो 25 मार्च, 1904 को सहकारी ऋण समिति कानून के रूप में पारित किया गया । इस प्रकार आधुनिक काल में सहकारिता का जन्म भारत में वर्ष 1904 में हुआ । इस कानून का प्रमुख उद्देश्य लघु कृषकों को आवश्यक मात्रा में ऋण-सुविधा उपलब्ध कराना था । भारत में सहकारी ऋण समितियों का संगठन हुआ । इस कानून में व्याप्त कमियाँ, जैसे—विपणन, परिष्करण, कृषि आदि कार्यों के लिए गैर-ऋण सहकारी समितियों के संगठन की व्यवस्था के न होने, जिला एवं राज्य स्तर पर सहकारी बैंक के नहीं होने आदि की स्थिति को दूर करने हेतु वर्ष 1912 में बृहद् सहकारी समिति कानून पारित किया गया । इस कानून के अनुसार सभी उद्देश्यों के लिए सहकारी समितियों की स्थापना की व्यवस्था की गई । इससे सहकारिता के विकास की गति में तीव्रता आई ।

सहकारी आन्दोलन में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु सरकार ने वर्ष 1914 में सर एडवर्ड मैकलेगन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने सहकारी आन्दोलन की प्रगति उचित दिशा में करने के लिए कई सुझाव दिए। वर्ष 1919 में सहकारिता को राज्याधीन दर्जा दिया गया और 1912 के कानून में आवश्यक सुधार करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया। फलतः विभिन्न राज्यों में सहकारिता के कानून पारित किए गए। विभिन्न राज्यों में स्थानीय स्थिति के अनुसार सहकारी आन्दोलन की प्रगति में तेजी आई।

वर्ष 1929 की विश्व-व्यापी मंदी का भारतीय सहकारी आन्दोलन पर विपरीत प्रभाव पड़ा। कृषकों के उत्पाद की कीमतें कम हो जाने के कारण उनकी आर्थिक दशा दयनीय हो गई तथा समितियों की बकाया ऋण की राशि में कई गुना वृद्धि हुई, जिसके कारण बहुत-सी समितियाँ बन्द करनी पड़ी। वर्ष 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई तथा उसके कृषि ऋण विभाग ने 1937 में सहकारी आन्दोलन पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, जिसमें बहुउद्देशीय समितियों के विकास करने का सुझाव दिया गया। द्वितीय महायुद्ध काल में कृषि-वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने के कारण कृषकों की स्थिति में सुधार हुआ। एवं युद्धकाल में देश में अनेक प्रकार की समितियों—फल एवं मछली उत्पादकों की सहकारी समितियाँ, उपभोक्ता समितियाँ, विपणन समितियों का विकास हुआ। वर्ष 1945 में सरगंध्या सहकारी नियोजन समिति ने सहकारी संस्थाओं को सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता तथा अन्य सुविधाएँ देकर उन्हें सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव दिए। श्री गोरवाला की अध्यक्षता में नियुक्त अखिल भारतीय ग्रामीण साख्त सर्वेक्षण समिति ने अपनी 1954 में प्रस्तुत रिपोर्ट में मत प्रकट किया कि 'भारत में सहकारिता असफल हुई है, किन्तु उसे सफल बनाना होगा' क्योंकि कृषकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए वर्तमान में सहकारिता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

स्वतन्त्र भारत में विभिन्न उद्देश्यों के लिए बनाई गई सहकारी-समितियों के विकास के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन पुस्तक के सम्बन्धित अध्यायों में किया गया है।

सहकारी समितियों का वर्गीकरण

रिजर्व बैंक ने सहकारी समितियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है—

- | | |
|-----------------------------|---|
| (I) सहकारी ऋण-समितियाँ | $\left\{ \begin{array}{l} \text{कृषि-ऋण सहकारी समितियाँ} \\ \text{गैर कृषि-ऋण सहकारी समितियाँ} \end{array} \right.$ |
| (II) सहकारी गैर-ऋण समितियाँ | |

अतः प्रमुखतया सहकारी समितियाँ चार प्रकार की होती हैं। इनका संक्षिप्त विवरण निम्न है :

1. कृषि ऋण सहकारी समितियाँ—ये सहकारी समितियाँ कृषकों को कृषि व्यवसाय के लिए आवश्यक ऋण कम व्याज दर पर उपलब्ध कराती हैं। सहकारी समितियाँ ग्राम्य एवं मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराती हैं जबकि दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंक उपलब्ध कराते हैं। इनका ढाँचा साधारणतया तीन-स्तरीय होता है। गाँव स्तर पर प्राथमिक सहकारी ऋण समितियाँ, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं राज्य-स्तर पर राज्य सहकारी बैंक या शीर्ष (Apex Banks) होते हैं। इसी प्रकार दीर्घकालीन ऋण के लिए प्राथमिक भूमि विकास बैंक, जिला भूमि विकास बैंक एवं राज्य भूमि विकास बैंक होते हैं। कुछ राज्यों में भूमि विकास बैंकों का ढाँचा दो स्तरीय होता है। विभिन्न स्तरीय सहकारी ऋण समितियों एवं भूमि विकास बैंकों की विस्तृत कार्य-प्रणाली, प्रगति एवं बाधक कारकों का विवेचन अध्याय 10 में कृषि-ऋण के संस्थागत अभिकरणों के खण्ड में किया गया है।

2. कृषि गैर-ऋण सहकारी समितियाँ—कृषकों को ऋण के अतिरिक्त, आवश्यक उत्पादन-साधनों—बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशी दवाइयाँ, कृषि-मशीन उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई सहकारी उन्नत कृषि समितियाँ, कृषकों को फार्म से प्राप्त उत्पादों के विपणन के लिए बनाई गई सहकारी कृषि-विपणन समितियाँ, कृषि-उत्पादों के परिष्करण (Processing) के लिए बनाई गई कृषि-उत्पादन परिष्करण सहकारी समितियाँ, पशुपालन सहकारी समितियाँ, मछली पालन सहकारी समितियाँ इसी श्रेणी में आती हैं। विभिन्न प्रकार की सहकारी कृषि समितियों का विवेचन अध्याय 8 में तथा सहकारी विपणन समितियों का विवेचन अध्याय 15 में किया गया है।

3. गैर कृषि सहकारी ऋण-समितियाँ—ये समितियाँ कृषि के अतिरिक्त ग्राम्य क्षेत्रों के व्यक्तियों को ऋण-सुविधा उपलब्ध कराती हैं, जैसे—शहरी बैंक, बचत एवं ऋण-समितियाँ, शहरी ऋण समितियाँ, आदि।

4. गैर-कृषि, गैर-ऋण सहकारी समितियाँ—ये समितियाँ मुख्यतया उप-भोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करती हैं। इनके अन्तर्गत उपभोक्ता-मण्डल, मकान-निर्माण समितियाँ, हाथ-करवा बुनकर समितियाँ आदि आती हैं।

सहकारिता की प्रगति में बाधक कारक :

सहकारिता के विकास के लिए वर्ष 1904 में पारित सहकारिता कानून के पश्चात् निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सहकारिता के विभिन्न क्षेत्रों—ऋण, विपणन, कृषि, परिष्करण में हुई प्रगति के आँकड़ों से स्पष्ट है कि भारत में सहकारिता की प्रगति धीमाधीन नहीं हुई है। उदाहरण के लिए सहकारी ऋण-

समितियाँ वर्तमान में कुल ऋण का 30 प्रतिशत से कम अंश ही कृषकों को प्रदान कर रही हैं। इसी प्रकार सहकारी विपणन समितियाँ अधिकांश राज्यों में उत्पादों का विक्रय नहीं करके उत्पादन-साधनों एवं आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति का कार्य कर रही हैं। सहकारिता के क्षेत्र में घटी प्रगति के प्रमुख कारण निम्न हैं। वैसे सहकारी ऋण, सहकारी विपणन एवं सहकारी कृषि की प्रगति में बाधक कारकों की विवेचना सम्बन्धित अध्यायों में पहले ही की जा चुकी है।

I. सामान्य कारण—निम्न सामान्य कारण सहकारिता की प्रगति में बाधक हैं—

1. सदस्यों में सच्ची सहकारिता की भावना का नहीं होना।
2. सहकारिता में ऋण को ही सर्वोपरि स्थान दिया गया है, जबकि अन्य प्रकार की सहकारी समितियों के विकास के लिए विशेष प्रयास नहीं किया गया है।
3. भारत में सहकारिता को एक सहकारी संस्था के रूप में माना जाता है, क्योंकि इनके संचालन में सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप होता है। भारत में सहकारिता आन्दोलन में राज्यों की भूमिका स्पष्टतया झलकती है।

II आन्तरिक कारण—निम्न आन्तरिक कारण भी सहकारिता की प्रगति में बाधक होते हैं—

1. सहकारिता कानून में कमियों का होना एवं सदस्यों का सही चुनाव नहीं किया जाना।
2. सहकारिता का प्रबन्ध ऐसे व्यक्तियों के नियन्त्रण में होना जिन्हें सहकारिता का अनुभव नहीं होता है।
3. सहकारिता में सदस्यों का एक-दूसरे के प्रति पक्षपात का दखल अमान्यता एवं ऋण स्वीकृति में पक्षपात करना।
4. सहकारी ऋण की राशि का सदस्यों पर बकाया रहना।
5. सहकारी समितियों के हिसाब में घोटाला, निरीक्षण समय पर नहीं किया जाना, दोषी पाये जाने पर व्यक्तियों को दण्ड नहीं दिया जाकर उनके आक्षेपों पर लीपा-पोती करना।
6. सहकारी समितियों के पास पर्याप्त धन नहीं होना, जिसके कारण वे सदस्यों को आवश्यक मात्रा में समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं होती हैं।
7. सभी राज्यों में सहकारी विकास की गति का समान नहीं होना।
8. कृषकों की ऋण के अतिरिक्त अन्य आवश्यकताएँ समितियों के द्वारा पूरी नहीं करना।
9. अधिकांश सहकारी समितियों का आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं होना।

सहकारिता के विकास के लिए सुझाव

सहकारी आन्दोलन भारत में असफल रहा है, लेकिन देश के आर्थिक विकास के लिए इसे सफल बनाना आवश्यक है। सहकारिता के विकास के बिना ग्रामीण भारत के उत्थान का सपना साकार नहीं हो सकता है। अतः सहकारिता के विकास के लिए निम्न सुझाव प्रेषित किये जाते हैं—

- 1 प्राथमिक समितियों का पुनर्गठन करके उन्हें बहुउद्देश्यीय समितियाँ बनाना चाहिए, जिससे वे आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो सकें।
- 2 प्राथमिक समितियों का कार्यक्षेत्र विस्तृत होना चाहिए, जिससे उन्हें सक्षम व संचलित होने का अवसर मिल सके।
- 3 सदस्यों को ऋण सुविधा सम्भावित पैदावार की मात्रा के आधार पर स्वीकृत करनी चाहिए।
- 4 कृषि ऋण का कृषि विपणन से समन्वय होना चाहिए जिससे कृषकों द्वारा उत्पादित माल के विन्य से प्राप्त कीमत से ऋण का सीधा भुगतान किया जा सके और बढ़ती हुई ऋण की बकाया राशि को कम किया जा सके।
- 5 सहकारी समितियों द्वारा गाँवों में उपलब्ध बचत की राशि को एकत्रित करने का कार्य भी किया जाना चाहिए।
- 6 केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय सहकारी बैंको एवं भूमि विकास बैंको की शाखाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।
- 7 सरकार द्वारा उपलब्ध की जाने वाली सहायता कृषकों को सीधे नकद रूप में न दी जाकर, सहकारी समितियों के माध्यम से वस्तु रूप में दी जानी चाहिए।
- 8 सहकारी कार्यकर्ताओं को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे वे कार्य को दक्षता से कर सकें।
- 9 सदस्यों में सहकारिता की भावना जागृत की जानी चाहिए।
- 10 सहकारी समितियों द्वारा रिजर्व कोष की स्थापना की जानी चाहिए। प्रारम्भ में निर्वल एवं अनार्थिक समितियों को सक्षम बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।
- 11 सहकारी समितियों द्वारा कृषकों को ऋण उत्पादन कार्यों के लिए ही स्वीकृत किया जाना चाहिए।

बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम एवं नई कृषि नीति

देश में 26 जून, 1975 को आपात स्थिति की घोषणा के साथ ही 1 जुलाई, 1975 को देश में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को लागू करने की घोषणा की गई। इस घोषणा का प्रमुख उद्देश्य प्रस्तावित कार्यक्रमों को निर्धारित समय में अपनाकर आर्थिक विकास लाना है। ये आर्थिक कार्यक्रम सरकार के लिए एक दिशा-सूचक का कार्य करते हैं। घोषित आर्थिक कार्यक्रम में अनेक सूत्र पहले से ही चल रहे थे एवं कुछ कार्यक्रम इनमें नये सम्मिलित किये गये हैं। वर्ष 1982 में इन आर्थिक कार्यक्रमों में संशोधन किये गये और 14 जनवरी, 1982 को नये 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की सरकार ने घोषणा की। नये आर्थिक कार्यक्रम के 20 सूत्र निम्न हैं—

- (1) देश में सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना एवं शुष्क भूमि कृषि हेतु आवश्यक उत्पादन-साधन उपलब्ध कराना।
- (2) तिलहन एवं दलहन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विशेष प्रयास करना।
- (3) एकीकृत ग्रामीण विकास एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाते हुए उनका विकास करना।
- (4) भूमि जोत की उच्चतम सीमा कानून को सख्ती से लागू करना एवं उसके कार्यान्वयन से प्राप्त अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन श्रमिकों व लघु एवं सीमान्त कृषकों में वितरित करना।
- (5) कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों की जाँच करना एवं उन्हें प्रभावशाली बनाना।

- (6) बन्धक मजदूरों के पुनर्वास की व्यवस्था करना ।
- (7) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए बनाये गये कार्यक्रमों को शक्ति देना ।
- (8) अभावग्रस्त गाँवों तक पीने का पानी पहुँचाना ।
- (9) ग्रामीण परिवारों को भवान बनाने हेतु भूमि आवंटन करना एवं मकान बनाने के लिए वित्त सुविधा उपलब्ध कराना ।
- (10) गन्दी बस्ती क्षेत्रों के बातावरण में सुधार लाना, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को मकान उपलब्ध कराने की योजना बनाना एवं भूमि की बढ़ती हुई कीमतों को रोकना ।
- (11) विद्युत् उत्पादन में वृद्धि करना एवं गाँवों तक बिजली पहुँचाना ।
- (12) जंगलात, सामाजिक एवं फार्म जंगल एवं बायो गैस एवं शक्ति के अन्य स्रोतों का अधिकधिक विकास करना ।
- (13) परिवार नियोजन कार्यक्रम को स्वेच्छा से जन-आन्दोलन के रूप में बढ़ाना ।
- (14) आवश्यक प्राथमिक सेवाओं में वृद्धि करना एवं कोड, टी० डी० एवं अन्धापन आदि बीमारियों का निराकरण करना ।
- (15) महिलाओं एवं बच्चों के लिए कल्याण कार्यक्रमों में वृद्धि करना एवं जनजाति, पहाड़ी एवं पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों, गर्भित महिलाओं एवं बच्चा पालने वाली माताओं के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाना ।
- (16) 6 से 14 वर्ष के बच्चों (विशेषकर लड़कियों) के लिए प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना एवं प्रौढ शिक्षा के लिए स्वेच्छिक संस्थाओं को प्रोत्साहन देना ।
- (17) उद्योगों में पूँजी निवेश की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए पूँजी निवेश नीति को उदार बनाना, विभिन्न योजनाओं को समय पर पूरा कराने, हस्तकला उद्योग, हैण्डलूम एवं लघु एवं कुटीर उद्योगों को नवीनतम तकनीकी एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना ।
- (18) जमाखोरो, तस्करो एवं कालाबाजारी तथा करो की चोरी करने की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकना ।

- (19) देश में सामाजिक वितरण प्रणाली का विस्तार करना, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें एवं कापियाँ प्राथमिकता के आधार पर सस्ती दर पर उपलब्ध कराना तथा उपभोक्ता की रक्षा के लिए जन-आन्दोलन को प्रेरणा देना ।
- (20) सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत व्यवसायो/उद्योगों की कार्य-क्षमता में वृद्धि करना ।

नई कृषि नीति

भारत सरकार द्वारा घोषित नई कृषि नीति 1992 के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं :

- 1 कृषि में व्यापार एवं पूँजी निवेश हेतु उद्योगों के समान सकारात्मक वातावरण उत्पन्न करना ।
- 2 कृषि क्षेत्र को उद्योगों के समान लाभप्रद स्थिति में लाने हेतु कार्यशील प्रणाली बनाना ।
- 3 नगरपालिका क्षेत्र में भूमि की कीमतों में हो रही वृद्धि से कृषकों को प्राप्त पूँजी लाभ की राशि को कर मुक्त रखना ।
- 4 सरकार की कर नीति से कृषि व्यवसाय को मुक्त रखना ।
- 5 कृषि व्यवसाय को लाभप्रद बनाने के लिए कृषकों को उत्पाद की लाभप्रद कीमतें दिलाना, जिससे उन्हें अच्छा लाभ प्राप्त हो सके ।
- 6 कृषि क्षेत्र में पूँजी निर्माण की दर में वृद्धि करना ।
- 7 कृषि क्षेत्र में सरकारी एवं निजी पूँजी निवेश को प्राथमिकता के साथ सुविधाओं के विकास पर अधिक धन व्यय करने के लिए प्रोत्साहन देना, जिससे कृषि क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ाने में सहायक हो सके ।
- 8 वर्षा पर आधारित एवं सिंचित फल, सब्जी, पुष्प, सुगन्धित एवं दवाई वाली फसलें तथा बागवानी वाली फसलों को बढ़ावा देने पर बल देना ।
- 9 घरेलू खपत एवं निर्यात में वृद्धि हेतु कृषि क्षेत्र में ससाधन एवं विपणन पर पूर्ण सहायता प्रदान किया जाना, जिससे कृषकों को उत्पादित उपज की कीमत में वृद्धि हो सके ।

- 10 कृषि के विभिन्न पहलुओं में किए गए अनुसन्धान से प्राप्त परिणामों का लाभ उठाने के लिए कृषकों को प्रेरित करना ।
- 11 वर्तमान में उपलब्ध साधनों का पूंजी निर्माण एवं वाधारघारिक सुविधाओं के विकास में प्रयुक्त करना ।
- 12 विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त क्षेत्रीय असमानता को कम करना ।
13. कृषि क्षेत्र में सिंचाई एवं अन्य कृषि कार्यों हेतु शक्ति के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना ।

* Farm Banking News, Vol 3(3), October-December, 1992, State Bank of Travancore.

□□□

भारत में गरीबी

गरीबी एक सामाजिक बुराई है, जिससे समाज का प्रत्येक वर्ग किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है। देश की दो प्रमुख समस्याओं—गरीबी एवं बेरोजगारी में गरीबी की समस्या सर्वोपरि है। गरीबी शब्द नया नहीं है। इसे सर्वप्रथम वर्ष 1876 में दादाभाई नोरोजी ने अपने लेख 'भारत में गरीबी', जो ईस्ट इण्डिया सघ की बम्बई शाखा के समक्ष प्रस्तुत किया था में उपयोग किया था।

मार्टिन रैन ने गरीबी की परिभाषा में जीवन निर्वाह (Subsistence), असमानता (Inequality) एवं बाह्यता (Externality) शब्द का उपयोग किया है। जीवन-निर्वाह से तात्पर्य व्यक्ति को स्वस्थ एवं उसमें कार्यशील क्षमता बनाए रखने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की वस्तुओं की पूर्ति से है। असमानता से तात्पर्य विभिन्न व्यक्तियों की आय सापेक्षता से है अर्थात् गरीब की परिभाषा करते समय सम्पन्न व्यक्तियों से तुलना की जाती है तथा बाह्यता से तात्पर्य इसके होने से समाज के अन्य वर्ग पर आने वाले सामाजिक प्रभाव से है।

गरीबी एक सामाजिक स्थिति है जिसमें समाज के सदस्य जीवन-निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकता की वस्तुएँ भी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। जब समाज के अधिकांश सदस्य न्यूनतम आवश्यकता की वस्तुएँ उचित मात्रा में प्राप्त कर पाने से वंचित होते हैं और वे न्यूनतम स्तर से भी कम स्तर पर जीवन निर्वाह करते हैं, तो उस समाज में गरीबी व्याप्त होना कहा जाता है। गरीबी को परिभाषित करने का प्रयास सभी देशों में किया गया है, लेकिन सभी ने न्यूनतम या उचित जीवन-स्तर प्रदान करने पर बल दिया है। भारत में गरीबी की परिभाषा में उचित जीवन-स्तर के स्थान पर न्यूनतम जीवन-स्तर को स्वीकार किया है। अतः विभिन्न देशों में गरीबी की परिभाषा में अन्तर विद्यमान है।

गरीबी दो प्रकार से होती है—एक तो तुलनात्मक (Relative) एवं दूसरे असम्बन्ध (Absolute)। तुलनात्मक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास दूसरे व्यक्ति

के मुकाबले में कम सम्पत्ति है, वह गरीब है। सम्पत्ति में व्याप्त इस प्रकार की असमानता को पूरी तरह मिटाना सम्भव नहीं है तथा भारत जैसे विकासशील देश की गरीबी को समझना भी इससे सम्भव नहीं है। अतः गरीबी नापने का असम्भव विधि ही उपयुक्त है। इसमें जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं की न्यूनतम मात्रा निर्धारित की जाती है और उन्हें रुपये के रूप में परिवर्तित करके आवश्यक आय अथवा प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय की राशि ज्ञात की जाती है। वह व्यक्ति या जनसंख्या जो न्यूनतम निर्धारित स्तर से भी कम स्तर पर उपभोग व्यय करता है वह निर्बलता रेखा/गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है।

गरीबी रेखा (Poverty Line) :

गरीबी रेखा शब्द का उपयोग सर्वप्रथम भारतीय धर्म सम्मेलन (1957) में किया गया था। इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम सम्मिलित किया था। विभिन्न लेखकों ने गरीबी रेखा का निर्धारण करने में निम्न तीन अवधारणाओं का उपयोग किया है—

- (i) प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय—इसमें विभिन्न व्यक्तियों द्वारा मासिक उपभोग व्यय के उपलब्ध आकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा के ऊपर एवं नीचे जनसंख्या को विभाजित किया जाता है। एक निश्चित मासिक उपभोग व्यय (निश्चित कीमत स्तर पर) से कम स्तर वाले व्यक्ति निर्बलता रेखा से नीचे कहे जाते हैं।
- (ii) कैलोरी आहार पर—इसमें सर्वप्रथम जीवन को घसाने के लिए पौष्टिक आहार के रूप में आवश्यक कैलोरी का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद इसे एक विशेष आहार वर्ष पर आय में परिवर्तित कर लिया जाता है।
- (iii) प्रति व्यक्ति मासिक आय
इन सभी अवधारणाओं की कुछ सीमाएँ हैं, जैसे—न्यूनतम आवश्यकता को परिभाषित करना कठिन है। कैलोरी आवश्यकता में भी जलवायु एवं आदतों के अनुसार विभिन्नता होती है।

गरीबी सामान्यतया कम आय, बचत का निम्न स्तर तथा कम विनियोजन के दुश्चक्र का परिणाम है, जिसके कारण रोजगार का अभाव एवं आय की कमी उत्पन्न होती है। उत्पादकता स्तर का कम होना, बाजार की अपूर्णता नए तकनीकी स्तर का कम उपयोग, जनसंख्या की अधिकता आदि कारक इस दुश्चक्र का और विस्तृत करते हैं। गरीबी के सामाजिक अवांछनीय परिणामों में उत्पादन वृद्धि की प्रेरणा का अभाव, शारीरिक एवं मानसिक प्रयासों का सदुपयोग नहीं होना एवं आत्म-विश्वास की कमी का होना है।

गरीबी का माप-दण्ड

भारत सरकार द्वारा गठित एक "विशिष्ट अध्ययन दल" ने जुलाई, 1962 के वृत्तान्त में कहा है कि निम्नतम राष्ट्रीय वांछित उपभोग प्रतिमाह 20 रुपये प्रति व्यक्ति (वर्ष 1960-61 की कीमतों पर) होना चाहिए। इसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए पृथक् उपभोग-दर तय नहीं की गई थी। प्रो. डाण्डेकर एवं रथ ने अपने अध्ययन के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 15 रुपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों के लिए 22.50 रुपये प्रतिमाह तय किया। योजना आयोग ने कैलोरी उपभोग के मानक का भी उपयोग किया है। योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने वर्ष 1977 में यह निश्चित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यक्ति के लिए 2400 कैलोरी प्रतिदिन एवं शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी ऊर्जा की प्रतिदिन न्यूनतम आवश्यकता होती है। इसे प्राप्त करने के लिए वर्ष 1979-80 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति औसतन कम से कम 76 रुपये और शहरी में 88 रुपये प्रतिमाह की आवश्यकता होती है।

प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपभोग व्यय स्तर पर विभिन्न वर्षों में गरीबी नापने का प्रायोगिक मापदण्ड सारणी 25¹ में प्रदर्शित है।

सारणी 25 1
गरीबी रेखा के माप-दण्ड

(रुपयों में)

कीमत-स्तर का वर्ष	(उपभोग व्यय प्रति व्यक्ति, प्रतिमाह)	
	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
1960-61	18.90	25.00
1973-74	49.09	56.64
1976-77	61.80	71.30
1977-78	65.00	76.00
1979-80	76.00	88.00
1983-84	101.88	117.50
1984-85	107.00	122.00
1985-86	106.66 अथवा	121.66 अथवा
(सातवी योजना)	6400 रु. प्रति	7300 रु. प्रति
	परिवार प्रतिवर्ष	परिवार प्रतिवर्ष

Source : Draft Five Year Plans, Planning Commission, Government of India, New Delhi.

सातवी योजना में गरीबी रेखा से नीचे के स्तर के व्यक्तियों को पुनः चार श्रेणी में वर्गीकृत किया है—

- (i) गरीबों में सर्वाधिक गरीब अथवा निराक्षय (Destitutes)—2265 रुपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष से कम उपभोग व्यय स्तर वाले व्यक्ति ।
- (ii) अत्यन्त गरीब (Very-Very Poor)— 2266 से 3500 रुपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष से कम उपभोग व्यय स्तर वाले व्यक्ति ।
- (iii) बहुत गरीब (Very Poor)—3501 से 4800 रुपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष से कम उपभोग व्यय स्तर वाले व्यक्ति ।
- (iv) गरीबों में धनवान (Richest among the poor)—4801 से 6400 रुपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष के उपभोग स्तर वाले व्यक्ति ।

भारत में गरीबी के अनुमान

भारत में अनेक व्यक्तियों ने गरीबी के विषय में अध्ययन किया है । इनके प्राप्त परिणामों में समय की भिन्नता एवं आकलन की अवधारणा के कारण विभिन्नता व्याप्त है । विभिन्न अध्ययनों के प्राप्त परिणाम सारणी 25.2 में प्रदर्शित हैं ।

सारणी 25.2

भारत में गरीबी का अनुमान

(मिलियन में)

अनुमानकर्ता	आधार	आकलन वर्ष	व्याप्त गरीबी		
			ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	कुल
1	2	3	4	5	6
1. पी डी मोन्टा	न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित 2250 कैलोरी प्रतिदिन की उपलब्धि हेतु वर्ष 1960-61 की कीमत पर मासिक उपभोग व्यय प्रति व्यक्ति रु 8 से 11 ग्रामीण क्षेत्र में एवं 15 से 18 रु. शहरी क्षेत्र में ।	1960-61	184.2 (51.6)	6.0 (7.6)	190.2 (44.0)
2. इपी डब्ल्यू हाकोस्टा	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर ।	1963-64	—	—	162 (34.9)

1	2	4	4	5	6
3 पी के वरधान वर्ष	1960-61 की	1960-61	131 0	—	—
	कीमत स्तर पर प्रति		(28 0)		
	व्यक्ति प्रतिमाह उपभोग	1967-68	220 5	—	—
	व्यय 15 रु० ग्रामीण		(54 0)		
	क्षेत्र में एवं 20 रु०				
	शहरी क्षेत्र में ।				
4 डाण्डेकर एवं	वर्ष 1960-61 की	1960-61	135 0	42 0	177 0
रथ	कीमत स्तर पर प्रति		(33 1)	(48 6)	—
	व्यक्ति प्रतिमाह उप-	1969-70	166 4	49 0	215 5
	भोक्ता व्यय के आधार		(40 0)	(50 0)	(41 0)
	पर 15 रु० ग्रामीण	1978-79	249	57	306
	क्षेत्र में एवं 22 50 रु०		(50 82)	(38 19)	(48 13)
	शहरी क्षेत्र में ।				
5 बी एस	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण	1969-70	210	—	—
मि-हास	से प्राप्त आंकड़ों पर वर्ष		(50 6)		
	1967-68 में प्रति				
	व्यक्ति 240 रु० वार्षिक				
	उपभोग व्यय (न्यूनतम				
	आवश्यकता के आधार				
	पर) ।				
6 सातवे वित्त	विस्तृत अध्ययन के	1970-71	225	52	277
आयोग	अनुसार ।		(53)	(51)	(52)
7 योजना आयोग	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण	1972-73	—	—	(51 5)
	के 32वें व 38वें दौर	1977-78	—	—	(48 3)
	की रिपोर्ट के आधार पर ।	1983	—	—	(37 4)
8. योजना आयोग	—	1980-85	259 6	57 2	316 8
		(छठी योजना)	(50 7)	(40 0)	(48 4)
9 योजना आयोग वर्ष	1973-74 की	1983-84	221 5	49 5	271 0
	कीमत स्तर पर रु०		(40 4)	(28 1)	(37 4)
	4909 प्रति व्यक्ति प्रति				
	माह ग्रामीण क्षेत्र में एवं				
	रु० 56 64 शहरी क्षेत्र ।				
10 CMIE	भारत सरकार ।	1977-78	(51 2)	(38 2)	—
		1984-85	(39 9)	(27 7)	—
		1989-90	(28 2)	(19 3)	—

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल जनसंख्या का प्रतिशत हैं ।

सातवें वित्त आयोग ने इन सभी व्यक्तियों द्वारा दिये गये अनुमानों को अस्वीकार करके एक नयी विचारधारा "तर्कयुक्त गरीबी की रेखा (Argumented Poverty Line)" प्रस्तुत की है। इसमें प्रति व्यक्ति प्रतिमाह व्यक्तिगत उपभोग पर किये गये व्यय के साथ-साथ सरकार द्वारा शिक्षा, समाज कल्याण, सड़कें, पानी, सफाई, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और प्रशासन पर किये गये व्यय को भी सम्मिलित किया गया है। गरीबी की इस विस्तृत अवधारणा के आधार पर 15 राज्यों के अध्ययन के अनुसार आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि वर्ष 1970-71 में 53 प्रतिशत व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 51 प्रतिशत व्यक्ति शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहते थे।

योजना आयोग के अनुसार छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत 48.4 एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में 38.4 प्रतिशत था। विभिन्न राज्यों के अध्ययन से स्पष्ट है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन-निर्वाह करने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता में बहुत विभिन्नता है। असम, बिहार, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश एवं पंजाब राज्य में गरीबी देश के औसत से अधिक है।

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा गरीबी के अनुमान में उनके द्वारा प्रयोगित विधि के कारण विभिन्नता है। उपरोक्त आकलन से निम्न तथ्य स्पष्ट है—

- (i) देश में गरीबी की समस्या में वृद्धि हुई है।
- (ii) गरीबी रेखा से नीचे जीवन-निर्वाह करने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता में कोई विशेष कमी नहीं हुई है।
- (iii) गरीबी की सर्वाधिक समस्या एवं प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में है। शहरी क्षेत्रों में बढ़ती हुई गरीबी का प्रमुख कारण गांवों से शहरों की ओर व्यक्तियों का पलायन करना है।
- (iv) विभिन्न राज्यों में गरीबी के स्तर में बहुत विभिन्नता है।

ग्रामीण कृषक परिवारों में व्याप्त गरीबी

सारणी 253 भारत के विभिन्न राज्यों में 4,800 रुपये प्रति परिवार एवं 6,400 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष उपभोग व्यय पर वर्ष 1985-86 में व्याप्त गरीबी प्रदर्शित करती है।

सारणी 25.3

भारत में निर्धनता रेखा से नीचे के ग्रामीण
रूपक परिवार, 1985-86

(संख्या लाखों में)

राज्य	वर्ष 1970-71	1985-86	
	के आधार वर्ष पर 1,728 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष के उपभोग व्यय पर	4,800 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष के उपभोग व्यय पर	6,400 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष के उपभोग व्यय पर
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	32 156 (59 32)	44.989 (58 76)	52 038 (67.96)
2. असम	10 196 (51 90)	9.085 (39.54)	10 290 (44.78)
3. बिहार	52 847 (69 74)	85 206 (75 87)	89 225 (79 45)
4. गुजरात	8 988 (36 95)	13.875 (47 35)	16,909 (57.71)
5. हरियाणा	2 692 (38 99)	2.224 (21.98)	3 256 (32.18)
6. कर्नाटक	16 773 (47.23)	23.275 (55 51)	27 411 (65 37)
7. मध्य प्रदेश	31.753 (60 48)	33 289 (51 92)	38 791 (60 51)
8. महाराष्ट्र	28 389 (57 34)	29 895 (43.44)	37 441 (54.41)
9. उड़ीसा	23 385 (68 63)	18 270 (54.89)	22.102 (66 41)
10. पंजाब	3.868 (35.28)	1 104 (10.75)	1 460 (14.21)
11. राजस्थान	20 223 (54.26)	23.933 (53 34)	28 012 (62.43)

1	2	3	4
12 तमिलनाडु	36 246 (68 20)	43 629 (61 02)	58 377 (81 63)
13 उत्तर प्रदेश	111 519 (71 30)	121 702 (67 91)	131 250 (73 26)
14 पश्चिम बंगाल	18 458 (43.77)	27 915 (47 49)	29 350 (49.93)
भारत	442 785 (+ 3 22)	536 577 (60 36)	602 473 (67 78)

Figures in parentheses indicate Percentage of Cultivating House holds below the poverty line to the total Cultivating Households.

स्रोत I J Singh, Agricultural Instability and Farm Poverty in India, Presidential Address to 48th Annual Conference of the Indian Society of Agricultural Economics held at B H U, Varanasi on December 27, 1988

स्पष्ट है कि वर्ष 1985-86 में देश में 6,400 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष के उपभोग व्यय स्तर पर 68 प्रतिशत एवं 4,800 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष के उपभोग ध्यय स्तर पर 60 प्रतिशत ग्रामीण कृषक परिवार गरीबी रेखा से नीचे थे। यह प्रतिशत वर्ष 1970-71 में 63 थी। अतः पिछले 15 वर्षों में निर्धनता की प्रतिशतता में तीन प्रतिशत की कमी आई है, लेकिन निर्धनों की संख्या में 93 लाख की वृद्धि हुई है। विभिन्न राज्यों के आँकड़ों से स्पष्ट है कि पंजाब राज्य के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में ग्रामीण कृषक परिवार जो निर्धनता रेखा से नीचे हैं, की संख्या में वृद्धि हुई है। पंजाब राज्य में निर्धनता रेखा से नीचे के ग्रामीण कृषक परिवारों की संख्या में कमी हुई है, जिसका मुख्य कारण राज्य में कृषि उत्पादन दर एवं विकास में निरन्तर द्रुत गति से वृद्धि होना है।

गरीबी उन्मूलन

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से ही सरकार गरीबी उन्मूलन के प्रति सचेष्ट रही है। गरीबी उन्मूलन को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66) में सम्मिलित किया गया। ग्रामीण गरीबी की समस्या के समाधान हेतु पाँचवी पंचवर्षीय योजना-काल से विशेष प्रयास किये गये हैं। इसके लिए अनेक योजनाएँ शुरू की गई हैं। उपरोक्त कार्यक्रमों को निम्न तीन श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है—

- (i) कृषि विकास के विशेष कार्यक्रम—जैसे—सघन कृषि कार्यक्रम, अधिक उपज देने वाले बीजों का विकास कार्यक्रम, हरित क्रांति आदि ।
- (ii) समस्याग्रस्त क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम—जैसे—सूखे की सम्भावना वाले क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम (डी पी ए पी), मरुस्थल विकास कार्यक्रम (Desert Development Programme) आदि ।
- (iii) कमजोर वर्गों के लिए विशेष कार्यक्रम—जैसे—लघु एवं सीमान्त कृषक विकास कार्यक्रम, आदिवासी विकास कार्यक्रम (Tribal Development Programme), अन्त्योदया कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार का स्वरित कार्यक्रम (Crash Scheme for Rural Employment), समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Intengreted Rural Development Programme), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (National Rural Employment Programme), भूमिहीन श्रमिकों के लिए ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (Rural Land-less Employment Guarantee Programme) ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम (TRYSEM), ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं एवं बच्चों के विकास कार्यक्रम (Development of Women and Children in Rural Areas—DWCRA) ।

उपरोक्त सभी कार्यक्रम रोजगार सृजन करने के साथ साथ आय में वृद्धि भी करते हैं । वर्तमान में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की दिशा में सर्वाधिक प्रभावशाली कार्यक्रम है ।

सातवी योजना के प्रारम्भ (1985-86) में ग्रामीण-क्षेत्रों में 39.4 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे स्तर पर जीवन बसर कर रहे थे । सरकार का इन कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाकर एवं उनका विस्तार करके वर्ष 1994-95 तक गरीबी के अनुपात को 10 प्रतिशत से कम लाने का लक्ष्य है । यह उपलब्धि तभी प्राप्त होना सम्भव है, जब गरीब वर्गों को न केवल गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत ही सहायता दी जावे बल्कि उन्हें अन्य सम्बन्धित कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहायक सेवाएँ भी उपलब्ध की जावें । इसी परिप्रेक्ष्य में छठी योजना में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियाँ बनाई गई थी, जिससे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर समन्वित रूप से ध्यान दिया जा सके, योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्यक्रमों का संचालन होवे और विभिन्न कार्यक्रमों के मध्य में यह सस्था आपस में तालमेल स्थापित करने का कार्य करे ।

पारिभाषिक शब्दावली

(Glossary of Terms)

(इस शब्दावली में अधिकांश हिन्दी पर्याय वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली प्रयोग, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित कृषि एवं प्रयत्नात्म शब्दावली से लिये गये हैं। अन्य शब्दों के चुनाव में निदेशालय द्वारा स्वीकृत सिद्धान्तों का यथासम्भव पूरा ध्यान रखा गया है।

अ	अधिशार	Surcharge
अन्नान्न	अधिशेष	Surplus
अग्रणी/लीड बैंक योजना	अधिक उपज देने वाली किस्में	High yielding varieties
	Scheme	
अचल/स्थायी पूंजी	अधोगामी कर/अवरोही कर	Regressive tax
अन्तरांगीय	अनन्त	Perpetual
अन्तरांकीय	अनुत्पादक ऋण	Unproductive t
अन्तराष्ट्रीय		
अन्तिम बाजार	अनुकूलतम/इष्टतम लाभ	Optimum profit
अर्थ-व्यवस्था	अनुकूलतम जोत	Optimum holding
अदक्ष श्रमिक	अनुकूलतम फसल योजना	Optimum cropping plan
अर्द्ध-विकसित/अल्प विकसित	अनुपाती	Proportionate
	अनुपातिक परिवर्तन	Proportionate change
अधिप्राप्ति/वसूली	अनुपस्थित जमींदारी	Absentee land'ordisq
अधिप्राप्ति-कीमत		
अधिग्रहणित-पूंजी		
	Capital	
अधिदेश श्रेणीचपन/श्रेणीकरण	Mandatory grading	

अनुबद्ध-मण्डारगृह	Bonded warehouse	अविकसित	Undeveloped
अनुमति प्राप्त मण्डार गृह	Licensed warehouse	असमानताएँ	Inequalities
अनार्थिक जोत	Uneconomic holding	अस्फीतिकारी	Non-inflationary
अनिवार्य उसाही/लेवी	Levy		ग्रा
अनियन्त्रित बाजार	Unregulated market	आकलन	Estimate
अनुज्ञात/ऐच्छिक	Permissive or optional grading	आकस्मिक श्रमिक	Temporary
अनुसूची	Schedule	आचलिक/क्षेत्रीय	Casual labourer
अपमिश्रण/मिलावट	Adulteration	ग्रामीण बैंक	Rural Banks
अपेक्षाकृत	Relatively	आहत	Commission
अपूर्ण प्रतिस्पर्धा का बाजार	Imperfect competition market	आदतिया	Commission agent
आकलन मशीनें	Calculating machines	आत्म-निर्भरता	Self-sufficiency
अदायगी क्षमता	Repayment capacity	आर्थिक जोत	Economic holding
अदायगी योजना	Repayment plan	आर्थिक प्रगति	Economic progress
अप्रत्यक्ष कर	Indirect tax	आर्थिक दक्षता/कार्यकुशलता	Economic efficiency
अभिकर्ता-मध्यस्थ	Agent middle-men	आर्थिक विकास	Economic development
अभिकरण/ऐजेंसी	Agency	आर्थिक स्थिरता	Economic stability
अपसारी/विरुद्ध	Divergent	आधार-भारिक संरचना/	Infra-structure
अभ्यारोपित-लागत	Imputed cost	आधार-ढाँचा	Basic holding
अम्बार	Bulk	आधार जोत	Imported
अमूर्त	Intangible	आयातित	Income tax
अरक्षित ऋण	Unsecured credit	आयकर	Income stability
अल्पकालीन ऋण	Short term credit	आय-स्थिरता	Progressive tax
अल्पाधिकार-बाजार	Oligopoly market	आरोही-कर	Imputed cost
अल्पक्रेताधिकार-बाजार	Oligopsony market	आरोपित लागत	Recurring expenditure
अवरोधक	Barriers	आवर्ती लागत	Allocation
अवसर-लागत	Opportunity-cost	आवटन	Partial farm planning
अवतल	Concave	आंशिक फार्म योजना	

इकाई	Unit	उपकर	Cess
इष्टतम लाभ	Optimum profit	उपभोग-पूंजी	Consumption capital
उ		उपभोग व्यय	Consumption expenditure
उच्चतम सीमा	Ceiling	उपभोक्ता	Consumer
उत्पादन शुल्क	Excise duty	उपभोक्ता की मांग	Consumer demand
उतार-चढ़ाव	Fluctuations	उपभोक्ता व्यय	Consumer expenditure
उत्पाद/उत्पत्ति	Product/Output	उपयोग	Utilization
उत्पत्ति के गुणांक	Input-output coefficient	उपयोगिता	Utility
उत्पादन	Production	उपसारी/अभिसारी	Convergent
उत्पादक	Producer	उपोत्पाद	By-product
उत्पादक कीमत	Producer's price	उपज	Produce
उत्पादकता	Productivity	उपदान/प्राथमिक सहायता	Subsidy
उत्पादन-लागत	Cost of production	उप-विभाजन	Sub-division
उत्पादन-फलन	Production function	उर्वरता	Fertility
उत्पादन-क्षमता	Production capacity	ऋणदाता	Creditor
उत्पादन-ऋण	Production credit	ऋणी	Debtor
उत्पादन-दक्षता	Production efficiency	ऋण-पत्र	Debenture
उत्पादन-अवशिष्ट	Producer's surplus	ऋणात्मक	Negative
उत्पादन-साधनों की सूची	Resource Inventory	ऋण-ग्रस्तता	Indebtedness
उत्पादन-पूंजी	Production capital	ऋण की अधिकतम सीमा	Maximum credit limit
उदग्र एकीकरण	Vertical integration	ऋण चुकाने की क्षमता	/Credit repayment capacity
उदासीनता वक्र	Indifference curve	ऋण-भुगतान-क्षमता	
उद्यम	Enterprises	ए	
उद्यमकर्ता	Enterpreneur	एकीकरण	Integration
उद्यमों के संयोग का सिद्धान्त	Principle of enterprise combination	एकीकृत प्रणाली	Integrated system
उत्पाद-सुधार-पूंजी	Product improving capital	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Integrated Rural Development Programme
उन्नतोदर	Convex	एकीकृत विज्ञान	Integrating science
उन्नत बीज	Improved seeds	एकीकरण	Assembling
		एकाधिकारी बाजार	Monopoly market

एकस्त्रोधिकारी बाजार	Monopsony market	न्य-समझौते	Purchase contracts
एकाधिकारी बाजार	Monopoly purchase	कार्यशील-पूंजी/चल-पूंजी	Working capital/Circulating capital
एकाधिकारात्मक बाजार	Monopolistic market	कार्यात्मक-दृष्टि कोण	Functional approach
एजेंट/प्रभिकर्ता मध्यस्थ	Agent middlemen	कार्यात्मक विकास	Functional approach
ऐच्छिक भू-धारण पद्धति	Tenancy at will	कार्यान्वयन/नियाम्बयन	Implement-ation
		करदा	Karda
औ		कार्यशील जोड़े	Operational holdings
औसत उत्पाद	Average product	काम के बढ़ते बनाव योजना	Food For Work Plan
औसत लाभ	Average profit	करदेय-शमता	Taxable capacity
औसत लागत	Average cost	कर-भार	Tax burden
औद्योगिक प्रयंत्रवस्था	Industrial economy	कर-योग्य आय	Taxable income
		कराधान के अनिनियम	Canons of taxation
क		कराधान जांच-प्रायोग	Taxation Enquiry Commission
कर्जदार/भूगुणी	Borrower	कारक	Factors
कीमत-तन्त्र	Price mechanism	काश्तकारी सुधार	Tenancy reforms
कीमत-संरचना/ढांचा	Price structure	कल्पनाएँ/मान्यताएँ	Assumptions
कीमत-विस्तार	Price spread	किसम नियन्त्रण	Quality control
कीमत-स्थिरीकरण	Price stabilization	कृषक सेवा	Farmer Service
कीमत-निर्धारण	Price determination	समितियाँ	Societies
कीमते-नियन्त्रण	Price fixation	कृषि-कर	Agricultural-tax
कीमतों का उतार-चढ़ाव	Price fluctuation	कृषि-जोत	Agricultural holding
कीमत परिवर्तन	Price-movement	कृषि-जोतकर	Agricultural holding tax
कीमत-विभेद	Price discrimination		
कीमत प्रवृत्ति	Price elasticity	कृषि-सम्पत्ति कर	Agr.cultural Wealth-tax
कीमत/आधिक दक्षता	Priming/economic efficiency	कृषि-कराधान	Agricultural taxation

कृषि-आयकर	Agricultural Income tax	कृषि ऋण को विपणन से जोड़ना	Linking of agricultural credit with marketing
कृषि अर्थव्यवस्था	Agricultural economy	कृषि-श्रमिक	Agricultural labourer
कृषि-उत्पादकता	Agricultural productivity	कृषि श्रमिकों का प्रवासन	Migration of agricultural labourers
कृषि कीमत	Agricultural prices	कृषि-पूंजी	Agricultural capital
कृषि-कीमत आयोग	Agricultural Prices Commission	फार्म-पूंजी अधिग्रहण	Acquiring farm capital
कृषि-लागत एवं कीमत आयोग	Commission for Agricultural Costs and Prices	कृषि के रूप	Types of farming
कृषि कीमत स्थिरीकरण	Agricultural price stabilization	कृषि की प्रणालियाँ	Systems of farming
कृषि कीमत नीति	Agricultural price policy	कृषित क्षेत्र	Cultivated area
कृषि-कीमत निर्धारण	Determination/ Fixation of agricultural prices	कृषि-विकास	Agricultural development
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	National Bank for Agriculture and Rural Development	कृषि-व्यवसाय	Agricultural business
कृषि-कीमतों के उतार-चढ़ाव	Fluctuations of agricultural prices	कृषि-क्षेत्र	Agricultural sector
कृषि विपणन	Agricultural marketing	कृष्य-भूमि	Cultivable land
कृषि वित्त	Agricultural finance	कृषि योग्य व्यर्थ भूमि	Cultivable waste land
कृषि वित्त निगम	Agricultural Finance Corporation	कुपोषण	Mal nutrition
कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम	Agricultural Refinance and Development Corporation	काबज प्रमेय	Cob Web theorem
कृषि ऋण	Agricultural credit		ख
कृषि ऋण निगम	Agricultural Credit Corporation	खण्ड	Block/section
		साखानी का शोक व्यापार	Wholesale trade in foodgrains
		खाद्य क्षेत्र	Food zones
		खुदकाश	Owner cultivation
		खुदरा-बाजार	Retail market
		खुदरा व्यापारी	Retailer
		खुली नीलामी	Open auction

ग्राम्य ऋण-ग्रस्तता	ग Rural indebted- ness	चल-सम्पत्ति की प्रतिभूति	Chattel security
ग्राम्य श्रमिक जाच समिति	ग Rural Labour Enquiry Committee	छ छूट की सीमा	Exemption limit
ग्राम्य बेरोजगारी	ग Rural unemployment	ज जमींदारी	Zamindari
ग्राम-अभिकरण योजना	ग Village Adoption Scheme	जल-निकास	Drainage
ग्रामीण क्षेत्र	ग Rural sector	जागीरदारी उन्मूलन	Jagirdari abolition
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	ग Rural Electrification Corporation	जोत केन्द्रीयकरण अनुपात	Holding Concentration ratio
ग्रामीण निर्माण कार्य	ग Rural works	जीवन-स्तर	Living standard
ग्रामोद्योग	ग Rural industries	ज्येष्ठाधिकार कानून	Law of primo- geniture
गुणांक	ग Coefficient	जोखिम-वहन	Risk bearing
गुणात्मक पहलू	ग Qualitative aspect	जोत का आकार	Size of holding
शैर-मोरुसी काश्तकार	ग Tenants-at will	जोत-उपविभाजन	Sub-division of holdings
शैर-वस्थागत, निजी अभिकरण	ग Non- institutional agencies	जोत-प्रपखण्डन	Fragmentation of holdings
घरेलू उत्पाद	घ Domestic product	जोत-चक्रबन्दी	Consolidation of holdings
घरेलू बचत	घ Domestic saving	जोत की उच्चतम सीमा	Ceiling on holdings
घाटे की वित्त-व्यवस्था	घ financing	ट ट्रैक्टरीकरण	Tractorisation
धुमकड़ सौदागर	घ Itinerant Beopari	ड डाल	Slope
चक्रबन्दी	च Consolidation	त तकनीकी परिवर्तन	Technological change
चक्रवृद्धि	च Compounding	तकनीकी व्यवहार्यता	Technical feasibility
चक्रीय परिवर्तन	च Cyclical move ments		
चक्रीय-कीमत उतार-चढ़ाव	च Cyclical price fluctuations		

तकनीकी या कार्यरत Technological
क्षमता Operational efficiency

तालिकाबद्ध नीलामी पद्धति

Roster bid system of auction

तुलनात्मक लाभ का सिद्धान्त Principle
of Comparative advantage

तुलनात्मक समय का सिद्धान्त Principle
of time Comparison

तुलाई Weighing
तौलारा Weighman

थ

थोक बाजार Wholesale market
थोक विक्रेता Wholesaler

द

दलाल Broker
दलाली Brokerage

द्वयाधिकार बाजार Duopoly market

द्वय क्रेताधिकार बाजार Duopsony
market

दक्ष श्रमिक Skilled labourer

दक्षता/कार्यकुशलता Efficiency

दीर्घकालीन Long term

दीर्घकालीन ऋण Long term loan

दुर्लभ साधन Scarce resources

दूरदर्शिता Foresightedness

दोहराव Duplication

दबी हुई स्फीति Suppressed inflation

ध

धलता Dhalta
धनात्मक Positive

न

नकद आय Cash income

नतोदर Concave

नाम मात्र के सदस्य Nominal members

निगम Corporation

निगमोकरण Incorporation

निगमित बचत Corporate saving

निगमित कृषि Corporate farming

निजी जोत Ownership holding

निजी बचत Private saving

निजी क्षेत्र Private Sector

नियत लागत/स्थायी लागत Fixed cost

नियन्त्रित बाजार Regulated market

निर्यात Export

निरन्तरता Continuity

निर्धनता का स्तर Poverty level

निर्धनता-रेखा Poverty line

निरीक्षण Inspection

निरपेक्ष लाभ Absolute margin

निवेश दर Investment rate

न्यूनतम Minimum

न्यूनतम मजदूरी Minimum wages

न्यूनतम जोत Minimum holding

न्यूनतम समर्थित कीमत Minimum
support price

न्यूनतम कीमत Minimum/Floor
price

प

पट्टीदार कृषि Strip cropping

पट्टा Lease

पट्टे पर दी गई भूमि Lease holding

परती भूमि	Fallow land	प्रशासनिक पहलू	Administrative aspect
परम्परागत/प्रचलित कृषि	Traditional farming	पशुधन	Livestock
परिवहन	Transport	पश्चायन विपणन-लाभ	Lagged marketing margin
परिवर्ती लागत/परिवर्तित लागत	Variable cost	प्रक्षेपी	Projected
परिष्करण/प्रोसेसिंग	Processing	प्रबन्ध	Management
परिद्वय	Outlay	प्रबन्धक	Manager
प्रच्छन्न/छिपी हुई बेरोजगारी	Disguised unemployment	प्रभावी माँग	Effective demand
परिवर्तनीय अनुपातों का सिद्धान्त	Principle of Variable proportions	पल्लेदार/हमाल	Pallepar/Hamal
परिसमापन	Liquidating	परिशोधित	Amortised
परिसमापन ऋण	Liquidating loans	परिशोधन-योजना	Amortisation plan
प्रगामी कर	Progressive tax	परिशोधन प्रदायगी योजना	Amortisation repayment plan
प्रचलित कीमत मापदण्ड	Ruling price criterion	प्रत्यक्ष-कर	Direct-tax
प्रतिकूल का सिद्धान्त	Principle of returns	मार्गदर्शी योजनाएँ	Pilot Projects
प्रतिबन्ध	Constraints/Restrictions	प्राथमिक मण्डी/बाजार	Primary market
प्रतिभूति	Security	प्राथमिक थोक बाजार	Primary wholesale market
प्रतिस्पर्धा	Competition	पारिवारिक-फार्म	Family-farm
प्रद्योतन-युक्त	Refrigerated	पारिवारिक जोन	Family holding
मण्डार	Warehouse	पुनर्गठन	Re-organization
प्रतिस्पर्धात्मक उद्यम	Competitive enterprises	पूँजी-निवेश	Capital investment
प्रतिस्थापन	Substitution	पूँजी-अधिग्रहण	Acquiring capital
प्रतिस्थापन दर	Substitution rate	पूँजी संचय	Capital accumulation
प्रतिस्थापन वस्तुएँ	Substitutab = goods	पूँजी-उत्पादन-अनुपात	Capital-output ratio
प्रतिशतता	Percentage	पूँजीगत आवश्यकताएँ	Capital requirements
प्रतिशत-लाभ	Percentage margin	पूँजी-आवर्त अनुपात	Capital turnover ratio
प्रसार	Extension	पूर्ण रोजगार	Full employment

पूर्ण बेरोजगारी	Full unemployment	फार्म-प्रबन्ध	Farm management
पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाला बाजार	Perfect competition market	फार्म-व्यवसाय आय	Farm business income
पूर्ति का नियम	Law of supply	फार्म-दक्षता/कार्यकुशलता के	
पूर्ति की लोच	Elasticity of supply	उपाय	Farm efficiency measures
पूर्वक्रय-अधिकार काय मे लेना	Exercise of pre-emption powers	फसल-ऋण प्रणाली	Crop loan system
पूर्वधारणाएँ/मान्यताएँ	Assumptions	फलों के बाग	Orchards
पूरक उद्यम/सहायक उद्यम	Complementary enterprises	फसल गहनता	Cropping intensity
पैकेजिंग/सवेष्टन	Packaging	फसल योजना	Cropping Scheme
पैमाने के प्रतिफल का नियम	Law of returns to scale	ब	
पैमाने का सीधा सम्बन्ध	Pure scale relationship	बकाया ऋण	Outstanding loan
प्रेरणाएँ	Incentives	बचाव का रस्ता	Loop holes
प्रेरणादायक कीमतें	Incentive prices	बट्टा	Discount
पौध संरक्षण	Plant protection	बट्टा विधि	Discounting
		बन्द निविदा पद्धति से विक्रय	Close tender system of sale
फ		बन्दरगाह के समीप के बाजार	Seaboard market
फार्म	Farm	बन्धक मजदूर प्रणाली	Bonded labour system
फार्म भर्जन	Farm earnings	बन्धक-ऋण	Pledge loan
फार्म आय	Farm income	बफर-स्टॉक	Buffer stock
फार्म की शुद्ध आय	Net farm income	बृहत् स्तर	Macro-level
फार्म की सकल आय	Gross farm income	बागान फसलें	Plantation crop
फार्म का आकार	Farm size	बाजार/मण्डी	Market
फार्म क्रियाएँ	Farm operations	बाजार-कीमत	Market price
फार्म बजट बनाना	Farm budgeting	बाजार दृष्टिकोण सूचना सेवा	Market outlook information service
फार्म-योजना बनाना	Farm planning		
फार्म-योजना क्षितिज	Farm planning horizon		

बाजार समाचार सेवा	Market news service	भू धृति/भू-धारण	Land tenure
बाजार निष्पादन/कार्य	Market Performance	भू-धारण अधिनियम	Land tenancy act
बाजार संगठन	Market organization	भू-धारण अधिकार	Land tenancy right
बाजार संरचना	Market structure	भू-धारण पद्धति वंशागत	Hereditary tenancy
बारानी क्षेत्र	Dry area		
बिचौलिया/मध्यस्थ	Middlemen	भू-धारण भाजीवन	Life tenancy
बैंको पर सामाजिक नियन्त्रण	Social control on banks	भू धारण-पद्धति	Land tenancy system
बैंक-राष्ट्रीयकरण	Bank nationalization	भू-धारी	Land holder
बेलोच मांग	Inelastic demand	भूमि-सुधार	Land reforms
बहु समिकरण दृष्टिकोण	Multi agency approach	भू स्वामी	Landlord/Land owner
बहु फसलीय कार्यक्रम	Multiple cropping programme	भू-स्वामित्व	Land ownership
बहुसंख्यक उत्पादन-लागत विधि	Bulk line cost of production method	भू-राजस्व	Land revenue
		भू-संरक्षण	Soil conservation
		भू-सम्पत्ति	Landed property
		भूमि विकास बैंक	Land Development Bank
		भूमि-कर	Land tax
भ		भू-समतल करना	Land leveling
भण्डार-व्यवस्था	Warehousing	भारतीय ऋण प्रतिभूमि निगम	Credit Guarantee Corporation of India
भण्डार गृह/गोदाम	Warehouse		
भारतीय मानक संस्था	Indian Standard Institutions	भौगोलिक विकास	Geographical development
बन्धक/रेहन ऋण	Hypothecation loan		
भिन्न वस्तुएं	Heterogeneous goods	म	
भूमि का उपयोग	Land utilization	मध्यकालीन/मध्यावधि	Medium term credit
भूमि की उच्चतम सीमा	Land ceiling	ऋण	
भू जोत	Land holding	मध्यवर्ती वस्तुएं	Intermediate goods

मानव-दिवस	Man-days	यादृच्छिक प्रतिचयन	Random
मानव-वर्ष	Man-years		selection
मानकीकरण	Standardization	योगात्मक	Additive
मान्यताओं	Assumptions	योजना आयोग	Planning
मांग	Demand		Commission
माग का नियम	Law of demand		
माग की लोच	Elasticity of demand	र	
मांग उत्पन्न करना/मांग-सृजन करना	Demand creation	रक्षित-ऋण	Secured loan
माध्यमिक धोक बाजार	Secondary wholesale market	राजकीय फार्म	State farm
मात्रात्मक पहलू	Quantitative aspect	राजस्व	Revenue
मिश्रित कृषि	Mixed farming	राजकोपीय नीति	Fiscal policy
मिश्रित बाजार	Mixed market	राष्ट्रीय उत्पाद	National product
मितव्ययिता का ममिनियम	Canon of economy	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण	National Sample Survey
मुआवजा	Compensation	रूप उपयोगिता	Form utility
मुद्रा	Money	रेखीय प्रोग्रामिंग	Linear programming
मुद्रा-परिचलन/संचलन	Money circulation	रोजगार-प्रवसर	Employment opportunities
मुद्रा-स्फीति	Money inflation		
मूल्यांकन	Valuation/Evaluation	ल	
मूल्य-ह्रास	Depreciation	लगान	Reat
मोहसी कासतकार	Occupancy tenant	लघु-विचार	Minor irrigation
य		लघु-कृषक-विकास अभिकरण	Small Farmers Development Agency
यन्त्र	Implicments	सम्बरूप/उदग्र	Vertical
यन्त्रीकरण	Mechanization	लचीलापन	Flexibility
यान्त्रिक कृषि	Mechanized farming	लागत	Cost
यादृच्छिक नीलामी विधि	Random bid system of auction	लागत का सिद्धान्त	Cost principle
		लागत-लेखा-विधि	Cost accounting method
		लागत-संरचना	Cost structure

लाभकारिता/लाभप्रदता	Profitability	वायदा-कीमत पद्धति	Forward pricing system
लीड बैंक योजना	Lead Bank Scheme	वाणिज्यिक बैंक	Commercial bank
लेवी लगाना	Imposing levy	विक्रीत-अधिशेष	Marketed surplus
लोचदार	Elastic	विक्रेय-अधिशेष (विक्री योग्य)	Marketable surplus
लोच का अभिनियम	Canon of elasticity	विक्रय-इकरार/सविदा विकल्प	Sale contract Alternative/choice
व	Curve	विकास	Development
वन-रोपण	Afforestation	विमुद्रीकरण	Demonetisation
वन-जाति विकास योजना	Tribal Development Project	विभेदक व्याज दर नीति	Differential rate of interest
वर्द्धित-मूल्य	Mark-up	विकासोन्मुख/विकासशील अर्थव्यवस्था	Developing economy
वर्द्धमान प्रतिफल का सिद्धान्त	Principle of increasing returns	विचरण-गुणांक	Variability coefficient
व्यक्तिगत कृषि	Individual farming	वित्त	Finance
व्यवहार-विधि दृष्टिकोण	Behavioural system approach	वित्त-व्यवस्था	Financing
वसूली	Procurement	वितरण	Distribution
वस्तुगत दृष्टिकोण	Commodity approach	विद्युतीकरण	Electrification
वस्तुओं की माग उत्पन्न करना/ माँग-सृजन करना	Demand creation	विनिमय कार्य	Exchange functions
वशानुगत कानून/उत्तराधिकार का नियम	Law of inheritance	विपणन	Marketing
व्यय	Expenditure	विपणन-कार्य	Marketing functions
व्यापार-अधिशृङ्खला	Taking over of trade	विपणन-माध्यम	Marketing channel
व्यापारी	Trader	विपणन मध्यस्थ	Marketing middlemen
वायदा बाजार	Forward market	विपणन-क्षमता	Marketing efficiency
		विपणन लाभ	Marketing margin
		विपणन लागत	Marketing cost
		विपणन-सूचना	Market information

विपणन प्रण्ययन के दृष्टिकोण	Approaches of the study of marketing	स्थायी ढचल पूँजी	Fixed capital
		स्थानीय बाजार	Local market
विभाज्यता	Divisibility	स्थावर सम्पदा की प्रातभूति	Real estate security
विविधीकृत कृषि	Diversified farming	स्थान उपयोगिता	Place utility
		सन्तुलन बिन्दु	Equilibrium point
विवेक सगत क्षेत्र	Rational zone		
विवेकपूर्ण	Rational	सशर्त बिन्नयनामा दस्तावेज	Conditional sale deed
विवेक धून्य क्षेत्र	Irrational zone		
विस्तृत कृषि	Extensive farming	स्पर्शी	Tangent
विशिष्ट कृषि	Specialised farming	सम्भावित आय	Potential income
विशिष्ट बाजार	Specialised market	समग्र/सकल	Aggregate/gross
		समयान्तर	Time-lag
स		सम-लागत वक्र	Iso-cost curves
सकल राष्ट्रीय उत्पाद	Gross national product	सम-सोमान्त प्रतिकल का सिद्धान्त	Principle of equi-marginal returns
संग्रहण	Storage		
संचयी	Cumulative	समता	Parity
संचयी प्रक्रिया	Cumulative process	समता-कीमत	Parity price
समरूप/सजातीय वस्तुएं	Homogeneous goods	समता-अनुपात	Parity ratio
सघन कृषि	Intensive agriculture	समग्र कीमत निर्धारण	Aggregate price determination
		समष्टि-भूतक दृष्टिकोण	Macro-economic approach
सरक्षण	Hedging		
सट्टा	Speculation	समष्टि-भूतक अर्थशास्त्र	Macro-economics
सट्टा-मध्यस्थ	Speculative middlemen	सकल कृषित क्षेत्र	Gross cultivated area
स्थायी अधिकार	Perpetuity rights		
स्थायी श्रमिक	Permanent labourer	समन्वय	Co-ordination
स्थायी/स्थिर लागत	Fixed/overhead cost	समपूरक उद्यम	Supplementary enterprises

समान किश्त परिस्रोघन योजना	Equal instalment amortised plan	सहकारी सामूहिक कृषि	Co-operative collective farming
समवर्ती विपणन लागत	Concurrent marketing margin	सहकारी उन्नत कृषि	Co-operative better farming
समोत्पत्ति-वक्र	Isoproduct curve	सहकारी विपणन	Co-operative marketing
समानुपाती	Proportional	सहकारी विपणन-समितिया	Co operative marketing societies
संयुक्त उत्पाद	Joint product	सहायक कार्य	Facilitating functions
संयुक्त स्वामित्व	Joint ownership	साधन	Resources
संयोग/संयोजन	Combination	साधन आवंटन	Resource allocation
संयोजन	Adjustment	सापेक्ष/सोषदार	Elastic
संरचना/ढाँचा	Structure	सापेक्ष लाभ	Relative advantage
संरचनात्मक बेरोजगारी	Structural unemployment	सापेक्ष कीमत	Relative price
संरचनात्मक परिवर्तन	Structural change	संपाश्विक प्रतिभूति	Collateral security
स्वामित्व	Ownership/possession	सामुदायिक विकास	Community Development
सर्वेक्षण विधि	Survey method	सामूहिक कृषि	Collective farming
स्वतन्त्र-उद्यम	Independent enterprises	सारणी	Table
संस्थागत दृष्टिकोण	Institutional approach	सार्वजनिक क्षेत्र	Public sector
संस्थागत ऋण	Institutional credit	साहूकार	Money lender
संस्थागत अभिकरण	Institutional agencies	साम्मे की कृषि/बटाई	Share cropping
सहकारी-कृषि	Co-operative farming	साहूकार कृषक	Agricultural money lender
सहकारी ऋण समिति	Co-operative credit society	साहूकार पेशेवर या व्यावसायिक	Professional money lender
सहकारी संयुक्त कृषि	Co-operative joint farming	सिंचित कृषि	Irrigated farming
		स्थिरीकरण	Stabilization
		स्थिरता	Stability
		स्निग्ध/चिकनाई के पदार्थ	Lubricant

स्फीतिकारी	Inflationary	शुष्क कृषि	Dry farming
सीमान्त	Marginal	शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद	Net national product
सीमान्त उत्पाद	Marginal product	शुष्क क्षेत्र	Dry area
सीमान्त कृषक	Marginal farmer	प्रशुल्क-नीति	Tariff policy
सीमान्त प्रतिफल	Marginal returns		
सीमान्त भौतिक उत्पाद	Marginal physical product	हरित क्रान्ति	Green revolution
सामान्य बाजार	General market	ह्रासमान प्रतिफल का सिद्धान्त	Principle of diminishing returns
सीमान्त आय	Marginal income	ह्रासमान किश्त	Diminishing instalment
सीमान्त लाभ	Marginal return	हाजिर बाजार	Spot market
सीमान्त लागत	Marginal cost		
सीमान्त समायोजन	Marginal adjustment	श्रम अवशोषण	Labour absorption
सीमितता	Finiteness	श्रम-दिवस	Labour-day
सीमित देयता दायित्व	Limited liability	श्रम-प्रधान	Labour oriented
सुदीर्घकालीन बाजार	Secular market	श्रम शक्ति	Labour force
सुधार-कर	Betterment levy	श्रम-प्रतिस्थापन	Labour substitution
सुरक्षित भण्डार स्टाक	Bufferstock	श्रेणीकरण/श्रेणीचयन	Grading
सूखा	Drought	श्रेणी-निर्देश	Grade specifications
सूखा-प्रवणता	Drought prone	क्षमता	Capacity
सूखा प्रवण (प्रवृत्त) क्षेत्र कार्यक्रम	Drought Prone Area Programme	क्षमता-प्रतिस्थापित	Installed capacity
सूखा-प्ररोधक	Drought resistant	क्षमता-अनुमति प्राप्त	Licensed capacity
सूचकांक	Index numbers	क्षेत्रीय/प्रादेशिक बाजार	Regional market
सूत्र	Formula		
सौदागर-मध्यस्थ	Merchant middlemen	क्षैतिज	Horizontal
		क्षैतिज एकीकरण	Horizontal integration
श्वेत क्रान्ति	White revolution	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	Regional Rural Banks
शीत सग्रहागार	Cold storage		
शुद्ध उत्पाद	Net product		
शुद्ध सम्पत्ति	Net worth		
शुद्ध कृषित क्षेत्र	Net sown area/Net cropped area		

नामानुक्रमणिका

‘अ’

- अकृष्य भूमि 77
अखिल भारतीय ऋण सर्वेक्षण समिति 353
अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण जाँच समिति 313
अखिल भारतीय शुष्क भूमि कृषि समन्वय अनुसन्धान प्रोजेक्ट 265
अग्रणी बैंक योजना (लीड बैंक योजना) 334
अच्छी विपणन पद्धति की विशेषताएँ 385
अचल पूँजी (स्थायी पूँजी) 154
अति मूल्यवादी कीमत 555
अति कीमत स्फीति 522
अर्थशास्त्र की परिभाषा 1
अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का देश के समग्र घरेलू उत्पाद में अंशदान 39
अदक्ष या साधारण श्रमिक 124
अई बेकारी 127
अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्था 21
अधिक अन्न उपजाने कार्यक्रम 24, 598
अधिक व्याज से मुक्ति दिलाने का कानून 298
अधिग्रहित पूँजी 155
अधिप्राप्ति या बसूली कीमत 71
अधिदेश श्रेणीचयन 414
अन्तर्राष्ट्रीय (विश्व) बाजार 389
अनाधिक जाँच 41
अनाधिक जाँचों को आर्थिक जाँचों में परिवर्तित करने के सुझाव 89
अनियमित कीमत उतार-चढ़ाव 514
अनियन्त्रित कीमत स्फीति 522
अनियन्त्रित बाजार 392
अन्तिम बाजार 390
अनिश्चितता के वतावरण में फार्म प्रबन्ध का योगदान 163
अनुकूलतम जाँच 85
अनुकूलतम फसल योजना 250
अनुकूलन (इष्टतम) लाभ 173
अनुत्पादक ऋण 283
अनुवृद्ध भण्डार गृह 425
अनुज्ञात (ऐच्छिक) श्रेणीचयन 414
अनुपस्थित जमींदारी 40
अनुसन्धान फार्म 273
अप्रत्यक्ष उत्पादन ऋण 283
अप्रत्यक्ष कृषि कर 564
अपरिसमापन ऋण 366
अपूर्ण स्पर्धा वाले बाजार 391
अन्तर्दया योजना 141
अधिकर्ता या ऐजेन्ट मध्यस्थ 398

अमृतं कारक 155

अरक्षित ऋण 285

अल्पकालीन कीमत 558

अल्पकालीन कीमत उतार-चढ़ाव 513

अल्पकालीन बाजार 390

अल्पकालीन ऋण 283

अल्पक्रेताधिकार बाजार 391

अल्पाधिकार बाजार 391

अवसर परिचय या वैकल्पिक लाभ 205-206

अस्थायी (आकस्मिक) श्रमिक 124

असम्बन्ध (स्वतन्त्र) उद्यम 212

असीमित पूँजी 224

अशकालीन कृषि 272

‘आ’

आकस्मिक (अस्थायी) श्रमिक 124

आधुनिक (क्षेत्रीय) ग्रामीण बैंक 339

आढतिया 399

आर्थिक जोत 85

आर्थिक जोत एवं आर्थिक जोत निर्धारण के आधार 87

आर्थिक जोत के प्रकार के निर्धारक तत्व 88

आदर्श मूलक विज्ञान 5

आधार जोत 84

आधारभूत संरचना का विकास 610

आरोप्य लगान राशि 251

आसामी कृषक 95

आर्थिक परिस्थिति ऋण 366

आर्थिक फार्म योजना एवं बजट 229-231

‘इ’

इष्टतम लाभ की राशि 173

इन्फ्लेट-ड्राइफ्ट गुणांक 242

‘उ’

उत्पादन अधिशेष 400

उत्पाद परिवर्तक पूँजी 155

उत्पाद घट्टक पूँजी 155

उत्पादों में विनाशशीलता का गुण 517

उत्पादन अर्थशास्त्र 6

उत्पादन कारकों के स्वामी 76

उत्पादन का पैमाना 9

उत्पादन की पूँजी 155

उत्पादक कीमत 449

उत्पादन पूँजी 154

उत्पादन काल के क्षेत्र 176-177

उत्पादन लाभ ज्ञात करना 236

उत्पादन साधनों एवं उत्पादों के गुणांक 237

उत्पादन-साधनों की प्रतिस्थापन दर 195

उत्पादन में समय-पश्चता 9

उत्पादन सम्भावना वक्र 213

उत्पादन सुधार पूँजी 155

उत्पादन-ऋण 283

—अप्रत्यक्ष उत्पादन-ऋण 283

—प्रत्यक्ष उत्पादन-ऋण 283

उदयम बिन्दु से घबराव 178

उदयम से उन्नत 189

उदय एकीकरण 455

उदासीनता वक्र 199

उद्यमों/किसानों का चुनाव 234

उद्यमों/किसानों का बजट बनाना 234

उद्यमों के संयोग का सिद्धान्त अथवा उद्यमों के प्रतिस्थापन का सिद्धान्त 212 221

उप पट्टेदारी 93

उपमोक्षा द्वारा दिए गए रुपये में से उत्पादक कृषक को प्राप्त भाग 449

उपभोग पूँजी 154

उपयोगिता 384

—रूप उपयोगिता 384

—समय उपयोगिता 384

—स्थान उपयोगिता 384

—स्वामित्व उपयोगिता 385

‘ए’

एकक्रेताधिकार बाजार 391

एकाधिकार ऋय 71

एकाधिकार बाजार 391

एकाधिकारमय बाजार 391

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 140,
625

एक मुश्त प्रदायगी योजना, 369

एगमार्क 415

ऐच्छिक या अनुज्ञात श्रेणीचयन 414

ऐच्छिक भू-धारण कृषि 280

एजेन्ट/अभिकर्ता मध्यस्थ 398

‘घो’

घोसत आय 36-37

घोसत उत्पाद 172-173

घोसत उत्पादन लागत विधि 546

घोसत पूँजी निवेश 239

‘क’

कपड़े की आड़ (आवरण) में गुप्त सकेतो
द्वारा विनियम करना 430

कम्प्यूटर्स फार्म 278

क्रमिक कीमत स्फीति 522

क्रय इकरार 153

क्रय-विनियम 429

कराधान के अभिनियम 563

कृषक साहूकार 354

कृषि आयकर 570-581

—से प्राप्त आय 572

—के पक्ष एवं विपक्ष में दिए गए
तर्क 574-575

—के लिए नियुक्त राज समिति 576

कृषि अर्थशास्त्र के अध्ययन की सीमाएँ 7

कृषि अर्थशास्त्र की परिभाषा ■

कृषि अर्थशास्त्र की प्रकृति 5

कृषि अर्थशास्त्र के विभाग 6

कृषि अर्थशास्त्र का क्षेत्र 4

कृषि उत्पादन का प्रकृति पर निर्भर होना
18

कृषि उत्पादों की उत्पादकता का स्तर
22, 30, 64

कृषि में उत्पादकता स्तर के कम होने के
कारण 30

कृषि उत्पादन मण्डल 289

कृषि एवं औद्योगिक अर्थव्यवस्था में
अन्तर 7

कृषि उपज (विकास एवं मण्डार व्यवस्था)
नियम अधिनियम 422

कृषि उपज (श्रेणीचयन एवं विपणन)
अधिनियम 415

कृषि उत्पादों की कीमत निर्धारण 545-
562

कृषि कराधान 563-584

कृषि करो का वर्गीकरण 564

—प्रत्यक्ष कृषि कर 564

—अप्रत्यक्ष कृषि कर 564

कृषि में तकनीकी ज्ञान का विकास
598-627

कृषि में प्राकृतिक प्रकोप 64

कृषि कीमतें 498-502

से तात्पर्य 498

के कार्य 498

- के अध्ययन की आवश्यकता 500
- के उतार-चढ़ाव 502-521
- के उतार-चढ़ाव के रूप 513
 - अल्पकालीन कीमत उतार-चढ़ाव 513
 - प्रनियमित कीमत उतार-चढ़ाव 513
 - षट्तीय कीमत उतार चढ़ाव 514
 - सौसमी कीमत उतार-चढ़ाव 514
 - वार्षिक कीमत उतार-चढ़ाव 514
 - सुदीर्घकालीन कीमत उतार-चढ़ाव 514
- कृषि कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ावों के कारण 517
- कृषि कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ावों का प्रभाव 514
- कृषि कीमत नीति को दूरदर्शी बनाना 532
- कृषि कीमत स्थिरीकरण 523-534
 - से तात्पर्य 523
 - के उद्देश्य 524
 - के उपाय 524
 - में कठिनाइयाँ 533
- कृषि-जोत 78
- कृषि जोतकर 577
- कृषि जोतकर के निर्धारण की विधि 578
- कृषि जोतों का वर्गीकरण 81-88
 - कृषि जोत 84
 - ग्राधार जोत 84
 - मनुकूलतम जोत 85
 - प्राथमिक जोत 85
 - निजी जोत 84
 - न्यूनतम जोत 85
 - पारिवारिक जोत 86
- कृषि कीमत नीति 535-544
- कृषि कीमत नीति के कार्यान्वयन में सुधार के उपाय 542
- कृषि कीमत नीति के निर्धारण के लिए नियुक्त समितियाँ एवं उनके सुभाव 536
- कृषि कीमत जाँच समिति 537
- कृषि कीमत परिवर्तन जाँच समिति 537
- कृषि कीमत नीति के उद्देश्य 535
- कृषि कीमतों के निर्धारण के माध्यम 546
 - घाँसत उत्पादन लागत विधि 546
 - बहुसंख्यक उत्पादन लागत विधि 547
 - प्रचलित कीमत विधि 547
 - समतता कीमत सूचक विधि 547
 - वायदा कीमत विधि 548
- कृषिगत उत्पादों के उत्पादन में विशिष्टीकरण एवं विविधता 220
- कृषि गैर श्रम सहकारी समितियाँ 645
- कृषि जीवन निर्वाह का साधन 19
- कृषि जनगणना 13, 73, 75
- कृषि पूँजी 151-155
- कृषि पूँजी अधिश्रृंखला स्रोत 152
- कृषि पूँजी के प्रकार 154
- कृषि में पूँजी निवेश 22
- कृषि में पूँजी एवं श्रम की आवश्यकता 287
- कृषि में पूँजी एवं श्रम की आवश्यकता के आकलन 288
- कृषि पुन वित्त एवं विकास निगम 347
- कृषि बीमा 628-639
 - रूफसल बीमा 628-637
 - पशु बीमा 637-639

कृषि योग्य व्यय भूमि 77, 79

कृषि मन्त्रीकरण एवं हरित क्रान्ति का

कृषि धर्म पर प्रभाव 145-150

कृषि के रूप निर्धारित करने वाले कारक
254

कृषि लागत एवं कीमत मायाग 71, 539

कृषि लागत एवं कीमत मायाग द्वारा
पोषित कीमतें 540

—अधि प्राप्ति वचूली कीमत 541

—न्यूनतम समर्थित कीमत 65,
540

कृषि के विभिन्न रूप एवं प्रणालियाँ
253-280

—कृषि के रूप 253-272

—कृषि की प्रणालियाँ 272-280

कृषि के विभिन्न रूपों एवं प्रणालियों का
वर्गीकरण 256-257

कृषि वस्तुओं के श्रेणीकरण के लिए
प्रमाण पत्र प्राप्त करने की विधि
415

कृषि वस्तुओं के श्रेणीकरण के लिए श्रेणी
निर्देश 416

कृषि वस्तुओं में परिवहन लागत 411

कृषि विस्तार सेवा 44

कृषि वित्त नियम 350

कृषि वित्त 281-298

कृषि वित्त के दृष्टिकोण 281

कृषि वस्तुओं की अधिकतम एवं न्यूनतम
कीमत नियत करना 226

कृषि वस्तुओं के व्यापार का सरकार
द्वारा अधिग्रहण 526

कृषि व्यवसाय में पूँजी निवेश दर 22

कृषि व्यवसाय में पूँजी एवं ऋण की
आवश्यकता के आकलन 283

कृषि व्यवसाय की सफलता के नियम
167

कृषि व्यवसाय की सफलता के व्यावसा-
यिक सिद्धान्त 168

कृषि व्यवसाय में कुशल प्रवर्धक की
आवश्यकता 156

कृषि वस्तुओं की माँग एवं पूर्ति की मात्रा
में असन्तुलन होना 517

कृषि वस्तुओं के विपणन में होने वाली
विपणन लागत एवं प्राप्त विपणन
लाभ 451-456

कृषि वस्तुओं की कीमतों के निर्धारण में
समय का महत्त्व 555

कृषि वस्तुओं की पूर्ति में कमी प्रपञ्च
वृद्धि का कीमतों पर प्रभाव 554

कृषि वस्तुओं की कीमत निर्धारण में
आवश्यक सावधानियाँ 545

कृषि विपणन 380

—की परिभाषा 380

—के उद्देश्य 382

—का आर्थिक विकास में महत्त्व
385

—के क्षेत्र में पारित प्रमुख अधि-
नियम 493

कृषि विपणन व्यवस्था के दोष निवारण
के उपाय 465

कृषि सवृद्धि, विकास एवं योजना 87

कृषि साख की एकीकृत योजना 422

कृषक सेवा समितियाँ 338

कृषि सम्पत्ति कर 581

कृषि सम्पत्ति कर के लिए राज सम्पत्ति
के सुझाव 282

कृषि धर्म जाँच समिति 118
 कृषि धर्मिक 118
 कृषि धर्मिक परिवार 119
 कृषि धर्मिकों का प्रवचन 151
 कृषि धर्मिकों का राष्ट्रीय कृषि जाय में योगदान 123
 कृषि धर्मिकों का वर्गीकरण 123
 —स्थायी धर्मिक 123
 —भ्रष्ट साधारण धर्मिक 124
 —अस्थायी/आकस्मिक धर्मिक 124
 —दक्ष धर्मिक 124
 कृषि धर्मिकों की समस्याएँ 125
 कृषि धर्मिकों की मजदूरी दर 135
 कृषि धर्मिकों की विशेषताएँ 119
 कृषि धर्मिकों की सख्या 120
 कृषि धर्मिकों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास 138
 कृषि धर्मिकों में बेरोजगारी एवं अर्द्ध बेकारी 126
 कृषि धर्मिकों में व्याप्त बेरोजगारी 41
 कृषि धर्मिकों में व्याप्त बेरोजगारी व अर्द्ध बेकारी के लिए नियुक्त समितियाँ 132
 —ईतिवाला समिति 132
 —भगवती समिति 133
 कृषि धर्मिकों में व्याप्त बेरोजगारी एवं अर्द्ध बेकारी का आकलन 128
 कृषि धर्मिकों में न्यूनतम मजदूरी लागू करने में बाधाएँ 137
 कृषि क्षेत्र पर व्यक्तियों की निर्भरता 23
 कृषित क्षेत्र 78
 —सकल कृषित क्षेत्र 78

—शुद्ध कृषित क्षेत्र 78
 कृषि ऋण निगम 351
 कृषि ऋण का वर्गीकरण 282
 कृषि ऋण की समस्याएँ 286
 कृषि ऋण के स्रोत 299-360
 कृषि ऋण सहकारी समितियाँ 645
 कृषि ऋण में साहकारों की प्रमुखता 354
 कृषि ऋण की विपणन से सम्बन्धिता 359
 कृषि ऋण के संस्थागत व्यवस्था पर अनौपचारिक हल 313
 कृषक ऋण अधिनियम 305
 कृषकों का उत्पादन अधिशेष 400
 —विक्रीय अधिशेष 400
 —विक्रीत अधिशेष 400
 कृषकों की जोखिम-बहन योग्यता 362, 376, 377
 कृषकों की ऋण धदायगी क्षमता 362, 364, 367
 कृषकों के लिए ऋण की आवश्यकता 282
 कायेस कृषि सुधार समिति 159
 कायेस भूमि सुधार समिति 84
 कॉंबेबेड प्रमेय की विभिन्न स्थितियाँ 9
 —धर्मसारी 9
 —उपसारी 9
 —सतत 9
 काम के बदले प्रनाज योजना 141
 कार्यगत कार्यशील चल पूँजी 154
 कार्यशील जोतों की सख्या एवं उनके अन्तर्गत क्षेत्रफल 82-83
 कार्यात्मक विपणन दृष्टिकोण 397

- काश्तकार कृषि 280
 काश्तकारी सुधार अधिनियम 96
 काश्तकारी सुधार के 'तीन' एफ 96
 किस्म नियन्त्रण 412
 किन्दुत फार्म 279
 कीमत उप समिति 536
 कीमत जोखिम 434
 कीमत निर्धारण एवं कीमतों का पता लगाना 436
 कीमत विस्तार 451
 कीमत स्फीति 521
 कीमत स्फीति के प्रकार 522
 —प्रति स्फीति 522
 —प्रतियन्त्रित स्फीति 522
 —क्रमिक/मन्द स्फीति 522
 —द्रुत स्फीति 522
 —दबी हुई स्फीति 522
 —मॉग जन्य स्फीति 522
 —लागत जन्य स्फीति 522
 कीमतों का विलोम अनुपात 186
 कीमत निर्धारण की विधियाँ 550
 —समूह/समग्र कीमत निर्धारण या समष्टि मूलक कीमत निर्धारण विधि 550
 —व्यष्टि मूलक कीमत निर्धारण या प्रति इकाई कीमत निर्धारण विधि 550
 कुवकुट पालन फार्म 263
 कुल उत्पाद 172
 कुल उत्पाद एवं सीमान्त उत्पाद में सम्बन्ध 175
 कुल विचरण गुणांक 377
 कुशल कृषि प्रबन्धक/व्यवस्थापक के कार्य एवं गुण 156-157
 क्रेडो 281
 केन्द्रीय वैकिम जाँच समिति 289
 केन्द्रीय भूमि सुधार समिति 113
 केन्द्रीय मण्डार गृह निगम 423
 केन्द्रीय सहकारी बैंक 309
 केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन 34
 कोलसोज फार्म 279
 ख
 खाद्य एवं कृषि संध 54
 खाद्य स्थिति 46
 खाद्यान्न उत्पादन की प्राथमिकता 17
 खाद्यान्नों के उत्पादन वृद्धि में क्षेत्रफल एवं उत्पादकता का योगदान 52
 खाद्यान्न जाँच समिति 537
 खाद्यान्न नीति समिति 536, 538
 खाद्यान्न फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थित कीमतें 527
 खाद्यान्नों का राशानिग 526
 खाद्यान्नों की कृषि 262
 खाद्यान्नों की कीमतों में उतार-चढ़ाव 508-512
 खाद्यान्नों की माँग की जाय-लोच 21
 खाद्यान्नों की वसूली कीमत 530
 खाद्यान्नों की वितरण प्रणाली 73
 खाद्यान्नों के क्रय में पूर्वक्रय अधिकार प्रथा 70
 खाद्यान्नों के थोक व्यापार का सरकार द्वारा अधिग्रहण 495
 खाद्यान्नों के वितरण के लिए नियत बिंदी कीमतें 74-75
 खाद्यान्नों के विपणन में पाए जाने वाले विपणन मध्यस्थ 398-399
 खाद्यान्नों के संचयन पर नियन्त्रण लगाता एवं खाद्य क्षेत्रों का निर्माण करना 525
 खाद्य क्षेत्रों का निर्माण 69
 खुदरा मण्डी (बाजार) 389, 392

सुदरा व्यापारी 398
 सुली नीलामी विक्रय विधि 431
 —फड नीलामी विधि 431
 —तालिकाबद्ध नीलामी विधि 431
 —यार्डचिह्नक नीलामी विधि 431
 सुले बाजार में छायाओं की खरीद 69

श

शक्तिशाल यन्त्रीकरण 266
 शरीबी की परिभाषा 652
 शरीबी का मापदण्ड 654
 शरीबी के प्रकार 652
 शरीबी रेखा 653
 शरीबी के अनुमान 655
 शरीबी उन्मूलन 659
 शान धमिग्रहण योजना 335
 शाम्य समाजशास्त्र 7
 शाम्य सुधार समिति 91
 ग्रामीण कृषक परिवारों में व्याप्त शरीबी 657
 ग्रामीण बाजार 389
 ग्रामीण व्यापारी 399
 ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के लिए रोजगार गारण्टी कार्यक्रम 141
 ग्रामीण रोजगार का क्लेश कार्यक्रम 140
 ग्रामीण बिद्युतीकरण निगम 352
 ग्रामीण श्रम जांच समिति 294
 ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के कारण 133
 ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी समस्या का निवारण 133
 ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं एवं बच्चों के विकास के कार्यक्रम (DWCRA) 143, 627

ग्रामीण ऋण ग्रस्तता 292
 —के आलोकन 292
 —के कारण 295
 —के दुष्परिणाम 297
 —का निवारण 297
 ग्रामीण युवाओं के लिए स्वतः रोजगार प्रशिक्षण (TRYSEM) 143, 627
 गैर कृषि गैर ऋण सहकारी समितियाँ 645
 गैर कृषि सहकारी ऋण समितियाँ 645
 गैर मौसमी काश्तकार 94
 गैर सत्यागत या निजी धनिकरण 285, 299, 353
 गेहूँ की शोक व्यापार नीति 72
 गोबर भूमि 77

‘घ’

घरेलू ऋणग्रस्त गृह 425
 घाटे की वित्त व्यवस्था 519
 धूमकण्ड सौदागर 399

‘च’

चक्रवृद्धि विधि 222
 चक्रीय कीमत उतार-चढ़ाव 514
 चसगाह भूमि 77
 चल पूंजी (कार्यशील पूंजी) 154
 चल सम्पत्ति की प्रतिभूति पर ऋण 284

‘छ’

छिपी हुई बेरोजगारी 127
 छोटे पैमाने पर कृषि 271

‘ज’

- जमींदारी एवं जागीरदारी पद्धति 93
जमींदारी एवं जागीरदारी प्रथा का
उन्मूलन 95
जवाहर रोजगार योजना 143
जागीर उन्मूलन कानून 96
जेष्ठाधिकार कानून 102
जोखिम वहन 434
—मौलिक जोखिम 434
—कौमन जोखिम 434
जोखिम बीमा सुविधा 10
जोत भण्डारण 169, 99
जोत उपविभाजन 98
जोत उपविभाजन एवं भण्डारण 40,
98
—के कारण 99
—के दोष 100
—को रोकने के उपाय 101
—के लाभ 100
जोत की उच्चतम सीमा/नू सीमा
106-114
जोत का घाटन आकार 16
जोतों की समस्याएं एवं आकार 13-16
जोत केंद्रीकरण अनुपात 107
जोत चक्रवर्ती 102-106
—की प्रगति 104
—की विधि 104
—के कार्य में आने वाली कठिनाइयाँ
106
—से लाभ 103

‘ट’

टिप्पणियाँ 91

ठोस कृषि नीति का अभाव 43
ठोस या नुद कृषि ऋण व्यवस्था के
गुण 285

‘ड’

देरी फार्म या दूध उत्पादन के फार्म
263

‘त’

तकावी ऋण 304-308
तालिकाबद्ध नीलामी विधि 431
तिलहन फसलों की घोषित मूल्य
समयित कीमत 529
तुलनात्मक लाभ/सापेक्ष लाभ 225
तुलनात्मक लाभ का सिद्धान्त 225-226
तुलनात्मक समय का सिद्धान्त 221-224
तज्जिद 395
तीलारा 399

‘थ’

थोक बाजार 392
थोक व्यापार नीति 72
थोक व्यापारी 398

‘द’

दंडा विक्रय 432
दबी हुई कीमत स्फीति 522
दयाधिकार बाजार 391
दत्तान्त 399
दक्ष धनिक 124

- क्षेत्र कृषक सहायता अधिनियम 297
 विक्रेताधिकार बाजार 391
 दीर्घकालीन कीमत (सामान्य कीमत)
 559
 दीर्घकालीन कीमत का उत्पादन लागत
 से सम्बन्ध 560
 दीर्घकालीन बाजार 390
 दीर्घकालीन ऋण 284
 द्रुत कीमत स्फोति 522
 दूध उत्पादन के फार्म (डेरी फार्म) 263

‘ध’

धनात्मक या यथार्थमूलक विज्ञान 5

‘न’

- नई कृषि नीति 650-651
 नमूने के द्वारा विक्रय 432
 नमूने के द्वारा विक्रय बाजार 390
 नाफेड 487-489
 नाबाई 343-346
 नाशवान कृषि वस्तुओं में अति अल्प-
 कालीन कीमतें छात करना 557
 निगम 347

—कृषि पुनः वित्त एवं विकास
 निगम 347

—कृषि वित्त निगम 350

—ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
 352

—कृषि ऋण निगम 351

—निगमीकरण 152

निगमित कृषि 279

निजी जोत 84

नियन्त्रित बाजार 392

नियन्त्रित मण्डिया 466-477

—की कार्य प्रणाली 469

—की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु
 राष्ट्रीय कृषि आयोग की
 सिफारिशें 474

—की प्रगति 472

—के उद्देश्य 467

—की स्थापना 467

—से सात्वय 466

—से कृषकों को लाभ 468

—से उपभोक्ताओं को लाभ 469

नियत विक्री कीमतें 73

निरपेक्ष लाभ 225, 449

निरीक्षण 418

न्यूनतम जोत 85

न्यूनतम मजदूरी 136

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 136

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को कृषि

क्षेत्र में लागू करने में बाधाएँ 137

न्यूनतम लागत का सिद्धान्त/साधनों एवं
 क्रियाओं के प्रतिस्थापन का सिद्धान्त
 193-205

—समान दर से उत्पादन साधनों
 में प्रतिस्थापन 196-197

—ह्रास दर से उत्पादन साधनों
 में प्रतिस्थापन 198-205

न्यूनतम समर्थित कीमत 71

‘प’

प्रच्छन्न बेरोजगारी 127

प्रचलित कृषि 266

प्रचलित कीमत विधि 548

पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि 585-
 597

पट्टीदार कृषि 264

पट्टे पर प्राप्त भूमि पर कृषि 280,

परती भूमि 77, 79
 परिप्रेक्ष्य योजना विभाग 54
 परिवर्तनशील लागत 208
 परिवर्तनीय अनुपात का सिद्धान्त 171,
 172-190
 —हासमान प्रतिफल का सिद्धान्त
 177-185
 —वर्द्धमान प्रतिफल का सिद्धान्त
 188-190
 —समान प्रतिफल का सिद्धान्त
 185-188
 परिवर्ती या आभास परिवर्ती परिशोधन
 योजना 371
 परिवहन 409-412
 परिवहन लागत 410
 परिवहन समस्याएं 411
 परिवहन साधन 410
 परिष्करण (प्रोसेसिंग) 429
 पल्लेदार (हमाल) 399
 पशुधन विपणन लाभ 448
 पशु बीमा 637-639
 पशु बीमा योजना की प्रगति 639
 पशु बीमा योजना के कार्यान्वयन में
 कठिनाइयाँ 637
 प्रतिफल का सिद्धान्त 7, 171-193
 प्रति व्यक्ति आय 36
 प्रतिस्पर्धात्मक उद्यम 215-220
 प्रतिशत लाभ 449
 प्रत्यक्ष कृषि कर 564
 प्रत्यक्ष उत्पादन ऋण 283
 प्रतिस्थापन/उद्यमों के संयोज का सिद्धान्त
 212-221
 प्रदर्शन फार्म 273
 प्रबन्ध 155-157, 160
 प्रबन्ध प्रतिफल 239

प्रबन्ध माधन की कार्यकुशलता ज्ञात
 करने के उपाय 239
 प्रबन्धक/व्यवस्थापक के कार्य एवं गुण
 156-157
 प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियाँ
 309
 प्राथमिक थोक बाजार 389
 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की प्रवृत्त ऋण
 सुविधा 327
 प्राथमिक सहकारी विपणन समितियाँ
 481
 पारिवारिक आवश्यकता की पूंजी 155
 पारिवारिक कृषि 272
 पारिवारिक जोत 86
 पारिवारिक फार्म 159
 पारिवारिक सदस्यों के श्रम द्वारा कृषि
 272
 पूंजी 151-155
 पूंजी अधिग्रहण 152, 281
 पूंजी-आवर्त अनुपात 288
 पूंजी उत्पादन अनुपात 239
 पूंजी निवेश प्रतिफल 239
 पूंजी प्रधान कृषि 273
 पूंजी संचय 153
 पूंजी साधन की कार्यकुशलता ज्ञात करने
 के उपाय 239
 पूर्ण रोजगार 127
 पूर्ण स्पर्धा के बाजार 391
 —प्रति 551
 पूरक उद्यम (सहायक उद्यम) 214
 प्रेरणादायक कीमत 609
 पैकेज कार्यक्रम (सघन कृषि जिला
 कार्यक्रम) 600
 पैकेज कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ
 601

पंकेज कार्यक्रम के उद्देश्य 601
पंकेजिंग (सर्वेस्टन) 408-409
पंतुक भू-धारण कृषि 280
पमाने के प्रतिफल का सिद्धान्त 171,
190-193

पेवोथर साहूकार 354
प्रोमेसिय (परिष्करण) 429
पौध संरक्षण सुविधा 613

'क'

कड नीलामी विधि 431
कलो के बाग 262
कसल उत्पादकता सूचकांक 240
कसल गहनता 238
कसल क्रम योजनाओं के जाच-पत्र तैयार
करना 238
कसल योजना तैयार करना 237
कसल बीमा 628-637
कसल बीमा योजना का कार्यान्वयन
630
कसल बीमा से लाभ 629
कसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में
ग्रामिणों की कठिनाईयाँ 636
कसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय कृषि
आयोग के सुझाव 636
कसल बीमा योजना के कार्यान्वयन से
प्राप्त परिणाम 631
कसल बीमा की पायलट योजना 632
कसल बीमा की व्यापक योजना 632-
636
कसल ऋण प्रणाली 332
कसलो के बजट बनाना 236
कार्म 158, 159

कार्म अर्जन 239
कार्म प्रबन्ध 160-162
कार्म प्रबन्धक 156-157
कार्म प्रबन्ध के उद्देश्य 162
कार्म प्रबन्ध का क्षेत्र 166
कार्म प्रबन्ध का कृषि विज्ञान के अन्य
विषयों से सम्बन्ध 164
कार्म प्रबन्ध एवं कृषि अर्थशास्त्र में
सम्बन्ध 165
कार्म प्रबन्ध के सिद्धान्त 171-226
कार्म कार्यकुशलता के उपाय 238
कार्म योजना के लिये जलमो का चुनाव
एवं उनके बजट तैयार करना 234
कार्म बजट 228
कार्म योजना 227-240
कार्म योजना एवं बजट बनाना 233
कार्म योजना एवं बजट बनाने की विधि
233
कार्म योजना एवं कार्म बजट की भाव-
शक्ति 228
कार्म योजना एवं कार्म बजट के प्रकार
229
— प्राथमिक कार्म योजना एवं बजट
229
— सम्पूर्ण कार्म योजना एवं बजट 229
कार्म योजना का विश्लेषण करना 238
कार्म योजना की विशेषताएँ 231
कार्म योजना को कार्यान्वित करना 240
फोर्ड संस्थान दत्त 538, 599

'ख'

खजूर एवं महुआ नूति 77
बट्टा विधि 222

बड़े पैमाने पर कृषि 272
 बन्द निविदा पद्धति से विक्रय 432
 बन्दरगाहों के समीप के बाजार 390
 बन्धक मजदूर प्रथा 139
 बन्धों (स्थिर) लागत 208
 बफर स्टॉक का निर्माण 526
 बहु प्रतिकरणा दृष्टिकोण 336
 बहु फसलीय कार्यक्रम 608
 बहु संयुक्त उत्पादन लागत विधि 547
 बाजार—परिभाषा 387
 बाजार—के लिए आवश्यकताएँ 388
 बाजार—विकसित की विशेषताएँ 388
 बाजार दृष्टिकोण सूचना सेवा 438
 बाजार निष्पादन/कार्य 459
 बाजार व्यवहार 459
 बाजार समारोह सेवा 438
 बाजार संरचना 459, 461
 बाजारों का वर्गीकरण 388-392
 बीजवर्धन फार्म 273
 बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम 346, 648
 बेगार प्रथा 96
 बेरोजगारी 126-135

—प्रबन्धन या छिपी हुई बेरोजगारी 127

—संरचनात्मक बेरोजगारी 127

बेरोजगारों के लिए रुडसेट 145

बेलोचदार भाँग 11

बैंक राष्ट्रीयकरण 321

वैको पर सामाजिक नियन्त्रण 321

‘भू’

भण्डार-गृहों का वर्गीकरण 424

भण्डारगृह नियम 423

—केन्द्रीय भण्डार गृह नियम 423

—राज्य भण्डार गृह नियम 423

भण्डार गृह निर्माण के उद्देश्य 424

भण्डार गृह व्यवस्था 422

भण्डार व्यवस्था नियम अधिनियम 422

भारत के विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति

घोसल घाय 36

भारत के विभिन्न राज्यों में 'जोती की

संख्या एवं घोसल आकार 82

भारत में कृषि यन्त्रीकरण के क्षेत्र में हुई

प्रगति 266

भारत में कृषि उत्पादकता 24-31

भारत में कृषि धर्मिक 120

भारत में कृषि विपणन व्यवस्था 462-

495

भारत में विभिन्न वर्षों में जनसंख्या

62-63

भारत में खाद्यान्नों की माँग एवं पूर्ति

53-57

भारत में खाद्यान्नों की कमी के कारण

60-66

भारत में खाद्यान्न उत्पादन आयात एवं

उत्पत्ति 50-52

भारत की खाद्य नीति 68

भारत में खाद्य समस्या का समाधान 66

भारत में खाद्य समस्या एवं पूर्ति के उपाय

47

भारत में ग्रामीण ऋणप्रस्तुता का

आकलन 292

भारत में गरीबी 652-660

भारत में भूमि का उपयोग 77

भारत में संचयण एवं भण्डार सुविधा का

विकास 425

भारत में सहकारिता 640-647

भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं

में खाद्य स्थिति 46-50

भारतीय अर्थव्यवस्था 21-24

भारतीय ग्रथव्यवस्था में कृषि का महत्त्व 19-21

भारतीय कृषि की विशेषताएँ 13

भारतीय कृषि में उत्पादन के कारक 76-157

भारतीय कृषि में पशुशक्ति का स्थान 18

भारतीय कृषि में पूँजी निवेश 17

भारतीय कृषि की समस्याएँ 40-44

—भूमि सम्बन्धी समस्याएँ 40

—श्रम सम्बन्धी समस्याएँ 41

—पूँजी सम्बन्धी समस्याएँ 42

—प्रबन्ध सम्बन्धी समस्याएँ 43

—अन्य समस्याएँ 43

भारतीय खाद्य निगम 532

भारत की खाद्य नीति 68

भारतीय खाद्यान्न सप्लाय संस्था 426

भारत में खाद्य समस्या 45-75

भारत में खाद्य समस्या के पहलू 57-60

—गुणात्मक पहलू 58

—आर्थिक पहलू 59

—मात्रात्मक पहलू 57

—प्रशासनिक पहलू 59

भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद 58

भारत सरकार के जनसंख्या रजिस्ट्रार जनरल 61

भारतीय मानक संस्था 490

भारतीय ऋण प्रतिभूति नियम 335

भूमि ग्रन्थशास्त्र 6

भूमि की उत्पादकता 24-30

भूमि की उर्वरा शक्ति में ह्रास 40

भूमि पर जनसंख्या का भार 18

भूमि प्रधान कृषि (विस्तृत कृषि) 263

भूमि विकास बैंक 315-318

भूमि सुधार 90-118

भूमि सुधार कार्यक्रमों की मालोचनात्मक समीक्षा 115-118

भूमि सुधार अधिनियम 304

भूमि सुधार पेनल 115

भूमि साधन की कार्यक्षमता या दक्षता ज्ञात करने के उपाय 238

भू-सीमा 106-114

भू-सीमा का निर्धारण 108

भू-सीमा निर्धारण के लाभ 107

भू-सीमा निर्धारण के विपक्ष में तर्क 108

भू-सीमा की प्रगति 114

भू-सीमा कानूनों में कमियाँ 112

भू-सीमा—भारत में 109

भूमि सुधारों के कार्यकारी दल 118

भू-धृति 91

भू-धृति पद्धति 92

भू-धृति पद्धति का वर्गीकरण 93

—जमींदारी एवं जागीरदारी 93

—रयतदारी 93

—महलदारी 93

भू-धृति की दोषयुक्त पद्धति 19, 40

भू-धृति पद्धति की समाप्ति 94

भू-राजस्व 565-570

—की विशेषताएँ 565

—की समाप्ति के पक्ष में दिए गए तर्क 568

—की समाप्ति के विपक्ष में दिए गए तर्क 569

—के गुण 565

—में आरोहीपन का गुण 570

—में अवरोहीपन का गुण 570

—में व्याप्त दोष 566

—मे सुधार के लिए सुझाव 570

— मे प्राप्ति आय 366

भौतिक जोखिम 434

‘भ’

भण्डा (बाजार) की परिभाषा 387

भण्डियों का विकास 393-395

—कार्यात्मक विकास 393

—भौगोलिक विकास 393

भण्डा समिति की आय 472

भण्डा समितियों के कार्य 471

मध्यकालीन ऋण 283

मध्यस्थों की समाप्ति 91

मन्दविष्ट 395

मन्द कीमत स्फीति 522

मन्दस्थल विकास कार्यक्रम 139

महलवारी पद्धति 93

मानकीकरण 412

माँग उत्पन्न करना 433

माँग जन्य कीमत स्फीति 522

मानव-भूमि अनुपात 41

माग 550

माँग एवं पूर्ति द्वारा कीमत निर्धारण का सिद्धान्त 551

माध्यमिक छोटे बाजार 389

मारकेटस् 387

मिश्रित कृषि 260

मिश्रित बाजार 390

मुद्रा बाजार 392

मृत कारक 155

मेट्रिक्स बीज बणिज 240

मोपम विक्रय विधि 432

मौरसी अधिकार 93

मौरसी कायतकार 94

मौरसी कीमत उतार-चढ़ाव 513

‘य’

यथार्थमूलक विज्ञान 5

यादृच्छिक नीलामी विधि 431

यात्रिक कृषि 266

योजना आयोग 585

योजना क्षितिज 233

‘र’

रक्षित ऋण 284

राजकीय कृषि 273

राज्य मण्डार गृह नियम 423

राज्य सहकारी बैंक 311

राज समिति 576

राजस्थान जमींदारी एवं विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 96

राजस्थान में जागीर प्रथा उन्मूलन 96

राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुन-ग्रहण कानून 96

राष्ट्रीय आय 31-40

राष्ट्रीय आय के अध्ययन की उपयोगिता 33

राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियाँ 33

—उत्पाद विधि 33

—आय विधि 33

—लागत विधि 33

राष्ट्रीय आय के आकलन 34-39

राष्ट्रीय कृषि आयोग 54, 55, 290
 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
 (नाबाड) 343-346
 राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन मंच
 (नाफेड) 487-489
 राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन कोष)
 343
 राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण कोष)
 343
 राष्ट्रीयकृत बैंको की प्रगति 323-328
 राष्ट्रीयकृत बैंको को कृषि ऋण के
 विस्तार में आ रही समस्याएँ 328
 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 141
 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 129, 130
 राष्ट्रीय बाजार 389
 राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान
 परिषद 54
 राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भण्डार
 गृह बोर्ड 422
 रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया 357-359
 रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के कृषि ऋण
 विभाग के कार्य 357
 रुइसेट 145
 रेलीय प्रोग्रामिंग 240
 रेलीय प्रोग्रामिंग विधि की मूलभूत
 मान्यताएँ 242
 रेलीय प्रोग्रामिंग विधि का उदाहरण 243
 रैबिग/पशुओं के चराई के फार्म 263
 रैयतवारी पद्धति 93
 रोजगार गारंटी कार्यक्रम 143

‘ल’

लघु/प्रत्यक्ष जोतों को आर्थिक जोतों
 में परिवर्तित करना 101

लघु कृषकों का विकास 621
 लघु कृषक विकास मस्याएँ 623
 लघु कृषकों की समस्याएँ 622
 लक्ष्य समीकरण 245
 लागत का सिद्धान्त 208-212
 लागत जन्य कीमत स्फीति 522
 लागत संकल्पना 250

—लागत a_1 250

—लागत a_2 251

—लागत b 251

—लागत b_1 एवं b_2 251

—लागत s , s_1 एवं s_2 251-
 252

लोक बैंक या ग्रामीण बैंक योजना 334

लेवी द्वारा छायापत्रों की वसूली 70,
 526

लोचदार मार्ग 11

‘ध’

वर्तमान कृषि विपणन व्यवस्था के दोष
 462
 वर्द्धित मूल्य 450
 वर्द्धमान प्रतिफल का सिद्धान्त 188-190
 वन भूमि (जबल) 77
 व्यक्तिगत कृषि 272
 व्यक्तिगत प्रतिभूति पर ऋण 284
 व्यक्तिगत भण्डार गृह 424
 व्यष्टिमूलक क्षेत्र 166
 व्यष्टिमूलक कीमत निर्धारण विधि 550
 वस्तुओं का बाजार 392
 वस्तुओं की माँग उत्पन्न करना 433
 वसूली (प्रतिप्राप्ति) कीमत 71
 वशागत अधिकार 84
 वशागत कानून 102

- वाणिज्यिक फसलों की घोषित न्यूनतम
समर्थित कीमतें 527
- वाणिज्यिक बंक 319-338
- व्यापारिक कृषि 272
- व्यापारिक फार्म 273
- वायदा कीमत विधि 549
- वायदा बाजार 392, 395 197
- वार्षिक कीमत उतार चढ़ाव 514
- विक्रय इकरार 153
- विक्रय माध्यम 432
- विक्रय की शर्तें 433
- विक्रय अधिरोप 400
- विक्रीत अधिरोप 400
- विकसित अर्थव्यवस्था 23
- विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था 24
- विकासशील अर्थव्यवस्था 24
- विचरण गुणांक 377
- वित्त व्यवस्था 428
- विदेशों में कृषि सहकारी विपणन संस्थाएँ
489
- विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएँ 586
- प्रथम पंचवर्षीय योजना 586
- द्वितीय पंचवर्षीय योजना 586
- तृतीय पंचवर्षीय योजना 587
- वार्षिक योजनाएँ 587
- चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 587
- पाँचवी पंचवर्षीय योजना 588
- छठी पंचवर्षीय योजना 588
- सातवी पंचवर्षीय योजना 589
- आठवी पंचवर्षीय योजना 590
- विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सांख्यिक क्षेत्र में परिवर्धित राशि 592
- विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में प्राप्त उपलब्धियाँ 595
- विभेदक व्याज दर नीति 336
- विविधकृत कृषि (सामान्य कृषि) 258
- विवेक समत क्षेत्र 177
- विवेक शून्य क्षेत्र 176
- विशिष्ट कृषि 257
- विशिष्ट बाजार 390
- विश्व बाजार 389
- विस्तृत कृषि/भूमि प्रधान कृषि 263
- विपणन अध्ययन के दृष्टिकोण 397
- कार्यात्मक दृष्टिकोण 397
- व्यवहारिक विधि दृष्टिकोण 398
- वस्तुगत दृष्टिकोण 398
- संस्थागत दृष्टिकोण 398
- विपणन उत्पादक क्रिया 384
- विपणन के वैज्ञानिक नियम 404
- विपणन कार्य 406-439
- विपणन कार्यों का वर्गीकरण 406
- विपणन की विपणन विधियाँ 430 432
- कपड़े के आवरण में गुप्त संकेतों द्वारा 430
- खुली नीलामी द्वारा विक्रय 431
- फड नीलामी विधि 431
- तालिकाबद्ध नीलामी विधि 431
- यादृच्छिक नीलामी विधि 431
- आपसी समझौते के द्वारा विक्रय 431
- नमून के द्वारा विक्रय 432
- दंडा विक्रय विधि 432
- बन्द निविदा पद्धति से विक्रय 432
- मोहम विक्रय विधि 432
- विपणन दक्षता 456-461
- से सात्पर्य 457
- के प्रकार 458
- तकनीकी/कार्यात्मक दक्षता 458

- कीमत/आर्थिक दक्षता 458
- ज्ञात करने की विधियाँ 458
- मे वृद्धि करने के उपाय 460
- विपणन-मध्यस्थ 398-399
- विपणन माध्यम 403
- विपणन-लागत 440-444
 - से तात्पर्य 440
 - के अध्ययन का महत्व 440
 - के मुख्य प्रवयव 441
 - मे परिवर्तन लाने वाले कारक 442
 - मे अधिकता के कारण 443
 - एव वस्तुओं की माँग की लोच मे सम्बन्ध 446
- विपणन-लाभ 444
 - से तात्पर्य 444
 - के अध्ययन 444
 - ज्ञात करने के तरीके 445
 - के प्रकार 448
 - पश्चाद्य विपणन लाभ 448
 - समवर्ती विपणन लाभ 448
- विपणन सूचना सेवा 437-439
 - बाजार इष्टिकोण सूचना सेवा 438
 - बाजार समाचार सेवा 438
- विपणन एव निरीक्षण निदेशालय 491
 - के कार्य 491
 - की प्रगति 492
 - का दाँचा 493
- विशेषकर 583
- ‘स’
- सकर एव बौनी बिस्म के बीजों का प्राविष्कार एव उनके अन्तर्गत क्षेत्रफल 602
- सग्रहण एव भण्डार व्यवस्था 421-428
- सग्रहण एव भण्डारण लागत 426
- सग्रहण एव भण्डारण सुविधाओं का कृषको द्वारा उपयोग नहीं करना 427
- सग्रहण की कृषि वस्तुओं मे प्रावश्यकता 421
- सघन या श्वम तथा पूँजी प्रधान कृषि 263
- सघन कृषि जिला कार्यक्रम (पैकेज कार्यक्रम) 600
- सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम 601
- सट्टा मध्यस्थ 399
- स्थानीय बाजार 389
- स्थायी पूँजी 154
- स्थायी यन्त्रीकरण 266
- स्थायी धर्मिक 123
- स्थावर सम्पदा की प्रतिभूति पर ऋण 152, 284
- सत्यापत अभिकरण 285, 299, 302
- सब्जी की कृषि 262
- स्पर्धा के अनुसार बाजार 391
- समग्र राष्ट्रीय उत्पाद 32
- समता अनुपात 549
- समता कीमत सूत्र विधि 548
- समता कीमत 549
- समान प्रतिफल का सिद्धान्त 185-188
- समपूरक उद्यम 212
- समलागत बक्र 200, 202-205
- समष्टिमूलक कीमत निर्धारण विधि 550
- समोत्पत्ति बक्र 199-205
- समवर्ती विपणन लाभ 448
- समान किस्त परिशोधन अदायगी योजना 369

समान दर से उत्पादन साधनों में प्रति-
स्थापन 196
सम आय रखाएँ 243
सम सीमान्त प्रतिफल का सिद्धान्त अथवा
सीमित साधन और अवसर परिचय
का सिद्धान्त 205-208
सम्भाव्य हला का क्षेत्र 243, 245
समझौता कानून 297
संपादित प्रतिभूति ऋण 284
संरक्षण विधि 435
संरक्षण एवं सहाय विधि द्वारा कीमत
जोखिम कम करना 435
सरकार द्वारा एकाधिकार क्रय प्रथा 70
सरकार की मौद्रिक नीति 518
सरकार की राजकोषीय नीति 519
सरकार की व्यापार एवं प्रशुल्क नीति
520
सरकारी भण्डार गृह 425
संरचनात्मक बेरोजगारी 127
सम्पूर्ण फार्म योजना एवं बजट 229
स्वतः परिस्थितिपूर्ण ऋण 366
स्वतः रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों
का प्रशिक्षण (Trysem) 627
स्वतन्त्र उद्यम/असम्बन्धित उद्यम 212
सर्वेष्ठन (पंक्तिगत) 408-409
साझे की कृषि (बटाई प्रणाली) 280
साधनों की लागत के अनुसार राष्ट्रीय
आय 32
साधनों/क्रियाओं के प्रतिस्थापन का
सिद्धान्त या न्यूनतम लागत का
सिद्धान्त 193-205
माधारण बाजार 390
सामान्य कीमत/दीर्घकालीन कीमत 559
सामान्य या विविधकृत कृषि 259
सामूहिक कृषि 278-279
मार्पेक्ष (तुलनात्मक) लाभ 225
सहकारी उन्नत कृषि 274

सहकारी कृषि 274-278
सहकारी कायंकारी कृषि 276
सहकारी कृषि का कार्यकारी दल 274
सहकारी ग्राम प्रबन्ध 114
सहकारी भण्डार गृह 425
सहकारी सामूहिक कृषि 101, 276
सहकारी संयुक्त कृषि 101, 275
सहकारी विपणन समितियाँ 478-490
—तात्पर्य 478
—के कार्य 479
—की व्यापार पद्धति 480
—की प्रगति 482
—की सदस्यता 480
—की पूर्णता 480
—का ढाँचा 480
—से कृषकों को लाभ 481
—का स्तूपकार ढाँचा 480
—की प्रगति के क्षेत्र में बाधक
कारक 485
—के विकास के लिए सुझाव 487
सहकारी ऋण समितियाँ 305-315
सहकारिता 640-647
—से तात्पर्य 640
—के सिद्धान्त 641
—में सम्मिलित व्यक्तियों के गुण
641
—से लाभ 642
—की प्रगति में बाधक कारक
645
सहकारी संस्थाओं का ढाँचा 642
सहकारी समितियों का वर्गीकरण 644
सहकारिता के विकास के लिए सुझाव
647
सहकारिता का भारत में इतिहास 643
सहायक (पूरक) उद्यम 214
सहायता कीमत 73

साहूकार 353-356

—कृषक साहूकार 354

—पेशेवर साहूकार 354

साहूकारों के पंजीयन एवं अनुज्ञापन
प्राप्त करने का कानून 298

सिंचाई कर 583

सिंचित कृषि 263

स्थिर (बन्धी) लागत 208

सीमित पूंजी 224

सीमान्त आय 180

सीमान्त उत्पाद 173

सीमान्त उत्पाद एवं औसत उत्पाद में
सम्बन्ध 175

सीमान्त लागत 180

सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक श्रमि-
करण 140

सीमित साधन और अवसर परिव्यय
अथवा सम सीमान्त प्रतिफल का
सिद्धान्त 205-208

सुद्ध/ठोस कृषि ऋण व्यवस्था के गुण
285

सुदीर्घकालीन कीमत उतार-चढ़ाव 514

सुदीर्घकालीन बाजार 390

सुधार कर 582

सूखा सम्भावना वाले क्षेत्रों के लिए
कार्यक्रम 139

सेवा-निवृत्त व्यक्तियों के लिए स्वतः
रोजगार उपलब्ध कराने का कार्यक्रम
347

सौदागर मध्यस्थ 398

‘श’

शहरी गरीबों के लिए स्वतः रोजगार
कार्यक्रम (सीपुर) 347

शिक्षण सहकारी विपणन समितियाँ 481

शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वतः
रोजगार योजना (सीयु) 346

शीघ्रनाशी कृषि वस्तुओं में अति-अल्प-
कालीन कीमत ज्ञात करना 555

शीघ्र विनाशशील कृषि वस्तुओं के समु-
चित विपणन के लिए सुझाव 477

शुद्ध फार्म आय 252

शुद्ध पैमाने का सम्बन्ध 191

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद 32

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (राष्ट्रीय आय बाजार
कीमत पर) 32

शुष्क कृषि 264

शुष्क कृषि का केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान
265

शुष्क भूमि कृषि समन्वय अनुसन्धान
प्रोजेक्ट 265

शुष्क भूमि कृषि 624

‘ह’

हमाल 399

हरित-क्रान्ति 617-641

—से तात्पर्य 617

—का आर्थिक प्रभाव 618

—का कृषि क्षेत्र का प्रभाव 618

—हरित क्रान्ति का सामाजिक
प्रभाव 619

—का प्रादुर्भाव 617

हरित क्रान्ति का कृषि श्रम की माँग पर
प्रभाव 148

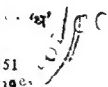
—हाजिर बाजार 392

हासमान किम्त परिशोधन प्रदायणी
योजना 370

हासमान प्रतिफल का सिद्धान्त 177-185

हासदार से उत्पादन साधनों में प्रति
स्थापन 198

हिसाब नियन्त्रण कानून 298



- श्रम 118-151
 श्रम प्रजनन 219
 श्रम प्रयत्नास्त्र 6
 श्रम अवशोषण 134
 श्रम उत्पादकता 30-31
 श्रम तथा पूँजी प्रधान कृषि 263
 श्रम प्रतिस्थापन पूँजी 155
 श्रमिक 118
 श्रमिकों का भूमि पर भार 41
 श्रमिकों की कार्यकुशलता 124
 श्रमिकों की कार्यकुशलता को प्रभावित करने वाले कारक 124
 श्रमिकों के श्रम द्वारा कृषि 272
 श्रम साधन की कार्यकुशलता ज्ञात करने के उपाय 239
 श्रेणी के अनुसार बाजार 391
 श्रेणीचयन (श्रेणीकरण) 412-421
 —के उद्देश्य 414
 —के प्रकार 414
 —के लाभ 413
 —के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने की विधि 415
 —के लिए श्रेणी निर्देश 416
 —के लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा दिए गए सुझाव 420

—की गई वस्तुओं को क्रय में उत्पादकों द्वारा प्राथमिकता नहीं देना 419

—में आने वाली परेशानियाँ 418

श्रेणी निर्देश 412

क्षेत्रीय एकीकरण 456

क्षेत्रीय/प्राचलिक प्रामीण बैंक 339-343

क्षेत्रीय बाजार 389

‘श्रु’

श्रुण-प्रदायगी योजना 369

श्रुण-प्रदायगी क्षमता 362, 364

श्रुण-प्रबन्ध के पाँच ‘पी’ 361

श्रुण-प्रबन्ध के चार ‘सी’ 361, 378

श्रुण-प्रबन्ध के तीन ‘भार’ 361

श्रुण-प्रबन्ध के सिद्धान्त 361-379

श्रुण-प्रबन्ध के सिद्धान्तों की जाँच करने की विधि 363-378

श्रुण परिशोधन योजना में श्रुण चुकाने की किश्त राशि ज्ञात करना 371

श्रुण समझौता कानून 298

श्रुणी की जोखिम वहन योजना 362

श्रुण की आवश्यकता 287

